ત્રીજી શ્રેણી)

પુસ્તક : ૧૦૯

ગુરૂવાર, તા.૧૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫
માઘ ૨૮, ૧૯૨૬ શાકે

થી

મંગળવાર, તા.૨૨ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫
ફાલ્ગુન ૩, ૧૯૨૬ શાકે

ગુજરાત વિધાનસભા

ચર્ચાઓ

સત્તાવાર અહેવાલ

અગિયારમી ગુજરાત વિધાનસભા

સાતમું અધિવેશન

ગુજરાત વિધાનસભાના અધિકાર હેઠળ પ્રકાશિત

ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય

ગાંધીનગર

અ નુ ક્ર મ ણિ કા

વિષય	પાના નંબર
ગુરૂવાર, તા.૧૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ / માઘ ૨૮, ૧૯૨૬ શાકે	
રાજયપાલશ્રીનું સંબોધન	૧ - ૩૪
રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ	૩૫ - ૩૫
શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૩૬ - ૪૯
સભાગૃહની બેઠક મુલતવી રાખવા અંગેનો પ્રસ્તાવ	૫૦ - ૫૧
શુક્રવાર, તા.૧૮મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ / માઘ ૨૯, ૧૯૨૬ શાકે	
તારાંકિત પ્રશ્નો	૫૨ - ૭૮
અતારાંકિત પ્રશ્નો	૭૯ - ૧૬૨
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો	૧૬૩ - ૧૬૪
અંદાજપત્રની રજૂઆત	૧૬૫ - ૧૮૪
સોમવાર, તા.૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ / ફાલ્ગુન ૨, ૧૯૨૬ શાકે	
તારાંકિત પ્રશ્નો	૧૮૫ - ૧૯૯
અતારાંકિત પ્રશ્નો	૨૦૦ - ૨૬૦
શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૨૬૧ - ૨૬૧
તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (નિયમ-૧૧૬)	૨૬૨ - ૨૬૨
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો	૨૬૩ - ૨૬૪
ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૬૫ - ૨૬૬
મુંબઈનું વજન અને માપ (અમલ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૬૭ - ૨૬૭
ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)(સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૬૮ - ૨૭૧

અ નુ ક્ર મ ણિ કા

વિષય **પાના નંબર**

સોમવાર, તા.૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ / ફાલ્ગુન ૨, ૧૯૨૬ શાકે

વિષય	પાના નંબર
મુંબઈ માપબંધી સંબંધી (તૈયારી ઓ તે ચાલુ રાખવા બાબતાન) ઉપાય બાબત (ગ	૨૭૨ - ૨૭૨
ભારત સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક ૨૦૦૫	૨૭૩ - ૨૭૪
મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૫ - ૨૯૦
વટહુકમ નામંજૂર કરતા પ્રસ્તાવો અને સરકારી વિધેયકો	૨૯૧ - ૨૯૧
મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.	૨૯૨ - ૨૯૩
ધાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનો) (રદ કર	૨૯૪ - ૨૯૪
મુંબઈનો બિન-વ્યાપારી કોરપોરેશનો (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૯૫ - ૨૯૫

મંગળવાર, તા.૨૨ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ / ફાલ્ગુન ૩, ૧૯૨૬ શાકે

પહેલી બેઠક

વિષય	પાના નંબર
રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૨૯૬ - ૩૨૮
પૉઈન્ટ ઑફ ઑર્ડર	૩૨૯ - ૩૨૯
રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેનાઆભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૩૦ - ૩૩૨

બીજી બેઠક

વિષય	પાના નંબર
તારાંકિત પ્રશ્નો	૩૩૩ - ૩૪૪
અતારાંકિત પ્રશ્નો	૩૪૫ - ૪૨૨
તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (નિયમ-૧૧૬)	૪૨૩ - ૪૨૪
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો	૪૨૫ - ૪૨૫
રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૨૬ - ૪૫૨

****

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુરૂવાર, તા.૧૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫
માઘ ૨૮, ૧૯૨૬ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧-૪૦ વાગ્યે મળ્યું.
અધ્યક્ષશ્રી પ્રો.મંગળભાઈ પટેલ અધ્યક્ષસ્થાને
(સભાગૃહની બેઠકની શરૂઆત "વંદે માતરમ્" સંગીતની ધૂન વગાડી કરવામાં આવી.)

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો

રાજયપાલશ્રીનું સંબોધન

સચિવશ્રી: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે નામદાર રાજયપાલશ્રીએ બંધારણની કલમ ૧૭૫(૧) અન્વયે ગુજરાત વિધાનસભાને સંબોધન કર્યુ હતું. નામદાર રાજયપાલશ્રીએ કરેલ સંબોધનની પ્રમાણિત નકલ મને મળી છે જે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની હું રજા લઉં છું.

નામદાર રાજયપાલશ્રીએ કરેલા સંબોધનની નકલ સભાગૃહના મેજ પર મૂકવામાં આવી.

રાજયપાલશ્રીનું સંબોધન

श्री नवलकिशोर शर्मा (महामहिम राज्यपाल श्री): माननीय अध्यक्ष महोदय एवं विधान सभा के सदस्यों,

ग्यारहवीं विधान-सभा के सातवें अधिवेशन के मंगल प्रारंभ के समय पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

इस गौरवान्वित सदन को सम्बोधन करने का यह मेरा पहला अवसर है । इस सदन ने लोकतान्त्रिक उच्च प्रणालियाँ प्रस्थापित करने में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। यह प्रथम अवसर मेरे जीवन में अपूर्व आनंद देने वाला है, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए मैं इस अधिवेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ।

जैसाकि आपको सुविदित है, यह अधिवेशन मुख्यत: वर्ष 2005-2006 का बजट, चालू वर्ष का संशोधित बजट तथा उसके लिए पूरक माँगे पेश करने तथा बजट प्रस्ताव सम्बन्धी करने के वैधानिक कार्य और अन्य संसदीय कार्य के लिए बुलाया गया है।

महात्मा गाँधी तथा लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की यह जन्मभूमि तथा कर्म भूमि पर उनकी विचाराधारा का अनुसरण करके ग्राम - स्वराज से लेकर रामराज्य तक का विकास का मार्ग प्रशस्त किया है और इसकी विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियाँ हासिल करके सारे देश एवं विश्व में अपना अलग प्रभाव उत्पन्न किया है। विकास की यह यात्रा 21 वीं सदी में अब समग्र देश के लिए दिशा बनी है और इसी लिए ही मेरी सरकार गुजरात का विकास वह राष्ट्र का विकास - इस मंत्र को अपनाकर विकास की गति अनवरत चालू रखने के लिए कटिबद्ध है।

<u>जल शक्ति</u>

सरदार सरोवर परियोजना बाँध की ऊँचाई 110.64 मीटर तक पूर्ण हुई है और केनाल हेड पावर हाउस द्वारा अगस्त-2004 में बिजली उत्पादन शुरू हुआ। 200 मेगा वाट की क्षमता वाला भूगर्भ जल बिजली केन्द्र जनवरी-2005 में कार्यान्वित हुआ और बिजली उत्पादन का शुभारंभ हुआ है।

जल ही जीवन है, ऐसे मंत्र को अपनाकर मेरी सरकार ने पानी को सहज तरीके से उपलज़्य बनाने के लिए राज्य की कुछ नदियों का अन्तर्राज्य संयोजन का कार्य हाथ में लिया है, जिसके अन्तर्गत, नर्मदा मुज़्य नहर को पार करने वाली मुज़्य 10 नदीयों में नर्मदा का पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण रिवर ग्रीड के लिए गुजरात देश में प्रथम राज्य बना है। नर्मदा नदी की बाढ़ के पानी से सौराष्ट्र क्षेत्र की 17 नदीयों तथा जलाशय भरने के लिए अनुमानत: 515 करोड़ रूपये की लागत की योजना को राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमति देकर ज़िल के कुल 107 चैकडेम सज़्बन्धी कार्य-प्रक्रिया हाथ में ली है।

- राज्य के दक्षिण एवं मध्य गुजरात क्षेत्र में लगभग 71 प्रतिशत, सौराष्ट्र में 16 प्रतिशत, उत्तर गुजरात में 11 प्रतिशत, कच्छ में केवल 2 प्रतिशत जल है, फिर भी, अब तक राज्य में सिंचाई के सभी प्राप्ति-स्थानों में से कुल 40.00 लाख हेक्टर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तगर्त शामिल किया गया है।

- सरदार पटेल सहभागी जलसंचय अन्तर्गत औसत 2 से 3 लाख रू. की लागत से 50,000 चैकडेम निर्मित किये गये हैं।

- औद्योगिक गृहों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सक्रिय सहकार से नदियों पर औसत 30 से 40 लाख रू. की लागत के बड़े 100 चैकडेम का निर्माण किया गया है और 500 बड़े चेकडेमों के निर्माण के लिए विविध चरण का कार्य प्रगति में है।

- जिन स्थानों पर चैकडेम के लिए अनुकूल स्थान न हो वहाँ पर तालाबों को गहरे करने के कार्य के अन्तर्गत,1500 से अधिक तालाब गहरे बनाये गये हैं।

<u>सुजलाम् सुफलाम् योजना</u>

पानी का अभाव तथा भूगर्भ पानी खींचे जाने से राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न होने पाए तथा राज्य की विकास गाथा आगे बढती रहे, इस उद्देश्य के साथ, सिंचाई और जल स्राव के लिए 4291 करोड़ रू. तथा पेयजल के लिए 1946 करोड़ रू. मिलाकर अनुमानत: कुल 6237 करोड़ की लागतवाली सुजलाम् सुफलाम योजना राज्य सरकार ने कार्यान्वित की है।

इस योजना के कार्यान्वयन से भूगर्भ जल की अधिक खींचनें का काम होने के कारण कच्छ सहित उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में से अकाल को हमेशा देशनिकाला मिलेगा, उतना ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के 4904 गाँवों के लिए पेयजल की समस्या हल होगी और जलसंचय कार्यों से खरीफ फसल बचेगी और अनेक गाँवों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति मिलेगी।

<u>पेयजल</u>

मेरी सरकार गुजरात की जनता को पीने योग्य पानी मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है।

राज्य के अभावग्रस्त इलाकों को पेयजल मुहैया कराने के लिए सरदार सरोवर नहर आधारित जल आपूर्ति योजना कार्यान्वित की है, जिसके ज़रिये 1343 कि.मीटर बल्क पाइप लाइन और 31 डिस्ट्रीब्युशन ग्रुप नेटवर्क का कार्य पूरा किया गया है और अहमदाबाद के भाल क्षेत्र, भावनगर, अमरेली, राजकोट, जामनगर, जूनागढ और कच्छ ज़िलों के 1826 गाँवों और बावन शहरों तक नर्मदा का पानी पहुँचाया गया है तथा अमरेली, अहमदाबाद,भावनगर, राजकोट,जामनगर, जूनागढ तथा कच्छ ज़िलों में अधिक 1774 गाँवों को नर्मदा का पानी पहुँचाने के लिए 336 कि. मी. लंबाई की बल्क पाइप लाईन और 30 डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क कार्य प्रगति में है। इस प्रकार, पेय जल की कठिनाई दूर करने के इस योजनागत आयोजन के अलावा विविध कदम उठाये हैं जैसे कि

- 20 सूत्र के तहत ***पीने का स्वच्छ पानी*** कार्यक्रम के अन्तर्गत, 600 गाँवों/फलियों के लक्ष्य की तुलना में 559 फलियों को दिसम्बर 2004 तक पानी की सुविधा में शामिल किया गया है।

- 873 करोड रू. के अनुमान वाली 86 ग्रामीण ग्रुप जल आपूर्ति योजनाओं में से 1185 फलियों को पेयजल देना शुरू किया गया है। बाकी फलियों को पेयजल देने की योजना प्रगति में है।

- जनजाति क्षेत्र के 2000 हैन्ड पंप के लक्ष्य सहित 3044 के लक्ष्य की तुलना में, 6781 हैन्ड पंप तथा 111 मीनी पाइप योजना दिसम्बर-2004 तक पूर्ण की गई है।

- भूकम्प से प्रभावित जल आपूर्ति योजनाओं के पुन:निर्माण तथा पुनर्वास के लिए 812 करोड़ रू की विशाल योजना, परिणाम-लक्षी हो रही है। इस योजना के 51 पैकेजों में से जों का कार्य पूर्ण हुआ हैं। 21 पैकेजों का कार्य प्रगति में है।

<u>कल्पसर</u>

21 वीं सदी के गुजरात के सर्वांगी विकास को पूर्ण करने की कल्पना से कल्पसर योजना का निर्माण हुआ है । इस योजना के विविध पहलूओं का सर्वेक्षण पूर्ण होने को है और अब दूसरे चरण में भूस्तरीय प्रभाव, भूस्तरशास्त्री अन्वेषण और उसके सामाजिक प्रभावों सहित भूमि सर्वेक्षण का प्रारंभ हुआ है।

<u>ज्ञान शक्ति</u>

मेरी सरकार शिक्षा क्षेत्र में राज्य को अग्रिम बनाने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य में जो शिक्षकों के पद रिकत थे, उन्हें 80,477 विद्यासहायकों की नियुकित से भरा गया है। राज्य की स्कूलों में प्रयोगशाला, वांचनालय, खेलकूद के साधन, नई बेन्चे, फर्स्ट ऐइड बोक्स तथा कम्प्यूटर मुहैया किये जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में सेनीटेशन संकुलों को बिजली की सुविधा, पेयजल की सुविधा और कम्पाउन्ड वोल बनायी गई है। इसके अलावा राज्य सरकारने निम्न लिखित कार्यवाही भी की है।

- साक्षरदीप कार्यक्रम द्वारा 14 दिवस तक 29,871 प्रशिक्षणार्थियों तथा 1,07,000 प्राथमिक शिक्षकों की सहायता से विशेष अभियान के ज़रिये निरक्षरों को शिक्षित बनाया गया।

- वांचन-लेखन-गणन अभिवृद्धि अभियान के दौरान बालकों की क्षमता में वृद्धि करने का एक सुन्दर कार्यक्रम भी चालू वर्ष में किया गया ।

- रतन टाटा ट्रस्ट और आइ.आइ.एम. के सहयोग से सारे देश में से 58 श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन किया गया, जिनमें से 30 शिक्षक गुजरात के हैं। यह गुजरात के लिए गौरव की बात है।

- एज्युसेट का अधिकतम उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समग्र देश में गुजरात को पसंद किया गया है और उसके बारे में कारवाई गति में है।

- पंचमहाल, डांग, कच्छ, वलसाड, सूरत, दाहोद तथा जामनगर के प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा के शिक्षकों को लोकबोली का प्रशिक्षण देकर बालक को अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देना शुरू किया गया हैं।

<u>कन्या शिक्षा</u>

कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालक्ष्मी बोन्ड की योजना के अमल के साथसाथ राज्य की स्थापना के बाद, मुख्यमंत्री को प्राप्त भेंट-सौगात का नीलाम करने से प्राप्त हो रही रकम कन्या शिक्षा के लिए दी जाती है। देश में ऐसा प्रेरणादायी प्रयोग करनेवाली मेरी सरकार ही है। जून, 2004 के दौरान, 20 प्रतिशत से कम साक्षरतावाले 2000 गाँव सहित 7765 अंदरूनी गाँवों में माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रीमंडल के सभी सदस्य और

वरिष्ठ अधिकारियों ने कन्या शिक्षा रथयात्रा आयोजित करके कन्या शिक्षा को उत्तेजन देने के लिए शाला प्रवेश उत्सव मनाया था। गुजरात कन्या शिक्षा निधि की रचना की है, जिसमें रू.280 लाख दान में मिला । राज्य के कन्या शिक्षा में पिछड़े 78 तालुका तथा 13 शहरी झोंपडियों वाले क्षेत्रों में नेशनल प्रोग्राम फार गर्ल्स एट एलिमेन्टरी लेवल (NPEGEL) का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

मेरी सरकारने, चालू वर्ष में 8 नये सरकारी इंजीनियरी कॉलेज, 3 स्व-निर्भर इंजीनियरी कॉलेज, 11 फार्मसी कॉलेज, 1 स्व-निर्भर पोलिटेकनिक, 8 एम.बी.ए. कॉलेज तथा 3 एम.सी.ए. कॉलेज शुरू करके 4,806 सींटे बढ़ाई हैं। इसके अलावा, बायो-मेडिकल तथा ओटोमोबाइल का डिग्री कोर्स भी शुरू किया है, उद्योगों एवं समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर डिप्लोमा पाठयक्रम नये सिरे से पुन:गठित किये जा रहे हैं। राज्य के पाँच डिग्री इंजीनियरी कॉलेज और दो पोलिटेकनिक संस्थाओं का आधुनिकीरण शुरू किया गया है। केनेडा-इन्डिया इन्स्टिटयुट इन्डस्ट्रीज लिन्केज प्रोजेकट के तहत कुल 13 संस्थाओं को व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण में शामिल किया गया हैं।

सोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि मेरी सरकार ने आगामी वर्ष से क्रियान्वित हो जाय उस तरह से सोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय किया है। संस्कृत भाषा जो हमारी प्रांचीन सुविकसित और राष्ट्र की धरोहर है, उसके प्रसार के लिये मेरी सरकार प्रतिबद्ध है।

मानव संसाधन विकास

राज्य की प्रशिक्षण देने वाली ***सरदार पटेल राज्य वहीवट भवन*** (S.P.I.P.A.) संस्था अपनी कार्यशैली में व्यावसायिकता ला सके और मुकाबला कर सके उसी उद्देश्य से उन्हें सम्पूर्ण स्वायत्तता दी है। इस संस्था के जरिए राज्य के विकास की चुनौतियों का सामना करने और कर्मचारी केवल एक तालीमबद्ध कर्मचारी ही नहीं, बल्कि सही अर्थ में कर्मयोगी का निर्माण हुआ है। इस के अलावा इस तालीम को एक उपयोगी और निपुण साधन मानकर ऐसी नई योजना शुरू की है। ताकि श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के राजपत्रित अधिकारियों को प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम तीन दिनों का प्रशिक्षण मिल सके।

राज्य के प्रशासन में क्रियात्मक तथा भाावनात्मक योगदान को प्रोत्साहित करने तथा उनके साथ भावनात्मक सम्बन्ध/सेतु बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारने राज्य के 5 लाख अधिकारियो/ कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाकर उनके दिलमें लोक सेवा की भावना पैदा करने के लिए सुझाव प्राप्त किये हैं। कर्मचारियों में पहलवृत्ति पैदा करके उन्हें अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मूल उद्देश्य है ।

वाइड एरिया नेटवर्क (जीस्वान)

मेरी सरकारने, ज़िला और तालुका मुज़्यालयों के 1400 कार्यालयों को जोड़कर 11 कार्यरत सर्वरों के साथ सर्वर फार्म की सुविधा के साथ, जीस्वान के तहत एशिया में सब से बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, जिसमें 108 वेबसाइट फिलहाल सफलतापूर्वक कार्यरत हैं।

सायन्स सीटी

मेरी सरकार ने अहमदाबाद के निकट विश्व स्तर की सायन्स सिटी की स्थापना की है, जो 21 वीं सदी में आधुनिक विज्ञान का यात्रा धाम बनी हैं, जहाँ प्रथम चरण में आइमेकस 3 डी थियेटर, चिल्ड्रन एक्टीवीटी सेन्टर,एज़्फ़ी थियेटर तथा एशिया में सब से बड़ा ज़्युजिकल फाउन्टेइनका लोकार्पण किया गया है।

पिछले वर्ष के प्रथम नव मास में 2,50,000 से अधिक लोगों ने सायन्स सिटी की मुलाकात ली हैं।

बायोटेकनोलोजी

गुजरात स्टेट बायोटेकनोलोजी मिशन को स्वायत्त संस्था के रूप में, राज्य में बायोटेकनोलोजी क्षेत्र के विकास के लिए, आयोजन, कार्यान्वयन और नीतियाँ तथा कार्यवाही का संकलन करने की जिज़्मेदारी सौंपी गई है। जिसके भाग के रूप में बडौदा में एक बायोटेकनोलोजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार का कदम उठानेवाला हमारा गुजरात समग्र देश में प्रथम सदस्य हैं।

अनिवासी भारतीय प्रभाग

गुजरात की प्रतिष्ठा को विदेश में पहुँचाने के लिए तथा एक दूसरे के दृष्टिबिंदु समझने तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिए गुजरात राज्य अनिवासी गुजराती प्रतिष्ठान कार्यरत है। अनिवासी गुजराती गुजरात के विकास में और विशेषकर अपने वतन के गाँव के विकास के क्रियाकलापों में सहभागी हो सकें, इसलिए ***वतन सेवा की विविध योजनाएँ*** के बारे में जानकारी प्रकाशित की हैं।

ऊर्जा शक्ति

राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए, बिजली आधारभूत आवश्यकता होने के कारण, मेरी सरकारने उपभोकता के संतोष के लिए अनेक कदम उठाये हैं।

पिछले वर्ष के दौरान राज्य की बिजली क्षमता 8683 मे.वाट की थी । चालू वर्ष के दौरान, केनाल हेड पावर हाउस की पाँच इकाइयाँ सरदार सरोवर निगम द्वारा कार्यान्वित की गई है। इसके अलावा राज्य के खनिज विकास निगम का 250 मे.वा. का लिग्नाइट आधारित अक्रीमोटा स्थित बिजली प्लांट शीध्र ही कार्यान्वित होने वाला हैं। जिसके कारण, बिजली निर्माण क्षमता में काफी वृध्धि होगी । पान्ध्रो में गुजरात विद्युत बोर्ड की 75 मे.वाट की लिग्नाइट आधारित इकाई का काम शुरू भी हो चुका हैं।

राज्य के विद्युत बोर्ड के विविध प्रयासों के फलस्वरूप, बिजली प्रवाहन और बिजली वितरण में होने वाला घाटा वर्ष 2002-2003 में 28.8 प्रतिशत था वह 2.3 प्रतिशत कम हुआ हैं।

ज्योतिग्राम योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे थ्री फेज पावर मुहैया कराने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने ***"ज्योतिग्राम योजना"*** कार्यान्वित की है और यह बतलाते हुए मुझे खुशी होती हैं कि अब तक 7000 गाँवों को इस योजना में शामिल किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप, ग्रामवासियों का जीवन-स्तर ऊपर आया हैं, रोज़गारी के नये अवसर बढ़ाने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं देने में सहायक हुआ हैं। जिससे राज्य के तमाम गाँवों को निश्चित कालावधि में ज्योतिग्राम बनाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है, उतना ही नहीं बल्कि बिजली क्षेत्र में सुधार करने की प्रवृत्ति आगे बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने गुजरात बिजली उद्योग (पुन:गठन और नियमन) अधिनियम, 2003 के तहत बिजली क्षेत्र में राज्य के विकास की जरूरत परिपूर्ण करने के लिए गुजरात विद्युत बोर्ड का पुन:गठन करके सात कज़्पनियों की रचना करके कारगर ढाँचा प्रस्थापित किया हैं।

गैस-पेट्रोलियम

यह बतलाते हुए मुझे आनंद होता है कि राज्य के पेट्रोलियम कारपोरेशनने, एक नई संशोधन लाइसेंस नीति के अन्तर्गत, नीलाम की बोली के दूसरे राउन्ड में, गेइल के साथ मे संयुक्त साहस के तहत, धोलका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल की मात्रा में से धन पैदा करने की कार्रवाई हाथ में ली हैं।

मेरी सरकार के दूरदर्शी अभिगम तथा सक्रिय सहयोग से यह संभव हुआ है, जो गौरवपूर्ण है।

मेरी सरकारने, राज्य में गेसग्रीड के काम में गति लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। यह बतलाते हुए मुझे आनंद होता है कि अहमदाबाद - कलोल तक गैस पाइप लाइन नेटवर्क कार्य पूर्ण हुआ हैं।

इसके अतिरिक्त दहेज में हाल ही में शुरू किये गये एल.एन.जी टर्मिनल (पेट्रोनेट एलएनजी) में से 10 लाख टन रीगेसीफाइड प्रवाही कृत प्राकृतिक गैस के आबंटन के कारण बिजली और रसायनिक खाद के क्षेत्र में राज्य के महत्त्वपूर्ण उद्योगों को अधिक मात्रा में गैस की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अलावा, सीएनजी के वितरण के कारण अहमदाबाद के पर्यावरण में व्यापक सुधार होगा। मुझे खुशी है कि अब गुजरात देश का पेट्रो-केपिटल बन रहा है। इस प्रकार गुजरात की अर्थ-व्यवस्था में गैस महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

रक्षा शक्ति

मेरी सरकार राज्य की जनता को राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण प्राप्त कराने हेतु असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों के विरुद्ध निरंतर सर्तकता बरत रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, पिछले दो बर्षो में क़ानून और व्यवस्था की स्थिति प्रभावकार ढंग से नियंत्रण में रही हैं। परिणाम स्वरूप, प्रत्येक सम्प्रदाय के धार्मिक उत्सव मेले तथा त्योहोरों को, लाखों लोगों की उपस्थिति में सम्पूर्ण शांतिपूर्वक मनाना संभव हुआ हैं। इसके अलावा, पुलिस आवास के कार्य में काफी सुधार हुआ हैं। इसके अतिरिकित, 6000 पुलिस कर्मचारियों तथा उनके 2,50,000 परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया हैं। लीज़ लाइन की कनेकटीवटी का काम शीध्र ही पूर्ण होगा। राज्य के सभी पुलिस थानों का कम्प्युटराइज़ेशन किया गया हैं।

परिवहन

मोटर वाहन विभाग के आधुनिकीकरण के भाग के रूप में, नवम्बर-2004 तक 35,74,275 स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस तथा दिसम्बर-2004 तक 2,59,169 कार्ड रजिस्ट्रेशन बुक दी गई हैं। सडक दुर्धटना के बारे में राज्य सरकार चिन्तित है और इस के लिए चार लेन (चर्तुमार्गी) रास्तों का निर्माण किया गया है ।

जेल

मानवीय अभिगम दिखलाकर 70 वर्ष से अधिक उमर के पुरूष कैदियों तथा तमाम महिला कैदियों के दिवाली के अवसर पर 10 दिन का पैरोल मंजूर किया गया था । राज्य की विद्यमान जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या के बारे में राज्य सरकार चिन्तित है। जिस से वडोदरा, पालारा, गारियाधर, गोंडल, दाहोद, अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में नई जेलों के निर्माण कार्य शुरू किया गया हैं और सूरत ज़िले में लाजपार में नई जेल के निमार्ण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया हैं।

न्यायतंत्र

राज्य के लोगों को शीध्रता से न्याय दिलाने के लिए 166 फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना करने के निर्णय की तुलना में हाल में 159 फास्ट ट्रेक कोर्ट चालू होने के कारण 23,000 से अधिक मामलों का तथा विधि प्राधिकरण द्वारा लोक-अदालतें करके कुल 21 लाख मामलों का निबटारा किया गया हैं।

मेरी सरकारने जेल और न्यायालय के बीच विडियो कोन्फरन्स से न्यायालय का काम चलाने का शुरू करके अद्यतन टेकनोलोजी के उपयोग से कार्यवाही सरल बनाई हैं।

पर्यावरण

मेरी सरकारने चालू वित्तीय वर्ष में कलीनर प्रोडकशन प्रोजेकट के तहत राज्य के विविध उद्योगों में निर्माण प्रक्रिया के दौरान होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं, जिन में उद्योगों की ओर से अलग अलग आवेदन-पत्र देने के बजाय "कोमन कन्सेन्ट और ओथोराइज़ेशन" सीसीए का अमल, स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स समिति द्वारा समीक्षा, गंदे पानी के शुद्धीकरण के बारे में 5124 प्लांट, जैविक-चिकित्सा कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निबटारा करने के लिए सामूहिक स्तर पर 11 स्थानों पर योग्य सुविधा आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के जरिये पर्यावरण के बारे में जनजागृति लाने तथा उसका प्रसार करने का निर्णय किया गया हैं।

स्वास्थ्य

प्राकृतिक या मानवसर्जित आपत्तियाँ जैसी दुर्धटनाग्रस्त मरीज़ों को आर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जरी वगैरह जैसी चिकित्सा जगत की अनेक शाखाओं की तेज़ तथा सधन चिकित्सा उपलज़्य कराने के उद्देश्य से चालू वर्ष में अहमदाबाद में ट्रौमा सेन्टर की स्थापना की है और मुज़्य 10 अस्पतालों को जोड़कर इमर्जन्सी मेडिकल सर्विसीस का प्रोजेकट शुरू किया है।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, लगभग एक करोड़ बालकों को परीक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है और दृष्टि कार्यक्रम के अन्तर्गत, 24178 बालकों को चश्मों का नि:शुल्क वितरण किया गया हैं। राज्य में पोलियो का एक भी केस नहीं है। राज्य के अस्पातालों में आधुनिक टेकनोलोजी के उपयोग से सुधार किया गया हैं।

राज्य में कुष्ठरोग निमूर्लन कार्यक्रम के प्रभावकारी अमल से, इस रोग से पीड़ित रोगियों की राष्ट्रीय औसत दर प्रति 10,000 की जन संज़्या में 2.6 की है, जिसे 0.86 तक नीचे लाइ गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस उपलब्धि की भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने भी सराहना की है और गुजरात को मोडल स्टेट मानकर अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने के लिए आहवान भी किया हैं।

राज्य में 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तीन अधिक विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलज़्य कराकर, इन केन्द्रों को ज़िला स्तर के अस्पातालों की श्रेणी में रखकर स्वास्थ्य सेवा को सघन बनाया गया हैं।

मातृ वंदना

स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कदम के तौर पर सगर्भा ज़्हिलाओं की देख-भाल के लिये एवम् उनको आवश्यक पोषण मुहैया कराने के लिये, मेरी सरकार ने मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किया है। जिसका बहुत ही अच्छा प्रतिभाव प्राप्त हुआ है। इस योजना द्वारा मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कम होगी।

श्रम और रोज़गार

ओद्योगिक क्षेत्र में शांति के लिए गुजरात राज्य का स्थान प्रथम पंकित का हैं।

असंगठित क्षेत्रों में काम करनेवाले श्रम योगियों के लिए एक विशेष सेल तैयार किया गया है। उनकी समस्याओं के प्रति ध्यान देने के लिए उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है।

श्रमिक कानून के तहत संगिठत क्षेत्र के श्रमिकों के जो अधिकार हैं उन पर बिना प्रतिकूल प्रभाव किये, क़ानून में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारने पहल की है।

स्थानीय श्रमिकों की 85 प्रतिशत रोजगारी अनिवार्य बनाने तथा रात्रि के समय में महिला श्रमिकों को काम करने से अमुक शर्तों को अधीन रहकर छूट देने वाला संशोधन किया गया है। भवन और अन्य निर्माण श्रमयोगी (रोज़गार का नियमन एवं नौकरी की शर्तें) अधिनियम, 1996 को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाकर, निर्माण व्यवसाय के साथ जुड़े हुए श्रमयोगियों को दुर्धटना के मामले में तत्काल सहायता, चिकित्सा इलाज और बालकों की शिक्षा के लिए लाभ दिये जाते हैं।

मेरी सरकार ने, स्कूल पढ़ाई छोड जानेवालों के लिये कम अवधिवाला एक अज़्यासक्रम शुरू किया है, जिसकी सहाय से उन्हे त्वरीत रोज़गार/व्यवसाय की प्राप्ति हो सकेगी। असंगठित एवं सेवा के क्षेत्र में ऐसी रोजगारी निर्माण होगी।

वीमा कवच

सरकार द्वारा श्रमिक सुरक्षा प्रकल्प के अंतर्गत असंगठित श्रमयोगियो की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। आकस्मिक मृत्यु की घटना पर रूपये 20,000 और आंशिक विकलांगता की स्थितिवाले किस्से में रूपये 10,000 की धनराशि अब तक दी जाती थी इसमें सुधार किया गया है। गत प्रजासत्ताक दिन से यह राशी रूपये 1 लाख और रूपये 50,000 की कर दी गई है। अकस्मात की घटना में मृत्यु होने पर या दो अंग जैसे दोनों नेत्र या एक नेत्र और शरीर का कोई ओर एक अंग नष्ट होने पर रूपये 1 लाख और एक नेत्र अंग के नष्ट होने पर अथवा अंशत: विकलांगताकी स्थिति में रूपये 50,000 की राशि दी जायेगी।

सहकार

सहकारी क्षेत्र में हमारे राज्य में एक विशाल नेटवर्क प्रस्थापित हो चुका है। विभिन्न क्षेत्र जैसे कि दूध, चीनी और बेंकींग वगैरह में कुल मिलाकर 60,000 के करीब सहकारी संस्थाए कार्यरत है जिन में 1.48 कोटि सदस्य विद्यमान हैं।

राज्य स्तर पर संचालित एक राज्य सहकारी बेंक के अलावा भिन्न भिन्न 18 जिल्लों में मध्यस्थ सहकारी बेंक कार्यरत है। 7000 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण अग्रिम मंडलीयाँ भी कृषि विषयक विभिन्न हेतुओं के लिये अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। पीछले तीन साल में कृषि विषयक ऋण राशि को द्विगुणीत करने का जो लक्ष्य रखा गया था इसमें प्रथम वर्ष दरज़्यान ही सहकारी बेंको द्वारा करीब 88 प्रतिशत की भव्य कामायाबी हँसिल कर दी है। इस लक्ष्यांक को 31 मार्च 2005 तक पूरी तरह हांसिल किया जायेगा ऐसी पूरी संभावाना है।

कला संस्कृति और खेलकूद

राज्य में ग्राज़्य बाजारपेठों की सुविद्या भी सुद्दढ हो रही है। जिसके अंतर्गत आज राज्य में करीब 201 कृषि पेदाश बाजारपेठ समितियाँ, 182 मुज़्य मार्केट यार्ड और 223 जितने सब मार्केट यार्ड स्थापित किये गये हैं। वैश्विक स्तर पर लागु हो रहे आर्थिक और व्यापारिक सुधारों के अवसर का योग्य फायदा उठाकर ग्रामिण बाजार को अद्यतन बनाने में सरकार वचनबद्ध हैं।

मेरी सरकारने उत्सवों में जन-हिस्सेदारी के बारे में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, नवरात्री, मकरसंक्रांति आदि पर्वो में प्रजा को बडे प्रोत्साहन के साथ प्रेरित किया जाता है और ऐसे सभी पर्व-उत्सवको विशिष्ठ दरज्जा बहाल करवाया है । खास करके प्रजा के युवावर्ग में राष्ट्र भावना के द्दढिकरण और अच्छे चरित्र -निमार्ण के हेतु लेकर एक पुस्तक श्रेणी "सरफरोशी" का प्रकाशन उपलब्ध करवाया है।

खेलकूद की प्रवृत्तियों का प्रर्याप्त अवसर ग्रामीण वर्ग को भी मिल सके इस शुभ हेतु से मेरी सरकारने इस वर्ष के दौरान तरणेतर और देवगढबारीआ में ग्रामीण ओलज़्पिक का आयोजन किया था । जिसके फलस्वरूप ग्राम प्रजा में खेल-कूद के प्रति नई चेतना का विकास निर्माण हुआ है।

मोढेरा का उतरार्ध उत्सव, वडनगरी का ताना-रीरी संगीत समारोह और संस्कृतिकुंज गांधीनगर में आयोजित वसंतमहोत्त्सव आदि आयोजनों के जरिये सरकारने गुर्जर भूमि को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रयोग-भूमि बनाया है।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक वृद्धि दर में हमारा राज्य गुजरात पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहता आया है। राज्य का आर्थिक विकास दर पिछले कुछ साल से निरंतर वृद्धि की राह पर है। औद्योगिक विकास भी अच्छा रहा है। सन 2003 के एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 2000 मध्यम कक्षा के और 2,91,000 छोटे उद्योग थे। सन् 2002-2003 में चीजों की पैदावारी रू.1,75,738 करोड़ की थी जिसमें 21,350 करोड़ रूपयों की बढौतरी 2003 के वर्ष दौरान हुई ।

मेरी सरकार द्वारा जनवरी 2005 में आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। विश्व के पूंजी निवेशको के साथ साथ एन.आर.आई और एन.आर.जी महानुभावों को गुजरात में पूंजी निवेश के लिये प्रोत्साहित

किया गया । इस परिषद और उत्सव के दौरान सरकार का रूपये 1,06,160 करोड़ की करीब 226 दरज़्वास्त दस्तखत करके प्राप्त हुई है। वर्ष 2003 में जो ***"वाईब्रान्ट गुजरात"*** की समीट आयोजित की गई थी जिसमें करीब रू. 66,068 करोड़ के एम.ओ.यु. के हस्ताक्षर हुआ था ।

कुटिर और ग्रामोद्योग

मेरी सरकार ने खादी को जन-साधारण में प्रचलित करने का आयोजन किया है जिससे खादी की बिक्री बढ़ेगी परिणाम स्वरूप, जो कुशल या अर्धकुशल कारीगर गाँव में या शहर में रहते है उन्हे अपने अपने विस्तारों में ही रोजगार का अवसर प्राप्त होगा वे आत्मा निर्भर बनेंगे । उसके अलावा राष्ट्रीय मार्गो पर "हाइवे-हाट" के निर्माण द्वारा अतिरिक्त रोजगारी का अवसर बहाल करने का भी आयोजन किया है। आणंद जिल्ले में "धर्मज" में ऐसे एक हाइवे हाट का निर्माण और अहमदाबाद में अर्बन हाट का शुरू किया गया निर्माण इस कार्यक्रम की मिसाल है।

पर्यटन

मेरी सरकारने अभी अभी अक्तूबर 2004 की नवरात्री के दौरान पर्यटन का प्रसंग के साथ संकलित करने का प्रयास किया ताकि पर्यटन प्रवृत्ति को बढावा मिल सके। जुलाई 2004 में विश्व संस्था युनेस्कोने हमारे चांपानेर और पावागढ को "हेरीटज साईट" की सूची में शामिल करके गुजरात का गौरवप्रदान किया है। मेहसाणा जिल्ले के वडनगर का हेरीटज टाउन और कच्छ में धोलावीरा को उसकी हरप्पन संस्कृति को लेकर विश्व हेरीटेज साईट की कक्षा में स्थान मिले इस प्रकार के विकास के प्रयत्न हो रहे है। साथ ही साथ कच्छ जिल्ले में आये हुए मांडवी समुद्री क्षेत्र का एक "मेगा बिच रीसार्ट" का स्थान मिले ऐसे प्रयत्न सक्रिय है। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि सन 2003 से लेकर सन 2010 की कालावधि में राज्य के पर्यटन क्षेत्र को सुयोजित पर्यटन नीति के जरिये गतिशील और गौरवशील बनाया जाय।

वंचितों का विकास

मेरी सरकार राज्य के वंचितो का और पिछडे वर्गों के उत्थान के लिये नये अभिगम के साथ कार्य कर रही है। ऐसे लोगों की सेवा के और उनकी आर्थिक प्रगति को अधिक तेज बनाने के विशेष प्रयत्न हो रहे हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार गुजरात में अनुसूचित वर्गों की कुल संज़्या 35.93 लाख यानि कि गुजरात की कुल जनसंज़्या के 7.09 प्रतिशत थी। उनके कल्याण के योजनाओं को शिक्षण, आर्थिक विकास, आरोग्य और आवास आदि चार घटको में वर्गीकृत किया गया है। चालु वित्तिय वर्ष में इसके लिये करीब रूपये 155.86 कोटि का प्रावधान किया गया है। विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक प्रवृत्तिओ के लिये करीब 59,62,589 छात्रों का छात्रवृत्ति के रूप में 74.96 करोड़ रूपयो चुकाये गए है।

- कुल मिलाकर 3 लाख छात्रों का गणवेश नि:शुल्क दिया गया है।
- कक्षा 8 से 10 में पढनेवाली करीब 5000 बालिकाओं को "सरस्वती साधना" योजना के अंतर्गत मुज़्त साईकिलों का वितरण किया है।
- करीब 20 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित करने हेतु प्रत्येक को रू. 5 लाख का ऋण इस वर्ष के दौरान देने का तय किया है।
- कुल 38 सरकारी छात्रालायों के 2375 छात्रों और 552 सहायक अनुदान प्राप्त छात्रालयों के करीब 17,554 छात्रों कों भोजन और निवास की मुज़्त सुविधा उपलब्ध की गई है।
- सरकार द्वारा 89 निवासी आश्रम शालाएं और 784 बालावाडी को संचालित किया जा रहा है।
- तबीबी और कानूनी अज़्यास के करीब 46 स्नातक छात्रों को ऋण का प्रबंध करवाया है।
- करीब 354 कानूनी स्नातकों को वरिष्ठ कायदाविदों से प्रशिक्षण दिलवाया जाता है।

- 3763 कन्याओको "कुंवरबाईनुं मामेरू योजना" के अंतर्गत ,17 दंपतीओंको, माई रमाबाई आंबडकर सात फेरा समूह लग्न योजना में और 96 दंपतीओं को आंतर-ज्ञातिय विवाह के अंतर्गत सहाय दी गई है। 1256 लोगों को आवास-सुविधा के लिये, 493 व्यक्तियोंको जो अत्यंत पिछडे हुऐ हैऔर अन्य 3984 व्यक्तियोंको तबीबी सहाय दी जाती है।

- हिज़्मतनगर और पोरबंदर में डॉ. आंबेडकर भवन के निर्माण का शिलान्यास और जुनागढ में छात्रों के लिये नये छात्रालय का उद्‌धाटन किया है।

आदिजाति कल्याण

समग्र देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति की औसत 8.01 प्रतिशत है ज्योंकि गुजरात में अनुसूचित जनजातिका प्रमाण 14.76 प्रतिशत है। याने राज्य में आदिजाति की आबादी करीब 74.81 लाख है। विशेषत: राज्य के पूर्वीय क्षेत्र में उनका जमाव रहा है। इस जनजाति की आर्थिक हालत संतोषप्रद न होने के कारण सरकारने उनके शीध्र विकास के प्रति अधिक लक्ष्य रखा है। आदिजाति पेटा प्रकल्प के जरिये और दूसरे कार्यक्रमों द्वारा इस वर्ष में उनके लिये रूपये 873.15 कोटी का प्रावधान किया है। उसके अलावा न्यू गुजरात पेटर्न के तहत इस वर्ष में 131.93 करोड़ का प्रावधान इस आदिजाति के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सुविधाओं के लिये किया गया है। जिसमें दिसेज़्बर-2004 तक 7,46,324 करोड़ रूपये खर्च किये गये है।

आदिवासी किसानों के पास उनकी जमीन बहुत अल्प मात्रा में और छोटे छोटे टुकडों में होने के कारण वे पोषणक्षम खेती नहीं कर पाते इस बात को ध्यान में रखकर बनासकांठा से लेकर पूर्वपट्टी डांग तक के क्षेत्र में करीब 12181 अेकड़ मे फलदार वृक्ष की "वाडी" योजना को कार्यान्वित किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में अेफ. अेफ. डी. सी. द्वारा कुछ सुगंधित और आयुर्वेदिक के उपयोगी लेमनग्रास और पामरोजा आदि को उगाने का प्रयोग किया जा रहा है और अच्छा उत्पादन भी मिलना शुरु हुआ है।

विचरती और विमुक्त जाति कल्याण

मेरी सरकार इन जातियों के विकास और कल्याण के बारे में विशेष चिंतित रही है, उनके लिये सरकार ने असंज्य आयोजन किये हैं जैसे कि :

- बजानीया, बनजारा, मदारी, फकीर,नट, ठाकोर वादी, तलाटी इत्यादि जातियों के लिये करीब 19 आवास कोलोनी का निर्माण पंडित दीन दयाल आवास योजना के तहत किया है और 7 कोलोनी बन रही हैं और अन्ये 50 के लिये काम शुरु होने वाला है।

- "सरस्वती साधना" प्रकल्प के तहत कक्षा 8 वीं में पढनेवाली करीब 16928 बालिकाओं को रू. 2.59 कोटी रूपये सायकल खरीदी के लिये चुकाये गए है।

- समाज सुरक्षा प्रभाग द्वारा इस जाति के अशक्त अनाथ, वृद्ध और पिछडे लोगों को सुश्रुषा और पुन:वसन जैसी सेवाएँ बहाल की जाती है।

- समाज के अरक्षित वर्ग के लोगों के कल्याण संदर्भ से करीब 25766 दुर्बल छात्रों को रूपये 177.57 लाख की छात्रवृत्ति और 1213 लाभार्थीओं को 16.78 लाख रूपये की सहायता बहाल की गई है।

- विकलांगों के पुनवर्सन प्रकल्प के अज़्यास हेतु 37 तालुकाओं में प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया गया जिस में करीब 163 लाख का खर्च किया जा रहा है।

- संत सूरदास प्रकल्प के तहत करीब 6538 विकलांग और निराधारों का रूपये 66.22 लाख सहाय के रूप में बांटे गये।

- 2855.56 लाख रूपये की सहाय करीब 93,201 वृद्धजनों को दी गई।

ग्राम विकास

ग्राज्यप्रजा की रोजगारी मेरी सरकार की निरंतर चिंता का विषय रहा है। अब तक स्वर्णजयंति ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60,364 घटको की रचना हुओ है। इस साल के दीसंबर-2004 तक अधिक 4847 स्वरोजगारी स्वसहाय घटकों को शामिल किया गया है।

इन स्व.सहाय घटकों को 720.56 लाख का ऋण और 379.11 लाख की सहाय दी गई है। व्यक्तिगत स्तर पर दी गई सहाय 1029.30 लाख रूपये और ऋण रूपये 2100.32 लाख हुओ है।

गृह के आदरणीय सदस्यों से निवेदन करते हुए मुझे बहुत ही खुशी है कि राज्य के करीब 18,000 गाँवो को सुनिश्चित कालावधि में ही प्राथमिक सुविधाए बहाल करने के भगीरथ कार्य समान गोकुल ग्राम योजना के अंतर्गत दिसंबर 2004 तक करीब 12481 गावाँ को संपूर्ण तया गोकुल ग्राम घोषित कर दिये गये है ।

ग्राज्य क्षेत्रो में अधिक वेतन रोजगार अनाज के रूप में देने का एलान सन 2001 के स्वातंत्र दिन पर किया गया था। ग्रामीण प्रजा की सुरक्षितता और पोषण के स्तर के सुधार के हेतु से "संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत-स्वतंत्र रूप से कार्यरत रही है। जिल्ला, तालुका और ग्रामय पंचायत स्तर पर से इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान दिसज़्बर-2004 तक 8971.35 लाख रूपये की राशि का खर्च हुआ है और करीब 1,20,258 मेट्रीक टन अनाज की वपराश के जरिये 184.67 लाख मानवदिनों की रोजगारी उपलब्ध की गई है।

इन्दीरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के दीन परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जी रहे है उनको नये आवास के निर्माण के लिये या पुराने को सुधारने के लिये नियत मात्रा में युनिटकोस्ट की मर्यादा में सहाय दी जाती है।

चालु वित्तीय वर्ष के दौरान नये आवासों के निर्माण और आवास सुधारणा हेतु 1378.08 लाख रूपये की रकम आबंटीत की गई जिसके सामने दिसज़्बर-2004 तक रू.3,548.78 लाख की लागत से 13,103 आवस का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है और 13,975 आवास की निर्माण कार्य प्रगति में है। आवास सुधारणा अंतर्गत रू. 708.29 लाख की लागत से 6415 आवास सुधारने का कार्य पूर्ण किया गया है 4196 का कार्य प्रगति में हैं।

मेरी सरकार ग्राज्य-दीन और दुर्बल लोगों के उत्थान के प्रति जागरुक है। राज्यभर में गृहनिर्माण की प्रवृत्ति को तेज बनाकर भूमिहिन कृषिकों और ग्राज्य कारीगरों को आवास के लिये जमीन का टुकडा मुज़्त में उपलब्ध करवा के उस पर शत-प्रतिशत सहाय से स्नान-गृह, पायखाना सहित पक्के आवास की सुविधा "सरदार पटेल" आवास योजना के तहत कार्यान्वित की गई है । इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष में करीब 36,670 आवासों के लक्ष्यांक के सामने 11,930 आवासों का निर्माण हुआ। जिसमें 1618 आवास अनुसूचित जाति के और 3055 आवास अनुसूचित जनजाति के लिये बनाये गये ।

इ. ग्राम विश्वग्राम के आदर्श की पूर्ति के लिये वर्ष 2004-2005 को इ.गवर्नन्स वर्ष के रुप में घोषित किया गया है। अत: राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज्य संस्थाएं जैसे कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिल्ला पंचायतों में कज़्युटराईजेशन के कार्यक्रम शुरू कर दिये है। मार्च 2005 तक करीब 5300 ग्राम पंचायतों को इ. पंचायत कर दी जायेगी। इस इ-ग्राम योजनामें राज्य के पिछडे हुए और आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस प्रोजेकट में शुल्क की वसूली, बी.पी.अेल. की लिस्ट, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, जाति के प्रमाणपत्र 7/12 और 8/अ के दाखिले आदि कार्य ग्रामिण डेटा-बेज पर आयोजित किये गये है। भविष्य में इस ई. पंचायत हमें विभिन्न सरकारी सेवाओं को कार्यान्वित करनेवाले इ.सर्वीस केन्द्र के रुप में निश्चित रूप से सहायभूत बनानेवाले है।

हर तालुका पंचायत को और पंचायती राज्य के प्रशिक्षण केन्द्र में टी.वी. सेट के साथ डायरेक्ट रिसेप्सन सिस्टम भी दी गई है। राज्य की 25 जिल्ला पंचायत और 190 तालुका विकास अधिकारी के दफ़्तर जी-स्वान (GSWAN) संकलन पद्धति के साथ जुड चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सुझाव, प्रशिक्षण और सरकार के प्रकल्पों की विस्तृत माहिती को तालुका स्तर पर सीधी ही दी जायेगी।

ग्रामसभा का चुनाव सर्वसंमत और निर्विरोध हो सके इस उदेश्य से 5000 तक की आबादीवाले गाँव की एकमत से चुनी गई पंचायत को रूपये 60,000 और 5000 से ज्यादा आबादीवाली पंचायत को रूपये 1 लाख का अनुदान दिया जाता है। अब तक इस समरस योजना के अंतर्गत 3794 ग्राम पंचायत समरस बन चुकी है। जिसके लिये रूपये 2306 लाख का प्रावधान रखा है।

ग्रामवासियों के बीच एकजूटता और संप की मात्रा बढती रहे इसी शुभाशय से इस साल से यह योजना को अमली बनाया गया है। चुने गये गाँवों को रूपये एक लाख का पुरस्कार दिया जाता है। अब तक करीब 126 गांवों को "तीर्थग्राम" घोषित किये हैं। इसके अलावा पंचवटी प्रकल्प के तहत ग्राम वन योजना के जरिये ग्रामजनों के आनंद प्रमोद और धूमने फिरने के लिये उद्यान और बगीचों की सुविधा उपलब्ध की जायेगी।

अब तक ग्रामसभाओं के आठ चरण पूर्ण किये गये हैं। इन आठ चरणों की 1.33 लाख ग्रामसभाओं द्वारा करीब 54.40 प्रतिशत प्रश्नों का हल स्थल पर किया गया है। अब तक 5,73,480 अर्थात् 93.46 प्रतिशत प्रश्नों का हल ग्रामसभाओं द्वारा लाया गया है।

सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक अधिकारिता समिति की रचना की गई है जो ग्रामसभा के प्रश्नों के बारे में गतिशीलता को प्रेरित करती है और जो प्रश्न अनिर्णित दशा में पडे रहते हैं उनका निकाल करती है। रूपये 12.50 कोटी की राशिका ऐसे अनिर्णित प्रश्नो के निकाल के लिये आबंटन किये हैं।

11 वाँ वित्त आयोग की सिफारीशों के अनुसार सन 2000 से 2005 दरम्यान सालाना रूपये 69.91 के हिसाब से पांच साल में रूपये 348.50 कोटी की केन्द्रीय सहाय गुजरात को मिलनेवाली है। इस योजना के तहत मार्ग, जोड मार्ग, शालाओं के कमरे, पेयजल की सुविधाएं, सिंचन सुविधाएं, पंचायत गृह, स्मशान गृह, स्नान गृह आदि कार्यों को शुरू कराये गये हैं। इसके अलावा ज्योतिग्राम योजना और इ. ग्राम योजना को भी 11 वां वित्त आयोग की सुचि में शामिल किया गया है।

महिला और बाल कल्याण

महिलाओं को समाज की मुज़्य घारा में रखना और उनके प्रति संवेदनशील रहकर उनका सामुदायिक सशक्तिकरण करना जरुरी है। महिलाओं के प्रति हो रही हिंसाचारी, महिलाओंका प्रजनन स्वास्थ्य, तरुणिका महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति प्रजा में जानकारी इत्यादी के लिये युनाईटेड नेशन्स पोप्युलेशन फंड (UNFPA)जैसी वैश्विक संस्था की सहाय के साथ एक अंन्डर रिसोर्स सेन्टर बनाया गया है। राष्ट्र की महिला नीति के संदर्भ में राज्य में महिला गौरव पोलीसी बनाई जा रही है, शीध्र ही उसे अमल में लाया जायेगा । इसके अलावा स्वशक्ति योजना के अंतर्गत 10 जिल्लों में 2600 स्वसहाय घटकों की रचना करके करीब 40,000 महिलाओं को उसका फायदा दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम विकास की अलग योजना के 25 हज़ार से अधिक स्वसहाय जूथ कार्य कर रहे है।

गुजरात का एक भी शिशु आरोग्य पोषण और शिक्षा से वंचित न रहे इस उद्देश्य से संकलित बाल विकास योजना के तहत सघन कार्यवाही हो रही है और स्टेट एकशन प्लान फोर चिल्ड्रन तैयार किया है।

20 मुद्दा कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में समाज की अधिकतम समस्याओं को समाविष्ट किया गया है। इस अंतर्गत चल रहे प्रकल्पों का मुज़्य ध्येय गरीबी निवारण का ही है।

बीस मुद्दा कार्यक्रम को गुजरात राज्यने बडी सजगता से कार्यान्वित किया है। सन 2003-2004 की अवधि दरज़्यान सम्रग देश में 100 प्रतिशत अमलीकरण के लक्ष्य में गुजरातने प्रथम क्रमांक पाया है।

यात्राधाम

मेरी सरकार ने द्वारिका, सोमनाथ, गिरनार, पालिताणा, डाकोर और अंबाजी पवित्र स्थानों को "यात्राधाम" का दरज्जा दिया है। इन यात्राधामों में यात्रिर्यां के लिये अनेकविध मूलभूत आवश्यकताए बहाल कर दी जाती है। इन यात्राधामों के समुच्चय विकास कार्यो के लिये रुपये 130 लाख का खर्च किया गया है।

साथ साथ गुजरात के यात्रियों को कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ की यात्राओं के लिये रूपये 1 लाख की सीमा तक का बिमा सुरक्षा कवच भी बहाल किया गया है।

गौ-सेवा

गायों और गौवंश की कल्याण प्रवृत्तिओं को गतिशीलता देने के लिए राज्य में सन 1999 में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। ॲनीमल वेलफेर बोर्ड ओफ इंडिया के साथ संकलन में रहकर गौशालाएं, पांजरापोल आदि के लिये वित्तीय सहाय का लाभ पशुओं की परवरिश के लिये मिलता रहे वह काम देखा जा रहा है। कुदरती आपत्ति में, सूखा- अकाल की स्थिति में पशुओं के निभाव का कार्य ठीक से चलता रहे ऐसी कार्यवाही इस आयोग द्वारा हो रही है।

नगर विकास एवं नगर गृहनिर्माण

मेरी सरकार द्वारा असरग्रस्तों को आधारभूत सुविधाओं बहाल करने का कार्य हो रहा है। नगर की संस्कृति के बारे में गुजरात अपनी अलग पहचान बना रखे इस प्रकार के विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि

- भूकंपग्रस्त कच्छ के भूज, भचाउ और अंजार आदि क्षेत्रों में आपत्ति संचालन कार्यक्रमों द्वारा करीब 13 नगर रचनाओं की योजनाओं को आखरी रूप दिया गया है।
- गुजरात नगर विकास कंपनी लिमीटेड के जरिये 410.14 कोटी रूपयों के करीब 66 पेकेज योजनाओं का अमली बनाया गया है। दिसज़्बर 2004 तक रूपये 211.84 कोटि की योजना परिपूर्ण कर दी है।
- वाल्मिकी, आंबडेकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के निज़्न स्तरवाले परिवारों को अहमदाबाद के जुग्गी विस्तारों में 2176 आवासों और 440 शौचालयों की सुविधा, सहाय की राशि का पूर्ण उपयोग कर के प्रदान की गई है।
- राजकोट में रूपये 134.89 लाख के खर्च से 648 शौचालयों का निर्माण सहाय की राशि से खर्च करके बनाये गये है।
- राज्य की करीब 143 नगरपालिकाओं में "बाजपाई नगर विकास योजना" का प्रथम चरण पूर्ण किया गया है और दुसरे चरण के लिये प्रत्येक नगरपालिकाओं के प्रकल्प खर्च में रुपये 50 लाख का इजाफा मंजूर किया है।
- दूसरे चरण की राशि में वृद्धि करके जल आपूर्ति, जलशुद्धिकरण प्लान्ट, वर्षा जल का संचय, आरोग्य और सफाई एवं घन, कूडा,कचरे के निकाल की सुविधाओं को प्राधान्य दिया गया है। करीब 60 नगरपालिकाओं

को 1691 कार्यों के लिये रूपये 84.71 कोटी खर्च की मंजूरी दी गई है। जिसके अंतर्गत अब तक रुपये 18.35 कोटी खर्च के साथ 424 कार्यों को पूर्ण किया गया है और शेष कार्यों की प्रगति हो रही है।

- मुज़्यमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिसज़्बर-2004 तक आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिये 32,108 आवास बनाये गये है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही संस्थाओं को प्रति आवास रूपये 5000 के अनुदान के रुप में रुपये 2210 लाख का भुगतान कर दिया है।

- स्थानिय स्वराज की प्रवृत्तियों में आधुनिकीकरण लाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष के दौरान प्रत्येक नगरपालिका को इ.गवर्नन्स की तहत लाया जा रहा है। जिस में अब तक 82 नगरपालिकाओं में कार्य पूर्ण हुआ है। शेष को मार्च 2005 तक शामिल किया जायेगा ।

कृषि और किसान एवं हरित क्रांति

मेरी सरकारने अपने किसानों की आमदानी को पांच साल में दुगुना करने के लक्ष्य को लेकर तीन स्तरीय ब्यूहरचना का गठन किया है। जिस में -

(1) कृषि संबंधी अनुसंधान को प्रत्यक्ष किसानों के साथ जोडना ।

(2) खेती की जमीन के तत्त्वों की सूक्ष्म जाँच और उनका पृथक्करण कार्य द्वारा फसल आयोजन, और

(3) उपलब्ध जलराशि के संरक्षण के उपाय - क्योंकि हमारा राज्य जल के बारे में एक आपत्तिग्रस्त क्षेत्र है और अनियमित वर्षा से कृषि को असर होती है। मेरी सरकार हमारे किसानों की खेती का असामान्य आबोहवा एवं वर्षा के सामने स्थिरता बहाल करने के कार्य में जूटी है। सन 2004 की खरीफ मौसम में 75.68 लाख हेक्टर में लगाई कृषि के सामने करीब 87.50 लाख मेट्रीक टन का उत्पादन मिला था । एक अनुमान के मुताबिक इस वर्षान्त में करीब 155.29 लाख मेट्रीक टन की फसल उपज से रुपये 21,055 कोटी मूल्य का उपार्जन रहेगा।

मेरी सरकारने सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम को जलराशि के कार्यक्षम और मितव्यय प्रयोग के उद्देश्य से बनाया है। जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तरण प्रवृत्ति को एक अभियान के स्वरुप में देखा गया है। किसानों को उनकी फसलों और आवश्यक सामग्री के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन देने के लिये राज्य की कृषि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सदैव तत्पर रहते हैं। राज्य में करीब 4.80 लाख की संज़्या में जमीन के सोईल हेल्थ कार्ड (जमीन चकासणी कार्ड) बनाये गये है। यह संज़्या आगामी वर्षों में 5 लाख तक पहुँचेगी ।

राष्ट्रीय कृषि उत्पादन वीमा योजना के तहत रु.193.03 लाख के दावा और हमारे राज्य के करीब 369 किसान परिवारों के रूपये 3.91 कोटी के भूगतान किसान आकस्मिक वीमा के अंतर्गत कर दिया गया है। 16274 किसानों को अत्याधुनिक कृषि-तकनीक के बारे में प्रशिक्षण केन्द्रों में ट्रेनींग दी गई है। उन्हे अपनी खेती को कैसे सघन बनाया जाय और प्रत्येक कृषि पहलू के बारे में जानकारी देकर सक्षम शिक्षित बनाया जाता है। कृषि के बारे में दिन-प्रतिदिन की नयी जानकारी किसानों को मिलती रहे इस हेतु से राज्य में किसान कॉल सेन्टरो की स्थापना कि गइ है। हमारा राज्य आज आम, केला, चीकु आदि के गुणवान फलों की फसलो के लिये विज़्यात बन चुका है। इसके अलावा मसालों की फसल जैसे की जीरा, वरीयाली और धनिया में भी वह अग्रिम स्थान पा चुका है।

मेरी सरकार ने कृषि शिक्षा और उसके विस्तरण कार्य को घनिष्ट बनाने की ठान ली है। उसके प्रयत्न स्वरुप राज्य में चार कृषि युनिवर्सिटी आणंद,नवसारी, जूनागढ और दांतीवाडा में कार्यरत की गई है। पिछले साल में राज्य का कृषि उत्पादन बंपर रहा जो अगली साल की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा हुआ है। कृषि का विकास दर करीब 12 प्रतिशत हांसिल हुआ है। कृषि की पैदावार की किंमत तय किये गये मूलभूत किंमतो से नीचे न गिरे इस प्रबंध में असरकारक कार्यवाही कर दी जाती है। वाईब्रान्ट गुजरात ग्लोबल सितज़्बर 2005 के अंतर्गत कृषि संलग्न सेवाओं के 34 करारनामे हस्ताक्षरित हुए है। जिन में रूपये 1,00,093 कोटि का निवेश सुनिश्चित किया गया है। कृषि ऋण वीमा और वित्तीय सहाय के आशय से 15 लाख किसान क्रेडीट कार्ड वितरीत किये गये है। चालु वर्ष में

नाबार्ड और अन्य बेंको के सहयोग से अतिरिक्त 5 लाख कार्ड वितरीत किये गये है। सितंबर 2004 तक रू.4500 कोटि की ऋण राशि राज्य के 1,18,000 किसानों को मंजूर कर दी गई है।

गुजरात के पास वन्य सृष्टि और जैविक वैविध्य की समृद्धि है और बढती हुई आबादी और उद्योगीकरण के कारण प्रदूषण की समस्या के सामने "प्रकृति दोहन" का मंत्र आत्मसात् करने के लिए गुजरात वन वृद्धि, वन संरक्षण और वन्य सृष्टि के जतन के लिए सामाजिक सहयोग और लोक शिक्षण के जरिए प्रवृतिशील रहा है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2001 में फोरेस्ट सर्वे ओफ इन्डिया की रिपोर्ट के अनुसार पीछले चार वर्ष में वनाच्छादित विस्तार में 2146 चोरस मीटर की वृद्धि हुई है। सहभागी वन व्यवस्था के अंतर्गत 1641 गाँवों में ग्रामवन संरक्षण समितियों कार्यान्वित है।

वनीकरण के लोग अभियान के अतिरिक्त गुजरात सरकारने रतनज्योत (Jetrofa) की खेती के लिए अभियान शुरू किया है। सरकार ने बायो ज़्युएल क्षेत्र में रतन ज्योत रोपण को प्रोत्साहन दिया है। इसके अतिरिक्त पागल बबूल (गांडा बावल)के आत्यंतिक उपद्रव से कृषि, जमीन और सार्वजनिक स्थानों, बिजली लाइनों एवं नागरिकों के हो रहे नुकशानको देख कर रक्षित एवं अनामत जंगल विस्तार के बिना किसी भी विस्तार में से पागल बबूल के दूर करने के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रजाहित के लिए इस कानून में सुधार किया गया है। इसकी लकडी या इसमें से तैयार किये गये कोयले के परिवहन के लिए भी पास लेने में से मुक्ति दी गई है। प्रकृत्ति शिक्षण, पर्यावरण रक्षण और वृक्ष वन के संरक्षण के लिए लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए और गीर फाउन्डेशन की आंतर राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

मार्ग विकास

मेरी सरकार ने मार्ग विकास के उल्लेखनीय आर्थिक विकास के लिए मूलभूत ढांचे की सुविधा को ध्यान में रखकर व्यापार उद्योग के लिए ऐसे परिवहन व्यवहार तेज़ हो सके और पेट्रोल और शक्ति की बचत हो ऐसे हेतु को लक्ष्य में लेकर मार्ग विकास क्षेत्र द्वारा विविध कार्य शुरू किये है।

- राज्य के 1850 कि.मी. के राजमार्ग को अद्यतन बनाने की विश्व बेंक सहायता योजना में संतोषकारक प्रगति हो सकी है। 755 कि.मी. लंबाई के रास्तों का काम रू.553/- करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है और 854 कि.मी. लंबाई का रास्तों काम रू.945/- करोड़ की लागत से प्रगति पर है।
- भूकंप पुन: निर्माण अंतर्गत 956 कि.मी. लंबाई के राज्य के राजमार्ग की सुधार योजना रू. 304/- करोड़ की लागत से विभिन्न स्थिति में प्रगति में है।
- कुल रू.1,000/- करोड़ की ग़ैर सरकारी निवेश द्वारा 8 योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की गई है।
- निजीकरण की प्रक्रिया द्वारा डीसा से पांथावाडा होकर राजस्थान सरहद के गुंदरी तक 45 कि.मी. लंबाई को रु.25/-करोड़ की लागत से निजी कक्षा पर विकसित करने का मंजूर किया गया है।
- किम मांडवी 38 कि.मी. हिंमतनगर बायपास 8.7 कि.मी. और सुईगाम सिद्धाडा 42 कि.मी. को निजी कक्षा पर शुरू करने की कार्यवाही गति में है।
- चालु वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना द्वारा नडियाद से बड़ौदा एक्सप्रेस वे का 50 कि.मी. का र्माग रू.345/- करोड़ की लागत से पूर्ण किया है।
- हिंमतनगर से चिलोडा सेकशन के 52 कि.मी. की कामगीरी रू.145/- करोड़ के खर्च से और सूरत से अतुल के 80 कि.मी. के मार्ग रू.390/- करोड़ के खर्च से चार लाईन चौड़ी करने की कामगीरी पूर्ण होने वाली है।

- मुझे आनंद है की ग्राज्य विस्तार की मार्गो द्वारा जुड़ने की प्राथमिकता अग्रिमता को भी ध्यान में लिया गया है। जो निज़ संदर्भ से स्पष्ट होगा ।

- भूकंपग्रस्त 12 जिल्लो में 1812 कि.मी. लंबाई के मार्ग को रू.106/- करोड़ के खर्च से एडीबी सहायता योजना शुरू की है। जिसमें 1135 कि.मी. लंबाई का काम पूर्ण हुआ है और बाकी के काम मार्च 2005 तक में भौतिक रूप से पूर्ण होगा ।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दौरान 1064 रास्ते कीरु. 287.51 करोड़ की योजना मंजूर हुई है जिसमें 1560 कि.मी. लंबाई के नए रास्ते तथा 679 कि.मी. लंबाई की मार्ग सुधार का समावेश होता है। इस के अंतर्गत 970 कि.मी. लंबाई के नए रास्ते और 574 कि.मी. लंबाई की मार्ग सुधार का काम पूर्ण हुआ है। इस योजना से 500 से भी अधिक जनसंज़्यावाले 1095 गाँव/पेटा विस्तार को डामर के स्तरवाले रास्ते से जुडे जायेंगे।

- इस के अतिरिक्त चालु वर्ष के दौरान 128 ग्राज्य मार्गो को रू.45.60 /- करोड़ की लागत से पहली बार डामर का स्तर करने का आयोजन करने से 130 गाँव पेटा विस्तार लाभान्वित होगे।

जल को कुदरत की अमूल्य भेंट मानकर सरकारी मकानों के नए निर्माणो में जल संचय को अनिवार्य करने से 7458 मकानों में अंदाजित 30.95 लाख चोरस मीटर छत विस्तार अंतर्गत 3465 मकानों के 21.85 लाख चो.मी. छत विस्तार के लिए जल संचय योजना का काम पूर्ण किया है।

बंदरगाह

मेरी सरकार द्वारा घोषित कि गई बंदरगाहनीति की सफलतापूर्वक के अमलीकरण के परिणामत: मुंद्रा और पीपावाव में दो आधुनिक बंदरगाह कार्यान्वित हुए है। दक्षिण गुजरात के हजीरा में एल.एन.जी. की आयात के लिए मे. शेलनी (आंतराष्ट्रीय कंपनी) द्वारा अंदाजित रु.3442 करोड़ के पूंजीनिवेश से और दक्षिण गुजरात में दहेज बंदरगाह पर केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम सार्वजनिक साहसों से बनी हुई संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मेसर्स पेट्रोनेट एल.एन. जी. ली. द्वारा एल. एन.जी. टर्मीनल विकसित करने की योजना अंदाजित रु. 3130 करोड़ की पूंजी निवेश से शुरू की गई है। जिसका निर्माण पूर्ण करके एल.एन.जी. प्रथम जहाज़ को फरवरी 2004 में लंगर डालकर ठहराया गया था।

मुंद्रा बंदरगाह और आदिपुर को जुडनेवाली ब्रोडगेज रेल्वे लाईन का काम पूर्ण हुआ है। विकास के प्रथम स्तर के भागस्वरूप मुंद्रा बंदरगाह में गुजरात अदाणी पोर्ट द्वारा कन्टेईनर टर्मीनल विकसित किया गया है। पीपावाव बंदरगाह को जोडनेवाली ब्रोड़गेज रेल्वे लाइन का काम भी शुरू कर दिया है, जो अंतिम स्तर पर है। इस प्रकार गुजरात के बंदरगाहों पर सोलीड कार्गो, कन्टेइनर्स और एल.एन.जी. जैसे कार्गो हेन्डल के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हुई है। इस तरह बंदरगाह के विकास के कदम का परिणाम से गुजरात देश की समृद्धि का प्रवेशद्वार बनता है।

मत्स्योद्योग

गुजरात राज्य के दरियाई मत्स्य उत्पादन का हिस्सा 93.06 प्रतिशत है और आंतरदेशीय मत्स्य उत्पादन का हिस्सा 6.94 प्रतिशत है । वर्ष 2004-2005 दौरान सितज़्बर 2004 तक मत्स्य उत्पादन 1.47 लाख हुआ है।

धोलाई और औखा मत्स्य बंदरगाह विकसित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही दोनों प्रोजेकट के लिए कुल रु. 400 लाख अनुदान रिलिज किया गया है।

राजस्व-प्रशासन

राज्य के जमीन दफतर की योग्यरूप से देखभाल हो तथा वह सुरक्षित रह सके और लौगों को सरलता से तथा त्वरित उपलब्ध होने के साथ ही जमीन दफतर व्यवस्थापन पद्वति पारदर्शक बन पाए उस हेतु से जमीन दफतर

कोज़्युटराइजेशन योजना द्वारा लगभग सभी गाँवों के सभी खातेदारों के 7/12 और 8-अ के रेकर्ड ओन लाइन किये गये है। पिछले स्वातंत्र्य दिन से 7/12 और 8-अ के हस्तलिखित नकल देने की प्रथा बंध करके कोज़्युटराईझड नकल को ही स्वीकृत मानी जाती है। खातेदारों को इन प्रलेखों की नकलों प्राप्त करने में परेशानियाँ न हो इस हेतु से पटवारी द्वारा गाँव में से ही प्राप्त हो जाए ऐसा आायोजन किया गया है। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल टेकनोलोजी के उपयोग तक ही सीमित नहीं है । लेकिन जमीन मालिक के हक्क भी सुरक्षित बने इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

मेरी सरकार ने दि. 11-6-2002 के हुकम से जिस व्यक्तियों ने स्टेज़ डयुटी की बकाया राशी और उसका सुद भरना हो तो उसे राशी में राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना जाहिर की है।

जनसेवा केन्द्र

मेरी सरकार द्वारा कलक्टर अहमदाबाद के नए मकान में अद्यतन सुविधाओं के साथ एक जनसेवा केन्द्र शुरू किया गया है। अरजदारों की जरूरत अनुसार प्रमाणपत्र, जमीन के 7/12 और 8-अ की नकलों और अनुज्ञापात्र रु. 20 जितनी नगण्य फी लेकर एक दिन में ही पूर्ण कर दिया जाएगा। अहमदाबाद के अतिरिक्त राज्य के अलग अलग जिले में कलेकटर और तहसीलदार के 100 से भी अधिक कार्यालयों में ऐसे जनसेवा केन्द्र शुरू किए गए है।

अतिरिक्त ज़मीन का वितरण

अतिरिक्ति हुई जमीन जरूरतमंद लाभार्थियों को वितरण की जाती है। जिस के अंतर्गत मेरी सरकार ने दिये गये 400 अेकड़ के लक्ष्यांक पर दिसज़्बर 04 तक 515 एकड़ तक का वितरण हो गया है अर्थात् 128 प्रतिशत सिद्धि हांसिल हुई है।

सुनामीग्रस्त को सहाय

आप सब परिचित ही है कि गत दिसज़्बर में इन्डोनेशिया में हुए भूकंप की सुनामी असरों आंदामान-निकोबार टापुओं, तामिलनाडु , पोंडीचेरी, आंध्रप्रदेश ओर ओरिस्सा राज्यों में हुई थी और तब सुनामी असरग्रस्तो को सहायता पहुँचानेवालों में मेरी सरकार सब से पहले थी ।

मेरी सरकार ने मुज़्यमंत्री के राहत निधि में से तामिलनाडु को रु. 5 करोड़, आंदामान-निकोबार को रु.2 करोड़,पोडिचेरी, आंध्रप्रदेश, ओरिस्सा सभी को 1 करोड़ और सब मिलाकर रु.10 करोड़ की रोकड़ नकद सहाय और इसके अलावा लोक सहयोग से सुनामीग्रस्त राज्य के हवाई, रेलवे और परिवहन मार्ग से जीवन जरूरी चीज़-वस्तुएँ मिलाकर अंदाजित रु.15 करोड़ की 3545 टन सहाय सामग्री भेजी है। इतना ही नहीं आंदामान-निकोबार के अनिश्चित संदेशा व्यवहार के ढांचे को पुन:स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने 10 सज़्यों की हेम रेडियों ओपरेटर की टीम को शीध्र ही आंदामान-निकोबार भेजी थी।

यह कहना जरूरी नहीं है कि गुजरात मानवता और करुणा के विषय में हंमेशा अग्रसर रहा है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

मेरी सरकार ने गरीबी-रेखा के नीचे जीनेवाले परिवार के लिए 12.5 किलोग्राम अनाज के थोंक के बदले अब प्रत्येक कार्डधारक परिवार को मासिक 20 किलोग्राम अनाज का थोंक सही भाव से मिल पाए ऐसा तय किया है। इसी तरह अंत्योदय योजना में 25 किलो के बदले 35 किलो अनाज में दो रुपिए प्रति किलों गेहूँ और 3 रु में प्रति किलो चावल गरीबी रेखा नीचे के और अन्य परिवार को देने का निश्चय किया है । राज्य की अन्नपूर्णा योजना के तहत् 65 वर्ष की आयु से उपर के व्यक्तियों जिसे राष्ट्रीय वृद्धत्व पेन्शन योजना में संमिलित किया गया नहीं है उन्हें मासिक 10 किलो ग्राम अनाज मुज़्त देने का निर्णय किया है।

जो परिवार रोजगारी और मज़दूरी के लिए अपने वतन से अन्यत्र धूमते रहते है उनके लिए प्रथम चरण में पंचमहाल जिल्लें में रोमींग रेशनकार्ड का कार्यक्रम अमल में लाया गया है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए यह एक सीमाचिन्हरूप कदम बन सकेगा ऐसा मुझे विश्वास है।

राज्य सरकारने 2004 की जनसंज़्या और 400 कार्ड की मर्यादा और 3 कि.मी. तक के अंतर में उपयुक्त दर की एक दुकान निश्चित की हुई है। लेकिन इस योजना को व्यवहारिक बनाने के लिए दीन दयाल योजना अंतर्गत स्थानिक बेरोज़गार व्यक्तियोमें से आत्मनिर्भर होने की इच्छावालें समुदाय को अग्रीम पसंदगी देने का निश्चित किया गया है।

<u>ग्राहक सुरक्षा</u>

राज्य में 19 जिल्ला ग्राहक तकरार निवारण फोरम तथा एक राज्य ग्राहक तकरार निवारण कमिशन कार्यालय है। जिसमें दर्ज किए गये 19,500 जितने केसों के अंतर्गत 12,900 जितने केसों का निकाल किया गया है। जब जिल्ला फोरम समक्ष दर्ज हुए 92,000 जितने केसों के सामने 74,000 जितने केसों का निराकरण भी किया है। बाकी रहे हुए केसों को समय मर्यादा में निकाल हो और ग्राहकों को शीध्र ही न्याय प्राप्त हो उसके लिए मेरी सरकारने अहमदाबाद शहर को अधिक जिल्ला फोरम की और राज्य कमीशन के लिए अधिकर सर्कीट बेंच की रचना की गई है।

<u>नशाबंधी</u>

गुजरात राज्य की स्थापना से राज्य संपूर्ण नशाबंधी नीतिमय है। सरकार नशाबंधी नीति को योग्य रूप से और उसके असली स्वरूप में सज़्ताई से अमलीकरण हो पाए उसके लिए कटिबद्ध है।

<u>सूचना एवं प्रसारण</u>

प्रवर्तमान समय में समूह प्रचार माध्यमों के क्षेत्र में आए हुए शीध्र परिवर्तन और व्यापक महत्त्व को ध्यान में रखकर गुजरात स्टेट मल्टीमीडिया रीसोर्स टेकनोवींग (जी. स्मार्ट)को अधिक कार्यरत किया गया ।

इसके अतिरिक्त चालु वर्ष में मीडिया रिस्पोन्स सीस्टम शुरू की गई है। जिसके द्वारा अखबारों में प्रसिद्ध होनेवाले रिपोर्ट की समीक्षा करके सुधारात्मक कदम लिया जाता है।

गुजरात चलचित्रों के निर्माता अधिक प्रमाण में गुजराती चलचित्र बनाने के लिए प्रेरित हो उस उद्देश्य से निर्माताओं को रु.5 लाख की आर्थिक सहाय भी दी जाती है। चालु वित्तीय वर्ष में नवज़्बर मास तक कुल 9 निर्माताओं को रु.45 लाख की सहाय दी गई है।

<u>वित्तीय प्रशासन</u>

मेरी सरकार का मितव्ययी प्रशासन के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति अंतिम दो वर्ष में उत्तरोत्तर सुधार पर है। परिणामत: प्रसिद्ध रेटींग एजेन्सी द्वारा राज्य को उच्च रेटींग दिया गया है। इसके साथ ही साथ राजस्व आय में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील है।

<u>सुराज्य का वैश्विक सन्मान</u>

मेरी सरकार की कामगीरी की असरकारकता निरंतर बढ सके उसके लिए प्रयत्नशील है। राज्य में भूकंप के बाद उसके पुन:निर्माण की प्रवृत्ति और संभवित आपत्ति में सुयोग्य आयोजन के लिए गुजरात राज्य आपत्ति व्यवस्थापन सत्तामंडल की स्थापना की गई थी । इस सत्तामंडल ने सन् 2003 के वर्ष के लिए डिझास्टर रिडकशन के लिए "युएन सासाकावा एवोर्ड" सन् 2004 की "इनोवशन्स इन गवर्नन्स" के लिए भी कोमनवेल्थ ऐसोशिएशन ओफ पब्लिक एडमीनीस्ट्रेशन (कापाम) नाम से प्रसिद्ध गोल्ड ट्रोफी प्राप्त हुई है।

<u>वैद्यानिक और संसदीय मुद्दे</u>

मेरी सरकार ने संसदीय कामगीरी करनेवाले विभाग द्वारा इ गर्वनन्स प्रोजेकट के भाग स्वरूप राज्य के प्रवर्तमान 436 अधिनियमों की इन्डेक्ष और राज्य कानून आयोग की ओर से प्रस्तुत किया गया 51 विवरण पत्रक तैयार करके वेबसाईट पर रखा है। एक समान विषय के अमली कानून का एकत्रीकरण करने की कार्यवाही तथा मुंबई अधिनियम का गुजरात अधिनियम के रूप में नामाभिधान करने की कार्यवाही भी आगामी वर्ष में करने का निश्चय किया है।

राज्य कानून आयोग की ओर से अंतिम छ वर्ष में प्रस्तुत हुए कुल 55 अहेवाल अंतर्गत कुल छ अहेवाल गत केलेन्डर वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया है। इस में से 30 जितने अहेवालों की कामगीरी पूर्ण की गई है। बकाया 25 अहेवालों की कामगीरी आगामी वर्ष में पूर्ण की जाएगी।

मेरी सरकार इस सत्र के अंदाजपत्र के वैधानिक कामकाज के अतिरिक्त निज़्न वैधानिक कामकाज सदन में विचार हेतु प्रस्तुत करेगी ।

(1) गुजरात प्रेत भोजन (नियंत्रण) (रद्द करने हेतु) विधेयक, 2005
(2) मुंबई वजन और नाप (अमलीकरण) गुजरात रद्द करने विषय) विधेयक, 2005.
(3) गुजरात मोटर वाहन (इन्धन उपयोग हेतु) नियमन विधेयक, 2005
(4) गुजरात सिनेमा (नियमन) (सुधारा) विधेयक, 2004
(5) गुजरात आवश्यक चीजवस्तु और पशु (नियंत्रण) विधेयक, 2005
(6) मुंबई नापबंधी संबंधी (तैयारे और उसे ज़ारी रखने विषय, उपाय संबंधी।
(7) भारत का स्टेज़्स,(गुजरात सुधारा) विधेयक, 2005
(8) मुंबई नशाबंधी (गुजरात सुधारा) विधेयक, 2005
(9) मुंबई मज़दूर क्ल्याण निधि (गुजरात सुधारा) विधेयक, 2005
(10) ध्रांगध्रा नगरपालिका (कर लागू करने के विषय में) (कानूनी साबित करने संबंधी) (रद्द करने के विषय में) विधेयक,2005
(11) गुजरात फोज़दारी कोर्ट, विधेयक, 2005
(12) मुंबई बिन-व्यापारी कोर्पोरेशन (गुजरात रद्द करने के विषय में) विधेयक, 2005
(13) द सेन्टर फोर एन्वायर्नमेंन्टल प्लानींग एन्ड टेकनोलोजी युनिवर्सिटी विधेयक, 2005
(14) द धर्मसिंह देसाई इन्स्टीटयूट ऑफ इन्फर्मेशन एण्ड टेकनोलोजी विधेयक, 2005
(15) गुजरात राजवित्तीय जिम्मेदारीयाँ विधेयक, 2005
(16) गुजरात मूल्य वर्धित कर (सुधारा) विधेयक,2005

मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे उद्बोधन में निर्देशित राज्य के विकास की यशगाथा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी सरकार सक्रिय है और उसमें सफलता भी हांसिल कर रही है। आप सब के अनुभव और निज़ी दीर्ध द्दष्टि से लोकतंत्र को मूर्तिमंत करने के लिए यह गृह की उच्च संसदीय प्रणाली और उसकी गरिमा को संभालकर योगदान देने की भावना के साथ चर्चा में भाग लेगें। ऐसी सदभावना से समापन करता हूं।

जय हिन्द

जय जय गरवी गुजरात ।

શ્રી નવલકિશોર શર્મા (નામદાર રાજયપાલશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી અને વિધાનસભાના સભ્યશ્રીઓ.

અગિયારમી વિધાનસભાના સાતમા સત્રના મંગલ પ્રારંભે આપ સૌનું હ્રદયપૂર્વક સ્વાગત કરૂં છું.

દેશની લોકશાહીમાં ઉચ્ચ પ્રણાલીકાઓ પ્રસ્થાપિત કરવામાં જેણે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે તેવા આ ગૌરવવંતા સભાગૃહને સંબોધવાનો મારો આ પ્રથમ અવસર મારા જીવન માટે આનંદનો અવસર છે તેવી લાગણી વ્યકત કરતા હું આ સત્રમાં આપ સવેર્ને આવકારૂ છું.

આપ જાણો છો કે આ સત્ર મુખ્યત્વે ૨૦૦૫-૨૦૦૬ ના વર્ષ માટેનું અંદાજપત્ર, ચાલુ વર્ષનું સુધારેલ અંદાજપત્ર અને તે માટેની પૂરક માંગણીઓ રજૂ કરવા તથા આ અંદાજપત્રીય દરખાસ્તોને આનુષંગિક વૈધાનિક કામગીરી માટે તથા અન્ય સંસદીય કાર્ય માટે બોલાવવામાં આવ્યું છે.

મહાત્મા ગાંધી તથા લોહ પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલની આ જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ ઉપર તેમની વિચારધારાને અનુસરીને ગ્રામ સ્વરાજથી રામરાજય સુધીની વિકાસની કેડી ગુજરાતે કંડારી છે અને તેની વિકાસ યાત્રામાં અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરીને સમગ્ર દેશ અને વિશ્વમાં પોતાની આગવી છાપ ઉભી કરી છે. વિકાસની આ યાત્રા ૨૧ મી સદીમાં હવે સમગ્ર દેશ માટેની દિશા બની રહી છે અને એટલે જ મારી સરકાર "ગુજરાતનો વિકાસ એ રાષ્ટ્રનો વિકાસ" એ મંત્ર અપનાવીને વિકાસ કુચ અવિરતપણે ચાલુ રાખવા સંકલ્પબધ્ધ છે.

જળ શકિત

સરદાર સરોવર પરિયોજનાના બંધની ઉંચાઇ ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી પૂર્ણ કરેલ છે અને ઓગષ્ટ-૨૦૦૪માં કેનાલ હેડ પાવર હાઉસ દ્રારા વીજ ઉત્પાદન થયું અને ૨૦૦ મે.વો. ક્ષમતાવાળુ ભૂગર્ભ જળ વિદ્યુત મથક જાન્યુઆરી-૨૦૦૫માં કાર્યાન્વીત થયું અને વીજ ઉત્પાદનનો શુભારંભ થયો છે.

જળ એજ જીવન છે એવા મંત્રને અપનાવીને મારી સરકારે પાણીને સહજ રીતે ઉપલબ્ધ બનાવવા રાજયની કેટલીક નદીઓના આંતર જોડાણની કામગીરી હાથ પર લીધેલ છે. જે અંતર્ગત નર્મદા મુખ્ય નહેરને ઓળંગતી મુખ્ય ૧૦ નદીઓમાં નર્મદાનું પાણી છોડવામાં આવ્યુ છે જેના કારણે **રીવરગ્રીડ માટે ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ રાજય બન્યું છે**. નર્મદા નદીના પૂરના પાણીથી સૌરાષ્ટ્ વિસ્તારની ૧૭ નદીઓ અને જળાશયો ભરવા અંદાજીત રૂ.૫૧૫ કરોડના ખર્ચવાળી યોજનાને રાજય સરકારે સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી આપીને જીલ્લાના કુલ ૧૦૭ ચેકડેમ અંગેની કામગીરીની પ્રક્રિયા હાથ પર લીધી છે.

- રાજયના દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાત વિસ્તારમાં અંદાજે ૭૧ ટકા, સૌરાષ્ટ્રમાં ૧૬ ટકા, ઉત્તર ગુજરાતમાં ૧૧ ટકા, કચ્છમાં ફકત ૨ ટકા પાણી છે. છતાં અત્યાર સુધીમાં રાજયમાં સિંચાઇના બધા સ્ત્રોતોમાંથી કુલ ૪૦.૦૦ લાખ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઇ હેઠળ આવરી લેવાયો છે.
- સરદાર પટેલ સહભાગી જળ સંચય અંતર્ગત સરેરાશ રૂ.૨ થી ૩ લાખની કિંમતના ૫૦,૦૦૦ ચેકડેમો બાંધવામાં આવ્યા છે.
- ઔધોગિક ગૃહો અને સેવાભાવી સંસ્થાઓના સક્રિય સહકારથી નદીઓ પર સરેરાશ રૂ. ૩૦ થી ૪૦ લાખની કિંમતના ૧૦૦ મોટા ચેકડેમો બાંધવામાં આવ્યા છે. અને ૫૦૦ મોટા ચેકડેમો બાંધવા માટેની જુદા જુદા તબકકાની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે.
- ચેકડેમ માટેનાં અનુકૂળ સ્થળ ન હોય તેવા સ્થળોએ તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી હેઠળ ૧૫૦૦ થી વધુ તળાવો ઉંડા કરેલ છે.

સુજલામ સુફલામ યોજના

પાણીની અછત અને ભુગર્ભ જળની ખેંચની વિપરીત અસર રાજયના અર્થતંત્ર પર ન પડે અને રાજયની વિકાસ ગાથા આગળ વધતી રહે તેવા ઉદ્દેશો સાથે સિંચાઇ અને જળ સ્ત્રાવ માટે રૂપિયા ૪૨૯૧ કરોડ અને પીવા માટે રૂપિયા ૧૯૪૬ કરોડ મળીને અંદાજે કુલ રૂપિયા ૬૨૩૭ કરોડના ખર્ચ વાળી સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના રાજય સરકારે અમલમાં મુકી છે.

આ યોજનાના અમલીકરણથી ભૂગર્ભ જળની વધારે પડતી ખેંચવાળા વિસ્તારો કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં દુષ્કાળ ભૂતકાળ બનશે. એટલું જ નહિં પરંતુ આ વિસ્તારના ૪૯૦૪ ગામો માટે પીવાના

પાણીનો પ્રશ્ન હલ થશે તથા જળસંચયના કામોથી ખરીફ પાક બચશે તથા અનેક ગામોને પીવાલાયક પાણીનો પુરવઠો પણ મળશે.

પીવાનું પાણી

મારી સરકાર, ગુજરાતની પ્રજાને પૂરતું શુદ્ધ પીવાલાયક પાણી પુરું પાડવા માટે કટિબદ્ધ છે.

રાજયના અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોને પીવાનું પાણી પુરું પાડવા માટે સરદાર સરોવર કેનાલ આધારિત પાણી પુરવઠા યોજના અમલમાં મૂકી છે. જેનાં દ્વારા ૧૩૪૩ કિ.મી. બલ્ક પાઇપ લાઇન અને ૩૧ ડીસ્ટ્રીબ્યુશન ગ્રુપ નેટવર્કનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને અમદાવાદના ભાલવિસ્તાર, ભાવનગર, અમરેલી, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ અને કચ્છ જિલ્લાઓના ૧૮૨૬ ગામો અને બાવન શહેરોને નર્મદાનું પાણી પહોંચાડયું છે તથા અમરેલી, અમદાવાદ, ભાવનગર, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ અને કચ્છ જિલ્લાઓનાં વધારાનાં ૧૭૭૪ ગામોને નર્મદાનું પાણી પહોંચાડવા માટે ૩૩૬ કિ.મી. લંબાઇની બલ્ક પાઇપ લાઇન તેમજ ૩૦ ડીસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કનાં કામો પ્રગતિ હેઠળ છે. આમ પીવાના પાણીની મુશ્કેલી દુર કરવાના આ યોજનાકીય આયોજન ઉપરાંત નીચેના પગલાં લીધાં છે.

- ૨૦ મુદ્દા હેઠળ પીવાનું સ્વચ્છ પાણી કાર્યક્રમ - અન્વયે ૬૦૦ ગામ/ફળીયાનાં લક્ષ્યાંક સામે ૫૫૯ ગામ/ફળીયાઓને ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ સુધીમાં આવરી લીધેલ છે
- કુલ રુ.૮૭૩ કરોડનાં અંદાજવાળી ૮૬ ગ્રામ્ય જુથ પાણી પુરવઠા યોજનાઓમાં ૧૧૮૫ ફળીયાઓને પીવાનું પાણી આપવાનું શરું કરાયું છે. બાકી ફળીયાઓને પીવાનું પાણી આપવાની યોજના ગતિમાં છે.
- આદિજાતિ વિસ્તારના ૨૦૦૦ હેન્ડપંપના લક્ષ્યાંક સહિત ૩૦૪૪ ના લક્ષ્યાંક સામે ૬૭૮૧ હેન્ડપંપ તેમજ ૧૧૧ મીની પાઇપ યોજના ડિસેમ્બર - ૨૦૦૪ સુધીમાં પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
- ભૂકંપથી અસર થયેલ પાણી પુરવઠા યોજનાઓનાં પુનઃબાંધકામ અને પુનઃવસન માટે રુ.૮૧૨ કરોડની વિરાટ યોજના પરિણામલક્ષી બની રહી છે અને તેના ૫૧ પેકેજ પૈકી ૩૦ પેકેજના કામો પૂર્ણ થયેલ છે, જયારે ૨૧ પેકેજના કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.

કલ્પસર

૨૧મી સદીના ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસને પરિપૂર્ણ કરવા માટેની કલ્પનામાંથી કલ્પસર યોજના જન્મી છે. આ યોજનાના વિવિધ પાસાઓનું સવેર્ક્ષણ પૂર્ણતાના આરે છે અને હવે બીજા તબક્કામાં ભુસ્તર અસરો ભુસ્તર શાસ્ત્રીઓએ અન્વેષણ અને તેની સામાજીક અસરો સહિત જમીન સવેર્ક્ષણ અંગેનો પ્રારંભ થયો છે.

જ્ઞાન શકિત

મારી સરકાર રાજ્યને શિક્ષણના ક્ષેત્રે અગ્રેસર બનાવવા કૃતનિશ્ચયી છે. રાજ્યમાં શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી હતી તે ૮૦,૪૭૭ વિદ્યાસહાયકોની નિમણુંકથી ભરી દીધી છે. રાજયની શાળાઓમાં પ્રયોગશાળા, વાંચનાલય, રમતગમતના સાધનો, નવી બેન્ચો, ફર્સ્ટ એઈડ બોક્ષ તથા કૉમ્પ્યુટરો પૂરા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત શાળાઓમાં સેનીટેશન સંકુલોને વીજળીની સગવડ, પીવાના પાણીની સગવડ અને કંપાઉન્ડ વૉલ પણ કરી આપેલ છે. આ ઉપરાંત રાજય સરકારે નીચેના પગલાંઓ પણ લીધા છે.

- સાક્ષરદીપ કાર્યક્રમ દ્વારા ૨૯,૮૭૧ તાલીમાર્થીઓ અને ૧,૦૭,૦૦૦ પ્રાથમિક શિક્ષકોની મદદથી ૧૪ દિવસની ખાસ ઝુંબેશ દ્વારા નિરક્ષરોને શિક્ષિત બનાવવામાં આવ્યા.
- વાંચન-લેખન-ગણન અભિવૃદ્ધિ અભિયાન દરમિયાન બાળકોની ક્ષમતામાં વધારો કરવાનો એક સુંદર કાર્યક્રમ પણ ચાલુ વર્ષે કરવામાં આવ્યો.
- રતન ટાટા ટ્રસ્ટ અને આઈ.આઈ.એમ.ના સહયોગથી સમગ્ર દેશમાંથી ૫૮ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોની પસંદગી કરવામાં આવી, તે પૈકી ૩૦ શિક્ષકો ગુજરાતના છે તે ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત બની.
- એજ્યુસેટનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે સમગ્ર દેશમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતને પસંદ કરવામાં આવેલ છે અને તે અંગે કાર્યવાહી ગતિમાં છે.

➢ પંચમહાલ, ડાંગ, કચ્છ, વલસાડ, સુરત, દાહોદ અને જામનગરના ધોરણ પહેલા અને બીજા ધોરણ માટેના શિક્ષકોને લોકબોલીની તાલીમ આપીને બાળકને તેમની માતૃભાષામાં પ્રારંભિક શિક્ષણ આપવાનું શરૂ કરેલ છે.

કન્યા કેળવણી

કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન આપવા વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડની યોજનાની સાથોસાથ રાજયની સ્થાપના પછી પ્રથમ વખત મુખ્ય મંત્રીને મળેલ ભેટ- સોગાદોની હરાજી કરીને મળતી રકમ કન્યા કેળવણી માટે આપવામાં આવે છે. દેશમાં આ મૂલ્યલક્ષી પ્રયોગ કરનારી મારી સરકાર જ છે. જૂન, ૨૦૦૪ દરમિયાન ૨૦ કરતા ઓછી સ્ત્રી સાક્ષરતાવાળા ૨૦૦૦ ગામો સહિત કુલ ૭,૭૬૫ જેટલા અંતરિયાળ ગામોમાં માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી સહિત મંત્રીમંડળ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ કન્યા કેળવણી રથયાત્રા યોજીને કન્યા કેળવણીને ઉત્તેજન આપવા માટે શાળા પ્રવેશોત્સવ ઉજવેલ છે. ગુજરાત કન્યા કેળવણી નીધિની રચના કરી છે, જેમાં રૂા.૨૮૦ લાખ દાનમાં મળેલ છે. રાજ્યના કન્યા શિક્ષણમાં પછાત એવા ૭૮ તાલુકાઓ અને ૧૩ શહેરી ઝુંપડપટ્ટીવાળા વિસ્તારોમાં નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર ગર્લ્સ એટ એલીમેન્ટરી લેવલ (NPFGEL) નો એક ખાસ કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ

મારી સરકારે ચાલુ વર્ષે ૮ નવી સરકારી ઈજનેરી કોલેજો, ૩ સ્વર્નિભર ઈજનેરી કોલેજો, ૧૧ ફાર્મસી કોલેજો, ૧ સ્વર્નિભર પોલીટેકનીક, ૮ એમ.બી.એ. કોલેજો અને ૩ એમ.સી.એ. કોલેજો શરૂ કરીને ૪,૮૦૬ બેઠકોનો વધારો કરેલ છે. આ ઉપરાંત બાયો-મેડિકલ અને ઓટોમોબાઈલ્સનો ડિગ્રી કોર્ષ પણ શરૂ કરેલ છે. ઉદ્યોગો અને સમાજની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લઈને ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમોને નવેસરથી પુનઃગઠિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્યની પાંચ ડિગ્રી એન્જીનિયરીંગ કોલેજ અને બે પોલીટેકનીક સંસ્થાઓનું આધુનિકરણ કરવાનું શરૂ કરવામાં આવેલ છે. કેનેડા-ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિન્કેજ પ્રોજેક્ટ હેઠળ કુલ ૧૩ સંસ્થાઓને વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણની તાલીમ હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે.

સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી

મને એ જણાવતાં આનંદ થાય છે કે મારી સરકારે આગામી વર્ષથી કાર્યરત થાય તે રીતે સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સંસ્કૃત ભાષા કે જે આપણી પ્રાચીન, સુવિકસીત અને રાષ્ટ્રની ધરોહર છે તેના પ્રસાર માટે મારી સરકાર પ્રતિબધ્ધ છે.

માનવ સંસાધન વિકાસ

રાજયની તાલીમ આપતી સરદાર પટેલ રાજય વહીવટ ભવન (S.P.I.P.A) સંસ્થા પોતાની કાર્યશૈલીમાં વ્યવસાયિકતા અને મૌલિકતા લાવી શકે તેવા ઉદેશથી સંપૂર્ણ સ્વાયત્તતા આપી છે. આ સંસ્થા દ્વારા રાજયના વિકાસના પડકારોને પહોંચી વળવા માત્ર એક તાલીમબધ્ધ કર્મચારી નહીં પરંતુ સાચા અર્થમાં કર્મયોગીઓનું નિર્માણ થયું છે. આ ઉપરાંત તાલીમને એક ઉપયોગી અને નીવડેલ સાધન તરીકે ગણીને વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના રાજયપત્રિત અધિકારીઓને દર બે વર્ષે ઓછામાં ઓછી ત્રણ દિવસની તાલીમ મળી રહે તેવી નવી યોજના દાખલ કરેલ છે.

રાજયના વહીવટમાં ક્રિયાત્મક અને ભાવનાત્મક યોગદાનને પ્રોત્સાહિત કરવા અને ભાવનાત્મક સંબંધ/સેતુ ઉભો કરવાના હેતુથી રાજય સરકારે રાજયના ૫ લાખ અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓને કર્મયોગી બનાવીને તેમના અંતરમાં રહેલી લોકસેવાની ભાવનાને પ્રજવલ્લિત કરવા વહીવટી સુધારણા માટેના સુચનો મેળવેલ છે. જેનો હેતુ કર્મચારીઓમાં પહેલવૃત્તિ ઉભી કરીને તેમને સારી કામગીરી માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.

વાઇડ એરીયા નેટવર્ક (જીસ્વાન)

મારી સરકારે જિલ્લા અને તાલુકા મુખ્ય મથકોની ૧૪૦૦ કચેરીને સાંકળી લઇને ૧૧ જેટલા કાર્યરત સર્વરો સાથે સર્વર ફાર્મની સુવિધા સાથે જીસ્વાન હેઠળ એશીયામાં સૌથી મોટું નેટવર્ક ઉભુ કર્યુ છે જેમાં ૧૦૮ વેબસાઇટો હાલ સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે.

સાયન્સ સીટી

મારી સરકારે અમદાવાદ નજીક વિશ્વકક્ષાના સાયન્સ સીટીની સ્થાપના કરી છે જે ૨૧ મી સદીમાં આધુનિક વિજ્ઞાનનું યાત્રાધામ બનેલ છે જયાં પ્રથમ ચરણમાં આઇમેક્સ ૩ડી થીયેટર, ચિલ્ડ્રન એક્ટીવીટી સેન્ટર, એમ્ફી થીયેટર તેમજ એશિયાના સૌથી મોટો મ્યુઝીકલ ફાઉન્ટેઇનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવેલ છે.

ગત વર્ષના પ્રથમ નવ માસમાં ૨,૫૦,૦૦૦ થી વધુ લોકોએ સાયન્સ સીટીની મુલાકાત લીધી છે.

બાયોટેકનોલોજી

ગુજરાત સ્ટેટ બાયોટેકનોલોજી મિશનને સ્વાયત્ત સંસ્થા તરીકે રાજ્યમાં બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રના વિકાસ માટે આયોજન, અમલીકરણ અને નીતિઓ અને પગલાંનું સંકલન કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જેના ભાગરૂપે વડોદરા ખાતે એક બાયોટેકનોલોજી પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રકારનું પગલું લેનારું આપણું ગુજરાત, સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સભ્ય છે.

બિન-નિવાસી ભારતીય પ્રભાગ

ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠાને વિદેશમાં પહોંચાડવા અને પરસ્પરના દ્રષ્ટિબિન્દુને સમજવામાં તેમજ વિચારોના આદાન-પ્રદાન માટે ગુજરાત રાજય બિન નિવાસી ગુજરાતી પ્રતિષ્ઠાન કાર્યરત છે બિન નિવાસી ગુજરાતીઓ ગુજરાતના વિકાસમાં અને ખાસ કરીને તેમના વતનના ગામની વિકાસ પ્રવૃત્તિઓમાં સહભાગી થઇ શકે તે માટે વતન સેવાની વિવિધ યોજનાઓ અંગેની માહિતી પ્રકાશિત કરી છે.

ઉર્જા શકિત

રાજયના સામાજિક અને આર્થિક વિકાસ માટે વીજળી માળખાકિય જરૂરિયાત હોવાથી મારી સરકારે ગ્રાહકના સંતોષ માટે સંખ્યાબંધ પગલાં લીધાં છે.

ગત વર્ષે રાજયની સ્થાપિત વીજ ક્ષમતા ૮૬૮૩ મે.વોટની હતી. ચાલુ વર્ષ દરમિયાન કેનાલ હેડ પાવર હાઉસના પાંચ એકમો સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ દ્વારા કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત રાજયના ખનીજ વિકાસ નિગમના ૨૫૦ મે.વો. ના લિગ્નાઇટ આધારિત અક્રીમોટા ખાતેના પાવર પ્લાન્ટ ટૂંક સમયમાં કાર્યાન્વિત થનાર છે તેના કારણે વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. પાનન્ધ્રો ખાતે ગુ.વિ.બોર્ડના ૭૫ મે.વોટનાં લિગનઇટ આધારિત એકમનું કામ શરૂ પણ થઇ ગયું છે.

રાજયના વિધુત બોર્ડના વિવિધ પ્રયાસોના પરિણામે, વીજ પ્રવહન અને વીજ વિતરણમાં થતી ખાદ્ય વર્ષ ૨૦૦૨-૦૩ માં જે ૨૮.૮ ટકા હતી તે ૨.૩ ટકા જેટલી ઘટી છે.

જયોતિગ્રામ યોજના

મારી સરકાર ગ્રામ્ય વિસ્તારોને ૨૪ કલાક થ્રી ફેઝ પાવર પૂરો પાડવાના હેતુથી "જયોતિગ્રામ યોજના" અમલમાં મૂકેલ છે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અત્યાર સુધીમાં ૭૦૦૦ જેટલા ગામોને આ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. જેના પરિણામે ગ્રામવાસીઓનાં જીવનધોરણનું સ્તર ઉંચું આવેલ છે, રોજગારીની નવી તકો વધારવામાં અને શિક્ષણ અને આરોગ્યની સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં મદદરૂપ થયેલ છે. જેથી રાજયના તમામ ગામોને નિશ્ચિત સમય મર્યાદામાં જયોતિગ્રામ બનાવવા મારી સરકાર પ્રતિબધ્ધ છે એટલું જ નહિં પરંતુ વીજળી ક્ષેત્રમાં સુધારણા કરવાની પ્રવૃત્તિ આગળ ધપાવવા મારી સરકારે ગુજરાત વીજળી ઉદ્યોગ (પુનઃ ગઠન અને નિયમન)અધિનિયમ, ૨૦૦૩ હેઠળ વીજક્ષેત્રે રાજયના વિકાસની જરૂરિયાત પરિપૂર્ણ કરવા ગુજરાત વિધુત બોર્ડનું પુનઃગઠન કરીને સાત કંપનીની રચના કરીને અસરકારક માળખું પ્રસ્થાપિત કરેલ છે.

ગેસ-પેટ્રોલિયમ

મને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે રાજયના પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન એ નવી સંશોધન પરવાના નીતિ અન્વયે હરાજીની બોલીના બીજા રાઉન્ડમાં ગેઇલ સાથેના સંયુકત સાહસ હેઠળ ધોળકા ક્ષેત્રમાં મોટા પ્રમાણમાં તેલનો જથ્થો શોધી કાઢયો છે. આ માટે સત્વરે ઉત્પાદન વ્યવસ્થા સ્થાપીને તેલના જથ્થામાંથી નાણાં પેદા કરવા પગલા હાથ ધરવામાં આવી રહયા છે. મારી સરકારના દુરદર્શી અભિગમ અને સક્રિય સહયોગથી આ શકય બન્યું છે, જે ગૌરવપૂર્ણ છે.

મારી સરકારે રાજયમાં ગેસગ્રીડ કામગીરીમાં વેગ લાવવા જરૂરી પગલા લીધા છે. મને એ જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમદાવાદ-કલોલ સુધી ગેસ પાઇપલાઇન નેટવર્કનું કામ પૂરું થયું છે

આ સિવાય દહેજ ખાતેના તાજેતરમાં શરૂ કરાયેલા એલ.એન.જી. ટમીર્નલ (પેટ્રોનેટ એલએનજી) માંથી ૧૦ લાખ ટન રીગેસીફાઇડ પ્રવાહીકૃત પ્રાકૃતિક ગેસની ફાળવણીને લીધે વીજળી અને રાસાયણીક ખાતરના ક્ષેત્રમાં રાજયના મહત્વના ઉદ્યોગોને વધુ પ્રમાણમાં ગેસ પૂરવઠો પૂરો પાડી શકાશે. આ ઉપરાંત સી.એન.જી. ના વિતરણના કારણે અમદાવાદના પર્યાવરણમાં વ્યાપક સુધારો થશે. મને આનંદ છે કે હવે ગુજરાત દેશનું પેટ્રો-કેપિટલ બની રહયું છે. આમ આ બાબત ગુજરાતના અર્થતંત્રમાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવશે.

રક્ષા શકિત

મારી સરકાર રાજયની પ્રજાને રાજયમાં શાંતિ પૂર્ણ વાતાવરણ મળી રહે તે માટે અસમાજીક અને રાષ્ટ્રવિરોધી તત્વો વિરૂધ્ધ સતત તકેદારી રાખી રહી છે જેને પરિણામે છેલ્લા બે વર્ષમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતી અસરકારક રીતે નિયંત્રણ હેઠળ રહી છે. પરિણામ સ્વરૂપ દરેક સંપ્રદાયના ધાર્મિક ઉત્સવો મેળાઓ અને તહેવારોની લાખો લોકોની હાજરીમાં સંપૂર્ણ શાંતિ પૂર્વકની ઉજવણી શકય બની છે. આ ઉપરાંત પોલીસ હાઉસીંગની કામગીરીમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે તેમજ ૬૦૦૦૦ પોલીસ કર્મચારીઓ અને તેમના ૨,૫૦,૦૦૦ પરિવાર જનોના આરોગ્યની ચકાસણી પણ કરવામાં આવી છે. લીઝ લાઇનની કનેકટીવીટીનું કામ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે. રાજયના બધા જ પોલીસ સ્ટેશનોનું કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે

વાહન વ્યવહાર

મોટર વાહન ખાતાના આધુનિકરણના ભાગ રૂપે નવેમ્બર, ૨૦૦૪ સુધીના ૩૫,૭૪,૨૭૫ સ્માર્ટ કાર્ડ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ અને ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ સુધીમાં ૨,૫૯,૧૬૯ કાર્ડ રજિસ્ટ્રેશન બુક આપવામાં આવી છે. માર્ગ અકસ્માતની બાબતમાં રાજય સરકાર ચિંતીત છે અને તે માટે ચતુર્માગીય રસ્તાઓના નિર્માણના અનેક અસરકારક પગલાઓ ભર્યા છે.

જેલ

માનવીય અભિગમ દાખવીને ૭૦ વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુરૂષ કેદીઓ અને તમામ મહિલા કેદીઓને દિવાળીના પ્રસંગે ૧૦ દિવસની પેરોલ મંજૂર કરવામાં આવી હતી. કેદીઓના સ્વાસ્થની બાબતમાં રાજય સરકાર ચિંતીત છે. રાજયની હયાત જેલોમાં ઓવરક્રાઉડીંગના પ્રશ્ને રાજય સરકાર ચિંતીત છે. આથી વડોદરા, પાલારા, ગળયાદર, ગોંડલ, દાહોદ, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરા ખાતે નવી જેલોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે અને સુરત જિલ્લામાં લાજપોર ખાતે નવી જેલના બાંધકામ માટે જમીનનું સંપાદન કરવામાં આવ્યું છે.

ન્યાય તંત્ર

રાજયની પ્રજાને ઝડપી ન્યાય અપાવવા ૧૬૬ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવાના નિર્ણય સામે હાલ ૧૫૯ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ ચાલુ થવાના કારણે ૨૩૦૦૦ ઉપરાંતના કેસોનો તથા કાનુની સત્તા મંડળ દ્વારા લોક અદાલતો હાથ ધરી કુલઃ૨૧ લાખ કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

મારી સરકારે જેલ અને કોર્ટ વચ્ચે વીડીયો કોન્ફરન્સથી કોર્ટની કાર્યવાહી ચલાવવાનું કામ શરૂ કરીને અદ્યતન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી આ કાર્યવાહીને સરળ બનાવી છે.

પર્યાવરણ

મારી સરકારે ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં કલીનર પ્રોડકશન પ્રોજેકટ હેઠળ રાજયના વિવિધ ઉદ્યોગોમાં ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દરમિયાન થતાં પ્રદૂષણનું નિયંત્રણ કરવા અનેકવિધ પગલાં ભર્યા છે જેમાં ઉદ્યોગો તરફથી જુદી જુદી અરજીઓ કરવાના બદલે કોમન કન્સેન્ટ અને ઓથોરાઇઝેશન (સીસીએ) નો અમલ, સ્થાનિક કક્ષાએ ટાસ્ક ફોર્સ સમિતિ દ્વારા સમીક્ષા, ગંદા પાણીના શુધ્ધિકરણ અંગે ૫૧૨૪ પ્લાન્ટ, જૈવિક તબીબી કચરાનો વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિથી નિકાલ કરવા માટે સામૂહિક ધોરણે ૧૧ જગ્યાએ યોગ્ય સુવિધા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત ઉર્જાની બચત અને પાણી જેવા કુદરતી સ્ત્રોતોની જાળવણી દ્વારા પર્યાવરણ અંગે લોકજાગૃતિ કેળવવાનું અને તેનો પ્રસાર કરવાનું નકકી કર્યું છે.

આરોગ્ય

મારી સરકારે કુદરતી કે માનવસર્જીત હોનારતો જેવી દુર્ઘટનામાં ભોગ બનેલા દર્દીઓને ઓર્થોર્પેડિક, ન્યુરોસર્જરી વગેરે જેવી તબીબી જગતની અનેક શાખાઓની ઝડપી અને સઘન સારવાર મળી રહે તે હેતુથી અમદાવાદ ખાતે ચાલુ વર્ષે ટ્રોમો સેન્ટરની સ્થાપના કરી છે તેમજ અગ્રગણ્ય ૧૦ હોસ્પિટલોને સાંકળી લઇ ઇમર્જન્સી મેડિકલ સર્વિસીસનો પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

શાળા આરોગ્ય પ્રોગ્રામ હેઠળ અંદાજે એક કરોડ જેટલા બાળકોને તપાસણી કાર્યક્રમ હેઠળ આવરી લીધા છે તથા દ્રષ્ટિ પ્રોગ્રામ હેઠળ ૨૪૧૭૮ જેટલા બાળકોને ચશ્માનું મફત વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજયમાં પોલીયોનો એક પણ કેસ નથી રાજયની હોસ્પિટલોમાં આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી સુધારા કરવામાં આવ્યા છે.

રાજયના રકતપિત્ત નિર્મૂલન કાર્યક્રમના અસરકારક અમલીકરણથી આ રોગથી પીડાતા દર્દીઓનો રાષ્ટ્રીય સરેરાશ દર ૧૦,૦૦૦ ની વસ્તીએ ૨.૬ નો છે જેને માત્ર ૦.૮૬ સુધી નીચો લાવી શકાયો છે.મને એ વાતનો આનંદ કે છે આ સિદ્ધિની ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પણ પ્રશંસા કરવામાં આવેલ અને અન્ય રાજયોને પણ ગુજરાતને મોડલ સ્ટેટ ગણીને અનુસરવા આહવાન કરેલ છે.

રાજયના ૨૧ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વધારાના ત્રણ ખાસ તજજ્ઞોની સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી આ કેન્દ્રોને જીલ્લા સ્તરની હોસ્પિટલોની હરોળમાં મુકીને આરોગ્ય સેવાને સઘન બનાવેલ છે.

માતૃ વંદના

આરોગ્ય ક્ષેત્રે વધુ એક કદમ તરીકે સગર્ભા બહેનોના સ્વાસ્થ્યની જાળવણી માટે તેમજ તેમને જરૂરી પોષણ આપવા માટે મારી સરકારે માતૃ વંદના યોજના શરૂ કરેલ છે જેને સુંદર પ્રતિભાવ મળેલ છે. આ યોજનાથી માતૃ મૃત્યુ દર અને બાળ મૃત્યુ દરમાં ઘટાડો થશે.

શ્રમ અને રોજગાર

ગુજરાત રાજ્ય ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે શાંતિ માટે પ્રથમ હરોળનું સ્થાન ધરાવે છે.

અસંગઠિત ક્ષેત્રોમાં કામ કરતાં શ્રમયોગીઓ માટે એક ખાસ સેલ ઉભુ કરવામાં આવેલ છે તથા તેમના પ્રશ્નો બાબતે ધ્યાન આપવા હાઇ લેવલ કમિટિની પણ રચના કરવામાં આવેલ છે.

સંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકોના શ્રમિક કાયદા હેઠળના હક્કોને બાધ ન આવે તે રીતે શ્રમિક કાયદાઓમાં સુધારા કરવામાં પણ રાજ્ય સરકારે પહેલ કરેલ છે.

૮૫ ટકા સ્થાનિક શ્રમિકોની રોજગારી ફરજીયાત કરવા બાબતનો તથા રાત્રીના સમય દરમ્યાન સ્ત્રી શ્રમિકોને કામ કરવામાંથી અમુક શરતોને આધીન રહીને છુટછાટ આપતો સુધારો કરવામાં આવેલ છે.

મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગીઓ (રોજગારીનું નિયમન અને નોકરીની શરતો) ધારો,૧૯૯૬ નો અમલ કરવા નિયમો ઘડીને બાંધકામ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ શ્રમયોગીઓને અકસ્માતના કિસ્સાઓમાં તાત્કાલીક સહાય, તબીબી સારવાર અને બાળકોના શિક્ષણ માટે લાભ આપવામાં આવશે.

મારી સરકારે સ્કૂલ છોડી જનારા માટે અત્રે ઝડપી રોજગારી મળે તે સારું ટૂંકાગાળાના કે ાર્સ શરુ કરેલ છે. આ રોજગારી અસંગઠિત વિસ્તાર તથા સેવા વિસ્તારમાં પણ ઉભી થઇ શકશે.

વિમા કવચ

ગ્રામ તેમજ શહેરી અસંગઠિત શ્રમયેાગીઓને સામાજીક સુરક્ષા કવચ આપવાના હેતુથી શ્રમિક સુરક્ષા યેાજના હેઠળ જેમાં અસંગઠિત શ્રમયેાગીઓને અકસ્માત મૃત્યુના કિસ્સામાં રુા. ૨૦,૦૦૦/-અને આંશિક અપંગતાના કિસ્સામાં રુા. ૧૦,૦૦૦/- શ્રમિક સુરક્ષા યેાજના અન્વયે ચૂકવવામાં આવતા હતા. તેમાં ગત પ્રજાસત્તાક દિનથી સુધારો કરીને અકસ્માત મૃત્યુના કેસમાં તથા બે અંગેા જેમાં બે આંખ, અથવા એક અંગ અને એક આંખ ગુમાવે તેા પ્રત્યેક માટે રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા એક અંગ અથવા એક આંખ ગુમાવવાના અંશતઃ અપંગતાના કિસ્સામાં ૫૦ ટકા લેખે રૂા.૫૦,૦૦૦/- કરવામાં આવ્યા છે.

સહકાર

દૂધ ઉત્પાદન, ખાંડ ઉત્પાદન અને બેંકીંગ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રમાં ૬૦,૦૦૦/- જેટલી વૈવિધ્યસભર સહકારી મંડળીઓ ૧.૪૮ કરોડ સભાસદો સાથે વિશાળ નેટવર્ક રાજયમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

રાજય કક્ષાએ ટોચની રાજય સહકારી બેંક વિવિધ ૧૮ જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો તથા ૭૦૦૦ થી વધુ પ્રાથમિક કૃષિ ધિરાણ મંડળીઓએ કૃષિ વિષયક વિવિધ ક્ષેત્રે ધિરાણ આપવામાં મહત્વનું યોગદાન આપેલ છે. ત્રણ વર્ષમાં કૃષિ વિષયક ગ્રામ્ય ધિરાણ પ્રવાહને બમણો કરવાના કાર્યક્રમ હેઠળ સહકારી બેંકેાએ પ્રથમ જ વર્ષમાં ૮૮ ટકા જેટલી ભવ્ય સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે અને તા. ૩૧/૦૩/૨૦૦૫ સુધીમાં પૂર્ણ લક્ષ્યાંક હાંસલ થવાની શકયતા છે.

રાજયમાં ૨૦૧ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ, ૧૮૨ મુખ્ય યાર્ડ તથા ૨૨૩ સબયાર્ડ છે. વૅશ્વિકસ્તરે થઇ રહેલ આર્થિક સુધારાઓના પરિણામે માકેર્ટીંગ ક્ષેત્રે નવી તકોનો યોગ્ય લાભ લઇ શકાય તે માટે ગ્રામ્ય કક્ષાએ માકેર્ટીંગ સુવિધાઓ સુદ્રઢ કરવા સરકાર કાર્યરત છે.

કલા સંસ્કૃતિ અને રમત ગમત

મારી સરકારે સ્વાતંત્ર્ય દિન, પ્રજાકસત્તાક દિન, નવરાત્રી, ઉતરાયણ જેવા ઉત્સવોને લોક ભાગીદારીથી ઉજવીને પ્રજા ઉત્સવનો દરજ્જો આપેલ છે. રાજ્યની પ્રજાના સર્વાંગી વિકાસ માટે તેમજ ભાવી યુવા પેઢીમાં રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના ચરીતાર્થ થાય તથા તેમના ચારિત્ર્યનુ ઘડતર થાય તે માટે "સરફરોશી પુસ્તક શ્રેણીનુ પ્રકાશન" એક નોંધપાત્ર કદમ છે.

રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓનો લાભ માત્ર શહેરી વર્ગને નહિં પણ ગ્રામ્ય પ્રજાને પણ મળે તે માટે મારી સરકાર દ્વારા ચાલુ વર્ષમાં તરણેતર તથા દેવગઢબારીયા ખાતે ગ્રામીણ ઓલમ્પિક યોજવામાં આવેલ છે. જેનાથી ગ્રામ્ય પ્રજામાં રમતગમત પરત્વેની ચેતનાનો સંચાર કર્યો છે.

વડનગર ખાતે ચાલુ વર્ષે યોજાયેલ તાનારીરી સમારોહ, મોઢેરા ખાતેનો ઉતરાર્ધ ઉત્સવ તથા સંસ્કૃતિકુંજના વસંત ઉત્સવનું આયોજન એ વાતની પ્રતિતી કરાવે છે કે ગુજરાત સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદની પ્રયોગ ભૂમિ બન્યું છે.

ઔદ્યોગિક વિકાસ

રાજયનો આર્થિક વિકાસદર છેલ્લાં કેટલાંક વષોર્થી એકધારો સતત વધતો રહેલ છે. તેમાંય ખાસ કરીને ઔદ્યોગિક વિકાસ ઘણો જ થવા પામેલ છે. ૨૦૦૩ના વાર્ષિક સવેર્ મુજબ રાજયમાં ૨૦૦૦ મધ્યમકક્ષાના ઉદ્યોગો તથા ૨,૯૧,૦૦૦ નાના ઉદ્યોગો હતા. રાજયમાં ૨૦૦૨-૦૩માં ઉત્પાદિત થયેલ વસ્તુઓની કિંમત રૂા.૧,૭૫,૭૩૮ કરોડ હતી. જેમાં ૨૧,૫૩૦ કરોડનો વધારો થયેલ છે. આમ દેશમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ ક્ષેત્રે રાજ્ય પ્રથમક્રમે બિરાજમાન છે.

સરકારશ્રીએ વૈશ્વિક રોકાણકારોની સાથોસાથ એન.આર.આઇ. અને એન.આર.જી. તરફથી મૂડી રોકાણ આકર્ષવા માટે આંતરરાષ્ટ્રિય પતંગ મહોત્સવનું જાન્યુ.૨૦૦૫માં આયોજન કરેલ. જેનાં પરિણામે સરકારશ્રી દ્વારા આ પરિષદ દરમ્યાન રૂા.૧૦૬,૧૬૦/- કરોડની કિંમતનાં કુલ ૨૨૬ એમ.ઓ.યુ.દસ્તખત કરવામાં આવ્યા છે.

વર્ષ ૨૦૦૩ના વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમીટ દરમ્યાન રૂા.૬૬,૦૬૮/-કરોડના એમ.ઓ.યુ. થયેલ હતા.

કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ

મારી સરકારે ખાદીને લોકભોગ્ય બનાવવા ખાદી ખરીદી ઉત્સવ દ્વારા રોજગારીની તકો ઘેરબેઠા ઉપલબ્ધ કરાવવા, તેમજ રાજયમાં ગરીબી રેખાથી નીચે જીવતા ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારોમાં રહેતા કુશળ અને અર્ધકુશળ કારીગરો તેમના વિસ્તારોમાં જ રોજગારી મેળવે અને તેઓ આત્મર્નિભર થાય, તે રીતનું આયોજન કરેલ છે. આ ઉપરાંત હાઇવે-હાટ ઉભી કરીને રોજગારી અપાવવાના પ્રયત્નો હાથ ધરેલ છે. આણંદ જિલ્લાનું ધર્મજ આનું ઉદાહરણ છે. અમદાવાદ ખાતે અર્બન હાટનું બાંધકામ શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે.

પ્રવાસન

પ્રસંગ આધારિત પ્રવાસનને વેગ આપવા માટે મારી સરકારે તાજેતરમાં ઓકટો.૨૦૦૪ દરમ્યાન નવરાત્રિ મહોત્સવ-૨૦૦૪નું આયોજન કરેલ. યુનેસ્કો તરફથી ચાંપાનેર - પાવાગઢને વર્લ્ડ હેરીટેજ સાઇટ તરીકે જુલાઇ ૨૦૦૪ માં જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે આપણા રાજય માટે ગૌરવની વાત છે. મહેસાણા જિલ્લાના વડનગરને એન્સીયન્ટ હેરીટેજ ટાઉન તરીકે વિકસાવવાની તથા કચ્છમાં આવેલ હડપ્પન યુગની સાઇટ ધોળાવીરાને વર્લ્ડ હેરીટેજમાં સ્થાન મળે તે માટેની તથા કચ્છ જિલ્લાના માંડવી દરિયા કિનારે મેગા બીચ રીસોર્ટની કામગીરી હાથ પર છે. આમ રાજયની આગવી છાપ ઉભી કરવાના આશયથી ૨૦૦૩-૨૦૧૦ ની નવી પ્રવાસન નીતિ અન્વયે પ્રવાસન ક્ષેત્રને ગતિશીલ અને વેગવંતુ બનાવવા રાજય સરકાર કટિબધ્ધ છે.

વંચિતોનો વિકાસ

મારી સરકાર વંચિતોના વિકાસ કરવાના નવા અભિગમ સાથે રાજયના છેવાડાના માનવીના ઉત્કર્ષની ભાવના રાખે છે અને તેથી તેવા લોકોના સામાજિક આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે ઝડપી ખાસ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહયા છે. સને. ૨૦૦૧ ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાતમાં અનુસુચિત જાતિઓની કુલ વસ્તી ૩૫.૯૩ લાખ

એટલે કે કુલ વસ્તીના ૭.૦૯ ટકા જેટલી થાય છે. જેમના કલ્યાણ ક્ષેત્રની યોજનાઓને શિક્ષણ, આર્થિક ઉત્કર્ષ, આરોગ્ય, આવાસ એમ ચાર જુથમાં વહેંચવામાં આવી છે. જે માટે ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં કુલ રૂા.૧૫૫.૮૬ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.જે અન્વયે -ચાલુ વર્ષ શિક્ષણની વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ કુલ ૫૯,૬૨,૫૮૯ છાત્રોને શિષ્યવૃત્તિ પેટે ૭૪.૯૬ કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા છે.

- કુલ ૩,૦૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને મફત ગણવેશ આપેલ છે.
- ધો.૮ થી ૧૦ માં ભણતી ૫૦૦૦ બાળાઓને સરસ્વતી સાધના યોજના નીચે મફત સાયકલો આપવામાં આવનાર છે.
- કુલ ૨૦ વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે પેરાય તે હેતુથી ચાલુ વર્ષ દરમ્યાન દરેકને રૂા.૫ લાખ મુજબ લોન આપવામાં આવનાર છે.
- કુલ ૩૮ સરકારી છાત્રાલયોમાં ૨૩૭૫ છાત્રોને તથા ૫૫૨ ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ છાત્રાલયોમાં ૧૭૫૫૪ છાત્રોને મફત રહેવા જમવાની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવી રહી છે.
- કુલ ૮૯ આશ્રમ શાળાઓ,૧૬ નિવાસી શાળાઓ અને ૭૮૪ બાલવાડીઓ ચલાવવામાં આવે છે.
- તબીબી તથા કાયદો મળીને ૪૬ સ્નાતકોને લોન સહાય આપવામાં આવેલ છે.
- કુલ ૩૫૪ કાયદા સ્નાતકોને સીનીયર કાયદા શાસ્ત્રી પાસે તાલીમ આપવામાં આવે છે.
- કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના નીચે ૩૭૬૩ કન્યાઓ, માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના નીચે ૧૭ દંપતિઓ, આંતર જાતિના લગ્ન માટે ૯૬ દંપતિઓ, આવાસ માટે ૧૨૫૬ વ્યકિતઓને, ૪૯૩ અતિ પછાત જાતિઓના વ્યકિતઓને, તથા ૩૯૮૪ વ્યકિતઓને તબીબી સહાય આપવામાં આવી છે.
- ડૉ. આંબેડકર ભવનના બાંધકામ માટે હિંમતનગર અને પોરબંદર ખાતે શિલારોપણ વિધિ તથા જૂનાગઢ ખાતે છોકરાઓ માટે નવા છાત્રાલયનું ઉદ્‌ઘાટન કરવામાં આવેલ છે.

આદિજાતિ કલ્યાણ

દેશની કુલ અનુસૂચિત જનજાતિની ૮.૦૧ ટકા વસ્તી સામે ગુજરાત ૧૪.૭૬ ટકા જેટલી એટલે કે ૭૪.૮૧ લાખની આદિવાસીની વસ્તી ધરાવે છે જે રાજયની પૂર્વ પટ્ટીના વિસ્તારમાં કેન્દ્રિત થઇ છે આ લોકોની આર્થિક સ્થિતિ નાજુક હોવાથી તેમના વિકાસ માટે આદિજાતિ પેટા યોજના અંતર્ગત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આના ભાગરૂપે આદિજાતિ પેટા યોજના નીચે જુદી જુદી યોજનાઓ/કાર્યક્રમો માટે ચાલુ વર્ષે રુપિયા ૮૭૩.૧૫ કરોડની જોગવાઇ કરેલ છે તથા ન્યુ ગુજરાત પેટર્ન હેઠળ ચાલુ વર્ષે રુપિયા ૧૩૧.૯૩ કરોડ આદિજાતિ વિસ્તારના જિલ્લાઓમાં જુદી જુદી માળખાકીય સવલતો ઉભી કરવા ફાળવાયેલ છે જે પૈકી ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ સુધી રુપિયા ૭૪.૬૩૨૪ કરોડનો ખર્ચ થયેલ છે.

આદિવાસીઓ ખેડૂતો પાસે નાના જમીનના ટૂકડા હોવાથી જીવન નિર્વાહ કરી શકતા નથી જેથી વર્ષો સુધી વળતર આપનારા ફળાઉ વૃક્ષો માટે પૂર્વ પટ્ટીમાં ૧૨,૧૮૧ એકર વિસ્તારમાં બનાસકાંઠાથી ડાંગ વિસ્તારમાં વાડી યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં એફ.એફ.ડી.સી. કનોજને સુગંધિત પાકો અને આર્યુવેદિક પાકોના વાવેતરમાં જોતરવામાં આવ્યું છે. એફ.એફ.ડી.સી.એ નવા પાકો જેવા કે ફેંચ તુલસી, મેન્થાસ્પે, સીટ્રોનેલા જાવા, લેમનગ્રાસ અને પામરોઝા જેવા પાકોનું ઉત્પાદન ૧૨ પ્રાયોજના વિસ્તારમાં શરુ કરેલ છે.

વિચરતી જાતિ અને વિમુકત જાતિ કલ્યાણ

વિચરતી અને વિમુકત જાતિઓના કલ્યાણ માટે પણ મારી સરકાર ચિંતીત છે આ જાતિઓ માટે પણ સરકારે સંખ્યાબંધ્ધ પગલાં લીધા છે.જેવા કે- બજાણીયા, વણઝારા મદારી, ફકીર, નટ, ઠાકોર, વાદી, તલાટી, વિગેરે માટે પંડિત દિન દયાળ ઉપાઘ્યાય આવાસ યોજના નીચે ૧૯ કોલોનીઓ બાંધવામાં આવી છે જયારે ૭ પ્રગતિમાં છે અને ૫૦ નવી કોલોનીઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ સાયકલ ખરીદવા માટે ધોરણ. ૮માં અભ્યાસ કરતી ૧૬૯૨૮ વિદ્યાથીર્નીઓને રૂા.૨.૫૯ કરોડ ચુકવવામાં આવ્યા છે.

સમાજ સુરક્ષા પ્રભાગ અશકત, અનાથ, વૃધ્ધ, ત્યજેલા, વગેરેના કલ્યાણ માટે તાલીમ, સારસંભાળ, પુનઃવસવાટ, જેવી સેવાઓ પૂરી પાડે છે

સમાજના અરક્ષિત વગોર્ના કલ્યાણ સંદર્ભમાં ૨૫૭૬૬ અશકત વિદ્યાર્થીઓને રૂા.૧૭૭.૫૭ લાખની શિષ્યવૃત્તિ તથા ૧૨૧૩ લાભાર્થીઓને રૂા.૧૬.૭૮ લાખની સહાય આપવામાં આવી છે.

વિકલાંગોના પુનઃવસવાટ કાર્યક્રમ માટે ૩૭ તાલુકાઓમાં ઘર દીઠ મોજણીની કામગીરી રૂા.૧૬૩ લાખના ખર્ચે કરવામાં આવી રહેલ છે.

સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ ૬૫૩૮ વિકલાંગો તથા નિરાધારોને રૂા.૬૬.૨૨ લાખ સહાય પેટે ચૂકવવામાં આવ્યા છે.

વૃધ્ધાવસ્થા સહાય પેટે ૯૩,૨૦૧ વૃધ્ધોને રૂા.૨૮૫૫.૫૬ લાખ સહાય આપવામાં આવી છે.

ગ્રામ વિકાસ

મારી સરકારે ગ્રામ્ય પ્રજાના રોજગાર માટે સતત ચિંતા સેવી છે **સ્વર્ણજયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના** હેઠળ અત્યાર સુધીમાં ૬૦૩૬૪ જૂથોની રચના થયેલી છે. આ અંગે ચાલુ વર્ષે ડીસે-૦૪ સુધીમાં ૪૮૪૭ સ્વરોજગારી સ્વસહાય જૂથો આવરી લેવાયેલ છે.

આ સ્વસહાય જૂથો ને રૂા.૭૨૦.૫૬ લાખની લોન અને રૂા.૩૭૯.૧૧ લાખની સહાય અને વ્યકિતગત ધોરણે કુલ મળીને રૂા. ૨૧૦૦.૩૨ લાખની લોન તથા રૂા.૧૦૨૯.૩૦ લાખની સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે.

આ ગૃહના સન્માનનિય સભ્યોને એ જણાવતાં મને ખુબ જ હર્ષ થાય છે કે રાજયનાં ૧૮,૦૦૦ ઉપરાંતના ગામોને સુનિશ્ચિત સમયગાળામાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે ચાલુ વર્ષે ગોકુળ ગ્રામ યોજના અંતર્ગત **ડીસેમ્બર - ૨૦૦૪ સુધીમાં ૧૨,૪૮૧ ગામોને સંપૂર્ણ ગોકુળ ગ્રામ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.**

ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વધારાની વેતન રોજગારી દ્વારા અન્ન સુરક્ષિતતા પુરી પાડવાના અને પોષણ સ્તરને સુધારવાના ઉદ્દેશથી સને ૨૦૦૧ ના સ્વાતંત્ર્ય દિને જાહેર કરેલ **"સંપૂર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના"** નામની નવી કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના સ્વતંત્ર યોજના તરીકે અમલમાં આવેલ છે. જેનું અમલીકરણ, જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા કરવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષમાં ડીસે-૦૪ અંતિત રૂા.૮૯૭૧.૩૫ લાખનું નાણાંકીય ખર્ચ કરી આ યોજના હેઠળ ૧૨૦૨૫૮ મેટ્રીક ટન અનાજના જથ્થાનો વપરાશ કરી રૂા.૧૮૪.૬૭ લાખ માનવદિન રોજગારી ઉત્પન્ન કરેલ છે.

ગ્રામીણ વિસ્તારનાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતાં ગ્રામીણ ગરીબોને આવાસની સુવિધા પુરી પાડવાનાં હેતુ સાથેની **ઇન્દીરા આવાસ યોજના** અન્વયે લાભાર્થીને નવા આવાસ તથા આવાસ સુધારણા (અપગ્રેડેશન) નો લાભ નિયત યુનિટ કોસ્ટની મર્યાદામાં આપવામાં આવે છે.

ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ માટે નવા આવાસો તથા આવાસ સુધારણા (અપગ્રેડેશન) માટે આ યોજના હેઠળ રૂા.૧૩૭૮.૦૮ લાખ ની કુલ નાણાંકીય ફાળવણી નકકી કરવામાં આવેલ છે, જેની સામે ડીસે-૦૪ સુધીમાં નવા આવાસોમાં રૂા. ૩૫૪૮.૭૮ લાખના ખર્ચે ૧૩૧૦૩ આવાસો પૂર્ણ કરેલ છે જયારે ૧૩૯૭૫ આવાસો બાંધકામ હેઠળ પ્રગતિમાં છે. આવાસ સુધારણા હેઠળ રૂા.૭૦૮.૨૯ લાખનો ખર્ચ કરી ૬૪૧૫ આવાસ સુધારણાના કામો પૂર્ણ કરેલ છે અને ૪૧૯૬ પ્રગતિ હેઠળ છે.

મારી સરકાર ગ્રામ્ય ગરીબો અને અન્ય નબળા વર્ગના ઉત્થાનને વરેલી છે. રાજયમાં ગૃહ નિર્માણની પ્રવૃત્તિ દ્વારા ભૂમિહીન ખેતમજુરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને મફત ઘરથાળની જમીન પુરી પાડી તેના પર ૧૦૦ ટકા સરકારી સહાયથી લાભાર્થીને જાજરુ - બાથરુમની સવલતવાળા પાકા મકાનની સુવિધા પુરી પાડવાના હેતુ સાથેની **સરદાર પટેલ આવાસ યોજના** અમલમાં છે. આ યોજના હેઠળ ચાલુ વર્ષે ૩૬૬૭૦ આવાસો બાંધવાનાં લક્ષ્યાંક સામે કુલ ૧૧૯૩૦ આવાસો બંધાયેલ છે. જેમાં ૧૬૧૮ આવાસો અનુસૂચિત જાતિ માટે અને ૩૦૫૫ આવાસો અનુસૂચિત જનજાતિ માટે બંધાયેલ છે.

ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામનો આદર્શ પુર્ણ કરવા વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ને ઇ-ગવર્નન્સ વર્ષ તરીકે જાહેર કરેલ છે ત્યારે રાજય સરકાર દ્વારા પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ જેવી કે, ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને જીલ્લા પંચાયતોનાં કોમ્પ્યુટરાઇઝેશનનો કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવેલ છે જેમાં માર્ચ ૨૦૦૫ સુધીમાં ૫૩૦૦ ગ્રામ પંચાયત ઇ-ગ્રામ પંચાયત થશે. ઇ-ગ્રામ બનાવવા માટે પછાત અને આદિવાસી વિસ્તારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં

આવેલ છે. આમ પ્રોજેકટ હેઠળ વેરાની વસુલાત, આકારણી, બી.પી.એલ. યાદી, જન્મ - મરણની નોંધણી, જાતિના પ્રમાણપત્રો, ૭/૧૨ અને ૮-અ ના ઉતારા ની વિગતો આપવાનું તથા ગ્રામ્ય ડેટાબેઇઝ ઉભું કરવાનું આયોજન છે. ભવિષ્યમાં ઇ-ગ્રામ પંચાયત એ જુદી જુદી સરકારી સેવા સંદર્ભમાં ઇ-સર્વિસ કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવશે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી.

દરેક તાલુકા પંચાયત અને પંચાયત રાજના તાલીમ કેન્દ્રને ટી.વી.સેટ સાથે ડાયરેકટ રીશેપ્શન સિસ્ટમ આપવામાં આવી રહેલ છે. રાજયની ૨૫ જીલ્લા પંચાયતો તથા ૧૯૦ તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી GSWAN કનેકટીવીટીથી ચાલુ વર્ષે સંકળાઇ ચૂકેલ છે. રાજય સરકાર દ્વારા માર્ગદર્શક સુચના, તાલીમ અથવા સરકારશ્રીની યોજનાની વિગતો તાલુકા ક્ક્ષાએ સીધી આપી શકાશે.

ગ્રામસભાની ચુંટણી સર્વસંમતિથી અને બિનહરીફ થાય તે હેતુથી સમરસ યોજના હેઠળ સર્વ સંમતિથી ચુંટાયેલ હોય તેવી ૫૦૦૦ સુધીની વસ્તી ધરાવતી ગ્રામ પંચાયતને રૂા.૬૦,૦૦૦/- અને ૫૦૦૦ કરતાં વધુ વસ્તીવાળી ગ્રામ પંચાયતને.૧.૦૦ લાખ સુધીનું અનુદાન આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી ૩૭૯૪ ગ્રામ પંચાયત સમરસ બનેલ છે જે માટે રૂા .૨૩૦૬ લાખ ફાળવી આપવામાં આવેલ છે.

ગામના લોકો વચ્ચે સંપ અને એકતાનો સંગમ સધાય તે હેતુથી ચાલુ વર્ષથી આ યોજના અમલમાં આવેલ છે. જે અંતગર્ત પસંદ થયેલ ગામોને એક લાખનો પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. અત્યાર સુધીમાં ૧૨૬ તીર્થગ્રામ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત પંચવટી યોજના હેઠળ ગ્રામ વન યોજનાને આધારે ગામજનોને હરવા-ફરવા અને આનંદ પ્રમોદની સુવિધા માટે બાગ-બગીચાનું સ્થળ પ્રાપ્ત થશે.

ગ્રામસભાના અત્યાર સુધીમાં ૮ તબકકા પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે. ૮ તબકકાની ૧.૩૩ લાખ ઉપરાંતની ગ્રામસભાઓમાં ૫૪.૪૦ ટકા પ્રશ્નોનો સ્થળ પર નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. અત્યાર સુધીમાં ૫,૭૩,૪૮૦ એટલે ૯૩.૪૬ ટકા પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

ગ્રામસભાના પ્રશ્નો અંગે રાજય સરકારે વરિષ્ઠ અધિકારીઓની એમ્પાવર્ડ કમિટીની રચના કરી હોવાથી પડતર પ્રશ્નોનો નિકાલ ઝુંબેશના ધોરણે મોટા પાયે કરવામાં આવ્યો છે. ચાલુ વર્ષે ગ્રામસભાના પડતર પ્રશ્નોના નિકાલ માટે રૂા..૧૨.૫૦ કરોડની રકમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

૧૧મા નાણાંપંચની ભલામણો અન્વયે વર્ષ ૨૦૦૦ થી ૨૦૦૫ ના ગાળા દરમ્યાન વાર્ષિક રૂા..૬૯.૯૧ કરોડ લેખે ૫ વર્ષના રૂા.૩૪૮.૫૦ કરોડની કેન્દ્રીય સહાય મળનાર છે. આ યોજના અન્વયે રસ્તા, આંતરિક રસ્તા, એપ્રોચ રોડ, શાળાના ઓરડા, પીવાના પાણીના કામો, સિંચાઇના કામો, પંચાયત ઘર, સ્મશાન ગૃહ, સેનેટરી વિગેરે કામો હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત જયોતિગ્રામ યોજના તથા ઇ-ગ્રામ યોજનાનો ૧૧મા નાણાંપંચમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

મહિલા અને બાળ કલ્યાણ

રાજયમાં મહિલાને સમાજની મુખ્ય ધારામાં લાવવા તથા તે પરત્વે સંવેદનશીલતા ઉભી કરવા માટે અને તેમાંય ખાસ કરીને મહિલાઓ તથા સામુદાયિક સશકિતકરણ, મહિલાઓ સામેની હિંસા પ્રત્યેની જાગૃતતા, મહિલાઓના પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય તથા તારુણ્ય જાતિય અને પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય પરત્વે લોકોને સંવેદનશીલ બનાવવા માટે એક જેન્ડર રીસોર્સ સેન્ટર (UNFPA) જેવી વૈશ્વકિ સ્તરની સંસ્થાની સહાયથી ઉભું કરવામાં આવ્યું છે .દેશની મહિલા નીતિને ધ્યાનમાં લઇ રાજયની નારી ગૈારવ નીતિ (જેન્ડર ઇકવીટી પોલીસી) નો મુસદ્દો તૈયાર છે જે ટૂંક સમયમાં અમલી બની જશે. આ ઉપરાંત સ્વશકિત યોજનાતળે ૧૦ જિલ્લાઓમાં ૨૬૦૦ જેટલા સ્વસહાય જૂથો બનાવી ૪૦,૦૦૦ જેટલી મહિલાઓને લાભાન્વીત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ગ્રામ વિકાસની અલગ- અલગ યોજનાઓના ૨૫ હજાર ઉપરાંતના સ્વસહાય જૂથો કામ કરી રહયા છે.

ગુજરાતનું એક પણ બાળક પોષણ કે આરોગ્ય તથા શિક્ષણ વગેરેની સુવિધાથી વંચિત રહી ન જાય તે માટે સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના હેઠળ સઘન કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે અને સ્ટેટ પ્લાન ઓફ એકશન ફોર ચિલ્ડ્રન (SPAC) તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

૨૦ મુદ્દા કાર્યક્રમ

આ કાર્યક્રમમાં સમાજની અધિકત્તમ સમસ્યાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. આમાંની ઘણી મહત્વની યોજનાઓનું મુખ્ય ધ્યેય ગરીબી નિવારણ માટેનું છે. જેનું અસરકારક અમલીકરણ કરીને ગુજરાતે ૨૦ મુદ્દા કાર્યક્રમના અમલીકરણમાં વર્ષ ૨૦૦૩-૨૦૦૪ દરમ્યાન સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ૧૦૦ ટકા સિદ્ધિ સાથે પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કયોર્ હતો.

યાત્રાધામ વિકાસ

મારી સરકાર દ્વારા દ્વારકા, સોમનાથ, ગિરનાર, પાલીતાણાં, ડાકોર અને અંબાજીને યાત્રાધામ તરીકેનો દરજજો આપીને આ યાત્રાધામો ખાતે યાત્રીઓને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે વિકાસના કામો માટે રૂા. ૧૩૦.૦૦ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.

વધુમાં કૈલાસ માનસરોવર તથા અમરનાથની યાત્રાએ જતાં યાત્રીઓને રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં વીમા સુરક્ષા કવચ પણ પુરું પાડવામાં આવે છે.

ગૌ-સેવા

ગાયો અને ગૌવંશની કલ્યાણ પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે રાજયમાં ગૌ સેવા આયોગની સ્થાપના વર્ષ ૧૯૯૯ માં કરવામાં આવી છે જેના દ્વારા એનીમલ વેલફેર બોર્ડ ઓફ ઇન્ડીયાની જુદી જુદી યોજનાઓ તથા ભારત સરકારની ગૌશાળા - પાંજરાપોળોને નાણાંકીય સહાયની યોજનાઓ જેવી કે, કુદરતી આપત્તી પ્રસંગની સહાય, અછતના સમયમાં પશુનિભાવ કામગીરી વિગેરેના અમલીકરણ માટે સક્રિય કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ

મારી સરકાર અસરગ્રસ્તોને માળખાકીય સુવિધા પુરી પાડીને તેની નગર સંસ્કૃતિ ગુજરાતની આગવી ઓળખ બને તે માટે સક્રિય છે. આ માટે વિવિધ કાર્યક્રમો અને યોજનાઓનું અમલીકરણ થઇ રહયુ છે. જેમ કે-

- ભૂકંપગ્રસ્ત કચ્છ વિસ્તારના ભૂજ, ભચાઉ અને અંજારમાં આપત્તિ સંચાલન કાર્યક્રમો સઘન રીતે હાથ ધરીને ૧૩ નગર રચના યોજનાઓ આખરી કરવામાં આવેલ છે.
- ગુજરાત શહેરી વિકાસ કંપની લીમીટેડ દ્વારા રૂા.૪૧૦.૧૪ કરોડના કુલ-૬૬ પેકેજની વિવિધ યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવામાં આવી રહેલ છે. ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ સુધીમાં રૂા.૨૧૧.૮૪ કરોડની પ્રાયોજનાઓ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
- વાલ્મિકી આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ ગરીબી રેખા હેઠળના કુટુંબો માટે અમદાવાદના ઝુંપડપટ્ટી વિસ્તારોમાં ૨૧૭૬ મકાનો અને ૪૪૦ શૈાચાલયો બનાવવાની કામગીરી સબસીડીની સંપૂર્ણ રકમ વાપરીને પુરી કરેલ છે.
- રાજકોટમાં ૬૪૮ શૌચાલયો નું બાંધકામ રૂા.૧૩૪.૮૯ લાખની સબસીડી વાપરીને પુરુ કરેલ છે.
- રાજયની ૧૪૩ નગરપાલિકાઓમાં અમલી એવી વાજપાઇ નગર વિકાસ યોજનાનો પ્રથમ તબકકો પૂર્ણ થતાં બીજા તબકકામાં દરેક નગરપાલિકા માટે કુલ પ્રોજેકટની કિંમતમાં રૂા.૫૦ લાખનો વધારો કરવામાં આવેલ છે.
- બીજા તબકકામાં સુધારો કરીને પાણી પુરવઠો, શુધ્ધિકરણ પ્લાન્ટ, વરસાદી પાણીના જળસંચય, આરોગ્ય સુખાકારી તથા ઘન કચરાના નિકાલ માટેની સુવિધાઓને અગ્રતા આપીને ૬૦ નગરપાલિકાઓના ૧૬૯૧ કામો રૂા.૮૪.૭૧ કરોડના ખર્ચે મંજૂર કરેલ છે. જે પૈકી ૪૨૪ કામો રૂા. ૧૮.૩૫ કરોડના ખર્ચ કરી પૂર્ણ કરેલ છે. બાકીના કામો પ્રગતિમાં છે.
- મુખ્યમંત્રીશ્રીના ૧૫ મુદ્દાના કાર્યક્રમ હેઠળ ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ સુધીમાં આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકો માટે ૩૨,૧૦૮ મકાનો બનાવેલ છે. આ પૈકી કાર્યક્રમનું અમલીકરણ કરતી સંસ્થાઓને મકાન દીઠ રૂા.૫,૦૦૦/- લેખે કુલ રૂા.૨૨૧૦.૦૦ લાખની સબસીડી ચૂકવવામાં આવેલ છે.
- સ્થાનિક સ્વરાજની પ્રવૃત્તિઓ પણ આધુનિકીકરણનું તત્વ દાખલ થાય તે માટે ચાલુ વર્ષમાં દરેક નગરપાલિકાઓને ઇ-ગર્વનન્સ હેઠળ આવરી લેવાનો નિર્ણય કરેલ છે, જે મુજબ ૮૨ નગરપાલિકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે, જયારે બાકીની ૫૯ ને માર્ચ ૨૦૦૫ સુધીમા આવરી લેવામાં આવશે.

કૃષિ અને કિસાન તથા હરિયાળી ક્રાંતિ

મારી સરકારે ગુજરાતના ખેડૂતોની આવક ૫ વર્ષમાં બમણી કરવાનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટેની ત્રણ તબકકાની વ્યુહ રચના નકકી કરી છે. જેમાં.

(૧) કૃષિ વિષયક સંશોધનને ખેડુતો સાથે સીધું જોડવું

(૨) ભૂમિ પૃથ્થકરણ આધારીત સૂક્ષ્મ સ્તરનું, કૃષિ આયોજન અને

(૩) પ્રાપ્ય જળ સંપત્તિના જળ સંરક્ષણનો સમાવેશ કરેલ છે. કેમ કે આપણું રાજય અછત સંભવીત રાજય છે. અને અનિયમીત વરસાદની પેટર્ન ખેતીની સ્થિરતાને અસર કરે છે. મારી સરકાર અસામાન્ય હવામાન સામે ટકી શકે તે રીતે કૃષિને સ્થિર બનાવવા માટે કૃતનિશ્ચયી છે રાજયમાં ખરીફ ૨૦૦૪ ઋતુમાં ૭૫.૬૮ લાખ હેકટરના વાવેતર સામે ૮૭.૫૦ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન મળેલ હતુ એક અંદાજ મુજબ વર્ષ આખરે ૧૫૫.૨૯ લાખ મે.ટન ખેત ઉત્પાદન દ્વારા રૂ.૨૧૦૫૫/- કરોડ મુલ્યનું ઉપાર્જન થશે.

મારી સરકારે પાણીનો કાર્યક્ષમ અને કરકસર પુર્વક ઉપયોગ કરવાના અભિગમ સાથે સુજલામ સુફલામ કાર્યકમ હેઠળ કૃષિ વિસ્તરણ પ્રવૃતિને એક અભિયાન તરીકે સ્વીકારેલ છે. ખેડુતોને પાકો અને તેની જરૂરી ખેતી સામગ્રીના ઉપયોગ માટે માર્ગદર્શન આપવા રાજયની કૃષિ. યુનિ.ના વૈજ્ઞાનીકોને વ્યકિતગત રીતે જોતર્યા છે. વધુમાં રાજયમાં ૪.૮૦ લાખ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ તૈયાર કરી આપવામાં આવ્યા છે જે આવતા વર્ષોમાં પાંચ લાખ થશે.

રાષ્ટ્રિય કૃષિ પાક વીમા યોજના હેઠળ રૂા.૧૯૩.૦૩ લાખ રૂપિયાના દાવા તથા ખેડૂત આકસ્મિક વીમા યોજના હેઠળ ૩૯૭ અસરગ્રસ્ત કુટુંબોને રૂા.૩.૯૧ કરોડના દાવાઓની ચુકવણી કરેલ છે. ખેડૂતોને આધુનિક કૃષિ જ્ઞાનથી સુસજજ કરવા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્રો ખાતે ૧૬૨૭૪ ખેડૂતોને સઘન તાલીમ આપેલ છે. તેમજ તેઓ ખેતી અંગેના દરેક ક્ષેત્ર ની માહિતી મેળવી શકે તે માટે રાજયમાં કિસાન કોલ સેન્ટર ચાલુ કરેલ છે. આજે રાજય કેરી, કેળા અને ચીકુના પાકની ગુણવત્તા માટે પ્રખ્યાત બન્યું છે અને મરી-મસાલાના પાકો જેવા કે જીરુ, વરિયાળી, અને ધાણામાં અગ્રેસર રહયુ છે.

મારી સરકારે કૃષિ-શિક્ષણ અને વિસ્તરણને સંગીન બનાવવાનું નકકી કર્યુ છે. તેના પ્રથમ પગલાંરુપે ચાર કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ, નવસારી,જુનાગઢ અને દાંતીવાડા ખાતે કાર્યરત કરેલ છે. ગત વર્ષે રાજયમાં મબલખ કૃષિ ઉત્પાદન થયેલ છે. જે આગળના વર્ષ કરતાં ૪૦ વધારે છે. ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ દર ૧૨ ટકા રહેલ છે. ઉપરાંત ખેત પેદાશોની કિંમત, નકકી કરેલ ટેકાના ભાવથી ઓછી ન થાય તે માટે અસરકારક પગલાં લેવામાં આવી રહેલ છે. વાઈબ્રાન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫ અંતગર્ત કૃષિ અને સંલગ્ન સેવામાં ૩૪ કરાર કરી રૂા.૧૦૦,૦૯૩ કરોડનું રોકાણ સુનિશ્ચિત કરેલ છે. કૃષિ ધિરાણ વિમો અને આર્થિક ટેકારૂપ ૧૫ લાખ કિશાન કેડીટ કાર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવેલ છે. ચાલુ વર્ષ નાબાર્ડ અને અન્ય બેંકોના સહયોગથી વધારાના ૫ લાખ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા છે. સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૪ સુધીમાં રૂ.૪૫૦૦ કરોડના ધિરાણની ૧,૧૮૦૦૦ ખેડુતોને લોન મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

વન

ગુજરાત વન્ય સૃષ્ટિ અને જૈવિક વૈવિધ્યનો સમૃધ્ધ વારસો ધરાવે છે અને વધતી જતી વસતિ તથા ઔદ્યોગિકરણના કારણે પ્રદૂષણની સમસ્યા સામે પ્રકૃતિના દોહન નો વિકાસ મંત્ર આત્મસાત કરવા વન વૃદ્ધી વન સંરક્ષણ તથા વન્ય સૃષ્ટિના જતન માટે સામાજિક સહયોગ અને લોક શિક્ષણ દ્વારા પ્રવૃત્તિશીલ રહયું છે. પરિણામે ૨૦૦૧ માં ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ પ્રમાણે છેલ્લા ચાર વર્ષોમાં ૨૧૪૬ ચો.મી નો વનસ્થાપિત વિસ્તાર વધ્યો છે. સહભાગી વન વ્યવસ્થામાં ૧૬૪૧ ગામોમાં ગ્રામવન સંરક્ષણ સમિતિઓ કાર્યરત છે.

વનીકરણની લોક ઝુંબેશ ઉપરાંત ગુજરાત સરકારે રતન જયોત (Jetrofa) ના વાવતેર માટેનું અભિયાન હાથ ધર્યુ છે બાયો ફયુએલના ક્ષેત્રે "રતન જયોત"ના વાવેતરને પ્રોત્સાહિત કરવાની પહેલ સરકારે કરી છે. આ ઉપરાંત ગાંડા બાવળ અતિશય ફેલાવાથી ખેતી, જમીન, જાહેર સ્થળો, વીજળીની લાઇનો અને નાગરિકોને થઇ રહેલા નુકશાનની વ્યાપકતા જોતા ગાંડા બાવળને દૂર કરવા, રહિયત કે અનામત જંગલ વિસ્તાર સિવાયના કોઇપણ વિસ્તારમાંથી તેને કાપવાની કોઇપણ પરવાનગી લેવાની જરૂર નથી તેવો પ્રજાહિતમાં કાયદાકીય સુધારો કર્યો છે અને તેના લાકડા કે તેમાંથી બનેતા કોલસાને વાહતુક હેતુના પાસ લેવામાંથી મુકિત પણ આપી દીધી છે. પ્રકૃતિ શિક્ષણ, પર્યાવરણ ંરક્ષણ અને વૃક્ષવનના જતન માટે લોક ભાગીદારીને પ્રેરિત કરવા તથા ગીર ફાઉન્ડેશનની આંતર રાષ્ટ્રીય ઓળખ ઉભી કરવાની પ્રતિલક્ષતા રાજય સરકારે દાખવી છે.

માર્ગ વિકાસ

મારી સરકારે માર્ગ વિકાસની નોંધપાત્ર આર્થિક વિકાસ માટે પાયારૂપ માળખાકીય સવલત ગણીને વેપાર ઉદ્યોગને તે મળી રહે તેમજ વાહન વ્યવહાર ઝડપી બને અને પેટ્રોલ અને શકિતનો બચાવ થાય તે હેતુને લક્ષમાં લઇને માર્ગ વિકાસ ક્ષેત્રે નીચેના કામો હાથ ધર્યા છે.

- રાજયના ૧૮૫૦ કિ.મિ.ના ધોરીમાર્ગોને અદ્યતન બનાવવાની વિશ્વબેંક સહાયિત યોજનામાં સંતોષકારક પ્રગતિ થયેલ છે. ૭૫૫ કિ. મિ. લંબાઇના રસ્તાનાં કામ રૂા. ૫૫૩ કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થયેલ છે અને ૮૫૪ કિ.મિ. લંબાઇના રસ્તાના કામો રૂા. ૯૪૫ કરોડના ખર્ચે પ્રગતિ હેઠળ છે.
- ભૂકંપ પુનઃર્નિમાણ હેઠળ ૯૫૬ કિ.મિ. લંબાઇના રાજય ધોરીમાર્ગની સુધારણાની યોજના રૂા. ૩૦૪ કરોડના ખર્ચે વિભિન્ન તબક્કે પ્રગતિ હેઠળ છે.
- કુલ રૂા. ૧,૦૦૦ કરોડના ખાનગી રોકાણ દ્વારા ૮ યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરેલ છે.
- ખાનગીકરણની પ્રક્રિયા હેઠળ ડીસાથી પાંથાવાડા થઇને રાજસ્થાન સરહદના ગુંદરી સુધીની ૪૫ કિ.મિ. લંબાઇને રૂા.૨૫ કરોડના ખર્ચે ખાનગી ધોરણે વિકસાવવા મંજુર કરેલ છે.
- કિમ-માંડવી ૩૮ કિ.મિ., હિંમતનગર બાયપાસ ૮.૭ કિ.મિ. અને સુઇગામથી સિધ્ધાડા ૪૨ કિ.મિ. ને ખાનગી ધોરણે હાથ ધરવાની કાર્યવાહી ગતિમાં છે.
- ચાલુ વર્ષે રાષ્ટ્રિય ધોરીમાર્ગ વિકાસ યોજના હેઠળ નડીયાદથી વડોદરા એકસપ્રેસ-વેના ૫૦ કિ.મી. નો માર્ગ રૂા.૩૪૫ કરોડ ખર્ચે પૂર્ણ કરેલ છે.
- હિંમતનગરથી ચિલોડા સેકશનના ૫૨ કિ.મિ. ની કામગીરી રૂા. ૧૪૫ કરોડના ખર્ચે અને સુરતથી અતુલના ૮૦ કિ.મિ. ના માર્ગને રૂા.૩૯૦ કરોડના ખર્ચે ચાર લેઇન પહોળા કરવાની કામગીરી પૂર્ણતાના અગ્ર તબક્કે છે.
- મને આનંદ છે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની માર્ગો દ્વારા જોડાણની અગત્યતાને પણ ધ્યાને રાખી છે તે નીચેની બાબતોથી ફલિત થશે.
- ભૂકંપગ્રસ્ત ૧૨ જિલ્લાઓમાં ૧૮૧૨ કિ.મિ. લંબાઇના માર્ગો ને રૂા.૧૦૬ કરોડના ખર્ચે એડીબી સહાયિત યોજના હાથ ધરી છે. જેમાં ૧૧૩૫ કિ.મિ. લંબાઇનું કામ પૂર્ણ થયેલ છે અને બાકીના કામો માર્ચ ૨૦૦૫ સુધીમાં ભૌતિક રીતે પૂર્ણ થનાર છે.
- પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ ૧૦૬૪ રસ્તાની રૂા. ૨૮૭.૫૧ કરોડની યોજના મંજુર થયેલ છે જેમાં ૧૫૬૦ કિ.મિ. લંબાઇના નવા રસ્તા તથા ૬૭૯ કિ.મિ. લંબાઇની માર્ગ સુધારણાનો સમાવેશ થાય છે. આ પૈકી ૯૭૦ કિ.મિ. લંબાઇના નવા રસ્તા અને ૫૭૪ કિ.મિ. લંબાઇની માર્ગ સુધારણાનું કામ પૂર્ણ થયેલ છે. આ યોજના દ્વારા ૫૦૦ થી વધુ વસ્તીવાળા ૧૦૯૫ ગામ / પરાને ડામર સપાટીના રસ્તાથી જોડાણ મળશે.
- આ ઉપરાંત ચાલુ વર્ષે ૧૨૮ ગ્રામ્ય માર્ગોને ૪૫.૬૦ કરોડના ખર્ચે પ્રથમવાર ડામર સપાટીના કરવાનું આયોજન હોવાથી ૧૩૦ ગામ / પરા લાભાન્વિત થશે.

પાણીને કુદરતની અમૂલ્ય ભેટ ગણીને સરકારી મકાનોના નવા બાંધકામોમાં જળસંચય ફરજીયાત કરવામાં આવેલ હોવાથી ૭૪૫૮ મકાનોમાં અંદાજે ૩૦.૯૫ લાખ ચો.મી. છત વિસ્તાર પૈકી ૩૪૬૫ મકાનોના ૨૧.૮૫ લાખ ચો.મી. છત વિસ્તાર માટે જળસંચય યોજનાનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે.

બંદરો

મારી સરકારે જાહેર કરેલ બંદરનીતિના સફળતાપૂવર્કના અમલીકરણને પરિણામે મુંદ્રા અને પીપાવાવ ખાતે બે આધુનિક બંદરો કાર્યાન્વિત થયા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં હજીરા ખાતે એલ.એન.જીની આયાત માટે મે. શેલની (આંતરરાષ્ટ્રીય કંપની) દ્વારા અંદાજે રૂા.૩૪૪૨ કરોડના મૂડીરોકાણથી તથા દક્ષિણ ગુજરાતમાં દહેજ બંદરે કેન્દ્ર સરકારના પેટ્રોલિયમ જાહેર સાહસોની બનેલી સંયુકત ક્ષેત્રની કંપની મે.પેટ્રોનેટ એલ.એન.જી લી. દ્વારા એલ.એન.જી ટર્મીનલ વિકસાવવાની યોજના અંદાજે રૂા.૩૧૩૦ કરોડના મૂડીરોકાણથી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. જેનું બાંધકામ પૂર્ણ કરી એલ.એન.જી. નું પ્રથમ જહાજ ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૪ માં લાંગરવામાં આવેલ હતું.

મુંદ્રા બંદર અને આદીપુરને જોડતી બ્રોડગેજ રેલ્વે લાઈનનું કામ પૂર્ણ થયું છે. વિકાસના પ્રથમ તબક્કાના ભાગરૂપે મુંદ્રા બંદર ખાતે મે. ગુજરાત અદાણી પોર્ટ લી. દ્વારા કન્ટેઈનર ટર્મીનલ વિકસાવવામાં આવેલ છે. પીપાવાવ બંદરને જોડતી બ્રોડગેજ રેલ્વે લાઈનનું કામ પણ હાથ ધરવામાં આવેલ છે, જે આખરી

તબક્કામાં છે. આમ, ગુજરાતના બંદરો પર સોલીડ કાર્ગો કન્ટેઈનર્સ તેમજ એલ.એન.જી. જેવા કાર્ગો હેન્ડલ કરવા માટેની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થયેલ છે. આમ બંદરીય વિકાસના આ પગલાંઓના પરિણામે ગુજરાત દેશની સમુધ્ધિનું પ્રવેશદ્વાર બને છે.

મત્સ્યોદ્યોગ

ગુજરાત રાજયનો દરિયાઈ મત્સ્ય ઉત્પાદનનો હિસ્સો ૯૩.૦૬ ટકા જેટલો છે અને આંતરદેશીય મત્સ્ય ઉત્પાદનનો હિસ્સો ૬.૯૪ ટકા જેટલો છે. વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ દરમ્યાન સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૪ સુધીમાં મત્સ્ય ઉત્પાદન ૧.૪૭ લાખ જેટલું થયેલ છે.

ધોલાઈ અને ઓખા મત્સ્ય બંદર વિકસાવવા માટે વહીવટી મંજૂરી મળતા આ બન્ને પ્રોજેકટ માટે કુલ રૂા.૪૦૦ લાખની ગ્રાન્ટ રીલીઝ કરેલ છે.

મહેસૂલી વહીવટ

રાજયના જમીન દફતરની જાણવણી ચોકસાઇપૂર્વક થાય તથા તે સુરક્ષિત રહે અને લોકોને તે સરળતાથી તથા ત્વરીત ઉપલબ્ધ થાય સાથોસાથ જમીન દફતર વ્યવસ્થાપન પધ્ધતિ પારદર્શક બને તે હેતુથી જમીન દફતર કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન યોજના હેઠળ લગભગ તમામ ગામોના તમામ ખાતેદારોના ૭/૧૨ અને ૮- અ ના રેકર્ડ ઓન લાઇન કરવામાં આવેલ છે. ગત સ્વાતંત્ર્યદિનથી ગામમાં નિભાવવામાં આવતા ૭/૧૨ અને ૮-અનાં હસ્ત લિખીત નમૂના આપવાની પ્રથા બંધ કરીને કોમ્પ્યુટરરાઇઝડ નકલને જ સ્વીકૃત ગણવામાં આવી છે. ખાતેદારોને આ દસ્તાવેજોની નકલો મેળવવામાં મૂશ્કેલી ન પડે તે હેતુથી તલાટી મારફતે ગામમાંથી જ મળે તેવુ આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આમ આ વ્યવસ્થા માત્ર ટેકનોલોજીના ઉપયોગ પૂરતી જ નહિં પરંતુ તેનાથી જમીન માલિકના હક્કો સુરક્ષિત બન્યા છે તે દ્રષ્ટિએ પણ મહત્વની છે.

મારી સરકારે તા.૧૧-૬-૨૦૦૪ના હુકમથી જે વ્યકિતઓએ સ્ટેમ્પ ડયુટીની બાકી રકમ અને તેનું વ્યાજ ભરવાનું થતું હોય તે રકમમાં રાહત આપવા માટે એમનેસ્ટી યોજના જાહેર કરેલ છે.

જનસેવા કેન્દ્રો

મારી સરકાર દ્વારા કલેકટરશ્રી અમદાવાદના નવા મકાનમાં અધતન સુવિધાઓ સાથેનું એક જનસેવા કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જયાંથી અરજદારોને જરૂરિયાત મુજબના પ્રમાણપત્રો, જમીનના ૭/૧૨ અને ૮-અ ના ઉતારાની નકલો અને પરવાનાઓ રૂા.૨૦/- જેટલો લઘુતમ ચાર્જ લઇને એક જ દિવસમાં પુરા પાડવામાં આવે છે. અમદાવાદ ઉપરાંત રાજયના જુદાજુદા જિલ્લાઓની કલેકટર અને મામલતદારની ૧૦૦ કરતાં પણ વધુ કચેરીઓ ખાતે પણ આવા જ જનસેવા કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

ફાજલ જમીન વહેંચણી

ફાજલ થયેલ જમીન જરૂરિયાતમંદ લાભાર્થીઓને વહેંચવામાં આવે છે જે અન્વયે મારી સરકારે તેને ફાળવવામાં આવેલ ૪૦૦ એકરના લક્ષ્યાંક સામે ડીસેમ્બર-૦૪ સુધીમાં ૫૧૫ એકરની ફાળવણી થઇ ગઇ છે એટલે કે ૧૨૮ ટકાની સિધ્ધિ હાંસલ થયેલી છે.

સુનામી ગ્રસ્તને સહાય

આપ સર્વે જાણો છો તેમ ગત ડીસેમ્બરમાં ઇન્ડોનેશિયામાં થયેલ ભૂકંપની સુનામી અસરો આંદામાન-નિકાબાર ટાપુઓ, તામિલનાડુ, પોંડિચેરી, આંધપ્રદેશ અને ઓરિસ્સા રાજયોમાં થઇ હતી અને ત્યારે સુનામી અસરગ્રસ્તોની મદદે પહોંચનાર મારી સરકાર સૌથી પહેલી હતી.

મારી સરકારે મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહતફંડમાંથી તામિલનાડુને રૂા.૫ કરોડ, આંદામાન - નિકોબારને રૂા.૨ કરોડ, પોંડિચેરીને રૂા.૧ કરોડ, આંધપ્રદેશને રૂા.૧ કરોડ અને ઓરિસ્સાને રૂા.૧ કરોડ મળી કુલ રૂા.૧૦ કરોડની રોકડ સહાય અને તે ઉપરાંત લોક સહયોગથી સુનામી અસરગ્રસ્ત આ રાજયોને હવાઇ, રેલવે અને રસ્તા માર્ગે જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ મળીને અંદાજે રૂા.૧૫ કરોડની ૩૫૪૫ ટન જેટલી રાહત સામગ્રી મોકલી આપેલ છે. એટલું જ નહી પરંતુ આંદામાન-નિકોબારમાં ખોરવાયેલા સંદેશા વ્યવહાર માળખાને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે રાજય સરકારે ૧૦ સભ્યોની હેમ રેડિયો ઓપરેટર્સની ટીમને તાત્કાલિક આંદામાન નિકોબાર મોકલી હતી.

એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કે ગુજરાત માનવતા અને કરૂણાની બાબતમાં હમેશાં અગ્રેસર રહયું છે.

જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા

મારી સરકારે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટુંબો માટે અગાઉ ૧૨..૫ કિલોગ્રામ અનાજના જથ્થાને બદલે હવે દરેક કાર્ડધારક કુટુંબને માસિક ૨૦ કિલોગ્રામ અનાજનો જથ્થો વ્યાજબી ભાવે પૂરો પાડવાનું નકકી કર્યુ છે. આજ પ્રમાણે અંત્યોદય યોજનામાં ૨૫ કિલો ને બદલે ૩૫ કિલો અનાજમાં બે રુપિયે પ્રતિકિલો ઘઉં અને ૩ રૂા.કિલોગ્રામ ચોખા ગરીબી રેખા નીચેના તેમજ અન્ય કુટુંબને આપવાનું ઠરાવેલ છે.રાજયની અન્નપૂર્ણા યોજના અન્વયે ૬૫ વર્ષની ઉપરના વ્યકિતઓ કે જેમનો રાષ્ટ્રિય વૃધ્ધત્વ પેન્શન યોજનામાં સમાવેશ થયેલ નથી તેમને માસિક ૧૦ કિલોગ્રામ અનાજ મફત આપવા નકકી કર્યુ છે.

જે કુટુંબો રોજગારી અને મજૂરી અર્થે પોતાના વતનથી અન્યત્ર ફરતાં રહે છે તેમના માટે પ્રથમ તબકકે પંચમહાલ જિલ્લામાં રોમીંગ રેશનકાર્ડનો કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકેલ છે. જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા માટે આ એક સીમાચિન્હરુપ પગલું બની રહેશે એવો મને વિશ્વાસ છે.

રાજય સરકારે ૨૦૦૦ ની વસ્તી ૪૦૦ કાર્ડની મર્યાદા અને ૩ કિ.મી. સુધીના અંતરમાં ૧ વ્યાજબી ભાવની દુકાન ફાળવવા ઠરાવેલ છે. પરંતુ આ યોજનાને વ્યવહારુ બનાવવા માટે દીનદયાળ યોજના હેઠળ સ્થાનિક બેકાર વ્યકિતઓના આત્મર્નિભર થવા માંગતા જૂથોને અગ્રિમ પસંદગી આપવાનું નકકી કર્યુ છે.

ગ્રાહક સુરક્ષા

રાજયમાં ૧૯ જિલ્લામાં ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ તથા એક રાજય ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશન કચેરી છે. જેમાં દાખલ થયેલ કુલ-૧૯૫૦૦ જેટલા કેસો પૈકી ૧૨૯૦૦ જેટલા કેસોનો નિકાલ કરેલ છે. જયારે જિલ્લા ફોરમ સમક્ષ દાખલ થયેલ ૯૨૦૦૦ જેટલા કેસો સામે ૭૪૦૦૦ જેટલા કેસોનો નિકાલ કરેલ છે. પડતર રહેલ કેસોનો સમય મર્યાદામાં નિકાલ થાય અને ગ્રાહકોને ઝડપથી ન્યાય મળે તે માટે મારી સરકારે અમદાવાદ શહેર માટે વધારાના જિલ્લા ફોરમની તેમજ રાજયકમીશન માટે વધારાની સકીર્ટ બેંચની રચના કરેલ છે.

નશાબંધી

ગુજરાત રાજયની સ્થાપનાથી રાજય સંપુર્ણ નશાબંધી નીતિને વરેલુ છે. સરકાર નશાબંધીની નીતિનો યોગ્ય રીતે અને તેના અસલ સ્વરૂપમાં સખ્તાઇથી અમલીકરણ થાય તે માટે કટિબધ્ધ છે.

માહિતી અને પ્રસારણ

પ્રવર્તમાન સમયમાં સમુહ પ્રચાર માધ્યમોના ક્ષેત્રમાં આવેલ ઝડપી પરિવર્તન અને વ્યાપના મહત્વને ધ્યાને લઇ ગુજરાત સ્ટેટ મલ્ટીમિડિયા રીસોર્સ ટેકનોવીંગ (જી-સ્માર્ટ)ને વધુ કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે.

આ ઉપરાંત ચાલુ વર્ષે મિડિયા રિસ્પોન્સ સીસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેના દ્વારા અખબારોમાં પ્રસિધ્ધ થતા અહેવાલોની સમીક્ષા કરી સુધારાત્મક પગલાં લેવામાં આવે છે.

ગુજરાતી ચલચિત્રોના ર્નિમાતા વધુ પ્રમાણમાં ગુજરાતી ચલચિત્રો બનાવવા પ્રેરાય તે હેતુથી આવા ર્નિમાતાઓને રૂા.૫.૦૦ લાખની આર્થિક સહાય પણ ચુકવવામાં આવે છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં નવેમ્બર માસ સુધીમાં કુલ - ૯ ર્નિમાતાઓને રૂા. ૪૫ લાખ જેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી છે.

નાણાકીય વહીવટ

મારી સરકારના કરકસરયુકત વહીવટના કારણે રાજયની આર્થિક સ્થિતિ છેલ્લા બે વર્ષમાં ઉત્તરોત્તર સુધરી રહી છે પરિણામે જાણીતી રેટીંગ એજન્સીઓ દ્વારા રાજયને ઉચું રેટીંગ આપવામાં આવેલ છે. આની સાથે સાથે જ મહેસૂલી આવક વધારવા માટેના મારી સરકારના પ્રયત્નો પણ જારી છે.

સુરાજયનું વૈશ્વકિ સન્માન

મારી સરકાર તેની કામગીરીની અસરકારતા સતત વધતી રહે તે માટે પ્રયત્નશીલ છે. રાજયમાં ભૂકંપ બાદ તેના પુનઃર્નિમાણની પ્રવૃત્તિ અને સંભવિત આપત્તિ સામેના સુયોગ્ય આયોજન માટે ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ સત્તામંડળને સન ૨૦૦૩ ના વર્ષ માટે ડિઝાસ્ટર રિડકશન માટે "યુએન સાસાકાવા એવોર્ડ" સને ૨૦૦૪ની ઇનોવેશન્સ ઇન ગવર્નન્સ માટેની કોમનવેલ્થ એસોસિએશન ઓફ પબ્લીક એડમિનીસ્ટ્રેશન (કાપામ) નામે ઓળખાતી ગોલ્ડ ટ્રોફી પ્રાપ્ત થઇ છે.

વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો

મારી સરકારના સંસદીય બાબતોને લગતી કામગીરી કરતાં વિભાગ દ્વારા ઇ-ગવર્નન્સ પ્રોજેકટના ભાગરૂપે રાજયના પ્રવર્તમાન ૪૩૬ અધિનિયમોની ઇન્ડેક્ષ તથા રાજય કાયદા પંચ તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલ ૫૧ અહેવાલોનું પત્રક તૈયાર કરીને વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવેલ છે. એક સરખા વિષયના અમલી કાયદાઓનું એકત્રીકરણ કરવાની કાર્યવાહી તથા મુંબઇ અધિનિયમનું ગુજરાત અધિનિયમ તરીકે નામાભિધાન કરવાની કાર્યવાહી પણ આગામી વર્ષમાં કરવાની નેમ છે

રાજય કાયદા પંચ તરફથી છેલ્લા છ વર્ષમાં રજૂ થયેલા કુલ ૫૫ અહેવાલ પૈકી કુલ છ અહેવાલ ગત કેલેન્ડર વર્ષ દરમ્યાન રજૂ કરેલ છે અને ૩૦ જેટલા અહેવાલોની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. બાકી રહેલા ૨૫ અહેવાલોની કામગીરી આગામી વર્ષમાં પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે.

મારી સરકાર આ સત્રમાં અંદાજપત્રના વૈધાનિક કામકાજ ઉપરાંત નીચેના વૈધાનિક કામકાજ ગૃહની વિચારણા માટે લાવવા ધારે છેઃ-

૧. ગુજરાત પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૨. મુંબઇ વજન અને માપ (અમલીકરણ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૩. ગુજરાત મોટર વાહન (બળતણના ઉપયોગ બાબત) નિયમન વિધેયક, ૨૦૦૫.
૪. ગુજરાત સિનેમા (નિયમન) (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૫. ગુજરાત આવશ્યક ચીજવસ્તુ અને ઢોર (નિયંત્રણ) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૬. મુંબઇ માપબંધી સંબધી (તૈયારી અને તે ચાલુ રાખવા બાબતના) ઉપાય બાબત (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૭. ભારતનો સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૮. મુંબઇ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૯. મુંબઇ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૧૦. ધ્રાગંધ્રા નગરપાલિકા (કર નાંખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનું) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫.
૧૧. ગુજરાત દિવાની કોર્ટ વિધેયક, ૨૦૦૫.
૧૨. મુંબઇ બિન - વ્યાપારી કોપોરેશનો (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક,૨૦૦૫.
૧૩. ધી સેન્ટર ફોર એન્વાયમેન્ર્ટલ પ્લાનીંગ એન્ડ ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી વિધેયક, ૨૦૦૫ .
૧૪. ધી ધર્મસિંહ દેસાઇ ઇન્ટીટયુટ ઓફ ઇન્ફોમેર્શન એન્ડ ટેકનોલોજી વિધેયક, ૨૦૦૫.
૧૫. ગુજરાત રાજવિત્તીય જવાબદારીઓ વિધેયક, ૨૦૦૫.
૧૬. ગુજરાત મૂલ્ય વર્ધિત વેરા (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.

ઉપસંહાર

મને લાગે છે કે મારા ઉદ્‌બબોધનમાં જણાવેલ રાજયના વિકાસની ગૌરવગાથાને આગળ ધપાવવા મારી સરકાર સક્રિય છે અને તેમાં સફળતા પણ હાંસલ કરી રહી છે ત્યારે આપ સર્વે આપના અનુભવ, અને આગવી સૂઝથી લોકશાહીને મૂર્તિમંત કરતાં આ ગૃહની ઉચ્ચ સંસદીય પ્રણાલીકાઓ અને તેની ગરિમાને જાળવીને યોગદાન આપવાની ભાવના સાથે ચર્ચામાં ભાગ લેશો એવી મારી અંતરની ઇચ્છા છે.

જય હિન્દ

જય જય ગરવી ગુજરાત

રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ

શ્રી શંકરભાઈ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, રાજયપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેશો પાઠવવોઃ-

"અમો આ સત્રમાં એકત્ર થયેલ ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ સમક્ષ કરેલ સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ."

શ્રી પ્રબોધકાંત દા. પંડયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીએ જે આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે તેને હું અનુમોદન આપું છું.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શોકદર્શક ઉલ્લેખો

ભારતના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી સ્વ.શ્રી પી.વી. નરસિંહ રાવ, ગુજરાતના પૂર્વ મંત્રી સ્વ.શ્રી નરસિંહભાઈ કરસનભાઈ મકવાણા, પૂર્વ મંત્રી સ્વ.શ્રી રસિકચંદ્ર દેવશંકર આચાર્ય, પૂર્વ મંત્રી સ્વ. શ્રી ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ આયર અને પૂર્વ મંત્રી સ્વ.શ્રી રામજીભાઈ દેવજીભાઈ કરકર, મુંબઈ વિધાનસભા તથા ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય સ્વ. ડૉ.શાંતિલાલ ત્રિકમલાલ પટેલ, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય સ્વ.શ્રી ભોગીલાલ કાનજીભાઈ પટેલ, પૂર્વ સભ્ય સ્વ.શ્રી કેશવજી ગોકલદાસ રાયચુરા, પૂર્વ સભ્ય સ્વ.શ્રી બટુકરાય હરગોવિંદદાસ વોરા, પૂર્વ સભ્ય સ્વ. શ્રી દાદુભાઈ છગનભાઈ વાઘેલા, પૂર્વ સભ્ય સ્વ.શ્રી રતનસિંહ અદેસિંહ રાઠોડ તથા પૂર્વ સભ્ય સ્વ.શ્રી ગોરધનજી ગીગાજી માળીના અવસાન અંગે.

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી (સભાગૃહના નેતાશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે ભારતના **ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રીશ્રી પી.વી.નરસિંહ રાવ**નું તારીખ ૨૩ મી ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ ના રોજ ૮૩ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રાવનો જન્મ તા. ૨૮ મી જૂન, ૧૯૨૧ ના રોજ આંધ્રપ્રદેશ રાજયના કરિમનગર જિલ્લાના વાનગરા મુકામે થયો હતો. તેઓશ્રી સ્વાતંત્રય સેનાની હતા. ખેતી તથા વકીલાતના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા. તેઓશ્રીએ બી.એસ.સી., એલ.એલ.બી. અને સાહિત્ય રત્નની પદવી મેળવી હતી.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રાવે આંધ્રપ્રદેશના જુદા જુદા વિભાગોના મંત્રીપદે તેમજ મુખ્યમંત્રી પદે રહી ઉમદા સેવાઓ આપી હતી. છઠ્ઠી, સાતમી, આઠમી, નવમી, દસમી અને અગિયારમી લોકસભામાં તેઓશ્રી સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા અને ભારત સરકારમાં વિદેશ, ગૃહ, આયોજન, સંરક્ષણ, માનવસંશાધન વિકાસ તેમજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ જેવા મહત્વના મંત્રાલયોના પ્રધાન તરીકે પણ સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રીએ આયોજન પંચના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે અને લોકસભામાં વિરોધપક્ષના નેતા તરીકે પણ ફરજો બજાવી હતી. શ્રી રાવે જૂન, ૧૯૯૧ થી મે ૧૯૯૬ સુધી ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે નોંધપાત્ર સેવાઓ આપી હતી.

એક જાગૃત્ત અને અભ્યાસુ વડાપ્રધાન તરીકે વિદેશનીતિ, સંરક્ષણનીતિ, જમીન સુધારણા અને આર્થિકનીતિની બાબતમાં તેઓએ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું.

તેઓશ્રી રાજકારણ ઉપરાંત વાંચન, લેખનકાર્ય, સંગીત, સાહિત્ય, નાટક અને સિનેમામાં પણ રસ ધરાવતા હતા. તેઓશ્રી ૧૭ ભાષાઓના જાણકાર હતા.

શ્રી રાવના અવસાનથી રાષ્ટ્રે એક બહુમૂખી પ્રતિભા ધરાવતા અગ્રણી નેતા ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે, ગુજરાત રાજયના **પૂર્વ મંત્રીશ્રી નરસિંહભાઈ કરસનભાઈ મકવાણા**નું તારીખ ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૪ના રોજ ૮૨ વર્ષની જૈફ વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી મકવાણાનો જન્મ તા. ૨જી જૂન, ૧૯૨૨ના રોજ ધંધુકા તાલુકાના બગડ ગામે થયો હતો.

સ્વર્ગસ્થશ્રી મકવાણાએ ૧૯૪૨ની "હિંદ છોડો" ચળવળમાં ભાગ લીધો હતો. તેઓશ્રીએ મિલ મજદૂર સભાના મંત્રી તરીકે પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી. સન ૧૯૫૬માં મહાગુજરાત આંદોલનમાં સક્રીય ભાગ લઈ જેલવાસ ભોગવ્યો હતો. તેઓશ્રીએ સન ૧૯૬૩માં પારડી સત્યાગ્રહ અને સન ૧૯૫૮ અને ૧૯૬૬માં શહીદ સ્મારક સત્યાગ્રહમાં પણ ભાગ લીધો હતો. સન ૧૯૬૧, ૧૯૬૫ અને ૧૯૬૯ દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોરપોરેશનમાં કાઉન્સિલર તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેઓશ્રીએ સન ૧૯૭૫માં સમગ્ર ગુજરાત વ્યાપી દલિતોની સૌથી મોટી સંસ્થા ગુજરાત હરિજન વિકાસ પરિષદની સ્થાપના કરી અને તેના આજીવન મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે રહી દલિતોના પ્રશ્નો માટે સતત ઝઝૂમ્યા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી મકવાણાએ ચોથી ગુજરાત વિધાનસભામાં કાંકરીયા મતવિસ્તારમાંથી અને પાંચમી ગુજરાત વિધાનસભામાં શહેર કોટડા મતવિસ્તારમાંથી પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ હતું અને તા. ૨૬-૧૨-૭૬ થી તા. ૮-૪-૭૭ સુધી રાજયના પંચાયત, સહકાર અને કુટિરઉદ્યોગ મંત્રી તરીકે નોંધપાત્ર સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રી સાતમી અને આઠમી લોકસભામાં ધંધુકા મતવિસ્તારમાંથી સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી મકવાણાના અવસાનથી રાજયએ એક પીઢ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, ઉમદા સમાજ સેવક અને દલિત આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે, ગુજરાત રાજયના **ભૂતપૂર્વ મંત્રીશ્રી રસિકચંદ્ર દેવશંકર આચાર્યનું** તા. ૨૯-૮-૨૦૦૪ના રોજ ૮૨ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થ શ્રી આચાર્યનો જન્મ તા. ૧૧મી મે, ૧૯૨૨ના રોજ થયો હતો. તેઓશ્રીએ એલ.એલ.બી. સુધીનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. તેઓ વ્યવસાયે વકીલ હતા.

સ્વર્ગસ્થ શ્રી આચાર્યએ સ્વાતંત્ર્ય ચળવળમાં સક્રિય ભાગ લીધો હતો. તેઓશ્રીએ ઉના નગરપંચાયત અને ઉના શહેરના નગર આયોજનમાં પ્રશંસનીય સેવાઓ આપી હતી. તેઓ મજૂર સંગઠન અને સહકારી પ્રવૃત્તિઓ સાથે પણ સંકળાયેલા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી આચાર્યએ પાંચમી ગુજરાત વિધાનસભા દરમિયાન રાજયના ઉના મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને ગુજરાત સરકારમાં તેઓશ્રીએ કાયદો અને જેલ વિભાગના મંત્રી તરીકે સુંદર કામગીરી બજાવી હતી.

તેઓશ્રીના અવસાનથી ગુજરાત રાજયે એક સ્વાતંત્ર્યસેનાની, ઉમદા સમાજ સેવક અને પીઢ આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે, ગુજરાત રાજયના **ભૂતપૂર્વ નાયબ મંત્રીશ્રી ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ આયર**નું તા. ૨૧-૯-૨૦૦૪ના રોજ ૭૬ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થ શ્રી ખીમજીભાઈનો જન્મ તા. ૧૫મી મે, ૧૯૨૮ના રોજ થયો હતો. તેઓશ્રી સમાજસેવાની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હતા.

અંજાર તાલુકા પંચાયત, ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ અંજાર અને ખરીદ વેચાણ સંઘના પ્રમુખ તરીકે ખીમજીભાઈએ પ્રશંસનીય સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રીએ ડિસ્ટ્રીકટ કો ઓપરેટીવ બેન્ક, ભૂજના ડિરેકટર તરીકે પણ સેવાઓ આપી હતી.

સ્વર્ગસ્થ શ્રી ખીમજીભાઈએ ચોથી અને છઠી ગુજરાત વિધાનસભા દરમિયાન રાજયના અંજાર મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને જૂન ૧૯૮૦થી સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૨ સુધી રાજયના વન અને કૃષિ વિભાગના નાયબ મંત્રી તરીકે સેવાઓ આપી હતી.

તેઓશ્રીના અવસાનથી ગુજરાત રાજયે એક સામાજિક અને સહકારી આગેવાન ગુમાવ્યો છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે ગુજરાત રાજયના **પૂર્વમંત્રીશ્રી રામજીભાઈ દેવજીભાઈ કરકર**નું તા. ૧૨-૧૦-૨૦૦૪ના રોજ ૭૧ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયું છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી કરકરનો જન્મ તા. ૧૩મી ડિસેમ્બર, ૧૯૩૩ના રોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના અંબાળા ગામે થયો હતો. તેઓશ્રીએ બી.એ. એલ.એલ.બી. સુધીનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું અને વકીલાતના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી કરકરે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, વીમા કંપનીઓ, જી.આઈ.ડી.સી., સહકારી મંડળીઓના પેનલ એડવોકેટ તરીકે બહુમૂલ્ય સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રી ધાર્મિક સંસ્થાઓને નિ:શૂલ્ક કાનૂની સલાહ આપતા હતા. તેઓશ્રીએ અનેક સંસ્થાઓના ટ્રસ્ટી, ડાયરેકટર અને પ્રમુખ તરીકે પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી.

સ્વર્ગસ્થશ્રી કરકર સન ૧૯૭૨માં ચોથી ગુજરાત વિધાનસભામાં રાજયના વિસાવદર મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટાઈ આવ્યા હતા અને તા. ૧૮-૭-૭૩ થી તા. ૯-૨-૭૪ સુધી ઉદ્યોગ, વીજળી અને સહકાર ખાતાના નાયબ મંત્રી તરીકે અમૂલ્ય સેવાઓ આપી હતી.

તેઓશ્રીના અવસાનથી ગુજરાત રાજયએ એક ઉમદા સમાજ સેવક અને સહકારી આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે મુંબઈ વિધાનસભા તેમજ ગુજરાત વિધાનસભાના **પૂર્વ સભ્યશ્રી ડૉ. શાંતિલાલ ત્રિકમલાલ પટેલ**નું તાજેતરમાં દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી પટેલનો જન્મ તા.૨૮મી જાન્યુઆરી, ૧૯૧૪ના રોજ અમદાવાદ જિલ્લાના કેળીયા વાસણા ગામે થયો હતો. તેઓશ્રી તબીબી વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી પટેલે ૧૯૪૨ની હિંદ છોડો ચળવળમાં સક્રિય ભાગ લીધો હતો અને સાબરમતી તથા નાસિક જેલમાં અટકાયતમાં રહ્યા હતા. તેઓશ્રીએ સાણંદ તાલુકા સમિતિ તથા અમદાવાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના મંત્રી અને પ્રમુખ તરીકે સેવાઓ આપી હતી.

તેઓશ્રી અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, પછાત વર્ગોની સામાજિક સુધારણા અને સામાજિક સંસ્થાઓના સંચાલનમાં રસ ધરાવતા હતા.

તેઓશ્રીએ મુંબઈ વિધાનસભા અને બીજી ગુજરાત વિધાનસભામાં એક જાગૃત સભ્ય તરીકે પ્રતિનિધિત્વ પૂરુ પાડયુ હતું.

તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજયે આઝાદીની લડતના લડવૈયા અને ઉમદા સમાજ સેવક ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે ગુજરાત વિધાનસભાના **પૂર્વ સભ્યશ્રી ભોગીલાલ કાનજીભાઈ પટેલ**નું તારીખ ૧૬મી ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ના રોજ ૭૮ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયું છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી પટેલનો જન્મ તા. ૩૧મી જાન્યુઆરી, ૧૯૨૭ના રોજ મહેસાણા મુકામે થયો હતો. તેઓશ્રીએ બી.એસ.સી., એલ.એલ.બી. સુધીનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું.

સ્વર્ગસ્થશ્રી પટેલે ૧૯૪૨ની "હિંદ છોડો" ચળવળમાં વિદ્યાર્થીઓની આગેવાની લીધી હતી અને જેલવાસ ભોગવ્યો હતો. તેઓશ્રીએ ઉત્તર ગુજરાત મેડીકલ મરચન્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે પણ સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રી અપંગ, અંધ, બહેરા મુંગા માનવીઓની સેવા તથા ગૌ સેવા અને મુંગા પ્રાણીઓ અને પશુ-પક્ષીઓની સેવા સહિત અનેકવિધ સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા હતા.

ત્રીજી ગુજરાત વિધાનસભામાં પાટણ જિલ્લાના ચાણસ્મા મત વિસ્તારનું તેમણે પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ હતું અને ધારાસભ્ય તરીકે સારી કામગીરી કરી હતી.

તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજયએ એક ઉમદા સમાજ સેવક ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે, ગુજરાત વિધાનસભાના **પૂર્વ સભ્યશ્રી કેશવજી ગોકલદાસ રાયચુરા**નું તારીખ ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૦૫ના રોજ ૮૫ વર્ષની જૈફ વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રાયચુરાનો જન્મ તા. ૧૪મી માર્ચ, ૧૯૧૯ના રોજ થયો હતો.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રાયચુરાએ ગ્રામ પંચાયતથી જિલ્લા પંચાયત સ્તરે જુદા જુદા હોદ્દા ઉપર પ્રશંસનીય સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રીએ સહકારી ખરીદ-વેચાણ સંઘ, સહકારી બેંકો અને સામાજિક સંસ્થાઓના હોદેદાર તરીકે પણ ઉમદા કામગીરી કરી હતી.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રાયચુરાએ ત્રીજી ગુજરાત વિધાનસભામાં જામનગર જિલ્લાના દ્વારકા મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ હતું.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રાયચુરાના અવસાનથી રાજયએ એક સહકારી આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે, ગુજરાત વિધાનસભાના **ભૂતપૂર્વ સભ્યશ્રી બટુકરાય હરગોવિંદદાસ વોરા**નું તા. ૧૯-૧૦-૨૦૦૪ના રોજ ૭૩ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી વોરાનો જન્મ તા. ૧૦મી ઓકટોબર, ૧૯૩૧ના રોજ થયો હતો.

સ્વર્ગસ્થશ્રી વોરાએ ૧૯૪૯થી તેમની રાજકીય કારકીર્દીની શરુઆત કરેલી અને ૧૯૫૮ થી ૧૯૬૦ સુધી પાલીતાણા સુધરાઈના ઉપપ્રમુખ અને પ્રમુખ તરીકે પ્રશંસનીય સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રીએ મજૂર સંગઠનો, કિસાનસભા, વિગેરે સંસ્થાઓમાં આગળ પડતો ભાગ લીધો હતો. તેઓશ્રીએ આફ્રોએશીયન લેખક સંઘ ની ભારતીય સમિતિના ખજાનચી તરીકે પણ સેવા આપી હતી.

સ્વર્ગસ્થશ્રી વોરાએ ચોથી ગુજરાત વિધાનસભા દરમિયાન રાજયના ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ હતું.

સ્વર્ગસ્થશ્રી વોરાના અવસાનથી ગુજરાત રાજયે એક ઉમદા સમાજસેવક ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી સૌ પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે, ગુજરાત વિધાનસભાના **ભૂતપૂર્વ સભ્ય શ્રી દાદુભાઈ છગનભાઈ વાઘેલા**નું તા. ૨૧મી ઓગષ્ટ, ૨૦૦૪ના રોજ ૭૩ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી વાઘેલાનો જન્મ તા. ૧લી મે, ૧૯૩૧ના રોજ થયો હતો. તેઓ પંચાયત અને સહકારી પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા હતા.

તેઓશ્રીએ પેટલાદ ખાતે ક્ષત્રિય સમાજની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓમાં ઉંડો રસ લઈ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું.

સ્વર્ગસ્થશ્રી વાઘેલાએ ચોથી ગુજરાત વિધાનસભા દરમિયાન રાજયના આણંદ જિલ્લાના સોજીત્રા મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ હતું.

સ્વર્ગસ્થશ્રી વાઘેલાના અવસાનથી ગુજરાત રાજયે એક ઉમદા સમાજસેવક અને સેવાભાવી આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી સૌ પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે ગુજરાત વિધાનસભાના **પૂર્વ સભ્યશ્રી રતનસિંહ અદેસિંહ રાઠોડ**નું તારીખ ૨૩મી જૂન, ૨૦૦૪ના રોજ ૬૩ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રાઠોડનો જન્મ તા. ૧લી નવેમ્બર, ૧૯૪૧ના રોજ કપડવંજ તાલુકાના ખડોલ ગામે થયો હતો. તેઓશ્રીએ બી.એ., એલ.એલ.બી. સુધીનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. તેઓશ્રી શિક્ષણના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રાઠોડે તમાકુ બજાર સમિતિ, આણંદના અધ્યક્ષ, કપડવંજ તાલુકા બજાર સમિતિના ચેરમેન, તેમજ સતત ૧૧ વર્ષ સુધી તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘના પ્રમુખ અને ખેડા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકના ડિરેકટર તરીકે મહત્વપૂર્ણ સેવાઓ આપી હતી.

તેઓશ્રીએ આઠમી ગુજરાત વિધાનસભામાં રાજયના ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ હતું.

તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજયએ એક સહકારી આગેવાન અને સમાજસેવક ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્‌ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે ગુજરાત વિધાનસભાના **પૂર્વ સભ્યશ્રી ગોરધનજી ગીગાજી માળી**નું તારીખ ૨૬મી જાન્યુઆરી, ૨૦૦૫ના રોજ ૪૯ વર્ષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી માળીનો જન્મ તા. ૧લી જૂન-૧૯૫૫ના રોજ બનાસકાંઠા જીલ્લાના મોરથલ ગોળીયા ગામે થયો હતો. તેઓશ્રી ખેતી, વેપાર અને કોલ્ડ સ્ટોરેજના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી માળીએ ડીસા મુકામે મહાત્મા જયોતિરાવ ફૂલે ઓલ ઈન્ડિયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ તરીકે હરિઓમ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી તરીકે રાજશ્રી શીત સ્ટોરેજ પ્રાઈવેટ લિમીટેડના ડીરેકટર તરીકે તેમજ જુદી જુદી સામાજીક શૈક્ષણિક અને સહકારી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા હતા.

તેઓશ્રીએ નવમી અને દસમી ગુજરાત વિધાનસભામાં રાજયના ડીસા મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને ગુજરાત રાજય જળસંપત્તિ નિગમના ચેરમેન તરીકે પણ બહુમૂલ્ય સેવાઓ આપી હતી.

તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજયએ એક ઉમદા સમાજસેવક ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા (ભા.રા.કો.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈને આવ્યા છે તેને હું મારું અનુમોદન આપું છું. આજે શોકદર્શક ઉલ્લેખમાં જેમના નામનો ઉલ્લેખ થયો એ એવા મહાનુભાવો હતા કે જે મહાનુભાવોએ આઝાદી સંગ્રામની અંદર ભાગ લીધો, પોતાનું સમગ્ર જીવન દેશ માટે સમર્પિત કર્યું અને આ દેશના અને રાજયના વિકાસમાં પોતાનો બહુમૂલ્ય ફાળો આપ્યો.

આપણા ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વશ્રી પી.વી. નરસિંહરાવજીનું જૈફવયે અવસાન થયું. નરસિંહરાવજી સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા અને તે વખતે રાજયના જે ટોચના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ હતા તેમાંના એક હતા. તે જમાનો એવો હતો કે ખૂબ ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કદાચ તેમણે ધાર્યું હોત તો વ્યવસાયિક પ્રગતિ કરીને

તેમાં પણ કારકિર્દી બનાવીને આગળ વધી શકયા હોત, પરંતુ તેમણે દેશસેવાનો માર્ગ અખત્યાર કર્યો. જેલમાં ગયા, સમગ્ર કારકિર્દી હોડમાં મૂકીને દેશને આઝાદી અપાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું. આઝાદી પછીના સમયમાં સ્વ.નરસિંહરાવજી રાજયના મંત્રી બન્યા, મુખ્યમંત્રી બન્યા અને પોતાના રાજયને નમૂનેદાર રાજય બનાવવા કોશિશ કરી. તેમની શકિતઓને પીછાણીને તે વખતના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ તેમને કેન્દ્રમાં લઈ ગયા, ત્યાં કેન્દ્ર સરકારના જુદાજુદા મંત્રાલયોના મંત્રી બન્યા અને છેવટે દેશના વડાપ્રધાન બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું. નરસિંહરાવજી એવા સમયે વડાપ્રધાન બન્યા જયારે દેશ આર્થિક કટોકટીમાંથી પસાર થતો હતો, પરંતુ નરસિંહરાવજીએ એ વખતે હિંમતપૂર્વક પગલાં ભરીને દેશને તેમાંથી બહાર લાવવાના પ્રયત્નો કર્યા અને તે વખતના પ્રખ્યાત અર્થશાસ્ત્રી અને આજના વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહને નાણાપ્રધાન બનાવ્યા, ઉદારીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ કરી, આર્થિક સુધારા લઈ આવ્યા અને દેશને મજબૂત બનાવવાનું કામ કર્યું એવું સારું વ્યકિતત્વ હતું. બહુમૂખી પ્રતિભા હતી. સારા વિચારક, લેખક અને એક ઉત્તમ રાજનીતિજ્ઞ હતા. તેમના જવાથી દેશને ન પૂરાય એવી ખોટ પડી છે. પરમકૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે તેમના આત્માને શાશ્વત શાંતિ આપે અને તેમના પરિવારજનો અને ફોલોઅરને દુઃખ સહન કરવાની શકિત આપે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ પછી આપણા ગુજરાતના જ એક દલિત આગેવાન અને જેમની બહુમુખી પ્રતિભા હતી અને રાજયની ખૂબ મોટી સેવા કરી છે એવા નરસિંહભાઈ મકવાણાનું અવસાન થયું છે. એમના પરિવારજનો સાથે હું પણ જોડાયેલ છું એમણે પણ આઝાદી સંગ્રામમાં ભાગ લીધેલો અને જે છેવાડાના માણસો ગરીબો હતા દેશના, રાજયના અને દલિત સમાજમાં એમને માટે એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે. અમદાવાદમાં મજૂર પ્રવૃત્તિમાં કામ કર્યું. વિધાનસભામાં ચૂંટાયા, મંત્રી બન્યા અને લોકસભાના સભ્ય તરીકે લોકસભાની અંદર પણ પોતાની ઉત્તમ કાર્યવાહી કરી. છેલ્લા દિવસો સુધી દલિત સમાજના, નબળાવર્ગના લોકોની સેવા કરતા રહ્યા. એમના જવાથી આઝાદી પહેલાંના ઉચ્ચકક્ષાના આગેવાન કાર્યકરની ખોટ પડી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉનાના વતની અને જૂનાગઢ જિલ્લાના શ્રી રસિકભાઈ આચાર્ય જેમણે રાજ્યની સારી સેવા કરી હતી, રાજય સરકારમાં મંત્રી પણ રહી ચૂકયા છે. એમનું પણ અવસાન થયું છે. તેમણે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ભાગ લીધો અને એના પછી રાજકીય પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારે પણ શિક્ષણ અને સમાજ સેવાના કામમાં સતત કાર્યરત રહ્યા. એમની સાથે મારો વ્યકિતગત પરિચય હતો. એમનું જીવન એટલું બધું સાદું અને સરળ હતું કે તેઓ નાના મકાનની અંદર જ રહેતા હતા જે મકાનમાં જન્મ્યા, એ જ મકાનની અંદર રહ્યા. ઉના નગરપાલિકામાં એમણે ઉત્તમ વહીવટ કહી શકાય એવો વહીવટ કર્યો. એમના જવાથી ઉચ્ચકક્ષાના એક આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શ્રી ખીમજીભાઈ આયર જે કચ્છની અંદર પંચાયત અને સહકારી પ્રવૃત્તિઓની અંદર ખૂબ અગ્રેસર હતા અને સારા ખેડૂત આગેવાન હતા. એ વિધાનસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા અને એ આપણા મંત્રીમંડળમાં નાયબ મંત્રી તરીકે પણ રહ્યા. તેઓ સારા ખેડૂત, ઉદ્યોગપતિ અને સમાજના આગેવાન હતા. નબળાવર્ગો માટે એમણે ખૂબ કામ કરેલું. એમના પરિવારજનો સાથે હું જોડાયેલો છું કચ્છના અને સમાજના નબળાવર્ગના લોકો અને રાજયના લોકોએ એક સારા આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શ્રી રામજીભાઈ દેવજીભાઈ કરકર જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના વતની હતા. એમણે એક ખેડૂત પરિવારમાં જન્મ લીધો અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરી, વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા અને એમણે પછી ગુજરાત સરકારની અંદર નાયબ મંત્રી તરીકે કામ કર્યું. તેઓ સારા વકીલ હતા, સમાજ સેવાની અંદર આગળ પડતા હતા. એમના પરિવાર સાથે મારો વ્યકિતગત નાતો હતો. એમના જવાથી સૌરાષ્ટ્રની અંદર એક ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલ ખેડૂત આગેવાન અને સહકારી આગેવાનની ખોટ પડી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ડો. શાંતિલાલ ત્રિકમલાલ પટેલ જે અમદાવાદમાંથી આવતા હતા અને મુંબઈ અને ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર સભ્ય હતા. એમના જવાથી પણ એક જૂની પેઢીના આગેવાનની ખોટ પડી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શ્રી ભોગીલાલ કાનજીભાઈ પટેલ સ્વાતંત્ર્યસેનાની હતા અને આ ગૃહના સભ્ય હતા. એમના જવાથી જૂની પેઢીના આગેવાનની ખોટ પડી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શ્રી કેશવજી ગોકલદાસ રાયચુરા જામનગર જિલ્લાના મારા પડોશના એકદમ નજીકના ગામના હતા. પોરબંદરમાં મારા ઘરની એકદમ નજીકમાં રહેનાર એક વડીલ હતા. તેઓ ધારાસભ્ય તરીકે રહ્યા. સહકારી અને પંચાયતની પ્રવૃત્તિઓમાં પણ એમણે ખૂબ ઉત્તમ રીતે ભાગ લીધો. માનનીય કેશવજી રાયચુરાનું અવસાન થયું એની માત્ર પાંચ મિનિટ પહેલાં જ એમની સાથે મેં વાત કરી હતી. તેઓ જૈફવયના હતા. એમનો ખૂબ સારો પરિવાર હતો. એમના જવાથી સૌરાષ્ટ્રના એક વડીલ આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શ્રી બટુકરાય વોરા. હું જ્યારે વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે આકાશવાણી ઉપર વિધાનસભાની કાર્યવાહી આવતી. કદાચ હું માનું છું કે, એ પક્ષમાંથી ચૂંટાયેલા માત્ર એક ધારાસભ્ય હતા અને વિધાનસભાની અંદર એમનું પ્રદાન ખૂબ મોટું હતું. એમણે સમાજ સેવાની ખૂબ સારી પ્રવૃત્તિઓ કરી. તેઓ ખૂબ સારા લેખક હતા. તેઓ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી કામ કરતા રહ્યા. સમાજના નબળાવર્ગના અને સમાજસેવી સંસ્થાઓને એમના જવાથી મોટી ખોટ પડી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શ્રી દાદુભાઈ છગનભાઈ વાઘેલા શિક્ષણ, પંચાયત અને સહકારી પ્રવૃત્તિના અગ્રણી હતા અને આ ગૃહના સભ્ય હતા. આણંદ જિલ્લાના પેટલાદ તાલુકાના વતની હતા. એમના જવાથી પણ એ ક્ષેત્રને અને ગુજરાતને એક સાચા સમાજ સેવકની ખોટ પડી હતી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી સ્વ. શ્રી રતનસિંહ રાઠોડ ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય હતા અને સાબરકાંઠાના કપડવંજ જિલ્લામાં જન્મેલા. શિક્ષણ, સહકાર અને પંચાયત અને ગ્રામ્ય પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાએલા હતા. એમના જવાથી પણ એક મુરબ્બી અને સેવાકીય આગેવાન આપણે ગુમાવ્યા છે. સ્વ. શ્રી ગોરધનજીભાઈ માળી, બહુ નાની ઉંમરે એમણે વિદાય લીધી. બનાસકાંઠામાં એમણે સામાજીક અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ કરેલી. આપણા જે ૧૨ મહાનુભાવોને આપણે અહીંયા શોકદર્શક ઉલ્લેખમાં અંજલિ આપેલ છે અને હું આપના મારફત એમના પરિવારજનોને આ એમની દુ:ખદ ઘડીએ પ્રભુ સહન કરવાની શકિત આપે એટલી પ્રાર્થના સાથે હું આ શોકદર્શક ઉલ્લેખને સમર્થન આપુ છું.

શ્રી અશોક ભટ્ટ (ભા.જ.પ.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહના નેતા અને વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખોનો પ્રસ્તાવ લાવ્યા છે, એમાં હું મારો સૂર પૂરાવું છું. નરસિંહરાવ એ આઝાદીની લડત અને આઝાદી પછી આ દેશની સમૃધ્ધિ માટે આંધ્રથી શરૂ કરીને દિલ્હી સુધી એમણે જીવનપર્યંત જે કાર્યો કર્યા એ કાર્યો આપણા માટે પ્રેરણારૂપ બન્યા છે. એક અભ્યાસુ ઉપરાંત દેશની ૧૭ ભાષાઓ જાણનાર વ્યકિત એ આ દેશના સુકાની બને એ ગૌરવની વાત હતી. તેઓ ગરીબ માણસની વાતને સમજનારા માનવી હતા.

ગુજરાતના ૧૧ પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રીઓને અંજલિ આપતા મારા નજીકના વિસ્તારની અંદર ૧૯૫૬ની ૮મી ઓગસ્ટે ગુજરાતને સૌથી પહેલો અન્યાય થયો. મહાગુજરાતનો, અલગ રાજય માટે જે લડત શરૂ થઈ એ લડતના એક સુકાની નરસિંહભાઈ હતા. દલિતોના માનવી હતા. ગરીબો માટે લડતા હતા અને કાંકરીયા બહેરામપુરા અને મજૂર વિસ્તારની અંદર એ પ્રજા સમાજવાદી પક્ષના એક કાર્યકર્તા તરીકે રહીને કોંગ્રેસની સામે ખૂબ મોટી લડાઈ એમના જીવનના પૂર્વકાળ દરમિયાન લડયા. સ્વ. શ્રી રસિકચંદ્ર આચાર્ય, હું વિધાનસભામાં પહેલી વખત ચૂંટાઈને આવ્યો ત્યારે એ કાયદા વિભાગ સંભાળતા હતા. ઉનાના એક સામાજિક કાર્યકર્તા ઉપરાંત સમગ્ર જીવન દરમિયાન ન્યાયતંત્ર અને ન્યાય માટેનું એમનું ખૂબ મોટું પ્રદાન રહેલ છે. કચ્છમાંથી ચૂંટાઈને આવેલા અને આ સભાગૃહની અંદર નાયબ કૃષિ મંત્રી તરીકે બેસતા સ્વ. શ્રી ખીમજીભાઈ માટે એટલું કહી શકાય કે એ માયાળુ માનવી હતા. પ્રેમાળ હતા, એમની પાસે જીવનના માનવીય સંબંધોના મૂલ્ય હતા. એ ખૂબ મિત્રતાના માનવ હતા. એવી જ રીતે ડૉ. શાંતિભાઈ પટેલ એ સાણંદ તાલુકામાંથી મુંબઈ વિધાનસભામાં અને ગુજરાત વિધાનસભામાં ચૂંટાઈને આવ્યા હતા. જિલ્લા પંચાયતની અંદર પણ એમણે ખૂબ મોટો ફાળો આપ્યો હતો અને ખાદી પ્રવૃત્તિ અને ગરીબોના માનવી હતા. સ્વ. શ્રી બટુકરાય વોરા એ વિધાનસભાના સભ્ય તો રહયા પરંતુ સમગ્ર જીવન એમણે એક લેખક, પત્રકાર અને ગુજરાતની ગાથાઓ લખવામાં ગાળ્યું. એ વ્યકિતત્વ આજે આપણી વચ્ચે નથી. સ્વ. શ્રી રામજીભાઈ કરકર, સ્વ. શ્રી ભોગીભાઈ પટેલ, સ્વ. શ્રી કેશવજીભાઈ રાયચુરા, સ્વ. શ્રી દાદુભાઈ વાઘેલા, શ્રી રતનસિંહ રાઠોડ આ બધા સભ્યશ્રીઓએ ગુજરાતની વિધાનસભાની અંદર ખૂબ મોટો ફાળો આપ્યો છે, થોડાક વર્ષો પહેલાં હમણાં જ આપણી વચ્ચે કામ કરતા પછાત જિલ્લાના બનાસકાંઠાના ગરીબ માણસોના પ્રશ્નને લઈને સદાકાળ એ હંમેશા જજુમતા હતા. ડીસા અને બનાસકાંઠાના વિકાસ માટે અને તેના અનેક જીવનના પ્રવાહોની વચ્ચે રહીને ગોરધનજીભાઈએ જે કંઈ કર્યુ છે એ ડીસા, બનાસકાંઠા જિલ્લો અને ગુજરાત એ ભૂલશે નહીં. આવા ૧૧ પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રીઓ અને પૂર્વ વડાપ્રધાનશ્રીને આ સભાગૃહ શ્રધ્ધાંજલિ અર્પે છે એમાં હું સૂર પૂરાવું છું.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ (ભા.રા.કો.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહના નેતા જે શોક પ્રસ્તાવ લાવ્યા છે એને હું ટેકો આપું છું. ભારતના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી સ્વર્ગસ્થ શ્રી પી.વી.નરસિંહરાવજી માટે જે કહેવાયું એ મુજબ એ ખૂબ સજ્જન વ્યકિત, તેજ આગેવાન, સૌમ્ય સ્વભાવવાળા હતા. એનો અનુભવ મને નવમી લોકસભામાં દોઢ વર્ષ માટે ટૂંકી લોકસભા હતી ત્યારે થયો હતો. વિરોધપક્ષની પાટલીએ બેસતા નરસિંહરાવજી પછી વડાપ્રધાન થયા. આ દેશને ઉદારીકરણ માટે આખો મોડ આપી અને જેના કારણે આજે વિશ્વ સત્તા બનવા માટે ભારત જઈ રહયું છે અને સદગત રાજીવ ગાંધીની ઉદારીકરણની નીતિને એમણે આગળ વધારી હતી એ આપણે આજે યાદ કરીએ છીએ. શ્રી નરસિંહભાઈ મકવાણા, માનનીય અશોકભાઈએ જે વાત કરી કે મહાગુજરાત જનતા પરિષદ વખતની લડાઈ અને પ્રજા સમાજવાદી પક્ષના આગેવાન અને પછી કાયદા મંત્રી તરીકે કોંગ્રેસની અંદર પણ એમનું જીવન બધાની સાથે એટલું બધું સરળ હતું અને એમનું વ્યકિતત્વ એમના વડિલપણાનો અહેસાસ કરાવે એવું હતું. આ ધારાસભામાં તેઓ બોલેલા એ વાંચીએ ત્યારે બિલ ઉપરની ચર્ચામાં ખૂબ જ વિચારપૂર્વક અને માર્ગદર્શક બને એવી શૈલી હતી. રસિકભાઈ આચાર્ય, એમની સાથે પણ પૂર્વ પરિચય, એ પણ કાયદા મંત્રી ૧૯૭૫માં જનતા મોરચાની સરકાર હતી ત્યારે બનેલા અને એમનું સાદગીભર્યું જીવન માર્ગદર્શક બને તેવું હતું. સ્વર્ગસ્થ ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ મારા જ જિલ્લાના વડીલ કહેવાય. અમે એમને ખીમજીબાપા તરીકે ઓળખીએ

અને મારા ઉપર ખૂબ સ્નેહ રાખે. એક ખેડૂત પરિવારમાંથી, પછાત વિસ્તારમાંથી આવતા એવા આગેવાન બે વખત ધારાસભ્ય થયેલા અને પ્રધાનપદું પણ ભોગવેલું. જાહેર જીવનમાં હંમેશા અંત સુધી છવાઈ રહેલા અને બધાના માર્ગદર્શક હતા. સ્વર્ગસ્થ શ્રી બટુકરાય વોરા કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના એક માત્ર ધારાસભ્ય હતા. ૧૯૭૨માં ચૂંટાયેલા એ પહેલા ખૂબ જ સંઘર્ષ કરેલો. પ્રધાન પણ હતા. પછી જાહેર જીવનમાં છવાઈ રહેલા. પત્રકાર તરીકે યાદ રહે એવા, ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા જેવા અખબારો અને બીજા અખબારોમાં એમની કોલમ નિયમિત રીતે લખાય અને કચડાયેલી પ્રજાના પ્રવાહોથી એ પત્રકારત્વમાં છવાયેલા હતા. સ્વર્ગસ્થ શ્રી ગોરધનજી માળી જેમ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અંજલિ આપતા કહયું એમ ગુજરાત જળસંપત્તિ વિકાસ નિગમના ચેરમેન તરીકેનું એમનું પ્રદાન કદાચ એ નિગમને તારનાર રહ્યું હતું. કેમ કે આ કોરપોરેશનને બંધ કરવાનો ઠરાવ થયેલો એ ચાલું રાખ્યું અને ચેરમેન તરીકેની એમની કામગીરી નોંધનીય છે. અન્ય સદગત સભ્યશ્રીઓ સ્વર્ગસ્થશ્રી રામજીભાઈ કરકર, શાંતિલાલ પટેલ, ભોગીલાલ પટેલ, કેશવજી રાયચુરા, બટુકરાય વોરા, દાદુભાઈ વાઘેલા, રતનસિંહ રાઠોડ એમની સાથે બહુ પરિચય નહિ. અમારી જૂની પેઢીના પણ અહીં તમામ સભ્યો ગુજરાતના જાહેર જીવનના માહિર આગેવાનો હતા અને પોતાના વિસ્તારમાં નહિ પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં એમની નામના હંમેશા રહી હતી. તમામ સદગત સભ્યશ્રીઓને મારા વતીથી અંજલિ આપું છું અને એમને વંદન કરું છું. ધન્યવાદ.

અધ્યક્ષશ્રી : બોલનારા સભ્યશ્રીઓ વધારે છે એટલે પોતાના વિસ્તારના હોય, નજીકના પરિચયમાં હોય એમના વિશે બોલશો તો સારું રહેશે.

શ્રી નારાયણભાઈ લ. પટેલ (ભા.જ.પ.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી શોક ઠરાવ લઈને આવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેને અનુમોદન આપ્યું છે તેમાં હું મારો સૂર પુરાવું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ડીસાના વતની અને મારા સહમિત્ર એવા ગોરધનભાઈ માળીનું તાજેતરમાં મૃત્યું થયું. તેઓ અનેકવિધ સંસ્થાઓમાં હતા. સારા ખેડૂત હતા અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ અને એવા એકમો ધરાવતા હતા. યુવાન વયે એમનું મૃત્યું થયું અને એમના કુટુંબીજનો ઉપર જે ઘેરો આઘાત લાગ્યો એ આઘાત સહન કરવાની પ્રભુ શકિત આપે અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા તેમના પરિવારજનોને શોકસંદેશો મોકલી આપીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એવા જ બીજા ભોગીલાલ કાનજીભાઈ પટેલ જે બી. કે. પટેલના હુલામણા નામે જાણીતા હતા. દવાનો મોટા પ્રમાણમાં એમનો વ્યવસાય હતો. ચાણસ્મા વિભાગનું એ પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા અને અનેકવિધ સંસ્થાઓ સાથે તેઓ સંકળાયેલા હતા. તેમના મૃત્યુ બાદ તેઓના પરિવારજનોને જે આઘાત લાગ્યો છે એ આઘાત સહન કરવાની પ્રભુ શકિત આપે અને આ શોકસંદેશો આપના દ્વારા એમના પરિવારજનોને મોકલી આપવામાં આવે.

શ્રી હરજીવન હી. પટેલ (ભા.જ.પ.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહના નેતાશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ્ લાવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેને સમર્થન આપ્યું છે એવા ભારતના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી સ્વ.શ્રી નરસિંહ રાવ, ગુજરાતના ચાર પૂર્વ મંત્રીશ્રીઓ નરસિંહભાઈ મકવાણા, રસિકચંદ્ર દેવશંકર આચાર્ય, ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ આયર, રામજીભાઈ દેવજીભાઈ કરકર અને સાત પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રીઓ શાંતિલાલ ત્રિકમલાલ પટેલ, ભોગીલાલ કાનજીભાઈ પટેલ, કેશવજી ગોકલદાસ રાયચુરા, બટુકરાય હરગોવિંદદાસ વોરા, દાદુભાઈ છગનભાઈ વાઘેલા, રતનસિંહ અદેસિંહ રાઠોડ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના ગોરધનજી ગીગાજી માળી. આજે ડીસાની અંદર ગોરધનજીભાઈ માળીનું ૨૭મી તારીખે જયારે અવસાન થયું એ દિવસે હું અમદાવાદથી માનનીય પૂર્વ અધ્યક્ષશ્રી ધીરુભાઈ શાહની દીકરીના લગ્ન પ્રસંગેથી પાલનપુર જતો હતો, રસ્તામાં મને સમાચાર મળ્યા, મને એક ભાઈએ કહ્યુંકે, ડીસામાં કાંઈ જાણ્યું? ગોરધનજીભાઈનું કાંઈ સાંભળ્યું? મેં કહ્યું શું વાત છે ? એમણે કહ્યું કે, એમનું અવસાન થયું છે. માનવામાં ના આવે, કદી કલ્પનામાં ના આવે, રાત્રે સાડાદસ વાગે સમાચાર મળ્યા. બીજે દિવસે સવારમાં જયારે અમે ડીસા પહોંચ્યાં. એમના નશ્વરદેહને જયારે જે સ્થિતિમાં જોયો ત્યારે એમના મોઢા પર હાસ્ય હતું. પંચભૂતની કાયા ઉપર લોકો એજ કહેતા હતા કે તમે હસતા હસતા ગયા ને લોકોને રડાવતા ગયા. ગોરધનજી બે વખત વિધાનસભામાં ચૂંટાઈને એમના મતવિસ્તાર ડીસાની અંદર ભગીરથકાર્યો કર્યા છે. એમણે ત્યાં કોર્ટ, સેસન્સકોર્ટ લાવવાના પ્રયત્નો કર્યા. બસસ્ટેન્ડ માટેના એમણે ભગીરથ પ્રયત્નો કર્યા. જળસંપત્તિ નિગમમાં રહીને જે ખોટ કરતું હતું એ જળસંપત્તિ નિગમને નફામાં ફેરવ્યું. ગોરધનજીભાઈના જવાથી બનાસકાઠાં જિલ્લામાં મોટી ખોટ પડી છે. ડીસા તાલુકાની જનતાને, ડીસા શહેરના નગરજનોને કદાચ એ ખોટ તો પૂરી શકશે. પરંતુ એમના પરિવારને જે ખોટ પડી છે, આટલી નાની વયે એમનું અવસાન થયું છે એ પરિવાર માટે બહુ દુ:ખદ સમાચાર છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પાર્થના કરીએ આપના મારફત એમના પરિવાર જનોને સંદેશો પાઠવીએ. એમના આત્માને પ્રભુ શાંતિ આપે એ જ પ્રાર્થના.

શ્રી શંકરભાઈ દે. વાઘેલા (ભા.રા.કો.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપણા મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ્ લઈને આવ્યાં છે એમાં હું મારો સૂર પુરાવું છું.

ભારતના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રીશ્રી પી.વી. નરસિંહ રાવ જેમણે ઉદારીકરણની નીતિ કરીને તેમજ અર્થકારણ જે નબળું પડયું હતું એને સારી સ્થિતિમાં મુકવાનું શ્રેય માનનીય માજી વડાપ્રધાનને જાય છે. ઉપરના અગિયાર જે મહાનુભવો છે એમાંના ઘણાની સાથે મારે પરિચય હતો રસિકચંદ્ર આચાર્ય, ખીમજીભાઈ, રામજીભાઈ, શાંતિલાલ, ભોગીલાલ, કેશવજી અને દાદુભાઈ છગનભાઈ જેઓ એક સામાન્ય ખેડૂતના દીકરા હતા, પણ હંમેશા સમાજની સેવા કઈ રીતે કરી શકાય? સારાય સમાજની સેવા કરી એક ધારાસભ્ય તરીકે તેઓ ચૂંટાયા. એમને ખેતીમાં રસ હતો, સામાન્ય માણસની ઉન્નતિ કઈ રીતે થાય એમાં એમને રસ હતો, સમાજના કામમાં પણ એમને રસ હતો. જયારે હું સમૂહ લગ્નોનું આયોજન કરતો ત્યારે ત્યારે એ પણ મારી સાથે આવતા અને એમાં પણ ભાગ લેતા. તેઓએ પંચાયતમાં, સહકારી પ્રવૃત્તિમાં અને સામાજિક સેવાઓમાં ઘણો ખરો ભાગ આપ્યો છે.

એજ રીતે સ્વ.શ્રી રતનસિંહ અદેસિંહ રાઠોડ જેઓ પણ અમારી સાથે હતા. તેઓએ દસ વર્ષ સુધી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી તરીકે ફરજો બજાવી, નાનામાં નાના માણસનો વિકાસ કઈ રીતે થઈ શકે, ગામડાની આબાદી કઈ રીતે વધી શકે અને ગામડાંને આબાદ કઈ રીતે કરી શકાય એ હંમેશા તેઓ નજરે રાખતા હતા, એજ રીતે અમૂલ ડેરીમાં ચેરમેન તરીકે પણ રહયા, ગરીબમાં ગરીબ માણસને અથવા પશુપાલનવાળાને કઈ રીતે વધારેમાં વધારે નફો આપી શકાય એવી દ્દષ્ટિ તેઓશ્રીની રહી હતી. એજ રીતે તમાકુ બજાર સમિતિમાં પણ પ્રમુખ તરીકે એમણે ફરજ બજાવી હતી ત્યારે આ જે મહાનુભાવોના અવસાનો થયાં,એમના કુટુંબીજનો ઉપર જે આફતો આવી છે, જે દુ:ખની લાગણીઓ એમણે અનુભવી, આપણે એમના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

શ્રી માલજીભાઈ દે. દેસાઈ (ભા.રા.કો.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મુખ્યમંત્રીશ્રી જયારે શોક પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જયારે એને અનુમોદન આપ્યું છે ત્યારે મારી લાગણી વ્યકત કરવા માટે ઉભો થયો છું.

સ્વ.શ્રી નરસિંહરાવને આ દેશ અને દુનિયા જાણે છે, આ દેશને ઉદારીકરણના અને વૈશ્વિકરણના રસ્તે લઈ જવામાં એમનું મોટું પ્રદાન રહયું છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ, એવા એક વિચક્ષણ પુરુષ, અનેક ભાષાઓના જાણકાર અને રાજકીય આગેવાન, એમના કુટુંબને જે કાંઈ ખોટ પડી એમાં આપણે સૌ સૂર પૂરાવીએ છીએ.

સ્વ.શ્રી નરસિંહભાઈ મકવાણા, દલિત સમાજમાંથી આવનારા, વિધાનસભામાં અને પાર્લામેન્ટમાં જનારા, શ્રમજીવી અને ગરીબ લોકોના હામી અને એક રાજકીય પુરુષ તરીકે એમનું એટલું મોટું વિશાળ રાજ લેવલનું કાંઠુ હતું કે સાધન સંપન્ન અને ભણેલા ગણેલા લોકો પણ નરસિંહભાઈની સલાહ લેતા, રાજકારણમાં પણ એમની આંગળી પકડી આગળ ચાલે, એવા નરસિંહભાઈ મકવાણા એક દલિત નેતા તરીકે એમનું ગુજરાત વ્યાપી બહું મોટું પ્રદાન હતું એવા નેતાને પણ આપણે અંજલિ આપીએ છીએ.

સ્વ.શ્રી રસિકચંદ્ર, સ્વ.શ્રી ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ આયર, અંજાર વિસ્તારમાંથી કચ્છમાંથી એક પછાત વિસ્તારની પ્રજામાંથી આવેલા એક સારા આગેવાન હતા એટલું જ નહિં પણ ર્ડા. શાંતિલાલ પટેલ, દેશની આઝાદીમાં જે કોઈ લોકોએ પ્રદાન કર્યા છે એમાં શાંતિલાલે પણ જેલવાસ ભોગવ્યો છે. ર્ડાકટર જેવી પદવી મેળવેલ માણસ, ભાલ જેવા પ્રદેશમાં મુની સતપાલજીનો પ્રભાવ હતો એ વખતના જે કોઈ લોકસવેકો એમના સંપર્કમાં આવ્યા અને એમણે જે કાંઈ પ્રજાકીય કામો કર્યા એમાં ર્ડા. શાંતિલાલનું પણ બહું મોટું પ્રદાન, પછાત વર્ગના શિક્ષણના કામો અને ખેડૂતોના એ હામી રહયા હતા. જિલ્લા પંચાયતની અનેકવિઘ પ્રવૃત્તિઓમાં એ સંકળાયેલા હતા,

મારા જ વિસ્તારમાંથી જયાંથી હું ચૂંટાઈને આવ્યો છું, ત્યાંથી ભાઈશ્રી ભોગીલાલ પટેલ, એક સાધનસંપન્ન કુટુંબમાં અને અમારા તાલુકામથક જેવા ચાણસ્મા ગામમાં જન્મેલા, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા અને બહુ સારા વેપારી તરીકે એમની નામના એવા ભોગીભાઈને પણ હું હદયપૂર્વક અંજલિ આપું છું.

ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ વિસ્તારના રતનસિંહ એમની સાથે મારો સીધો પરિચય, ડેરી સાથેના કામોમાં એ સંકળાયેલા અને એક સારા આગેવાન તરીકે અમારા પાડોશી સ્વ.શ્રી ગોરધનજીભાઈ માળી, આ બધા જે કોઈ જાહેર જીવનમાં પ્રદાન કરનારા આપણા આગેવાનો, એમના કુટુંબીજનોને શોક સંદેશો આપના ઘ્વારા મોકલો એમાં મારો સૂર પૂરાવું છું.

શ્રી કાંતિલાલ ધ. કચોરિયા) (ભા.જ.પ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઠરાવ લાવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેને અનુમોદન આપ્યું છે તેમાં હું મારો સૂર પૂરાવું છું. દેશના અને રાજયના આ ૧૨ જેટલા મહાનુભાવોએ આ ગૃહમાંથી આ રાજયની સેવા કરી છે એ પૈકીના

મારા જિલ્લાના સ્વ.ગોરધનજી ગીગાજી માળી સાથે આ ગૃહમાં કામ કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે અને જિલ્લામાં પણ, ફીલ્ડમાં પણ અને પાર્ટીમાં પણ એમની સાથે કામ કરવાની મને તક મળી છે. ગોરધનજીભાઈની કામ કરવાની આગવી છટા હતી. એમના એકાએક અવસાનથી મને અને સમગ્ર જિલ્લાને આંચકો લાગ્યો છે. ગોરધનજીભાઈને ગૃહમાં રજૂઆત કરતા મેં જોયા છે. ગોરધનજીભાઈને જિલ્લાની જુદીજુદી કચેરીઓમાં અને રાજયના જુદાજુદા વિભાગોમાં કામ કરતા જોયા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના એક અદના આગેવાન, અદનો કાર્યકર્તા અને આગવી દ્રષ્ટિવાળો આગેવાન ખોવાનો અમને ખૂબ જ રંજ છે, દુ:ખ છે. એમણે શિક્ષણક્ષેત્રે પણ જિલ્લા અને તાલુકામાં ખૂબ જ ઉત્તમ સેવા કરેલી. ડીસાનું ડીસાનું બસસ્ટેન્ડ સમગ્ર ગુજરાતમાં ઉત્તમ, આદર્શ અને જોવાલાયક બસસ્ટેન્ડ બને એવી ગોરધનજીભાઈની ઈચ્છા અને સ્વપ્ન હતું. એમની એક કિલોમીટર લાંબી સ્મશાનયાત્રામાં ભાઈ અને બહેનોની આંખોમાંથી આંસુ વહેતાં હતાં એ ઉપરથી ડીસાના સમગ્ર વિસ્તાર અને બનાસકાંઠા વિસ્તારમાં એમના પ્રત્યેની લાગણી જોવા મળેલી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આગેવાન ગુમાવ્યો એનો રંજ છે. આપના થકી એમના પરિવારજનોને શોક સંદેશો મોકલી આપીએ.

શ્રી વજુભાઈ પ. ડોડિયા (ભા.જ.પ.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના માનનીય નેતા શોક દર્શક ઉલ્લેખો લઈને આવ્યા છે એ તમામ મહાનુભાવોને હું શોકાંજલી આપીને ટેકો આપું છું. ખાસ કરીને સાણંદના ડો.શાંતિલાલ ત્રિકમલાલ પટેલે વ્યવસાયે ડોકટર તરીકે જે નામના મેળવી છે અને ગરીબોની સેવા કરી છે, ગરીબોને દવા મફત આપી છે. એ સમયે આ આખો વિસ્તાર એમનો ઋણી રહયો છે. તેઓશ્રીએ સહકાર અને શિક્ષણક્ષેત્રે આ બને ક્ષેત્રે કચડાયેલા માનવીઓનો સમાજ છે ત્યાં પણ એમના પ્રદાનનાં ક્ષેત્રો ખૂબ જ સફળ રહયાં છે. એમણે જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ, ધારાસભા, ખરીદવેચાણ સંઘ, કોટન સેલ, એ.પી.એમ.સી., આ બધા ક્ષેત્રોમાં અધ્યક્ષ તરીકે ખૂબ જ પારદર્શક વહીવટ આપીને છેવાડાના માનવીને ન્યાય મળે એવા વહીવટ પ્રમાણે ખૂબ જ નિષ્ઠાવાળા અને બિલકુલ વ્યકિતગત રીતે દરેકને ન્યાય મળે એ જોનારા હતા. આ સમયે અમારો વિસ્તાર એમના ખૂબ જ સંભારણા કરી રહયો છે .એવા સમયે આજની વિધાનસભાની આ બેઠકના ઉલ્લેખને હ્રદયપૂર્વક ટેકો જાહેર કરી એમના આત્માને પરમાત્મા શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું.

ડૉ. દિનેશ પરમાર (ભા.રા.કો.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના નેતા જે પ્રસ્તાવ લાવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાએ સૂર પૂરાવ્યો છે, એમાં હું મારો સૂર પૂરાવવા ઉભો થયો છું. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રીશ્રી પી.વી.નરસિંહરાવ, ગુજરાતના પૂર્વ મંત્રી સ્વ.શ્રી નરસિંહભાઈ કરસનભાઈ મકવાણા, પૂર્વ મંત્રી સ્વ.શ્રી ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ આયર, પૂર્વ સભ્યશ્રી કેશવજી ગોકલદાસ રાયચુરા અને અન્ય આઠ મહાનુભાવોના નિધનને લીધે આ ગૃહમાં જે પ્રસ્તાવ આવ્યો છે એમાં હું મારો સૂર પૂરાવું છું.

ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રીશ્રી પી.વી. નરસિંહ રાવનું ૨૩ મી ડિસેમ્બર ૨૦૦૪ ના રોજ ૮૩ વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું. તેઓશ્રીએ ભારત સરકારમાં વિદેશ ખાતું, ગૃહ અને સંરક્ષણ, માનવ સંશાધન વિકાસ, આરોગ્ય પરિવાર જેવા મહત્વના મંત્રાલયોમાં કામ કર્યુ. આંધ્રપ્રદેશમાં પણ પોતે જુદા જુદા ખાતામાં અને મુખ્યમંત્રીશ્રી સુધી પણ કામ કરેલું. તેઓશ્રીએ આયોજન પંચના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે પોતાની ફરજો બજાવેલી. વિરોધપક્ષના નેતા તરીકે કામકાજ કરેલું અને ૧૯૯૧ અને ૧૯૯૬ માં તેઆએ આ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે પણ પોતાની ફરજો આપી. પહેલો બનાવ હશે કે જયારે માઈનોરિટી સરકાર હોવા છતાં પૂરાં પાંચ વર્ષ સુધી શાસન ચલાવી શકે એવી ક્ષમતા અને સૂઝબૂઝવાળા, સૌમ્ય પ્રતિભાવાળા શ્રી પી. વી. નરસિંહ રાવજીને કદાચ વિરોધપક્ષના લોકો પણ સહકાર આપતા હોય તેવું એક સમયે તો વાતાવરણ ખડું થઈ ગયેલું કે આવું વ્યકિતત્વ ટકી રહે તો વધુ સારું એમ માની વિરોધ પક્ષના લોકો પણ એમની સરકાર ટકી રહે એના માટે ચિંતિત હતા. એવું વ્યકિતત્વ ધરાવનાર શ્રી પી.વી.નરસિંહ રાવજી આ દેશની અંદર જયારે અર્થતંત્રની અંદર જયારે દેશ ઉપર બરાબર કટોકટી હતી, ત્યારે એની વિદેશ નીતિ હોય કે જુદુ જુદુ આયોજન હોય, સંરક્ષણ બાબતના પ્રશ્નો હોય તેમાં કુનેહભરી દ્રષ્ટિના લીધે તેમણે દેશને યોગ્ય સુકાન પૂરું પાડયું છે. પી.વી. નરસિંહ રાવના સમયમાં વર્તમાન વડાપ્રધાનશ્રી મનમોહનસિંહ જે ટેકનોગ્રેડ કહેવાય અથવા તો નિષ્ણાત કહેવાય, સારામાં સારા અર્થશાસ્ત્રી કહેવાય એમને નાણા મંત્રી તરીકે રાખી અને દેશને એક જુદી દિશા આપી. લિબરલાઈઝેશન, પ્રાઈવેટાઈઝેશન અને ગ્લોબલાઈઝેશનની દિશાની અંદર દેશને લઈ જઈ અને વિશ્વના ફલક ઉપર જે રીતે વિકાસની દિશાની અંદર આપણા દેશની જે જનશકિત છે, એને બધાને કામે લગાડીને વધુને વધુ દેશને પ્રગતિની દિશામાં લઈ જવાનું કામ જો કર્યુ હોય તો નરસિંહ રાવે કર્યુ છે, તે આપણે કયારેય ભૂલી શકીએ તેમ નથી. તેઓશ્રી સાયન્સના ગ્રેજ્યુએટ હતા અને ઉપરાંત એડવોકેટ હતા. ૧૭ જેટલી ભાષાઓ જાણતા હતા. આવી વ્યકિતના જવાથી દેશને ન પૂરી શકાય તેવી ખોટ પડી છે. એમના પરિવારજનો ઉપર જે દુ:ખ આવી પડયું છે. આવી બહુમુખી પ્રતિભા સંપન્ન વ્યકિત અને એક નેતા ગયા છે અને આપણા બધાને એની ખોટ પડી છે. સદગતના આત્માને ચિરશાંતિ પ્રાપ્ત થાય તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપના ધ્વારા એમના પરિવારજનોને સંદેશો પાઠવીએ.

ગુજરાતના પૂર્વ મંત્રીશ્રી નરસિંહભાઈ કરશનભાઈ મકવાણા અનુસૂચિત જાતિના ખૂબ જ ઓછું ભણેલા વ્યકિત પણ રાજનીતિમાં અને જુદી જુદી પ્રવૃત્તિમાં જે રીતે બુલંદી ઉપર પહોંચેલા અને જે કુનેહ, આવડત અને કુશાગ્રબુધ્ધિ એમનામાં હતી, એ ખરેખર એમ કહી શકાય કે ભણેલા ગણેલા વિધ્વાન પણ એમની સલાહ લેતા હોય તેવા શ્રી નરસિંહભાઈ મકવાણા મિલમાં સામાન્ય મજદૂર તરીકે કામ કરી મિલની એકિટવિટિસ, યુનિયનની એકિટવિટિસ તરીકે એની અંદર મિલ મજદૂર સભાના મંત્રી તરીકે સેવા આપી. ૧૯૫૬ માં મહા ગુજરાતના આંદોલનમાં સક્રીય રીતે ભાગ લીધો અને જેલવાસ ભોગવેલ. ૧૯૬૧, ૧૯૬૫ અને ૧૯૬૯ દરમ્યાન કોર્પોરેટર તરીકે મહાનગરપાલિકા અમદાવાદમાં પોતે ચૂંટાઈ આવીને પોતાની સેવા પ્રદાન કરી. ૧૯૭૫ માં રણમલપુરાનો બનાવ બન્યો. દલિતો ઉપર જે અત્યાચાર અને જૂલમ થયો એના લીધે સુરેન્દ્રનગરની અંદર મહા સંમેલન દલિતોનું બોલાવી અને ત્યારપછી હરિજન વિકાસ પરિષદ નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી તેના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે પોતે સેવા આપી. જીવ્યા ત્યાં સુધી પોતે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે રહ્યા. દલિતોના પ્રશ્નો માટે કાયમ માટે ઝઝૂમતા રહ્યા. ચોથી વિધાનસભામાં કાંકરિયા મત વિસ્તારમાંથી પોતે પ્રતિનિધિત્વ કરેલું. પાંચમી ગુજરાત વિધાનસભામાં અમદાવાદમાં શહેર કોટડામાંથી પોતે પ્રતિનિધિત્વ કરેલ અને તેઓશ્રી ૨૬-૧૨-૧૯૭૬ થી ૮-૪-૧૯૭૭ સુધી રાજયનું પંચાયત, નાણા, સહકાર અને કુટિર ઉધોગના મંત્રી તરીકે નોંધપાત્ર સેવાઓ આપી. તેઓશ્રી સાતમી, આઠમી લોકસભામાં ધંધૂકા મત વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઈ આવ્યા અને સંસદસભ્ય તરીકે પોતાની સેવાઓ આપી. સ્વ.નરસિંહભાઈ મકવાણાના અવસાનથી રાજયને એક પીઢ સ્વાતંત્ર સેનાની, ઉમદા સમાજ સેવક, અડિખમ દલિત આગેવાન ગુમાવ્યાનું દુખ છે અને ખોટ પડી છે. તેઓશ્રીના આત્માને ચિરશાંતિ પ્રાપ્ત થાય તે માટે તેમના પરિવારજનો ઉપર આવી પડેલ દુ:ખમાં સહભાગી થવા માટે આપના દ્વારા સંદેશો મોકલવામાં આવે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભૂતપૂર્વ નાયબ મંત્રીશ્રી ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ આયર જેમને કચ્છ જિલ્લામાં પોલિટીકલ હવાલો જયારે મારી પાસે પાંચ વર્ષ સુધી હતો ત્યારે તેમના સંપર્કમાં આવેલો અને ત્યારે એક સંસદ સભ્યના ઉમેદવારનું અવસાન થવાથી તેનું બાય ઈલેકશન આવેલ ત્યારે અંજાર વિસ્તારની જવાબદારી મેં સંભાળેલી ત્યારે તે માણસ આટલી મોટી ઉંમરે, આંખે ઓછું દેખાય અને જે એમનું વ્યકિતત્વ અને જે રીતે લોકો ઉપર એમની ઈમેજ, જે રીતે મેં એમને કામ કરતા જોયેલા. રાતના ત્રણ-ત્રણ વાગ્યા સુધી આંખે દેખાય નહીં તેમ છતાં કામ કરતા મેં તેમને જોયેલા. ત્યારે મને એમ થયું કે ખરેખર માણસની જો લોક ચાહના હોય અને બહાર ન નીકળે તો મત ઉપર અથવા તો રાજનીતિ ઉપર ઘણી મોટી અસર થતી હોય છે અને જયારે બહાર નીકળ્યા પછી કેટલી મોટી અસર થઈ શકતી હોય છે તે મેં નજરે નિહાળેલું. તેવા સ્વ.ખીમજીભાઈ ચોથી, છઠ્ઠી ગુજરાત વિધાનસભામાં અંજાર મત વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઈ આવેલા અને રાજયના વન અને કૃષિ વિભાગના મંત્રી તરીકે સેવા આપેલી. સ્વ.ખીમજીભાઈના આત્માને પ્રભુ શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફતે તેઓના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે પૂર્વ સભ્યશ્રી કેશવજી ગોકલદાસ રાયચુરાનું ૧૫મી જાન્યુઆરી ૨૦૦૫ના રોજ ૮૫ વર્ષની જૈફ વયે દુ:ખદ અવસાન થયું છે. તેઓ જામનગર જિલ્લાના એક સારા એવા પ્રતિનિધિ હતા. તેઓ દ્વારકા મત વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઈને આવેલા. સ્વ.શ્રી રાયચુરાનો જન્મ ૧૪મી માર્ચ ૧૯૧૯ના રોજ થયેલો. ગ્રામ પંચાયતના સભ્યથી પોતાની જીવનની કારકીર્દિ શરૂ કરી જિલ્લા પંચાયત સુધી જુદા જુદા હોદ્દા ઉપર અને સહકારી પ્રવૃત્તિઓમાં ખરીદ વેચાણ સંઘની અંદર કે સહકારી બેંકોમાં, સામાજિક સંસ્થાઓમાં ઉમદા કામગીરી બજાવેલી. સ્વ.શ્રી રાયચુરાએ ત્રીજી ગુજરાત વિધાનસભામાં જામનગર જિલ્લાના દ્વારકા મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું. સ્વ.રાયચુરાના અવસાનથી રાજ્યને એક સહકારી આગેવાનની ખોટ પડી છે. સદગતના આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

શ્રી ગોપાલભાઈ ગા. ધુઆ (ભા.જ.પ.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ જે શોકદર્શક પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે, તેમાં મારો સૂર પુંરાવું છું. બાર જેટલા મહાનુભાવોના દુ:ખદ અવસાનના જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈને આવ્યા છે, તેને મારું સમર્થન આપું છું. મારા વિસ્તાર કચ્છ જિલ્લાના શ્રી ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ આયર પૂર્વ વનમંત્રી હતા. હું જે વિસ્તારમાંથી ચૂંટાયેલો તે ગાંધીધામ તાલુકાના કિડાણા ગામના તેઓ વતની હતા, તેઓનો વ્યવસાય ખેતીનો હતો. વામનમાંથી વિરાટ બનેલા હતા કારણકે ૧૯૫૪-૫૫ ની અંદર કંડલા પોર્ટનું બાંધકામ શરૂ થયું ત્યારે તેઓ તેમાં શ્રમજીવી તરીકે જોડાયેલા અને તે કંડલા પોર્ટનું બાંધકામ કેમ આગળ વધે તેમાં તેઓએ સક્રિય ફાળો આપેલો. આયર સમાજનો જેમ બને તેમ વિકાસ થાય તે માટે તેઓ આગળ વધેલા. તેઓ પ્રથમ કિડાણા ગામના સરપંચ બનેલા તે પછી અંજાર તાલુકામાં જયારે ૧૯૬૩ ની અંદર પંચાયતી રાજની સ્થાપના થઈ ત્યારે અંજાર તાલુકા પંચાયતના પ્રથમ પ્રમુખ બનેલા. તેઓ અંજાર તાલુકામાં સહકારી પ્રવૃત્તિઓ જે હતી તેવા અંજાર તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘ તથા અંજાર બજાર સમિતિ અને અન્ય ક્ષેત્રોના પ્રમુખ બનેલા. કચ્છ જિલ્લાની અંદર અમારી મધ્યસ્થ સહકારી બેન્કના તેઓ

ડાયરેકટર બનેલા અને ખેડૂતલક્ષી અને સમાજના અને ઘણા બધા દલિત સમાજના કામો તેમણે કરેલાં. હું હંમેશાં તેઓની સાથે સંકળાયેલો અને જયારે તેઓનું દુ:ખદ અવસાન થયું ત્યારે સમગ્ર કચ્છ જિલ્લાની જનતાને ખૂબ દુ:ખ થયેલ. છેલ્લે ૧૯૮૨-૮૩ ની અંદર અંજાર મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા અને રાજય સરકારમાં વનમંત્રી બનેલા અને સારી પ્રગતિ કરેલી હતી. તેમના દુ:ખદ અવસાનથી સમગ્ર કચ્છની જનતાને અને આયર સમાજને અને ખાસ કરીને દલિત સમાજને ઘણું દુ:ખ થયું છે ત્યારે આપના માધ્યમથી તેમના કુટુંબીજનો ઉપર આવી પડેલ આફતમાં શોક ઠરાવ મોકલાવીએ તેવી અભ્યર્થના.

શ્રી ઇશ્વરભાઇ ધ. મકવાણા (ભા.જ.પ.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી અને વિરોધપક્ષના માનનીય નેતાશ્રી જે શોકદર્શક પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે તેના સમર્થનમાં હું મારા બે શબ્દો કહેવા માટે ઉભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક વાત ખરી છે કે ભારતના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી સ્વ. શ્રી પી. વી. નરસિંહ રાવ ઉદારીકરણના જનક હતા, એવી જ રીતે આદરણિય સ્વ. શ્રી નરસિંહભાઈ મકવાણા એ દલિત સમાજના હિતરક્ષક અને એમના હૃદયના જનક હતા, દલિત સમાજમાં મુરબ્બી સ્વ. શ્રી નરસિંહભાઈનું ખૂબ નામ, એમનું કામ પણ એટલું, હું નાનો હતો ત્યારે હું એમને જોઉં, જયારે જોઈએ ત્યારે નરસિંહ દાદા.. નરસિંહ દાદાના નામે સમગ્ર દલિત સમાજ એમને ઓળખે. દલિતોના હામી તરીકે જ નહીં પણ રાજકીય રીતે પણ, રાજકીય પક્ષમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી અને દલિત સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું, આ બંને સાથે ચલાવીને એમણે માત્ર રાજકારણમાં નહીં પણ સમાજમાં પણ એમનું પ્રભુત્વ જમાવ્યું, વિકસાવ્યું અને આજે દલિત સમાજને એમની ખોટ છે, આ એક નિર્વિવાદ સત્ય આ ગૃહના ધ્યાન ઉપર મૂકવા હું નમ્ર અપીલ કરું છું.

એવી જ રીતે ભોગીલાલ એ ચાણસ્મા વિધાનસભા મતક્ષેત્રમાંથી ચૂંટાયેલા હું પણ મહેસાણામાં જન્મેલ, એમનું રહેવાનું મહેસાણામાં, બી. કે. પટેલના નામે ઓળખાય. એમને જોઈએ તો બુશર્ટ ને પેન્ટ અને ચંપલ, બજારમાં ચાલતા જાય, સાદો સીધો માણસ ધારાસભ્ય હશે, એવું કોઈની કલ્પનામાં પણ ન આવે. દવાની દુકાન ચલાવે, પ્રામાણિકતાથી, જરાય ખોટું ના થાય, બહુ સાવધાની, એમ કહેવાય છે કે એ વખતે સિનેમાગૃહોનું સમાજમાં ખૂબ વર્ચસ્વ, એવા સમયે એમણે સિનેમાગૃહ બનાવેલ, બી. કે. સિનેમા, મહેસાણામાં પણ મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે, સિનેમાનો માલિક, સુખી-સંપન્ન માણસ, પોતાના થિયેટર ઉપર કાળાબજાર ન થાય અને એ વખતે ખૂબ કાળાબજાર થતાં પણ મહેસાણાના બી. કે. થિયેટર ઉપર સામાન્ય મહિલા પણ સરળતાથી પિકચર જોવાની ટિકિટ મેળવી શકતી, એનું કારણ એ હતું કે, મેં નજરે જોયેલા કે બી. કે. પટેલ જાતે ધોકો લઈને ઉભા રહે, કોઈ મોટો દાદા પણ એમને જોઈને આગળ આવી શકે નહીં. ફરકે નહીં ત્યાં, એવી એમની ધાક છતાંય સાદગી, આજે અમારા જેવા નાના કાર્યકર્તાઓને એ પ્રેરણાદાયી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એવી જ રીતે પૂર્વ સભ્ય સ્વ. શ્રી ગોરધનજી માળી, આજે નથી વિચારી શકાતા કે તેઓશ્રીનું અવસાન થયું છે. એ અડીખમ તાકાતવાળો માણસ સમાજમાં નેતૃત્વ કરે, માળી સમાજમાં, પછાતવિસ્તારમાં પણ તાકાત લગાવીને જે માણસે સમાજની પડખે રહીને વિપક્ષમાં રહીને પણ ભારતીય જનતાપાર્ટીના કર્મનિષ્ઠ કાર્યકર્તા તરીકે એમણે જે સેવાઓ પ્રદાન કરી છે એ માત્ર બનાસકાંઠામાં જ નહીં, પણ સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને અમારા જેવા ઉગતા કાર્યકર્તાઓને પણ એમનાં પ્રેરણા, બળ અને માર્ગદર્શન પૂરાં પાડે તેવાં છે.

આ સાથે તમામ સ્વર્ગસ્થ આગેવાનોને હું શ્રધ્ધાંજલિ પાઠવી એમના પરિવારજનોને આપના તરફથી સાંત્વન પ્રાપ્ત થાય એવી વિનંતી કરું છું

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી/ (ભા.રા.કો.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઠરાવ લઈને આવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેને સમર્થન આપ્યું છે, એમાં હું મારો સૂર પૂરાવું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ દેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી સ્વ. શ્રી પી. વી. નરસિંહરાવ, એ એક ચાણકય અને સૂઝ ધરાવતી વ્યકિત હતી, જેમણે બહુમતિ ન હોવા છતાં પણ પાંચ વર્ષ સુધી સ્થાયી સરકાર આ દેશને આપી હતી એનો આજે આપણે બધી જગ્યાએ દાખલો આપી શકીએ છીએ. આ દેશના વિકાસ માટે એમની સુઝથી ઉદારીકરણ અને પાંચ વર્ષની સરકારમાં તમામ કાર્યો કર્યા છે એ કાયમ આપણે યાદ કરીએ કારણ કે એમની સુઝ બુઝ એ રીતની હતી કે આ દેશના વિકાસ માટે એમણે કાયમ માટે વિપક્ષને સાથે લઈને એમનું સમર્થન લઈને પાંચ વર્ષ સુધી સ્થાયી સરકાર આપી હતી, એમના જવાથી આપણા દેશને મોટી ખોટ પડી છે.

ગુજરાતના પૂર્વ મંત્રી સ્વ. શ્રી નરસિંહભાઈ મકવાણા એ ભલે દલિત સમાજના હતા પણ એમના વિચારો, એમની કામ કરવાની પધ્ધતિ એવી હતી કે, એ સદાય તમામ સમાજોને સાથે લઈને ચાલ્યા હતા અને ગુજરાત અને દેશના તમામ કાર્યોમાં એમનો મોટો ફાળો રહેલો છે.

વધુમાં ખાસ કરીને ડીસાના ધારાસભ્ય સ્વ. શ્રી ગોરધનજી માળી, કે જેમનું હમણાં જ ટૂંક સમય પહેલાં અવસાન થયું છે, એ એક ખેડૂત પુત્ર હતા, વેપારી પણ હતા અને ઉત્કર્ષ (ઉત્કૃષ્ઠ) ખેડૂત કહીએ તો એ પણ હતા. એક નાનકડા ગામડામાં જન્મ લઈને એમણે ડીસાની અંદર દરેક ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરી હતી. એ કાયમ એમની

યાદગીરી રહેશે. તેઓ બે વખત વિધાનસભાની અંદર ચૂંટાઈને આવ્યા હતા. ખેડૂતોની વાત હોય, વિકાસની વાત હોય એ દરેકમાં તેઓ કાયમ અગ્રેસર રહ્યા છે. આજે પણ ડીસાની અંદર એમના લોકહિતનાં જે કાર્યો છે એ એમની કાયમ યાદ અપાવશે. તેઓશ્રીના અવસાનથી ડીસા અને સમગ્ર જિલ્લાના લોકોને મોટી ખોટ પડી છે. નાની ઉંમરમાં એમનું અવસાન થવાથી આ વિસ્તારને ખૂબ દુ:ખ થયું છે અને મોટી ખોટ પડી છે, ભગવાન એમના આત્માને શાંતિ આપે અને એમના કુટુંબીજનો પર આવી પડેલ દુ:ખ સહન કરવાની પ્રભુ શક્તિ આપે એવી જ પ્રાર્થના કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પુ છું.

શ્રી બિમલ શાહ (ભા.જ.પ.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના નેતા અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈને આવ્યા છે અને જેને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ ટેકો આપ્યો છે તેમાં હું પણ મારી શોકની લાગણી વ્યકત કરું છું. ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન અને આપણા રાજયના માનનીય માજી મંત્રીશ્રીઓ અને માજી સભ્યશ્રીઓ, જેમાં માનનીય ગોરધનજી માળી જેમની સાથે સહકાર્યકર્તા તરીકે અને સહધારાસભ્ય તરીકે કામ કરવાનો મને મોકો મળ્યો એવા ગોરધનજી માળીનો હસતો ચહેરો વિસરાતો નથી આવા એક સાથી મિત્ર આપણે ગુમાવ્યા છે ત્યારે એનું સ્વાભાવિક રીતે દુ:ખ થાય, એમને હું મારી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું.

સાથોસાથ શ્રી રતનસિંહ અદેસિંહ રાઠોડ મારા મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાતા હતા, તેમને હું મામા તરીકે ઓળખતો હતો. મારા પરિવાર સાથે જોડાયેલા હતા તેઓ ૧૧ વર્ષ સુધી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે રહ્યા હતા અમૂલ ડેરીના પણ ચેરમેન તરીકે રહ્યા હતા. અમારા તાલુકાના દરેક વિકાસના કામોની અંદર એમનો ફાળો રહેલો છે અને એના કારણે લોકો આજે પણ એમને યાદ કરે છે. તેઓ જ્યારે એલ.એલબી થયા ત્યારે ધીકતો ધંધો છોડીને પોતાના સમાજની સેવા કરવા માટે તેમણે શિક્ષણનું કાર્ય સ્વીકાર્યું. એ એટલા માટે કે સમાજના વધુમાં વધુ બાળકોનું તેઓ ઉત્થાન કરી શકે. એમણે એ દિશામાં ક્ષત્રિય સમાજ, ઠાકોર સમાજની ખૂબ સારી સેવા કરી. ઠાકોર સેવા સમાજના અગ્રેસર કાર્યકર તરીકે એમણે ખૂબ સારી સેવા કરી. મુરબ્બી શ્રી રતનસિંહને આજે યાદ કરીએ ત્યારે એમના અનેક કાર્યો એમની અનેક વાતો યાદ આવે છે તેઓ કોંગ્રેસના પ્રમુખ હતા પણ જયારે વિકાસની વાત આવતી હતી ત્યારે મને યાદ છે તેઓ પક્ષાપક્ષીથી પર રહીને સાથે રહીને વિકાસના કાર્યમાં જોડાતા હતા. એમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ એમની સરળતા, એમની નિખાલસતા અને કોઈપણ જાતના પક્ષાપક્ષી વગર વિકાસને કેવી રીતે આગળ વધારી શકાય, પોતાના સમાજને કેવી રીતે બેઠો કરી શકાય એ જ લાગણી સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈને આવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેને સમર્થન આપ્યું છે એમના પરિવારજનો અને ગ્રામજનો પર આવી પડેલી આફત સહન કરવાની ઈશ્વર શક્તિ આપે તેટલું કહીને હું મારી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ (ભા.રા.કો.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના નેતા અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈને આવ્યા છે અને અમારા પક્ષના નેતાશ્રીએ જેને સમર્થન આપ્યું છે તેમા હું પણ મારો સૂર પુરાવું છું. ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વ. પી.વી. નરસિંહરાવ અને ગુજરાતના પૂર્વ મંત્રીશ્રીઓ અને આ સન્માનનીય ગૃહના પૂર્વ સભ્યશ્રીઓના અવસાન અંગે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અને અમારા પક્ષના નેતાશ્રીએ જે વાત કરી છે તેમાં હું પણ મારો સૂર પુરાવું છું અને તેમાં પણ અમારા ઉના મત વિસ્તારના શ્રી રસિકચંદ્ર દેવશંકર આચાર્ય કે જેઓએ મારા મત વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઈ આવીને આ ગૃહમાં બેસીને રાજયના વિકાસમાં જેમણે કામગીરી કરી છે. એવા શ્રી રસિકભાઈ જેઓનું મૂળ વતન અમરેલી જિલ્લાનું જાફરાબાદ પરંતુ એમની કર્મભૂમિ તેમણે ઉના તાલુકાને બનાવી હતી. ઉના તાલુકાના વિકાસ માટે એમણે સારી એવી કામગીરી કરી હતી. વ્યવસાયે તેઓ એડવોકેટ હતા. શિક્ષણની અંદર અમારે ત્યાંની સંસ્થા ઉના તાલુકા કેળવણી મંડળના મંત્રી તરીકે તેઓ રહ્યા હતા તેમજ મહિલા કોલેજની તેમણે સ્થાપના કરી અને ઉના શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં શિક્ષણના સારા ઉમદા કાર્યો જિંદગીના છેલ્લાં શ્વાસ સુધી કર્યા છે. તેમની વિશેષતા સરળ સ્વભાવ, સરળ વ્યકિતત્વ અને નાનામાં નાના માણસ માટેની કામ કરવા માટેની તેમની લાગણી હતી. વ્યવસાયે એડવોકેટ હોવા છતાં જયારે ન્યાયતંત્રમાં ન્યાય મેળવવો અત્યારે મોંઘો છે ત્યારે કોઈ પણ વ્યકિત તેમની પાસે જાય ત્યારે તેમની પાસે પૈસા હોય કે ના હોય ત્યારે તેમના વતી કોર્ટમાં કેસ લડવા માટે ફીની અંદર તે સેવા આપતા હતા. ઉના નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે રહી સેવાઓ આપી. રાજયની અંદર નગરપાલિકાઓની અંદર પ્રથમ વખત ટી.પી.સ્કીમનું અમલીકરણ કરાવવાનો શ્રેય જો મળતો હોય તો તે સ્વ.રસિકભાઈ આચાર્યને જાય છે, તે ઉનામાંથી શરુ કરાવવામાં આવ્યો હતો. રાજયમાં પ્રથમ લોક અદાલતની જયારથી શરુઆત કરવામાં આવી ત્યારે રાજયમાં પ્રથમ લોક અદાલત ઉનાની અંદર થયેલી અને તેમાં પણ સ્વ.રસિકભાઈ આચાર્યએ સારો એવો ફાળો આપીને કામગીરી કરેલી અને છેલ્લા શ્વાસ લીધા ત્યારે ઉના નગરપાલિકા દ્વારા હાઉસ ટેકસ નાખવામાં આવેલો અને તેના અંગે ઉના શહેરીજનોના આગેવાનોની મિટિંગ બોલાવેલી અને તેમાં સંબોધન કરતી વખતે માઈક હાથમાંથી છટકી જતાં પોતે પડી ગયા અને તે પછી તે કોમામાં સરી પડયા અને ત્રણ દિવસ પછી તેનું મૃત્યુ થયુ. જીંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી તે લોકોના પ્રશ્નો અને લોકોની ચિંતા કરતા કરતા એક આવું સરળ

વ્યકિતત્વ આજે ગુજરાતના જાહેર જીવનમાંથી ગયું છે ત્યારે ગુજરાતના જાહેર જીવનને એક મોટી ખોટ પડી છે. તેમના કુટુંબીજનો ઉપર આ અવસાનથી જે દુઃખ આવ્યું છે તેમને સહન કરવાની પરમકૃપાળુ પરમાત્મા શાંતિ અને શકિત અર્પે તે જ પ્રાર્થના.

શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા (ભા.જ.પ.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના નેતા અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખો લઈને આવ્યા છે તેમાં માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ સૂર પૂરાવ્યો છે તેમાં હું મારા વિચારો વ્યકત કરું છું.

પાલિતાણા ગારીયાધાર વિસ્તારની અંદર બટુકભાઈ વોરા નામનું એક વ્યકિતત્વ, એક અનોખું વ્યકિતત્વ હતું તેઓનો જન્મ પાલિતાણા તાલુકાના લુણાવદર ગામમાં ૧૯૩૧ની અંદર થયો હતો. તેમના બાપુજી લીલીયા ખાતે નોકરી કરતા હતા. નાના કર્મચારી હતા તે દરમિયાન ૧૯૪૮ની અંદર, તેમના જીવનની અંદર એક ઘટના બનેલી. ૧૯૪૮માં લીલીયાની અંદર ૧૮ વર્ષની વયે તેઓ રસ્તાની એક બાજુએથી પસાર થતા હતા અને બાજુમાં યજ્ઞ જેવો કાર્યક્રમ ચાલતો હતો અને એક દલિત પરિવારના થોડા લોકો તે વિસ્તારમાંથી નીકળ્યા અને તે જોઈને કેટલાક પંડિતોએ તેમને મારવા લીધા. આ પ્રસંગ જોઈને તેમના દિલની અંદર ખૂબ લાગી આવેલું તેમણે જે દલિતો હતા તેમને બચાવવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો અને તેમને પણ ખૂબ માર પડયો અને ત્યારથી ૧૮ વર્ષની વયે તેઓ ઘર બાર છોડી કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર જોડાયા અને ૧૯૪૮ થી ૧૯૭૭ સુધી તેઓ જાહેર જીવનની અંદર ખૂબ સક્રિય રહયા, આ દરમિયાન તેમની સાથે કામ કરવાનો મોકો તો મળ્યો નથી, પરંતુ જયારે તેઓ ધારાસભ્ય હતા, મારા વતનના ગામથી તેમનું ગામ માત્ર ચાર કિલોમીટરના અંતરનું હતું એટલે વિદ્યાર્થી હતા ત્યારે તે ગામમાં આવતા. સાઈકલ ઉપર બેસીને ગામમાં આવતા અને મને એક પ્રસંગ બરાબર યાદ છે કે, અમે પ્રાથમિક શાળાની અંદર બેઠેલા હોય, વિદ્યાર્થીઓ ભણતાં હોય ત્યારે કયારેય શાળાની અંદર દાખલ થતા નહીં પણ જયારે રિસેસ પડે અને બાળકો બહાર આવે ત્યારે બાળકો સાથે મીઠી વાતો કરતા અને ચોકલેટ આપતા, તે પ્રસંગ અમને આજસુધી યાદ છે. જયારે તેઓ ધારાસભ્ય હતા ત્યારે ખૂબ સાદગીથી જીવતા હતા, ખૂબ સાદગીથી રહયા હતા. સાઈકલ ઉપર પ્રવાસ કરતા હતા. આ વિસ્તારમાં તેમનું ખૂબ માન અને સન્માન હતું. તે ઉપરાંત તેઓશ્રીએ પાલિતાણા નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે પણ ૧૯૫૮ થી ૧૯૬૨ સુધી કાર્ય કર્યું હતું. તેમણે તેમના જીવનના પ્રસંગોને લગતું ઝેર પીતા નરવા અને નરવા એવું પુસ્તક લખ્યું છે. તેમાં પણ તેમના જીવનની ખૂબ રસપ્રદ બાબતો મારા ધ્યાનમાં આવી છે. તેમાં તેમણે ખાસ કરીને ૧૯૫૨ થી ૧૯૫૪ દરમિયાન ભાવનગરમાં પૃથ્વીસિંહ આઝાદ કે જેઓ ભગતસિંહ સાથે ખૂબ નિકટતમ તેમના સાથી ક્રાંતિવીર હતા તેમની સાથે પણ કામ કરવાનો મોકો મળેલો. આ ઉપરાંત તેઓએ ૧૯૭૧ થી ૧૯૭૪ દરમ્યાન પાલીતાણા મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, ત્યારપછી ૧૯૮૫ થી ૧૯૯૫ સુધી અમેરિકા રહયા હતા અને ૧૯૯૫ થી પાછા હિન્દુસ્તાન આવીને અમદાવાદ ખાતે સ્થાયી થયા હતા અને જીવનપર્યંત એટલે કે તા. ૧૯-૧૦-૨૦૦૪ ના રોજ તેમનું અવસાન થયું ત્યાંસુધી કર્ણાવતી ખાતે રહીને આજુબાજુના સામાયિકોમાં કટાર લેખક તરીકે ખૂબ ઉમદા કાર્ય કર્યું હતું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે તેઓશ્રી તેમના પરિવાર અને આપણી વચ્ચે નથી ત્યારે તેમના આત્માને શાશ્વત શાંતિ મળે અને તેમના કુટુંબીજનો ઉપર આવેલ દુઃખ સહન કરવાની પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તેઓશ્રીને શકિત આપે એટલી પ્રાર્થના સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું.

શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઉ. વાઘેલા(ભા.જ.પ.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહના નેતાશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખો લઈને આવ્યા છે, તેમાં હું પણ મારો સૂર પૂરાવું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રીશ્રી પી.વી.નરસિંહ રાવ, પૂર્વ મંત્રીશ્રી રસિકચંદ્ર આચાર્ય, પૂર્વ મંત્રીશ્રી ખીમજીભાઈ આયર, સ્વ.શ્રી રામજીભાઈ કરકર, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી ડો. શાંતિલાલ પટેલ, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી ભોગીલાલ પટેલ, શ્રી કેશવજી રાયચુરા, શ્રી બટુકરાય વોરા, શ્રી દાદુભાઈ વાઘેલા, શ્રી રતનસિંહ રાઠોડ, શ્રી ગોરધનજી માળી વગેરે નેતાઓના અવસાનથી તેઓશ્રીના કુટુંબીજનો ઉપર આવી પડેલ દુઃખ સહન કરવાની પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તેમને શકિત આપે તેવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સ્વ. શ્રી નરસિંહભાઈ કરસનભાઈ મકવાણા જેઓ દલિત સમાજમાં પોતાનું આગવું સ્થાન ધરાવતા હતા. પોતે એક મિલ કામદાર હોવાના નાતે ગરીબોની પરિસ્થિતિથી સારી રીતે વાકેફ હતા. તેઓએ દલિત નેતા તરીકે પોતાની આગવી છાપ ઉભી કરી હતી. દલિતોના ઉત્થાન માટે હરહંમેશ તેઓ લડતા રહયા હતા. એક મિલ કામદાર હોવાના નાતે તેઓ મજૂર મહાજનના પ્રતિનિધિ તરીકે રહયા હતા અને મજૂર મહાજનના પ્રતિનિધિથી માંડીને ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે તેઓશ્રી રહયા હતા અને ગુજરાત વિધાનસભામાં રહીને અલગ અલગ વિભાગના મંત્રીશ્રી તરીકે તેઓએ સેવાઓ આપી હતી અને એ રીતે તેમણે દલિત સમાજની જે સેવા કરી હતી તેને આજે પણ અમારો દલિત સમાજ યાદ કરે છે. અમે તેમને 'દાદા'ના

હુલામણા નામથી ઓળખતા હતા. તેમણે અમારા દલિત સમાજના નવયુવાનોને સારો એવો બોધપાઠ આપ્યો હતો જેને આજે પણ અમારા યુવાનો યાદ કરે છે.

આવા અમારા દાદાના જવાથી અમારા દલિત સમાજને ભારે મોટી ખોટ પડી છે. પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ આપે અને આ સર્વે સ્વર્ગસ્થ મહાનુભાવોના કુટુંબીજનો ઉપર આવી પડેલ દુ:ખ સહન કરવાની પ્રભુ શકિત આપે, એ જ અભ્યર્થના.

શ્રી પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ(ભા.રા.કોં.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહના માનનીય નેતાશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખો લઈને આવ્યા છે અને માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેને સમર્થન આપ્યું છે, તેમાં હું પણ મારો સૂર પૂરાવું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક સ્વાતંત્રય સેનાની તરીકેની જવાબદારી નિભાવી દેશના સર્વોચ્ચ સ્થાને બેસીને જેમણે સારી એવી કામગીરી કરી છે એવા શ્રી પી.વી. નરસિંહ રાવ આજે આપણી વચ્ચે નથી. આજે પણ તેમની સારી કામગીરીથી અને સારી કાર્યશૈલીથી આપણે પરિચિત છીએ.

આ ઉપરાંત શોકદર્શક ઉલ્લેખમાં જેમના નામનો ઉલ્લેખ થયો છે એવા દલિત સમાજના હામી અને જેમણે સમગ્ર ગુજરાતના દલિત સમાજન માટે ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે એવા શ્રી નરસિંહભાઈ મકવાણા કે જેમને અમે 'દાદા'ના હુલામણા નામથી ઓળખીએ છીએ. શ્રી નરસિંહભાઈ મકવાણાએ એક મિલ કામદારથી લઈને વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે અને લોકસભાના સભ્ય તરીકે પણ ખૂબ જ સારી કામગીરી કરી હતી. તેઓશ્રી મારા પિતાશ્રીના અંગત મિત્ર હતા અને ગુજરાત હરિજન વિકાસ પરિષદમાં મારા પિતાશ્રીએ તેમની સાથે ખૂબ જ કામગીરી કરી હતી. દલિત સમાજમાં રહેલા જુદા જુદા કુરિવાજોને નાબૂદ કરવામાં તેમણે ખૂબ મોટું યોગદાન આપેલ છે જેના લીધે આજે પણ દલિત સમાજમાં તેમનું આગવું સ્થાન રહેલ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શ્રી નરસિંહભાઈ મકવાણા જયારે એમના છેલ્લા દિવસોમાં પથારીવશ હતા ત્યારે તેમના અવસાન પહેલાં હું જયારે તેમને મળવા ગયો હતો ત્યારે એ સાંભળતા હતા, પરંતુ બોલી શકતા ન હતા. મેં જયારે તેમને મારા પિતાશ્રીએ તેમની ખબર પૂછી છે તેવો સંદેશો આપ્યો ત્યારે તેમની આંખમાંથી આંસુ વહી રહયાં હતાં. તેમની આંખમાંનાં આંસુ જોઈને મને પણ એમ થયું કે આજે પણ તેમની ગુજરાતના દલિત સમાજ માટે કેટલી ચિંતા છે? તેમણે દલિત સમાજ માટે જે કામગીરી કરી છે એ દલિત સમાજ આજીવન યાદ કરશે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપશ્રીના માધ્યમથી તેમનાં કુટુંબીજનો અને જેમને ભવ્ય વારસો આપ્યો છે એવા ગુણવંતભાઈ મકવાણા કે જેઓ આ વિધાનસભાના સભ્ય રહી ચૂકયા છે તેમને આપના મારફતે શોકસંદેશો મોકલાવીએ.

બીજા બટુકભાઈ વોરા મારા વતન પાલિતાણાના હતા, દલિતો માટે એમને ખૂબ જ લાગણી હતી, મારા પિતાજીના તેઓ પણ ખૂબ સારા મિત્ર હતા, તેઓ લેખક તરીકે પણ ખૂબ સારી કામગીરી બજાવતા હતા. મારા પિતાજી જયારે ૧૯૭૫ માં પ્રમુખ હતા ત્યારે તેઓ વિરોધપક્ષમાં હોવા છતાં તેઓએ ખૂબ સારી કામગીરી બજાવી હતી તેઓશ્રીના અવસાન અંગે પણ આ સભાગૃહ મારફત શોક સંદેશો પાઠવીએ.

શ્રી મુળુભાઈ હ. બેરા (ભા.જ.પ.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભાગૃહના નેતાશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈને ગૃહ સમક્ષ આવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેને અનુમોદન આપ્યું છે તે બધા મહાનુભાવોને હું પણ શોકાંજલિ અર્પુ છું. અમારા જામનગર જિલ્લાના દ્વારકા વિસ્તારના કલ્યાણપુરના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય કેશવજીભાઈ રાયચુરા કે જેઓ દ્વારકા-કલ્યાણપુર જેવા પછાત વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે ખૂબ સારી કામગીરી બજાવી હતી, તેઓ પછાત લોકોના અને સહકારી આગેવાન તરીકે જિલ્લાના અડીખમ આગેવાન હતા. કલ્યાણપુર તાલુકાના લાંભા ગામના તેઓ વતની હતા. સમાજ સેવકની સાથે સાથે મોટા ઉદ્યોગપતિ પણ હતા.

બીજા મહાનુભાવ શ્રી ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ આયર, અમારા આહિર સમાજના રાજય કક્ષાના આગેવાન હતા. સમાજ સુધારણા માટે ખૂબ પ્રશંસનીય કામગીરી કરતા હતા. કચ્છ જિલ્લામાં ખૂબ નામના ધરાવતા હતા.

ત્રીજા ગોરધનજીભાઈ માળી કે જેઓ ૯મી અને ૧૦મી ગુજરાત વિધાનસભામાં સભ્ય તરીકે રહી ચૂકયા છે તેમની સાથે કામ કરવાનો મને મોકો મળ્યો હતો. હું જયારે સિંચાઈ મંત્રી હતો ત્યારે આ વિભાગ હેઠળના જળ સંપત્તિ નિગમમાં તેઓ ચેરમેન તરીકે હતા ત્યારે એમણે ખૂબ જ સારી કામગીરી બજાવી હતી. તેઓશ્રીના અવસાન અંગે પણ આ તકે હું શોકાંજલિ અર્પુ છું. આ બધા મહાનુભાવોના કુટુંબીજનોને આપશ્રીના મારફત શોક સંદેશો પાઠવવામાં હું મારો સૂર પૂરાવું છું. તેમજ ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરસિંહ રાવજીના અવસાન અંગે પણ હું શ્રધ્ધાંજલિ અર્પુ છું.

શ્રી ભીખાભાઈ ગ. જોષી (ભા.રા.કો.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સભાગૃહના નેતાશ્રી, જે ૧૨ મહાનુભાવોના અવસાન અંગે શોક ઠરાવ લઈને આવ્યા છે અને અમારા વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેમાં સૂર

પૂરાવ્યો છે તેમાં હું પણ મારો સૂર પુરાવું છું અને દુ:ખની લાગણી અનુભવું છું. આ મહાનુભાવો પૈકી રામજીભાઈ કરકર મારા વિસ્તારના અંબાળા જેવા નાના ગામમાં જન્મી અને ખેડૂતના દીકરા તરીકે ત્યાં અભ્યાસની કોઈ સગવડ નહોતી છતાં પણ બહાર અભ્યાસ કરી અને બેરિસ્ટર તરીકેની તેમણે પદવી પ્રાપ્ત કરી અમારા જિલ્લામાં સફળ બેરિસ્ટર તરીકે પ્રચલિત થયા હતા. એવી જ રીતે ધારાસભામાં ચૂંટાઈ અને સફળ રાજકારણી તરીકે પણ તેઓએ સારી કામગીરી બજાવી હતી. અંબાળા ગામ મારા ગામથી બે કિલો મિટરના અંતરે આવેલ છે. અને ૧૯૬૬માં જયારે હું તાલુકા પંચાયતની પહેલી ચૂંટણી લડયો ત્યારથી પાંચ ટર્મ સુધી આ રામજીભાઈ કરકરનું હંમેશા માર્ગદર્શન મળતું રહયું હતું. તેઓ મારા રાજકીય ગુરુ હતા. તેમના જવાથી અમારા જિલ્લામાં મોટી ખોટ પડી છે. તેઓશ્રીના આત્માને પ્રભુ શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના સાથે વિરમું છું.

શ્રીશંકરભાઈ લ. ચૌધરી (ભા.જ.પ.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના નેતાશ્રી જે ૧૨ મહાનુભાવોના અવસાન થયા છે તે અંગેનો શોકદર્શક ઠરાવ લઈને આવ્યા છે તેમાં હું મારો સૂર પૂરાવું છું.

અમારા બનાસકાંઠાના શ્રી ગોરધનજી માળી, આજે તેમના આગળ સ્વર્ગસ્થ શબ્દ લગાડતાં દુ:ખ થાય છે. કોઈને ખબર નહોતી કે સવારે ઘેરથી જાતે હોસ્પિટલ ગયા અને બીજા દિવસની સવાર એમને જોઈ જ નહિ. કેટલાક લોકો પોતાની યાદ એવી છોડતા હોય છે જે હરહંમેશ યાદ રહેતી હોય છે. ગોરધનજીભાઈ ધારાસભ્ય નહોતા ત્યારે પણ વિધાનસભાનું સત્ર ચાલુ થાય ત્યારે પહેલા દિવસે અચૂક અહીંયા આવતા. આજે અમે આવ્યા ત્યારે ગોરધનજીભાઈ અહીંયા નહોતા ત્યારે હદયની અંદર ખૂબ દુ:ખ થાય છે. નાની ઉંમરે અનેક સમાજ ઉપયોગી કામો છોડતા ગયા છે.

ડીસાના ખેડૂતો બટાકા પકવે. એ પકવેલ માલ લાંબો સમય સુધી ન રહી શકે એટલા માટે એને લાંબો સમય સંગ્રહી રાખવા માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજની એક આખી શ્રેણી તેઓએ ઉભી કરી, એટલું જ નહિ પરંતુ એ બટાકાના પાકને વિશ્વસ્તરે પહોંચાડવા પોતે સરકારના માધ્યમથી અને બહારથી અનેક પ્રયત્નો કરતા રહેતા. ડીસાના ખેડૂતો બટાકાના પાક સિવાય પણ બીજા પાકો પકવે એટલા માટે થઈને ગોરધનજીભાઈ પોતાના ખેતરમાં નવા પ્રયોગો કરે. એ જ રીતે એમણે મગફળીનો પ્રયોગ પણ કરેલો અને બટકાની જેમ મોટા પ્રમાણમાં એનું પણ ઉત્પાદન થઈ શકે છે એવો એક સફળ પ્રયોગ કર્યો. એમાં સ્પ્રીંકલર નામની આધુનિક પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને પોતે પ્રયોગ કરેલો અને આ ફુવારા પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ગામડે ગામડે ખેતી થઈ શકે છે એની તેઓએ પ્રતીતિ કરાવેલી. આજે તેઓ આપણી વચ્ચે નથી. તેઓશ્રી તથા બાકીના મહાનુભાવો આપણી વચ્ચે નથી ત્યારે તેઓના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ કે તમારા દુ:ખની અંદર અમે પણ દુ:ખી છીએ. પ્રભુ એમના કુટુંબીજનોને દુ:ખ સહન કરવાની શકિત અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીને વિરમુ છું.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ગૃહના નેતાશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈને આવ્યા છે, જેને વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ અનુમોદન આપેલ છે અને ગૃહના લગભગ ૧૯ જેટલા સભ્યશ્રીઓએ એમાં પોતાનો સૂર પૂરાવ્યો છે એમાં હું પણ મારો સૂર પૂરાવું છું.

સાચા અર્થમાં જોઈએ તો આ બારે બાર મિત્રો એક સાચા કર્મયોગી હતા. તેઓએ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન સતત પ્રજાની વચ્ચે રહીને એમના પ્રશ્નો સમજીને આ વિધાનસભાના સભ્યના નાતે આ વિધાનસભામાં અવારનવાર વ્યકત કરતા રહયા હતા, રજૂ કરતા રહયા હતા. આ બધા જ મિત્રો આજે આપણી વચ્ચે નથી, ત્યારે એમના કુટુંબીજનો ઉપર આવી પડેલી આપત્તિ પ્રભુ સહન કરવાની શકિત અર્પે તેવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરીએ.હવે આપણે સૌ આપણા સ્થાન ઉપર ઉભા થઈ બે મિનિટ મૌન પાડી સ્વર્ગસ્થોને અંજલિ આપીશું.

(બે મિનિટ મૌન બાદ)

સૌ સભ્યો પોતાનું સ્થાન લે. સભાગૃહનો આ સંદેશો સ્વર્ગસ્થશ્રીઓના કુટુંબીજનોને મોકલી આપવામાં આવશે.

સભાગૃહની બેઠક મુલતવી રાખવા અંગેનો પ્રસ્તાવ

શ્રી અશોક ભટ્ટ (વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહની એવી પરંપરા રહી છે કે, પૂર્વ વડાપ્રધાનશ્રીને શ્રધ્ધાંજલિ અર્પીને એમના માનમાં ગૃહ મુલતવી રાખીએ છીએ. તેથી હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરુ છું કે પૂર્વ વડાપ્રધાનશ્રી પી.વી. નરસિંહરાવને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી સભાગૃહની આજની બેઠકનું કામકાજ મુલતવી રાખીએ.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી અશોકભાઈ ભટ્ટે જે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે તેને હું ટેકો આપું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : સભાગૃહની આજની બેઠકનું કામકાજ મુલતવી રાખવામાં આવે છે .

સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ૩.૧૦ વાગ્યે પૂરુ થતાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર સભાગૃહ શુક્રવાર, તા. ૧૮મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના રોજ સવારના ૮.૩૦ વાગ્યે ફરી મળવા મુલતવી રહ્યું.

ગુજરાત વિધાનસભા
શુક્રવાર, તા.૧૮મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫
માઘ ૨૯, ૧૯૨૬ શાકે

સભાગૃહ સવારના ૮-૩૦ વાગ્યે મળ્યું.
અધ્યક્ષશ્રી પ્રો.મંગળભાઈ પટેલ અધ્યક્ષસ્થાને

તારાંકિત પ્રશ્નો

રાજયના બંદરોની કાર્ગોની હેરફેરની ક્ષમતા

***૮૮૮૩ શ્રી કાળુભાઇ હી. માલીવાડ** (લુણાવાડા): માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

રાજયના બંદરો, મહાબંદરોની સાપેક્ષમાં કાર્ગોની હેરફેર કરવા સક્ષમ છે કે કેમ?

મુખ્યમંત્રીશ્રી (બંદરો):

હા,જી.

શ્રી કાળુભાઇ હી. માલીવાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયનાં દરિયાકિનારે જે બંદરો આવેલાં છે તેમાં મોટાં અને નાનાં બંદરો છે. તો નાના બંદરોને પણ મોટા બંદરોની સાથે સુવિધાક્ષમ બનાવવા માટે શું શું કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયોના બંદરોના વિકાસે ગુજરાતના વિકાસમાં એક નવી તાકાત આપેલ છે. માનનીય સભ્યશ્રીનો જે પ્રશ્ન છે કે રાજયના બંદરો મહા બંદરોની સરખામણીએ કેટલા સક્ષમ છે? તો જે પ્રમાણે રાજયના બંદરોનો વિકાસ થયો છે એ સ્થિતિ જોતાં ચાહે ટ્રાફિકની દ્રષ્ટિએ હોય, ચાહે સુવિધાની દ્રષ્ટિએ હોય, ચાહે ખાનગી ક્ષેત્રમાં આગવી રીતે પ્રાપ્તિ માટેનું કાર્ય હોય એમાં નાનાં બંદરોએ અનેક પ્રકારનો ગુજરાતમાં વિકાસ હાથ ધર્યો છે.

મહાબંદરો અને નાનાં બંદરોની સરખામણીની દ્રષ્ટિએ વાત કરું તો મુંબઈ અને કંડલા મહાબંદરોનો ટ્રાફિક વૃદ્ધી દર ૧૦ થી ૧૩ ટકા જેટલો છે એની સરખામણીમાં ગુજરાતનાં બંદરોનો એટલે કે જે નાનાં બંદરો છે એના ટ્રાફિકનો વૃદ્ધી દર ૨૨ ટકા જેટલો છે. હયાત મહા બંદરોનો ડ્રાફ્ટ ૧૦ થી ૧૩ મિટર જેટલો છે જયારે ગુજરાતના બંદરોનો ડ્રાફ્ટ ૧૦ થી ૧૭ મિટર જેટલો પ્રાપ્ત થાય છે. મહાબંદરોએ લાંગરતી શિપોની સાઈઝ ૪૦ હજાર ડી.ડબલ્યુ.ટી. થી ૫૦ હજાર ડી.ડબલ્યુ.ટી. રહેલી છે જયારે ગુજરાતના બંદરોએ લાંગરતા શીપોની સાઈઝ...(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : તેમણે જવાબ માગ્યો છે, એટલે તો મંત્રીશ્રી એ પ્રમાણે જવાબ આપે છે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય સભ્યશ્રીએ જવાબ માગ્યો છે અને જો તમારે જવાબ ના જોઈતો હોય તો હું બેસી જાઉં. તમને ગુજરાતના વિકાસમાં રસ ના હોય તો જવાબ ના સાંભળો. (અંતરાય) તેમણે આ રીતે માહિતી માંગી જ છે. ગુજરાતના બંદરો જે પ્રકારે અન્ય રાજયોની....(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : એમણે પ્રશ્ન એવો પૂછયો છે કે....

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : તમે ગુજરાતનો વિકાસ ના જોઈ શકતા હોય તો કમસેકમ સાંભળો તો ખરા? એલ.એન.જી તથા...(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય મંત્રીશ્રી, એક મિનિટ, એમનું શું કહેવું છે? (અંતરાય)

શ્રી કાળુભાઈ હી. માલીવાડ: મેં પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ તો સાંભળો.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમણે બંદરોની સરખામણીની વિગતો માગી છે. મહા બંદરોની સરખામણીએ એલ.એન.જી. તથા કેમિકલ કારગો હેન્ડલ કરવાની ખાસ પ્રકારની સુવિધા દેશમાં અન્ય સ્થાનો ઉપર ઉપલબ્ધ નથી જયારે એલ.એન.જી. તથા કેમિકલ કારગો હેન્ડલ કરવા માટેની ખાસ પ્રકારની બંદરીય સુવિધા ગુજરાતમાં ઉપલબ્ધ બની છે

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી વિગતવાર જવાબ આપે એમાં અમને કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ બીજા પ્રશ્નોમાં અમે વિગતો માગીએ એ માનનીય મંત્રીશ્રીઓ આપતા નથી અને સરકારની ફેવરમાં જે જોઈતી હોય એ વિગતો આપે છે.(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી: માનનીય અર્જુનભાઈ. હજુ બીજા પ્રશ્નો તો આવવા દો,

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અર્જુનભાઈએ સમજવું જોઈએ કે આ વિધાનસભાગૃહમાં આ પહેલો જ પ્રશ્ન છે અને ગુજરાતમાં અન્ય બંદરોની સરખામણીએ કયા પ્રકારનો વિકાસ

થયો છે. ત્યારે મારે માનનીય સભ્યશ્રી કાળુભાઈને બે બાબતે માહિતી આપવાની છે કે ખાનગી મૂડી રોકાણ અન્ય રાજ્યોમાં ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં આવે છે જ્યારે ગુજરાત આ ક્ષેત્રે સમગ્ર રાજયમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. ૧૩ હજાર કરોડ રૂપિયા કરતા વધારે ખાનગી મૂડી રોકાણ આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થયેલ છે. અંતરની દૃષ્ટિએ એટલે કે ડિસ્ટન્સની દૃષ્ટીએ પણ ગુજરાતના બંદરો શ્રેષ્ઠ સ્થાન ધરાવે છે.

શ્રી સી. ડી. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપશ્રી દ્વારા પૂછવા માગું છું કે ૧૯૯૫ની બંદર નીતિ જાહેર થઈ ત્યારે ટ્રાફિક કેટલો હતો અને હાલમાં ટ્રાફિક કેટલો છે? આ ઉપરાંત ખેડા જિલ્લામાં ખંભાત બંદરના વિકાસ માટે ભવિષ્યની કોઈ યોજનાનો વિચાર કર્યો હોય તો તે પણ જણાવે.

શ્રી ઈન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સરકારે બંદર નીતિની જાહેરાત કરી હતી એટલું જ નહીં પણ રાજયમાં એક આકર્ષક સ્વરૂપ સાથે લાગુ કરેલ છે. ૧૯૯૫માં બંદર નીતિ જાહેર થઈ તે સમયે ગુજરાતના નાના બંદરો ઉપર ટ્રાફિક ૧૭.૧૫ મિલિયન ટન હતો એ વધીને ૨૦૦૩-૨૦૦૪માં ૮૯.૩૫ મિલિયન ટન થયો છે. માનનીય સભ્યશ્રીએ ખેડા જિલ્લાની વાત કરી છે, તો રાજયમાં કુલ નાના અને મધ્યમ કક્ષાના ૪૦ બંદરો આવેલા છે અને રાજય સરકારની બંદર નીતિ મુજબ બંદરોની જુદી જુદી સ્થિતિ અને જુદી જુદી પરિસ્થિતિ મુજબ તબક્કાવાર તમામ બંદરોનો વિકાસ કરવાનો સૈદ્ધાંતિક સ્વીકાર કરેલ છે.

વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં ગ્રામીણ વીજળીકરણ યોજનાનો લાભ

***૮૯૧૨ શ્રી જીતુભાઈ હ. ચૌધરી** (મોટા પોંઢા) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) સરકારની ૮૦ ટકા નોર્મલ યોજનામાં ગ્રામીણ વીજળીકરણ હેઠળ ખેતીવાડી માટેના કૂવાના વીજળીકરણ આદિવાસી વિસ્તાર વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં સને ૨૦૦૩-૦૪ના નાણાકીય વર્ષમાં કેટલા લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યો?

મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) :

(૧) જિલ્લાનું નામ	લાભાર્થીઓની સંખ્યા
વલસાડ	૨૫૩
નવસારી	૨૨૩

શ્રી જીતુભાઈ હ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે વલસાડ જિલ્લામાં ૮૦ ટકા નોર્મલમાં ખરેખર ૨૦૦૩-૦૪માં કેટલી અરજીઓ આવી અને આદિવાસીઓને ખરેખર લાભ કેટલો મળ્યો?

શ્રી સૌરભ પટેલ : ૨૫૩ અને ૨૨૨ અરજીઓના કામ આપણે કર્યા છે અને આવતા દિવસોમાં વલસાડ જિલ્લામાં બાકીના ૨૪૦ અરજીઓના કામ અત્યારે ચાલુ છે જે એપ્રિલ સુધીમાં પૂર્ણ થશે.

શ્રી જીતુભાઈ હ. ચૌધરી : આ તો છાપેલો જવાબ આપી દીધો, પણ કેટલી અરજીઓ આવી તે મેં પૂછેલું છે, ખરેખર તો આદિવાસીઓને અન્યાય થાય છે અને ઓપન કેટેગરીમાં લાભ આપવામાં આવે છે પણ આદિવાસીઓને લાભ મળતો નથી.

શ્રી સૌરભ પટેલ : વલસાડમાં ૯૫૨ અરજીઓ પેન્ડિંગ છે અને બને એટલું જલદી કરીશું.

શ્રી જીતુભાઈ હ. ચૌધરી : ખરેખર આદિવાસીઓને તેનો લાભ નથી મળતો, એટલે હું એ જાણવા માગું છું કે ખરેખર આદિવાસીઓની અરજીઓ કેટલી આવી છે અને ઓપન કેટેગરીની કેટલી આવી છે?

શ્રી સૌરભ પટેલ : આદિવાસીઆ માટેના ટી.એસ.પી. પ્રોગ્રામ હેઠળ જ આ અરજીઓ આવેલી છે અને તે પ્રમાણે જ આ અરજીઓ લેવામાં આવે છે.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર : માનનીય સભ્યશ્રીએ બહુ સ્પેસિફિક પ્રશ્ન પૂછેલ છે કે આદિવાસીઓની કેટલી અરજીઓ આવેલી છે? કેટલી અરજીઓનો નિકાલ કરેલ છે તેનો જવાબ આપ્યો પણ કુલ કેટલી આવી તે જાણવા માગું છું.

શ્રી સૌરભ પટેલ : વલસાડમાં ૧૯૯૯માં ૩૭૬ આવેલી છે......

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય મંત્રીશ્રી, એક મિનિટ, આમાં આપ સૌ પ્રશ્ન જોઈ જાઓ, આમાં આદિવાસી વિષેનો પ્રશ્ન નથી પૂછયો પણ આદિવાસી વિસ્તાર માટેનો પ્રશ્ન પૂછયો છે. આપ જૂઓ.

શ્રી સૌરભ પટેલ : હું આ ટી.એસ.પી. યોજનામાં જે અરજીઓ આવેલી છે તેની માહિતી આપું છું. ૨૦૦૪માં ૨૫૬ અરજીઓ આવી હતી તે સંપૂર્ણપણે આદિવાસીઓની જ અરજીઓ આવી છે. આ યોજના જ આદિવાસીઓની છે.

શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે : મારે એ જાણવું છે કે ૨૫૩ અરજીઓ વલસાડ અને ૨૨૩ નવસારી જિલ્લામાં આવેલી છે. તો એમાં આદિવાસી ખેડૂતોની ખરેખર અરજીઓ હોય તેવી કેટલી મંજૂર થયેલી છે અને બાકી રહેલી છે તે કયારે મંજૂર કરવામાં આવશે?

શ્રી સૌરભ પટેલ : મંજૂરી ક્રમાંક પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. જેટલી અરજીઓ આવેલી છે એ આદિવાસી ખેડૂતોની આવેલી છે.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય મંત્રીશ્રીએ બતાવ્યું, પરંતુ અમારો પ્રશ્ન પૂછવાનો આશય એ છે કે જે આદિવાસીભાઈઓ માટેની સ્કીમ છે પણ તમામ ખેતીવાડીના જોડાણો છે એ સરેરાશ જિલ્લાઓને ભાગે આવે છે એ પ્રમાણે આપવામાં આવેલ છે કે સ્પેશ્યલ આદિવાસી ખેડૂતોને એગ્રીકલ્ચર જોડાણ આપવામાં આવેલ છે?

શ્રી સૌરભ પટેલ : આ ફક્ત વલસાડ અને નવસારી જિલ્લા પૂરતો જ પ્રશ્ન છે એટલે એના પૂરતો જ જવાબ આપવામાં આવેલ છે. બીજા જિલ્લાઓની માહિતી જોઈતી હોય તો અલગ નોટિસ આપવામાં આવે.

અધ્યક્ષશ્રી : આ આદિવાસી ભાઈઓ માટેની સ્કીમ છે એનો અમલ કરેલ છે.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : ટોટલ ખેતીવાડી જોડાણો દરેક જિલ્લાને ભાગે આવે છે એ આપેલ છે કે આદિવાસીભાઈઓને અલગ આપવામાં આવેલ છે?

શ્રી સૌરભ પટેલ : જે પ્રમાણે બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવે છે એ પ્રમાણે અરજીઓનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : કેટલી અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવેલ હતી અને કેટલી મંજૂર કરવામાં આવી હતી?

શ્રી સૌરભ પટેલ : એકેય અરજી નામંજૂર કરવામાં આવેલ નથી. આમાં સોએ સો ટકા પૈસા રાજય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે અને એના કારણે જે કોઈ આદિવાસી વિસ્તારના ખેડૂતો અરજી કરે છે એની અરજી માન્ય રાખીએ છીએ અને એ પ્રમાણે એ લોકોને કનેકશનો આપવામાં આવે છે.

વિરમગામ, દેત્રોજ અને માંડલ તાલુકામાં જયોતિગ્રામ યોજનામાં સમાવિષ્ટ ગામો

***૮૫૯૨ શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ (માંડલ)**: માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ઊર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) વિરમગામ, દેત્રોજ અને માંડલ તાલુકામાં ડિસેમ્બર,૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં જયોતિગ્રામ યોજના નીચે કેટલા ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે,

(૨) તે પૈકી કેટલા ગામોમાં કામ પૂર્ણ થયેલ છે, અને

(૩) બાકી કામો કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે?

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ઊર્જા):

(૧) અને (૨) વિરમગામ, દેત્રોજ અને માંડલ તાલુકામાં ડિસેમ્બર,૨૦૦૪ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં જયોતિગ્રામ યોજના નીચે સમાવિષ્ટ ગામો, તે પૈકી કામ પૂર્ણ થયેલ ગામોની તાલુકાવાર સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	યોજનામાં સમાવિષ્ટ ગામોની સંખ્યા	પૂર્ણ થયેલ ગામોની સંખ્યા
૧.	વિરમગામ	૬૬	૩૬
૨.	દેત્રોજ	૫૫	૨૫
૩.	માંડલ	૩૭	૨૫

(૨) શકય તેટલા વહેલા.

શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા માંડલ મત વિસ્તારની અંદર વિરમગામ, માંડલ અને દેત્રોજ એ ત્રણ તાલકા આવેલા છે. જેમાં એના ૧૫૮ ગામોનો પૂરેપૂરો સમાવેશ કરી ૮૬ ગામો છે એને ૨૪ કલાક થ્રીફેઈઝ વીજળી ચાલુ કરી છે એ માટે પ્રથમ તો હું રાજય સરકારનો આભાર માનુ છું. ઉર્જા મંત્રીશ્રીનો વિશેષ આભાર માનુ છું કેમ કે ૫૦ વર્ષે અમે વીજળીના દીવે દિવાળી કરી. મારો પ્રશ્ન એ છે કે (અંતરાય) તમને આ બધું નહિ દેખાય, તમને ૨૪ કલાક વીજળી મળે છે એ નહિ દેખાય. ગુજરાત સરકાર જયારે આખા રાજયમાં ૨૪ કલાક વીજળી આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહી છે ત્યારે ગામડાંના કેટલાક લોકો ખેતરોમાં રહે છે, કેટલાક લોકો ગામતળથી પરા વિસ્તારમાં રહે છે. જે લોકો નવા પરામાં રહે છે એના માટે ૨૪ કલાક વીજળીનું શું આયોજન કરેલ છે? એવા પણ કેટલાક વિસ્તાર છે જે આઉટ ઓફ સિટી એટલે કે નગરપાલિકા વિસ્તારની બહાર છે જે કોઈપણ તાલુકા પંચાયતની અંદર કે ગ્રામ પંચાયતની અંદર નથી આવતા

કે જે આઈસોલેટેડ એરિયા કહેવાય, તો નગરપંચાયતમાં ન આવતા હોય કે ગ્રામ પંચાયતમાં ન આવતા હોય એવી સોસાયટીઓ માટે સરકારે શું આયોજન કરેલ છે?

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગામડાંને બેઠાં કરવા માટે ૨૪ કલાક જયોતિગ્રામ યોજના અમલમાં મૂકી છે. આ જ યોજના બે વર્ષ પહેલા હાઉસની અંદર મૂકી ત્યારે સભ્યશ્રીઓ મશ્કરી કરતા હતા. આજે કહેતા મને આનંદ થાય છે કે રાજયમાં ૭૧૩૧ ગામડાંને ૨૪ કલાક વીજળી આપવામાં આવે છે. જેનાથી ખૂબ મોટો ફાયદો છે. પણ આજની તારીખે અમદાવાદ જિલ્લાની વાત કરીએ તો અમદાવાદ જિલ્લામાં ૫૪૫ ગામડાંમાંથી ૪૧૨ ગામડાંને ૧૯ કરોડના ખર્ચે ૨૪ કલાક વીજળી મળે એના માટે જયોતિગ્રામ યોજનામાં સમાવેશ કર્યો છે. આજની તારીખમાં અમદાવાદ જિલ્લાના ૧૩૩ ગામો બાકી છે એને એપ્રિલ ૩૦ સુધીમાં સંપૂર્ણપણે જયોતિગ્રામ યોજનામાં સમાવેશ કરવાનું આયોજન છે. માનનીય ધારાસભ્યશ્રીની ચિંતા છે કે ખેડૂતો ખેતરોમાં રહે છે એને ૨૪ કલાક વીજળી આપવા માટે શું આયોજન છે. તો મને કહેતા આનંદ થાય છે કે એના માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી દીધી છે અને આવતા દિવસોમાં એને પણ વીજળી આપવામાં આવશે.

શ્રી માધાભાઈ લા. બોરીચા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું જાણવા માગું છું કે આવી યોજના દેશના અન્ય કોઈ રાજયોમાં અસ્તિત્વમાં છે ખરી અને છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી લંબાઈની વીજળી લાઈનો ગુજરાતમાં નાખવામાં આવી તેના આંકડાઓ મળી શકશે?

શ્રી સૌરભ પટેલ: ગુજરાત એક માત્ર રાજય એવું છે કે જે આખા દેશને દિશા બતાવે છે અને જેણે ૨૪ કલાક થ્રી ફેઝ વીજળી આપવાનું આયોજન કર્યું છે. હિંદુસ્તાનમાં એક પણ ગામડું એવું નથી કે જયાં ૨૪ કલાક થ્રી ફેઝ વીજળી આપવામાં આવે છે. આ યોજના એટલી મોટી છે કે બીજી રાજય સરકાર આ યોજના સમજી શકીને ગભરાય છે. એટલા માટે કે એક લાખ કિલોમીટરની લાઈનો આપણે નાખીએ છીએ. બીજાં રાજયોમાં પ્લાનીંગ કમિશનમાં વાત કરી તો તેમણે ૧૫ મિનિટ આ વિષે પૂછયું અને અભિનંદન આપ્યા કે ગામડાંને બેઠાં કરવા માટે જો કોઈએ આટલું સારું કામ કર્યું હોય તો ગુજરાત સરકારે કર્યું છે. માનનીય સભ્યશ્રી અત્યારે ચિંતા વ્યકત કરે છે પણ પોતાના વિસ્તારમાં જઈને કહે કે મારે જયોતિગ્રામ નથી જોઈતી.

ટ્રેકટરને ગાડાનો દરજજો આપવા અંગે

***૮૭૪૬ શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા(પાલીતાણા)** : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧).ટ્રેકટરને રાજય સરકારે ગાડાનો દરજજો આપ્યો છે, તે સાચું છે, અને
(૨).જો હા, તો ટ્રેકટરમાં મુસાફરો પ્રસંગોપાત જ બેસી શકે કે ગમે ત્યારે લોકો ટ્રેકટરમાં મુસાફરી કરી શકે અને કેટલી સંખ્યામાં?

મુખ્યમંત્રીશ્રી(ગૃહ):

(૧) અને (૨) ગૃહ વિભાગના તા. ૧૮/૩/૧૯૯૬ના ઠરાવ પ્રમાણે ખેતી વિષયક ટ્રેકટર કમ ટ્રેઈલરમાં લગ્ન અથવા બીજા સારા નરસા સામાજિક પ્રસંગોએ, અમુક શરતોને આધીન બિન ધંધાદારી વ્યકિતઓને લાવવા લઈ જવાની છૂટ આપેલ છે. આવા પ્રસંગોમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે પૂજા, મેળા, યાત્રા, વ્યાખ્યાનો વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

આ ઉપરાંત સામાન્ય સંજોગોમાં ટ્રેકટર ટ્રેઈલરના માલિક અથવા તેને ભાડે રાખનાર કે નોકરો પણ કામ ઉપરની વ્યકિતઓને કામે લાવવા લઈ જવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ટ્રેકટર એ સૌરાષ્ટ્રનું અને ખાસ કરીને સમગ્ર ગુજરાતનું સગવડીયું સાધન છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેડૂતોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ અથવા તો ગામડાંના ઈન્ટીરીયર વિસ્તારમાં જયાં એસ.ટી. પહોંચતી નથી ત્યાં ટ્રેકટર હોય છે તો આવા ટ્રેકટરોમાં લોકોને કાયમી મુસાફરી માટે છૂટ આપી શકાય કે કેમ? જવાબમાં કહયું છે કે ચોકકસ સ્પેસિફીક કારણોસર મુસાફરી કરતા હોય તો છૂટ આપી છે,પણ તેમને નિયમિત રીતે ગમે ત્યારે પ્રજા ટ્રેકટરમાં મુસાફરી કરી શકે એવી કોઈ વ્યવસ્થા કરી શકાય કે કેમ અને જો ન કરી શકાય તો તેના શું કારણો છે?

શ્રી અમિત અ. શાહ : જયાં સુધી ધારાસભ્યની લાગણીનો સવાલ છે ત્યાં સુધી સરકાર આ લાગણી સાથે સંમત છે. આપણાં દેશનો આત્મા ગામડાંમાં છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વાહનવ્યવહાર માટે આજે પણ ટ્રેકટર એ અગત્યનું સાધન છે. પરંતુ કાયદાના પ્રશ્નમાં વિચારવા જઈએ તો રૂલ્સ-૧૯૮૯ના નિયમ-૨-બી હેઠળ કૃષિવિષયક યાદી છે તેમાં ટ્રેકટરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે ટ્રેકટરને કાયમી વાહનવ્યવહાર માટે પરમિશન આપી શકાય તેમ નથી, પરંતુ ગામડાંના વિસ્તારની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે આમાં છૂટછાટ આપીને અમુક હેતુ માટે દા.ત. ધાર્મિક મેળાવડા હોય, કયાંય સામાજીક પ્રસંગ હોય, લગ્ન પ્રસંગ હોય, મરણ

પ્રસંગ હોય, આ પ્રકારના પ્રસંગોમાં જવાનું હોય તો લોકોને ટ્રેલરમાં બેસીને જવાની છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. આ છૂટછાટ આપવાનો ઈનિશિયેટીવ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે લીધો છે બાકી કોઈએ નથી લીધો.

શ્રી કનુભાઇ મે. ભલાળા : ટ્રેકટર અત્યારે ખેડૂતોનું આધુનિક બળદગાડું હોય તો ટ્રેકટરમાં મજૂરોને લાવવા માટેની, હેરફેર કરવાની જરૂરિયાત પડતી હોઈ એક તાલુકાએથી બીજાં તાલુકા સુધી જવાનું થતું હોય તો મજૂરોની હેરફેર માટે આવી છૂટછાટ સરકાર આપવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી અમિત અ. શાહ : અમે તો ધારાસભ્યો આવે તો પણ બોલતા નથી. કાલે ધારાસભ્યો ટ્રેકટરમાં આવ્યા તો પણ કંઈ ન બોલ્યા. ધારાસભ્યો પણ ટ્રેકટરમાં આવ્યા. મજૂરોનો પ્રશ્ન છે ત્યાં સુધી એવી કોઈ સ્પેસિફિક છૂટછાટ આપી નથી પણ જે છૂટછાટ આપી છે તેમાં અત્યારે પરિવહન ચાલુ જ છે.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ નિર્ણય કર્યો છે. તો આ નિર્ણય સંપૂર્ણપણે પોકળ છે. આજેપણ ખેડૂતોના ટ્રેકટરોને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી ડિટેઈન કરવામાં આવે છે, પ્રસંગોપાત જાય છે ત્યારે ડિટેઈન કરવામાં આવે છે. 'સલામત સવારી, એસ.ટી. અમારી' સૂત્ર આપીને એસ.ટી.ની બસોને ખખડધજ કરાવી નાખી છે એના કારણે આ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. આજે સ્કૂલના બાળકોને પણ સ્કૂલે જવા માટે ટ્રેકટરનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. માનનીય મંત્રીશ્રીને સ્પષ્ટપણે કહેવા માગું છું કે ખેડૂતોને અને મજૂરોને માટે થઈને સ્પષ્ટપણે કાયમી ધોરણે જવા આવવા માટે તમે છૂટછાટ આપવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, થોડુંક વિષયાંતર કર્યું છે. આ ગૃહની અંદર મારા વિભાગની ચર્ચા આવશે ત્યારે એનો વિગતવાર જવાબ આપીશ. અત્યારે જયાં સુધી ખેડૂતોને કનડવાનો સવાલ છે એ બાબતે છેલ્લા એક વર્ષની અંદર એકપણ ખેડૂતનું ટ્રેકટર ડિટેઈન થયું નથી અને એક રૂપિયાનો દંડ પણ લેવામાં આવ્યો નથી. આ ગૃહને એમણે ગેરમાર્ગે દોર્યું છે. (અંતરાય)

રાજયમાં પી.એસ.આઈ., પી.આઈ. અને ડી.એસ.પી. ની ખાલી જગ્યાઓ

***૮૪૧૮ શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર(મહુધા)** : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) રાજયમાં તા.૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ પી.એસ.આઈ., પી.આઈ., ડી.એસ.પી.ની કુલ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૨) આ જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાં આવશે?

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) :-

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૪ના રોજ ખાલી જગ્યાઓની માહિતી નીચે મુજબ છે.

(૧)	પો.સ.ઈ.:	૭૨૯
(૨)	પો.ઈ.:	૬
(૩)	ડી.એસ.પી.:	૯

(૨) વહીવટીય અનુકૂળતાને આધીન રહીને શકય તેટલી વહેલા આ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયમાં કેટલી ખાલી જગ્યાઓ છે? એમાં પી.એસ.આઈ.ની કેટલી છે, પોલીસ કોન્સ્ટેબલની કેટલી ખાલી છે, ડી.એસ.પી.ની કેટલી ખાલી છે અને ડી.વાય.એસ.પી.ની કેટલી ખાલી છે?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જવાબ છાપેલો જ છે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કાયદો અને વ્યવસ્થાના તંત્ર સાથે આ વિભાગ સંકળાયેલો છે. એટલે અહીંયાં જે માહિતી આપી છે એમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટરથી માંડીને ડી.એસ.પી. સુધીની આ જગ્યાઓ ખાલી રહેવાથી અધિકારીઓ ઉપર મોટું ભારણ આવ્યું છે. ત્યારે આપના દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રીને એ પૂછવા માગું છું કે, આ રાજય સરકાર છે એ જગ્યાઓ ખાલી રાખી અને અધિકારીઓ પાસે એ વધારાનો ચાર્જ આપી અને એમની પાસે રોજમદારીના ધોરણે કામ લેવામાં આવે છે. આ જગ્યાઓ D.G.P., Additional D.G.P., Inspector General of Police અને છેક પી.એસ.આઈ. સુધીની છે અને છેલ્લા એક વર્ષથી D.G.P. વગેરેની જગ્યા ખાલી રાખી મનગમતા અધિકારીઓને કામ આપી ગેરકાયદેસર કૃત્યો કરાવવામાં આવે છે અને તેમનો રાજકીય હાથા તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. (અંતરાય)

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી,....

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ઈન્ટરવીન થાય છે. આપને પછી ચાન્સ આપું છું. ગૃહના નેતા ઈન્ટરવીન થઈ શકે છે.

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી : પ્રશ્ન છે જ નહીં......(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ગૃહના નેતા ઈન્ટરવીન થઈ શકે.(અંતરાય) ગૃહના નેતા ઈન્ટરવીન થઈ શકે.(અંતરાય) એમને ઈન્ટરવીન થવું છે, એ થઈ શકે (અંતરાય) (ઘોંઘાટ) પ્લીઝ, પ્લીઝ, બધા બેસી જાઓ, ઈશ્વરભાઈ પ્લીઝ, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી....

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : આપ બોલ્યા છો એનો જવાબ આપે છે (અંતરાય) એ આપ બોલ્યા છો એનો જવાબ આપે છે. એમને ઈન્ટરવીન થવું છે. (અંતરાય) મુખ્યમંત્રીશ્રીનો અધિકાર છે કે એમને જ્યારે ઈન્ટરવીન થવું હોય ત્યારે થઈ શકે.

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહની ઉજજવળ પરંપરાને ખાતર મારી આપને નમ્ર પ્રાર્થના છે કે વિધાનસભાની અંદર સીધે સીધા પ્રશ્નો પૂછાય. પૂર્વભૂમિકાની કોમેન્ટ, વિષય બહારની કોમેન્ટને રોકાવી જોઈએ, આ મારી રજૂઆત છે. બીજી બાબત મારી અપેક્ષા હતી કે કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી જૂની પાર્ટી એ ખૂબ યોગ્ય વ્યકિતને વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકેની કામગીરી સોંપી રહી છે, પરંતુ આજે પહેલો જ બોલ નો બોલ ગયો. પહેલો જ બોલ નો બોલ ગયો એનું દુ:ખ છે અને ત્રીજી બાબત એ કે ગયું જે વિધાનસભાનું સત્ર એક દિવસ માટે મળ્યું હતું ત્યારે શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડીયા વિધાનસભાની અંદર નેતા તરીકે ચાર્જમાં હતા આ નેતા તરીકે ચાર્જમાં હતા એ શું રોજમદારી હતી? એ નક્કી થવું જોઈએ કે એક દિવસ માટે શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડીયા નેતા તરીકે ચાર્જમાં હતા એ ચાર્જમાં હોવું એ રોજમદારી હતી? એ પહેલા વિપક્ષના નેતા પોતે એક દિવસ ચાર્જમાં ગઈ વિધાનસભામાં હતા એ કોંગ્રેસની રોજમદારી હતી? આ પણ જરા સ્પષ્ટ થઈ જાય એ જરૂરી છે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમારે ઉપદેશની જરૂર નથી. અમારે તો માત્ર અમારા પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ છે અને પ્રશ્ન પૂરો સાંભળવાની તૈયારી રાખવી પડશે. શાસન ચલાવવું હોય તો આ અમારો અધિકાર છે અને અમે એ અધિકારનો ઉપયોગ કરવાના જ છીએ. હું આપના દ્વારા એ પૂછવા માગું છું કે આ ડાયરૅક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસથી માંડીને જે નીચેના અધિકારીઓ સુધી એમને એક દિવસનો હવાલો આપી અને લટકતી તલવાર ઉપર રાખી અને એમની પાસેથી ગેરકાયદેસર કામગીરી લેવાય છે. આ ખાલી જગ્યાઓ સરકાર ભરવા માગે છે કે કેમ? ડાયરૅક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસથી માંડીને જેટલી જગ્યાઓ ખાલી પડી છે એના માટે હું એમનો જવાબ માગું છું.

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડીયાએ જે પ્રશ્ન એમણે ઊભો કર્યો એ મને લાગે છે કે એમની બેઝિક સમજની અંદર ક્યાંક ગરબડ છે. સાહેબ, હું એવું તો ના કહી શકું કે સમજ નથી પણ બેઝિક સમજની અંદર ગરબડ છે ત્યારે (અંતરાય) સાહેબ મેં એમને સાંભળ્યા છે એટલે એ હવે મને સાંભળે. મારે આપનું રક્ષણ જોઈએ છે. સાહેબ મેં એમને સાંભળ્યા છે. ઈરિલેવન્ટ બોલ્યા તો પણ મેં સાંભળ્યું છે અને હું એક મંત્રી તરીકે બોલું છું તો પણ નથી સાંભળતા, તો આ રીતે વિધાનસભા કઈ રીતે ચાલશે? એમની બેઝીક સમજમાં ગરબડ છે. આ રાજયના ડી.જી.પી. ઈન્ચાર્જ નથી. ડી.જી.પી. ભાર્ગવનું પ્રમોશન એક વર્ષ પહેલાં થઈ ગયેલું છે. એ ડી.જી.પી. છે એ એમને ખ્યાલમાં નહિ હોય. હું ગૃહ સમક્ષ સ્પષ્ટતા કરું છું કે ભાર્ગવ આપણા જે ડાયરેકટર જનરલ ઓફ પોલીસ છે એમને એક-સવા વર્ષ પહેલાં ડી.જી.પી. તરીકે પ્રમોશન આપેલ છે અને ડી.જી.પી. તરીકે પોલીસ તંત્ર સંભાળી રહ્યા છે. આમ તો અર્જુનભાઈ.....(અંતરાય)

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : કાયમી ધોરણે કોની નિમણૂંક થયેલી છે? ડાયરેકટર જનરલ ઓફ પોલીસની જગ્યા ઉપર કાયમી ધોરણે કોની નિમણૂંક થયેલી છે એ મારો પ્રશ્ન છે?(અંતરાય)

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રેકર્ડ ઉપર વાત મૂકી છે ત્યારે જવાબ પણ રેકર્ડ ઉપર આવી જવો જોઈએ. માનનીય વિરોધપક્ષના નેતા શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ જે પ્રશ્ન ઉપાડ્યો છે કે ખોટી નિમણૂંકો થઈ છે, તો જી.એ.ડી.ના નિયમોની એમને ખબર નથી, પ્રમોશન થયું છે. આખા ભારતમાં એ સિનિયર મોસ્ટ આઈ.પી.એસ. છે. એપોઈન્ટમેન્ટનો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થયો નથી, જયારે ઘટનો સવાલ કરે છે ત્યારે કહેવા માગું છું કે કોંગ્રેસના શાસનમાં કરકસરની નીતિ ચાલુ કરી હતી એના લીધે મોટી ઘટ છે. અમે ભરતી કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે અને ૬૦૦૦ લોકોનાં ઈન્ટર્વ્યુ પતી ગયાં છે, શારીરિક પરીક્ષા, લેખિત પરીક્ષા પતી ગઈ છે અને થોડા દિવસોમાં ટ્રેનિંગમાં જશે. એમના વખતમાં દેવાળું નીકળ્યું હતું અને કાપ મૂક્યો હતો એના કારણે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી.

અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપરથી અનૈતિક ધંધા હેઠળ મહિલાઓ પકડાવા અંગે

***૯૩૩૫ શ્રી વેચાતભાઈ હ. બારિયા(પાવી-જેતપુર)** : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

(૧) અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ એકપોર્ટ ઉપરથી મહિલાઓને આરબ દેશોમાં અનૈતિક ધંધા માટે મોકલવામાં આવતી હોવાની હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને
(૨) જો હા, તો કેલેનડર વર્ષ ૨૦૦૩ અને વર્ષ ૨૦૦૪માં આવા કુલ કેટલા કેસો પકડાયેલ છે?

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ):
(૧) હા.
(૨) ૧ કેસમાં ૦૪ આરોપીઓ પકડાયેલ છે.

શ્રી વેચાતભાઈ હ. બારિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું એ પૂછવા માગું છું કે આ મહિલાઓ પાસેથી આવા પ્રકારના ધંધા કરાવવા પાછળનો આરોપીઓનો હેતુ શું હતો અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આ ગુનામાં કોઈ આરોપીઓ પકડવાના બાકી છે કે કેમ?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આરોપીઓનો હેતુ આ છોકરીઓને લાલચ આપી અનૈતિક ધંધો કરવા આરબ દેશોમાં લઈ જઈ કમાણી કરવાનો હતો. પકડવાના બાકી છે એ પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવું કે ચારેય આરોપીઓને પકડી લેવામાં આવેલ છે.

શ્રી સુનીલ બા. ઓઝા : આ બનાવ કયારે બનેલો, ગુનો કયા પોલીસ સ્ટેશનમાં બન્યો છે, એની તપાસ હાલ કયા તબક્કે છે, ચાર્જશીટ કરવામાં આવ્યું છે કે નહિ અને નિકાલની વિગતો શું છે?

શ્રી અમિત અ. શાહ : આ બનાવ તા. ૧૬-૧૨-૨૦૦૩ના રોજ રાતના ૨૨-૦૦ કલાકે બનેલો હતો. ગુનો ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન, અમદાવાદ શહેરમાં નોંધાયેલ છે. આ કેસ કોર્ટમાં ચાલવા પર પડતર છે. ચાર્જશીટનો સવાલ છે તો તા. ૨૬-૨-૨૦૦૪ના રોજ ચાર્જશીટ મૂકી દેવામાં આવેલ છે. કોર્ટની પ્રાયોરિટી આવ્યેથી તરત હિયરીંગ ચાલું થશે.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : માનનીય મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે એક કેસમાં ચાર આરોપીઓ પકડાયેલા છે. આ ઈન્ટરનેશનલ અનૈતિક ધંધાના કામમાં જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ મહિલાઓ માટે થયું છે એ જોતાં માનનીય મંત્રીશ્રીને જણાવવાનું કે એક કેસમાં માત્ર ચાર આરોપીઓ હશે, પણ મૂળ સુધીમાં આખી ટોળી પડેલી છે. તો વિભાગ માત્ર ચાર આરોપીઓને પકડીને આઈડેન્ટીફાઈ કરીને મૂકી દેવા માગે છે કે મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવા માગે છે?

શ્રી અમિત અ. શાહ : આના મૂળ સુધી પોલીસ વિભાગ પહોંચેલ છે આ મૂળતઃ આરોપીઓ બોમ્બે બેઈઝ છે. વર્ષોથી જુદી જુદી યુવાન છોકરીઓને લાલચ આપીને દુબઈમાં લઈ જવાનું કામકાજ કરતા હતા અને અહીં એક જ વાર ટ્રાય કરી અને પહેલા ટ્રાયમાં પકડાઈ ગયા છે. જયાં સુધી ગુજરાતનો સવાલ છે ત્યાં સુધી આમાંથી કોઈ આરોપી ગુજરાતના નથી. મહારાષ્ટ્રની અંદર તંત્ર પકડવા બાબત હું કાંઈ કહી ના શકું, એમના પક્ષની સરકાર છે એ જરા ત્યાંથી માહિતી મેળવી લે.

શ્રી પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ : જે ચાર આરોપીઓ પકડાયા છે એમની પાસેથી રિમાન્ડ લઈ એમણે અત્યાર સુધીમાં કેટલી સ્ત્રીઓને વિદેશ મોકલી એવી કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ છે કે કેમ?

શ્રી અમિત અ. શાહ : સાહેબ, રિમાન્ડની માહિતી હું અહીં ગૃહમાં કઈ રીતે રજૂ કરી શકું?

અધ્યક્ષશ્રી : ના, પણ બીજી કેટલી સ્ત્રીઓ બહાર મોકલી છે?

શ્રી અમિત અ. શાહ : ગુજરાતની અંદર આ પ્રકારના બીજા કોઈના મેળવાપીપણાંની વિગત પ્રાપ્ત થઈ નથી અને આ ચાર્જશીટની વિગત છે અને ચાર્જશીટ કોર્ટમાં પેન્ડિગ છે (અંતરાય) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં સ્પેસિફિક જવાબ આપ્યો છે. ગુજરાતની અંદર આની કોઈ કડીઓ રિમાડની અંદર મળી આવેલ નથી. (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : એવું નથી કહેવા માગતા, પણ આના સિવાય બીજી કોઈ સ્ત્રી આ લોકોએ બહાર મોકલી છે?(અંતરાય)

શ્રી અમિત અ. શાહ : સાહેબ, આ રીતે (અંતરાય) તમે બેસી જાવ, હું ઊભો છું એટલે. આ રીતે મોકલવાનો નિયમિત ધંધો કરવાવાળા આ ચાર લોકો હતા. ગુજરાતની અંદર એક જ ઘટના થઈ છે અને અમારે જે માહિતી મહારાષ્ટ્રના પોલીસતંત્રને મોકલવાની હોય એ અધિકૃત મોકલી આપી છે.

શ્રી પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ : સ્ત્રીઓની માહિતી મળી છે? આ વર્ષોથી ધંધો કરતા હતા...

અધ્યક્ષશ્રી : નેકસ્ટ પ્રશ્ન....

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ-૨૦૦૫ હેઠળ થયેલા એમ.ઓ.યુ.

*૮૩૧૪ **શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ(વાગરા)** : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી(ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે :-
(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ ૨૦૦૫ હેઠળ કેટલા રોકાણકારોએ કેટલા કરોડના મૂડીરોકાણ કરવાની તૈયારી બતાવી છે, અને
(૨) આ અન્વયે કેટલા ઉદ્યોગ સાહસિકોએ કેટલા મૂડીરોકાણના વિધિવત સમજુતી કરારો એમ.ઓ.યુ. કર્યા અને કયા કયા સેકટરમાં?

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) :
(૧) અને (૨) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ ૨૦૦૫ હેઠળ કુલ ૨૨૬ રોકાણકારોએ રૂ.૧,૦૬,૧૬૦ કરોડ મૂડીરોકાણ કરવાની તૈયારી બતાવી છે, જેની સંપૂર્ણ વિગતો પત્રક સ્વરૂપે આ સાથે સામેલ છે.

Agro MOUs

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project	Invest-ment in Crs.	Location	MOU /Announcement
૧	Deepkiran Foods P Ltd	Expansion of food processing units	૨.૫૩	Gandhinagar	MOU
૨	MAC Fills Enterprises P Ltd	Ready to eat snacks food	૩૪.૦૦	Ahmadabad	MOU
૩	Bharat Food Co-Op Ltd	Oil Refinary	૪૦.૫૦	Gandhidham	MOU
૪	Maxo (I) Pharmachem P Ltd	Biofuel from Jatroph	૩૫.૦૦	Navsari/ South Gujarat	MOU
૫	Inde's Great Food CO P Ltd	Proceesed Gherkins	૪૪.૭૦	Valsad	MOU
૬	Capital Foods P Ltd	Food Park	૪૫.૦૦	Gandhidham	MOU
૭	Best Roses Biotech P Ltd	Floriculture expansion project	૬.૫૦	Navsari	MOU
૮	Godrej Agrovet Ltd	Palm Oil Processsing & Cultivation	૨૫૦.૦૦	South Gujarat	MOU
૯	Harsh Flora	Floriculture	૦.૫૦	Navsari	MOU
૧૦	Bharat Agritech	Floriculture	૧.૫૦	navsari	MOU
૧૧	Laxmi Hotels Inc USA	૧૦૦ % EOU for Isabgil	૭.૫૦	Mehsana/siddhpur	MOU
૧૨	Well Spun	Cotton farming	૨૦૦.૦૦	Surendranagar /SK/BK/ Patan/Kutch	Announcement*
૧૩	P M Marketing	Cold Chain Project Food Park	૧૭.૦૦	Ahmadabad	MOU
૧૪	Greenfield /Canada	Solar Powered Green House	૧૦.૦૦	Ahmadabad/ Baroda	MOU
૧૫	Urjamandir Agro Park	Agro Park	૫૦.૦૦	Baroda	MOU
૧૬	Clary Ltd. UK	R&D in Tobacco and	૧૩૦.૦૦	Gujarat	MOU

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project	Invest-ment in Crs.	Location	MOU /Announcement
		Cigarette manufacturing			
૧૭	NAFED	Cultivation of Jatropha	૩૦	Gujarat	MOU
૧૮	National Botanical Research Institute, Luknow	(૧) Collaborative Research in BT Cotton (૨) Navsari Agri. University (૩) Gujarat State Seed Corporation Ltd.	--	Gujarat	MOU
૧૯	Gujarat Oleo Chem Ltd	Biofuel	૧૦.૦૦	Bharuch	MOU
૨૦	APEDA	AEZ for sesam seeds	૮.૦૭	Saurastra	MOU
૨૧	Aaditya Aeromadic & Bioenergies P ltd	Biofuel	૫.૦૦	Navsari	MOU
૨૨	Sonpal Export P Ltd	Processing of Sesame seeds	૩.૭૫	Amreli	MOU
૨૩	Vasundhara Khadigram Udyog, Surat	Herbal & Floriculture Park	૩૮.૭૦	S.Gujarat	MOU
૨૪	Ganesh Foundation, Kadi	Processing & packing of horticulture, floriculture & medicinal plants	૩૪.૨૦	N Gujarat	MOU
૨૫	Shivshiva Agri business Services Pvt. Ltd., Ahmedabad	૧૦૦% EOU solar photovoltaic powered unit for barley powder	૨.૬૫	Ahmadabad	MOU
૨૬	Dhruv Makhan(I) Ltd., Ahmedabad	Composite Agro park	૨૮.૫૦	Ahmadabad	MOU
૨૭	NDDB and Anand Agriculture University	Embryo transfer technology	૧.૬૧	Anand	MOU
૨૮	Ace Rosil Exports, Surat	Floriculture in Greenhouse system cut Roses	૧.૭૫	Surat	MOU
૨૯	Farm Fresh, Surat	Greenhouse for Gerbera and vegetable ε capsicum	૧.૧૮	Surat	MOU
૩૦	Mehul Flora, Navsari	Floriculture in Greenhouse system for Gerbera and Carnation	૦.૩૩	Navsari	MOU
૩૧	Universal Floritech,	Floriculture in	૦.૬૪	Surat	MOU

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project	Invest-ment in Crs.	Location	MOU /Announcement
	Surat	Greenhouse system for Gerbera and Carnation			
૩૨	Janvi Flora, Surat	Floriculture in Greenhouse system for Gerbera and Carnation	૦.૫૭	Surat	MOU
૩૩	Payal Flora, Navsari	Floriculture in Greenhouse system for Gerbera	૦.૫૬	Navsari	MOU
૩૪	Sheetal Agro Indistries, Kutch	Aloevera processing plant and plant	૨.૬૦	Kutch	MOU
	૩૪	**Total**	**૧૦૪૪.૮૪**		

Power

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project (MW)	Invest-ment in Rs. Crs.	Location	MOU /Announcement
૧	GIPCL stage-II Ext (with GSECL)	૨૫૦ ઙ Lignite	૧૧૬૫	Mangrol Surat	MOU
૨	GPCL	૫૦૦-Lignite	૨૦૦૦	Bhavnagar	MOU
૩	GMDC	૫૦૦ Lignite/carbonacious Shale	૨૫૦૦	Kutch	MOU
૪	Essar Power with GPCL	૧૦૦૦ Gas/RLNG	૩૭૭૦	Hazira	announce ment*
૫	NHPC	study of hydro power	--	Kalpsar	MOU
૬	Adani Pvt Ltd	૧૦૦૦ Lignite/Imported fuel	૪૦૦૦	Mundra	announce ment*
૭	Torrent Group	૧૦૦૦ Lignite/Imported fuel	૩૯૦૦	South Gujarat	announce ment*
૮	L&T	૩૫૦ Gas / Other	૧૦૦૦	Utran/ Dhuvaran	announce ment*
૯	GSEG	૫૦૦ gas	૧૭૫૦	Hazira	MOU
૧૦	NTPC for Gandhar Stage II & III	Gas	૮૦૦૦	Gandhar	Announc ment
૧૧	Nuclear Power Corp.	Nuclear	૨૦૦૦	Tarapur	Announce ment

૧૨	NEPC India	૨૦૦ wind power	૧૦૦૦	kutch/Jamnagar/ Junagadh	MOU
૧૩	Enercon Ltd.	૬૫૦ wind power	૩૦૦૦	Jamnagar/ Porbandar	MOU
૧૪	Suzlon Industries	૫૦૦ wind power	૨૫૦૦	Jamnagar/ Kutch	MOU
૧૫	NEG Micon	૨૫૦ wind power	૧૨૫૦	Kutch/ porbandar	MOU
૧૬	Riyen Ramani, UK	૨૩	૧૪૬.૧	Hydo, Bharuch	MOU
૧૭	Riyen Ramani, UK	૫૦	૨૨.૨	Hydro, Karjan Dam	MOU
	૧૭	**Total**	**૩૮૦૦૩.૩**		

Oil & Gas

Sr. No.	Name of the Company/Group	Type of Project	Invest-ment in Rs. Crs	Location	MOU /Announce ment
૧	CAIRN ENERGY	New Projects / operation of CB/OS - ૨ Blocks	૨૨૫	Gulf of Cambay	Announce-ment
૨	NIKO	Investment in various oil and gas fields & drilling in Gujarat	૯૯	Surat	Announce-ment
૩	JTI	Investment in various oil and gas fields & Dholka and Verali	૪૫	Ahmadabad-Dholka	Announce-ment
૪	INTERLINK	Investment in hydrocarbon sector	૩૩	Ahmadabad-Bawala	Announce-ment
૫	PRIZE PETROLEUM CO. LTD.	Drilling and Installation in Ahmedabad, Mehsana and Cambay field	૭૫	Ahmadabd-Mehsana-Cambay	Announce-ment
૬	ONGC	Exploration and Installation in Ahmedabad, Bharuch, Mehsana and Cambay field	૧૭૦૦	Ahmadaba/baroda /ankleshwar/ Mehsana	Announce-ment
૭	HOECL	Exploration of block no. CB-ON/૭, North Balol	૫૦	Mehsana/cambay/ Tarapur	Announce-ment
૮	JUBILIANT EMPRO	Exploration on CB-ONN-૨૦૦૨/૨ and ૨૦૦૨/૩ at Mehsana and Ahmedabad	૫૨	Ahmadabad/ Mehsana	Announce-ment
૯	JOHN ENERGY	Drilling service	૨૦	Ahmadabad/ Gujarat	Announce-ment
૧૦	SELAN EXPLORATION TECH. LTD	Drilling and testing services at Indrora	૮.૧૫	Ahmadabad/ Gandhinagar/ Mehsana	Announce-ment
૧૧	GSPCL	Drilling and testing services at Dholka, Cambay and other fileds	૬૦૦	various fields in Gujarat	Announce-ment
૧૨	Gujarat Oleo	Bio-disel plant	૧૫૦	Kutch/Bharuch	Announce-

	Chem Ltd.				ment
૧૩	Geo Global Resources	Exploration & Production	૧૧.૨૫	Sanand/Mehsana	Announce-ment
૧૪	SHELL	Expansion of LNG Terminal from ૫ MMTPA to ૧૦ MMTPA	૨૬૨૦	Hazira	Announce-ment
૧૫	LNG PETRONET Ltd.	Expansion of LNG Terminal from ૫ MMTPA to ૧૦ MMTPA	૧૦૦૦	Dahej	Announce-ment
૧૬	ADANI	Natural Gas distribution network including CNG at Vadodara and Ahmedabad	૨૩૫	Ahmadabad/ Baroda	Announce-ment
૧૭	Gujarat Gas Co. Ltd.	Investment in gas distribution network and CNG in Gujarat	૨૦૦	Surat/Bharuch	Announce-ment
૧૮	IOCL	Investment in retail outlets and installation	૨૧૫.૯૨	various location in Gujarat	Announce-ment
૧૯	CHAROTTAR GAS SAHKARI MANDLI	Distribution network and CNG in Anand	૨૯	Anand	Announce-ment
૨૦	HPCL	CNG network at Ahmedabad and Mundra. Delhi POL pipeline	૫૮૨.૭૫	Ahmadabad	Announce-ment
૨૧	BPCL	CNG network at Gandhinagar, Mehsana and Sabarkantha	૩૫૫	Gandhinagar/ Mehsana/SK	Announce-ment
૨૨	GSPL	Gas grid development in Gujarat	૧૨૦૦	N Gujarat/ Saurastra	Announce-ment
૨૩	KRIBHCO	Expansion of Phase II of Urea plant at Hazira and revamp of KRIBHCO Hazira plant of Phase I	૨૧૫૦	Hazira	Announce-ment
૨૪	GNFC	Revamp of Menthol ૨ Plant and synthesis gas generation unit. Conversion of feedstock from LSHS to LNG. Generation of power - ૩૧ MW. Acetic acid plant - ૧૫૦૦૦૦ MTA	૧૬૨૦	Bharuch	MOU
૨૫	Oren Hydrocarbon UAE	Oil Based Cement & Calcium Chrloride Prills	૧૧.૨૫	Kutch	MOU
	Sub Total	**૨૫**	**૧૩૨૮૭**		

Emerging Technologies - IT

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project	Investments (Rs. Cr.)	Location	Employment Generation	MOU /Announcement
૧	Effective Teleservice Expansion (USA)	**IT** : ETI Expansion	૫૦	Abd-Gngr	૩૦૦૦	MOU
૨	ACi Laptop Mfg (UK)	**IT:** Laptop Manufacturing	૫૦	Abd-Gngr	૨૦૦	MOU
૩	Infinium India Ltd	**IT** : SATCOM Manufaturer	૧૪	Abd-Gngr	૧૨૫	MOU
૪	Effective Gujarat Education (USA-GOG)	**IT** : BPO Training	૧૦	Abd-Gngr	૪૦૦૦	MOU
૫	Motif India Infotech P Ltd	**IT** : BPO	૫	Abd-Gngr	૫૦૦	MOU
૬	Compubits -British Telecom facilities Management & BPO (UK)	**IT** : Facilities management for UK Telecom & BPO	૫	Abd-Gngr	૧૫૦	MOU
૭	Apex International Expansion-call center	**IT** : International Call Center	૩.૫	Abd-Gngr	૧૫૦	MOU
૮	Netrique Teleservices - call centers (Canada)	**IT** : Contact center operation	૨.૫	Abd-Gngr	૭૫	MOU
૯	Congruent Vventures LLC		૬૦	Abd-Gngr		MOU
૧૦	Ugam Solutions		૬૦	Abd-Gngr	૩૦૦૦	Announcement
૧૧	Cybage		૧૦	Abd-Gngr	૭૦૦	Announcement
૧૨	PCS		૫	Abd-Gngr	૫૦૦	Announcement
૧૩	Birla Soft		૫	Abd-Gngr	૩૦૦	Announcement
૧૪	Rolta		૩	Abd-Gngr	૨૦૦	Announcement
૧૫	PRISM Semiconductors and BPO USA		૨.૫	Abd-Gngr	૨૦૦	Announcement
૧૬	Recreate Solution and Profile Tech. - Interactive and TV Programming UK		૧.૨૫	Abd-Gngr	૫૦	Announcement
૧૭	TICS Instruments and BPO UK		૧	Abd-Gngr	૫૦	Announcement
૧૮	Cadila Pharma	**BT** Production of cytokinis/agent	૨૦	Kadi		MOU

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project	Invest ments (Rs. Cr.)	Location	Employ-ment Genera-tion	MOU /Announcement
		s/polymers				
૧૯	Concord Biotech	**BT** Production of industrial enzymes	૨૦	Ahmadabad		MOU
૨૦	MAPs India Ltd	**BT** Manufacture of Enzymes /Micro organisams/bio fuels	૧૦	Oran		MOU
૨૧	Synchron Research Service P Ltd	**BT** CRO	૫	Ahmadabad		MOU
૨૨	Floro-O Foods	**BT** Protein extraction	૫.૨૫	Jaipur Rajasthan		MOU
	૨૨	**Sub Total**	૩૪૮			

Tourism

Sr. No.	Name of the Company/Group	Type of Project	Location	Invest-ment in Rs. Crs.	Location	MOU /Announcement
૧	NG Foundation Ahmedabad	Themepark in Special Entertainment Zone	Dandi Navsari	૩૦૦૦	Navsari/ Dandi	MOU
૨	Swapnasiddhi Entertainment P Ltd	Special Entertainment Zone in South Gujarat	South Gujarat	૩૬૦૦	South Gujarat	MOU
૩	Bharat Hotels , Delhi	૫ Star Hotels & Golf Course		૩૫૦	Ahmadabad	MOU
૪	Kutch Steel Pvt. Ltd	૫ Star Hotel at Kutch	Bhuj	૪૦	Bhuj	MOU
૫	RF Gandhi - AKT Ltd., Mauritius	Ecotourism Project at Karjan Dam and Panchmahal Safari	Karjan Dam	૨૫	Panchmahal/ Karjan	MOU
૬	World Welfare Organisation	Religious tourism project at Gandhinagr	Gandhinagar	૨૦	Gandhinagar	MOU

૭	Ayush Foundation Ahemadabd Lalit Purohit	Ayurvedic Centre & Resort	Ahmadabad	૧૭	Ahmadabad	MOU
૮	Hotel Ravi International, Baroda	૩ Star Hotel & Hotel management Institute		૧૧	Surat	MOU
૯	Heeldeep Farms	Star Categorise hotel	*************	૧૦	Gandhinagar	MOU
૧૦	Narayani Farms, Ahmedabad (Gopiram Gupta)	Canal Tourism	Gandhinagar	૫	Gandhinagar	MOU
૧૧	RF Gandhi - AKT Ltd., Mauritius	Floating Resturant & Beach Resort	Somnath	૪.૫	Junagadh -Somnath	MOU
૧૨	Gujarat Thor Entertainments Pvt. Ltd.	Theme Park at Thor, Near Ahmedabad		૯૦	N Gujarat	MOU
૧૩	Naimisha Group in association with EIH	Royal Orient and Trident Hillton		૧૬૪	Gandhinagar	Announcement
૧૪	Lake District Private Ltd.	Entertainment and Tourism Institute		૧૫	Kevadia	Announcement
	૧૪	**Total**		**૭૩૫૧.૫**		

Urban Development

Sr.	Name of the Company/Group	Type of Project	Location	Invest-ment in Rs. Crores	MOU / Announcement
૧	Sahara India Parivar	Sahara India City Home	Multiple	૭૨૧૬	MOU
૨	Delamore & Owl Group of Companies, UK	Development of Sabarmati River Front Ahmedabad	Ahmedabad	૪૦૦	MOU
૩	Ramky Infrastructure Co.Ltd., Hyderabad Kochar Transport Delhi	Public Transport in Ahmedabad ૧૨૦૦ CNG buses	Ahmedabad	૨૨૦	MOU
૪	ICICI Bank, Mumbai	Infrastructure Development Work in Ahmedabad	Ahmedabad	૪૦૦	MOU

Sr.	Name of the Company/Group	Type of Project	Location	Invest-ment in Rs. Crores	MOU / Announcement
૫	Ramky Infrastructure Co.Ltd., Hyderabad	Medical Education Institution in Nursing College, Ahmedabad	Ahmedabad	૧૫૫	MOU
૬	Ramky Infrastructure Co.Ltd., Hyderabad	Lake Development in Ahmedabad	Ahmedabad	૧૬	MOU
૭	Djai Power Delhi	Solid Waste Management in Ahmedabad Power Generations	Ahmedabad	૫૦	MOU
૮	IVRCL, Hyderabad	Water Treatment Plant at Raska and Kotarpur Weir, Ahmedabad	Ahmedabad	૫૩	MOU
૯	Karnavati Medical and Education Trust	Dendistry, Pharmaceutical Engineering and Management & Nursing School	Gandhinagar	૧૨૦	MOU
૧૦	Torrent Group	Sky Scraper Building	Gandhinagar	૧૦૦	Annoucement
૧૧	Bank of India	Heritage	Vadodara	૦.૨૫	Annoucement
૧૨	United Education Foundation, UK	International School , Gandhinagar	Gandhinagar	૭૦	MOU
૧૩	Abme NRG	Township nr. Adalaj	Adalaj	૩૦૦	MOU
	૧૩	**Total**		**૯૧૦૦.૨૫**	

Chemical					
Sr. No.	**Name of the Company/ Group**	**Type of Project**	**Location**	**Investment in Rs. Crores**	**MOU /Announce-ment**
૧	Archean Chemical Industries	Salt based chemical	Kutch	૩૯૦	MOU
૨	Atul Limited	Speciality chemical/power generation	Valsad	૨૦૦	MOU

૩	Godrej Industries Ltd	Fatty Alchohol	Bharuch	૪૫	MOU
૪	Gujarat Fluoro Chemicals Ltd	HFC refractories/chemcials	Bharuch	૨૫૦	MOU
૫	Gujarat Pharma Technoopark Ltd	Techno park	Ahmadabad	૩૦૦	MOU
૬	Heubac Colours	Organic/Inorganic pigments	Bharuch	૧૫૦	MOU
૭	Interpharma Inc	Pharmaceutical & R&D project	Ahmadabad	૩૦	MOU
૮	J K Papers Ltd	Duplex Board Chlorine Dioxide,	Surat	૨૫૦	MOU
૯	Sanghi Industries Ltd.	Projects of Cement,Poy, HDPE etc.	Kutch	૧૦૪૫	announce-ment*
૧૦	Syntex Industries Ltd.	Projetcs of Garments & made ups, Prefab. Building & Structures,Underground petroleum and water tanks,Plastic moulded products, captive power	Mehsana//Kutch	૬૦૦	MOU
૧૧	Torrent Pharmasueitical Ltd	a.Pharma-ceuitical Project-. B .R & D Centre	Chhatral Bhat-G'nagar	૨૦૦	MOU
૧૨	Resylene Neochem	Metal salts of tangsten	Baroda/Ahmedabad	૨૫	MOU
૧૩	Resylene Neochem	Molybdenum copper	Ahmedabad	૧૬૦	MOU
	૧૩	**Total**		**૩૬૪૫**	

Textile and Apparel

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project	Location	Investment in Rs. Crores	MOU /Announce -ment
૧	Apprel & Leather Technics P Ltd, (ALT) Banglore	To set up training institute in Gujarat for apprels		૫	MOU
૨	Jetpur Dyeing and priniting association, Jet pur	Mutual co-operation for setting up a high tech textile park near jetpur	Jetpur	૭૫	MOU
૩	Apprel Export promotion council (AEPC) New Delhi	Settin up of an apprel park and design centre	Surat/ Ahmedabad	૫	MOU
૪	Amadabad Power looms owners asociations	Mutual co-operation for setting up a high tech weaving park at Ahmadabad	Ahmadabad	૨૫	MOU
૫	Arvind Mills Ltd	Denim/Khakhis garments manufacturing plant (phase I & II)	Ahmadabad	૧૦૦	Annoucement
૬	Arvind Mills Ltd	Knitted garmenting plant	Ahmadabad	૧૮	Annoucement
૭	Arvind Mills Ltd	To set up textile park - Phase I & II	Khatraj	૨૦	Annoucement
૮	Arvind Mills Ltd	Knitted and woven fabric plant	Khatraj	૪૦	Annoucement
૯	India Industrial Garment Machines P Ltd	Training center for apprels	Surat	૫	MOU
૧૦	Safari Exports P Ltd	To set up an Export oriented Apprel manufacturing unit on land alloted by GIDC at Surat Apprel park	Surat	૧૨	MOU
	૧૦	**Total**		૩૦૫	

Gems & Jewellery

Sr. No.	Name of the Company/Group	Type of Project	Location	Investment in Rs. Crores	MOU /Announcement
૧	Charotar Vidya Mandal, CL Patel	Mutual Co-operation between Industry & academia			MOU
૨	Val Organics Ltd.	To set up	Sarigam	૨.૬	MOU

		manufacturing unit at Sarigam for chloro benzine			
૩	Atithi Gokul Pvt. Ltd. (Dinesh Bhai Bharward)	high tech textile park at Limdi	Limdi	૩૦	MOU
૪	Indocount Industries	Manufacturing unit for cotton & Synthetic fabrics	Sarigam	૧૫૦	MOU
૫	Shri Sunil Kr. Pathodia	manufacturing unit	Sarigam	૧૨૫	MOU
૬	Mc Leod Phramaceutical	Manufacturing unit	Sarigam	૪૦	MOU
૭	Nitex Chemicals I Ltd	manufactring unit	Sarigam	૮૦	MOU
	૭	Total		૪૨૭.૬	

Port

Sr. No.	Name of the Company/Group	Type of Project	Location	Invest-ment in Rs. Crores	MOU /Announcement
૧	Gulf-Omkar	Simar Port	Simar	૨૧૦૦	MOU
૨	Adani Exports/NG Group/Gulf Omkar/Balaji Infra/AVG Ship Yard	Maroli Port	Maroli-Umargaon	૬૦૦૦	Annoucement
૩	Gujarat Adani Port Ltd	Ship Engineering facilities-new port	Mundra	૧૮૦૦	Annoucement
૪	Hazira Port P Ltd (Shell)	Development of NON LNG cargo terminal	Hazira	૨૩૦૦	Annoucement
૫	Sanghi Industries Ltd /Shreeji Shipping/ABG Ship Yard/Mercator lines/Well Worth	Hazira Common user Jetty	Hazira	૧૦૦	Annoucement
૬	Shreeji Shipping Service	Strengthing of Sheet Pile Wharf	Okha	૫	MOU
૭	Sanghi Industries Ltd	Jajeshwar Jetty at Dahej	Dahej	૪૦	Annoucement
૮	Sanghi Industries Ltd	Navlakhi Jetty	Navlakhi	૪૦	Annoucement
૯	Shree Venkatesh Engg works	Out source service for oil reception facilities for Gulf of Kutch	Kutch	૩	MOU

૧૦	Arcadia Shipping	Rozi Pier Bedi old port	Bedi	૧૭	MOU
૧૧	Keyur Shipping	Sailing vessels port facility at Porbandar	Porbandar	૪	MOU
૧૨	Shrreji Shipping Services (I) Ltd/Jaisu Shipping	bedi-dry dock & ship way at bedi port	Bedi	૩	MOU
૧૩	Saurshtra Fuel P Ltd	Mundra (Old port) new jetty	Mundra	૩૫	MOU
૧૪	Essar Group	Expansion of existing captive jetty	Hazira	૧૦૦	MOU
૧૫	Saurshtra Fuel P Ltd	new jetty near Mandvi Port	Mandvi	૪૫	MOU
૧૬	Goodearth Maritime Ltd	development of port facilities ε Koteshwar	Kutch	૪૫	MOU
૧૭	Petronet LNG Ltd	Soild Cargo Terminal Dahej	Dahej	૩૦૦	MOU
૧૮	Gujarat Pipavav Port Ltd	Expansion of Pipavav Port	Pipavav	૧૦૦૦	MOU
૧૯	DMCC Oil Terminal Ltd	Development of multipurpose port terminal	Navlakhi	૬૦૦	MOU
૨૦	ABG Ship Yard	Ship Yard at Jageshwar Dahej/Hazira	Hazira	૪૦૦	MOU
૨૧	Welspun Gujarat Ltd	Expansion of port facilities at Old Dahej	Dahej	૧૫૦	MOU
૨૨	Ramci Enviro Eng Ltd	Hazardous Waste diposal facility	Alang	૫૫	MOU
૨૩	Ramci Infrastructure	Oil Reception Facilities at Alang	Alang	૧૬	MOU
૨૪	Seaspan Shipping Ltd	Cruise training ship	-	૭	MOU
૨૫	Project Consultancy group/Ouram Shipyard	Mechanised bulk handling system	Porbandar	૫	MOU
૨૬	Arcadia Shipping	Mechanisation of wharf	Bedi	૫	MOU
૨૭	Shree Venkatesh Engg works	Ship Building & Repairing	Sikka	૪	MOU
૨૮	Shreeji Shipping Service	Incomplete well foundation wharf	Navlakhi	૨	MOU
૨૯	Orum Ship Yard Ltd	Dry Dock & Slipwell	Porbandar	૨	MOU

૩૦	Orum Ship Yard Ltd/Jaisu	Dry Dock	Okha	૨	MOU
૩૧	Seaspan Shipping Ltd	Dry Dock repair/training	-	૨	MOU
૩૨	Hautchison Port Holding	Feasibility Study of Mahuva Port	Mahuva		MOU
૩૩	Daya Lubricants	Oil Reception Facilities	Alang	૬૮	MOU
૩૪	Gujarat Adani Port Ltd	Purhase of dredger	Mundra	૩૦	MOU
૩૫	Mercator Line Ltd	Vansi bori Port	Vansi bori	૩૦૦	MOU
	૩૫	**Total**		**૧૫૫૮૫**	

GIDB

Sr. No.	**Name of the Company/Group**	**Type of Project**	**Location**	**Invest-ment in Rs. Crores**	**MOU /Announcement**
૧	Ministry of Railways/Rail Vikash Nigam Ltd	Gauge conversion projects	Dahej-Bharuch	૧૬૦	MOU
૨	Ministry of Railways/Rail Vikash Nigam Ltd	Gauge conversion projects	Bhildi-Samdari	૩૦૦	MOU
૩	Ministry of Railways/Rail Vikash Nigam Ltd	Gauge conversion projects (includes ૧૮-૨૦ km of new link)	Hazira Port link	૧૪૦	MOU
૪	Patel & Kothari Inudtrial Park P Ltd	Industrial Park	Vadodara-jambua	૧૧.૬	MOU
	૪	Total		૬૧૧.૬	

Engineering and Automible Industry

Sr. No	**Name of the Company/Group**	**Type of Project**	**Location**	**Investment in Rs. Crs.**	**MOU /Announce -ment**
૧	Essar Steel Ltd	Steel Expansion phase I-II Project//bypass road	Hazira	૫૧૬૫	announcement
૨	Ajanta Manufaturing Ltd	Ceramic products/clocks	Kutch	૪૦૦	MOU

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project	Location	Investment in Rs. Crs.	MOU /Announce-ment
૩	Videocon International Ltd.	Consumer white goods/Glass shells	Kutch/Bharuch	૧૬૩૦	announcement
૪	S.A.L. Steel Ltd.	Steel Project	Kutch	૨૦૦૦	announcement
૫	Suzlon Group Industries	Engg Products and R & D center	Baroda	૧૨૦	announcement
૬	Kalpataru Power Transmission Ltd.	Transmission towers	Elec.GIDC G'ngr	૩૫	MOU
૭	KHS Machinaries P Ltd	Industrial Machinaries	Ahmadabad	૧૦૦	MOU
૮	Global Hightech	sponge iron Steel ingot/ Captive power plant/fero allyos	Kutch	૩૩૦	MOU
૯	Electrotherm (I) Ltd	Pig Iron/Pipes/Alloy Steel	Kutch	૯૨	MOU
૧૦	MID India Eng Ltd	Sponge iron/steel/alloy steel/SS	Kutch	૨૦૦	MOU
૧૧	Ratnamani Metals & Tube Ltd	CS /SS Pipes/ERW/SAW Pipes	Kutch/Chhatral	૧૨૭	MOU
૧૨	AIA Eng P Ltd	Steel Casting/Grinding Mac/Captive Power	Ahmadabad/Dahej/ Vilayat	૧૦૦	MOU
૧૩	Welspun Gujarat Stahel Rohen ltd.	Steel plate mill	Kutch	૧૨૫૦	announce-ment
૧૪	Asia Motors Works Ltd	Heavy Vehicles/Cars	Kutch	૨૦૦૦	MOU
૧૫	Kutch Steel P Ltd	Steel Plant with Sponge iron	Kutch	૧૦૦	announce-ment
૧૬	Echjay Industries P Ltd	Blast furnace for Steel	Rajkot	૧૫૦	MOU
૧૭	Gujarat Borosil Ltd.	Float Glass	Govali Dist. Bharuch	૨૦૦	MOU
૧૮	Anchor Daewoo Industries Ltd.	FMCG Division & Electricals Division	Paddhar & Lakhond, Kutch	૧૦૦	MOU
૧૯	PSL Ltd.	Steel Pipes	Kutch, Pipavav	૨૫૦	MOU
૨૦	Aroma High Tech Ltd.	Submersible	Vill.	૧૦૦	MOU

Sr. No	Name of the Company/Group	Type of Project	Location	Investment in Rs. Crs.	MOU /Announce -ment
		Pumps, Motors, Winding Wire, Copper Rods, etc.	Lakadia, Kutch		
૨૧	Torrent Cable Ltd	Cable manufacturing facilities	Nadiad	૧૦	announce-ment
૨૨	Ashapura Minchem Ltd.	Expansion of bleaching clay project, geo-synthetic clay liners	Bhuj	૪૦	MOU
૨૩	L & T Ltd.	Hazira unit expansion, Engg Resource park	Hazira, Surat, Baroda	૩૦૦	announce-ment
૨૪	General Motors Pvt. Ltd.	Expansion of Automobile plant	Halol	૩૦૦	announce-ment
૨૫	Mann Industries India Ltd.	ERW Pipe	Kutch	૧૫૦	MOU
૨૬	Gopal Iron & Steel	Sponge Iron	Bhachau	૩૬	MOU
૨૭	Suzlon Industries Ltd.		Kutch	૧૬૫	announce-ment
૨૮	Akash Ceramic Pvt. Ltd.	Vitrified tiles	Mansa	૨૦	MOU
૨૯	Birla Cellolose	Viscous stable fibre	Bharuch	૩૦૦	MOU
૩૦	Swami Multi Industries Coop Ltd.	Textile park	Surat	૫૦૦	MOU
૩૧	Santaram Spinners	Integrated Textile unit		૮૧	MOU
૩૨	Vinod Fabric Pvt. Ltd.	Denim & other textile projects	Ahmedabad	૧૦૦	MOU
	૩૨	**Total**		**૧૬૪૫૧**	

શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે એમ.ઓ.યુ. થયા પછી ખરેખર કેટલું મૂડી રોકાણ આવ્યું?

શ્રી અનિલભાઇ ત્રિ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વાયબ્રન્ટ ગુજરાત, ૨૦૦૫ એ ત્રણ કાર્યક્રમોના એક સંમલિત કાર્યક્રમ હતો અને એ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે રાજયના ઔદ્યોગિક વિકાસ દ્વારા રાજયને સમગ્ર વિશ્વના નકશા ઉપર મૂકી શકાય એના માટેનો આ કાર્યક્રમ હતો અને આ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે ૨૨૬ (અંતરાય) ૧,૦૬,૦૦૦ કરોડના મૂડી રોકાણોની દરખાસ્તો રાજય સરકારને મળી છે (અંતરાય) હું આપના પ્રશ્નનો (અંતરાય) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના આદરણીય સભ્યોને માહિતી હશે કે ઉદ્યોગ સ્થાપવા અને ઉદ્યોગોની મૂડી રોકાણ કરવાની પ્રક્રિયા એ સમય માગી લેતી પ્રક્રિયા હોય છે. રાતોરાત ઊંઘમાંથી ઊઠીને ઊભા થઈએ એટલે મૂડી રોકાણ થઈ જાય? જયારે આપણો કાર્યક્રમ જાન્યુઆરીમાં કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે ફેબ્રુઆરીમાં એના આંકડા પૂછીએ કે કેટલું મૂડી રોકાણ આવ્યું? તો એ કેટલું યોગ્ય ગણાય? આવતા વર્ષે આ સમયે માનનીય ધારાસભ્યશ્રી પૂછે તો એનો જવાબ યોગ્ય રીતે આપી શકાશે.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફત માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે વાયબ્રન્ટ ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ, ૨૦૦૫ અંર્તગત ગઈ વખતે જેમ ૬૬૦૦૦ કરોડના એમ.ઓ.યુ. થયા હતા એમ આ વખતે ૧,૦૬,૦૦૦ કરોડના એમ.ઓ.યુ. થયા છે તો આ એમ.ઓ.યુ. માટે પહેલાં તો અભિનંદન, પરંતુ ગઈ વખતે જેમ વિદેશથી માત્ર ૧૧૦૦૦ કરોડનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યું તેમ આ વખતે આવશે? ૧૧૦૦૦

કરોડ રૂપિયા ખાલી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યું હતું, એ રીતે હકીકતમાં આ વર્ષે કેટલું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ આવવાનું છે જેનાથી ગુજરાત વાયબ્રન્ટ થશે?

શ્રી અનિલભાઇ ત્રિ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વાયબ્રન્ટ ગુજરાત, ૨૦૦૫ ઉપક્રમે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે સાથે પ્રવાસી ગુજરાતીઓ જે ગુજરાતની બહાર અને વિશ્વમાં પથરાયેલાં છે એમનો ગુજરાતી પ્રવાસી દિવસ તરીકે આપણે આપણા આંગણે આ રાજ્યના સપુતોને બોલાવીએ. આ ગુજરાત જે દિશામાં પ્રગતિ કરી રહ્યો છે એ પ્રગતિની જાણકારી આપવાનો પ્રયત્ન આપણે સેમિનાર મારફત આપણે પ્રદર્શનોના માધ્યમ મારફતે યોજીને એ કાર્યક્રમોના ભાગરૂપે એ એન.આર.આઈ.એ અને ફોરેન ડાયરેકટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટોએ જે દરખાસ્તો કરી છે જેની આજે શરૂઆત છે અને એમાં ૪૦ પ્રોજેકટો મારફતે ૯૩૭૧ કરોડ રૂપિયાનું મૂડી રોકાણ કરવા માટેની દરખાસ્તો એન.આર.આઈ. અને ફોરેન ડાયરેકટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ માટેની કરવામાં આવી છે અને આ પ્રકારના કાર્યક્રમો મારફતે જે કામગીરી થતી હોય છે, આ રાજયની શકિત અને આ રાજયની પ્રજાની જે ઔદ્યોગિક શકિત છે એ શકિતને વિશ્વભરના લોકો સમક્ષ મૂકવાનો આ ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સમિત અને વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫ના કાર્યક્રમો મારફતે ગુજરાતની પ્રજાની શકિતની ઓળખ વિશ્વના મૂડી રોકાણકારોને કરાવવા આની પાછળના આશયો હતા.

શ્રી સી. જે. ચાવડા : વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૩માં ૬૬,૦૦૦ કરોડનું રોકાણ અને આ વખતે એક લાખ ૬ હજાર કરોડનું રોકાણ એવા એમ.ઓ.યુ. થયા છે, પેલા એમ.ઓ.યુ. અને આ એમ.ઓ.યુ. જુદા છે? અને પહેલાં ૬૬૦૦૦ કરોડના એમ.ઓ.યુ. થયા એમાંથી કેટલું મૂડી રોકાણ થયું?

શ્રી અનિલભાઇ ત્રિ. પટેલ : કોઈપણ મૂડી રોકાણ બે અલગ કાર્યક્રમો હોય ત્યારે એના અલગ જ હોય એમાં કોઈ કોમન મૂડી રોકાણનો કે એમ.ઓ.યુ.નો સામાન્ય ભાગ હોઈ શકે જ નહીં એટલે જે ૬૬,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના જે મૂડી રોકાણો અગાઉ ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટ સમિત-૨૦૦૩માં આવ્યા હતા અને ૧ લાખ ૬ હજાર કરોડ રૂપિયાની જે દરખાસ્તો આવી છે એ કાર્યક્રમની પછી આપણે જિલ્લાવાર આ એમ.ઓ.યુ. માટે જે કોઈને હજુ પણ ઈચ્છા હોય આ કાર્યક્રમ પછી એની પણ વિગતો આ બંને બધા અલગ જ હતા અને ૧૧,૭૫૯ કરોડ રૂપિયાના, ૧ લાખ ૬ હજાર પછી જિલ્લાવાર જે ગોળમેજી પરિષદ કરવામાં આવી એમાં જે ઉદ્યોગકારોએ ઉત્સાહ બતાવ્યો એના કારણે જિલ્લાવાર પણ મારી પાસે આંકડા છે, ૧૧,૬૫૯ કરોડ રૂપિયાના મૂડી રોકાણો એમાં આવેલા છે, જે હું આપને બધી જ વિગતો આપું છું, બધી જ વિગતો હું પૂરી પાડું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : એમને સંતોષ છે. નેકસ્ટ પ્રશ્ન ક્રમાંક-૧૪.

બંદર વિકાસ નીતિ અન્વયે બંદરો વિકસાવવાનું આયોજન

***૮૨૪૫ શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ(ઉના) :** માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

(૧) રાજયમાં બંદર વિકાસ નીતિ અન્વયે ખાનગી અને સરકારી ધોરણે કેટલા બંદરો વિકસાવવાનું આયોજન છે,
(૨) તે પૈકી કયા કયા બંદરોનો કયા કયા હેતૂ માટે વિકસાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો, અને
(૩) આ બંદરોના વિકાસની કાર્યવાહી તા.૧-૧-૦૫ ની સ્થિતિએ કયા તબકકે છે?

મુખ્યમંત્રીશ્રી (બંદરો) :

(૧) રાજય સરકારશ્રી ધ્વારા જાહેર થયેલા ડિસેમ્બર-૧૯૯૫ની બંદર નીતિ અન્વયે ૬ (છ) બંદરો સંપૂર્ણ ખાનગી મૂડી રોકાણથી અને ૪(ચાર) બંદરો સંયુકત સાહસમાં વિકસાવવા આયોજન છે.
(૨) બંદર નીતિમાં નીચે મુજબના હેતૂ માટે બંદર વિકસાવવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

-સંયુકત સાહસમાં વિકસાવવામાં આવનાર બંદરો

૧). મુન્દ્રા-જનરલ કાર્ગો બંદર
૨). દહેજ-ઔદ્યોગિક બંદર તથા એલ.એન.જી.
૩). પોસીત્રા- કન્ટેનર તથા પેટ્રોલીયમ બંદર
૪). રોઝી (બેડી)-એગ્રીકલ્ચર બંદર

-ખાનગી મૂડીરોકાણથી વિકસાવવામાં આવનાર બંદરો

૧). હજીરા-ઔદ્યોગિક બંદર તથા એલ.એન.જી.
૨). ધોલેરા-જનરલ કાર્ગો પોર્ટ
૩). મરોલી ઔદ્યોગિક પોર્ટ
૪). સીમર-પાવર પોર્ટ
૫). મીઠીવીરડી-સ્ટીલ તથા ઓટોમોબાઈલ પોર્ટ

૬). વાંસી-બોરસી-પેટ્રોલીયમ અને કેમીકલ પોર્ટ

(૩)આ બંદરોના વિકાસની કાર્યવાહી તા.૧-૧-૦૫ની સ્થિતિએ કયા તબકકે છે.

-સંયુકત સાહસમાં વિકસાવવામાં આવનાર બંદરો

૧). મુન્દ્રા-બંદર કાર્યરત થયેલ છે.

૨). દહેજ-એલ.એન.જી. ટર્મીનલ અને કેમીકલ ટર્મીનલ કાર્યરત થયેલ છે.

૩). પોસીત્રા-જમીન સંપાદન તથા પર્યાવરણ અંગેની મંજૂરી મેળવવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે.

૪). રોઝી(બેડી)- એક ખાનગી કંપની ધ્વારા બાયબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫ દરમિયાન ઓફર રજૂ થયેલ છે.

-ખાનગી મૂડી રોકાણથી વિકસવવામાં આવનાર બંદરો

૧). હજીરા-એલ.એન.જી. ટર્મીનલનું બાંધકામ પૂર્ણ થવામાં છે.

૨). ધોલેરા- પર્યાવરણ અંગેની મંજૂરી મેળવવાની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે.

૩). મરોલી, સીમર,મીઠીવીરડી અને વાંસી-બોરસી બંદર સ્થળના વિકાસ માટે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫ દરમિયાન ખાનગી કંપનીઓ ધ્વારા ઓફરો રજૂ થયેલ છે.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ મારા જવાબમાં જણાવ્યું છે એમાં ખાનગી મૂડી રોકાણથી વિકસાવવામાં આવનાર બંદરોની સંખ્યા છ બતાવવામાં આવી છે. તો આ ખાનગી મૂડી રોકાણથી બંદરોને વિકસાવવાનો નિર્ણય પ્રથમ વખત કયારે કરવામાં આવ્યો? બીજો સવાલ એ છે કે સીમર છે એને મારા વિસ્તારના પાવર પોર્ટ માટે ખાનગી રીતે વિકસાવવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે. તો છેલ્લે આ પાવર પોર્ટ બંદરને વિકસાવવા માટે કઈ કંપની મારફતે સરવે કરવામાં આવેલ છે કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજય સરકારે ૧૯૯૫માં બંદર નીતિ જાહેર કરી અને બંદર નીતિ જાહેર કર્યા પછી દસ જેટલા બંદરોને સંયુકત સાહસ અને ખાનગી સાહસ તરીકે વિકસાવવાનો નિર્ણય કર્યો અને તબકકાવાર બધી જ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ચાર બંદરોને સંયુકત સાહસમાં અને છ બંદરોને ખાનગી મૂડી રોકાણથી વિકસાવવાના છે. બીજા કયા બંદર માટે તમે પૂછયું?

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : સીમરનું, એનો કઈ કંપની મારફતે સરવે કરવામાં આવ્યો, એનો પ્રિ-ફિઝિબલી રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે કે કેમ ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : જે છ બંદરો છે એમાં મરોલી છે....

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : પ્રશ્નના જવાબમાં ચાર નંબર ઉપર જે જણાવવામાં આવ્યું છે કે સીમર....

અધ્યક્ષશ્રી : ખાનગી મૂડી રોકાણમાં સીમર.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : પ્રશ્નના જવાબમાં જે ક્રમ નંબર-ચાર ઉપર બતાવવામાં આવેલ છે.

અધ્યક્ષશ્રી : એમને જોવા દો, ખાનગી મૂડીરોકાણમાં ક્રમ-૪.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : મે. રીન્ડોલ, પોમર એન્ડ ટીટ્રોન કંપની દ્વારા વિકસાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : મેં પૂછયું કે એમનો પ્રિફિઝિબિલિટી રિપોર્ટ છે એટલે કોઈ કંપની મારફત સર્વે કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? હા કે ના?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : આ બધા બંદરોનો તજજ્ઞોનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. કહેતા હોય તો બધા વાંચી જઉં. રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

ડૉ. દિનેશ પરમાર : સરકારશ્રીએ બંદરોના વિકાસની નીતિ માટે કામકાજ ઉપાડયું છે. જામનગરના રોજી બંદર અને બેડી વિસ્તારમાં સરકારનો એગ્રીકલ્ચર ડૅવલપમેન્ટ પ્લાન છે. ૨૦ જેટલા બાર્ઝ ડૂબી ગયા છે અને સોયાબીનની ચોરી થાય છે એટલે બંદર અસલામત છે તો સરકાર કોઈ કાર્યવાહી કરવા માગે છે કે કેમ? પોસીત્રા બંદર અગાઉ ડેવલપ કરવા સર્વે થઈ ગયો, જમીન ખરીદાઈ પણ સરકારની બેદરકારીને લીધે આખો પ્રોજેકટ મહારાષ્ટ્રમાં જતો રહ્યો. તો પોસીત્રા બંદર ડેવલપ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે ત્યારે અગાઉ થયું હતું તેનું પુનરાવર્તન તો નહીં થાય ને તેની ખાતરી આપે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : રાજયમાં ૪૦ જેટલાં બંદરો આવેલાં છે. એ ૪૦ બંદરો વિકસાવવાની કાર્યવાહી જુદાજુદા તબક્કે ચાલુ જ છે. (અંતરાય) સાંભળો તો ખરા,

ડૉ. દિનેશ પરમાર : જવાબ બરાબર મળતો નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : તમને ઇચ્છા હોય તેવો જવાબ ન મળે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : તમારા પ્રશ્નમાં છે એ પ્રકારની કોઈ ઈલિગલી કાર્યવાહી ચાલતી હશે તો ચોક્કસ પગલાં ભરવામાં આવશે. આવી કોઈ બાબત તમે ધ્યાન ઉપર મૂકી હોય તેવું મારા ધ્યાનમાં આવ્યું

નથી. પોસીત્રાના દસે દસ બંદરો અને અન્ય ત્રીસ બંદરો રાજય સરકાર વિકસાવવા માગે છે અને ખૂબ સારી દરખાસ્તો બધા માટે પ્રાપ્ત થઈ રહી છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં ડીટેઈન કરેલા વાહનો અને દંડ

***૮૩૭૯ શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ. સોલંકી(ઘોઘા) :** માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-
(૧) ભાવનગર જિલ્લામાં છકડા-ટેમ્પોને ખોટી રીતે ડીટેઈન કરવામાં આવે છે તે વાત સાચી છે,
(૨) ૨૦૦૪ના કેલેન્ડર વર્ષમાં ભાવનગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આવ્યા અને
(૩) ડીટેઈન થયેલા વાહનો માટે દંડની શું જોગવાઈ છે?

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) :
(૧) ના, જી.
(૨)

તાલુકાનું નામ	ડીટેઈન કરેલા વાહનોની સંખ્યા	તાલુકાનું નામ	ડીટેઈન કરેલા વાહનોની સંખ્યા
ભાવનગર	૧૭૭	ગઢડા	૦૨૦
ઘોઘા	૦૩૪	બોટાદ	૦૭૧
તળાજા	૧૩૫	વલ્લભીપુર	૦૦૨
મહુવા	૨૨૧	ઉમરાળા	૦૦૬
ગારીયાધાર	૯૩૬	શિહોર	૦૨૧
પાલીતાણા	૦૭૮		
		કુલ:	૮૨૩

(૩) ડીટેઈન થયેલા વાહનો માટે દંડ અંગેની કાર્યવાહી મુંબઈ મોટર વાહન વેરા અધિનિયમ, ૧૯૫૮ હેઠળ વાહનોના બાકી નીકળતા વેરા માટે કલમ-૧૨(એ) અને ૧૨(બી) મુજબ વાહનની અટકાયત કરવામાં આવેલ હોય તો, જ્યાં સુધી આવી બાકી નીકળતી ટેક્સની રકમ વાહન માલિક ભરપાઈ કરે નહિ ત્યાં સુધી વાહન મુક્ત કરવાપાત્ર થતું નથી.

શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ. સોલંકી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના દ્વારા હું જાણવા માગું છું કે ભાવનગર જિલ્લામાં ટેમ્પો અને બીજા વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષમાં ઘણા ટેમ્પો અને વાહનો જે ડીટેઈન કરવામાં આવ્યા છે તે અતિશય, લિમિટ બહાર અને જે પોલીસની તાનાશાહી કહેવાય અને પોલીસે અતિશય જે રીતે ૧૫૦૦૦ દંડ અને ૮૫ માણસોને પકડયા અને આ રીતે એસ.પી. અને એમના માણસો ખુલ્લેઆમ દાદાગીરી અને.....

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્ન ઉપર આવો.

શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ. સોલંકી : એ માટે વાહન વ્યવહાર મંત્રીશ્રી અને ગૃહ મંત્રીશ્રીને મારી નમ્ર અપીલ છે કે આના માટે તમે શું પગલાં લેવા માગો છો અને આ ખાસ કરીને મારા વિસ્તારને ટારગેટ બનાવ્યું તો એની સામે શું પગલાં લેવા માગે છે? આ અધિકારી સામે પગલાં લેશે એવી નમ્ર અપીલ કરું છું.(અંતરાય)

શ્રી અમિત અ. શાહ : સૂચનાત્મક પ્રકારનો પ્રશ્ન છ (અંતરાય) પરેશભાઈ, તમે પ્રશ્ન પૂછોને, તમને પ્રશ્ન પૂછવાની છૂટ છે, આમ તો સૂચનાત્મક પ્રકારનો પ્રશ્ન છે. આમા સ્પષ્ટતા કરી લઉં. (અંતરાય) ધારાસભ્યશ્રી પોતે પ્રશ્ન ન પૂછે અને બીજાના પ્રશ્નમાં હોબાળો કર્યા કરે તે કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? પોતે પ્રશ્ન પૂછતા નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો જવાબ સાંભળે એવી વ્યવસ્થા કરી આપો. આ રીતે દર વખતે ઉભા થવું જરૂરી નથી. હું સહેજ સ્પષ્ટતા એટલા માટે કરી દઉં કે બહુ મોટી ગેરસમજ સમગ્ર રાજયની અંદર પ્રસરી રહી છે. વર્ષોથી ૨૦૦૩ સુધી આ છકડાને વાહન વ્યવહારના વાહન તરીકે કોઈ સ્વીકારતું નહોતું. આ મિત્રો સત્તા ઉપર હતા ત્યારે છકડા ચાલતા હતા. અમારી રાજય સરકારે ૨૦૦૩ ની અંદર છકડાની અંદર અમુક છૂટછાટ મૂકી. ફેરવવા માટે અધિકૃત કરી આપ્યા. એ પહેલાં આખા રાજયમાં કોઈપણ રીતે છકડા ફેરવવા માટે મંજૂરી નહોતી અને હજે ૨૦૦૩ માં અધિકૃત કરી આપ્યા. હવે પ્રશ્ન એટલો છે કે છકડા બે પ્રકારના છે , ગુડઝ લઈ જવાવાળો છકડો અને બીજો જેની પેસેન્જર બોડી બાંધેલ હોય તેવો છકડો. ગુડઝ લઈ જવાવાળા ૨૫-૨૫ માણસો બેસાડી હાઈવે ઉપર લઈ જતા હોય અને અકસ્માત થાય પછી લોકો મરે એના

માટે તંત્ર એટલો આગ્રહ રાખે કે માપના માણસો બેસાડે. પાંચ-છ બેસાડે. બોડી બાંધેલ છકડાની પરમિશન લઈ લે. માત્ર એનો અમલ કરાવવા માટે છકડા પકડવામાં આવતા હોય તેને પોલિટિકલ ઈસ્યુ ન બનાવવો જોઈએ. આ તો ઉતારુઓની સલામતી માટે લેવાયેલ પગલું છે. બોડી બાંધવી એ તો સલામતી માટે છે. એમાં રાજય સરકારનું હિત નથી. તમે બધા વિરોધપક્ષની પાટલી ઉપરથી હોબાળો કરો છો, પણ તમે જયારે સત્તા ઉપર હતા ત્યારે એકપણ ઉતારુને બેસાડવાની પરમિશન નહોતી આપી. અમે છ-સાત ની આપી છે. એ વખતે એકેય નહોતી આપી.

શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ. સોલંકી : મારે એટલું જ કહેવું છે કે ગાંધીનગર આપણું કેપિટલ છે. હાઈવે ઉપર જે જીપો ફરે છે, એ આર.ટી.ઓને નથી દેખાતું? અમારા છેક છેવાડાના વિસ્તારની અંદર આર.ટી.ઓ. ૧૫-૧૫ હજાર દંડ કરે. અહીયાં કાયદો નથી દેખાતો અને ત્યાં કાયદો દેખાય છે? ન્યાય કરો એવી હોમ મિનિસ્ટરને મારી અપીલ છે. ૧૫-૧૫ હજાર રૂપિયા દંડ કરે તો ગરીબો કયાંથી કાઢી શકે? આ તો અન્યાય છે. ન્યાય કરો. એસ.પી. ને કહો કે ગરીબોની બદદુઆ લેવાનું બંધ કરે.

શ્રી અમિત અ. શાહ : ૧૫-૧૫ હજાર દંડની વાત કરો છો તેમાં સહેજ ગેરસમજ છે. દંડ નથી. તેમાં જૂનો ટેકસ બાકી હોય તે અને દંડની રકમ મળીને એ રકમ થતી હોય છે. જૂનો ટેકસ વાહન પકડાય ત્યારે ભરવામાં આવતો હોય છે.

વઘઈ ખાતે આવેલ આર.ટી.ઓ. ચેકપોસ્ટમાં થયેલી આવક

***૮૯૧૮ શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે(ડાંગ-વાંસદા)** : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે :

(૧) સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ અને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ ના નાણાકીય વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં ડાંગ જિલ્લાના વઘઈ ખાતે આવેલ આર.ટી.ઓ. ચેક પોસ્ટમાં કેટલી આવક થઈ અને

(૨) આ ચેકપોસ્ટ ઓફિસ માટે બિલ્ડિંગ બનાવવા રાજય સરકારે જોગવાઈ કરી છે કે કેમ?

મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) :

(૧) આર.ટી.ઓ. ચેકપોસ્ટ વઘઈ ખાતે સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ ના વર્ષમાં રૂપિયા ૧,૫૮,૯૨,૩૩૮/- અને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ ના નાણાકીય વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં રૂપિયા ૧,૦૯,૨૯,૪૯૩/-ની આવક થયેલ છે.

(૨) વઘઈ ચેકપોસ્ટના મકાન બાંધકામ માટેના નકશા અને અંદાજો મંજૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે, આથી હાલ નાણાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવેલ નથી.

શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ જે જવાબ આપ્યો છે કે વઘઈની અંદર આર.ટી.ઓ.ચેકપોસ્ટ ઑફિસ લાખો રૂપિયાની આવક ધરાવે છે. મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને કહેવું છે કે ત્યાં વઘઈની અંદર આર.ટી.ઓ.ને રહેવાની કે આર.ટી.ઓ. ઑફિસની સુવિદ્યા નથી. જયારે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે કે આ બાબતના નકશા અને પ્લાન માટે નાણાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં આવી ચેકપોસ્ટો ઉપર લાખો રૂપિયાની આવક આવે છે અને એટલું જ નહીં ત્યાં ઓવર લોડ કરીને લાખો રૂપિયા લૂંટાય છે. તો આ બાબતમાં માનનીય મંત્રીશ્રી શું કરવા માગે છે તે જણાવે અને બીજી વાત કે ચેકપોસ્ટ માટે તાત્કાલિક સુવિદ્યા કરવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ખાલી વઘઈ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતની ચેકપોસ્ટો માટે આ પ્રકારની સુવિદ્યાઓ જયાં બાકી છે ત્યાં કરવા માગીએ છીએ. આવતા વર્ષમાં કરવાનો હમણાં રાજય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે ત્યારે જે નાના મોટા પ્રશ્નો હતા તેમાં રહેઠાણ અને ઑફિસ તથા બધાને ગાડીઓ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેમાં વઘઈ ચેકપોસ્ટને આવરી લેવામાં આવી છે. નકશા અને અંદાજો બનાવવાની કામગીરી ચાલુ છે તે પૂરી થતાં તુરતજ કામ હાથ ઉપર લેવાના જ હતા.

શ્રી પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય પરસોત્તમભાઈનો પ્રશ્ન ભાવનગર જિલ્લાના એસ.પી. (અંતરાય)

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વઘઈનો પ્રશ્ન છે.

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રવિણભાઈ, પ્રશ્ન ઉપર આવો.

શ્રી સુનીલ બા. ઓઝા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આર.ટી.ઓ.નો સવાલ છે. આ ચેકપોસ્ટો ભૂતકાળમાં પણ ખૂબ જ અગત્યની રહી છે અને અત્યારે પણ છે. મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એટલું જાણવું છે કે, ૨૦૦૧-૦૨, ૨૦૦૨-૦૩, ૨૦૦૩-૦૪ માં આ રાજયની ચેકપોસ્ટોની કુલ આવક વર્ષ વાઈઝ કેટલી થઈ હતી?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સુનિલભાઈએ જે વાત કરી તે ખૂબ જ સાચી છે. આર.ટી.ઓ.ની. ચેકપોસ્ટની આવક તે રાજયની રેવન્યુની અંદર આવકનો એક મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. મને

આ ગૃહને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે આ રાજયમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવી ત્યારે ૪૦ કરોડ રૂપિયાની ચેકપોસ્ટની આવક હતી. તે વધીને ૨૦૦૩માં ૯૩૫ કરોડ રૂપિયાની થઈ છે. ૪૦ કરોડથી વધીને ૯૩૫ કરોડ રૂપિયાની થઈ છે. સાંભળો, સાંભળો, આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં આવક આટલા કરોડે પહોંચાડી છે. સુનિલભાઈએ પ્રશ્ન પૂછયો છે તેનો જવાબ આપું છું. ૨૦૦૧-૦૨ માં ૬૮૬.૪૮ કરોડ, ૨૦૦૨-૦૩ માં ૮૦૧.૬૧ કરોડ થઈ હતી.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પ્રશ્નનો ભાગ છે? આપે પ્રવિણભાઈને....

અધ્યક્ષશ્રી : પેટા પ્રશ્નમાં આવે છે. સુનિલભાઈના પેટા પ્રશ્નમાં આવ્યું છે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પ્રશ્નનો ભાગ છે?

અધ્યક્ષશ્રી : પેટા પ્રશ્નમાં આવ્યું છે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એ જાણવું છે કે દરેક જિલ્લાને તમે ટારગેટ આપ્યા છે અને તેમાં કેટલાક કેસોમાં બળજબરી કરીને ઉઘરાણું કરવામાં આવે છે. કાયદેસરના વાહનો ચાલતા હોય છે તેઓની પાસે બળજબરીથી પહોંચ આપી ટાર્ગેટ પૂરા કરવામાં આવે છે આ વાત સાચી છે?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ ઔચિત્યભંગ કર્યો છે. એક પ્રશ્ન ચાલુ હતો અને બીજો પ્રશ્ન પૂછયો છે. તેમ છતાં વિરોધપક્ષના નેતા છે એટલે હું તો શું શિખામણ આપું. પહેલાં હું સુનિલભાઈના પ્રશ્નનો જવાબ આપું પછી તેના પ્રશ્નનો જવાબ આપીશ. (અંતરાય) પબ્લિકે શિખામણ આપી દીધી છે. તમે છોડો, એટલે તો અહીં બેઠા છો પ્રજાએ શિખામણ આપી છે. સુનિલભાઈના પ્રશ્નનો સવાલ છે ત્યાં સુધી ૨૦૦૧-૦૨ માં ૬૮૬.૪૮ કરોડ, ૨૦૦૨-૦૩ માં ૮૦૧.૬૧ કરોડ, ૨૦૦૩-૦૪ માં ૯૩૫.૩૬ કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ છે. ૨૦૦૪-૦૫ ની અંદર ડિસેમ્બર સુધીની આવક ૮૬૦.૦૭ કરોડ રૂપિયાની થઈ છે. સતત તેમાં ૧૭ અને ૧૮ ટકાનો વધારો થયો છે. હવે હું માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાના પ્રશ્નનો જવાબ આપીશ. અમે તો ટારગેટ આપ્યા છે. સાંભળો, તમારા નેતાના પ્રશ્નનો જવાબ આપું છું. સાંભળો અમે લક્ષ્યાંક આવક વધારવાના આપ્યા છે. રાજયની આવક વધારવામાં સરકાર કશુ ખોટું માનતી નથી. મને ખબર છે જયારે તમે સત્તા ઉપર હતા ત્યારે શેના લક્ષ્યાંકો આપતા હતા. અમે તો ઑફિશ્યલ પહોંચ ફાડી સરકારમાં જમા કરાવવાના લક્ષ્યાંક આપ્યા છે. જે દંડ લેવાય છે તેની પહોંચ ફાડી જમા થાય છે અને સરકારના ચોપડે આવે છે એટલે તો ૪૦ કરોડ થી વધારીને ૮૬૦ કરોડે પહોચ્યા છીએ. પહેલાં શેના લક્ષ્યાંક આપતા હતા તેનું અર્જુનભાઈ પોતે આત્મચિંતન કરે.

શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ કહયું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આવક વધારી છે. મારે એ જાણવું છે કે આ જે જે ચેકપોસ્ટો છે અને બાઉન્ડ્રી ઉપર છે ત્યાં કરોડો રૂપિયાની કરચોરી થાય છે.

અધ્યક્ષશ્રી :પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પૂરો થાય છે. નેકસ્ટ.

અતારાંકિત પ્રશ્નો
(તારાંકિત પ્રશ્નોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ)

મોરબી સિરામીક ઉદ્યોગ વિસ્તારમાં લૅબૉરૅટરી ઊભી કરવા અંગે

૮૦૯૧**શ્રી મોહનભાઈ ક. કુંડારીયા(ટંકારા) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ખાણ અને ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**

(૧) મોરબી સિરામિક ઉદ્યોગ વિસ્તારમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેબોરેટરી ઊભી કરવાનું આયોજન છે કે કેમ, (૨) જો હા, તો ક્યારે મંજૂરી આપવામાં આવી, અને (૩) આ કામ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે?	(૧), (૨) અને (૩) કલ્સ્ટર વિકાસના કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે મોરબી, વાંકાનેર, સિરામીક એસોશીએશન દ્વારા કોમન ફેસીલીટી સેન્ટર તેમજ સંશોધન, વિકાસ અને ટેસ્ટીંગ સેન્ટર શરૂ કરી શકાય તે માટે એસોશીએશનને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. એસોશીએશન આ માટે દરખાસ્ત તૈયાર કરી રાજ્ય સરકારને મોકલે તો કલ્સ્ટર વિકાસ યોજના હેઠળ લાભ આપી લેબોરેટરીની સ્થાપના માટે વિચારી શકાશે.

રાજ્યમાં પાઈપલાઈન મારફતે ગેસ પૂરો પાડવા સંબંધમાં પગલાં બાબત

૯૧૯૦ **શ્રી દિપસિંહ શં. રાઠોડ(પ્રાંતિજ)** : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (પેટ્રોકેમિકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) જાન્યુઆરી, ૨૦૦૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં પાઈપલાઈન મારફત વિવિધ ક્ષેત્રોને ગેસ પૂરો પાડવા સંબંધમાં શાં પગલાં લેવાયેલ છે,	(૧) રાજય સરકારે ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિ. (જી.એસ.પી. એલ.) મારફત રાજયના સુરત જિલ્લાના હજીરાથી ગાંધીનગર જીલ્લાના કલોલ સુધીની ગેસ પરિવહન માટેની ૪૩૦ કિ.મી. લાંબી પાઈપલાઈન નાંખી છે. આ રૂટમાં આવતા હજીરા, મોરા, ઉતરાણ, દહેજ, પગુથન, ભરૂચ, વડોદરા, નડીયાદ, અમદાવાદ અને કલોલના વિસ્તારોમાં ગ્રાહકોને ગેસ પૂરો પાડવામાં આવે છે.
(૨) હાલ કયા વિસ્તારો માટેની કેટલી પાઈપ લાઈન કાર્યરત છે, અને	(૨) ગેસ ગ્રીડના પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી ચાલુ છે. અંદાજીત ૪૩૦ કિ.મી. જેટલી પાઈપ લાઈન નંખાઈ ગઈ છે. તે હજીરાથી અમદાવાદ અને કલોલ સુધી વિસ્તરેલી છે. જે પાઈપ લાઈન નંખાઈ ગઈ છે અને કાર્યરત છે અને જેમાં સ્પર પાઈપ લાઈનનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેની યાદી નીચે મુજબ છે.

૧.હજીરા-મોરા	૧૫	કિ.મી.
૨. મોરા-ઉતરાણ	૨૫	કિ.મી.
૩. મોરા-સુવાલી	૭	કિ.મી.
૪. મોરા-ક્રિભકો	૩	કિ.મી.
૫. મોરા-સજોદ	૫૮	કિ.મી.
૬. અંબોલી-દહેજ	૪૫	કિ.મી.
૭. પેટ્રોનેટ-એલ.એન.જી.	૯	કિ.મી.
૮. ભાડભુથ-પગુથન	૨૫	કિ.મી.
૯. વીડીયોકોન-સ્પરલાઈન	૧	કિ.મી.
૧૦. જી.એન.એફ.સી સ્પરલાઈન	૫	કિ.મી.
૧૧. પગુથન-વડોદરા	૮૩	કિ.મી.
૧૨. અમદાવાદ-કલોલ	૧૩૪	કિ.મી.
૧૩. કલોલ-સાંતેજ	૧૫	કિ.મી.
૧૪. એ.ઈ.સી. વટવા	૮	કિ.મી.
૧૫. ઈફકો-કલોલ	૩	કિ.મી.
૧૬. અંબાપુર-ગાંધીનગર	૧૯	કિ.મી.

(૩) ભવિષ્યનું શું આયોજન છે ?

(૩) ગેસ ગ્રીડના ભાગ તરીકે જી. એસ. પી. એલ. નીચે દર્શાવ્યા મુજબના રૂટોમાં પાઈપ લાઈન નાંખવાનું આયોજન કરી રહેલ છે.

૧. આંકલાવ-ધુવારણ	૩૦	કિ.મી
૨. કલોલ-હિમતનગર	૭૫	કિ.મી.
૩. કલોલ-મહેસાણા	૪૮	કિ.મી.
૪. આણંદ-રાજકોટ	૨૩૦	કિ.મી.
૫. ધારોડ-(જી.સુરેન્દ્રનગર) પીપાવાવ	૨૨૫	કિ.મી.
૬. થાન-વાંકાનેર-મોરબી	૬૦	કિ.મી

જી.એસ.પી.એલ ગુજરાતનાં બધાજ જિલ્લાઓના વડામથકોને પાઈપલાઈનથી તબક્કાવાર સાંકળવાનું આયોજન કરી રહેલ છે.

નર્મદા યોજના બંધની ૧૧૦ મીટરની ઊંચાઈથી સરફેસ ઈરીગેશનમાં વધારો થવા બાબત

૮૦૩૬ **શ્રી ગોરધનભાઈ પ્રા. ઝડફિયા(રખિયાલ) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા યોજના બંધની ઊંચાઈ ૧૧૦ મીટર થતાં ચોમાસામાં નર્મદા કેનાલમાં કેટલા ક્યુસેક પાણી વહેતું થયું છે,	(૧) ઓછામાં ઓછુ ૩૦૭૯ કયુસેકથી વધુમાં વધુ ૧૪૮૫૯ કયુસેક.
(૨) આ વધારાના પાણીની ઉપલબ્ધી થવાથી રાજ્યની કેટલી નદીઆને જોડવામાં આવી છે, અને	(૨) પાણીની ઉપલબ્ધી અને યોજનાના પિયત વિસ્તારની જરૂરીયાતને ધ્યાનમાં લઈ વધારાનું પાણી યોજનાની નહેરોને ઓળંગતી ૨૧ નદીઓમાં વહેવડાવવામાં આવ્યું છે.
(૩) સિંચાઈમાં સરફેશ ઈરીગેશનમાં કેટલો વધારો થયો છે ?	(૩) સિંચાઈમાં સરફેશ ઈરીગેશનમાં ૩૨૮૮૮૧ એકરનો વધારો થયેલ છે.

રાજ્યમાં મહિલાઓને લગતા વિવિધ ગુનાઓ બાબત

૮૧૫૮ **ડૉ. માયાબેન સુ.કોડનાની** (નરોડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં મહિલાઓને લગતા છેડતી, બળાત્કાર, દહેજ, દાઝી જવાથી મૃત્યુ કે ઈજાઓના કેટલા બનાવો જિલ્લાવાર નોંધાયા?

જવાબ

અ. નં.	શહેર-જીલ્લો	છેડતી	બળાત્કાર	દહેજ	દાઝી જવાથી મૃત્યુ	દાઝી જવાથી ઈજા
૧.	અમદાવાદ શહેર	૭૮	૩૮	૩૫૩	૧૮૭	૭૯
૨.	રાજકોટ શહેર	૧૦	૯	૫	૫૫	૮
૩.	સુરત શહેર	૩૦	૨૬	૫૮	૫૮	૨૮
૪.	વડોદરા શહેર	૧૦	૬	૦	૮૨	૦
૫.	અમદાવાદ રૂરલ	૩	૨	૩૭	૪	૦
૬.	ખેડા	૨૭	૭	૫૫	૪	૦
૭.	આણંદ	૨૩	૧૩	૦	૦	૦
૮.	ગાંધીનગર	૧૬	૮	૪૫	૩૯	૧૨
૯.	સાબરકાંઠા	૫૪	૧૬	૦	૨૪	૩૮
૧૦.	મહેસાણા	૨૭	૩	૧૧૩	૩૭	૬
૧૧.	જામનગર	૨૬	૯	૧	૨	૧૯
૧૨.	રાજકોટ રુરલ	૪૭	૧૭	૧૫	૧૪૬	૬૬
૧૩.	સુરેન્દ્રનગર	૩૬	૧૧	૨૧	૭૭	૦
૧૪.	બનાસકાંઠા	૪૨	૧૫	૦	૦	૦

૧૫.	કચ્છ-ભુજ	૨૬	૧૩	૧	૧	૦
૧૬.	પાટણ	૧૯	૭	૩૫	૨૭	૧૧
૧૭.	અમરેલી	૨૫	૬	૨	૧૨૮	૦
૧૮.	ભાવનગર	૪૨	૩૦	૨૭	૨૪	૦
૧૯.	જુનાગઢ	૫૦	૯	૧૧	૧૧૫	૧૫
૨૦.	પોરબંદર	૬	૧	૦	૩૯	૦
૨૧	વડોદરા રુરલ	૪૧	૧૯	૭	૦	૦
૨૨.	ભરુચ	૨૮	૩૧	૭	૩	૦
૨૩.	નર્મદા	૨	૬	૦	૦	૦
૨૪.	ગોધરા	૩૪	૮	૦	૧૦	૦
૨૫.	દાહોદ	૨૮	૧૮	૨	૧	૦
૨૬	સુરત રુરલ	૧૧	૧૭	૨૪	૪૮	૦
૨૭.	વલસાડ	૧૨	૯	૧૦	૩૬	૦
૨૮.	નવસારી	૧	૩	૦	૧૦	૦
૨૯.	ડાંગ-આહવા	૩	૨	૧	૪	૦
૩૦.	પ.રે.વડોદરા	૯	૩	૦	૪	૦

સરદાર સરોવર ડેમની ૧૨૧.૯૨ મીટરની ઊંચાઈએ સાથી રાજ્યોને લાભ

૮૯૦૧ **શ્રી ભરત બારોટ** (દરિયાપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી વધવાથી મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનને શું લાભ મળશે,	(૧) સરદાર સરોવર ડેમની મુખ્ય છલતીની ઉંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ વિદ્યુત ઉત્પાદન કરવાનું આયોજન છે. આ વિદ્યુતના ૫૭ ટકા મધ્યપ્રદેશ રાજયને અને ૨૭ ટકા મહારાષ્ટ્ર રાજયને ભાગે મળશે. રાજસ્થાનને મુખ્ય નહેર પૂર્ણ થતાં ૦.૫૦ મીલીયન એકરફીટ પાણીનો લાભ મળશે.
(૨) ૧૨૧.૯૨ મીટર ઊંચાઈ વધવાથી કેટલું વીજ ઉત્પાદન થશે, અને	(૨) વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ.
(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી થતાં રાજ્યના કેટલા વિસ્તારને સિંચાઈ માટે પાણી આપી શકાશે?	(૩) બંધની ઉંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી થતાં રાજયમાં સને ૨૦૦૫-૦૬ માં આશરે ૭.૪૦ લાખ એકર વિસ્તારને સિંચાઈ માટે પાણી આપવાનું આયોજન છે.

વેરાવળ શહેરમાં કોમી રમખાણ બાબત

૮૪૩૮ **શ્રી જેસાભાઈ ભા.બારડ (સોમનાથ) : માનનીય મુખ્ય** મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જૂનાગઢ જિલ્લાના વેરાવળ શહેરમાં તા. ૨૬-૭-૨૦૦૪ના રોજ ૧૨-૪૫ કલાકે કોમી રમખાણોની શરૂઆત થઈ તે વાત ખરી છે,	(૧) વેરાવળ શહેરમાં તા. ૨૬-૭-૨૦૦૪ના રોજ ૧૨.૧૫ કલાકે વિદ્યાર્થીનીની છેડતીનો બનાવ બનેલ ત્યારબાદ કોમી રમખાણની શરુઆત થઈ.

(૨) જો હા, તો પોલીસ તંત્રને કયારે જાણ થઈ,	(૨) તા. ૨૬-૭-૨૦૦૪ના રોજ ૧૨.૪૫ કલાકે છેડતીના બનાવની જાણ થઈ. કોમી તોફાન શરુ થયાની જાણ ૧૩.૧૫ કલાકે થઈ.
(૩) થયેલ કોમી રમખાણોમાં કેટલી જાનહાનિ થઈ અને કેટલી માલમિલકતોનું નુકસાન થયું,	(૩) આ બનાવથી ૩ વ્યકિતઓના મૃત્યુ થયા અને મિલકતોમાં રૂ. ૯૬,૭૭,૨૪૫/-નું નુકશાન થયું.
(૪) કેટલા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી, અને	(૪) ૧૩૪ વ્યકિતઓની આ બનાવમાં ધરપકડ કરવામાં આવી.
(૫) વેરાવળ શહેરમાં કોમી રમખાણો ભવિષ્યમાં ન બને તે માટે સરકારે કાયમી ધોરણે શાં પગલાં લીધા?	(૫) સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગ ગોઠવેલ છે અને એસ.આર.પી. નું એક પ્લાટુન રિઝર્વ રાખેલ છે.

ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ સમીટ ૨૦૦૫માં થયેલ એમ.ઓ.યુ. બાબત

૯૩૫૨ **શ્રી નરેશકુમાર મી.કનોડીયા(કરજણ)** : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર સમીટ-૨૦૦૫ દરમ્યાન રાજયમાં ઔદ્યોગિક મૂડી રોકાણ માટે સરકારને કુલ કેટલી દરખાસ્તો મળી,	(૧) અને (૨) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ ૨૦૦૫ હેઠળ કુલ ૨૨૬ રોકાણકારોએ રૂા. ૧,૦૬,૧૬૦ કરોડ મુડી રોકાણ કરવાની તૈયારી બતાવી છે.જેની સંપૂર્ણ વિગતો પત્રક સ્વરૂપે આ સાથે સામેલ છે.
(૨) આ સમીટ દરમ્યાન કેટલા પ્રોજેકટ માટે સરકારે એમ.ઓ.યુ. કર્યા, અને	
(૩) એમ.ઓ.યુ. થી રાજયમાં કુલ કેટલુ મૂડી રોકાણ થવાનો અંદાજ છે ?	(૩) રાજયમાં કુલ રૂા.૧,૦૬,૧૬૦ કરોડનું મૂડી રોકાણ થવાનો અંદાજ છે.
	* પત્રક તા. પ્ર. ક્ર. ૮૩૧૪,અગ્રતાક્રમ ૧૩માં છાપ્યા મુજબ.

હિન્દુ કન્યાઓને અન્ય ધર્મના લોકો દ્વારા ઉઠાવી જવાના કિસ્સા

૯૨૦૦ **શ્રી પ્રવિણભાઈ મો. માકડીયા(ઉપલેટા)** : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧)રાજયના વિવિધ વિસ્તારમાં હિન્દુ કન્યાઓને અન્ય ધર્મના લોકો દ્વારા ઉઠાવી જવાના કુલ કેટલા બનાવો ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં બનેલ છે,	(૧)રાજયના વિવિધ વિસ્તારમાં હિન્દુ કન્યાઓને અન્ય ધર્મના લોકો ઉઠાવી જવાના કુલ-૪૧ બનાવો ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં બનેલ છે.
(૨)તે પૈકી કેટલી કન્યાઓને છોડાવવામાં આવી અને કેટલા લોકોને પકડવામાં આવ્યા, અને	(૨)તે પૈકી ૩૨ કન્યાઓને છોડાવવામાં આવી અને ૬૧ લોકોને પકડવામાં આવ્યા.
(૩)ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના બનાવો બનતા અટકે તે માટે કયા પગલાં વિચારવામાં આવ્યા છે ?	(૩)રાજ્યના જિલ્લા/શહેરોમાં એન્ટી રોમીઓ સેલ કાર્યરત છે. આ સેલ દ્વારા સ્કુલ-કોલેજો તેમજ જાહેર જગ્યાઓ ઉપર વોચ રાખી જરૂરી કાયર્વાહી કરવામાં આવે છે, અને ફરિયાદો અંગે યોગ્ય તે તપાસ કરવામાં

આવે છે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં વિવિધ ગુનાઓ

૯૩૭૮**શ્રી જગદીશ ઠાકોર(દહેગામ): માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧)ગાંધીનગર જિલ્લામાં જાન્યુ. ૨૦૦૨થી ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ સુધી લૂંટ, બળાત્કાર, ખૂન, ચોરી, છેડતી, આર્થિક ગુનાઓમાં કુલ કેટલા બનાવો પોલીસ સ્ટેશન વાઈઝ બન્યા,

(૨) તેમાંથી કેટલા કિસ્સા વણઉકલ્યા રહ્યા છે,

(૩) તેના કારણો શાં છે, અને

(૪) આ માટે શું શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે કે આવશે ?

જવાબ

(૧)

પો. સ્ટે.	લૂંટ	બળાત્કાર	ખૂન	ચોરી	છેડતી	આર્થિક ગુના
સે. ૨૧	૨૩	૦૦	૦૫	૪૨૬	૦૪	૩૬
સે. ૭	૩૬	૦૨	૦૪	૩૩૫	૦૧	૨૨
ડભોડા	૦૭	૦૪	૧૩	૦૬૩	૦૪	૦૮
પેથાપુર	૧૧	૦૩	૦૯	૦૭૧	૦૪	૧૦
દહેગામ	૦૩	૦૨	૧૫	૦૬૦	૧૧	૦૫
રખિયાલ	૦૧	૦૦	૦૪	૦૨૦	૦૨	૦૨
અડાલજ	૨૬	૦૧	૧૨	૧૬૪	૦૨	૧૮
માણસા	૦૦	૦૦	૦૫	૦૬૮	૦૯	૦૮
કલોલ સીટી	૦૬	૦૦	૦૪	૧૬૧	૦૨	૨૬
કલોલ તાલુકા	૧૯	૦૩	૦૮	૧૮૭	૧૭	૩૧

(૨)

પો. સ્ટે.	લૂંટ	બળાત્કાર	ખૂન	ચોરી	છેડતી	આર્થિક ગુના
સે. ૨૧	૧૧	--	૦	૩૦૪	૦	૮
સે. ૭	૨૪	૦	૧	૨૬૫	૦	૪
ડબોડા	૫	૦	૫	૩૪	૦	૨
પેથાપુર	૧૦	૦	૦	૪૯	૦	૨
દહેગામ	૨	૦	૨	૩૨	૦	૦
રખિયાલ	૦	--	૧	૩	૦	૦
અડાલજ	૧૭	૦	૭	૧૧૮	૧	૪
માણસા	--	--	૨	૩૪	૦	૦
કલોલ સીટી	૪	--	૨	૮૫	૦	૪
કલોલ તાલુકા	૧૧	૧	૫	૯૮	૦	૩

(૩) આરોપીઓના નામઠામ નમુદ ન હોવાના કારણે વણઉકેલ્યા રહેવા પામેલ છે.

(૪) આવા પ્રકારના ગુનાઓમાં અગાઉ પકડાયેલ ગુનેગારોની સઘન પુછપરછ કરવામાં આવે છે. તેઓની અવારનવાર તપાસ રાખી તેમની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે, ભરોસાના બાતમીદારો મારફતે હકીકત મેળવી ગુનાઓ શોધવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

હાલોલ તાલુકામાં આવેલી શિવરાજપુર માઈન્સ ચાલુ કરવા બાબત

૮૧૧૭ **શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર(હાલોલ) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ખાણ અને ખનિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

પ્રશ્ન

(૧)હાલોલ તાલુકામાં આવેલ શિવરાજપુર માઈન્સ સરકાર શરૂ કરવા માગે છે કે કેમ, અને

જવાબ

(૧)હા, ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ મારફત શરૂ કરવા માંગે છે.

(૨)જો હા, તો ક્યારે ?	(૨)નિયમાનુસાર જરૂરી પ્રક્રિયા હાથ ધરી જેમ બને તેમ જલ્દી આ માઈન્સ શરૂ કરવા વિચારેલ છે.

ફાયરીંગના બનાવમાં વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશનમાં અધૂરી તપાસ સામે પગલાં લેવા અંગે

૯૩૧૪ **શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમાર(તાલાલા) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ. ર. નં. ૮૪/૨૦૦૦ મુજબ આજોઠા ફાયરીંગ પ્રકરણમાં વપરાયેલ મોટર સાયકલ (સુઝુકી) કબ્જે કર્યા બાદ વેરાવળ પાલીસ સ્ટેશનમાથી ચોરીની ખોટી ફરીયાદ નોંધાયેલ છે, તેમાં પણ અધૂરી તપાસ કરી આરોપીઓને છાવરેલ છે, તો તપાસ કરનાર અધિકારી સામે સરકાર કોઈ પગલાં ભરવા માગે છે કે કેમ, અને	(૧) વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર. નં. ૮૪/૨૦૦૦ એ આજોઠા ફાયરીંગ પ્રકરણ અંગેનો ગુન્હો નથી.
(૨) જો હા, તો શું પગલાં લેવા માગે છે ?	(૨) ઉપર મુજબની હકિકત હોઈ પગલાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

નર્મદાની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં રાજ્યને થનાર લાભ

૮૮૬૯ **શ્રી બિમલ શાહ(કપડવંજ) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧)નર્મદા બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં રાજ્યને શું લાભ થશે,	(૧)નર્મદા બંધની મુખ્ય છલતીની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવાનું આયોજન છે, જેનો ૧૬ ટકા ભાગ ગુજરાત રાજ્યને મળશે, સને ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન આશરે ૭.૪૦ લાખ એકર વિસ્તાર સિંચાઈ હેઠળ આવરી લેવાનું આયોજન છે અને પીવાનું પાણી શક્ય તેટલી વધારે જગ્યાએ આપવામાં આવશે.
(૨)૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી કયા સ્તરે પડતર છે, અને	(૨)નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પર્યાવરણ પેટા જુથ ધ્વારા તેમની ૪૧મી બેઠકમાં તા. ૬-૧-૨૦૦૫ના રોજ મંજૂરી અપાયેલ છે. આજ પ્રકારની મંજૂરી નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પુનઃવસન પેટા જૂથ ધ્વારા મેળવવાની બાબત પ્રગતિ હેઠળ છે, અને આ મંજૂરી મળ્યા બાદ નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટી ધ્વારા બંધનું કામ ૧૨૧.૯૨ સુધી આગળ વધારવા માટે ટૂંક સમયમાં મંજૂરી મળવાની સંભાવના છે.
(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર વધારવા માટે કેટલો ખર્ચ થશે ?	(૩)બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી લઈ જવા માટે આશરે રૂા. ૧૨૫ કરોડનો ખર્ચ થશે.

૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી નર્મદા ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરીની પ્રક્રિયા

૮૧૨૩ **શ્રી માધાભાઈ લા. બોરીચા (કેશોદ)** : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧)૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી નર્મદા ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી કયા સ્તરે પડતર છે,	(૧) બંધને ૧૧૦.૬૪ મીટરથી ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી લઈ જવા માટે નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પર્યાવરણ પેટા જુથ ધ્વારા તેની તા. ૬-૧-૦૫ના રોજ મળેલ ૪૧મી બેઠકમાં મંજૂરી આપેલ છે. આજ પ્રકારની મંજૂરી નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પુનઃવસન પેટા જુથ ધ્વારા મેળવવાની બાબત પ્રગતિ હેઠળ છે અને આ મંજૂરી મળ્યા બાદ નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટી ધ્વારા બંધનું કામ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી આગળ વધારવા માટે નજીકના ભવિષ્યમાં આખરી મંજૂરી મળવાની સંભાવના છે.
(૨)બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં કેટલા વિસ્તારને સિંચાઈ માટે પાણી આપી શકાશે,	(૨) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં ૭.૪૦ લાખ એકર વિસ્તારને સને ૨૦૦૫-૦૬માં સિંચાઈ માટે પાણી આપવાનું આયોજન છે,
(૩)બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં સરદાર સરોવરમાં કેટલું પાણી ઉપલબ્ધ થશે, અને	(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં સરદાર સરોવરમાં આશરે ૧૫૭ કરોડ ઘન મીટર પાણી ઉપલબ્ધ થશે.
(૪)આ પાણીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે ?	(૪) વિજળી ઉત્પાદન ઉપરાંત, આ પાણી સિંચાઈ માટે, દ ારગથ્થું વપરાશ માટે અને ઔધોગિક એકમોને આપવાનું આયોજન છે.

કર્મયોગી તાલીમ અંગે ખર્ચ

૮૧૩૮ **ડૉ. સી. જે. ચાવડા(ગાંધીનગર)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કર્મયોગી માટે રાજ્યના કર્મચારીઓને તાલિમ કઈ કઈ સંસ્થા/એજન્સી ધ્વારા આપવામાં આવે છે,	(૧) સરદાર પટેલ રાજ્ય વહીવટ સંસ્થા અને આઈ.એલ.એન્ડ એફ. એસ. એજ્યુકેશન એન્ડ ટેકનોલોજી સર્વીસીઝ લિ. ધ્વારા
(૨) સરકારે કઈ પધ્ધતિથી આ એજન્સી/સંસ્થાને તાલીમ માટે મંજૂર રાખેલ છે, અને	(૨) સંસ્થાએ કરેલ પ્રેઝન્ટેશન તથા રજૂ કરેલ તાલિમની જરૂરિયાતોના વિશ્લેષણને આધારે પ્રથમ સચિવાલયના ચાર હાજર અધિકારીઓને/કર્મચારીઓને આ તાલીમ આપવાનો નિર્ણય લેવાયેલ છે. આ તાલિમને અદભૂત સફળતા અને હકારાત્મક પરિણામો મળતાં, અમદાવાદ અને ગાંધીનગર ખાતેની જિલ્લા કચેરીઓના એક લાખ અધિકારી, કર્મચારીઓને તાલિમ હેઠળ આવરી લેવાનો નિર્ણય મુખ્ય સચિવશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને રચાયેલ સ્ટીયરીંગ કમિટિ ધ્વારા લેવામાં આવેલ છે.
(૩) ડિસેમ્બર ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ વર્ષવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?	(૩) તા. ૧-૧-૨૦૦૩થી ૩૧-૧૨-૨૦૦૩ સુધીનો ખર્ચ શુન્ય. તા.૧-૧-૦૪થી ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીનો ખર્ચ રૂા. ૯૧,૪૬,૫૦૦

કુલ ખર્ચ રૂા. ૯૧,૪૬,૫૦૦

પોલીસ દળને ચુસ્ત રાખવા માટેની નવી તાલિમ સંસ્થાઓ સ્થાપવા અંગે

૯૩૪૭ **શ્રી પુનમ ર. પરમાર (પાદરા)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજય સરકાર દ્વારા પોલીસ દળને ચુસ્ત રાખવા કોઈ તાલિમ સંસ્થાઓ ચલાવવામાં આવે છે કે કેમ,	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો હયાત તાલિમ સંથાઓ ઉપરાંત કોઈ નવી સંસ્થાઓ સ્થાપવાનું વિચારણા હેઠળ છે કે કેમ, અને	(૨) હાલ ૪ (ચાર) તાલિમ સંસ્થાઓ હયાત છે. નવી તાલિમ સંસ્થાઓ સ્થાપવાની વિચારણા નથી.
(૩) જો હા, તો કઈ જગ્યાએ અને ક્યારે ?	(૩) ના.

નર્મદા યોજનામાં જમીન સંપાદનની કાર્યવાહી ઝડપી બનાવવા પગલાં

૮૮૮૮ **શ્રી મોહનભાઈ ધ. ઢોડિયા (મહુવા)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા યોજનામાં જમીન સંપાદનની કાર્યવાહીમાં ઝડપ લાવવા અને સંપાદનમાં કોર્ટ કચેરીની કાર્યવાહી ઘટાડવા સરકારે શું પગલાં લીધાં છે ?	(૧) નર્મદા યોજનામાં જમીન સંપાદનની કાર્યવાહીમાં ઝડપ લાવવા રાજ્ય સરકારે જસ્ટીશ શ્રી ડી. પી. બુચ (નિવૃત્ત) ના અધ્યક્ષ સ્થાને એક ઉચ્ચ કક્ષાની તજજ્ઞ સમિતિની નિમણુંક કરી છે. આ તજજ્ઞ સમિતિ જમીનની ફળદ્રુપતા, વિસ્તાર જેવા મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરી સંપાદન હેઠળની જમીનની યોગ્ય અને વ્યાજબી કિંમત બાબતે જમીન સંપાદન અધિકારીને માર્ગદર્શન આપશે. જમીન સંપાદનની કામગીરીમાં કોર્ટ કચેરીની કાર્યવાહી ઘટાડવા અને સંમતિ એવોર્ડથી જમીન સંપાદન કરવા તેમજ કોર્ટમાં પેન્ડીંગ લેન્ડ રેફરન્સ કેસોનો સમજુતીથી નિકાલ કરવા માટે અધિક કલેકટરશ્રી (નર્મદા) અમદાવાદ અને વડોદરા ના અધ્યક્ષ સ્થાને જિલ્લા કક્ષાની બે સમિતિઓની રચના કરી છે. આમ, તજજ્ઞ સમિતિ અને જિલ્લા કક્ષાની સમિતિઓને કારણે જમીન સંપાદનની કાર્યવાહી ઝડપી બનશે. અને કોર્ટ કચેરીની કાર્યવાહી ઘટવા પામશે.

લિગ્નાઈટ આધારિત પાવર પ્રોજેકટ અંગે લીધેલાં પગલાં

૮૮૯૧ **શ્રી કાંતિભાઈ ભા. તડવી (સંખેડા)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં લિગ્નાઈટ આધારિત પાવર પ્રોજેકટ કરવાની દિશામાં સરકારનું શું આયોજન છે,	(૧) રાજ્યમાં લિગ્નાઈટ આધારિત પાવર પ્રોજેક્ટ કરવા અંગે નીચે મુજબનું આયોજન છે. ૧) ૨૫૦ મે. વો. ઘોઘા જી. ભાવનગર ૨) ૨૫૦ મે. વો. અક્રીમોટા, જી, કચ્છ ૩) ૭૫ મે. વો. પાનન્દ્રો, જી. કચ્છ ૪) ૨૫૦ મે. વો. માંગરોળ, જી. સુરત ૫) ૫૦૦ મે. વો. કચ્છ જીલ્લામાં ૬) ૨x૧૦૦૦ મે. વો. દક્ષિણ ગુજરાત ખાતે

	૭) ૫૦૦ મે. વો. ભાવનગર જીલ્લામાં
(૨) આ અંગે સરકારે કોઈ ચોક્કસ પગલાં લીધા છે કે કેમ, અને	(૨) હા, જી.
(૩) જો હા, તો તેની વિગતો શું છે ?	(૩) સામેલ પત્રક મુજબ.

પત્રક

(૧) ૨૫૦ મે. વો. ના ઘોઘા તાલુકાના ઘોઘા ખાતે સ્થાપવા માટે જી.પી.સી.એલ. દ્વારા કરવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક દરખાસ્તોનું મુલ્યાંકનની પ્રક્રિયાને આધારે મેસર્સ નિરમા કેમિકલ વર્કસ લીમીટેડ સાથે સમજુતી કરાર કરી આગળ વધવાની મંજૂરી આપેલ છે.

(૨) ૨૫૦ મે. વો. નું લિગ્નાઈટ આધારિત વીજમથક જિલ્લાના અકરીમોટા ખાતે સ્થાપવાની કાર્યવાહી ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે જે પુર્ણ થઈ આ વર્ષમાં કાર્યાન્વિત થવાનો અંદાજ છે.

(૩) કચ્છ જિલ્લામાં પાનાન્દ્રો ખાતે ગુજરાત ઈલેકટ્રીસીટી બોર્ડના વીજ મથક ખાતે ૭૫ મે. વો. ની વીજ વિસ્તરણની કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, આ વીજ વિસ્તરણ યોજનાની કાર્યવાહી નવેમ્બર-૨૦૦૬માં પૂર્ણ થઈ કાર્યાન્વિત થવાનો અંદાજ છે.

(૪) સુરત જિલ્લાના માંગરોલ ખાતે ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પાવર કંપની લીમીટેડ દ્વારા ૨૫૦ મે. વો. ની વીજ વિસ્તરણ કરવાની મંજૂરી રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે આ વીજ યોજના સ્થાપવા માટે ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પાવર કંપની લીમીટેડ અને ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેકટ્રીસીટી કોર્પોરેશન વચ્ચે ગુજરાત વાયબ્રન્ટ ઈન્વેસ્ટર સમિત ૨૦૦૫માં સમજૂતિ કરાર કરવામાં આવ્યા છે.

(૫) કચ્છ જીલ્લામાં વધુ ૫૦૦ મે. વો. નું વીજ મથક સ્થાપવા માટે ગુજરાત સરકારના ઊર્જા વિભાગ અને ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન વચ્ચે ગુજરાત વાઈબ્રન્ટ ઈન્વેસ્ટર સમિત ૨૦૦૫માં સમજૂતિ કરાર કરવામાં આવ્યા છે.

(૬) દક્ષિણ ગુજરાતમાં વધુ ૨x૧૦૦૦ મે.વો. નું વીજમથક સ્થાપવા માટે ગુજરાત સરકારના ઊર્જા વિભાગ અને ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પાવર કંપની લીમીટેડ વચ્ચે ગુજરાત વાયબ્રન્ટ ઈન્વેસ્ટર સમિત ૨૦૦૫માં સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે. ભાવનગર જીલ્લામાં વધુ ૫૦૦ મે. વો. નું વીજ મથક સ્થાપવા માટે ગુજરાત સરકારના ઊર્જા વિભાગ અને ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લીમીટેડ વચ્ચે ગુજરાત વાયબ્રન્ટ ઈન્વેસ્ટર સમિત ૨૦૦૫માં સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે.

(૭) ભાવનગર જિલ્લામાં વધુ ૫૦૦ મે.વો. નું વીજ મથક સ્થાપવા માટે ગુજરાત સરકારના ઉર્જા વિભાગ અને ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ વચ્ચે ગુજરાત વાયબ્રન્ટ ઈન્વેસ્ટર સમિત ૨૦૦૫ માં સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે.

રાજ્ય સરકાર ધ્વારા લઘુઉદ્યોગકારોને સબસીડીમાં કાપ

૯૩૬૯ **શ્રી પુનાભાઈ ઘે. ગામીત (વ્યારા)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્ય સરકારે સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ લઘુ ઉદ્યોગકારોને આપવામાં આવતી શરતો (સબસીડી)માં વર્ષવાર કેટલા ટકા કાપ મુક્યો છે, અને	(૧) કોઈ કાપ મૂકવામાં આવેલ નથી.
(૨) આ કાપ મૂકવાના કારણો શાં છે ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

રાજ્યમાં "પોટા" હેઠળ ધરપકડ બાબત

૮૩૬૪ **શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાળા (જમાલપુર)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં પોટા હેઠળ કેટલા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે,	(૧) ૨૨૯
(૨) પોટા રીવ્યુ કમીટીએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તે પૈકીના કેટલા કેસોની સમીક્ષા કરી છે, અને	(૨) એક કેસની સમીક્ષા કરી છે.
(૩) સમીક્ષામાં શું ઠરાવ્યું છે ?	(૩) પોટાની કઈ જોગવાઈઓ સમીક્ષા હેઠળના કેસમાં લાગુ પડે અથવા ન પડે તે અંગે ભલામણ કરેલ છે.

અમદાવાદ શહેરમાં સોનાના દોરાની ચીલ ઝડપના નોંધાયેલા બનાવો

૮૫૫૬ **શ્રી મોહંમદફારુક હુ. શેખ(કાલુપુર)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સુધીમાં પોલીસ સ્ટેશન દીઠ સોનાના દાગીના (ચેન) ની ચીલ ઝડપના કુલ કેટલા બનાવો નોંધાયા	(૧)

પોલીસ સ્ટેશન	ગુનાની સંખ્યા
નારણપુરા	૨૧
નવરંગપુરા	૧૪
ઘાટલોડિયા	૧૪
સોલા	૦૫
સેટેલાઈટ	૨૩
વેજલપુર	૦૩
એલીસબ્રિજ	૦૪
કારંજ	૦૨
શાહપુર	--
માધવપુરા	૦૩
સાબરમતી	૦૭
શહેરકોટડા	૦૧
કાલુપુર	--
હવેલી	૦૧
ખાડીયા	૦૨
શાહીબાગ	૦૪
દરીયાપુર	--
મેઘાણીનગર	૦૧
સરદારનગર	૦૭
નરોડા	૧૬
બાપુનગર	૧૭
ઓઢવ	૦૮
અમરાઈવાડી	૦૬
રખીયાલ	--
ગોમતીપુર	--
કાગડાપીઠ	૦૭
દાણીલીમડા	--
મણીનગર	૨૦
વટવા	૦૩
જી.આઈ.ડી.સી.	૦૨
ક્રાઈમ	--

(૨) આવા સોનાના દોરા તોડનાર ઈસમ પકડાય છે અને કબુલ કરે છે પરંતુ પોલીસ તંત્ર તરફથી આવા સોનાના ચેન કોને ક્યારે વેચ્યા તેની તપાસ ઝડપથી થતી નથી, તે હકીકત સાચી છે, અને	(૨) ના, જી.
(૩) છેલ્લા એક વર્ષમાં આવા ચોરાયેલા સોનાના દોરા ખરીદનાર કેટલા ઈસમોની સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી ?	(૩) છેલ્લા એક વર્ષમાં આવા ચોરાયેલા સોનાના દોરા ખરીદનાર ૧૧ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ ગુન્હો દાખલ કરી નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ કરવામાં આવેલ છે.

-------- --------

અમદાવાદ શહેરમાં સી. એન. જી. સ્ટેશનો

૮૯૦૪ **શ્રી પ્રદિપસિંહ ભ.જાડેજા (અસારવા)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરમાં વાહનો માટે સી. એન. જી. સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે તે માટે સરકારનું શું આયોજન છે,	(૧) અમદાવાદ શહેરમાં ગેસ વિતરણ માટેની આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ વિકસાવવા સરકારે મેસર્સ ગુજરાત અદાણી એનર્જી લિ.ને "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર" આપેલ છે. જુન-૨૦૦૪ માં અમદાવાદને નેચરલ ગેસ પૂરો પાડતી મુખ્ય લાઈન જી.એસ.પી.સી.એ નાંખી દીધી છે અને વટવા જી.આઈ.ડી.સી. ખાતે એ.ઈ.સી. કંપનીને ગેસ પૂરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત રાજ્ય સરકારે હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશનની અમદાવાદ માટે એક મુખ્ય મથક (મધર સ્ટેશન) તથા ૯ ગૌણ મથકો (ડોટર સ્ટેશન) અંગેની દરખાસ્ત પણ મંજુર કરેલ છે.
(૨) તા. ૩૧-૧-૦૫ની સ્થિતિએ કેટલા સી.એન.જી. સ્ટોશનો કાર્યરત છે, અને	(૨) ૩(ત્રણ)
(૩) શહેરની જરૂરિયાત પ્રમાણે ભવિષ્યનું શું આયોજન છે ?	(૩) જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને અદાણી ગ્રુપ તથા હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પો. લિ. (એચ.પી.સી.એલ.) મારફત કુલ ૨૦ (વીસ) સી.એન.જી. સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન છે.

----- -----------

રીવર બેડ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન બાબત

૮૮૭૬ **શ્રી શંકરભાઈ લ.ચૌધરી (રાધનપુર)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા યોજના આધારીત રીવર બેડ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન કયારથી શરૂ થયું,	(૧) તા. ૧-૨-૨૦૦૫થી
(૨) જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ના અંત સુધીમાં રીવર બેડ પાવર હાઉસમાંથી કેટલું વીજ ઉત્પાદન થયું,	(૨) -- શુન્ય -
(૩) આ વીજ ઉત્પાદન કયાં સુધી ચાલુ રહેશે, અને	(૩) મુખ્ય બંધના જળાશયમાં પાણીનું સ્તર ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી નીચું જાય ત્યાં સુધી

(૪) પાવર હાઉસની છેલ્લી પરિસ્થિતિ શું છે?	(૪) નહેર આમુખ જળવિધુત મથકની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. નદી તળ ભૂર્ગભ જળ વિધુત મથકની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. ૨૦૦ મેગાવોટની સ્થાપિત ક્ષમતા વાળું પ્રથમ એકમ કાર્યાન્વિત કરવામાં આવેલ છે. અને બાકીના પાંચ એકમો જુન-૨૦૦૬ સુધીમાં તબક્કાવાર કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન છે.

કચ્છ જિલ્લામાં વીજળીની જરૂરિયાત

૮૦૨૯ **શ્રી ગોપાલભાઈ ગા. ધુઆ (મુન્દ્રા)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં ડીસેમ્બર -૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી વીજળી વપરાશની જરૂરિયાત છે,	(૧) અનિયંત્રિત ૫૨૩.૫ મે.વો. વીજમાંગ (લોડ શેડીંગ વિના)
(૨) આ જરૂરિયાત સામે કચ્છ જિલ્લાને કેટલી વીજળી પૂરી પાડવામાં આવે છે,	(૨) ૩૮૨ મે.વો.
(૩) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૦૫ નીચે આ વીજળીની જરૂરિયાતને પૂરી પાડવા કોઈ એમ.ઓ.યુ. થયેલ છે કે કેમ, અને	(૩) હા, જી.
(૪) જો હા, તો તેની શી વિગતો છે ?	(૪) કચ્છની વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા રાજયના અન્ય વીજમથકો સાથે જોડાયેલી છે. આથી કચ્છની માંગ પુરી પાડવા રાજયના અન્ય વીજ મથકોમાં ઉત્પાદીત વીજળી પુરી પાડવામાં આવે છે. આમ છતાં કચ્છ જીલ્લામાં વીજ ઉત્પાદનની શક્યતાઓ ધ્યાને લઈને વાયબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫માં ગુજરાત ખનીજ વિકાસ નિગમ ધ્વારા ૫૦૦ મે.વો. અને અદાણી પ્રા.લિ. ધ્વારા ૧૦૦૦ મે.વો. ના વીજળી ઉત્પાદન પ્રોજેકટો સ્થાપવા સમજૂતી કરાર થયેલ છે.

જેતપુર અને ગોંડલ તાલુકામાં દહેજને કારણે સ્ત્રીઓને આપઘાતની ફરજ અને મૃત્યુ

૮૨૧૩ **શ્રીમતી જસુબેન સ.કોરાટ(જેતપુર)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં સન ૨૦૦૪ના કેલેન્ડર વર્ષમાં કેટલી સ્ત્રીઓ દહેજના કારણસર મૃત્યુ પામી અથવા આપઘાતની ફરજ પાડવામાં આવી,	(૧) ૬ (છ)
(૨) તે માટે કેટલા ગુનાહિત સાસરિયા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી,	(૨) ૧૭ (સત્તર)
(૩) કેટલાની ધરપકડ બાકી છે, અને	(૩) એક પણ નહીં.
(૪) બાકી રહેલા આરોપીઓની ધરપકડ કયારે કરવામાં આવશે ?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

મહેસાણા જિલ્લામાં જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ લાભાન્વિત ગામો

૯૧૭૯ **ડૉ. અતુલ કે.પટેલ (કલોલ)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) મહેસાણા જિલ્લામાં ૨૦૦૪-૦૫માં કુલ કેટલા ગામોને જયાતિગ્રામ યોજના હેઠળ લાભ મળેલ છે, અને	(૧) ૫૦૪
(૨) કેટલા ગામોને લાભ આપવાનો બાકી છે ?	(૨) મહેસાણા જિલ્લાના તમામ ગામો જયોતિગ્રામ હેઠળ આવરી લેવાયેલ હોવાથી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પાલનપુર શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખીત ફરિયાદો પરથી દાખલ થયેલા ગુના

૯૩૬૭ **શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી (દાંતા)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર શહેર પોલીસ થાણામાં સને ૨૦૦૪ના વર્ષમાં લેખીત ફરિયાદો પરથી કેટલા ગુનાઓ દાખલ થયા,	(૧) ૭૪
(૨) આ ગુન્હાઓ પૈકી કેટલા ગુનાઓમાં કોર્ટમાં ચાર્જશીટ મુકવામાં આવ્યા, અને	(૨) ૫૧
(૩) ચાર્જશીટ મુકાયા વગરના કેટલા ગુનાઓમાં કયા-કયા પ્રકારની સમરીઓ માંગવામાં આવી ?	(૩)

એ-સમરી એન.સી. સમરી	બી-સમરી		સી-સમરી
૧૧	૧	૧	૧

રાજ્યમાં ગેસીફાયર વીજ મથકો

૯૩૬૧ **શ્રી છબીલદાસ ના. પટેલ** (માંડવી) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ની સ્થિતિએ ગેસીફાયર આધારિત કેટલા વીજ મથક કેટલા કીલો વોટના છે,	(૧) ૫૦૦ કિ.વો. ક્ષમતાનું એક વીજમથક છે.
(૨) આ વીજ મથક કયારે સ્થાપવામાં આવ્યા હતા,	(૨) સને ૧૯૯૯
(૩) તે પૈકી કયા કયા વીજ મથક હાલ બંધ હાલતમાં છે, તેના કારણો શાં શાં છે, અને	(૩) આ વીજ મથક હાલ નીચેના કારણસર બંધ છે. (૧) આ વીજમથકમાં બળતણ માટે લાકડામાંથી ઉત્પન્ન થયેલ ગેસ અને ડીઝલ વાપરવામાં આવતું હતું ડીઝલની કિંમતમાં થયેલ વધારાને કારણે વીજ ઉત્પાદન મોઘું પડે છે.
(૪) બંધ પડેલા વીજ મથકો કયારે ફરી શરૂ કરવામાં આવનાર છે?	(૪) આ વીજ મથક સંપૂર્ણ ગેસીફાયરમાંથી ઉત્પન્ન કરેલ ગેસથી ચલાવવા આયોજન કરેલ છે. જે માટે કેન્દ્ર સરકારની નાણાકિય સહાય માગેલ છે જે મળ્યાબાદ

તેમજ અન્ય પ્રક્રિયાઓ પૂરી થયે આ વીજ મથક ચાલું કરી શકાશે.

સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની કામગીરી સમયસર થવા બાબત

૮૮૮૦ **શ્રી યોગેશભાઈ ના.પટેલ**(રાવપુરા) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ ૧૦૦ મીટર, ૧૧૦.૬૪ મીટર અને ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી વધારવાની મંજૂરી મળી, અને	(૧) સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ ૧૦૦ મીટર અને ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી વધારવાની મંજુરી તા. ૧૪-૫-૦૩ અને તા. ૧૬-૩-૦૪ના રોજ મળેલ હતી. ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી વધારવાની મંજુરી મળેલ નથી.
(૨) સમય મર્યાદામાં કામગીરી પૂર્ણ થઈ કે કેમ?	(૨) હા. જી. મળેલ મંજુરીઓ મુજબ કામગીરી સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થયેલ છે.

રાજકોટ જેલની ક્ષમતા અને કેદીઓની સંખ્યા

૮૯૨૫ **શ્રી ટપુભાઈ લીંબાસિયા**(રાજકોટ-૧) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ રાજકોટની જેલમાં કેદીઓની સંખ્યા કેટલી છે, અને આ જેલમાં કેદીઓ રાખવાની ક્ષમતા કેટલી છે, અને	(૧) કેદીઓની સંખ્યા -૭૪૫ કેદીઓ રાખવાની ક્ષમતા -૨૧૨
(૨) રાજકોટ જિલ્લા જેલનું મધ્યસ્થ જેલમાં રૂપાંતર કરવા માટે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે?	(૨) નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરી છે. (૧) કેન્દ્ર પુરસ્કૃત જેલ સુધારણા યોજના (૭૫ ટકા કેન્દ્ર સરકારનો ફાળો) હેઠળ જેલનાં વિસ્તરણ માટે સને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ નાં વર્ષ માટે રૂા. ૪.૬૧/-કરોડની જોગવાઈ કરી છે, વહીવટી મંજૂરી પણ આપી દીધી છે. (૨) આ જ યોજના હેઠળ સને- ૨૦૦૬-૨૦૦૭નાં વર્ષ માટે રૂા. ૨.૮૯/- કરોડ ફાળવવાનું આયોજન કર્યું છે. (૩) જેલની પશ્ચિમ દિશાએ આવેલ વધારાની સર્વે નં. ૬૨૬ની જમીન (૨૪૨૫ ચો.મી.) મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાસેથી રૂા. ૩૦/- લાખમાં ખરીદવા સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬નાં અંદાજપત્રમાં જોગવાઈ સૂચવી છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં નર્મદા નહેરોનું કામ શરૂ કરવા અંગે

૮૮૬૨ **શ્રી સુનીલ બા.ઓઝા**(ભાવનગર શહેર દક્ષિણ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ

(૧) ભાવનગર જિલ્લામાં નર્મદા યોજનાની નહેરોનું કામ કયા કયા તાલુકામાં કયારે શરૂ કરવામાં આવશે,	(૧) ભાવનગર જીલ્લામાં પાંચ તાલુકા પૈકી બે તાલુકા (વલ્લભીપુર અને ભાવનગર)માં નર્મદા યોજનાની નહેરોના કામો હાથ ધરવામાં અ ાવેલ છે, જ્યારે બાકી રહેતા ત્રણ તાલુકા (બોટાદ, ગઢડા અને ઉમરાળા)માં નર્મદા યોજના નહેરના કામો સને ૨૦૦૫-૦૬થી શરૂ કરવાનું આયોજન છે.
(૨) આ કામો કયારે પૂરા કરવામાં આવશે, અને	(૨) શાખા નહેરો તથા પિયત વિસ્તારના કામો સને ૨૦૦૭-૦૮ સુધીમાં પૂરા કરવાનું આયોજન છે.
(૩) કેટલો વિસ્તાર સિંચાઈ હેઠળ આવશે ?	(૩) ભાવનગર જીલ્લાના ૬૩૮૦૦ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઈ હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે.

સરકારની તાલીમ સંસ્થા હોવા છતાં કર્મયોગીની તાલીમનો કોન્ટ્રાક્ટ બીજી સંસ્થાને આપવા બાબત

૮૫૨૨ **શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ(લીંબડી): માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્ય સરકારના કર્મચારી/અધિકારીઓને તાલીમ આપવાની સંસ્થા સ્પીપા હોવા છતાં કર્મચારીઓને તાલીમ માટે કર્મયોગી યોજના ધ્વારા તાલીમ અપાઈ તેનું બજેટ કેટલું છે; અને	(૧) રૂા. ૨૩૭.૫૦ લાખ (વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫) (મૂળ જોગવાઈ).
(૨) સરકારની પોતાની તાલીમ સંસ્થા હોવા છતાં બીજી સંસ્થાને કોન્ટ્રાકટ આપવાની જરૂર કયા કારણોસર પડી છે?	(૨) બે વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં પટાવાળાથી માંડી અધિક સચિવશ્રી સુધીના બધા કર્મચારી/ અધિકારીઓને આ તાલીમમાં આવરી લેવાનો લક્ષ્યાંક હોવાથી પ્રોફેશનલ એજન્સીની મદદ લેવી જરૂરી જણાય છે.

------------ -

ખાનગી એકમો પાસેથી વીજળીની ખરીદી કરવા બાબત

૮૮૪૩ **શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર**(કડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સરકાર દ્વારા ખાનગી એકમો પાસેથી કેટલી તથા કયા ભાવે વીજળી ખરીદી કરવામાં આવી, અને	(૧) ૨૦૦૩માં ૧૧૧૪૧ મી.યુ. ૨૦૦૪માં ૧૩૩૬૫ મી.યુ. સરેરાશ રૂ. ૨.૮૧ અને રૂા. ૨.૪૫ પ્રતિ યુનિટના ભાવે ખરીદ કરવામાં આવી છે.
(૨) જુદા જુદા એકમો પાસેથી જુદા જુદા ભાવે વીજળી ખરીદ કરવા માટેના કારણો શાં છે ?	(૨) જુદા જુદા એકમો ચલ ખર્ચ, વપરાતા બળતણ અને સમયાનુસાર બદલતી બળતણની કિંમત ધ્યાને લઈ વીજળી ખરીદવા માટે ખાનગી એકમો સાથે બોર્ડ દ્વારા કરાર કરવામાં આવેલ છે. જેથી જુદા જુદા ભાવે વીજળી ખરીદવામાં આવે છે.

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૦૫માં થયેલા એમ. ઓ. યુ.

૮૭૨૮ **શ્રી દીલુભા ટે. ચુડાસમા**(વડોદરા ગ્રામ્ય) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૦૫ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમીટમાં ઉદ્યોગ સાહસિકો અને સરકાર વચ્ચે કુલ કેટલી રકમના રોકાણ માટે એમ. ઓ.યુ. થયા,	(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમીટમાં કુલ રૂા. ૧,૦૬,૧૬૦ કરોડના મૂડી રોકાણ એમ. ઓ.યુ. પ્રોજેકટ જાહેરાતો થઈ.
(૨) તે પૈકી વડોદરા માટે કુલ કેટલી રકમ માટેના કેટલા એમ.ઓ.યુ. થયા, અને	(૨) કુલ રૂા. ૨૪૫૧.૮૫ કરોડના રકમ માટેના ૯ એમ.ઓ.યુ./પ્રોજેક્ટ જાહેરાતો મળેલ છે.
(૩) આ એમ.ઓ.યુ. પૈકી વાસ્તવિક રોકાણની સંભાવનાઓ શું છે ?	(૩) આ એમ.ઓ.યુ.માં જાહેર થયેલ મહત્તમ રોકાણની સંભાવનાઓ છે.

રાજ્યમાં સીધી ભરતીની પી. એસ.આઈ. ની ખાલી જગ્યાઓ

૯૩૧૯ **શ્રી નારાયણભાઈ લ. પટેલ**(ઉંઝા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ ખાતામાં પી.એસ.આઈ. ની સીધી ભરતીથી ભરવાપાત્ર કેટલી જગ્યાઓ બાકી છે; અને	(૧) ૨૯૬
(૨) આ જગ્યાઓ ભરવા સરકારે શું આયોજન કરેલ છે ?	(૨) ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ૧૮૬ જગ્યાઓ ઉપર ભરતી કરવાની સૂચના ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળને આપી છે.

હીરા ઉદ્યોગને ધબકતો કરવાનું આયોજન

૮૧૮૪ **શ્રી જ્યંતિલાલ રા.કવાડીયા** (હળવદ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં હીરા ઉદ્યોગ આજે ભયંકર મંદીમાં સપડાયેલ છે તે વાત સાચી છે;	(૧) ના, જી.
(૨) જો હા, તો આ હીરા ઉદ્યોગને ધબકતો કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ; અને (૩) જો, હા, તો કેવા પ્રકારનું ?	(૨) અને (૩) આ હીરા ઉદ્યોગ મંદીમાં સપડાયેલ નથી આમ છતાં આ ઉદ્યોગને ધબકતો રાખવા માટે ગુજરાત હીરા વિકાસ બોર્ડ દ્વારા રાજ્યમાં હીરા ઉદ્યોગને તાલીમ આપતા તાલીમ કેન્દ્રો સ્થાપી તે દ્વારા વધુમાં વધુ રોજગારી ઉભી કરવામાં આવી રહી છે. તેમજ આ ઉદ્યોગના તાંત્રિક વિકાસ આધુનિકરણ તથા નવી ટેકનોલોજીનો આભ્યાસ કરી ગુજરાતમાં તે ફેલાવવાના કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત હીરા વિકાસ બોર્ડ દ્વારા ત્રણ ડાયમંડ પાર્ક અનુક્રમે સુરત, અમદાવાદ અને ગાંધીનગર ખાતે બનાવવા માટે ખાનગી કંપનીના સહયોગથી આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં સામુહિક આત્મહત્યાના બનાવો

૮૭૧૦ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી**(ભાવનગર શહેર ઉત્તર) : **માનનીયમુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભાવનગર જિલ્લામાં ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુટુંબની સામુહિક આત્મહત્યાના કુલ કેટલા બનાવો નોંધાયા,	(૧) ૨ (બે)
(૨) તે પૈકી કુલ કેટલા લોકોના મૃત્યુ થયાં; અને	(૨) ૪ (ચાર)
(૩) ઉપરોક્ત બનાવો પૈકી બેકારી અને દેવું વધી જવાથી કેટલા બનાવો બન્યા હતા?	(૩) ૧ (એક)

સાવલી તાલુકામાંથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલ દ્વારા તળાવ ભરવા અંગે

૮૯૩૫ **શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર. ગોહિલ**(સાવલી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સાવલી તાલુકામાંથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલ મારફતે તાલુકાના ૧૦ સિંચાઈ તળાવોમાં પાણી આપવાની કોઈ યોજના છે કે કેમ;	(૧) સરદાર સરોવર યોજનામાં પાણીની ઉપલબ્ધિને લક્ષમાં રાખીને માગણી આવ્યેથી સાવલી તાલુકામાં યોજનાના પિયત વિસ્તારમાં આવેલા સિંચાઈ તળાવોને પાણી આપી શકાશે.
(૨) જો હા, તો કયારે પૂરી થશે; અને	(૨) ઉપર જણાવેલ (૧) મુજબ.
(૩) હયાત તળાવોમાંથી ગામડાઓના ખેડૂતોને ખેતી માટેના પાણીનો લાભ કયાર સુધીમાં મળશે?	(૩) જૂન-૨૦૦૬ સુધીમાં.

રાજ્યમાં ખૂન, લૂંટ, ચોરી અને આત્મહત્યાના બનાવો

૮૪૭૮ **શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી**(અમરેલી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

રાજ્યમાં તા. ૧-૧-૦૪ થી તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં ખૂન, લુંટ, ચોરી અને આત્મહત્યાના કેટલા બનાવો પોલીસ દફતરે નોંધવામાં આવ્યા?

જવાબ

ખુન	૧૧૦૮
લૂંટ	૧૧૨૬
ચોરી	૧૮૫૧૫ અને
આત્મહત્યા	૪૫૨૧ બનાવો નોંધાયા.

ક્વાંટ અને છોટા ઉદેપુરમાં ખુનના બનાવો

૮૯૨૪ **શ્રી શંકરભાઈ વી. રાઠવા**(છોટા ઉદેપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૦૩-અને ૨૦૦૪માં ક્વાંટ અને છોટાઉદેપુરમાં કેટલા ખૂન થયા;	(૧) સને ૨૦૦૩ / સને૨૦૦૪ ક્વાંટ ૦૫ ૦૮ છોટાઉદેપુર ૦૯ ૧૩
(૨) તે પૈકી કેટલાનો ભેદ ખૂલ્યો;	(૨) ક્વાંટ ૦૫ ૦૮ છોટાઉદેપુર ૦૭ ૧૦
(૩) ખૂન અંગે મોટા ભાગના કારણો કયા હતા; અને	(૩) આદિવાસી વિસ્તાર હોવાથી અંધશ્રધ્ધા તથા અંગત અદાવત, જમીનના ઝઘડાના કારણો મુખ્યત્વે છે.
(૪) આવા ગુન્હા અટકાવવા પોલીસે શી કાર્યવાહી કરી?	(૪) સી.આર.પી.સી. અન્વયે કડક અટકાયતી પગલાં ભરી, ગામલોકોની રૂબરૂ મુલાકાત વખતે કાયદાની સમજ, સુલેહ ભંગ ન થાય તે માટે સમજ આપી કાયદાની સરળ સમજ માટે પત્રિકાઓ દ્વારા પ્રચાર, આ પ્રદેશની ગામઠી ભાષામાં જ કાયદાની જાણકારી મળી રહે તે માટે સ્થાનિક સંસ્થાઓની મદદની તજવીજ કરવામાં આવે છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં માર્ગ અકસ્માતો

૯૩૪૯ **શ્રી ધારશીભાઈ લ. ખાનપુરા** (કાંકરેજ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ની સાલમાં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ માર્ગ અકસ્માતના કેટલા બનાવ બનેલ છે; અને	(૧) ૯૦૫
(૨) તેમાં કેટલાએ જાન ગુમાવેલ છે?	(૨) ૨૧૫

રીવર બેડ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન બાબત

૮૮૭૨ **શ્રી અંબાલાલ આ.રોહિત (સોજીત્રા)** : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા યોજના આધારિત રીવર બેડ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન ક્યારથી શરૂ થયું,	(૧) તા.૧-૨-૨૦૦૫ થી
(૨) જાન્યુઆરી--૨૦૦૫ના અંત સુધીમાં રીવર બેડ પાવર હાઉસમાંથી કેટલું વીજ ઉત્પાદન થયું,	(૨) -શુન્ય-

(૩) આ વીજ ઉત્પાદન ક્યાં સુધી ચાલુ રહેશે, અને

(૩) મુખ્ય બંધના જળાશયમાં પાણીનું સ્તર ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી નીચું જાય ત્યાં સુધી.

(૪) પાવર હાઉસમાં કામગીરીની છેલ્લી પરિસ્થિતિ શું છે ?

(૪) નહેર આમુખ જળવિદ્યુત મથકની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. નદી તળ ભૂગર્ભ જળ વિદ્યુત મથકની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. ૨૦૦ મેગાવોટની સ્થાપિત ક્ષમતા વાળું પ્રથમ એકમ કાર્યાન્વિત કરવામાં આવેલ છે. અને બાકીના પાંચ એકમો જુન-૨૦૦૬ સુધીમાં તબક્કાવાર કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન છે.

ઓકટોબર--૦૩ નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન થયેલા મુડી રોકાણના પ્રોજેક્ટોની કાર્યવાહી

૮૯૧૫ **શ્રી ગોવાભાઈ હ.રબારી**(ડીસા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) દેશ વિદેશના મૂડી રોકાણકારોને આકર્ષવા ઓકટોબર-૦૩ના નવરાત્રિ મહોત્સવ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત વખતે ૭૬ ટકા જેટલા મૂડી રોકાણના પ્રોજેકટો પર કરાર કરવામાં આવ્યા હતા તે હકીકત સાચી છે,

(૨) જો હા, તો આ પ્રોજેકટો પૈકી કયા કયા અને કેટલા પ્રોજેકટો કયા કારણોસર પડતા મૂકવામાં આવ્યા , અને

(૩) તે અન્વયે કેટલા પ્રોજેક્ટોને હજુ સુધી જમીન ફાળવવામાં આવી નથી, અને તેના કારણો શું છે ?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) આ પ્રોજેકટો પૈકી કુલ ૬ પ્રોજેક્ટ વિવિધ કારણસર પડતા મૂકાયેલ છે. જે આ સાથે પરિશિષ્ટ ૧ મુજબ છે.

(૩) ખંડ-૨ સંદર્ભમાં લાગુ પડતું નથી.

પરિશિષ્ટ -- ૧
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમીટ-૨૦૦૩ દરમ્યાન મળેલા એમ.ઓ.યુ./આઇ.ઈ.એમ./પ્રોજેક્ટ પ્રપોઝલની સ્થિતિ.

પ્રોજેકટ નંબર ૧	કંપનીનું નામ ૨	પ્રોજેકટ ૩	સ્થળ ૪	રોકાણ (રૂા. કરોડમાં) ૫	પરિસ્થિતિ ૬
પડતા મૂક્યા.					
૧૭.	મીના એજન્સી	હાઈ એલ્યુમિનીયમ સીમેન્ટ	કચ્છ	૨૦,૦૦	ઉદ્યોગકારો તરફથી પ્રોજેક્ટોમાં ઉત્સુકતા ન બતાવવાના કારણે તેમજ કેટલાક પ્રોજેક્ટ વાયેબલ ન જણાતાં પડતા મુકવામાં આવેલ છે.
૨૮.	શ્રી મેટાલીકસ લીમીટેડ	ઈન્ટીગ્રેટેડ સ્ટીલ પ્લાન્ટ	કચ્છ	૩૦૪.૦૦	
૫૫.	પૌરર એનર્જી અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર પ્રા.લી.	પાવર પ્રોજેક્ટ	રાધનપુર	૧૫૦૦.૦૦	
૬૪.	મિ.બ્રિજ ભૂષન	પ્રિ-એસઈએ. ટ્રેનીંગ ફોર મરચન્ટ નેવી.	--	--	
૭૦.	ટીસીજીએલ	ટેક એસીસ્ટન્ટ	--	--	

પ્રોજેકટ નંબર ૧	કંપનીનું નામ ૨	પ્રોજેકટ ૩	સ્થળ ૪	રોકાણ (રૂા. કરોડમાં) ૫	પરિસ્થિતિ ૬
	વર્લ્ડ ટૂરીઝમ ઓર્ગેનાઈઝેશન સાથે એમ.ઓ.યુ.	પ્રોજેક્ટ			
૭૩.	ટીસીજીએલ વિસ્તાસ્ટાર હોટલ્સ એન્ડ લ્યૂઝર્સ સાથે એમ.ઓ.યુ.	સ્પેશ્યલ એન્ટરટેઈન્મેન્ટ ઝોન	--	૧૪૦૦.૦૦	

દસાડા અને લખતર તાલુકામાં જી.આઈ.ડી.સી. સ્થાપવાની કામગીરી

૮૦૭૪ **શ્રી મનહરલાલ મ.મકવાણા**(દસાડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા અને લખતર તાલુકામાં જી.આઈ.ડી.સી. સ્થાપવાની કાર્યવાહી તા. ૨૫-૧-૦૫ ના રોજની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે?

જવાબ

દસાડા તાલુકાના ખારાઘોડા મુકામે ૧-૯૬-૨૭ હેકટર સરકારી તથા ૧૧૧-૧૦-૧૯ હેકટર ખાનગી જમીન મળી કુલ ૧૧૩-૦૬-૪૬ હેકટર જમીનમાં વસાહત સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. પરંતુ નીચેના કારણોસર ખારાઘોડા વસાહતનું આયોજન પડતું મુકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે.

(અ) સરકારી જમીન અંગે ગણોત ધારા કેસ તથા નામદાર હાઈકોર્ટમાં દાખલ થયેલ કેસમાં હાઈકોર્ટના મનાઈ હુકમના લીધે સરકારી જમીનની માંગણી કલેકટરશ્રીએ નામંજૂર કરેલ હોવાથી,

(બ) મીઠા ઉદ્યોગ સિવાય અન્ય ઉદ્યોગ આવવાની નહિવત શક્યતાઓ હોવાથી,

(ક) વસાહત માટે પૂરતી માગણી ન હોવાથી,

જ્યારે લખતર તાલુકામાં લખતર ખાતે ૩-૮૨-૪૩ હેકટર ખાનગી જમીનમાં વસાહતની સ્થાપના કરાયેલ છે. હાલ ઉકત વસાહતમાં ૧૬ પ્લોટોની ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે.

ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરીના આધુનિકરણની યોજના

૯૩૨૮ **શ્રી મધુભાઇ બા. શ્રીવાસ્તવ** (વાઘોડીયા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે** -

પ્રશ્ન

(૧) રાજયની ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરીના આધુનિકરણની કોઈ યોજના અમલમાં છે કે કેમ

જવાબ

(૧) હા, જી.

આધુનિકરણની કોઈ યોજના અમલમાં છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૦૩માં તે પેટે કેટલી રકમ ખર્ચવામાં આવી, અને

(૨) પોલીસ દળ આધુનિકરણ યોજના હેઠળ ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી માટે કુલ રૂા. ૪૬૦/- લાખનું અનુદાન ફાળવેલ હતુ જેમાંથી સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષમાં રૂા. ૪૫૭.૯૬/- લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

સદર ખર્ચ નાણાંકીય વર્ષ મુજબ ગણાતો હોવાથી તે મુજબની વિગતો રજૂ કરી છે.

(૩) આ રકમ પૈકી કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી કોઈ રકમ મેળવવામાં આવેલ છે કે કેમ ?

(૩) આ યોજના ૬૦ ટકા કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના છે. આથી ૬૦ ટકા ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર ભોગવે છે.

અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં સલાહકાર સમિતિની રચના અને મુદત

૮૬૨૫ **ડૉ. જીતેન્દ્રભાઈ બા.પટેલ**(સાબરમતી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે** -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ સ્ટેશનોમાં સલાહકાર સમિતિની રચના છેલ્લે ક્યારે થઈ, અને	(૧) સમગ્ર અમદાવાદ શહેર માટે પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવાની હોય છે, જેની છેલ્લે ગૃહ વિભાગના તા. ૨૪/૬/૯૯ ના ઠરાવથી રચના કરાયેલ.
(૨) આ સલાહકાર સમિતિની મુદત કેટલા સમય માટેની હોય છે ?	(૨) સરકારી સભ્યો સિવાયના બીન સરકારી સભ્યોની નિમણૂંકની મુદત બે વર્ષની અથવા નવી સમિતિની રચના થાય- બેમાંથી જે વહેલું હોય ત્યાં સુધીની હોય છે. જ્યારે સંસદ સભ્યશ્રીઓ/ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમના હોદ્દાની મુદત સુધી બિનસરકારી સભ્યો તરીકે નિમણૂંક પામેલ ગણાશે.

દાહોદ જિલ્લા પોલીસ સંવર્ગવાર મહેકમ અને ખાલી જગ્યાઓ

૯૩૭૨ **શ્રી મહેશભાઈ સો. ભુરિયા**(લીમડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે** -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લા પોલીસ માટેનું સંવર્ગવાર મહેકમ કેટલું મંજૂર થયેલ છે,	(૧) સામેલ પત્રક--૧ મુજબ
(૨) મંજુર મહેકમમાં જિલ્લાની નવરચના બાદ ઉભી થયેલી નવીન જગ્યાઓનો સમાવેશ થયેલ છે કે કેમ ,	(૨) હા, જી.
(૩) મંજુર મહેકમ પૈકી સંવર્ગવાર ભરેલ જગ્યાઓ અને ખાલી જગ્યાઓ કેટલી છે,	(૩) સામેલ પત્રક-૨ મુજબ
(૪) ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ભરેલ નથી,	(૪) અને (૫) વહીવટી કારણોસર થોડા સમયથી જગ્યાઓ ખાલી છે.
(૫) ખાલી જગ્યાઓ રહેવાના કારણો શા છે, અને	
(૬) ખાલી જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાં આવશે ?	(૬) જેમ બને તેમ વહેલી.

પત્રક-૧
મંજૂર મહેકમની વિગતો

સંવર્ગ	મંજૂર જગ્યા
પોલીસ અધિક્ષક	૧
નાયબ પોલીસ અધિક્ષક	૩
પોલીસ ઈન્સ્પેકટર	૪
પો.સ.ઈ.	૨૧
એ.એસ.આઈ. બિન-હથિયારી	૮૩
એ.એસ.આઈ. હથિયારી	૨૩
એ.એસ.આઈ. મહિલા	૦૫
અ.હે.કો.	૫૯
આ.હે.કો.	૪૪
મહિલા હે. કો.	૮
બિન-હથિયારી પો.કો.	૨૦૩
હથિયારી પો.કો.	૨૩૭
મહિલા પો. કો.	૪૦

પત્રક-૨

ભરેલ જગ્યાઓ અને ખાલી જગ્યાઓની વિગતો

સંવર્ગ	મંજૂર	હાજર	ખાલી
પોલીસ અધિક્ષક	૧	૧	---
નાયબ પોલીસ અધિક્ષક	૩	૧	૨
પોલીસ ઈન્સ્પેકટર	૪	૭	+૩
પો.સ.ઈ.	૨૧	૧૩	-૮
એ.એસ.આઈ. બિન-હથિયારી	૮૩	૭૭	-૬
એ.એસ.આઈ. હથિયારી	૨૭	૨૬	-૧
એ.એસ.આઈ. મહિલા	૫	૧	-૪
હે.કો. બિન હથિયારી	૫૯	૫૯	-
હે.કો. હથિયારી	૪૪	૪૪	-
હે.કો. મહિલા	૦૮	૦૨	-૬
પો.કો. બિન હથિયારી	૨૦૩	૧૯૯	-૪
પો. કો. હથિયારી	૨૩૭	૨૨૨	-૧૫
પો.કો. મહિલા	૪૦	૧૦	-૩૦

નર્મદા બંધની ૧૨૧.૯૨ મીટર ઊંચાઈએ રાજ્યને થનાર લાભ અંગે

૮૮૬૩ **શ્રી હરજીવન હી. પટેલ**(ધાનેરા): **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં રાજ્યને શો લાભ થશે,	(૧) નર્મદા બંધની મુખ્ય છલતીની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવાનું આયોજન છે, જેનો ૧૬ % ભાગ ગુજરાત રાજ્યને મળશે. સને ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન આશરે ત્રણ લાખ હેકટર વિસ્તાર સિંચાઈ હેઠળ આવરી લેવાનું આયોજન છે અને પીવાનું પાણી શક્ય તેટલી વધારે જગ્યાએ આપવામાં આવશે.

(૨) ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી કયા સ્તરે પડતર છે, અને	(૨) નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પર્યાવરણ પેટા જુથ દ્વારા તેમની ૪૧મી બેઠકમાં તારીખ ૬-૧-૨૦૦૫ના રોજ મંજૂરી અપાયેલ છે. આ જ પ્રકારની મંજૂરી નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પુનઃવસન પેટા જુથ દ્વારા મેળવવાની બાબત પ્રગતિ હેઠળ છે, અને આ મંજૂરી મળ્યા બાદ નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટી દ્વારા બંધનું કામ ૧૨૧.૯૨ સુધી આગળ વધારવા માટે ટૂંક સમયમાં મંજૂરી મળવાની સંભાવના છે.
(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર વધારવા માટે કેટલો ખર્ચ થશે ?	(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી લઈ જવા માટે આશરે રૂા. ૧૨૫ કરોડનો ખર્ચ થશે.

રાજ્યમાં વિદેશ મોકલવાના નામે છેતરપીંડીના બનાવો

૯૩૮૭ **શ્રી રાકેશ રાવ**(માતર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જાન્યુઆરી, ૦૫ની સ્થિતિએ એક વર્ષમાં રાજ્યમાંથી વિદેશ મોકલવાના બહાના હેઠળ નિર્દોષ નાગરિકોને છેતરતી ટોળકીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલા કેટલા ગુનાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે,	(૧) ૭૬ ગુનાઓ.
(૨) આવા લોકોની વાતોથી લોકો છેતરપીંડીનો ભોગ ન બને તે માટે રાજ્ય સરકારે લોક જાગૃતિ માટે શું પ્રયત્નો કર્યા છે,	(૨) પકડાયેલા ઈસમો વિરૂદ્ધ ગુનાઓ દાખલ કરી સખત શિક્ષા થાય તે માટે નામદાર કોર્ટમાં મોકલી આપવામાં આવે છે.
(૩) પોલીસના કેટલાક અમલદારો આવી ટોળકીના સાથમાં રહી મદદ કરતા હોવાની કોઈ હકીક્ત જાણમાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૩) ના, જી.
(૪) જો હા, તો આવા અમલદારો સામે રાજ્ય સરકારે શી કાર્યવાહી કરેલ છે ?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી મળી આવેલ બિનવારસી લાશો

૮૩૯૭ **શ્રી ધનરાજભાઈ કેલા**(વઢવાણ): **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તારીખ ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં બિનવારસી લાશો કેટલી મળેલ છે,	(૧) ૯૩ (ત્રાણું)
(૨) તેમાંથી કેટલા કેસોનો ઉકેલ આવ્યો અને કેટલા કેસો ઉકેલવાના બાકી છે, અને કયારથી બાકી છે, અને	(૨) ૩૬ (છત્રીસ) કેસોનો ઉકેલ આવ્યો ૫૭ (સત્તાવન) કેસો ઉકેલવાના બાકી છે. વર્ષ ૨૦૦૨-૧૭, ૨૦૦૩-૨૩, ૨૦૦૪-૧૭ થી બાકી છે.
(૩) બાકીના કેસો ઝડપથી ઉકેલવા માટે સરકારે શું આયોજન કરેલ છે ?	(૩) લાશોના ફોટાઓની ટી.વી.માં તથા સમાચાર પત્રોમાં પ્રસિધ્ધિ, આજુબાજુના રહીશોની પુછપરછ જેવા ઉકેલ લાવવાના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવેલ છે.

મધ્યસ્થ જેલમાં ઈલેક્ટ્રોનિક વીડિયો લીકેજ સીસ્ટમથી આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા અંગે

૮૮૫૧ **શ્રી કાંતિલાલ રા. લકુમ**(બાવળા)**: માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદ શહેરમાં આવેલી મધ્યસ્થ જેલમાં ઈલેક્ટ્રોનિક વિડિયો લીંકેજ સીસ્ટમથી આરોપીઓ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા માટેની વ્યવસ્થા અમલમાં છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો વર્ષ, ૨૦૦૪માં કુલ કેટલા આરોપીઓને આ સીસ્ટમ હેઠળ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા ?	(૨) આ સીસ્ટમ હેઠળ વર્ષ ૨૦૦૪માં કુલ-૩૬૭૩ આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવ્યા.

સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં જી.આઈ.ડી.સી.નું ખાત મુહુર્ત

૯૧૮૭ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા**(ભીલોડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં જી.આઈ.ડી.સી.નું ખાત મુહુર્ત ક્યારે કરવામાં આવ્યું, અને	(૧) ભિલોડા તાલુકાના વાંકાનેર મુકામે ઔદ્યોગિક વસાહતનું ખાત મુહુર્ત તા. ૨૬-૪-૨૦૦૨ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ જી.આઈ.ડી.સી. દ્વારા વાંકાનેર (ભિલોડા) વસાહત ખાતે ૧૬ ઉદ્યોગોને જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે.
(૨) છેલ્લા બે વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ નવરાત્રી મહોત્સવ, પતંગ મહોત્સવ અને વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતથી કેટલા ઉદ્યોગો ભિલોડા તાલુકામાં આવવાના છે?	(૨) નવરાત્રી, પતંગ મહોત્સવ અને વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત મહોત્સવ સમયે ભિલોડા તાલુકામાં ઉદ્યોગ સ્થાપવા કોઈ દરખાસ્ત મળેલ નથી.

માંગરોળ અને શીલ પોલીસ સ્ટેશન નીચે બનેલા ખૂનના ગુનાઓ

૮૫૪૧**ડૉ. ચંદ્રીકાબેન કા. ચુડાસમા**(માંગરોળ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) છેલ્લા બે વર્ષમાં ડિસે. ૦૪ની સ્થિતિએ જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના માંગરોળ અને શીલ પોલીસ સ્ટેશન નીચે કેટલા ખૂનના ગુનાઓ નોંધાયા, અને

(૨) આ કેસોમાં કેટલા ગુનેગારો પકડાયા ?

જવાબ

(૧) નોંધાયેલ ખૂનના ગુનાઓની સંખ્યા

પો. સ્ટે.	સન-૨૦૦૩	સન-૨૦૦૪	કુલ
માંગરોળ	૦૩	૦૨	૦૫
શીલ	૦૨	૦૨	૦૪

(૨) પકડાયેલા ગુનેગારોની સંખ્યા

પો. સ્ટે.	સન-૨૦૦૩	સન-૨૦૦૪	કુલ
માંગરોળ	૨૪	૦૩	૨૭
શીલ	૧૧	૦૫	૧૬

બારડોલી તથા માંડવી પોલીસ સ્ટેશનમાં મંજૂર અને ખાલી પોલીસ મહેકમ

૮૫૭૦ **શ્રી અનિલકુમાર મો. પટેલ**(બારડોલી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) બારડોલી તથા માંડવી પોલીસ સ્ટેશનમાં સંવર્ગવાર કેટલું મહેકમ મંજૂર થયેલ છે,	(૧) આ અંગે પત્રક-૧ સામેલ છે.
(૨) તે પૈકી ડિસેમ્બર - ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કયા કયા પોલીસ સ્ટેશન અને આઉટ પોસ્ટ ચોકીમાં	(૨) આ અંગે પત્રક-૨ સામેલ છે.

કેટલી જગ્યા ખાલી છે,

(૩) અપુરતા સ્ટાફથી ગુનેગારોને પકડી શકાતા નથી, એ વાતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને

(૪) જો હા, તો આ ઘટ કયારે પૂરવામાં આવશે ?

(૩) ગુનેગારોના નામઠામ ખુલેલ ન હોવાના કારણે પકડાયેલ નથી.

(૪) ભરતી અંગેની પ્રક્રીયા પૂર્ણ થયેથી.

પત્રક-૧

મંજૂર મહેકમની વિગતો

પો. સ્ટે.	મંજૂર મહેકમ						
	PI	PSI	UHC	UPC	AHC	APC	કુલ
(૧) બારડોલી	૧	૨	૧૬	૧૯	૬	૨૪	૬૮
-કડોદ આ. પો.	--	--	૧	૪	-	-	૫
-મઢી આ. પો.	--	--	૨	૫	--	--	૭
સરભોણ આ.પો.	--	--	--	૨	--	--	૨
(૨) માંડવી	--	૨	૧૪	૨૫	૯	૨૯	૭૯
-અરેઠ આ.પો.	--	--	૧	૨	--	--	૯
-તડકેશ્વર આ.પો.	--	--	૧	૨	--	--	૩

પત્રક-૨

ખાલી જગ્યાની વિગતો

પો. સ્ટે.	ખાલી જગ્યા						
	PI	PSI	UHC	UPC	AHC	APC	કુલ
(૧) બારડોલી	--	--	--	--	+૧	-૧૨	--
-કડોદ આ. પો.	--	--	--	-૨	-	-	-
-મઢી આ. પો.	--	--	--	-૩	--	--	--
-સરભોણ આ.પો.	--	--	--	-૧	--	--	--
(૨) માંડવી	--	-૧	--	-૯	-૧	-૧૧	-૨૨
-અરેઠ આ.પો.	--	--	--	-૧	--	--	--
-તડકેશ્વર આ.પો.	--	--	--	--	--	--	--

ચોટીલા અને સાયલા તાલુકામાં મંજૂર થયેલા ૬૬ કે.વી. સબસ્ટેશનો

૮૮૦૭ **શ્રી પોપટભાઈ સ. જીંજરીયા** (ચોટીલા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા અને સાયલા તાલુકામાં સને ૨૦૦૫-૦૬ અને ૨૦૦૬-૦૭ માટે કેટલા ૬૬ કે.વી. સબસ્ટેશન મંજૂર થયેલ છે?

જવાબ

વર્ષ	તાલુકાનું નામ	મંજૂર થયેલ સબસ્ટેશનનું નામ
૧	૨	૩
(૧) ૨૦૦૫-૦૬	ચોટીલા સાયલા	તરણેતર શુન્ય
(૨) ૨૦૦૬-૦૭	ચોટીલા સાયલા	લાખણકા શુન્ય

ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા ન્યાયાધીશો અને એડવોકેટો માટેનો તાલીમ કોર્ષ

૯૩૩૧ **શ્રી કાંતીભાઈ ત્રિ. ભીલ**(નસવાડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યની ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા ન્યાયધીશો અને એડવોકેટો માટે કોઈ

જવાબ

(૧) રાજ્યની ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા ન્યાયાધીશો માટે ગુન્હાની તપાસ માટે વપરાતી અદ્યતન

પ્રકારના તાલીમ કોર્ષ યોજવામાં આવે છે કે કેમ, અને	વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિઓથી વાકેફ કરવા માટે નિયમીત ધોરણે તાલીમ કોર્ષનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
(૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૦૪માં કેટલા ન્યાયધીશો અને એડવોકેટોએ આ તાલીમ કોર્ષમાં હાજરી આપેલ છે ?	(૨) સને ૨૦૦૪ના વર્ષમાં કુલ -૪૧૬ ન્યાયાધીશોને ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરીની કામગીરીની જાણકારી તેમજ આ અંગેની જરૂરી તાલીમ આપેલ છે.

ધોલેરા બંદર વિકસાવવાનો પ્રોજેકટ

૯૩૨૧ **શ્રી ભરતભાઈ પંડયા** (ધંધુકા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (બંદરો)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
ધોલેરા બંદર વિકસાવવા માટેનો પ્રોજેકટ હાલ કયા તબકકામાં છે ?	ધોલેરા બંદરનો પ્રોજેકટ હાલ પર્યાવરણ મંજૂરી મેળવવાના તબકકામાં છે.

ધરમપુર તાલુકામાં વડાપ્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના હેઠળ મળેલી અરજીઓ

૮૮૪૬ **શ્રી છનાભાઈ કો. ચૌધરી**(ધરમપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ધરમપુર તાલુકામાં વડાપ્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના અન્વયે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રમાં કેટલી અરજીઓ તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં મળી, અને	(૧) ૯૭
(૨) તે અન્વયે કેટલી અરજીઓ મંજૂર થઈ ?	(૨) ૫૮

અમદાવાદ શહેરમાં જી.એસ.ટી.સી. હેઠળની બંધ મીલો અને કામદારોને ચૂકવાયેલ નાણા અંગે

૮૬૧૬ **શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઉ. વાઘેલા(શહેર કોટડા) : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ અમદાવાદ શહેરમાં જી.એસ.ટી.સી. હેઠળ કુલ કેટલી મીલો બંધ છે,	(૧) ૧૨ મીલો તા. ૬-૨-૯૭ થી લીકવીડેટર હસ્તક છે.
(૨) આ બંધ મીલના કામદારોને કેટલા નાણાં ચૂકવાયા છે અને કેટલા નાણાં ચૂકવવાના બાકી છે, અને	(૨) રૂા. ૨૧૮ કરોડનું ચૂકવણું થયેલું છે. કોઈ નાણાં અત્રેથી ચૂકવવાના બાકી નથી.
(૩) આ બાકી નાણાં ક્યારે ચૂકવવામાં આવશે ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ઉનાવા ખાતે મીરાંદાતરમાં હિન્દુ યુવતીઓને ધર્માતરણ કરાવવા અંગે ફરિયાદ

૯૩૮૧ **શ્રી કાંતિલાલ ધ.કચોરિયા**(પાલનપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઉંઝા તાલુકાના ઉનાવા ગામે મીરાંદાતારમાં હિન્દુ યુવતીઓને ધર્માંતરણ કરવા બાબતે સરકાર સમક્ષ તાજેતરમાં કોઈ ફરિયાદ મળેલ છે કે કેમ, અને	(૧) ના, પરન્તુ માનસીક અસ્વસ્થ બાળાને ભગાડી જઈ તેની માનસીક સ્થિતિનો ગેરલાભ ઉઠાવી ધર્માન્તર કરી લગ્ન કરી લેવાની રજુઆત તા. ૬-૪-૦૪ના રોજ મળતા ઉંઝા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર. નં. ૮૮/૦૪ ઈ.પી.કો. ક. ૩૬૩, ૩૬૬(ક), ૩૪ મુજબ દાખલ કરવામાં આવેલ.
(૨) જો હા, તો આ અંગે સરકાર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે કે કેમ ?	(૨) બે તહોમતદારોને પકડેલ છે અને બંને વિરૂદ્ધ તા. ૪-૧૧-૦૪ના રોજ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ કરેલ છે.

સરદાર સરોવર યોજના વિદ્યુત મથકોની ક્ષમતા

૮૮૭૭ **શ્રી રતિલાલ ગો. સુરેજા**(માણાવદર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરદાર સરોવર યોજના વિદ્યુત મથકોની ક્ષમતા શું છે, અને	(૧) સરદાર સરોવર યોજનામાં બે જળ વિદ્યુત મથકો છે. (૧) નહેર આમુખ વિદ્યુત મથક અને (૨) નદીતળ ભૂગર્ભ વિદ્યુત મથક નહેર આમુખ વિદ્યુત મથકની સ્થાપિત ક્ષમતા ૨૫૦ મેગાવોટની છે, જ્યારે નદીતળ ભૂગર્ભ વિદ્યુત મથકની સ્થાપિત ક્ષમતા ૧૨૦૦ મેગાવોટની છે. આમ વિદ્યુત મથકોની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા ૧૪૫૦ મેગાવોટની છે.
(૨) ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઈએ વિદ્યુત ઉત્પાદન કેટલું થાય છે ?	(૨) ડેમમાં પાણીની ૧૧૦.૬૪ મીટરની સપાટીએ નહેર આમુખ વિદ્યુત મથકના એક એકમમાંથી ૧૮ મેગાવોટ વિદ્યુત ઉત્પાદન થાય, જ્યારે નદીતળ ભૂગર્ભ વિદ્યુત મથકના એક એકમમાંથી ૧૬૪ મેગાવોટ વિદ્યુત ઉત્પાદન થાય.

અમદાવાદ શહેરમાંથી આતંકવાદ ધારા હેઠળ નોંધવામાં આવેલા કેસો

૮૮૫૨ **શ્રી વજુભાઈ પ. ડોડિયા** (વિરમગામ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરમાંથી વર્ષ ૨૦૦૩ અને વર્ષ ૨૦૦૪ દરમ્યાન કેટલા લોકો ઉપર આતંકવાદ વિરોધી ધારા હેઠળ કેસો નોંધવામાં આવેલા છે,	(૧) ૧૨૦
(૨) આ કેસોની રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની "પોટા રીવ્યુ સમિતિ" દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવી છે કે કેમ, અને	(૨) હા, જી
(૩) આ સમીક્ષાના અંતે કેટલા લોકો ઉપરથી પોટાની કલમો રદ કરવામાં આવી ?	(૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રચવામાં આવેલ પોટા રીવ્યુ કમીટીએ ૩ આરોપીની અરજી બાબતે કરેલ સમીક્ષા અન્વયે પોટાની કલમ-૨૨(૨)(૫) યથાવત રાખવામાં આવી છે. અને કલમ-૩(૩), ૨૦(૧) તેમજ ૨૧(૧) રદ કરવામાં આવેલ છે. કેન્દ્ર સરકારની પોટા રીવ્યુ કમિટિ તરફથી કોઈ આરોપી બાબતે રાજ્ય સરકારને ભલામણ મળેલ નથી.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એટ્રોસીટીના કેસો અંગે

૮૩૩૫ **શ્રી દોલતભાઈ પરમાર**(વડગામ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં એટ્રોસીટીઝ એકટ હેઠળ કેટલા ગુનાઓ નોંધાયા છે,	(૧) ૧૧૩
(૨) તેમાંથી કેટલા કેસો કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે,	(૨) ૧૦૫
(૩) કેટલા કેસોમાં તહોમતદારોને સજા થઈ છે અને કેટલા કેસોમાં નિર્દોષ છૂટ્યા છે,	(૩) તમામ કેસો કોર્ટમાં પેન્ડીંગ છે.

(૪) કેટલા કેસોમાં ડી.વાય.એસ.પી. કક્ષાના અધિકારીએ કેસની તપાસ ન કરવાથી તેમજ જાતિ અંગેનું સર્ટિફીકેટ પોલીસે રજુ ન કરવાથી કેસોમાં હાર થઈ છે, અને

(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૫) આ અંગે સરકારે સંબંધિત અધિકારીઓ સામે શાં પગલાં લીધાં છે ?

(૫) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ધારાસભ્યશ્રી ઉપર હુમલો કરી લૂંટ કરવાનો બનાવ

૮૯૩૨ **શ્રી હેમાજી દ. રાજપૂત** (વાવ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તાજેતરમાં વાવ મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય પર હુમલો કરી ૨૦ હજાર રૂપિયાની લૂંટ કરી ભાગી ગયેલ હુમલાખોરો સામે ફરિયાદ આપ્યા પછી કાર્યવાહી ન થવાના કારણો શું છે, અને	(૧) ફરિયાદના આધારે ગુન્હો વિસનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફ.ગુ.ર.નં. ૩૦૭/૦૪ દાખલ કરેલ છે અને પોલીસ તરફથી હુમલાખોરોને શોધવાના પ્રયત્નો સતત અને સઘનરીતે ચાલુ છે.
(૨) હુમલાખોરોના નામ આપવા છતાં તેમની સામે કાર્યવાહી ન કરવાના શાં કારણો છે ?	(૨) આપેલ હુમલાખોરના નામો ચોક્કસ નથી. તપાસ ચાલુ છે.

અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ શહેર તથા જિલ્લામાંથી પકડાયેલા ઘાતક શસ્ત્રો

૮૮૯૮**શ્રી ધીરૂભાઈ હ. ગજેરા**(સુરત શહેર ઉત્તર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ શહેર તથા જિલ્લામાંથી કેટલા અને કયા કયા ઘ ાતક શસ્ત્રો પકડાયા,	(૧) ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ શહેર તથા જિલ્લામાંથી કુલ ૧૦૩૬ ઘાતક શસ્ત્રો પકડાયેલ છે, આ ઘાતક શસ્ત્રોમાં દેશી રીવોલ્વર, વિદેશી રીવોલ્વર, દેશી પિસ્તોલ, વિદેશી પિસ્તોલ, દેશી તમંચા, દેશી ગન, વિદેશી ગન, દેશી બોમ્બ, કારતુસ, એ.કે. ૫૬, ૪૭ રાયફલસ, રોકેટ લોન્ચર અને વિદેશી બોમ્બનો સમાવેશ થાય છે.
(૨) આ હથિયારો કયા દેશની બનાવટના હતા,	(૨) આ હથિયારો યુ.એસ.એ. પાકિસ્તાન, ફ્રાન્સ, જર્મન, ઈટાલી, ભારત વિગેરે દેશોની બનાવટના હતા.
(૩) કેટલા ગુનેગારો પકડાયા અને કેટલા ફરાર છે, અને	(૩) ઉપરોકત ઘાતક શસ્ત્રોના કેસોમાં કુલ -૧૩૧૧ આરોપી પકડાયેલ છે, અને ૪૧ આરોપીઓ ફરાર છે.
(૪) તેમની સામે કયા કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી ?	(૪) પકડાયેલ આરોપી વિરૂધ્ધ ગુના દાખલ કરી હથિયારો સંબંધે ઘનિષ્ઠ તપાસ હાથ ધરવામાં આવે છે, અને તપાસના અંતે કાયદા અનુસારની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

નર્મદા બંધની ઊંચાઈએ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં રાજ્યને થનાર લાભ

૮૮૬૬ **શ્રી સી. ડી. પટેલ**(પેટલાદ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં રાજ્યને શું લાભ થશે,	(૧) નર્મદા બંધની મુખ્ય છલતીની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં આશરે વાર્ષિક ૧૫૦ કરોડ યુનિટ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવાનું આયોજન છે, જેનો ૧૬ % ભાગ ગુજરાત રાજ્યને મળશે. સને ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન આશરે ૩ (ત્રણ) લાખ હેકટર વિસ્તાર સિંચાઈ હેઠળ

	આવરી લેવાનું આયોજન છે અને ઘરગથ્થું વપરાશ માટે અને ઔદ્યોગિક એકમોને પાણી આપવામાં આવશે.
(૨) ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી કયા સ્તરે પડતર છે, અને	(૨) નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પર્યાવરણ પેટા જુથ દ્વારા તેમની ૪૧મી બેઠકમાં તારીખ ૬-૧-૨૦૦૫ના રોજ મંજૂરી અપાયેલ છે. આ જ પ્રકારની મંજૂરી નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પુનઃવસન પેટા જુથ દ્વારા મેળવવાની બાબત પ્રગતિ હેઠળ છે, અને આ મંજૂરી મળ્યા બાદ નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટી દ્વારા બંધનું કામ ૧૨૧.૯૨ સુધી આગળ વધારવા માટે ટૂંક સમયમાં મંજૂરી મળવાની સંભાવના છે.
(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર વધારવા માટે કેટલો ખર્ચ થશે ?	(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી લઈ જવા માટે આશરે રૂા. ૧૨૫ કરોડનો ખર્ચ થશે.

સુરત શહેરમાં મંજૂર અને ખાલી પોલીસ મહેકમ

૯૧૮૪ **શ્રી મનીષ ન. ગીલીટવાલા** (સુરત શહેર પૂર્વ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ સુરત શહેરમાં પોલીસ મહેકમ સંવર્ગવાર કેટલું મંજૂર થેયલ છે,	(૧) આ સાથે સામેલ પત્રક-૧ મુજબ છે.
(૨) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને	(૨) આ સાથે સામેલ પત્રક-૨ મુજબ
(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે?	(૩) ભરતી અંગે પ્રક્રીયા પૂર્ણ થયેથી.

પત્રક-૧

સુરત શહેરમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ

અ.નં.	સંવર્ગ	મંજૂર મહેકમ
૧	પોલીસ કમિશનર	૧
૨	સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર	૧
૩	અધિક પોલીસ કમિશનર	૨
૪	નાયબ પોલીસ કમિશનરશ્રી	૪
૫	મદદનીશ પોલીસ કમિશનરશ્રી	૧૦
૬	પોલીસ ઈન્સ્પેકટર	૩૦
૭	પો.સ.ઈ.	૨૦૨
૮	એ.એસ.આઈ. બિન-હથિયારી	૩૫૮
	હથિયારી	૯૮
	વુમન	૧૯
	ટોટલ	૪૭૫
૯	હેડ કોન્સ્ટેબલ બિન-હથિયારી	૫૪૧
	હથિયારી	૧૫૦
	વુમન	૨૮
	ટોટલ	૭૧૯
૧૦	પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બિન-હથિયારી	૧૨૮૬
	હથિયારી	૬૫૬
	મહિલા	૬૮
	કુલ	૨૦૧૦

પત્રક-૨
ખાલી જગ્યાઓની વિગત

અ.નં.	જગ્યાનું નામ	ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા	કેટલા સમયથી ખાલી છે			
			છ માસ સુધી	છ માસથી ૧૨ માસ	૧૨ માસથી ૨ વર્ષ	૨ વર્ષ ઉપર
૧	મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર	૩	૧	૨	--	--
૨	પો.સ.ઈ.	૭૪	૮	૬	-	૬૦
૩	એ.એસ.આઈ.(આર્મ/અનાર્મ /વુમન)	૪૯	૧૦	૯	૩૦	-
૪	હેડ કોન્સ્ટેબલ (આર્મ/અનાર્મ/વુમન)	૩૯	૧૦	૧૧	૧૩	૫
૫	પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (આર્મ/અનાર્મ/વુમન	૨૧૩	૨૧	૧૯	૭૭	૯૬
	કુલ	૩૭૮	૫૦	૪૭	૧૨૦	૧૬૧

વૈશ્વિક મૂડી રોકાણ વધારવા માટે રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓનો વિદેશ પ્રવાસ

૮૨૮૪**શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં વૈશ્વિક મૂડી રોકાણ વધારવા માટે રાજ્યના કયા કયા મંત્રીઓએ ક્યારે અને કયા કયા દેશોમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લાં છ માસમાં પ્રવાસ કર્યો,

જવાબ

(૧) વૈશ્વિક મૂડી રોકાણ વધારવા ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ સમિટ-૨૦૦૫ના ઉપક્રમે નીચે જણાવ્યા મુજબ મંત્રીશ્રીઓએ જુલાઈ-૨૦૦૪ થી ૩૧ ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ દરમ્યાન વિદેશ પ્રવાસ કરેલ

ક્રમ	નામ	વિદેશ પ્રવાસ તારીખ.	દેશો.
૧.	શ્રી નરેન્દ્ર મોદી મા. મુખ્યમંત્રીશ્રી	૨૭-૧૧-૨૦૦૪ થી ૨/૧૨/૨૦૦૪.	સિંગાપુર, હોંગકોંગ
૨.	શ્રી નરેન્દ્ર મોદી મા. મુખ્યમંત્રીશ્રી	૧૨-૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪	ઓસ્ટ્રેલિયા
૩.	શ્રી નરોત્તમભાઈ પટેલ. મા.મંત્રીશ્રી, પાણી પુરવઠો અને શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસ્મા, મા.મંત્રીશ્રી, કૃષિ	૧૧-૧૨-૨૦૦૪ થી ૧૯-૧૨-૨૦૦૪	યુ. કે. બેલ્જીયમ
૪.	શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ મા.મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ અને શ્રી અનિલભાઈ પટેલ, મા.રા.ક.મંત્રીશ્રી ઉદ્યોગ.	૨૭-૧૧-૨૦૦૪ થી ૫-૧૨-૨૦૦૪	યુ.એસ.એ.
૫.	શ્રી આઈ.કે.જાડોજા મા.મંત્રીશ્રી, આરોગ્ય અને શ્રી કૌશિકભાઈ	૨૧-૧૧-૨૦૦૪ થી ૨૮-૧૧-	કેન્યા અને યુગાન્ડા

	પટેલ, મા.મંત્રીશ્રી ૨૦૦૪ મહેસૂલ
	૬. શ્રી અશોકભાઈ ભટ્ટ, ૧૦-૧૭ દુબઈ, માન.મંત્રીશ્રી કાયદો ડિસેમ્બર ઓમાન, અને શ્રી સૌરભભાઈ ૨૦૦૪ કતાર દલાલ મા.રા.ક.મંત્રીશ્રી, ઉર્જા.
(૨) પ્રવાસે ગયેલ અધિકારીગણ અને મંત્રીગણ માટે રાજ્ય સરકારે કુલ કેટલું ખર્ચ કર્યુ, અને	(૨) ઉપરોકત પ્રવાસ માટે ટીકીટો અને ભાડા-ભથ્થાં પેટે અત્યાર સુધીમાં (તા. ૮-૨-૨૦૦૫) કુલ રૂા. ૩૨,૭૩,૧૭૧-૦૦ ચુકવેલ છે.
(૩) કયા કયા દેશોમાં આ મીટીંગો કરવામાં આવી, અને	(૩) ઉપર્યુકત ખંડ (૧)માં જણાવેલ દેશોમાં મીટીંગો કરવામાં આવેલ છે.
(૪) આ મીટીંગોમાં શું થયું ?	(૪) ઉપરોકત દેશોમાં રાજ્ય સરકારના માનનીય મંત્રીશ્રી અને અન્ય મંત્રીશ્રીઓના નેજા હેઠળ ગયેલ પ્રતિનિધિ મંડળે ચર્ચામાં વ્યાપાર અને મૂડી રોકાણની તકો વધારવા માટે બિનનિવાસી ભારતીય, બિનનિવાસી ગુજરાતીઓ તેમજ આ દેશના વિવિધ ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ આ દેશોની કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ તેમજ અન્ય સંગઠનો, રાજકીય અગ્રણીઓ અને સરકારી અધિકારીઓ સાથે મુલાકાતો કરી આ દેશોમાંથી ગુજરાતમાં મૂડી રોકાણ વધે તે માટે પ્રયાસ કરવામાં આવેલ. આ મીટીંગોમાં આ દેશોના પ્રતિનિધિઓ તેમજ બિનનિવાસી ભારતીય અને બિનનિવાસી ગુજરાતીઓને વાયબ્રન્ટ ગુજરાત વૈશ્વિક નિવેષક પરિષદના તા. ૧૧ થી ૧૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૫ દરમ્યાન યોજાનાર કાર્યક્રમોની વિગતો આપી તેમને આ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા ખાસ આમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ તેમજ ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે ઉપલબ્ધ તકોથી માહિતગાર કરવામાં આવેલ.

વાડીનાર બંદરને કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટમાંથી મુકત કરવા કેન્દ્ર સરકારમાં રજૂઆત

૮૭૮૧ **શ્રી મુળુભાઈ હ. બેરા** (ભાણવડ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (બંદરો)** જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જામનગર જિલ્લામાં આવેલ વાડીનાર બંદરને સ્વતંત્ર રીતે વિકસાવવા, કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટમાંથી મુકત કરવા કેન્દ્ર સરકારને ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી વખત રજૂઆત કરવામાં આવી, અને,	(૧) ૧૮ વખત
(૨) આ બાબતે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોઈ નિર્ણયની રાજ્ય સરકારને જાણ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ?	(૨) હા,જી.

નર્મદાની મહેમદાવાદ શાખાની કામગીરી

૮૮૬૧ **શ્રી રાજેશભાઈ પાઠક**(બાલાસિનોર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) નર્મદા યોજનાની મહેમદાવાદ શાખાનું કામ ક્યારે પુરૂં થશે, અને,
(૨) આનાથી કયા વિસ્તારને કેટલી સિંચાઈનો ફાયદો થશે?

(૧) મહેમદાવાદ શાખા નહેરનું કામ ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.
(૨) આનાથી ખેડા જિલ્લાના નીચે જણાવેલ તાલુકાના ગામોને સિંચાઈનો ફાયદો થશે.

તાલુકો	પિયત વિસ્તાર (હેકટરમાં)
કઠલાલ	૧૬૭૯
કપડવંજ	૯૭૭૦
મહુધા	૧૯૬
મહેમદાવાદ	૭૪
	૧૧૭૧૯

ઉપલેટા તાલુકાના ખીરસરા ગામે પોલીસ અને લોકો વચ્ચે અથડામણ

૮૮૫૭**શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળીયા**(જસદણ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના ખીરસરા ગામે તા. ૧૫/૧/૦૫ના રોજ પોલીસ અને લોકો વચ્ચે અથડામણમાં કયા ગુન્હા સબબ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી, અને	(૧) ભાયાવદર પો.સ્ટે. ગુ.ર. નં. ૩૦૦૮/૦૫ હેઠળ ૬ ઈસમોની તથા ગુ.ર.નં. ૩/૦૫ હેઠળ ૩૨ ઈસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી. જ્યારે ગુ.ર. નં. ૫/૦૫ની તપાસ ચાલુ છે.
(૨) આ અન્વયે ઘરવખરીની તોડફોડ થઈ છે, તે અંગે સરકારે શી કાર્યવાહી કરી ?	(૨) ઘરવખરીની તોડફોડ થઈ નથી, તેથી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કચ્છ જિલ્લામાં ગૌવંશની હત્યા અંગે પાસા હેઠળ અટકાયત બાબત

૮૦૩૧ **શ્રી શિવજીભાઈ ક. આહીર** (ભૂજ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ૨૦૦૪ના વર્ષમાં કચ્છ જિલ્લામાં કેટલા ગૌ વંશ હત્યારાઓ કે ગૌ વંશની હત્યા માટે હેરાફેરી કરનારા તેમજ કતલખાનાના સંચાલકો સામે "પાસા" લાગુ પાડવામાં આવ્યા, અને	(૧) ૬(છ) વ્યકિતઓની પાસામાં અટકાયત કરવામાં આવેલ છે.
(૨) ઉપરોક્ત પૈકી કેટલા આરોપીઓએ આ પ્રકારના ગુન્હા વારંવાર કરેલા હતા ?	(૨) ઉપરોક્ત તમામ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ મુંબઈ પશુ સરંક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૫૪ તળે શિક્ષાપાત્ર એક-એક ગુન્હો નોંધાયેલ છે.

આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ આવરી લીધેલાં ગામો

૮૬૫૬ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધી. પરમાર**(બોરસદ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ નાં વર્ષમાં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલા ગામોનો ૧૦૦% વીજળીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ?	(૧) આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં ડીસેમ્બર-૦૪ ની સ્થિતિએ જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ સમાવિષ્ટ ગામોની વર્ષવાર/તાલુકાવાર ગામોની વિગતો નીચે મુજબ છે. જિલ્લાનું નામ :-આણંદ

વીજળીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ?

અ.ન.	તાલુકાનું નામ	૨૦03-૦૪માં સમાવિષ્ટ ગામોની સંખ્યા	૨૦૦૪-૦૫માં (ડીસે.૦૪) અંતિત ગામોની સંખ્યા	કુલ
૧.	આણંદ	૫	૩૪	૩૯
૨.	આંકલાવ	૦	૩૨	૩૨
૩.	બોરસદ	૦	૪૪	૪૪
૪.	સોજીત્રા	૫	૧૫	૨૦
૫.	પેટલાદ	૧૪	૨૬	૪૦
૬.	ખંભાત	૪	૧૪	૧૮
૭.	તારાપુર	૦	૨૨	૨૨
૮.	ઉમરેઠ	૪	૧૨	૧૬
	કુલ	૩૨	૧૯૯	૨૩૧
જિલ્લાનું નામ :- ખેડા				
૧.	નડીયાદ	૧૧	૧૬	૨૭
૨.	મહુધા	૦	૦	૦
૩.	ઠાસરા	૦	૨૫	૨૫
૪.	બાલાસિનોર	૦	૦	૦
૫.	કઠલાલ	૨	૪	૬
૬.	કપડવંજ	૦	૨૮	૨૮
૭.	મહેમદાવાદ	૯	૭	૧૬
૮.	ખેડા	૦	૧૭	૧૭
૯.	માતર	૦	૧૭	૧૭
૧૦.	વિરપુર	૨	૧	૩
	કુલ	૨૪	૧૧૫	૧૩૯

સુરત જિલ્લા અને શહેરમાં પાસા હેઠળ અટકાયત

૮૦૧૬ **શ્રી ધનસુખભાઈ ના. પટેલ** (ઓલપાડ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સુરત જિલ્લામાં અને શહેરમાં તા. ૧/૧/૨૦03 તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ દરમ્યાન પાસા હેઠળ કુલ કેટલા ઈસમોની અટકાયત કરવામાં આવી છે,	(૧) સુરત જીલ્લો: ૯૭, સુરત શહેર: ૬૫૦, કુલ: ૭૪૭
(૨) આ ઈસમો કયા કયા ગુન્હામાં સંડોવાયેલ હતા, અને	(૨) પ્રોહીબીશન ધારા ભંગના ગુનાઓ, ઈ.પી.કો. પ્રકરણ ૧૬, ૧૭ નીચેનાં વાહન ચોરી, ઘરફોડ ચોરી, લુંટ, ધાડ, અપહરણ, ખૂન, ધાકધમકી આપવાના અને વેશ્યાવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ અંગેના અનૈતિક વેપારના ગુનેગાર તેમજ ક્રુર વ્યક્તિઓ કે જેઓ ગેરકાયદેસર ગૌવંશ હત્યા કરવા સંદર્ભે પશુસંરક્ષણ ધારાભંગના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ હતા.

(૩) તે પૈકી પુરૂષો કેટલાં અને મહિલાઓ કેટલી ?	(૩) પુરૂષો -- ૬૧૩ મહિલાઓ -- ૧૩૪

રાજ્યમાં કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે તાલીમની જોગવાઈ બાબત

૮૮૮૫ **શ્રીમતી રમીલાબેન બે. બારા** (ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે મોટા પાયે તાલીમની જોગવાઈ કરી છે, તે વાત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ અંગેની શું વિગતો છે ?	(૨) રાજ્ય સરકારના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને આવરી લેવાય તેવી વી-ગવર્નન્સની તાલીમ ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૪ થી શરૂ કરાયેલ છે. કર્મચારી/અધિકારીઓમાં હકારાત્મક અભિગમ લાવવા માટે, મૂલ્ય સભાનતા તેમજ આધુનિકરણ પ્રત્યેનો અભિગમ વિકસાવવા માટે કર્મયોગી મહા અભિયાનના ભાગરૂપે આ તાલીમ આપવામાં આવે છે. જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ સુધીમાં એક લાખ કર્મચારી/અધિકારીઓને આ તાલીમ આપવામાં આવી છે. કુલ પાંચ દિવસના દરરોજના ચાર કલાક લેખે જેતે વિભાગ કચેરીના સ્થળે, જિલ્લાના મુખ્ય મથકે, તાલુકા મથકે આ તાલીમ આપવામાં આવે છે. વધુમાં રાજ્ય સરકારના તમામ વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓને દર બે વર્ષે ઓછામાં ઓછી ત્રણ દિવસની તાલીમ લેવાનું ફરજીયાતપણે ઠરાવેલ છે. ઉપરાંત રાજ્યની ટોચની તાલીમ સંસ્થા સરદાર પટેલ રાજ્ય વહીવટ સંસ્થા, અમદાવાદને તા. ૩૦-૯-૨૦૦૪ના ઠરાવથી સ્વાયત્ત જાહેર કરીને ઉક્ત સંસ્થાના ઉપક્રમે તાલીમ કાર્યક્રમો, સેમીનાર, પરિસંવાદ દ્વારા નિરંતર તાલીમની વ્યવસ્થા અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

રાજકોટ જિલ્લામાં ઉદ્યોગોને ચૂકવવાની સબસીડી

૮૦૯૨ **શ્રી મોહનભાઈ ક. કુંડારીયા** (ટંકારા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં ઉદ્યોગોને રેગ્યુલર સબસીડી આપવા માટે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલા એકમોને સબસીડી ચૂકવવામાં આવી,	(૧) ૧૨૭ એકમોને સબસીડી ચૂકવવામાં આવી.
(૨) કયા કયા એકમોને, અને	(૨) પરિશિષ્ટ-અ માં દર્શાવેલ એકમોને
(૩) બાકી રહેતી સબસીડી કેટલા સમયમાં ચુકવવામાં આવશે ?	(૩) બનતી ત્વરાએ ચુકવવામાં આવશે.

પરિશિષ્ટ--અ

કોટડાસાંગાણી તાલુકો :

ક્રમ	એકમનું નામ, સરનામું	રકમ રૂા.
૧	જૈન પ્રોડક્ટસ	૯૩૬૩૪૦
૨	જૈમિન એન્જી પ્રા. લી.	૧૧૧૨૬૨૦
૩	રેલ્કો ઈન્ડ.	૧૧૫૯૯૭
૪	મેટ્રોમેટલ ફોલ્ડ પ્રા. લી.	૧૦૯૦૪૦૬
૫	અમર પી.વી.સી. પ્રોડક.	૯૭૩૦૯૯
૬	માઈક્રો થમ ઈન્ડ.	૩૫૫૪૮૫
૭	કેપ્ટન પોલી પ્લાસ્ટ	૯૨૦૧૬૪
૮	સીલ્વર લાઈન પ્લાસ્ટોમેક	૧૩૨૭૨૯૦
૯	સોહમ ધાણા ઈન્ડ.	૧૬૧૦૦૦
૧૦	માર્ક ઈન્ડ.	૨૫૪૦૦૦
૧૧	મારૂતી ઈન્ડ. પ્રોડક.	૮૦૬૪૬૦
૧૨	એક્ટીવ મશીન ટુલ્સ	૨૩૧૭૫૦
૧૩	બાલાજી મેટલ્સ	૧૪૦૬૭૪૦
૧૪	એન્જલ ઈન્ડ.	૧૪૮૭૯૧
૧૫	લોટસ જ્વેલરી	૧૨૬૫૮૫૬
૧૬	ધીરજ મેટલ્સ	૭૫૧૩૯
૧૭	બી.બી. કેમીક્લ વર્કસ	૧૮૫૪૦૦
૧૮	ભીમાણી કેમીકલ્સ	૯૪૧૭૮
૧૯	રોયલ ઈન્ડ.	૨૭૯૩૫૭
૨૦	ઈન્ડીકા બેરીંગ	૪૯૦૭૦
૨૧	પ્રશાંત પોલીપેક	૨૪૫૧૨૦
૨૨	રેવલોન ઈન્ડ.	૮૬૩૭૯૨
૨૩	બાલસન પોલીપ્લાસ્ટ	૭૭૪૩૮
૨૪	રામેશ્વર કોટન જીનીંગ	૧૪૯૯૯૧૦
૨૫	રઘુકુળ કોટન જીનીંગ	૧૫૦૦૦૦૦
૨૬	જયદીપ કોટન ફાઈબર	૧૫૦૦૦૦૦
૨૭	શ્યામ જીનીંગ ફેકટરી	૧૫૦૦૦૦૦
૨૮	પ્રકાશ ફૂડ પ્રોડક.	૨૪૭૦૦૦
૨૯	ખોડીયાર સ્ટોન ક્સર	૨૦૭૮૦૦
	કુલ રૂા.	૧૯૨૪૩૧૪૨

પાઈપ લાઈન એકમો

૩૦	આશીર્વાદ ઈન્ડ.	૧૫૨૫૧૦
૩૧	જેનીશન સ્ટીલ	૧૮૮૪૪૫
૩૨	યુનીટેક એન્જી પ્રા.લી.	૩૧૩૪૯૧
૩૩	પટેલ પ્રોટીશન્સ પ્રા.લી.	૭૫૦૦૦૦
૩૪	સંજય ઈરપાત પ્રા.લી.	૪૫૬૫૬૫
૩૫	માણેક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ	૧૨૮૭૧૦૦
	કુલ રૂા.	૩૧૪૮૧૧૪

લોધીકા તાલુકો

૩૬	ગુરુકૃપા ફાસ્ટનર્સ	૧૧૫૦૦૦
૩૭	શ્રીજી ઈન્ડકસ	૨૦૦૦૦૦
૩૮	હીરો એગ્રોપ્લાસ્ટ	૧૦૬૨૯૯૭

ક્રમ	એકમનું નામ, સરનામું	રકમ રૂા.
૩૯	લોટસ ઈન્ડ.	૩૮૬૮૨
૪૦	રૂબી પોલીમર્સ	૪૮૬૬૦૦
૪૧	ન્યુ સહજાનંદ મારબલ	૨૦૦૦૦૦
૪૨	સંતોષ આઈસ ફેક્ટરી	૮૬૪૦૬
૪૩	ઓવરસીઝ એન્જી.	૮૮૭૯૩૫
૪૪	ક્રિસ્ટલ કુક એન્જી.	૧૫૦૦૦૦૦
૪૫	એપેક્સ ઈન્ડ.	૩૧૧૬૮૦
૪૬	લીપ્સન્સ એપ્લાઈન્સીઝ	૩૨૬૬૩૮
૪૭	મારૂં ફેબ્રીકેશન	૭૦૮૬૯૨
૪૮	અમર મેટલ ઈન્ડ.	૩૩૪૫૩૬
૪૯	અમી ઈન્ડ.	૯૩૭૦૦
૫૦	બેગોન એન્જી.	૨૯૮૬૦૦
૫૧	સાગર પોલીમર્સ	૩૫૧૫૬૧
૫૨	ઓમ્ની એન્જી.	૧૩૧૨૫૩૯
૫૩	ઉત્તમ ઈન્ડ.	૧૬૩૫૭૩
૫૪	પાન આર્યુવેદિક લી.	૨૮૧૨૧૮
૫૫	શ્રીનાથજી મારબલ	૯૨૫૨૦
૫૬	મહેતા કેમ ઈન્ડ.	૧૦૧૮૮૬૮
૫૭	શ્રીરામ પ્લાસ્ટીક્સ	૮૮૧૮૧
૫૮	મહેતા હરબલ પ્રા. લી.	૧૨૮૨૩૯૨
૫૯	દિનેશ સોપ ફેક્ટરી	૩૨૩૬૦૫
૬૦	અલવરસીઝ એલોય સ્ટીલ	૧૦૫૨૪૯૩
૬૧	એપોલો ફેબ્રીકેશન	૧૪૮૮૨૮
૬૨	રાહીલ ઈન્ડ.	૩૪૦૯૩૪
૬૩	ટીંકુ એન્ડ. કું	૪૫૪૨૨૮
૬૪	જ્યોતી એન્ટરપ્રાઈઝ	૧૫૦૦૦૦૦
૬૫	બાલાજી ઈન્ડ.	૨૦૩૨૩૧
	કુલ રૂા.	૧૫૨૬૫૬૩૭

પાઈપ લાઈન એકમો

૬૬	દિનેશફોર્જ	૧૩૮૦૦૦
૬૭	મહાકાળી સીમેન્ટ હોલો બ્લોક	૧૦૦૦૦૦
	કુલ રૂા.	૨૩૮૦૦૦
	વાંકાનેર તાલુકો	
૬૮	ગ્લોસી સીરામીક પ્રાલી,	૧૦૦૦૦૦૦
૬૯	અમનાથ સીરામીક્સ	૪૮૬૩૦૫
૭૦	રવિ કિરણ ઈન્ડ.	૧૧૬૯૪૦
૭૧	અમૃત સીરામીકસ	૧૦૦૦૦૦૦
૭૨	અજય સીરામીક્સ	૩૬૫૯૫૭
૭૩	સુર્યા સીરામીક્સ	૫૨૫૮૪૦
૭૪	ગંગોત્રી ગ્લેઝસ્ટાઈલ્સ	૧૦૦૦૦૦૦
૭૫	શ્રીનાથજી ઈન્ડ.	૬૧૮૬૮૪
૭૬	જય જલારામ જીનીંગ	૨૫૮૫૪૧
૭૭	મહેસાણીયા જીનીંગ પ્રેસીંગ	૧૦૦૦૦૦૦
૭૮	ભારત ઈન્ડ. (પાઈપ લાઈન)	૩૮૪૮૫૪

ક્રમ	એકમનું નામ, સરનામું	રકમ રૂા.
	કુલ રૂા.	૬૭૫૭૧૨૧

માળીયા મીયાંણા તાલુકો :

૭૯	અપ્પુ પ્લાસ્ટીક ઈન્ડ.	૪૧૦૪૨૦
૮૦	રવીરાજ જીનીંગ પ્રેસીંગ	૧૪૬૯૨૮૮
	કુલ રૂા.	૧૮૭૯૭૦૮

પડધરી તાલુકો :

૮૧	જનક પરફ્યુમર્સ	૩૯૯૫૦૦
૮૨	અંબાફોર્જ	૧૨૫૯૧૦૮
૮૩	ભારત ઓફસેટ	૧૧૬૫૬૯૩
૮૪	બાલકૃષ્ણ જીનીંગ ફેકટરી	૧૩૮૫૪૦૬
	કુલ રૂા.	૪૨૦૯૭૦૭

રાજકોટ તાલુકો :

૮૫	હારમની ડીજીટલ કેકોડીંગ	૨૪૭૦૦૦
૮૬	ગુરૂકૃપા મેટલ્સ	૧૭૫૭૧૨
	કુલ રૂા.	૪૨૨૭૧૨

જસદણ તાલુકો :

૮૭	જીત કોટન મીલ પ્રા.લી.	૧૫૦૦૦૦૦

મોરબી તાલુકો :

૮૮	પેરાકીય પાવર પ્રા.લી.	૨૩૪૦૦૦

ગુણવત્તા સુધારણા યોજના (આઈ. એસ.ઓ.)ની યોજનામાં ચૂકવાયેલ એકમની યાદી.

૮૯	આકાર બેવરેજીસ, મોરબી	૧૭૩૦૩૭
૯૦	બ્લોસમ કીચનવેર પ્રા.લી. કો.સા.	૩૪૦૩૭
૯૧	પરમાર મેટલ પ્રા. લી. કો.સા.	૩૮૦૦૦
૯૨	પ્લોટેક એન્જી. પ્રા. લી. કો.સા.	૧૭૦૧૦૫
૯૩	મહારાજા પ્લા. પઢધરી	૨૦૦૦૦૦
૯૪	આયુ લેબ પ્રા.લી. રાજકોટ	૭૩૫૧૩
૯૫	રોયલ પ્લા. ધોરાજી	૭૫૬૨૫
૯૬	ભુકી પોલી પલાસ્ટ પ્રા.લી. ધોરાજી	૨૦૦૦૦૦
૯૭	ઓલ્મપિક પ્લ. પ્રા,લી. કોસા.	૨૦૬૨૫
૯૮	કન્કાઈ ઈન્જી. પ્રા.લી. રાજકોટ	૧૬૫૬૩૯
૯૯	સ્ટાર ઈન્ડ. રાજકોટ	૨૦૦૦૦૦
૧૦૦	સનરાઈઝ એન્જી.કું. કો.સા.	૪૬૪૨૪
૧૦૧	મેટ્રોમેટલ ફોલ્ડ પ્રા.લી. કો.સા.	૭૮૨૫૧
૧૦૨	કૈલાર સીમેન્ટ ઈન્ડ. લોધીકા	૧૪૮૬૫૩
૧૦૩	રામા વોચ ઈન્ડ. કો.સા.	૧૭૨૦૪
૧૦૪	સીન્થેટીક ઈન્ડ. રાજકોટ	૧૬૫૫૮૫
૧૦૫	પ્રમુખ સીમેન્ટ પ્રા.લી. કો.સા.	૧૭૦૭૯૯
૧૦૬	કીવી. પમ્પસ, રાજકોટ	૨૦૦૦૦૦
૧૦૭	વેલ્સન એન્જી. વર્કસ, રાજકોટ	૭૬૩૪૦
૧૦૮	રાજન ટેકનોકાસ્ટ પ્રા.લી. કો.સા.	૧૦૬૩૭૦
૧૦૯	સીધ્ધી વિનાયક બેવરેજીસ, લોધીકા	૧૪૬૯૧૬
૧૧૦	ડેકોડા કોટીંગ પ્રા.લી. કો.સા.	૪૭૨૨૬
૧૧૧	આસુતોષ રબ્બર પ્રોડ. રાજકોટ	૨૦૦૦૦૦
૧૧૨	મેટલ ફોલ્ડ, કો.સા.	૬૨૪૦૦

ક્રમ	એકમનું નામ, સરનામું	રકમ રૂા.
૧૧૩	એવરેસ્ટ ઈલેક. રાજકોટ	૪૫૯૮૦
૧૧૪	યુનીટેક એન્જી. પ્રા.લી. રાજકોટ	૧૬૮૧૯૯
૧૧૫	સીરોયા એન્જી. વર્કસ, રાજકોટ	૧૬૬૦૪૧
૧૧૬	એડવાન્સ મીકેનીકલ વર્કસ, રાજકોટ	૯૬૪૨૯
૧૧૭	ક્રીમ ઈન્ડ. રાજકોટ	૩૪૧૦૦
૧૧૮	વેલનટીક મશીન્સ પ્રા.લી. રાજકોટ	૩૩૦૬૦
૧૧૯	રંગાણી એન્જી. પ્રા. લી. કો.સા.	૫૨૩૮૮
૧૨૦	અદાણી ફુડ પ્રોડ. લોધીકા	૫૪૫૦૦
૧૨૧	ડી.એન.એ. એન્જી. રાજકોટ	૧૮૦૨૬૮
૧૨૨	સીલીકોન ઈલેક. રાજકોટ	૧૭૯૬૯૮
૧૨૩	સીમ્પોલો સીરેમીક, મોરબી	૨૦૦૦૦૦
૧૨૪	રામેશ્વર ડેરીંગ પ્રા.લી. રાજકોટ	૮૩૯૩૯
૧૨૫	ન્યુ ટેસ્ટીમી, રાજકોટ	૧૮૦૯૬૯
૧૨૬	હીર્તી ફોર્જીંગ, રાજકોટ	૩૫૯૪૨
૧૨૭	સરીતા ડ્રીન્કીંગ વોટર, મોરબી	૧૫૧૨૬૨
	કુલ રૂા.	૪૪૮૯૫૨૩

અમદાવાદ શહેરમાં સી..એન.જી.ના સ્ટેશનો

૯૧૯૧ **શ્રી દિપસિંહ શં. રાઠોડ(પ્રાંતિજ) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (પેટ્રોકેમિકલ્સ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરમાં વાહનો માટે સી.એન.જી. સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે તે સારૂં સરકારનું શું આયોજન છે;	(૧) તા. ૨૧-૪-૨૦૦૩ના રોજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા અદાણી ગ્રુપને અમદાવાદ સીટી ગેસ ડીસ્ટ્રીબ્યુશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચરના વિકાસ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેમના દ્વારા શુધ્ધ બળતણ તરીકે સીએનજીને વિકસાવવા અગ્રતા આપવાની રહેશે અને પરિવહન માટે સીએનજીનો ઉપયોગ કરાશે. જૂન-૨૦૦૪માં અમદાવાદને નેચરલ ગેસ પૂરો પાડતી મુખ્ય લાઈન જી.એસ.પી.એલ.એ નાંખી દીધી છે અમદાવાદ શહેરમાં હાલમાં અદાણી ગૃપ દ્વારા ત્રણ સ્ટેશનો કાર્યરત થયા છે, અને તા. ૩૧-૩-૦૫ સુધીમાં બીજા ૭ સ્ટેશનો કરવાનું આયોજન છે. ઉપરાંત વાહનોમાં સી.એન.જી સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવવા રાજ્ય સરકારે હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશનને અમદાવાદ શહેરમાં એક મધર સ્ટેશન તથા ૯ ડોટર સ્ટેશન નાંખવાની મંજૂરી આપેલ છે.
(૨) હાલ કેટલા સ્ટેશનો કાર્યરત છે; અને	(૨) ૩ (ત્રણ)
(૩) ભવિષ્યનું આયોજન શું છે ?	(૩) ચાલુ કેલેન્ડર વર્ષમાં અદાણી ગૃપ અને એચ. પી. સી. અલ. દ્વારા મળીને કુલ ૨૦ સી.એન.જી, સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન છે.

વલસાડ જિલ્લામાં ખૂન, લૂંટ અને આત્મહત્યાના બનાવો

૮૯૧૩ **શ્રી જીતુભાઈ હ. ચૌધરી** (મોટા પોંઢા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન

(૧) સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ સુધીમાં વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખૂન, લૂંટ અને આત્મહત્યાના કેટલા બનાવો પોલીસ દફતરે નોંધાયા; અને

(૨) તે અન્વયે સંડોવાયેલ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) તા. ૦૧/૦૪/૦૩ થી ૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં બનેલ બનાવોની તાલુકાવાર વિગત.

તાલુકાનું નામ	ખૂન	લૂંટ	આત્મહત્યા
વલસાડ	૦૯	૧૫	૫૧
પારડી	૩૧	૩૭	૬૩
ઉમરગામ	૧૪	૩૧	૩૦
ધરમપુર	૦૩	૦૦	૨૫
કપરાડા	૦૩	૦૨	૨૩

(૨)

તાલુકાનું નામ	ખૂન	લૂંટ	આત્મહત્યા
વલસાડ	૧૭	૩૬	-
પારડી	૪૮	૧૦૧	-
ઉમરગામ	૪૫	૮૧	-
ધરમપુર	૦૩	૦૦	-
કપરાડા	૧૨	૦૪	-

જીસ્વાન દ્વારા જોડાયેલી તાલુકાની કચેરીઓ

૯૩૨૬ **શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના.પટેલ**(માંડલ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) જીસ્વાન દ્વારા રાજ્યના કેટલા તાલુકાઓની કેટલી કચેરીઓ જોડાયેલી છે; અને

(૨) તેની પ્રવૃત્તિઓ શી છે?

જવાબ

(૧) રાજયના કુલ ૨૨૫ તાલુકાઓની કુલ : ૬૭૪ કચેરીઓ.

(૨) આ કચરીઓ દ્વારા ૭/૧૨ના દાખલા, રેશનીંગ કાર્ડ, જન્મ-મરણ પ્રમાણપત્ર, આવકનો દાખલો, જાતિ પ્રમાણપત્ર, રહેઠાણનો દાખલો વગેરે માહિતી આપવામાં આવે છે.

થ્રી વ્હીલ ટેમ્પોરીક્ષામાં પેસેન્જર બેસાડવાની મંજૂરી

૮૭૪૭ **શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવીયા** (પાલીતાણા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) થ્રી વ્હીલ ટેમ્પોરીક્ષામાં પેસેન્જર બેસાડવાની રાજ્ય સરકારે મંજૂરી આપી છે કે કેમ; અને

જવાબ

(૧) કેટલાક ચોક્કસ હેતુઓ માટે ડીઝલથી ચાલતી માલવાહક ટેમ્પો રિક્ષામાં, બિનવાણિજિયક સેવાના ધોરણે, વ્યકિતઓના વહન માટે છુટ આપવામાં આવી છે.

(૨) જો હા, તો વર્તમાન સમયમાં તેનો અમલ ચાલુ છે કે કેમ?	આવી છે. (૨) હા, જી.

ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ સમીટ-૨૦૦૪ના આયોજન દરમ્યાન થયેલા એમ.ઓ.યુ.

૮૧૫૯ **ડૉ. માયાબેન સુ. કોડનાની**(નરોડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ સમીટ-૨૦૦૪ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતના આયોજન દ્વારા કેટલી રકમના એમ.ઓ.યુ. સાઈન થયા હતા; અને	(૧) ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ સમીટ-૨૦૦૪-૦૫ દ્વારા રૂા. ૧,૦૬,૧૬૦ કરોડના મૂડી રોકાણની ૨૨૬ દરખાસ્તો મળેલ છે.
(૨) કયા કયા ક્ષેત્રમાં થયા હતા ?	(૨) એગ્રો, પાવર, ઓઈલ અને ગેસ, આઈ.ટી અને બી.ટી., ટુરીઝમ, શહેરી વિકાસ, પાણી., કેમીકલ, ટેક્ષટાઈલ અને એપેરલ, જેમ્સ અને જવેલરી પોર્ટ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર, એન્જીનીયરીંગ અને ઓટોમોબાઈલ.

નર્મદા બંધની ૧૨૧.૯૨ મીટરની ઊંચાઈએ થનાર લાભ

૮૯૦૨ **શ્રી ભરત બારોટ**(દરિયાપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં રાજ્યને શું લાભ થશે;	(૧) નર્મદા બંધની મુખ્ય છલતીની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવાનું આયોજન છે, જેનો ૧૬ % ભાગ ગુજરાત રાજ્યને મળશે. સને ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન આશરે ૩ (ત્રણ) લાખ હેકટર વિસ્તાર સિંચાઈ હેઠળ આવરી લેવાનું આયોજન છે અને પીવાનું પાણી શકય તેટલી વધારે જગ્યાએ આપવામાં આવશે.
(૨) ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી કયા સ્તરે પડતર છે; અને	(૨) નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પર્યાવરણ પેટા જુથ દ્વારા તેમની ૪૧ મી બેઠકમાં તા. ૬-૧-૨૦૦૫ના રોજ મંજૂરી અપાયેલ છે. આ જ પ્રકારની મંજૂરી નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીના પુનઃવસન પેટા જુથ દ્વારા મેળવવાની બાબત પ્રગતિ હેઠળ છે, અને આ મંજૂરી મળ્યા બાદ નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટી દ્વારા બંધનું કામ ૧૨૧.૯૨ સુધી આગળ વધારવા માટે ટૂંક સમયમાં મંજૂરી મળવાની સંભાવના છે.
(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨મીટર વધારવા માટે કેટલો ખર્ચ થશે ?	(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨મીટર સુધી લઈ જવા માટે આશરે રૂા. ૧૨૫ કરોડનો ખર્ચ થશે.

જુનાગઢ જિલ્લામાં તત્કાળ વીજ જોડાણ યોજના હેઠળ આવેલી અરજીઓ

૮૪૩૯ **શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ**(સોમનાથ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ

(૧) ૩૧મી ડીસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં તત્કાળ વીજ જોડાણ યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ માટેની કુલ કેટલી અરજીઓ સરકારને મળી;	(૧) ૧૪,૬૫૭
(૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો; અને	(૨) ૫,૫૪૪
(૩) બાકી રહેતા વીજ જોડાણો કયાં સુધી આપવામાં આવશે ?	(૩) પાંચ કિસ્સામાં વાંધાનો નિકાલ થયેથી તથા અન્ય પડતર અરજીઓમાં અરજદારો તરફથી નાણાં ભરપાઈ થયે તબક્કાવાર.

રાજ્યમાં વીજ માંગ અને વીજ ઉત્પાદન

૮૩૧૫ **શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ**(વાગરા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં વાર્ષિક વીજ ઉત્પાદન કેટલું છે,

(૧) કુલ ૫૭૮૬૮.૬૫૦ મી.યુ.

(૨) તેની સામે કૃષિ ઉદ્યોગ અને ઘર વપરાશ માટે વાર્ષિક કેટ કેટલી વીજળીની જરૂર પડે છે; અને

(૨) સને ૨૦૦૪માં થયેલા કુલ વીજ વેચાણ ૩૩૧૪૭ મી.લી. યુનિટ પૈકી કૃષિ ક્ષેત્રે -૧૨૩૮૬ મી.યુ., ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે-૧૦૬૮૪ મી. યુ. ઘરવપરાશ માટે-૩૭૯૫ મી.યુ. જરૂરીયાત રહી છે.

(૩) આ જરૂરીયાતને પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકારે સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના બજેટ વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ શા ભાવે કોની કોની પાસેથી કેટ કેટલી વિજળી ખરીદી ?

(૩) ગુ. વિ. બોર્ડે નીચે મુજબ વીજ ખરીદી કરેલ છે.

સ્ત્રોત	૨૦૦૩-૦૪		૨૦૦૪-૦૫ ડીસે. ૦૪ સુધી.	
	મી.યુ.	સરેરાશ ભાવ રૂ.	મી.યુ.	સરેરાશ ભાવ રૂ.
કેન્દ્રિય સહાય	૧૦૮૭૬	૧.૬૮	૮૦૬૩	૧.૫૪
આઈપીપી	૧૧૨૩૫	૨.૭૮	૧૦૪૦૨	૨.૩૯
અન્ય	૨૩૨૮	૨.૭૦	૧૪૩૪	૨.૬૨
કુલ..	૨૪૪૩૯	૨.૨૮	૧૯૮૯૯	૨.૦૬

રાજ્યમાં ઓદ્યોગિક મૂડી રોકાણની દરખાસ્તો

૯૩૫૩ **શ્રી નરેશકુમાર મી.કનોડિયા** (કરજણ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ સુધીમાં રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક મૂડી રોકાણ માટેની કેટલા અને કયા પ્રકારના ઉદ્યોગો માટેની દરખાસ્તો મળી;

(૧), (૨) અને (૩)
ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટેની દરખાસ્તો રાજ્ય સરકાર સાથે કરારખત કરીને અને તેની સાથોસાથ અથવા તે સિવાય મધ્યમ અને મોટા કદના ઉદ્યોગો માટે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી આઈ.ઈ.એમ. રજુ કરીને કરવામાં આવે

(૨) મળેલી દરખાસ્તોમાં કુલ કેટલા મૂડી રોકાણનો સમાવેશ થનાર છે; અને

(૩) આ મૂડી રોકાણથી આશરે કેટલી રોજગારી ઉભી થશે ?

સરકાર સમક્ષ આઈ.ઈ.એમ. રજુ કરીને કરવામાં આવે છે. ૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષમાં ૭૬ એકમો તરફથી કુલ રૂા. ૬૬૦૬૮ કરોડના કરારખત રાજ્ય સરકાર જોડે કરવામાં આવેલ છે અને તે પૈકી અથવા તે સિવાય મોટા અને મધ્યમ કદના ૫૯૦ એકમો તરફથી રૂા. ૩૨.૪૭૦ કરોડના આઈ.ઈ.એમ.થયા છે.

૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષ દરમ્યાન ૨૨૬ એકમો તરફથી કુલ રૂા. ૧,૦૬,૧૬૦ કરોડના કરારખતમાં રાજ્ય સરકાર સાથે સહી કરવામાં આવેલ છે. અથવા આ એકમો તરફથી મૂડીરોકાણ અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે પૈકી અથવા તે સિવાય મોંટા અને મધ્યમ કદના ૪૧૧ અકમો તરફથી રૂા. ૧૬,૪૩૮ કરોડના આઈ.ઈ.એમ.રજુ કરવામાં આવેલ છે.

આવા મૂડી રોકાણની દરખાસ્તન કારણે કેટલી રોજગારી ઉભી થશે તે પ્રોજેકટ / ઉદ્યોગો શરૂ થયા બાદ જ વિગતો જાણી શકાશે.

ઉના તાલુકામાં દેશી તથા વિદેશી દારુ પકડવા અંગે

૮૨૪૬ **શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ** (ઉના) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) જૂનાગઠ જિલ્લામાં ઉના તાલુકામાં સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ અને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના બજેટ વર્ષમા તા. ૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં વર્ષવાર કેટલો દેશી તથા વિદેશી દારુ પકડવામાં આવ્યો;

(૧)

વર્ષ	દેશી દારુ (લીટર)	વિદેશી દારુ (બોટલ)
૨૦૦૩-૦૪	૫,૬૯૧	૩૮,૪૯૩
૨૦૦૪-૨૦૦૫ (૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં)	૬,૩૯૮	૨૩,૭૯૫

(૨) કેટલા ઈસમોની ધરપકડ કરી કેસો દાખલ કરવામાં આવ્યા;

(૨) સને ૨૦૦૩-૦૪ના વર્ષમાં ૬૮૨ ઈસમોની ધરપકડ કરી, ૫૩૬ કેસો દાખલ કરેલ છે. જ્યારે સને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ (૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં) ૫૯૬ ઈસમોની ધરપકડ કરી, ૫૬૫ કેસો દાખલ કરેલ છે.

(૩) તે પૈકી એકથી વધુવાર પકડાયા હોય તેવા કેટલા ઈસમો છે; અને

(૩) સને ૨૦૦૩-૨૦૪ના વર્ષમાં ૨૧ ઈસમો અને સને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ (તા. ૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં)૨૫ ઈસમો એકથી વધુ વાર પકડાયેલ છે.

(૪) આવા ઈસમો સામે શાં પગલાંઓ લેવામાં આવ્યા ?

(૪) આવા ઈસમો સામે જરૂરી અટકાયતી પગલાં (સને ૨૦૦૩-૦૪ના વર્ષમાં હદપારી-૧ અને પ્રોહી. એકટની કલમ-૯૩ મુજબ કુલ-૧૨૨ તથા સને ૨૦૦૪-૦૫, તા. ૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં પ્રોહી. એકટની કલમ-૯૩ મુજબ કુલ-૧૦૫) લેવામાં આવેલ છે.

રાજ્યમાંથી જાલી નોટો પકડવાના કેસો

૯૨૦૧ **શ્રી પ્રવિણભાઈ મો. માકડીયા** (ઉપલેટા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) રાજ્યના કયા કયા શહેરોમાંથી ડીસે. ૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષ દરમ્યાન જાલી નોટો પકડાવાના બનાવો બન્યા છે;

(૧)

અ. નં.	શહેર-જીલ્લા	જાલી નોટોના કેટલા બનાવો બન્યા
૧.	અમદાવાદ શહેર	૦૭
૨.	રાજકોટ શહેર	૦૬
૩.	સુરત શહેર	૦૬
૪.	વડોદરા શહેર	૦૩
૫.	અમદાવાદ રૂરલ	૦૨
૬.	ખેડા	૦૫
૭.	આણંદ	૧૦
૮.	ગાંધીનગર	૦૩
૯.	સાબરકાંઠા	૦૪
૧૦.	મહેસાણા	૦૦
૧૧.	જામનગર	૦૬
૧૨.	રાજકોટ રુરલ	૦૧
૧૩.	સુરેન્દ્રનગર	૦૪
૧૪.	બનાસકાંઠા	૦૪
૧૫.	કચ્છ-ભુજ	૦૧
૧૬.	પાટણ	૦૪
૧૭.	અમરેલી	૧૦
૧૮.	ભાવનગર	૧૪
૧૯.	જુનાગઢ	૦૧
૨૦.	પોરબંદર	૦૨
૨૧	વડોદરા રુરલ	૦૦
૨૨.	ભરુચ	૦૫
૨૩.	નર્મદા	૦૧
૨૪.	ગોધરા	૦૭
૨૫.	દાહોદ	૦૨
૨૬	સુરત રુરલ	૦૦
૨૭.	વલસાડ	૦૪
૨૮.	નવસારી	૦૧
૨૯.	ડાંગ-આહવા	૦૧
૩૦.	પશ્ચીમ રેલ્વે	૦૨

(૨) સરકારને આમાં કોઈ વ્યવસ્થિત ષડયંત્ર હોય તેવું ધ્યાન પર આવ્યું છે, અને

(૨) ના, જી.

(૩) કેટલી રકમની જાલી નોટો પકડાઈ છે ?

(૩) રૂા. ૧૩,૭૭,૨૦૦/- ની જુદા જુદા દરની જાલી નોટો પકડાયેલ છે.

ભાવનગર જિલ્લાના અલંગ અને મણાર ખાતે જી.આઈ.ડી.સી. નહી બનાવવા બાબત

૮૩૮૦ **શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ.સોલંકી(ઘોઘા)** : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

પ્રશ્ન

ભાવનગર જિલ્લામાં અલંગ અને મણાર ખાતે જી.આઈ.ડી.સી. ન બનાવવા માટે નિર્ણય ક્યારે

જવાબ

(૧) ગુજરાત ઓદ્યોગિક વિકાસ નિગમ દ્વારા અલંગ મણાર ખાતે ઔદ્યોગિક વસાહત નહીં સ્થાપવા

જી.આઈ.ડી.સી ન બનાવવા માટે નિર્ણય કયારે લેવાયેલ છે?	મણાર ખાતે ઔદ્યોગિક વસાહત નહીં સ્થાપવા દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે, જે બાબત સરકારશ્રી કક્ષાએ વિચારણા હેઠળ છે.

ગાંધીનગર જિલ્લાનાં ગામો અને પેટા પરાઓનું બાકી વિજળીકરણ

૯૩૭૯ **શ્રી જગદીશ ઠાકોર (દહેગામ) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ગાંધીનગર જિલ્લામાં વીજળીકરણ વિનાના તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ ની સ્થિતિએ કયા કયા ગામો અને કયા પેટાપરાઓ છે;	(૧) વીજળીકરણ વિનાના વસ્તી ધરાવતા ગામોની સંખ્યા-શૂન્ય અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની પુસ્તિકા મુજબના પેટાપરાઓની સંખ્યા-શૂન્ય
(૨) આ ગામો અને પેટા પરાઓનું અત્યાર સુધી વીજળીકરણન થવાનાં કારણો શાં શાં છે; અને	(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આ ગામો અને પેટાપરાઓનું વીજળીકરણ કેયલા સમયમાં કરવામાં આવશે?	

સરદાર સરોવર ડેમની ૧૨૧.૯૨ મીટરની ઉંચાઈએ સાથી રાજ્યોને લાભ

૮૮૭૦ **શ્રી બિમલ શાહ** (કપડવંજ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી વધવાથી મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનને શું લાભ મળશે;	(૧) સરદાર સરોવર ડેમની મુખ્ય છલતીની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ વિદ્યુત ઉત્પાદન કરવાનું આયોજન છે. આ વિદ્યુતના ૫૭ ટકા મધ્યપ્રદેશ રાજ્યને અને ૨૭ ટકા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યને ભાગે મળશે. રાજસ્થનમાં મુખ્ય નહેર પૂર્ણ થતાં ૦.૫૦ મીલીયન એકરફીટ પાણી આપી શકાશે.
(૨) ૧૨૧.૯૨ મીટર ઊંચાઈ વધવાથી કેટલું વીજ ઉત્પાદન થશે; અને	(૨) વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ
(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી થતાં રાજ્યને કેટલા વિસ્તારને સિંચાઈ માટે પાણી આપી શકાશે ?	(૩) બંધની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી થતાં રાજ્યમાં સને ૨૦૦૫-૦૬માં આશરે ૩ (ત્રણ) લાખ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઈ માટે પાણી આપવાનું આયોજન છે.

જી. એ. એસ. વર્ગનું કેડર શિડયુલ બહાર પાડવા બાબત

૮૧૩૯ **ડૉ. સી. જે. ચાવડા(ગાંધીનગર) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ગુજરાત વહીવટી સેવા (જી. એ. એસ.)વર્ગનું કેડર શિડયુલ છેલ્લે કયારે બહાર પાડવામાં આવ્યું;	(૧) ગુજરાત વહીવટી સેવા (જી.એ.એસ.) વર્ગ - ૧ સંવર્ગનું કેડર શિડયુલ છેલ્લે સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. ૯/૨/૧૯૯૯ના ઠરાવથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

(૨) આ કેડર શિડયુલ જાહેર કરવા માટે વિલંબ થયેલ છે કે કેમ; અને	(૨) ના, જી.
(૩) સરકાર જી.એ.એસ. કેડર શિડયુલ કયારે બહાર પાડવા માંગે છે ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

નર્મદા નહેરમાં ડૂબવાના બનાવો અટકાવવા બાબત

૮૮૮૯ **શ્રી મોહનભાઈ ધ. ઢોડિયા(મહુવા) : માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા યોજનાની મુખ્ય નહેરમાં ડૂબવાના બનાવો અવારનવાર બને છે, તે માટે સરકાર સજાગ છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આવા બનાવો નિવારવા માટે સરકારે શું પગલાં લીધા છે ?	(૨) આવા બનાવો નિવારવા માટે સરકારે શ્રેણીબધ્ધ પગલાંઓ લીધા છે, (૧) મુખ્ય નહેર પર અગત્યના રોડ ક્રોસીંગ પર નહેરમાં ન ઉતરવા બાબતે જાહેર ચેતવણીના બોર્ડ મુકવામાં આવેલ છે. (૨) મુખ્ય નહેર પરના અગત્યના સ્ટ્રકચરો કે જ્યાં લોકોની અવરજવર વધારે રહે છે ત્યાં કેનાલની બંન્ને બાજુ કાંટાળી તારની વાડ બનાવેલ છે (૩) મુખ્ય નહેરનાં રસ્તા પર મોટા વાહનો પ્રવેશ ન કરે તે માટે લોડીંગ ફ્રેઈમ મૂકેલ છે તેમજ નાના વાહનો નહેરના રસ્તા ઉપર ન પ્રવેશી શકે તે માટે લો-હેડ બેરીકેડ મૂકવામાં આવેલ છે. (૪) મુખ્ય નહેર પરના ગાંધીનગર-અમદાવાદ નજીકના ત્રણ પુલો પરથી કોઈ નહેરમાં ન ઉતરે તે કામગીરી માટે સુરક્ષા કમર્ચારી મૂકવામાં આવેલ છે. (૫) મુખ્ય નહેર પરના અગત્યના પુલોની પેરાપેટ ઉપર જાળી લગાવવામાં આવેલ છે.(૬) અમદાવાદ-ગાંધીનગર નજીકની મુખ્ય નહેર પર જ્યાં લોકોની અવરજવર વધારે રહે છે ત્યાં ડૂબતા માણસોને બચાવવા હલેસાવાળી બોટ તથા યાંત્રિક બોટને ફરતી કરવામાં આવેલ છે (૭) શહેર નજીકના પુલો પર લાઈટ મૂકવામાં આવેલ છે જેથી રાત્રે પણ ડૂબતા માણસોને બચાવી શકાય. (૮) અગત્યના પુલો નીચે ડૂબતા માણસ પકડી શકે તે માટે દોરડાની જાળી મૂકવાનું આયોજન છે. લોક જાગૃતિ માટે મુખ્ય નહેર આસપાસના ગામોમાં ચેતવણીદશર્ક પત્રો પણ મોકલવામાં આવેલ છે તથા રેડિયો કાયક્રમ મારફત લોકોમાં સંદેશો પહોંચાડી આવા બનાવો ન બને તે માટે જાગૃતિ લાવવા પ્રચાર કરવામાં આવેલ છે.

ધોળકા વિસ્તારમાં તેલ ભંડારો મળી આવવા અંગે

૮૮૯૨ **શ્રી કાંતિભાઈ ભા.તડવી** (સંખેડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં ધોળકા વિસ્તારમાં વિપુલ પ્રમાણમાં તેલના ભંડારો મળી આવ્યા છે, તે વાત સાચી છે,	(૧) હા,
(૨) જો હા, તો કેટલી માત્રામાં મળેલ છે, અને	(૨) શરૂઆતમાં ક્રુડનો જથ્થો ૫-૧૦ કરોડ બેરલ જેટલો છે.

(૩) તેણે કારણે રાજ્યને ભવિષ્યમાં કેટલા કરોડ રૂપિયાનો લાભ મળશે ?

(૩) ધોળકા વિસ્તાર એ સંશોધન ક્ષેત્ર છે. જે ભારત સરકાર દ્વારા ગેઈલ અને જીએસપીસીના સંયુકત સાહસને ફાળવવામાં આવેલ છે. જેમાં બન્નેની સરખી હિસ્સેદારી છે. ઉત્પાદન વહેંચણી કરાર મુજબ રાજ્ય સરકારને રોયલ્ટી મળવાપાત્ર છે. જ્યારે જે જગ્યાએથી ક્રુડ ઓઈલ પ્રાપ્ત થાય છે તેનો વિસ્તાર કેટલો હોઈ શકે તે અંગેનું સંશોધન હજી ચાલુ હોઈ, રાજ્ય સરકારના લાભ વિષે ચોક્કસ કહેવું હાલના તબક્કે શક્ય નથી.

ઉદ્યોગોના ગંદા પાણીને શુદ્ધ કરવાના પ્રોજેકટ માટે અમેરિકન કંપની સાથે કરાર

૯૩૭૧ **શ્રી પુનાભાઈ ધે. ગામીત** (વ્યારા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) રાજ્ય સરકારે ઉદ્યોગોના ગંદાપાણીને શુધ્ધ કરવાના પ્રોજેકટો માટે અમેરીકન કંપની સાથે કરારો કર્યા હતાં કે કેમ,

(૧) રાજ્ય સરકારે ગંદાપાણીના પુનઃવપરાશ માટે શક્યતાદર્શી અહેવાલ તૈયાર કરવા માટે કરાર કરેલ છે.

(૨) જો હા તો ક્યારે અને કેટલા ખર્ચે,

(૨) તા. ૧૫-૬-૨૦૦૧ના રોજ યુએસટીડીએ સાથે ફીઝીબીલીટી સ્ટડી અંગેનો કરાર થયેલ અને તા. ૧૯-૯-૨૦૦૨ના રોજ મેસર્સ ટેટ્રા ટેક ઈએમઆઈએનસી સાથે ૨,૦૨,૬૨૦-૦૦ યુ.એસ. ડોલર્સના ખર્ચ અંગેનો કરાર કરાયેલ, જે માટે ગ્રાંન્ટની ફાળવણી યુએસટીડીએ દ્વારા કોન્ટ્રાકટરને કરવામાં આવે છે.

(૩) કરારમાં હેતુઓ, અમલીકરણ અને મોનીટરીંગ અંગે શું જોગવાઈઓ હતી, અને

(૩) ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમની અંકલેશ્વર,ઝઘડીયા તથા પાનોલી વસાહતો અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તેમજ તેમાં આવેલા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોના ગંદાપાણીનું શુદ્ધિકરણ કરી તેના પુનઃવપરાશ માટે શક્યતા અહેવાલ તૈયાર કરાવી પ્રોજેકટના અમલીકરણનો હેતુ રહેલો છે.

મે. ટેટ્રા ટેક ઈએમઆઈએનસીનો અહેવાલ મલેલ છે જે ચકાસણી હેઠળ છે.

પ્રોજેકટનું મોનીટરીંગ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર તરફથી નક્કી થયેલ નિયમાનુસાર કરવામાં આવશે.

(૪) આ અંગે રાજ્ય સરકારનું આગામી વર્ષોમાં શું આયોજન છે ?

(૪) તજજ્ઞ તરફથી મળેલ અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ તાંત્રિક તથા આર્થિક બાબતોની ચકાસણી બાદ પોષણક્ષમ જણાયે તેની અમલવારી અને તે દ્વારા પર્યાવરણની જાળવણી માટે સરકારનું આયોજન છે.

અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં આપઘાત, ખૂન અને લૂંટના બનાવો

૮૩૬૫ **શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાળા**(જમાલપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ એક વર્ષમાં કેટલા આપઘાત, ખૂન અને લૂંટના ગુના બન્યા,

(૧) અમદાવાદ શહેર

આપઘાત	ખૂન	લૂંટ
૫૦૪	૯૫	૨૭૧

અમદાવાદ જિલ્લો

આપઘાત	ખૂન	લૂંટ
૯૯	૨૬	૨૮

(૨) આ ગુના સબબ કેટલા લોકોની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી, અને

(૨) અમદાવાદ શહેર

આપઘાત	ખૂન	લૂંટ
૬૫	૧૭૩	૩૧૩

અમદાવાદ જિલ્લો

આપઘાત	ખૂન	લૂંટ
--	૯૫	૧૯

(૩) આવા ગુનાઓ બનતા અટકાવવા સરકારે શાં પગલાં લીધા છે ?

(૩) પોલીસ તરફથી જરૂરી અટકાયતી પગલાં, નાકાબંધી, સરપ્રાઈઝ વાહન ચેકીંગ વગેરે જેવા અસરકારક પગલાં લેવામાં આવેલ છે અને પકડાયેલ આરોપીઓને કડક સજા થાય તેવા પગલાં લીધા છે.

અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નરની હકુમત હેઠળના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા વિવિધ ગુના

૮૫૫૭ **શ્રી મોહંમદફારુક હુ. શેખ** (કાલુપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) અમદાવાદ પોલીસ કિમશ્નરશ્રીની હકુમત હેઠળના દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં ખૂન, લૂંટ, ચોરી અને આત્મહત્યાના કુલ કેટલા બનાવો તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં નોંધાયા, અને

જવાબ

(૧)

પો.સ્ટે.	ખૂન	લુંટ	ચોરી	આત્મહત્યા
વેજલપુર	૦૧	૦૩	૧૪૭	૧૪
એલીસબ્રિજ	૦૨	૧૯	૫૪૫	૧૫
સેટેલાઈટ	૦૭	૨૧	૬૭૨	૨૪
નવરંગપુરા	--	૧૬	૭૯૫	૦૮
નારણપુરા	૦૫	૦૯	૩૩૨	૧૫
ઘાટલોડીયા	૦૩	૦૭	૨૦૧	૨૨
સોલા	૦૫	૦૭	૧૦૩	૧૩
સાબરમતી	૦૨	૦૭	૨૦૯	૧૬
માધવપુરા	૦૭	૦૬	૧૬૮	૨૫
શાહપુર	--	૦૨	૭૩	૦૮
કારંજ	--	૦૫	૨૪૯	૦૩
કાલુપુર	૦૧	૦૧	૧૫૪	૦૩
શહેરકોટડા	૦૨	૧૨	૧૬૨	૩૧
ખાડીયા	--	૦૧	૪૭	૦૫
હવેલી	૦૧	૦૪	૬૭	૧૦
દરીયાપુર	૦૧	--	૨૪	૦૫
શાહીબાગ	--	૦૭	૨૩૧	૧૨
સરદારનગર	૦૧	૦૯	૬૬	૨૬
મેઘાણીનગર	૦૮	૦૫	૪૭	૧૬
નરોડા	૦૬	૧૦	૧૪૫	૩૩
ગોમતીપુર	૦૩	૦૪	૪૩	૧૩
રખીયાલ	૦૧	૦૪	૩૩	૦૩
બાપુનગર	૦૪	૧૭	૧૪૦	૧૯

અમરાઈવાડી	૦૪	૨૦	૧૭૫	૩૩
ઓઢવ	૦૫	૧૫	૧૧૨	૨૨
વટવા	૦૮	૨૦	૨૮૯	૩૫
જી.આઈ.ડી.સી.	૦૨	૦૩	૪૨	૦૮
મણીનગર	૦૪	૨૪	૩૮૧	૦૯
કાગડાપીઠ	૦૬	૧૦	૨૩૧	૪૬
દાણીલીમડા	૦૬	૦૧	૫૧	૧૨
ક્રાઈમ	--	૦૨	--	--

(૨) તે અન્વયે કેટ કેટલા ઈસમોની સંડોવણી અંગે ધરપકડ થઈ?

(૨)

ખૂન	લુંટ	ચોરી	આત્મહત્યા
૧૭૩	૩૧૩	૧૭૮૧	૬૫

રાજ્યને પેટ્રોકેપિટલ બનાવવાનું આયોજન

૮૯૦૯ **શ્રી પ્રદિપસિંહ ભ.જાડેજા**(અસારવા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) ગુજરાત રાજ્યને દેશમાં પેટ્રો કેપીટલ બનાવવા માટે રાજ્ય સરકારનું આયોજન શું છે, અને

જવાબ

(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવાયેલ/લેવાઈ રહેલ પગલાઓ નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે છે.

(૧) દહેજ (જિ. ભરૂચ) ખાતે ૫ એમએમટીપી એ ક્ષમતાવાળુ એલ.એન.જી. ટર્મિનલ તા. ૯-૨-૦૪થી કાર્યરત.

(૨) હજીરા ખાતે ૨.૫ એમએમટીપીએ ક્ષમતાવાળુ બીજુ ટર્મિનલ કાર્યાન્વિત થવાના આખરી તબક્કામાં છે.

(૩) આ બન્ને ટર્મિનલોને ૧૦ એમએમટીપીએ સુધી વિસ્તારવાનું આયોજન.

(૪) એલ.એન.જીના વધુ પુરવઠાને ખરીદવા ઈન્ડીયન ઓઈલ કોર્પો. સાથે કરારો કર્યા.

(૫) ગુજરાતના ૧૬૦૦ કી.મી.ના દરિયા કિનારે પેટ્રોલીયમ માટે સ્પેશ્યલ ઈકોનોમીક ઝોન વિકસાવવાની વિચારણા.

(૬) ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિ. દ્વારા હઝીરાથી કલોલ સુધીની ૪૩૦ કી.મી. લાંબી ગેસ પરિવહન લાઈન કાર્યરત વિવિધ ગ્રાહકોને ગેસ વિતરણની કામગીરી ચાલુ.

(૭) ઉર્જા ઉત્પાદન તથા ઔધોગિક એકમોને હાલમાં અપાતા ૧૭ એમ.એમ.એસ.સીએમ.ડી. ગેસના પુરવઠામાં વધારો કરી સને ૨૦૦૭ સુધીમાં ૪૦

એમ.એમ.એસ.સી.એમ.ડી. સુધી કરવાનું આયોજન.

(૮) પાઈપલાઈન મારફત અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ ભાવનગર જી.આઈ.ડી.સી. વિસ્તાર તથા સૌરાષ્ટ્રના બાકીના વિસ્તારોમાં ગેસ વિતરણ માટેના પગલાં લેવાયા.

(૯) અમદાવાદ ખાતે વાહનોના ઉપયોગ સારૂ સીએન.જી. પૂરો પાડવા ત્રણ સીએન.જી સ્ટેશનો કાર્યરત વર્ષના અંત સુધીમાં કુલ ૨૦ સીએન.જી.સ્ટેશનો સ્થાપવાનું આયોજન.

(૧૦) રાજ્યના સિરામીક તથા અન્ય ઉદ્યોગોને ગેસ ઉપલબ્ધ કરવાનું આયોજન.

(૧૧) વાહનોમાં સી.એન.જીના ઉપયોગને વ્યાપક બનાવવા અંગેના કાયદાની વિચારણા.

(૧૨) ગુજરાતમાં નિષ્ણાત વિદેશી સંસ્થાના સહયોગથી પેટ્રોલિયમ તથા ગેસ અંગે લોકોને તાલીમ આપવા તથા સંશોધનો કરવા ગુજરાત એનર્જી રીસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઈન્ટીટ્યુટની સ્થપના.

(૨) તા. ૩૧-૧-૦૫ના રોજની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કુદરતી ગેસની કુલ ઉપલબ્ધી કેટલી છે ?

(૨) તા. ૩૧-૧-૦૫ના રોજની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કુદરતી ગેસની કુલ ઉપલબ્ધી નીચે મુજબ છે.

- ૪.૦૦ એમ.એમ.એસ.સી.એમ.ડી. - જીએસ.પી.સી. નાઈકો
- ૧.૮૦ એમ.એમ.એસ.સી.એમ.ડી.-ક્રેઈન એર્નજી લી.
- ૦.૨૦ એમ.એમ.એસ.સી.એમ.ડી.-નાઈકો રીસોર્સીઝ લી.
- ૭.૫૦ એમ.એમ.એસ.સી.એમ.ડી.-પેટ્રોનેટ એલએનજી
- ૧૮.૦૦ એમ.એમ.એસ.સી.એમ.ડી.-ઓએનજીસી-ગેઈલ.
- ગુજરાતમા કુલ ગેસ ઉપલબ્ધ ૩૧.૦૦ એમ.એમ. એસ.સી.એમ.ડી.ની છે.

કચ્છ જિલ્લામાં ગુમ થયેલ કે ખોવાયેલ ગયેલ વ્યકિતઓ

૮૦૩૦ **શ્રી ગોપાલભાઈ ગા.ધુઆ** (મુન્દ્રા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં સને ૨૦૦૪ના કેલેન્ડર વર્ષમાં કુલ કેટલી વ્યકિતઓ ગુમ થઈ કે ખોવાઈ ગઈ છે,	(૧) ૨૦૦ (બસો)
(૨) તે પૈકી તા. ૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા કુલ કેટલી વ્યક્તિઓને શોધી કાઢવામાં આવી,	(૨) ૧૦૩ (એકસોત્રણ)

(૩) બાકી રહેલી વ્યક્તિઓને શોધી કાઢવા પેલીસતંત્ર દ્વારા શું આયોજન થયેલ છે, અને	(૩) નામ. સર્વોચ્ચ અદાલતે ક્રિમીનલ રીટ પીટીશન નં. ૬૧૦/૧૯૯૬માં આપેલ ચુકાદામાં આપેલ માર્ગદર્શક સુચનાઓ મુજબ આયોજન કરવામાં આવે છે.
(૪) આ જવાબદારી કોને સોપવામાં આવી છે?	(૪) પોલીસ તંત્રમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ/આસીસ્ટન્ટ સબ ઈન્પેક્ટર સંવર્ગના કર્મચારીઓને આ જવાબદારી સોંપેલ છે વધુમાં ગુમ થયેલ કે ખોવાયેલ વ્યક્તિના વર્ણન તેમજ અન્ય જરૂરી માહિતી સાથેના મેસેજ સંબંધિત જિલ્લામાં તેમજ સમગ્ર રાજ્યમાં મોકલવામાં આવે છે. ઉપરાંત દૂરદર્શન અમદાવાદ પર આવી વ્યક્તિઓના ફોટા પ્રસિધ્ધિ હેતુ માટે મોકલવામાં આવે છે.

જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં એફ.આઈ.આર. નહીં નોંધવા અંગે

૮૨૧૪ **શ્રીમતી જસુબેન સ.કોરાટ**(જેતપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં સન ૨૦૦૪ના કેલેન્ડર વર્ષમાં પેલીસ સ્ટેશનમાં એફ.આઈ.આર. ન નોંધવાના કેટલા કિસ્સા બન્યા છે,	(૧) એક પણ નહી.
(૨) કયા કયા કર્મચારીઓ તેને માટે જવાબદાર ઠેરવાયા, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) તેમને શી શિક્ષા થઈ ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ફોરેન્સીક લેબોરેટરીની આધુનિકરણની યોજના

૯૨૧૪ **ડૉ. અતુલ કે. પટેલ** (કલોલ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યની ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરીના આધુનિકરણની કોઈ યોજના અમલમાં છે, કે કેમ,	(૧) હા,જી.
(૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૦૩-૨૦૦૪માં તે પેટે કેટલી રકમ ખર્ચવામાં આવી, અને	(૨) પોલીસદળ આધુનિકરણ યોજના હેઠળ ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી માટે કુલ રૂા. ૪૬૦/- લાખનું અનુદાન ફાળવેલ હતું જેમાંથી સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષમાં રૂા. ૪૫૭.૯૬/-લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.
(૩) આ રકમ પૈકી કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી કોઈ રકમ મેળવવામા આવેલ છે કે કેમ ?	(૩) આ યોજના ૬૦ ટકા કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના છે આથી ૬૦ ટકા ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર ભોગવે છે.

પાલનપુર શહેરમાં ચોરીના બનાવો

૯૩૬૮ **શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી**(દાંતા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર શહેરમાં સને ૨૦૦૪ના વર્ષમાં ૬૨ [illegible] ઘરફોડ ચોરીઓ	(૧) ચોકીઓના નામ

સને ૨૦૦૪ના વર્ષમાં દર માસે પ્રત્યેક પોલીસ ચોકીની હકુમત હેઠળના વિસ્તારમાં ચોરીના કેટલા બનાવો બન્યા,

માસ	ઢુંઢીયા વાડી	સીમલા	માન સરોવર	નાની બજાર
જાન્યુ.	૦૧	૦૨	--	--
ફેબ્રુ.	૦૧	૦૧	--	--
માર્ચ	૦૨	૦૪	--	--
એપ્રિલ	૦૩	૦૪	૦૧	૦૨
મે	૦૩	૦૪	--	૦૧
જૂન	૦૧	૦૬	૦૨	--
જુલાઈ	૦૨	૦૧	--	૦૨
ઓગષ્ટ	૦૧	૦૨	૦૨	--
સપ્ટે.	૦૧	૦૨	--	--
ઓકટો.	૦૩	૦૧	--	--
નવે.	૦૫	--	--	--
ડીસે.	૦૨	૦૨	૦૨	૦૧
કુલ	૨૫	૨૯	૦૭	૦૬

(૨) દરેક બનાવમાં કેટલા ચોર પકડવામાં આવ્યા તેમ કેટલી રકમનો ચોરીનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો, અને

(૨)

અ.નં	ગુ.ર. નં.	તહોમતદારો ની સંખ્યા	કબજે કરેલ ચોરીના મુદ્દામાલની રકમ રૂા.
૧	૧૨/૦૪	૦૨	રૂા. ૧૦,૯૦૦/-
૨	૨૨/૦૪	૦૪	રૂા.૨,૫૦,૦૦૦/-
૩	૨૩/૦૪	૦૨	રૂા. ૪,૫૦૦/-
૪	૩૯/૦૪	૦૩	રૂા. ૧,૨૫,૦૦૦/-
૫	૫૧/૦૪	૦૨	રૂા. ૫૦,૦૦૦/-
૬	૫૫/૦૪	૦૧	---
૭	૫૬/૦૪	૦૧	---
૮	૫૮/૦૪	૦૧	---
૯	૫૯/૦૪	૦૧	---
૧૦	૬૪/૦૪	૦૨	રૂા. ૧,૨૯,૨૫૧/-
૧૧	૮૭/૦૪	૦૧	રૂા. ૫૦,૪૦૬૫/-
૧૨	૧૧૪/૦૪	૦૧	---
૧૩	૧૪૩/૦૪	૦૨	---
૧૪	૧૪૮/૦૪	૦૩	રૂા. ૪૦,૫૦૦/-
૧૫	૧૯૮/૦૪	૦૧	રૂા. ૪૦,૦૦૦/-
૧૬	૨૧૬/૦૪	૦૧	રૂા. ૬૦૦/-
૧૭	૨૧૮/૦૪	૦૧	રૂા. ૧,૦૦૦/-
૧૮	૨૧૯/૦૪	૦૧	રૂા. ૩૧૫૦/-
કુલ	૧૮	૩૦	રૂા.૧૧,૫૮,૯૬૬/-

(૩) ચોરીના ઉપદ્રવ સામે શહેર પોલીસની ઉદાસીનતા નાબુદ કરવા લેવાયેલ પગલાંની વિગતો શું છે?

(૩) એલ. સી. બી. તેમજ સ્થાનિક પોલીસના માણસો/અધિકારીઓ દ્વારા રાત-દિવસ ચોરીના બનાવો સામે ખાનગી કપડામાં, ખાનગી વાહનોમાં પેટ્રોલીંગ ચાલુ રાખેલ છે. પોલીસ મિત્ર બનાવી ખાનગી રાહે હકિકત મેળવવામાં આવે છે. તેમજ નંબર વગરના વાહનોને ડીટેઈન કરવામાં આવે છે. વેચાયેલ વાહનોની માલીકી બાબતે ચેકીંગ પણ કરવામાં આવે છે તથા પોલીસના કસુર બદલ શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં આવે છે.

કેનાલ ડેમ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન

૮૮૮૧ **શ્રી યોગેશભાઈ ના.પટેલ** (રાવપુરા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ની સ્થિતિએ સરદાર સરોવર યોજનાના વીજ મથકો કયા તબક્કે છે,	(૧) (૧) નહેર આમુખ વિદ્યુત મથકના ૫૦ મેગાવોટના એક એવા પાંચ એકમો કાર્યાન્વિત થયેલ છે. (૨) નદીતળ ભૂગર્ભ જળ વિદ્યુત મથકનું ૨૦૦ મેગાવોટનું પ્રથમ એકમ જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ના અંતમા કાર્યાન્વિત થયેલ છે. બાકીના એકમોની કાર્યવાહી જુદા જુદા તબક્કે છે.
(૨) કેનાલ ડેમ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન ક્યારથી શરૂ થયું,	(૨) તા. ૧૬-૮-૨૦૦૪થી
(૩) જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ના અંત સુધીમાં કેનાલ હેડ પાવર હાઉસમાંથી કેટલું વીજ ઉત્પાદન થયું, અને	(૩) ૧૫.૦૭ કરોડ યૂનિટ
(૪) આ વીજ ઉત્પાદન ક્યાં સુધી ચાલુ રહેશે?	(૪) મુખ્ય બંધના જળાશયમાં પાણીનું સ્તર ૧૧૦.૧૮ મીટર સુધી નીચું જાય ત્યાં સુધી નહેર આમુખ વિદ્યુત મથક કાર્યરત રહેશે.

રાજ્યમાં મોલાસીસનું ઉત્પાદન અને નિકાસ

૮૯૨૬ **શ્રી ટપુભાઈ લીંબાસિયા**(રાજકોટ-૧) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં ખાંડસરીમાંથી મોલાસીસનું ઉત્પાદન કેટલા ટન થયું,	(૧) મોલાસીસ વર્ષ (ઓકટોબર થી સપ્ટેમ્બર) મે. ટનમાં ૨૦૦૨-૦૩ - ૫,૬૩,૦૮૪ ૨૦૦૩-૦૪ - ૪,૪૬,૭૫૫
(૨) રાજ્યના ઉદ્યોગ માટે મોલાસીસની કેટલા ટનની જરૂરીયાત છે, અને	(૨) ચાલુ મોલાસીસ વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં ૭,૩૫,૮૨૦ મે.ટનની જરૂરીયાતનો અંદાજ છે.
(૩) ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં ડિસેમ્બર-૦૪ સુધીમાં ગુજરાતમાંથી મોલાસીસની કેટલા ટનની નિકાસ કરવામાં આવી ?	(૩) વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં (એપ્રિલ-૦૪ થી ડિસે-૦૪ સુધી) ૫૩,૮૧૦ મે.ટનની નિકાસ કરવામાં આવી.

લીંબડી શહેરમાં દારુના અડ્ડાઓ અંગે મળેલ ફરિયાદો

૮૫૨૩ **શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ** (લીંબડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૧-૧-૦૪ થી તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં લીંબડી શહેરમાં દારુના અડ્ડાઓ બંધ કરવા બાબત કેટલી ફરિયાદો રાજ્ય સરકારને તેમજ પોલીસવડા સુરેન્દ્રનગરને મળેલ છે,	(૧) પાંચ.
(૨) આ અંગે સરકારે, પોલીસવડાએ, સ્થાનિક પોલીસે તથા નશાબંધી ખાતાએ શી કાર્યવાહી કરી છે	(૨) કુલ-૧૨૩ રેઈડો કરી, ૭૧-ગુના શોધી કરવામાં આવેલ છે

પોલીસે તથા નશાબંધી ખાતાએ શી કાર્યવાહી કરી છે.

કાઢવામાં આવેલ છે.

(૩) કેટલી ધરપકડો થઈ છે, તેમજ કેટલો દારૂ પકડાયેલ છે, અને

(૩) કુલ-૭૫ તહોમતદારોની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે, તથા દેશી દારૂ-૫૧૩ લીટર અને વિદેશી દારુ-૨૫૯ બોટલ પકડાયેલ છે.

(૪) દારુના કેટલા દરોડા નિષ્ફળ ગયા છે ?

(૪) ૫૨. (બાવન)

કડી તાલુકામાં દારુના અડ્ડાઓ ઉપર દરોડા

૮૮૪૫ **શ્રી બળદેવજી ચં.ઠાકોર** (કડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કડી તાલુકામાં દારુના અડ્ડાઓ ઉપર કેટલા દરોડા પાડવામાં આવ્યા,

(૧) ૧૨૪૯.

(૨) કેટલા ગુનેગારો પકડાયા,

(૨) ૧૦૫૯

(૩) આ ગુનેગારો સામે શું પગલાં ભરવામાં આવ્યા,

(૩) નશાબંધી અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. તથા રીઢા ગુનેગારો સામે પાસા હેઠળ એક, પ્રોહી. એકટની કલમ-૯૩ મુજબ કુલ : ૯૩ અને બોમ્બે પોલીસ એકટની કલમ-૫૬ (ખ) મુજબ-૪ હદપારીના પગલાં લેવામાં આવેલ છે.

(૪) કેટલી રકમનો દારુનો જથ્થો પકડવામાં આવ્યો, અને

(૪) દેશી દારૂ-૪૦૪૭ લીટર, કિંમત રૂા. ૮૦૯૪૦/- અને વિદેશી દારૂ-૨૬૫૮ બોટલ, કિંમત રૂા. ૮,૧૦,૩૦૪ પકડાયેલ છે.

(૫) દારુના અડ્ડાઓ સામે અસરકારક પગલાં ભરવામાં પોલીસની નિષ્ક્રીયતા સંદર્ભે કેટલી કેટલી ફરિયાદો મળી અને શાં પગલાં ભરવામાં આવ્યા ?

(૫) આવી કોઈ પરિયાદ મળેલ નથી, પરંતુ નશાબંધી ખાતાના એક કોન્સ્ટેબલ વિરૂધ્ધ લાંચના આક્ષેપો કરતી એક અનામી રજુઆત મળેલ. જે અંગે નાયબ કમિશ્નર અને પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, નશાબંધી અને આબકારી મારફત તપાસ કરાવતા, આક્ષેપો ખોટા હોવાનું જણાયેલ છે.

વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ ગામોનો સમાવેશ

૮૭૨૯ **શ્રી દિલુભા ટે. ચુડાસમા** (વડોદરા ગ્રામ્ય) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ઉર્જા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ ગામો પૈકી ૨૪ કલાક વિજ વિતરણ અંગેની જ્યોતિગ્રામ યોજનામાં કુલ કેટલા અને કયા કયા ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે,

(૧) વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારના બધાજ ગામો (૧૫૪૮) જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ આવરી લીધેલ છે.

(૨) ડીસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ તે પૈકી કુલ કેટલા ગામોમાં આ યોજનાનો વાસ્તવિક અમલ શરૂ થયેલ છે, અને.

(૨) ૮૯ ગામો

(૩) અન્ય લાભાર્થી ગામોમાં અમલ શરૂ કરવા અંગેના આયોજનની વિગતો શું છે ?

(૩) શક્ય તેટલા વહેલા.

મહેસાણા જિલ્લામાં ઘરફોડ ચોરીના બનાવો

૯૩૨૦ **શ્રી નારાયણભાઇ લ.પટેલ**(ઉંઝા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં મહેસાણા જિલ્લામાં કેટલી ઘરફોડ ચોરીઓ થઇ,	(૧) ૨૨૧.
(૨) કેટલા કિસ્સામાં ગુનેગારો પકડાયા,	(૨) ૪૮.
(૩) કેટલા કિસ્સામાં તપાસ બાકી છે, અને	(૩) ૨૦.
(૪) ક્યારે પૂર્ણ થશે ?	(૪) ૧૧ કેસો અનડીટેકટ હોઇ સજેશનવાળા ઇસમોને તપાસવા પર બાકી છે. તથા ૯ કેસોમાં ચાર્જશીટ કરવા પર બાકી છે.

રાજ્યમાંથી આતંકવાદીઓ પકડવા અંગે

૮૧૮૫ **શ્રી જયંતિલાલ ૨ા. કવાડિયા**(હળવદ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્યમાંથી છેલ્લા એક વર્ષમાં આંતકવાદીઓને પકડવામાં આવ્યા છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો કેટલા પકડવામાં આવ્યા, અને	(૨) ૩૦ (ત્રીસ).
(૩) આવા આતંકવાદીઓ પાસેથી કેટલા હથિયારો અને દારુગોળો પકડાયો છે?	(૩) ૨ (બે) વિદેશી પિસ્તોલ તથા ૨૦ (વીસ) કારતુસ.

ભાવનગર જિલ્લામાં લૂંટના નોંધાયેલ ગુનાઓ

૮૭૧૧ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી**(ભાવનગર શહેર ઉત્તર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૫ સુધી ભાવનગર જિલ્લામાં છેલ્લા વર્ષમાં લૂંટના કેટલાં અને કયા કયા ગુન્હા નોંધાયા,	(૧) ૯૫ (પંચાણું).
(૨) દરેકમાં કેટલી રકમની લૂંટ થયેલ અને રકમ પરત આવી કે કેમ, અને	(૨) રૂા.૨૧,૬૬,૮૬૯/-ની લૂંટ થયેલ અને રૂા.૮,૮૬,૨૦૯/- પરત આવેલ.
(૩) લૂંટના આ ગુનાઓમાં કેટલા તહોમતદારો પકડાયા અને કેટલા બાકી છે?	(૩) ૧૭૦ તહોમતદારો પકડાયા. ૩૭ તહોમતદારો પકડવાના બાકી છે.

સરદાર સરોવરના પાણીથી સાવલી તાલુકાના ગામોને સિંચાઇનો લાભ

૮૯૩૭ **શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર.ગોહિલ** (સાવલી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સાવલી તાલુકામાં સરદાર સરોવરના પાણીથી સિંચાઇનો કેટલા ગામોને લાભ મળે છે,	(૧) લાભિત ૧૧૪ પૈકી ૫૮ (અઠ્ઠાવન) ગામોને લાભ મળે છે.
(૨) ૨૦૦૪-૦૫ ના વર્ષમાં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ તાલુકામાં કેટલા તળાવો ભરવામાં આવ્યા છે, અને	(૨) ૨ (બે).
(૩) આવતા ઉનાળામાં તળાવો ભરવાનું શું આયોજન છે?	(૩) જે તે ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા/જિલ્લા પંચાયત સત્તા મંડળ તરફથી આવેલ માંગણી અને નર્મદા યોજનામાં પાણીની ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમાં લઇ માંગણી મુજબ તળાવો ભરવાનું આયોજન કરવામાં આવશે.

અધિકારી/કર્મચારીઓને કર્મયોગીની તાલીમ

૮૪૮૦ **શ્રી પરેશભાઇ ધી.ધાનાણી** (અમરેલી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ કુલ કેટલા અધિકારીઓ-કર્મચારીઓને કર્મયોગીની તાલીમ આપવામાં આવી,	(૧) ૯૬,૫૬૫.
(૨) તેની પાછળ કુલ કેટલો ખર્ચ થયો,	(૨) ચૂકવવાપાત્ર ખર્ચની રકમ રૂ.૨,૪૧,૪૧,૨૫૦ ખરેખર ચૂકવેલ ખર્ચની રકમ રૂ.૮૩,૧૦,૭૫૦ (ડિસેમ્બર-૦૪ અંતિત)
(૩) આ કર્મયોગી અંતર્ગત સ્થાન્તઃ સુખાય કાર્યક્રમ હેઠળ અધિકારીઓ દ્વારા હાથ ધરાયેલ જિલ્લા કક્ષાના ૫૩ તથા તાલુકા કક્ષાના ૨૭૦ પ્રોજેકટો પૈકી કેટલા પૂર્ણ થયા, અને કેટલા બાકી છે, અને	(૩) કર્મયોગી યોજના અંતર્ગત સ્વાન્તઃ સુખાય કાર્યક્રમ હેઠળ અદ્યતન માહિતી મુજબ જિલ્લા કક્ષાએ ૮૦ પ્રોજેકટ અમલમાં મુકાયેલ છે તે પૈકી ૪૯ પ્રોજેકટ પૂર્ણ થયેલ છે. જયારે તાલુકા કક્ષાના કુલ ૩૦૭ પ્રોજેકટ અમલમાં મુકાયેલ છે. તે પૈકી ૧૮૩ પ્રોજેકટ પૂર્ણ થયેલ છે, જયારે ૧૨૪ પ્રોજેકટ બાકીમાં છે.
(૪) આ પ્રોજેકટથી પ્રજાને શું ફાયદો થાય તેમ છે?	(૪) (૧) જળસંચય યોજના દ્વારા પાણીનો સ્તર ઉંચો લાવવાનો. (૨)રેકર્ડનો કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન દ્વારા લોકોને ત્વરિત નકલો આપવાનો (૩)શિક્ષણ ક્ષેત્રે સાક્ષરતા વધારો, કન્યા કેળવણી દરમાં વધારાનો. (૪) આરોગ્ય ક્ષેત્રે બાળ તથા માતાના મરણ દરમાં ઘટાડાનો, કુટુંબ નિયોજનની જાગૃતિ આણવાનો અને બાળકોને ૧૦૦% રસીકરણનો. (૫)ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા જનસેવા કેન્દ્ર હેઠળ લોક ઉપયોગી કાર્યક્રમ કરીને વહીવટી સેવાઓ અસરકારક બનાવવાનો.

	(૬)લોકોની પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં વધારો કરવાનો. (૭)જિલ્લા/તાલુકાના પ્રોજેકટ માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સર્વાંગી વિકાસ, પ્રજાભિમુખ વહીવટ દ્વારા કામગીરીમાં વેગ લાવવાનો. (૮)ઉર્જા ક્ષેત્રે સૌર શકિત દ્વારા વીજળી ઉત્પાદન કરીને રાજ્યની ઉર્જા શકિતમાં વધારો લાવવાનો. (૯)સામાજિક રીતે પછાત તથા અપંગ સહાય યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને વધુને વધુ લાભ મળે તેવો. (૧૦)આપત્તિનો સામનો જાતે કરવા અંગે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો.

ઔદ્યોગિક નીતિ જાહેર કર્યા બાદ લીધેલાં પગલાં

૯૩૩૯ **શ્રી શંકરભાઇ વી. રાઠવા**(છોટા ઉદેપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
રાજ્ય સરકારે સન ૨૦૦૩માં નવી ઔદ્યોગિક નીતિ જાહેર કરી ત્યાર પછી તેના અમલીકરણ માટે કયા પગલાંઓ લીધાં છે?	રાજ્ય સરકારે સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૩માં નવી ઔદ્યોગિક નીતિ જાહેર કરી ત્યાર પછી તેના અમલીકરણ માટે જુદા જુદા પ્રોત્સાહનોને લગતાં ઠરાવો બહાર પાડેલ છે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે. ૧. લઘુ ઉદ્યોગ તેમજ મધ્યમ કક્ષાના એકમો માટે વ્યાજ સહાય યોજના. ૨. લઘુ તેમજ મધ્યમ કક્ષાના એકમો માટે ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠળ સહાય યોજના. ૩. લઘુ અને મધ્યમ કદના એકમો માટે ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન યોજના. ૪. રીસર્ચ અને ડેવલોપમેન્ટ માટેની સહાય યોજના. ૫. ક્રિટીકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર પ્રોજેકટ યોજના. ૬. કોમન પોલ્યુશન કન્ટ્રોલ એન્ડ ડીસ્પોઝલ યોજના. ૭. કલ્સ્ટર ડેવલપમેન્ટ યોજના. ૮. ડેવલપેન્ટ કાઉન્સીલની રચના. ૯. ઔદ્યોગિક પાર્ક યોજના. ૧૦. પર્યાવરણની જાળવણી માટે યોજના. ૧૧. માંદા એકમોના પુનરુત્થાન માટે યોજના.

બનાસ નદીમાં નર્મદાનું પાણી આપવા અંગે

૯૩૫૦ **શ્રી ધારશીભાઇ લ.ખાનપુરા** (કાંકરેજ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યની બનાસ નદીમાં નર્મદાનું પાણી વહેતું કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવ	(૧) પાણીની ઉપલબ્ધી અને યોજનાના પિયત વિસ્તારની જરૂરીયાત ધ્યાને લઇ વધારાનું પાણી

વહેતું કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ આયોજન કરેલ છે, અને	વિસ્તારની જરૂરીયાત ધ્યાને લઇ વધારાનું પાણી જરૂરીયાત અનુસાર બનાસ નદીમાં વહેવડાવી શકાશે.
(૨) જો હા, તો તેની શી વિગતો છે?	(૨) મુખ્ય નહેરમાં બનાસ નદી પર એસ્કેપ મૂકવાનું આયોજન છે.

સરદાર સરોવર યોજના વિદ્યુત મથકની ક્ષમતા

૮૮૭૩ **શ્રી અંબાલાલ આ.રોહિત**(સોજીત્રા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરદાર સરોવર યોજના અંતર્ગત વિદ્યુત મથકોની ક્ષમતા શું છે, અને	(૧) સરદાર સરોવર યોજનામાં બે જળવિદ્યુત મથકો છે. (૧) નહેર આમુખ વિદ્યુત મથક અને (૨) નદી તળ ભૂગર્ભ વિદ્યુત મથક. નહેર આમુખ વિદ્યુત મથકની સ્થાપિત ક્ષમતા ૨૫૦ મેગાવોટની છે. જયારે નદીતળ ભૂગર્ભ વિદ્યુત મથકની સ્થાપિત ક્ષમતા ૧૨૦૦ મેગાવોટની છે. આમ વિદ્યુત મથકોની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા ૧૪૫૦ મેગાવોટની છે.
(૨) ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઇએ વિદ્યુત ઉત્પાદન કેટલું થાય?	(૨) ડેમમાં પાણીની ૧૧૦.૬૪ મીટરની સપાટીએ નહેર આમુખ વિદ્યુત મથકના એક એકમમાંથી ૧૮ મેગાવોટ વિદ્યુત ઉત્પાદન થાય, જ્યારે નદીતળ ભૂગર્ભ વિદ્યુત મથકના એક એકમમાંથી ૧૬૪ મેગાવોટ વિદ્યુત ઉત્પાદન થાય.

વીજ ખાધ ઘટાડવા કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળેલી સહાય

૮૯૧૬ **શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી**(ડીસા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યના વિજળીના પ્રસારણ અને વિતરણમાં જતી ખોટ ઘટાડવા માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્ય સરકારને ૨.૭૫ કરોડ ફાળવેલ છે તે હકીકત સાચી છે,	(૧) "ત્વરિત વીજળી વિકાસ અને સુધારણા કાર્યક્રમ" (એપીડીઆરપી) હેઠળ તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ રૂા.૧૭૧.૬૦ કરોડ મળેલ છે.
(૨) જો હા તો રાજ્ય સરકારે વીજ ખાધ ઘટાડવા આ રકમનો ઉપયોગ કર્યો છે કે કેમ, અને	(૨) એપીડીઆરપી યોજના હેઠળ મળેલ રકમનો ઉપયોગ વીજ તંત્રની સુધારણા માટે હોઇ, તેના થકી વીજવ્યય ઘટાડવા પણ ઉપયોગ થાય છે.
(૩) જો હા, તો તેની વિગતો કઇ કઇ છે?	(૩) બોર્ડ દ્વારા વીજ ખાધ ઘટાડવા સામાન્ય વિકાસ યોજના અંતર્ગત સીસ્ટમ સુધારણા યોજના હેઠળ સાત મુદ્દાનો કાર્યક્રમ ઘડેલ છે, જે અન્વયે મુખ્યતઃ વધુ ભાર ધરાવતા વીજ રેષાઓનું વિભાજન, વિતરણ કેન્દ્રને લોડ સેન્ટર નજીક ખસેડવું, જુના જર્જરીત વીજરેષાઓ બદલવા, ખામીયુકત તથા બંધ પડી ગયેલ મીટર બદલવા, દરેક વીજ જોડાણોને સંપૂર્ણપણે વીજચોરીથી સુરક્ષિત કરવા, ગેરકાયદેસર વીજ વપરાશ

તથા વીજચોરી ડામવા સઘન વીજ સ્થાપનનું ચેકીંગ વિગેરે હાથ ધરવામાં આવે છે.

આ સીસ્ટમ સુધારણા યોજના હેઠળ ગત બે વર્ષ દરમ્યાન કરેલ કાર્યવાહીની વિગત પત્રકમાં સામેલ છે.

પત્રક

સીસ્ટમ સુધારણા યોજના હેઠળ કરેલ કામગીરી વિગત

અનુ. નં.	વિગત	૨૦૦૨-૦૩		૨૦૦૩-૦૪		૨૦૦૪-૦૫ (ડિસેમ્બર-૦૪ સુધી)	
		લક્ષ્યાંક	સિધ્ધિ	લક્ષ્યાંક	સિધ્ધિ	લક્ષ્યાંક	સિધ્ધિ
૧.	વીજરેષા વિભાજન (સંખ્યા)	૫૩૧	૯૮	૬૭૨	૨૩૬	૭૦૯	૨૪૧
૨.	વીજ વિતરણ કેન્દ્ર લોડ સેન્ટરમાં લાવ્યા (સંખ્યા)	૧૩૪૩	૬૪૮	૧૧૫૬	૬૫૦	૧૦૪૮	૫૦૨
૩.	જુના જર્જરીત વીજરેષા બદલવા (કિ.મી.)	૧૨૮૪૧	૬૭૫	૧૫૦૦૭	૮૦૯	૧૬૨૫૭	૧૪૪૦

રાજ્યમાથી મીઠાની નિકાસ

૯૩૩૦ **શ્રી મધુભાઇ બા. શ્રીવાસ્તવ**(વાઘોડિયા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) મીઠાના ઉત્પાદન પૈકી ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ વાર્ષિક કેટલું મીઠું રાજ્યમાંથી દેશ બહાર નિકાસ થાય છે, અને	(૧) ગુજરાત રાજ્યમાંથી જાન્યુઆરી-૦૪ થી ડિસેમ્બર-૦૪ સુધીમાં ૨૦.૮૧ લાખ મે.ટન મીઠું નિકાસ થયેલ છે.
(૨) આ નિકાસ વધે તે માટે સરકાર કોઇ પગલાં લેવાં માંગે છે કે કેમ?	(૨) આ અંગેના જરૂરી પગલાં લેવાયાં છે.

અમદાવાદ શહેરમાં પી.આઇ.ની અને પોલીસ કર્મચારીઓની ખાલી જગ્યાઓ

૮૬૨૬ **ડૉ. જીતેન્દ્રભાઇ બા.પટેલ**(સાબરમતી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદ શહેરના પોલીસ સ્ટેશનોમાં તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર તથા પોલીસ કર્મચારીઓની જગ્યા ખાલી છે, અને	(૧) (૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ના રોજ અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ ઇન્સ્પેકટરની કોઇ જગ્યા ખાલી નથી, અને (૨) પોલીસ કર્મચારીઓની કુલ ૧૦૫૩ જગ્યાઓ ખાલી છે.
(૨) આ જગ્યાઓ કયારે ભરવામાં આવશે?	(૨) વહીવટી અનુકૂળતાને આધીન શક્ય તેટલી વહેલાં.

એસ.ટી.ની સમાંતર ગેરકાયદે ચાલતા પરિવહન અંગે વસૂલ આવેલ દંડ

૯૩૭૪ **શ્રી મહેશભાઇ સો. ભુરિયા** (લીંમડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) એસ.ટી. સમાંતર ગેરકાયદેસર ચાલતા ખાનગી પરિવહનમાં મોટા ભાગના વાહનો પોલીસના અથવા તેમના સગાઓ મારફતે ચાલે છે તે હકીકત સાચી છે,	(૧) ચેકીંગ દરમ્યાન આવી કોઇ બાબત ધ્યાન ઉપર આવેલ નથી.
(૨) ૨૦૦૪ના કેલેન્ડર વર્ષમાં ગેરકાયદેસર પરિવહનના કેટલા કેસ કરવામાં આવ્યા,	(૨) કુલ : ૪૪,૦૫૭.
(૩) કેટલા વાહનો ડીટેઇન કરવામાં આવ્યા, અને	(૩) કુલ : ૯૬૬૭.
(૪) કેટલો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો?	(૪) કુલ રૂા.૭,૮૪,૩૮,૦૬૯/-.

સરદાર સરોવર બંધની ૧૨૧.૯૨ મીટરની ઊંચાઇએ સાથી રાજ્યોને મળનાર લાભ

૮૮૬૪ **શ્રી હરજીવન હી. પટેલ** (ધાનેરા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી વધવાથી મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનને શું લાભ મળશે,	(૧) સરદાર સરોવર ડેમની મુખ્ય છલતીની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ વિદ્યુત ઉત્પાદન કરવાનું આયોજન છે. આ વિદ્યુતના ૫૭ ટકા મધ્યપ્રદેશ રાજ્યને અને ૨૭ ટકા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યને ભાગે મળશે. રાજસ્થાનને મુખ્ય નહેર પૂર્ણ થતાં ૦.૫૦ મીલીયન એકરફીટ પાણી મળશે.
(૨) ૧૨૧.૯૨ મીટર ઊંચાઇ વધવાથી કેટલું વીજ ઉત્પાદન થશે, અને	(૨) વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ.
(૩) બંધની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી થતાં રાજ્યમાં કેટલા વિસ્તારને સિંચાઇ માટે પાણી આપી શકાશે?	(૩) બંધની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી થતાં રાજ્યમાં સને ૨૦૦૫-૦૬ માં આશરે ત્રણ લાખ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઇ માટે પાણી આપવાનું આયોજન છે.

વઢવાણ તાલુકામાંથી બાંધકામના પત્થરની રોયલ્ટી ચોરી અંગે દંડ

૮૩૯૮ **શ્રી ધનરાજભાઇ કેલા** (વઢવાણ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વઢવાણ તાલુકામાંથી બાંધકામના પત્થરની રોયલ્ટી ચોરીના કેટલા અરજદારો પાસેથી કેટલો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો?	તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વઢવાણ તાલુકામાંથી બાંધકામના પત્થરના કુલ નવ અરજદારો પાસેથી કુલ રૂા.૧,૦૧,૪૦૦/- નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો.

વર્ષ	કરેલ કેસ	વસૂલ કરેલ દંડની રકમ (રૂા.)
૨૦૦૩	૦૨	૬,૦૦૦/-
૨૦૦૪	૦૭	૯૫,૪૦૦/-

કુલ :	૦૯	૧,૦૧,૪૦૦/-

ધોળકા તાલુકાના ગામોમાંથી ઢોરોની ચોરી થવાના બનાવો

૯૨૦૩ **શ્રી કાંતિલાલ રા. લકુમ** (બાવળા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ધોળકા તાલુકાના ગામોમાંથી છેલ્લા એક વર્ષથી ખેતરમાંથી અને ગામમાંથી રાત્રિના સમય દરમ્યાન વાછરડા, ગાયો અને બળદ ચોરવાનું પ્રમાણ વધી ગયેલ છે, તે વાત સાચી છે, અને

(૨) જો હા, તો તેને રોકવા શું આયોજન કરવામાં આવેલ છે?

જવાબ

(૧) ના, જી.

(૨) ગુનાનું પ્રમાણ સામાન્ય છે છતાં નાઇટ પેટ્રોલીંગ કરવામાં આવે છે.

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ખૂન, લૂંટ અને દારૂના કેસો

૯૧૮૮ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કુલ કેટલા ખૂનના, લૂંટના અને દારૂના કેસો નોંધાયા, અને

(૨) ખૂનના વધતા જતા પ્રમાણને રોકવા સરકાર શું પગલાં ભરવા માંગે છે?

જવાબ

(૧)

૨૦૦૩-૨૦૦૪			
તાલુકો	**ખૂન**	**લૂંટ**	**દારૂ**
હિંમતનગર	૦૭	૧૨	૧૭૧૪
પ્રાંતિજ	૦૫	૦૯	૮૪૭
તલોદ	૦૫	૦૩	૭૪૯
તાલુકો	**ખૂન**	**લૂંટ**	**દારૂ**
ઇડર	૧૦	૦૮	૮૬૧
વડાલી	૦૨	૦૧	૪૨૭
ખેડબ્રહ્મા	૧૧	૦૮	૫૦૯
વિજયનગર	૦૩	૦૧	૧૭૭
ભિલોડા	૧૬	૦૩	૭૬૬
મોડાસા	૦૩	૦૦	૨૦૩૦
મેઘરજ	૦૬	૦૨	૨૨૨
માલપુર	૦૨	૦૨	૨૧૮
ધનસુરા	૦૧	૦૧	૩૯૪
બાયડ	૦૪	૦૨	૮૩૪
કુલ :	**૭૫**	**૫૨**	**૯૭૪૮**

(૨) આવા ગુનાઓ ન બને તે સારૂ જુની અદાવતો, જમીન અને પાણીની તકરારોની જાણ થયેથી અસરકારક અટકાયતી પગલાં લેવા માટે સબંધિતોને સૂચના આપવામાં આવે છે.

પતંગ મહોત્સવ પાછળ થયેલ ખર્ચ

૮૫૪૨ **ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા** (માંગરોળ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

સન ૨૦૦૫માં સરકારે ઉજવેલ પતંગ મહોત્સવ પાછળ કુલ કેટલો ખર્ચ થયેલ છે?

જવાબ

થયેલ ખર્ચના બિલોની ચકાસણી કરીને ચૂકવણી કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં રૂા.૧૦૩.૧૪ લાખની રકમની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે.

સુરત જિલ્લામાં માટી ચોરીની ફરિયાદ

૮૫૭૨ **શ્રી અનિલકુમાર મો.પટેલ** (બારડોલી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) સુરત જિલ્લામાં તા.૧.૧.૦૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગેરકાયદે માટી ખોદીને વેચી મારવાની કેટલી ફરીયાદ મળી,

(૨) તે પૈકીની કેટલી ફરિયાદ માટે પગલાં ભરવામાં આવ્યા, અને

(૩) રોયલ્ટી ચોરી માટે કેટલો દંડ કરવામાં આવ્યો અને કયા શિક્ષાત્મક પગલાં કયા સ્થળે કયા ઇસમો સામે ભરવામાં આવ્યા?

જવાબ

(૧) સુરત જિલ્લામાં તા.૧.૧.૨૦૦૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગેરકાયદેસર માટી ખોદીને વેચી મારવાની ૧૮ ફરિયાદો મળી.

(૨) તે પૈકીની ૧૧ ફરિયાદમાં પગલાં ભરવામાં આવ્યા, એક ફરીયાદમાં તપાસ ચાલુ છે.

(૩) રોયલ્ટી ચોરી માટે **નીચે જણાવેલ પત્રક મુજબ ૨૮** ઇસમોને કુલ રૂા.૩,૮૭,૧૯,૭૬૫ નો દંડ કરવામાં આવેલ છે.

પ ત્ર ક

ક્રમ	કસુરદારનું નામ	સ.નં./બ્લોક નં.	ગામનું નામ	કરવામાં આવેલ દંડની રકમ (રૂપિયા)
૧	શ્રી રમેશભાઇ પટેલ	૭૧	મહુવા	૨,૫૦,૦૦૦
૨.	શ્રી ડી.જી.પટેલ	૬૦૮	માસમા	૧,૪૦,૦૦૦
૩.	શ્રી હઠેસિંહ મૂળજીભાઇ	૬૦૮	માસમા	૨,૫૦૦
૪.	શ્રી ડાહયાભાઇ ના.પટેલ	૬૦૮	માસમા	૨,૪૦૦
૫.	શ્રી ઇશ્વરભાઇ કલ્યાણભાઇ	૬૦૮	માસમા	૨,૦૦૦
૬.	શ્રી ભગવતીભાઇ પરાગભાઇ	૬૦૮	માસમા	૧૧,૮૦૦
૭.	શ્રી મનોજભાઇ મધુભાઇ	૬૦૮	માસમા	૨,૪૦૦
૮.	શ્રી કેતનભાઇ શાંતિભાઇ	૬૦૮	માસમા	૧,૬૦૦
૯.	શ્રી અલ્પેશભાઇ લલ્લુભાઇ	૬૦૮	માસમા	૧,૪૦૦
૧૦.	શ્રી પરીમલભાઇ પ્રમોદભાઇ	૬૦૮	માસમા	૧૮,૦૦૦
૧૧.	શ્રી અજયભાઇ પાનવાલા	૬૦૮	માસમા	૪૪,૮૦૦
૧૨.	શ્રી દુર્લભભાઇ જી.પટેલ	૩૮	જાફરાબાદની સીમ	૬૯,૭૦૦
૧૩.	શ્રી ફીરોજ અહમદ શેખ	૬૭	લીડીયાત	૭,૪૦૦
૧૪.	શ્રી પરશોત્તમભાઇ નારાયણભાઇ	૬૧૦	ભાઠા	૯,૦૦૦
૧૫.	શ્રી ભીખા દેવા આહીર	તળાવ	કોળીભરથાણા	૧૦,૦૦૦
૧૬.	શ્રી વિજયભાઇ નાનુભાઇ	૩૧	સોનારી	૩૦,૦૧૫
૧૭.	શ્રી સબ્બીર ઇસ્માઇલ કાસુજી	૧૦૭/૧૩૦	લાજપોર	૩૪,૬૫,૦૫૦

૧૮.	શ્રી ઇલીયાસ ઇસ્માઇલ કાસુજી	૧૦૩/૫૫	લાજપોર	૨૯,૨૯,૬૫૦
૧૯.	શ્રી મહંમદ સબીર કાસુજી	૧૩૪/૧૭૩	લાજપોર	૯,૨૫,૯૫૦
૨૦.	શ્રી અયુબ ઇસ્માઇલ કાસુજી	૧૧૦/૧૩૪	લાજપોર	૨૪,૨૧,૪૫૦
૨૧.	શ્રી હલીમા અહમદ કાસુજી	૧૧૪/૪	લાજપોર	૮,૮૩,૨૦૦
૨૨.	શ્રી ઇલીયાસ ઇસ્માઇલ કાસુજી	૧૩૬/૧૬૬	લાજપોર	૨૯,૫૧,૧૫૦
૨૩.	શ્રી ઇલીયાર ઇસ્માઇલ કાસુજી	૧૩૫/૧-બ	લાજપોર	૬૭,૯૬,૪૫૦
૨૪.	શ્રી ઐયબ ઇસ્માઇલ કાસુજી	૧૩૫/૨-અ	લાજપોર	૧૦,૧૯,૨૦૦
૨૫.	શ્રી ઇલીયાસ ઇસ્માઇલ કાસુજી	૨૧/૨૦	લાજપોર	૩૦,૩૩,૮૦૦
૨૬.	શ્રી સબ્બીર ઇસ્માઇલ કાસુજી	૮૬/૧, ૮૭/૧	લાજપોર	૪૭,૮૧,૩૫૦
૨૭.	શ્રી મોહન બાબર રાઠોડ	૧૧૨/૧૧૬	લાજપોર	૬૨,૫૫,૬૦૦
૨૮.	શ્રી મનોજકુમાર બી.પટેલ	૫૦૭	આભવા	૨૬,૫૪,૦૦૦
	કુલ :			**૩,૮૭,૧૯,૮૬૫**

જયારે નીચેના બે કેસોમાં આઇ.પી.સી. ૩૭૯ હેઠળ પોલીસ ફરીયાદ કરવામાં આવી છે.

ક્રમ	**કસુરદારનું નામ**	**સ.નં./બ્લોક નં.**	**ગામનું નામ**	**કરવામાં આવેલ દંડની રકમ (રૂપિયા)**
૧	શ્રી યોગેશભાઇ ગો.પટેલ તથા ૧૧ ઇસમો	૫૦૭	આભવા	૧૦,૦૦૦
૨.	અજાણ્યા ઇસમો	૧૪૪	ભેસ્તાન	૨,૦૦,૦૦૦
	કુલ :			**૨,૧૦,૦૦૦**

નવી ઔદ્યોગિક નીતિ અન્વયે લીધેલાં પગલાં

૯૩૩૩ **શ્રી કાંતીભાઇ ત્રિ. ભીલ** (નસવાડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

રાજ્ય સરકારે સપ્ટે.૨૦૦૩માં નવી ઔદ્યોગિક નીતિ જાહેર કરી ત્યાર પછી તેના અમલીકરણ માટે કયા પગલાંઓ લીધાં છે?

જવાબ

રાજ્ય સરકારે સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૩માં નવી ઓદ્યોગિક નીતિ જાહેર કરી ત્યાર પછી તેના અમલીકરણ માટે જુદા જુદા પ્રોત્સાહનોને લગતાં ઠરાવો બહાર પાડેલ છે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

૧. લઘુ ઉદ્યોગ તેમજ મધ્યમ કક્ષાના એકમો માટે વ્યાજ સહાય યોજના.

૨. લઘુ તેમજ મધ્યમ કક્ષાના એકમો માટે ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠળ સહાય યોજના.

૩. લઘુ અને મધ્યમ કદના એકમો માટે ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન યોજના.

૪. રીસર્ચ અને ડેવલોપમેન્ટ માટેની સહાય યોજના.

૫. ક્રિટીકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર પ્રોજેકટ યોજના.

૬. કોમન પોલ્યુશન કન્ટ્રોલ એન્ડ ડીસ્પોઝલ યોજના.

૭. ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ યોજના.
૮. ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સીલની રચના.
૯. ઔદ્યોગિક પાર્ક યોજના.
૧૦. પર્યાવરણની જાળવણી માટે યોજના.
૧૧. માંદા એકમોના પુનરુત્થાન માટે યોજના.

ધરમપુર તાલુકામાં ખૂન, લૂંટ અને આત્મહત્યાના ગુનાઓ

૮૮૪૭ **શ્રી છનાભાઇ કો.ચૌધરી** (ધરમપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ		
	ખૂન	**લૂંટ**	**આત્મહત્યા**
છેલ્લા બે વર્ષમાં તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં ધરમપુર તાલુકામાં ખૂન, લૂંટ અને આત્મહત્યાના કેટલા બનાવો પોલીસ દફતરે નોંધાયા?	૦૩	-	૧૬

અમદાવાદ શહેરમાં અનુસૂચિત જાતિના લોકો ઉપર અત્યાચારના બનાવો

૮૬૧૭ **શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઉ. વાઘેલા** (શહેર કોટડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં અમદાવાદ શહેરમાં અનુસૂચિત જાતિના લોકો પર અત્યાચારના કેટલા બનાવો બન્યા,	(૧) ૩૭.
(૨) આ અત્યાચારો અમદાવાદ શહેરના કયા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયા,	(૨)

	પોલીસ સ્ટેશનનું નામ	**સંખ્યા**
૧.	વેજલપુર	૦૫
૨.	એલીસબ્રિજ	૦૧
૩.	સેટેલાઇટ	૦૧
૪.	નવરંગપુરા	૦૩
૫.	સાબરમતી	૦૨
૬.	શાહપુર	૦૧
૭.	શહેરકોટડા	૦૧
૮.	ખાડીયા	૦૧
૯.	મેઘાણીનગર	૦૪
૧૦.	નરોડા	૦૧
૧૧.	ગોમતીપુર	૦૧
૧૨.	રખીયાલ	૦૧
૧૩.	બાપુનગર	૦૩
૧૪.	ઓઢવ	૦૪
૧૫.	વટવા	૦૩
૧૬.	મણીનગર	૦૪
૧૭.	દાણીલીમડા	૦૧
	કુલ :	**૩૭**

(૩) તેમાંથી કેટલા ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી, અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અને	(૩) ૮૮ ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી. એકપણ ઇસમની ધરપકડ બાકી નથી.
(૪) હજુ સુધી ધરપકડ નહિ કરવાના કારણો શા છે?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમીટ ૨૦૦૫માં થયેલ એમ.ઓ.યુ.

૯૩૮૨ **શ્રી કાંતિલાલ ધ.કચોરિયા** (પાલનપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમીટ ૨૦૦૫માં કેટલા એકમો માટે કેટલા રૂપિયાના એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવ્યા,	(૧) કુલ રૂપિયા ૧,૦૬,૧૬૦ કરોડના મૂડી રોકાણની ૨૨૬ દરખાસ્તો મળેલ/એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવ્યા.
(૨) થયેલ એકમોના એમ.ઓ.યુ. પૈકી સૌથી વધુ કયા કયા એકમ માટે એમ.ઓ.યુ. થયા, અને	(૨) થયેલ એકમોના એમ.ઓ.યુ. પૈકી ઉર્જા ક્ષેત્રમાં વધુ રકમ માટે એમ.ઓ.યુ. થયા.
(૩) તેનાથી રાજ્ય સરકારને કેટલો ફાયદો થનાર છે?	(૩) આ મૂડી રોકાણ અસ્તિત્વમાં આવવાથી સ્થાનિક કક્ષાએ સીધી અને આડકતરી રોજગારી ઉભી થશે તેમજ ભવિષ્યમાં કરની આવકોમાં પણ વધારો થશે તેમજ આ ઉદ્યોગો આધારિત આનુષાંગિક ઉદ્યોગો પણ સ્થપાશે.

ચોમાસા દરમ્યાન નર્મદા બંધમાંથી પાણીનો ઓવરફ્લો

૮૮૭૮ **શ્રી રતિલાલ ગો.સુરેજા** (માણાવદર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગત ચોમાસા દરમ્યાન નર્મદા બંધમાંથી કેટલા સમય માટે પાણીનો ઓવરફ્લો ચાલુ રાખ્યો, અને	(૧) ગત ચોમાસા દરમ્યાન નર્મદા બંધમાંથી ઓવરફ્લો તા.૬.૮.૨૦૦૪ થી તા.૧૮.૧૦.૨૦૦૪ સુધી ચાલુ રહ્યો.
(૨) આ સમયગાળા દરમ્યાન કેટલા પ્રવાસીઓએ બંધની મુલાકાત લીધી?	(૨) આ સમયગાળા દરમ્યાન ૨,૨૪,૫૩૨ પ્રવાસીઓએ બંધની મુલાકાત લીધી.

વિરમગામ તાલુકામાં સોકલીથી જાલમપુરા નર્મદા પેટા કેનાલનું કામ

૮૨૩૨ **શ્રી વજુભાઇ પ.ડોડિયા** (વિરમગામ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વિરમગામ તાલુકામાં નર્મદાની પેટા કેનાલ સોકલીથી જાલમપુરાનું કામ કયારે શરૂ કરવામાં આવેલ છે અને કયારે પુરૂ કરવાનું આયોજન છે, અને	(૧) સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેરમાંથી નીકળતી નરસિંગપુરા પેટા શાખા નહેરનું માટીકામ પૂર્ણ થયેલ છે, જયારે નાળાં તેમજ અસ્તરકામ ઓકટોબર-૦૧ માં શરૂ કરેલ છે અને જુન-૨૦૦૫ માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

(૨) આ કેનાલ ચાલુ થતાં કેટલા વિસ્તારને સિંચાઇનો લાભ મળશે, કયારથી?

(૨) આ પેટા શાખા નહેરના કામો પૂર્ણ થયેથી ૨૦૦૫-૦૬ થી શરૂ કરી ૨૦૦૭-૦૮ સુધીમાં તબક્કાવાર ૨૯૬૬૫ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઇનો લાભ મળશે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિવિધ ગુનાઓ

૮૩૩૭ **શ્રી દોલતભાઇ પરમાર** (વડગામ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ચોરી, લૂંટ, ધાડ, ખૂન, અપહરણનાં કેટલા કેસો નોંધાયા છે,

(૧)

ચોરી	લૂંટ	ધાડ	ખૂન	અપહરણ
૬૫૯	૬૧	૧૮	૭૬	૭૪

(૨) કેટલા કેસોમાં કોર્ટમાં ચાર્જશીટ મૂકવામાં આવી છે,

(૨)

ચોરી	લૂંટ	ધાડ	ખૂન	અપહરણ
૨૨૮	૩૪	૧૧	૬૨	૫૦

(૩) કેટલા ગુનાઓમાં કેટલા ઇસમો પકડાયા છે, અને

(૩)

	ચોરી	લૂંટ	ધાડ	ખૂન	અપહરણ
કેસો	૨૨૮	૩૪	૧૨	૬૫	૫૦
તહોમત-દારો	૩૮૨	૭૪	૧૦૯	૧૭૩	૯૧

(૪) જિલ્લામાં ગુનાઓનું પ્રમાણ ઘટાડવા સરકારે શું પગલાં લીધાં છે?

(૪) શહેર તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અસરકારક પેટ્રોલીંગ રાખવામાં આવેલ છે. પોલીસ દ્વારા શકદારો, ગુનેગારોની તપાસ રાખવામાં આવે છે, કાયદાકીય જોગવાઇઓ પ્રમાણે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવેલ છે.

વાવ-થરાદ તાલુકામાં નર્મદાનું ખેતી માટે પાણી આપવાનું આયોજન

૮૯૩૩ **શ્રી હેમાજી દ. રાજપૂત** (વાવ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ, થરાદ તાલુકામાં નર્મદાનું પાણી ખેતી માટે મળશે કે કેમ, અને

(૧) હા, જી.

(૨) જો હા, તો ખેતી માટે ક્યારે પાણી આપવાનું આયોજન છે ?

(૨) તબક્કાવાર વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ થી શરૂ કરી વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ સુધીમાં.

નર્મદા યોજનાના ભાગીદાર રાજ્યો પાસેથી લેણી રકમ

૮૯૦૦ **શ્રી ધીરૂભાઇ હ.ગજેરા** (સુરત શહેર ઉત્તર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) સરદાર સરોવર યોજનાના ભાગીદાર રાજ્યો પાસેથી ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ ના અંતે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં બાકી રહેલ રકમ પૈકી કેટલી કેટલી રકમ ક્યારે ક્યારે ગુજરાતને મળી,

જવાબ

(૧) સરદાર સરોવર નર્મદા યોજના હેઠળ ભાગીદાર રાજ્યો પાસે તા.૩૧.૧૨.૦૪ના અંતે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં બાકી રહેલ રકમ પૈકી કેટલી રકમ મળી તેની વિગત નીચે મુજબ છે.

(રૂા. કરોડમાં)

ક્રમ	ભાગીદાર રાજ્યનું નામ	છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં મળેલ રકમ
૧	મધ્યપ્રદેશ	૮૪૭.૪૭
૨	મહારાષ્ટ્ર	૧૦૪.૯૫
૩	રાજસ્થાન	૩૪૨.૦૬
	કુલ :	**૧૨૯૪.૪૮**

(૨) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ અંતીત કેટલી રકમ લેવાની બાકી છે, અને

(૨) સહભાગી રાજ્યો પાસેથી તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ નીચેની વિગતે રકમ મેળવવાની બાકી છે.

(રૂા. કરોડમાં)

ક્રમ	રાજ્યનું નામ	બાકી રકમ	વિવાદીત રકમ	બિન વિવાદીત રકમ
૧	મધ્યપ્રદેશ	૧૧૮૭.૦૭	૧૦૯૫.૩૪	૯૧.૭૩
૨	મહારાષ્ટ્ર	૭૧૭.૪૦	૫૧૮.૮૫	૧૯૮.૫૫
૩	રાજસ્થાન	૨૨૬.૩૩	૧૮૫.૬૦	૪૦.૭૩
	કુલ :	**૨૧૩૦.૮૦**	**૧૭૯૯.૭૯**	**૩૩૧.૦૧**

(૩) આ રકમ મેળવવા શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી?

(૩) નિગમ તરફથી નિયમીત પત્રો દરેક રાજ્યને બાકી ફાળો જમા કરાવવા માટે લખવામાં આવે છે. તદ્ઉપરાંત માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી કક્ષાએથી ભાગીદાર રાજ્યોના મુખ્ય મંત્રીશ્રીઓને બાકી શેરફાળાના ચુકવણા માટે સમયાંતરે પત્રો લખવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત કેબીનેટ સેક્રેટરીશ્રી દ્વારા રાજ્યના મુખ્ય સચિવશ્રીની-૨ (બે) મીટીંગમાં તેમજ નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીની મીટીંગમાં તેમજ સરદાર સરોવર કન્સ્ટ્રકશન એડવાઇઝરી કમીટીની મીટીંગમાં બાકી શેરફાળાના ચુકવાણા માટે રજુઆત થયેલ છે. તેમજ નિગમના ડાયરેકટર/મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરશ્રીઓ રાજ્યોની મુલાકાત લઇ આ રકમ સમયસર મળે તે અંગે પ્રયત્નો કરે છે.

સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં સાથી રાજ્યોને થનાર લાભ

૮૮૬૭ **શ્રી સી. ડી. પટેલ** (પેટલાદ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી વધવાથી મધ્યપ્રદેશ,

જવાબ

(૧) સરદાર સરોવર ડેમની મુખ્ય છલતીની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં વાર્ષિક આશરે ૧૫૦

મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનને શું લાભ મળશે,	કરોડ યુનિટ વિદ્યુત ઉત્પાદન કરવાનું આયોજન છે. આ વિદ્યુતના ૫૭ ટકા મધ્યપ્રદેશ રાજ્યને અને ૨૭ ટકા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યને ભાગે મળશે. રાજસ્થાનને મુખ્ય નહેર પૂર્ણ થતાં ૦.૫૦ મીલીયન એકરફીટ પાણી મળશે.
(૨) ૧૨૧.૯૨ મીટર ઊંચાઇ વધવાથી કેટલું વીજ ઉત્પાદન થશે, અને	(૨) વાર્ષિક આશરે ૧૫૦ કરોડ યુનિટ.
(૩) બંધની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી થતાં રાજ્યના કેટલા વિસ્તારને સિંચાઇ માટે પાણી આપી શકાશે?	(૩) બંધની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી થતાં રાજ્યમાં સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬ માં ૩ (ત્રણ) લાખ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઇ માટે પાણી આપવાનું આયોજન છે.

સુરત શહેરમાં ખૂન, બળાત્કાર, અને આત્મહત્યાના બનાવો

૯૧૮૫ **શ્રી મનીષ ન. ગીલીટવાલા** (સુરત શહેર પૂર્વ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સુરત શહેરમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા ખૂન, બળાત્કાર અને આત્મહત્યાના બનાવો પોલીસ દફતરે નોંધાયા, અને	(૧) **ખૂન** ૭૪, **બળાત્કાર** ૩૦, **આત્મહત્યા** ૩૫૩
(૨) તે અન્વયે બચી ગયેલા કેટલા ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી?	(૨) આત્મહત્યાની કોશિષના બનાવોમાં બચી ગયેલ (જીવીત રહેલ) ૨-આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે.

રાજ્યમાં વીજ માંગ અને વીજ ઉત્પાદન

૮૨૮૬ **શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્યમાં વીજ માંગ કેટલી હતી,	(૧) અનિયંત્રિત ૯૯૯૫ મે.વો. વીજમાંગ
(૨) આની સામે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વીજ ઉત્પાદન કેટલું કરાયું અને વીજ ખરીદી કેટલી કરાઇ, અને	(૨) ૨૬૦૨૪ મી.યુ. વીજ ઉત્પાદન ૨૬૪૬૩ મી.યુ. વીજ ખરીદી.
(૩) રાજ્યના વીજ ઉત્પાદનનો પ્રતિ યુનિટ ખર્ચ કેટલો હતો અને વીજ ખરીદી પ્રતિ યુનિટ ખર્ચ કેટલો હતો?	(૩) રૂા.૧.૮૮ પ્રતિ યુનીટ વીજ ઉત્પાદન ખર્ચ. રૂા.૨.૦૭ પ્રતિ યુનીટ વીજ ખરીદી ખર્ચ.

"સ્વાગત કાર્યક્રમ" માં મળેલ પ્રશ્નો અને નિકાલ

૮૭૮૨ **શ્રી મુળુભાઇ હ.બેરા** (ભાણવડ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી દ્વારા સામાન્ય અરજદારોના પ્રશ્નોના નિકાલ માટે "સ્વાગત કાર્યક્રમ" હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા તો તે કાર્યક્રમ હેઠળ કુલ કેટલા પ્રશ્નો જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ની સ્થિતિએ મળ્યા અને તે પૈકી કેટલા પ્રશ્નોનો નિકાલ થયો,	(૨) જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ની સ્થિતિએ મળેલ પ્રશ્નો તથા નિકાલ થયેલ પ્રશ્નો.

	મળેલ પ્રશ્નો	નિકાલ થયેલ પ્રશ્નો
રાજ્યકક્ષાએ	૬૧૮	૬૧૦
જિલ્લા કક્ષાએ	૧૭૮૨૬	૧૫૭૨૯

પ્રશ્ન	જવાબ
(૩) આ પ્રકારની વ્યવસ્થા ભારતના અન્ય કોઇ રાજ્યમાં છે કે કેમ, અને	(૩) આજ પ્રકારની વ્યવસ્થા અન્ય કોઇ રાજ્યમાં પ્રસ્થાપિત થયેલ હોવાનું જાણમાં નથી.
(૪) આ વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ અન્ય કોઇ આંતરરાષ્ટ્રીય/રાષ્ટ્રીટ સંસ્થાઓએ કરેલ છે કે કેમ?	(૪) હા જી, યુ.કે. સ્થિત કોમનવેલ્થની ઇ-ગવ.ફોર ડેવલપમેન્ટ શાખાએ કરેલ છે. અભ્યાસના અંતે સ્વાગત કાર્યક્રમને પ્રશ્નોના નિકાલ માટેની સૌથી વધુ પારદર્શક પધ્ધતિ તરીકે દર્શાવવામાં આવેલ છે.

નવરાત્રી અને પતંગ મહોત્સવ દરમ્યાન એમ.ઓ.યુ. થયેલા ઉધોગોના કામ

૮૮૫૮ **શ્રી કુંવરજીભાઇ મો. બાવળીયા** (જસદણ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉધોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સને ૨૦૦૩-૦૪ના વર્ષ દરમ્યાન યોજાયેલા નવરાત્રી મહોત્સવ અને પતંગ મહોત્સવના થયેલા એમ.ઓ.યુ. અંગે રાજ્યમાં કયા કયા ઉધોગોએ ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ કામ શરુ કર્યા, અને	(૧) રાજ્યમાં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ કુલ રૂા.૬૬૦૬૮.૫૦ કરોડના મૂડી રોકાણ સાથેના ૭૬ એમ.ઓ.યુ.ની દરખાસ્તો પૈકી ૧૦ પ્રોજેકટો રૂપિયા ૬૪૭૦/- કરોડના મૂડી રોકાણ સાથે ઉત્પાદનમાં ગયેલ છે. અને ૪૬ પ્રોજેકટો રૂપિયા ૪૮૦૬૪ કરોડના મૂડી રોકાણ સાથે અમલીકરણના તબક્કામાં છે.
(૨) તે પૈકી રાજકોટ જિલ્લામાં કેટલા ઉધોગો શરુ થયા?	(૨) આ એમ.ઓ.યુ. પૈકી રાજકોટ જિલ્લામાંથી કોઇ દરખાસ્ત મળેલ ન હતી.

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫ અન્વયે થયેલા એમ.ઓ.યુ.

૮૦૩૨ **શ્રી શિવજીભાઇ ક. આહીર** (ભૂજ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉધોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫ અન્વયે કુલ કેટલી રકમના એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવ્યા,	(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૦૫ અન્વયે રૂા.૧,૦૬,૧૬૦ કરોડના રોકાણની ૨૨૬ દરખાસ્તો મળેલ છે.
(૨) તે પૈકી કચ્છ જિલ્લા માટે કેટલી રકમના એમ.ઓ.યુ. થયા	(૨) કચ્છ જિલ્લા માટે રૂા.૩૨૩૬૧ કરોડના એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવ્યા

રકમના એમ.ઓ.યુ. થયા,	એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવ્યા.
(૩) કયા કયા ઉધોગો માટે એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવ્યા, અને	(૩) કૃષિ આધારિત ઉધોગો, વીજળી, એન્જીનીયરીંગ, ઓટોમોબાઇલ્સ, રસાયણક્ષેત્ર, બંદરક્ષેત્ર, પ્રવાસન અને ઓઇલગેસ ક્ષેત્રે એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવ્યા.
(૪) થયેલા એમ.ઓ.યુ. અન્વયે વાસ્તવિક કામગીરી કયારે શરુ થનાર છે?	(૪) શક્ય તેટલી વહેલી તકે શરુ થઇ જશે.

રાજ્યમાં જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ ગામો

૮૦૧૭ **શ્રી ધનસુખભાઇ ના. પટેલ** (ઓલપાડ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૧.૧.૨૦૦૩ થી તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ સુધીમાં રાજ્યના કુલ કેટલા ગામોને જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે,	(૧) ૫૬૫૭
(૨) આ યોજના હેઠળ તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા ગામોનો સમાવેશ કરવાનો બાકી છે, અને	(૨) ૧૨૪૦૮
(૩) આ યોજના નીચે કેટલા સમયમાં બધા ગામોને આવરી લેવાનું આયોજન છે?	(૩) શક્ય તેટલા વહેલાં.

વી-ગવર્નન્સ તાલીમના પરિણામો

૮૮૮૬ **શ્રીમતી રમીલાબેન બે. બારા**(ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા વી-ગવર્નન્સ તાલીમ કે જેને કર્મયોગી તાલીમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે તાલીમ દ્વારા ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલા સરકારી અધિકારી/કર્મચારીઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે,	(૧) ૯૯,૯૦૮
(૨) આ તાલીમના શા પરિણામો સામાન્ય રીતે જોવા મળેલ છે અને આ તાલીમના નિષ્પક્ષ મુલ્યાંકન માટેની કોઇ જોગવાઇ કરવામાં આવી છે કે કેમ, અને	(૨) તાલીમ લીધા બાદ કર્મચારીઓમાં વિધેયાત્મક, કાર્યક્ષમ અને પરિણામ લક્ષી કામગીરી તરફ દ્રષ્ટિકોણ કેળવાયેલ જણાય છે અને હા જી.
(૩) જો હા, તો તેની વિગતો શું છે?	(૩) આઇ.સી.ઇ.સી.ડી. (ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર ઇન્ટરપ્રિન્યોરશીપ એન્ડ કેરિયર ડેવલપમેન્ટ) નામની સંસ્થાને આ તાલીમના નિષ્પક્ષ મુલ્યાંકનની કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

રાજકોટ જિલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર બાજપાઇ સ્વરોજગાર યોજના અન્વયે મળેલ અરજીઓ

૮૦૯૩ **શ્રી મોહનભાઇ ક.કુંડારીયા** (ટંકારા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રમાં બાજપાઇ સ્વરોજગાર યોજના અન્વયે છેલ્લા બે વર્ષમાં તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી અરજીઓ આવી,	(૧) ૫૪૪૦
(૨) રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી-ટંકારા અને મોરબી તાલુકાના આવા કેટલા શિક્ષિત બેરોજગારોને લોન આપવામાં આવી,	(૨) **તાલુકો** — **લાભાર્થી** પડધરી — ૨૮ ટંકારા — ૬૬ મોરબી — ૧૩૯ **કુલ : ૨૩૩**
(૩) બાકી રહેતાં અરજદારોને કેટલા સમયમાં લોન આપવામાં આવશે, અને	(૩) બેંકમાં ભલામણ કરેલ અરજીઓ બેંક દ્વારા ચકાસણી કરી સામાન્ય રીતે ૩૦ દિવસમાં નિકાલ કરવામાં આવે છે.
(૪) મંજૂર કરવામાં આવેલ લોન પૈકી કેટલી સબસીડી ચૂકવવામાં આવી?	(૪) રૂા.૧૪.૨૯ લાખ.

વલસાડ જિલ્લામાં બંધ પડેલા ઉધોગો

૮૯૧૪ **શ્રી જીતુભાઇ હ. ચૌધરી** (મોટા પોંઢા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉધોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લામાં કેટલા નાના અને મોટા ઉધોગો કેટલા સમયથી બંધ પડેલા છે, અને	(૧) રાજ્ય સરકારે વર્ષ ૨૦૦૦માં કરેલ સર્વે મુજબ વલસાડ જિલ્લામાં ૪૪ મધ્યમ અને મોટા એકમો અને ૨૧૯૭ લઘુ ઉધોગો બંધ જોવા મળેલ છે.
(૨) આ બંધ પડેલા ઉધોગોને પુનઃ ચાલુ કરવા સરકારે શું આયોજન કરેલ છે?	(૨) નવી ઔધોગિક નીતિ હેઠળ રાજ્ય સરકારે બીઆઇએફઆર અને જીબીઆઇએફઆરમાં નોંધાયેલા એકમો માટે રાહતો જાહેર કરેલી છે. આ યોજના હેઠળ એકમો રાજ્ય સરકારના લેણી રકમનો વનટાઇમ સેટલમેન્ટ કરી શકે છે.

"બાયસેગ" પ્રવૃત્તિઓ અને વિકાસનું આયોજન

૯૩૨૭ **શ્રી પ્રાગજીભાઇ ના.પટેલ** (માંડલ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બાયસેગની પ્રવૃત્તિઓ શી છે, અને	(૧) ૧. રાજ્યના વિકાસ અને આયોજનલક્ષી યોજનાઓમાં રિમોટ સેન્સીંગનાં ઉપયોગથી રાજ્યની કુદરતી અને માનવસર્જીત સંપદાઓની માહિતી નકશા સ્વરૂપે પુરી પાડવી. ૨. ગુજરાત સેટકોમ નેટવર્ક (ગુજસેટ) દ્વારા દૂરવર્તી તાલીમ, શિક્ષણ અને વિચારણા અંગે.

	૩. સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ, શિક્ષણ સંશોધન અને તાલીમની પ્રવૃત્તિઓ.
	૪. રિમોટ સેન્સીંગ તથા જી.આઇ.એસ.ની ઉપયોગ અંગેના કાર્યશિબિર તથા તાલીમ વર્ગોનું આયોજન અને
	૫. જીઓગ્રાફીક ઇન્ફોર્મેશન સીસ્ટમ (જીઆઇએસ) નાં ઉપયોગથી જુદા જુદા વિભાગો માટે મલ્ટી-પરપઝ, ડીઝીટલ ડેટાબેઝ અને નકશા તૈયાર કરવા અંગેની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે.
(૨) ભવિષ્યમાં તેનાં વિકાસ માટે શું આયોજન કરેલ છે?	(૨) બાયસેગનાં ભવિષ્યના વિકાસ માટે કેડેસ્ટ્રલ ડીઝીટલ ડેટાબેંક તૈયાર કરવા, ઇ-ગવર્નન્સ માટે નિર્ણય-સહાયક પ્રણાલી તૈયાર કરવા અને સમગ્ર રાજ્યને આવરી લેતો કુદરતી સંપદા જાળવણી અંગેનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવાનું આયોજન છે. તેમજ એકેડેમી ઓફ જીઓ-ઇન્ફોર્મેટીકસ ક્ષેત્રે ટૂંકા સમયનો સર્ટીફીકેટ કોર્ષ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડીપ્લોમાના કોર્ષ શરુ કરવાનું આયોજન છે.

ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમીત, ૨૦૦૫નો ખર્ચ

૮૩૧૬ **શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ** (વાગરા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમીત, ૨૦૦૫માં રાજ્ય સરકારે કુલ કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો?	થયેલ ખર્ચના આખરીકરણની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં રૂા.૪૯૩.૨૪ લાખનું ખર્ચ થયેલ છે.

પ્રજા અને પોલીસ વચ્ચે સહકાર અને માહિતીના આદાન પ્રદાન માટે લોક દરબાર

૯૩૫૪ **શ્રી નરેશકુમાર મી. કનોડિયા** (કરજણ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પ્રજા અને પોલીસ વચ્ચે સહકાર અને માહિતીના આદાન પ્રદાન વધે તે માટે તમામ જિલ્લાઓમાં લોક દરબાર યોજવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ એક વર્ષમાં પોલીસ કમિશ્નરે વડોદરા શહેરમાં કેટલા લોક દરબાર યોજેલ છે?	(૨) ૮૪.

જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી મનોરંજન કરની વસૂલાત

૮૨૪૭ **શ્રી પુંજાભાઇ ભી. વંશ** (ઉના) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (માહિતી) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના બજેટ વર્ષમાં ડિસેમ્બર-૦૪ સુધીમાં મનોરંજન કર પેટે જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી કેટલી રકમ વસૂલ કરવામાં આવી, અને

(૧) ૨૦૦૩-૦૪ - રૂા.૧,૦૫,૨૪,૧૦૭/-
૨૦૦૪-૦૫ - રૂા. ૭૨,૭૩,૨૦૫/-.

(૨) કેટલી રકમ હજુ વસૂલ કરવાની બાકી છે?

(૨) રૂા.૧,૬૯,૩૩૧/-.

જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ ભાવનગર જિલ્લાના ગામોનો સમાવેશ

૮૩૮૨ **શ્રી પરસોત્તમભાઇ ઓ.સોલંકી** (ઘોઘા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ ૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, અને

(૨) કેટલા ગામોમાં કામ પૂર્ણ થયેલ છે?

જવાબ

(૧) અને (૨) : જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ ૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લાની તાલુકાવાર વિગતો નીચે મુજબની છે.

તાલુકાનું નામ	સમાવેશ કરાયેલ ગામોની સંખ્યા	સમાવેશ કરાયેલ પૈકીના કામ પૂર્ણ થયેલ ગામોની સંખ્યા
બોટાદ	૫૨	૧૬
ગઢડા	૭૪	૪
શિહોર	૭૮	૯
ગારીયાધાર	૫૦	૩૯
પાલીતાણા	૯૨	૨૦
ઘોઘા	૪૭	૨
મહુવા	૧૩૧	૮
ભાવનગર	૫૭	૨૮
વલ્લભીપુર	૫૬	૧૬
ઉમરાડા	૪૧	૪
તળાજા	૧૧૨	૦
કુલ :	**૭૯૦**	**૧૪૬**

વાહનવ્યવહારના નિયમોના અમલના અભાવે અકસ્માતો થવા અંગે

૯૩૮૦ **શ્રી જગદીશ ઠાકોર** (દહેગામ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં વાહનવ્યવહારના નિયમોનો અમલ થતો ન હોવાને કારણે ઘણા અકસ્માતો થાય છે તે હકીકત સાચી છે, અને

(૧) ના, જી.

(૨) જો હા, તો આ અકસ્માતો વધુ ન બને તે માટે સરકારે શું વ્યવસ્થા ઊભી કરેલ છે કે કરવા

જવાબ

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

તે માટે સરકારે શું વ્યવસ્થા ઉભી કરેલ છે કે કરવા માંગે છે?

સરદાર સરોવર બંધની ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઊંચાઇએ રાજયને લાભ

૮૮૭૧ **શ્રી બિમલ શાહ** (કપડવંજ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરદાર સરોવર બંધની ઉંચાઇ ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી લઇ જવાની મંજુરી કયારે મળી, અને તે ઉંચાઇ સુધી પહોંચતા કેટલો સમય થયો,	(૧) તા.૧૬.૩.૨૦૦૪ના રોજ તા.૩૦.૬.૨૦૦૪ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
(૨) સરદાર સરોવર બંધ હાલ કઇ ઉંચાઇએ છે, અને	(૨) સરદાર સરોવર બંધની મુખ્ય છલતી હાલ ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઇએ છે, જયારે નોન ઓવરફલો બ્લોકસ ૧૧૦.૬૪ મીટર કરતાં વધારે, વિવિધ ઉંચાઇએ છે.
(૩) તેનાથી રાજ્યને શો લાભ થયેલ છે?	(૩) સરદાર સરોવર બંધની ઉંચાઇ ૧૧૦.૬૪ મી. થવાથી નહેર આમુખ જળ વિદ્યુત મથક ઓગસ્ટ-૨૦૦૪ થી અને નદી તળ ભૂગર્ભ જળ વિદ્યુત મથકનું પ્રથમ એકમ જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ના અંત ભાગમાં કાર્યાન્વિત થયેલ છે. ચોમાસા દરમ્યાન ૨૧ નદીઓને સજીવન કરવામાં આવેલ છે. અને ૧,૩૩,૧૫૦ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઇનો લાભ આપવામાં આવેલ છે.

કલ્પસર યોજનાનો ખર્ચ

૮૧૪૦ **ડૉ. સી.જે.ચાવડા** (ગાંધીનગર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (કલ્પસર પ્રભાગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કલ્પસર યોજના પાછળ તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૫ સુધી કેટલું ખર્ચ કરેલ છે, અને	(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૫ સુધીનો કેટલો ખર્ચ થયેલ છે તે સવાલ આગોતરો હોઇ જવાબ આપવો શક્ય નથી. કલ્પસર યોજના પાછળ તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ સુધી રૂા.૨૩.૫૮ કરોડનો ખર્ચ કરેલ છે.
(૨) આ યોજના હાલ કયા તબક્કે છે?	(૨) આ યોજના માટે હાલ વિગતવાર યોજનાકીય અહેવાલો બનાવવાની કામગીરી ચાલે છે.

નર્મદા નહેરના પાણીનો શિસ્તપૂર્વક લઘુતમ વપરાશ કરવાનું આયોજન

૮૮૯૦ **શ્રી મોહનભાઇ ધ.ઢોડિયા** (મહુવા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા યોજનામાં ખેડુતો નહેરોને પોતીકી ગણી પાણી વિતરણ જાતે કરે તે માટે શું આયોજન છે,	(૧) નર્મદા યોજનાના આયોજન મુજબ પિયત વિસ્તારને ૨૦૦ થી ૫૦૦ હેકટરના ગ્રામ્ય સેવા વિસ્તારમાં વિભાજીત કરી તેની પિયત સહકારી મંડળી બનાવી ફકત મંડળીને જ સિંચાઇ માટે પાણી આપી તેના વિતરણનું આયોજન કરેલ છે.

(૨) આ યોજનામાં પાણીનો શિસ્તપૂર્વક લઘ ુતમ વપરાશ થાય તે માટે શું વ્યવસ્થા વિચારેલ છે, અને	(૨) પાણીનો શિસ્તપૂર્વક લઘુતમ વપરાશ થાય તે માટે દરેક ખેડૂતને તેના ક્ષેત્રફળ મુજબ પાણી વર્ષમાં ૨૧ ઇંચ જેટલા મર્યાદિત જથ્થામાં માપીને વારાબંધી પધ્ધતિથી આપવામાં આવનાર છે.
(૩) નર્મદા યોજનામાં પાણીનો વપરાશ વધે અને છેવાડાના ખેડૂતોને સમાનતાના ધોરણે પાણી મળી રહે તે માટે સરકારે શું આયોજન કરેલ છે?	(૩) ઉપર મુજબ વારાબંધી પધ્ધતિથી પિયત સહકારી મંડળી દ્વારા પાણી આપવાથી સમાનતાના ધોરણે છેવાડાના ખેડૂતને પાણી મળી રહેશે.

જીસ્વાન દ્વારા જોડાયેલી કચેરીઓ

૮૮૯૩ **શ્રી કાંતિભાઇ ભા. તડવી** (સંખેડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ના રોજની સ્થિતિએ જીસ્વાન દ્વારા રાજ્યના કેટલા તાલુકાઓની કેટલી કચેરીઓ જોડાયેલી છે, અને	(૧) રાજ્યના કુલ ૨૨૫ તાલુકાઓની કુલ : ૬૭૪ કચેરીઓ.
(૨) તેની પ્રવૃત્તિઓ શી છે?	(૨) આ કચેરીઓ દ્વારા ૭/૧૨નાં દાખલા, રેશનીંગ કાર્ડ, જન્મ-મરણ પ્રમાણપત્ર, આવકનો દાખલો, જાતિ પ્રમાણપત્ર, રહેઠાણનો દાખલો વગેરે માહિતી આપવામાં આવે છે.

અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક શાખા દ્વારા વસૂલ કરવામાં આવેલા દંડ

૮૩૬૬ **શ્રી સાબીરભાઇ અ. ખેડાવાળા** (જમાલપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યની ટ્રાફિક શાખાઓ દ્વારા ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ જે દંડ વસૂલ કરવામાં આવે છે તેની ૫૦ ટકા રકમ તે વિસ્તારના ટ્રાફિકના નિયમન કે વિકાસ માટે ખર્ચ કરવામાં આવે છે, તે હકિકત સાચી છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક શાખા દ્વારા કેટલો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો, અને	(૨) વર્ષ-૨૦૦૨ રૂા.૧,૭૪,૭૪,૧૫૮/- વર્ષ-૨૦૦૩ રૂા.૩,૦૪,૧૯,૮૨૫/- વર્ષ-૨૦૦૪ રૂા.૪,૫૯,૮૯,૪૪૨/-
(૩) તે પૈકીની કેટલી રકમ તે વિસ્તારનાં ટ્રાફિક નિયમન કે વિકાસના કાર્યમાં વાપરવામાં આવી?	(૩) શૂન્ય

અમદાવાદ શહેરમાં ક્રિકેટ અને બીજી રમતોના સટ્ટાઓ રમવા અંગે ધરપકડ કરવા બાબત

૮૫૫૮ **શ્રી મોહંમદફારુક હુ.શેખ** (કાલુપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
અમદાવાદ શહેરમાં મોટા પાયે ક્રિકેટના અને બીજી રમતોના સટ્ટાઓ રમવા અંગે છેલ્લા એક વર્ષમાં	૬૮.

રમતોના સટ્ટાઓ રમવા અંગે છેલ્લા એક વર્ષમાં તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં કુલ કેટલી વ્યિક્તઓની ધરપકડ કરવામાં આવી,

----

નર્મદા કચ્છ શાખા નહેરનું કામ

૯૨૧૧ **શ્રી ગોપાળભાઇ ગા. ધુઆ** (મુન્દ્રા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

	પ્રશ્ન		જવાબ
(૧)	નર્મદાની કચ્છ શાખા નહેરનું કામ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવશે,	(૧)	ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫.
(૨)	આ કામો ક્યારે પૂરા કરવામાં આવશે,	(૨)	માર્ચ-૨૦૦૮.
(૩)	કેટલો વિસ્તાર સિંચાઇ હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે ?	(૩)	૧,૭૫,૮૮૯ હેકટર.

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૦૫ અન્વયે રાજકોટ જિલ્લા માટે થયેલા એમ.ઓ.યુ.

૮૨૧૫ **શ્રીમતી જસુબેન સ. કોરાટ** (જેતપુર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૦૫ અન્વયે રાજકોટ જિલ્લામાં ક્યા ક્યા ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે કેટલા એમ.ઓ.યુ. કરારો થયા, અને	(૧) અને (૨) : રાજકોટ જિલ્લામાં ટેક્ષટાઇલ એન્જીનીયરીંગ ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે કુલ ૨ એમ.ઓ.યુ. કરારો થયા,
(૨) ક્યા ક્યા ઉદ્યોગો માટે થયા ?	

ફોરેન્સીક લેબોરેટરી દ્વારા ન્યાયાધીશો અને એડવોકેટો માટે તાલીમ કોર્ષ

૯૨૧૫ **ડૉ.અતુલ કે. પટેલ** (કલોલ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યની ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા ન્યાયાધીશો અને એડવોકેટો માટે કોઇ પ્રકારના તાલીમ કોર્ષ યોજવામાં આવે છે કે કેમ, અને	(૧) રાજ્યની ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા ન્યાયાધીશો માટે ગુન્હાની તપાસ માટે વપરાતી અધ્યતન વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિઓથી વાકેફ કરવા માટે નિયમીત ધોરણે તાલીમ કોર્ષનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
(૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૦૪માં કેટલા ન્યાયાધીશો અને એડવોકેટોએ આ તાલીમ કોર્ષમાં હાજરી આપેલ છે?	(૨) સને ૨૦૦૪ના વર્ષમાં કુલ-૪૧૬ ન્યાયાધીશોને ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરીની કામગીરીની જાણકારી તેમજ આ અંગેની જરૂરી તાલીમ આપેલ છે.

રાજકોટ શહેરમાં વિવિધ ગુનાઓ

૮૯૩૦ **શ્રી ટપુભાઇ લીંબાસિયા** (રાજકોટ-૧) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજકોટ શહેરમાં તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં ચોરી, ઘરફોડ ચોરી, ચીલઝડપ, વાહનચોરીના કુલ કેટ કેટલા બનાવો

જવાબ

(૧)

	હેડ	બનેલ બનાવો
૧.	ચોરી	૧૨૧૬
૨.	ઘરફોડ ચોરી	[illegible]

નોંધાયા છે,

૨.	ઘરફોડ ચોરી	૩૩૨
૩.	ચીલઝડપ	૫૬
૪.	વાહનચોરી	૬૧૩
	કુલ :	**૨૨૧૭**

(૨) તે પૈકી કેટલા ગુનાઓની તપાસ કરી ગુનેગારોની ધરપકડ કરવામાં આવી, અને

(૨) કુલ ૨૨૧૭ ગુનાઓની તપાસ કરી ૮૨૬ ગુનેગારોની ધરપકડ કરવામાં આવી.

(૩) કેટલા ગુનાઓમાં ગુનેગારો પકડવાના બાકી છે ?

(૩) ૧ (એક)

નવલખી બંદરને કુદરતી હોનારતો દરમ્યાન થયેલ નુકસાન

૮૧૮૬ **શ્રી જયંતિલાલ રા.કવાડિયા** (હળવદ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ જિલ્લાના નવલખી બંદરને તા.૧૫.૬.૯૮ના વાવાઝોડા અને તા.૨૬.૧.૦૧ના ભૂકંપ દરમ્યાન ખૂબ જ નુકસાન થયેલ છે, તે હકીકત સાચી છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તેના પુનઃવિકાસ માટે આજ દિન સુધી કોઇ પગલાં લેવાયેલ છે કે કેમ, અને	(૨) હા, જી.
(૩) જો હા, તો કેવા પ્રકારનાં પગલાં લેવામાં આવ્યા છે ?	(૩) (૧) તાકીદના કામો પુરા કરી ટ્રાફીક ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. (૨) બંદરના નવિનીકરણ માટે માસ્ટર ડેવલપમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરેલ છે. (૩) આ માસ્ટર પ્લાન હેઠળ જેટીના બાંધકામની કામગીરી પુરી કરેલ છે અને રસ્તા તેમજ સ્ટેકીંગ પ્લેટફોર્મ અને વિદ્યુતીકરણના કામો પ્રગતિમાં છે.

ભાવનગર શહેરમાં ટ્રાફીક અડચણના કેસો

૮૭૧૨ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી** (ભાવનગર શહેર ઉત્તર) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભાવનગર શહેરમાં ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા છ માસમાં આઇ.પી.સી. કલમ ૨૮૩ નીચે ટ્રાફીક અડચણ બાબતે કુલ કેટલા કેસો નોંધાયા, અને	(૧) કુલ-૨૩૦ કેસો.
(૨) કેટલા કેસોમાં આરોપીને રાત્રે લોક-અપમાં રાખી બીજા દિવસે જામીન આપવામાં આવ્યા ?	(૨) કુલ-૩૦૬ આરોપીઓને.

૧૭૧

અમરેલી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખૂન, લૂંટ, બળાત્કાર અને આત્મહત્યાના બનાવો

૮૪૮૧ **શ્રી પરેશભાઇ ધી. ધાનાણી** (અમરેલી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) તા.૧.૧.૦૪ થી તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં અમરેલી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખૂન, લૂંટ, બળાત્કાર અને આત્મહત્યાના કેટલા બનાવો પોલીસ દફતરે નોંધવામાં આવ્યા,

(૨) તે પૈકી કેટલા ગુનાઓનો ઉકેલ આવ્યો, અને

(૩) કેટલા તહોમતદારોની ધરપકડ કરવામાં આવી?

જવાબ

(૧)

	તાલુકાનું નામ	**ગુનાનો પ્રકાર અને સંખ્યા**			
		ખૂન	**લૂંટ**	**બળાત્કાર**	**આત્મહત્યા**
૧	અમરેલી	૩	૨	૨	૨૭
૨	લાઠી-દામનગર	૭	૦	૧	૧૧
૩	લીલીયા	૦	૦	૦	૧૦
૪	બાબરા	૩	૦	૦	૧૭
૫	વડીયા-કુંકાવાવ	૨	૦	૦	૩
૬	બગસરા	૦	૧	૦	૮
૭	ધારી	૭	૧	૧	૧૮
૮	સા.કુંડલા	૨	૨	૦	૨૯
૯	ખાંભા	૦	૧	૦	૩
૧૦	રાજુલા	૨	૩	૧	૯
૧૧	જાફરાબાદ	૨	૧	૧	૯
	કુલ :	**૨૮**	**૧૧**	**૬**	**૧૪૪**

(૨) **ગુનાનો પ્રકાર ઉકેલ આવેલ ગુનાની વિગત**

૧.	ખૂન	૨૬
૨.	લૂંટ	૦૯
૩.	બળાત્કાર	૦૪
૪.	આત્મહત્યા	૧૧૯

(૩) **ગુનાનો પ્રકાર ધરપકડ કરવામાં આવેલ તહોમતદારોની સંખ્યા**

૧.	ખૂન	૮૪
૨.	લૂંટ	૦૮
૩.	બળાત્કાર	૦૭
૪.	આત્મહત્યા	૦૦

ગરુડેશ્વર વિયરના બાંધકામ બાબત

૮૮૭૪ **શ્રી અંબાલાલ આ.રોહિત** (સોજીત્રા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) નર્મદા યોજના આધારીત ગરૂડેશ્વર વિયરના બાંધકામની કામગીરી ક્યારથી હાથ પર લેવામાં આવનાર છે,	(૧) નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬ માં બાંધકામની કામગીરી હાથ પર લેવાનું આયોજન છે.
(૨) આ વિયર બાંધવાથી શું લાભ મળશે, અને	(૨) નદીતળ ભૂગર્ભ વિદ્યુત મથક દ્વારા વિજળી ઉત્પન્ન થયા બાદ, નદીમાં આવતા પાણીને રોકી, આ વિયર દ્વારા રચાનાર જળાશયનું પાણી ઉદવહન કરી ફરીથી આ પાણી બંધના જળાશયમાં ઠાલવી, મહત્તમ વિદ્યુતની જરુરીયાત વાળા સમયમાં ફરીથી વિદ્યુત ઉત્પાદન કરી શકાશે, એમ કરવાથી ઓછા જરુરીયાતવાળા સમયમાં ઉપલબ્ધ ફાજલ વિજળી શક્તિના ઉપયોગથી મહત્તમ જરુરીયાતવાળા સમયમાં વિજળી ઉત્પાદન માટે જળ સંગ્રહ કરી શકાય. વિયર બાંધવાથી રચાનાર જળાશયથી આ વિસ્તારના પર્યાવરણમાં પણ સુધારો થશે.
(૩) આ વિયર બાંધવાનો કેટલો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે ?	(૩) રૂ.૪૦૬ કરોડ.

એપેરલ પાર્કનું ઉદ્દઘાટન

૮૯૧૭ **શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી** (ડીસા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્ય સરકારે એપેરલ પાર્કની દરખાસ્ત કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ ક્યારે કરી, અને	(૧) રાજ્ય સરકારે સુરત જિલ્લાના સચીન તાલુકાના ચોર્યાસી ખાતે એપેરલ પાર્ક સ્થાપવા માટેની દરખાસ્ત ભારત સરકારને તા.૧૯.૧૨.૨૦૦૧ના રોજ અને અમદાવાદ ખાતે શ્રી અંબિકા મિલની જમીન ઉપર ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ દ્વારા સ્થાપવામાં આવનાર એપેરલ પાર્ક માટે તા.૨.૧૧.૨૦૦૪ના રોજ કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ દરખાસ્ત રજુ કરેલ હતી.
(૨) આ એપેરલ પાર્કનું ઉદ્દઘાટન રાજ્ય સરકારે ક્યારે કર્યુ ?	(૨) સુરત જિલ્લાના ચોર્યાસી તાલુકાના સચીન ગામે નિકાસલક્ષી એપેરલ પાર્કની ખાત મુહુર્ત વિધિ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી અને કેન્દ્ર સરકારના કાપડ મંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં તા.૨૦.૧.૨૦૦૩ના રોજ કરવામાં આવેલ અને અમદાવાદ ખાતે આવેલ બંધ અંબિકા મિલની જમીન ઉપર નિકાસલક્ષી એપેરલ પાર્કનો ભૂમિ પૂજન સમારોહ માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રીની નિશ્રામાં તા.૩૧.૧૦.૨૦૦૪ના રોજ સંપન્ન થયેલ છે.

અમદાવાદ શહેરમાં અપમૃત્યુ, ચોરી, લૂંટ અને છેતરપીંડીના બનાવો

૮૬૨૭ **ડૉ.જીતેન્દ્રભાઇ બા.પટેલ** (સાબરમતી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં અપમૃત્યુ, ચોરી, લૂંટ અને છેતરપીંડીના કેટલા બનાવો બન્યાં, અને	(૧)

અપમૃત્યુ	ચોરી	લૂંટ	છેતરપીંડી
૯૦૦	૫૯૩૪	૨૭૧	૩૯૦

(૨) આવા બનાવો બનતા અટકાવવા માટે સરકારે શી કાર્યવાહી કરી છે ?

(૨) અપમૃત્યુના બનાવો આકસ્મિક બનતા હોય છે. ચોરી, લૂંટના બનાવો બનતા અટકાવવા અસરકારક પેટ્રોલીંગ, નાઇટ રાઉન્ડ, નાકાબંધી અને વાહન ચેકીંગ કરવામાં આવે છે.

દાહોદ જિલ્લામાં પ્રોહીબીશન એક્ટ હેઠળ થયેલા કેસો

૯૩૭૫ **શ્રી મહેશભાઇ સો.ભુરિયા** (લીમડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) ૨૦૦૪ના કેલેન્ડર વર્ષમાં દાહોદ જિલ્લામાં પ્રોહીબીશન એક્ટ હેઠળ કેટલા કેસ થયા,

(૧) ૨૫૬૦.

(૨) કેટલા કેસોમાં કેટલા તહોમતદારોની ધરપકડ કરવામાં આવી,

(૨) ૨૫૬૦ કેસોમાં ૨૬૩૪ તહોમતદારોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

(૩) કેટલો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો ?

(૩) જપ્ત કરવામાં આવેલ મુદ્દામાલની વિગત નીચે મુજબ છે.

વિગત	જથ્થો	કિંમત રૂા.
દેશી દારુ	૧૨૪૮૨.૭૫ લીટર	૧,૫૩,૪૯૫/-
વિદેશી દારુ	૬૭૮૬૦ બોટલ	૫૪,૩૦,૧૬૩/-
વોશ	૯૫૮૦ લીટર	૪૬,૫૫૦/-
તાડી	૯૪ લીટર	૧,૧૭૦/-
ગાંજાના લીલા છોડ	૯૬ કિલો	૩૮,૦૦૦/-
મહુડાના ફુલ	૯૦૦ કિલો	૧૮,૦૦૦/-
સફેદ આલ્કોહોલ	૨૦૦ લીટર	૬૦,૦૦૦/-

(૪) કેટલો દંડ કરવામાં આવ્યો,

(૪) નીલ.

(૫) કેટલા તહોમતદારો વિરુધ્ધ પાસા માટે ભલામણ કરવામાં આવી,

(૫) ૧૬ (સોળ).

(૬) વર્ષ દરમ્યાન કેટલા દરોડા પાડવામાં આવ્યા, અને

(૬) ૨૬૪૧.

(૭) પ્રોહીબીશન માટેનું આગવું વ્યવસ્થાતંત્ર હોવા છતાં જિલ્લામાં દારુનું પરિવહન વેચાણ દિન પ્રતિદિન વધી રહેલ છે તેના કારણો શું છે, અને નિયંત્રણ માટેના ઉપાયો શાં છે ?

(૭) દાહોદ જિલ્લામાં દારુનું પરિવહન વેચાણ દિન પ્રતિદિન વધી રહેલ છે તે હકીકત સાચી નથી. દાહોદ જિલ્લો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન રાજ્યની સરહદે આવેલો છે. તેમજ તે રાજ્યોમાં દારુબંધી ન હોવાથી, અસામાજિક તત્વો ચોરીછૂપીથી દાહોદ જિલ્લાની સરહદેથી રાજ્યમાં દારુ ઘુસાડવાની પ્રવૃત્તિ કરતાં હોવાથી, પોલીસ ખાતા તથા નશાબંધી ખાતા દ્વારા નાકાબંધી કરી, ખાનગી બાતમીદારોથી હકીકત મેળવી, ગુના શોધી કાઢવામાં આવે છે. વારંવાર પકડાતા ગુનેગારો વિરુધ્ધ પાસા, પ્રોહી. એક્ટની કલમ-૯૩ અને હદપારી જેવા અટકાયતી પગલાં ભરી, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ નિયંત્રણમાં લેવામાં આવી રહી છે.

સરદાર સરોવર બંધની ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઇએ રાજ્યને મળતો લાભ

૮૮૬૫ **શ્રી હરજીવન હી.પટેલ** (ધાનેરા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરદાર સરોવર બંધની ઉંચાઇ ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી લઇ જવાની મંજુરી કયારે મળી, અને તે ઉંચાઇ સુધી પહોંચતા કેટલો સમય થયો,	(૧) તા.૧૬.૩.૨૦૦૪ના રોજ. તા.૩૦.૬.૨૦૦૪ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
(૨) સરદાર સરોવર બંધ હાલ કઇ ઉંચાઇ છે, અને	(૨) સરદાર સરોવર બંધની મુખ્ય છલતી હાલ ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઇએ છે, જયારે નોન ઓવરફ્લો બ્લોકસ ૧૧૦.૬૪ મીટર કરતાં વધારે વિવિધ ઉંચાઇએ છે.
(૩) તેનાથી રાજ્યને શો લાભ થયેલ છે?	(૩) સરદાર સરોવર બંધની ઊંચાઇ ૧૧૦.૬૪ મી. થવાથી નહેર આમુખ જળ વિદ્યુત મથક ઓગસ્ટ ૨૦૦૪ થી અને નદી તળ ભૂગર્ભ જળ વિદ્યુત મથકનું પ્રથમ એકમ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫ના અંત ભાગમાં કાર્યાન્વિત થયેલ છે. ચોમાસા દરમ્યાન એકવીસ નદીઓને સજીવન કરવામાં આવેલ છે. અને ૧,૩૩,૧૫૦ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઇનો લાભ આપવામાં આવેલ છે.

ધોળકા વિસ્તારમાં રાત્રીના સમયે વાયર ચોરીના બનાવો

૯૨૦૪ **શ્રી કાંતિલાલ રા. લકુમ** (બાવળા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ધોળકા વિસ્તારમાં રાત્રીના સમયે ખેડૂતોના ટયુબવેલ પરથી વાયરો ચોરવાનું પ્રમાણ ખુબજ વધેલ છે, તે વાત સાચી છે,	(૧) ના, જી.
(૨) જો હા, તો તે સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ લેવામાં આવતી નથી, તે સરકાર જાણે છે, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) જો, ના, તો આવી ફરિયાદ દાખલ કરવા અને વાયર ચોરનારાઓને પકડવા શી કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે?	(૩) ગુનો બન્યા બાદ ગુનો રજીસ્ટર કરી અને આરોપીઓની અટક કરવા અને નાઇટ પેટ્રોલીંગનું આયોજન કરવામાં આવે છે તેમજ ખાનગી બાતમીદારો દ્વારા હકિકતો મેળવવામાં આવે છે.

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભિલોડા તાલુકામાં આદિવાસી ગામોને જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ

૯૧૮૯ **ડૉ.અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉર્જા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા આદિવાસી ગામોને જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ ૨૪ કલાક સીંગલ ફેઇઝ લાઇટ આપવામાં આવે છે, અને	(૧) થયેલ ૮ ગામો પૈકી ૬ આદિવાસી ગામોનો સમાવેશ થાય છે.
(૨) તમામ ગામોને તથા પેટાપરાઓને ૨૪ કલાક સીંગલ ફેઇઝ લાઇટ ક્યાં સુધીમાં આપવામાં આવશે?	(૨) શક્ય તેટલાં વહેલા.

સીંગલ ફેઇઝ લાઇટ કયાં સુધીમાં આપવામાં આવશે?

નર્મદા યોજના બંધની ઉંચાઇનું કામ

૮૫૪૩ **ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા.ચુડાસમા** (માંગરોળ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નર્મદા યોજના અન્વયે બંધનું ચણતર કરવા માટે રાજ્ય સરકારે જાન્યુઆરી-૦૫ ની સ્થિતિએ કેટલા મીટર સુધીની પરવાનગી મેળવી છે,	(૧) નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરીટીએ તા.૧૬.૩.૨૦૦૪ના રોજ બંધની મુખ્ય છલતીને ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી લઇ જવાની પરવાનગી આપી હતી.
(૨) આ મુજબનું કામ કાજ પુરૂ થવાની સંભાવના કયાં સુધીમાં છે, અને	(૨) આ મુજબનું કામકાજ તા.૩૦.૬.૨૦૦૪ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
(૩) કેટલો ખર્ચ થશે?	(૩) ઉપરોકત કામ પૂર્ણ કરવામાં આશરે રૂા.૧૨૦ કરોડ ખર્ચ થયેલ છે.

અમદાવાદ શહેરમાં એપરલ પાર્ક બનાવવાની યોજના

૮૬૧૮ **ડૉ. જીતેન્દ્રકુમાર ઉ. વાઘેલા** (શહેર કોટડા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ઉધોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરમાં એપરલ પાર્ક બનાવવાની કોઇ યોજના છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ એપરલ પાર્ક કયારથી અને કયા વિસ્તારમાં બનાવવામાં આવશે, અને	(૨) અમદાવાદ ખોખરા બ્રીજ પાસે આવેલ ફડચામાં ગયેલ શ્રી અંબિકામીલ્સ લી. ની જમીન ઉપર આ પાર્ક ઉભો કરવામાં આવી રહયો છે. આ પાર્કમાં પાયાની સુવિધાઓ જુન-૨૦૦૫ સુધીમાં સંપન્ન થતાં કાર્યાન્વિત થશે.
(૩) આ એપરલ પાર્કમાં અંદાજે કેટલાં લોકોને રોજગારી મળશે?	(૩) આ પાર્ક સંપૂર્ણપણે કાર્યાન્વિત થતાં તેમાં અંદાજે ૩૫૦૦૦ લોકોને રોજગારી મળવાની ધારણા છે.

રાજ્યમાં પોલીસ અનામત દળનો વધારો કરવા અંગે

૮૮૫૩ **શ્રી વજુભાઇ પ.ડોડિયા** (વિરમગામ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યની સુરક્ષા, સલામતી, કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ વગેરેને સુદ્રઢ બનાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેના અનામત દળમાં (સ્ટેટ રીઝર્વ પોલીસ) વધારો કરવા માટે કોઇ વિચારણા કરવામાં આવી છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તેની વિગતો શું છે?	(૨) (૧) સને ૨૦૦૪-૦૫ ના વર્ષ માટે

નર્મદા જિલ્લાના કેવડીયા કોલોની ખાતે નવી એસ.આર.પી. બટાલીયન ઉભી કરવામાં આવી રહી છે.

(૨) ઉપરાંત ઓ.એન.જી.સી., વડોદરા તેમજ સોરઠ ચોકી, જુનાગઢ ખાતે નવી એસ.આર.પી. બટાલીયન ઉભી કરવાની બાબત વિચારણા હેઠળ છે.

સરદાર સરોવર બંધની ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઇએ રાજ્યને મળતો લાભ

૮૮૬૮ **શ્રી સી.ડી.પટેલ** (પેટલાદ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરદાર સરોવર બંધની ઉંચાઇ ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી લઇ જવાની મંજુરી કયારે મળી, તે ઉંચાઇ સુધી પહોંચતા કેટલો સમય થયો,	(૧) તા.૧૬.૩.૨૦૦૪ના રોજ. તા.૩૦.૬.૨૦૦૪ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
(૨) સરદાર સરોવર બંધ હાલ કઇ ઉંચાઇએ છે, અને	(૨) સરદાર સરોવર બંધની મુખ્ય છલતી હાલ ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઇએ છે, જયારે નોન ઓવરફલો બ્લોકસ ૧૧૦.૬૪ મીટર કરતાં વધારે, વિવિધ ઉંચાઇએ છે.
(૩) તેનાથી રાજ્યને શો લાભ થયેલ છે?	(૩) સરદાર સરોવર બંધની ઉંચાઇ ૧૧૦.૬૪ મી. થવાથી નહેર આમુખ જળ વિદ્યુત મથક ઓગસ્ટ ૨૦૦૪ થી અને નદી તળ ભૂગર્ભ જળ વિદ્યુત મથકનું પ્રથમ એકમ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫ના અંત ભાગમાં કાર્યાન્વિત થયેલ છે. ચોમાસા દરમ્યાન એકવીસ નદીઓને સજીવન કરવામાં આવેલ છે. અને ૧,૩૩,૧૫૦ હેકટર વિસ્તારને સિંચાઇનો લાભ આપવામાં આવેલ છે.

ઓખા અને બેટ દ્વારકા વચ્ચે પુલ બાંધવા અંગે

૮૭૮૩ **શ્રી મુળુભાઇ હ.બેરા** (ભાણવડ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) યાત્રાળુઓની સુવિધા માટે ઓખા-બેટ દ્વારકા વચ્ચે બ્રીજ બનાવવા અંગે હાલમાં શું આયોજન છે, અને	(૧) સરકારશ્રીની સક્રીય વિચારણા હેઠળ છે.
(૨) આ બ્રીજ કયારે પૂરો કરવામાં આવશે ?	(૨) ખંડ-૧ ધ્યાનમાં લેતાં, હાલ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

લાંચ રૂશ્વત અંગે પોલીસ અધિકારીઓને પકડવા અંગે

૮૮૫૯ **શ્રી કુંવરજીભાઇ મો. બાવળીયા** (જસદણ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા પોલીસ અધિકારીઓને લાંચ રુશ્વત લેવા માટે પકડવામાં આવ્યા, અને	(૧) સન ૨૦૦૩-૦૪ના દરમ્યાન સાત પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને લાંચ રુશ્વત બાબતે પકડવામાં આવ્યા. - એપ્રિલ-૦૪ થી ડિસેમ્બર-૦૪ દરમ્યાન આઠ પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને લાંચ રુશ્વત બાબતે પકડવામાં આવ્યા.
(૨) તે પૈકી તેમની સામે શાં પગલાં લીધા?	(૨) -તપાસની કાર્યવાહી ચાલુ કરવામાં આવી છે. -સંબંધિતો સામે બદલી અથવા ફરજ મોકુફીના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. -પ્રોસીકયુશન માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. -ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવેલ છે.

કચ્છ જિલ્લામાં બંધ પડેલા બંદર વિકસાવવા આયોજન

૮૦૩૩ **શ્રી શીવજીભાઇ ક. આહીર** (ભૂજ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં બંધ પડેલા તથા મૃતપાય અવસ્થામાં આવેલા કયા કયા બંદરોને સને ૨૦૦૫ અને ૨૦૦૬ માં વિકસાવવાનું આયોજન છે, અને	(૧) કચ્છ જિલ્લામાં માંડવી, કોટેશ્વર, અને જુના મુન્દ્રા બંદર ખાનગી મૂડીરોકાણથી, અને ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડના પોતાના ભંડોળમાંથી બંદરીયા સુવિધાઓ વિકસાવવાનું આયોજન છે.
(૨) આ કામગીરી કોને સોંપવામાં આવનાર છે?	(૨) નીચે જણાવ્યા મુજબની ખાનગી કંપનીઓએ કચ્છ જિલ્લાના બંદરો વિકસાવવા માટે રસ દાખવેલ છે. ૧. **માંડવી :-** (૧) મે.સૌરાષ્ટ્ર ફયુઅલ લી. પોરબંદર (૨) મે.વિરાટ મરીન એન્ડ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કો.ઓ.લી. માંડવી. ૨. **મુન્દ્રા (જુનું બંદર) :** (૧) મે.સૌરાષ્ટ્ર ફયુઅલ લી., પોરબંદર (૨) મે.શુભમ શીપીંગ સર્વિસીસ પ્રા.લી., મુન્દ્રા ૩. **કોટેશ્વર :-** (૧) મે.ગુડઅર્થ મેરીટાઇમ લી., ગાંધીનગર નિયમોનુસાર ચકાસણી કરીને કામગીરી સોંપવામાં આવનાર છે.

"સ્વાગત કાર્યક્રમ" માં મળેલ પ્રશ્નો અને નિકાલ

૮૮૮૭ **શ્રીમતી રમીલાબેન બે. બારા** (ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી દ્વારા સામાન્ય અરજદારોના પ્રશ્નોના નિકાલ માટે "સ્વાગત કાર્યક્રમ" હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે વાત સાચી છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તે કાર્યક્રમ હેઠળ કુલ કેટલા પ્રશ્નો જાન્યુઆરી-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ મળ્યા અને તે પૈકી કેટલા પ્રશ્નોનો નિકાલ થયો,	(૨) જાન્યુઆરી-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ મળેલ પ્રશ્નો તથા નિકાલ થયેલ પ્રશ્નો

	મળેલ પ્રશ્નો	**નિકાલ થયેલ પ્રશ્નો**
રાજ્યકક્ષાએ	૪૯૮	૪૯૮
જિલ્લાકક્ષાએ	૯૩૪૦	૮૧૫૮

(૩) આ પ્રકારની વ્યવસ્થા અન્ય કોઇ રાજ્યમાં છે કે કેમ, અને	(૩) આજ પ્રકારની વ્યવસ્થા અન્ય કોઇ રાજ્યમાં પ્રસ્થાપિત થયેલ હોવાનું જાણમાં નથી.
(૪) આ વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ અન્ય કોઇ આંતરરાષ્ટ્રીય/રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓએ કરેલ છે કે કેમ?	(૪) હાજી, યુ.કે. સ્થિત કોમનવેલ્થની ઇ-ગવ.ફોર ડેવલપમેન્ટ શાખાએ કરેલ છે અભ્યાસના અંતે સ્વાગત કાર્યક્મને પ્રશ્નોના નિકાલ માટેની સૌથી વધુ પારદર્શક પધ્ધતિ તરીકે દર્શાવવામાં આવેલ છે.

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો

વટહુકમ તથા વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સંજોગો સમજાવતું નિવેદન

શ્રી રમણલાલ ઈ. વોરા (શ્રમ અને રોજગારમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૦૪નો વટહુકમ ક્રમાંક-૩-સન ૨૦૦૪નો મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સંજોગો સમજાવતું નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

વટહુકમ અને નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની અધિસૂચના

શ્રી અનિલભાઇ ત્રિ. પટેલ (રાજય કક્ષાના ઉદ્યોગ અને ખાણમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની સન ૨૦૦૪ના ગુજરાત ખાસ આર્થિક ઝોન અધિનિયમ અન્વયેની તારીખ ૧૫-૫-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંકઃ-જીએચયુ-૨૦૦૪(૨)/એસઈઝેડ-૨૦૦૩-૬૧૭-જી સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અધિસૂચના સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવી.

ગૃહ વિભાગની અધિસૂચનાઓ

શ્રીઅમિત અ. શાહ (રાજય કક્ષાના વાહન વ્યવહારમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું ગૃહ વિભાગની-
(ક) સન ૧૯૫૮ના મુંબઈ મોટર વાહન વેરા અધિનિયમ અન્વયેની તા.૪-૮-૨૦૦૪ની અધિસૂચના ક્રમાંક: જીએચજી/૨૦૦૪/૭૮/એમટીએ/૧૭૦૩/૪૩૨૪/ખ ,
(ખ) સન ૧૯૭૨ના ગુજરાત આવશ્યક સેવા જાળવણી અધિનિયમ અન્વયેની તા.૧૮-૮-૨૦૦૪ની અધિસૂચના ક્રમાંક : જીએચજી/૨૦૦૪/૮૪/એમવીડી/૧૦૦૪/૨૭૯૨/ખ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અધિસૂચનાઓ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવી.

વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોના વિભાગની અધિસૂચનાઓ

શ્રીઅશોક ભટ્ટ(વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોના મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોના વિભાગની-
(ક) સન ૧૯૬૦ના ગુજરાત વિધાનસભા (અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ) પગાર તથા ભથ્થા અધિનિયમ અન્વયે ગુજરાત વિધાનસભા (અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ) ને (હવાઈ મુસાફરીનો ખર્ચ) ભરપાઈ કરવા બાબતના નિયમો ઘડતી તા.૧૮-૫-૨૦૦૪ની અધિસૂચના ક્રમાંક: -જીએચ/એલએન્ડપીએ /૧૨૯/૨૦૦૪/૧૫૧/એ,
(ખ) સન ૧૯૭૯ના ગુજરાત વિધાનસભા (વિરોધપક્ષના નેતા) પગાર તથા ભથ્થા અધિનિયમ અન્વયે ગુજરાત વિધાનસભા (વિરોધપક્ષના નેતા) ને (હવાઈ મુસાફરીનો ખર્ચ) ભરપાઈ કરવા બાબતના નિયમો
ઘડતી તા.૧૮-૫-૨૦૦૪ની અધિસૂચના ક્રમાંક:-જીએચ/એલએન્ડપીએ /૧૩૦/૨૦૦૪/૧૫૨/એ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અધિસૂચનાઓ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવી.

ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગની અધિસૂચના

શ્રીસૌરભ પટેલ(રાજય કક્ષાના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૧૯૭૨ના ગુજરાત આવશ્યક સેવા જાળવવા બાબતના અધિનિયમ હેઠળ વીજળી ઉત્પાદન, પ્રવહન અને વીજ પુરવઠાની વહેંચણી કરતા અથવા વહેંચતા હોય તેવા ઉદ્યોગોમાંના તમામ રોજગારને આવશ્યક સેવા તરીકે જાહેર કરતી ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગની તા.૨-૯-૨૦૦૪ની અધિસૂચના ક્રમાંક: જીએચયુ-૨૦૦૪(૫૪)-જીઈબી-૧૦-૦૩-૭-૧.ક સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અધિસૂચના સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવી.

ગુજરાત રાજય બાંહેધરી અધિનિયમ અન્વયે બાંહેધરીની વિગત દર્શાવતું પત્રક

શ્રીવજુભાઈ વાળા(નાણામંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૧૯૬૩ના ગુજરાત રાજ્ય બાંહેધરી અધિનિયમ અન્વયે-
(ક) રાજય સરકારે સન ૨૦૦૩-૨૦૦૪ દરમિયાન આપેલ બાંહેધરીની વિગત દર્શાવતું પત્રક,
(ખ) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાંહેધરી આપવાના કારણે સન ૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષ દરમિયાન રાજ્યના એકત્રિત ભંડોળમાંથી ચૂકવાયેલ રકમોની વિગત દર્શાવતું પત્રક,
(ગ) બાંહેધરી આપનારની રૂએ સરકારે ચૂકવેલ રકમ પૈકી સન ૨૦૦૩-૨૦૦૪ દરમિયાન જે તે સંસ્થાઓ/વ્યક્તિઓએ ભરપાઈ કરેલ રકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

બાંહેધરીની વિગત દર્શાવતાં પત્રક સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

અનુમતિ મળેલાં વિધેયકો

સચિવશ્રી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું અગિયારમી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રમાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલું અને જેને રાષ્ટ્રપતિશ્રીની અનુમતિ મળી છે તેવું સન ૨૦૦૩નું વિધેયક ક્રમાંક: ૩૧ અને પાંચમા

સત્રમાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલા અને જેને રાજયપાલશ્રીની અનુમતિ મળી છે તેવાં સન ૨૦૦૪ના વિધેયક ક્રમાંક: ૨૧, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૩૦, ૩૧, ૩૨ અને ૩૩ ને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અનુમતિ મળેલાં વિધેયક સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

ખર્ચના પૂરક પત્રકની રજૂઆત

શ્રી વજુભાઈ વાળા(નાણામંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના વર્ષ માટેના ખર્ચનું પૂરક પત્રક રજૂ કરવાની રજા લઉં છું.

ખર્ચનું પૂરક પત્રક રજૂ કરવામાં આવ્યું.

અંદાજપત્રની રજૂઆત

શ્રી વજુભાઈ વાળા(નાણામંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૦૫-૨૦૦૬ના નાણાકીય વર્ષ માટેનું અંદાજપત્ર રજૂ કરવા ઉભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી,
મારા માટે આનંદ અને ગૈારવની બાબત છે કે, આ સન્માનનીય સભાગૃહ સમક્ષ અગિયારમી વખત બજેટ અંગેનું પ્રવચન રજૂ કરવા ઉપસ્થિત થાઉં છું. મને મળેલી આ અનેરી તક માટે આ સન્માનનીય સભાગૃહ મારફત ગરવી ગુજરાતના પ્રજાજનો પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યકત કરું છું.

સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદના પ્રેરણામૂર્તિ સ્વામી વિવેકાનંદનો મંત્ર હતો કે ઊઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્ત સુધી કાર્યરત રહો. આ જ મંત્ર અમારો પ્રેરણાપથ બની રહ્યો છે. જ્ઞાનશકિત, જળશકિત, ઉર્જાશકિત, જનશકિત અને રક્ષાશકિતની પંચામૃત યોજના દ્વારા રાજયના સર્વાંગી અને આધુનિક વિકાસ માટે આપણે સતત કાર્યરત છીએ. વિશ્વભરમાં પથરાયેલ ગુજરાતી સમાજ માટે જય જય ગરવી ગુજરાતની સાથે જય જય ગ્લોબલ ગુજરાત અને વાયબ્રન્ટ ગુજરાત એ ઘર ઘરમાં ગુંજતો શબ્દ થઇ ગયો છે. અમારી સરકારનું નેતૃત્વ કરતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આપણા ગુજરાતને વાયબ્રન્ટ ગુજરાત તરીકે સમગ્ર દેશમાં તેમજ વિશ્વમાં આગવી ઓળખ અપાવી છે.

ગત દસકામાં વિકાસ સાથે કોપોર્રેટ કલ્ચર જોડાયેલ છે અને હવે તમામ તંત્રોમાં નવી કાર્ય સંસ્કૃતિનો આરંભ કરવો જરૂરી છે. તે માટે સતત પ્રયત્નો કરવા પડે તે સ્વાભાવિક છે. હું એ કહેતાં આનંદ અનુભવું છું કે, ગુજરાતે કર્મચારીઓને કર્મયોગી બનાવી એવું એક નવું મોડલ વિકસાવ્યું છે કે સમગ્ર તંત્ર વિકાસલક્ષી તથા પ્રજાહિતલક્ષી કાર્ય કરે અને બધા સાથીઓ કર્મયોગીની ભાવનાથી પોતાની ફરજો બજાવે તેવી વ્યવસ્થા રાજય સરકારે ગોઠવી છે. ગુજરાત સરકારે કર્મયોગી મહાઅભિયાન અંતર્ગત કર્મચારીઓને તાલીમ અને મોટીવેશન માટે અનેકવિધ પ્રયત્નો કર્યા છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કાર્ય સંસ્કૃતિની નવી દિશા સૂચવી છે. કાર્યક્ષમતા, તાલીમ, ગુણવત્તા, આત્મીયતા, સંવેદનશીલતા, પારદર્શિતા અને ટીમવર્કની ભાવના ઉજાગર કરવા માટે વહીવટીતંત્ર ચેતનવંતુ બન્યું છે. સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬નું બજેટ રજૂ કરતાં આ સૈા કર્મયોગીઓનો આભાર માનું છું અને તેમણે અપનાવેલા અનોખા અભિગમ માટે અભિનંદન આપું છું.

કમનસીબે આપણે ત્યાં મતદાનથી શરૂ થતી લોકશાહી મતદાન સાથે પૂરી થાય છે. લોકો અને સરકાર વચ્ચે અંતર વધતું જાય છે. સામાન્ય જનજીવનમાં સરકાર એ અલગ તંત્ર છે તેવો ખ્યાલ પ્રબળ બની ગયો છે. આ સ્થિતિ લોકશાહીની દૃષ્ટિએ અત્યંત પીડાદાયક કહી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ છે. જીવંત લોકશાહીમાં ડગલેને પગલે લોકો ભાગીદાર બને તે આવશ્યક છે. આથી રાજય સરકારે લોકભાગીદારીના આ પ્રયાસને સાચા અર્થમાં વિકાસની પ્રક્રિયા સાથે સફળતાપૂર્વક જોડ્યો છે.

રાજયનો વિકાસ દર

આ સરકારનો મંત્ર રહ્યો છે કે ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ. પંચામૃત યોજના દ્વારા સુયોજિત વિકાસ પ્રક્રિયાના કારણે દેશના સરેરાશ વિકાસ દર કરતાં ગુજરાતે ખૂબ ઊંચો વિકાસદર હાંસલ કરેલ છે. વાવાઝોડાં, અછતનાં વર્ષો, ભૂકંપ જેવી અનેક આફતો વચ્ચે ગુજરાતે ૨૦૦૨-૦૩ના વર્ષમાં ૧૦.૫ ટકાના

વિકાસદરમાંથી હરણફાળ ભરી ૨૦૦૩-૦૪માં ૧૫.૪ ટકાનો વિકાસદર નોંધાવી વિક્રમસર્જક કામગીરી કરી છે. આટલો ઊંચો વિકાસદર માત્ર ભારતમાં જ નહીં પણ એશિયાના મોખરાના દેશમાં ગુજરાતને મહત્ત્વનું સ્થાન અપાવે છે.

રાજયની ૨૦૦૫-૦૬ની વાર્ષિક વિકાસ યોજના

માનનીય સભાગૃહને જાણ છે જ કે સને ૨૦૦૪-૦૫ની રાજયની વિકાસ યોજનાનું કદ રૂા.૮,૫૧૮ કરોડનું રહ્યું છે. વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪ની વાર્ષિક યોજનાના રૂા.૬,૭૪૦ કરોડના કદ સામે રૂા.૭,૫૮૪ કરોડની સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવી હતી. જે ૧૧૨ ટકા થવા જાય છે. આ વર્ષે પણ યોજનાના અમલમાં ૧૦૦ ટકા લક્ષ સિદ્ધિ હાંસલ થશે. ૨૦૦૩-૦૪ ના વર્ષમાં વિકાસ અને લોકકલ્યાણનાં કામો જે ઝડપથી થયા છે તેનાથી આ સભાગૃહના માનનીય સભ્યશ્રીઓ સારી રીતે વાકેફ છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને એ જણાવતાં આનંદ થાય છે કે રાજયની આર્થિક શિસ્ત, કરકસર તેમજ બિનજરૂરી ખર્ચ ઉપરના અંકુશને કારણે આપણા રાજયે નાણાકીય સુવ્યવસ્થા ધરાવતાં રાજયોની યાદીમાં અગ્રસ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. યોગ્ય નાણાકીય વહીવટને કારણે મહેસૂલી ખાધમાં ઉત્તરોત્તર નોંધપાત્ર ઘટાડો થઇ રહ્યો છે. આના કારણે રાજયની વિકાસલક્ષી યોજનાઓ માટે વધારે નાણાકીય સાધનો પ્રાપ્ત થઇ રહ્યાં છે. ૨૦૦૫-૦૬ ની વાર્ષિક યોજનાનું કદ નક્કી કરવા માટે આયોજન પંચની સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા-વિચારણા થતાં રૂા.૧૧,૦૦૦ કરોડની વાર્ષિક યોજના નિર્ધારિત કરી છે. વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ની સરખામણીમાં અંદાજે રૂા. ૨,૫૦૦ કરોડ એટલે કે ૨૯ ટકા જેટલો વિક્રમજનક વધારો થયો છે. રાજય સરકારની વિકાસગાથામાં આ એક સુવર્ણ પૃષ્ઠ લેખાશે.

આ સન્માનનીય સભાગૃહને જણાવતાં મને આનંદ થાય છે કે ભારતના આયોજનપંચે વાર્ષિક યોજનાની ચર્ચા દરમિયાન અનેક ક્ષેત્રોમાં ગુજરાત સરકારે કરેલી કામગીરીને બિરદાવી છે.

આયોજન પંચના અભિપ્રાય મુજબ ગુજરાતમાં ગરીબીનું પ્રમાણ ૧૪.૦૭ ટકા છે જયારે દેશમાં આ પ્રમાણ ૨૬.૧૦ ટકા છે. ૧૯૯૨-૯૩માં રાજયમાં ગરીબી રેખા હેઠળના લોકોની સંખ્યા ૬૨.૧૦ લાખ હતી જે ૧૯૯૯-૨૦૦૦ના સરવે મુજબ ૩૯.૮૦ લાખ થઇ છે. જેમાં પણ સતત ઘટાડો થઇ રહ્યો છે. ભારતના આયોજન પંચના અંદાજ મુજબ ગરીબી નિવારણનો લક્ષ્યાંક સિધ્ધ કરવામાં ગુજરાત મોખરે રહેશે.

આયોજન પંચના મતે રોજગારીના ક્ષેત્રે સમગ્ર ભારતમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૭.૧ ટકા અને શહેરી વિસ્તારમાં ૭.૭ ટકા બેરોજગારીનું પ્રમાણ છે જયારે ગુજરાતમાં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ફકત ૪.૮ ટકા અને શહેરી વિસ્તારમાં ૪.૨ ટકા છે. રોજગાર ક્ષેત્રે છેલ્લાં બે વર્ષમાં તમામ રાજયોમાં ગુજરાતની કામગીરી પ્રથમ ક્રમાંકે રહી છે.

પાણીના ક્ષેત્રે ગુજરાતના ૬૪.૮૮ લાખ હેકટરની ક્ષમતા સામે ૪૧.૪૦ લાખ હેકટરમાં સિંચાઇની સવલતની ૬૩.૮ ટકા કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.

શિક્ષણ, જયોતિગ્રામ યોજના, જળસંચય, ગરીબી નિવારણના ૨૦ મુદ્દા કાર્યક્રમ, બેરોજગારી નિવારણ, આદિજાતિ વિકાસની ગુજરાત પેટર્ન અને આર્થિક શિસ્તની બાબતમાં આ સરકારની કામગીરીને પણ આયોજન પંચે બિરદાવી છે.

રાજયનાં સરકારી અને સંયુકત ક્ષેત્રના એકમોની કામગીરીમાં નોંધપાત્ર સુધારા દ્વારા નફાનું પ્રમાણ ચાર ગણું કરવામાં આવ્યું છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬ની વાર્ષિક યોજના હેઠળ સદરવાર ફાળવણી નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	સદર	જોગવાઇ રૂા. કરોડમા
૧	કૃષિ અને સંલગન્ સેવાઓ	૫૮૯.૩૮
૨	ગ્રામીણ વિકાસ	૪૯૯.૬૪
૩	સિંચાઇ અને પૂર નિયંત્રણ	૨,૯૮૩.૭૭
૪	ઊર્જા	૮૩૯.૫૨
૫	ઉદ્યોગ અને ખનીજ	૩૯૨.૩૮
૬	વાહનવ્યવહાર	૧,૨૬૩.૨૪
૭	સંદેશાવ્યવહાર	૧૯.૫૭
૮	વિજ્ઞાન, પ્રૌદ્યોગિક અને પર્યાવરણ	૧૪૩.૧૩
૯	સામાન્ય આર્થિક સેવાઓ	૨૩૫.૮૬
૧૦	સામાજિક સેવાઓ	૪,૦૨૫.૯૮
૧૧	સામાન્ય સેવાઓ	૭.૫૩
	કુલ	૧૧,૦૦૦.૦૦

કૃષિ સંસ્કૃતિ
આપણો દેશ ઋષિ અને કૃષિ સંસ્કૃતિને વરેલો છે. ઋષિ સંસ્કૃતિ એ જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાં ચેતનાનું કેન્દ્રબિંદુ છે. કૃષિ સંસ્કૃતિ આર્થિક ચેતનાનું કેન્દ્રબિંદુ છે. કૃષિ ક્ષેત્રને ગતિશીલ બનાવવા માટે સુયોજિત વિવિધતાસભર અને એકબીજાને પૂરક એવા સમયબદ્ધ પગલાં લઇને ગુજરાતના કિસાનોની આવકમાં જંગી વધારો કરવા માટે રાજય સરકાર કૃતનિશ્ચયી છે. રાજય સરકારે કૃષિ ક્ષેત્રે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અપનાવી સોઇલ ટુ સેટેલાઇટ અને લેબ ટુ લેન્ડ જેવા પ્રોજેકટથી આધુનિક વિજ્ઞાનના ઉપયોગ દ્વારા કિસાનોની ખેતી આધુનિક બને તે માટે આયોજન કર્યું છે.

દેશમાં પ્રથમ હરિયાળી ક્રાંતિ વિપુલ પ્રમાણમાં પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હતો તેવા વિસ્તારમાં થઇ હતી. હવે બીજી હરિયાળી ક્રાંતિની વેળા આવી છે. આ તબક્કે મહત્તમ પાણીનો નહીં પરંતુ પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદન કરવાની દિશામાં ગુજરાતે કામગીરી શરૂ કરી છે. નર્મદા યોજના ગુજરાતની જીવાદોરી છે. છેલ્લાં બે વર્ષમાં પંદર મિટર જેટલી ઊંચાઇ વધારી નર્મદાનાં નીર આજે ૨૧ નદીઓમાં અને લાખો ખેતરોમાં વહી રહ્યાં છે. સુજલામ્ સુફલામ્ જેવી વિશાળ યોજના પણ ડિસેમ્બર-૨૦૦૫ સુધીમાં પૂરી કરવા માટે રાજય તરફથી ભગીરથ પુરુષાર્થ આદર્યો છે. ચેકડેમ, બોરીબંધ, ખેત તલાવડી અને વોટરશેડની કામગીરી લોક સહયોગથી અભૂતપૂર્વ રીતે થઇ છે. આના કારણે ગત વર્ષે ગુજરાતે મગફળીનો વિક્રમસર્જક પાક મેળવ્યો અને આ વર્ષે કપાસનો પણ મબલખ પાક મળ્યો છે. કિસાનોના સ્થાનિક પ્રશ્નો યોગ્ય રીતે સમજી ઉકેલવાની દિશામાં વૈજ્ઞાનિક ફાળો આપી શકે તે માટે રાજય સરકારે ચાર કૃષિ યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના કરી છે. આ કૃષિ યુનિવર્સિટીઓને ઉત્કૃષ્ટતાના કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવી, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ કિસાનોની સાથે જોડવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે. સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ યોજના હેઠળ ખેતરની જમીનનું પૃથક્કરણ કરી, જમીનની તાસીર જાણી તેમાં જરૂરી ખાતર અને પૂરક બાબતોની વ્યવસ્થા કરવાથી કિસાનોને ખર્ચ ઘટાડી આવક વધારવા માટે માર્ગદર્શન મળ્યું છે. કિસાનો સાથે કૃષિ ક્ષેત્રે પાણીની વ્યવસ્થા સાથે ધિરાણની જરૂરિયાત રહે છે. રાજયના કૃષિધિરાણ માટે સહકારી માળખું સારી રીતે કાર્યક્ષમ છે. રાષ્ટ્રીય બેંકો તરફથી પણ ધિરાણ માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ ધરાવતા દસ લાખ ખેડૂતોને રૂા. એક લાખ સુધીનું અકસ્માત વીમા રક્ષણનું કવચ પૂરું પડાયેલું છે. રાજયમાં ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓના વિકાસ માટે બજેટમાં રૂા. ૧૦.૭૬ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. રાજયમાં ૧૮ જિલ્લા સહકારી બેંકોમાંથી છ સહકારી બેંકોની કામગીરી સુધારણા માંગે છે. ભારત સરકારે નીમેલ વૈદ્યનાથન સમિતિના અહેવાલના આધારે આ બેંકોને કાર્યક્ષમ કરવા રાજય સરકાર જરૂરી પગલાં લેશે. રાજય સરકારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની બંધ પડેલી ડેરીઓને પુનઃજીવિત કરવાનું પેકેજ અમલમાં મૂકયું છે. એન.ડી.ડી.બી. સાથે સમજૂતિ કરાર હેઠળ આ ડેરીઓને આગામી નાણાકીય વર્ષમાં કાર્યાન્વિત કરવામાં આવશે. ઘાસચારાના વિકાસ માટે દરેક જિલ્લામાં એક ગામ પસંદ કરી પચીસ હેકટર જમીનમાં
ઘાસ ઉગાડવા માટેની યોજનાનો પણ બજેટમાં સમાવેશ કર્યો છે. બાગાયત, ફળાઉ, ઔષધિ અને અન્ય પાકોના વધારે વિકાસ માટે રૂા. ૫૨.૪૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. વોટરશેડ કાર્યક્રમ હેઠળ રૂા. ૮૩.૨૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. રાજયમાં ડેરી ઉદ્યોગમાં શિક્ષિત બેરોજગારોને નાબાર્ડની લોન મળી શકે તે માટે વ્યાજની રકમમાં ૫૦ ટકા સબસિડી સાથે રૂા. ૧ કરોડ જેટલી જોગવાઇ સૂચવી છે. રાજયમાં મરઘાં અને બતકાં ઉછેર માટે પણ જે યોજનાઓ છે તેમાં વધારાની ફાળવણી સૂચવાઇ છે. એકંદરે કૃષિ, સહકાર અને પશુપાલન ક્ષેત્રે વર્ષ ૨૦૦૪ -૨૦૦૫ની રૂા. ૨૮૩.૩૫ કરોડની જોગવાઇ સામે આયોજન હેઠળ રૂા. ૩૩૨.૬૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. કૃષિ અને સંલગન્ ક્ષેત્રોના વિકાસ માટે બિનઆયોજન સદરે રૂા. ૩૦૫.૫૬ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

વન

ગુજરાત રાજયમાં ફકત ૯.૭૩ ટકા જેટલો વન વિસ્તાર છે. રાજય સરકાર દ્વારા ગુજરાતનાં વિવિધ વૃક્ષોની ચોકકસ ગણતરી કરવામાં આવી છે. દરેક જિલ્લામાં સાનુબકૂળ રીતે ઊગતાં વૃક્ષોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવા માટે વન વિભાગે રોપા ઉછેરવાનું કામ દર વર્ષની જેમ નોંધપાત્રરીતે ચાલુ રાખ્યું છે. વન મહોત્સવ દરમિયાન વધારે રોપા ઉપલબ્ધ થાય અને તેમાં પણ ફળાઉ ઝાડના રોપાની સંખ્યા વધારે રહે તે માટે કાળજી લેવામાં આવી રહી છે. ચાલુ વર્ષે રૂા. ૧૪૯.૬૦ કરોડની આયોજનની જોગવાઇ ૨૦૦૫-૦૬ના વર્ષમાં વધારીને રૂા. ૧૬૦ કરોડની સૂચવી છે. આમાંથી રૂા. ૪૮ કરોડ આદિજાતિ વિસ્તાર માટે અને રૂા. ૬ કરોડ ખાસ અંગભૂત યોજના માટે રાખવામાં આવ્યા છે. વન વિભાગ દ્વારા એક કરોડ તેર લાખ જેટલી માનવદિનની રોજગારી ખાસ કરીને આદિવાસી અને પછાત વિસ્તારમાં પૂરી પાડવા માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નળસરોવર, કચ્છના રણમાં અને વેળાવદરમાં ઇકોટૂરિઝમ પ્રોજેકટ માટે રૂા. ૫૭ લાખની જોગવાઇ સૂચવી છે. સૌરાષ્ટ્રના બોડા ડુંગર અને ઉજજડ વિસ્તારમાં ટપક સિંચાઇથી વનીકરણ કરવા માટે રૂા. ૨.૩૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે પર્યાવરણની જાળવણી માટે રાજય સરકાર ચિંતા સેવે છે. શહેરી પરિવહન સી.એન.જી. દ્વારા અને ઉદ્યોગો દ્વારા પાણી, હવા અને જમીનમાં પ્રદૂષણ ન ફેલાય તે માટે તમામ સ્તરે કાળજી લેવામાં

આવી રહી છે. ગુજરાતને વધારે હરિયાળું બનાવવા માટે તેમજ પ્રદૂષણની માત્રા ઘટાડવા માટે આ સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે.

સર્વાંગી ગ્રામીણ વિકાસ

ભારત ગામડાંઓનો દેશ છે તે સુવિદિત છે. કમનસીબે શહેરો અને ગામડાંઓ વચ્ચે અનેકવિધ ક્ષેત્રોમાં તફાવત વધતો ચાલ્યો છે. આ પ્રક્રિયા વિકાસના કાયોર્માં બાધારૂપ બની છે અને અસમતુલન પેદા થયું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ગુજરાત જેવા પ્રગતિશીલ રાજયમાં ગ્રામીણ વિકાસ સુયોજિત રીતે આવશ્યક બન્યો છે. ગામડાનું જીવન માળખાકીય સુવિધા દ્વારા શહેરોની સમકક્ષ બને, ગામડાનું અર્થતંત્ર સુયોજિત બને, ગામડાનો સમાજ સમરસ બને તો જ વિકાસની નવી ક્ષિતિજોને આંબી શકાય. અમારી સરકારના એ સતત પ્રયત્નો રહ્યા છે કે ગ્રામીણ વિકાસને અગ્રતા આપવી. ગોકુળ ગ્રામ યોજના દ્વારા ટૂંકા સમયમાં રસ્તા, શાળાના ઓરડા, કોમ્યુનિટી હોલ અને પાણીની સુવિધા જેવા હજારો માળખાકીય વિકાસના કામો થયા છે. ભારત સરકાર દ્વારા ગ્રામીણ વિકાસ માટે સુવર્ણ જયંતી ગ્રામીણ સ્વરોજગાર યોજના, વોટરશેડ યોજના, સંપૂર્ણ ગ્રામ રોજગાર યોજના, ટોટલ સેનિટેશન યોજના અને રાષ્ટ્રીય સમવિકાસ યોજના અમલમાં છે. આ યોજનાઓમાં મળતા ભંડોળ સામે રાજયનો ફાળો આપવાની પૂર્ણ જોગવાઇ સૂચવી છે. આ ઉપરાંત ખેત તલાવડીના સફળ કાર્યક્રમ માટે રાજયના બજેટમાં રૂા. ૧૦ કરોડની ખાસ વધારાની જોગવાઇ સૂચવાઇ છે. ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેત્રે વિવિધ યોજનાઓ કાર્યરત છે તેના માટે પણ પૂરતી જોગવાઇ કરી આગામી વર્ષે કુલ એક લાખ જેટલા આવાસો ગરીબોને પ્રાપ્ત થાય તે માટે રાજય સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે.

ઇ-ગ્રામ-વિશ્વગ્રામ

ઇ-ગ્રામ દ્વારા અમે ગુજરાતના ગામડાને વિશ્વગ્રામ બનાવી રહ્યા છીએ. લોકસભા જેટલી જ પ્રતિષ્ઠા ગામડાની ગ્રામસભાને મળે અને લોકોના પ્રશ્નોનો સ્થાનિક કક્ષાએ નિકાલ થાય તે દિશામાં અમારા પ્રયાસો સફળ રહ્યા છે. સાથોસાથ અગિયારમા નાણાપંચે ગ્રામીણ વિકાસ માટે ફાળવેલ રકમનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવામાં રાજય સરકાર સફળ રહી છે. આગામી બજેટમાં તીર્થગ્રામ માટે રૂા. ૧૦ કરોડ અને પંચવટી યોજના માટે રૂા. ૧૦ કરોડ મળી કુલ રૂા. ૨૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયત વિભાગની જરૂરીયાત પૂરી કરવા માટે આયોજન હેઠળ રૂા.૪૨૯ કરોડ અને બિન-આયોજન સદરે રૂા. ૬૦૫ કરોડ એમ કુલ રૂા. ૧૦૩૪ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

જળ વ્યવસ્થાપન

જળ અને ઊર્જા ગુજરાત રાજયના વિકાસ રથના બે પૈડાં છે. સરદાર સરોવર યોજના, સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના, પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇન, ચેકડેમ, બોરીબંધ, વોટર શેડ અને ગામ તળાવની સુધારણા જેવા તમામ જરૂરી કાર્યક્રમો માટે પૂરતી જોગવાઇ સૂચવવામાં આવી છે. માનનીય સભ્યશ્રીઓની એવી લાગણી હતી કે લોકભાગીદારીથી થતા ચેકડેમોના નિર્માણ માટે સરકારનો ફાળો ૬૦ ટકા અને લોક ફાળો ૪૦ ટકા છે. તેમાં ફેરફાર કરી સરકારી ફાળો ૮૦ ટકા કરવો જોઇએ. જે ગામો પછાત અને ગરીબ છે અને ચેકડેમ યોજનાનો પૂરો લાભ લઇ શકયાં નથી તેમને આ લાભ પહોંચાડવાના હેતુથી અમારી સરકારે સરદાર સહભાગી સિંચાઇ યોજનામાં ફેરફાર કરી ચેકડેમ માટે ૮૦ ટકા સરકારી ફાળો આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના હેઠળ સાગરકાંઠાના સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાની જમીનોમાં ખારાશ પ્રવેશતી રોકવા માટે નિયંત્રણો મૂકવાનાં કામોને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને તે માટે જરૂરી નાણાકીય જોગવાઇ સૂચવાઇ છે. પીવાના પાણીની સમસ્યાના નિરાકરણ માટે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતનાં ૮૨૧૫ ગામો અને ૧૩૫ શહેરોને નર્મદા કેનાલ આધારિત યોજના હેઠળ આવરી લેવાની કામગીરી નિયત સમયપત્રક પ્રમાણે આગળ ધપી રહી છે. આ જ વિસ્તારના બીજાં ૪૯૦૪ ગામોની પીવાના પાણીની ગુણવત્તાની સમસ્યા હલ કરવા માટે સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના હેઠળ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આદિજાતિ વિસ્તારના ૯૨૯ ફળિયાંઓ અને નબળી ગુણવત્તાવાળા પીવાના પાણીની અસરવાળાં ૨૪૦૮ ફળિયાંઓની સમસ્યા દૂર કરવા બે વર્ષમાં યોજના પૂર્ણ કરવાનો આ સરકારે નિર્ધાર કર્યો છે. પીવાના પાણી માટેની યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજયમાં જે ઝડપી અને અસરકારક પ્રગતિ થઇ રહી છે તેનો અભ્યાસ કરવા અન્ય પ્રદેશોના લોકો અહીં આવે છે.

નર્મદા યોજના

વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ દરમિયાન સરદાર સરોવર યોજનામાં આગળનાં તમામ વર્ષોની સરખામણીએ સૌથી વધુ કામ થયું છે. બંધની ઊંચાઇ જે અગાઉના વર્ષોમાં વધુમાં વધુ એક સાથે પાંચ મિટરથી વધુ થઇ શકતી ન હતી તે ચાલુ સાલે ૧૦.૬૪ મિટર પ્રથમવાર વધી છે અને નિર્ણાયક ૧૧૦.૬૪ મિટરની ઊંચાઇ ઉપર પહોંચી છે. માત્ર ચાર માસના ટૂંકા સમયમાં ૧,૬૪,૬૯૯ ઘનમિટર ક્રોંક્રીટ કરવામાં આવ્યું તે પણ એક વિક્રમ છે. પહેલીવાર ચાલુ વર્ષમાં નર્મદાના પાવર હાઉસમાંથી વીજળી મળતી થઇ ગઇ છે અને આગામી ચોમાસા સુધીમાં બન્ને પાવર હાઉસના તમામ એકમો કાર્યરત થઇ જશે.

ચાલુ સાલે મુખ્ય નહેરની બાકીની ૧૦૧ કિ.મિ.ની લંબાઇનાં કામો શરૂ કરવામાં આવ્યાં. શાખા નહેરોના ૬૪૧ કિ.મિ.ની લંબાઇનાં નવાં કામો હાથ ધરવામાં આવ્યાં અને ૨૦૧ કિ.મિ.ની લંબાઇનાં લાઇનિંગ કામ શરૂ કરવામાં આવ્યાં. વિતરણ પદ્ધતિના ૨૫૭૬ કિ.મિ.ના લંબાઇનાં કામ પૂરાં થયાં છે. નહેરોનાં આ તમામ કામો પાછળ ડિસેમ્બર સુધીમાં રૂા. ૯૫૮ કરોડનો ખર્ચ થઇ ચૂકયો છે.
ચાલુ વર્ષે પિયત વિસ્તાર વિકાસનાં કામો હાથ ધરીને ત્રણ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં સિંચાઇની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાશે.

સિંચાઇ અને પાણી પુરવઠો

નાની, મધ્યમ અને મોટી સિંચાઇ યોજના અને પીવાના પાણી માટે વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ની રૂા.૨,૩૪૪ કરોડની જોગવાઇ સામે આગામી બજેટમાં રૂા.૨,૯૮૩ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

ઊર્જા

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય ઊર્જા નીતિની જાહેરાત થઇ છે તે હેઠળ વર્ષ-૨૦૧૨ માં માથાદીઠ વીજ વપરાશ ૧૦૦૦ યુનિટનો થાય તેવો રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. મને એ કહેતાં ગૌરવની લાગણી થાય છે કે આ લક્ષ્યાંક ગુજરાતે ગત વર્ષે જ હાંસલ કરેલ છે અને વર્ષ-૨૦૧૨ માં ગુજરાતમાં માથાદીઠ વીજ વપરાશ ૧૫૦૦ થી ૧૬૦૦ યુનિટનો થાય તેવી શકયતા છે. ઊર્જા ક્ષેત્રે રાજયમાં પ્રાપ્ત થતા ગેસ અને પેટ્રોલિયમ પેદાશોનું નિયમન રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ થાય છે. રાજયની સ્થાપિત ઊર્જા શકિત માટે કોલસો અને ગેસ એ બે મહત્ત્વનાં બળતણનાં સાધનો છે. ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ તેમજ ઉદ્યોગો આયાતી કોલસાનો પણ વિશેષ ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે.

ગુજરાત રાજય પ્રથમ એવું રાજય છે કે જયાં એલ.એન.જી.ના બે ટર્મિનલ સ્થપાયાં છે. અમારી સરકારની નેમ છે કે સૌરાષ્ટ્રના પીપાવાવ બંદરે પણ ત્રીજું એલ.એન.જી. ટર્મિનલ સ્થપાય. ગુજરાત રાજયમાં હાલ ઊર્જાની જે સ્થાપિત શકિત છે અને માંગ છે તેના વચ્ચેનો તફાવત પૂરો કરવા માટે અને ભવિષ્યની ઊર્જાની જરૂરિયાત પૂરી પાડવા માટે રાજય સરકારે વિવિધ પ્રોજેકટો ઉપર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ઊર્જા ક્ષેત્રે સુધારણા બાબતે પણ ગુજરાત અગ્રેસર રહ્યું છે. ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડનું ચાર વિતરણ કંપની, એક ઉત્પાદન કંપની, એક પરિવહન કંપની અને એક વિકાસ કંપની એમ સાત કંપનીઓમાં સફળતાપૂર્વક વિભાજન કર્યું છે. અલગ અલગ કંપનીઓ પોતાની જવાબદારીઓ વધારે સક્ષમ રીતે નિભાવે તે માટે યોગ્ય માળખું અને સાધનોની ગોઠવણ કરવામાં આવી છે. આગામી નાણાકીય વર્ષમાં કચ્છના એક્રિમોટા પ્રોજેકટ, (૨૫૦ મેગાવોટ) સરદાર સરોવર પાવર પ્રોજેકટમાંથી ૨૩૨ મેગાવોટ, ધુવારણ ગેસ આધારિત પ્રોજેકટ (૧૧૨.૫ મેગાવોટ) પૂર્ણપણે ઉત્પાદનમાં આવે તેવું આયોજન છે. આના કારણે રાજયમાં અંદાજિત ૬૦૦ મેગાવોટ વધારાની ક્ષમતા ઉપલબ્ધ થાય તેમ છે તેમજ કેન્દ્રિય ફાળા પૈકી ૨૩૯ મેગાવોટ પાવર વિંધ્યાચલ વીજ મથકમાંથી મળશે.

ગ્લોબલ ગુજરાત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમીટમાં ૨૦૦૩ અને ૨૦૦૫ માં મૂડીરોકાણકારોએ ઊર્જા ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર રસ દાખવ્યો છે. રાજય દ્વારા લિગ્નાઇટની નીતિને ઉદાર બનાવી વીજ મથક સ્થાપવા લિગ્નાઈટ ખોદકામની ખાનગી ક્ષેત્રમાં સવલત આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આગામી ત્રણ વર્ષમાં ૩૦૦૦ મેગાવોટ જેટલી લિગ્નાઈટ આધારિત વીજક્ષમતા સ્થાપવાનો રાજય સરકારનો દૃઢ નિર્ધાર છે. રાજયમાં પવનચક્કી દ્વારા ઊર્જા પ્રાપ્તમિાં ઝડપથી વધારો થઇ રહ્યો છે. આગામી ત્રણ વર્ષમાં ઊર્જા ક્ષેત્રે પવનચક્કી આધારિત ૧૫૦૦ મેગાવોટ કેપેસિટી નિર્માણ થાય તે માટે રાજય સરકાર જરૂરી કાર્યવાહી કરી રહી છે. માન. અધ્યક્ષશ્રી, મને આ સભાગૃહના માન. સભ્યશ્રીઓને એ જણાવતાં આનંદ થાય છે કે ગ્રીન સીટી ગાંધીનગરને હવે સૂર્યનગરી (સોલર સીટી)ની ઓળખ આપવાનો માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સંકલ્પ કર્યો છે. ગાંધીનગરમાં સૂર્ય ઊર્જા દ્વારા ઊર્જાની જરૂરિયાત પૂરી પાડવાનો અભિગમ ગાંધીનગરને વધારે સ્વચ્છ અને સુંદર બનાવશે અને અન્ય શહેરો માટે એક ઉદાહરણ પૂરું પાડશે.

ઊર્જા અને પાણી ક્ષેત્રે કલ્પસર યોજના ભવિષ્ય માટે આગવું મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ પ્રોજેકટ આગળ ધપાવવા માટે તમામ પ્રકારના અભ્યાસો પૂર્ણતાને આરે છે. મેં અગાઉ જણાવ્યું તેમ રાજયના વિકાસ માટે પાણી અને ઊર્જા એ બે ચાલકબળ છે. જળનો સંચય અને તેનો કરકસરભયાૅર ઉપયોગ આપણા માટે વિકાસના મહત્ત્વનાં પરિબળ બની રહે તેમ છે. ભૂતકાળમાં ડ્રીપ ઇરિગેશન ક્ષેત્રે મર્યાદિત કામગીરી થઇ હતી તેની સામે આગામી વર્ષમાં ખૂબ ઝડપથી કામગીરી થાય તે માટે રાજય સરકારે મહત્ત્વાકાંક્ષી આયોજન કર્યુ છે. ડ્રીપ ઇરિગેશન યોજનાનો અમલ જી.એસ.એફ.સી. અને જી.એન.એફ.સી. દ્વારા સ્થપાનાર ગુજરાત ગ્રીન રિવોલ્યુશન કંપની કરશે. આ કંપની દ્વારા પ્રથમ તબકકે રૂા.૧,૫૦૦ કરોડનો પ્રોજેકટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં રૂા.૩૦૦

કરોડની શેરમૂડી, રૂા.૬૦૦ કરોડની લોન અને રૂા.૬૦૦ કરોડની સબસીડીની જોગવાઇ રહેશે. આયોજન પંચના પરામર્શમાં ગુજરાતમાં બીજી હરિયાળી ક્રાંતિ કરવા માટે ડ્રીપ ઇરિગેશન યોજનાને ઝડપથી આગળ લઇ જવા વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬માં રૂા.૧૫૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. આનાથી ગુજરાતમાં ટીપે ટીપું પાણી વપરાશમાં આવશે અને કૃષિ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં અનેક ઘણો વધારો થશે. કિસાન ભાઇઓને મારૂં આહ્‌વાન છે કે,

ચાલો, બીજી હરિયાળી ક્રાંતિનું નેતૃત્વ કરીએ.
ચાલો કિસાનભાઇઓ, આધુનિક ખેતીનો રસ્તો અપનાવીએ.
ચાલો કિસાનભાઇઓ, કરકસરથી પાણીનો ઉપયોગ કરીએ.
ચાલો, વીજળી પણ બચાવીએ.

ચાલો, આપણી ખેતીની આવક વધારીએ.

જયોતિગ્રામ

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સભાગૃહને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે અગાઉ આ જ સભાગૃહમાં માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ ગુજરાતનાં તમામ ગામડાઓને ૨૪ કલાક માટે થ્રી ફેઇઝ વીજ પુરવઠો આપવાની જાહેરાત કરી હતી અને આજે આ કાર્ય સફળરીતે પૂર્ણતાને આરે છે. ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ દ્વારા ગુજરાતનાં ૧૮,૦૦૦ જેટલાં ગામડાઓમાંથી ૭,૦૦૦ ઉપરાંતનાં ગામડાંઓને જયોતિગ્રામ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યાં છે. રાજય સરકારને મળેલ સર્વેક્ષણ મુજબ ગામડાંઓનાં જીવન ધોરણમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો છે. દરેક ગામડામાં નવી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા રોજગારીમાં વધારો થયો છે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ માટે ટી.વી. તથા કોમ્પ્યુટર દ્વારા જ્ઞાન, અને પરિવારને મનોરંજન મેળવવામાં સવલત થઇ છે. ડિસેમ્બર-૨૦૦૫ સુધીમાં જયોતિગ્રામ હેઠળ ગુજરાતના દરેક ગામના દરેક ઘરમાં સતત ૨૪ કલાક થ્રી ફેઇઝ વીજ પુરવઠો મળતો થશે ત્યારે ગુજરાત સાચા અર્થમાં કવિ વીર નર્મદની એ પંક્તિ સાર્થક કરશે કે વીતી ગઇ છે રાત..... અને દીપે અરુણું પરભાત

જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ રૂા. ૩૦૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

સામાજિક સેવાઓ

આ સરકાર લોકકલ્યાણને વરેલી છે. રાજયનો માત્ર ભૌતિક વિકાસ જ નહીં પરંતુ સામાન્ય માનવીના જીવનમાં આ વિકાસનો લાભ દેખાય, જીવનધોરણ ઊંચું આવે, ગરીબમાં ગરીબ પરિવારને શિક્ષણ અને આરોગ્ય ઉપલબ્ધ થાય, મહિલા અને બાળકલ્યાણ ક્ષેત્રે ઉમદા કામગીરી થાય, ગરીબ માનવી આર્થિક રીતે પગભર થાય તે માટે શ્રમ અને રોજગાર ક્ષેત્રે પૂરતું પ્રોત્સાહન મળે, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતાનું કામ હોય કે આદિવાસી વિકાસની પેટાયોજના હોય કે ગુજરાત પેટર્ન હોય-નાણાનો ધોધ સામાન્ય માનવી સુધી પહોંચાડવામાં આ સરકારે મોટી હરણફાળ ભરી છે. રૂા.૧૧,૦૦૦ કરોડની વાર્ષિક યોજનામાંથી ૩૬.૬૦ ટકા એટલે કે ૩૭ ટકા જેટલી જંગી રકમ સામાજિક સેવાઓના ક્ષેત્રે ફાળવીને અભૂતપૂર્વ ડગ માંડ્યું છે.

શિક્ષણ

અમારી સરકાર શિક્ષણ ક્ષેત્રને ભાવિ પેઢીના ઘડતર માટે સૌથી મહત્ત્વનું પરિબળ માને છે. ગુજરાત રાજયમાં કોઇપણ વ્યકિત નિરક્ષર ન હોય તે માટે તમામ પગલાં રાજય સરકાર લઇ રહી છે. રાજયમાં શાળા પ્રવેશોત્સવ, કન્યા કેળવણી રથયાત્રા, વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ, સેનિટેશન સંકૂલો અને ૧૦૦ ટકા શિક્ષકોની ભરતી દ્વારા તમામ બાળકો શાળામાં દાખલ થાય અને ધોરણ-૭ સુધી સતત અભ્યાસ કરી શકે તે માટે રાજય સરકાર તમામ સ્તરે કાળજી અને પ્રયત્નો કરી રહી છે. સરકારનું સમગ્ર તંત્ર અને જનભાગીદારીના પ્રયાસોને કારણે પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે આજે ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઇ રહી છે.

ભારતમાં સૌ પ્રથમવાર શાળાએ જતા તમામ બાળકોનું હેલ્થ ચેકઅપ કરાવી ૯૪ લાખ બાળકોમાંથી જે જે બાળકો રોગગ્રસ્ત જણાયાં તેમને સંપૂર્ણ નિઃશૂલ્ક સારવાર આપવાની કામગીરી કરી છે. આ યોજના હેઠળ ૪૦,૦૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને મફત ચશ્મા અને ૫૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ગંભીર પ્રકારનાં ઓપરેશનો રાજય સરકારના ખર્ચે કરાવી આપ્યાં છે. આગામી વર્ષે તમામ શાળાઓમાં ફેસ્ટ એઇડ બોકસ રાખવાની તેમજ આગ પ્રતિરોધક વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે. વિદ્યાદીપ યોજના હેઠળ કે.જી. થી પી.જી. સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને વીમા સુરક્ષા કવચ પ્રાપ્ત છે. રાજય સરકારના આ ઘનિષ્ઠ પ્રયત્નોને કારણે ડ્રોપ આઉટ રેટ ૩૮ ટકામાંથી ઘટીને ૧૭.૫ ટકા થયો છે. ગત વર્ષે સાક્ષરદીપ યોજના હેઠળ તાલીમાર્થી શિક્ષકો દ્વારા ૮ લાખ કરતાં વધુ નાગરિકોને અક્ષરજ્ઞાન આપવાનો સફળ પ્રયોગ થયો છે. જે પૈકી પાંચ લાખ જેટલી મહિલાઓએ પણ અક્ષરજ્ઞાન મેળવ્યું છે જે બતાવે છે કે મોટી ઉંમરે પણ મહિલાઓમાં શિક્ષણ મેળવવાની તાલાવેલીના દર્શન થાય છે. આ પ્રયોગ શિક્ષણ પ્રક્રિયાનું કાયમી અંગ બને તે માટે આગામી બજેટમાં સાક્ષરદીપ યોજના માટે રૂા. ૫ કરોડની

ફાળવણી સૂચવવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી કન્યા કેળવણી નિધિમાં પ્રાપ્ત થતી રકમો દ્વારા કન્યા કેળવણીમાં જે અંતરાયો છે એ સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા રાજય સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે બિનઆયોજન સદરે આ બજેટમાં રૂા.૩,૮૧૦.૫૮ કરોડની અને આયોજન સદરે રૂા.૪૭૭. ૦૮ કરોડની ફાળવણી સૂચવાઇ છે.

ઔદ્યોગિક વિકાસ

ગુજરાતમાં થયેલા ઔદ્યોગિક વિકાસને કારણે ગુજરાત દેશમાં ઝડપી ઔદ્યોગિકરણ માટે પંકાયેલ છે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસને નવી દિશા અને ગતિશીલતા આપવા માટે રાજય સરકારે એક નવતર પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે. ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમીટ, ૨૦૦૩ અને ૨૦૦૫ના બે ઐતિહાસિક પ્રસંગો દ્વારા ગુજરાત આજે સમગ્ર વિશ્વમાં રોકાણ માટેનું એક આકર્ષક રાજય બન્યું છે. વર્ષ ૨૦૦૩માં રૂા. ૬૬,૦૦૦ કરોડના રોકાણવાળા ૭૬ પ્રોજેકટોમાંથી ૫૬ પ્રોજેકટોમાં રૂા.૫૪,૪૦૦ કરોડનું મૂડીરોકાણ કાર્યાન્વિત થઇ રહેલ છે. ૨૦૦૫ના ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમીટમાં ૨૨૬ સમજૂતિના કરાર સાથે રૂા.૧,૦૬,૧૬૦ કરોડના મૂડીરોકાણના પ્રોજેકટો ગુજરાતમાં સ્થાપવા માટે જાણીતા ઉદ્યોગગૃહો, વિદેશી કંપનીઓ અને નવ-સાહસિકોએ સંકલ્પ જાહેર કરેલ છે. મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે આગામી દિવસોમાં આ વિશાળ મૂડીરોકાણને કારણે ગુજરાતનો આર્થિક વિકાસદર ઊંચો રહેશે અને અનેક લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થશે. ગુજરાત રાજયના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં ટેક્ષ્ટાઇલ અને હીરા ઉદ્યોગનો સિંહફાળો રહ્યો છે. આ બંને ઉદ્યોગોને વૈશ્વકિ કક્ષાએ સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે ગુજરાત સરકાર કટિબદ્ધ છે. સૂરતમાં જેમ્સ અને જવેલરી પાર્ક, અમદાવાદમાં તથા સૂરતમાં એપેરલ પાર્કની યોજના ઝડપથી આકાર લઇ રહી છે. મુન્દ્રા અને દહેજમાં નવા સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનની મંજૂરી સાથે ગુજરાતમાં સાત સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન માટે કાર્યવાહી થઇ રહી છે. ગુજરાતનો આગામી વિકાસ તેનાં બંદરો મારફત થશે તે હકીકતનો સૌ સ્વીકાર કરે છે. રાજયમાં છેલ્લાં થોડાં વર્ષોમાં મુન્દ્રા, પીપાવાવ, દહેજ, હજીરા અને સિક્કા બંદરોના ટ્રાફિકમાં અભૂતપૂર્વ વધારો થયો છે. ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ નાનાં બંદરોના વિકાસ માટે પણ પૂરતું મૂડીરોકાણ કરી શકે તેમ છે. ચાલુ વર્ષે રાજયના બંદરો ઉપરનો ટ્રાફિક ૧૦૯ મિલિયન ટન જેટલો થતાં એક નવો વિક્રમ સ્થાપિત થશે. મત્સ્યોદ્યોગ માટે જખૌ બંદરમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને ધોલાઇ બંદરે આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજયના મત્સ્યોદ્યોગને આધુનિકરણ તરફ લઇ જવા માટે પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. માછીમારોના સામાજિક અને શૈક્ષણિક વિકાસ માટે પણ ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડનાં નાણાકીય સાધનો ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. કચ્છના અખાતમાં જહાજોની અવર-જવર સરળ બનાવવા માટે રૂા.૧૬૫ કરોડના ખચેર્ મેરીટાઇમ બોર્ડ અને કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટ અતિ આધુનિક ટ્રાફિક સિસ્ટમની સ્થાપનાની કામગીરી હાથ ધરશે.

ધરતીકંપની સૌથી વ્યાપક અસર પામેલા કચ્છ જિલ્લાના આર્થિક વાતાવરણને ચેતનવંતુ બનાવવા અને ઉદ્યોગોને આકર્ષિત કરવા કેન્દ્ર સરકારે કચ્છ જિલ્લામાં તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૦૫ સુધીમાં ઉત્પાદનમાં જનાર નવા ઔદ્યોગિક એકમોને પાંચ વર્ષ માટે આબકારી જકાતમાંથી મુકિત આપી છે. રાજય સરકારે પણ પ્રોત્સાહન યોજના જાહેર કરી તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૦૫ સુધીમાં ઉત્પાદનમાં જનાર નવા એકમોને વેચાણવેરાનો લાભ આપવાનું ઠરાવેલ છે તેમજ પાઈપલાઈન કેસોના ઔદ્યોગિક એકમો તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૦૭ સુધી ઉત્પાદનમાં જાય તો આ યોજનાનો લાભ મેળવશે.

આ યોજનાઓને પરિણામે કચ્છ જિલ્લામાં ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણને પ્રભાવશાળી પ્રતિસાદ મળેલ છે. ભૂકંપ બાદ ૩૭ પ્રોજેકટ ઉત્પાદનમાં ગયેલ છે. જેમાં કુલ રૂા. ૨,૮૯૪ કરોડનું મૂડીરોકાણ થયેલ છે. ઉપરાંત તારીખ : ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ૩૭૫ પ્રોજેકટ અમલીકરણના વિવિધ તબક્કે છે. જેમાં કુલ રૂા.૧૫,૫૦૦ કરોડનું મૂડીરોકાણ થશે જેના પરિણામે ૭૯,૦૪૦ વ્યકિતઓ માટે રોજગારીની તકો ઊભી થશે.

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમીટ-૨૦૦૫ના કાર્યક્રમમાં કચ્છ જિલ્લામાં રૂા.૨૧,૨૧૧ કરોડના મૂડીરોકાણના ૩૨ સમજૂતિ કરાર થયા છે.

કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ

ગુજરાત રાજય તેની પરંપરાગત કળા અને હુન્નર માટે વિખ્યાત છે. ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં રોજગારી પૂરી પાડવામાં કૃષિ પછી કુટીર ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર આવે છે. ગુજરાતમાં અંદાજે ૨૧ લાખ કારીગરો સ્વરોજગારી મેળવી રહ્યા છે. કુટીર ઉદ્યોગમાં કાપડ આધારિત ખાદી, હાથશાળ, ભરતકામ અને અન્ય હસ્તકળાની કામગીરીને રાજય સરકાર સતત પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. માટી આધારિત ઉદ્યોગ, લાકડાં અને વાંસ આધારિત ઉદ્યોગો તેમજ પતંગ ઉદ્યોગ, ચર્મ ઉદ્યોગના ક્ષેત્રે નવી રોજગારી પ્રાપ્ત થાય અને આવક થાય તે માટે રાજય સરકારે ચોક્કસ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે.

પ્રવાસન

પ્રવાસન ક્ષેત્રે ગુજરાતની ક્ષમતાઓનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. રાજયનાં પુરાતત્ત્વનાં સ્થળો, સમુદ્ર કિનારાના બીચ તેમજ ધાર્મિક સ્થળોનો વિકાસ કરવા માટે રાજય સરકાર મૂડીરોકાણ આકર્ષી રહી છે અને સાથેસાથે બજેટમાં પણ રૂા. ૩૫ કરોડની જોગવાઇ દ્વારા ટૂરિસ્ટ ગાઇડ, તરણેતર મેળો ઉપરાંત વ્યૂહાત્મક રીતે ઇવેન્ટ બેઇઝ ટૂરિઝમને અગ્રિમતા આપી છે જેમાં નવરાત્રિ મહોત્સવ, આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ અને કચ્છ-ઉત્સવ જેવા લોકપ્રિય પ્રસંગોનું આયોજન કરી રહી છે. મેડિકલ ટૂરિઝમ માટે પણ આરોગ્ય વિભાગ ખાસ યોજનાઓનો અમલ કરશે. ૨૦૦૪-૦૫ ના વર્ષમાં બંદરોઅને મત્સ્યોદ્યોગ વિભાગ માટે રૂા. ૫.૮૩ કરોડની ફાળવણી વધારીને રૂા.૬.૪૨ કરોડની સૂચવી છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ તરફથી બંદરો અને મત્સ્યોદ્યોગના વિકાસ માટે કુલ રૂા. ૮૦ કરોડનું મૂડીરોકાણ થાય તેવું આયોજન છે. ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ, ખાણ અને પ્રવાસન વિભાગ માટે વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ની રૂા. ૨૪૭.૨૭ કરોડની ફાળવણી સામે રૂા.૩૭૮.૧૮ કરોડની ફાળવણી સૂચવાઇ છે, આમ રાજયના ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે રાજય સરકારે પૂરતી જોગવાઇ કરેલ છે. કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ ક્ષેત્રે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિના વધારે યુવક-યુવતિઓને રોજગારી મળે તે માટે સવિશેષ ફાળવણી સૂચવાઇ છે.

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ

રાજયમાં હોસ્પિટલોના સર્વાંગી વિકાસ માટે સેવાની ગુણવત્તા અને ધોરણ સુધારવા માટે લોકભાગીદારીથી આર્થિક સ્ત્રોતો ઊભા કરી રોગી કલ્યાણ સમિતિની રચના કરવા માટે નાણાકીય જોગવાઇ કરી છે. તદ્‌ઉપરાંત ઇ-ગવર્નન્સ માટે ૨૫ જિલ્લા હોસ્પિટલો તેમજ ૬ સરકારી મેડિકલ હોસ્પિટલોમાં કોમ્પ્યુટર વગેરેની જોગવાઇ કરવા માટે રૂા.૨૧.૧૭ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. આના કારણે રાષ્ટ્રીય પ્રોજેકટનું ઓનલાઇન મોનિટરિંગ થઇ શકશે તેમજ દર્દીઓની સારવારમાં સુધારો થશે.

રાજયમાં પરિચારિકાઓની તાલીમ અને શિક્ષણ માટે બે નવી નર્સિંગ સ્કૂલો બનાવવાનું આયોજન કરેલ છે. રાજયમાં આવેલ હોસ્પિટલોમાં તબીબી ઉપકરણો મારફતે તબીબી પરીક્ષણ માટે નેટવર્ક ગોઠવેલ છે અને તેને સુદૃઢ કરવા માટે રૂા.૪.૫૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

રાજયમાં આદિજાતિ વિસ્તારમાં પ્રવર્તતા ન્યુમોનિયા રોગને નિયંત્રિત કરવા માટે ખાસ પ્રોજેકટ અમલમાં મૂકેલ છે અને આ માટે રૂા.૫ કરોડની રકમ સૂચવી છે.

રાજયમાં મ્યુનિસિપાલિટીના વિસ્તારોમાં આરોગ્યની સેવાઓ સુધારવા માટેની ખૂબ જ તાતી જરૂરિયાત છે. આ તાતી જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લઇને ખાસ શહેરી આરોગ્ય કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવાનું વિચારેલ છે જેનાથી ખાસ કરીને સ્લમ વિસ્તારમાં ૨૭ લાખની વસ્તીને સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે.

રાજયમાં બાળ-મરણ તથા માતૃ-મરણના દરને ઘટાડવા માટે ૧૦૨ જેટલા યુનિટોમાં જુદા-જુદા તજજ્ઞોની નિમણૂક કરવામાં આવશે અને તેને સુદૃઢ કરવામાં આવશે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં લેપ્ટોપાયરોસિસ રોગનું નિયંત્રણ કરવા માટે જિલ્લા હોસ્પિટલો તેમજ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો તેમજ મેડિકલ હોસ્પિટલમાં તબીબી ચકાસણી માટેની સેવાને સુદૃઢ કરવામાં આવશે.

રાજયમાં આવેલ મેડિકલ કોલેજો, હોસ્પિટલોમાં ટ્રોમા સેન્ટરો બાંધવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. અમદાવાદ, વડોદરા અને જામનગર ખાતે બંધાયેલાં ટ્રોમા સેન્ટરો માટે રૂા.૫.૨૪ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. આ ઉપરાંત વડોદરા, સૂરત અને જામનગર ખાતે એમ.આર.આઇ. સેન્ટરો શરૂ કરવા માટે રૂા.૯ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. રાજયની મેડિકલ કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓને મેરીટ આધારિત ૧૩૦ વધારાની બેઠકો ઉપલબ્ધ થાય તે માટે વ્યવસ્થા કરી છે જેના કારણે રાજય સરકાર ઉપર રૂા. ૩ કરોડનો વધારાનો બોજ આવશે.

૬ મેડિકલ કોલેજો, હોસ્પિટલોમાં ટેલિરેડિયોલોજી સાધનો વસાવવા માટે રૂા.૯ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. ગુજરાત આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટીના વિકાસ માટે સહાયક અનુદાન પેટે રૂા.૯૧ લાખની જોગવાઇ સૂચવી છે.

શહેરી વિકાસ

ઝડપી આર્થિક વિકાસ અને ઔદ્યોગિકરણને કારણે રાજયમાં શહેરીકરણની પ્રક્રિયા ઝડપી બની રહી છે. રાજયની ૪૦ ટકા જેટલી વસ્તી શહેરોમાં નિવાસ કરે છે, અનેક ગામડાના પરિવારો આજીવિકા, શિક્ષણ અને આરોગ્યની સુવિધા માટે શહેરો ઉપર આધારિત છે. ગુજરાતનાં શહેરોના જીવનધોરણમાં, સુવિધાઓમાં અને સેવાઓમાં નોંધપાત્ર સુધારો થાય તે માટે ૨૦૦૫ના વર્ષને રાજય સરકારે શહેરી વિકાસવર્ષ, ૨૦૦૫ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય કરેલ છે. ગુજરાતના શહેરીજનોને સુંદર, સ્વચ્છ, વિકાસલક્ષી અને ધબકતા શહેરોમાં રહેવાનું ગૌરવ મળે તે માટે રાજય સરકારે લોકભાગીદારી દ્વારા શહેરી વિકાસના કાર્યક્રમનો સંકલ્પ કર્યો છે. અગાઉ વાજપેયી નગરવિકાસ યોજનાના પહેલા તબક્કામાં રાજય સરકારે કુલ રૂા.૧૪૨ કરોડના ખર્ચે શહેરોની પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડી છે. શહેરી વિકાસવર્ષ, ૨૦૦૫ માટે રાજય સરકારે અમુક ચાવીરૂપ ક્ષેત્રો નકકી કર્યાં છે. જેમાં પીવાનું પાણી, ગટર-વ્યવસ્થા, સ્વચ્છતા, સોલિડ વેસ્ટના નિકાલની વ્યવસ્થા, રસ્તા, બાગ-બગીચા જેવી સવલતોનો સમાવેશ થાય છે. આ પાયાનાં કામો કરવા માટે સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓને રાજય સરકાર પૂરતો

નાણાકીય ટેકો આપવા તત્પર છે. શહેરી વિસ્તારના ભાવિ આયોજનમાં ઉપકારક થાય તેવા સુધારાઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, મ્યુનિસિપાલિટી અને ટાઉન પ્લાનિંગને લગતા કાયદામાં કરવા માટે પણ રાજય સરકાર ઉત્સુક છે. સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓનો વહિવટ વધારે કાર્યક્ષમ, પારદર્શક અને લોકાભિમુખ બને તે જરૂરી છે. આ માટે ઇ-ગવર્નન્સ, સુયોગ્ય હિસાબી વ્યવસ્થા, મિલકત વેરો અને વિવિધ સેવાઓ માટેના સુયોગ્ય ચાર્જિસની ગણતરી કરવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. રાજય સરકાર શહેરી વિકાસવર્ષ, ૨૦૦૫ની યોજનાને એક અર્બન મિશન સ્વરૂપે આગળ ધપાવવા માંગે છે. તેને પૂરતાં નાણાકીય સાધનો ઉપલબ્ધ કરવા માટે ગુજરાત શહેરી આંતરમાળખાકીય ભંડોળની પણ રચના કરવાનો રાજય સરકારે નિર્ધાર કર્યો છે. શહેરી વિસ્તારનાં વિકાસ કામોમાં જાહેર અને ખાનગીક્ષેત્ર વચ્ચે સુયોગ્ય ભાગીદારીનું નિર્માણ થાય તેવું રાજય સરકાર ઇચ્છે છે. રાજયનાં શહેરોના ઐતિહાસિક વારસાને ઉજાગર કરી, શહેર સાથે દરેક નાગરિક આત્મીયતાનો અનુભવ કરે તેવી રાજય સરકારની નેમ છે. સાગરકાંઠા વિસ્તારનાં શહેરો, સરહદ ઉપર આવેલાં શહેરો, ધાર્મિક સ્થળો અને આદિજાતિ પટ્ટીમાં આવેલાં શહેરોના વિકાસ ઉપર વધારે લક્ષ કેન્દ્રીત કરવાની જરૂરિયાત છે. રાજય સરકાર દ્વારા સ્લમ વસવાટોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે, સ્વરોજગારી માટે શહેરોમાં સુવ્યવસ્થિત તકો ઊભી કરવા તેમજ શહેરી ગરીબોને શિક્ષણ અને આરોગ્યની સુવિધા પહોંચાડવા માટે સંકલ્પબદ્ધ છે. શહેરની મિલકતોના રજિસ્ટ્રેશનનું કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન, શહેરોના ૫૦ ટકા પરિવારોને પાઇપલાઇન મારફત ગેસ પૂરો પાડવો, શહેરોના રસ્તાઓ સુંદર બનાવવા, બાગ-બગીચા દ્વારા શહેરોની સુંદરતામાં વધારો કરવાના રાજય સરકારના લક્ષ્યાંકો છે. રાજય સરકારે આ મહત્ત્વાકાંક્ષી યોજનાઓના અમલ માટે વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં રૂા.૧૨૬.૬૪ કરોડની જોગવાઇ કરી હતી તેમાં રૂા.૩૬૬ કરોડનો વધારો કરી સુધારેલ અંદાજમાં શહેરી વિકાસ માટે કુલ રૂા.૪૯૨.૬૪ કરોડ આયોજન સદરે દર્શાવેલ છે. વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬માં શહેરી વિકાસ વિભાગ માટે આયોજન સદરે રૂા.૫૯૦ કરોડ સૂચવ્યા છે જેમાં ગુજરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર દ્વારા શહેરી વિસ્તાર માટે ફાળવાયેલ રૂા.૧૯૮ કરોડનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ગૃહ વિભાગ

કોઇપણ રાજયના વિકાસમાં સલામતી, સુરક્ષા પૂર્વશરત હોય છે. રાજયમાં લોકરક્ષકની ૪,૦૦૦ જગ્યાઓ ઊભી કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પોલીસદળના આધુનિકરણની યોજના હેઠળ રૂા.૧૦૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. જેમાંથી પોલીસ આવાસોનું બાંધકામ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રૂા.૭૦.૬૯ કરોડના ખર્ચે પોલીસ સ્ટેશનો, પોલીસ ચોકીઓ, આઉટ પોસ્ટ અને કચેરીઓના મકાનોનું બાંધકામ કરવામાં આવશે. ફિંગર પ્રિન્ટ બ્યૂરો અને સિવિલ ડિફેન્સની કામગીરી માટે પણ અનુક્રમે રૂા.૪૫ લાખ અને રૂા.૪૨ લાખની જોગવાઇ સૂચવી છે.

રૂા.૧૧.૭૯ કરોડના ખર્ચે જેલોની સુવિધા વધારવાની, નવી જેલોના બાંધકામ અને આધુનિકરણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.

રાજયમાં સરહદી વિસ્તારોના વિકાસ અને સુરક્ષા માટે એક વિસ્તૃત યોજના ભારત સરકારને રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાનો ભારત સરકારે સ્વીકાર કર્યો છે. આગામી વર્ષથી કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના તરીકે આ યોજના અમલમાં આવતાં રાજયના સરહદી વિસ્તારોની વ્યવસ્થા વધારે સુદૃઢ થશે.

ગુજરાતના સામાન્ય નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓ માટે એસ.ટી.ની સેવા એક આવશ્યક સેવા છે. છેલ્લા થોડા વર્ષથી ડિઝલ, ટાયર વગેરેના ભાવોમાં થયેલા વધારાના કારણે અને અન્ય ખર્ચમાં વૃદ્ધિ થતાં, એસ.ટી.ના સંચાલનમાં જે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઇ છે તેને નિવારવા સરકારે એસ.ટી.ને વધારાની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનું નક્કી કર્યું છે. આ બજેટમાં નવી બસો ખરીદવા માટે ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમને રૂા. ૧૨૦ કરોડ મૂડી સ્વરૂપે આપવામાં આવશે. આ નવી બસોમાં જયાં જયાં શકય હોય ત્યાં સી.એન.જી. બસોનો પણ સમાવેશ કરાશે. એસ.ટી.નું સંચાલન કાર્યક્ષમ બને તે માટે પણ રાજય સરકાર પ્રયત્નશીલ છે.

મહિલા અને બાળકલ્યાણ

રાજય સરકારે ત્રણ વર્ષ પહેલાં મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગની અલગ રચના કરી આ વિભાગને મહત્ત્વની જવાબદારી સોંપી છે. સમાજમાં મહિલા વ્યકિતત્વના વિકાસના જે અંતરાયો છે તે દૂર કરીએ તો જ આપણે સાચા અર્થમાં પ્રગતિશીલ બની શકીએ. આપણા સૌ માટે ઘેરી ચિંતાનો વિષય એ છે કે, રાજયમાં સ્ત્રી-પુરુષો વચ્ચેનું પ્રમાણ અસંતુલિત થયું છે. રાજય સરકાર ભ્રૂણહત્યાના પ્રશ્નને ગંભીરતાથી જુએ છે. આ અંગે મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગ તેમજ રાજય સરકારના તમામ વિભાગો તરફથી લોકશિક્ષણ અને તપાસની કામગીરી કરી માનવતા સામેના આ અપરાધને રોકવા માટે તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. માતૃવંદના કાર્યક્રમ હેઠળ આરોગ્ય વિભાગ જે કાર્યવાહી કરે છે તેની પૂરક કાર્યવાહી કરી, મહિલાઓમાં સ્વશક્તિ અને સશક્તિકરણ થાય તેવી તાલીમ યોજનાનો અમલ ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ દ્વારા થશે. રાજય સરકારે સ્ત્રી-પુરુષો વચ્ચે સમાનતા સ્થપાય અને મહિલા પર કોઇ પ્રકારની હિંસાના બનાવ ન બને તે માટે

દેખરેખ રાખવા જેન્ડર રિસોર્સ સેન્ટરની સ્થાપના કરી છે અને વિભાગની કામગીરી માટે રૂા.૩.૭૮ કરોડની જોગવાઇ કરી છે. સમાજમાં નિરાધાર વિધવા સન્માનભેર જીવન જીવી શકે તે માટે વિધવા સહાય યોજનાનો અસરકારક અમલ થઇ રહ્યો છે. હાલ ૯૨,૦૦૦ વિધવા બહેનોને રાજય સરકાર તરફથી પોસ્ટ ઑફિસ મારફત નિયમિત પેન્શનની ચુકવણી થાય છે. આ માટે બજેટમાં રૂા.૬૬.૯૨ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. આ યોજનાની જોગવાઇમાંથી વિધવાઓને તાલીમ અને સાધન સહાય પણ આપવાની જોગવાઇ છે. મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમની કામગીરીને વિસ્તારવા માટે રૂા.૨ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. રાજયમાં ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ દ્વારા સ્વસહાય જૂથોની રચના સાથેસાથે મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગ તરફથી સ્વશક્તિ પ્રોજેકટ અને સ્વયંસિદ્ધાનો પણ અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સમાજમાં મહિલાઓને સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને આર્થિક રીતે સ્વાવલંબન પ્રાપ્ત થાય તે માટે ઘનિષ્ઠ પ્રયત્ન કરવાનો રાજય સરકારનો અભિગમ રહ્યો છે.

વિરામનો સમય રદ કરવા અંગે

શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ (મુખ્યદંડકશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય નાણામંત્રીશ્રીનું અંદાજપત્ર પ્રવચન પૂરું થાય એ માટે વિરામનો સમય રદ કરવા મારી વિનંતી છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી હું સંમત છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિરામનો સમય રદ કરવામાં આવે છે.

શ્રી વજુભાઈ વાળા (નાણામંત્રીશ્રી) :

બાળ કલ્યાણ અને પોષણ

બાળવિકાસની યોજનાઓ હેઠળ આંગણવાડીનું સંચાલન, શાળાએ જતાં બાળકોને મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના હેઠળ પોષણ આપવાની યોજનાઓની ફાળવણીમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાનો રાજય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. સને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં પોષણ અને બાળકલ્યાણ કાર્યક્રમ હેઠળ રૂા.૧૭૦.૨૩ કરોડની જોગવાઇ હતી તે વધારીને રૂા.૨૨૮.૨૪ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

સાયન્સ અને ટેકનોલોજી

રાજયના સર્વાંગી વિકાસમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વિશાળ પાયા ઉપર ઉપયોગ થાય તે દૃષ્ટિએ રાજય સરકારે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગની અલગ રચના કરી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સન્માનનીય સભાગૃહને એ જણાવતાં મને આનંદ થાય છે કે છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા અનેક મહત્ત્વપૂર્ણ કામગીરી સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજયમાં ૯૨મી અખિલ વિજ્ઞાન પરિષદનું અધિવેશન યોજાયું ત્યારે સાયન્સ સીટીએ યજમાન બનીને દેશના રાષ્ટ્રપતિ સહિતના તમામ અગ્રણી વૈજ્ઞાનિકોને ગુજરાતે સાધેલ વિકાસની ઝાંખી કરાવી છે. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક, ભારત સંચાર નિગમ અને ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા ટેલિફોનની સંખ્યામાં થયેલ અભૂતપૂર્વ વધારો અને ઇ-ગવર્નન્સને પૂર્ણતા તરફ લઇ જવાના પ્રયત્નો ઉલ્લેખનીય છે. મને એ જણાવતાં આનંદ થાય છે કે મહેસૂલ વિભાગે ઇ-ધરા પ્રોજેકટ પૂર્ણ કરેલ છે અને તમામ જિલ્લામાં અને તાલુકામાં નાગરિક સુવિધા કેન્દ્રની સેવાઓ વન-ડે ગવર્નન્સરૂપે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ કરાવી છે. બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રે બાયોટેકનોલોજી કાઉન્સિલની રચના કરી વેન્ચર ફંડની સ્થાપના કરી રિસર્ચ અને વિસ્તરણની કામગીરી માટે સાનુકૂળ સ્થિતિ નિર્માણ કરી છે. સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગ માટે સને ૨૦૦૪-૦૫ની રૂા.૬૭ કરોડની જોગવાઇ સામે વર્ષ ૨૦૦૫-૨૦૦૬માં રૂા.૧૩૪ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આયોજન ખર્ચની રકમ બેવડી કરી રાજય સરકારે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનું મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે. ભવિષ્યમાં શિક્ષિત લોકોની રોજગારીમાં પણ આ ક્ષેત્રનું પ્રદાન મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.

સેટેલાઇટ દ્વારા જમીન અને સમુદ્રના પરિબળોનો વ્યવસ્થિત સચિત્ર અભ્યાસ કરવાની કામગીરીમાં ભાસ્કરાચાર્ય ઇન્સ્ટિટયૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લિકેશન એન્ડ જીઓઇન્ફોર્મેટીકસ (બાયસેગ) દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી થઇ છે. આ સચિત્ર માહિતીના આધારે કૃષિ, વોટરશેડ, વન વિસ્તાર, માછીમારી જેવાં ક્ષેત્રોમાં લોકોપયોગી માહિતી સહેલાઇથી ઉપલબ્ધ થઇ છે. એજયુસેટ નામના સેટેલાઇટ દ્વારા ગુજરાતમાં દૂરસંચાર માધ્યમથી તમામ શાળાઓમાં આધુનિક શિક્ષણ આપવાની સવલત પણ વિકસી રહી છે.

માર્ગ વિકાસ

રાજયના ૧,૮૫૦ કિ.મિ. લંબાઇના રાજય ધોરીમાર્ગોને અદ્યતન કરવાની વિશ્વબેંક સહાયિત યોજનાની પ્રગતિ સંતોષકારક રીતે થઇ રહેલ છે. સદર યોજના પૈકી ૭૫૫ કિ.મિ. લંબાઇના માર્ગોનાં કામો રૂા. ૫૫૩ કરોડના

ખર્ચે પૂર્ણ થયેલ છે અને ૮૫૪ કિ.મિ. લંબાઇના ધોરીમાર્ગોના કામો રૂા. ૯૪૫ કરોડના ખર્ચે પ્રગતિ હેઠળ છે. સદર યોજના માટે રૂા. ૪૭૫ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

વિશ્વબેંક સહાયિત પુનઃર્નિમાણ યોજના હેઠળ રૂા.૩૦૪ કરોડના ખર્ચે ૯૫૬ કિ.મિ. લંબાઇના રાજય ધોરીમાર્ગોની સુધારણાનાં કામો વિવિધ તબક્કે પ્રગતિ હેઠળ છે.

ઉપરાંત ભૂકંપગ્રસ્ત ૧૨ જિલ્લાઓના ૧,૮૧૨ કિ. મી. લંબાઇના ગ્રામ્ય માર્ગોને રિસરફેસિંગ કરવાની રૂા.૧૦૬ કરોડની એડીબી સહાયિત યોજના પૂર્ણતાના આરે છે.

કોર નેટવર્ક

ઔદ્યોગિક વિકાસ, બંદરો, ખેતી પેદાશ કેન્દ્રો તથા અગત્યનાં શહેરોનાં જોડાણને ધ્યાને રાખી, ૮,૯૫૪ કિ.મિ. લંબાઇના ધોરીમાગોર્ની કોર-નેટવર્ક સુધારણા માટે નિયત કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ૨,૭૮૮ કિ.મિ. લંબાઇના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને ૬,૧૬૬ કિ.મિ. લંબાઇના રાજય ધોરીમાર્ગોનો સમાવેશ થાય છે.

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગનાં કામો

ગુજરાત રાજયમાં વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ દરમ્યાન રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વિકાસ યોજના હેઠળ નડિયાદ-વડોદરા એકસપ્રેસ વે ના ૫૦ કિ. મી. રૂા.૩૪૫ કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. હિંમતનગર-ચિલોડા સેકશનમાં બાવન કિ. મી.ની કામગીરી રૂા.૧૪૫ કરોડના ખર્ચે અને સૂરત-અતુલ ૮૦ કિ.મિ. રૂા.૩૯૦ કરોડના ખર્ચે ચાર લેઇન પહોળા કરવાની કામગીરી પૂર્ણતાના અગ્ર તબકકે છે. ઉપરાંત ગુજરાત રાજયમાંથી પસાર થતા પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરીડોરના રાજસ્થાન સરહદથી પોરબંદર સુધીના ૫૮૩ કિ. મી. લંબાઇનાં કામોનાં ટેન્ડરો રૂા.૨,૫૮૩ કરોડની કિંમતે તાજેતરમાં મંજૂર થયેલ છે. આ કામો આગામી વર્ષ દરમ્યાન ચાલુ થનાર છે.

પથવિકાસ

રસ્તાઓનાં કામોમાં ગુજરાત અન્ય રાજયોની તુલનામાં ઘણી સારી સ્થિતિમાં છે પણ પહેલીવાર ગુજરાત સરકારે વ્યૂહાત્મક રીતે રસ્તાઓનું નેટવર્ક તૈયાર કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે.

ગુજરાતને ઉત્તર દક્ષિણ, પૂર્વ પશ્ચિમ કેવી રીતે જોડાય, શહેરો ગામડા સાથે કેવી રીતે જોડાય અને શહેરોમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ કેવી રીતે સુધરે તેવા નવતર અભિગમ સાથે વ્યૂહાત્મક પથવિકાસ હાથ ધર્યો છે. આઠથી દસ કલાકમાં એકથી બીજા છેડામાં માલ- સામાન પહોંચાડવા આ માર્ગ વિકાસની વ્યૂહરચના ઉપયોગી બનશે.

પ્રગતિપથ યોજના

આ વ્યૂહાત્મક માર્ગ રચનાના ભાગરૂપે પ્રથમ યોજના છે પ્રગતિપથ યોજના. જેમાં લાંબા અંતરના નવ હાઇસ્પીડ કોરીડોર તૈયાર કરવામાં આવશે.

પ્રગતિપથ એક :- પીપાવાવ- અંબાજી આબુ

પ્રગતિપથ બે :- રાધનપુર - શામળાજી

પ્રગતિપથ ત્રણ :- નારાયણ સરોવર દ્દાહોદ

પ્રગતિપથ ચાર :- ડાકોર-દ્વારકા

પ્રગતિપથ પાંચ :- સૂરત - આહવા

પ્રગતિપથ છ :- વાપી- શામળાજી

પ્રગતિપથ સાત :- દહેજ - સાગબારા

પ્રગતિપથ આઠ :- દ્વારકા- ભાવનગર

પ્રગતિપથ નવ :- વાવ- થરાદ - નર્મદા ડેમ

આ યોજનાના ઝડપી અમલ માટે રાજય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અને ખાનગી સાહસિકોનો સહયોગ રહેશે. અગાઉ મેં રજૂ કરેલ પૂરક માગણીઓમાં આ કામ માટે રૂા. ૧૦૦ કરોડની વધારાની જોગવાઇ દર્શાવી છે અને આ કાર્યને આગળ ધપાવવા ૨૦૦૫-૨૦૦૬ ના વર્ષમાં હું રૂા.૫૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું.

વિકાસપથ યોજના

રાજયના અનેક નગરોમાંથી રાજય ધોરીમાર્ગો પસાર થાય છે પરંતુ તેના આધુનિકરણ અને નિભાવ માટે વિશેષ ધ્યાન આપી શકાયેલ નથી. આ માર્ગોને આધુનિકતાના ધોરણે સુધારણાની આવશ્યકતાને ધ્યાનમાં લઇને નગરો કે મહાનગરોમાંથી પસાર થતા રાજય ધોરીમાર્ગને વિકાસપથ યોજના હેઠળ આધુનિક ધોરણે વિકસાવવાનો નિર્ણય કરેલ છે.

વિકાસપથ યોજના હેઠળ રાજયના શહેરી વિસ્તારના આ રસ્તાઓને પહોળા અને મજબૂતીકરણ કરવા, વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે બંધ ગટર, ફૂટપાથ અને સેન્ટ્રલ વર્જ તથા સ્ટ્રીટ લાઇટ જેવી સુવિધા આપવા નિર્ણય કરેલ છે. અગાઉ મેં રજૂ કરેલ પૂરક માંગણીઓમાં આ કામ માટે રૂા.૧૦૦ કરોડની વધારાની જોગવાઇ દર્શાવી છે. અને આ કાર્ય આગળ ધપાવવા સને ૨૦૦૫-૦૬ માટે રૂા.૫૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવેલ છે.

શહેરી વિકાસવર્ષ, ૨૦૦૫ એક મહત્ત્વાકાંક્ષી આયોજન છે. શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા બનેલી યોજનાના ભાગરૂપે શહેરોમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધાનું આધુનિક આયોજન કરવાનું છે, તે પૈકી શહેરોની અંદરના માર્ગોના વિકાસ માટે **સુવિધાપથ યોજના** કાર્યરત થશે, સાથે સાથે પ્રત્યેક નગરનો એક ઉત્તમ માર્ગ બને તે હેતુથી નગરના રસ્તા પૈકીનો એક રસ્તો **ગૌરવપથ** બને તેવું આયોજન છે.

કિસાનપથ યોજના

ગ્રામીણ વિસ્તારના વિકાસ માટે ગામોને જોડતા એપ્રોચ રોડ ઘણા અગત્યના છે આ માર્ગો દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારની ખેતપેદાશોનું વહન તેમજ આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવી સામાજિક જરુરિયાત પરિપૂર્ણ થાય છે. શહેરો અને ગામડાનું અંતર ઘટે, ગામડાને પણ શહેરો જેવી સુવિધા પ્રાપ્ત થાય તેવા ઉમદા હેતુથી ગ્રામીણ રસ્તાની આધુનિકતા અને વિકાસ માટે કિસાનપથ યોજના અમલમાં મૂકાશે. કિસાનપથ યોજનાને કારણે ગ્રામીણ અર્થકારણને ગતિ મળશે, કિસાનોને ખેતપેદાશો ખરીદ વેચાણ સંઘોમાં પહોંચાડવાની અનુકૂળતા વધશે. મહ્દઅંશે આ માર્ગો કિસાનોને અનેક રીતે લાભકર્તા થવાના હોવાથી આ યોજના કિસાનપથ યોજના તરીકે અમલમાં આવશે. કિસાનપથ યોજના હેઠળ સને ૨૦૦૫-૦૬ માટે રૂા.૫૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. અગાઉ મેં પૂરક માંગણીઓમાં આ કાર્ય માટે રૂા.૧૦૦ કરોડની માગણી રજૂ કરેલ છે. તદ્ઉપરાંત તાલુકાથી તાલુકા તથા તાલુકાથી જિલ્લાના જોડાણ તેમજ અન્ય જિલ્લા માર્ગો માટે રૂા.૫૫ કરોડની જોગવાઇ સૂચવેલ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતના સંતુલિત વિકાસ માટે અને એક વિકસિત રાજયની જરૂરિયાત સંતોષી શકે તેવા રોડ નેટવર્ક માટે આ સરકારે અત્યાર સુધીમાં મહત્તમ નાણાંની ફાળવણીનો નિર્ણય કરીને તમામ વિસ્તારોની અગત્યની જરુરિયાતો પૂરી કરવાની દિશામાં મહત્ત્વનું કદમ ઉઠાવ્યું છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફત હું માનનીય સભ્યશ્રીઓને સહર્ષ જણાવવા માગું છું કે આગામી વર્ષે તેમના તમામ વિસ્તારોમાં નવા માર્ગોના કામો અને હયાત રસ્તાઓના મજબુતીકરણનાં કામો દ્વારા આ નોંધપાત્ર સુધારો અનુભવી શકાશે.

યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

આપણી ભાવિ પેઢી સ્વસ્થ જીવન, સંસ્કાર અને કલા દ્વારા ગુજરાતની અસ્મિતા વધારે તેવી વ્યવસ્થા કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ધાર છે. મેં અગાઉ રજૂ કરેલ પૂરક માગણીમાં રાજ્યમાં રમત-ગમત સંકુલ બનાવવા, વિકસાવવા તથા જયશંકર સુંદરી નાટયગૃહના રિનોવેશન જેવી બાબતો માટે જોગવાઇ દર્શાવાયેલી છે. સને ૨૦૧૦માં રાષ્ટ્રસમૂહની રમત ભારતમાં યોજાય ત્યારે, ગુજરાતમાં વિવિધ રમતોનું આયોજન થાય તેવી સુવિધાવાળા રમત-ગમત સંકુલનું નિર્માણ યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવા રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે. રમત-ગમતની પ્રવૃત્તિઓનો ગ્રામીણ સ્તરે વિકાસ થાય તે માટે ગ્રામીણ ઓલમ્પિકનું આયોજન, દરેક જિલ્લામાં સ્પોર્ટસ સંકુલ, મહિલા ખેલાડીઓને શિષ્યવૃત્તિ, સ્વરક્ષણની તાલીમ, એડવેન્ચર ટૂરિઝમ, ટ્રેકિંગ વગેરે પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાજ્ય સરકારે જરૂરી વ્યવસ્થા કરી છે. ૨૧ ક્રાંતિવીરોના જીવન ઉપર આધારિત સરફરોશી પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાનું કાર્ય પણ આગામી વર્ષે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. યુવક સેવા, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ અને રમત-ગમતના વિકાસ માટે વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં રૂા.૨૭.૧૪ કરોડની જોગવાઇ સામે રૂા.૩૧.૮૬ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

શ્રમ

રાજ્યના યુવકોને રોજગારીની તકો પ્રાપ્ત થાય, રાજ્યના શ્રમિકોનું કલ્યાણ થાય અને રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક શાંતિ જળવાઇ રહે તે હેતુ માટે શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ માટે હું બિનઆયોજન સદરે રૂા.૭૫.૩૪ કરોડ અને આયોજન સદરે રૂા.૪૧.૪૯ કરોડ એમ કુલ રૂા. ૧૧૬.૮૩ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું. ગુજરાત રાજ્ય ઔદ્યોગિક શાંતિમાં મોખરે છે. સમગ્ર દેશમાં હડતાળ અને લોકઆઉટને કારણે ગુમાવવા પડતા માનવદિનમાં ગુજરાતનો આંક સૌથી નીચો છે. ગુજરાતમાં આઇ.ટી.આઇ.ના અભ્યાસક્રમોમાં આધુનિકરણ લાવી ઉદ્યોગો સાથે તેનું સંકલન વધારવાનો રાજ્ય સરકારનો નિંધાર છે.

નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક સુરક્ષા

ગરીબીરેખા નીચે જીવતાં કુટુંબો માટે પ્રતિ કિલો રૂા.૨ લેખે ઘઉં અને પ્રતિ કિલો રૂા. ૩ લેખે ચોખાની રાજય સરકારની યોજના તેમજ ભારત સરકારની અંત્યોદય યોજના હેઠળ કુલ રૂા.૧૩૮ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

ગ્રાહકોનાં હિતની રક્ષા માટે ત્રણ શહેરોમાં વધારાના ત્રણ ગ્રાહક ફોરમ અને નવસારી, પાટણ અને આણંદ નવા જિલ્લામાં ગ્રાહક ફોરમની રચના કરવામાં આવશે. અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોના વિભાગની કામગીરીમાં આધુનિકરણ યોજના હેઠળ રોજીરોટી માટે સ્થળાંતર કરતા પરિવારોને સુવિધા આપવાના હેતુથી રોમિંગ રેશન કાર્ડ આપવાનો પ્રોજેકટ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. પાયલોટ પ્રોજેકટ પંચમહાલ જિલ્લામાં અમલમાં આવ્યો છે અને ભવિષ્યમાં અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે.

માહિતી અને પ્રસારણ

રાજય સરકારે વિકાસમાં લોકભાગીદારીને ખૂબ મહત્ત્વનું અંગ ગણ્યું છે અને આ મહત્ત્વને ધ્યાનમાં રાખીને લોકસમુદાય સુધી વિકાસની બધી ગતિવિધિઓ પહોંચે અને જનસમૂહ તેનાથી પરિચિત થાય તેમજ છેવાડાના માનવી સુધી યોજનાઓના કલ્યાણકારી પગલાંની માહિતી પહોંચે તે માટે માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ પ્રવૃત્ત છે. રાજયની તમામ માહિતી કચેરીઓ અને માહિતી નિયામકની કચેરી વચ્ચે તેમજ વિવિધ વર્તમાનપત્ર માટે ઇ-મેલ વ્યવહાર પ્રસ્થાપિત થયો છે. બજેટમાં માહિતી અને પ્રસારણ સદરે રૂા.૨૭.૯૩ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે. આ જોગવાઇ દ્વારા પ્રિન્ટ મિડિયા અને ઇલેકટ્રોનિકસ મિડિયાને ઉપયોગી માહિતી સમયસર પૂરી પાડવાનો રાજય સરકારનો સંકલ્પ છે.

ન્યાયતંત્ર

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે ભૂકંપમાં નુકસાન પામેલી ન્યાય કોર્ટના મકાનોનું મરામત કામ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. આગામી વર્ષે રાજયના દરેક જિલ્લા મથકોએ જિલ્લા અદાલતની સ્થાપનાની કામગીરી પૂર્ણ થશે અને લીંક કોર્ટને તાલુકા કોર્ટમાં અપગ્રેડ કરવાનું કામ પણ હાથ ઉપર લેવામાં આવ્યું છે. રાજયની જેલો અને અદાલતોનું વીડિયો લીન્કેજનું કામ નોંધપાત્રરીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. ન્યાયતંત્રમાં કેસોના નિકાલમાં ઝડપ લાવવા માટે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની રચના, કમ્પ્યુટરાઇઝેશન અને તમામ જરૂરી સવલતો આપવા માટે રાજય સરકારે જરૂરી જોગવાઇ કરી છે. કાયદા વિભાગ માટે કુલ રૂા.૧૯૦.૨૦ કરોડની જોગવાઇ સૂચવી છે.

આદિજાતિ કલ્યાણ

વંચિતોના વિકાસ માટે રાજયની પ્રગતિનાં ફળ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવાની રાજય સરકારની નેમ રહી છે ગુજરાતના પૂર્વ પટ્ટીમાં વસતાં આદિજાતિ ભાઇબહેનોના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે રાજય સરકારે આગામી બજેટમાં વધારે નાણાં ફાળવણી કરી વિકાસની ગતિ વધે તે માટે વ્યવસ્થા કરી છે. ટ્રાયબલ એરિયા સબ પ્લાનમાં વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ની રૂા ૮૨૧ કરોડની જોગવાઇમાં ધરખમ વધારો કરી આગામી વર્ષે હું રૂા.૧૩૮૭ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું. ગુજરાત પેટર્નમાં વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં રૂા.૨૦૮ કરોડની જોગવાઇ છે, તેમાં વધારો કરી, હું રૂા.૪૧૪ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું. આદિજાતિ પેટા યોજનામાં ૬૯ ટકાનો વધારો કરીને, રાજય સરકાર વંચિતોના વિકાસની દિશામાં પણ હરણફાળ ભરવા માંગે છે. સમાજના સૌથી છેવાડે વસતા આદિજાતિ પરિવારોનું જીવનધોરણ નોંધપાત્રરીતે સુધરે તે માટે પર્યાપ્ત નાણાકીય જોગવાઇ સૂચવાયેલ

છે. શાળામાં અભ્યાસ કરતાં બાળકોને પુસ્તકો, ગણવેશ વગેરે વિનામૂલ્યે પૂરાં પાડવા, ઉપરાંત આશ્રમ શાળાનું સંચાલન તથા આદિજાતિ કન્યાને વિનામૂલ્યે સાયકલ પૂરી પાડવામાં રાજય સરકાર અગ્રેસર રહી છે. આદિજાતિ વિસ્તારમાં સૌથી પછાત એવા આદિમ જૂથના લાભાર્થીઓમાં જનશ્રી વીમા યોજના હેઠળ ૫,૦૦૦ કુટુંબોને આવરી લેવામાં આવશે. ગુજરાત પેટર્ન યોજના હેઠળ રૂા.૪૧૪ કરોડની પૂરતી ફાળવણી થવાને કારણે વિકાસના અનેક નાનાં-મોટાં કામો સ્થાનિક જરુરિયાતને લક્ષમાં લઇને પૂરાં કરી શકાશે. ૨૦૦૫-૦૬નું વર્ષ, આદિજાતિ વિકાસ અને કલ્યાણના ક્ષેત્રમાં એક સીમાચિન્હ બની રહે તે માટે રાજય સરકારે આ ભગીરથ પુરુષાર્થની શરૂઆત કરી છે. આદિજાતિ વિસ્તારમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, આંતરમાળખાકીય સુવિધા, વીજળી તેમજ રોજગારી ક્ષેત્રે મહત્તમ કામગીરી થાય તે માટે રાજય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ રહી છે.

અનુસૂચિત જાતિઓનું કલ્યાણ

ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જાતિઓએ શિક્ષણક્ષેત્રે સારી પ્રગતિ કરી છે તેવી આયોજન પંચે પણ નોંધ લીધી છે. અનુસૂચિત જાતિના પરિવારોના આર્થિક ઉત્થાન અને સામાજિક વિકાસ માટે આગામી વર્ષે આયોજન સદરે રૂા.૧૧૭.૧૭ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું. રાજયના અનુસૂચિત જાતિના વિકાસ માટે ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૦૪-૨૦૦૫માં રૂા.૩૧૫ કરોડની જોગવાઇ છે તે સામે વર્ષ ૨૦૦૫-૨૦૦૬માં રૂા.૪૦૩ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું.

વિકસતી જાતિ કલ્યાણ

સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ, વિચરતી વિમુકત જાતિઓ, અલ્પ સંખ્યકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે વર્ષ ૨૦૦૪-૨૦૦૫ની રૂા.૧૧૩ કરોડની આયોજન સદરની જોગવાઇમાં વધારો કરી, હું રૂા.૧૪૩.૧૭ કરોડ સૂચવું છું.

સમાજ સુરક્ષા

રાજયમાં વિકલાંગોના વિકાસ માટે, વસ્તીગણતરી હેઠળ જે માહિતી ઉપલબ્ધ થઇ છે તેને લક્ષમાં રાખીને એક સર્વગ્રાહી યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે. રિમાન્ડ હોમના બાળકો, ભિક્ષુકોના પુનઃ સ્થાપન માટે તેમજ નિરાધાર બહેનો અને વૃદ્ધો માટે પણ આર્થિક સહાયની યોજનાઓ કેન્દ્રિય સહાય સાથે ચાલુ રહેશે.

સમાજ સુરક્ષાની વિવિધ યોજના માટે આયોજન સદરે વર્ષ ૨૦૦૪-૨૦૦૫ની રૂા ૧૪.૭૪ કરોડની જોગવાઇ સામે, આગામી વર્ષે રૂા.૩૪.૭૪ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું. જે બમણા કરતાં પણ વધારે છે.

સુશાસન અને આર્થિક વ્યવસ્થાપન

ગુડ ગવર્નન્સ, આ શબ્દ જાણે વિકસિત રાષ્ટ્રોનો ઇજારો હોય તેવી માન્યતા વચ્ચે ગુજરાત સરકારે ગુડ ગવર્નન્સના ક્ષેત્રે નક્કર કામગીરી દ્વારા સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. યુનાઇટેડ નેશન્સનો સાસાકાવા એવોર્ડ-૨૦૦૩, પર્યાવરણનો વિશ્વ બેંકનો સર્વોચ્ચ ગ્રીન એવોર્ડ અને તાજેતરમાં કોમનવેલ્થ ગોલ્ડ એવોર્ડ ફોર પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ એમ- વિશ્વ કક્ષાના ત્રણ એવોર્ડ મેળવી સુશાસન ક્ષેત્રે ગુજરાતે ગૌરવવંતુ સ્થાન હાંસલ કર્યુ છે. આ કાર્ય માટે આ સભાગૃહના તમામ માનનીય સભ્યશ્રીઓ, મંત્રીમંડળના મારા સાથીઓ, રાજય સરકારના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ યશના સહભાગી છે. ગુજરાત સરકારે કર્મયોગી મહાઅભિયાન હેઠળ કર્મચારીઓની વાયબ્રન્ટ ગવર્નન્સ માટેની તાલીમ માટે પૂરતી કાળજી લીધી છે. ૨૦૦૫-૦૬ના બજેટમાં આ જોગવાઇ બમણી કરી રૂા. ૫ કરોડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકારની માર્ગદર્શક સૂચના મુજબ રાજયની કાર્યસંસ્કૃતિમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવાના હેતુથી દરેક વિભાગ તેના પગાર- ભથ્થાંના બજેટના ૦.૨ ટકા રકમ તાલીમ માટે વાપરે તેવી સૂચનાઓનો અસરકારક અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સભાગૃહને જણાવતાં હું આનંદ અને ગૌરવ અનુભવું છું કે કુદરતી આપત્તિઓની વિષમ પરિસ્થિતિઓમાંથી ગુજરાત રાજય સફળતાપૂર્વક બહાર આવ્યું છે. ચાલુ વર્ષે રાજયની આવકનો પ્રવાહ સંતોષકારક રહ્યો છે અને ધારણા કરતાં તેમાં નોંધપાત્ર સુધારો પણ થયો છે. રાજય સરકાર દ્વારા મહેસૂલી ખાધ નિવારવા માટે સઘન આયોજન કરી સફળતા હાંસલ કરવામાં આવી છે. આના જ કારણે રાજય સરકારે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ભારત સરકારની ડેબ્ટ સ્વેપ યોજના હેઠળ રૂા.૯,૨૫૬ કરોડ જેટલી રકમનું ઊંચા વ્યાજ દરનું દેવું પરત ચૂકવી રાજયના વધતા જતાં દેવાંના બોજ તથા વ્યાજ ચૂકવણી નિયંત્રણમાં લાવવામાં સફળતા હાંસલ કરી

છે. ભારત સરકાર દ્વારા નાણાકીય વ્યવસ્થાપનનાં જે ધારા-ધોરણ નક્કી કરવામાં આવ્યાં છે તે સંપૂર્ણ પૂરા કરી, મધ્યમ સમયની નાણાકીય પુનઃવસન યોજના અંગે જરૂરિયાતો પૂરી કરી રૂા.૫૦ કરોડની સહાય મેળવવામાં સફળતા હાંસલ કરેલી છે. સુનિયોજિત નાણાકીય સંચાલન દ્વારા કરનો દર વધાર્યા વિના રાજયની મહેસૂલી આવક વધારવી, મહેસૂલી ખર્ચ નિયંત્રિત કરવો, વ્યાજનું ભારણ ઘટાડવું અને વિકાસનાં કામો માટે વિશેષ ભંડોળ ઉપલબ્ધ કરવું તે આ સરકારનો પાયાનો અભિગમ રહ્યો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું મારા પ્રવચનના ભાગ-ક નું સમાપન કરું ત્યારે રાજય સરકાર દ્વારા ડ્રીપ ઇરિગેશન, જયોતિગ્રામ, માતૃવંદના, વિકાસપથ, સુવિધાપથ-ગૈારવપથ અને કિસાનપથ તેમજ સાક્ષરદીપ જેવી નવી યોજનાઓ માટે પૂરતી ફાળવણી સૂચવ્યાનો આનંદ વ્યકત કરું છું. રાજયના બજેટમાં આદિજાતિ વિકાસ, ગુજરાત પેટર્ન, અનુસૂચિત જાતિનો વિકાસ, સામાજિક-શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે પછાતવગોર્નો વિકાસ- એમ વંચિતોના વિકાસ માટે જે અભૂતપૂર્વ જોગવાઇઓ કરી છે તે છેવાડાના માનવી પ્રત્યેની અમારી નિષ્ઠાનો સચોટ પુરાવો છે. પાણીના સંગ્રહ અને પાણીના વ્યવસ્થિત ઉપયોગ માટે મહાકાય નર્મદા યોજનાથી માંડીને નાની ખેત તલાવડી સુધી તમામ વિકલ્પો અંગે રાજય સરકારે ચિંતન કર્યું છે અને ગુજરાતની સૂકી ધરતી અને સૂકા પેટાળને નવપલ્લવિત કરવા માટે સુજલામ્-સુફલામ્ જેવી વિશાળ યોજનાને ઓછામાં ઓછા સમયમાં પૂરી કરવા ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો છે. શિક્ષણ અને આરોગ્યના ક્ષેત્રે સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મક નોંધપાત્ર સુધારો થાય તે માટે સમગ્ર તંત્ર તેમજ લોકોને સાંકળ્યા છે. ગરીબો માટે પૂરતા આવાસો, ગ્રામીણ કક્ષાએ સંપૂર્ણ સુવિધાઓ અને શહેરી વિકાસ માટે સર્વગ્રાહી આયોજન એ આ બજેટની આગવી વિશેષતાઓ છે. રાજયના ઝડપી ઔદ્યોગિક વિકાસ અને ઊર્જાની જરૂરિયાત માટે પૂરતી બજેટ જોગવાઇઓ અને ખાનગી મૂડીરોકાણ માટેના ઉત્તમ વાતાવરણનું સર્જન કરવામાં રાજય સરકાર સફળ રહી છે. પરિવહન માટે, પ્રદૂષણ નિવારણ માટે સી.એન.જી. બસોનો ઉપયોગ અને રોજગાર ક્ષેત્રે એપેરલ પાર્ક, જેમ્સ એન્ડ જવેલરી પાર્ક અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન દ્વારા નવી રોજગારીની તકોનું નિર્માણ કરવામાં પણ રાજય સરકાર આગળ વધી રહી છે.

૨૦૦૩-૦૪ના હિસાબ

હવે હું ૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષની ખરેખર આવક અને ખર્ચની સમીક્ષા હાથ ધરીશ. વર્ષ દરમિયાન ચોખ્ખી લેવડ દેવડના કારણે રૂા. ૪૦૬.૬૨ કરોડની ખાધ રહેશે તેવી ધારણા સુધારેલા અંદાજમાં હતી પરંતુ ૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષ માટેના હિસાબ ચોખ્ખી લેવડ દેવડના કારણે માત્ર રૂા. ૨૩ લાખની ખાધ દર્શાવે છે.

(રૂા. કરોડમાં)

	૨૦૦૩-૨૦૦૪ના સુધારેલ અંદાજ	**૨૦૦૩-૨૦૦૪ નો હિસાબ**
(૧) એકત્રિત ફંડ		
મહેસૂલી આવક	**૨૦૧૪૫.૮૩**	**૧૮૨૪૭.૫૨**
મહેસૂલી ખર્ચ	**૨૩૬૦૭.૪૩**	**૨૧૯૫૪.૧૩**
મહેસૂલી હિસાબ પર ખાધ/પુરાંત	**(-) ૩૪૬૧.૬૦**	**(-) ૩૭૦૬.૬૧**
મૂડી આવક	**૨૩૯૨૮.૭૧**	**૨૨૩૬૮.૪૧**
લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહિત મૂડી ખર્ચ	**૨૧૬૯૬.૨૧**	**૧૮૧૯૨.૭૪**
મૂડી હિસાબ પર ખાધ/પુરાંત	**() ૨૨૩૨.૫૦**	**() ૪૧૭૫.૬૭**
સરવાળો (૧) એકત્રિત ફંડ (ચોખ્ખું)	**(-) ૧૨૨૯.૧૦**	**() ૪૬૯.૦૬**
(૨) આકસ્મિક ફંડ(ચોખ્ખું)	--	**(-) ૮૧.૦૪**
(૩) જાહેર હિસાબ(ચોખ્ખો)	**() ૮૨૨.૪૮**	**(-) ૩૮૮.૨૫**
(૪) સરવાળો ચોખ્ખી લેવડદેવડ(૧૨૩)	**(-) ૪૦૬.૬૨**	**(-)૦.૨૩**

૨૦૦૪-૦૫ના સુધારેલ અંદાજ

૨૦૦૪-૨૦૦૫ના અંદાજમાં ચોખ્ખી લેવડ-દેવડોને કારણે ખાધ રૂા. ૨૨૬.૦૭ કરોડની થવાની ધારણા હતી પરંતુ સુદૃઢ નાણાકીય વહિવટ, વેરાની વસૂલાત, કરકસરના પગલાં, ઊંચા વ્યાજ દરની લોનની પૂર્વ ચૂકવણી વગેરે પગલાંને કારણે સુધારેલા અંદાજમાં ચોખ્ખી લેવડ દેવડના કારણે રૂા. ૨૮.૮૨ કરોડની પુરાંત રહેવાની ધારણા છે.

(રૂા. કરોડમાં)

	૨૦૦૪-૨૦૦૫ ના ફેરફાર કરેલ અંદાજ	**૨૦૦૪-૨૦૦૫ ના સુધારેલ અંદાજ**
(૧) એકત્રિત ફંડ		
મહેસૂલી આવક	**૨૦૮૧૩.૬૭**	**૨૦૨૦૫.૬૮**
મહેસૂલી ખર્ચ	**૨૩૭૮૬.૩૩**	**૨૪૦૭૪.૯૨**
મહેસૂલી હિસાબ પર ખાધ /પુરાંત	**(-) ૨૯૭૨.૬૬**	**રૂં(-) ૩૮૬૯.૨૪**
મૂડી આવક	**૯૬૩૯.૮૧**	**૧૭૨૭૯.૩૦**
લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહિત મૂડી ખર્ચ	**૭૧૭૧.૯૫**	**૧૩૮૩૯.૫૭**
મૂડી હિસાબ પર ખાધ / પુરાંત	**() ૨૪૬૭.૮૬**	**() ૩૪૩૯.૭૩**
(૧) એકત્રિત ફંડ (ચોખ્ખું)	**(-) ૫૦૪.૮૦**	**(-) ૪૨૯.૫૧**
(૨) આકસ્મિક ફંડ(ચોખ્ખું)	--	--
(૩) જાહેર હિસાબ(ચોખ્ખો)	**() ૨૭૮.૭૩**	**() ૪૫૮.૩૩**
(૪) સરવાળો ચોખ્ખી લેવડદેવડ(૧૨૩)	**(-) ૨૨૬.૦૭**	**() ૨૮.૮૨**

* (૧) ડેબ્ટ સીન્કીંગ ફંડમાં રૂા ૨૪૦ કરોડ તથા ગેરંટી રિડમ્પ્શન ફંડમાં રૂા.૨૦૦ કરોડનું રોકાણ.

(૨) કૃષિ વિષયક સબસિડીની રૂા. ૮૩૫ કરોડની જોગવાઈ.

(૩) શહેરી વિસ્તારની સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ માટે રૂા.૩૧૦ કરોડની જોગવાઈ.

૨૦૦૫-૦૬નો અંદાજ

૨૦૦૫-૨૦૦૬ના અંદાજ નીચે પ્રમાણે રૂા. ૮૭.૧૪ કરોડની એકંદર પૂરાંત દર્શાવે છે.

(રૂા. કરોડમાં)

(૧) એકત્રિત ફંડ	**૨૦૦૫-૨૦૦૬ના અંદાજ**
મહેસૂલી આવક	**૨૩૨૧૭.૪૧**
મહેસૂલી ખર્ચ	**૨૪૬૫૬.૦૭**
મહેસૂલી હિસાબ પર ખાધ /પુરાંત	**(-) ૧૪૩૮.૬૬**
મૂડી આવક	**૧૨૩૩૮.૮૪**
લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહિત મૂડી ખર્ચ	**૧૧૦૪૬.૧૨**
મૂડી હિસાબ પર ખાધ / પુરાંત	**() ૧૨૯૨.૭૨**
સરવાળો (૧) એકત્રિત ફંડ (ચોખ્ખું)	**(-) ૧૪૫.૯૪**
(૨) આકસ્મિક ફંડ(ચોખ્ખું)	--

(૩) જાહેર હિસાબ (ચોખ્ખો)	**() ૨૩૩.૦૮**
(૪) સરવાળો ચોખ્ખી લેવડદેવડ(૧૨૩)	**() ૮૭.૧૪**

હવે હું મારા પ્રવચનનો ભાગ-ખ રજૂ કરીશ.

૨૦૦૫-૨૦૦૬
ભાગ-ખ

આદરણીય અધ્યક્ષશ્રી,

રાજયની આર્થિક સ્થિતિ સુદ્દઢ કરવાના હેતુથી અમારી સરકારે અમલમાં મૂકેલા સુચારુ નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને વિકાસલક્ષી આર્થિક નીતિના ફળસ્વરૂપે, સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬ના વર્ષના અંદાજો અનુસાર, એકદંર પુરાંત રૂપિયા ૮૭.૧૪ કરોડની રહેશે.

(૨) અમારી સરકારના સાતત્યપૂર્ણ અને કાર્યક્ષમ પ્રયાસોને પરિણામે, નાણાકીય ખાધની પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી, પુરાંતવાળી પરિસ્થિતિમાં પહોંચ્યા છીએ ત્યારે, સરકારે હવે આ સ્થિતિને વધુ સુદ્દઢ બનાવવાના હેતુથી, કરવેરાના માળખાને સરળ, સંતુલિત અને અસરકારક બનાવવાની દિશામાં પ્રયાસો જાળવી રાખવાનો મકકમ નિર્ણય કર્યો છે. વર્ષ ૨૦૦૫-૨૦૦૬ના અંદાજોમાં પુરાંતવાળી પરિસ્થિતિ રહેનાર હોવાથી રાજયની પ્રજાને રાહત મળે, શિક્ષણને પ્રોત્સાહન મળે, વેપાર ઉદ્યોગનો વિકાસ થાય, વગેરે જેવી અનેકવિધ અગત્યની બાબતોને ધ્યાનમાં લઇને, શકય તેટલી વેરા રાહતો આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

(૩) પ્રવર્તમાન સમયમાં વૈશ્વિકરણ, ઉદારીકરણ, રાજયની આર્થિક વ્યવસ્થા, વેપાર-ઉદ્યોગની સમસ્યાઓ, વગેરેને કેન્દ્રસ્થાને રાખી કરવેરાની દરખાસ્ત કરવાનું આવશ્યક બન્યું છે. જેથી કરીને આમ જનતા, વેપાર ઉદ્યોગ અને રાજય ઉત્તરોત્તર આર્થિક વિકાસ પામે.

(૪)હવે હું વર્ષ ૨૦૦૫-૨૦૦૬ના વર્ષ માટેની કરવેરાની દરખાસ્ત રજૂ કરું છું.

વેલ્યુએડેડ ટેક્સ

(૫) આ ગૃહે માર્ચ ૨૦૦૩ ની સાલમાં, ગુજરાત રાજય વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ બિલ, ૨૦૦૩ પસાર કર્યુ હતું. આ બિલને ત્યારબાદ, રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી અર્થે ભારત સરકારને મોકલી આપવામાં આવ્યું હતું.

(૬) ભારત સરકારે આ અંગે થયેલી ચર્ચાવિચારણાઓના સંદર્ભમાં, મે, ૨૦૦૩ની સાલમાં વેલ્યુએડેડ ટેક્સના કાયદાને અમલમાં લાવવાનું મોકૂફ રાખ્યું હતું. આ ચર્ચા વિચારણાઓનો સૂર એ હતો કે (અ) વેલ્યુએડેડ ટેક્સની જોગવાઇઓ, બધાં જ રાજયો વચ્ચે એક સમાન થાય તથા (બ) સઘળાં રાજયો એક સાથે વેલ્યુએડેડ ટેક્સ દાખલ કરે તો જ તેમાં સફળતા મળે તેમ છે.

(૭) આ સંજોગોમાં, રાજયોના નાણામંત્રીશ્રીઓની બનેલી એમ્પાવર્ડ કમિટિમાં થયેલ ચર્ચા વિચારણાઓને અંતે એવો નિર્ણય થયો છે કે આ કમિટિએ નકકી કરેલા ચોકકસ મુદ્દાઓ મુજબ (common points of convergence) દરેક રાજય તેના વેટ એકટમાં જરૂરી સુધારા કરે.

(૮) ભારત સરકારે નીમેલી એમ્પાવર્ડ કમિટિ ધ્વારા સ્ટેટ લેવલ વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ અંગેનું વાઇટ પેપર તારીખ ૧૭-૧-૨૦૦૫ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

(૯) ગુજરાત રાજય વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ બિલ, ૨૦૦૩ ને ભારતના રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી તારીખ ૧૭-૧-૨૦૦૫ના રોજ મળી ગઇ છે. આ મંજૂરી મળતાં, તારીખ ૨૫-૧-૨૦૦૫ના ગેઝેટમાં, વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ બિલ, ૨૦૦૩ને, વર્ષ ૨૦૦૫ના કાયદા ક્રમાંક-૧ તરીકે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. આથી હવે, ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ, કોમન પોઇન્ટ ઓફ કન્વર્ઝન્સ તથા વાઇટ પેપરને ધ્યાનમાં લઇને, ગુજરાત વેલ્યુએડેડ ટેક્સ એકટ, ૨૦૦૩ માં જરૂરી સુધારા વધારા કરવાના થાય છે.

(૧૦) આ તબકકે એ બાબત ખૂબ જ અગત્યની બની જાય છે કે વેલ્યુ એડેડ ટેક્સનો અમલ દેશનાં બધાં જ રાજયો ધ્વારા એક સાથે કરવામાં આવે. આમ કરવામાં આવશે તો જ વેટ એકટને ધારી સફળતા મળી શકશે. આ સંજોગોમાં, અમારી સરકારની, કેન્દ્ર સરકારને રજૂઆત છે કે જો વેલ્યુ એડેડ ટેક્સના કાયદાનો અમલ તા. ૧-૪-૨૦૦૫થી કરવાનો હોય તો, તમામ રાજયો દ્વારા તે એક સાથે થાય તે બાબત સવેળા સુનિશ્ચિત કરે. અમુક રાજયો ધ્વારા વેટના કાયદાનો અમલ શરૂ થાય અને અમુક રાજયો દ્વારા અમલ શરૂ ન થાય તો વેટ અને વેપાર માટે સમસ્યાનું નિર્માણ થશે. આથી બધાં રાજયો દ્વારા, વેટનો અમલ એક સાથે થાય તે બધી રીતે ઉચિત રહેશે.

વેચાણવેરો

(૧૧) રાજયમાં વાયુ પ્રદૂષણનું નિયંત્રણ કરવા માટે અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજયમાં સી.એન.જી. સંચાલિત વાહનોના વપરાશને પ્રોત્સાહન મળે તેવો અમારી સરકારનો અભિગમ છે. આ અભિગમના અમલીકરણના ભાગરૂપે સી.એન.જી. કીટના વપરાશને પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુથી, સી.એન.જી. કીટ ઉપર હાલ વેચાણવેરાનો દર ૮ ટકા છે તેને વેચાણવેરામાંથી સંપૂર્ણ વેરામુકત કરવાની મારી દરખાસ્ત છે. આ વેરામુકિતનો મહત્તમ લાભ બસો, ટેક્સીઓ અને ઓટોરિક્ષાઓને મળશે.

વીજળી ઉપરના વેરા

(૧૨) રાજયના વેપાર-ઉદ્યોગનો ઝડપી વિકાસ થાય. સાથેસાથે રાજયની વેરાની આવકો પણ જળવાઇ રહે તે રીતે કરવેરાનું માળખું સરળ અને તર્કસંગત બનાવવાનો રાજય સરકારનો અભિગમ રહેલો છે.

(૧૩) આ અભિગમના ભાગરૂપે રાજય સરકારે વીજક્ષેત્રે અગાઉનાં વર્ષોમાં વીજકરના વેરાનું ભારણ શકય તેટલું ઓછું થાય તે હેતુથી જુદા જુદા વીજવપરાશકારોને તબકકાવાર જુદી જુદી રાહતો આપેલ છે.

વીજળી ઉપરના વેરામાં અગાઉ અપાયેલી રાહતો.

(૧૪) રહેણાકના ૬૫ લાખ જેટલા ગ્રાહકોને લાગુ પડતા વીજકર દરમાં રૂપિયા ૫૮ કરોડની રાહત આપેલ.

૧૮ વર્ષથી વસૂલ કરવામાં આવતો વીજળી ઉપરનો વેચાણવેરો તા. ૧-૪-૨૦૦૨થી રદ કરી અંદાજે ૯૦ લાખ જેટલા ગ્રાહકોને રૂપિયા ૨૬૦ કરોડની રાહત આપવામાં આવેલ.

વાણિજિયક તથા રેસિડયુઅરી કક્ષાના ૧૨ લાખ ગ્રાહકોને રૂપિયા ૬૨ કરોડની રાહત આપેલ.

૨૨ વર્ષથી સિંચાઇના હેતુ માટે વાપરવામાં આવતી વીજળી ઉપરની ડયુટી રદ કરીને ૬,૫૧,૦૦૦ જેટલા કિસાનોને રાહત આપેલ.

ઉપરોકત રીતે અમારી સરકારે તમામ ક્ષેત્રના વીજ વપરાશકારોને અંદાજે રૂપિયા ૪૦૦ કરોડની રાહતો આપેલ.

વીજકર દરમાં વધુ રાહતો.

(૧૫) વીજ ક્ષેત્રે કરવેરાનું માળખું સરળ અને તર્કસંગત બને તે હેતુસર શરૂ થયેલી આ પ્રક્રિયાને, આગળ લઇ જવાના ભાગરૂપે, હવે વીજળી ઉપરના વેરામાં વધુ રાહતો આપવાની જાહેરાત કરું છું.

માન્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓ

(૧૬) વિદ્યાર્થીઓ માટેનાં કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયો સહિત, માન્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓને રાહત મળે તે હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને, માન્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટેના ગ્રામ્ય વિસ્તારના હાલના વીજકર દરને, ૨૦ ટકાથી ઘટાડીને ૧૫ ટકા કરવાની દરખાસ્ત છે.

શહેરી વિસ્તારમાં આવેલી માન્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે મહિનાના ૪૦ યુનિટ સુધીના વપરાશ માટે હાલનો વીજકર દર ૨૫ ટકા છે તેને ઘટાડી ૨૦ ટકા કરવાની મારી દરખાસ્ત છે.

તેમજ મહિનાના ૪૦ યુનિટથી વધુ વપરાશ માટે વીજકર દર ૪૦ ટકા છે તે ઘટાડીને ૩૫ ટકા કરવાની મારી દરખાસ્ત છે.

આ દરો ઘટવાથી સમગ્ર રાજયમાં આવેલી માન્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓના નિભાવ ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. જે શિક્ષણની પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહિત કરશે.

સેવા આપતા એકમો

(૧૭) સેવા આપતા એકમોમાં, મરામત કામ કરનાર, નવીનીકરણનું કામ કરનાર, એસેમ્બલિંગનું કામ કરનાર, ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા પ્રોસેસિંગ તથા ક્લિનિંગની પ્રવૃત્તિ કરતા એકમો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આવા એકમોના મોટિવ પાવરનો વીજકર દર ૩૦ ટકાથી ઘટાડીને ૧૫ ટકા કરવાની મારી દરખાસ્ત છે. આ ઘટાડાને કારણે ગ્રામ્ય તથા શહેરી વિસ્તારોમાં કાર્યરત આવા સેવા આપતા એકમોને તેમના વીજકર ખર્ચમાં સારા પ્રમાણમાં રાહત મળશે.

રેસિડયુઅરી કક્ષાના ગ્રાહકો

(૧૮) રેસિડયુઅરી કક્ષાના ગ્રાહકોમાં મહદ્અંશે નાના દુકાનદારો, ગોડાઉન, ધંધાદારી તેમજ વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિ કરનારા, સંશોધન સંસ્થાઓ, ખાનગી લાયબ્રેરી, ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, ટેલિફોન સર્વિસ, કેબલ સર્વિસ, ખાનગી - નફાના ધોરણે ચાલતાં દવાખાનાં અને હોસ્પિટલ, ટી.વી. સ્ટુડિયો, પેટ્રોલ પંપ, ગેસ સ્ટેશન, રીફીલીંગ પ્લાન્ટ, એસ.ટી.ડી. પી.સી.ઓ., આઇસ્ક્રીમ પાર્લર, મીઠાઇ અને ફરસાણની દુકાનો,અનાજ કરિયાણાંની દુકાનો, પાનના ગલ્લા, શાકભાજીના દુકાનદારો, ઝેરોક્સ-કોપિયર્સ, બુકસ્ટોલ અને સ્ટેશનરીની દુકાનો, દરજી અને હજામની દુકાનો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

આવા પ્રકારના વીજગ્રાહકોનો વીજકર દર હાલ ૪૫ ટકા છે. આ કર ઘટાડીને ૩૫ ટકા કરવાની મારી દરખાસ્ત છે.

રેસિડ્યુઅરી કક્ષાના ગ્રાહકો માટે થતા આ ઘટાડાથી સમાજના નાના નાના ધંધા અને વ્યવસાય કરતા લોકોના એક વિશાળ સમુદાયને રાહત મળશે અને સ્વરોજગારીની પ્રવૃત્તિને વેગ મળશે જેથી રોજગારીની તકો વધશે.

હોલ, પ્રેક્ષકગૃહ, સિનેમાઘર

(૧૯) હોલ, પ્રેક્ષકગૃહ, સિનેમાઘર માટે હાલમાં ૪૫ ટકાનો વીજકર દર લાગુ પડે છે. મનોરંજન તેમજ પ્રવાસન જેવા ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી આ દરમાં ઘટાડો કરી ૩૫ ટકા કરવાની મારી દરખાસ્ત છે.

હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ

(૨૦) હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગનો રાજયમાં સારો વિકાસ થયેલ છે. આ ક્ષેત્રમાં હજી પણ વિકાસને વેગ મળે તે હેતુથી તેના ઉપરના હાલના ૪૫ ટકાના વીજકર દરને ઘટાડીને ૩૫ ટકા કરવાની મારી દરખાસ્ત છે.

(૨૧) આ તબકકે હું ગૃહનું ધ્યાન દોરવા માગું છું કે, ઉપરોકત દરખાસ્તોમાં વીજકર દર, જયાં જયાં ૪૫ ટકાથી ઘટાડી, ૩૫ ટકા કરવાની દરખાસ્ત છે તેનાથી, સમાજના જુદા જુદા વર્ગોના અંદાજે ૧૨ લાખ કરતાં વધારે ગ્રાહકોને આ ઘટાડાનો લાભ મળશે. એક સાથે, આટલા મોટા પ્રમાણમાં, વીજકર રાહત આપવામાં આવતી હોય તેવી આ એક મોટી ઘટના હશે. જેનાથી મહદ્અંશે ગરીબ, મધ્યમવર્ગના લોકો તથા સ્વરોજગાર કરતા લોકો દ્વારા ચલાવવામાં આવતા એકમોને લાભ થશે.

ઔદ્યોગિક એકમો

(૨૨) દેશમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે રાજયે આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલું છે. રાજયની ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિને વેગ મળે તે હેતુથી સરકારે ગુજરાત ઔદ્યોગિક નીતિ - ૨૦૦૩ જાહેર કરેલ છે. જે અંતર્ગત ઔદ્યોગિક વિકાસને

પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુથી વિવિધ યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. રાજયના ઉદ્યોગોનો વધુ વિકાસ થાય, અન્ય રાજયોના ઔદ્યોગિક એકમો સાથે તેઓ તંદુરસ્ત સ્પર્ધા કરી શકે તથા વૈશ્વકિરણના આ સમયમાં તેઓ વૈશ્વકિ પડકારોનો સબળતાથી સામનો કરી શકે તેવા હેતુથી, ઉદ્યોગો ઉપરના વીજકર દરના ભારણને ઘ ટાડવાનું સરકારની વિચારણા હેઠળ હતું. તદ્અનુસાર ઉચ્ચ દબાણવાળા (H.T.)ઔદ્યોગિક એકમો માટે વીજકરનો દર જે હાલ ૨૦ ટકા છે તેમાં ઘટાડો કરી, ૧૫ ટકા કરવાની મારી દરખાસ્ત છે. આ રાહત ઉદ્યોગોને વધુ પ્રગતિ કરવામાં અને સ્પર્ધાત્મક બનવામાં મદદરૂપ થશે.

સ્વવીજ કેટેગરીના રેસિડ્યુઅરી કક્ષાના ગ્રાહકો

(૨૩) સ્વવીજ ઉત્પાદન કેટેગરીના રેસિડ્યુઅરી કક્ષાના ગ્રાહકો માટેનો વીજકર દર યુનિટ દીઠ ૭૦ પૈસા છે તેમાં, ૩૦ પૈસાનો ઘટાડો કરી, યુનિટ દીઠ ૪૦ પૈસા કરવાની મારી દરખાસ્ત છે. આ ઘટાડાથી મહદ્અંશે પેટ્રોલિયમ પેદાશોનું સંગ્રહ અને વહન કરતા હોય તેવા ગ્રાહકો તથા હંગામી કામગીરી કરતા કોન્ટ્રાકટરોને રાહત મળશે.

(૨૪) ઉપર સૂચવેલ ફેરફારોથી, વીજ ખરીદી માટેનો મહત્તમ વીજકર દર, ૪૫ ટકાથી ઘટીને હવે ૩૫ ટકા થશે. તેમજ વીજકરના સ્તરોની સંખ્યા જે હાલ ૮ છે તે ઘટીને ફકત ૪ થશે. સ્વવીજ ઉત્પાદનના ક્ષેત્રે મહત્તમ દર, યુનિટ દીઠ ૭૦ પૈસા છે તે ઘટીને, હવે ૪૦ પૈસા થશે. આ ફેરફારોથી વહીવટી રીતે પણ સરળીકરણ થશે.

(૨૫) ઉપરોકત તમામ રાહતોને કારણે સરકારની વીજકરની આવકમાં અંદાજી રૂપિયા ૨૨૯ કરોડનો ઘ ટાડો થશે. પરંતુ આ ઘટાડાને કારણે માન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સહિત રાજયના વેપાર ઉદ્યોગને બહોળા પ્રમાણમાં રાહત મળશે અને વિકાસની પ્રક્રિયાને વેગ મળશે. રાજયનું અર્થતંત્ર ચેતનવંતુ બનશે. ટેક્સ કોમ્પ્લાયન્સ વધશે અને રાજયની આવકમાં વધારો થશે. આમ છતાં, બાકી રહેતી એકંદર ખાધ, કરકસરયુકત વહીવટથી ઓછી કરવામાં આવશે.

સમાપન

(૨૬) સને ૨૦૦૫-૦૬ના વર્ષના અંદાજપત્રની આખરી પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે રહેશે.

	(રકમ રૂપિયા કરોડમાં)
અંદાજ અનુસારની પુરાંત	૮૭.૧૪
કરવેરામાં સૂચિત રાહત વીજકર	૨૨૯.૦૦
અંદાજી એકંદર ખાધ	૧૪૧.૮૬

માનનીય સભાગૃહની વિચારણા અર્થે હું આ અંદાજપત્ર રજૂ કરું છું.

૨૦૦૫-૨૦૦૬ના વર્ષ માટેનું અંદાજપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું.

સભાગૃહનું કામકાજ સવારના ૧૧-૧૩ વાગ્યે પુરું થતાં, અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર સભાગૃહ, સોમવાર તા. ૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના રોજ બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે ફરી મળવા મુલતવી રહ્યું.

ગુજરાત વિધાનસભા
સોમવાર, તા.૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫
ફાલ્ગુન ૨, ૧૯૨૬ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે મળ્યું.

અધ્યક્ષશ્રી પ્રો.મંગળભાઈ પટેલ અધ્યક્ષસ્થાને

તારાંકિત પ્રશ્નો

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઘટ

*૮૫૨૪ **શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ(લીંબડી)** : : **માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં તાલુકાવાર કેટલા શિક્ષકોની ઘટ છે, શાળાના કેટલા ઓરડાઓની ઘટ છે, અને

(૨) શિક્ષકોની ઘટ તથા ઓરડાઓની ઘટ પૂરી કરવા સરકારે શું વ્યવસ્થા કરેલ છે ?

માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી :

(૧) શિક્ષકોની ઘટ પત્રક-અ મુજબ ઓરડાઓની ઘટ પત્રક-બ મુજબ

(૨) શિક્ષકોની ઘટ જેમ બને તેમ જલ્દી પુરવામાં આવશે. જ્યારે ૩૩૭ નવા ઓરડાઓ બાંધવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તેમજ બાકી રહેતા ઓરડાઓ ક્રમશઃ બાંધવા માટે આયોજન કરવામાં આવશે.

પત્રક-અ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ તાલુકાવાર શિક્ષકોની ઘટ દર્શાવતું પત્રક			**પત્રક-બ** સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ તાલુકાવાર ઓરડાઓની ઘટ દર્શાવતું પત્રક		
ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ઘટ**	**ક્રમ**	**તાલુકાનું નામ**	**ઓરડાઓની ઘટ**
૧	વઢવાણ	૧૦	૧	વઢવાણ	૨૮૭
૨	લીંબડી	૩	૨	લીંબડી	૮૩
૩	ચુડા	૩	૩	ચુડા	૩૭
૪	મુળી	૭	૪	મુળી	૧૧૮
૫	સાયલા	૩	૫	સાયલા	૧૫૩
૬	ચોટીલા	૫	૬	ચોટીલા	૨૭૦
૭	હળવદ	૫	૭	હળવદ	૧૯૫
૮	ધ્રાંગધ્રા	૭	૮	ધ્રાંગધ્રા	૧૫૦
૯	લખતર	૮	૯	લખતર	૯૧
૧૦	પાટડી	૨	૧૦	પાટડી	૬૧
	કુલઃ-	૫૩		કુલઃ-	૧૪૪૫

શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૩૩૭ જેટલા ઓરડાઓ બાંધવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, તેમાંથી આજ કેટલા ઓરડાઓ બાંધવામાં આવ્યા છે અને કયા કયા તાલુકાઓમાં બાંધવામાં આવેલ છે? ૨૦૦૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આ વિસ્તાર માટે કુલ કેટલા ઓરડાઓ બનાવવામાં આવ્યા અને કેટલા શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવી? રાજય સરકાર દ્વારા પ્રત્યેક વર્ગ માટે એક શિક્ષક અને એક વર્ગ ખંડના બાંધકામની જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેમાં.........

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ભવાનભાઈ, આપ પ્રશ્ન પૂછો.

શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પ્રશ્ન પૂછું છું, કુલ કેટલા શિક્ષકોની અને કેટલા વર્ગોની જરુરિયાત રહે છે અને તે શિક્ષકો અને ઓરડાઓની ઘટ કયારે પૂરી કરવામાં આવશે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સુરેન્દ્રનગરમાં ૫૩ ઘટ છે અને અત્યાર સુધીમાં ૩૦૮૪ જેટલા વિદ્યા સહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી છે. છેલ્લા તબક્કામાં ૮૯૨ શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવી છે. અત્યારે શિક્ષકોની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ખાસ ઘટ નથી. અને જે છે તે નવા વર્ષે પૂરી કરવામાં આવશે. ૨૦૦૨-૨૦૦૩માં ૨૨૬ વિદ્યા સહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી હતી, ૨૦૦૩-૨૦૦૪માં ૨૪૮ ની ભરતી કરવામાં આવી હતી. છેલ્લે ૮૯૨ ની ભરતી કરવામાં આવી છે. જે ઓરડાઓ ફાળવામાં આવ્યા છે તેમાં આ વર્ષે હમણાં જ ઓરડાઓ ફાળવી દેવામાં આવ્યા છે અને હવે એ ઓરડાઓ શરૂ થઈ જશે. એટલે તાલુકાદીઠ જે ઘટ છે તે ટોટલ ૧૪૪૫ની ઘટ છે તે વઢવાણ, લીંબડી, ચૂડા, સાયલા, મૂળી, ચોટીલા, હળવદ, ધ્રાંગધ્રા, લખતર અને પાટડી, એમાં આ વર્ષે લગભગ ૩૦૦ થી ૩૨૫ ઓરડાઓ ફાળવવામાં આવેલ છે અને કામ ચાલુ છે અને નવા વર્ષના બજેટમાં ૨૦૦૫-૨૦૦૬માં ૭૮૨૯ ઓરડાઓ બજેટમાં મૂકવામાં આવેલ છે અને ૩૩૭ ઓરડાઓ બનાવવામાં આવશે, આવતા વર્ષે ૫૦૦૬બંધાશે.

શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્યમાં ૮૦ હજાર કરતાં વધારે શિક્ષકોની ભરતી રાજય સરકારે કરી એમાં સુરેન્દ્રનગરમાં કુલ કેટલા શિક્ષકોની ભરતી થઈ અને એમાંથી છેલ્લા ૩ વર્ષમાં કેટલા વિદ્યા સહાયકોને પૂર્ણ પગારમાં લેવામાં આવ્યા છે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયમાં અત્યાર સુધીમાં ૮૦ હજાર જેટલા વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરી છે, એમાં પ્રથમ તબક્કામાં ૨૮૭ વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરી છે, બીજા તબક્કામાં ૭૭૦ની ભરતી કરી છે, ત્રીજા તબક્કામાં ૨૮૯ની ભરતી કરી છે, ચોથા તબક્કામાં ૪૮૬ની ભરતી કરી છે, પાંચમાં તબક્કામાં ૧૬૯ની કરી છે અને છઠ્ઠા તબક્કામાં ૧૯૧ની ભરતી કરી છે અને છેલ્લા તબક્કામાં ૮૯૨ની ભરતી કરી છે. એમ કુલ ૩૦૮૪ વિદ્યા સહાયકોની ભરતી કરી છે અને પુરા પગારમાં ૧૦૫૭ શિક્ષકોને આવરી લેવામાં આવેલ છે અને જેમ જેમ પાંચ વર્ષ પૂરાં થતાં જશે એમ તમામ વિદ્યાસહાયકોને પૂરા પગારમાં લેવામાં આવશે.

શ્રી મનહરલાલ મ. મકવાણા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૮૯૨ શિક્ષકોની છેલ્લે ભરતી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કરી ત્યારે ખરેખર ટકાવારીના ધોરણે કરવામાં આવી હતી કે તેની જગ્યાઓ બતાવી અને ત્યારબાદ કરવામાં આવી હતી? નંબર બે કે અત્યારે ૧૪૪૫ ઓરડાઓ બાંધવાના બાકી છે તો તેના માટે શું વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે? શિયાળા અને ચોમાસા જેવો પિરિયડ ગયો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ માટે શું વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી છે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ (મંત્રીશ્રી) : અત્યારે જેટલા શિક્ષકો છે એટલા ઓરડાઓ તો ઉપલબ્ધ છે જ, પરંતુ જેમ જેમ શિક્ષકોની વધારે ભરતી થતી જાય છે, બાળકોની સંખ્યા વધતી જાય છે અને સીમ શાળાઓ શરૂ થતી જાય છે અને પ્રવેશોત્સવના કારણે સંખ્યા વધતી જાય છે એટલા માટે આ વધારાના ઓરડાઓ બાંધવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે.

શ્રી મનહરલાલ મ. મકવાણા : આ ઓરડાઓની ઘટ તો પહેલેથી છે જ.

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : નવા નવા બાળકો દાખલ થતા જાય અને શિક્ષકો આવતા જાય. એક શિક્ષકને એક વર્ગ ખંડ એટલે એક વર્ગ મળવો જોઈએ. આના આધારે વર્ગો બનાવવાની વાત છે.

શ્રી મનહરલાલ મ. મકવાણા : આ સૂચિત ઘટ છે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : આવતા દિવસોમાં આટલી ઘટ થશે એમ કરીને કરતા જઈએ છીએ. આપણે શાળાઓમાં અપગ્રેડેશન કરતા ગયા. જ્યાં ત્રણ ધોરણની શાળા હોય ત્યાં ચોથું ધોરણ આપવાનું હોય, એટલે આખા રાજયમાં ચોથું ધોરણ કયાં થશે એની ગણતરી કરતા જઈએ છીએ. પાંચમું ધોરણ આવતા વરસે શરૂ થવાનું હોય એને એક વર્ગ જોઈએ એટલે આપણે આ પ્રગતિ કરતા રહીએ છીએ. છેલ્લા તબક્કામાં ૮૯૨ શિક્ષકોની ભરતી કરી છે, એમાં જે રિઝર્વેશન છે એ પ્રમાણે ભરતી કરવામાં આવી છે.

શ્રી જયંતિલાલ રા. કવાડિયા : શિક્ષકોનું જે પત્રક છે, એ મુજબ તો એક શાળામાં પહેલા આટલી ઘટ રહેતી હતી એના બદલે હવે એક તાલુકામાં એટલી ઘટ થઈ ગઈ છે એ બદલ હું માનનીય શિક્ષણમંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું. મારો પ્રશ્ન એ છે કે ઓરડાઓની ઘટ કુલ ૧૪૪૫ બતાવી એમાંથી ૩૩૭ ઓરડા બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. પણ ચાર તાલુકામાં બહુ ઘટ ઓછી છે અને અન્ય છ તાલુકામાં દ

ાટ વધારે છે. તો આ દરેક તાલુકામાં ઘટનું ધોરણ સરખું રહે એના માટે જે તાલુકામાં વધારે ઘટ છે ત્યાં વધારે ઓરડાનું આયોજન કરીને લક્ષ્યાંક પૂરો કરવા માગે છે કે કેમ?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : છ તાલુકા એવા છે કે જેમાં શાળાના ઓરડાની ઘટ પ્રમાણમાં વધારે છે. ૩૩૭ ઓરડા બનાવવાના છે એના માટે ગ્રાન્ટ રાજય સરકાર જિલ્લા પંચાયતને ફાળવી આપે છે પછી જે તે શિક્ષણ સમિતિએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જ્યાં વધારે ઘટ લાગતી હોય એને પહેલા સપ્રમાણ ફાળવી આપવા જોઈએ.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર જ્યાં ઓરડાની ઘટ છે તો એને ઓરડા ફાળવી દેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ એક વાત મારા ધ્યાને આવી છે કે સિન્ટેક્ષના ઓરડા ખૂબ હલકી પ્રકારના હલકી ગુણવત્તાવાળા બનાવવામાં આવે છે. આ સિન્ટેક્ષના ઓરડાનું આયુષ્ય દોઢથી બે વરસ જેટલું પણ નથી. આ મેં મારી નજરે જોયેલું છે અને એનો પુરાવો પણ છે. તેથી આ સિન્ટેક્ષના ઓરડા સીમ શાળાઓમાં અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફાળવવામાં આવે છે એના બદલે ડી.પી.એ.પી. અથવા તો પાકા બાંધકામવાળા ઓરડા ફાળવવા માગે છે કે કેમ? **શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ** : સિન્ટેક્ષના ઓરડાની આજસુધી કોઈ ફરિયાદ આવી નથી. ડી.પી.એ.પી. ની ગ્રાન્ટ છે એ પ્રમાણે એ ઓરડા પણ થાય છે. રાજયસરકારની ગ્રાન્ટ છે એમાં ઝડપથી ઓરડા થાય, સમય મર્યાદાની અંદર થાય એટલા માટે આ બનાવીએ છીએ.

નાણાપંચ દ્વારા રાજય સરકારને ફાળવેલ રકમ

***૮૯૪૮શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી (ડીસા)**: માનનીય નાણામંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) કેન્દ્ર સરકારના નાણા પંચે રાજય માટે સને ૨૦૦૨-૨૦૦૩, ૨૦૦૩-૨૦૦૪, અને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના વર્ષમાં રાજય સરકારને ખરેખર કેટલી રકમ ફાળવવાની નક્કી કરેલ, અને
(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટ-કેટલી રકમ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં ક્યારે મળી?

માનનીય નાણામંત્રીશ્રી:
(૧).કેન્દ્ર સરકારે નીમેલ નાણા પંચ કેન્દ્ર સરકારને તમામ રાજયોને કેટલી રકમ આપવી તેની ફોર્મ્યુલા નક્કી કરે છે.
(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : પ્રશ્ન છાપ્યો છે એમાં જણાવેલ છે કે ફોર્મ્યુલા નક્કી નથી. મેં મંત્રીશ્રી પાસે વિગતો માગી હતી કે ૨૦૦૨-૦૩, ૨૦૦૩-૦૪, ૨૦૦૪-૦૫માં ખરેખર કેટલી રકમ મળી, તે અન્વયે ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલી રકમ મળી એનો જવાબ માનનીય મંત્રીશ્રીએ ઉડાડી દીધો છે. ફોર્મ્યુલા નક્કી કરે છે. મેં ફોર્મ્યુલા નથી માગી.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ગોવાભાઈ, તમે પ્રશ્ન પૂછયો છે કે કેટલી રકમ ફાળવવાનું નક્કી કરેલ છે.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : મેં સ્પષ્ટ પૂછયું છે કે તે અન્વયે વર્ષવાર કેટ-કેટલી રકમ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં ક્યારે મળી એવું મેં સ્પષ્ટ પૂછયું છે.

શ્રી વજુભાઈ વાળા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પહેલા પ્રશ્નમાં એમ લખ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારના નાણા પંચે રાજય માટે સને ૨૦૦૨-૦૩, ૨૦૦૩-૦૪, અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં રાજય સરકારને ખરેખર કેટલી રકમ ફાળવવાની નક્કી કરેલ. અને તે પછી પૂછયું છે કે તે અન્વયે વર્ષવાર કેટ-કેટલી રકમ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં કયારે મળી?

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, છતાં એ રીતે જવાબ આપું પણ પ્રશ્નનો જવાબ મેં બરાબર આપ્યો છે કે પંચ છે એ આને આટલી રકમ આપવી એ રકમ નક્કી નથી કરતું, પંચ છે એ કેન્દ્ર સરકારને ભલામણ કરે અને ફોર્મ્યુલા આપે કે આખા રાજયની, જે કેન્દ્ર સરકારની તમામ આવક થતી હોય તેમાંથી આપણને હિસ્સો ન આપે. કેન્દ્ર સરકારમાં ઈનકમટેક્સની આવક આવે, એકસાઈઝની આવક આવે, એડિશનલ એકસાઈઝની આવક આવે અને કસ્ટમ ડયૂટીની આવક આવે. એ ચારમાંથી કેન્દ્ર સરકાર ૧૦૦ રૂપિયા મેળવે તો ૨૯.૫ રૂપિયા એટલે ૨૯.૫ ટકા હિંદુસ્તાનના તમામ રાજયો છે એ તમામ રાજયોની વચ્ચે આપે. આ ૨૯.૫ છે એ પણ તમામ રાજયોને વસતિ પ્રમાણે નથી વહેંચતા, તેની પણ ફોર્મ્યુલા નક્કી કરે છે. તેમાં ચાર ભાગ પાડે. તેમાં પહેલી જે વાત કરે તો તેમાં વેઈટેજ આપે, જુદા જુદાને. દરેક રાજયની વસતિ કેટલી છે તો વસતિનું પ્રમાણ ૧૦ ટકા ગણવું. પછી ડિસ્ટન્સ એટલે દરેક રાજયની માથાદીઠ આવક કેટલી છે, જેટલી જેની આવક ઓછી હોય તેમાં તેને સરકાર ફાળવણી વધુ કરે. તેને વેઈટેજ આપે. ૬૨.૫ ટકાનું. પછી તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે, એ ક્ષેત્રફળને ૭.૫ ટકાનું વેઈટેજ આપે. પછી આંતર માળખાકીય સુવિધા. એ રાજયમાં ઈન્ટરનલ શું સુવિધા છે તો

એના પરથી આપે તો ૭.૫ ટકા. આ રીતે ફોર્મ્યુલા નક્કી કરે અને ફોર્મ્યુલામાંથી કેન્દ્ર સરકારને જે કોઈ આવક આવે તેના પર્સન્ટેજ આપે. પણ આપ જે કહો છો કે કેન્દ્ર સરકારને આટલી આવક આપવી એવું નક્કી ન કરે. એટલા માટે કે એને પણ ખબર ન હોય કે કસ્ટમની આવક કેટલી આવે. જે ખરેખર આવે તેમાંથી આપે. ૨૦૦૨-૨૦૦૩માં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રાજયને મળ્યા છે એ ૧૬૨૯.૪૪ કરોડ મળ્યા છે. ૨૦૦૩-૨૦૦૪માં ૨૧૫૨.૭૬ કરોડ મળ્યા અને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ એટલે કે અત્યારે ડિસેમ્બર સુધીમાં બાકીના પૈસા આવવાના બાકી છે. ૧૬૮૦.૦૨ પૈસા મળ્યા. આ ત્રણ વર્ષમાં આટલી રકમ મળી છે. (અંતરાય) રકમ બધી વપરાઈ જ જાય છે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : વપરાઈ કેટલી?

શ્રી વજુભાઈ વાળા : આ તો કલેકટીવ આપણી પોતાની આવક, કેન્દ્રમાંથી આવેલી આવક એ બધાનું કોન્સોલિડેટેડ ફંડ થાય અને બધા માટે થઈને એ વાપરવામાં આવે. એક પણ રૂપિયો એવો નથી કે વપરાયા વગર બાકી હોય. એ કોઈ ઈયરમાર્ક કરીને નથી આપતા કે આ પૈસા આમાં વાપરવા. જે ઈયરમાર્ક કરીને આપે એ એમાં વપરાય અને ઈયરમાર્ક કરીને ન આપે એ કોમન ફંડમાં વપરાય.

કચ્છ જિલ્લામાં પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની ઘટ

***૯૪૧૭ શ્રી છબીલદાસ ના. પટેલ (માંડવી):** માનનીય શિક્ષણમંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧).તા. ૩૧-૧-૦૫ની સ્થિતિએ રાજયમાં જિલ્લાવાઈઝ કેટલી પ્રાથમિક શાળાઓ શિક્ષકોના અભાવે બંધ છે,

(૨).તે પૈકી કચ્છ જિલ્લામાં તાલુકાવાર આવી શાળાઓ કેટલી છે અને

(૩).આ માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા શું શું ગોઠવવામાં આવી છે?

શિક્ષણમંત્રીશ્રી:

(૧).રાજયમાં કોઈ પણ જિલ્લામાં એક પણ પ્રાથમિક શાળા શિક્ષકોના અભાવે બંધ નથી.

(૨). પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩). પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી છબીલદાસ ના. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ 'દીકરી રુડી સાચી મૂડી' ની *(પોકળ) વાતો થઈ રહી છે કારણ કે મારા મતવિસ્તારમાં એવી કેટલીય સ્કૂલો છે કે જ્યાં શિક્ષક નથી પણ..

શ્રી અશોક ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી,**(પોકળ) શબ્દ અસંસદીય છે તે પાછો ખેંચવો જોઈએ.

અધ્યક્ષશ્રી : **(પોકળ) શબ્દ અસંસદીય છે આપ પાછો ખેંચી લો.

શ્રી છબીલદાસ ના. પટેલ : મારો શબ્દ પાછો ખેંચું છું. મારા મતવિસ્તારમાં પઈવાડી, ગોધરાવાડી, મેરઉવાડી વિસ્તારની જે સ્કૂલો છે તેમાં એક પણ શિક્ષક નથી. બહારથી એક-બે દિવસ માટે બીજી સ્કૂલમાંથી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરીને આપવામાં આવે છે અને એક-બે દિવસ સ્કૂલ ચાલે અને બાકીના દિવસો બંધ રહે છે. મારું કહેવાનું એ છે કે બંધ ભલે નથી, સ્કૂલ ચાલુ છે. પણ શિક્ષક વગરની સ્કૂલ ચાલુ છે. એટલે ગૃહને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવે છે. તો આ શિક્ષકોની ભરતી ક્યારે કરવામાં આવશે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કચ્છ જિલ્લામાં આ છેલ્લા તબક્કામાં ૧૬૨૮ વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરી છે અને એમાં કચ્છ જિલ્લામાં ૧૯ શાળાઓ સીમ શાળાઓ છે. આ શાળાઓની શરૂઆત ૨૦૦૫ના થોડા સમય પહેલાં જ કરી છે. એટલે કે કેટલીક શાળાઓ પહેલા મહિનામાં એટલે કે જાન્યુઆરી ૦૫ અને કેટલીક ફેબ્રુઆરી ૦૫ અને કેટલીક શાળાઓ ડિસેમ્બર ૦૪માં શરૂ થઈ છે. અને એવી ૧૯ શાળાઓમાં ભરતી થઈ શકી નથી. આ શાળાઓ શરૂ થઈ એ પહેલાં ભરતી થઈ ગયેલ હોવાથી એ શાળાઓના શિક્ષકોની ભરતી થઈ શકી નથી. એ ભરતી હવે પછી નવી ભરતી કરીશું એની અંદર થશે. આ જે ૧૯ શાળાઓ છે એની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. એમના શિક્ષકોના નામ પણ છે જેને જવાબદારી સોંપવામાં આવેલી છે. પે સેન્ટરના નામ પણ છે અને આપણે બાળકોની સંખ્યા પ્રમાણે શિક્ષકોની નિયુક્તિ પણ કરી છે.

* ( ) આ અસંસદીય શબ્દ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો.

જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ વગરની શાળાઓ

***૮૨૧૭ શ્રીમતી જસુબેન સ. કોરાટ (જેતપુર): માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

૧) જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકાની કઈ કઈ પ્રાથમિક શાળામાં બ્લેક બોર્ડ, પાણી, વીજળી, મુતરડી જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ નથી,

૨) તેના શાં કારણો છે, અને

૩) સરકારે આ સુવિધા પૂરી પાડવા શી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે ?

શિક્ષણ મંત્રીશ્રી :-

(૧).શાળાઓના નામની યાદીનું પત્રક-૧ સામેલ છે.

(૨).આ અંગેની જોગવાઈ આયોજન હેઠળ કરવામાં આવતી હોઈ બજેટ જોગવાઈની મર્યાદાઓને કારણે તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂર્ણ કરી શકાયેલ નથી.

(૩).પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ વિકસાવવા સારુ આયોજન યોજના હેઠળ રાજ્ય કક્ષાએ થતા આયોજન અનુસાર તબક્કાવાર શાળાઓને આવરી લેવામાં આવે છે.

પત્રક-૧

જેતપુર અને ગોંડલ તાલુકાઓની પીવાના પાણીની સુવિધા વગરની શાળાઓ

અનુ. ક્રમ	તાલુકો	પેટાક્રમ	શાળાનું નામ
૧	જેતપુર	૧	દેવકી ગાલોલ કન્યા પ્રાથમિક શાળા
૨	ગોંડલ	૧	ખાખીવાડા પ્રાથમિક શાળા
		૨	વોરાકોટડા પ્રાથમિક શાળા
		૩	શ્રીનાથગઢ પ્રાથમિક શાળા
		૪	કમઢીયા પ્રાથમિક શાળા
		૫	સાજડીયાળી પ્રાથમિક શાળા
		૬	ધરાવા પ્રાથમિક શાળા
		૭	પાટખોલોરી પ્રાથમિક શાળા
		૮	ઉધાટીંબી પ્રાથમિક શાળા
		૯	ધુડશીયા પ્રાથમિક શાળા
		૧૦	મોટા સખપુર પ્રાથમિક શાળા
		૧૧	ધોધવદર પ્રાથમિક શાળા
		૧૨	રૂપાવટી પ્રાથમિક શાળા
		૧૩	ખાંડાધાર કુમાર પ્રાથમિક શાળા
		૧૪	ખાંડાધાર કન્યા પ્રાથમિક શાળા
		૧૫	વાછરા પ્રાથમિક શાળા
		૧૬	આંબરડી પ્રાથમિક શાળા
		૧૭	હરમતીયા પ્રાથમિક શાળા
		૧૮	બેટાવડ પ્રાથમિક શાળા
		૧૯	વાવડી પ્રાથમિક શાળા
		૨૦	સીમ શાળા કોલીથડ પ્રાથમિક શાળા
		૨૧	મોટા દડવા પ્રાથમિક શાળા
		૨૨	કરમાળ પ્રાથમિક શાળા
		૨૩	ડેમ સીમ પ્રાથમિક શાળા-૧
		૨૪	ડેમ સીમ પ્રાથમિક શાળા-૨
		૨૫	ગોવિંદપર પ્રાથમિક શાળા
		૨૬	સોનારીયા પ્રાથમિક શાળા
		૨૭	ભોજનપરા પ્રાથમિક શાળા

		૨૮	સિંધાવદર પ્રાથમિક શાળા
		૨૯	રીબડા પ્રાથમિક શાળા
		૩૦	રજ્_ળા પ્રાથમિક શાળા
		૩૧	મોંઘીબા કન્યા તા. શાળા
		૩૨	ગોંડલ શાળા નં. -૧
		૩૩	ગોંડલ શાળા નં. -૪
		૩૪	ગોંડલ શાળા નં. -૫
		૩૫	ગોંડલ શાળા નં. -૫-અ
		૩૬	ગોંડલ શાળા નં. -૭
		૩૭	ગોંડલ શાળા નં. -૧૫
		૩૮	ગોંડલ શાળા નં. -૧૬
		૩૯	ગોંડલ શાળા નં. -૮
		૪૦	ગોંડલ શાળા નં. -૨
		૪૧	ગોંડલ શાળા નં. -૬
		૪૨	ગોંડલ શાળા નં. -૧૧
		૪૩	ગોંડલ શાળા નં. -૧૨
		૪૪	ગોંડલ શાળા નં. -૧૪

બ. જેતપુર અને ગોંડલ તાલુકાઓની વીજળીની સુવિધા વગરની શાળાઓ

ક્રમ	તાલુકો	પેટાક્રમ	શાળાનું નામ
૧	ગોંડલ	૧	ઉધાટીંબી પ્રાથમિક શાળા
		૨	ખંભાળીડા પ્રાથમિક શાળા
		૩	વાવડી પ્રાથમિક શાળા
		૪	પડવલા પ્રાથમિક શાળા
		૫	ગુંદાસરા પ્રાથમિક શાળા
		૬	મોંધીબા કન્યા તા. શાળા
		૭	ગોંડલ શાળા નં. -૪
		૮	ગોંડલ શાળા નં. -૭
		૯	ગોંડલ શાળા નં. -૧૫
		૧૦	ગોંડલ શાળા નં. -૨
		૧૧	ગોંડલ શાળા નં. -૬
		૧૨	ગોંડલ શાળા નં. -૧૨
		૧૩	ગોંડલ શાળા નં. -૧૪
૨	જેતપુર		માહિતી શુન્ય છે.

ક. જેતપુર અને ગોંડલ તાલુકાઓની મૂતરડીની સુવિધા વગરની શાળાઓ

ક્રમ	તાલુકો	પેટાક્રમ	શાળાનું નામ
૧	ગોંડલ	૧	વોરાકોટડા પ્રાથમિક શાળા
		૨	ઉધાટીંબી પ્રાથમિક શાળા
		૩	વાછરા પ્રાથમિક શાળા
		૪	વાવડી વીડો પ્રાથમિક શાળા
		૫	ચોરડી પ્રાથમિક શાળા
		૬	સોનારીયા પ્રાથમિક શાળા
		૭	રીબડા પ્રાથિમક શાળા
		૮	મોંધીબા કન્યા તા. શાળા
		૯	ગોંડલ શાળા નં. -૪
		૧૦	ગોંડલ શાળા નં. -૨

		૧૧	ગોંડલ શાળા નં. -૧૪
૨	જેતપુર	૧	મેવાસા પ્રાથિમક શાળા

શ્રીમતી જસુબેન સ. કોરાટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. એમાં મારે મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવું છે કે જેતપુર તાલુકાના અને ગોંડલ તાલુકાની ૪૪ શાળાઓમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા નથી એ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા ક્યારે કરવા માગો છો? અને બીજો પ્રશ્ન વીજળીની સુવિધા નથી. ૧૪ ગામોની અંદર વીજળીની સુવિધા નથી તો વીજળીની સુવિધા ક્યારે ઉપલબ્ધ કરાવવા માગો છો? અને ત્રીજો પ્રશ્ન એ છે કે ૧૨ ગામોની અંદર શાળાઓની અંદર મુતરડીની વ્યવસ્થા નથી તો એ ક્યારે ઉપલબ્ધ કરાવવા માગો છો?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જેતપુર તાલુકાની એક શાળા એવી છે કે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા અને ટોઈલેટ નથી. ગોંડલ તાલુકામાં ૧૨૧ શાળાઓ છે એમાંથી પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા ન હોય એવી ૪૪, વીજળીકરણ ન હોય એવી ૧૩ અને ટોઈલેટ ન હોય તેવી માત્ર અગિયાર છે. આ વર્ષના બજેટમાં રાજકોટ જિલ્લાની ૧૨૧ શાળાઓને આવરી લેવામાં આવી છે અને એટલે જેતપુર અને ગોંડલની બધીજ શાળાઓમાં આ પ્રકારની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થઈ જશે.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જેતપુર અને ગોંડલ તાલુકાની ૪૪ શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સુવિધા નથી. હું આપના મારફત એ જાણવા માગું છું કે, રાજય સરકાર ઘણી બધી મોટી મોટી વાતો કરે છે. મધ્યાહન ભોજન યોજના અંગે મને યાદ છે કે જ્યારે ગામડાઓમાં જઈએ છીએ ત્યારે જે શાળાઓમાં બાળકોને બપોરનું ભોજન આપવામાં આવે છે એ શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સુવિધા હોતી નથી તે બાળકો પોતાના હાથ અને વાસણ સાફ કર્યા વગર એંઠા વાસણ લઈને બજારમાંથી જતા હોય છે. રાજય સરકાર આવી વાતો કરતી હોય તો રાજકોટ જિલ્લાની આવી તમામ શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સુવિધા ઉભી કરવા માગે છે કે કેમ? અને કયાં સુધીમાં?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પોકળ વાતો નથી, થોકબંધ કાર્યો થયેલાં છે. તમારા વખતમાં એકપણ ટોઈલેટ કયાં હતું? પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કયાં હતી? આ સરકાર આવ્યા પછી પીવાના પાણીની કાયમી વ્યવસ્થા હાથ ધરી છે. અત્યારે પાણીની ટાંકીઓ તો ઉપલબ્ધ છે જ. પણ રાજય સરકાર કાયમી વ્યવસ્થા કરવા માગે છે. ૧૨૧ શાળાઓની અંદર આ સુવિધા પૂર્ણ કરવા માગીએ છીએ. આ વર્ષોથી પેન્ડીંગ પ્રશ્નો હતા એ અમે ઉકેલી રહ્યા છીએ.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે મંત્રીશ્રી પાસેથી એટલું જાણવું છે કે, કાળા પાટિયા એટલે કે બ્લૅક બોર્ડ વગરની આ ૪૫ પૈકી કેટલી શાળાઓ છે? અને જ્યાં આ બ્લૅક બોર્ડ નથી ત્યાં શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ કઈ રીતે અપનાવી છે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કોઈપણ પ્રાથમિક શાળા બ્લૅક બોર્ડ વગર ચાલી શકે નહીં. સો ટકા શાળાઓની અંદર બ્લૅક બોર્ડ છે. એકે એક શાળાઓની અંદર બ્લૅકબોર્ડ છે. એટલા જ માટે જે નવા મકાનો બંધાઈ રહ્યા છે એમાં બે બે બ્લૅક બોર્ડ આપ્યા છે. જે નવા ઓરડા છે એની અંદર બે બે બ્લૅક બોર્ડ છે. એક સામે છે અને એક પાછળના ભાગની અંદર છે એટલે બે-બે બ્લૅક બોર્ડ છે એટલે પરેશભાઈ આપણે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.

રાજયમાં ઉર્દૂ શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ

***૮૩૬૮ શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા (જમાલપુર)**: માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

(૧) રાજયમાં ઉર્દૂ શિક્ષણ કેટલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં આપવામાં આવે છે,
(૨) કેટલા ઉર્દૂ શિક્ષકોની જગ્યાઓ મંજૂર થયેલી છે,
(૩) તે પૈકીની કેટલી જગ્યાઓ ડીસે. ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ભરાયેલ છે અને કેટલી ખાલી છે?
(૪) ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનું સરાકારનું શું આયોજન છે?

શિક્ષણ મંત્રીશ્રી :-

(૧) ૧૫૨
(૨) ૧૨૬૪
(૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ-૧૧૬૫
(૪) જેમ બને તેમ જલદી ભરવામાં આવશે.

શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા(જમાલપુર): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગયા બજેટમાં મારા આ જ પ્રશ્નના જવાબમાં શિક્ષકોની એ જગ્યા ભરવા માટે જેમ બને તેમ જલદીથી શિક્ષકોની જગ્યા ભરાઈ જશે એમ જવાબ આપ્યો હતો પરંતુ એક વર્ષનો સમયગાળો વિતવા છતાં આ જગ્યા ભરાઈ નથી અને ૯૯ જગ્યાઓ હજી ભરવાની બાકી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : આપ શું કહેવા માગો છો?

શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા(જમાલપુર) : આ ખાલી જગ્યા ૯૯ ભરવાની બાકી છે એ ક્યારે ભરાઈ જશે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમદાવાદ શહેર, સુરત, ગોધરા અને ભાવનગર આ ચાર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર આપણે છેલ્લા તબક્કાની અંદર સુરતમાં ૧૬૨ વિદ્યા સહાયકોની ભરતી માટે ઇજાજત આપી. ગોધરામાં ૨૭, અમદાવાદમાં ૧૯૨ એ પ્રમાણે એમણે ભરતી કરવાની હતી. હવે જિલ્લા પંચાયતો અને નગર શિક્ષણ સમિતિએ નિર્ણય કરવો જોઈએ કે અમારે ત્યાં કયા પ્રકારના માધ્યમના શિક્ષકોની જરૂરિયાત છે અને એ પ્રમાણે એમણે ત્યાં જાહેરાતો આપવી જોઈએ. પરંતુ અમદાવાદ શહેરે એ પ્રકારની જાહેરાતો ન આપી અને ૪૭ શિક્ષકોની ભરતી કરી અને ૧૧ શિક્ષકોની ભરતી નથી કરી શક્યા કારણ કે એમણે જાહેરાતો એ પ્રમાણે ન આપી કે ઉર્દૂમાં અમારે આટલા ભરવાના છે અને એટલા માટે ખાલી જગ્યા રહી એટલે જવાબદારી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હતી કે એ પ્રમાણે જાહેરાત આપવી જોઈએ અને એ પ્રમાણે જ શિક્ષકોની ભરતીની અરજીઓ માગવી જોઈએ. બીજું ગોધરામાં જે શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવી એમાં ૧૪ શિક્ષકોની ભરતી કરવાની હતી. ઉર્દૂ માધ્યમની અંદર પણ એસ.સી. અને એસ.ટી.નો રેશીયો જાળવવાનો હોય છે અને એટલે ૧૪ જગ્યાઓ જ્યારે ભરવા ગયા ત્યારે વાલ્મિકી સમાજના ૨ વિદ્યા સહાયકો એના ઉપર સ્ટે લઈ આવ્યા અને એના કારણે અત્યારે હાઈકોર્ટમાં સ્ટે હોવાના કારણે ગોધરાની અંદર આપણે ભરતી કરી શકયા નથી. સુરત અને અમદાવાદની અંદર આપણે આ જ પરિસ્થિતિ પેદા થઈ અને એના કારણે અ આ ભરતી કરી નથી શકયા અને એટલા માટે હવે પછી જ્યારે ભરતી કરવા માટે રાજય સરકાર એમની જે સંખ્યા આપે એની અંદર એ પોતે નક્કી કરી લે કે અમારે કેટલા ઉર્દૂના, કેટલા મરાઠીના, કેટલા બીજા માધ્યમના શિક્ષકો જોઈએ છે, એ પ્રમાણે જાહેરાત આપશે તો આ બધી જ જગ્યાઓ ભરાઈ જશે.

શ્રી પ્રવિણભાઈ છ. રાઠોડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે ૧૫૨ પ્રાથમિક શાળાઓ આપી છે એમાં જિલ્લા વાઈઝ કેટલી કેટલીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને આ ૧૫૨ જગ્યાઓ છે એમાં રાજય સરકારને કુલ કેટલો ખર્ચ થાય છ?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વિદ્યા સહાયકોને ૨૫૦૦ રૂપિયાનું માનદ્ વેતન આપીએ છીએ આપણે અને રાજયમાં છેલ્લા તબક્કાની અંદર ૧૪હજાર જેટલા વિદ્યા સહાયકોની ભરતી કરી છે આપણે.

મહિલા આયોગની રચના થયા બાદ મળેલ મિટિંગો

*** ૮૫૪૪ ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા(માંગરોળ)** : માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

(૧) રાજયમાં મહિલા આયોગની રચના ક્યારે કરવામાં આવી,
(૨) કેટલા સમયથી કાર્યાન્વિત થઈ છે,
(૩) રચના થયા પછી તા:૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી મિટિંગો થઈ, અને,
(૪) મિટિંગો ન થવાના કારણો શું છે?

મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી :-

(૧), (૨) , (૩) અને (૪) સરકારશ્રીએ તા: ૧૬-૨-૦૫ના રોજ ગુજરાત મહિલા આયોગની રચના કરતું જાહેરનામું બહાર પાડેલ છે.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મહિલા આયોગની રચના સમસ્ત દેશ અને સમસ્ત રાજયોમાં થઈ. આપણે મહિલા આયોગની રચના માટેનું બિલ અને સૈદ્ધાંતિક વહીવટની મંજૂરી આપી દીધી. મારો પ્રશ્ન પૂછયા પછી તા:૧૬-૦૨-૦૫ના રોજ જાહેર નામું બહાર પાડયું. તો મારે પૂછવું છે કે મહિલા આયોગની રચના અને બિલની મંજૂરી પછી અત્યાર સુધી એને કાર્યવંત કરવાનું વિલંબ કરવાના કારણો શું છે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હમણાં જ રાજય સરકારે એની નિયુકિત કરી દેવામાં આવી છે. નિમણૂક કરી દેવામાં આવી છે અને હવે મહિલા આયોગે કામગીરી શરૂ કરી છે.

ડૉ.ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રચનાને કાર્યવંત કરી, સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપ્યાને કેટલો સમય થયો એ સમય વચ્ચેનો વિલંબ, બિલ આવી ગયું, વિધેયક પાસ કરી દીધું, ધારાસભાએ મંજૂરી આપી, આપણે સૈદ્ધાંતિક સ્વીકાર કર્યો એ પછી મહિલા આયોગની રચના અત્યાર સુધી નહીં કરવાનું કારણ શું?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમાં કોઈ કારણ નથી. લગભગ દોઢેક વર્ષ થયું છે. મહિલા આયોગની રચના કરવામાં અને દોઢ વર્ષનો ગાળો છે અને હવે રાજય સરકારે કામ પૂરું કરી દીધું છે.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : આ મહિલા આયોગ માટે નીતિ બનાવી છે એમાં વિલંબ કરવાનું કારણ શું? શા માટે વિલંબ કરવામાં આવ્યો ?

શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે : મહિલા આયોગ છે એના અધ્યક્ષ કોણ છે? મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવું છે કે એના અધ્યક્ષ કોણ છે અને ક્યારે ઑર્ડર આપ્યો? ન નિમાયા હોય તો ક્યારે ભરતી કરવા માગો છો?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રીમતી શોભનાબેન પટેલ છે એમની નિયુકિત કરી દેવામાં આવી છે.

યાત્રાધામ વિકાસ માટે બ્લ્યુ પ્રિન્ટ

***૯૨૧૯ શ્રી પ્રવિણભાઈ મો. માકડિયા(ઉપલેટા)** : માનનીય યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

(૧).રાજયના તમામ યાત્રાધામોના વિકાસ માટે સરકારે કોઈ બ્લ્યુ પ્રિન્ટ બનાવેલ છે કે કેમ,

(૨).જો હા, તો કયા યાત્રાધામો માટે કઈ બ્લ્યુ પ્રિન્ટ બનાવવામાં આવેલ છે, અને

(૩).તે મુજબ કયા કયા કામો શરૂ થયાં છે?

યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી :

(૧).ના.

(૨).પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩).પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી પ્રવિણભાઈ મો. માકડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જવાબમાં જણાવ્યું છે પરંતુ માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે ગુજરાતના કેટલાય યાત્રાધામો ખૂબ ખંડેર હાલતમાં પડયાં છે. તો એના માટે સરકાર અલગ ફંડ ફાળવી અને એના માટે કોઈ પ્લાનીંગ કરવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી અશોક ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમનો પ્રશ્ન સમગ્ર ગુજરાતના યાત્રાધામો માટેનો છે. સમગ્ર ગુજરાતના બધા યાત્રાધામો છે એનો વહીવટ પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એકટ હેઠળ થાય છે. દરેક યાત્રાધામ પોતાનો એકશન પ્લાન તૈયાર કરે છે. એટલા માટે સરકારની જવાબદારી રહેતી નથી. એ યાત્રાધામના વિકાસ માટે સરકારે જે કાંઈ કરવાનું હોય છે એના માટે ચેરિટી કમિશનર સાથે રહીને વિકાસની જે અનુમતિઓ માગે છે એ અનુમતિઓ રાજય સરકાર આપે છે.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : માનનીય સભ્યશ્રીએ પહેલા પ્રશ્નમાં પૂછયું છે કે રાજયના તમામ યાત્રાધામોના વિકાસ માટે સરકારે કોઈ બ્લ્યુ પ્રિન્ટ બનાવેલ છે કે કેમ? હું એ જાણવા માગું છું કે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને આ વિભાગના માનનીય મંત્રીશ્રી જે યાત્રાધામના ટ્રસ્ટી તરીકે અને પ્રભારી મંત્રી તરીકે છે એ યાત્રાધામ માટે કોઈ બ્લ્યુ પ્રિન્ટ બનાવીને આગળની કાર્યવાહી કરવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી અશોક ભટ્ટ : કોઈ ટ્રસ્ટમાં હું ટ્રસ્ટી નથી અને મુખ્યમંત્રીશ્રી પણ ટ્રસ્ટી નથી.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : પ્રભારી મંત્રી તરીકે પણ એક યાત્રાધામમાં ટ્રસ્ટી છે.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : કયા યાત્રાધામમાં, આપ કહોને?

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : અંબાજી.

(આ તબક્કે માનનીયશ્રી અશોક ભટ્ટે નકારમાં માથું હલાવ્યું)

શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉનાઈમાં ઉના પાણી આવે છે અને દક્ષિણ ગુજરાતનું યાત્રાધામ છે એની અંદર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને માનનીય અશોકભાઈએ કહ્યું હતું કે આ ઉનાઈને આપણે વિકસાવીશું. આજની તારીખે એ ઉનાઈનું મંદિર પૂરું થયેલ નથી. ધંધાદારી શોપીંગો બની ગયા છે. આ મંદિરનો જેમને કોન્ટ્રાકટ આપવામાં આવેલ એ માણસ પાસે પૂરતા સાધનો નથી. ડિઝાઇન પ્રમાણે કાર્યવાહી નથી કરી તો એની સામે કોઈ પગલાં લેવા માગો છો કે કેમ? અને આ ક્યારે પૂરું કરવામાં આવશે?

શ્રી અશોક ભટ્ટ : અત્યાર સુધીમાં ઉનાઈમાં ૯૪ લાખનો ખર્ચ થયો છે. આવતા અઠવાડિયે હું મુલાકાત લેવાનો છું. જે કોન્ટ્રાકટરે કામ નથી કર્યું એની સામે પગલાં લઈ એનું કામ રદ કરી, એ નવા કોન્ટ્રાકટરને આપી કાર્યવાહી આગળ ધપાવવામાં આવશે.

રાજકોટ જિલ્લાના પેન્શનના બાકી પડતર કેસો

***૮૦૯૪ શ્રી મોહનભાઈ ક. કુંડારીયા(ટંકારા)** : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-
(૧).નિયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડની કચેરીમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા પેન્શન કેસો બાકી છે,
(૨).તે પૈકી રાજકોટ જિલ્લાના કેટલા છે, અને
(૩).કેસોનો ઝડપી નિકાલ લાવવા સરકારનું આયોજન શું છે?

નાણા મંત્રીશ્રી :
(૧).૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ૩૦૧ કેસ બાકી હતા.
(૨).૨૭ કેસ
(૩).પેન્શન કેસોની પ્રક્રિયાના સરળીકરણ કર્યા બાદ તેનું કોમ્પ્યુટરાઈઝ મોનીટરીંગ પણ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પેન્શન કેસોના સ્ટેટસ બાબતની માહિતી ઓનલાઈન વેબ સાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. જેથી પારદર્શકતા અને ઝડપ બંને શકય બનશે.

શ્રી મોહનભાઈ ક. કુંડારીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજકોટ જિલ્લાના જે ૨૭ કેસો ચૂકવણું કરવાના બાકી છે એ ૨૭ કેસોનું ચૂકવણું કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને એ લોકોને વહેલામાં વહેલી તકે પૈસા મળે એ માટે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે?

શ્રી વજુભાઈ વાળા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે આ ૨૭ કેસો પેન્ડિગ હતા એ ૩૧/૧૨ ની સ્થિતિએ હતા એ તમામ કેસો મંજૂર કરી દીધા છે, એટલું જ નહિ પરંતુ ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ ની સ્થિતિએ આખા રાજ્યમાં પણ જે ૩૦૧ કેસો બાકી હતાને એ પણ તમામ મંજૂર થઈ ગયા છે, ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ ની સ્થિતિએ કોઈ કેસ બાકી નથી.

અમદાવાદ શહેરના વિસ્તારની આંગણવાડીઓ

***૮૬૯૩ શ્રી અંબાલાલ આ. રોહિત(સોજીત્રા)** : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -
(૧) અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોરપોરેશન વિસ્તારમાં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી આંગણવાડીઓ છે, અને
(૨) જે વિસ્તારોમાં આંગણવાડીઓ નથી તે માટે સરકાર શું પગલાં લેવા ધારે છે?

મહિલા અને બાળ વિકાસમંત્રીશ્રી :
(૧).ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કુલ-૧૧૫૬ આંગણવાડીઓ છે જે પૈકી ૭૮૧ આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે.
(૨).જે વિસ્તારમાં આંગણવાડીઓ નથી તેવા વિસ્તારોમાં આંગણવાડી સેવા પૂરી પાડવા સરકાર પ્રયત્નશીલ છે.

શ્રી અંબાલાલ આ. રોહિત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગુ છું કે, અમદાવાદ જિલ્લામાં ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી આંગણવાડીઓ છે અને જે વિસ્તારમાં આંગણવાડીઓ નથી ત્યાં સરકાર શું કરવા માગે છે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમદાવાદ શહેરમાં ૧૧૫૬ આંગણવાડીઓ મંજૂર કરવા માટેની મંજૂરી આપણને મળેલી ૧૯૮૮, ૧૯૯૬ ત્યારપછી ૧૯૯૮ આ બધા સમયમાં મળેલી. હવે આંગણવાડી શરૂ કરવાનું કામ સર, મ્યુનિસિપલ કોરપોરેશનનું હોય છે અને મ્યુનિસિપલ કોરપોરેશન અમદાવાદની એ આંગણવાડી ચલાવવા નથી માગતી એટલા માટે રાજ્ય સરકારે એન.જી.ઓ.ની પાસે આ આંગણવાડીઓ શરૂ કરાવવી પડી છે. હવે જ્યારે મેં મિટિંગ બોલાવી એક વર્ષ ઉપર કે મ્યુનિસિપલ કોરપોરેશનની જવાબદારી છે આંગણવાડી ચલાવવાની, અને એ જો ચલાવવા ના માગતી હોય તો એના કારણો શું છે? એમણે મને એટલું કહ્યું કે, આઠ વર્ષ પહેલા અગાઉ કોઈ સ્કીમ ચાલતી હશે ભારત સરકારની અને એ સ્કીમ જ્યારે પૂરી થઈ ગઈ એટલે એના જે કર્મચારીઓ હતા એ કોર્ટમાં ગયા અને એ કોર્ટમેટર બની એટલે

કોરપોરેશને પોતે ઠરાવ કરી દીધો કે હવે અમે કોઈ ભારત સરકારની આવી કોઈ યોજના હશે તો લેવા માગતા નથી, એટલા માટે સર, જવાબદારી રાજ્ય સરકારની બની. એટલા માટે હાલ ૧૧૫૬ આંગણવાડીઓમાંથી ૭૯૯ આંગણવાડીઓ અમે શરૂ કરી દીધી છે અને અત્યારે હાલ ચાલુ છે, ૧૫૮ આંગણવાડીઓ હમણાં મંજૂર કરી છે એટલે હવે ૧૯૯ આંગણવાડીઓ બાકી છે એ પણ અમારો પ્રયાસ રહેશે કે આવતા ત્રણેક મહિનામાં ૧૯૯ આંગણવાડીઓ કોઈને કોઈ માધ્યમ દ્વારા ચાલુ થાય.

રમત ગમત ક્ષેત્રે મહિલાઓની સિદ્ધિઓ

***૯૪૪૨ શ્રી પુનમ ર. પરમાર (પાદરા)** : માનનીય રમત ગમત મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) મહિલાઓ રમતગમત ક્ષેત્રે સક્રિય રીતે ભાગ લે તે માટે કોઈ યોજના છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો તેની વિગતો શું છે, અને

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રમતગમત ક્ષેત્રે કેટલી મહિલાઓએ સિદ્ધિઓ મેળવી?

રાજ્ય કક્ષાના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓના મંત્રીશ્રી :

(૧) હા, જી.

(૨) રાજ્ય અને રાષ્ટ્રકક્ષાએ મહિલા માટે પ્રતિવર્ષ ૨૧ રમતોનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રકક્ષાએ ભાગ લેનાર તથા રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાં વિજેતા/ઉપવિજેતા મહિલા ખેલાડીઓને સ્કૉલરશિપ આપવાની યોજના અમલમાં છે.

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ૧૩૫ મહિલાઓએ અને રાજ્યકક્ષાએ ૩૩૯૦ મહિલાઓએ મળીને કુલ : ૩૫૨૫ મહિલાઓએ સિદ્ધિઓ મેળવી.

શ્રી પુનમ ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી હું જાણવા માગુ છું કે, ૨૧ રાષ્ટ્ર કક્ષાની રમતો પૈકી ગુજરાતની કોઈ મહિલાને રાષ્ટ્રીય ચંદ્રક પ્રાપ્ત થયા છે કે કેમ?

શ્રી બાવકુભાઈ ના. ઉંધાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની જે સ્પર્ધાઓ થઈ છે એમાં ગુજરાતની જે મહિલાઓ છે એમાં છેલ્લાં ૨૦૦૩ ના વર્ષમાં રાષ્ટ્ર કક્ષાએ કુલ ૧૩૫ મહિલાઓએ સિદ્ધિ મેળવેલ છે એમાં ૮૪ મહિલા ૨૦૦૩-૦૪ માં ૪૧ મેડલો મેળવવાની સિદ્ધિ મેળવેલ છે ત્યારપછી ૨૦૦૪-૦૫ ની જે સ્પર્ધા થઈ છે એમાં રાષ્ટ્ર કક્ષાએ ૫૧ મહિલાઓએ ૫૫ મેડલ મેળવીને કુલ ૯૬ મેડલ છેલ્લા બે વર્ષમાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મહિલા ક્ષેત્રે આપણે સિદ્ધિ મેળવી છે અને છેલ્લી સ્થિતિની જો વાત કરું તો અત્યાર સુધીમાં વધારેમાં વધારે મેડલ આપણા ખેલાડીઓએ મેળવેલ છે. ૧૪૭ મેડલો આપણે રાષ્ટ્ર કક્ષાએ મેળવી શક્યા છીએ. એમાં ૧૪૭ મહિલાઓએ ૭૮ મેડલ એટલે પુરુષ કરતા ૯ મેડલ વધારે મેળવી રાજ્યની મહિલાક્ષેત્રે ખૂબ ગૌરવ વધારેલ છે.

ડૉ.ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી એ જે માહિતી આપી અને મહિલાઓએ જે ગૌરવ વધાર્યું અને એમને બિરદાવ્યા એ બદલ આભાર. મારે એ પૂછવું છે કે, આ જે સિદ્ધિઓ અપાવનારી આપણી બહેનો અને મહિલાઓ છે એને રાજય સરકાર કોઈ સ્પેશિયલ મદદ કરવા માગે છે ખરી? એટલા માટે કે આ બધી જ મહિલાઓ રાજકીયક્ષેત્રે હોવા છતાં, મધ્યમવર્ગની હોય છે, ગરીબવર્ગની હોય છે, નોકરી માટે સમસ્યા હોય છે. મહિલાઓ ગૌરવ અપાવે છે એવું આપે કહ્યું તો મારે એ કહેવું છે કે, એના માટે રાજય સરકાર કાંઈ વધુ કરવા માગે છે?

શ્રી બાવકુભાઈ ના. ઉંધાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે મહિલાઓ રાજ્યકક્ષાએ અને રાષ્ટ્રકક્ષાએ જે રમતગમતમાં સિદ્ધિઓ મેળવે છે એમાં રાષ્ટ્રકક્ષામાં જે મહિલાઓ ભાગ લે છે અને સિદ્ધિ મેળવે છે એને સ્કૉલરશિપ તરીકે ૪,૮૦૦/- રૂપિયા આપ્યા છે અને જે મહિલાઓ રાજ્યકક્ષાએ પ્રથમ નંબરે આવે, વ્યકિતગત રમતમાં અથવા સાંઘિક રમતમાં તેમને પણ ૪,૮૦૦/- રૂપિયા સ્કૉલરશિપ આપવામાં આવે છે, બીજા નંબરે જે મહિલાઓ આવે છે એમને ૩,૬૦૦/- રૂપિયા સ્કૉલરશિપ તરીકે આપવામાં આવે છે અને ત્રીજા નંબરને ૨,૪૦૦/- રૂપિયા સ્કૉલરશિપ તરીકે આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પણ...(અંતરાય)

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : પ્રશ્નનો સમય ખોટો જાય છે.

શ્રી બાવકુભાઈ ના. ઉંધાડ : તમે પૂછયું છે એનો જવાબ આપું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : ગોવાભાઈ, બહેને એ પ્રશ્ન પૂછયો છે.

શ્રી બાવકુભાઈ ના. ઉંધાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે મહિલા ખેલાડીઓએ રાજ્યકક્ષાએ અને રાષ્ટ્રકક્ષાએ જેણે સિદ્ધિઓ મેળવેલી હોય છે એવી તમામ મહિલાઓને એવોર્ડ પણ આપવામાં આવે છે અને એમાં એકલવ્ય એવોર્ડ આપવામાં આવે છે આ એવોર્ડમાં બે મહિલાઓને એક-એક લાખ રૂપિયાના એવોર્ડ આપવામાં આવે છે અને એકલવ્ય એવોર્ડમાં સિનિયર અને જુનિયર આ રીતે બે એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બીજા એવોર્ડ છે સરદાર પટેલ એવોર્ડ, એમાં પણ સિનિયર અને જુનિયર, બે-બે એવોર્ડ પચાસ-પચાસ હજાર અને

એકલવ્ય એવોર્ડમાં એક-એક લાખ રૂપિયાના એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. જયદિપસિંહજી એવોર્ડ, જે દસ મહિલાઓએ સિદ્ધિ મેળવેલ હોય એવી મહિલાઓને એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. આવી રીતે રાજયમાં (અંતરાય) પણ તમે માહિતી માગી છે અને હું માહિતી આપું છું (અંતરાય) મહિલાઓને જે આપવામાં આવે છે એની વિગતો હું સદસ્ય ડૉ.ચંદ્રિકાબેને પૂછયું છે એનો હું જવાબ આપું છું માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અત્યાર સુધીમાં ૨૬૬૬ મહિલાઓને આપણે સ્કૉલરશિપ આપી છે અને ૧ કરોડ ૧૨ લાખ ૫૪ હજાર અને ૮૦૦ રૂપિયા તમામ મહિલાઓને ચૂકવી આપેલા છે આ ઉપરાંત સમગ્ર રાજયમાં ક ોઈપણ સ્કૉલરશિપ બાકી હોય તો છેલ્લા એક મહિના પહેલા તમામે તમામ જિલ્લાઓને (અંતરાય)

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : અમે સ્કૉલરશિપનું પૂછયું નથી, શું કામ તમે (અંતરાય) દસ મિનિટનો સમય ખોટો, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મંત્રીશ્રીને આપ કહો.

અધ્યક્ષશ્રી : ગોવાભાઈ પ્રશ્ન (અંતરાય)

શ્રી બાવકુભાઈ ના. ઉંધાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ઉપરાંત રાજયની અંદર મહિલાઓ અને રમતવીરોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ વર્ષે ગ્રામિણ ઓલિમ્પિકસનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ, તરણેતરના મેળામાં અને દેવગઢબારિયામાં પણ.

અધ્યક્ષશ્રી : હવે પૂરું કરું છું.

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપણે ત્યાં સાંસ્કૃતિક પરંપરા એવી રહી છે કે, બહેનોના મોઢેથી સાચી વાત નીકળી જ જાય, સહજ રીતે બહેનો સત્યને વરેલી હોય છે અને તેથી પ્રશ્ન પણ એવો પૂછાઈ ગયો, હવે પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો અને સાચી માહિતી આવતી હોય એટલે બાકી મિત્રોને તકલીફ થઈ રહી છે પણ હું ચંદ્રિકાબેનનો આભારી છું.

વલસાડ જિલ્લામાં કેળવણી નિરીક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ.

***૯૨૨૭ શ્રી લક્ષ્મણભાઈ બા. પટેલ(પારડી)** : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

(૧).તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૪ ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લા પ્રાથમિક શાળામાં કેળવણી નિરીક્ષકોની કુલ જગ્યાઓ કેટલી મંજૂર થયેલ છે,

(૨).આ સ્થિતિએ કેટલા કેળવણી નિરીક્ષકો ફરજ બજાવે છે અને,

(૩).ખાલી જગ્યાઓ સરકાર કેટલા સમયમાં ભરવા માગે છે?

શિક્ષણ મંત્રી :

(૧).૨૩

(૨).૧૦

(૩).જેમ બને તેમ જલદી.

શ્રી લક્ષ્મણભાઈ બા. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી હું જાણવા માગું છું કે વલસાડ જિલ્લાની અંદર પ્રાથમિક શાળામાં કેળવણી નિરીક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે. કુલ જગ્યા ૨૩ છે અને મને જવાબ મળ્યો છે કે ૧૦ જગ્યા ભરાયેલી છે. અને ૧૩ જગ્યા ખાલી છે. એક તો કેટલા વર્ષોથી આ જગ્યા ખાલી છે એ જાણવા માગું છું અને બીજો પ્રશ્ન છે કે અત્યાર સુધી નિરીક્ષકોની જગ્યા ન ભરાવાનું કારણ શું અને વલસાડ જિલ્લાની અંદર તાલુકાવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે? અને મને જવાબ મળ્યો છે કે જેમ બને તેમ જલદી તો એના બદલે મને ચોકકસ માહિતી મળે કે કેટલા સમયમાં આ જગ્યાઓ મંત્રીશ્રી દ્વારા ભરવા માગે છે?

શ્રીમતી આનંદી બેન મ. પટેલ : ધરમપુર તાલુકામાં તા.૩૦-૬-૦૨ થી ત્રણ કેળવણી નિરીક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે. કપરડા તાલુકામાં ૨ જગ્યા ૧-૭-૦૨થી ખાલી છે. ૩ જગ્યા ૧-૯-૦૩ થી ખાલી છે, ૪ જગ્યા ૧-૫-૦૩થી ખાલી છે. ઉમરગામમાં એક જગ્યા ૧-૧૧-૦૩ થી ખાલી છે, ૧-૧૧-૨૦૦૨ થી, પારડીમાં ૨-૦૩થી, વલસાડમાં ખાલી ચાર જગ્યા ૧-૯-૦૪, બીજી ૧-૯-૦૨ અને ૧-૦૩ના સમયથી ખાલી છે. ત્રીજા વર્ષથી ખાલી છે. ૧૩ જગ્યા ખાલી છે. નિયમ એવો છે કે ૫૦ ટકા સીધી ભરતીથી નિયુકત થાય છે. અને ૫૦ ટકા પ્રમોશનથી થાય છે. પ્રમોશન આપવાના છે એની કાર્યવાહી ચાલુ છે. ૩૧ માર્ચ પહેલા પ્રમોશનથી ભરતી પૂર્ણ કરાશે અને ૫૦ ટકા સીધી ભરતીથી ખાલી છે એ સીધી ભરતી માટે નાણા વિભાગની મંજૂરી મળી છે. નવા આર.આર. મંજૂર થઈ ગયા છે. થોડા સમયમાં આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

શ્રી જીતુભાઈ હ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કપરડા તાલુકામાં ૧૩૦ ગામ આવેલા છે. ભયંકર જંગલ વિસ્તાર છે. છેલ્લા બે વર્ષથી કેળવણી નિરીક્ષકની ત્રણ જગ્યા ખાલી છે તો જલદી કયારે ભરવા માગે છે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કપરડામાં ખાલી જગ્યા છે પરંતુ ઈન્ચાર્જ મૂકવામાં આવ્યા છે. અધિકારી કામ કરી રહ્યા છે. આર.આર. નક્કી થઈ ગયા છે અને નાણા વિભાગની મંજૂરી મળી ગઈ છે. આવતા બે મહિનામાં આ બધી ખાલી જગ્યાઓ ભરી દેવામાં આવશે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ડી.પી.ઈ.પી.યોજના હેઠળ નવા રૂમો સીમ શાળાઓના રીપેરીંગ અંગે

***૯૩૯૩ શ્રી જગદીશ ઠાકોર(દહેગામ)** : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

(૧).ગાંધીનગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર ડી.પી.ઈ.પી. યોજના હેઠળ ૨૦૦૪ ના વર્ષના નવા રૂમો, સીમા શાળાઓ રીપેરીંગ અને અન્ય સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની કેટલી દરખાસ્તો આવી છે?

(૨).આ પૈકી કેટલી મંજૂર થઈ અને કેટલી બાકી રહી, અને

(૩).આ સુવિધાઓ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે?

શિક્ષણ મંત્રીશ્રી :-

(૧).ગાંધીનગર જિલ્લાનો સમાવેશ ડી.પી.ઈ.પી. અંતર્ગત થયેલ ન હોવાથી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૨).પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩).પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગાંધીનગર જિલ્લામાં ડી.પી.ઈ.પી.યોજના હેઠળ ગાંધીનગર જિલ્લાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી એનું કારણ શું? અને સીમા શાળા અને શાળાના ઓરડાનું રીપેરીંગ કઈ યોજનામાંથી થાય છે? કેટલી દરખાસ્ત આવી અને કેટલું કામ બાકી છે?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : ગાંધીનગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર ડી.પી.ઈ.પી. યોજના હેઠળ ૨૦૦૪ ના વર્ષમાં નવા રૂમ, સીમ શાળા રીપેરીંગ અને અન્ય સુવિધા પૂરી પાડવાની કેટલીક દરખાસ્ત છે. આ ડી.પી.ઈ.પી. કાર્યક્રમ ૧૯૯૭-૯૮માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજય સરકારને આપવામાં આવ્યો હતો. એમાં ત્રણ જિલ્લા હતા ડાંગ, બનાસકાંઠા અને દાહોદ - ગોધરા. એ વખતે એક જ જિલ્લો હતો. ત્રણ જિલ્લામાં ડી.પી.ઈ.પી.ચાલતી હતી એટલે જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. ગાંધીનગર જિલ્લામાં કોઈ ડી.પી.ઈ.પી. ચાલતી નથી. પરંતુ આપે પ્રશ્ન પૂછયો એટલે મને થયું જગદીશભાઈ અભ્યાસુ છે, સક્રિય છે એટલે પોતે પ્રશ્ન નહીં પૂછયો હોય પરંતુ પી.એસ. દ્વારા પૂછાયો હશે એટલે એમને ખબર નહીં હોય.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર : ગાંધીનગર જિલ્લામાં મારા તાલુકામાં શાળા રીપેરીંગની કેટલીક દરખાસ્ત છે. એમાં આવી મહત્વની ભારત સરકારની ગ્રાન્ટમાંથી જિલ્લાને સારા પૈસા મળતા હોય. ત્યારે ગાંધીનગરમાં પણ એનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે નહિ ? એટલું જ જાણવું છે.

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : ગાંધીનગર જિલ્લા સહિત પૂરા ગુજરાતને સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગર જિલ્લાને પણ સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે અને એમને એમના જિલ્લાની અંદર દહેગામ, ગાંધીનગર, કલોલ અને માણસામાં એડિશનલ કલાસરૂમ ૫ બંધાઈ રહેલ છે, જેનો ૪.૫૪ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. નવીન શાળા ૪ માગી હતી, જેનું કામ ચાલુ થયું છે, જેનો ૮.૨૧ લાખનો ખર્ચ થશે. સી.આર.સી. પે સૅન્ટરો ઉપર બાંધકામ થઈ રહ્યું છે, એમાં ૧૨ ગુજરાતમાં બંધાઈ રહેલ છે, જેનું કામ પ્રગતિમાં છે અને ૧૦.૨૩ લાખનો ખર્ચ થશે. પીવાના પાણીની સુવિધા ૧૦ શાળામાં કરવામાં આવશે. ૧.૧૦ લાખનો ખર્ચ થશે, જે પ્રગતિમાં છે. કંપાઉન્ડ વૉલ ૮૯ શાળામાં બંધાઈ રહેલ છે. ૨૨.૨૪ લાખનો ખર્ચ થશે. સેનિટેશન યુનિટ ૩૦ શાળામાં માગ્યા હતા, તેમાંથી ૨૯ માં ચાલુ થયા છે. એક પૂરું થયું છે. ૪.૨૭ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે. રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગમાં ૩૦ શાળાને આવરી લીધેલ છે, જેમાં ૧૮.૦૩ ના ખર્ચે કામ ચાલુ છે. મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કીચન શેડ ૫ શાળામાં ૧.૮૫ લાખના ખર્ચે કરી રહ્યા છીએ. આમ ટોટલ ખર્ચ ૭૦.૪૭ લાખ રૂપિયાનો થશે. આ એક-બે મહિનામાં કામગીરી પૂર્ણ થશે. શાળાના રિપેરિંગ માટે....

અધ્યક્ષશ્રી : ઘણું બધું કર્યુ છે.

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : રિપેરિંગનો પ્રશ્ન અગત્યનો છે. આ રાજય સરકારે પહેલીવાર શાળાના રિપેરિંગનો પ્રશ્ન હાથ ઉપર લીધો છે. એમની ૨૧૮ શાળામાં રિપેરિંગ માટેની દરખાસ્ત હતી. આ રાજય સરકારે દહેગામમાં ૨૦૪, ગાંધીનગરમાં ૧૭૧, કલોલમાં ૧૦૮ અને માણસામાં ૯૪ શાળામાં રિપેરિંગ કરવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે. ત્રીસ લાખ અઠાણું હજાર રૂપિયા વી.ઈ.સી.ને ફાળવી દેવામાં આવેલ છે. એ કામ પૂરું કરશે. ધારાસભ્યશ્રીને વિનંતી છે કે તેમના વિસ્તારમાં કામ જોતા રહેશે, જેથી સારું કામ થાય.

રાજયમાં કન્યા કેળવણી રથયાત્રા દરમ્યાન મળેલ પ્રવેશ

***૮૫૯૪ શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ(માંડલ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે :

(૧) કન્યા કેળવણી રથયાત્રાનું આયોજન રાજય સરકારે સન ૨૦૦૪ માં કરેલ તે કાર્યક્રમમાં રાજયનો કેટલો વિસ્તાર આવરી લેવાયો હતો, અને

(૨) આ કાર્યક્રમ દરમ્યાન કેટલા વિધાર્થીઓએ પ્રવેશ મેળવ્યો?

શિક્ષણ મંત્રીશ્રી :

(૧) રાજયમાં ૨૮૧૮ ગામોનો વિસ્તાર આવરી લેવાયો હતો.
(૨) ૨૮૧૮ ગામોમાં જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં ૭૫૨૪૪ બાળકોએ પ્રવેશ મેળવ્યો હતો.

શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું જાણવા માગું છું કે મહિલા શિક્ષણ વધે તે માટે કન્યા કેળવણી રથયાત્રામાં કોણ કોણ જોડાયું? રાજય કક્ષાએ શું આયોજન થયું? રાજયમાં કેટલા ટકા બાળકો આ કાર્યક્રમના કારણે દાખલ થયાં?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : ગુજરાત રાજયમાં ૫૫ વર્ષની આઝાદી પછી માત્ર ૫૮ ટકા કન્યા કેળવણીનું પ્રમાણ હતું. રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વિશેષ ધ્યાન આપવાનું નક્કી કર્યું. છેલ્લા ૩ વર્ષથી ગુજરાતનાં જેટલાં ગામડાઓમાં ખાસ કરીને રાજય સરકારના મુખ્યમંત્રીશ્રી, તમામ મંત્રીશ્રી, આઈ.પી.એસ., આઈ.એ.એસ. અધિકારીઓ મળીને લગભગ ૨૬૮ જેટલા સિનિયર અધિકારીઓએ ૨૦ ટકા કરતા ઓછા સ્ત્રી સાક્ષર દર વાળાં ગામડાઓમાં જવાનું નક્કી કર્યુ અને ૩ દિવસ સુધી ઝૂંબેશ ચલાવવામાં આવી. રાજય સરકારનું આયોજન ૨૦ ટકા કરતા ઓછા સાક્ષરતા દરવાળા ગામડાઓને પસંદ કરેલ. જિલ્લા કક્ષાએ આયોજન થયું, એમાં કલેકટરશ્રી, ડી.ડી.ઓ. પૂરી એમની ટીમ બધાં ગામડાઓ આવરી લે એ અંગેની વ્યવસ્થા ઊભી કરી શકેલ હતાં. રાજય સરકાર તરફથી જે અમારા મંત્રીશ્રી વગેરે ગયા, તેમાં ૨૮૧૮ ગામડાઓનો એની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. અમે જે કાર્યક્રમમાં ગયા એ સમય દરમ્યાન ૭૫૨૪૪ બાળકોને શાળામાં દાખલ કરાવી શક્યા હતાં. જિલ્લા કક્ષાએ આયોજન થયું, એની અંદર ૭૭૬૫ ગામની અંદર એમાં ૯૪૫૮ જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓને આવરી લેવામાં આવેલ હતી. આ બધાની અંદર જિલ્લા કક્ષાના, સ્ટેટ કક્ષાના જવાબદાર વગેરે અધિકારીઓ પહોંચ્યા. એમાં જે બાળકો દાખલ થયાં, એ લગભગ ૯૮ ટકા જેટલાં બાળકોને કન્યા કેળવણી રથયાત્રા દ્વારા તેમને દાખલ કરાવી શક્યાં. ૨,૧૨,૪૫૦ બાળકો આ સમય દરમ્યાન દાખલ થયાં, જેમાં ૧,૦૩,૬૧૬ કન્યા હતી અને ૧,૦૮,૮૩૪ છોકરા હતા. આ પ્રવેશ દરમ્યાન લોક ભાગીદારી જે આપણને પ્રાપ્ત થઈ. આંકડા જાણવા જેવા છે. લોક ભાગીદારીથી કે જન શકિતનો ઉપયોગ કરીને પણ આ કન્યા કેળવણીનું કામ કરવું જોઈએ અને જે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી કરી રહ્યા છે ત્યારે એમાં ૨૧,૩૩,૪૦૨ આ સમય દરમ્યાન રોકડા શાળાઓને મળ્યા છે. રૂા.૩૫,૯૮,૫૦૦ નર્મદા બૉન્ડ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થયા છે અને ૯૦,૩૨,૮૭૪/- ભેટ સોગાદ સ્વરૂપે શાળાઓને પ્રાપ્ત થયા છે. આમ કુલ ૧,૪૭,૬૪,૭૭૬/- કન્યા કેળવણી રથયાત્રા દ્વારા રાજય સરકારને અને શાળાઓને પ્રાપ્ત થયા છે. સાંભળવાની જવાબદારી લો હવે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કેળવણી રથયાત્રા દ્વારા એમાં કોણે ભાગ લીધો તે પ્રશ્ન હતો અને જવાબ બીજો આપ્યો છે. હું એ જાણવા માગું છું કે ૧૯૯૧ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે આ રાજયનો ક્રમાંક સાક્ષરતાના દરમાં અગ્રતા ક્રમે હતો. નવમા નંબરે હતો. ૨૦૦૧ની વસ્તી ગણતરીએ આપણે ૧૬મા નંબરે પહોંચી ગયા છીએ. બિમારૂ રાજય રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ પણ આપણાથી આગળ નીકળી ગયા છે. આ રાજયએ અને મોટોભાગે આ રાજય સરકારે કામ કરેલું. આપણી અધોગતિ થઈ છે. તો હું એ જાણવા માગું છું કે રથયાત્રા મારફતે સાક્ષરતા વધવાની નથી. સાક્ષરતા તો વિદ્યાર્થીઓ કલાસમાં આવે અને આખું વર્ષ કલાસમાં ભણે તો સાક્ષરતા વધી શકે. હું આપણી મારફતે એ જાણવા માગુ છું કે, આ રથયાત્રાના *(XXX)ને બદલે તે ડ્રોપ આઉટ ન થાય

અધ્યક્ષશ્રી : **(XXX)* શબ્દ અસંસદીય છે તેને રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી હું રથયાત્રાને *(XXX)[*] કહું છું, કન્યા કેળવણીને નહીં. કન્યા કેળવણી કોને કહેવાય તેની આપને ખબર નથી. ડ્રોપ આઉટ ન થાય એટલા માટે સરકારે શું પગલાં લીધા. કારણકે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર..(અંતરાય) અમને રસ છે. અમે ગુજરાતી દીકરીઓને ભણાવીએ છીએ, તમને ભણાવતાં નથી આવડતું. ડ્રોપ આઉટ ન થાય અને સાક્ષરતા વધે એટલા માટે આ રાજય સરકાર શું પગલાં લેવા માગે છે. અમને કન્યા કેળવણી રથયાત્રામાં નહી દીકરીઓ ભણે તેમાં રસ છે. દીકરીઓને ભણાવવામાં શું પગલાં લીધા તે જાણવા માગું છું.

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ૧૯૯૧માં વસ્તી ગણતરી થઈ હશે. તે ૧૯૯૧ની શરૂઆતમાં ન કરે તે ચાર વર્ષ પહેલાં કરી હોય એટલે ૧૯૯૧માં આપણી સામે આવી શકે. એટલે અર્જુનભાઈ એમ ન કહીએ કે ૧૯૯૧માં...........

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહને ગેરમાર્ગે ન દોરાય. ૧૯૯૧ના આંકડા છે. ચાર વર્ષ પહેલાંના નહી.

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૧૯૯૧ના આંકડા ચોકકસ છે. પરંતુ આ આંકડાઓની ગણતરી ચાર વર્ષ કે બે વર્ષ પહેલાં થતી હોય છે.

[*] (XXX) આ અસંસદીય શબ્દ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવલામાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યો છે.

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમને જે ડ્રોપ આઉટનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો વિસ્તારથી જવાબ શિક્ષણમંત્રીશ્રી આપશે. પરંતુ સાથી પક્ષના નેતાને નાનકડી વાત કહેવાનું ઉચિત લાગે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દુનિયામાં એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી કે ભણેલા અભણ થાય. તેવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી.એટલે કોઈ ભણેલા હતા અને અમે આવીને અભણ કર્યા છે તેવી કોઈ શકતા નથી. એટલે ભૂતકાળમાં જે અભણ રહ્યા હતા તે સંખ્યાનો બોજ અમે આગળ ઢોળી રહ્યા છીએ અને અમારી કોશિશ છે અને જયારે ઉભો થયો છું ત્યારે કન્યા કેળવણી રથયાત્રા શબ્દ ન ગમે તો ન વાપરીએ પરંતુ ગૃહના બધા સાથીઓને વિનંતી કરીશ કે ૧૨,૧૩ અને ૧૪ જુન ૪૪ ડીગ્રી ટેમ્પરેચર હોય છે આપણે બધા ત્રણ દિવસ આ રાજયની કન્યા ભણે તેના માટે સમર્પિત કરીએ. જે પદ્ધતિ ઠીક લાગે તે પદ્ધતિથી ઘેર ઘેર જઈએ અને દીકરીઓને શાળામાં દાખલ કરાવીએ. હું માનું છું કે આ રાજયની મોટી સેવા હશે અને મારે પાલીતાણાના માનનીય ધારાસભ્યશ્રીને અભિનંદન આપવા છે. એમણે પોતાના વિસ્તારમાં એક એક ગામમાં પગપાળા થઈ એક મોટું આંદોલન ચલાવ્યું અને તેના કારણે તેમના વિસ્તારમાં આ ક્ષેત્રમાં બહું પ્રગતિ થઈ છે. આ સામૂહિક જવાબદારી છે. હું ઇચ્છું કે ભાઈશ્રી સાથી પક્ષના મિત્રો ૧૩,૧૪ અને ૧૫ જુન ૪૪ ડીગ્રી ટેમ્પરેચરમાં ગામડાઓમાં ગરીબ ઘરોમાં જઈને દીકરીઓને ભણાવવા માટે હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ તો રાજયનું ભલું થશે. ડ્રોપ આઉટનો વિપક્ષના નેતાશ્રીનો પ્રશ્ન છે અને જવાબ મળવો જોઈએ.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૪૪ ડીગ્રી ટેમ્પરેચરમાં જ અમે રહીએ છીએ પણ જે લોકો નથી રહેતા એ ૪૪ ડીગ્રી ટેમ્પરેચરમાં જાય, અમે તો રહીએ છીએ, આપ અમને ઉદ્દેશ ન આપો અમે તો ત્યાં જ રહીએ છીએ અને મારી તો આપને વિનંતી છે કે, આપના પક્ષના સાથી સભ્યશ્રીઓ આદિવાસી વિસ્તારમાં ગયા નથી, એ ઊંડાણના વિસ્તારોમાં જાય, ત્યાં દીકરા-દીકરીઓ કેવી હાલતમાં રહે છે એ અમને ખબર છે, અમને ઉદ્દેશની જરૂર નથી પણ માત્ર ત્યાં શિક્ષકો મોકલી આપો તો બાળકો ભણશે, એટલે શિક્ષકોને મોકલી દો. શિક્ષકોની તકલીફ છે.

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી,...

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ મૂળ પ્રશ્નનો ભાગ નથી ના, ના, જરાય નહીં, બીજો પ્રશ્ન લો, (અંતરાય) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ ટેબલ ઉપર મૂકી દેજો, અમારે ભાષણ નથી સાંભળવું, અમારે તો પ્રશ્નનો જવાબ સાંભળવો છે. એના પછીનો પ્રશ્ન લો.

અધ્યક્ષશ્રી : એક મિનિટ, માનનીય મંત્રીશ્રી ડ્રોપઆઉટનો જવાબ આપતા હતા, જવાબ ચાલુ છે એટલે જવાબ પૂરો કરે.

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ડ્રોપઆઉટનો રેઈટ ૧૯૯૪માં ૩૮ હતો એ અત્યારે ૧૭ ઉપર લાવ્યા છીએ, અત્યારે ૧૭ ડ્રોપઆઉટનો રેઈટ થયો છે અને આવતા બે વર્ષોમાં એ ૧૦ ઉપર આવે તેના માટેના રાજય સરકારના પ્રયાસો છે, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જ્યારે કન્યા કેળવણી રથ યાત્રા ચાલતી હતી ત્યારે માનનીય બળદેવભાઈ અને જગદીશભાઈ, આ બેને વિધાનસભાની બહાર નીકળ્યા પછી મને અભિનંદન આપ્યા હતા કે આ તમે કામ સારુ કર્યુ છે કારણ કે અમારા સમાજની દીકરીઓ શાળામાં નહોતી દાખલ થતી એ અમારા જ્ઞાતિની દીકરીઓ શાળામાં દાખલ થશે અને અમને મોટામાં મોટો ફાયદો થશે, સાહેબ, આ વાત એમની છે.

માંગરોળ ઉમરપાડા તાલુકામાં કૉલેજ શરૂ કરવા અંગે

***૯૪૨૨શ્રી ગણપતભાઈ વે. વસાવા(માંગરોળ)** : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) માંગરોળ અને ઉમરપાડા તાલુકા ૧૦૦ ટકા આદિવાસી વિસ્તાર હોવા છતાં બંને તાલુકામાં એક પણ કૉલેજ નથી તે હકીકત સાચી છે, અને

(૨) સરકાર કૉલેજ આપવા માગે છે કે કેમ અને આપવા માગે છે તો કેટલા સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે?

શિક્ષણમંત્રીશ્રી :

(૧) હા, જી.

(૨) કોઈ સંસ્થા માગણી કરશે તો કૉલેજ મંજૂર કરવામાં આવશે.

શ્રી ગણપતભાઈ વે. વસાવા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી આપના દ્વારા મને જવાબ મળ્યો છે પરંતુ મારો મત વિસ્તાર એ સો ટકા આદિવાસી વિસ્તાર છે. ત્યારે કૉલેજ આપવાની હા પાડી છે પણ નૉન ગ્રાન્ટેબલ કૉલેજ લગભગ કોઈ સંસ્થા માગશે નહીં ત્યારે સરકારશ્રી ગ્રાન્ટેબલ કૉલેજ આપવા માગે છે કે કેમ?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પ્રશ્ન મારો એ છે કે, રાજયની અંદર જ્યારે આટલું મોટું મૂડી રોકાણ આવતું હોય છે ત્યારે એ મૂડી રોકાણનો ઉપયોગ રોજગારી મેળવવા માટે

વિદ્યાર્થીઓ કરી શકે એના માટે રાજય સરકારે ઉદ્યોગ વિભાગ, શિક્ષણ વિભાગ, સાયન્સ એન્ડ ટૅક્નૉલૉજી વિભાગ અને મારો વિભાગ, એ બધાની સાથેની એક કમિટી બનાવી છે અને અમે થરોલી અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ કે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં જ્યારે કરોડો રૂપિયાનું મૂડીરોકાણ આવી રહ્યું છે ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતનો વિદ્યાર્થી હોય કે ઉત્તર ગુજરાતનો વિદ્યાર્થી હોય એને રોજગારીની તકો કયા પ્રકારના અભ્યાસક્રમો યુનિવર્સિટીઓમાં શરૂ કરીએ તો એ વિદ્યાર્થીઓને રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ થાય એનો એક થરોલી અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને એ અભ્યાસના આધારે આ જે જે ક્ષેત્રોની અંદર આ કરવા જેવું લાગતું હશે એની અંદર રાજય સરકાર વિચાર કરશે.

શ્રી પ્રવિણભાઈ છ. રાઠોડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માંગરોળ અને ઉમરપાડા તાલુકા સો ટકા આદિવાસી વિસ્તાર છે ત્યાં કોઈ સંસ્થા હોતી નથી કે આ જવાબદારી કૉલેજ શરૂ કરવા માટે ઉઠાવી શકે, તો ખરેખર નવા વર્ષના આયોજનમાં આ વિસ્તારમાં કૉલેજ ચાલુ થાય એ માટે માનનીય મંત્રીશ્રી કોઈ જવાબ આપવા માગે છે કે કેમ?

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં કહ્યું એમ જે થરોલી અભ્યાસ કરવામાં આવશે અને કયા કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની આ વિસ્તારોમાં આવશ્યકતા છે એનો અભ્યાસ કરી રાજય સરકાર એના ઉપર વિચાર કરશે

અંબાજી મંદિરના ભંડારમાંથી ચોરીનો બનાવ

***૯૪૧૧શ્રી હરજીવન હી. પટેલ(ધાનેરા)** : માનનીય દેવસ્થાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) તાજેતરમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંબાજી દેવસ્થાન ખાતે મંદિરના ભંડારમાંથી ચોરીનો બનાવ બન્યો તે વાત સાચી,

(૨) જો હા, તો ચોરી કરનાર ઇસમો સામે શું કાર્યવાહી કરી, અને

(૩) અંબાજી મંદિરમાંથી થતી ચોરીઓ અટકાવવા માટે સરકારે શાં પગલાં લીધાં છે?

દેવસ્થાન મંત્રીશ્રી :

(૧) હા, દાનપેટીમાંથી ચોરીની કોશિશ કરવાનો બનાવ બન્યો હતો.

(૨) ત્રણ ઇસમો પકડાયેલ તેમની સામે એફ.આઈ.આર. નં. ૧૫૭/૦૪ દાખલ કરી પોલીસ કેસ કરવામાં આવેલ છે, તથા એક ઇસમને ફરજમાંથી મોકૂફ કરેલ છે. અન્ય બે ઇસમોની સેવા લેવાનું બંધ કરેલ છે.

(૩) મંદિરના તમામ ગાર્ડને મંદિરમાંથી હટાવી દેવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિકયુરીટી ફૉર્સ સર્વીસ અમદાવાદ પાસેથી ૧૯ ગાર્ડ તથા એ. એસ. આઈ. મળી કુલ ૨૦ જવાનોની સેવા લેવામાં આવી છે.

સભામંડપના ઉપરના ભાગે વધુ સુરક્ષા માટે લોખંડની નવી જાળી ફીટ કરવામાં આવેલ છે.

વહીવટદારશ્રી, જિલ્લા પોલીસ અધિકારીશ્રી, પાલનપુર તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રીની સિક્યોરિટી અને સલામતી બાબતે કમિટીની રચના કરેલ છે.

શ્રી હરજીવન હી. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૬ વિકાસયાત્રામાં અંબાજીનો વિકાસ જે છેલ્લા ચાર પાંચ વર્ષમાં થયો છે એના માટે આ સરકારને હું અભિનંદન આપું છું. પણ મારે એ પૂછવું છે કે, આ કેસમાં જે ત્રણ ઈસમો પકડાયેલા હતા એ કેટલા સમયથી ત્યાં ફરજ બજાવતા હતા અને એમને છૂટા કરવા સિવાય બીજાં કોઈ પગલાં કાયદાકીય રીતે લીધાં છે?

શ્રી અશોક ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ત્રણ જણા ઉપર ફોજદારી કેસ ચાલુ છે એમાંથી એક અંબાજી વહીવટી તંત્રની અંદર હતા એને મોકૂફ કરવામાં આવ્યા છે અને બાકીનાની સેવાઓ લેવાનું બંધ કરી દીધું છે.

શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એ જાણવું છે કે, જ્યારે કળશ ચડાવવામાં આવ્યા એ દિવસે ત્યાં લોકો (અંતરાય) ચોરાયાની વાત સાચી છે?

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પૂરો થાય છે.

અતારાંકિત પ્રશ્નો
(તારાંકિત પ્રશ્નોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ)

ટ્રાયબલ વિસ્તારમાં કર્મચારીઓને ટ્રાયબલ એલાઉન્સ આપવા અંગે

૯૪૩૯ **શ્રી છોટુભાઈ અ. વસાવા(ઝગડિયા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ટ્રાયબલ વિસ્તારમાં અગાઉ કર્મચારીઓને ટ્રાયબલ એલાઉન્સ આપવામાં આવતું હતું તે વાત સાચી છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ ટ્રાયબલ એલાઉન્સ બંધ કરવાના શાં કારણો છે,	(૨) ગુજરાતના આદિજાતિ વિસ્તારોમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને હવે પાયાની સગવડો ઉપલબ્ધ હોઈ, આ ભથ્થું ચાલુ રાખવાની જરૂર જણાતી નથી.
(૩) શહેરોમાં કર્મચારીઓને સીટીએલાઉન્સ આપવામાં આવે છે તે વાત સાચી છે, અને	(૩) માત્ર છ (૬) વર્ગીકૃત શહેરોમાં સ્થાનિક વળતર ભથ્થું અપાય છે.
(૪) જો હા, તો ટ્રાયબલ એલાઉન્સ સરકાર આપવા માંગે છે કે કેમ ?	(૪) ખંડ (૨) ના જવાબમાં જણાવેલ વિગતે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અનામતની બાકી જગાઓની નિમણુંકની માધ્યમિક શાળાઓ

૮૩૩૮ **શ્રી દોલતભાઈ પરમાર(વડગામ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેર, અમદાવાદ જિલ્લા અને બનાસકાંઠા જિલ્લાની નોન-ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક સ્ટાફની ભરતીમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની અનામત જગાઓ માટે કેવા પ્રકારની જોગવાઈ સરકારે કરી છે,	(૧) ના જી.
(૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક કેટલી અનામત જગાઓ ભરવાની બાકી છે, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આ જગાઓ સરકાર કેટલા સમયમાં ભરવા માંગે છે ?	(૩) લાગુ પડતું નથી.

કચ્છ જિલ્લામાં વિધવા, અને નિરાધારોના સહાયના પડતર કેસ

૯૨૨૪ **શ્રી ગોપાલભાઈ ગા. ધુઆ(મુંદ્રા) : માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં તાલુકાદીઠ સને ૨૦૦૨-૦૩, સને ૨૦૦૩-૦૪માં ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ સુધીમાં નિરાધાર વિધવા સહાય માટે કેટલી અરજીઓ આવી,	(૧) અને (૨) સાથેના પત્રક મુજબ.
(૨) તેમાંથી તાલુકાદીઠ કેટલી મંજૂર કરી અને કેટલી નામંજૂર કરી,	

(૩) ના મંજૂર કરવાનાં કયાં કારણો છે, અને

(૩) (૧) પુખ્ત વયનો પુત્ર હોવાથી
(૨) આવક વધુ હોવાથી
(૩) ઉંમર વધુ હોવાથી
(૪) બીજીવાર અરજી આવવાથી વગેરે કારણોસર

(૪) મંજૂર થયેલ અરજીઓ પૈકી કેટલી વ્યકિતઓની સહાય મળી રહી છે, કેટલી બંધ થઈ ગઈ છે, અને બંધ થવાનાં કારણો શું છે ?

(૪) મંજુર થયેલી ૬૨૭ પૈકી ૫૯૨ વ્યકિતઓને સહાય મળે છે. ૪૫ કેસોમાં સહાય બંધ કરેલ છે. બંધ થવાના કારણો પ્રશ્ન ખંડ-૩ મુજબ.

પત્રક

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	૨૦૦૨-૨૦૦૩			૨૦૦૩-૨૦૦૪			૨૦૦૪-૨૦૦૫		
		મળેલ અરજીઓ	મંજૂર થયેલ અરજીઓ	નામંજૂર થયેલ અરજીઓ	મળેલ અરજીઓ	મંજુર થયેલ અરજીઓ	નામંજુર થયેલ અરજીઓ	ડીસે.-૨૦૦૪ સુધીમાં આવેલ અરજીઓ	મંજુર	નામંજુર
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧
(૧)	રાપર	૬૯	૩૯	૩૦	૩૧	-	-	૧૪	૦૩	૦૧
(૨)	અંજાર	૯૮	૯૦	૦૮	૬૪	-	-	૪૩	૦૯	૧૮
(૩)	અબડાસા	૪૫	૩૪	૧૧	૧૮	-	૦૬	૧૫	-	૧૪
(૪)	માંડવી	૯૧	૭૫	૧૬	૩૯	-	-	૨૭	૬	૪૨
(૫)	મુંદ્રા	૭૩	૪૬	૨૭	૦૪	-	-	૧૭	૦૩	૦૯
(૬)	ગાંધીધામ	૬૯	૬૫	૦૪	૬૨	-	-	૩૦	૧૦	૦૮
(૭)	નખત્રાણા	૩૭	૨૭	૧૦	૨૪	-	૧૨	૧૩	૦૨	૧૨
(૮)	ભચાઉ	૭૨	૫૦	૨૨	૩૮	-	-	૪૩	૦૩	૧૯
(૯)	ભૂજ	૧૬૮	૧૩૭	૩૧	૩૫	-	-	૪૩	૧૮	૨૪
(૧૦)	લખતર	૧૫	૦૭	૦૮	૦૪	-	૦૨	૧૯	૦૩	૧૦
	કુલ	૭૩૭	૫૭૦	૧૬૭	૩૧૯	-	૨૦	૨૬૪	૫૭	૧૫૭

રાજ્યમાં માથાદીઠ આવક અને દેવું

૮૨૪૮ **શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ(ઉના) : : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) સને ૨૦૦૩-૦૪ના વર્ષમાં રાજયમાં માથાદીઠ કેટલી આવક હતી, અને

(૨) તે સામે માથાદીઠ રાજ્યમાં કેટલું દેવું છે?

જવાબ

(૧) સને ૨૦૦૩-૦૪ના વર્ષમાં રાજ્યમાં માથાદીઠ આવક ચાલુ ભાવે રૂા. ૨૨૦૪૭ હતી.

(૨) તે સામે રાજ્યમાં માથાદીઠ દેવું રૂ. ૯૬૫૮ હતું.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અકસ્માતના પડતર કેસ

૯૪૦૬ **શ્રી કાંતિલાલ ધ. કચોરિયા(પાલનપુર)** : : **માનનીય ન્યાયતંત્ર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ વિવિધ કોર્ટોમાં અકસ્માતના કેટલા કેસો પડતર છે ?	૧૦૩૮૭ કેસો.

જામનગર જિલ્લાના સ્મારકોની જાળવણી અંગે

૮૭૮૪ **શ્રી મુળુભાઈ હ. બેરા(ભાણવડ)** : **માનનીય સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જામનગર જિલ્લામાં આવેલ પ્રાચીન સ્મારકોની જાળવણી માટે સરકાર દ્વારા કોઈ પગલાં લેવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો કયા કયા સ્મારકો માટે સન ૨૦૦૪માં શી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે ?	(૨) સન : ૨૦૦૪ દરમિયાન લાખોટા કોઠા, જામનગર અને ખંભાળીયા દરવાજો જામનગરની પુરારક્ષણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જ્યારે છેલેશ્વર મંદિર, ઘુમલી, રામપોળ દરવાજો ઘુમલી, ગણેશ મંદિર ઘુમલી, વિકીયાવાવ ઘુમલી ખાતે પુરારક્ષણ કાર્ય હાથ ધરવા માટે અંદાજો તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

ડીગ્રી ઈજનેરી કોલેજોમાં ભરાયેલ સીટોની સંખ્યા

૮૦૩૭ **શ્રી ગોરધનભાઈ પ્રા. ઝડફિયા(રખિયાલ)** : : **માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં ડીગ્રી ઈજનેરી કોલેજોમાં જુદા જુદા ટ્રેડની મળીને કુલ કેટલી સીટો તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ ઉપલબ્ધ છે,	(૧) રાજ્યમાં ડીગ્રી ઈજનેરી કોલેજોમાં જુદા જુદા ટ્રેડની મળીને કુલ ૧૧૯૮૫ બેઠકો તા.૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ ઉપલબ્ધ હતી.
(૨) આ ઉપલબ્ધ સીટો મુજબ તમામ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયેલ છે, અને	(૨) ના જી.
(૩) ખાલી સીટ રહેવાના કારણો શાં છે ?	(૩) (૧) સદર બેઠકો સ્વનિર્ભર સંસ્થાઓની છે. જેઓનું ફીનું ધોરણ સરકારી તથા અનુદાનીત સંસ્થાઓની સરખામણીમાં વિશેષ હોઈ વિદ્યાર્થીઓએ ઓછો રસ દર્શાવ્યો હોય તેમ જણાય છે. (૨) ધોરણ-૧૨ પછી ઈલેકટ્રોનીકસ મિકેનીકલ કોમ્પ્યુટર એન્જિનીયરીંગ વિગેરે જેવી બહુ પ્રચલિત ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમની વિદ્યાશાખાઓમાં પ્રવેશ ઉપલબ્ધ હોઈ, વિદ્યાર્થીઓએ ડીગ્રી ઈજનેરી અભ્યાસક્રમની ખાલી રહેલ બેઠકોમાં ઓછો રસ બતાવ્યો હોય તેમ જણાય છે.

કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના અન્વયે વિદેશી લોનો, બહારનું અનુદાનના વ્યાજ અંગે

૯૨૨૩ **શ્રી મનીષ ન. ગીલીટવાલા(સુરત શહેર (પૂર્વ) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષમાં રાજ્ય સરકારને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી યોજના બહારનું અનુદાન અન્ય આયોજન, ઉચ્ચક અનુદાન અને કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજનાઓ માટે કુલ કેટલી રકમો પ્રાપ્ત થઈ,	(૧) નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૦૧-૦૨, ૨૦૦૨-૦૩, ૨૦૦૩-૦૪ અને તા. ૦૧-૦૪-૨૦૦૪ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન મળેલ રકમોની વિગતોનું પત્રક સામેલ રાખેલ છે.
(૨) આમાંથી વિદેશી લોનો કેટલી રકમની હતી, અને	(૨) લાગુ પડતું નથી.
(૩) આ લોનો કેટલી રકમની વ્યાજે લેવામાં આવી ?	(૩) લાગુ પડતું નથી.

રાજ્ય સરકારને તા. ૩૧મી ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષમાં મળેલી રકમો દર્શાવતું પત્રક

(રૂ. કરોડમાં)

ક્રમ	વિગત	૨૦૦૧-૦૨	૨૦૦૨-૦૩	૨૦૦૩-૦૪	તા. ૦૧-૦૪-૦૪થી તા. ૩૧-૧૨-૦૪
૧	યોજના બહારનું અનુદાન	૩૫૧.૦૨	૨૧૨૩.૪૯	૩૯૨.૭૮	૯૩.૪૭
૨	અન્ય આયોજના	૬૭૪.૪૫	૪૨૫.૨૫	૧૦૪૮.૬૨	૧૬૪૩.૩૫
૩	ઉચ્ચક અનુદાન	શૂન્ય	૮૮.૧૫	શૂન્ય	શૂન્ય
૪	કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજનાઓ	૩૪૬.૭૦	૩૦૭.૩૨	૩૦૦.૯૨	૨૭૧.૮૨

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સેલ્સટેક્ષની આવક અને ચોરીના કેસ

૮૮૦૮ **શ્રી પોપટભાઈ સ. જીંજરિયા(ચોટીલા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સેલ્સટેક્ષની કેટલી આવક થઈ,	(૧) રૂા. ૪૩.૩૯ કરોડ.
(૨) આ સમયગાળા દરમ્યાન સેલ્સટેક્ષની ચોરીના કેટલા કેસો કરવામાં આવ્યા, અને	(૨) ૩૦ કેસો.
(૩) ચોરી કરનાર સામે કેટલો દંડ વસૂલ કરવામા આવ્યો ?	(૩) રૂ. ૧,૬૩,૧૪૧.

રાજ્યમાં ખાનગી માધ્યમિક સંસ્થાઓને મંજૂરી

* ૮૦૭૫ **શ્રી મનહરલાલ મ. મકવાણા(દસાડા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જે ખાનગી સંસ્થાઓને માન્યતાઓ માધ્યમિક શિક્ષણમાં આપવામાં આવી છે તેને તાલુકા એકમમાં ગણવામાં આવી છે તે વાત સાચી છે, અને	(૧) ના, જી.
(૨) જો હા, તો તેના કારણો શાં છે ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

આણંદ જિલ્લામાં નિરંતર શિક્ષણ યોજના હેઠળ ખરીદી

૮૦૬૭ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધી. પરમાર(ભાદરણ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં આણંદ જિલ્લામાં નિરંતર શિક્ષણ યોજના હેઠળ ઓપરેશન બ્લેક બોર્ડ અંતર્ગત કેટલી ખરીદી કરવામાં આવી, તેની કિંમત કુલ કેટલી છે,	(૧) નિરંતર શિક્ષણ યોજના હેઠળ ઓપરેશન બ્લેકબોર્ડ યોજના અસ્તિત્વમાં નથી.
(૨) આ ખરીદી પૈકી જિલ્લામાં તાલુકાવાર શાળાઓને કેટ કેટલી ફાળવણી કરવામાં આવી, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આવી ખરીદી સરકારી પ્રવર્તમાન નિયમો વિરૂધ્ધ કરવામાં આવી છે તે હકીકત સાચી છે ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા લીધેલ ઓવરડ્રાફ્ટ

૮૨૮૭ **શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિધ્ધપુર) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા** કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્ય સરકારે તા. ૦૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી વખત અને કેટલી રકમોના ઓવરડ્રાફ્ટ લીધા,	(૧) શુન્ય
(૨) આ ઓવરડ્રાફ્ટો કેટલા વ્યાજના દરે લીધા હતા,	
(૩) આ અંગે કુલ કેટલી રકમ વ્યાજ ચૂકવણીમાં ચૂકવવામાં આવી, ક્યારે, અને	(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૪) આ ઓવર ડ્રાફ્ટો લેવાના કારણો કયા કયા હતા ?	

રાહતો આપેલ એકમો પૈકી ગ્રામ વિકાસના એકમોએ ભરેલ રકમ અંગે

૮૯૩૯**શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ(રાપર) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં સેલ્સ ટેક્ષ ભરવામાંથી માફી મેળવતા કે વિલંબીત ચુકવણીનો લાભ મેળવતા એકમો પૈકી વર્ષ ૨૦૦૨-૦૩/૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના ડીસેમ્બર ૩૧/૦૪ સુધી વર્ષવાર ૧૦ કરોડ રૂપીયા કરતા	(૧) * પત્રક-અ મુજબ

પ્રશ્ન	જવાબ
કર માફી કે વિલંબીત ચુકવણી કયા કયા ઓદ્યોગિક ગૃહો કે અકમોએ કેટ કેટલી રકમની લીધી છે,	
(૨) આ એકમોએ આવી સવલતો અન્વયે મળતી રકમ પર ગ્રામ વિકાસ અંગે બે અગર ત્રણ ટકા ભરવાની રકમ કોણે કોણે કેટ કેટલી વર્ષવાર સરકારમાં ભરી.	(૨) * પત્રક-બ મુજબ
(૩) ગ્રામ વિકાસની આ રકમ ન ભરતા આવા એકમો પૈકી ખર્ચની વ્યવસ્થા કરવા આ રકમ રાખવા કયા એકમોને અનુમતી આપી; અને	(૩) આવી કોઈ અનુમતિ કોઈપણ એકમને આપવામાં આવી નથી.
(૪) ગ્રામ વિકાસ માટે આવા એકમોને રકમ ન ભરતાં ગ્રામ વિકાસની પ્રવૃત્તિ માટે ખર્ચ કરવાની અને વ્યવસ્થા ગોઠવવાની અનુમતી આપવામાં આવી હોય તો અકમોના નામ અને આ વર્ષોમાં થયેલ ખર્ચની વિગત ?	પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. ***(પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)**

જુનાગઢ જિલ્લાની સિવિલ કોર્ટમાં અકસ્માત અંગેના નિકાલ વગરના પડતર કેસ

૯૪૫૨ **શ્રી ગોવિંદભાઈ વ. પરમાર(તલાલા) : માનનીય ન્યાયતંત્ર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જુનાગઢ જિલ્લામાં તા. ૩૦-૧૧-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ સિવિલ કોર્ટોમાં કેટલા એકસીડન્ટ કેસ, રેગ્યુલર સિવિલ દાવાઓ તથા ફોજદારી કેસોના આખરી નિકાલ વગરના કેટલા કેસો પડતર છે, અને	(૧) (૧) મોટર અકસ્માત વળતર દાવાઓ : ૧૦,૯૧૭ (૨) સીવીલ સ્યુટસ : ૨૦,૧૦૯ (૩) અન્ય દિવાની દાવા : ૧૫,૬૧૮ (૪) ફોજદારી દાવા : ૮૮,૮૩૭
(૨) નિકાલ વગરના અને કલેઈમ દાવાઓ એક વર્ષથી વધુ સમયનાં કેટલા છે ?	(૨) ૧૦,૬૬૭ કેસો.

પગાર વિસંગતતા સમિતિના અહેવાલ પર કરાયેલ નિર્ણય

૮૭૩૧ **શ્રી દિલુભા ટે. ચુડાસમા(વડોદરા (ગ્રામ્ય)) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-**

પ્રશ્ન	જવાબ
પાંચમા પગાર પંચ અંગે રચાયેલ પગાર વિસંગતતા સમિતિના અહેવાલ અને કરાયેલ નિર્ણયની વિગતો શું છે ?	પગાર વિસંગતતા સિમિતિનો અહેવાલ જાહેર કરાયેલ નથી તેમજ તે ઉપર હજી આખરી નિર્ણય થયેલ નથી.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા લીધેલ ઓવરડ્રાફ્ટ

૮૪૨૨ **શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર(મહુધા): માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-**

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજય સરકારે તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલા ઓવરડ્રાફ્ટ લીધા અને	(૧) શૂન્ય

છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલા ઓવરડ્રાફ્ટ લીધા, અને	
(૨) કંઈ સંસ્થા પાસેથી લીધા છે ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કરજણ અને શિનોર તાલુકાના પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોનું સેટઅપ

૯૪૧૩ **શ્રી નરેશકુમાર મી. કનોડિયા(કરજણ) : શ્રી નરેશભાઈ કનોડીયા (કરજણ) માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-**

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ કરજણ-શિનોર તાલુકામાં પ્રાથમિક શાળાના વિધાર્થી માટે મંજૂર થયેલ મહેકમ કરતા શિક્ષકોની ઘટ છે તે સાચું છે, અને	(૧) હા
(૨) જો હા, તો આ ઘટ પુરી કરવા સરકારે શાં પગલાં લીધા છે ?	(૨) નવી જગ્યા મંજૂર કર્યેથી ઘટ પૂરી કરવામાં આવશે.

પવિત્ર યાત્રાધામોમાં માંસ-ઈંડા-મરઘી તથા માંસાહારી પદાર્થોના વેચાણનો પ્રતિબંધ

૯૪૦૧ શ્રી શીવજીભાઈ ક. આહીર(ભૂજ) : માનનીય યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં આવેલા છ પવિત્ર યાત્રાધામોમાં માંસ-ઈંડા-મરઘી તથા માંસાહારી પદાર્થોના વેચાણથી યાત્રાળુઓ તથા ધાર્મિક જનતાની લાગણી દુભાઈ રહી છે તે સરકાર જાણે છે,	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો પવિત્ર યાત્રાધામોની પવિત્રતા જળવાઈ રહે તથા ધાર્મિક લાગણી પણ જળવાઈ રહે તે માટે આવા પદાર્થોનું વેચાણ રોકવા શી વ્યવસ્થા વિચારવામાં આવી છે, અને	(૨) સંબંધિત વિભાગોનાં પરામર્શમાં જરૂરી તમામ પાસાઓ અને કાયદાકીય પરિસ્થિતિ/જોગવાઈઓનો અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.
(૩) આ જવાબદારી કોને સોંપાઈ છે ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

રમતગમત ક્ષેત્રે આપવામાં આવતા એવોર્ડ

૮૭૬૬ **શ્રી યોગેશભાઈ ના. પટેલ(રાવપુરા) : માનનીય રમતગમત મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-**

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં રમતગમતના પ્રોત્સાહન માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કયા કયા એવોર્ડ આપવામાં આવે છે,	(૧) રાજ્યમાં રમતગમતના પ્રોત્સાહન માટે સરકાર દ્વારા નીચેના એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. (૧) એકલવ્ય એવોર્ડ (૨) સરદાર પટેલ એવોર્ડ (૩) જયદીપસિંહજી એવોર્ડ (૪) જુનીયર એકલવ્ય એવોર્ડ (૫) જુનીયર સરદાર પટેલ એવોર્ડ (૬) જુનીયર જયદીપસિંહજી એવોર્ડ

(૭) રાજ્ય રમતવીર એવોર્ડ

(૮) શ્રી અંબુભાઈ પુરાણી સ્ટેટ મેરીટ એવોર્ડ

(૯) ખાસ એવોર્ડ

(૨) આ એવોર્ડ માટે પ્રમાણપત્ર સાથે રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

(૨) હા, જી.

(૩) જો હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલા એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા?

(૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં ૪૧૭ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા.

ગાંધીનગર અને ભાવનગર જિલ્લામાં રમત-ગમતના ખોટા સર્ટિફીકેટ મેળવી વિધાસહાયકમાં થયેલ ભરતી

૮૧૪૧ **ડૉ. સી. જે. ચાવડા (ગાંધીનગર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-**

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં ગાંધીનગર અને ભાવનગર જિલ્લામા કેટલા વિધાસહાયકની ભરતી કરવામાં આવી,

(૨) ભરતી બાદ આ બે જિલ્લાઓમાં રમત-ગમતના ખોટા સર્ટિફીકેટ મેળવીને ભરતી થયેલ હોય તેવા કિસ્સાઓ અંગે ફરિયાદ મળેલ છે,

(૩) જો હા, તો સરકારે શાં પગલાં લીધેલ છે, અને

(૪) ભરતી થયેલ કુલ વિધાસહાયકોમાં કેટકેટલા અરજદારોએ રમતગમતના નેશનલ કક્ષાના સર્ટિફીકેટ રજૂ કરેલ છે ?

જવાબ

(૧) ગાંધીનગર-૨૩૧

ભાવનગર-૧૭૮૫

(૨) ગાંધીનગર જિલ્લામાં રમતગમતના ખોટા સર્ટિફીકેટ મેળવ્યા અંગેની ફરિયાદ મળેલ છે. ભાવનગર જિલ્લામાં આવી કોઈ ફરિયાદ મળેલ નથી.

(૩) ગાંધીનગર અને ભાવનગર જિલ્લાના વિદ્યાસહાયકોના સર્ટિફીકેટની ચકાસણી કરતાં બરાબર માલુમ પડેલ છે.

(૪) ગાંધીનગર-૮ (આઠ)

ભાવનગર-૩ (ત્રણ)

અમદાવાદ શહેરની શાળાઓમાં ડોનેશનની ફરિયાદો

૮૫૫૯ **શ્રી મોહંમદફારુક હુ. શેખ(કાલુપુર) : મોહંમદ ફારૂક શેખ (કાલુપુર) માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-**

પ્રશ્ન

છેલ્લા એક વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં અમદાવાદ શહેરની શાળાઓમાં ડોનેશન લેવા અંગે કઈ કઈ શાળાઓ સામે સરકારે શાં પગલા લીધા ?

જવાબ

(ક) નેલ્સન પ્રાથમિક શાળા-મણીનગર અમદાવાદ અને

(ખ) સિલ્વર બેલ્સ પ્રાથમિક શાળા બાપુનગર, અમદાવાદ

બે શાળાઓમાં ડોનેશન લેવા અંગે ફરીયાદ મળેલ.

ફરીયાદને આધારે તપાસ કરાવતાં નેલ્શન

પ્રાથમિક શાળા મણીનગર, અમદાવાદ સામેના આક્ષેપો પુરવાર થયેલ નથી.

જ્યારે સિલ્વર બેલ્સ પ્રાથમિક શાળા બાપુનગર, અમદાવાદની તપાસમાં આક્ષેપોને સમર્થન મળતું હોવાથી શાળાની માન્યતા રદ કરવા માટે કારણદર્શક નોટિસ આપવામાં આવેલ છે.

વેચાણવેરાની ચોરી અટકાવવા ચેક પોસ્ટ દ્વારા મેળવેલ રકમ અંગે

૯૪૪૮ શ્રી સુનીલ બા. ઓઝા(ભાવનગર શહેર (દક્ષિણ) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્યમાં વેચાણવેરાની ચોરી અટકાવવા માટે રસ્તા પર ઉભી કરવામાં આવેલી ચેક પોસ્ટ કેટલી, અને	(૧) ૩૨.
(૨) આ ચેક પોસ્ટ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલી રેવન્યુ કેટલી ?	(૨) રૂ. ૫૬.૬૯ લાખ.

રાજયમાં ૧૦ ટકા થી ઓછા પરિણામવાળી માધ્યમિક શાળાઓ

૮૬૮૨ **શ્રી બિમલ શાહ(કપડવંજ) : શ્રી બિમલભાઈ શાહ (કપડવંજ) માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-**

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ૧૦ ટકાથી ઓછું પરિણામ લાવતી માધ્યિમક શાળાઓ કેટલી છે, અને	(૧)

વર્ષ	શાળાઓ
માર્ચ-૨૦૦૨	૯૦
માર્ચ-૨૦૦૩	૮૦૧
માર્ચ-૨૦૦૪	૪૧૧

(૨) આ શાળાઓનું પરિણામ સુધારવા રાજ્ય સરકારે શું પ્રયત્ન કરેલ છે. ?

(૨)
૧. આચાર્યશ્રીઓની મિટીંગ કરી પરિણામ વધારવા માટે માર્ગદર્શન
૨. નિદાન કસોટી
૩. ઉપચારાત્મક શિક્ષણ
૪. ગ્રાન્ટ કાપ
૫. કર્મયોગી યોજના હેઠળ શિક્ષકોના તાલીમ વર્ગ
૬. શાળાઓને પ્રશ્ન બેંક
૭. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી કચેરી દ્વારા એકશન પ્લાન તૈયાર કરી માર્ગશન આપવામાં આવેલ અને તજજ્ઞ રીપોર્ટ શાળાઓને વિતરણ કરવામાં આવેલ.
૮. રજાના દિવસે તેમજ સ્કુલ તાસમાં

વધારાના વર્ગો ગોઠવી નબળા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપી માસિક ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

૯. રાત્રિ વર્ગોની વ્યવસ્થા કરી શિક્ષકો મારફતે વધુ માર્ગદર્શન મળી રહે તેવા પગલાં ભરવા સૂચવેલ છે.

૧૦. ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

૧૧. ગુજરાતી, ગણિત, સમાજવિદ્યા વિષયમાં સામાન્યતઃ પરિણામ ઓછું આવે છે તે અંગે બોર્ડ દ્વારા આવી ઉત્તરવહીઓનું પૃથ્થકરણ કરી બાળકો કયા પ્રકારની કયા પ્રશ્નમાં કયા કયા વિષયોમાં ભૂલો કરે છે તે તરફ ધ્યાન દોરી આ પ્રકારની ભૂલો ન થાય તે માટે સંબંધિત શાળાઓને જાણ કરવામાં આવી.

૧૨. રાજ્ય કક્ષાએ તમામ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીઓની હાજરીમાં પરિસંવાદ યોજી દરેક જિલ્લાઓએ પોતાના જિલ્લાની આવી શાળાઓ માટે કાર્ય શિબિર યોજી પરિણામ સુધારવા પ્રયત્નો કરવા જરૂરી માર્ગદર્શન આપેલ છે.

સુરત જિલ્લા અને શહેરમાં કોર્ટોના મકાનો

૮૦૧૮**શ્રી ધનસુખભાઈ ના. પટેલ(ઓલપાડ)** : માનનીય ન્યાયતંત્ર મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ સુરત જિલ્લા અને શહેરમાં કેટલી કોર્ટો કાર્યરત છે,	(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ના રોજ સુરત શહેરમાં ૩૦ અને સુરત જિલ્લાના તાલુકામાં ૧૨ મળી કુલ ૪૨ કોર્ટો કાર્યરત છે.
(૨) જે પૈકી કેટલી કોર્ટો સરકારી મકાનમાં છે તેમજ કેટલી કોર્ટો ભાડેના મકાનમાં બેસે છે, અને	(૨) ૪૧ કોર્ટો સરકારી મકાનમાં અને ૧ કોર્ટ ભાડાના મકાનમાં બેસે છે.
(૩) સુરત શહેરમાં ન્યાયસંકુલ નવું બનાવવાનું કોઈ આયોજન છે, કે કેમ ?	(૩) ના, જી.

ભાવનગર જીલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઘટ અંગે

૮૩૮૩ **શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ. સોલંકી(ઘોઘા)** : : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભાવનગર જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઘટ છે, અને	(૧) એક પણ ઘટ નથી.

(૨) આ ઘટ પૂરવા સરકારે શું આયોજન કરવામાં આવેલ છે ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

સાયન્સસીટી ખાતે યોજાયેલ વિજ્ઞાન મેળો

૮૯૪૪ **શ્રી પ્રદિપસિંહ ભ. જાડેજા(અસારવા)** : : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તાજેતરમાં સાયન્સ સીટીમાં રાજ્ય કક્ષાનો વિજ્ઞાન મેળો ભરાયો તેમાં રાજ્યની કેટલી શાળાઓએ ભાગ લીધો હતો,	(૧) કુલ-૩૮૮
(૨) અન્ય કઈ સંસ્થાઓએ ભાગ લીધો હતો,	(૨) ગુજરાત રાજ્યની ઈજનેરી કોલેજ, સાયન્સ કોલેજ, પીટીસી સંસ્થાઓ તેમજ અન્ય સરકારના ૧૧ વિવિધ વિભાગો અને સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓ
(૩) કુલ કેટલી કૃતિઓ આવી હતી, અને	(૩) ૪૭૫ કૃતિઓ
(૪) રાજય બહારની કેટલી કૃતિઓ હતી ?	(૪) ૫૧ કૃતિઓ

સાવલી તાલુકામાં શાળાના ઓરડાઓની ઘટ

૮૯૫૧ **શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર. ગોહિલ(સાવલી)** : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સાવલી તાલુકામાં તા. ૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ પ્રાથિમક શાળાના કેટલા ઓરડાઓની ઘટ છે, અને	(૧) ૧૮૧ ઓરડા.
(૨) આ ઘટ પૂરી કરવા શું આયોજન કરેલ છે?	(૨) ૩૦ નવા ઓરડાઓ બનાવવાનું આયોજન કરેલ છે અને બાકીના ઓરડાઓ ક્રમશ : પુરા કરવામાં આવશે.

બોગસ પ્રમાણપત્રોને આધારે શિક્ષકોની નિમણુંક

૮૯૬૧**શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા(જસદણ)** : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્ય બહારની યુનિવર્સિટીઓના બોગસ પ્રમાણપત્રો લઈ માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓમાં કેટલાક શિક્ષકોને નિમણૂંક આપ્યાનું રાજ્ય સરકારના ધ્યાને આવ્યું, અને	(૧) ૧૮૬ શિક્ષકો
(૨) તે દરેક સામે સરકારે શાં શાં પગલાં લીધા ?	(૨) નીચે મુજબના પગલાં લેવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. ૧ નોકરી સમાપ્ત કરવાની. ૨. નિમણુંક તારીખથી અત્યાર સુધીના પગાર ભથ્થાંઓ તેમજ શાળાએ મેળવેલ ગ્રાન્ટ અમાન્ય કરી વસુલાત લેવાની. ૩. સંબંધિતો સામે સી.આઈ.ડી (ક્રાઈમ) મારફતે

તપાસ કરવા વિચારણા ચાલે છે.
૪. પોલીસ કેસ કરવામાં આવેલ છે.

પંચમહાલ જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં ટ્રેઝરી કચેરી શરૂ કરવા બાબત

૮૬૬૪ **શ્રીકાળુભાઇ હી. માલીવાડ(લુણાવાડા)** : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે --

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પંચમહાલ જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકા મથકે ટ્રેઝરી કચેરી કયાં સુધીમાં શરૂ કરવામાં આવનાર છે, અને	(૧) આનુસાંગિક કાર્યવાહી પૂર્ણ થયે તરત જ.
(૨) આ અંગેના સ્ટાફની નિમણુંકો કેટલા સમયમાં થશે?	(૨) ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તરફથી મહેકમની ફાળવણી થયેથી.

રાજ્યના ધાર્મિક સ્થાનો પાછળ કરેલ ખર્ચ

૮૧૫૭ **ડૉ માયાબેન સુ. કોડનાની(નરોડા) :માનનીય દેવસ્થાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -**

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કયા કયા ધાર્મિક સ્થાનોના નવ નિર્માણના કાર્યો સરકાર દ્વારા હાથ ધરાયા, (૨) દરેક પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને	(૧) અને (૨) રાજ્યમાં ધાર્મિક સ્થાનોનો વહીવટ જે તે ટ્રસ્ટ દ્વારા થતો હોવાથી બધા ધાર્મિક સ્થાનોનું નવ નિર્માણ સરકાર દ્વારા થતું નથી. પરંતુ આ સાથેના પરિશિષ્ટમાં દર્શાવેલ યાત્રાધામો યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ હસ્તક હોઈ તેના વિકાસમાં સરકાર દ્વારા વિકાસ માટે ખર્ચ થયેલ છે.
(૩) નવ નિર્માણનું કામ હાલ કયા તબક્કે છે?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી

<u>પરિશિષ્ટ</u>

(રૂા. લાખમાં)

અ.નં.	યાત્રાધામનું નામ	કામની વિગત	તા. ૧-૧-૨૦૦૩ થી ૩૧-૧૨-૨૦૦૩માં થયેલ ખર્ચ	કામની વિગત	તા. ૧-૧-૨૦૦૪ થી ૩૧-૧૨-૨૦૦૪માં થયેલ ખર્ચ
૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧.	ગિરનાર	(૧) સીડી રીપેરીંગ	૩.૮૨ લાખ	(૧) સીડી રીપેરીંગ	૧.૧૩ લાખ
		(૨) માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરવાનું કામ	૧.૬૮ લાખ	(૨) દામોદર કુંડની સફાઈ તથા રીનોવેશન (ટેન્ડર)	૩૮.૦૯ લાખ
		(૩) શિવરાત્રી મેળો	૨.૦૦ લાખ	---	---
		કુલ	૭.૫૦ લાખ	કુલ	૩૯.૨૨ લાખ
૨	પાલીતાણા	(૧) ગારીયાધાકર રોડને વાળડલીંગ અને રીસરફીસીંગનું કામ.	૧૫.૪૨	---	---
		(૨) વાઈડીલીંગ ઓન બોથ	૪૧.૩૨	---	---

		સાઈડ એન્ડ રીસરફેસીંગનું તળેટી રોડ			
		કુલ	૫૬.૭૪		
૩	અંબાજી	(૧) અંબાજી ગ્રામ પંચાયતને સફાઈ અને સ્વચ્છતા માટે નવું ટ્રેકટર ખરીદ કરી, આપવાનું કામ	૩.૨૨	(૧) ભાદરવી પૂનમ મેળા ઉત્સવ	૨.૦૦
૪	ડાકોર	(૧) ગોમતીઘાટ નવનિર્માણ કરવાનું કામ.	૧૨.૭૬	(૧) ગોમતીઘાટ નવનિર્માણ કરવાનું કામ.	૫૦.૨૪
		---	---	(૨) કંકુ દરવાજાના નયનરમ્ય કરવાનું કામ.	૩.૦૦
		---	---	(૩) સાઈનેઝ બોર્ડનું કામ.	૩.૦૦
		---	---	(૪) કલોકરૂમનું કામ.	૪.૦૦
		---	---	(૫) પાણીની પરબનું કામ	૫.૦૦
		---	---	(૬) ફાગણી પૂનમ ઉત્સવ	૫.૦૦
		---	---	(૭) દુકાનો સંપાદન કરવાનું કામ	૨૫.૦૦
		કુલ	૧૨.૭૬	કુલ	૯૫.૨૪
૫	દ્વારકા	જન્માષ્ટમી ઉત્સવ	૧.૫૧	(૧) ગોમતીઘાટ છપ્પન સીડીનું કામ.	૫૦.૦૦
				(૨) જન્માષ્ટમી ઉત્સવ	૦૭.૦૦
				(૩) વીજ રાહત	૪.૪૦
		કુલ	૧.૫૧	કુલ	૬૧.૪૦
૬	સોમનાથ	---	---	(૧) સોમનાથ યાત્રીઓની અને મંદિરની સુરક્ષા માટે રીટનીંગ વોલનું કામ.	૨૧.૦૦
				(૨) વીજ રાહત	૩.૦૦
				(૩) ગેસ્ટ હાઉસની ગટરો સુધારી નગર પાલીકાની મુખ્ય ગટર સાથે	૯.૦૦

				જોડવાનું કામ.	
		કુલ	૮૩.૭૩	કુલ	૧૯૭.૮૬

ભિલોડા, વિજયનગર, મેઘરજ અને ખેડબ્રહમા તાલુકાઓમાં ૧૦ ટકાથી ઓછા પરિણામની શાળાઓ

૯૨૨૮ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા(ભીલોડા)** : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન

(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ૨ વર્ષમાં ભિલોડા, વિજયનગર, મેઘરજ અને ખેડબ્રહમા તાલુકાઓમાં તાલુકાવાર ધોરણ-૧૦ અને ૧૨નું પરિણામ ૧૦ ટકા થી ઓછુ કેટલી શાળાઓમાં આવ્યું છે,

જવાબ

(૧) ૧૦ ટકા કરતાં ઓછુ પરિણામ ધરાવતી શાળાઓની સંખ્યા

માર્ચ-૨૦૦૩

ક્રમ	તાલુકો	ધો. ૧૦નું પરિણામ	ધો. ૧૨નું પરિણામ	
			સા. પ્રવાહ	વિ. પ્રવાહ
૧	ભિલોડા	૬૦	૧૦	૦૩
૨	વિજયનગર	૨૬	૦૩	૦૨
૩	મેઘરજ	૩૧	૦૨	૦૧
૪	ખેડબ્રહમા	૧૪	૦૧	૦૨

૧૦ ટકા કરતાં ઓછુ પરિણામ ધરાવતી શાળાઓની સંખ્યા

માર્ચ-૨૦૦૪

ક્રમ	તાલુકો	ધો. ૧૦નું પરિણામ	ધો. ૧૨નું પરિણામ	
			સા. પ્રવાહ	વિ. પ્રવાહ
૧	ભિલોડા	૩૫	૦૫	૦૨
૨	વિજયનગર	૧૨	૦૧	૦૨
૩	મેઘરજ	૧૦	૦૧	૦૧
૪	ખેડબ્રહમા	૦૭	૦૧	૦૦

(૨) નબળા પરિણામવાળા વિષય શિક્ષક સામે સરકારે શાં પગલાં લીધાં, અને

(૨) ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, વ્યાયામ અને ચિત્ર જેવા વિષય શિક્ષકોના તાલીમ વર્ગ યોજવામાં આવ્યા અને અભ્યાસક્રમના દ્રષ્ટિ બિન્દુઓને સરળતાથી બાળકો સમક્ષ રજુ કરવાની પધ્ધતિ શિખવવામાં આવી તેમજ પરિણામ સુધારવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી.

(૩) આ પરિણામ સુધારવા સરકારે શાં પગલા ભર્યા ?

(૩) ૧. બોર્ડ દ્વારા પરિણામ સુધારવા પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગુજરાતી, ગણિત, સમાજવિદ્યા વગેરે વિષયોની

પગલા ભર્યા ?	ગુજરાતી, ગણિત, સમાજવિદ્યા વગેરે વિષયોની ઉત્તરવહીઓનું નિષ્ણાત શિક્ષકો દ્વારા પૃથ્થકરણ કરવામાં આવ્યું અને નિદાનાત્મક અને ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમ સંદર્ભે જરૂરી સાહિત્ય આપવામાં આવ્યું. ૨. બોર્ડ દ્વારા તૈયાર થયેલ પ્રશ્ન બેન્ક નબળા પરિણામ ધરાવતી શાળાઓને આપવામાં આવી. ૩. બોર્ડ કરતાં નીચુ પરિણામ લાવતી શાળાઓને ગ્રાન્ટ કાપ. ૪. રજાના દિવસે તેમજ સ્કુલ તાસમાં વધારાના વર્ગો અને રાત્રિ વર્ગો મારફતે વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન મળી રહે તેવા પગલાં. ૫. કર્મયોગી યોજના અંતર્ગત શિક્ષક તાલીમ કાર્યક્રમ. ૬. ૩૦ ટકા કરતાં ઓછુ પરિણામવાળી શાળાઓ સાથે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ મેળવતી શાળાઓ સાથે જોડાણ દત્તક યોજના. ૭. CBSE. NCERT ની પેટર્ન મુજબ નવા સંતુલિત પ્રશ્નપત્રના પરિરૂપ તૈયાર કરવામાં આવ્યા. ૮. આગામી વેકેશનમાં વિજ્ઞાનના વિષય શિક્ષકોને તાલીમ માટેનું આયોજન.

આંગણવાડી કાર્યકરોને તાલીમ

૯૪૪૪ **શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ(વાઘોડિયા) :માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં આવેલ આંગણવાડી કાર્યકરોને તાલીમ અંગે સરકારે કોઈ વ્યવસ્થા કરેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા,
(૨) જો હા તો કેટલી કાર્યકર બહેનોને ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ તાલીમ આપી ?	(૨) રાજ્યમાં આઈસીડીએસ યોજના હેઠળ ફરજ બજાવતા આંગણવાડી કાર્યકરોને ડિસેમ્બર ૨૦૦૪ સુધીમાં ૨૮૫૩૮ (અઠયાવીસ હજાર પાંચસો આડત્રીસ) બહેનોને જોબ તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

સરકારી ગ્રંથાલયો કોમ્પ્યુટરાઈઝડ કરવા અંગે

૮૬૪૮ **શ્રી ભરત બારોટ(દરિયાપુર-કાઝીપુર) : માનનીય સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં જાહેર ગ્રંથાલયો કેટલા છે,	(૧) ૪૭૯૮.

(૨) તે પૈકી સરકારી કેટલા,	(૨) ૧૨૩.
(૩) સરકારી ગ્રંથાલયોને આધુનિક બનાવવા માટે સરકાર તેને કોમ્પ્યુટરાઈઝડ કરવા માંગે છે કે કેમ, અને	(૩) હા, જી.
(૪) જો હા, તો તેની વિગતો શી છે ?	(૪) સરકારી ૨ મધ્યસ્થ ગ્રંથાલયો તેમજ ૨૪ જિલ્લા પુસ્તકાલયોના કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન માટે આયોજન કરેલ છે જે પૈકી પાંચ જિલ્લા પુસ્તકાલયોનું કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન થઈ ગયેલ છે. વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ માં ૨ મધ્યવર્તી પુસ્તકાલયો અને ૧૩ જિલ્લા પુસ્તકાલયોનું કોમ્પ્યુટરાઈઝડ કરવાનું આયોજન કરેલ છે. જ્યારે બાકી રહેતા ૬ જિલ્લા ગ્રંથાલયો પૈકી સને ૨૦૦૫-૦૬ દરમ્યાન ૫ જિલ્લાના ગ્રંથાલયોને કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન કરવાનું આયોજન કરેલ છે. અને જીલ્લા પુસ્તકાલય ભુજનું નવું મકાન ઉપલબ્ધ થયે કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન કરવામાં આવશે.

રાજ્યની માથાદીઠ આવક અને દેવું

૮૪૮૨ **શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી(અમરેલી) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં માથાદીઠ આવક કેટલી છે, અને	(૧) સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષમાં રાજ્યમાં માથાદીઠ આવક ચાલુ ભાવે રૂા. ૨૨૦૪૭ તથા તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રૂા. ૧૬૭૭૯ હતી,
(૨) તે સામે માથાદીઠ દેવું રાજ્યમાં કેટલું છે?	(૨) તે સામે રાજ્યમાં માથાદીઠ દેવું ૨૦૦૩-૦૪ના વર્ષમાં રૂા. ૯૬૫૮ અને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રૂા.૧૦૬૮૧ હતું.

કડી તાલુકામાં રાજ્ય સરકાર હસ્તકના દેવસ્થાનો

૮૯૪૫ **શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર(કડી) :માનનીય યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧)કડી તાલુકામાં સરકાર હસ્તકના કેટલા અને કયા કયા દેવસ્થાનો આવેલા છે; અને	(૧) કડી તાલુકામાં સરકાર હસ્તકના કુલ ૯ દેવસ્થાનો આવેલા છે; ૧ શ્રી ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ-ચંદ્રાસણ ૨ શ્રી વેરાઈ માતા-વડુ ૩ શ્રી કાલેશ્વર માતા-ઈન્દ્રાડ ૪ શ્રી રામજી મંદિર -વડુ ૫ શ્રી લાભેશ્વર મહાદેવ-રાજપુર ૬ શ્રી શ્રી રંગેશ્વર મહાદેવ- અચરાસણ

	૭ શ્રી રામજી મંદિર-થોળ
	૮ શ્રી વૈજનાથ મહાદેવ -થોળ
	૯ શ્રી યવતેશ્વર મહાદેવ-કડી
(૨) આ દેવસ્થાનના વહીવટ અને વિકાસ માટે શું આયોજન સરકારે કરેલ છે ?	(૪) શ્રી યવતેશ્વર મહાદેવ મંદિરના જીર્ણોધ્ધાર તથા વિકાસના કામો માટે પ્રાંત અધિકારીશ્રી મહેસાણાની અધ્યક્ષતા હેઠળ સમિતિની રચના કરી વિકાસ કરવા સરકારે આયોજન કર્યું છે. બાકીના માટે કલેકટરશ્રી પાસેથી દરખાસ્ત મળેથી યોગ્ય વિચારણા કરવામાં આવશે.

ડૂબત નિધિ હેઠળ મૂકેલ રકમો અંગે

૯૪૨૭ શ્રી પુનાભાઈ ધે. ગામીત(વ્યારા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગુજરાત રાજ્ય ડૂબત નિધિ હેઠળ ડિસેમ્બર-૦૪ સ્થિતિએ કેટલું ભંડોળ ઉપલબ્ધછે;	(૧) રૂા. ૩૦૪.૦૦ કરોડ
(૨) આ નિધિનો ઉપયોગ કયા હેતુઓ માટે કરવામાં આવે છે, અને	(૨) રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર બજારની લોનની પરત ચુકવણી માટે.
(૩) આ સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સરકાર દ્વારા આ નિધિમાં કુલ કેટલી રકમો મૂકવામાં આવી ?	(૩) રૂા. ૩૦૪.૦૦ કરોડ.

ડાંગ, વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં શાળાના વર્ગો વધારવાની મંજૂરી

૮૯૫૫ **શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે(ડાંગ-વાંસદા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ડાંગ, વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં ધો. ૧૦, ૧૧ અને ૧૨ના વર્ગો વધારવા માટેની કેટલી અરજીઓ ૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં માન્ય રાખી વધારાના વર્ગોને છેલ્લા એક વર્ષમાં મંજૂરી આપવામાં આવી?	જિલ્લા અને ધોરણવાર માન્ય રાખેલ અરજી/વધારાના વર્ગોને આપેલ મંજૂરી નીચે મુજબ છે.

ક્રમ જિલ્લો	ધો-૧૦	ધો-૧૧	ધો-૧૨	કુલ
ડાંગ	--	--	--	
વલસાડ	૦૩	૦૧	--	૦૪
નવસારી	૦૧	૦૧	--	૦૨
કુલ	**૦૪**	**૦૨**	**--**	**૦૬**

વાંસદા તાલુકામાં શિક્ષકોની ઘટ

૮૯૪૦ **શ્રી છનાભાઈ કો. ચૌધરી(ધરમપુર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વાંસદા તાલુકામાં ૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ પ્રાથમિક શિક્ષકોની કેટલી ઘટ કેટલા સમયથી છે; અને	(૩) ૩૦ ની ઘટ એક વર્ષથી છે.

(૨) આ ઘટ પુરી કરવા સરકારે શાં પ્રયાસો કર્યા ?	(૨) આ ઘટ પૈકી-૬ જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે. બાકીની જગ્યાઓ જેમ બને તેમ જલ્દી મંજૂર કરવામાં આવશે.

વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં થયેલ ઘટાડો

૮૧૮૭ **શ્રી જયંતિલાલ રા. કવાડિયા(હળવદ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં વિજ્ઞાનપ્રવાહમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં સતત ઘટાડો થતો જાય છે તે વાત સાચી છે;	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો રાજ્ય સરકારે આ બાબતે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં સંખ્યા વધે તે માટે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા કોઈ પ્રયત્નો કર્યા છે કે કેમ, અને	(૨) હા, જી.
(૩) જો હા, તો કયા કયા પ્રયત્નો કર્યા છે ?	(૩) વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટવાના કારણોનો અભ્યાસ કરવા સંશોધન કાર્ય ધરી તારણો મેળવવામાં આવેલ છે. અને તે અન્વયે કારણોના નિવારણ માટે નીચે મુજબ પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવેલ છે. (૧) માન.મંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક-વીડીયો કોન્ફરન્સ યોજી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના આચાર્યોને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવે તે માટે જરુરી માર્ગદર્શન-પ્રોત્સાહન પુરુ પાડવા પ્રયાસો હાથ ધરવા સૂચના આપવામાં આવેલ છે. (૨) CBSE અને NCRERT ની પેટર્ન મુજબ પ્રશ્નપત્રના પરિરૂપ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. (૩) ધોરણ-૮ થી ૧૦ના વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન પ્રવાહ તરફ આકર્ષણ વધે તે માટે કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ છે. (૪) વિદ્યાર્થીઓ-વાલીઓને માર્ગદર્શન મળે તે માટેનું સાહિત્ય તૈયાર કરવામાં આવી રહેલ છે.

ધોળકા, બાવળા અને સાણંદ તાલુકાની શાળાઓમાં વીમા સહાય

૯૪૦૫ **શ્રી કાંતિલાલ રા. લકુમ(બાવળા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) ધોળકા, બાવળા, સાણંદ તાલુકામાં પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતાં બાળકોનો વીમો ઉતારવામાં આવેલ છે તેમાં તા. ૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ સુધીમાં અકસ્માતે કેટલા બાળકોનું મૃત્યુ થયું,

(૧)

ક્રમ	તાલુકો	અકસ્માતે મૃત્યુ પામેલ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા.
૧	બાવળા	૧૯
૨	ધોળકા	૧૩
૩	સાણંદ	૧૮
	કુલ	૫૦

(૪) તેમાંથી કેટલા બાળકોને વીમાની સહાય મળી,

(૨)

ક્રમ	તાલુકો	અકસ્માતે મૃત્યુ પામેલ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા.
૧	બાવળા	૫
૨	ધોળકા	૨
૩	સાણંદ	૧
	કુલ	૮

(૫) કેટલા બાળકોને વિમાની સહાય મળેલ નથી, અને

(૩) ચાર કેસો ચકાસણી હેઠળ છે, જ્યારે વીમા યોજનાની પાત્રતા ન ધરાવતા ૩૮ કેસો નામંજૂર થયેલ છે.

(૪) સહાય નહીં મળવાના કારણો શું ?

(૪) -કુદરતી મૃત્યુ થવાથી.
-પોસ્ટ મોર્ટમ રીપોર્ટ રજૂ ન કરવાને કારણે.
-એફ.આઈ.આર.ની નકલ સામેલ ન હોવાને કારણે.
-કંપની દ્વારા વિદ્યાર્થીના ઘરે રૂબરૂ ચકાસણી કરતાં મૃત્યુ અકસ્માતે થયેલ ન હોવાને કારણે.

સિમેન્ટ કંપની પાસેથી વેચાણવેરાની બાકી વસુલાત

૮૪૪૨**શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ(સોમનાથ) :માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) રાજ્યમાં કઈ કઈ સિમેન્ટ કંપની પાસેથી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ની સ્થિતિએ વેચાણવેરા પેટે કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી છે,

(૧) પત્રક મુજબ.

(૨) બાકી વસુલાત સમયસર નહીં કરવાના કારણો શાં છે, અને

(૨) બી.આઈ.એફ.આર.સીક ઈન્ડ. એકટ હેઠળ માંદા એકમો હોવાથી, વિવાદ તથા વેચાણવેરા પંચ સમક્ષ અપીલમાં હોવાથી ફડચામાં ગયેલ હોવાથી, ધંધો બંધ હોવાથી, બી.આઈ.એફ.આર. સીક ઈન્ડ.ના કેસમાં એ.એ.આઈ.એફ.આર.નો એવોર્ડ હોવાથી, સી.ડી.આર. પેકેજ હોવાથી, તેમજ રીફંડનો દાવો વિચારણા હેઠળ હોવાથી.

(૩) તે કયાં સુધીમાં વસુલ કરી લેવામાં આવશે?

(૩) શકય તેટલુ વહેલા

પત્રક

એકમનું નામ	બાકી રકમ રૂા. લાખમાં
એસોસીએટેડ સીમેન્ટ કું.	૭.૧૫
એલ.એન્ડ ટી.	૨૩.૧૬
કાશી વિશ્વનાથ સિમેન્ટ	૪.૮૭
બાલારામ સિમેન્ટ	૨૨૧૫.૩૭
રાધાકિશન સિમેન્ટ	૨૧૫.૯૬
સોમાની સિમેન્ટ કંપની	૭૭૩.૨૧
મહાકાળી સિમેન્ટ	૧૫.૨૭
પંચમહાલ સિમેન્ટ કંપની લી.	૮૪૭.૯૦
સેવાલીયા સિમેન્ટ વર્કસ	૪૫૩.૩૮
વી. કી. સિમેન્ટ પ્રા.લી.	૪૨.૮૯
સંદીપ સિમેન્ટ પ્રા. લી.	૮૬.૬૬
અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લી.	૬૪૨૭.૦૭
ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ લી.	૩૪૪.૪૩
ગજ અંબુજા સિમેન્ટ કંપની	૧૧૪૦.૫૦
ગુજરાત હાઈટેક ઈન્ડ.	૫૦૪.૭૦
ગુજરાત સિધ્ધિ સિમેન્ટ કંપની	૯૯૬૧.૯૪
કામદાર સિમેન્ટ કંપની	૧૨૧.૧૮
સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લી.	૪૬૯૭.૮૧
એચ. એમ. પી સિમેન્ટ કંપની	૪૪૫૯.૦૭
ગુજરાત હિમાલીયા સિમેન્ટ કંપની	૧૩૧.૮૫
દિગ્વીજય સિમેન્ટ કંપની	૬૪૯૪.૦૦
અજમેરા સિમેન્ટ પ્રા. લી.	૩.૭૦
સરદાર સિમેન્ટ પ્રા. લી.	૪૩૫.૬૩
કાંગારૂ સિમેન્ટ પ્રા. લી.	૧૪.૦૨
પટેલ એન્ડ લાલકા સિમેન્ટ લી.	૮.૦૪
સુવિન સિમેન્ટ પ્રા. લી.	૧૧૯.૪૫
ગાયત્રી સિમેન્ટ એન્ડ કેમીકલ	૩.૭૧
શકિત સિમેન્ટ	૧.૩૫
જયુપીટર સિમેન્ટ કંપની	૬૫૮.૦૦
દ્વારકા સિમેન્ટ	૨૮.૦૦

બાળકોની વિમા સુરક્ષાની યોજના અંગે

૮૬૮૯ **શ્રી ભૂપેન્દ્ર ગ. લાખાવાલા(વડોદરા શહેર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧)બાળકોની વિમા સુરક્ષા માટે સરકારે કોઈ યોજના હાથ ધરેલ છે કે કેમ,	(૨) હા જી,
(૨)જો, હા, તો આ યોજનાની વિગતો શું છે, અને	(૨) રાજ્યના પ્રાથમિક/માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને અકસ્માતથી થતાં અવસાન માટે વીમા રક્ષણ આપવા અંગેની યોજના વિદ્યાદીપ વીમા યોજના તરીકે ઓળખાય છે. જેમાં અકસ્માતથી અવસાન પામતાં પ્રાથમિક/આશ્રમ શાળાના કિસ્સામાં રૂા. ૨૫,૦૦૦/- અને માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક કિસ્સામાં રૂા. ૫૦,૦૦૦/- તેમના વારસદારોને આપવામાં આવે છે.
(૩)સન ૨૦૦૪ના વર્ષમાં કેટલા બાળકોને આ યોજના હેઠળ વિમાનો લાભ આપવા આયોજન કરેલ છે ?	(૩) પ્રાથમિક/આશ્રમ શાળાના ૮૫ લાખ માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાના ૨૯ લાખ કુલ ૧૧૪ લાખ

લખતર ખાતેની ફાર્મસી કોલેજ પુનઃ શરૂ કરવાનું આયોજન

૮૯૫૮ **શ્રી ધીરૂભાઈ હ. ગજેરા(સુરત શહેર (ઉત્તર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) લખતર ખાતેની ફાર્મસી કોલેજ કયારથી અને કયા કારણે બંધ છે,	(૧) લખતર ખાતેની ફાર્મસી કોલેજ વર્ષ ૨૦૦૧ ના જાન્યુઆરી માસ દરમ્યાન આવેલ ભુકંપના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થતાં વર્ષ ૨૦૦૨-૦૩ થી બંધ થયેલ છે.
(૨) આ કોલેજ પુનઃ શરૂ કરવા રાજ્ય સરકારે શું પગલાં લીધા, અને	(૨) આ કોલેજના શૈક્ષણિક, વહિવટી તથા વિદ્યાર્થીઓ માટેની હોસ્ટેલના મકાનો ભુકંપના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થતાં માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા બિન વપરાશી જાહેર કરવામાં આવતાં સમગ્ર સંકુલના મકાનો રિટ્રોફીટીંગ, પુનઃ બાંધકામ તથા નાના મોટા મરામતના કામો ગુજરાત રાજ્ય આપત્તિ નિવારણ સંસ્થા (ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી) દ્વારા માર્ગ અને મકાન વિભાગના સહયોગમાં રહી રૂા. ૪૨.૬૦ લાખના પુર્ણ કરવામાં આવ્યા છે.
(૩) તે કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે ?	(૩) આ કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે સને ૨૦૦૩-૦૪થી રાજકોટ સ્થિત બી.કે. મોદી સરકારી ફાર્મસી કોલેજ ખાતે પ્રથમ તથા દ્વિતિય વર્ષના વિદ્યાર્થીઓના સ્થળાંતર દ્વારા અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવાની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. જુન-૨૦૦૫થી લખતર ખાતે કોલેજ ચાલુ થશે.

વિજ્ઞાનપ્રવાહનું ઓછું મેરીટ હોવાથી વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંકમાં થતા અન્યાય અંગે

૮૨૩૫ **શ્રી વજુભાઈ પ. ડોડિયા(વિરમગામ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પી.ટી.સી. પ્રવેશમાં વિજ્ઞાનપ્રવાહના ઉમેદવારો માટે ૩૦% બેઠકો અનામત રાખવામાં આવેલ છે. આ ઉમેદવારો પી.ટી.સી. થતાં વિદ્યાસહાયકની ભરતીમાં આવી જોગવાઈ ન હોવાથી વિજ્ઞાનપ્રવાહનું મેરીટ ઓછું થતાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંકમાં અન્યાય થાય છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે ખરી,	(૧) પ્રવેશ અને ભરતી એ બંને બાબતો અલગ હોવાથી અન્યાયનો પ્રશ્ન રહેતો નથી.
(૨) જો હા, તો આ માટે સરકાર કોઈ વિચારણા કરવા માંગે છે કે કેમ, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) જો હા, તો કેટલા સમય સુધીમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શહેરા અને લુણાવાડા તાલુકામાં પેન્શનરોના પડતર કેસો

૮૯૬૪ **શ્રી જેઠાભાઈ ઘે. ભરવાડ(શહેરા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં શહેરા અને લુણાવાડા તાલુકાના કેટલા પેન્શનરોની અરજીઓ તા. ૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ પેન્ડીંગમાં છે, અને	(૧) કોઈપણ અરજી પેન્ડીંગ નથી.
(૨) પેન્ડીંગ અરજીઓનો નિકાલ કયારે કરવામાં આવનાર છે ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શાળાના નબળા વિદ્યાર્થીઓને સારૂ શિક્ષણ આપવા અંગે

૯૪૨૯ **શ્રીમતી રમીલાબેન બે. બારા(ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પ્રાથમિક શાળાઓમાં વાંચન લેખન અને ગણનામાં નબળા વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારૂ શિક્ષણ આપવા કોઇ યોજના કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા જી
(૨) જો હા તો તેનું શું પરિણામ આવ્યુ ?	(૨) સમગ્ર રાજ્યમાં ગતસાલ થયેલ વાંચન, લેખન, ગણન ક્ષમતા અભિવૃદ્ધી અભિયાન કાર્યક્રમમાં ૯,૭૧,૨૪૧ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ૭,૫૦,૩૮ વિદ્યાર્થીઓમાં વાંચન, લેખન, ગણનની કક્ષામાં સુધારો થયો છે એટલે કે, સરેરાશ ૭૭ ટકા બાળકોમાં સિધ્ધિ જોવા મળી છે.

રાજ્યમાં સંપૂર્ણ સાક્ષરતા અભિયાન હેઠળના જીલ્લાઓ

૮૭૧૩ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી(ભાવનગર શહેર (ઉત્તર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં ૧૦૦% સાક્ષર કેટલા જીલ્લાઓ છે, કયા કયા,	(૧) શૂન્ય
(૨) આ જીલ્લાઓમાં બી.એડ. અને પી.ટી.સી.ના વિદ્યાર્થીઓને સાક્ષરતા અભિયાનનું કામ સોંપવામાં આવેલ કે કેમ, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) ૧૦૦% સાક્ષર જીલ્લાઓમાં પણ સાક્ષરતા અભિયાનની જરૂર કેમ ઉભી થઇ ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

યોગાસનની પ્રવૃત્તિના પ્રચાર પ્રસાર અંગે

૮૬૫૨ **શ્રી સી. ડી. પટેલ(પેટલાદ) : માનનીય સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બાળકો અને યુવાનોમાં યોગાસન પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે રૂચિ કેળવાય તે માટે સરકારે કોઇ આયોજન કરેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો યોગના પ્રચાર પ્રસાર અર્થે સરકારે શું પગલાં લીધા?	(૨) રાજ્યના તમામ જીલ્લાઓમાં યોગ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રો તા. ૧/૮/૨૦૦૪થી કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે તદુપરાંત યોગાસન તાલીમ શીબીર દ્વારા અને જિલ્લા તથા રાજ્ય કક્ષાની યોગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરી આમ જનતા સમક્ષ નિદર્શન દ્વારા યોગનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં આવે છે.

કન્યા કેળવણી રથયાત્રામાં થયેલ ખર્ચ અને મળેલ સૂચનો

૯૪૨૪**શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી(દાંતા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧)સને ૨૦૦૪ના જૂન માસમાં રાજ્યભરમાં કન્યા કેળવણી રથયાત્રા ફેરવવા પાછળ થયેલ ખર્ચની વિગતો શું છે,	(૧) કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અંગેનો ખર્ચ લોક સહયોગથી કરેલ છે.
(૨) રથયાત્રાની સમાપ્તિ બાદ, કન્યા કેળવણીને ઉત્તેજન આપવા સરકારને કુલ કેટલાં સૂચનો મળ્યા, અને	(૨) શિક્ષણને સ્પર્શતા કુલ ૬૮ સૂચનો મળ્યા છે, જેમાં કન્યા કેળવણીને ઉત્તેજન માટેનાં ૯ સૂચનોનો સમાવેશ થાય છે.
(૩) મળેલ સૂચનો પૈકી સરકારે કયા સૂચનનો અમલ કયારથી કર્યો છે ?	(૩) મહદઅંશે તમામ સૂચનો અમલીકરણ હેઠળ છે.

પવિત્ર યાત્રાધામ પાલીતાણા પાછળ કરેલ ખર્ચ અંગે

૮૭૪૯ **શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા(પાલીતાણા):માનનીય યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
પવિત્ર યાત્રાધામ પાલીતાણા અંગે તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં યાત્રાધામ વિકાસમાં કુલ કેટલું ખર્ચ કરવામાં આવ્યું ?	રૂા. ૧,૦૧,૫૩૭.૦૦

રાજ્યની ખાનગી શાળા/કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લેવાતી વધારે ફી

૮૬૨૯ડૉ.**જીતેન્દ્રભાઈ બા. પટેલ(સાબરમતી) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગુજરાત રાજ્યમાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળા/કોલેજોને મંજૂરી આપવામાં આવે છે. તે મુજબ શાળા/કોલેજો ફી ઉઘરાવે છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો ના, તો વધારાની ઉઘરાવેલ ફી વિદ્યાર્થીઓને કેટલાં સમયમાં પરત કરશે, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) મંજૂરીની શરતો મુજબ શાળા કોલેજોમાં અપૂરતી સગવડો અપાય તો તે સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે ?	(૩) નિયમાનુસાર

તમાકુ યુક્ત ગુટખા પાઉચ પેકિંગ ઉપર સુખ સુવિધા કરની આવક

૮૩૧૭**શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ(વાગરા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
સને ૨૦૦૪ના વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં તમાકુયુક્ત ગુટખા પાઉચના વેચાણ ઉપર કેટલી સુખ સુવિધા કરની આવક રાજ્ય સરકારને મળી ?	રૂા. ૪૦,૯૧,૮૪,૭૪૯

સતલાસણા તાલુકા મથકે કોર્ટની સુવિધા

૯૩૯૬ **શ્રીમતી રમીલાબેન રા. દેસાઈ(ખેરાલુ) : માનનીય ન્યાયતંત્ર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં નવનિર્મિત તાલુકા મથકોએ તાલુકા કોર્ટની સવલત આપવા સરકારે વિચારેલ છે તે સાચુ છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો સતલાસણા તાલુકાને કોર્ટની સુવિધા ક્યારે આપવામાં આવશે ?	(૨) અંદાજપત્રમાં નાણાંકીય જોગવાઇ અને માળખાગત સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થયેથી.

ખાનગી શાળાઓમાં કન્યાઓ પાસેથી લેવાતી ગેરકાનૂની ફી

૮૫૨૫ **શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ(લીંબડી) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કન્યા કેળવણી મફત આપવાની યોજના અમલમાં છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો ખાનગી શાળાઓમાં કન્યાઓની ફી લેવાય છે તેના શું કારણો છે,	(૨) ગ્રાન્ટેડ ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓ તેમજ માધ્યમિક શાળાઓમાં કન્યાઓ પાસેથી ફી લેવામાં આવતી નથી.
(૩) સુરેન્દ્રનગરની ખાનગી શાળાઓમાં કન્યાઓ પાસેથી કેટલી ફી વર્ષ દરમિયાન લેવાઇ છે,	(૩) ગ્રાન્ટેડ ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓ તેમજ માધ્યમિક શાળાઓમાં કન્યાઓની ફી લેવામાં આવતી નથી.
(૪) આ ફી રાજ્ય સરકાર ચૂકવવા માંગે છે કે કેમ, અને	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૫) જો હા, તો તેનાં શું કારણો છે ?	(૫) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શાળાઓને મોકલેલ પ્રોગ્રામમાં ભૂલો

૮૯૪૯ **શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી(ડીસા) : શ્રી ગોવાભાઇ રબારી** (ડીસા) : **માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યના માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ચાલુ સાલે નવા શૈક્ષણિક વર્ષની શરૂઆતમાં એકસૂત્રતા જળવાય તે માટે શાળાઓને મોકલેલ પ્રોગ્રામ કેલેન્ડરમાં અસંખ્ય ભૂલો છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે,	(૧) માત્ર ત્રણ ભૂલો ધ્યાને આવેલ છે.
(૨) જો હા, તો આવી કઇ કઇ મોટી ભૂલો સરકારના ધ્યાને આવી, અને	(૨) કોઇ મોટી ભૂલ ધ્યાને આવેલ નથી.
(૩) આ માટે જવાબદારો સામે સરકારે શાં પગલાં લીધાં ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ભરૂચ જિલ્લામાં બોગસ પ્રમાણપત્રોને આધારે નોકરી કરતા શિક્ષકો

૯૪૪૦**શ્રી છોટુભાઈ અ. વસાવા(ઝગડિયા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ભરૂચ જિલ્લામાં બોગસ પ્રમાણપત્રો કૌભાંડ અંગે કયા ગામની કઈ કઈ શાળાઓમાં સન-૨૦૦૪માં ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું, અને	(૧) * પત્રક-ક-મુજબ
(૨) કેટલા બોગસ પ્રમાણપત્રો અંગેના શિક્ષકો પકડવામાં આવ્યા,	(૨) ૭
(૩) આ બોગસ પ્રમાણપત્ર ધારણ કરનાર શિક્ષકોને શાળાઓમાંથી સરકાર છૂટા કરવા માગે છે કે કેમ ?	(૩) છૂટા કરી દેવામાં આવેલ છે. **(* પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)**

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક સુવિધાવાળી પ્રાથમિક શાળાઓ

૮૩૩૯ **શ્રી દોલતભાઈ પરમાર(વડગામ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૧-૧-૦૩થી તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કેટલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં વીજળી, પાણી, શૌચાલય જેવી પ્રાથમિક સગવડો પૂરી પાડવામાં આવી છે,	(૧) વીજળી પીવાનું પાણી શૌચાલય સેનીટેશન કમ્પાઉન્ડ વોલ કુલ : ૦ ૧૯ ૩૪ ૪૦ શાળાઓ
(૨) હજુ કેટલી પ્રાથમિક શાળાઓ પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત છે, અને	(૨) વીજળી પીવાનું પાણી શૌચાલય સેનીટેશન કમ્પાઉન્ડ વોલ કુલ : ૭૫૦ ૫૪૯ સંડાસ ૭૫૨ શાળાઓ ૧૧૫૫ બાથરૂમ ૧૯૩૮
(૩) સરકાર કેટલા સમયમાં વંચિત પ્રાથમિક શાળાઓને સુવિધાઓ પૂરી પાડશે ?	(૩) પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ વિકસાવવા સારૂ આયોજન યોજના હેઠળ રાજ્ય કક્ષાએ થતા આયોજન અનુસાર તબક્કાવાર શાળાઓને આવરી લેવામાં આવશે.

જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકાની રમત-ગમતના મેદાનોથી વંચિત શાળાઓ

૮૨૧૮ શ્રીમતી જસુબેન સ. કોરાટ(જેતપુર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં કઈ કઈ પ્રાથમિક તથા માધ્યમિક શાળાઓ પાસે રમત-ગમતના મેદાનો ડિસેમ્બર-૦૪ ની સ્થિતિએ નથી, અને	(૧) પત્રક-અ મુજબ
(૨) તે માટે સરકારે શાં પગલાં ભર્યા છે ?	(૨) ગ્રામપંચાયતની ગામતળની જમીન ધ્યાને લઈ ઉપલબ્ધ ખુલ્લા મેદાનોમાં હાલ રમત ગમતની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે. તેમજ ગ્રામ પંચાયત અને રેવન્યુ અધિકારીશ્રી સાથે પરામર્શ કરીને પ્રશ્નના હલ માટે આયોજન હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ માધ્યમિક શાળાઓને મેદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા સૂચના આપેલ છે.

પત્રક-અ

જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં જે પ્રાથમિક શાળાઓ પાસે રમત ગમતના મેદાનો ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ નથી તેવી પ્રાથમિક શાળાઓની યાદી

ક્રમ	તાલુકો	પ્રાથમિક શાળાનું નામ/ગામ
૧	જેતપુર	૧. ખીરસરા કન્યા શાળા ૨. પેઢલા કન્યા પ્રા. શાળા ૩. મેવાસલા કન્યા પ્રા. શાળા ૪. જેતલસર જં. કન્યા પ્રા. શાળા ૫. જેતલસર ગ્રામ કુમાર પ્રા. શાળા

		૬.	જાંબુડી પ્રા. શાળા
૨	ગોંડલ	૧.	ખારાવડી પ્રાથમિક શાળા, ખારાવડી
		૨.	બાંદરા પ્રા. શાળા, બાંદરા
		૩.	કંટોલીયા પ્રા. શાળા, કંટોલિયા
		૪.	કમરકોટડા પ્રા. શાળા, કમરકોટડા
		૫.	કમઢીયા પ્રા. શાળા, કમઢીયા
		૬.	દેરડી કુંભાજી કન્યા પ્રા. શાળા, દેરડી
		૭.	ઉંધા ટીંબી પ્રા. શાળા, ઉંધા ટીંબી
		૮.	રાણસીકી પ્રા. શાળા, રાણસીકી
		૯.	વાવડી પ્રા. શાળા, તા. વાવડી
		૧૦.	પાટીદડ કુ. તા. શાળા, પાટીદડ
		૧૧.	ઓરડી પ્રા. શાળા નં. ૧, ઓરડી
		૧૨.	ઓરડી પ્રા. શાળા નં. ૨, ઓરડી
		૧૩.	પ્રાથમિક શાળા નં. ૨, ગોંડલ
		૧૪.	પ્રાથમિક શાળા નં. ૧૪, ગોંડલ
		૧૫.	પ્રાથમિક શાળા નં. ૪, ગોંડલ
		૧૬.	તક્ષશીલા પ્રા. શાળા એસ.આર.પી. ગૃપ, ગોંડલ
		૧૭.	ભંડારીયા પ્રા. શાળા, ભંડારીયા

માધ્યમિક શાળાઓ પાસે રમત-ગમતનું મેદાન નથી તેવી શાળાઓની યાદી

ક્રમ	તાલુકાનું નામ		માધ્યમિક શાળાનું નામ/ગામ
૧	જેતપુર	૧.	એ.એસ.વિનય મંદિર, મુ. આરબટીબડી, તા. જેતપુર
		૨.	શ્રી મોઘીબા ગર્લ્સ હાઈસ્કુલ, મુ. વીરપુર (નીગરામ)
		૩.	સરકાર હાઈસ્કુલ, અમરનગર, તા. જેતપુર
૨	ગોંડલ	૧.	શ્રીમતી કે. બી. બેરા કન્યા વિદ્યાલય, ગોંડલ
		૨.	નૂતન કન્યા વિદ્યાલય, ગોંડલ
		૩.	માધવ વિદ્યાલય, ગોંડલ
		૪.	ગોંડલ હાઈસ્કુલ, ગોંડલ
		૫.	નવજીવન હાઈસ્કુલ, ગોંડલ

ધો-૮ના પુસ્તકમાં રહી ગયેલી ક્ષતિ

૮૩૭૦ શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા(જમાલપુર): માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સને ૨૦૦૪ના વર્ષમાં ધો. ૮ના પુસ્તકોમાં રહી ગયેલી ક્ષતિઓ અને ભુલો અંગે કેન્દ્રના માનવ સંશોધન મંત્રાલયે તેની ગંભીર નોંધ લઈને રાજ્ય સરકાર પાસેથી સ્પષ્ટતા માગી હતી તે વાત સાચી છે	(૧) ના.

તે વાત સાચી છે,

(૨) જો હા, તો આ ભુલો કે ક્ષતિ કે ક્ષતિઓ કયા પ્રકારની હતી,	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) તેને સુધારવા માટે શું પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે, અને	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૪) આ ક્ષતિઓ માટે જવાબદાર લોકો સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે ?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કચ્છ જિલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ભરતી અને ઘટ

૯૨૨૫ **શ્રી ગોપાલભાઈ ગા. ઘુઆ(મુંદ્રા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં તા. ૩૧મી ડીસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં તાલુકા વાઈઝ કેટલા પ્રાથમિક શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવી,	(૧) પત્રક-અ મુજબ
(૨) કચ્છ જિલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની કેટલી ઘટ તાલુકાવાઈઝ છે, અને	(૨) પત્રક-બ મુજબ
(૩) આ ઘટ કેટલા સમયમાં પુરવામાં આવશે?	(૩) નવી જગ્યાઓ મંજૂર કર્યેથી ઘટ પુરી કરવામાં આવશે.

પત્રક-અ

કચ્છ જિલ્લામાં તાલુકાવાઈઝ પ્રાથમિક શિક્ષકોની ભરતી

ક્રમ	તાલુકો	ભરવામાં આવેલી જગ્યાઓ
૧	ભૂજ	૩૧૨
૨	માંડવી	૧૬૪
૩	મુંદ્રા	૧૦૭
૪	અંજાર	૧૨૯
૫	ગાંધીધામ	૧૭
૬	ભચાઉ	૧૨૬
૭	રાપર	૨૬૪
૮	નખત્રાણા	૨૧૨
૯	અબડાસા	૨૦૨

૧૦	લખપત	૧૫૫
	કુલ	૧૬૮૮

પત્રક-બ

ક્રમ	તાલુકો	ભરવામાં આવેલી જગ્યાઓ
૧	ભૂજ	૧૦
૨	માંડવી	૯
૩	મુંદ્રા	૩
૪	અંજાર	૩
૫	ગાંધીધામ	૨
૬	ભચાઉ	૭
૭	રાપર	૮
૮	નખત્રાણા	૬
૯	અબડાસા	૨
૧૦	લખપત	૧
	કુલ :-	૫૧

સિમેન્ટ કંપનીઓ પાસે વેચાણવેરા પેટે વસૂલ લેવાની બાકી રકમ

૮૫૬૧ **ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા(માંગરોળ)** : તા. ૨૭-૨-૨૦૦૩ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક ૧૨૫ (અગ્રતાક્રમ-૧૧) ના અનુસંધાને માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	જવાબ
તા. ૧-૪-૨૦૦૨ની સ્થિતિએ વેચાણવેરા પેટે વસુલ લેવાની બાકી રકમ પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલી રકમ વસુલ કરવામાં આવી છે ?	રૂા. ૪૮.૧૦ કરોડ

જુનાગઢ જિલ્લામાં આઈ.સી. ડી. એસ. બ્લોક ખાનગી સંસ્થાને સોંપવા અંગે

૮૨૫૦ **શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ(ઉના) : માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જુનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર આઈ.સી. ડી. એસ. બ્લોક ખાનગી સંસ્થાને સોંપવા સામે છેલ્લા આઠ માસમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલી રજુઆતો સરકારને મળી, અને	(૧) જુનાગઢ જિલ્લામાંથી તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં ૧૯ (ઓગણીસ) સંસ્થાઓની આંગણવાડીઓના સંચાલન માટે જુદાજુદા ઘટકમાં પૂર્ણ/ અંશતઃ ઘટકની ફાળવણી માટે રજૂઆતો મળેલ છે.
(૨) આવી આઈ.સી.ડી.એસ.બ્લોક ખાનગી સંસ્થાને સોંપવાના કારણો શાં છે ?	(૨) ભારત સરકારની માર્ગદર્શન નીતિ મુજબ બિન સરકારી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને આંગણવાડીના સંચાલનમાં સામેલ કરી શકાય છે.

રાજકોટ જિલ્લામાં વેચાણ ખાતાના દરોડા અંગે

૯૨૨૦ **શ્રી પ્રવિણભાઈ મો. માકડિયા(ઉપલેટા)** : : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં વેચાણવેરા ખાતા દ્વારા ૨૦૦૩ અને ૨૦૦૪ના વર્ષ દરમ્યાન તાલુકા વાઈઝ કેટલા દરોડા પાડવામાં આવ્યા, અને

જવાબ

(૧)

તાલુકા	**દરોડાની** ૨૦૦૩	**સંખ્યા** ૨૦૦૪
રાજકોટ	૭૮	૩૦૭
મોરબી	૪૨	૩૮
ટંકારા	૪	૯
ગોંડલ	૨૨	૮
જેતપુર	૧૧	૨
ધોરાજી	૭	૨
ઉપલેટા	૫	-
લોધીકા	૧	૬
જસદણ	૧	--
વાકાંનેર	૩	૨
કોટડાસાંગાલી	૪	૧૧
પડધરી	--	૨

(૨) દરોડા દરમ્યાન દંડની કેટલી રકમ વસુલ કરવામાં આવી ?

(૨) રૂા. ૬૪,૪૮,૫૦૫

રાજકોટ જિલ્લાના પેન્શનપાત્ર કર્મચારીઓને સમયસર પેન્શન ન ચૂકવવા અંગે

૮૦૯૫ **શ્રી મોહનભાઈ ક. કુંડારીયા(ટંકારા)** : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજકોટ જિલ્લાના કેટલા પેન્શનપાત્ર કર્ચારીઓને પેન્શન ચૂકવવામાં આવે છે,	(૧) ૧૮૬૩૪ પેન્શનરોને પેન્શન ચૂકવવામાં આવે છે.
(૨) મે-૨૦૦૨ થી ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલા પેન્શનપાત્ર કમર્ચારીઓને પેન્શન ચૂકવવાના હુકમો કરવામાં આવ્યા,	(૨) ૨૬૧૩ કર્મચારીઓને પેન્શન ચૂકવવાના હુકમો કરવામાં આવ્યા છે.
(૩) પેન્શન ચૂકવવામાં થયેલા વિલંબના કારણો કયા છે, અને	(૩) તિજારી કક્ષાએથી ચુકવણીમાં કોઈ વિલંબ નથી.
(૪) બાકી રહેતા કેસોનો નિકાલ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ગાંધીનગર જિલ્લાની શાળાઓમાં ગેરરીતિ અને અનિયમિતતાઓ

૯૩૯૪ **શ્રી જગદીશ ઠાકોર(દહેગામ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીએ ગાંધીનગર દ્વારા સને-૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષમાં ગાંધીનગર જિલ્લાની કેટલી શાળાની મુલાકાત લીધી,	(૧) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ જાતે લીધેલ મુલાકાતો-૫૬
(૨) આ મુલાકાતો દરમ્યાન કઈ કઈ ગેરરિતી તથા અનિયમિતતાઓ જાણવા મળી, અને	(૨) શાળાઓમાં નીચે મુજબ અનિયમિતતાઓ જોવા મળેલ છે. અ. શાળા લાયક મકાનોનો અભાવ બ. પર્યાપ્ત શૈક્ષણિક સુવિધાઓનો અભાવ ક. શૈક્ષણિક અનિયમિતતાઓ
(૩) જવાબદારો ઉપર શું પગલાં લેવાયા ?	(૩) લેવામાં આવેલ પગલાં શાળા લાયક મકાન ન હોય તેવી શાળાઓનું મકાન ભાડું ચૂકવવાનું બંધ કરેલ છે. ૧. શાળાનું શૈક્ષણિક સ્તર સુધારવા માટે શૈક્ષણિક સૂચનો કરેલ અને તેનું સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવ્યું. ૨. શાળાની ભૌતિક સુવિધાઓની અધુરાશ દુર કરવા શાળાઓની સુનાવણી કરવામાં આવી, અને રેકર્ડ આધારિત અનિયમિતતાઓ દુર કરવાની તાકીદ કરવામાં આવી. ૩. ધો-૧૦-૧૨ નું પરિણામ ઉંચું લાવવા જરુરી સૂચનો કરવામાં આવ્યા. ૪. ૩૦ ટકાથી ઓછું પરિણામ ધરાવતી શાળાઓને પરિણામ સુધારવા સૂચનો કરવામાં આવ્યા. ૫. જિલ્લાની વિજ્ઞાન પ્રવાહની શાળાઓને વિદ્યાર્થી સંખ્યા વધારવા સૂચનો કરવામાં આવ્યા. ૬. સતત નીચું પરિણામ લાવતી શાળાઓના શિક્ષકોના ઈજાફા સ્થગીત કરવામાં આવ્યા/રોકવામાં આવ્યા.

કન્યા કેળવણી નિધિમાં જમા થયેલ ભંડોળ

૮૫૯૫ **શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ(માંડલ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન		જવાબ
(૧) કન્યા કેળવણીને ઉત્તેજન આપવા માટે રાજ્ય સરકારે કન્યા કેળવણી નિધિની રચના કરી છે; તેના ઉદ્દેશો કયા છે,		(૧) પત્રક-અ મુજબ.
(૪) આવી નિધિ અગાઉ રચાઇ હતી કે કેમ, અને		(૫) ના જી,
(૫) ડીસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ આ નિધિમાં કેટલું ભંડોળ જમા થયેલું છે ?		(૬) રૂા. ૨,૫૪,૦૬,૩૭૮/-

પત્રક-અ

કન્યા કેળવણી નિધિની રચના કરવાના ઉદ્દેશો

૧ રાજ્યમાં કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન આપવું અને સ્ત્રી સાક્ષરતાનો દર વધારવો.

૨. રાજ્યની કોઇપણ પ્રકારની શાળાઓની વિદ્યાર્થીનીઓને શિક્ષણની સુવિધાઓ પૂરી પાડવી અને બાળાઓના શાળા છોડી જવાના દરમા ઘટાડો કરવો.

૩. ૧૦૦ ટકા નામાંકન અને કન્યાઓના શાળા પ્રવેશ માટે શાળા પ્રવેશોત્સવની ઉજવણી કરવી અને ધો. ૧માં પ્રવેશ મેળવતી કન્યાને વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ આપવા.

૪. વિદ્યાર્થીનીઓને નાણાંકીય સહાય કે ઇનામ પુરસ્કાર આપવા.

૫. કન્યા કેળવણી સબંધિત કાર્યક્રમો માટે યોગ્ય તે વ્યક્તિ કે સંસ્થાને અનુદાન કે સહાય આપવી.

૬. વિદ્યાર્થીનીઓ માટે શાળાઓમાં સેનીટેશન સુવિધા પુરી પાડવી, કોઇપણ પ્રકારના યાંત્રિક કે વિજાણું સાધનો પુરા પાડવા, ફર્નિચરની સુવિધા પુરી પાડવી.

૭. શાળાઓમાં કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન મળે તેવા બાંધકામો કરવા તથા નિધિ હસ્તકની અસ્કયામતો યોગ્ય તે સરકારી કે બિનસરકારી સંગઠન/સંસ્થાને કન્યા કેળવણી માટે ઉપલબ્ધ કરાવવી.

૮. વિદ્યાર્થીનીઓને પુસ્તકો, નોટબુકો, ઈતર સાહિત્યના પુસ્તકો, ફી, ગણવેશ, તબીબી સહાય અને લોન શિષ્યવૃત્તિ કે તે પ્રકારની અન્ય સવલતો પુરી પાડવી.

૯. વિદ્યાર્થીનીઓના સામાજીક અને શૈક્ષણિક વિકાસને ઉત્તેજન આપે તેવી સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવી.

૧૦. વિદ્યાર્થીનીઓના સાંસ્કૃત્તિક સાહિત્યક, અભ્યાસિક, સ્પર્ધાત્મક ગુણોના વિકાસ માટેના કાર્યક્રમો સ્પર્ધાઓ આયોજીત કરવા.

૧૧. નિધિની વહીવટી/હિસાબી કામગીરી માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી ખરીદવી.

૧૨. નિધિને સબંધિત કાનૂની પ્રવૃત્તિ કે કાર્યવાહી કરવી.

જામનગર જિલ્લામાં વડાપ્રધાનશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી બનાવેલ શાળાઓ

૮૭૮૫ **શ્રી મુળુભાઈ હ. બેરા(ભાણવડ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન		જવાબ

(૧) જામનગર જિલ્લામાં ભૂકંપ બાદ તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં વડાપ્રધાનશ્રીની ગ્રાંટમાંથી કેટલી માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓના બિલ્ડીંગ બનાવવામાં આવ્યા, અને		(૧) વડાપ્રધાનશ્રી તરફથી કોઇ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી નથી, પરંતુ વડાપ્રધાનશ્રી રાષ્ટ્રીય રાહત કોષ પ્રોજેકટ અંતર્ગત જામનગર જિલ્લામાં ૨૧ શાળાઓના બિલ્ડીંગ બનાવવામાં આવેલ છે.
(૨) આ બિલ્ડીંગો માટે કેટલી રકમ વાપરવામાં આવી ?		(૨) રૂા. ૨૧૫૮.૩૪ લાખ.

પવિત્ર યાત્રાધામોમાં દારૂ-ઈંડા-માંસ-મરઘીના વેચાણનો પ્રતિબંધ

૮૦૫૯ **શ્રી ગોરધનભાઈ પ્રા. ઝડફિયા(રખિયાલ) : માનનીય યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યના પવિત્ર યાત્રાધામોમાં દારૂ-ઈંડા-માંસ-મરઘીના વેચાણ પરનો પ્રતિબંધ કરવા માટે કોઈ વિચારણા કરી છે કે કેમ, અને	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો આ પ્રતિબંધ લગાવવાનો અમલ કયારથી કરવામાં આવનાર છે ?	(૨) સંબંધિત વિભાગોના પરામર્શમાં આ અંગેના જરૂરી તમામ પાસાઓ અને કાયદાકીય પરિસ્થિતિ/જોગવાઈઓનો અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

રાજ્ય સરકારનું આંતરિક અને બાહ્ય દેવું

૮૮૦૯**શ્રી પોપટભાઈ સ. જીંજરિયા(ચોટીલા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકારનું આંતરિક અને બાહ્ય દેવુ કેટલું છે, અને	(૧) અંદાજીત રૂા. ૫૬,૪૩૮ કરોડ.
(૨) રાજ્યનું દેવું ઘટાડવા સરકારે શું આયોજન કરેલ છે ?	(૨) બિન-વિકાસલક્ષી ખર્ચ અને આયોજન બહારના મહેસુલ ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખી મહેસુલી ખાદ્ય ઘટાડવામાં આવી છે. જેથી દેવા પર નિર્ભર રહેવું ન પડે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર અને દસાડા તાલુકામાં પ્રાથમિક શિક્ષકો દ્વારા હેડકવાર્ટરમાં ન રહેવા બાબત

૮૦૭૬ **શ્રી મનહરલાલ મ. મકવાણા(દસાડા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ની સ્થતિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં લખતર અને દસાડા તાલુકામાં પ્રાથમિક શાળાના કેટલા શિક્ષકો ફરજ બજાવે છે;	(૧) તાલુકો શિક્ષકો લખતર ૩૩૪ દસાડા ૭૩૫

(૨) તે પૈકી કેટલા શિક્ષકો નોકરીના સ્થળે રહે છે, અને	(૨) શિક્ષકોને તેમની ફરજના સ્થળ ઉપર રહેવા માટેની સૂચના જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ છે.
(૩) સરકારના પ્રવર્તમાન નિયમો મુજબ હેડકવાર્ટસમાં શિક્ષકોએ રહેવાનું હોય તેનું પાલન ન કરતા કેટલા શિક્ષકો સામે છેલ્લા એક વર્ષમાં ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ સુધીમાં પગલાંઓ લેવામાં આવ્યા ?	(૩) કોઈ ફરિયાદ મળવામાં નથી.

આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વિધવા મહિલા લાભાર્થીઓ

૮૬૫૭**શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધી. પરમાર(ભાદરણ) : શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સન ૨૦૦૪ના વર્ષમાં આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વિધવા સહાય પેન્શન યોજના અન્વયે કેટલા લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યા;	(૧)

તાલુકો	લાભાર્થીઓ
ઉમરેઠ	૩૯૦
આંકલાવ	૨૭૧
આણંદ	૧૬૪૨
તારાપુર	૮૬
બોરસદ	૫૮૨
પેટલાદ	૩૯૭
ખંભાત	૫૭૯
સોજીત્રા	૧૮૩
કુલ...	**૪૧૩૦**

(૨) તે અન્વયે કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને	(૨) રૂા. ૪૪૩.૦૯ લાખ.
(૩) આવી સહાયો ઘણા સમયથી ચુકવાતી નથી તે અન્વયે સરકારે શી કાર્યવાહી કરી ?	(૩) લાભાર્થીઓના પોસ્ટલ બચત ખાતાઓમાં સહાયની રકમ નિયમિતપણે દર માસે જમા કરવામાં આવી જ રહી છે.

રાજ્યની શાળાઓમાં શિક્ષકો અને ઓરડાઓની ઘટ

૮૨૮૮ **શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિધ્ધપુર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) વર્ષ ૨૦૦૪ના અંતે રાજ્યમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ કેટલી આવેલી છે;	(૧) ૩૧૭૧૦ પ્રાથમિક શાળાઓ અને ૭૭૫૫ માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ.
(૨) આ શાળાઓમાં શિક્ષકો અને ઓરડાઓ કેટલા છે, અને	(૨) પ્રાથમિક વિભાગમાં ૧૭૨૬૨૦ શિક્ષકો અને ૧૬૦૬૫૨ ઓરડાઓ તથા માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં ૭૬૨૨૨ શિક્ષકો છે.

(૩) ડિસેમ્બર, ૦૪ની સ્થિતિએ આ શાળાઓમાં શિક્ષકો અને ઓરડાની ઘટ કેટલી છે ?	(૩) પ્રાથમિક વિભાગમાં ૧૯૪૨ શિક્ષકો અને ૨૨૭૭૯ ઓરડાઓની ઘટ છે. જ્યારે માધ્યમિક વિભાગમાં ૨૩૪૮ શિક્ષકોની ઘટ છે. માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ઓરડાઓની ઘટનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી, કારણ કે ભૌતિક સુવિધા/વર્ગખંડો ઉપલબ્ધ હોય તેની ખાતરી કર્યા બાદ શાળાની નોંધણી કરવામાં આવે છે.

રાજ્યના ભૂકંપગ્રસ્ત વિસ્તાર માટે જમા થયેલ રકમ અને વ્યાજ

૯૨૧૮ **શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ(રાપર) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં ભૂકંપગ્રસ્ત વિસ્તારમાં રાહત કાર્યો તથા પુનઃવસન અને માળખાકીય સુવિધા માટે રાજ્યની તિજોરીમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં ગ્રાન્ટ, લોન દ્વારા કેટ કેટલી રકમ જમા થઈ, અને	(૧) રાજ્યમાં ભૂકંપગ્રસ્ત વિસ્તારમાં રાહત કાર્યો તથા પુનઃવસન અને માળખાકીય સુવિધા માટે રાજ્યની તિજોરીમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં ગ્રાન્ટ, પેટે રૂા.૩૫૩૯.૮૮ કરોડ તેમજ લોન પેટે રૂા. ૪૧૩૭.૮૩ કરોડ જમા થયેલ છે.
(૨) આ રકમમાંથી વણ ખર્ચાયેલી રકમ પર કેટલું વ્યાજ જમા કરવામાં આવ્યું ?	(૨) વણ ખર્ચાયેલી રકમ પર ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી ખાતે જમા થયેલ વ્યાજની રકમ રૂા. ૨૯ કરોડ સરકારના ખાતે જમા કરવામાં આવેલ છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે આશ્રિતોને રહેમરાહે નોકરીની અરજીઓ

૯૪૫૩ **શ્રી ગોવિંદભાઈ વ. પરમાર(તલાલા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં તા. ૩૦-૧૧-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં શિક્ષણ ખાતામાં અવસાન પામેલ કર્મચારીઓનાં આશ્રિતોને રહેમરાહે નોકરી માટે કેટલી અરજીઓ આવી છે;	(૧) ૨૯૨.
(૨) તે પૈકી જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓમાં રહેમરાહે નોકરીનાં હુકમો કરેલ છે, અને	(૨) ૦૬. (મેંદરાડા-૧, માંગરોળ-૧, માળિયા હાટીના-૧, જૂનાગઢ-૧, વિસાવદર-૧, વેરાવળ-૧).
(૩) બાકી અરજીના હુકમો કેટલા સમયમાં કરવામાં આવશે ?	(૩) શકય તેટલા ઝડપથી.

વડોદરા જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર હસ્તકનાં દેવસ્થાનો

૮૭૩૨ **શ્રી દિલુભા ટે. ચુડાસમા(વડોદરા (ગ્રામ્ય) : માનનીય દેવસ્થાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા જિલ્લામાં સરકાર હસ્તક્ના દેવસ્થાનો કેટલા;	(૧) ૯૫ દેવસ્થાનો
(૨) તે પૈકી, વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કેટલા;	(૨) ૪ દેવસ્થાનો
(૩) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ કેટલાં દેવસ્થાનો મરામત માંગી લે તેવા છે, અને	(૩) એક પણ નહીં.
(૪) આ અંગે કરાયેલ આયોજનની વિગતો શું છે?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કરજણ અને શિનોર તાલુકાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ

૯૪૧૪ **શ્રી નરેશકુમાર મી. કનોડિયા(કરજણ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કરજણ-શિનોર તાલુકામાં ડીસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ પ્રાથમિક શાળામાં કુલ વિદ્યાર્થીઓ કરતાં બેસવા માટે ઓરડાઓની સંખ્યા ઓછી છે, તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) સરકારશ્રી આ ઘટ પૂરી કરવા માંગે છે કે કેમ?	(૨) હા, જી

મહિલા આયોગની રચના

૯૪૦૨ **શ્રી શીવજીભાઈ ક. આહીર(ભૂજ) : માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગુજરાત રાજ્યમાં રાજ્ય કક્ષાએ મહિલા આયોગની રચના કરવા સને ૨૦૦૧ની સાલમાં સૈધ્ધાંતિક સ્વીકાર કરી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો તે હકિકત સાચી છે,	(૧) (૨), (૩) અને (૪) સરકારશ્રીએ તા. ૧૬-૨-૦૫ના રોજ ગુજરાત મહિલા આયોગની રચના કરતું જાહેરનામું બહાર પાડેલ છે.
(૨) જો હા, તો આ આયોગની રચના ડીસે-૦૪ની સ્થિતિએ કરવામાં આવી નથી. તે હકિકત પણ સાચી છે,	
(૩) જો હા, તો તેના શા કારણો છે, અને	
(૪) આ આયોગની રચના સરકાર ક્યાં સુધી કરવા માંગે છે ?	

મહિલાઓ માટે સ્વરક્ષણ યોજના

૮૭૬૭ **શ્રી યોગેશભાઈ ના. પટેલ(રાવપુરા) : માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) મહિલાઓના સ્વરક્ષણ અંગે સરકાર દ્વારા કોઈ યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૧) અને (૨) રાજ્યની નિરાધાર વિધવા મહિલાઓને વિધવા સહાય આપવા ઉપરાંત અનૈતિક વ્યાપાર ધારા ૧૯૫૬ હેઠળ નારી સંરક્ષણ કેન્દ્રો તથા નારી સંરક્ષણ ગૃહો ચલાવતી યોજનાઓ અમલમાં છે.
(૨) જો હા, તો તેની વિગતો શું છે ?	

નોન ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને ગ્રાન્ટેબલ કરવા અંગેની પડતર અરજીઓ

૮૧૪૨ **ડૉ. સી. જે. ચાવડા(ગાંધીનગર)** : **માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં સન ૨૦૦૪ના વર્ષમાં કુલ કેટલી નોન ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને ગ્રાન્ટેબલ કરવામાં આવી,	(૧) ૨૦
(૨) કઈ કઈ કોલેજોને ગ્રાન્ટેબલ કરવામાં આવી,	(૨) પત્રક-અ મુજબની કોલેજોને ગ્રાન્ટેબલ કરવામાં આવી.
(૩) ગ્રાન્ટેબલ કરવા માટે કેટલી કોલેજોની માંગણી નામંજુર કરવામાં આવી, (૪) આ વર્ષમાં કઈ કઈ કોલેજોની ગ્રાન્ટેબલ માટેની અરજીઓ પડતર છે, અને	(૩) (૪) અને (૫) અગાઉની નિયમાનુસાર અનુદાનપાત્ર થતી કોલેજોની વિચારણા કરવામાં આવે છે. હાલ કાયમી સ્વનિર્ભરતાના ધોરણે કોલેજ શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવાની સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન નીતિના અનુસંધાને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૫) ક્યારે નિકાલ કરવામાં આવશે ?	

પત્રક-અ

૨૦૦૪ના વર્ષમાં ગ્રાન્ટેબલ કરવામાં આવેલ કોલેજોની યાદી

ક્રમ	કોલેજનું નામ
૧	શ્રીમતી ડી. જે. શાહ પરિવાર સાયન્સ કોલેજ, ધોળકા, જિ. અમદાવાદ
૨	ઉમીયા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ફોર ગર્લ્સ, સોલા, જિ. અમદાવાદ
૩	આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, મુવાલ, તા. પાદરા, જિ. વડોદરા
૪	આર્ટસ કોલેજ, સાવલી, તા. શિનોર, જિ. વડોદરા
૫	આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, પીપલીયા, તા. વાઘોડિયા, જિ. વડોદરા
૬	સાયન્સ કોલેજ, પીપલીયા, તા. વાઘોડિયા, જિ. વડોદરા
૭	આર્ટસ કોલેજ, આંકલાવ, તા. બોરસદ, જિ. આણંદ
૮	ફીઝીકલ એજ્યુકેશન કોલેજ, મહેમદાવાદ, જિ. ખેડા

૯ આર્ટસ કોલેજ, સીમલીયા, જિ. પંચમહાલ

૧૦ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, સરભાણ, તા. આમોદ, જિ. ભરૂચ

૧૧ જે.બી.ધારુકાવાલા આર્ટસ કોલેજ, વરાછા રોડ, જિ. સુરત

૧૨ શ્રી એસ.એન.જાડેજા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, કુતિયાણ, જિ. પોરબંદર

૧૩ મહિલા આર્ટસ કોલેજ, ઉના, જિ. જુનાગઢ

૧૪ શ્રી એમ.બી. કહોર આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, વડીયા, જિ. અમરેલી

૧૫ શ્રી એમ.પી.વોરા કોમર્સ કોલેજ, વઢવાણ સીટી, જિ. સુરેન્દ્રનગર

૧૬ ભીખાભાઈ પટેલ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ

૧૭ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, રાજેન્દ્રનગર, જિ. સાબરકાંઠા

૧૮ મહિલા આર્ટસ કોલેજ, ધોરાજી, જિ. રાજકોટ

૧૯ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, કાલાવડ જિ. જામનગર

૨૦ વી.આર.ભકત મહિલા બી. એડ કોલેજ, કામરેજ, જિ. સુરત

અમદાવાદ શહેરમાં સેલ્સટેક્ષના ખોટા નંબરો અંગે

૮૫૬૦ **શ્રી મોહંમદફારુક હુ. શેખ(કાલુપુર) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરના રીલીફરોડ પર આવેલી ઈલેકટ્રોનીક માર્કેટની મોટા ભાગની દુકાનોમાંથી વસ્તુઓનું વેચાણ થાય છે જેના બીલોમાં સેલ્સટેક્ષ નંબરો ખોટા છાપી સરકાર સાથે છેતરપીંડી કરાય છે તે હકિકત સાચી છે,	(૧) આવો કોઈ કિસ્સો સરકારશ્રીના ધ્યાને આવેલ નથી.
(૨) જો હા, તો આ અંગે વેચાણવેરા ટીમે છેલ્લા એક વર્ષમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં કેટલી રેડ પાડી, અને (૩) કેટલી ગેરરીતીઓ પકડી?	(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ભાવનગર જિલ્લામાં ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ અંગે

૯૪૪૯**શ્રી સુનીલ બા. ઓઝા(ભાવનગર શહેર (દક્ષિણ) : માનનીય ન્યાયતંત્ર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬ની સાલમાં કેટલી નવી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની રચના કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું, અને	(૧) અને (૨) ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની રચના અને તેને લગતી આનુષંગિક કાર્યવાહી નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. નામદાર ગુજરાત

કરવામાં આવ્યું, અને	હાઈકોર્ટ તરફથી હજુ આવી કોઈ દરખાસ્ત મળેલ નથી.
(૨) તે પૈકી ભાવનગર જિલ્લામાં કેટલી અને ક્યાં?	

રાજ્યની શાળાના વિદ્યાર્થીઓને મફત પાઠ્યપુસ્તકો પૂરા પાડવા અંગે

૮૬૮૩ **શ્રી બિમલ શાહ(કપડવંજ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) પ્રાથમિક શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય સરકાર મફત પાઠ્યપુસ્તકો પૂરા પાડે છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો રાજ્ય સરકારે તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓને આવા પાઠ્યપુસ્તકો મફત પૂરા પાડેલ છે?	(૨) વર્ષ / પાઠ્યપુસ્તકોના સેટની સંખ્યા ૨૦૦૩ — ૬૭,૦૩,૧૯૨ ૨૦૦૪ — ૬૩,૦૬,૦૫૫

રાજ્ય સરકારના દેવસ્થાનો પાછળ ફાળવેલ રકમ

૮૦૧૯ **શ્રી ધનસુખભાઈ ના. પટેલ(ઓલપાડ) : માનનીય દેવસ્થાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર હસ્તક જિલ્લાવાર કેટલા દેવસ્થાનો છે,	(૧) કુલ ૧૮ જિલ્લામાં ૩૭૯ દેવસ્થાનો છે.
(૨) તે પૈકી સરકારે દેવસ્થાનોનાં વિકાસ પાછળ કેટલા રૂપિયાની છેલ્લા બે વર્ષમાં ફાળવણી કરી, અને	(૨) રૂા. ૪૫.૦૦ લાખ.
(૩) સરકાર હસ્તક પૈકી કેટલા દેવસ્થાનોની માંગણી દેવસ્થાન લેવા માટે ટ્રસ્ટો તરફથી અરજી આવેલ છે?	(૩) પાંચ.

ભાવનગર જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળામાં નબળા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવા અંગે

૮૩૫૩ શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ. સોલંકી(ઘોઘા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પ્રાથમિક શાળાઓમાં વાંચન, લેખન અને ગણિતમાં નબળા વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારૂ શિક્ષણ આપવા કોઈ યોજના કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તેનું શું પરિણામ આવેલ છે, અને	(૨) ભાવનગર જિલ્લામાં ૮૫ ટકા બાળકોમાં સિધ્ધિ જોવા મળી છે.

(૩) ભાવનગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર સન ૨૦૦૪ના વર્ષમાં શું પરિણામ આવેલ છે?

(૩) જિલ્લો ભાવનગર.

અ.ન.	તાલુકા	ધો.૩થી ૭ની સંખ્યા	* તે પૈકી પ્રિય બાળકોની સંખ્યા	પ્રિય બાળકોની ટકાવારી	અભિયાનમાં સિધ્ધિ ટકાવારી
૧	ભાવનગર	૧૯૩૭૮	૪૮૪૩	૨૪.૯૯	૮૯.૮૮
૨	ઘોઘા	૧૦૬૨૧	૩૧૪૮	૨૯.૬૪	૭૫.૫૭
૩	તળાજા	૩૨૯૯૩	૮૬૪૨	૨૬.૧૯	૭૩.૮૧
૪	મહુવા	૩૭૪૪૬	૧૦૦૧૭	૨૬.૭૫	૮૬.૮૨
૫	પાલીતાણા	૧૯૨૦૭	૪૯૧૪	૨૫.૫૮	૮૭.૩૦
૬	ગારિયાધાર	૧૩૧૪૭	૪૧૬૪	૩૧.૬૭	૮૯.૫૫
૭	શિહોર	૨૨૪૧૪	૬૮૨૩	૩૦.૪૪	૮૨.૫૧
૮	ઉમરાળા	૯૮૮૫	૩૨૫૧	૩૨.૮૯	૮૭.૮૨
૯	બોટાદ	૧૫૭૮૩	૪૯૯૦	૩૧.૬૨	૮૭.૬૭
		૧૮૦૮૭૪	૫૦૭૯૨	૨૯.૦૦	૮૫.૦૦

- પ્રિય બાળકો એટલે વાંચન-ગણન-લેખનમાં સંતોષ જનક સિધ્ધિ નહી ધરાવતાં બાળકો.

સાવલી તાલુકામાં શિક્ષકોની ખાલી જગાઓ

૮૯૫૩ **શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર. ગોહિલ(સાવલી) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧-૧-૦૫ની સ્થિતિએ સાવલી તાલુકામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની કેટલી ખાલી જગાઓ છે, અને	(૧) ૨૬૯ જગ્યાઓ.
(૨) સરકાર આ ખાલી જગાઓ કેટલા સમયમાં ભરવા માંગે છે.?	(૨) વિદ્યાસહાયકની ભરતી થયેથી તુર્ત જ ખાલી જગ્યા ભરવામાં આવશે.

સેલ્ફ ફાઈનાન્સ શાળાઓની તપાસણી અને પગલાં

૮૯૬૩શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા(જસદણ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજયમાં મંજૂરી અપાયેલ સેલ્ફ ફાઈનાન્સ શાળાઓમાં તપાસણી કરતાં ક્ષતિયુકત જણાયેલ કેટલી શાળાઓની રાજય સરકારે નોધણી રદ કરી, અને	(૧) અને (૨) ૨૪ સંસ્થાઓની નોંધણી રદ કરેલ છે.
(૨) તેની સામે શાં પગલાં લીધા ?	

તોશાખાનામાં જમા થયેલ ચીજ વસ્તુઓની કન્યા કેળવણી પાછળ કરેલ ખર્ચ અંગે

૮૧૬૧ **ડૉ. માયાબેન સુ. કોડનાની(નરોડા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજયમાં મંજૂરી અપાયેલ સેલ્ફ ફાઈનાન્સ શાળાઓમાં તપાસણી કરતાં ક્ષતિયુકત જણાયેલ કેટલી શાળાઓની રાજય સરકારે નોધણી રદ કરી, અને	(૧) અને (૨) ૨૪ સંસ્થાઓની નોંધણી રદ કરેલ છે.
(૨) તેની સામે શાં પગલાં લીધા ?	

ભિલોડા તાલુકાની શાળાઓ ખાનગી સંસ્થાને આપવા અંગે

૯૨૩૦ **અનિલ જોષીયારા(ભીલોડા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાની કેટલી સરકારી શાળાઓ ખાનગી સંસ્થાઓને આપવામાં આવી,	(૧) ૧ (એક)
(૨) ખાનગી સંસ્થાઓને આપવાના કારણો શું, અને	(૨) શાળાનું શૈક્ષણિક સ્તર સુધારવા અને ગુણાત્મક પરિણામો મેળવવા માટે
(૩) આ ખાનગી સંસ્થાઓને સ્કૂલનું સંચાલન સોંપ્યા પછી ધોરણ-૧૦ના પરિણામમાં કેટલો સુધારો થયો ?	(૩) વહીવટ સોંપેલ શાળાનું પરિણામ સને ૨૦૦૩માં ૦ ટકા હતુ જેમાંથી સુધારો થઈ સને ૨૦૦૪ માં ૫ ટકા થવા પામેલ છે.

રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી સ્પર્ધા

૮૬૪૯ શ્રી ભરત બારોટ(દરિયાપુર-કાઝીપુર) : માનનીય રમતગમત મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રાજય સરકાર દ્વારા કઈ કઈ સ્પર્ધાઓમાં ટીમો મોકલવામાં આવે છે,

(૧) રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રાજય સરકાર દ્વારા નીચેની સ્પર્ધાઓમાં ટીમ મોકલવામાં આવે છે.

(૧) સ્કૂલ ગેમ્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા યોજાતી શાળાકીય (અંડર ૧૪,૧૭,૧૯) સ્પર્ધા

(૨) સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા યોજાતા ગ્રામિણ રમતોત્સવ અને મહિલા રમતોત્સવ.

(૩) સુબ્રતો મુખરજી સ્પોર્ટસ એજયુકેશન સોસાયટી, નવી દિલ્હી આયોજિત સુબ્રતો સુખરજી જુનિયર / સબ જુનિયર હોકી સ્પર્ધાઓ.

(૪) જવાહરલાલ નહેરૂ હોકી ટુર્નામેન્ટ સોસાયટી નવી દિલ્હી આયોજિત જવાહરલાલ નહેરૂ જુનિયર / સબ જુનિયર હોકી સ્પર્ધા.

(૨) રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેતા પહેલા ખેલાડીઓને ખાસ કોચીંગ આપવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે કેમ, અને

(૨) હા, જી.

(૩) જો હા, તો છેલ્લા બે વર્ષમાં તા.૩૧-૧૨-૦૪ સુધી કઈ સ્પર્ધામાં કેટલા મેડલ મળ્યા ?

(૩)

વર્ષ	સ્પર્ધા	મળેલ કુલ મેડલ
૨૦૦૩-૦૪	શાળાકીય સ્પર્ધા (૧૨ રમતો)	૬૮
	મહિલાઓ (૨ રમતો)	૦૪
	ગ્રામણિ સ્પર્ધા (૧ રમત)	૦૩
	કુલ :	**૭૫**
૨૦૦૪-૦૫ (૩૧-૧૨-૦૪ સુધી)	શાળાકીય સ્પર્ધા (૭ રમતો)	૯૭
	મહિલા સ્પર્ધા (૨ રમતો)	૦૪
	ગ્રામણિ સ્પર્ધા (૧ રમત)	૦૨
	કુલ :	**૧૦૩**

નાણા પંચ દ્વારા ફાળવેલ તેમજ વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટ

૮૪૮૩ **શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી(અમરેલી) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) કેન્દ્ર સરકારના નાણા પંચે રાજય માટે સને ૨૦૦૨-૨૦૦૩ અને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ તેમજ ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના વર્ષ માટે કેટલી રકમ ફાળવવાની નકકી કરેલ હતી,

(૧) કેન્દ્ર સરકારે નિમેલ નાણા પંચ કેન્દ્ર સરકારને તમામ રાજયોને કેટલી રકમ આપવી તેની ફોર્મ્યુલા નકકી કરે છે.

(૨) તે પૈકી વર્ષવાર કેટલી રકમ કયારે મળી, અને

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩) તે પૈકી વણવપરાયેલી રકમ કેટલી છે ?

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પ્રાથમિક શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ

૮૯૪૬ **શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર(કડી) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રાજયના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની કુલ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૨) આ જગ્યાઓ કયારે ભરવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) પત્રક-અ મુજબ

(૨) જેમ બને તેમ જલ્દી.

પત્રક-અ

જિલ્લાવાર શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાની વિગત દર્શાવતું પત્રક. (તા.૩૧/૧૨/૦૪)

Table 1

ક્રમ	જિલ્લાનું નામ	ખાલી જગ્યા
૧	**૨**	**૩**
૧	અમદાવાદ	૫૯૭
૨	વડોદરા	૧૯૩૫
૩	રાજકોટ	૩૫૭
૪	સુરત	૯૧
૫	ખેડા	૨૫૭
૬	આણંદ	૩૪૦
૭	પંચમહાલ	૬૮૨
૮	ઞ્ઞહોદ	૬૫૧
૯	સાબરકાંઠા	૩૧૬
૧૦	જૂનાગઢ	૬૨૪
૧૧	પોરબંદર	૧૪૨
૧૨	મહેસાણા	૨૨૯
૧૩	પાટણ	૪૦૬
૧૪	ભાવનગર	૪૯૬

૧૫	જામનગર	૧૦૯
૧૬	અમરેલી	૧૦૫
૧૭	કચ્છ	૪૩૧
૧૮	ભરૂચ	૨૦૦
૧૯	નર્મદા	૫૬
૨૦	વલસાડ	૨૯૫
૨૧	નવસારી	૧૪૨
૨૨	બનાસકાંઠા	૮૧૬
૨૩	સુરેન્દ્રનગર	૪૬૧
૨૪	ગાંધીનગર	૧૦૩
૨૫	ડાંગ	૧૦૨
૨૬	ગાંધીનગર શહેર	૨૪
	કુલ	૯૯૬૭
	નગરપાલિકાઓ	૮૪૪
	એકંદર કુલ	૧૦૮૧૧

રાંધણ ગેસના વેચાણવેરા પેટે થયેલ આવક

૮૯૫૬ **શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે(ડાંગ-વાંસદા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં તા.૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં રાજય સરકારને રાંધણ ગેસના સીલીન્ડરોના વેચાણ પેટે વેચાણવેરાની કેટલી રકમ મળી, અને

(૨) આ રાંધણ ગેસના એક સીલીન્ડર પાછળ વેચાણવેરો કેટલો વસૂલ કરવામાં આવે છે ?

જવાબ

(૧) ૨૦૦૩-૦૪માં રૂા.૯૪.૫૧ કરોડ અને

૨૦૦૪-૦૫માં રૂા.૭૭.૨૧ કરોડ

(૨) ૧૪ ટકાના દરે.

એન્જીનીયરીંગ, બી.એડ. પી.ટી.સી. કોલેજોની સીટોમાં કરેલ વધારો

૮૧૮૮**શ્રી જયંતિલાલ રા. કવાડિયા(હળવદ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજયમાં એન્જીનીયરીંગ કોલેજો, બી.એડ. કોલેજો અને પી.ટી.સી. કોલેજોની જિલ્લાવાર સંખ્યા કેટલી,

(૨) તેમાંથી સ્વનિર્ભર કોલેજો કેટલી, તેમજ ગ્રાન્ટેડ કોલેજો કેટલી, અને

(૩) આવી કોલેજોમાં રાજયમાં તા.૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કોર્ષ વાર કેટલી સીટોનો વધારો કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) પત્રક - ૧ સામેલ છે.

(૨) કુલ ૩૮૬ સંસ્થાઓ પૈકી ૨૫૧ સ્વનિર્ભર કોલેજો તથા ૮૮ ગ્રાન્ટેડ કોલેજો છે.

(૭) આવી કોલેજોમાં તા.૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કોર્ષ વાર નીચે મુજબ કુલ ૧૨૦૮૬ સીટોનો વધારો કરવામાં

વાર કેટલી સીટોનો વધારો કરવામાં આવ્યો ?

આવ્યો

વર્ષ	૨૦૦૨	૨૦૦૩	૨૦૦૪	કુલ
એન્જી. કોલેજો	૨૬૬	-૬૯૯	૧૦૪૫-	૨૦૧૦
બી.એડ. કોલેજ	--	૩૦૮૮-	૫૮૬૫-	૮૯૫૩
પી.ટી.સી કોલેજો	૮૦	--	૧૦૪૩-	૧૧૨૩
કુલ	૩૪૬-	૩૭૮૭-	૭૯૫૩-	૧૨૦૮૬

પત્રક-૧

રાજયમાં એન્જીનીયરીંગ કોલેજો, બી.એડ. કોલેજો અને પી.ટી.સી. કોલેજોની જિલ્લાવાર સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક

ક્રમ નં.	જિલ્લાનું નામ	એન્જીનીયરીંગ કોલેજો	બી.એડ. કોલેજો	પી.ટી.સી. કોલેજો	કુલ
૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧	અમદાવાદ	૦૫	૧૪	૨૫	૪૪
૨	આણંદ	૦૪	૧૧	૧૪	૨૯
૩	અમરેલી	--	૦૪	૦૭	૧૧
૪	બનાસકાંઠા	--	૦૨	૦૫	૦૭
૫	ભરૂચ	૦૩	૦૩	૦૫	૧૧
૬	ભાવનગર	૦૨	૦૬	૦૮	૧૬
૭	દાહોદ	૦૧	૦૩	૦૫	૦૯
૮	ગાંધીનગર	૦૨	૦૫	૨૪	૩૧
૯	જામનગર	--	૦૫	૦૬	૧૧
૧૦	જુનાગઢ	--	૦૬	૧૩	૧૯
૧૧	કચ્છ (ભૂજ)	૦૧	૦૨	૦૫	૦૮
૧૨	ખેડા	૦૨	૦૧	૦૭	૧૦
૧૩	મહેસાણા	૦૩	૧૪	૨૨	૩૯
૧૪	નવસારી	૦૧	૦૩	૦૨	૦૬
૧૫	પંચમહાલ	૦૧	૦૧	૦૫	૦૭
૧૬	પાટણ	૦૧	૦૩	૦૭	૧૧
ક્રમ નં.	જિલ્લાનું નામ	એન્જીનીયરીંગ કોલેજો	બી.એડ. કોલેજો	પી.ટી.સી. કોલેજો	કુલ

૧૭	પોરબંદર	--	૦૧	૦૧	૦૨
૧૮	રાજકોટ	૦૩	૧૩	૧૩	૨૯
૧૯	સાબરકાંઠા	૦૧	૦૯	૧૪	૨૪
૨૦	સૂરત	૦૪	૦૮	૧૧	૨૩
૨૧	સુરેન્દ્રનગર	૦૧	૦૩	૦૮	૧૨
૨૨	વડોદરા	૦૩	૦૩	૦૯	૧૫
૨૩	વલસાડ	૦૧	૦૧	૦૭	૦૯
૨૪	નર્મદા	--	--	૦૨	૦૨
૨૫	ડાંગ	--	--	૦૧	૦૧
	કુલ	**૩૯**	**૧૨૧**	**૨૨૬**	**૩૮૬**

નવરચિત તાલુકાઓમાં જુનિયર ડીવીઝન કોર્ટ શરૂ કરવા અંગે

૮૪૪૩ **શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ(સોમનાથ) : માનનીય કાયદા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ નવરચિત તાલુકાઓમાં જુનિયર ડીવીઝન કોર્ટો કેટલી શરૂ કરવામાં આવી, કેટલી બાકી છે;	(૧) ૦૨ કોર્ટ શરૂ કરવામાં આવી, ૨૬ કોર્ટો બાકી છે.
(૨) તેમાં જૂનાગઢ જિલ્લાનો નવરચિત સુત્રપાડા તાલુકામાં ક્યારે કોર્ટ શરૂ કરવામાં આવનાર છે, અને	(૨) હાઈકોર્ટ તરફથી દરખાસ્ત મળ્યેથી અને નાણાંકીય આયોજન થયેથી.
(૩) તે અંગેનું આગામી નાણાંકીય વર્ષમાં સરકારે શું આયોજન કરેલ છે?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

જસ્ટીસશ્રી આર.જે. શાહ સમિતિની કામગીરી

૮૯૫૯ **શ્રી ધીરૂભાઈ હ. ગજેરા(સુરત શહેર (ઉત્તર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) જસ્ટીસ શ્રી આર. જે. શાહ સમિતિની મુદત કઈ તારીખ સુધીની હતી, અને મુદત કેટલી, કયા કારણોસર વધારવામાં આવી;	(૧) શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃએસસીએફ/ ૨૦૦૩/સીસી.૫૯/સ તા. ૨૬-૧૨-૨૦૦૩ મુજબ આ સમિતિની મુદત કામગીરી પૂર્ણ થાય અથવા એક વર્ષ બેમાંથી જે વહેલુ હોય તેટલો સમય પૂરતી રાખવામાં આવી હતી. આ સમિતિને તેને સોંપાયેલ કામગીરીના સંદર્ભમાં ઉપરોકત મુદત પછી પણ યથાવત ધોરણે કાર્યરત છે. તે જોતાં આ સમિતિની મુદત ચાલુ રાખીને વધુ બે વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવી છે.

(૨) આ સિમતિની કામગીરી પાછળ ડીસે.-૦૪ની સ્થિતિએ કુલ કેટલો ખર્ચ થયો, અને	(૨) રૂા. ૭,૩૯,૧૧૧/- ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
(૩) આ સિમિતએ તબક્કાવાર કયા કયા અભ્યાસક્રમો માટે કયા કયા પ્રકારની કામગીરી કરી છે?	(૩) આ સમિતિએ રાજ્યની સ્વનિર્ભર સંસ્થાઓના એન્જિનીયરીંગ, ફાર્મસી, એમ.બી.એ., એમ.સી.એ, આર્કીટેકચર, હોટલ એન્ડ ટુરીઝમ, બી.એડ, બી.પી.એડ, પી.ટી.સી. વિગેરે અભ્યાસક્રમો માટેનું ફી નું ધોરણ તથા મેનેજમેન્ટ ક્વોટામાં પ્રવેશ માટે અનુસરવાની માર્ગદર્શક સૂચના આપેલ છે.

બી.એડ. થયેલા ઉમેદવારને વિદ્યા સહાયકની જગ્યા પર નિમણુંક

૮૭૧૪ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી(ભાવનગર શહેર (ઉત્તર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં પ્રાથમિક શિક્ષણમાં બી.એડ. થયેલ ઉમેદવારોને વિદ્યા સહાયક તરીકે લેવાનો હુકમ સરકારે કઈ તારીખે કર્યો;	(૧) તા. ૫-૬-૨૦૦૪
(૨) આ હુકમની તારીખથી તા. ૩૧-૧-૨૦૦૫ સુધીમાં રાજ્યમાં બી.એડ. થયેલ કેટલા ઉમેદવારોને વિદ્યાસહાયક તરીકે પસંદ કરીને નિમણુંક આપવામાં આવી, અને	(૨) ૭૭૫૧
(૩) બી.એડ. અને પી.ટી.સી. બન્નેનો સમાવેશ થતા પ્રાથમિક શિક્ષકોની તા.૩૧-૧-૨૦૦૫ સુધીમાં ખાલી રહેલ બધી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરાઈ જશે?	(૩) ૧૩૭૯૭ જગાઓ ભરવામાં આવી છે. બાકીની જગાઓ જેમ બને તેમ જલ્દી ભરવામાં આવશે.

દાંતા, અમીરગઢ અને પાલનપુર તાલુકાની શાળાઓમાં નવીન ઓરડાઓ

૯૪૨૫ **શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી(દાંતા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) બનાસકાંઠા જીલ્લાના દાંતા, અમીરગઢ તથા પાલનપુર તાલુકાના ગામો અને એનાં પેટાં પરાઓમાં પ્રાથમિક શાળાઓના નવીન ઓરડાઓ ઉભા કરવા સને ૨૦૦૪ની સાલમાં સરકારે શી કાર્યવાહી કરી;	(૧) કુલ ૬૬ નવા ઓરડાઓ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
(૨) તેની વિગતો શી છે, અને	(૨) દાંતામાં ૨૦, અમીરગઢમાં ૧૪, અને પાલનપુરમાં ૩૨ નવા ઓરડાઓ બનાવવામાં આવનાર છે.
(૩) જો કોઈ કાર્યવાહી ન કરી હોય તો તે પાછળનાં શું કારણો છે?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પાછળનાં શું કારણો છે?

રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં આચાર્ય તેમજ પ્રાધ્યાપકોની ખાલી જગાઓ

૮૩૧૮**શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ(વાગરા) : માનનીય મંત્રીશ્રી શિક્ષણ** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં ગ્રાન્ટેડ કોલેજો પૈકી કેટલી કોલેજોમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ આચાર્યની નિમણુંકો થઈ નથી, અને	(૧) ૮૦ (એંશી)
(૨) ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં પ્રાધ્યાપકોની નિમણુંક બાકી હોય તેવી કેટલી કોલેજો છે ?	(૨) ૯૯ (નવ્વાણું)

સતલાસણા સબ ટ્રેઝરી કાર્યરત કરવા અંગે

૯૩૯૭ **શ્રીમતી રમીલાબેન રા. દેસાઈ(ખેરાલુ) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં નવનિર્મિત તાલુકાઓમાં સબટ્રેઝરીની સુવિધા આપવી તેવું સરકારે સ્વીકારેલ છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો નવનિર્મિત સતલાસણા તાલુકામાં સબટ્રેઝરીની સુવિધા ક્યારથી આપવામાં આવશે?	(૨) આનુસાંગિક કાર્યવાહી પૂર્ણ થયેથી તુર્તજ.

બાલાસડી સૈનિક સ્કૂલ જામનગર ખાતે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લેવાતી ફી

૮૫૨૬ **શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ(લીંબડી) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૧-૪-૦૪ થી તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં બાલાસડી સૈનિક સ્કૂલ જામનગર ખાતે કેટલી ફી વિદ્યાર્થીવાર લેવાય છે;	(૧) સૈનિક સ્કૂલ, બાલાચડી જિ. જામનગરમાં વિદ્યાર્થીદીઠ ચાર હપ્તાની મળીને વાર્ષિક રૂા. ૩૨,૨૧૦/- લેવાયેલ છે.
(૨) અનુસુચિત જાતિ, જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી કેટલી ફી લેવાઈ છે;	(૨) અનુસુચિત જાતિ, જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ચાર હપ્તાની મળીને વાર્ષિક રૂા.૩૨,૨૧૦/- લેવાયેલ છે.
(૩) અનુસુચિત જાતિ, જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓને ફી માફીની યોજના બંધ કરવાના શું કારણો છે, અને	(૩) અગાઉથી સ્કોલરશીપ યોજના ચાલુ છે.
(૪) ફીના કારણે અનુસુચિત જાતિ, જનજાતિના કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભણતર છોડી ગયેલ છે?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અનામતની ટકાવારી મુજબ વિદ્યાસહાયકોની બાકી નિમણુંક અંગે

૮૩૪૦ **શ્રી દોલતભાઈ પરમાર(વડગામ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં સને ૨૦૦૨-૦૩ અને ૨૦૦૩-૦૪ના વર્ષમાં જિલ્લાવાર પ્રાથમિક શિક્ષકોમાં કેટલા વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી છે;

(૨) આ વિદ્યાસહાયકોમાં અનુસુચિત જાતિ અને જનજાતિના કેટલા વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી છે;

(૩) સરકારે ઠરાવેલી અનામતની ટકાવારી પ્રમાણે હજુ કેટલી જગાઓ તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં ભરવાની બાકી છે, અને

(૪) જગાઓ ભરવામાં અનામતની ટકાવારી જળવાઈ નથી તેનાં શાં કારણો છે?

જવાબ

(૧) પત્રક-અ સામેલ છે.

(૨) અનુ.જાતિ ૮૫૮
અનુ.જનજાતિ ૧૬૫૧

(૩) જિલ્લા કક્ષાએ અનામતની કેટેગરીના રોસ્ટર રજીસ્ટરો તૈયાર કરી તેની ચકાસણીની કામગીરી ચાલુ છે. જે પુરી થયેથી આગામી વિદ્યાસહાયક ભરતી વખતે જે તે કેટેગરીના બેકલોગની જગાઓ સૌ પ્રથમ ભરવામાં આવશે.

(૪) જિલ્લા કક્ષાએ અનામત કેટેગરીના રોસ્ટર રજીસ્ટરો તૈયાર કરી તેની ચકાસણીની કામગીરી ચાલુ છે. જે પુરી થયેથી આગામી વિદ્યાસહાયક ભરતી વખતે જે તે કેટેગરીના બેકલોગની જગાઓ સૌ પ્રથમ ભરવામાં આવશે.

પત્રક-અ

જિલ્લાવાર વિદ્યાસહાયકોની ભરતીની વિગતો			
ક્રમ	જિલ્લો	૨૦૦૨-૦૩	૨૦૦૩-૦૪
૧	અમદાવાદ	૨૨૮	૫૪૩
૨	વડોદરા	૨૨૯	૩૦૩
૩	રાજકોટ	૬૮	૨૨૨
૪	સુરત	૩૭૦	૨૫૨
૫	ખેડા	૬૮૫	૦
૬	આણંદ	૨૭૨	૫૮૭
૭	પંચમહાલ	૨૨૧	૦
૮	દાહોદ	૪૨૬	૩૮૧
૯	સાબરકાંઠા	૩૭૧	૧૫
૧૦	જૂનાગઢ	૧૧૭	૧૪૪
૧૧	પોરબંદર	૨૫	૧૩
૧૨	મહેસાણા	૩૭૧	૦
૧૩	પાટણ	૧૬૪	૧૭૮
ક્રમ	જિલ્લો	૨૦૦૨-૦૩	૨૦૦૩-૦૪

૧૪	ભાવનગર	૧૪૪	૧૭૬
૧૫	જામનગર	૧૭૦	૧૪૨
૧૬	અમરેલી	૧૦૫	૬૫
૧૭	કચ્છ	૯૦	૩૦
૧૮	ભરૂચ	૭૬	૭૧
૧૯	નર્મદા	૧૭	૧૨
૨૦	વલસાડ	૨૧૮	૧૧૦
૨૧	નવસારી	૧૭૫	૦
૨૨	બનાસકાંઠા	૧૦૧૩	૪૧૩
૨૩	સુરેન્દ્રનગર	૧૬૯	૧૯૧
૨૪	ગાંધીનગર	૨૭૨	૦
૨૫	ડાંગ	૪૧	૦
	કુલ	૬૦૩૭	૩૮૪૮
	નગરપાલિકા	૫૫૪	૦
	એકંદર કુલ	૬૫૯૧	૩૮૪૮

જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં સાક્ષરતા અભિયાન

૮૨૧૯ **શ્રીમતી જસુબેન સ. કોરાટ(જેતપુર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં ડીસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતએ કેટલા પ્રૌઢ વ્યક્તિ સાક્ષરતાથી વંચિત છે;	(૧) જેતપુર-૧૬૯૯૬ ગોંડલ-૩૬૩૧૩
(૨) તેમને સાક્ષરતા બનાવવા સરકારે શું આયોજન કર્યુ છે, અને	(૨) નિરંતર શિક્ષણ કાર્યક્રમમાં આવરી લેવામાં આવશે.
(૩) આ જવાબદારી કોને સોંપાઈ છે ?	(૩) જિલ્લા સાક્ષરતા સમિતિ.

વેટ કાયદાના અમલ અન્વયે વેચાણવેરાની આવકમાં થનાર વધઘટ

૮૩૭૧ **શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા(જમાલપુર) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજયમાં વેટના કાયદાના અમલના કારણે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રાજયની કેટલી રકમનું વળતર મળે તેમ છે, અને	(૧) વેટના કાયદાના અમલના કારણે જો વેરાની આવકમાં નુકશાન થાય તો કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રાજયને ૨૦૦૫-૦૬માં ૧૦૦ ટકા, ૨૦૦૬-૦૭માં ૭૫ ટકા અને ૨૦૦૭-૦૮માં નુકશાનનાં ૫૦ ટકા રકમનું વળતર મળશે.

(૨) વેચાણવેરાની રાજયને થતી વાર્ષિક આવક અને આ વેચાણવેરાની વધતી જતી આવકના દરની થતી રકમની સામે ગણત્રી કરતા, આના કારણે રાજય સરકારને કેટલી રકમનું નુકશાન જવાનો અંદાજ છે ?

(૨) નુકશાનનો અંદાજ હાલના તબકકે બાંધી શકાય નહીં.

કચ્છ જિલ્લામાં વેચાણવેરાની બાકી રકમ

૯૨૨૬ **શ્રી ગોપાલભાઈ ગા. ધુઆ(મુંદ્રા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કચ્છ જિલ્લામા રાજય સરકાનું તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૪ના રોજ વેચાણવેરાનું કેટલું લેણું બાકી છે,	(૧) રૂા. ૩૯૬.૮૯ કરોડ
(૨) સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ની સાલમાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલા બાકી લેણાની વસૂલાત થઈ, અને	(૨) રૂા. ૧.૫૪ કરોડ
(૩) બાકી લેણા માટે વ્યાજનો દર શું છે, આ દરમાં કુલ કેટલી રકમની રાહત આપવામાં આવી છે?	(૩) તા.૧/૯/૨૦૦૧ પહેલા વાર્ષિક ૨૪ ટકા તથા તા.૧/૯/૨૦૦૧ થી વાર્ષિક ૧૮ ટકા વ્યાજનો દર છે. આ દરમાં કોઈ રકમની રાહત આપવામાં આવેલ નથી.

રાજયમાં રૂા. ૧ કરોડથી વધુ વેચાણવેરાની બાકી રકમ

૮૫૬૨ **ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા(માંગરોળ) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૪ની સ્થિતિએ રાજયમાં રૂા. ૧ કરોડ કરતાં વધુ વેચાણવેરા બાકી હોય તેવા કેટલા એકમો છે, અને	(૧) ૪૨૧
(૨) આવા એકમો પાસેથી નીકળતી રકમ વસૂલ લેવા માટે સરકારે શું પગલાં લીધાં છે ?	(૨) શકય વસૂલાતવાળા કેસોમાં ગુજરાત વેચાણવેરા કાયદા હેઠળના તથા જમીન મહેસૂલ કાયદા હેઠળના પગલાં લેવામાં આવેલ છે.

રાજય સરકારને થયેલ આવક અને વહીવટી ખર્ચ

૮૦૯૬ **શ્રી મોહનભાઈ ક. કુંડારીયા(ટંકારા) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજય સરકારને છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષમાં રાજયની કુલ આવક અને વહીવટી ખર્ચ કેટલો થયો, અને	(૧) છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષમાં રાજયની કુલ આવક રૂા. ૮૩,૧૧૫.૪૫ કરોડ હતી અને કુલ વહીવટી ખર્ચ રૂા. ૫,૦૨૦.૧૫ કરોડનો હતો.

(૨) તે પૈકી વહીવટી ખર્ચ અને વિકાસના કામો પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

(૨) તે પૈકી વહીવટી ખર્ચ રૂા. ૫,૦૨૦.૧૫ કરોડનો હતો અને વિકાસના કામો પાછળ રૂા. ૩૧,૯૨૯.૫૮ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.

દહેગામ તાલુકાની માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ

૯૩૯૫ **શ્રી જગદીશ ઠાકોર(દહેગામ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) ગાંધીનગર જિલ્લામાં દહેગામ તાલુકામાં સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં તા.૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ કયા કયા વિષયોના શિક્ષકોની કેટલી જગ્યાઓ કેટલા વખતથી ખાલી છે,

(૨) ખાલી પડેલી જગ્યાઓએ વચગાળા માટે કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, અને

(૩) ખાલી પડેલી જગ્યાઓ સરકાર કયારે પૂરવા માગે છ ?

જવાબ

(૧) દહેગામ તાલુકામાં એક પણ સરકારી માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળા આવેલી નથી,

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

જામનગર જિલ્લામાં વિધાદીપ યોજનાના લાભાર્થીઓ

૮૭૮૯ શ્રી મુળુભાઈ હ. બેરા(ભાણવડ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) જામનગર જિલ્લામાં સન ૨૦૦૪ના વર્ષમાં વિધાદીપ યોવના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલા બાળકોને લાભ આપવામાં આવેલ છે, અને

(૨) આ યોજના હેઠળ આ વર્ષમાં જિલ્લામાં કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી ?

જવાબ

(૧)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	પ્રાથમિકના	માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક
૧	કાલાવડ	૧	૧
૨	ભાણવડ	૦	૧
૩	જામનગર	૨	૩
૪	ધ્રોળ	૨	૧
૫	કલ્યાણપુર	૨	૦
૬	લાલપુર	૨	૦
૭	ખંભાળીયા	૧	૦
	કુલ :	૧૦	૬

(૨) પ્રાથમિકના કિસ્સામાં બાળકદીઠ રૂા. ૨૫,૦૦૦/- અને માધ્યમિક ઉચ્ચત્તર માધ્યમિકના કિસ્સામાં બાળકદીઠ રૂા.૫૦,૦૦૦/- લેખે સંબંધિત વારસદારોને કુલ રૂા.૫,૫૦,૦૦૦/- ની રકમ ચૂકવવામાં આવેલ છે.

રાજય સરકાર દ્વારા લીધેલ ઓવર ડ્રાફટ

૮૮૧૧ શ્રી પોપટભાઈ સ. જીંજરિયા(ચોટીલા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સન ૨૦૦૪-૨૦૦૫ ના વર્ષમાં તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં રાજય સરકારે કેટલી વખત અને કેટલી રકમનો ઓવર ડ્રાફટ લીધા છે,	(૧) શૂન્ય.
(૨) ઓવર ડ્રાફટ લેવાના કારણો કયાં કયાં છે, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં રાજયની તિજોરી ઉપર કુલ આર્થિક ભારણ કેટલું છે ?	(૩) તા.૩૧.૧૨.૦૪ ની સ્થિતિએ રાજયનું કુલ દેવું રૂા.૫૬,૪૩૮ કરોડ છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વિધાર્થીઓને વિમા કવચની સહાય

૮૦૭૭ શ્રી મનહરલાલ મ. મકવાણા(દસાડા) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સન ૨૦૦૩-૨૦૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલુ અભ્યાસે મૃત્યુ પામનાર વિધાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી,	(૧) ૨૦૦૩-૦૪ ૫૬ ૨૦૦૪-૦૫ ૩૫
(૨) આ વિધાર્થીઓને વિમા કવચ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા હોય તો તેમને વિમા સહાય કયારે ચૂકવી, અને	(૨) પાત્રતા ધારવતા છ (૬) કિસ્સામાં જે તે વર્ષમાં વિમા સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે.
(૩) આવી વિમા કવચની સહાય હજુ સુધી ચૂકવાઈ ન હોય તો તેના કારણો શાં છે ?	(૪) કુદરતી મૃત્યુ થવાથી પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ રજૂ ન કરવાને કારણે એફ.આઈ.આર.ની નકલ સામેલ ન હોવાને કારણે કંપીન દ્વારા વિધાર્થીના ઘરે રૂબરૂ ચકાસણી કરતાં મૃત્યુ અકસ્માતે ન થયેલ હોવાના કારણે.

આણંદ જિલ્લાની શાળાઓમાં શૈક્ષણિક સાધનોની ખરીદી

૮૬૫૮ શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધી. પરમાર(ભાદરણ): માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સર્વ શિક્ષા કાર્યક્રમ ઓપરેશન બ્લેક બોર્ડ યોજના હેઠળ આણંદ જિલ્લાની કુલ ૨૬૩ પ્રાથમિક	(૧) સર્વ શિક્ષણ અભિયાન અંતર્ગન આણંદ જિલ્લાની ઓપરેશન બ્લેક બોર્ડ યોજનામાં સમાવેશ

શાળાઓને કયા કયા શૈક્ષણિક સાધનો સને ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ ના વર્ષમાં તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં આપવમાં આવ્યા, અને	થયેલ શાળાઓને પરિશિષ્ટ ઘ ક ની યાદી પૈકી જરૂરિયાત મુજબના શૈક્ષણિક સાધનો ખરીદવા ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે.
(૨) આ સાધનોની ખરીદી કિંમત શું છે ?	(૨) આ સાધનોની ખરીદી કિંમત રૂા.૧૨૮.૫૦ છે.

પરિશિષ્ટ - ક

ઓપરેશ બ્લેક બોર્ડ યોજના હેઠળ પ્રાથમિક શાળાઓ માટે ખરીદવાના સાધનોની યાદી

૧	સ્ટીલ ખુરશી	૨૨	બાળ સાહિત્યના પુસ્તકો-શૈક્ષણિક હેતુ માટેના પુસ્તકો શિક્ષકો માટેનું સંર્ભ સાહિત્ય (અન.બીટી. અને સી.બી.ટી.
૨	સ્ટીલ ટેબલ	૨૩	જોમેટ્રીકલ કીટ
૩	કાળું પાટીયું (બ્લેક બોર્ડ)	૨૪	બેડ મીન્ટન સેટ
૪	સ્ટુલ	૨૫	શૈક્ષણિક ચાર્ટ
૫	સ્ટીલ કબાટ	૨૬	માઈક્રોસ્કોપ
૬	ઘંટ	૨૭	કેલકયુલેટર
૭	નકશાઓ (જિલ્લો, રાજય, દેશ અને દુનિયા)	૨૮	સ્ટીલ રેક
૮	પૃવીનો ગોળો	૨૯	કચરા ટોપલી
૯	આસન પટ્ટા	૩૦	ગણિત પેટી
૧૦	મંજીરા	૩૧	વિજ્ઞાના સાધનો
૧૧	હારમોનીયમ	૩૨	વિજ્ઞાન પેટી
૧૨	ઢોલક (તબલા)	૩૩	રબ્બર બોલ
૧૩	કૂદવાના દોરડા	૩૪	વિધાર્થીઓ માટે બેંચો
૧૪	ફૂટબોલ- વોલીબોલ	૩૫	શૈક્ષણિક રમકડાં
૧૫	એર પમ્પ	૩૬	વીઝડમ બ્લોક
૧૬	કેરમ સેટ	૩૭	બર્કસ એન્ડ એનીમલ પઝલ
૧૭	ક્રિકેટ સેટ	૩૮	ડુપ્લીકેટી મશી
૧૮	રબ્બર રીંગ	૩૯	ભીંત ઘડિયાળ
૧૯	ડ્રમસેટ	૪૦	શાળા માટે પંખો
૨૦	પાણીના સાધનો	૪૧	રૂા.૨૦૦૦-૦૦ પરચુરણ ખર્ચ
૨૧	સામયિકો		

પાટણ જિલ્લામાં વિધવા મહિલાઓને બાકી પેન્શનની ચૂકવણી

૮૨૮૯ શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિધ્ધપુર) : માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	**જવાબ**

(૧) પાટણ જિલ્લામાં ૧લી જાન્યુઆરી ૨૦૦૫ની સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી વિધવા મહિલાઓને પેન્શન ચૂકવવાનું બાકી છે,

(૧)

તાલુકો	લાભાર્થી
સિધ્ધપુર	૬
પાટણ	૪
કુલ :	૧૦

(૨)

ક્રમ	તાલુકો	આવેલ અરજીઓ	મંજૂર થયેલ અરજીઓ
૧	ચાણસમા	૮૧	૪૨
૨	રાધનપુર	૩૧	૦૯
૩	હારીજ	૪૨	૧૭
૪	સિધ્ધપુર	૧૧૧	૫૮
૫	પાટણ	૨૨૩	૧૦૮
૬	સાંતલપુર	૧૪	૦૭
૭	સમી	૪૩	૨૨
	કુલઃ	૫૪૫	૨૬૩

(૩) મંજૂર થયેલ અરજીઓ પૈકી કેટલાને પેન્શન ચૂકવવામાં આવ્યું ?

(૩) મંજૂર થયેલ અરજીઓ પૈકી ૨૫૩ને પોસ્ટ ઓફિસના બચતખાતા દ્વારા સહાય ચૂકવવામાં આવી.

વેચાણવેરાની માફી અંગેના એકમો

૯૨૩૨ શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ(૨૫૨) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં એકવાજેલ કંપનીમાં બનતી સાબુ અને અનુષાંગિક પ્રોડકટ મલ્ટી નેશનલ કંપનીના નામની હોવા છતાં સેલ્સટેક્ષની વિલંબીત ચૂકવણી અગર સેલ્સટેક્ષની માફી યોજનાનો લાભ મળે છે તે હકીકત સાચી છે,	(૧) હા.જી.
(૨) આ કંપનીને મૂડીરોકાણ સામે કેટલા કરોડના લાભો રાજયના સેલ્સટેક્ષ અન્વયે નકકી કરાયા છે, અને	(૨) રૂા.૮૭૮૧.૮૬ લાખ
(૩) આ કંપની દ્વારા ટ્રેડમાર્ક ટેક્ષ કે બ્રાન્ડટેક્ષ અન્વે તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં એક વર્ષમાં કેટલી રકમ જમા કરવામાં આવી ?	(૩) કોઈ રકમ જમા કરાવેલ નથી.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વિધવા મહિલા સહાયના પડતર કેસ

૯૪૫૪શ્રી ગોવિંદભાઈ વ. પરમાર(તલાલા) :માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન

(૧) જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર તા.૩૦.૧૧.૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વિધવા મહિલાઓને સહાય મેળવવાની કેટલી અરજીઓ પડતર છે,

જવાબ

(૧) તા.૩૦.૧૧.૦૪ ની સ્થિતિએ તાલુકાવાર પડતર અરજીઓની વિગત નીચે મુજબ છે.

તાલુકો	પડતર અરજીઓ
જૂનાગઢ	૧૬
વિસાવદર	૦૪
માણાવદર	૦૧
વંથલી	૦૩
વેરાવળ	૦૭
ઉના	૧૬
ભેંસાણ	૦
તલાલા	૦૪
કોડીનાર	૦૨
સૂત્રાપાડા	૦૧
કેશોદ	૦૮
માળીયા	૦૮
માંગરોળ	૦૨
મેંદરડા	૧૧
કુલ :	૮૩

(૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજૂર અને કેટલી ના મંજૂર કરવામાં આવી છે,

(૨) અરજીઓ ચકાસણી હેઠળ છે.

(૩) બાકી અરજીઓનો નિકાલ કેટલા સમયમાં કરવામાં આવશે, અને

(૩) શકય તેટલી વહેલી તકે.

(૪) મંજૂર થયેલ સહાયની રકમ ચૂકવવા સરકારે શું આયોજન કરેલ ?

(૪) મંજૂર કેસોમાં પોસ્ટ ઓફિસ બચત ખાતા ખોલવાની સહાયની રકમ લાભાર્થીઓના બચત ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે.

કચ્છી સાહિત્ય અકાદમીની કામગીરી

૯૪૦૪ **શ્રી શીવજીભાઈ ક. આહીર(ભૂજ) : માનનીય યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં કચ્છી સાહિત્ય અકાદમી મંજુર થયા બાદ ડિસેમ્બર, ૨૦૦૪ની સ્થિતિએ તેની વ્યવસ્થિત કામગીરી શરૂ થઇ નથી તે સરકાર જાણે છે,	(૧) હા જી.
(૨) જો હા, તો તેના શાં કારણો છે, અને	(૨) કચ્છી સાહિત્ય અકાદમીનું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું છે આ બંધારણની જોગવાઇ અનુસાર કચ્છી સાહિત્ય અકાદમીના સભ્યોની નિમણૂંક અંગેની કાર્યવાહી ગતિમાં છે. આ નિમણૂંકો થયા બાદ કચ્છી સાહિત્ય અકાદમીની કામગીરી શરૂ કરી શકાશે.
(૩) આ અકાદમી વ્યવસ્થિત કામ કરતી થાય તે માટે સરકારે શી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે ?	(૩) ઉપર મુજબ.

વડોદરા શહેરમાં વિધવા મહિલા સહાયની ચૂકવણી અંગે

૮૭૭૦ **શ્રી યોગેશભાઈ ના. પટેલ(રાવપુરા) : માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા શહેરમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ૨ વર્ષમાં વિધવા મહિલા સહાયની કુલ કેટલી અરજીઓ આવી, અને	(૧) ૩૯૦ અરજીઓ.
(૨) તે પૈકી કેટલી વિધવા સહાયની ચૂકવણી કરવામાં આવી ?	(૨) મંજુર થયેલ ૬૨ કેસોમાં રૂા. ૫,૫૮,૪૦૦/-ની સહાય ચૂકવવામાં આવી.

વડોદરા જિલ્લાની માધ્યમિક શાળાઓ ખાનગી ટ્રસ્ટોને સોંપવા અંગે

૮૯૫૪ **શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર. ગોહિલ(સાવલી) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧-૦૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વડોદરા જિલ્લામાં માધ્યમિક શાળાઓ ખાનગી ટ્રસ્ટોને સોંપવા માટે સરકારશ્રી વિચારે છે કે કેમ,	(૪). કોઇ ખાનગી ટ્રસ્ટની માંગણી સામે ગુણવત્તાના આધારે વિચારણા થઇ શકે.
(૨) જો હા, તો આવી શાળાઓ સંભાળવા માટે કેટલા ખાનગી ટ્રસ્ટોની માંગણીઓ આવી, અને	(૨) એકપણ નહિ.
(૩) જો હા, તો તે પૈકી કેટલા ટ્રસ્ટોને સરકારી માધ્યમિક શાળાઓ સોંપવામાં આવી ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટો દ્વારા નિકાલ થયેલ કેસો

૮૧૬૨ **ડૉ. માયાબેન સુ. કોડનાની(નરોડા) માનનીય કાયદા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટો કાર્યરત છે, અને	(૧) ૧૫૨ કોર્ટો
(૨) આ સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં આવી કોર્ટોમાં કેટલા કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો ?	(૨) ૩૨૯૮૮ કેસો.

રાજ્યમાં ગરબા મહોત્સવના આયોજન

૮૬૫૧**શ્રી ભરત બારોટ(દરિયાપુર-કાઝીપુર) : માનનીય રમત-ગમત મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગુજરાતના ગરબાની કળાના પ્રચાર પ્રસાર અર્થે કોઇ મહોત્સવનું આયોજન થાય છે કે કેમ, અને	(૧) હા જી.
(૨) ભવિષ્યના આયોજન માટે સરકાર શું પગલા લેવા માંગે છે ?	(૨) આગોતરુ આયોજન કરી દર વર્ષે જિલ્લા કક્ષાએ અને રાજય કક્ષાએ રાસ ગરબા સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે.

કડી તાલુકામાં વેચાણવેરાની કરચોરી

૮૯૪૭**શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર(કડી) : માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કડી તાલુકામાં વેચાણવેરાની કેટલી કરચોરી પકડવામાં આવી, અને

(૧) રૂા. ૨,૯૦,૩૫,૨૪૧.

(૨) કરચોરી કરતા એકમોની બાકી લેણી રકમની વસુલાત માટે સરકારે શું પગલા ભર્યા ?

(૨) કલમ-૪૮(એ) હેઠળ ટાંચ, ચકાસણી તેમજ વસુલાત અર્થે નમુના-૨૦૦, નમુના-૪૫, નમુના-૩૬, ૬(ખ)ની નોટીસ આપેલ છે.

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કન્યા શાળાઓને મંજૂરી

૮૪૪૪ **શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ(સોમનાથ) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) રાજ્યમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કન્યા શાળાઓની કેટલી મંજૂરી આપી, તેમા ગ્રાન્ટેબલ શાળાઓ કેટલી,

(૧)

વર્ષ	માધ્યમિક		ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક	
	ગ્રાન્ટ સાથે	ગ્રાન્ટ વિના	ગ્રાન્ટ સાથે	ગ્રાન્ટ વિના
૨૦૦૨	૦૦	૧૭	૦૮	૧૧
૨૦૦૩	૦૦	૧૩	૦૦	૦૯
૨૦૦૪	૦૦	૧૨	૦૧	૧૧
કુલ:	૦૦	૪૨	૦૯	૩૧

(૨) તે શાળાઓ ક્યારે શરુ કરવામાં આવી,

(૨) જે તે વર્ષમાં મંજુર થયેલ શાળાઓ શરુ કરવામાં આવી છે.

(૩) હવે સરકાર રાજ્યમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ગ્રાન્ટેબલ કન્યા શાળાઓને મંજૂરી આપવા માંગે છે કે કેમ, અને

(૩) નાણાંકીય ઉપલબ્ધીના આધારે યોગ્ય સમયે વિચારણા કરવામાં આવશે.

(૪) જો હા, તો તાલુકાવાર ઓછામાં ઓછી આવી ગ્રાન્ટેબલ શાળાઓની કેટલી મંજૂરી આપવા વિચારણા છે ?

(૪) નાણાંકીય ઉપલબ્ધીના આધારે યોગ્ય સમયે વિચારણા કરવામાં આવશે.

બી. એડ. અને બી. પી. એડ. ના અભ્યાસક્રમોના નિયમો અંગે

૮૯૬૦**શ્રી ધીરૂભાઈ હ. ગજેરા(સુરત શહેર (ઉત્તર) : માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

બી.એડ., બી.પી.એડ.ના અભ્યાસક્રમો ચાલુ કરવા માટે વર્ષ ૨૦૦૩ અને ૨૦૦૪માં કેટલા એન.ઓ.સી. આપવામાં આવ્યા તે પૈકી એન.સી.ટી.ઈ. એ કેટલી સંસ્થાને મંજૂરી આપી

વર્ષ ૨૦૦૩માં આપેલ એન.ઓ.સી.

બી.એડ.	૬૭
બી,પી.એડ.	૦૮

એન.સી.આર.ટી. એ કેટલી સંસ્થાને મંજૂરી આપી ?	કુલ ૭૫ વર્ષ ૨૦૦૪માં આપેલ એન.ઓ.સી. બી.એડ. ૪૮ બી.પી.એડ. ૦૪ કુલ : ૫૨ એન.ઓ.સી. મેળવેલ સંસ્થાને એન.સી.આર.ટી. એ મંજૂરી આપવાની થતી નથી. પરંતુ એન.સી.ટી.ઇ. ભોપાલ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવે છે.જેની વિગત નીચે મુજબ છે. વર્ષ ૨૦૦૩ : બી.એડ. ૨૬ બી.પી.એડ. ૦૯ કુલ. ૩૫ વર્ષ ૨૦૦૪ : બી.એડ. ૦૮ બી.પી.એડ ૦૨ કુલ : ૧૦

વિધવા મહિલાઓને રોજગારની તાલીમ આપવા અંગે

૮૭૧૫ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી(ભાવનગર શહેર (ઉત્તર) : માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ૪૦ વર્ષથી નીચેની ઉંમરની વિધવા મહિલાઓ માટે રોજગારની તાલીમ આપવાની નવી યોજના સરકાર દ્વારા ક્યારથી શરૂ કરવામાં આવી,	(૧) ૧૮ થી ૪૦ વર્ષની વિધવા સહાય મેળવતી વિધવા મહિલાઓના પુનઃ સ્થાપન માટે તેમને સ્વરોજગારી મળી રહે તેવી તાલીમ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના સહયોગમાં રહીને આપવામાં આવી રહી છે.
(૨) રાજ્યમાં તા. ૩૧-૧-૦૫ સુધીમાં કેટલી વિધવા બહેનોને આવી તાલીમ અપાઇ, અને	(૧) ૫૦૩૪.
(૩) આ યોજનામાં કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?	(૨) તાલીમ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના સહયોગથી અપાઇ રહી હોવાથી સરકારને શિરે કોઇ ખર્ચ કરવાનો પ્રશ્ન નથી.

ભરૂચ જીલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઘટ

૮૩૧૯ **શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ(વાગરા) માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ ભરૂચ જીલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાથમિક શિક્ષકોની કેટલી ઘટ કેટલા સમયથી છે, અને	(૧) એક પણ નહિ.
(૨) આ ઘટ પુરવા રાજ્ય સરકારે શી કાર્યવાહી કરી ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શોકદર્શક ઉલ્લેખો

ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય સ્વ.શ્રી મોહનભાઈ વીસાભાઈ દેસાઈના અવસાન અંગે

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી (મુખ્યમંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતા દુ:ખ થાય છે કે, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય શ્રી મોહનભાઈ વીસાભાઈ દેસાઈનું ૧૫મી સપ્ટેંબર, ૨૦૦૪ના રોજ દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે. સ્વર્ગસ્થશ્રી દેસાઈનો જન્મ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા તાલુકાના ગજનીપુર મુકામે થયો હતો. તેઓશ્રી ખેતીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ હતા. તેઓ ૧૯૬૮માં જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય અને ૧૯૭૨ થી ૧૯૭૮ દરમ્યાન બનાસકાંઠા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બૅન્કના ઉપપ્રમુખ રહ્યા હતા. તેઓશ્રીએ છઠ્ઠી ગુજરાત વિધાનસભામાં બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. સ્વર્ગસ્થશ્રી દેસાઈના અવસાનથી રાજયે એક ઉમદા સમાજ સેવક અને સહકારી આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા (વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આ ગૃહના પૂર્વસભ્ય સ્વર્ગસ્થ મોહનભાઈ વીસાભાઈ દેસાઈના અવસાન અંગે જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈએ આવ્યા છે એમાં હું મારો સૂર પુરાવું છું.

સ્વર્ગસ્થશ્રી મોહનભાઈ દેસાઈ બનાસકાંઠા જેવા પછાત વિસ્તારમાં જન્મ્યા હોવા છતાં સહકારી ક્ષેત્રે ઉત્તમ કામ કર્યું અને જીવનના અંત સુધી તેઓ આ વિસ્તારની સેવા કરતા રહ્યા.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સ્વર્ગસ્થશ્રી મોહનભાઈએ આ ગૃહનું સભ્યપદ શોભાવેલ અને એમના જવાથી એ વિસ્તારને એક ઉમદા માનવીની ખોટ પડી છે. હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના શોકદર્શક ઉલ્લેખમાં મારો સૂર પુરાવું છું અને આપશ્રી મારફત એમના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવવા વિનંતી કરું છું.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી (ભા.રા.કો.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઠરાવ લઈને આવ્યા છે અને વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીએ સમર્થન આપ્યું છે એમાં હું મારો સૂર પુરાવું છું.

સ્વર્ગસ્થશ્રી મોહનભાઈ દેસાઈ મારા તાલુકાના અને મારા રિલેટિવ હતા. એમનું નામ મોહનભાઈ હતું પરંતું તેઓ મફાભાઈના હુલામણા નામે ઓળખાતા હતા. મફાભાઈ બિલકુલ ઓછા ભણેલા હતા પરંતુ કુદરતી સૂઝ અને સમજ એટલી હતી કે એમણે સહકારી લેવલે છેક ૧૯૬૮માં પંચાયતમાં ચૂંટાયા હતા, જે લોકલ બોર્ડ હતું તે વખતે ત્યારે પણ તેમાં તેઓ હતા. પંચાયત આવ્યું ત્યારે પણ આવ્યા અને સહકારી લેવલે બૅન્ક, સહકારી મંડળી, ડીસા તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘમાં પણ બે ટર્મ રહ્યા હતા અને સાથે સાથે એક ગોપાલક છાત્રાલય પણ એમણે ૧૯૮૨-૮૩માં ચાલુ કર્યું હતું એ આજે પણ ચાલુ છે. સ્વર્ગસ્થશ્રી મોહનભાઈ દેસાઈ મારા વિસ્તારના સમગ્ર જિલ્લાના અને ગુજરાતના રબારી સમાજના એક મોટા આગેવાન હતા. જેમણે સમાજના રીતરિવાજો માટે પણ ક્રાંતિરૂપ કાર્ય કર્યું હતું એ અમે ગુજરાત અને બનાસકાંઠા જિલ્લો કદી ભૂલી શકીએ એમ નથી. સ્વર્ગસ્થશ્રી મોહનભાઈ કાયમ માટે શિક્ષણ અને ખેડૂતો માટેની વાત લઈને નીકળતા હતા. એમણે અંત સુધી સહકારી લેવલની સંસ્થાઓ કેવી રીતે મજબૂત થાય અને એમાં ખેડૂતોને લાભ કેવી રીતે વધુ મળે એ એમનો કાયમ ધ્યેય રહ્યો હતો એ આજે અમે કદી ભૂલી શકીએ એમ નથી. સ્વર્ગસ્થશ્રી મોહનભાઈના જવાથી સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાને અને ગુજરાતના માલધારી-રબારી સમાજને એક મોટી ખોટ પડી છે. સ્વર્ગસ્થશ્રી મોહનભાઈના આત્માને પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતિ આપે અને એમના કુટુંબીજનો ઉપર આવી પડેલ દુ:ખ સહન કરવાની પ્રભુ એમને શકિત આપે એજ પ્રાર્થના સાથે હું એમને મારી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પુ છું.

શ્રી હરજીવન હી. પટેલ (ભા.જ.પ.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહના નેતા જે શોકદર્શક પ્રસ્તાવ લાવ્યા છે અને વિરોધપક્ષના નેતાએ જેને સમર્થન આપ્યું છે તેમાં હું પણ મારો સૂર પૂરાવું છું. મોહનભાઈ વીસાભાઈના અવસાનના સમાચાર મળ્યા પછી તે વિસ્તારની અંદર જે પછાત વિસ્તાર હતો ત્યાં બે દિવસ શોકનું વાતાવરણ સર્જાયું. તેમનું જે હુલામણું નામ હતુ મફાભાઈ, તે મફાભાઈના હુલામણા નામથી પ્રસિધ્ધ હતા. એક ધારાસભ્ય બન્યા પછી તે માજી ધારાસભ્ય થયા પછી પણ લોકો તેમની પાસે ગમે તે કામ લઈને ગયા, નાના મોટા કામમાં કયારેય પોતે પાછી પાની કરી નથી અને સદાય તેમનો હસમુખો ચહેરો, તમે ગમે ત્યારે મળો તો તેમના મોઢા ઉપર હાસ્ય હોય. આવો એક કર્મઠ માજી ધારાસભ્ય બનાસકાંઠા જિલ્લાએ ગુમાવ્યો છે. તેમના વિસ્તારના લોકોને, તેમના સમાજને જે મોટી ખોટ પડી છે પ્રભુને પ્રાર્થના કે તેમના આત્માને શાંતિ અર્પે અને તેમના પરિવારજનોને દુ:ખ સહન કરવાની શકિત અર્પે.

શ્રી શંકરભાઈ લ. ચૌધરી (ભા.જ.પ.): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીયશ્રી મફાભાઈ જેમના મૃત્યુથી માલધારી સમાજને ખાસ કરીને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે સમાજો શિક્ષણમાં પછાત રહી ગયા છે તેમને મફાભાઈના મૃત્યુને કારણે બહુ મોટી ખોટ પડશે. ગરીબમાં ગરીબ માણસ તેમને માટે પણ ચિંતા કરવાવાળા આ માણસ હતા. એક વખત બનાસકાંઠા જિલ્લાની ગાયો સરહદ ઉપર ચરતા ચરતા પાકિસ્તાનની સરહદમાં જતી

રહી. તે પછી પરત લાવવા માટે શું કરવું? તો ત્યાંના સરહદના માલધારી ગરીબ હોય તે લોકો કોની પાસે વાત લઈ જાય, કોણ તેમની વાત સાંભળે એવો સમય આજથી ૧૫ વર્ષ પહેલાં હતો ત્યારે આ મોહનભાઈ મફાભાઈ તેમણે આ ગરીબ પરિવારની વાત સાંભળી અને તેમના માટે છેક રાજય સરકાર અને દિલ્હી સુધી પ્રયત્ન કરી ગરીબ માણસની ગાયો પરત લાવવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. શિક્ષણના ક્ષેત્રે પણ તેમણે ખૂબ સારું કામ કર્યુ છે. અમારા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે પછાત જ્ઞાતિઓ છે ત્યાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ઓછું છે તેવી તમામ જ્ઞાતિઓને અને ખાસ કરીને માલધારી સમાજને મફાભાઈની ખૂબ મોટી ખોટ પડશે. તેમના મૃત્યુથી તેમના પરિવારજનો ઉપર જે આફત આવી છે પરમાત્મા તેમને દુ:ખ સહન કરવાની શકિત અર્પે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ગૃહના નેતાશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઈને આવ્યા છે અને માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જેને અનુમોદન આપ્યું છે અને માનનીય ગોવાભાઈ, હરજીવનભાઈ, શંકરભાઈએ તેમાં જે સૂર પૂરાવ્યો છે, તેમાં હું પણ મારો સૂર પૂરાવું છું, માનનીય મોહનભાઈ રબારી સમાજમાંથી આવતા હતા, માલધારી સમાજમાંથી આવતા હતા. માલધારી સમાજમાં જે કુરૂઢિઓ કહેવાય, કેટલીક પ્રથાઓ જે નાબૂદ કરવા જેવી હોય, તે વિવાદો દૂર કરવા માટે તેમણે જે ખૂબ જહેમત ઉઠાવી. આખા રબારી સમાજની આગેવાની લઈને જે પ્રશ્નો હતા, તે તમામ પ્રશ્નોમાં તેઓ સાથ આપતા હતા, છેલ્લે શંકરભાઈએ જે વાત કરી, તેમ તેઓ સામાન્ય માનવીની વાત પણ સાંભળતા હતા, આપણે એક સેવાભાવી, કર્મવીર ગુમાવ્યો છે, આપણે બધા આપણા સ્થાન ઉપર ઉભા થઈ સદ્‌ગતના માનમાં બે મિનિટ મૌન પાળીએ.

(બે મિનિટ મૌન બાદ)

ગૃહની આ લાગણી તેમના સ્વજનોને વહેલામાં વહેલી તકે મોકલી આપવામાં આવશે.

તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (નિયમ-૧૧૬)
રાષ્ટ્રીય પક્ષીની ક્રૂર હત્યા કરવા અંગે

શ્રી શીવજીભાઈ ક. આહીર(ભૂજ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નિયમ-૧૧૬ અન્વયે નીચે જણાવેલી તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય વનમંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરું છું અને તે અંગે તેમને નિવેદન કરવા વિનંતી કરું છું.

"તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકાના પીપરાળી ગામની સીમમાં છ રાષ્ટ્રીય પક્ષી એટલે કે ચાર ઢેલ અને બે બચ્ચાંની ક્રૂર હત્યા કરી જમીનમાં દાટી દેવાયેલ મળી આવતાં રોષ તથા ધિક્કારની લાગણી દૂર કરવા, આરોપીને શિક્ષા કરવા તથા મોરના રક્ષણ માટે સરકારે લીધેલાં કે લેવા ધારેલાં પગલાં."

શ્રી મંગુભાઈ છ. પટેલ (વન અને પર્યાવરણમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તારીખ ૧૨-૨-૨૦૦૫ના રોજ પરિક્ષેત્ર વન અધિકારી ચોટીલાને બાતમી મળેલ હતી કે પીપરાળી ગામના રહેવાસી શ્રી વાઘાભાઈ મેરાભાઈની વાડીમાં મોર મારી દાટી દીધેલ છે જેથી પરિક્ષેત્ર વન અધિકારી, ચોટીલા, પશુ ચિકિત્સા અધિકારી, ચોટીલા વન ખાતાનો સ્ટાફ તથા પંચો સાથે પીપરાળીથી નાવીયાણી ગામે જતાં રસ્તા ઉપર આવેલ શ્રી વાઘાભાઈની વાડીમાં તપાસ કરતાં વાડીમાં શ્રી વાઘાભાઈના પુત્ર શ્રી વેલસી વાઘા હાજર હતાં. વાડીમાં તપાસ કરતાં ખડાવાડ બાજુ દુર્ગંધ આવતા કપાસની સાઠીના ઢગલા નીચે તાજો ખાડો ખોદી માટી પૂરાયેલ જણાતાં, ખાડો ખોદી જોતાં તેમાંથી ચાર ઢેલ અને બે બચ્ચાના મૃતદેહ મળી આવેલા હતાં. આ મોરના મૃત્યુ ૫ થી ૬ દિવસ પહેલાં થયાનું જણાતું હતું. મૃતદેહ કોહવાઈ ગયેલ હતાં જેથી સ્થળ ઉપર પશુ ચિકિત્સા દ્વારા પરીક્ષણ કરેલ હતું. મૃતદેહ સડી ગયેલ હોવાથી વિશેરા (જઠર, આંતરડા અને યકૃતનો ભાગ) લઈ શકાયેલ ન હતો.

શ્રી વેલસી વાઘાની પૂછપરછ કરતાં જણાયેલ કે આજથી ૫ થી ૬ દિવસ પહેલાં તેમની વાડીની બાજુમાં ચાર ઢેલ અને બે બચ્ચાં મરી ગયેલ પડેલ હતાં જેથી દુર્ગંધ ન આવે તે હેતુથી તેણે તેની વાડીમાં ખડાવાડમાં ખાડો ખોદી દાટી દીધેલ હતાં.

સદરહુ બાબતે વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨ અન્વયે ચોટીલા રાઉન્ડ ગુના નંબર ૨/૨૦૦૪-૦૫ અન્વયે ગુનો નોંધી શ્રી વેલસી વાઘાની ધરપકડ કરી ફર્સ્ટ કલાસ જયુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટ, ચોટીલામાં તારીખ:૧૪-૨-૨૦૦૫ના રોજ રજૂ કરવામાં આવેલ હતા. આરોપી સગીર વયનો હોવાથી સુરેન્દ્રનગર બાળ અદાલતમાં રજૂ કરવાનો હુકમ કરતાં આરોપીને સુરેન્દ્રનગર ખાતે બાળ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવેલ હતો. બાળ અદાલતે આરોપીને જામીન પર મુકત કરેલ છે. શ્રી વાઘાભાઈ મેરાભાઈ, ઉંમર વર્ષ-૬૦, રહેવાસી પીપરાળીની તારીખ ૧૮-૨-૨૦૦૫ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે.

ઢેલ અને બચ્ચાંના મૃત્યુના કારણો અંગે ચોટીલા રેન્જના સ્ટાફ દ્વારા તપાસ ચાલુ છે. આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ કરતાં બીજો કોઈ મોર મૃત હાલતમાં મળી આવેલ નથી. આસપાસના ખેડૂતોને આ અંગે તકેદારી રાખવા જણાવવામાં આવેલ છે. આમ, રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરના મૃત્યુથી જનતામાં રોષ ફેલાયેલ નથી તથા ધિક્કારની લાગણી થયેલ નથી. આરોપીને શિક્ષા માટે નામ.કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલ છે. આવા બનાવો ન બને તે

માટે ખેડૂતોને શિબિરો યોજી જાગૃતિ લાવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે તેમજ વન ખાતાના સ્ટાફને પણ આ અંગે સતર્કતા જાળવવા સૂચના આપેલ છે.

શ્રી શીવજીભાઈ ક. આહીર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચોટીલા તાલુકાના પીપરાળી ગામની સીમમાં રાષ્ટ્રીય પક્ષી ઢેલ અને તેમના બચ્ચાંની ક્રૂર હત્યા કરી અને દાટી દેવામાં આવેલ. રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરની રાજયમાં છેલ્લાં ત્રણ વર્ષની બેફામ હત્યા થઈ રહી છે આ બાબતે વારંવાર સરકારને લેખિતમાં રજૂઆત કરેલ છે. દુ:ખની વાત એ છે કે, સમગ્ર દેશમાં મોરની હત્યાનું વધુમાં વધુ પ્રમાણ ગુજરાત રાજયમાં છે. રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરની હત્યા રાજયમાં કેમ અટકાવી શકાતી નથી? રાષ્ટ્રીય પક્ષીની હત્યા અટકાવવા માટે રાજયવ્યાપી કોઈ વિશેષ પગલાં સરકાર લેવા માગે છે કે નહી? ગાય અને ગૌવંશ હત્યા માટે પાસાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવેલ છે. મોર તો રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે અને વન્ય સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ રક્ષિત છે છતાં ગંભીર ગુન્હો અટકાવવા માટે સરકારના પાસાની કલમ લેવા માગે છે કે નહીં કે પછી વિશેષ જોગવાઈ કરવા માગે છે કે નહીં તે આપના મારફતે હું જાણવા માગું છું.

શ્રી મંગુભાઈ છ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૧૯૭૨ના અધિનિયમ હેઠળ તેના ઉપર ગુન્હો દાખલ કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તેમણે ચોખ્ખું પૂછેલું છે કે તેમને પાસા હેઠળ કે કડકમાં કડક શિક્ષા કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? આ રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે અને આવા અનેક પક્ષીઓનું મૃત્યુ થતું હોય ત્યારે તેની સામે કડકમાં કડક શિક્ષા અને તે અંગે કોઈ નિયમો ઘડવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી મંગુભાઈ છ. પટેલ : જે નિયમો બનેલાં છે નિયમમાં જે ગુન્હો કર્યો છે તેની જે કલમ છે તે કલમ હેઠળ ગુન્હો દાખલ કરેલો છે અને તેમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : નિયમ છે છતાં પણ આવા બનાવો વારંવાર દરેક જિલ્લામાં બનતાં હોય છે અને રાષ્ટ્રીય પક્ષીની હત્યા થતી હોય છે તો નિયમને કોઈ કડક બનાવવા કે સુધારા કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી મંગુભાઈ છ. પટેલ : આમાં કડક નિયમો છે જ તે જો સાબિત થાય તો ત્રણથી સાત વર્ષ સુધીની સજા થાય છે અને ૨૫ હજાર સુધીનો દંડ થાય છે.

શ્રી યોગેશભાઈ ના. પટેલ : આ પક્ષીઓ મારવાની બાબતમાં મોર મારવાની બાબતમાં અત્યાર સુધીમાં કોઈને સજા થઈ છે કે કેમ?

શ્રી મંગુભાઈ છ. પટેલ : ગુન્હો સાબિત થાય તો સજા થાય છે.

શ્રી શંકરભાઈ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મોરની કોઈએ હત્યા કરી હોય અથવા તેનું નેચરલી મૃત્યું થયુ હોય તો આ બન્ને વચ્ચે કઈ રીતે અલગ કરી શકાય. બીજું મોરનું નેચરલી આયુષ્ય કેટલું? કે જેના આધારે ખબર પડે કે આ મોરને તેની ઉંમરના આધારે નકકી થઈ શકે કે તેનું મૃત્યું બિમારીના કારણે કે કોઈના મારી નાખવાથી કે કુદરતી રીતે થયુ છે.

શ્રી મંગુભાઈ છ. પટેલ : નેચરલી મૃત્યુનું કારણ નથી પરંતુ પશુ ચિકિત્સક તેનું જઠર અને તે લઈને પછી સાયન્સ લેબોરેટરીમાં લઈ જાય છે અને તેની ચકાસણી કરીને ખબર પડે છે કે ખરેખર આને કોઈને મારી નાંખ્યુ છે કે કેમ.

શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મોર રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે જે વ્યકિતએ શિકાર કર્યો છે તે વ્યકિતએ ઢેલ અને તેનાં બચ્ચાંને તેના જ ખેતરમાં દાટી દીધાં. તેણે શિકાર કર્યો તો તે ખાઈ જાય તો તેને દાટી શું કામ દીધા? તો આ તપાસ માગી લેવા જેવો દાખલો છે. તો આની કાયદેસર તપાસ થઈ છે કે જે સાચા ગુન્હેગારો હોય તેને પકડવા જોઈએ. નિર્દોષ લોકો તેમાં સંડોવાય નહીં, ખેતરનો માલિક તે માટે હું સરકારનું ધ્યાન દોરું છું.

શ્રી મંગુભાઈ છ. પટેલ : વેલજી વાઘા એ છોકરાએ પોતે કબૂલ કર્યું છે કે પોતે દાટયા છે અને તે રીતે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેના પિતાશ્રી વાઘા મેરા તેમની પણ ધરપકડ કરી છે અને પછી તેમને જામીન ઉપર છોડયાં છે.

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો

ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલના ઓડિટ અહેવાલ

શ્રી વજુભાઈ વાળા (નાણામંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું

(૧) **(ક)** ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલનો સન ૨૦૦૨-૨૦૦૩ ના વર્ષનો ઓડિટ અહેવાલ (મુલ્કી),

(ખ) ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલનો સન ૨૦૦૨-૨૦૦૩ ના વર્ષનો ઓડિટ અહેવાલ (મહેસૂલી આવક)

(ગ) ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલનો સન ૨૦૦૨-૨૦૦૩ ના વર્ષનો ઓડિટ અહેવાલ (વાણિજિયક)
-સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.
ઓડિટ અહેવાલો સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યા.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના મારફત ઓચિત્ય ભંગનો મુદ્દો ઉપસ્થિત કરવા માગું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય નેતાશ્રી, ઔચિત્ય ભંગનો મુદ્દો ઉપસ્થિત કરતા પહેલા આપે મારું ધ્યાન દોરવું જોઈએ. મને લેખિત આપવું જોઈએ અને પછી આ ઔચિત્ય ભંગનો મુદ્દો ઉપસ્થિત કરી શકાય. અત્યારે કરી શકાય નહીં.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ...

અધ્યક્ષશ્રી : નો, નો. આ રૂલીંગ છે. નેકસ્ટ.

ગુજરાત રાજય મૂડી રોકાણ નિગમ લિમિટેડનો વાર્ષિક અહેવાલ

શ્રી વજુભાઈ વાળા : (નાણામંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું ગુજરાત રાજય મૂડી રોકાણ નિગમ લિમિટેડનો સન ૨૦૦૩-૨૦૦૪ નો વાર્ષિક અહેવાલ, હિસાબો અને ઓડિટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલની ટિપ્પણ તથા નિગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવાની રજા લઉં છું.

ઓડિટ અહેવાલ, ટિપ્પણ, અને સમીક્ષા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

ગુજરાત સ્ટેટ ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડનો વાર્ષિક અહેવાલ

શ્રી વજુભાઈ વાળા (નાણા મંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું ગુજરાત સ્ટેટ ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડનો સન ૨૦૦૩-૨૦૦૪નો વાર્ષિક અહેવાલ, હિસાબો અને ઓડિટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલની ટિપ્પણ તથા નિગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

ઓડિટ અહેવાલ, ટિપ્પણ, અને સમીક્ષા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

સામાન્ય વહીવટ વિભાગની અધિસૂચના

શ્રી અમિત અ.શાહ (રાજય કક્ષાના ગૃહ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સામાન્ય વહીવટ વિભાગની સન ૧૯૬૦ ના ગુજરાત મંત્રીશ્રીઓના પગાર અને ભથ્થાં અધિનિયમ, અન્વયેની તા. ૮-૧-૨૦૦૫ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:-ગસ/૦૫/૧/એમ.ટી.આર-૨૦૦૫/(૧)-કેયુ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અધિસૂચના સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવી.

નાણા વિભાગની અધિસૂચનાઓ

શ્રી વજુભાઈ વાળા (નાણામંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું
(ક) નાણા વિભાગની-
સન ૧૯૬૯ ના ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ અન્વયેની-
(૧) તા. ૧-૬-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૧૪)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૮૭)-ઠ
(૨) તા. ૧૧-૬-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૧૫)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૮૮)-ઠ
(૩) તા. ૧-૭-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૧૯)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૮૯)-ઠ
(૪) તા. ૧-૭-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૨૦)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૯૦)-ઠ
(૫) તા. ૧૨-૭-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૨૧)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૯૧)-ઠ
(૬) તા. ૧૨-૭-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૨૩)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૯૨)-ઠ
(૭) તા. ૨૨-૭-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૨૪)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૯૩)-ઠ
(૮) તા. ૨૩-૭-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૨૬)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૯૪)-ઠ
(૯) તા.૩૦-૭-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૨૭)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૯૫)-ઠ
(૧૦) તા. ૧-૯-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૩૮)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૯૬)-ઠ
(૧૧) તા. ૧૧-૯-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૩૯)જીએસટી-૨૦૦૪- (એસ.૪૯)(૩૯૭)-ઠ
(૧૨) તા. ૯-૧૧-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૫૧)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૨૩)(૪)-ઠ
(૧૩) તા. ૯-૧૧-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૫૨)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૪૯)(૩૯૮)-ઠ

(૧૪) તા. ૧૦-૧૨-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૫૪)જીએસટી-૨૦૦૪-(એસ.૨૩)(૫)-ઠ
(૧૫) તા. ૨૨-૬-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૧૭)જીએસઆર-૨૦૦૪ (૧૦૮)-ઠ
(૧૬) તા. ૧૨-૭-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૨૨)જીએસઆર-૨૦૦૪(૧૦૯)-ઠ
(૧૭) તા. ૧-૧૧-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૪૪)જીએસઆર -૨૦૦૪-(૧૧૦)-ઠ,

(ખ) સન ૧૯૫૮ ના મુંબઈ મોટર સ્પિરીટ અધિનિયમ અન્વયેની તા.૧૧-૬-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૧૬)એમએસએ-૨૦૦૪-(એસ.૩૫)(૫૯)-ઠ,
(ગ) સન ૧૯૭૬ ના ગુજરાત રાજય વ્યવસાય, વ્યાપાર, ધંધા અને રોજગાર વેરા અધિનિયમ અન્વયેની-
(૧) તા. ૨૪-૮-૨૦૦૪ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૩૪)પીએફટી-૨૦૦૪(એસ.૨૭)(૧)(૮)-ઠ,
(૨) તા. ૧-૧૧-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૪૫)પીએફટી-૨૦૦૪-એસ.૨૭)(૯)-ઠ,
(ઘ) સન ૧૯૮૯ ના ગુજરાત શેરડી ઉપર ખરીદવેરા અધિનિયમ અન્વયેની તા. ૧-૧૧-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક: (જીએચએન-૪૬)જીપીઆર-૨૦૦૪-(૫)-ઠ,
(ચ) સન ૧૯૯૫ ના ગુજરાત સુખસુવિધા ચીજવસ્તુ કર અધિનિયમ અન્વયેની તા. ૧-૧૧-૨૦૦૪ ની અધિસૂચના ક્રમાંક:(જીએચએન-૪૭)એલ.સી.આર-૨૦૦૪-(એસ.૬)(૨)-ઠ,
-સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અધિસૂચનાઓ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવી.

અધ્યક્ષશ્રીની જાહેરાત
વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સેનેટ પર સભ્યશ્રીની ચૂંટણી અંગે

અધ્યક્ષશ્રી : મારે એક જાહેરાત કરવાની છે. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સેનેટ પર ગુજરાત વિધાનસભાના એક પ્રતિનિધિની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ હું નીચે મુજબ ઠરાવું છું.

નામ નિર્દેશન પત્રો સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય : મંગળવાર, તા.૧-૩-૨૦૦૫ સાંજના ૬ વાગ્યા સુધી.

નામ નિર્દેશન પત્રોની ચકાસણીની તારીખ, સમય અને સ્થળ : બુધવાર, તા.૨-૩-૨૦૦૫, બપોરના ૩-૦૦ વાગ્યે, નાયબ સચિવ શ્રી મહેન્દ્ર જે.પરમારની ચેમ્બરમાં.

નામ નિર્દેશન પત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય: બુધવાર, તા.૯-૩-૨૦૦૫, સાંજના ૫-૦૦ વાગ્યા સુધી.

મતદાન જો જરૂરી બને તો તારીખ અને સમય : પાછળથી જાહેર કરવામાં આવશે.

આ ચૂંટણી માટેના નામ નિર્દેશન પત્રો કામકાજના દિવસ અને સમય દરમ્યાન વિધાનસભાના મકાનમાં પહેલા માળે આવેલ સમિતિ શાખા-૧ માંથી મળી શકશે.

વિધાનસભાની નાણાકીય સમિતિઓના ચૂંટણી કાર્યક્રમની જાહેરાત

અધ્યક્ષશ્રી : હું એક જાહેરાત કરું છું. અંદાજ સમિતિ, જાહેર હિસાબ સમિતિ, જાહેર સાહસો માટેની સમિતિ અને પંચાયતી રાજ સમિતિની ચૂંટણી માટે હું નીચે મુજબનો કાર્યક્રમ ઠરાવું છું.

નામ નિર્દેશન પત્રો સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય : મંગળવાર, તા.૧-૩-૨૦૦૫,સાંજના ૬-૦૦ વાગ્યા સુધી.

નામ નિર્દેશન પત્રોની ચકાસણીની તારીખ, સમય અને સ્થળ : બુધવાર,તા.૨-૩-૨૦૦૫,સાંજના ૫-૩૦ કલાકે નાયબ સચિવશ્રી મહેન્દ્ર જે.પરમારની ચેમ્બરમાં.

નામ નિર્દેશન પત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય : બુધવાર, તા.૯-૩-૨૦૦૫,સાંજના ૫-૦૦ વાગ્યા સુધી.

મતદાન જો જરૂરી બને તો તારીખ, સમય અને સ્થળ : પાછળથી જાહેર કરવામાં આવશે.

આ ચૂંટણી માટેના નામ નિર્દેશન પત્રો કામકાજના દિવસ અને સમય દરમ્યાન વિધાનસભાના મકાનમાં પહેલા માળે આવેલ સમિતિ શાખા-૧ માંથી મળી શકશે.

વટહુકમ નામંજૂર કરતા પ્રસ્તાવો અને સરકારી વિધેયકો

સન ૨૦૦૫ નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક:૧
ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫
ગુજરાતનો પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) બાબતનો અધિનિયમ, ૧૯૬૩ રદ કરવા બાબત વિધેયક

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ(અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા.નામંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજપત્રમાં અગાઉ પ્રસિધ્ધ થયેલા સન ૨૦૦૫ નું વિધેયક ક્રમાંક-૧-સન ૨૦૦૫ નું ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયકને હું આપની પરવાનગીથી દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫ નું વિધેયક ક્રમાંક-૧-સન ૨૦૦૫ નું ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું પહેલું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૧૯૬૩ માં ગુજરાત પ્રેત ભોજન નિયંત્રણ અધિનિયમ, ૧૯૬૩ અધિનિયમ જે તે સમયની વર્તમાન જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અને જાહેર હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખીને ધાર્મિક વિધિ પાછળ થતા ખાદ્ય સામગ્રી અને ખાદ્ય પદાર્થોના દૂરૂપયોગને અટકાવવા માટેનો હેતુ ધ્યાનમાં રાખીને આ વિધેયક જે તે સમયે અમલમાં લાવવામાં આવેલ હતું. ખાસ કરીને તે વખતે જયારે ખાદ્ય પદાર્થોની અછત અને અભાવ હોવાથી અને તેનો આવી મૃત્યુ પછીની ધાર્મિક વિધિઓ છે તેમાં અનાજનો બગાડ થતો હતો એને અટકાવવા માટે જે તે સમયે આ વિધેયક લાવવામાં આવેલ હતું. આ વિધેયકની જોગવાઈઓ અને કલમોને રદબાતલ કરતું સન ૨૦૦૫ નું નવું વિધેયક આ સભાગૃહમાં લાવવામાં આવ્યું છે. આ જ બાબતોને લગતું અને આ જ ઉદ્દેશોને લગતું નવું વિધેયક ૧૯૬૯ Gujarat Food Stuff Order and Regulation of Use or Disposal in Sacrifice Order ૧૯૬૯. આ ૧૯૬૯ નું આ વિધેયક અત્યારે અમલમાં છે અને જે જૂનું વિધેયક હતું એની તમામ કાર્યવાહી અને જોગવાઈઓ આ વિધેયકના દ્વારા કરવામાં આવી છે. એટલે ૧૯૬૩ નું જે વિધેયક છે એ બિનજરૂરી હોવાથી આજે આ સભાગૃહમાં ઐ વિધેયક રદબાતલ કરવા માટેનું વિધેયક હું લાવ્યો છું.

શ્રી ટપુભાઈ લીંબાસિયા (રાજકોટ-૧): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી ગુજરાત પ્રેત ભોજન રદ કરવા અંગેનુ જે વિધેયક લઈને આવ્યા છે તેને હું મારું અનંમોદન આપું છું અને આ વિધેયક દ્વારા એનો કાયદાકીય રીતે જે દૂરુપયોગ થતો હતો જેમ કે ગામડાંની અંદર અભણ માણસોને પંચાયતની ચૂંટણી કે એવા સમયે અંદરોઅંદર વેરઝેર હોય એ સમયે જેને આ કાયદાનો ખ્યાલ નહોતો અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા એનો કાયદાકીય રીતે ખોટી રીતે દૂરુપયોગ કરીને કેસ કરવામાં આવતા હતા. હવે આ નિયંત્રણ આવાથી એ દૂર થશે અને ગ્રામ્ય પ્રજાને જે ખટપટનો ભોગ બનવું પડતું હતું એમાં આ નિયંત્રણ આવવાથી એમને મોટો ફાયદો થશે. આ કાયદો જે લાવવામાં આવ્યો છે એના માટે હું માનનીય મંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું અને સરકારને પણ અભિન્નંદન આપું છું.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી (ડીસા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી આ વિધેયક લઈને આવ્યા છે તેમાં અમને કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ માનનીય સભ્યશ્રીએ વાત કરી કે લોકો ઉપર ખોટા કેસ થતા હતા એ વાત ખોટી છે. જે તે વખતે અનાજ અને દરેક ચીજવસ્તુઓની અછત હતી, આપણે ત્યાં એનું ઉત્પાદન ઓછું હતું. એટલે એની જરૂરિયાત જળવાઈ રહે અને ગરીબ અને બીજા માણસોને હેરાનગતિ ના થાય એના માટેનું આ વિધેયક હતું. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે એમણે વાત કરી કે કાયદાનો સહારો લઈને ખોટા કેસ થતા હતા, પરંતુ એવું નથી. એ વખતે તો આપણે આઝાદ થયેલા હતા અને દેશમાં ખાવા માટે અનાજ નહોતું અને બહારથી સડેલા ઘઉં લાવીને આપણે ખાતા હતા. તો આ પરિસ્થિતિ હોવાને લીધે તે વખતે આ વિધેયક લાવવામાં આવેલ હતું અને ખોટા કેસ થતા હતા તેવી વાત નથી.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૧-સન ૨૦૦૫નું ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું બીજું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.
કલમ-૨ અને કલમ-૧, દીર્ઘસંજ્ઞા અને ઈનેકટીંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

* (વિધેયક તા.૫ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ ના ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.)

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૧-સન ૨૦૦૫નું ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે અને તેને પસાર કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૧-સન ૨૦૦૫નું ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે છે અને તેને પસાર કરવામાં આવે છે.

સન ૨૦૦૫નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક-૨.

મુંબઈનું વજન અને માપ (અમલ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫

ગુજરાત રાજયને લાગુ પડતો હોય તેટલા પૂરતો, સન ૧૯૫૮નો મુંબઈનો વજન અને માપ (અમલ) અધિનિયમ રદ કરવા બાબત વિધેયક.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ (અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા.નામંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૨-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈનું વજન અને માપ (અમલ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક હું આપની પરવાનગીથી દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૨-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈનું વજન અને માપ (અમલ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૧૦૫૮માં વજન અને માપના ધોરણોના અમલ માટેની જોગવાઈ કરવા માટે વજન માપ ધોરણ અમલ અધિનિયમ અધિનિયમિત કરવામાં આવ્યો હતો. અને તેની કલમો, શરતો અને જોગવાઈઓ અમલમાં હોવા છતાં કેન્દ્ર સરકારે નવો અધિનિયમ ૧૯૮૫ અધિનિયમિત કરેલ છે. તેની કલમ ૭૫ મુજબ જે તે રાજયોમાં આ બાબતનો કાયદો હોય તો તે રદ કરવાની જોગવાઈ એમાં સામેલ કરવામાં આવી છે, એટલે આ તબક્કે ગુજરાત રાજયનો આ અધિનિયમ ૧૯૫૮ વજન અને માપના ધોરણના અમલ માટેની જોગવાઈઓને રદ કરવાનું જરૂરી જણાયું હોય આ વિધેયકને હું સભાગૃહ સમક્ષ લાવ્યો છું.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરુ છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૨-સન ૨૦૦૫નું મુંબઇનું વજન અને માપ (અમલ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું બીજું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ-૨, કલમ-૧ દીર્ઘસંજ્ઞા અને ઈનેકિટંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરુ છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૨-સન ૨૦૦૫નું મુંબઇનું વજન અને માપ (અમલ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે અને તે પસાર કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫નું મુંબઇનું વજન અને માપ (અમલ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે છે અને તે પસાર કરવામાં આવે છે.

સન ૨૦૦૫નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક-૩

ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)(સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫

ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)અધિનિયમ, ૨૦૦૪ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક

* **વિધેયક તા.૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.**

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા (માહિતી અને પ્રસારણમંત્રીશ્રીનો હવાલો): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજયપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૩-સન ૨૦૦૫નું ગુજરાત સિનેમા (નિયમન) (સુધારા) વિધેયક આપની પરવાનગીથી હું દાખલ કરુ છું

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરુ છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૩-સન ૨૦૦૫નું ગુજરાત સિનેમા (નિયમન) (સુધારા) વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત સિનેમા અધિનિયમ ૨૦૦૪ની કલમ-૪ હેઠળ પોલીસ કમિશ્નરશ્રીના વિસ્તારમાં વિડિયો અને સિનેમાના પરવાના અધિકારી તરીકે પોલીસ કમિશ્નરશ્રી રહેલ છે. જ્યારે જિલ્લાઓમાં પરવાના અધિકારી તરીકે સબંધિત જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રીઓ રહેલા છે. પોલીસ કમિશ્નરશ્રીના વિસ્તારમાં પરવાના અધિકારી અને મનોરંજન કરની વસુલાત કરનાર અધિકારી બંને અલગ અલગ સંસ્થાઓ છે. તેથી બંનેની કચેરીઓ પણ અલગ અલગ રહેલી છે.

પોલીસ કમિશ્નરશ્રીના વિસ્તારના સિનેમા સંચાલકો તથા વિડિયો સંચાલકોને પરવાના મેળવવા, પરવાના રીન્યુ કરવા અથવા પરવાના સબંધિત અન્ય નિયમોના પાલન માટે પોલીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીએ જવું પડે છે. જ્યારે આજ વિસ્તારના સિનેમા સંચાલકોને, વિડિયો સંચાલકોને મનોરંજન કર અને મનોરંજન કરના પાલન સબંધિત અન્ય કામગીરી માટે મનોરંજન કર એટલે કે કલેકટરશ્રીની કચેરીમાં જવું પડે છે. એમ પોલીસ કમિશ્નરશ્રીના વિસ્તારના સિનેમા સંચાલકો તથા વિડિયો સંચાલકોને બે-બે કચેરીઓમાં જવું પડે છે. આવી સ્થિતિમાં સંચાલકોને હાલાકી પડે છે. તેથી સરકાર અને લોકોના હિતમાં તે રહેલ નથી અને આવી મુશ્કેલી નિવારવા સરળતા ખાતર આપણે આ પ્રકારની કાર્યવાહી સૂચવેલ છે. બધી જગ્યાએ જિલ્લા કલેકટરશ્રીને મનોરંજન કર જિલ્લા કલેકટરશ્રીઓને આપવામાં આવે. પોલીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી અને કલેકટરશ્રીની કચેરીની કામગીરી તદ્દન ભિન્ન રહેલી છે. જ્યારે સિનેમાનો કાયદો અને મનોરંજનનો કાયદો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. તેથી કર વસુલાત અધિકારી અને પરવાના અધિકારી જો એકજ હોય તો બંને કાયદા હેઠળ નિયમોનું પાલન પણ સારી રીતે થઈ શકે. આની સાથે સાથે લોકોને બે અલગ અલગ જગ્યાએ ધક્કા ખાવા ન પડે. એક જગ્યાએ નિયમ અનુસાર મંજૂરી અને બાકીની મંજૂરી વસુલાત માટે સરળ રીતે બની શકે. પોલીસ કમિશ્નર વિસ્તારમાં વિડિયો તથા સિનેમા ગૃહોને લાઇસન્સ આપવાની સત્તા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રીને આપવા ગુજરાત સિનેમા અધિનિયમ ૨૦૦૪ના બિલમાં સુધારો કરવા સૂચવેલ છે.

ડો ચંદ્રિકા બેન કા. ચુડાસમા (માંગરોળ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી ગુજરાત સિનેમા નિયમન સુધારા વિધેયક લઈને અહીં આવ્યા છે. હમણાં જ એમણે આ વિધેયક શા માટે લાગુ પડે તેનું નિવેદન ગૃહ સમક્ષ કર્યું. તેમણે જે ઉદ્દેશો અને નિયમો આપ્યા તેમાં બહુ સ્પષ્ટ વાત કરી કે એક અધિકારી અને બીજાં અધિકારી કમિશ્નર અને જિલ્લા મૅજીસ્ટ્રેટને સત્તા આ કલમના આધારે આપવાની થાય છે. એમણે ઉદ્દેશમાં એક વાત લખી અને નવાઈ લાગી કે આવડા મોટા વિસ્તારોમાં લાંબા સમયથી મનોરંજન કરની સરકારની લેણાની બાકી રકમ ખૂબ મોટી છે. વિધેયક લાવવાનો ઉદ્દેશ શું તો કે કમિશ્નર હસ્તક આ સત્તા હતી. ઘણી મોટી લેણાંની રકમ બાકી હતી. મારે એ પૂછવું છે કે આ વિધેયક એટલા માટે લાવ્યા છીએ કે આ રકમ બાકી છે. આટલી મોટી રકમ બાકી નીકળતી હોય તો સંકલન ન કરી શકાય? કમિશ્નર અને મૅજીસ્ટ્રેટ બેનું સંકલન કરીને આ લાયસન્સ રદ નહોતા કરી શકાતા? છતાં આ રકમ બાકી રહી છે અને લેણાંની રકમ બાકી રહે ત્યારે માનનીય મંત્રીશ્રીને આ વિધેયક લાવવું પડ્યું. ઉદ્દેશ સારો છે એકને સત્તા આપવી તેની સામે મારી કોઈ વાત નથી. પરંતુ આવડી મોટી રકમની જ્યારે વાત નીકળી છે ત્યારે મને એ નવાઈ લાગે કે સરકાર શું કરે? સરકારે વહીવટી તંત્રમાં શું કામગીરી કરી કે રકમ ન આપી શક્યા? લેણાંની રકમ ન આપી શકતા હોય તો તેના લાયસન્સ રદ કરવાની પ્રક્રિયા સરકારે કેમ ન કરી? સવાલ તેમણે જ કહ્યું તેમાં ઉપસ્થિત થાય છે કે જિલ્લા મૅજીસ્ટ્રેટને આ સત્તા આપી. લાયસન્સ પણ તેણે આપવા, કર પણ તેણે વસૂલ કરવો. અધિકારો જેને છે તેણે જુદી જુદી ઑફિસમાં જવું પડે. સવાલ એટલો જ છે કે માત્ર વિધેયક લાવ્યા છીએ અને વિધેયક લાવ્યા પછી વિધેયક પસાર કરી દીધા પછી હમણાં જ સવારે કહ્યું કે બહુજનનું નિયમન છે પણ નિયમનને કારણે સ્પષ્ટ પરિસ્થિતિ અને સુધારો કેટલો થયો? જ્યારે વિધેયક લાવી દઈએ છીએ ત્યારે આટલી મોટી રકમની લેણાંની વસૂલાત છે તેના માટે શું આયોજન છે? માત્ર વિધેયક લાવીને એક સત્તા બીજાંને આપ્યા પછી પણ જો આ લેણાંની રકમ ન આવવાની હોય તો વિધેયક લાવવાની જરૂર નથી. મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને સ્પષ્ટ પૂછવું છે કે સત્તા આપીએ, સત્તા સાથે રકમની લેણાંની પ્રક્રિયા માટે શું? લેણી રકમ લાવવા માટેના પ્રયત્નો શા અને સત્તા

* **વિધેયક તા.૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.**

આપ્યા પછી ફરીવાર એવું ન થાય કે આ વિધેયક લાવીને સત્તા કોઈ ત્રીજાને આપવામાં આવે કે એમ કે આટલી મોટી લેણી રકમ સરકારમાંથી આવી શકતી નથી ત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે કે આ માત્ર વિધેયક લાવવાથી નહીં પણ સરકારની મક્કમતા કેટલી છે, સરકાર આ લેણી રકમ લેવા માટેના પ્રયત્નો કેટલા કરવા માગે છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ. માત્ર વિધેયક લાવવાથી એક સત્તા બીજાંને આપીએ. બીજાંની સત્તા ત્રીજાંને આપીએ તેનાથી કોઈ અર્થ નહીં નીકળે એટલું જ કહેવા માગું છું.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ (રાપર): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય શહેરી વિકાસ ખાતાના મંત્રીશ્રી આ જે બિલ લઈને આવ્યા છે તેમાં તેમણે જે ઉદ્દેશો કહ્યા તેમાં એક ઉદ્દેશમાં એમ કહ્યું કે મનોરંજન કરની ઝડપી વસૂલાત કરવા માટે લાયસન્સ આપવાની સત્તા સુવ્યવસ્થિત બનાવવા અને એક જ સત્તા અધિકારી દ્વારા કર વસૂલાત થાય તે માટે લાયસન્સ આપવાની પોલીસ કમિશ્નરની સત્તા પાછી ખેંચવાનું અને સદરહુ સત્તા જિલ્લા મૅજીસ્ટ્રેટ જેઓ મનોરંજન કર વસૂલાત અધિકારી છે તેમને સોંપવાનું જરૂરી જણાયું છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પોલીસ કમિશ્નરને સત્તા માત્ર મનોરંજન કર કે એના માટેની નહીં પરંતુ તેને લાયસન્સ આપતાં પહેલાં ત્યાં ટ્રાફિક નિયમન બરાબર થાય છે કે કેમ? તેની સલામતી બરાબર જળવાય છે કે કેમ? તે થિયેટરમાં કોઈ અકસ્માત થાય તો નીકળવાના રસ્તા બરાબર છે કે નહીં. તે જોવાનું કામ સલામતીનું છે. એ પોલીસ અધિકારીના ભાગમાં આવતું હોય છે અને આ મનોરંજન કરની ઝડપી વસૂલાત કરવા માટેનો શબ્દ છે તે હાસ્યાસ્પદ શબ્દ છે. મારે નમ્રતાપૂર્વક આપના મારફતે તેમનું ધ્યાન દોરવું છે કે આ રાજયની અંદર થિયેટરોની સંખ્યા વધતી જાય, વિડિયો ચેનલોની સંખ્યા વધતી જાય છે, વિડિયો થિયેટરોની સંખ્યા વધતી જાય છે પણ કરની આવક દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે. તેના ઉપર તેમણે કોઈ દિવસ મનન કર્યું છે ખરું? કારણ કે આ જે આવક થાય છે તેને કારણે શહેરી વિસ્તારોમાં ફાળે પડતી રકમ મ્યુનિસિપાલિટી એરિયામાં જાય છે. એ પણ એમના ભાગમાં જ આવે છે. આજે એ રકમનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે ઘટતું જાય છે. ઓકયુપન્સી કેટલા થિયેટરોમાં અને આ મનોરંજન કરની ઉધરાણી ન કરી એટલા માટે થઈને એને કોમ્પોઝીટ કરવેરાની વ્યવસ્થામાં મૂકેલા છે. ૩ લાખ સુધીના શહેરોની અંદર વર્ષે એકવાર વેરો ભરે પછી ગમે તેટલા હોય. પરંતુ જે મહાનગરો છે એની અંદર થિયેટરોની સીટોની જે ઓકયુપન્સી છે એ ૫૦ ટકા ઓકયુપન્સીનો ટેક્સ ભરાય છે ખરો? અને એની વસુલાત કરવા માટે કેવી મિલીઝૂલી હોય છે એ મિલીઝૂલીવાળાને સત્તા આપી છે અને એટલા માટે આ ક્રોસ ચેક કરવા જરૂરી છે અને કેટલાક ઠેકાણે સુપ્રિમકોર્ટ દ્વારા અવાજના પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા માટે પણ આ સૂચના આપવામાં આવેલ છે અને અવાજના નિયંત્રણ માટે કોણ જાય છે.પોલીસ કમિશ્નર પાસે એનું લાયસન્સ હોય તો એ રદ કરી શકે અને સામાન્ય પ્રજા જે છે અને એની સુખાકારી માટેની જે જાળવણી કરવાની છે આના કારણે સત્તા જતી રહેશે તો એને જે ચેક કરવા માટેની જે વ્યવસ્થા છે, નિયંત્રણ કરવા માટેની જે વ્યવસ્થા છે જેની અંદર નુકસાન થશે. એટલે એના માટે મંત્રીશ્રીને કહેવું છે કે કોઈનું સૂચન આવે અને તરંગી વિચારને અમલમાં મૂકીને પોલીસ કમિશ્નર પાસેથી સત્તા જતી રહે અને કલેકટરશ્રી પાસે એકહથ્થુ સત્તા થઈ જાય તો એનાથી મનોરંજન કરની આવકો ઘટતી જશે. પરંતુ આના કારણે ખૂબ મોટી માફીયા ટોળીયો ઉભી થશે. એના પાસેથી ટેક્સ વસૂલ કરવા માટેની કોઈ સત્તા નહીં. એટલે આવક વધારવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આપના મારફત મારે કહેવું છે કે થિયેટરો માટેના ટેક્સ વગેરેની વસૂલાત માટે છે એની મંજૂરી માટેની વ્યવસ્થા છે એના કડક નિયંત્રણ હોવા જરૂરી છે. મનોરંજન કર કમિશ્નર છે અને આ સીધે સીધું નિયંત્રણ ગૃહ વિભાગની દેખરેખ નીચે છે. એ ગૃહ વિભાગની દેખરેખ નીચેથી લઈ જવું એ ઉચિત નથી. આ શા માટે કરવામાં આવે છે એ મને સમજાતું નથી એટલું મારું કહેવું છે.

શ્રી ધનસુખભાઈ ના. પટેલ (ઓલપાડ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી મનોરંજન અધિનિયમ-૨૦૦૪ સુધારા વિધેયક લઈને આવ્યા છે એને આવકારી મારા વિચારો વ્યક્ત કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જ્યારે શહેરી વિસ્તારમાં જે થિયેટરો છે એના એક તો વેરા વસૂલ થતા નથી. શહેરી વિસ્તારોમાં વિડિયો અને નાના સિનેમાઘરો છે એને પોલીસ કમિશ્નર લાયસન્સ આપે છે અને પોલીસ કમિશ્નર જે રીતે સત્તાનો દુરુપયોગ કરે છે અને નાના ઉદ્યોગકારોને સતાવવામાં આવે છે અને કેટલાકના લાયસન્સ પણ રદ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને એના કારણે નાના ઉદ્યોગ પડી ભાંગ્યા છે અને કેટલાક લોકોએ લાખો રૂપિયાનું મૂડી રોકાણ કર્યું છે અને આવા લાયસન્સ રદ કરવાથી રાજયની આવક ઉપર ખૂબ મોટી અસર થયેલ છે. વિડિયો થિયેટરો ઓછા થયા છે અને વસૂલાત પણ ઓછી થઈ છે. એટલે સારા ઉદ્દેશથી આ વિધેયક લાવવામાં આવ્યું છે. સાથોસાથ પોલીસ કમિશ્નર પાસેથી આ સત્તા ખેંચી લેવામાં આવી છે એ પ્રશંસનીય કામગીરી છે. પોલીસ ડિપાર્ટમૅન્ટ તરફથી ખૂબજ હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે. એના અનેક દાખલાઓ પણ છે. આ સત્તા કલેક્ટર અને મહેસૂલ વિભાગની આપવામાં આવી છે એ અભિનંદનને પાત્ર છે. એનાથી રાજયની કરવેરાની આવક પણ વધશે. મારી એક વિનંતી છે કે જે મૂડી રોકાણ કરેલ છે અને જે શહેરોમાં નાના ઉદ્યોગકારો છે અને પોલીસ કમિશ્નરશ્રીએ જે રદ કર્યા છે જે વર્ષોથી ચાલતા હતા એમાં એમને પણ આ કાયદામાં આવરી લેવામાં આવે અને એની સત્તા કલેક્ટરને આપવામાં આવે એવી મારી વિનંતી છે.

શ્રી શંકરભાઈ લ. ચૌધરી (રાધનપુર): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી આ જે વિધેયક લઈને આવ્યા છે એને હું આવકારું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પહેલાંના જમાનાથી જોઈએ તો વહીવટ કરવા માટે વાણિયા પહેલાં હતા. કોઈને પણ વસૂલાત કે ધંધો કરવો હોય તો સીધું અને સરળ કયાં પડે ? કોઈ કડક માણસ ત્યાં આગળ બેઠો હોય અને તેની પાસેથી કંઈ લેવા જવું હોય તો કોઈ માણસ ન જાય. અત્યારે કોઈને ધંધો ઉદ્યોગ કરવો હોય એના લાઈસન્સની પ્રોસિઝર હોય તો સરળતાથી એને ત્યાં જતા ડર ન લાગે. સામાન્ય રીતે પોલીસની આવી ઈમેજ બનેલી હોય છે કે પોલીસ પાસે જવું એટલે સહેજ ડર લાગે છે. પહેલેથી આ પરંપરા રહેલી છે. પહેલેથી જ માનસિકતા રહી છે કે પોલીસ પાસે જવું એટલે થોડોક લોકોને ડર લાગતો હોય છે. આ સત્તા જે સોંપેલી પોલીસને એની જગ્યાએ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ પાસે સત્તા જશે તો લોકોને સરળતા રહેશે. નવા લોકોને કંઈ પોતાનું નવું કામ કરવું હોય, નવું થિયેટર બનાવવું હોય તો એ સરળતાથી એ પોતાનું લાઈસન્સ મેળવી શકશે. રહી વાત હમણાં મારા મિત્ર શ્રી બાબુભાઈ વાત કરતા હતા કે પોલીસની પાસે હોય તો કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ છે એના ઉપર ધ્યાન રાખી શકાય. હું માનું છું કે કાયદો અને વ્યવસ્થાનું ધ્યાન રાખવાની જવાબદારી પોલીસની છે જ અને એ માત્ર પોતાને લાઈસન્સ આપવાનો અધિકાર હોય તો જ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવે અને બીજા કોઈ લાઈસન્સ આપતા હોય તો કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારી જે તે લાઈસન્સ આપવાવાળા અધિકારીની હોય એવું હું નથી માનતો. પોલીસની સમગ્ર રીતે ટ્રાફિકની વાત હોય કે બાકીની વ્યવસ્થા હોય એ કરવાનું જે કામ છે એ તો પોલીસ પોતે પોલીસનું કામ કરશે જ પરંતુ આ સત્તા આપવાથી જે રીતે આર.ટી.ઓ. ચેક પોસ્ટ ઉપર ૩૫ કરોડની જગ્યાએ ૮૦૦ કરોડથી પણ વધુ આપણે મેળવી શકયા. થોડાક ફેરફાર કરીને એ જ પ્રમાણે અહીંયા આગળ માનનીય મંત્રીશ્રીએ જે પોલીસ કમિશ્નરશ્રીમાંથી જિલ્લા મૅજીસ્ટ્રેટને આ અધિકારો આપવાનું વિધેયક લાવ્યા છે મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા સમયમાં આનાથી રાજયની કરની આવક વધશે અને જે વસૂલ કરવાની પધ્ધતિ છે એમાં પણ સરળતા રહેશે અને હું માનનીય મંત્રીશ્રી જે વિધેયક લઈને આવ્યા છે એને સમર્થન કરું છું.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીઓએ એમના સૂચનો કહ્યા છે એમના સૂચનોને હું આવકારું છું. ચંદ્રિકાબેનની લાગણી સાથે હું સહમત છું કે આનો હેતુ વહીવટી સરળતાની સાથોસાથ સરકારની તિજોરીમાં પણ ઝડપથી પૈસા આવે, વસુલાત ઝડપથી કરી શકાય એ પણ હેતુ રહેલો છે અને કોઈપણ સરકારો એ હેતુ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યાન્વિત થતી હોય છે. જે લાઈસન્સ અને બાકીની પ્રક્રિયા પોલીસ કમિશ્નરશ્રી પાસે રહેલી હોય છે એના કારણે વસુલાતની બાકીની કાર્યવાહીમાં અનેક વખત એ મહાનગર વિસ્તારમાં કલેકટરશ્રીને અડચણ થતી હોય છે એના કારણે એનો પત્ર વહેવાર, બાકીની પદ્ધતિમાં સમય પસાર થતો હોય છે અને એ સ્થિતિમાં જો જિલ્લા કલેકટરશ્રીની પાસે સત્તા આવશે તો ચોકકસપણે સરળતાની સાથે આવકની બાબત પણ સરકાર માટે વધવાની છે. માનનીય બાબુભાઈએ જે રિપોર્ટ અને સલામતી ટ્રાફિક અને બાકીના પ્રશ્નો અને એમણે જે સૂચનો કર્યા છે, જિલ્લા કલેકટરશ્રી પણ એ પ્રકારની જ્યારે મંજૂરી આપતા હોય છે ત્યારે પોલીસનો અહેવાલ હંમેશા માગતા જ હોય છે. અને ત્યારબાદ મંજૂરી મળતી હોય છે અને બાકીની બાબતોમાં પણ જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં નિયમ મુજબ કાર્યવાહી થતી હોય છે. માનનીય બાબુભાઈએ આવકના ઘટાડાની વાત કરી પણ જે પ્રકારે પ્રવાસન ઉદ્યોગને ગુજરાતમાં વેગ મળ્યો છે, મલ્ટીફલેકસ થિયેટરો ગુજરાતમાં જે પ્રકારે વિકાસ પામી રહ્યા છે અને એ બધામાં છૂટછાટ આપવા છતાં ૨૦૦૨-૦૩માં કુલ મનોરંજન કરની આવક ૩૬,૪,૯૮,૦૦૦ હતી એ ૨૦૦૩-૦૪માં ૪૨,૪૧,૫૨,૩૪૯ થઈ છે એટલે કે રાજય સરકારે આ પ્રકારના પ્રયત્નો કરીને એ દિશામાં આવક વધારવા ચોક્કસ પ્રયત્નો કર્યા જ છે પરંતુ સાથે સાથે લોકોને એ બે જગ્યાએ પોતાની બધી જ કાર્યવાહી કરવાની થતી હોવાથી થોડીક હાડમારી અને તકલીફ રહે છે એની સાથે સાથે રાજય સરકારને પણ જો એક જ સત્તા પાસેથી કામ લેવાનું હોય તો એ લોકો પાસેથી ઝડપથી વસુલાત પ્રાપ્ત કરી શકે એમ છે. એમ આ વિધેયક વહીવટી સરળતાની સાથોસાથ રાજય સરકારની તિજોરીમાં પણ આવકનું પ્રમાણ વધશે એ પ્રકારનું વિધેયક છે એટલે હું માનનીય સભ્યશ્રીઓના સૂચનોને આવકારું છું.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : *(XXXXXX)

અધ્યક્ષશ્રી : આજે તો બોલવાની છૂટ આપી છે પણ હવે પછી કંઈ પણ કહેવું હોય તો મંત્રીશ્રી જવાબ આપે એ પહેલાં કહેવું પડે.(અંતરાય) એમના આ શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

---

* (XXX) આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે......(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : કોઈ સુધારો નથી.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : અમે રાજયના હિતની વાત કરવા માગીએ છીએ.

શ્રી વજુભાઈ વાળા : એકને એક બિલ ઉપર એકવાર બોલી લીધા પછી બીજીવાર ન અપાય. તમે દસ વાર ઊભા થશો એટલે દસ વાર ન બોલાય. સુધારો બિલ ઉપર મૂક્યો હોય તો ચોક્કસ બીજા વાચનમાં કરી શકો.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : દરેક બિલમાં અમારા સભ્યો બોલતા નથી. પરંતુ માત્ર ટેકનિકલી જવું હોય તો દરેક બિલમાં અમને અધિકાર છે અને અમે બોલીશું. પરંતુ બાબુભાઈને રાજયના હિતમાં થોડી વાત કરવી હોય તો અશોકભાઈએ ઊભા થવાની જરૂર નથી. એમાં એલાઉ કરવા જોઈએ. માનનીય મંત્રીશ્રી જવાબ આપી શકે, એમની તૈયારી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : આ ગૃહની પ્રથા રહી છે કે વિધેયકના પહેલા વાચનમાં જે વાત કરવી હોય એ કહી શકે છે. બીજા વાચન વખતે આપણે સુધારા મૂકીએ છીએ અને સુધારા મૂક્યા પછી જેમણે સુધારા મૂક્યા હોય એ પોતાની વાત કહી શકે. આ આપણી પ્રણાલિકા રહી છે, આ આપણી પદ્ધતિ રહી છે. એમાં ચૂક થાય એ ઠીક નથી.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં પહેલા વાચન ઉપર મારા વિચારો કહ્યા, એનો માનનીય મંત્રીશ્રીએ જવાબ આપ્યો. એટલે મેં થોડી માહિતી માગી કે એમણે મારી માહિતી હતી એને ખંડિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એના પુરાવા આપ્યાં, બજૅટની બુકમાંથી આંકડાથી માહિતી આપી કે મને માહિતી આપો કે રાજયની આવક વધી છે કે ઘટી એટલું જ પૂછેલું છે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : એમણે જે પ્રકારનો વિષય મૂક્યો, મેં બધા સભ્યોના સૂચનોને આવકાર્યા છે. એમની લાગણીના હાર્દ સાથે સંમત થયો, પણ મેં એમ કહ્યું કે માનનીય બાબુભાઈ એમ કહે છે કે સતત આવક ઘટતી આવે છે. એટલે મારી પાસે છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આંકડા હતા એ બોલ્યો અને ત્રણ વર્ષમાં આવકો ઘટતી નહિ પણ વધતી આવે છે.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : ૨૦૦૧માં ૬૦ કરોડની હતી એ ઘટીને ૪૦ કરોડ થઈ છે એ ઘટતી કહેવાય કે નહિ એટલું જ પૂછયું હતું. આ ચાલું વર્ષના બજૅટની બુક આપવામાં આવેલ છે એના આધારે આંકડા આપ્યા છે.

શ્રી વજુભાઈ વાળા : એ આંકડા સરકારના સાચા જ છે. માનનીય મંત્રીશ્રીએ આપેલા છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આંકડા ખોટા હોય તો માનનીય સભ્યશ્રી કહી શકે. આંકડા આપેલા બોલ્યા છે એ અને છાપેલા છે એ જુદા છે. એની પહેલાના વર્ષની વાત કરે છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષના બદલે એના અગાઉના આંકડા આપ્યા છે.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : માનનીય મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરુ (અંતરાય) મેં કહેલાં આંકડા છેલ્લા ૩ વર્ષના છે ૨૦૦૧-૦૨, ૨૦૦૨-૦૩, ૨૦૦૩-૦૪ (અંતરાય)

શ્રી વજુભાઈ વાળા : એ જે બોલે છે બાબુભાઈ, (અંતરાય)

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : આ ભા.જ.પ. સરકારની અંદર આવકો ઘટી છે એ વાત સાચી છે (અંતરાય) ૩ વર્ષના આંકડા છે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બિલની અંદર બાબુભાઈ એમ કહે કે, ૧૦ વર્ષના આંકડા આપો તો ક્યાંથી લાવીએ? છેલ્લા ૩ વર્ષના આંકડા આપણે આપ્યા છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય બાબુભાઈ, મંત્રીશ્રી જે વર્ષના આંકડાની વાત કરે છે, એ વર્ષની આવક ઘટી હોય તો આપ વાત કરો.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં કહ્યું સતત રાજયની અંદર આવક ઘટતી જાય છે એ ચિંતાનો વિષય છે અને અમને જે પ્રકાશન આપવામાં આવેલું છે એની અંદર આંકડા આપ્યા છે (અંતરાય) ચાલુ વર્ષના બજૅટમાં (અંતરાય) આંકડા છે એ મંત્રીશ્રી એ રીતના આપે છે.

અધ્યક્ષશ્રી : નહિ, એમણે જે આંકડા આપ્યા છે (અંતરાય)

શ્રી વજુભાઈ વાળા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સાત વર્ષના આંકડા ભેગા કરશે તો ઉત્તરોત્તર ઘટાડો એટલા માટે આવશે કે ગુજરાતમાં ૭૦૦ થિયેટર હતા એના બદલે અત્યારે ૨૫૦ થિયેટર જ રહ્યાં છે. સાત વર્ષના આંકડા કરશો તો દિવસે ને દિવસે ઘટાડો જ આવશે પણ છેલ્લા ૩ વર્ષના આંકડા બતાવ્યા છે એ બરાબર છે (અંતરાય)

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એટલા માટે કેmultiplexની અંદર જ્યાં રાજ્યની આવક ઘ ટતી હોય encourage કરવા માટેનું નાણામંત્રીશ્રીને (અંતરાય)

શ્રી વજુભાઈ વાળા : તમે નાણામંત્રી હતાને ત્યારે આવક ઘટી છે બાબુભાઈ આંકડા જોઈ જાવ તમારાં આગલા વર્ષના (અંતરાય)

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું તો નાણામંત્રી એક વર્ષ હતો પણ આપ તો ૧૧ વર્ષ નાણામંત્રી રહ્યાં છો. (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય બાબુભાઈ એક મિનિટ (અંતરાય)

શ્રી અશોક ભટ્ટ : માનનીય સભ્યશ્રી, નાણામંત્રીશ્રી જાણે છે કે માનનીય મંત્રીશ્રીએ પૂરા આંકડા આપવાનો પ્રયાસ આ સભાગૃહમાં કર્યો છે. (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : એક મિનિટ, આપને તક આપું.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : અશોકભાઈ નાણામંત્રી (અંતરાય)ઊભા થાય.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : સાહેબ, કાયદાનો પ્રશ્ન છે, સંસદીય બાબતોનો વિભાગ મારો છે ઊભા થવાનો પ્રશ્ન નથી વિરોધપક્ષના નેતા(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : અશોકભાઈ આપણા સંસદીય મંત્રી છે (અંતરાય)

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : એમને નાણામંત્રીનો વહેમ છે, એટલે કહું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : નહિ, નહિ (અંતરાય)

શ્રી અશોક ભટ્ટ : વિરોધપક્ષના નેતાને ગૃહની કાર્યવાહી કઈ રીતે ચાલે એ થોડો સમય લાગશે તમને, તમે જરા સમજવાનો પ્રયાસ કરો.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : ગૃહની કાર્યવાહી કે (અંતરાય) બીજું જરા આપને (અંતરાય)

શ્રી અશોક ભટ્ટ : એટલા માટે લાગશે કે જે સિનિયર મેમ્બર છે એમની પાસેથી જરા પૂછીલે શંકરભાઈ જેવાને (અંતરાય)

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : સંસદીય જન્મજાત રીતે સમજી ગયા છે એટલે એમને વાર લાગે (અંતરાય) કોઈપણ નવા સભ્યને આ રીતે ઉતારી પાડવાનો વર્તાવ માનનીય સંસદીય મંત્રીશ્રીનો બરાબર નથી. (અંતરાય)

શ્રી અશોક ભટ્ટ : આમાં જન્મજાત ના ઉમેરો (અંતરાય) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું તો કાયમી સભ્ય છું. મારી તો આપને એટલી જ વિનંતી છે કે માનીનય મંત્રીશ્રીએ જે જવાબ આપ્યો છે એ પૂરતો છે, સરળીકરણ છે અને બીજું વાંચનનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે એમાં એમને કહેવું હતું એ કહી દીધું છે, હવે આગળ ચાલો.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫ ના વિધેયક ક્રમાંક-૩નું બીજું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ-૨ અને કલમ-૧ દીર્ઘ સંજ્ઞા અને ઈનેકટિંગ ફૉરમ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫ ના વિધેયક ક્રમાંક -૩નું ત્રીજું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૩નું ત્રીજું વાંચન કરવામાં આવે છે અને તે પસાર કરવામાં આવે છે.

સન ૨૦૦૫નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક. ૮.

મુંબઈ માપબંધી સંબંધી (તૈયારી અને તે ચાલુ રાખવા બાબતના) ઉપાય બાબત (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક,૨૦૦૫.

ગુજરાત રાજયને લાગુ પડતો હોય તેટલા પૂરતો મુંબઈ માપબંધી સંબંધી (તૈયારી અને તે ચાલુ રાખવા બાબતના) ઉપાય બાબતનો અધિનિયમ, ૧૯૪૭ રદ કરવા બાબત વિધેયક.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ (અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનામંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજયપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૮-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ માપબંધી સંબંધી (તૈયારી અને તે ચાલુ રાખવા બાબતના) ઉપાય બાબત (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકને આપની અનુમતિથી દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૮- સન ૨૦૦૫ના મુંબઈ માપબંધી સંબંધી (તૈયારી અને તે ચાલુ રાખવા બાબતના) ઉપાય બાબત (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું પહેલું વાંચન કરવામાં આવે.

* (વિધેયક તા.૧૬મી ફેબ્રુઆરી,૨૦૦૫ના ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે).

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૧૯૪૭ના The Bombay Rationing (Preparatory and Continuance)Measures Act જે તે વખતે ઘડવામાં આવ્યો હતો. આ એકટ ઘડવામાં જે મુખ્ય હેતુ હતો રેશનિંગ દાખલ કરવાની પૂર્વ તૈયારી માટે ભોજન પૂરું પાડતી સંસ્થાઓ અને વ્યકિતઓને લગતી માહિતી એકત્રિત કરવી અને મકાનોને નંબર આપવા માટે આ એકટ ૧૯૪૭માં ઘડવામાં આવ્યો હતો. આજ કાયદાના હેતુઓ અને ઉદેશ્યોને પરિપૂર્ણ કરવા માટે ૧૯૭૫માં Gujarat Catering Establishment Display of Price of Milk Refreshment and Beverage Act ૧૯૭૫, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વર્તમાન સમયમાં ૧૯૭૫નો આ એકટ અમલમાં છે એટલે ૧૯૪૭નો જે જૂનો અધિનિયમ છે એ અત્યારે હાલના સમયમાં અપ્રચલિત છે અને તેને ચાલુ રાખવાનું કોઈ જરૂરી લાગતું નથી એટલે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આ ગૃહમાં વર્તમાન જે જૂનો ૧૯૪૭નો એકટ છે એને રદ કરવા બાબતનું વિધેયક લઈને આવ્યો છું.

અધ્યક્ષશ્રી : કોઈ સભ્યશ્રીને કાંઈ કહેવું હોય તો? કહી શકે છે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી **કૌશિકભાઈ જ. પટેલ :** માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૮નું બીજું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ-૨, કલમ-૧, દીર્ઘસંજ્ઞા અને ઈનેકટિંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૮નું ત્રીજું વાંચન કરવામાં આવે અને તે પસાર કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૮નું ત્રીજું વાંચન કરવામાં આવે છે અને તે પસાર કરવામાં આવે છે.

સન ૨૦૦૫નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક: ૫

ભારત સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક ૨૦૦૫

ગુજરાત રાજયને લાગુ પડતો હોય તેટલા પૂરતો, ભારત સ્ટૅમ્પ અધિનિયમ, ૧૮૯૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ.પટેલ (અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનામંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજયપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલા સન ૨૦૦૫ નું વિધેયક ક્રમાંક-૫ સન ૨૦૦૫ નું ભારત સ્ટૅમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક આપની અનુમતિથી હું દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૫-સન ૨૦૦૫નું ભારત સ્ટૅમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું પહેલું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂકરવામાં આવ્યો.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભારતીય સ્ટૅમ્પ અધિનિયમ ૧૮૯૯ની કલમ-૯ કલમ-૯(ક) દાખલ કરવા માટે આ ગૃહમાં સુધારા બીલ લઈને આવ્યો છું. ગુજરાત રાજયમાં અવાર નવાર રેવન્યુ સ્ટૅમ્પની અછત બાબત અથવા સ્ટૅમ્પના વધુ પૈસા લેવા બાબત અવારનવાર ફરિયાદ ઉઠાવવામાં આવતી હોય છે. નાસિક સિક્યોરિટીમાંથી સમયસર સ્ટૅમ્પનો પુરવઠો પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. ઘણી વાર પુરવઠો આવે છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં લઈ શકાય એ રીતે પુરવઠો આવતો નથી. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ૧૮૯૯ના આર્ટિકલ ૫૩ મુજબ કલમ-૯ સાથે કલમ-૯(ક) ઉમેરીને કેન્દ્ર સરકાર પાસે માગણી કરી છે કે ૫૦૦૦ ઉપરના જે વ્યવહાર થાય એમાં એકસામટી સ્ટૅમ્પડયૂટી લેવા માટે મુંબઈ સરકારને કેન્દ્ર સરકારે પરમિશન આપી છે. ગુજરાત સરકારે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી માગણી કરી છે અને કેન્દ્ર સરકારે માગણી માન્ય રાખી છે. એનાથી કેટલાક ફાયદા રાજયને થવાના છે. એમાં પહેલો ફાયદો, મોટા ટ્રાન્ઝેકશન કરતી, વ્યવહાર કરતી કંપની છે, જે પબ્લિક યુટીલીટી કંપની છે એમના પ્રત્યેક ડોકયુમેન્ટસમાં ઈન્ડીવીડયુઅલ સ્ટૅમ્પ લગાવવી નહીં પડે. રાજય સરકારને સ્ટૅમ્પ ડયૂટી એડવાન્સ મળશે એટલે રાજય સરકારને ફાયદો થશે. રાજય સરકાર સ્ટૅમ્પ વેચવામાં કમિશન આપતી હોય છે એ કમિશન આપવામાંથી બચી જશે. સ્ટૅમ્પ છપામણી માટે ખર્ચ કરવો પડે છે. એમાંથી રાજય સરકારને ફાયદો થશે. કલમ-૯(ક) ઉમેરવાથી રાજય સરકારને સ્ટૅમ્પ ડયૂટી એટલે જે મોટા ગૃહો છે અને

* (વિધેયક તા.૧૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના ફેબ્રુઆરી ગુજરાત ગર્વન્મેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે)

અવારનવાર તમામ ડોકયુમેન્ટ ઉપર સ્ટેમ્પ લગાડવામાંથી મુકિત મળશે અને રાજય સરકારને નાણાકીય ફાયદો થશે. એ રીતે કલમ-૯(ક) ઉમેરવાનું વિધેયક લઈને આ ગૃહમાં હું આવ્યો છું.

શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી જે સુધારો લઈને આવ્યા છે. એનું અમલીકરણ પણ કરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. રાજયની મહેસૂલી આવક સ્ટૅમ્પ ડયૂટીમાં વધતી જાય છે. મહારાષ્ટ્રનાં પ્રમાણમાં આપણી આવક ખૂબ ઓછી છે. રાજયની આવકનાં જે સ્ત્રોત હોય આપણે ત્યાં આબકારી જકાત નથી કારણકે નશાબંધીને કારણે પરંતુ સેલટેકસ પછીની જે આવક છે રાજય સરકારની સ્ટૅમ્પ ડયૂટીમાં ખનીજ રોયલ્ટી અને આર.ટી.ઓ. ટેકસ મારફત છે. સ્ટૅમ્પ ડયૂટીમાં જે રકમ ભરાય છે એના કરતા રાજયનો જે વ્યવહાર છે રીયલ એસ્ટેટ ગણીએ કે સરકારી જમીન જે અપાય છે એની કિંમત આંકવામાં આવે તો હજી આના કરતાં વધી શકે તેવી છે. મારી પાસે લિસ્ટ છે. આ વખતે બોલવાનું ઉચિત લાગતું નથી પરંતુ એમના ધ્યાન ઉપર મૂકું કે માત્ર એમની કિંમત દસમા ભાગની પણ આંકવામાં આવતી નથી. આના કારણે અબજો રૂપિયાની સ્ટૅમ્પ ડયૂટીની આવક ગુમાવવી પડે છે. એની પણ મહેસૂલ મંત્રી કાળજી લે કારણકે નાણા ખાતામાં આવતું નથી પણ મહેસૂલ ખાતામાં આવે છે. આજુબાજુના પાંચ સાલના ઉતારા જુઓ, ચકાસણી કરો, સ્ટૅમ્પ ડયુટી માટે કલેકટરની પોષ્ટ પણ છે જિલ્લામાં પરંતુ એમના દ્વારા ચકાસણી થયા પછી આવક કેટલી વધે છે. એમાં આવી કાળજી લો એ ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે આ વિધેયકની અંદર જે કંઈ સુધારો આવતો હોય એ રાજ્યના હિતમાં આવતો હોય એ આવકાર્ય છે. આ ખૂબ જરૂરી હતું અને મહારાષ્ટ્રમાં આ કયારનુય શરૂ થઈ ગયું છે અને અહી શરૂ થઈ ગયું હશે. એની અંદરની ટ્રાન્સપરન્સી હતી, એ આમાં ખતમ થઈ જશે. સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટીના કેટલાક પેપરો લેવાય, તેના કારણે મિલકતો કેટલામાં લેવાય છે, તેની ખબર પડતી હતી, હવે એ ખબર નહિ પડે. નાનાં સેન્ટરો હોય ત્યાં સ્ટૅમ્પ કેટલી લેવાય અને કેટલાક અખબારો તો મોટી સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટી લેવાઈ હોય ત્યારે અખબારમાં આટલું કહેતા હતા કે આટલી સ્ટૅમ્પો સોદા માટે થઈને ખરીદાય છે, એટલે આના માટે જેટલું બની શકે રાજયની આવક વધે એની કાળજી લો. માનનીય મંત્રીશ્રીને ખ્યાલ આપવાનો છે કે જે જમીનની લેવડદેવડ થાય છે, તેની તપાસ કરો તો તરત ખબર પડી જશે. કેટલી મિલકતની લે-વેચ થઈ અને કેટલી સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટી ભરાઈ એનું પ્રમાણ ૫-૧૦-૧૫ ટકા હોય તો સમજી શકાય. જંત્રીના ભાવે હોય. સરકારી પ્રોપર્ટીઝ વેચાઈ હોય કે સરકારે પ્રોપર્ટી ખરીદી હોય કે કોઈ કૉર્પોરેટ સૅકટરે ખરીદી હોય તો એના ભાવની સરખામણી કરો તો આની સરખામણી થઈ શકે મારે એટલું જ કહેવું છે.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા (માંગરોળ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી જે સુધારા લઈને આવ્યા છે, તેને હ્દયપૂર્વક આવકારું છું. મારા પહેલાના સભ્યશ્રી બાબુભાઈએ જે વાત કરી અને એમણે પોતે પણ માનનીય મંત્રીશ્રીએ નિવેદનમાં વાત કરી તે સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટીની બાબત છે, એની અંદર નાશિકની અંદર છપાવવાની પ્રક્રિયાના કારણે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કેટલાક મોટા કૌભાંડો સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટીની અંદર રાજ્યમાં ઉપસ્થિત થયા હતા. સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટીની બાબત લઈને આવ્યા છે, ત્યારે તે બાબતની અંદર માનનીય મંત્રીશ્રી ધ્યાન આપે, એટલા માટે સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટીની આવક એ માનનીય વજુભાઈ નાણામંત્રીશ્રીની મહેસૂલી આવકમાં મહત્ત્વનો હિસ્સો હોય તે આમાં છે. આજની તારીખે પણ આપણે આપણા વિભાગોનો સરવે કરીએ. હમણા પરામર્શ કમિટીમાં સરવે કરાવ્યો તો ખ્યાલ છે કે સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટીની આવકની અંદર આજની તારીખે પણ જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ છે, એની અંદર સંતોષજનક સ્થિતિ નથી. કલમ ૯ (ક) લઈ આવ્યા છે. કલમ ૯(ક) લઈને આવ્યા પછી જે પરિસ્થિતિ છે, એમાં સુધારો માગી લેવાનો છે. હું એટલું જ કહીશ કે રેવન્યુ મહેસૂલ વિભાગનો સુધારો આખરે તો રાજય સરકારના વિકાસને અને નાણાં વિભાગને સુદૃઢ બનાવવા માટેનો હોય છે, ત્યારે સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટી બાબતની પ્રક્રિયા છે. એક તો મુદ્રણ ખર્ચ ઘટાડવાની બાબત લઈને આવ્યા છે. બીજી બાબત સભ્યશ્રીએ ધ્યાન દોર્યુ કે ૫,૦૦૦ થી નીચેની બાબત આવશે ત્યારે મોટી આવકની સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટી નહિ લેવાય, ત્યારે ક્યાંકને ક્યાંક બે નંબરનું થશે. એ બાબત ન થાય એ કાળજી સાથે આ સુધારો લાવે તેવી વિનંતી છે.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ધારાસભ્યશ્રી બાબુભાઈ, ચંદ્રિકાબેને રાજયની આવક અને એ પણ સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટી દ્વારા વધારો થાય એ સૂચન કર્યુ છે, એને હું આવકારું છું. આ મૂળ બિલ કલમ-૯(ક) ઉમેરવાના આશયથી છે એ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે છે. એમની ચિંતા વ્યાજબી છે કે સ્ટૅમ્પ ડ્યૂટીની આવક વધે. બીજી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે આ જે લોકોને આ ફૅસિલિટી આપીશું. રાજય સરકારનો હેતુ એવો છે કે જે પબ્લિક યુટિલિટી છે, એને જ આ ફૅસીલીટીનો લાભ આપવો અને એનું ઑડિટ કરવું એ એડવાન્સ સ્ટૅમ્પના પૈસા આવશે, ત્યારે જે કઈ વેચાણ દસ્તાવેજો થયા હશે, તેનું ઑડિટ કરવામાં આવશે અને ઑડિટ સાથે સરખાવવામાં આવશે. એની અંદર ચિંતા છે કે કઈક ખોટું, ગેરરીતિ થવાની સંભાવના છે, તે ટળી શકશે, એટલે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે કલમ-૯(ક) મહારાષ્ટ્રમાં જે ફૅસિલિટી પ્રાપ્ત થઈ છે, તે ગુજરાતમાં પ્રાપ્ત થાય, તો રેવન્યુ સ્ટૅમ્પના પર્ટીક્યુલર જે ૫,૦૦૦ થી ઉપરના દસ્તાવેજોમાં છે, એના ઉપર ૧ રૂપિયાનો સ્ટૅમ્પ લગાવવાનો છે એ સામટો આપણને મળે, એટલે કે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આ કલમ ઉમેરવામાં આવી છે. હું માનું છું ત્યાં સુધી બાબુભાઈ, ચંદ્રિકાબેને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, તેને ખાસ ધ્યાને લઈશું.

પ્રશ્ન મત માટે મુકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂં કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૫ સન ૨૦૦૫નું ભારત સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું બીજું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ-૨ અને કલમ-૧ દીર્ઘ સંજ્ઞા અને ઈનેકટીંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી કૌશિકભાઈ જ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂં કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૫ સન ૨૦૦૫નું ભારત સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૫ સન ૨૦૦૫નું ભારત સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાંચન કરવામાં આવે છે અને વિધેયક પસાર કરવામાં આવે છે.

સન ૨૦૦૫ નું વિધેયક ક્રમાંક-૭
મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫
મુંબઈ નશાબંધી અધિનિયમ,૧૯૪૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક

શ્રીઅમિત અ. શાહ (રાજય કક્ષાના નશાબંધી અને આબકારીમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજયપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલા સન ૨૦૦૦૫ નું વિધેયક ક્રમાંક-૭ સન ૨૦૦૫ના મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વધેયકને આપની અનુમતિથી દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂં કરું છું કે સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૭ સન ૨૦૦૦૫ ના મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું પહેલું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કેફી પદાર્થોના સેવન અટકાવવા આરોપીઓને કેદના બદલે સમાજસેવા કરાવવા અને તેઓને કેફી પદાર્થોના સેવનમાંથી કાયમ માટે વ્યસન મુકત કરવા માટે અને તબીબી સારવાર માટે મોકલવાના ઉદેશથી ગુજરાત રાજય વિધાનસભાએ મુંબઈ નશાબંધી અધિનિયમ ૧૯૪૯ માં સુધારો કરી કલમ-૯૨ દાખલ કરી હતી. પરંતુ અનુભવે જોવામાં આવ્યું કે ૧૯૪૯ના કાયદાની કલમ-૬૬ અને ૮૫ માં ઓછામાં ઓછી કેદની જોગવાઈ હતી તેના કારણે કલમ-૯૨ની જોગવાઈઓનો અસરકારક અમલ થતો નથી. તેના લીધે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કેસો ગુજરાતની જુદી જુદી કોર્ટોમાં પેન્ડિંગ છે અને ઓછામાં ઓછી સજાની જે જોગવાઈ છે તેને કોર્ટની વિવેકબુદ્ધિ પર છોડી દઈએ, ન્યાયમૂર્તિઓની વિવેકબુદ્ધિ પર છોડી દઈએ તો આપણે પહેલાં જે સુધારો થયો છે કલમ-૯૨ નો તેનો સાચી રીતે અમલ કરી શકીએ. હવે પછી વિધાનસભામાં કેટલાક કૉમ્યૂનિટિ સર્વીસમાં સુધારા કરી અમલમાં મૂકવાના છે તે વખતે આ સુધારો થઈ જાય અને સાચા અર્થમાં નવી કલમ-૯૨ દાખલ કરી તેનો આપણે સારી રીતે અમલ કરી શકીશું.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા (પોરબંદર): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રી મુંબઈ નશાબંધી અધિનિયમ ૧૯૪૯ ઉપર સુધારા વિધેયક લઈને આવ્યા છે. માનનીય મંત્રીશ્રી જે સુધારા વિધેયક લઈને આવ્યા છે તેના ઉદ્દેશો તેમણે બતાવ્યા છે પણ તેનાથી જે અત્યારની કાનૂની પરિસ્થિતિ છે તેની અંદર શું અસરો પડવાની છે તે બાબત તેઓએ શરમાતા શરમાતા અથવા તો છૂપાવી વાત કરી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અત્યારે જે કોઈ વ્યકિત દારૂબંધીના ગુના નીચે પકડાય તો પહેલા ગુના વખતે એને ઓછામાં ઓછી ત્રણ માસની સજાની જોગવાઈ છે અને પછીના ગુનાઓ ઉપર સતત સજાઓ ૬ મહિના, ૯ મહિના એવી રીતે વધતી રહે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી જે સુધારા વિધેયક લઈને આવ્યા છે એમાં કેદની જોગવાઈ, ઓછામાં ઓછી કેદની જોગવાઈ છે એ રદ કરવાની બાબત છે. આમેય અત્યારનો જે દારૂબંધીનો કાયદો છે એ હું આપના મારફત કહેવા માગું છું કે, માત્ર કાગળ ઉપરનો કાયદો રહેવા દીધો છે. અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાં ખુલ્લેઆમ દારૂ ગામડાંમાં, શહેરોમાં, મોટી હોટૅલોમાં વેચાય છે, પોલીસની નજર સામે વેચાય છે, મોટી માત્રામાં એની અંદર હપતાઓ લેવાય છે. અને આ પૈસાઓ છે એ આખી જે ગેરકાનૂની વ્યવસ્થા છે. એ વ્યવસ્થાની અંદર મોટા પાયે એ પૈસા જનરેટ થાય છે અને અસમાજિક પ્રવૃત્તિને એના દ્વારા પ્રોત્સાહન અપાય છે.

* (વિધેયક તા.૧૬મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૫ના ગુજરાત ગવર્નમેંન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.)

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે આપના મારફત એ પણ ગૃહમંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરવાનું છે કે, એમની વાત સાચી છે કે આ કાયદા હેઠળ લોકોની સંખ્યા ખૂબ મોટી છે પણ કાયદો જે હેતુથી બનાવેલો છે એના માટે માત્ર કેસોની સંખ્યા દરવર્ષે નક્કી કરેલી સંખ્યાની અંદર થાય એટલે ગમે ત્યાંથી જે હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડર્સ, દારૂ પીનારા એ લોકોને પકડી અને એનો કવોટા પૂરો કરવામાં આવે છે. જો દારૂના મૂળમાં જવાય અને વેચનાર અને ઉત્પન્ન કરનારા જે લોકો છે એનું અને પોલીસ તંત્રનું જે નેક્સેસ છે એ જો નેક્સેસ તોડી નાખવામાં આવે તો જે અહીયાં જે કારણથી કે ગુના કરનારા લોકોની સંખ્યા અને એને કારણે કેસોનો ભરાવો થાય છે એ કદાચ ઓછો રહે પણ માત્ર કાગળ ઉપર કાયદોનો અમલ કરવો એનાથી કાયદાના ઉદ્દેશો છે એ બળ આવવાના નથી, એના માટે માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રી પાસે વિશાળ તંત્ર છે અને એ ઇચ્છે તો આ નેક્સેસ છે એ નેક્સેસને તોડી અને દારૂબંધીનો કડક અમલ કરી શકાય.

હું આપના મારફત માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રીનું અને ટ્રેજરી બેચનું ધ્યાન દોરવા માગું છું કે, દારૂ બનાવનાર અને વેચનાર ઉપર આના દ્વારા જો વધારે કડક સજાની જોગવાઈને લઈને આવ્યા હોત અને એના પછી આ કંઈક કર્યુ હોત તો જુદી વાત છે, પણ પાછલા બારણેથી આ સુધારા દ્વારા દારૂબંધીને છૂટ આપવાની એક જોગવાઈ આની અંદર આવે છે અને એના દ્વારા હવેથી ૬ બી, અને એની જે બીજી કલમ છે એના હેઠળ કોઈપણ જે દારૂ પીનારા છે એના ઉપર સજાની જોગવાઈ રહેતી નથી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નીતિવિષયક નિર્ણય છે મંત્રીમંડળનો અને એમાં કદાચ દારૂબંધીની છૂટ આપવા માગતા હોય અને ખુલ્લેઆમ જાહેરાત કરે તો મને વાંધો નથી, એમ કરે તો અમે વિરોધ કરી શકીએ પણ અહીંયાં સુધારો લઈને આવ્યા છે એમાં તો પાછલા બારણેથી દારૂબંધીને છૂટી કરવાની વાત છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અહીયાં દારૂની અંદર, દારૂબંધી રાખીને લોકકલ્યાણનો એક માર્ગ આપણે અપનાવ્યો છે અને એના માટે થઈને રાજય પોતાની બહુ મોટી આવક, જે બીજા રાજયો મેળવે છે દારૂને છૂટ આપીને, એનો ભોગ પણ આપે છે, જ્યારે આટલો મોટી આવકનો ભોગ આપતા હોય ત્યારે ખરેખર અર્થમાં આ કાયદો છે એ લોક કલ્યાણ માટે થાય એ રાજય સરકારે જોવું જોઈએ એક બાજુ આપણે આવક ગુમાવીએ છીએ અને બીજી તરફથી જે કાયદો બનાવવા માટે લોક કલ્યાણનો હેતુ આપણે રાખ્યો છે એ હેતુ બળ ન આવતો હોય, એ બંને ઉદ્દેશો છે એને નુકસાન જાય છે તો મારી માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીને વિનંતી છે કે, કદાચ એણે કેસોનો ભરાવો જે થયેલો છે એ કદાચ એમણે ઘટાડવો હોય તો એના માટેના ઘણા બધા રસ્તા છે, પરંતુ દારૂબંધીનો કાયદાથી અમલ થવો જોઈએ. ભલે ઉપલા વર્ગ માટે જે કરવું હોય તે કરે પણ સમાજનો નબળો વર્ગ છે એને આ કાયદાનો કડક રીતે અમલ થાય તો એને એનાથી ફાયદો થવાનો છે એટલે હું માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીનું આપના મારફત ધ્યાન દોરું છું કે આ સરકારે જે નીતિ નક્કી કરેલ છે એ નીતિની વિરુદ્ધમાં છે અને સરકારે હંમેશા એક ઉદેશ અને એક નીતિ રાખવી જોઈએ. નીતિ એક જાહેર કરવી અને ઉદેશ જુદો જાહેરાત કરવી અને કાયદો એનાથી વિરુદ્ધનો લાવવો એ યોગ્ય થતું નથી.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી નશાબંધી સુધારા વિધેયક લઈને આવ્યા છે એમાં હું મારા વિચારો વ્યક્ત કરું છું અને સૂચનો પણ કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નશાબંધીનો કાયદો માત્ર ગરીબો અને ગામડાના લોકો માટે જ એમને લાગે છે. નશાબંધીનો દુરુપયોગ સુખી સંપન્ન માણસો ૮૦ ટકા કરતા હોય છે એને જોઈ જોઈને દેખાદેખીમાં ગામડાનો ગરીબ માણસ એમ વિચારે છે કે આ મોટો માણસ કઈક પીવે છે તો સારું હશે એમ વિચારીને એમની ઘરે પાણી ઉકાળીને દેશી બનાવીને પીએ છે અને અમે પણ એમની જોડે બેસીએ એવું વિચારે છે તો એમને ગુનો લાગે છે. ઘરમાં એ ગાળીને બનાવે છે કેમ કે એની પાસે પૈસા નથી એટલે એ પેલાની હરોળમાં જવા માટે કરે છે તો તમે માનનીય મંત્રીશ્રી એના આંકડા મંગાવો ગુજરાતમાંથી આવો ધંધો કરતા હશે એમને ત્યાં રેડ પાડીને પકડ્યા હશે પણ વિદેશી દારુની ટ્રકોની ટ્રકો ઠલવાઈ છે એની ઉપર કેસ નહીં થયો હોય. એકાદ કેસ થયો હશે નજરે ચડ્યો હોય તો બાકી નહીં. કેમ કે એની બધી વાત થયેલી જ હોય. તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દારુ માટે તો કડકમાં કડક કાયદો હોવો જોઈએ એમાં અમને વાંધો નથી પરંતુ સાથે સાથે જે પેલા ઘોલરા છે, ગાંજો છે એ તો મંદિરમાં બાવા-સાધુ હોય એ જન્મજાતથી જ ગાંજો પીતા હોય એને ત્યાંજ ઊગતો હોય, કોઈ વેપાર કરતો નથી એ ગાંજો પીને સૂઈ જાય છે એ સમાજને નુકસાન નથી કરતો. હવે એવા માણસ સામે રાજકીય કિન્નાખોરી રાખીને આ કાયદો લાવવામાં આવશે તો મોટા મોટા મહાન સંતો પણ આમાં સંડોવાઈ જશે ખોટી રીતે. એતો જન્મજાતથી શંકર ભગવાનના એક વરદાનથી સાધુ-સંતો જય ભોલેનાથ કરીને ભાંગ પીવે છે, ગાંજો પીવે છે..(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : ગોવાભાઈ, તમે ગૃહમાં બોલી રહ્યા છો.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું વાસ્તવિક વાત કરું છું, હું રાજકીય વાત નથી કરતો. જે હું જોવ છું એ હકીકતનો માનનીય મંત્રીશ્રીને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય ગામડાંની આ હકીકતની વાત કરું છું. આ હકીકત છે. માટે જે આવા ગાંજો-ઘોલરા એવા પોતે વ્યકિતગત કયાંય આવું કરતા હોય તો એના ઉપર આ નહીં લાગવું જોઈએ. દંડ કરવા માટેના બીજા ઘણાં બધા ઉપાયો છે એમાંથી પૈસા લેજો. જે દારુ પીને

ધમાલ કરે છે, ખોટુ કરે છે એવા માણસો છે એના ઉપર સજજડબંબ કાયદો કરો, દસ વર્ષની સજા કરો અમે સંમત છીએ. પણ બિચારા પેલા ડોસા, આપ પણ જાણો છો, આપ પણ ઉત્તર ગુજરાતના છો બાજુમાં રાજસ્થાનનું પેલા ઘોલરાનું-ગાંજાનું વ્યસન થયું છે એ મરી જશે આમાં રાજકીય કિન્નાખોરી રાખશો તો એમની દશા બગડી જશે. એટલે માત્ર ઘોલરા અને બાવા પુરતી થોડીક રહેમ દ્દષ્ટિ રાખીને કાયદો હળવો કરો કારણ કે, ડોડાની આજ રામાયણ છે તમે ગામડામાં જાવ તો એનો ખ્યાલ આવે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં હકીકત કહી છે બીજુ કંઈ રાજકીય અવલોકન નથી કર્યું. તમે બધા જાણો છો પણ તમે નહીં બોલો અને હું બોલું છું. ખરેખર તમે અને અમે બધા જ્યારે ગામડામાં ચૂંટણી વખતે જઈએ છીએ ત્યારે પેલા ડોસા કહેતા હોય છે કે આ જે લાયસન્સ લે છે અને દારુ પીવાનું લાયસન્સ લઈને બેફામ પીને ફરે છે એનું કોઈ નામ લેતું નથી. અમે ખાલી જન્મજાતથી આ ઘોલરા ચાલુ હતો ત્યાં કહુંબો પીને સૂઈ જઈએ છીએ એમાં તમે ગુનો લગાડો છો. એમણે કહ્યું કે તમે આ રજૂઆત કેમ નથી કરતા ? તો આજે સુધારો લાવ્યા છો તો વિનંતી કરું છું, તમને બધાને વિનંતી કરું છું આ હાઉસમાં બેઠા છે એ બધા જાણે છે આ હકીકત સાચી છે અને એ લોકો મરી જશે એ લોકો ઉપર રાજકીય કિન્નાખોરી રાખીને ગુનો લગાડીને એક વખત, બે વખત અને ત્રીજી વખતે ગુનો કરશે તો સીધો જેલમાં લાવીશું તો એ ત્યાં જઈને મરી જશે અને બાવો એક પણ નહીં બચે. ૯૯ ટકા સાધુ-સંતો આનો ઉપયોગ કરતા હોય છે માટે જો સાધુ-સંતો માટે કાંઈ પણ સરકારની રહેમ દ્દષ્ટિ હોય તો એમને માટે લાયસન્સની-પરમિટની વ્યવસ્થા કરજો. એ એની પરમિટનો દુરુપયોગ કરે, એ લઈને જો સમાજનું અહિત થતું હોય એવું કરે, લોકોનું અહિત થતું હોય એવું કરે તો ભલે એના ઉપર ગુનો લગાડો. બાકી સાધુ-સંતો માટે પણ એમના મંદિર પુરતી એમની ઉપર થોડી ઘણી રહેમ દ્દષ્ટિ રાખીને દંડ ઓછો કરો અને સાથે સાથે પરમિટ આપવાની પણ જોગવાઈ કરો. આવા સંતોને પરમિટ આપવી અથવા આવા જે ૭૦-૮૦ વર્ષના ડોસા છે એને વ્યસન પડી ગયું છે અને એને ફરજિયાત પરમિટ લેવી હોય તો આપવી આ બધું કરજો તો એ પણ બચી શકશે અને બીજુ ઘણી આવક થશે. માટે મારી વિનંતી છે કે, આ દારુના કાયદાને હવે કડક કરો કેમ કે જે ધમાલ કરે છે, ન્યુસન્સ છે એનું કશું થતું નથી અને બિચારા સીધા માણસો મરી જાય છે.

(વિ રા મ - ૨-૩૦ થી ૩-૧૫ સુધી)

અધ્યક્ષશ્રી અધ્યક્ષસ્થાને

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગાંધીજીના ગુજરાતમાં નશાબંધીના સુધારા થવા જોઈએ, તેનો કડક અમલ થવો જોઈએ, પરંતુ સાથે સાથે દારૂ પીવા વાળા કરતા તે પીવડાવવાનો ધંધો કરે છે, બહારથી લાવીને કોઈની રહેમ નજર હેઠળ આ ધંધો કરે છે તેના ઉપર કડક જોગવાઈઓ કરવી જોઈએ. આમાં જે લોકો ભૂલચૂકથી સપડાઈ ગયા હોય તેના ઉપર કાયદો લગાડવામાં આવે છે, પણ નશાબંધીનું જે મૂળ છે તે કયાંથી આવે છે, તેની પાછળ કોણ છે, કઈ ગેંગ છે તેને પકડીને જડમૂળથી તેને ખતમ કરવાની જરૂર છે. તો જ આનો અમલ થઈ શકશે. વધુમાં કહેવાનું કે આ ડોડા અને ગાંજા વાળા જે છે તેની પરમીટ આપવામાં આવે છે તેમાં કાયદેસર ડોકટર કહેતા હોય, ડોકટરનું સર્ટિફિકેટ હોય તો તેમને તો આ લોહીમાં ભળી ગયું હોય છે તેને પરમીટ આપવી જરૂરી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : એ ઘણી વખત કહેવાઈ ગયું છે, પુનરાવર્તન થઈ રહયું છે. એકવાર બે વાર ત્રણ વાર ઘ ણી વખત કહેવાઈ ગયું છે.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી એ જોઈને કહે કે કરશું તો વાંધો નહીં,

શ્રી સુનીલ બા. ઓઝા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હમણાં મહાશિવરાત્રી આવે છે, ગોવાભાઈ આમંત્રણ આપે તો બધા જઈએ.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : હું આમંત્રણ નહીં આપું તો પણ ભાઈને પૂછો, બધા જવાના જ છે. એટલે અહીં આપણે બધા બેઠા છીએ તે નશાબંધી કાયદાનો અમલ કરવા માટે કડક રીતે અને પૂરી શ્રદ્ધા સાથે વાત કરીશું કે બંધ કરવું જ છે તો સો ટકા થઈ શકશે, પણ પાછલા બારણે આપણે ચલાવીએ અને પછી આ કાયદાની વાત કરીએ તો આ કાયદાનો પુરો અમલ થઈ શકવાનો નથી. આ ગાંધીજીના ગુજરાતમાં આ કાયદાનો ખરેખર પૂરેપૂરો અમલ થવો જોઈએ એમ જો આપણે ગાંધીજીને યાદ કરીને કહેતા હોઈએ તો ચોક્કસ તેનો અમલ થશે. અને નશાબંધી પાછળનું જે મૂળ છે તે મૂળમાં જવું પડશે, તેનું મૂળ છે તે આપણા રાજયની બન્ને બાજુ જે રાજયો આવેલા છે રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર, આ બન્ને રાજયોમાં નશાબંધીની છૂટ છે, તેથી તેની નાકાબંધી કરી નાખો તો કોઈ આવશે નહીં, પરંતુ કાયદાનો પૂરેપૂરો અમલ ન થાય અને સાચા માણસો સંડોવાય તેને દંડ થાય તે બરાબર નથી. અને તેથી તેના માટે સુધારો કરવો જોઈએ, ખાસકરીને પરમિટ વાળાને પૂરેપૂરી છૂટ મળે, અને ડોકટરનું સર્ટિફિકેટ હોય તો તેને પરમિટ મળે તેવો સુધારો કરજો તેવું મારું સૂચન છે.

શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર(મહુધા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ સાહેબ જે નશાબંધી ખાતાનો કાયદો લાવ્યા છે એમાં તેઓ તો વાણિયા છે, અને વાણિયા તો ડાહી મા ના દીકરા કહેવાય, અને વાણિયાનો કારોબાર પહેલા બહુ સારો હતો, પણ હવે બગડી ગયો છે. હવે સરકાર જયારે આ કાયદો લાવી છે ત્યારે એ કાયદામાં ગરીબ લોકો આ વધુ પીવે છે તેથી ગરીબ લોકોને વધુ મુશ્કેલી પડશે. અને ઉજળિયાત લોકો જે પીવે છે તેને પકડતા નથી, કારણ કે જે પીવે છે તે અભણ માણસો હોય અને ગમે તે ગમે ત્યારે તેઓ પોલીસના હાથમાં આવી જાય છે, અને હોંશિયાર લોકો જે પીવે છે એ પકડાતા નથી. તેથી તેને પકડવાનું કરો તો સારું. આમાં તો શું થાય છે કે ગરીબ માણસો મજૂરી કરે છે અને દંડાય છે. એટલે આપ એવી જાહેરાત કરો કે આવો કાયદો કર્યો છે એટલે કોઈ પીશે તો આ સજા થશે એવું કંઈક કરો. બે ચાર વખત પેપરમાં પણ આપો. તો આ ઓછું થાય. અને આ રીતે અમલમાં હોય તો ગરીબ માણસોને ખબર ન પડે અને અભણ માણસો હોય તે વધુ દંડાય. પહેલાના જમાનાથી ગાંજો વગેરે ચાલે છે, બાવા-સાધુને ગાંજા વગર ચાલે નહીં, સંતો મહંતોને ગાંજા વગર ચાલે નહીં. ઘણાં પોષડોડા છે, અફીણ છે હવે પોષડોડાનો લોકો ઉપયોગ કરે છે પણ તે ડોકટરનું સર્ટીફિકેટ આપે છે ચાલી શકે તેમ નથી તો પરમીટ બરમીટ કાઢજો કારણકે ગામડામાં ડોસા જે પાઘડીવાળા છે તે બહુ પીવે છે. અમારા સમાજમાં પણ બહુ પીવે છે. બધું વ્યસન અમારા સમાજમાં છે તો પણ હજુ અમારા સમાજવાળા સમજતા નથી હું કહી કહીને થાકયો તો સુધરે એવું કરજો. કારણકે તમે ડાહીમાના દીકરા અમારા કરતા બુધ્ધિજીવી વધુ છો તો કંઈક સુધારો આવે એવું કરજો. આંધળે બેરું કૂટી મરે એવું કંઈ ન કરતા. કારણકે આ દારુ બંધ થાય તે સારું છે પણ તે બહુ શકય લાગતું નથી. આ કાયદો કરશો તેમ વધુ પીવાય બીજા રાજયોમાં કાયદો નથી ત્યાં ઓછું થયુ છે. જેમ પેલા તમાકુની પરમીટ હતી તો લોકો વધુ દાણચોરી કરતા હતા એટલે કાયદો છે પણ તેનો અમલ બરાબર થાય અને લોકો દંડાય નહીં અને બંધ કરે કારણકે બીજા મોટા મોટા બહારથી બીજા રાજયોમાંથી દારુ લાવે છે તે પકડાતા નથી તે પકડાય એવું કરો તો બંધ થાય પણ તે કરતા નથી. તમે ડાહીમાના દીકરા પોલમ પોલ ન રાખશો કાયદો સજ્જડ કરો. કોઈ સારો માણસ કે ગરીબ માણસ મરી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખજો. કારણકે આમાં ખરો ગુન્હેગાર તો તમારા હાથમાં આવતો નથી અને નિર્દોષ તમારા હાથમાં આવી જાય છે તો તેનું ધ્યાન રાખશો અને દંડ થાય તેનો વાંધો નહીં પણ ગુન્હેગાર પકડાય એવી મારી વિનંતી છે. આ કાયદાની જાહેરાત કરજો અને જયારે કોઈ ખોટા માણસને પકડો નહીં પણ ગરીબ કે નાસમજ માણસ પકડાય છે ...અંતરાય... બીજું જે કાયદો સજા કરી તેનો વાંધો નહીં પણ પરમીટો છે, જેને ટેવ છે, ડોકટરે સલાહ આપી છે કે અફીણ કે દારુ કે ગાંજા વગર નહીં ચાલે તો તેની પરમીટનું કરજો. તે ના પીવે તો તેને પગ ઘસવા પડે છે ખાસ કરીને અફીણમાં તો તેને પગ ના ઘસવા પડે એવું કરજો.

ડૉ. અનિલ જોષીયારા (ભીલોડા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી જે સુધારા વિધેયક લાવ્યા છે તેમાં મારે એક જ સુધારો રજૂ કરવો છે એક તો ડોકટર દ્વારા જે પ્રમાણપત્ર.

અધ્યક્ષશ્રી : સુધારો અત્યારે ના મૂકી શકાય.

ડૉ. અનિલ જોષીયારા : સૂચન રજૂ કરું છું કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં કે જયાં તાડના ઝાડ પુષ્કળ છે તેની ઉપર લોકોની રોજી-રોટી અને આજીવીકાનું સાધન છે અને જયારે ખુલ્લેઆમ નીરો તો ચાલે છે દરેક જગ્યાએ અને સવારમાં નીરો અને સાંજે તાડી કહેવામાં આવે છે આમાં એમ લખ્યું છે કે ઝાડને છેદે અથવા છેદવાની છૂટ આપે તેને આ કાયદો લાગુ પડશે તે થોડુંક ગંભીર છે આમાં ફેરફાર કરવાની મને જરુરિયાત લાગે છે કારણકે આદિવાસી વિસ્તારને ખૂબ નુકસાનકર્તા છે. આમાં નીરો માટે છૂટ છે તો આવા સંજોગોમાં મારું સૂચન છે ઝાડ પૂરતું, આ તાડના ઝાડ પૂરતું અને ડોકટરના સર્ટીફિકેટના આધારે જે પરમીટો ઘણી બધી અપાય છે તેનો પણ સરવે કરવામાં આવે તો ઘણાં બધા કેસો નીકળી શકે તમે છે. દરેક જિલ્લા લેવલે સરવે કરવાની જરુર છે. મોટા જે તવંગર માણસો છે તમે સરવે કરો ખોટાં સર્ટીફિકેટ અપાયેલાં છે તેનો સરવે કરો.

અધ્યક્ષશ્રી : આ ગુજરાત માટે અતિ ગંભીર બિલ છે તેને આટલા લાઈટ મૂડમાં બધા લેશો તે ઠીક નહીં, ગંભીરતા ખૂબ જરુરી છે.

ડૉ. અનિલ જોષીયારા : ના, અમે લાઈટમાં લેવા માગતા નથી પણ આ તાડી પૂરતું જે આદિવાસીઓનું આજીવીકાનું સાધન છે તેમાં આ કેસ જો દાખલ થાય તો તેને ખૂબ મોટું નુકસાન થાય તેમ છે.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી (અમરેલી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી આ સન્માનનીય ગૃહ સમક્ષ મુંબઈ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક લઈને આવ્યા છે અને જેની અંદર પ્રથમથી જ મારા વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ પોતાની જે વાત મૂકી છે એ વાતમાં હું પણ મારો સૂર પૂરાવતાં માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીએ આ બિલ લાવવા માટેના જે વિચારો રજૂ કર્યા છે એ વિચારો માત્ર વિચારો જ ના રહે અને એ વિચારોનો અમલ એક અસરકારક રીતે જો કરવામાં આવશે તો જ આ દારૂબંધીનો વિષય એ વાસ્તવમાં ગાંધીના ગુજરાતમાં સફળ થયો છે એમ લાગશે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી આ વિધેયકમાં જે સુધારો લઈને આવ્યા છે એમાં કલમ ૮૫ નો પાર્ટ-૧ કે 'જેમાં પ્રથમ વખત કોઈ વ્યકિત પોહિબિશન એકટનો ભંગ કરે અને છાકટો થાય અને પોતાની

સંભાળ લેવાને અસમર્થ હોય એટલે કે પોતાની જાતને. સંભાળી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં ના હોય તો એના માટેની દંડની જે જોગવાઈ છે એ દંડની જોગવાઈ ન્યાયાધીશને તેમની મુનસબી ઉપર યોગ્ય લાગે કે સાબિત ના થતું હોય તો એકથી ૭ દિવસ સુધીની સજા અને ૨૫ રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ છે.' તો મને લાગે છે કે આ જોગવાઈથી દારૂબંધીનો જે વિચાર માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીએ આ સન્માનનીય ગૃહ સમક્ષ મૂકયો. છે એની સામે એક પ્રશ્નાર્થવિરામ આવી જશે. આજના આ વિકસતા યુગમાં ૨૫ રૂપિયાનો દંડ એ બહુ જ મામૂલી રકમ છે અને સાત દિવસની સજા એ પણ બહુ મામૂલી દિવસો છે. દારૂબંધી જેવી બાબત આવતી હોય ત્યારે માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રીને હું વિનંતી કરવા માગું છું કે આ દારૂડીયાઓ છે એ બીજી વખત, ત્રીજી વખત અને પછી વારંવાર એ રીતે દારૂ પીતા રહેશે અને એના માટે કોઈ કાયદો કામમાં લાગવાનો નથી, પરંતુ જે વ્યકિત આ દૂષણમાં પ્રથમ વખત જ પગ મૂકે છે એને પ્રથમ વખત જ સખતમાં સખત સજાની જોગવાઈ થવી જોઈએ કે જેથી એ આની અંદર પ્રવશે કરતો જ અટકે. આટલાથી પૂરું થતું નથી, પરંતુ મારે માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીને એ પણ વિનંતી કરવી છે કે આપે આ બિલથી દારૂબંધીનો એક વિચાર ચોકકસ મ્રકયો છે, પરંતુ એમાં નિષ્ઠા તો તો જ સાબિત થાય કે ડાળીઓને ઝૂડવાનું બંધ કરીને થડને જ કાપવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આજે તો પ્રોહિબિશન એકટનો ભંગ કરનાર વ્યકિત માટે ખાસ કરીને જોગવાઈ છે એ સુધારવા માટેનો માત્ર વિચાર મૂકયો છે, પરંતુ આવા દૂષણને ડામવું ચોકકસ જરૂરી છે કારણ કે આજના ગાંધીના ગુજરાતમાં દરરોજની લગભગ ૧૦૦ જેટલી ટ્રકોની દારૂની હેરાફેરી થાય છે. આજે ગુજરાતમાં પ્રોહિબિશન એકટનો ભંગ થતો જાય છે અને ખાસ પ્રસંગોમાં દારૂનું સેવન કરવાનો એક ટ્રેડ વધતો જાય છે અને એ ગૃહ વિભાગના ધ્યાનમાં આવતું નથી એ એક દુ:ખદ બાબત છે. તો હું માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું કે આપણે દારૂબંધીનો વિચાર ચોકકસ લાવ્યા છીએ, પરંતુ એનો ચોકકસ અમલ કરાવવાની નિષ્ઠા સાબિત થવી જોઈએ. દારૂ પીનારાઓ કરતાં જે એના વેચનારાઓ છે, જે એનું ગેરબંધારણીય રીતે ઉત્પાદન કરતા હોય, એવી ઉત્પાદન કરતી ફેકટરીઓ એ પણ માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીના ખ્યાલમાં હશે કે વાપી અને આસપાસનો વિસ્તાર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ છે ત્યાં માત્ર લેબલિંગ કરીને ઉત્પાદન કરીને સમગ્ર ગુજરાતમાં દારૂનો સપ્લાય કરવામાં આવે છે. તો આ અંગેનો એક સખતાઈપૂર્વકનો કાયદો જો વિધાનસભા સમક્ષ આવે તો ચોકકસ આવકાર્ય હોય.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી,, આ દારૂની સૌથી મોટી અસર થતી હોય તો એ યુવાવર્ગને થાય છે. યુવાનવર્ગ આજે ગાંધીના ગુજરાતમાં ગાંધીનાં મૂલ્યોને ભૂલતો જાય છે. એટલા માટે કે આ જે પરંપરા છે એમાં કોઈ પ્રથમ વખત પગ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પ્રથમ વખત મૂકેલા પગમાંથી એ પાછો વળી શકતો નથી, એમાં એ લપસાતો જ જાય છે. તો પ્રથમ વખત એ ગુનો કરે તો એના માટે સખતમાં સખત સજાની જોગવાઈ થશે તો ચોકકસ આ પ્રોહિબિશન એકટનો ભંગ કરતા કેસો બને છે એમાં નિયંત્રણ લાવી શકાશે. આવા કેસો ઓછા થાય એવું આપણે પરિણામ લાવવું છે એ પણ મેળવી શકીશું.અફીણ અને ગાંજા માટેની વાત ઘણાં માનનીય સભ્યશ્રીઓએ આ સન્માનનીય ગૃહ સમક્ષ કરી છે, પરંતુ અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં એક પ્રણાલિ છે કે આજે પણ દરબારગઢમાં લગ્નનો પ્રસંગ હોય તો મહેમાનોનું સ્વાગત કાલાથી અને અફિણથી થાય છે, આ ચિંતાનો વિષય એટલા માટે છે કે માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રીના ધ્યાન ઉપર મુકવા માગું છું કે મારા અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકામાં તાંતણીયા જેવા નાના ગામમાં કાલાના લાયસન્સ તો આપ્યા, પણ તેનો જથ્થો મર્યાદિત કરી અને તેમાં ઘટાડો કર્યો તેનાથી બ્લેક માર્કેટિંગને મોટું પ્રોત્સાહન મળે છે અને કાલાના બંધાણીની તો એવી પરિસ્થિતિ હોય છે કે, જે રીતે પેટમાં ભૂખ લાગી હોય અને માણસ તડપે તેમ કાલાના બંધાણી ભાઈ-સાહેબ, બાપા કરતા એજન્ટને પકડતા હોય છે અને પોતાની ક્ષમતાથી વધારે ખર્ચ કરીને પણ કાલા લેવા માટે મજબૂર બને છે. અને તેથી આ જથ્થો ઘટાડીને જે રીસ્ટ્રીકશન મુકયું છે તેના અંગે અભ્યાસ કરી અને વાસ્તવિક બંધાણી છે તેના માટે જરૂરિયાત મુજબનો જથ્થો આપવા માટેની કોઈ વાત લાવ્યા હોત તો ચોકકસ આવકાર્ય હોત, પણ આ કાલાનું બંધાણ હવે પછીની પેઢીને ન થાય, તેના માટે જોગવાઈ કરવી પણ જરૂરી છે, આપણા બાપ-દાદા, વડ-દાદાઓને વારસામાં જે વ્યસન મળ્યું છે તે નવી પેઢીને ન મળે તેના માટે કડકમાં કડક જોગવાઈ થાય અને તેના માટેનો વિચાર આ બિલ થકી થયો હોત તો આપણે ચોકકસ આવકાર્યુ હોત, આમાં વિચાર ચોકકસ લઈને આવ્યા છે, પણ તે વિચારમાં સી.એલ.પી. લીડરે વાત કરી એમ વિચારથી આ થવાનું નથી, આમાં સાત દિવસ અને પચ્ચીસ રૂપિયાની જે જોગવાઈ છે તેનાથી તો ઈનડાયરેકટ આપણે ગાંધીજીના ગુજરાતમાં દારૂ પીવાની છૂટ આપતા હોઈએ તેવું મને લાગે છે, તો આ મહાત્મા ગાંધીજીના મૂલ્યોને નિષ્ઠાથી લઈ અને વધુ કડકમાં કડક જોગવાઈ થાય તેવી આપશ્રી મારફત હું વિનંતી કરું છું.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર (દહેગામ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રી નશાબંધી સુધારા વિધેયક લઈને આવ્યા છે તેમાં મારા વિચારો વ્યકત કરવા માટે ઉભો થયો છું. આ ગૃહમાં જયારે બેઠા હોઈએ ત્યારે સમગ્ર સમાજની ચિંતા કરવી અને સમગ્ર ગુજરાતની ચિંતા કરવી તે આપણી ફરજ થઈ પડે છે. અને આવા મહત્વના બિલ ઉપર આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે હું આ સભાગૃહના ધ્યાન ઉપર મૂકવા માગું છું, આ વાતમાં કદાચ અવિવેક થતો હોય તો મને ક્ષમ્ય ગણજો. આ માનનીય સભાગૃહના માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ

તાજેતરમાં પોતાની દીકરીના લગ્ન, સમૂહ લગ્નમાં કર્યા અને સુધારા વાદી હોવાનો એક ઉત્તમ નમૂનો પૂરો પાડયો છે. તે બદલ સમગ્ર ગૃહ વતી હું આપશ્રીએ જે ચીલો પાડયો છે તે બદલ અભિનંદન આપું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : આપ અધ્યક્ષશ્રીની વાત આ ગૃહમાં નહીં કહી શકો.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એટલા માટે મેં કહ્યું છે કે ક્ષમ્ય ગણજો, પણ સાહેબ આ સુધારા વાદની વાત કયાંક તો લેવી પડે ને. એટલા માટે અવિવેક થતો હોય તો ક્ષમ્ય ગણજો. આ સભાગૃહના મારા વિદ્વાન સભ્યશ્રીઓએ એમની વાત કરી છે. આ નશાબંધી કેમ કડક થવી જોઈએ, તેના માટે ખૂબ ચિંતા કરવી પડશે. સાહેબ જ્યારે દીકરી વિધવા થાય છે ત્યારે તેના માટે સમાજમાં કયાંક આપણે ચિંતા વ્યકત કરવી પડશે. આ વ્યસન બધી વ્યકિતઓ માટે, અને એમાંય ખાસ કરીને દેશી દારૂના વ્યસન કરવા વાળા વ્યકિતઓ છે તે પાંચ સાત કે દસ વર્ષનાં વ્યસનમાં જ ખતમ થઈ જાય છે, લાંબુ વ્યસન કરી શકતા નથી. તેઓ લાંબુ આયુષ્ય પણ ભોગવી શકતા નથી. પંદર કે સોળ વર્ષે લગ્ન થાય છે અને દસ વર્ષનું એનું વ્યસનનું આયુષ્ય હોય છે, જયારે પચ્ચીસ વર્ષે પહોંચે છે ત્યારે બે ચાર દીકરા થાય છે અને પચ્ચીસ કે છવ્વીસ વર્ષની ઉમરે તો મોટા ભાગના વ્યસનીઓ મૃત્યુ પામતા હોય છે. અને તેમની પાછળ વિધવા અને ત્રણ ચાર બાળકો અનાથ બનતા હોય છે. નિરાધાર બનતા હોય છે. આ વ્યસન કોઈ એક સમાજ પૂરતું સીમિત નથી. જેટલા પાર્ટી પ્લોટો જોવા જઈશું કે લગ્નની સીઝનમાં જેટલા પણ પાર્ટી પ્લોટો અને જે કંઈ વૈભવી લગ્નો થતા હોય એના આગળના દિવસનું રસોડું થતું હોય ત્યાં કંઈક ચિંતા કરો. ત્યાં પાંચ-પંદર અંગ્રેજી દારુની બાટલીઓ સાથે મહેફિલ માણતા બનાવો આપણે જોયા છે.

કેટલાક રીત રિવાજો એવા છે કે એમના લગ્નમાં દારુ પીરસાતો હોય છે. કેટલાક ગૃહના સભ્યશ્રીઓએ પોતાની વ્યકિતગત રીતે વાત કરી છે. પણ હું સ્પષ્ટપણે માનુ છું કે જ્યાં સુધી અફીણ અને પોસડોડાની વાત છે ત્યાં સુધી ૬૦-૭૦ વર્ષની ઉંમરના માણસો છે એના માટે કંઈક જુદી વ્યવસ્થા કરવી પડે તો એમાં વાંધો નથી, પરંતુ ડાયરામાં જે લોકો બેસે છે એમાં પાંચ સાત ટોળકીના સભ્યો કેમ વધે, લે જવાન તારે કહુંબો કરવો પડે અમારો હાથ પાછો ન પડે એમ કરીને ગરીબ સમાજને ખતમ કરવાનું કામ છે એની સામે સજા મૂકવામાં આવે. ગરીબ અને બક્ષીપંચનો સમાજ દારુ પીતો કેમ વધારે કરવો એવું અમને ચોક્કસ દેખાય છે. જેને માટે છૂટછાટ, જેના માટે વાતો, અમુક વિસ્તારમાં છૂટછાટ અને અમુક સમાજ માટે છૂટછાટ રાખવી પડશે. આ દૂષણનો ભોગ અમે બન્યા છીએ, એ દૂષણનો ભોગ અમારો સમાજ બન્યો છે. આમાં સાત દિવસની સજા અને ૨૫ રૂપિયાનો દંડ એમાં હું માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરુ કે મહત્તમ સજા કેટલી કરી શકો છો. અને સજા પામે ત્યારે એને સેવાના કામમાં જોતરવા આવે તો અમને ચોક્કસ આનંદ થશે. પરંતુ એને જેલમાં મૂક્યા પછી કાળી મજૂરી કરાવવાને બદલે એ વ્યસન કેમ ભૂલે અને એ ભૂલીને સમાજમાં પાછો આવે એવું જો જેલમાં કરવા માગતા હશે તો આ વિધેયક લાવવાનો જશ મળશે એવી આપને નમ્ર વિનંતી કરું છું.

દારુબંધીનો સવાલ છે એમાં દારુ વેચવાવાળા માણસોની પોલીસ સાથેની સાંઠગાંઠ એવી સભ્યશ્રીઓની વાત આવે છે, વર્તમાનપત્રોમાં પણ લખાય છે. ધારાસભ્યશ્રીઓ સો સો કાગળો લખે કે ફલાણી જગ્યાએ દારુ વેચાય છે તેમ છતાં એ બંધ થયેલ નથી અને દારુના ધંધાવાળા પાવરફૂલ બની રાજકીય નેતાઓને અને તંત્રને ગળી જવાની વાત કરતા હોય છે. પોલીસ દરોડો પાડવા જાય એને પકડવા જાય ત્યારે એની આજુબાજુ જે નિર્દોષ લોકો રહે છે જેને આ ધંધા સાથે લેવાદેવા પણ નથી એવા લોકોને મારઝૂડ થાય છે. ત્યારે પ્રજા અને પોલીસ સામસામે આવે ત્યારે ત્રણ ત્રણ-ચાર ચાર દિવસ સુધી ગામ ખાલી થઈ જાય છે અને માનનીય મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરીએ ત્યારે થાળે પડવાનો અવસર આવે છે. તેથી જે ધંધો કરનાર વ્યકિતઓ છે એને ઓળખી લેવા જોઈએ અને ધારાસભ્યશ્રીઓની અથવા તો નનામી અરજી આવે ત્યારે એના ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપીને કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.

શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ (માંડલ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી જે બિલ લઈને આવ્યા છે એને હું મારુ અનુમોદન આપું છું.

આ બિલ ઉપર ગૃહના ઘણા માનનીય સભ્યશ્રીઓએ ચર્ચા કરી. ગોવાભાઈ જેવા સન્માનનીય સભ્યશ્રીએ *(xxxx) કરી. (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય પ્રાગજીભાઈ, આપ કહો છો એવી વાત નથી. તેથી કાર્યવાહીમાંથી આ શબ્દો દૂર કરવામાં આવે છે.

શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ : ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસના શાસનની અંદર લઠો પીનાર મૃત્યુ પામે તો વળતર અપાતું હતું. પરંતુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ વળતર બંધ કરેલ છે. વળતર મળે, પીનારાના પરિવારને વળતર મળે. એ પૈસા આવે પછી તેનો વારસદાર પીવાનું શરૂ કરે. પછી એને વળતર મળે. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે બંધ કર્યું છે.(અંતરાય)

* (xxx) આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય પ્રાગજીભાઈ, આ બિલ ગંભીર છે. આ ગુજરાતની ઉપર તેની ઘણી મોટી અસર થાય છે. કોઈના ઉપર આક્ષેપો, પ્રતિઆક્ષેપો નહીં કરવા અને બિલની ચર્ચા કરો.

શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયની સરકારે નશાબંધીના અમલીકરણ માટે વિવિધ કાર્યક્રમો કર્યા છે. વિવિધ પગલાં ભર્યા છે. નશાબંધી બોર્ડ પણ અલગ બનાવ્યું છે. રાજય કક્ષાએ, તાલુકા કક્ષાએ અને જિલ્લા કક્ષાએ નશાબંધી અમલીકરણની સમિતિ બનાવી છે અને આવી સમિતિઓ બનાવીને મોટા ભાગના કેસોનો ભરાવો ગ્રામ્ય વિસ્તારોનો છે. ગામડાંના લોકોને સમજ પડે તેના માટે રાજય સરકાર વારંવાર વર્ષાન્તે વ્યસનમુકિત સપ્તાહ ઉજવીને કાર્યક્રમો કરી રહી છે અને પ્રચાર માધ્યમો માટે સમાજના આગેવાનોને પણ જોડવામાં આવે છે. આવા જે નશાબંધીના અમલીકરણ માટે જે કોઈ કાયદા જ્યારે જ્યારે અનિવાર્ય હોય ત્યારે સભાગૃહમાં આવે અને તેમાં ફેરફાર કરવાની સરકારની પણ જવાબદારી છે ત્યારે ગૃહમંત્રી જે કાયદો લઈને આવ્યા છે તેને મારું અનુમોદન આપું છું.

શ્રી પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ (ગઢડા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય નશાબંધી અને આબકારી મંત્રીશ્રી મુંબઈ નશાબંધી સુધારા વિધેયક-૨૦૦૫ લઈને આવ્યા છે તેમાં મારા વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે ઉપસ્થિત થયો છું. મારા વિધાનસભાના સાથી મિત્રો જગદીશભાઈ, પરેશભાઈ, ગોવાભાઈએ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા તેમાં મારું સમર્થન આપું છું. ગાંધીના ગુજરાતની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે અને નશાબંધીની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે સભ્યશ્રીઓએ જે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી તેમાં પરમિટના નામે ગુજરાતની અંદર લાખો ટન વજનનો દારુ પીવાય છે. સુધારા વિધેયકમાં આ પરમિટ રદ કરવાનું સુધારા વિધેયક લાવ્યા હોત તો મને ખૂબ જ ગમત. કારણ કે ગાંધીજીના ગુજરાતમાં પરમિટના નામે જે મોટા પાયે દારુનો ધંધો થઈ રહ્યો છે, દારુ વેચાઈ રહ્યો છે એ ખૂબ જ દુ:ખદ ઘટના છે. સભ્યશ્રીએ હમણાં જે કોંગ્રેસની સરકારની વાત કરી તો હંમેશા સમાજ સારું ઇચ્છે છે. સમાજમાં જો સારા સંસ્કાર આપવા હોય તો, સારું શિક્ષણ આપવું હોય તો હંમેશા દારૂબંધીના કાર્યક્રમો આપવાથી થતું નથી પણ વાસ્તવિક રીતે અમલીકરણ થાય ત્યારે નશાબંધીનો હેતુ સફળ થયો ગણાશે. માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું કે અત્યારે લાખો લોકોને પરમિટ આપી છે. તે આવતા વિધેયકમાં રદ કરવી જોઈએ. ખરેખર જો નશાબંધી અમલમાં મૂકવી હોય તો પરમિટ પ્રથા રદ કરીને આરોગ્યના નામે વાત કરતા હોય, આરોગ્યના નામે જ્યારે પરમિટ આપતા હોય ત્યારે કદાચ દારુ ન પીવાથી જો મૃત્યુ થતું હોય તો એ પણ મંજૂર રાખીને સરકારશ્રીએ એ દિશામાં આગળ પગલાં ભરવા જોઈએ એ ભરવા જોઈએ. આજે બૉર્ડર ઉપર દારુ મોટા પ્રમાણમાં આવે છે. ત્યારે બૉર્ડર ઉપરના પોલીસ અધિકારીની નિમણૂંક માટે લાખો રૂપિયાની લાંચ લેવાય છે. જ્યારે બૉર્ડર ઉપરથી દારુ આવે છે ત્યારે લોકો પીવે છે. લગ્ન સમારંભોમાં પણ પુષ્કળ દારુ પીવાતો હોય અને વિધાનસભાના સભ્યો પણ જો પરમિટ ધરાવતા હોય તો માનનીય મંત્રીશ્રીએ જાહેરમાં મેજ ઉપર મૂકવું જોઈએ અને આરોગ્યની ફરી તપાસણી થવી જોઈએ. માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કે નશાબંધીની વાતો કરીને સમગ્ર ગુજરાતમાં જ્યારે બેફામ દારુ પીવાય છે. આજે મોબાઈલ ઉપર હોમ ડિલિવરીથી દારુ મળે છે. તમે મોબાઈલ ઉપર ફોન કરો અને ઘરે જે બ્રાન્ડની દારુની બૉટલ જોઈતી હોય તે મળે છે. છેવાડાના ગામડાંમાં સામાન્ય ગરીબ વર્ગના દારુ પીનારને પકડવામાં આવે છે. પરંતુ ઘરે ઘરે તપાસ કરવામાં આવે તો હજારો લોકોના ઘરમાંથી દારુ મળશે. પરંતુ એ તરફ કંઈ કરવામાં આવતું નથી. આજે નશાબંધીના પી.એસ.આઈ. કે નશાબંધીમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ રાત્રે દારુ પીને રેડ પાડવા જતા હોય છે. તેની તરફ સરકારનું ધ્યાન દોરું છું.

ભાવનગર જિલ્લાની વાત કરું તો બગદાણા ખૂબ જ મોટું ધાર્મિક સ્થળ છે. બજરંગદાસબાપાના ધાર્મિક ભજનો ગવાતા હોય ત્યારે તેને બંધ કરવા માટે અધિકારીઓ જાય છે. પણ દારુ વેચતા લોકો માટે ફરિયાદ કરવામાં આવે છે ત્યારે નજર ફેરવતા નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે તે દારૂના વેપારીઓ હોય એને ૩ મહિને કે ૫ મહિને કહેવામાં આવે છે કે તમે હાજર થઈ જાઓ, એક કેસ કરવો પડશે. આ રીતે સૂચના આપી વેપાર થાય છે એ બંધ કરવા તરફ સરકાર વળે એ માટે વિનંતી કરું છું કે, આ પરમિટ પ્રથા છે એ સદંતર બંધ થવી જોઈએ અને આરોગ્ય માટે પૈસા ફાળવવા જોઈએ. આ થવું ખૂબજ અગત્યનું છે. એમના આરોગ્ય માટે દવાઓ ઘણી બધી છે. આ પરમિટ સાથે ગુજરાતમાં દારૂનો પ્રવેશ થાય એટલે તો એ પીવાના છે. એટલે પરમિટ હોય કે ન હોય એ બધા પીવાના. આવતા દિવસોમાં માનનીય મંત્રીશ્રી સારું વિધેયક લાવે એવી વિનંતી સાથે વિરમું છું.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ (ઉના): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રી મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) અધિનિયમ-૧૯૪૯ વધુ સુધારા વિધેયક લઈને આવ્યા છે. એમાં મારા વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે ઉપસ્થિત થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજય નશાબંધીને વરેલું રાજય છે. નશાબંધીની નીતિનો રાજય સરકારે અમલ કર્યો છે. નશાબંધીના જે કોઈ કાયદાઓ અત્યાર સુધી છે એ અમલમાં છે. સમય જતાં એમાં સુધારા કરી

એમાં નવો ઉમેરો કરવો એ જરૂરી છે. પણ જે કાયદાઓ છે અને જેનો અમલ થાય છે અને દારૂબંધીની નીતિના કડક અમલ અંગે ગૃહમાં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. મારા મિત્રોએ વાત કરી કે, કૉન્ગ્રેસી શાસન, ભાજપનું શાસન આ કોઈના શાસનનો સવાલ નથી, સવાલ સમગ્ર સમાજનો છે. આ પક્ષની સરકાર કે પેલા પક્ષની સરકાર. ભૂતકાળમાં પણ આ ગૃહની અંદર દારૂબંધીની ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ છે. છતાં આપણને ગમે કે ન ગમે પણ છતાં નરી વાસ્તવિકતા છે. દારૂબંધીની નીતિ અમલમાં હોવા છતાં ખુલ્લંખુલ્લા દારૂ વેચાય છે એ વાસ્તવિકતા આપણે આજે સ્વીકારવી પડશે. જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. વિદેશી દારૂ રાજયમાં ઉત્પન્ન થાય છે? આપણે કોઈ ઉત્પાદકોને પરમિટો આપી છે? નથી આપી તો રાજયમાં દારૂ આવે છે કયાંથી? એકબાજુ રાજસ્થાન સરહદ, બીજી બાજુ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, દીવ, દમણ(વાપી). આ ત્રણેય ક્ષેત્રો એવા છે કે ત્યાંથી વિદેશી દારૂ ગુજરાતમાં ઠલવાય છે. જે દારૂ અહીંયાં આવે છે, જે દારૂનું વેચાણ કરતા હોય છે. અહીંયાં પરમિટની વાત કરવામાં આવી. રાજયમાં કેટલા લોકોને દારૂની પરમિટો આપી છે? અને જેટલા લોકોને પરમિટો આપી છે એની જરૂરિયાત કેટલી? અને એ જરૂરિયાત સામે રાજયમાં દારૂ આવે છે કેટલો? જગદિશભાઈએ વાત કરી એમાં ર બાબતો છે. વી.વી.આઈ.પી અને એક ગામડાનો ગરીબ અને છેવાડાનો માણસ. આજે વી.વી.આઈ.પી.ઓ પાર્ટી પ્લૉટના નામે, બીજા કોઈ ફંક્શનના નામે, ક્યાંક મહેમાન તરીકે જઈએ અને ડાઈનીંગ ટેબલ ઉપર વિદેશી દારૂની બૉટલ આવે અને તમે ક્યાંક ના પાડો તો આશ્ચર્ય વ્યક્ત થાય છે. લે, તમે પીતા નથી? આ વાસ્તવિકતા છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એની સામે દેશી દારૂ જે ગાળવાની વાત આવે છે અને જ્યાં દેશી દારૂ ગાળવામાં આવે છે અને દેશી દારૂમાં જેનો વપરાશ થાય છે એવી વસ્તુ ગોળ એની સામે નવસાર અને આજે તો બૅટરીના જે પાવર આવે છે એ પાવરનો પણ ઉપયોગ થાય છે અને એ ઉપયોગને કારણે દારૂ પીનારા અને વ્યસની માણસો લાંબુ જીવતા નથી. અને પરિણામે વિધવાઓ બને છે અને એની સંખ્યા દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. જે બુટલેગરો આજે વેચાય છે માનનીય મંત્રીશ્રીએ વ્યવસ્થા કરી કે રાતના ૧૨-૦૦ વાગ્યા પછી સો એન્ડ સો ટેલિફોન નંબર ઉપર ટેલિફોન કરજો, તમારું નામ છે એ જાહેરાત કરવામાં આવશે નહીં પરંતુ આવી ટેલિફોન ઉપરથી તમે કેટલી રેડો પાડી? અને કેટલો દારૂ પકડ્યો? આજે આ સાંઠગાંઠ છે એ ચાલુ જ છે. દારૂબંધીની નીતિનો અમલ કડક હાથે કરવા માટે કડક નીતિ આપણે દાખલ કરી છે, નીતિ દાખલ કરી છે પણ એનું અમલીકરણ કરવા માટે નિયત સાફ નથી અને નિયત જો સાફ હોય તો આ વસ્તુ આપણે કડક રીતે ડામી શકીએ એમ છીએ પણ કડક રીતે ડામી શકતા નથી. જેમ હમણાં કહેવામાં આવ્યું કે જ્યાં જ્યાં સારી પોસ્ટો છે ત્યાં આવવા માટે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ, ડી. એસ.પી. અને આઈ.જી. કક્ષાના અધિકારીઓ લાઈનમાં હોય છે સરકારમાં કે અમારી નિમણૂક અને અમારું પોસ્ટીંગ અહીં કરો એવી પરિસ્થિતિના નિર્માણને કારણે આજે દીવથી ગુજરાતમાં દારૂ ઠલવાય, દમણથી ઠલવાય, રાજસ્થાનથી ઠલવાય, આ બાજુ પૂર્વમાંથી સાબરકાંઠા વિસ્તારમાં બૉર્ડર ઉપરથી દારૂ ઠલવાય. આ વાસ્તવિકતા છે છતાં આપણે એમાંથી પસાર થઈએ છીએ જેની સામે કેસો કરવામાં આવ્યા છે અને એ દારૂનો પકડાયેલો માણસ કે એ વેચનાર માણસ જે સાચા બુટલેગર છે એનું નામ કયાંય રૅકૉર્ડ ઉપર આવતું નથી. એની જગ્યાએ ડમી નામ જે તે પોલીસ સ્ટેશનના પી. આઈ. અથવા જવાબદાર અધિકારીઓ ડમી નામ દાખલ કરી અને એના નામે એફ. આઈ. આર. ફાડે છે. મુખ્ય વ્યકિત, હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેંટ કયાંય નથી આવતું બુટલેગર તરીકે નામ તો જે કોઈ આખા રાજયમાં ગમે તાલુકાઓ જોવો વરલી મટકાનો ધંધો કરાનારો કે દારૂનો ધંધો કરનારને તમે લોકો ઓળખતા હોવ કે ફલાણો ભાઈ આ દારૂનો ધંધો કરે છે. આ પોલીસને જેટલો ખ્યાલ છે એટલો પ્રજાને ખ્યાલ છે. પોલીસ આ જાણે છે છતાં આપણે કડક હાથે કામ નથી લઈ શકતા. જે પકડાય એને પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ આવવામાં આવે, ૩ કલાકમાં જામીન ઉપર છૂટી જાય. કાર્યવાહી થાય અને ૨૪ કલાક એ માણસ જેલમાં પણ નથી રહેતો. એકને એક વ્યકિત વારંવાર પકડાય અને પછી રેકર્ડ ઉપર એફ. આઈ. આર.માં નામો આવ્યા પછી આવી વ્યકિત સામે આપણે કડક હાથે કેટલાની સામે કામો લીધા છે? કેટલા લોકોને પાસામાં લીધા છે આપણે? આપણી પાસે કાયદાઓ છે. કાયદાનો અમલ આપણે પૂરેપૂરો કરતા નથી અને જો પૂરેપૂરો કરવામાં આવે તો દારૂબંધીની નીતિને, રાજય સરકારની નીતિ છે એનું અમલીકરણ કરવાની આ રાજય સરકારની નિયત જો સાફ રાખી અને કામ કરે તો આવી જે સાંઠગાંઠ છે, પોલીસ વિભાગની સાંઠગાંઠ છે આમાં આ છાકટાવેડા શબ્દપ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે કે જે લોકો પીને છાકટાવેડા કરે અને એમની સામે આ પ્રકારનું અમલીકરણ કરવામાં આવે, છાકટાવેડા જાહેરમાં કરે એમને કંઈ નહીં અને બીજી જગ્યાએ જઈને જતા હોય તો એમાં છાકટાવેડા પીધેલા હોય તો કોઈપણ જાતની કંઈ પણ તકલીફ જ નથી થતી. મુશ્કેલી જ નથી થતી અને છતાં અહીં જાહેરમાં જ બધું થતું હોય . હું હમણાં એક દાખલો આપીશ. અમારા ઉનાની અંદર જે થયું એ માનનીય મંત્રીશ્રીના ધ્યાન ઉપર મૂકવા માગું છું કે દીવમાંથી દારૂ આવતો હતો, કસ્ટમના લોકોએ દારૂ પકડ્યો, એ દારૂના બુટલેગરોએ કસ્ટમના અધિકારીઓને બેરહેમ રીતે માર્યા અને એમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા. આ કયા પ્રકારની નીતિ છે? જાહેર રોડ ઉપર ઉનાથી દેલવાડા રોડ વચ્ચે કસ્ટમના અધિકારીઓને માર્યા, આપ તપાસ કરાવજો. એફ.આઈ. આર. દાખલ કરી છે. અને જે લોકોની સામે એફ.આઈ. આર.દાખલ

કરી છે એમાં મુખ્ય નામો તો હતા જ નહીં અને ૩ કલાકની અંદર છૂટીને પાછા ધરે આવ્યા. ખુલ્લમખુલ્લા આ પ્રકારની નીતિ જો ચાલુ રહેશે તો રાજયમાં ભવિષ્યની અંદર કેવી સ્થિતિ નિર્માણ થશે એની કલ્પના જ ન કરી શકીએ. કોંગ્રેસ કે ભા.જ.પ. એની બાજુ પર રાખીને એક સારા સમાજનું નિર્માણ કરવા માટે તમે સુધારા વિધેયક લઈને આવ્યા છો એનો વધારે કડક રીતે અમલ કરવા માટે પોલીસ અને રાજકીય કે જે કોઈ ચમરબંધી હોય એની સાંઠગાંઠ તોડી અને એની સામે કડકમાં કડક પગલાં ભરવામાં આવે તો એનો હેતુ બર આવશે.

શ્રી માધાભાઈ લા. બોરીચા (કેશોદ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહ રાજય મંત્રીશ્રી જે મુંબઈ નશાબંધી અધિનિયમ સુધારા કરતું વિધેયક લઈને આવ્યા છે એમાં મારા વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે અને આ સુધારાના સમર્થનમાં ઊભો થયો છું.

અધ્યક્ષશ્રી : બધાનું ધ્યાન દોરું છું કે સમગ્ર બિલની ઉપર ચર્ચા ન થાય. જે સુધારા કર્યા છે એ મુદ્દાની અંદર જ ચર્ચા થાય એ વધારે જરૂરી છે.

શ્રી માધાભાઈ લા. બોરીચા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વિષય, આ વાત રાજકીય વિવાદોથી પર હોવી જોઈએ. કારણ કે આપણા ગાંધીના ગુજરાતની અંદર અને ગુજરાત એક આદર્શ રાજય, ગુજરાત એક સુરેખ વહીવટ આપવામાં સફળ અને સમગ્ર ભારતમાં પ્રથમ સ્થાને, અવ્વલ મંજીલ તરફ જઈ રહ્યું છે ત્યારે એવા સંજોગોમાં સમાજમાં કેટલાક બૌધ્ધિકોએ, કેટલાક આવકવેરાના નિષ્ણાંતોએ આ સરકારને એવી સલાહો પણ આપી છે કે ગુજરાતની અંદર પ્રવાસનની સારામાં સારી તકો છે. ગુજરાતમાં પ્રવાસનનો વિકાસ કરવો હોય તો દારૂબંધી ઉઠાવી લેવી જોઈએ. આવો પણ એક મત પ્રબળ બની રહ્યો છે અને એવી લાગણી અહીં વ્યક્ત થયેલ છે. પરંતુ આ રાજય સરકાર ગરીબોની હામી છે. આ રાજય સરકાર દલિતોના વિકાસમાં, સમાજના દીન હીન પછાતવર્ગોમાં જ્યાં વ્યસન ઊંડે સુધી વ્યાપ્ત છે એ વ્યાપ્ત વ્યસનમાં આ સમાજના વંચિતો વધારે ખૂંપે નહિ અને સમાજને વધારે નુકસાન ન થાય એટલા માટે મહાત્મા ગાંધીજીના આદર્શોને એની મોટી કરોડો રૂપિયાની ટેક્સની આવક ગુમાવીને આ રાજય સરકારે દારૂબંધીનો અમલ સખત બનાવવા માટે પોતાની પ્રતિબધ્ધતા વ્યક્ત કરી છે ત્યારે આ નીતિને, આ કાયદાને વધારે સુસંગત અને ગુનેગારો ઉપર સખત તવાઈ ઉતરે એના માટેનો આ બિલમાં પ્રયાસ થયો છે. હું આ રાજયના ગૃહમંત્રીને અને સમગ્ર ગૃહ વિભાગને અભિનંદન આપું છું. આપણે તુલનાત્મક રીતે અભ્યાસ કરીએ તો કેફી દ્રવ્યોનું સેવન કરતાં લોકો માટે એની આયાત રાજયમાં દાણચોરીથી કે બીજી રીતે ભૂતકાળમાં થતી હતી અને અત્યારે પણ થતી હશે એમાં ઘટાડો થયો છે. સૌથી વધારે ગુનેગારોને જેલમાં મુકવામાં, સખત અટકાયતી પગલાઓ લેવામાં આ રાજય સરકારને સફળતા મળી છે. એટલું જ નહિ પરંતુ આ રાજય સરકારના વહીવટની અંદર આવ્યા પછીથી હું અભિનંદન આપીશ કે આ રાજયમાં એક પણ લઠ્ઠાકાંડ સર્જાવા પામ્યો નથી. મારા મિત્રોએ ટીકા કરી કે રાજય સરકાર આમાં નિષ્ફળ ગઈ છે. પણ જરા તુલનાત્મક રીતે વિચારીએ તો આ ગુજરાતમાં એવા અનેક કાયદાઓ છે કે જેને સમાજનું સમર્થન ન મળવાના કારણે આ કાયદાઓમાં આપણે ધારી સફળતા હાસલ કરી શક્યા નથી. ત્યારે આપણે આ વાતને પણ જો ગુજરાતનું હિત આપણા હૈયે હોય તો આપણે રાજકીય વિવાદોમાં નહિ પણ સામાજિક ચેતનાની અંદર, સામાજિક ચળવળના રૂપમાં આ દારૂબંધીનો અમલ સખત રીતે થાય એ રીતે સામાજિક સહયોગ એને મળે એ કરીશું તો વધારે સારું લાગશે. મારે ટીકાટિપ્પણ ન કરવી જોઈએ, પણ ભૂતકાળની વાત મારા મિત્રોએ કરી છે, ભૂતકાળમાં જે તે વખતના શાસકોના સમયમાં આ રાજયની અંદર દારૂબંધી અમલમાં હોવાછતાં પણ દ ણા બધા ગંભીર બનાવો બનતા. લઠ્ઠાકાંડ તો થતા પણ મેં સાંભળ્યું અને વાંચ્યું એ પ્રમાણે એક મંત્રીની કારમાં આ વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ થતી હતી. એની કારમાંથી નીકળી હતી, હથિયારો અને આ વસ્તુ, ત્યારે આપણે સૌ આ બિલને આવકારીએ. આ બિલ વધુ સખત બને. જ્યારે માનનીય મંત્રીશ્રી બિલ લઈને આવ્યા છે એને અનુમોદન આપીએ અને વાસ્તવિક રીતે આ દેશમાં, ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો અમલ થાય એ રીતે દિશાસૂચક બનીએ એ વાત સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું.

ડૉ. નીમાબેન બ. આચાર્ય (અંજાર): : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહમંત્રીશ્રી જે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૭- સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક લઈને આવ્યા છે એને ખરેખર હું અભિનંદન આપું છું કે, ગુજરાત સરકારે નશાબંધીના જે સામાજિક દુષણો આજના દિવસે મોટામાં મોટું બની રહે છે તેના માટે ચિંતા કરી છે અને આવું વિધેયક લઈને આવ્યા છે. સજા કોઈપણ ગુનાની અંદર કરવામાં આવે, એની જોગવાઈ કરવામાં આવે એ તો જરૂરી જ છે, કારણ કે, ડર વગર discipline આવતી નથી. પરંતુ જે જે સામાજિક દુષણો છે, વ્યસન પણ સામાજિક દુષણ છે, દહેજ પણ સામાજિક દુષણ છે આવા અનેક સામાજિક દુષણો આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈપણ દુષણ female foeticide સામાજિક દુષણ છે, અનેક કાયદાઓ પણ છે, કડક સજા પણ છે પણ આપણે જોઈએ છીએ અને એ આપણા માટે ચિંતાનો વિષય છે અને એટલા જ માટે આ બિલ અહીંયા રજૂ કર્યુ છે ત્યારે મારાં એક-બે સૂચનો છે.

કોઈપણ સામાજિક દુષણ આવે ત્યારે આ દારૂબંધીની અંદર, નશાબંધીની અંદર આના origin ક્યાં છે? ક્યાંથી દારૂ બને છે? દારૂ કોણ બનાવે છે? દારૂ કોણ વેચે છે? નશાયુકત પદાર્થ કોણ બનાવે છે? કોણ વેચે છે? ખરેખર જોવા જઈએ તો ગરીબ માણસોનું જ વધુ ને વધુ શોષણ થતું હોય છે, તેનું જ વધારે

exploitation થતું હોય છે. પૈસાદાર માણસો, ભણેલ-ગણેલ માણસો જેને દારૂની habit હોય છે, નશાની habit રાખતા હોય છે પણ એમને ખબર છે કે આરોગ્યને નુકસાન કરનાર છે. વારંવાર ડૉકટરના ચેકઅપ કરાવીને પરમિટ લઈને પ્રમાણસર શરીરને નુકસાન ના થાય એ રીતે એ લોકો તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. જ્યારે ગરીબ માણસને કાંઈ જ ખબર નથી, અજ્ઞાનતા છે અને એ લોકો તો આવી ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર જે દેશી દારૂના ભઠ્ઠા હોય છે એમાંથી દારૂ લઈને પીતા હોય છે અને પોતાની તબિયતને નુકસાન કરે છે અને સમાજને પણ નુકસાન કરે છે, કુટુંબ અને બાળકને પણ નુકસાન કરે છે. મારી દૃષ્ટિએ આ દારૂ જ્યાં બનતો હોય છે એમાં પણ ખાસ કરીને જે દેશીદારૂના ભઠ્ઠા ગામની અંદર ઝૂંપડપટ્ટીમાં આવે છે એ તાત્કાલિક બંધ થઈ જાય એવું precaution લઈને આપણે વિચારવું જોઈએ અને મારું એક સૂચન એવું પણ છે કે જે રીતે આપણે જી.ઈ.બી.માં ચોરી અટકાવવા માટે જેમ સેન્ટ્રલ લેવલની સ્કવોડ બનાવી છે એવી સૅન્ટર લેવલની સ્કવોડ જો આની અંદર દારૂ માટેની હોય અને જે અરજી આવે ફરિયાદની એ અરજી સીધી આ સ્કોડને મળે અને એ સ્કવોડ જ તાત્કાલિક તપાસ કરીને જેમ ઇન્કમટૅક્સની રેડ કવરબંધમાં જઈને એજ જગ્યાએ ખોલવાનું હોય અને ખબર પડે કે અહીંયા રેડ પડવાની છેકે કોઈને ખબર પણ ના પડે, આવી જાતની કાંઈ ફોર્મ્યુલા વિચારી એવી રીતે જો દારૂનાં ભઠ્ઠા બંધ કરવામાં આવે તો આ દુષણ દૂર થઈ શકે.

બીજું મારું સૂચન એવું પણ છે કે, આ પરમિટો આપવામાં આવે એ ખરેખર મારી દૃષ્ટિએ હેલ્થમાં કોઈ ડૉકટર એવું નથી કહેતા કે કોઈ માણસને દારૂની જરૂર છે અને દારૂથી તબિયત સુધરી જાય અને એના હાર્ટને બ્લડ સપ્લાય વધી જાય આવી કોઈ સૂચન, ડૉકટરનું આવું કોઈ prescription હોતું જ નથી કે આ વ્યકિતને દારૂ પીવાની જરૂર છે. ખરેખર તો પરમિટ પ્રથા પણ રદ કરવી જ જોઈએ અને પરમિટ આપવાની પ્રથા દૂર કરવામાં આવે તો લોકોની જે પણ તબિયતને નુકસાન કરે છે એ બંધ થાય.

ત્રીજું સૂચન એવું છે કે, જે લોકોને સજામાં તો કડક સુધારા કર્યા, સજા વધારી, દંડ વધાર્યો એ તો ઠીક છે પણ એથી વિશેષ એવું કરવું જોઈએ કે વ્યસન મુકિત સૅન્ટરો દરેકે દરેક તાલુકા અને મોટા શહેરોમાં કરવા જોઈએ અને જે કોઈ કેસ આવે દારૂનો, પોલીસ જેને પકડે તે સીધો જ વ્યસન મુકિત સૅન્ટરને રીફર કરે અને આવા આપણે કુટુંબ નિયોજન સલાહ કેન્દ્રો ચલાવીએ છીએ, કાઉન્સલિંગ સૅન્ટરો તો આવા જે કાઉન્સલિંગ સૅન્ટરો નશાબંધી મુકિત માટે કરવા જોઈએ કે જેથી કરીને એ સૅન્ટરોની અંદર એ લોકોને સમજાવવામાં આવે અને વારંવાર સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા કાઉન્સલિંગ કરવામાં આવે, સામાજિક જાગૃતિ ઊભી કરવામાં આવે, લોકોને સમાજ સેવાના કામમાં પણ જોડવામાં આવે તો આ રીતે મને લાગે છે કે આ દુષણને આપણે દૂર કરી શકીએ. આ રાજ્ય સરકાર માટે બહુ મોટો ચિંતાનો વિષય છે અને આ દુષણ દૂર થાય એના માટે જે કાંઈ સુધારાઓ અને સૂચનો આવે એનો અમલ કરવામાં આવે એવી મારી ખાસ વિનંતી છે.

શ્રી યોગેશભાઈ ના. પટેલ (રાવપુરા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહ રાજ્યમંત્રીશ્રી નશાબંધીનું બિલ લઈને આવ્યા છે એને હું અનુમોદન આપું છું અને મારા વિચારો પણ રજૂ કરું છું. જ્યારે ગુજરાતે આખા દેશમાં, આખી દુનિયામાં એકજ આ રાજ્ય એવું છે કે જયાં દારૂબંધી પાછી અમલમાં છે.

આજે જ્યારે આપણે સુધારા લઈને આવ્યા છીએ તો જે પેટા કલમ ૯૨માં જે દર્શાવ્યું છે કે કલમ ૮૫માં(૧) અને કલમ-૬૬માં(૧), આમાં સજા કરવાને બદલે સમાજસેવાની વાત કરી છે, બધા જ ધારાસભ્યોની લાગણી છે કે, જો રાજયમાં દારૂબંધીનો અમલ કરવો હોય તો કડકમાં કડક શિક્ષા થવી જોઈએ. મને એવું લાગે છે કે, દારૂબંધીને લીધે ગલીએ ગલીએ જે એન્ટી સોશિયલો, દારૂના જે અડ્ડા ચલાવે છે નાના છોકરાઓ પણ સંકળાયેલા હોય છે અને આનાથી એક ગૅન્ગ ઊભી થાય છે અને શહેરોમાં અને ગામડાઓમાં એક ગૅન્ગવોર ઊભી થાય છે આ બધાને દાબી દેવા માટે દારૂ વેચનારાને સખતમાં સખત સજા થવી જ જોઈએ એને સમાજની સેવાની કોઈપણ વ્યવસ્થા ઊભી ના થવા દેવી જોઈએ. કારણ કે, દારૂબંધીનો જો રાજયમાં આપણે અમલ કરતા હોઈએ અને એનાથી રાજયને બારસો કરોડ જેટલું નુકસાન થતું હોય અને ગાંધીજીના ગુજરાતમાં આપણે જો દારૂબંધીની વાત કરતા હોઈએ તો દારૂ વેચનારા પણ સજાને પાત્ર છે અને જો એને સમાજ સેવાની વાત કરીશું તો દારૂ વેચનારા તો આમેય છૂટી જતા હોય છે અને આ છૂટવાના એના કારણો ઊભા થશે, આ મારા વિચારો છે અને બીજું કે જે પોશ એરિયામાં મકાનોમાં બે-ત્રણ ફ્રીજ રાખીને પણ દારૂ રાખવામાં આવે છે આવી જગ્યાઓએ પણ દરોડા પાડી દારૂ જપ્ત કરવો જોઈએ અને રાજય મંત્રીશ્રી જે પણ વિચારો, જે પણ સુધારા લઈને આવ્યા છે એને હું મારો ટેકો આપું છું.

શ્રી વેચાતભાઈ હ. બારિયા (પાવી-જેતપુર): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહ રાજયમંત્રીશ્રી જે આ સુધારો લઈને આવ્યા છે એને મારું અનુમોદન આપું છું પણ સાથે સાથે ૬૬(૧)માં (ક) અને (ડ) એમાં તાડી ઉત્પન્ન કરતું કોઈપણ ઝાડ છેદે અથવા છેદવાની છૂટ આપે આનો પણ આ સમાવેશ શિક્ષામાં કરવામાં આવ્યો છે એની બાબતમા મારું એક મંતવ્ય રજૂ કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમારા પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તારમાં ખજૂરીના ઝાડ અને તાડના ઝાડમાંથી નીરો ઉત્પન્ન થતો હોય છે આજે પણ અમારા વિસ્તારોમાં તાડ અને નીરાનો ગોળ ઉત્પન્ન કરતી મંડળીઓ અમલમાં છે અને આ તાડી જે છેદવામાં આવે છે એ તાડી એ એવો પદાર્થ છે, તાડ અને ખજૂરીમાંથી જે રસ ઉત્પન્ન થાય છે એ

રસ બપોરના એક વાગ્યા સુધી એ નીરાનું સ્વરૂપ હોય છે એમાં મીઠાશ હોય છે એને ઉકાળીને ગોળ પેદા કરવામાં આવે છે એ નીરો પીવાથી એક આરોગ્યનું મોટામાં મોટું કારણ છે, મહાત્માગાંધીજીના અક્ષરદેહમાં પણ આપેલું છે પણ એ કલમ મને યાદ નથી એટલે ઉલ્લેખ નથી કરતો પણ એક વાગ્યા પછી બપોરના સમયે જ્યારે સૂર્યનો તડકો લાગતો હોય છે ત્યારે પછી એ નીરાનું પરિવર્તન તાડીમાં થાય છે. અહીંયા તાડીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે પણ તાડી જે વૃક્ષમાં નીરો પેદા થાય છે હવે છેદવાનું જો અટકાવવામાં આવશે તો આપણે આ વિધેયકના ભાગ ક , ડ ઉપરથી નીરાના ઉત્પાદનને આપણે અટકાવી શકીશું એનો આ એક અર્થ થાય છે. એટલે માનનીય મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરવા માગું છું કે, આ બાબતમાં આનું કાંઈ વ્યવસ્થિત અર્થઘટન કરવામાં આવે, માર્ગદર્શન કરવામાં આવે નહીં તો આ નીરો ઉત્પન્ન થતો જ બંધ થઈ જશે. આજે પણ ગોળનું ઉત્પાદન અમારે થાય છે અને ગામડા લેવલે આ ગોળ વપરાશમાં છે જે નીરામાંથી જ ગોળ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે એટલે જ મારું એક સૂચન છે કે, આ બાબતમાં પોલીસને જે નીરો ઉત્પાદન કરનારા લોકો ઉપર અત્યાચાર કરવાની એક મોટામાં મોટી છૂટ મળી જશે અને નશાબંધીની બાબતમાં જે મોટા દારુના ઉત્પાદન કેન્દ્રો ઉપર પગલા લેવા જોઈએ અને દારૂબંધીનો કડકમાં કડક અમલ કરવો જોઈએ, એ ન કરી, જે નીરો ઉત્પાદન કરતા ગરીબ માણસો છે એના ઉપર આ લોકો અત્યાચાર કરશે, એના ઉપર વધુમાં વધુ કેસો કરશે એટલે આનાથી ગરીબ માણસો જે છે, નીરો પેદા કરશે એ તકલીફમાં મૂકાઈ જશે એવી વાત છે. સન્માનીય ગૃહને મારી વિનંતી છે કે આ બાબતમાં પણ બધા વિચાર કરે, દારૂબંધીનો અમલ થવો જ જોઈએ, ગરીબ માણસોને દારૂના આ વ્યસનથી ખૂબ જ નુકસાન થાય છે એ સુવિદિત વાત છે પણ આ તાડી અંગે અને નીરા અંગેની, નીરા માટેની છૂટછાટ હોવી જોઈએ, બપોરના એક વાગ્યા પછી જે નીરાનું રૂપાંતર તાડીમાં થાય છે, એ તાડી ના વેચાવી જોઈએ એના માટે કડક અમલ થવો જોઈએ. એના માટે કડક અમલ થવો જોઈએ. તાડીનો વ્યસન તરીકે પ્રયોગ ન થાય એ જોવાની જવાબદારી આપણી છે જ. પણ તાડીને અટકાવવા નીરોનું ઉત્પાદન અટકાવી દેવામાં આવે એ જોખમકારક બનશે આટલી મારી વાત છે.

શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ (લીંબડી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં પોલીસમાં ૧૩ વર્ષ નોકરી કરી છે એમાં ઘણા અનુભવો થયા છે. એમાં આ સુધારા બીલ નશાબંધી બાબત લઈને આવ્યા છે. નશાબંધી અને પોલીસ એ બે એક જ વિભાગમાંથી જુદા પડેલા છે. હું તો માનું છું કે સરકારને આ મોટું દેવું ઊભું થયેલું છે. પોલીસ કોઈને પણ દારૂયુકત પકડે કે નશાયુકત પકડે એટલે પોલીસ સ્ટેશને લઈ જાય છે. પોલીસની કામગીરી ચાલુ રહે છે. નશાબંધીવાળા, પોલીસવાળા કોને લાવીને મૂકે છે જે હપતા ન આપતા હોય. પોલીસમાં કોનું પોષ્ટીંગ થાય છે જેને સારા ઈનામો હોય, સારી કામગીરી હોય એનું નહીં. હોમ મિનિસ્ટરનો લૅટર આવે, એનું પોષ્ટીંગ થાય. હું આંધ્રપ્રદેશ ગયો હતો ત્યાંના અધિકારી નશાબંધીમાંથી નિવૃત્ત થયેલા છે. ત્યાં એમણે ગુજરાત ભવન લખ્યું છે. ભવાનભાઈ, નશાબંધીમાં નોકરી કરી એટલે ગુજરાત ભવન, દારુના પૈસા મળ્યા એટલે બનાવ્યું. રાજયની બહારના આઈ.પી.એસ. અધિકારીઓ અઢળક ગુજરાતના આઈ.પી.એસ.ને અન્યાય કરે છે. *(xxx) હું તો ચા, પાન, બીડી, સિગરેટ પીતો નથી. (xxx)

શ્રી અશોક ભટ્ટ : સાહેબ, આ ના ચાલે. એમણે વિસ્તાર કહ્યો છે, (xxx) કહ્યું છે.

શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ : હું નામ નથી બોલ્યો સાહેબ.

અધ્યક્ષશ્રી : તમે બેસો. (xxx) બોલ્યા છો, એટલે પાછા ખેંચી લો તેમ નહીં, એ શબ્દોને રદ કરવામાં આવે છે.

શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ : આજની તારીખમાં ૧૨-૧૨-૨૦૦૨ ના રોજ ઈલેકશન આવેલું એમાં લીમડી શહેરની વસ્તીએ મને કહેલું કે અમારી ગલી કૂંચીએ, વાણિયા બ્રાહ્મણની સોસાયટી પાસે દારૂ વેચાય છે. આ દારૂ જો તમે બંધ કરાવો તો વોટ આપીએ અને લોકોએ વોટ આપ્યા. હું તો ના ગામ, ના ઠામ, ના કોઈ માણસને ઓળખું છતાં પણ ૨૨૦૦૦ વોટથી ચૂંટાયો સામેની વ્યકિત કરતાં વધારે. આજની તારીખમાં સો કાગળો લખ્યા છે છતાં દારૂ બંધ થતો નથી. ચાર અધિકારીઓ સસ્પૅન્ડ થયા છે. એક રીબેરો ડાયરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ આજથી ૨૦ વર્ષ પહેલા અમદાવાદમાં એમનું પોષ્ટીંગ થયેલું એમણે એવું કર્યું કે પોલીસ ચોકીના પી.આઈ. પાસે એવું લખાણ કરાવ્યું કે ૧૦૦૦૦ થી વધારે કિંમતનો દારૂ પકડાશે તો તેમને સસ્પૅન્ડ કરવામાં આવશે. પી.આઈ. પાસેથી ડી.એસ.પી.એ, ડી.એસ.પી. પાસેથી આઈ.જી. પી. અને આઈ.જી.પી. પાસેથી ડી.જી.એ લખાવી લીધું. હું માનું છું કે ૪-૫ પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પૅન્ડ થયેલા પણ દારૂ વેચાતો નહોતો. આજે દારૂ બંધ કરવો હોય તો દારૂની ફેકટરીથી રાજસ્થાન, એમ.પી., યુ.પી. સુધીના હપતા હોય, (XXX) તો મારું સજેશન છે કે આ રીતે કામ લેવામાં આવે તો દારૂ ન વેચાય...અંતરાય..

શ્રી અશોક ભટ્ટ : (XXX) સુધી વાત કરે છે, આક્ષેપ કરવાની, ગમેતેમ બોલવાની છૂટ કેવી રીતે મળે?

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : આક્ષેપ નથી કર્યા એમણે.

---

* (XXX) આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : એમને શિખવાડો, ગૃહની અંદર ધારાસભ્ય તરીકે બોલે છે. પોલીસ ખાતાના અનુભવો કહેવા માટે ગૃહ નથી.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : એમણે પોતાના અનુભવ કીધા છે. બંધબેસતી પાઘડી પહેરવી ન જોઈએ. એમને પોતાના વખતના અનુભવ કહેવાની પણ છૂટ નથી?

શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ : હું સજેશન આપું છું કે રીબેરો લાવ્યા એ રીતે.. અંતરાય.. ઘોંઘાટ..એ રીતે હોમ મિનિસ્ટર લાવે અને દારૂબંધી થાય તો હું રાજીનામુ મૂકી દઉં. આઈ.જી. સુધીની સાંઠગાંઠ ક્યારે હોય જ્યારે સરકારની નીતિ ઢીલી હોય, (XXX)

અધ્યક્ષશ્રી : પ્લીઝ, હું તમને બેસાડી દઈશ. (અંતરાય) ભવાનભાઈ, તમે ગૃહના સભ્ય છો, નિયમની ખબર હોવી જોઈએ, જ્યારે હું ઊભો હોઉં ત્યારે બેસી જવું પડે, નહિતર બહાર કાઢવા પડશે. (XXX) એવું નહિ બોલવું જોઈએ. સીધો આક્ષેપ ન કરવો જોઈએ. આ શબ્દો રેકર્ડમાં છે તે દૂર કરવામાં આવે.

શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારું સજેશન છે મારા કોઈના ઉપર આક્ષેપ નથી. જે રીતે રીબેરો સાહેબ કાયદો કરતા હતા. એવી આજની તારીખમાં અધિકારીઓની જે સાંઠગાંઠ છે તે બંધ કરાવો. પી.એસ.આઈ. પાસેથી પી.આઈ. સાહેબ લખાણ લે અને દારૂ બંધ થઈ જાય અને નશાબંધી નાબૂદ કરી નાખવી જોઈએ. પોલીસમાં મિક્સ કરી દેવું જોઈએ અને અધિકારીઓના ખોટા પગારો ચઢે છે. કેટલાક અધિકારીઓ આ બાબતમાં સસ્પેન્ડ થાય છે, તો આ બધું દૂષણ બંધ કરાવો એવું મારું સજેશન છે.

શ્રી હેમાજી દ. રાજપૂત (વાવ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નશાબંધી અંગેની જે ચર્ચા થતી હતી, એમાં અમારા ધારાસભ્યશ્રી કઈક બોલ્યા તો બધા ઊભા થઈ ગયા. ઈશ્વરની સાક્ષીએ વાત કરો. આબુરોડથી રોજની ૧૦૦ ગાડી ચાલે છે, જો એ ગૃહમંત્રીને ખબર હોય તો સોગંદ ખાય. હપ્તો છે. હપ્તો નહિ તો બીજું શું? આ બિલ લાવ્યા સારું કર્યુ. શું સારું કર્યુ? શરમાવો. નશાબંધી કઈ રીતે અને કઈ રીતે આખું પોલીસ ખાતું. દારૂવાળાને પાસામાં મોકલે અને પાસામાં જઈને આવે, એટલે ડી.એસ.પી. બોલાવે કે ભાઈ તમે કેમ બેઠા છો? ચાલુ કરો. અધિકારીઓ સાથે રહીને આમ કરે. આમ, ભગવાનની શાક્ષીએ કહું છું. તમે બધા જ જાણો છો, સામાવાળાને આ બધા. ગૃહમંત્રી આખોય ગુજરાતનો ઈતિહાસ જાણે છે. દારૂ વિષેનું આ બિલ લઈને આવ્યા છે. અમારી બાજુમાં રાજસ્થાન ૧૦ કિ.મી. છે, રોજની ૧૦૦ ગાડી ધોળે દિવસે ગાડી આવે. સરપંચ છે અમારો. દારૂ કોને વેચવા જવું. મને પોલીસના દીકરાએ કહ્યું તમારા વેવાઈ છે, એને ના પાડો. આ તમારો ધંધો બંધ કરાવશે. આમાં અમને નુકસાન પડે છે, સાહેબ. જગજાહેર ધંધો થઈ ગયો છે. પોલીસ ખાતું છે. જે ગૃહમંત્રી આખો ઈતિહાસ જાણે છે. હપ્તા એટલે કેવા હપ્તા. આબુરોડની એક વ્યકિત ૫૦ લાખ મહિને આપે છે. તેની ગાડી પકડવાની કોઈની તાકાત નથી. મંત્રીશ્રી અજાણ હોય તો સોગંદ ખાય. સાહેબ શરમાવવા જેવી વાત છે. જો ગાંધીજીનું નામ લેતા હોય, ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે ચાલવા માગતા હોય તો દારૂ બંધ કરાવો તો પોલીસ ખાતું કડક કરવું પડશે. પણ શું થાય. ગુજરાતનો એવો કોઈ ખૂણો નથી કે જ્યાં આગળ દારૂના હપ્તા ન લેવાતા હોય. બનાસકાંઠાથી ગાંધીનગર તરફ અને ગાંધીનગરથી બનાસકાંઠા તરફ રોજની ૧૦૦ ગાડી આબુરોડ પર સો ગાડી નામજોગ કહેવા માગું છું. ફલાણાની ગાડી અને માનનીય હરજીવનભાઈ સોગંદ ખાઈને કહે. માનનીય મંત્રીશ્રી મહેરબાની કરીને દેશનું પતન ન કરો. સત્તા લોકોએ આપી છે તો તેનો સદ્દુપયોગ કરો. લોકોનું નિકંદન નીકળી જાય છે. દારૂ ગંભીર બાબત છે. આપણે શા માટે તેને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. કડકાઈથી દારૂબંધીનો અમલ ન કરો તો શું કામ ટેક્ષ ખોવો છો. છૂટી આપી દો. કોઈ ફરિયાદ કરતું નથી. આ બહું ગંભીર બાબત છે. તમને શરમાવવું જોઈએ, મંત્રીમંડળના સભ્યો પણ જોઈ રહયા છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય હેમાભાઈ માઈકનો ઉપયોગ કરો.

શ્રી હેમાજી દ. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીને રીકવેસ્ટ કરું છું આ લોકોને બંધ કરો. જે નસીબમાં હશે તે આવશે. પણ હપ્તા લેવાનું છોડી દો.

શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે (ડાંગ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી જે વિધેયક લઈને આવ્યા છે તેમાં ઘણી ચર્ચાઓ થઈ છે. વ્યસન મુકિત અને દારૂ મુકિત બંધ થવી જોઈએ. આ ગૃહની અંદર આપણે વર્ષોથી આની ચર્ચા કરતા આવ્યા છીએ. આજે આપણા દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રીને અને આ ગૃહમાં બેઠેલા માનનીય સભ્યશ્રીઓને વિનંતી કરવા માગુ છું કે વ્યસન મુકિત, દારૂ મુકિત, તાડી મુકિતની વાત કરીએ છીએ તેમાં ગૃહમાં બેઠેલા કેટલા મિત્રો છે તે ૬.૪૫ પછી નથી લેતા. આ દારૂબંધી કયારે થશે કે જયારે સંત પૂજય મોરારીબાપુ, સત્ય સાંઈબાબા જેવા અનેક સંતો છે અને તેમના દ્વારા અને અમારે ત્યાં આદિવાસી વિસ્તારમાં હું આપને આમંત્રણ આપું છું મારા ડાંગ વિસ્તારમાં, આદિવાસી વિસ્તારમાં જયો ૮૦ ટકા લોકો દારૂ પીતા હતા. આજે ૮૦ ટકા લોકો સંતના સત્સંગથી વ્યસન મુકત બન્યા છે. કાયદાથી નહીં. હું દાખલો આપી શકીશ કે દરેક લોકો દારૂ ન પીતા હોય તો દારૂ પાવામાં, દારૂનો વેપાર કરવામાં પોલીસ મદદ કરે છે. અમારે ત્યાં નાસિકથી દારૂ આવે છે, નવાપુરથી દારૂ આવે છે અને મહારાષ્ટ્રના દમણથી દારૂ આવે છે. અમારે ત્યાં લોકોએ દારૂ બંધ કરી દીધો છે. મોક્ષમાર્ગી સત્સંગ દ્વારા દારૂ બંધ કરી દીધો છે ત્યારે ડી.એસ.પી. કહે કે ભાઈ કેમ બંધ કરી દીધો? શા માટે દારૂ બંધ કરી દીધો. આ સરકારે આજથી સો વર્ષ પહેલાંની વાત દાખલા સાથે આપીશ. આપના

દ્વારા મારી સરકારને વિનંતી છે કે સાહેબ આજે પૂજય મોરારીબાપુ જેવા સંતો છે તેવા લોકોના સત્સંગથી દારૂ મુકિત થાય છે. કાયદાથી નહી. આજે લાખો રૂપિયાના હપ્તા લેવાય છે. અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ કોઈના નામ નથી દેતો. ચૂંટણી આવે ત્યારે કહે કે તમારે ત્યાં ખોખા આવી ગયા, આ ખોખા આપવાનું બંધ કરો. અમે તો નથી આપતા. પીતા પણ નથી અને આપતા પણ નથી. આ ખોખા અને કવાટરીયા આપવાનું બંધ કરો. લોકશાહીની રીતે પૂજય મહાત્મા ગાંધીના ગુજરાતની અંદર લોકશાહીની લાગણી કેળવતા હોવ તો લોકોમાં જાઓ. લોકોને કહો કે આ વ્યસનથી આ નુકસાન થાય છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અમિતભાઈ શાહ અમારા ડાંગ જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી છે. એમને ખબર છે. આજથી દસ પંદર વર્ષ પહેલાંની પરિસ્થિતિ શું હતી. આજે અમે દર વર્ષે મહાન સંતોને બોલાવીને ભાગવત સપ્તાહ બેસાડીને સત્સંગ કરાવીએ છીએ. તેના દ્વારા, સંત દ્વારા, સંતવાણી દ્વારા અમારા આદિવાસીઓમાં ફેર પડયો છે. અમારા આદિવાસીઓમાં કહેવત છે કે, ઊંચ તે નીચ, ને નીચ તે ઊંચ, આજે તો બ્રાહ્મણ દ્વારા એ પીતા થયા અને અમારા આદિવાસીઓ પીલા કરતા થયા એટલે ટીકા કરતા થયા, આ પરિસ્થિતિ આજે થઈ ગઈ છે એટલે માત્ર ગૃહમાં જે કાયદો કરીએ છીએ એ કાયદાનો અમલ પહેલાં અહીંયાં ગૃહમાં બેઠેલા મિત્રો છે એ કરે અને પછી આપણે લોકોની ટીકાઓ કરીએ. અધિકારીઓને આપણે હાથા બનાવીએ છીએ, પોલીસ ઉપર આક્ષેપ કરીએ, પણ મારે એક દાખલો આપવો છે કે, દમણમાં દારૂ બને અને આપણા નેતાઓ એમ કહે કે , ભાઈ ચૂંટણી આવે છે કેટલા બૉક્સ ઉતારશો? એટલે અમુક જે પોલિંગ ઑફિસર હોય, પોલિંગ એજન્ટ હોય એ કહે કે ફલાણાના ત્યાં દશ બૉક્સ ઉતારજો, તો આ જે બૉક્સ ઉતારવાનું છે એ બંધ થાય તો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે, આ પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીના ગુજરાતમાં દારૂ બંધ થશે પણ ગૃહમાં બેઠેલા મિત્રોને બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના છે કે, પહેલાં તમે બંધ કરો અને ૬.૪૫ પછી જાત જાતના બ્રાન્ડ જે આવે છે, મને ખાતરી છે અને આજે પણ એમ કહું કે કયાં કયાં મળે તો એમને કદાચ નક્કી કરેલા જ હોય કે છગનભાઈ બે બૉક્સ લાવજો અને મગનભાઈ બે ચાર બૉક્સ લાવજો, આ બ્રાન્ડ લાવજો, આ બ્રાન્ડ આપણે તો કરીએ છીએ આ ગૃહની અંદર કહે છે કે સત્યમાં જય થશે, નહીં તો માત્રને માત્ર આ ચર્ચા કરવા સિવાય બીજું કંઈ દારૂબંધી થતી હતી, આજે મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ, મહારાષ્ટ્રની બાઉન્ડ્રીમાં હું છું. મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ તો કોઈ દિવસે કોઈ પણ આદિવાસી કે કોઈપણ માણસ દારૂપીને લથડતો દેખાશે નહીં. કોઈપણ દિવસ નહીં દેખાય અને મોટા લોકો હોય એ ફાઈવ સ્ટાર હોટલોમાં અહીયાં ગુજરાતમાંથી જાય, મોજ મજા કરવા એ લથડતા દેખાય, આ ગાંધીજીના ગુજરાતમાં સાંજે નીકળીએ ત્યારે આદિવાસીઓને બદનામ કરવાનું કામ, ગરીબ લોકોને બદનામ કરવાનું કામ થઈ રહ્યું છે,અને દારૂમાં ગોળ, અમારા મિત્રોએ કહ્યું કે હવે તો નવસારો વાપરતા નથી, હવે બૅટરીના પાવર વાપરવામાં આવે છે, અહીયાં કોને શીખવવાનું છે?

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમારા ત્યાં એક મિત્રએ એમ કહ્યું કે, આમના ડાંગીભાઈઓ ઈસા સાંગતા હા કાઈ દારૂ પેવલા તો નવસારા ટાકુલા નીહી પણ બૅટરીના પાવર ટાકેલા તો પોટના આંતડાયા બગડ તાહા તો દારૂ પેવલા વેટ આહા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દારૂમાં બૅટરીના પાવર નાખવાથી તો આંતરડા કહોવાઈ જાય છે, આ દશા જે થઈ છે એટલે મારે આપના દ્વારા કહેવું છે કે, આ સરકાર રામભકત કહેનારી છે, આ સરકાર એમ કહે છે કે, અમે ગામેગામ મંદિરો બંધાવીશું, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી આપશ્રી દ્વારા આ સરકારને અને માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી છે કે, તમે માત્ર ભગવી વાત ન કરો, રાજકીય વાત ન કરો પણ જો દારૂબંધી કરાવવી હોય તો એક વખત અમારા એક વિસ્તારની અંદર મોરારીબાપુએ કહેલું, અમારા આહવામાં જ્યારે આવેલા ત્યારે કે ગુજરાતના ગૃહની અંદર જો મને એક દિવસ બેસાડે તો ગુજરાતમાં જે ૧૮૨ બેઠા છે તેઓને હું સત્સંગ કરી આપું અને એટલું જ્ઞાન આપું, આ વાત છે આ વાત પૂજ્ય મોરારીબાપુએ કરેલી, તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ રીતે મારી વિનંતી છે માનનીય અમીત સાહેબને કે આ બાબતે કંઈક વિચારે અને આ દારૂબંધીના વિરોધી કાયદા ગુજરાતમાં સદંતર બંધ કરે અને દારૂબંધી કાયમ રહેવી જ જોઈએ એવી મારી ખાતરી અને વિનંતી છે.

શ્રી અમિત અ. શાહ (રાજય કક્ષાના નશાબંધી અને આબકારીમંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બિલ ઉપર બધા જ માનનીય વિરોધ પક્ષના નેતાથી માંડીને છેલ્લે વિરોધ પક્ષના ઉપનેતા સુધી બધા જ સભ્યશ્રીઓએ પોત પોતાના મંતવ્યો વ્યકત કર્યા છે અને હું એક ચીતથી બધા જ મંતવ્યો સાંભળતો હતો એટલે મારી સમગ્ર ગૃહને વિનંતી છે કે, મારે વધારે નથી બોલવું પણ હું જેટલો સમય બોલું એટલીવાર શાંતિથી સાંભળે. એનું કારણ એવું છે કે, આ જે વિધેયકની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એ વિધેયકનો હાર્દ ઘણાં બધા લોકોએ સમજયા વગર અહીંયા ટેબલ ઉપર વાત કરી છે એટલે મારે કેટલીક સ્પષ્ટતા કરવી છે. વિરોધ પક્ષમાં દેખીતી રીતે જ ભાગલા દેખાતા હતા. કોઈએ સાધુ-સંતોને છૂટ આપવાની વાત કરી તો કોઈએ પોસના ડોડાની વાત કરી. માનનીય વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીએ પૈસાપાત્ર લોકો પુરતો વાંધો નથી એવું કહીને હીમાયત કરી. (અંતરાય)

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને ખોટો કોટ કરે છે. મને ખોટા કોટ ન કરો.

શ્રી અમિત અ. શાહ : શબ્દો પૂછી લો એમણે એમ કહ્યું છે. હું મારી જગ્યા ઉપર ઉભો રહીને બોલી રહ્યો છું. (અંતરાય) કાલે પ્રીન્ટ મંગાવીને જોઈ લેજો હું બહુ જવાબદારીપૂર્વક કહું છું.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને ખોટો કોટ કરવામાં આવે છે હું જે બોલ્યો છું એમાં કોઈને છૂટ આપવાની વાત કરી નથી.

શ્રી અમિત અ. શાહ : મેં સાંભળ્યું છે. આક્ષેપ કરતા હતા ત્યારે હું વચ્ચે ઉભો નથી થયો. તમે આક્ષેપ કરો ત્યારે અમારે સાંભળવાના અને જયારે જવાબ આપીએ ત્યારે વચ્ચે ઉભા થઈને ડીસ્ટર્બ કરવાના એ રીતની વાત નહીં ચાલે. (અંતરાય) વિરોધ પક્ષના નેતા જવાબદાર વ્યકિત હોય તો હું પણ ગૃહમાં જવાબદાર વ્યકિત છું.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને ખોટો કોટ કરવામાં આવે છે. મેં તો માત્ર એમ કહ્યું કે જે ઉદ્દેશો છે દારુબંધીના એ જે નીચલો વર્ગ છે એના પૈસા છે એ દારુમાં ન જાય, એની જિંદગી ખલાસ ન થઈ જાય એટલા માટે થઈને આપણે કરોડો રૂપિયાની આવક ગુમાવીએ છીએ અને આ દારુબંધીનો જે સુધારો લઈ આવ્યા છીએ એનાથી તમે આવક મેળવતા નથી અને આડકતરી રીતે દારુની છૂટ આપો છો એટલે મેં એના કારણે વિરોધ કરેલ છે. માટે મેં તો ગરીબ વર્ગની ચિંતા કરેલ છે. હું ઉપલા વર્ગને દારુ પીવાની છૂટ આપો એમ વાત નથી કરતો. ઉપલા વર્ગની હું બહું ચિંતા નથી કરતો. ચિંતા કરું છું એ જે અમારા જગદીશભાઈએ વાત કરી, અમારા પ્રવીણભાઈએ વાત કરી, પુંજાભાઈએ વાત કરી કે આ ગરીબ વર્ગના માણસોને જે એના બાળકોના પેટમાં દૂધ આપવાની વાત છે એ દૂધ નહીં મળે અને એને આડકતરી રીતે દારુ પીવડાવવાનું પ્રોત્સાહન આપો છો એ વાત મેં કરી છે. એટલે અમીતભાઈની વાત છે એની સાથે હું સંમત થતો નથી.

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક વાતની બહુ મક્કમતાપૂર્વક સ્પષ્ટતા કરવા માગું છું કે આ સરકાર નશાબંધીની નીતિને એટલી જ મજબૂતાઈથી વળગી રહી છે જેટલી મજબૂતાઈથી લાગુ કરવા માગે છે. એને ડાઈલ્યુટ કરવાની વાત અથવા એમાં છૂટછાટ આપવાનો વિચાર પણ આ સરકારના નીતિ-નિર્ધારણ કરવાવાળા લોકોના મનમાં આવી જ ન શકે. એનું કારણ એ છે કે અમને ખબર છે અમે વિરોધ પક્ષમાં વર્ષો સુધી રહ્યા છીએ, નીચેના ગામડાના તળના માણસોના સંપર્કમાં રહ્યા છીએ, અમારા કાર્યકર્તાઓએ વર્ષો સુધી ગરીબોની વેદનાને સમજી છે. આ મધ્ય ગુજરાતમાં દારુ પીવા માટે ડાંગરનું ધરું વેચીને જયારે પુરુષ ઘરમાં આવે ત્યારે સ્ત્રીની હાલત કેવી થાય, બાળકોની હાલત કેવી થાય એની વેદના અમને ખબર છે. બીજા કોઈને ખબર ન હોય એ લોકો આજે ડાઈલ્યુટ કરવાની વાત કરી શકે અમે ન કરી શકીએ. જે લોકો આક્ષેપ કરે છે, ભવાનભાઈએ કહ્યું કે હપતા લેવાય છે, છેક સુધી લેવાય છે. ભવાનભાઈ એ તો તમે નોકરી કરતા હતા એ વખતની વાત છે અને એ વખતે કોનું શાસન હતું એ તમને ખબર છે? તમને ખબર છે, કોનું શાસન હતું ? એમણે કહ્યું કે 'હું મારા જાત અનુભવની વાત કરું છું.' (અંતરાય) બેસો ભવાનભાઈ, મને સાંભળો. ઉશ્કેરાટથી ગૃહમાં વાત ન થાય. પોતાની વાત નિયમો મુજબ અને મક્કમતાથી મુકવી પડે. એમણે જાતે કહ્યું છે. એ શબ્દો જોવા હોય તો જોઈ લે. 'હું મારા સ્વાનુભવની વાત કરું છું' એમ કહ્યું છે. 'સ્વાનુભવની વાત કરું છું જયારે હું આટલા વર્ષો પોલીસમાં હતો ત્યારની વાત કરું છું' એવું એમણે કહ્યું છે. એ વખતે કોનું શાસન હતું એ એમને ખબર હોવી જોઈએ. એ વખતે ભારતીય જનતા પક્ષનું શાસન ન હતું આ રાજયમાં. જયારે ભવાનભાઈ નોકરી કરતા હતા એ વખતે આ રાજયમાં ભારતીય જનતા પક્ષનું શાસન ન હતું. (અંતરાય) હું રેકર્ડ ઉપરની વાત કરું છું. આપ બેસો ભવાનભાઈ. સાહેબ, મને રક્ષણ આપવું જોઈએ. મેં બધાને શાંતિથી સાંભળ્યા છે. (અંતરાય) સાહેબ, હું આજે આ ગૃહની અંદર રેકર્ડ સિવાયની કોઈ વાત કહેવા માગતો નથી. મેં ભવાનભાઈને કહ્યું એમણે બોલેલા શબ્દો અને એમના સમયની એમણે વાત કરી છે અને બીજી વાત આ વિરોધપક્ષની પાટલી પરથી જે લોકો અમને શિખામણ આપે છે એમને મારે કહેવું છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અહીંયા આવ્યા પછી આ રાજ્યની અંદર એકપણ લઠ્ઠાકાંડ થતા નથી, જે પહેલાં છાશવારે થતા હતા, એ વખતે કોણ સત્તા પર હતું? કોણ નશાબંધીનો અમલ નહોતું કરાવતું? આ રેકર્ડ પરની વાત કહું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી આ રાજયની અંદર એકપણ લઠ્ઠાકાંડ નથી થયો. આ રાજ્યનો એકપણ નાગરિક ઝેરી દારૂ પીને નથી મર્યો. ગરીબોની વાત કરો છો, તમારા સમયની અંદર આ રાજ્યની અંદર છાશવારે ગરીબો ઝેરી દારૂ પીને મરી જતા હતા. અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાજ્ય સરકાર આવી પછી આ નથી થયું. એમના શાસનની અંદર આ થયું છે. આક્ષેપો કરવા સહેલા છે, પણ સાચી વાત સાંભળવાની આવે ત્યારે તમતમાટ થાય છે. (અંતરાય) ભવાનભાઈ બેસો (અંતરાય) સાહેબ હું એક અક્ષર વચ્ચે બોલ્યો નથી. આપ યાદ રાખો એવી મારી વિનંતી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : પ્લીઝ બેસો, પરેશભાઈ બેસો.

શ્રી અમિત અ. શાહ: સાહેબ, એક સભ્યશ્રીએ વિરોધપક્ષની બેન્ચ પરથી કહ્યું કે આ ગૃહના કેટલા સભ્યો જોડે દારૂ પીવાની પરમીટ છે? ભા.જ.પ.ના એકપણ સભ્ય જોડે પરમીટ નથી. આપ પરમીશન આપો તો બાકીનાની તપાસ કરાવડાવું? ભા.જ.પ.ના એકપણ સભ્ય જોડે નથી. બાકીનાની આપ મંજૂરી આપો તો હું તપાસ કરાવું કે કોની જોડે છે? બાકી ભા.જ. પ.ના એકપણ સભ્ય જોડે પરમીટ નથી.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીને આપના દ્વારા ચેલેન્જ છે કે તમે રેકોર્ડ મૂકો કોના સભ્યો દારૂ પીધેલા પકડાયા છે, કોના સભ્યો દારૂ વેચતા પકડાયા છે, રેકર્ડ પર માગું છું હું તમને ખુલ્લી ચેલેન્જ માગું છું. રેકોર્ડ પર મૂકો, મારી માગણી છે. કેટલા પકડાયા છે એની વિગત મૂકો..

અધ્યક્ષશ્રી : પ્લીઝ બેસો, પ્લીઝ બેસો બેસો.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રેકોર્ડ પર મૂકે તો દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય સભ્યશ્રીઓ મેં શરૂઆતથી જ વાત કરી છે કે, દારૂબંધીનો વિષય ગુજરાત માટે અતિગંભીર છે, આપણને સૌને એની ચિંતા છે. એકબીજા પર આક્ષેપોની વાત કર્યા સિવાય આ પ્રશ્ન માટે આપસૌ વિચાર કરો એવી મારી વિનંતી છે. માનનીય મંત્રીશ્રી આપ પણ દારૂબંધી માટે સીધી વાત કરો એવી વિનંતી છે.

શ્રી અમિત અ. શાહ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું કોઈની સામે આક્ષેપો કરવા માગતો નથી, પરંતુ જે આક્ષેપો રેકોર્ડ પર મૂક્યા છે અને જે સત્યથી વેગળા છે એનો હું જો ગૃહના રેકોર્ડ પર જવાબ ના મૂકું તો હું ચોક્કસ માનું છું કે હું મારી ફરજ ચૂક્યો છું, એટલા માટે એમણે જે વસ્તુનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એટલા પૂરતો જ હું મારો જવાબ આપું છું, મારે ભૂતકાળના કોઈ ક્વોટેશન નથી કરવા, પરંતુ એ લોકો બોલતા હોય અને આક્ષેપો કરતા હોય વિરોધપક્ષના નેતાની ફરજ હતી કે વિધેયકની ચર્ચા વિષય પર મર્યાદિત રાખવી જોઈતી હતી, એમના સભ્યોને એમણે ટપારવા જોઈતા હતા અને એમણે એમના સભ્યોને ટપાર્યા નહિ, શિસ્તમાં રાખ્યા નહિ અને પછી જેમ તેમ આક્ષેપો કર્યા હોય તો જવાબ સાંભળવાની એમણે તૈયારી રાખવી પડે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપની અપીલ છે એટલે હું કોઈ વધારે રાજકીય અવલોકનો કરવા માગતો નથી, વિષય પર આવું છું આ વિધેયકની અંદર હું એટલું કહેવા માગું છું કે, દારૂબંધીને અમે કોઈપણ પ્રકારે ચલાવવા માગતા નથી. પરંતુ નશો કરવાની જેને આદત પડી છે અને નશો કરે છે એને શિક્ષાત્મક જોગવાઈની જગ્યાએ શિક્ષણાત્મક જોગવાઈઓમાં અમે બદલવા માગીએ છીએ. એક યુવાન વર્ગના ગરીબ છોકરાએ દારૂ પીધો, પહેલીવાર દારૂ પીધો અને અમે એને જેલમાં પુરી દઈએ અને હાર્ડ ફોર ક્રિમિનલ સાથે રહી એ વધુ ગુનેગાર બને એની જગ્યાએ ગયા વખતના ગૃહની અંદર પણ અમે વિધેયક લાવ્યા હતા અને કોમ્યુનિટિ સર્વિસ દ્વારા એને થોડી શરમ ઉત્પન્ન થાય, એ પ્રકારની સજાઓ કરીને એને દારૂ પીતો અટકાવવા માટેની આ બધી જોગવાઈઓ છે. આ જોગવાઈઓ રાજય સરકાર તેમની ઈચ્છાથી નથી લાવી કાયદા વિભાગ અને હાઈકોર્ટની વચ્ચે કેસોનું ભારણ ઘટાડવા માટે ચર્ચા યોજાય હતી તે ચર્ચાની અંદર એક સૂચન આવ્યું તો આ પ્રકારના સુધારા કરીએ તો ૧૨ લાખ કરતા વધુ કેસો દારુ પીવાના આ રાજયની અંદર પડતર છે અને આ કેસો પડતર હોવાને લીધે ચોરી, લૂંટ, બળાત્કાર, ધાડ આ બધા કેસો ચાલવા ઉપર પણ અસર પડે છે કારણકે કેસો બધા એક લાઈનમાં ક્રિમિનલ કેસો ચાલતા હોય છે. આ ભારણ અટકે, વધુ ગંભીર ગુન્હાની અંદર ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય એટલા માટે આ કર્યુ છે અને આની અંદર દારુબંધી હળવી કરવાની કોઈ જગ્યાએ વાત નથી. જે જે સભ્યશ્રીઓએ ચિંતા કરી છે તે બધાને જ હું ખાતરી આપવા માગુ છું કે દારુબંધી હળવી કરવાની કોઈ વાત નથી. જયારથી આ સરકાર અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી પકડાયેલા નશાના જે પદાર્થો છે તેનો આંકડો પહેલાં એવરેજ ૨૪ કરોડ રહેતો હતો આ સરકારના ત્રણેય વર્ષની અંદર પર કરોડ કરતાં વધારે રહયો છે. એટલે કયાંય કોઈ તબકકે નશાની વાતને ઢીલી મૂકવાની તો વાત જ નથી અને હું જે આંકડા કહું છું તે જવાબદારીપૂર્વક કહું છું વેગ વાતો નથી કરતો. વ્યકિતઓમાં પણ વધારો થતો હોય છે, કેસોમાં પણ વધારો થયો છે. વ્યકિત અને કેસો બન્નેમાં વધારો થયો છે એટલા માટે હું ધ્યાન દોરવા માગુ છું કે નશાબંધી હળવી કરવાની કોઈ વાત નથી પરંતુ એક શિક્ષણાત્મક અભિગમ સરકાર સ્વીકારે અને જે દારુ પીવાવાળા છે તેને victim.બનાવવાની જગ્યાએ તેને કોમ્યુનીટી સર્વિસ તેને માધુભાઈએ કહયું તે રીતે ધાર્મિક રીતે, બીજી રીતે વાળીને નશાબંધી વ્યસન મુકિત કેન્દ્રની અંદર તેને નિયમિત રીતે આવતો થાય કારણકે સજા નથી પડતી ત્યાં સુધી તેને વ્યસન મુકિત કેન્દ્રની અંદર પણ નથી લઈ જઈ શકતા અને ૧૨ લાખ કેસો પેન્ડીંગ હોય , તેને સજા ૨૦ વર્ષે પડે અને ૨૦ વર્ષે પડે તો ત્યાં સુધી તો તે રીઢો આદતી બની જાય છે વ્યસન મુકિત કેન્દ્રોનો કોઈ અર્થ જ નથી રહેતો એટલા માટે આ જોગવાઈઓ લાવવાની જરુરિયાત ઉભી થઈ છે અને આ પેટન્ટ ઉપર નાર્કોટીક એકટની અંદર પણ જેની જોડેથી નાર્કોટીક ખાતા પકડાય અથવા તો થોડુંક પકડાય તેની કેન્દ્ર સરકારે દશ વર્ષની સજા ઘટાડીને છ માસની કરી તેની પાછળ પણ કારણ હતું કે વ્યસન કરનારો ગુન્હેગાર નથી પણ વ્યસન કરવા માટે મજબૂર કરનાર ગુન્હેગાર છે. આ સરકારનો પણ આ અભિગમ છે જે વ્યસન કરે છે તેની પ્રત્યે માનવીય અભિગમ રાખો, તેને સુધારવાની દિશામાં લઈ જાવ, તેને કોમ્યુનીટી સર્વિસ આપી તેનામાં નશો કરતી વખતે શરમ ઉત્પન્ન થાય એવી સ્થિતિ ઉભી કરવી, તેને વ્યસન મુકિત કેન્દ્ર ઉપર મેડિકલ સહાય આપવી અને ધીરે ધીરે આ રીતે વ્યસન કરનાર વ્યકિત વ્યસન મુકત બને તેને માટે આ વિધેયક લાવવામાં આવ્યું છે. મારી એક બન્ને પક્ષના મિત્રોને વિનંતી છે કે આ વિધેયક ખરેખર શુભ આશયથી લાવ્યા છીએ અમારા આશય ઉપર

મહેરબાની કરીને શંકા ના કરશો. તમારા જેટલી ચિંતા અમને ગુજરાતના ગરીબ સમાજની, ગુજરાતના તળના લોકોની, ગુજરાતના લોકોના આરોગ્યની છે એટલે મારી વિનંતી છે કે, મેં પૂરતી સ્પષ્ટતાઓ કરી છે શરુઆતમાં આક્ષેપો થયા હતા એટલે મારાથી જવાબ અપાઈ ગયો પણ આના આશય ઉપર કોઈ શંકા ના કરવી જોઈએ અને આ વિધેયકને સર્વાનુમતે આ ગૃહ નશાબંધી અટકાવવા માટે કટિબધ્ધ છે તે રીતે પસાર કરે એવી હું વિનંતી કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : માધુભાઈ પ્લીઝ,... હવે હું પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકું છું.

પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૭-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું બીજુ વાંચન કરવામાં આવે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દારૂબંધીને લગતો જે કાયદો છે એ રાજનીતિ અને પક્ષથી પરનો છે અને અહીંયાં મોટાભાગના સભ્યશ્રીઓએ જે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા છે એમાં એક વાત જે કાંઈ સુધારાની છે એ સુધારો સર્વગ્રાહી રીતે સમાજની અંદર કાયમી ધોરણે એ બદીનું નિવરણ આવે અને એના કરતાં પણ જે હેતુથી આ કાયદો બનાવેલો છે એમાં મેં કહયું તેમ કરોડો રૂપિયાની આવક ગુમાવીને સમાજ કલ્યાણનો અને લોક કલ્યાણનો રસ્તો આપણે અપનાવ્યો છે. તો મને ચોકસપણે ભય લાગે છે કે જો આ સુધારાનો અમલ થશે તો દારૂ પીવાના કારણે સમાજમાં ડર છે એ ડર નીકળી જવાની શકયતા છે. એટલે હું ઈચ્છું છું કે માત્ર આ એક કાયદો નહીં, પણ દારૂબંધીને લગતા કાયદાઓમાં થોડીક વિચારણા કરવા માટે અને વધારે કડકાઈથી એનો અમલ કેવી રીતે કરી શકાય અને એમાં સભ્યશ્રીઓએ જે ચિંતા કરી છે એવા ભ્રષ્ટાચારનું જે એલિમેન્ટ છે એ કેવી રીતે દૂર કરી શકાય એની વિચારણા કરવા માટે આ બિલ પ્રવર સમિતિને સોંપવામાં આવે અને એની વિચારણા કર્યા પછી આખું આ બિલ નવેસરથી આવે એ સભાગૃહ સમક્ષ મૂકવામાં આવે.

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ જે પ્રસ્તાવ મૂકયો છે એના ઉપર ચર્ચા કરવામાં કોઈ વાંધો હોઈ શકે નહીં. આજે નશાબંધીનો કાયદો અમલમાં છે જ અને હું એક નાનકડો સુધારો લઈને આ ગૃહ સમક્ષ આવ્યો છું અને એ સુધારો પસાર થયા પછી પણ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખે અને બધા જ સભ્યોની જો એક સમિતિ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાની અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની સંમતિથી બનતી હોય તો એ સ્વતંત્ર વિચાર કરે અને ફરીવાર આપણે સુધારા વિધેયક લાવીશું, પણ એના માટે અત્યારે આ વિધેયકને અટકાવવાની જરૂર નથી. અત્યારે તો કાયદો તો અમલમાં છે જ અને મેં નાનકડો સુધારો સૂચવ્યો છે અને હું પણ માનું છું કે સર્વગ્રાહી વિચાર નશાબંધીની નીતિ અને નિયમ માટે થવો જોઈએ, પરંતુ એના માટે માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી માનનીય સભાગૃહના નેતાશ્રીને એટલે કે મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખે અને બન્ને સર્વસંમતિથી આપની પાસે આવ્યા પછી ગૃહના સભ્યોની સમિતિ વિચારણા માટે બનતી હોય તો વાંધો નથી, પરંતુ અત્યારે આ સુધારા માટે મોડું કરવાનું થાય એની સાથે હું સંમત નથી.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું એમના સૂચન સાથે સંમત ચોકકસ થયો હોત, પરંતુ આ જે સુધારા વિધેયક છે એને પસાર કરવામાં આવે તો જે દારૂ ગાળનારાઓ છે એમની પ્રત્યે સખતાઈ બતાવી શકીશું નહીં અને જે દારૂ પીનારાઓ છે એમને કોઈ જાતનો ડર રહેવાનો નથી. એટલે સ્વાભાવિક પણે જે દારૂનું કન્ઝમ્પ્શન છે એ મોટા પ્રમાણમાં વધવાનું છે. એના માટેની કોઈ સજાની જોગવાઈ રહેતી નથી એટલે આડકતરી રીતે આ દારૂબંધી નાબૂદ કરવાની વાત છે એની સાથે હું સંમત થઈ શકતો નથી, પરંતુ ફરી પાછી મારી વાત દોહરાવું છું કે આ બિલ પ્રવર સમિતિને સાંપવામાં આવે તો સર્વગ્રાહી રીતે વિચારણા કરવાની અમારી તૈયારી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ પ્રસ્તાવ મૂકયો છે અને માનનીય મંત્રીશ્રીએ એનો જવાબ આપ્યો છે. હવે હું પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકીશ.

વિધેયક પ્રવર સમિતિને સાંપવા માટેનો પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને નામંજૂર કરવામાં આવ્યો.
બીજા વાચન માટેનો પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.
કલમ ૨ થી ૪, કલમ ૧, દીર્ઘ સંજ્ઞા અને ઈનેકટિંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫ નું વિધેયક ક્રમાંક-૭-સન ૨૦૦૫ નું મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે અને વિધેયક પસાર કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫ નું મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે છે અને વિધેયક પસાર કરવામાં આવે છે.

માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રીનું નિવેદન (નિયમ-૪૪)
જોબનંબરની રકમમાં વધારો કરવા અંગે

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા (માર્ગ અને મકાનમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું કલમ ૪૪ હેઠળ નિવેદન કરું છું કે, માર્ગ અને મકાન વિભાગની રસ્તાના મરામતની જોગવાઈઓ તથા માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી અને મારી પાસે થયેલ રજૂઆતો તેમજ માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓની લાગણીને ધ્યાને લેતાં માનનીય ધારાસભ્યશ્રીને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આપેલ રસ્તાઓના રૂા. ૩૦ લાખના જોબનંબર ઉપરાંત વધારાના રૂા. ૧૫ લાખના જોબ નંબર ખાસ કિસ્સા તરીકે આપવાનો વિભાગે નિર્ણય કરેલ છે. કિસાનપથમાં મહત્ત્વની કડીરૂપ નોન-પ્લાન રસ્તાને પણ માનનીય ધારાસભ્યશ્રી ઈચ્છે તો આ જોબ નંબરમાં મેળવી શકશે, એટલે કે રસ્તાઓને મેટલથી ડામર અથવા ડામર રસ્તાનું રીસરફેસીંગ કરવા માટે માનનીય ધારાસભ્યશ્રીના મત વિસ્તાર દીઠ પંચાયત હસ્તકના વધારાના રૂા. ૧૫ લાખના જોબ નંબર હાલમાં આપવાનો નિર્ણય કરેલ છે. જે બાબત સન્માનનીય ગૃહને જણાવતાં આનંદ અનુભવું છું.

વટહુકમ નામંજૂર કરતા પ્રસ્તાવો અને સરકારી વિધેયકો (ક્રમશ:)

ડૉ.ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા(માંગરોળ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું વિધાનસભાના નિયમોના નિયમ ૧૫૨(૨) અન્વયે પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે આ સભાગૃહ સન ૨૦૦૪નો વટહુકમ ક્રમાંક-૩-સન ૨૦૦૪નો મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વટહુકમ નામંજૂર કરે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

સન ૨૦૦૫ નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાક-૪
મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.
મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ અધિનિયમ, ૧૯૫૩ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક.

શ્રી રમણલાલ ઈ. વોરા (શ્રમ અને રોજગારમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજપત્રમાં અગાઉ પ્રસિધ્ધ થયેલ સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૪-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક હું આપની પરવાનગીથી દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી રમણલાલ ઈ. વોરા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૪-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી રમણલાલ ઈ. વોરા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજયની સ્થાપના થયા પછી આ ગુજરાત લેબર વેલ્ફેર બોર્ડની રચના કરવામાં આવી. ખાસ કરીને સમગ્ર ગુજરાતમાં જે કામદારો કામ કરે છે એ કામદારો અને એમના કુટુંબીજનો અને એમના બાળકો માટે અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ આ કામદાર કલ્યાણ બોર્ડ કરે છે. એના માટે વાંચનાલય, પુસ્તકાલય, રમતગમતની વ્યવસ્થા, મનોરંજન, સિવણના વર્ગો, પ્રવાસ, પર્યટન આવી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે ત્યારે આ માટે ૧૯૭૩માં નક્કી થયું કે આને માટે ત્રિપક્ષીય ફાળો ઉઘરાવવો. ૧૯૭૩માં કામદારના ૨૫ પૈસા, માલિકના ૫૦ પૈસા અને સરકારના ૫૦ પૈસા એમ એક રૂપિયો અને પચ્ચીસ પૈસા ત્રિપક્ષીય ફાળા તરીકે લેવામાં આવતા હતા. ૧૯૮૧માં એમાં વધારો કરીને ૨૫ પૈસાને બદલે ૫૦ પૈસા, ૫૦ પૈસા લેવામાં આવતા હતા એના બદલે એક રૂપિયો લેવામાં આવતા હતો. પરંતુ ૧૯૮૧ થી ૨૦૦૪

---

* **(વિધેયક તા. ૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.)**

સુધીમાં ઘણો સમય ગયો છે. ત્યારે આધુનિકતા લાવવા માટે બોર્ડને ફરજ પડે એટલે આ વખતે આ વટહુકમ દ્વારા રાજય સરકારે કામદારોનો ફાળો ૫૦ પૈસા હતો એના બદલે ૩ રૂપિયા, માલિકનો ફાળો એમાં પણ છ ગણો વધાર્યો અને સરકારનો ફાળો પણ છ ગણો એમ કરીને વાર્ષિક ૩૦ રૂપિયા. પહેલા પાંચ રૂપિયા લેતા હતા એના બદલે ૩૦ રૂપિયા વધારો રાજય સરકારે સૂચવ્યો છે.

અત્યાર સુધીમાં જે ૪૫ લાખ રૂપિયા જેટલી ત્રિપક્ષીય ફાળા દ્વારા રાજય સરકાર અને બોર્ડને આવક થતી હતી એમાં ત્રણ કરોડ રૂપિયા જેટલો ફાળો થશે અને આ ફાળા દ્વારા ગુજરાતના કામદારો, એમના પરિવાર કલ્યાણ માટે એના ઉપયોગ માટે રાજય સરકાર આ વટહુકમ લઈને આવી છે. એમાં મેં આ પ્રકારના સુધારા રજૂ કરેલ છે.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા: (માંગરોળ) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી મુંબઇ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫ વિધાનસભા સમક્ષ લઈને આવ્યા છે. આ વિધેયકને વટહુકમ તરીકે પહેલા રજૂ કરીને આ વિધેયક તરીકે લાવ્યા. આ વિધેયકને બહાર પાડવા અંગેનું આ સંજોગો અને એનું નિવેદન પણ મૂક્યું છે. આ સંજોગોનો અને નિવેદનનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે. ૧૯૬૦ અને ૧૯૮૧ પછી આમાં સુધારા માટે આ પહેલી વખત આ વિધાનસભામાં વટહુકમ તરીકે મંજૂર કરવામાં આવ્યું. માનનીય મંત્રીશ્રીએ એમના નિવેદનની અંદર કામદારોનો અને કામદારની સાથે જોડાયેલ દરેક વ્યકિતઓની ચિંતાનો પ્રયત્ન કર્યો, મારે પૂછવું છે કે વટહુકમ કરવાની જરૂર પડી અને વટહુકમ કરીને આ સભાગૃહ સમક્ષ લાવ્યા. માનનીય મંત્રીશ્રી જવાબમાં પણ કહેશે કે વરસોથી અહીંયા નથી થયું. એક કરોડ રૂપિયા જેવી ખોટ વટહુકમ ન થયો હોત અને વિધેયક તરીકે લાવ્યા હોત તો થાત. મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને કહેવું છે કે કામદારોની વાત, નાના ગરીબ માણસોની વાત, મિલ મજૂરની વાત, ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા નાના વ્યકિતની વાત, એ વ્યકિતની વાત સાથે જોડાયેલ વટહુકમ અથવા વિધેયક, ૧૯૮૧ પછી આમાં એકપણ સુધારો આવ્યો નથી. ત્રણ વર્ષ પહેલા કે પાંચ વર્ષ પહેલા સુધારાની વાત આમાં થઈ નથી. પરંતુ આ ચિંતા આપણે ગત સત્રમાં, ગઈ વિધાનસભામાં કરી શક્યા હોત. આ ચિંતા ચાર પાંચ વર્ષ પહેલા કરીને તે વખતના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી લાવી શક્યા હોત. પરંતુ વટહુકમ તરીકે વિધેયક લાવવામાં આવ્યું છે. વિધેયક તરીકે લાવ્યા ત્યારે એમનું નિવેદન મેં જોયું. એમના બે વર્ષ, છ વર્ષ કરીને માનનીય મંત્રીશ્રી મારફત કહીશ કે જે ચિંતાના વિષય સાથે વિધેયક લાવ્યા કામદાર કલ્યાણ બોર્ડ, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવું છે કે કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રોની હાલત આપે જોઈ છે ખરી? અત્યારે ચાલતા કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રોના મકાનો આપે જોયા છે ખરા? જે કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રોમાં ગરીબ કામદાર મિલમજૂર એ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલ માણસની સેવાકીય પ્રવૃત્તિનું મોટું નિવેદન આપે બહાર પાડ્યું. પણ એ મકાનની હાલત શું છે? એ મકાનમાં રીપૅરીંગ પાછળ એક રૂપિયો ખર્ચ થયો છે ખરો? તેનાથી આગળ વધીને કહેવા માગું છું કે કામદારની ચિંતા કરીને આજે એક કરોડ થયા, કાલે ત્રણ કરોડ થશે. સારું થશે પણ આવતા દિવસોમાં શું? મારે એક વાત એ પણ કહેવી છે, વિધેયક લઈને આવ્યા, વટહુકમ કર્યો. મારે પૂછવું છે કે કેટલા કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રો વધ્યા? સ્લમ એરિયામાં મજૂરવર્ગ રહેવા ગયો છે. પરા વિસ્તારમાં મજૂર વર્ગ રહેવા ગયો છે અને તેનાથી આગળ નાના-નાના ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ છે. તો વિભાગે કેટલા નવા કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રો બનાવ્યા? વિભાગે બનાવેલા કેન્દ્રોમાં મજૂરો માટે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કેટલી થાય છે? પહેલાંના વખતમાં કામદાર એટલે મિલમજૂર. આજે મિલમજૂરની વાત મૂકી દો. ટૅક્સટાઈલની વાત તો પડી ભાંગી. મિલો તો બંધ થઈ અને મિલો બંધ થયા પછી નવા ઉદ્યોગો પણ આવ્યા. ત્યારે મારે એક વાત કરવી છે કે આ જ હેતુસર કૅબિનૅટ મિટિંગમાં ત્રણ સભ્યોની કમિટીની રચના થઈ છે એવું મને જાણવા મળ્યું છે. આ સબકમિટીની રચના થઈ તેનો અભ્યાસ કરીને સંપૂર્ણ સંજોગો, પરિસ્થિતિ અને ભવિષ્યમાં પાંચ વર્ષ ચાલે તેનો અભ્યાસ થયા પછી વિધેયક આવ્યું હોત તો તે ઘણાં સુધારા-વધારા સાથે આવ્યું હોત. તેનાથી આગળ વધીને મારે વાત કરવી છે તે કામદારની વાત. પેટા કમિટીની રચના કરી, એનો અભ્યાસ ક્યારે થશે? આજે વટહુકમ થયો, વિધેયક આવ્યું, આજે પસાર પણ થઈ જશે. એ પછી પેટા કમિટીના ત્રણ સભ્યો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરશે ત્યારે ફરી આ કામદારોની ચિંતા કરીને વિધેયક લાવીશું?

મારે બે-ત્રણ મહત્ત્વની બાબતો કહેવી છે. માનનીય આઈ.કે. જાડેજા, આરોગ્ય મંત્રીશ્રી અહીં બેઠાં છે. વીમા કામદાર હૉસ્પિટલોની સ્થિતિ છે. વીમા કામદાર હૉસ્પિટલ બની તે કામદારો માટે બની હતી. આજે એ કામદાર, મિલમાંથી છૂટો થયેલો માણસ, રોજ કરોડોના ઉદ્યોગો આવે છે. છ મહિના ઉદ્યોગ ચાલે અને અચાનક બંધ થઈ જાય. ત્યાં નોકરી કરતો માણસ રોડ ઉપર આવી જાય. કામદાર યોજનામાં હૉસ્પિટલ હોય ત્યારે હોય પણ રોડ ઉપર આવેલ એ કામદારની સ્થિતિની ચિંતા કરનાર વર્ગ કયો? અહીં બેઠેલાં તમામ લોકોને એ કામદારની ચિંતા છે. રોડ ઉપર આવેલ એ વ્યકિતને વીમા કામદાર હૉસ્પિટલમાંથી એક રૂપિયાની સારવાર મળતી નથી. ત્યારે માનનીય મંત્રીશ્રીએ એ વિષયને આવરી લીધો હોત તો મને આનંદ થાત. તેનાથી આગળ વધીને જે સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે તેમાં જે મકાનો સ્લમ એરિયામાં છે ત્યારે હાઉસીંગ બોર્ડના મકાનો ઘણી જગ્યાએ ખાલી પડ્યા છે. આવા જે ખાલી પડેલા મકાનો છે તેમાં કામદાર કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ માટે એ

મકાનો ટોકન રેટથી પણ લઈ શકાય અને આ મકાનો ભાડા પટ્ટે પણ લઈ શકાય અને એમાં પણ આવી કામદાર કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ કરી શકાય. કામદાર શબ્દ એ સામાન્ય નાનો શબ્દ નથી. કામદાર વર્ગમાં ૭૫૦ પછીની તમામ વ્યકિતઓને આવરી લીધી છે. માનનીય મંત્રીશ્રી બે-ત્રણ વાત લઈને આવ્યા, જેને વટહુકમ કરવો પડે એવી ચિંતાજનક સ્થિતિ લઈ આવ્યા. ચિંતા કરવી પડે, સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે પણ ચિંતા કરીને વટહુકમ કર્યો છે ત્યારે સમગ્ર કામદાર વર્ગનો વિચારપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હોત તો મને વાંધો નહોતો. તેનાથી આગળ વધીને માનનીય મંત્રીશ્રીએ કલમો સુધારી. તેમાં તેમ કહ્યું કે ત્રણ વર્ષની મુદત છે તેમાં દોઢ વર્ષ કરીને છ મહિના કરી નાખ્યા અને એક વર્ષની મુદત કરી. વિધેયક લાવ્યા છે ત્યારે એક વર્ષ શા માટે? તેનો એક વર્ષથી છ માસ કરતા ટૂંકો ગાળો ન થઈ શક્યો હોત? તેનાથી આગળ વધીને જોગવાઈ કલમ-૩ની ૨માં એક વર્ષની મુદત કરી. તેમાં પણ ૬ ટાટાડી. તમામ કલમો જયારે મંત્રીશ્રી ખૂબ જ લાગણીથી કામદારના પ્રશ્નની ચિંતા કરીને ૧૯૮૧ પછી પ્રથમ વખત વિધાનસભામાં કામદાર વિધેયકમાં સુધારા બિલ આવ્યું છે, કામદાર કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલું બિલ આવ્યું છે ત્યારે હું એમ માનું છું કે કામદાર માટે અહીં બેઠેલાં તમામ સભ્યશ્રીઓને ચિંતા છે.
ચિંતા છે, સૌને લાગણી છે એના માટે કાંઈક કરવાની હોંસ છે ત્યારે આ બિલને વધુ સુધારા સાથે વધુ સૂચનો સાથે લાવ્યા હોત તો ખૂબ આનંદ થાત. માનનીય મંત્રીશ્રી આ બાબતમાં જુએ એવી વિનંતી છે.

શ્રી રમણલાલ ઈ. વોરા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બિલમાં બહેનશ્રી ચંદ્રિકાબેને સુધારો રજૂ કર્યો છે, એમણે થોડીક ચિંતા વ્યકત કરી છે કે બિલ કેમ મોડું આવ્યું? મને એમ કે અભિનંદન આપશે. ૨૧ વર્ષ પછી, ૧૯૮૧ પછી ૨૩મા વર્ષે પહેલી વખત હું લાવ્યો એટલે એ અભિનંદન આપશે પણ આ તો આટલું મોડું કેમ આવ્યું? એમ એમણે કહ્યું. સામાન્ય રીતે આ બિલ કામદારોના હિત માટે છે. બહેનની લાગણી સાથે, ભાવના સાથે એમના સજેસન સાથે હું સો ટકા સંમત છું. કેબિનેટની અંદર આ બિલ આવ્યું ત્યારે પહેલાં અધિકારીઓની એક સમિતિ બનાવી અને ૪૫ લાખથી માંડીને ૩ કરોડ રૂપિયા જયારે આ કામદાર કલ્યાણ બોર્ડને મળવાના છે, એની વ્યવસ્થાનો વ્યાપ વધે, એમાં આધુનિકતા આવે, અત્યારે જે સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે, એના બાળકોને લાભ મળે એ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અધિકારીઓની એક સમિતિ બનાવી, એ સમિતિએ પોતાનો રિપોર્ટ આપ્યો, પછી આ વટહુકમ અમે ન કર્યો હોત તો પહેલી જાન્યુઆરી ૨૦૦૫થી આ વટહુકમ અમલમાં ન આવત અને પહેલા ૬ મહિના માટેના ૧ કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ આ કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રને મળવાપાત્ર છે એ કદાચ ન મળત. એટલા માટે વટહુકમ લાવીને એની અસરકારકતા પહેલી જાન્યુઆરીથી થાય એ રાજય સરકારનો આશય છે. બહેને કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રની સ્થિતિની જે વાત કરી, માત્ર ૪૫ લાખ, એમની વાત સાચી છે. આટલું મોટું તંત્ર, એના પગારો અને બાકીની બધી વસ્તે કરવામાં, કામદારોના હિતોના કામ કરવા જોઈએ એ ન થઈ શકે. એટલા માટે મેં અગાઉ કહ્યું એ પ્રમાણે ૬ ગણી વધારે રકમ કરીને જયારે કર્યું છે ત્યારે શ્રી અશોકભાઈ ભટ્ટના નેતૃત્વ નીચે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કેબિનેટની એક સબ કમિટિ બનાવી છે. એમાં શ્રી આઈ.કે. જાડેજા અને હું એમ ૩ સભ્યો છીએ અને એક જ મહિનાની અંદર, અધિકારીઓએ શું કરવું જોઈએ એ વાત કરી છે. એનાથી પણ આગળ જઈને એમાં આધુનિકતા આવે, એનો વ્યાપ વધે, માત્ર ટેકસટાઈલ ઉદ્યોગ જ નહીં અન્ય જી.આઈ.ડી.સી. અને બાકીના કામદારોનો પણ એમાં સમાવેશ કરીને બધા કામદારોને એનો લાભ મળે એ રાજય સરકારનો આશય છે. એમણે કામદાર રાજય વિમા યોજનાના દવાખાનાની પણ વાત કરી. મેં અગાઉ કહ્યું તે પ્રમાણે આરોગ્ય મંત્રી આ સમિતિના સભ્ય છે તો એનો લાભ મળશે. આ બાબતમાં વિશેષ વાત ન કરતાં મોડામાં મોડા પણ કામદારોના હિતના રક્ષણ કરવા માટે રાજય સરકારે ૪૫ લાખથી ૩ કરોડની જોગવાઈ કરી છે અને એટલે કામદારોના રક્ષણ માટે બોર્ડને સક્ષમ બનાવી જયારે મજૂરોના હિતોની વાત કરી છે ત્યારે બહેનશ્રી ચંદ્રિકાબેનને હું વિનંતી કરું છું કે એ એમનો પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચી લે અને આ ગૃહના સર્વે સભ્યો સર્વાનુમતે આ બિલને મંજૂર કરે એવી વિનંતી છે.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ એમના પ્રવચનમાં જે વાત કરી, ત્યારે હું ફરીથી વાત કરું છું કે, ટેકસટાઈલ નહીં પરંતુ તમામ ઉદ્યોગો સાથે જોડાય, નાના ઉદ્યોગ પણ એની સાથે જોડાય, તમામનો કામદાર રાજયની અંદર સમાવેશ કરી મેં કરેલા સૂચનોનો અભ્યાસ કરી ફરી એના માટે ચિંતા સેવે એ વાત સાથે હું મારો વટહુકમ નામંજૂર કરતો પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચી લેવાની આપની પરવાનગી માગું છું. જેને સભાગૃહ અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : હું મારો પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વટહુકમ નામંજૂર કરતો પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચવામાં આવે છે.

શ્રી રમણલાલ ઈ. વોરા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક:૪-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું બીજું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ ૨થી ૫, કલમ ૧, દીર્ઘ સંજ્ઞા અને ઈનેકટિંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી રમણલાલ ઈ. વોરા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક:૪-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાંચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૪નું ત્રીજું વાંચન કરવામાં આવે છે અને વિધેયક પસાર કરવામાં આવે છે.

સભાગૃહનો સમય લંબાવવા બાબત

શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ :(મુખ્ય દંડકશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ક્રમાંક- ૮ અને ૯ ઉપરના વિધેયકો રદ કરવાને પાત્ર છે તો એ કામકાજ પૂરું થાય ત્યાં સુધી ગૃહનો સમય લંબાવવામાં આવે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા :(વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમાં બે મહત્ત્વના બિલો બાકી રહે છે અને સરકારી કામકાજ માટેની ત્રણ બેઠકોમાં કોઈ એજન્ડા એવો છે નહીં એટલે હવે આ એક અને આના પછીનું એક વિધેયક આપણે લઈ લઈએ. રદ કરવાના છે એમાં મને વાંધો નથી પણ બાકીના જે છે એ આપણે આગળના કામકાજની યાદીમાં લઈ લઈએ.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : આપણે ૮ અને ૯ લઈ લઈએ છીએ. ૧૦ અને ૧૧ પછી રાખીશું.

સન ૨૦૦૫નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક: ૧૨

ધાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનો) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫

ધાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનો અધિનિયમ, ૧૯૭૭ રદ કરવા બાબત વિધેયક.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા (શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણમંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજયપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૧૨-સન ૨૦૦૫નું ધાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનો) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક આપની પરવાનગીથી દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા (શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણમંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૧૨-સન ૨૦૦૫નું ધાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનો) (રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું પહેલું વાંચન કરવામાં આવે.

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સ્વયંસ્પષ્ટ વિધેયક છે. ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકામાં તા. ૧-૭-૧૯૪૯ થી તા. ૨૩-૪-૧૯૬૫ દરમિયાન જે ટેકસ નાખવામાં આવેલો અને સુપ્રીમ કોર્ટ એ બાબતે વિરુધ્ધાત્મક રહેલ એ સ્વરૂપમાં જે તે સમયે રાજય સરકાર એને કાયદેસરતા આપતું વિધેયક લાવેલ અને એ પછી જુદા જુદા વિધેયકો અને જેના કાયદાની જરૂરિયાત હવે નહિ રહેવાથી ગુજરાત લોક કમિશને એના ૨૧માં અહેવાલમાં પણ આ અધિનિયમને રદ કરવાનું જણાવેલ છે. એ અનુસાર આજે અહીં લાવ્યો છું. મારી સભાગૃહને વિનંતી છે કે આ કાયદાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી ન હોવાથી માનનીય સભ્યશ્રીઓ એમાં સહમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને વિના વિરોધે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક: ૧૨-સન ૨૦૦૫નું ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનો) (રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું બીજું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને વિના વિરોધે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ-૨ અને કલમ-૧, દીર્ઘસંજ્ઞા અને ઈનેકટિંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

* (વિધેયક તા.૧૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના ગર્વન્મેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.)

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક: ૧૨-સન ૨૦૦૫નું ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનો) (રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને વિના વિરોધે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક:-૧૨નું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે છે અને વિધેયક પસાર કરવામાં આવે છે.

સન ૨૦૦૫નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક:૬

મુંબઈનો બિન-વ્યાપારી કોરપોરેશન (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫
મુંબઈનો બિન-વ્યાપારી કોરપોરેશન અધિનિયમ, ૧૯૫૯ રદ કરવા બાબત વિધેયક.

શ્રી વજુભાઈ વાળા (નાણામંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજયપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૬-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ બિન-વ્યાપારી કોરપોરેશનો (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકને આપની અનુમતિથી દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી વજુભાઈ વાળા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૬-સન ૨૦૦૫ના મુંબઈ બિન-વ્યાપારી કોરપોરેશનો (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી વજુભાઈ વાળા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ કાયદો બૉમ્બે નોન ટ્રેડીંગ કોરપોરેશન એકટ ૧૯૫૯માં થયેલો. ત્યારપછી એમાં જે લોકો સંગીતની દ્રષ્ટિએ, નૃત્યની દ્રષ્ટિએ, કોમર્શિયલ દ્રષ્ટિએ આ બધી પ્રવૃત્તિઓ કરતા હતા એને નોન ટ્રેડીંગ કરવા માટેની પદ્ધતિ હતી. પરંતુ ત્યારપછી આપણે કો-ઓપરેટીવ એકટ આવ્યો, એ પછી પણ આપણે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એકટ આવ્યો. એટલે કો-ઓપરેટીવ એકટ અને નોન ટ્રેડીંગ એની કલમો સામસામે વિસંગત થવા માંડી. પબ્લિક ટ્રસ્ટ એકટની કલમો વિસંગત થવા માંડી. એટલા માટે આ કાયદો છે, જે લોકો આ નીચે રજિસ્ટર્ડ થયેલ છે એવા લોકોને સેઈવ કરીને ભવિષ્યમાં નવા લોકોને કોઈને રજિસ્ટ્રેશન ન આપવું એના માટે આ કાયદો કરવામાં આવ્યો છે. આ કાયદો રદ કરવાથી કોઈને નુકસાન થવાનું નથી. અત્યારે હાલની તારીખે જેટલા લોકો છે એ બધાને જનરલ કલોઝિસ એકટ નીચે એને સેઈવ કરી લેવામાં આવ્યા છે. ભવિષ્યમાં રજિસ્ટ્રેશન ન મળે અને રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય તો કો-ઓપરેટીવ એકટ નીચે અને પબ્લિક ટ્રસ્ટ એકટ નીચે કરે કે જેનાથી એક જ રીતે બધાનું સંચાલન ચાલે એના માટે આ કાયદો લાવ્યો છું. આથી આ કાયદો સૌ મંજૂર કરે એવી માનનીય સભાગૃહને વિનંતી છે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી વજુભાઈ વાળા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૬-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ બિન-વ્યાપારી કોરપોરેશનો (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું બીજું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજુર કરવામાં આવ્યો.

કલમ-૨ અને કલમ-૧, દીર્ધસંજ્ઞા અને ઈનેકટિંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી વજુભાઈ વાળા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૦૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૬-સન ૨૦૦૫નું મુંબઈ બિન-વ્યાપારી કોરપોરેશનો (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે અને તે પસાર કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજુર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૦૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૬નું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે છે અને તે પસાર કરવામાં આવે છે.

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૫-૨૧ વાગ્યે પૂંરું થતાં સભાગૃહ અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર મંગળવાર, તા.૨૨મી ફેબ્રુઆરી,૨૦૦૫ ના રોજ સવારના ૮-૩૦ વાગ્યે ફરી મળવા મુલતવી રહયું.

* (વિધેયક તારીખ ૧૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.)

ગુજરાત વિધાનસભા
મંગળવાર, તા.૨૨ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫
ફાલ્ગુન ૩, ૧૯૨૬ શાકે
પહેલી બેઠક
સભાગૃહ સવારના ૮.૩૦ વાગ્યે મળ્યું
અધ્યક્ષશ્રી પ્રો. મંગળભાઈ પટેલ અધ્યક્ષસ્થાને

રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)

અધ્યક્ષશ્રી : નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટે તા.૧૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના રોજ માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી તરફથી જે આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને જેને માનનીય સભ્યશ્રી પ્રબોધકાંત પંડયાએ અનુમોદન આપ્યું છે તે આ પ્રમાણે છે.

રાજ્યપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેશો પાઠવવો-

" અમો આ સત્રમાં એકત્ર થયેલા ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો રાજ્યપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ સમક્ષ કરેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ. "

હવે માનનીય સભ્યશ્રીઓ પોતાના સુધારા રજૂ કરે.

શ્રી પુનાભાઈ ધે. ગામીત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક :૧ રજૂ કરુ છું.

"રાજ્યમાં બનતા બળાત્કાર-લૂંટ-ધાડ અને અપહરણના બનાવો અટકાવવામાં સરકાર નિષ્ફળ ગઈ છે તે બાબતમાં પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક :૧ રજૂ કરવામાં આવ્યો

શ્રી મનીષ ન. ગીલીટવાલા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક: ૨ રજૂ કરુ છું.

"વિધવા અને ત્યક્તા મહિલાઓને અપાતી સહાય બંધ કરી દેવામાં આવી છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક :૨ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

ડૉ. દિનેશ પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક :૩ રજૂ કરુ છું.

"રાજ્યમાં મહિલા આયોગ રચવાની સરકારની જાહેરાતને ચાર વર્ષ પૂરા થવા છતાં મહિલા આયોગની રચના થઈ શકી નથી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક :૩ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી અમિત ચાવડા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક :૫ રજૂ કરુ છું.

"રાજ્યમાં બોગસ ડિગ્રી ધારક શિક્ષકોની ભરતી સબંધમાં શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા જવાબદારો સામે પગલાં લેવાનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક :૫ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક: ૬ રજૂ કરુ છું.

રાજ્યમાં બંધ પડેલા ઉદ્યોગોને પુનઃ ધમધમતા કરવા બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી.

સુધારો ક્રમાંક: ૬ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક:૭ રજૂ કરુ છું.

માર્ગોના વિકાસના નામે પ્રજા પાસેથી ટોલટેકસના નામે પ્રજાને માથે પડેલા બોજને દૂર કરવાનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી.

સુધારો ક્રમાંક :૭ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી શંકરભાઈ મં. વારલી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક: ૧૦ રજૂ કરુ છું.

"રાજ્યની વીજ ક્ષમતામાં કોઈ અસાધારણ વધારો થયો હોય તેમ જોવા મળતું નથી. જયોતિગ્રામ યોજના અમલમાં હોવા છતાં આજે પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૧૪ કલાક અંધારપટ રહે છે પરિણામે વિદ્યાર્થીઓ, ખેડૂતો અને ગ્રામ્ય કારીગરોનો મહામૂલ્ય સમય વેડફાય છે અને હાડમારીઓ ભોગવે છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક: ૧૦ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હુંનીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૧ રજૂ કરુ છું.

"રાજ્યમાં વીજ માંગ કેટલી છે અને કેટલી વીજળી કયા ભાવે બહારથી ખરીદી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૧ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી હેમાજી દ. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૩ રજૂ કરુ છું.

"સરકાર દ્વારા કલ્પસર યોજનાની કામગીરી થઈ નથી, નકશા અંદાજો તૈયાર થયા નથી અને અમલીકરણ ક્યારથી શરૂ થશે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૩ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી ભીખાભાઈ ગ. જોષી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૪ રજૂ કરુ છું.

"વન વિસ્તારના ગામો-નેસડાઓ માટે પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરવા અંગેના આયોજનનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી. "

સુધારો ક્રમાંક :૧૪ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી જીતુભાઈ હ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હુંનીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૫ રજૂ કરુ છું.

"સરકારે કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહિત કરવા શાળા પ્રવેશ જેવા કાર્યક્રમો યોજ્યા છે પરંતુ શાળાઓના વર્ગોની બિસમાર હાલતનો તેમજ વર્ગોની સંખ્યા વધારવાનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૫ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૬ રજૂ કરુ છું.

"દર વરસે વિદ્યાર્થીઓને ઇજનેરી કૉલેજોમાં એડમિશન મેળવવા માટે પડતી ભારે હાડમારી તથા વિલંબનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૬ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી લક્ષ્મણભાઈ બા. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક :૧૮ રજૂ કરુ છું.

"દર વરસે ધોરણ-૧૧ અને ૧૨માં સાયન્સ વિભાગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં થતાં ઉત્તરોત્તર ઘટાડાનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક :૧૮ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૯ રજૂ કરુ છું.

"કન્યા કેળવણી મફત આપવાનો સરકારનો પરિપત્ર હોવા છતાં તેનો અમલ સેલ્ફ ફાઈનાન્સ શાળા-કૉલેજોમાં થઈ શક્યો નથી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંકઃ ૧૯ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હુંનીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૨૨ રજૂ કરુ છું.

"સુજલામ સુફલામ યોજના અંતર્ગત ઉત્તર ગુજરાત માટે ૯૦/૧૦ અને સૌરાષ્ટ્ર માટે ૬૦/૪૦ નો રેશિયો રાખી બેવડી નીતિ અપનાવાઈ છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક ૨૨ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

ડૉ. અનિલ જોષીયારા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૨૩ રજૂ કરુ છું.

"સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજનામાં ચેકડેમોના બાંધકામની ગુણવત્તા હલકી કક્ષાની છે તેવી ફરિયાદો થઈ છે તેના નિરાકરણ બાબતમાં સરકારે લીધેલા પગલાંનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંકઃ ૨૩ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ૨૫ રજૂ કરુ છું.

"ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ગુજરાતની પીછેહઠ થઈ રહી છે તેના નક્કર પગલાં લેવાને બદલે ઉત્સવો ઉજવવા પાછળ ખોટા ખર્ચા થઈ રહ્યા હોવા બાબતનો પ્રવચનનો કોઈ ઉલેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંકઃ૨૫ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રીમતી ભારતીબેન ન. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંકઃ ૨૬ રજૂ કરુ છું.

"બેકાર યુવકો માટે રોજગારીની તકો વધારવા અને રોજગાર કચેરીઓમાં નોંધાયેલા બેરોજગારોને સરળતાથી રોજગારી મળી રહે તે માટેના આયોજનનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક: ૨૬ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી પરેશભાઈ ગો. વસાવા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક :૨૭ રજૂ કરુ છું.

"આરોગ્ય ક્ષેત્રે હૉસ્પિટલોમાં આધુનિક ટૅક્નૉલૉજીના મશીનો વસાવવામાં આવ્યા છે પરંતુ આવા આધુનિક મશીનો કુશળ કર્મચારીઓના અભાવે ઘણા વરસોથી બંધ છે અને દર્દીઓની હાડમારીઓ વધતી જાય છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક :૨૭ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી છનાભાઈ કો. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નીચે મુજબનો મારો સુધારો ક્રમાંક: ૨૯ રજૂ કરુ છું.

"નર્મદા કેનાલ આધારિત પાણી પુરવઠા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નૅટવર્કને પાઈપ લાઈનના નબળા કામથી પાણી વિતરણમાં પડતી હાડમારીઓ નિવારવા અંગેનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી."

સુધારો ક્રમાંક: ૨૯ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર સુધારા સુધારાની એકત્રિત યાદી

અ નં ૧	સુધારો ૨	રજૂ કરનાર સભ્યશ્રી ૩
	પ્રસ્તાવના અંતે નીચેના શબ્દો ઉમેરવા :- **"પરંતુ દિલગીર છીએ કે -**	
૧	રાજયમાં બનતા બળાત્કાર-લૂંટ- ધાડ અને અપહરણના બનાવો અટકાવવામાં સરકાર નિષ્ફળ ગઈ છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી પુનાભાઈ ગામીત
૨	વિધવા અને ત્યકતા મહિલાઓને અપાતી સહાય બંધ કરી દેવામાં આવી છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી મનીષ ગિલીટવાલા
૩	રાજયમાં મહિલા આયોગ રચવાની સરકારની જાહેરાતને ચાર વર્ષ પૂરા થવા છતાં મહીલા આયોગની રચના થઈ શકી નથી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	ડો.દિનેશ પરમાર
*૪	રાજયમાં માનવ અધિકાર પંચની રચના કરવા બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી દોલતભાઈ પરમાર
૫	રાજયમાં બોગસ ડીગ્રી ધારક શિક્ષકોની ભરતી સંબંધમાં શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા જવાબદ ારો સામે પગલા લેવાનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી અમીતભાઈ ચાવડા
૬	રાજયમાં બંધ પડેલા ઉધોગોને પુન: ધમધમતા કરવા બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી બલવંતસિંહ રાજપુત
૭	માર્ગોના વિકાસના નામે પ્રજા પાસેથી ટોલટેક્ષ નામે પ્રજાના માથે પડેલા બોજને દૂર કરાવાનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી બળદેવજી ઠાકોર
*૮	પીપાવાવ પ્રોજેકટ માટે રાજય સરકારે વારંવાર કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ ગેસ ફાળવવા માંગણી કરી છે પરંતુ અચાનક આ પ્રક્રિયા બંધ કરી હજીરા માટે ગેસ ફાળવવા સરકારે કેન્દ્રને વિકલ્પ રજૂ કર્યો છે, તેના પરિણામે ગેસ સમયસર મળી શકતો નથી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી ગૌતમભાઈ ઝાલા
*૯	ગુજરાતને ગેસની ફાળવણીમાં થતો અન્યાય દૂર કરવા અને વધુ ગેસ મેળવવા બાબત તેમજ દહેજ ખાતેના પેટ્રૉનેટ એલએનજીમાંથી પ્રવાહી પ્રાકૃતિક ગેસની ફાળવણી ખૂબ જ ઓછી થાય છે તે અંગે કેન્દ્રમાં રજૂઆત કરી વધુ ગેસ મેળવવા બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી માલજીભાઈ દેસાઈ
૧૦	રાજયની વીજ ક્ષમતામાં કોઈ અસાધારણ વધારો થયો હોયખ તેમ જોવા મળતું નથી જયોતિ ગ્રામ યોજના અમલમાં હોવા છતાં આજે પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૧૪ કલાક અંધારપટ રહે છે પરિણામે વિધાર્થીઓ, ખેડૂતો અને ગ્રામ્ય કારીગરોનો મહામુલ્ય સમય વેડફાય છે અને હાડમારીઓ ભોગવે છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી શંકરભાઈ વારલી

૧૧	રાજયમાં વીજ માંગ કેટલી છે અને કેટલી વીજળી કયા ભાવે બહારથી ખરીદી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	ડૉ.ચંદ્રિકાબેન ચુડાસમા
*૧૨	સરકારે ગુજરાત વીજળી ઉદ્યૉગ અધિનિયમ ૨૦૦૩ હેઠળ સાત કંપનીઓની રચના કરી છે અને બીજી તરફ વિદ્યુત કર્મચારીઅ ૉને ખાનગીકરણના મુદ્દે ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી અનિલભાઈ પટેલ
૧૩	સરકાર દ્વારા કલ્પસર યોજનાની કામગીરી થઈ નથી, નકશા અંદાજો તૈયાર થયા નથી અને અમલીકરણ કયારથી શરૂ થશે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી હેમાજી રાજપૂત
૧૪	વન વિસ્તારના ગામો-નેસડાઓ માટે પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરવા અંગેના આયૉજનનૉ પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી ભીખાભાઈ જૉષી
૧૫	સરકારે કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહિત કરવા શાળા પ્રવેશ જેવા કાર્યક્રમો યોજયા છે પરંતુ શાળાઓના વર્ગોની બિસ્માર હાલતનો તેમજ વર્ગોની સંખ્યા વધારવાનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી
૧૬	દર વરસે વિધાર્થીઓને ઈજનેરી કોલેજોમાં એડમિશન મેળવવા માટે પડતી ભારે હાડમારી તથા વિલંબનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રીમતી રશીદાબેન પટેલ
*૧૭	સેલ્ફ ફાયનાન્સ કોલેજો દ્વારા નિયમ કરતા ખૂબજ ઉંચી ફી લેવાય છે અને કોલેજોમાં પૂરતી સવલતો પણ અપાતી નથી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી માધુભાઈ ભૉયે
૧૮	દર વરસે ધોરણ-૧૧ અને ૧૨માં સાયન્સ વિભાગમાં વિધાર્થીઓની સંખ્યામાં થતા ઉત્તરોઉતર ઘટાડાનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી લક્ષ્મણભાઈ પટેલ
૧૯	કન્યા કેળવણી મફત આપવાનો સરકારનો પરિપત્ર હોવા છતાં તેનો અમલ સેલ્ફ ફાયનાન્સ શાળા-કોલેજોમાં થઈ શકયો નથી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી કુવરજીભાઈ બાવળીયા
*૨૦	રાજયમાં ઈન્ડીસન્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ વીમેન્સ એકટ અમલમાં હોવા છતાં વર્તમાનપત્રો- સમાયિકો અને ટી.વી. ચેનલો જેવા માધ્યમોમાં સ્ત્રીઓ અને યુવતીઓની બિભત્સ જાહેરાતો કરવામાં આવી રહી છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી બાબુભાઈ શાહ
*૨૧	સરદ ાર સરોવર પરિયોજનાના બંધની ઉંચાઈ ૧૧૦.૬૪ મીટર સુધી પૂર્ણ કરેલ છે પરંતુ નિર્ધારિત સમયમાં ડેમની ઉંચાઈ વધારી શકાઈ નથી તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી મનહરલાલ મકવાણા
૨૨	સુજલામ સુફલામ યૉજના અંતર્ગત ઉતર ગુજરાત માટે ૯૦/૧૦ અને સૌરાષ્ટ્ર માટે ૬૦/૪૦ નો રેશિયો રાખી બેવડી નીતિ અપનાવાઈ છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી પૂંજાભાઈ વંશ
૨૩	સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યૉજનામાં ચેક ડેમોના બાંધકામની ગુણવત્તા હલકી કક્ષાની છે તેવી ફરિયાદો થઈ છે, તેના નિરાકરણ બાબતમાં સરકારે લીધેલાં પગલાંનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	ર્ડા. અનિલ જૉષીયારા
*૨૪	પશુપાલન અને ડેરી વિકાસ માટે કોઈ નકકર દિશાકે પગલાં કે સરકારની કાર્યવાહીની બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	ર્ડા. સી. જે. ચાવડા
૨૫	ઔધોગિક ક્ષેત્રે ગુજરાતની પીછે હટ થઈ રહી છે તેના નકકર પગલાં લેવાને બદલે ઉત્સવો ઉજવવા પાછળ ખોટા ખર્ચાઓ થઈ રહયા હોવાની બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળીયા
૨૬	બેકાર યુવકો માટે રોજગારીની તકો વધારવા અને રોજગાર કચેરીઓમાં નોંધાયેલા બેરોજગારોને સરળતાથી રોજગારી મળી રહે તે માટેના આયોજનનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રીમતી ભારતીબેન પટેલ
૨૭	આરોગ્ય ક્ષેત્રે હોસ્પિટલોમાં આધુનિક ટેકનોલોજીના મશીનો વસાવવામાં આવ્યા છે પરંતુ આવા આધુનિક મશીનો કુશળ કર્મચારીઓના અભાવે ઘણા વર્ષોથી બંધ છે અને દર્દીઓની હાડમારીઓ વધતી જાય છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી પરેશભાઈ વસાવા
*૨૮	રાજય વાહનવ્યવહારની શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોની એસ.ટી. બસૉના રીપેરીંગના અભાવે સંખ્યાબંધ ગામો વાહનવ્યવહારની સુવિધાઓથી વંચિત રહે છે તે બાબતનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી પરેશભાઈ ધાનાણી
૨૯	નર્મદા કેનાલ આધારિત પાણી પુરવઠા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કની પાઈપલાઈનના નબળા કામથી પાણી વિતરણમાં પડતી હાડમારીઓ નિવારવા અંગેનો પ્રવચનમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી	શ્રી છનાભાઈ ચૌધરી

* આ સુધારા સભાગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા નહીં.

શ્રી શંકરભાઈ લ. ચૌધરી(રાધનપુર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૧૧મી ગુજરાત વિધાનસભાના સાતમા સત્રમાં નામદાર રાજ્યપાલશ્રીએ આ સભાગૃહને જે સંબોધન કર્યું તે બદલ તેમનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. હું નામદાર રાજ્યપાલશ્રીનો આભાર એટલા માટે માનું છું કે નામદાર રાજ્યપાલશ્રી જ્યારે આ સભાગૃહને સંબોધન કરવા માટે આવ્યા ત્યારે મારા મનમાં એવું લાગતું હતું કે તેમની ઉંમર, આટલું લાંબું વાંચવાનું એટલે નામદાર રાજ્યપાલશ્રી થોડું ઘણું વાંચીને પૂરું કરશે. મારી સાથે સાથેં ઘણાં બધાંના મનમાં પણ એવું હતું, પરંતુ મારે મહામહિમ્ રાજ્યપાલશ્રીનો હૃદયપૂર્વક આભાર એટલા માટે માનવો પડે કે સતત દોઢ કલાક સુધી આખું સંબોધન વાંચીને આખો વિષય સભાગૃહની વચ્ચે મૂક્યો. એ સંબોધન માત્ર રાજ્યપાલશ્રીનું નહોતું, પરંતુ ગુજરાતના વિકાસ માટેની ગીતા તેમના શબ્દોમાં કહીએ તો એ હતી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એટલા માટે મારે વાત કહેવી છે કે મહામહિમ્ રાજ્યપાલશ્રી તો બહુ અનુભવી વ્યકિત છે. તેમણે જાહેર જીવનમાં અનેક વર્ષો વિતાવ્યાં છે, આ દેશમાં અનેક સરકારોનો વહીવટ જોયો છે. આટલા અનુભવો પછી આ સભાગૃહને સંબોધન કરતા હોય ત્યારે મહામહિમ્ રાજ્યપાલશ્રીએ એ વાત કરી કે સાચા અર્થમાં ગુજરાત સરદાર પટેલ અને મહાત્મા ગાંધીની ભૂમિ ગ્રામ સ્વરાજ્ય તરફથી રામરાજ્ય તરફથી તરફ જઈ રહ્યું છે. આ વાત અમારા જેવા લોકોએ કરી હોત તો ગુજરાતના વિરોધીઓ પૈકીના કેટલાય લોકો તેની ટીકા કરત, પરંતુ આ વાત જ્યારે મહામહિમ્ રાજ્યપાલશ્રીએ કરી છે ત્યારે મને લાગે છે કે ગુજરાતના વિરોધીઓ માટે પણ ચૂપકીદી સેવવી પડે તેવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. મેં અગાઉના સત્રમાં વાત કરી છે અને હું જ્યારે વાત કરતો હોઉં ત્યારે પોલીટીકલ બાબતોથી બહાર ઊઠીને વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોઉં છું. (અંતરાય) સો ટકા, એ વાત પણ કરીશ. માનનીય અર્જુનભાઈની આ ઇચ્છા હોય, પરંતુ અમારો ઇતિહાસ એ નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્યપાલશ્રીએ આખા ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાતની પ્રગતિ એનું અહીં વર્ણન કર્યું છે ત્યારે મનમાં કેટલાક વિચારો સ્વાભાવિક રીતે ઊઠે કે આટલાં વર્ષો પછી ગુજરાતનો વિકાસ કઈ દિશામાં જશે? આ વાત આજે મૂકવી પડે. રાજ્યપાલશ્રીએ આ સભાગૃહને સંબોધન કર્યું અને તેની અંદરથી અલગ-અલગ આયામો બહાર નીકળ્યા છે. કોઈને સહજ આનંદ થાય. વિરોધપક્ષના મિત્રોને પણ આનંદ થશે કે આટલા વર્ષો પછી ગુજરાત સાચી દિશામાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. સૌથી પ્રથમ વિષય લીધો છે જળ વ્યવસ્થાપનનો. જળ વ્યવસ્થાપનમાં ગુજરાત ડંકાની ચોટ પર દુનિયાને કહી શકે કે અમે એક એવું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે કે આવનારી પેઢીઓમાં બાકીના લોકો માટે પથદર્શક બને. ગુજરાતમાં શું નહોતું? ૪૦-૫૦ વર્ષમાં ઘણું બધું થઈ શક્યું હોત એવું ગુજરાતમાં છે. વસતિની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ઈંગ્લેન્ડની છ કરોડની પ્રજા હોય તો ગુજરાતની પાંચ કરોડની પ્રજા છે. દુનિયાના કોઈ પ્રદેશને ન મળી હોય એવી કુદરતી ભેટો ગુજરાતને મળી છે. વિશાળ સમુદ્રકિનારો, ૫૦ ટકા કરતાં પણ વધુ ખેડવાલાયક જમીન, જે ચાઈના જેવા આટલા વિશાળ દેશમાં ભલે તેનો ભૂભાગ આટલા મોટા પ્રમાણમાં હોય પણ તેની ૧૫ ટકા જમીન ખેડવાલાયક છે. એની જગ્યાએ ગુજરાતની કુલ જમીનના ૫૦ ટકા કરતાં પણ વધારે જમીન ખેડવાલાયક જમીન છે.

બીજી વાત કરું તો ભૂગર્ભમાં અનેક વર્ષોથી સુષુપ્ત રહેલા ખનિજ પદાર્થની રાજ્યને સૌથી વધારે કુદરતની ભેટ મળી છે તેમાંની આ એક વાત છે ભૌગોલિક રીતે ત્રણ ઋતુઓવાળો પ્રદેશ છે. જે અન્ય દુનિયાના દેશોમાં જોઈએ તો ભાગ્યે જ મળતું હોય છે. બીજી વાત સૌથી શકિતશાળી આ ગુજરાતની પ્રજા, તેનું ખમીર, તેનું બુદ્ધિચાતુર્ય અને સાહસિકતા. જેના જોર ઉપર ગુજરાતને ઈંગ્લેન્ડ નહીં ઈંગ્લેન્ડથી પણ આગળ મૂકી શકે એટલી તાકાત ગુજરાતમાં હતી અને આ તાકાત હું કહું છું કે આજે આવી છે? અને આજે રાજ્યપાલશ્રીએ વર્ણન કરવું પડ્યું. એ વાત નથી. એ તાકાત વર્ષો પહેલાં હતી. શ્રી અમરસિંહભાઈના જમાનામાં પણ હતી અને એ પહેલાં શ્રી જીવરાજભાઈ મહેતા હતા ત્યારથી હતી. છતાં, ગુજરાત અત્યાર સુધીમાં કોઈ પ્રગતિ ન કરી શક્યું અને ગુજરાતની પ્રગતિ માટેનો નવો ઇતિહાસ, ગુજરાતની પ્રગતિ માટેના છઠ્ઠીના લેખ આ રાજ્યપાલશ્રીએ કરેલા સંબોધનની અંદર છે અને એ વિધાતાએ નિર્માણ કર્યા છે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હાથે આ નિયતિએ નક્કી કરેલી વાત છે, આ હું ડંકાની ચોટ ઉપર કહી શકું છું, આત્મવિશ્વાસ સાથે કહું છું. આ દેશના રાષ્ટ્રપતિશ્રીએ, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ વાત કરી છે કે, ૨૦૨૦ની સાલમાં ભારત મહાસત્તા હશે એમ કેટલાય મહાનુભાવોએ વાત કરી છે, રાજ્યપાલશ્રીએ પણ વાત કરી છે. ગુજરાતના વિકાસ થકી આ દેશનો વિકાસ છે અને આ દેશને ૨૦૨૦ની સાલમાં જે સ્થાન ઉપર લઈ જવાશે એના મૂળ આધાર ઉપર ભૂમિકા ગુજરાતની છે અને ગુજરાત આજે એ દિશાની અંદર આગળ વધી રહ્યું છે. અને શું સ્થિતિ હતી કેટલાય વર્ષો પહેલાં? મને ખબર છે કે, પહેલાં અગાઉના સમયમાં વિરોધપક્ષ તરફથી એક વાત આવતી હતી કે પાણી માટે રમખાણો થશે, પીવાના પાણીના ગૃહયુદ્ધો થશે. ગામડે ગામડે ટૅન્કરો ચલાવવાં પડશે. ચાલીસ ચાલીસ વર્ષ પછી પ્રજા પીવાનું પાણી માગતી હતી. ચાલીસ વર્ષ પછી પણ પ્રજાને પીવાનું પાણી ન પહોંચાડી શક્યા. (અંતરાય) શ્રી અર્જુનભાઈ એક વર્ષ પછી તમે જોજો કે એવી સ્થિતિ નિર્માણ થશે કે

રમખાણો થવાની વાત તો બાજુએ રહી પણ દુનિયાભરની અંદર ન હોય એટલા મોટા પ્રમાણમાં પીવાના પાણીની પાઈપલાઈનો કરીને સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને આખા ગુજરાતના ગામડે ગામડે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે અને કોઈ જગ્યાએ રમખાણો નહીં થાય. પછી લાગ્યું કે આપણે તો વિચારતા હતા કે ટૅન્કરો મુકાશે પછી જેમ અગાઉ થતું હતું, ટૅન્કરોના ભાવ બોલાશે, ત્યાં ઝઘડાઓ થશે. પણ આ ન થઈ શક્યું. શ્રી ગોવાભાઈ વર્ષો સુધી તમે એમને ટૅન્કરો પહોંચાડ્યા છે અને ટૅન્કરોમાં શું થતું હતું? એ આખું ગુજરાત જાણે છે. તમે પાણી નથી આપ્યું. તમે આ દેશને વારસામાં આપ્યો છે ભ્રષ્ટાચાર, તમે આપી છે અરાજકતા, તમે આપી છે અસ્થિરતા, તમારો ઇતિહાસ અસ્થિરતાનો છે. ગુજરાતનો વિકાસ ન થતો હોય તો એમાં એક વાત અસ્થિરતાની છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સૌથી પહેલાં મુખ્યમંત્રીશ્રી જીવરાજભાઈ હતા એમને સ્થિર થવા ન દીધા. (અંતરાય) નર્મદા ડૅમની વાત ત્યાં કરો. તમે તો વર્ષોથી વાતો કરતા હતા. કેટલીય વખત ચૂંટણી આવે ત્યારે *નર્મદાનું પાણી આપીશું, નર્મદાનું પાણી આપીશુ*, આવી વાતો કરો છો. ગોવાભાઈ, નર્મદાનું પાણી પાકિસ્તાનની સરહદ સુધી, આપણી બનાસ નદીમાં, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પહોંચાડ્યું છે. તમે વર્ષો સુધી વાતો કરી છે અને અમે આ વાસ્તવિકતા કરી છે. આ સૂર્યને ધૂળ ઉડાડીને તમે ઢાંકી નહીં શકો, જે સત્ય છે એને છૂપાવી નથી શકાતું. અમારે કોઈના સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી. કોઈના સર્ટિફિકેટના આધારે આ સરકાર નથી ચાલતી. સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે.

"ન અભિસેકો ન સંસ્કાર: સિંહસ્ય ક્રિયતે મૃગા,
વિક્રમાદિત્ય રાજ્યસ્વં સ્વયં મેવમ્ મૃગાધ્રા."

સાહેબ, રાજાઓને, સિંહને કોઈ હરણીયાઓએ રાજ્યાભિષેક કરવાની જરૂર હોતી નથી. એ તો સ્વયં સિંહ છે. એના માટે ગુજરાત વિરોધીઓ, અથવા તો ગુજરાત સરકારના વિરોધીઓના સર્ટિફિકેટના આધારે આ સરકાર નથી ચાલવાની, મારે આ વાત કહેવી છે. માનનીય અર્જુનભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની અંદર કોઈના કોન્ટ્રાકટના આધારે, અશોકભાઈને કદાચ ખોટું લાગે અમદાવાદની ભકિતના કારણે. અમારે ત્યાં કાલ બપોરે આવ્યા, અમારાથી પહેલાં આવેલા માણસો એકદમ બહુ ટોચ ઉપર નથી પહોંચતા. અહીંયાં સિનિયર માણસો બેઠા છે એમની વેદના તો પૂછો? અને કયાં કયાં ચાલે છે? તમે અનેક પક્ષમાં વહેંચાયેલા છો. કાચના દ્‍ારમાં બેસીને કાંકરીચાળો કરવાનો? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમની સ્થિતિ તો જુઓ?

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતમાં વર્ષો પહેલાં એક સ્વપ્ન કેટલાક સ્વાતંત્રવીરોએ જોયું હશે, સાહેબ હું વાત કરું કે બલિવેદી ઉપર ચડતાં પહેલાં વીર ભગતસિંહ, સરદાર અને ચંદ્રશેખર આઝાદે એક ગીત ગાયું હતું વંદે માતરમ્. એ વંદે માતરમ્ ગીત ગાતા ગાતા એ ફાંસીના માંચડા ઉપર ચડી ગયા હતા. બલિવેદી ઉપર આખું તન ન્યોછાવર કર્યુ હતું, મન ન્યોછાવર કર્યુ હતું ત્યારે ગીત શું ગાતા હતા, વંદે માતરમ્, સુજલામ્, સુફલામ્, શું કલ્પના હશે એમની? આ ભારત માતા માટે બલિવેદી ઉપર ચડતા સમયે એ નવયુવાનના મનની અંદર એ ભાવના હતી કે અમારી ભારત માતા, અમારી માતૃભૂમિ સુજલામ્ સુફલામ્ બને અને આ ભારત માતાનો એક પણ દીકરો, એક પણ સંતાન રાત્રે ભૂખ્યો સૂએ નહીં , આ કલ્પના સાથે વંદે માતરમ્નું ગીત ગાયું. ૪૦ વર્ષ પછી આ મહાત્માઓએ જોયું પણ હશે અને ત્યાં આગળ એમના આત્માને શાંતિ પણ મળતી હશે કે ૪૦-૫૦ વર્ષ પછી ગુજરાતની ભૂમિ ઉપરથી એમણે જોયેલું સ્વપ્ન સાચું પડ્યું છે. આજે ગુજરાત સુજલામ્ સુફલામ્ની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. સુજલામ્ સુફલામ્ આ ધરતીને બનાવવા માટે આખા ગુજરાતમાં કેનાલોનું, નહેરોનું, ખેત તલાવડીઓનું, બોરીબંધનું, આડબંધનું એક મોટું જબરજસ્ત અભિયાન ચાલી રહ્યું છે અને સાચા અર્થમાં ગુજરાતની ધરતી સુજલામ્ સુફલામ્ બને એના માટે માત્ર વાત નહીં નાણાકીય જોગવાઈ કરી, એટલું જ નહીં પણ સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે. આટલા સમયમાં આટલું કામ પૂરું કરવું પડે અને એમાં ઝડપી પ્રગતિ ચાલી રહી છે. આજે નર્મદાજીનું કામ ૧૧૦ મિટરનું પૂરું થઈ ગયું છે અને બસ અમને સંતોષ છે એવું નહીં છેક રાજસ્થાનની સરહદ સુધી, કચ્છની સરહદ સુધી એક સાથે પહેલાના સમયમાં ૧૦ કિલોમિટરનું કામ, ૧૨ કિલોમિટરનું કામ વર્ષે દહાડે થાય જયારે આ સરકાર ૧૫-૨૦ પાર્ટના અલગ અલગ નાના નાના ટેન્ડરો આપીને એક સાથે છેક રાજસ્થાનની સરહદ સુધી કામ એકી સાથે ચાલે એ રીતે કામ કરે છે અને આજે રાધનપુરથી છેક રાજસ્થાનની સરહદ ઉપર એક સાથે યુદ્ધના ધોરણે કામ ચાલી રહ્યું છે. દોઢ વર્ષના સમયમાં આ કામ પૂરું થાય અને આ કામ પૂરું થતાની સાથે જે અમારા સરહદી વિસ્તારો છે, જે પાકિસ્તાનની સરહદ ઉપર આવેલા છે, રાજસ્થાનની સરહદ ઉપર આવેલા છે, જ્યાં રણ હરહંમેશ આગળ ધપી રહ્યું છે, એવા વિસ્તારો છે જયાં અમારી પ્રજા વર્ષોથી પાણી માટે વલખાં મારે છે. અમારા વડીલો તો કહેતા હતા કે અમારા જીવતાજીવ આ નર્મદા આવશે કે કેમ? અમે તો જવાન હતા ત્યારથી નર્મદાની વાતો સાંભળીએ છીએ, પણ નર્મદાજી આમારે આંગણે આવશે કે કેમ એ જે સ્વપ્ન હતું એ આજે સાકાર થઈ રહયું છે અને નદીઓ જોડવાનું અભિયાન આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ અને ૨૦ જેટલી નદીઓ જે સૂકી બંજર જેવી પડી હતી, એને નર્મદાના પાણીથી ભરી દેવામાં આવી. છલોછલ વહેતી કરી દેવામાં આવી અને નર્મદાજીનું

કેવડીયા કોલોનીથી છૂટેલું પાણી જયારે અમારી બનાસમૈયાની અંદર પાકિસ્તાનની સરહદ સુધીના વિસ્તાર સુધી પહોંચ્યું અને ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં બનાસકાંઠા અને પાટણની પ્રજા એને વધાવવા માટે આવી હતી અને ત્યારે હું હાજર હતો અને એ સમયે વડીલોના ઉદ્દગારો હતા એ એવન હતા કે, અમે તો સ્વપ્ન જોતા હતા કે અમારે ત્યાં અમારા જીવતાજીવત નર્મદાજી આવશે કે કેમ? પરંતુ આપણા આ નવા ભગીરથી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ નર્મદાજીને અમારા ત્યાં જીવતાજીવત લાવ્યા. અમારો તો જન્મારો પણ જે એળે જવાનો હતો એ જન્મારો સુધારી નાખ્યો. એમની આંખો ભીની અને સ્વર આ હતા એની કલ્પનાનો બહાર બેઠાં વિચાર ન કરી શકો એ દ્રશ્યો અમે જોયા છે. હજારોની સંખ્યામાં જવાનીયાઓ પોતાના માબાપને લઈને ત્યાં આગળ આવતા હતા અને કહેતા હતા કે લો, નર્મદાજીની અંદર તમે સ્નાન કરો અને આ ખાલી એક વખત આવી ગયું એટલું નહીં સીઝનમાં ૩-૩ વખત બનાસ નદીને પૂરેપૂરી ભરી દે અને છેક કચ્છના રણ સુધી બનાસ, સરસ્વતી અને રૂપેણ આ બધી નદીઓની અંદર પાણી વહાવીને ત્યાંના ખેડૂતો આજે મબલખ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન લઈ રહ્યા છે. આ કામ સાચી દિશાનું કામ છે. ખાલી ટેન્ડર આપી આપીને એક નાનકડો સંતોષ નહિ. પહેલાના સમયમાં બંધો તો બંધાતા હશે. પહેલાં કોઈ કોન્ટ્રાકટર બંધાવતા, અત્યારે લોકો બંધો બાંધે છે. ગામડે ગામડે લોક ભાગીદારીથી લોકો જાતે બંધો બાંધે. આટલું પૂરતું નહિ, પરંતુ અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી, અમારી પાર્ટીના કાર્યકર્તા જેમને આ જવાબદારી આપી હતી એવા શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, બધા કાર્યકરો, અમારા મિનિસ્ટરો ખભા ઉપર થેલીઓ ઉપાડીને પ્રજા વચ્ચે જઈને ગરમીમાં પરસેવો પડતો હોય ત્યારે ઈસ્ત્રી ટાઈટ કપડાં પહેરીને નહિ, પરસેવાથી લોથપોથ થઈને અમારા હોદ્દેદારો, કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આખા ગુજરાતમાં બોરીબંધો બંધાયા છે.

ગઈકાલે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એ જ વાત કરી હતી. શિક્ષણના રથમાં પણ કેટલાકને તમાશો દેખાય છે. કોઈ વાત આવે તો તમાશો છે એમ કહે. આ તમાશો શબ્દ મને લાગે છે કે આપણો નથી, આ શબ્દ ઉત્તર પ્રદેશ કે બિહારનો હોય એમ લાગે છે. અહીંયાં આપણે બીજો શબ્દ વાપરીએ છીએ. એમને દીકરીઓને શિક્ષણ આપવાની વાત હોય તો તમાશો લાગે, વાયબ્રન્ટ ગુજરાતના કાર્યક્રમની વાત હોય તો તમાશો લાગે, ચેકડેમ કે બોરીબંધની વાત હોય તો તમાશો લાગે. મને લાગે છે કે ખેડૂતો વગરના ખેડૂતો માટેના ટ્રેકટરની રેલી લઈને જાય તો એમને તમાશો નથી લાગતો? અનેક લોકોના ખભે બંદૂકો ફોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ગુજરાતમાં પહેલો વિચાર કર્યો કે પીવાના પાણી માટે રમખાણો કરાવીએ. એમના મગજમાં ગુજરાતની પ્રગતિ માટે સારી વાત કરી સોંપીએ એવો વિચાર આવતો નથી. એમને વિચાર આવે છે ટેન્કર રમખાણ કરાવીએ, તમાશાની વાત કરીએ. વારંવાર પ્રયત્નો કર્યા પણ કોઈ સફળતા ન મળે અને છેવટે થાકીને આવે અને પછી અંદરો અંદર ચાલે. મૂળ વિષય એ કહેવો છે કે ગુજરાતની અંદર ચાલીસ-ચાલીસ વર્ષ પછી ગુજરાતના ખેડૂતોને પોતાના ખેતરમાં ખેતી માટે પાણીની જગ્યાએ એમ કહેવું પડે કે ધરતીમાંથી ૧૦૦૦ ફૂટ ઊંડેથી પાણી કાઢવું છે માટે વીજળી આપો. આ દુર્ભાગ્ય નથી? ખેડૂતોની આ દશા કરવા માટેનું પાપ કોણે કર્યું? આટલા વર્ષ સુધી ગુજરાતના ખેડૂતોને પાણી ન પહોંચાડી શક્યા, આ જવાબદારી કોની હતી? શું ૧૦ વર્ષમાં અમે આવ્યા પછીનો આ પ્રશ્ન છે? ગુજરાતની ધરતીનું પાણી પારાવાર કાઢી લીધું અને ખેડૂતોનું આવતીકાલે શું થશે એનો વિચાર ન કર્યો? (અંતરાય) મુકેશભાઈ, બાકીનો ઈતિહાસ મારાથી ન કહેવાય તો સારું. વળી ગઈ વખત જેવું થાય. મારો વિષય તો મારે એ કહેવું હતું કે જળ વ્યવસ્થાપનની બાબતમાં જોઈએ તો નર્મદાના વિષયથી લઈને માઈક્રો લેવલે બોરીબંધો, ખેત તલાવડીઓ માટે મોટું કામ કર્યું છે. નર્મદાનું પાણી વિશાળ જથ્થામાં સમુદ્રમાં વહી જતું હોય છે. માઈક્રો લેવલ સુધી ખેતરનું પાણી ખેતરમાં અને ગામનું પાણી ગામમાં રહે એ પણ પ્રજાના સહભાગીકરણથી. આ પ્રજાનું સહભાગીકરણ પહેલાં પણ થઈ શકતું હતું, પણ આટલાં વર્ષ સુધી કેમ ન થયું? ગુજરાતમાં કેટલી સુષુપ્ત શકિતઓ પડેલી છે એ જાણવું એ નાનો વિષય નથી. એના માટે આ ધરતી ખૂંદેલી હોવી જોઈએ. આ ધરતીની કણેકણની સુગંધ આવવી પડે એ માણસ આ કરી શકે. આ ગુજરાતનું નેતૃત્વ જેના હાથમાં છે એણે ગુજરાતના કણેકણની સુગંધ પારખી જાણી છે. જેનાથી આ શકય બન્યું છે. લોકો શું ઈચ્છે છે? અઠવાડિયા પહેલાનો દાખલો છે. અમારા થરા ગામમાં ભરવાડ સમાજના સંમેલનમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી આવ્યા. અઢીથી ત્રણ લાખની પ્રજા ત્યાં હતી, એક ધાર્મિક કાર્યક્રમ હતો. ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સ્ટેજ ઉપરથી એક સંબોધન કર્યું અને સંબોધન કર્યા પછી એમણે વાત કરી કે તમે આવ્યા છો તો મારે તમારી પાસેથી કંઈક માગવું છે એ તમે મને આપશો? અત્યારસુધી કોઈએ વાત નહોતી કરી કે તમારી પાસેથી માગવું છે. હું તને ટુકડો આપું, મુરઘો આપું એ જ વાતો ચાલતી હતી. આપવાની વાત કરવાની જગ્યાએ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમ કહ્યું કે આજે મારે માગવું છે, તમે કંઈ આપશો? અને આપવાના હોય તો વચન આપો અને બે હાથ ઊંચા કરો. મારે આનંદ સાથે કહેવું છે કે ત્યાં બેઠેલી પ્રજાએ, અઢીથી ત્રણ લાખ લોકોએ બે હાથ ઊંચા કરીને કહ્યું કે તમે માગો, તમે માગો એ અમે આપીશું. અને સાહેબ ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું છે મારે એ માગવું છે કે અહીં આગળ ઉપસ્થિત તમામ વ્યકિતઓ પોતાની દીકરીને ભણાવે અને એકપણ વ્યકિતની પોતાની દીકરી ભણ્યા વગરની ના રહે એનું મને વચન આપો. ફરી હાથ ઉચા કરવામાં આવ્યા અને પ્રતિજ્ઞા કરાવી, ત્યાં આગળ વાળીનાથ ભગવાનની સાક્ષીએ લોકોએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે, અદ્‌ભૂત દાખલો છે. આ વાતને માત્ર પોલિટિકલ દ્રષ્ટિથી ના જોવી જોઈએ અને હું તો વાત કરું છું કે આવું

વ્યકિતત્વ જો કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર બેઠા હોય ને તો પણ અમે કહીએ કે આ ગુજરાતનું ગૌરવ છે, પણ દુર્ભાગ્ય એ છે કે વિરોધપક્ષ આવું વ્યકિતત્વ નથી મેળવી શક્યો. નરેન્દ્ર મોદી એ માત્ર કોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની વાત નથી, નરેન્દ્ર મોદી એ માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી કે કોંગ્રેસ પાર્ટીનું વ્યકિતત્વ નથી, નરેન્દ્ર મોદી એ ગુજરાતની આવતીકાલને ગુજરાતને દુનિયાની ચોટ ઉપર, દુનિયાના ડંકાની ચોટી પર ગુજરાતને આગવું સ્થાન અપાવવા માટેનું વિદ્યાતાએ નિર્માણ કરેલું વ્યકિતત્વ છે. આ વાતને તમારે સ્વીકારવી પડશે અને આ બાબતને તમે ના સ્વીકારી શકતા હોય તો તમારું તમને મુબારક છે. પાર્ટી પૉલિટિક્સથી ઉપર ઊઠો, ભાઈ-મિત્રો, રાજનૈતિક બાબતથી ઉપર ઊઠીને ગુજરાતનું ભલુ ક્યાં આગળ થઈ રહ્યું છે તે દિશામાં કોંગ્રેસના મિત્રો તમારે એ વિચાર કરવો પડે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શિક્ષણની બાબતમાં આમૂલ પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે, મહામહીમ રાજ્યપાલશ્રીએ વાત કરી. એમની વાતોમાં જે એનો અર્થ હતો જે અત્યાર સુધીમાં નહોતું થયું, દુ:ખ થાય, ગઈકાલે, પરમ દિવસે ચર્ચા ચાલતી હતી અને માનનીય મુખ્યમંત્રીએ એનો જવાબ પણ આપ્યો હતો. શિક્ષણની ટકાવારી - ડ્રોપ આઉટ રેશિયો જે આખા રાજ્યની અંદર ક્યાં પહોંચ્યો હતો? જે બાળક ભણવા જાય એની ટકાવારી, નામકરણ ૫૦ ટકા, ૩૫ ટકાએ પહોંચ્યું હતું, દીકરીનું તો ૩૦-૩૫ ટકા રહેતું હોય અને ભણવા ગયા પછી પણ ડ્રોપ આઉટ રેશિયો કેટલો? શાળામાં ગયેલા વિદ્યાર્થી ત્યાં આગળ ૭ - ૭ ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ જ ના કરે, ૫૦ ટકા સુધીના બાળકો ૭ ધોરણ પહેલાં ઊઠી જાય આવી સ્થિતિ ગુજરાતમાં હતી. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વાત આપી કે રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ અને અધિકારીશ્રીઓ બધા ગામડે ગામડે જઈને પ્રજાને સમજાવે અને ખાલી કાર્યક્રમ નહિ એકેએક ગામડે ગામડે ફરીને, ગરમીની અંદર પરસેવો વળતો હોય, અમારે ત્યાં માનનીય મંત્રીશ્રી આઈ.કે.જાડેજા આવ્યા હતા એ સરહદી ગામની અંદર જતા હતા જ્યાં આગળ રણપ્રદેશની એકલી ઉનાળાની લૂ આવતી હોય, ત્યાં એવા પ્રદેશમાં જઈને ગામના લોકોને વાત કરી, માતા-બહેનોને ભેગા કરીને કહે કે તમારી દીકરીને ભણવા માટેનું કહેવા માટે અમે અહીં આવ્યા છીએ અને ગામના લોકો સહજ સ્વીકારી લે. અરે, સરકાર અમારી દીકરીને ભણાવવા માટેનું કહેવા માટે છેક ગાંધીનગરથી અહીં આગળ કહેવા માટે આવી અને આ વાત બહેનો માટે ખૂબ અપીલિંગ હતી અને એમણે માતાઓને કહ્યું હતું કે, તમારી દીકરીને તમે ભણાવો અને સાહેબ, એના પરિણામ સ્વરૂપ નામાંકરણ થયેલું આટલા મોટા પ્રમાણમાં અને ડ્રોપ આઉટ રેશિયો પણ ઘટીને એનો ગ્રાફ ઉત્તરોત્તર નીચો આવ્યો. આ સ્થિતિ વર્ષો પહેલાં થઈ શકી હોત, પરંતુ પહેલાંની સ્થિતિ કેવી? બાળકોને ભણવા મૂકવા હોય પણ શિક્ષક ના હોય. ૧ થી ૪ ધોરણ હોય, ખુરશી આમ ફેરવે એટલે પહેલું ધોરણ, ખુરશી આમ ફેરવે એટલું બીજું ધોરણ. શાળાના ઓરડા પણ ના હોય, શાળામાં રૂમ પણ ના હોય, આ સુવિધા જ ના હોય ત્યાં શિક્ષકની વાત કરવી કેવી અલગ વાત લાગે છે. એવા સંજોગોમાં રાજ્ય સરકારે નવી નેમ, આટલા વિશાળ પ્રમાણમાં શિક્ષકોની ભરતી, આ આટલા મોટા પ્રમાણની અંદર શાળાના ઓરડા આપ્યાં અને એટલું જ નહિ પાયાથી શિક્ષકોને ટ્રેનિંગ આપીને એક આગવું શિક્ષણ ગુજરાતનું બનાવે, ગુજરાતની આવતી પેઢી, આવતીકાલ યશસ્વી બને એના માટે પ્રયત્ન કર્યો છે. મારા વિસ્તારમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને શિક્ષણમંત્રીશ્રી મારાં પ્રભારીમંત્રી છે એમના માર્ગદર્શનમાં મારા વિસ્તારથી એક નવો પ્રયોગ થયો. જિલ્લાભરની પી.ટી.સી. કોલેજોએ એમણે વિચાર કર્યો, બાકીના બધા સંચાલકો મળીને, એક તાલુકો એવો લઈ જેની અંદર જેટલા અભણ વ્યકિત એમને ભણવા માટે શાળા કૉલેજના વિદ્યાર્થી ત્યાં આગળ જાય એક પણ રૂપિયાના ખર્ચા સિવાય રાધનપુર, સાંતલપુર વિસ્તારની અંદર આ પ્રયોગ થયો. અમારાં જિલ્લાના સાડા ચારસો જેટલા કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓએ પાંચ-પાંચ વિદ્યાર્થીની એક ટીમ બનાવીને ગામડે ગામડે પહોંચ્યાં. સાથે તેના સ્થાનિક શિક્ષકો ગોઠવાયા, ગામની અંદર જે ભણેલા યુવાનો હતા એ પણ એમની સાથે જોડાયા. દિવસે શાળાના વિધાર્થીઓ જે ભણવામાં કાચા હોય એમને અલગ તારવીને ભણવામાં તૈયાર કરવા, લખતા-વાંચતા કરવા અને રાત્રીના સમયે, જે લોકો ચાળીસ-ચાળીસ વર્ષ સુધી ભણી નથી શક્યા, એમનું આયખું ભણ્યા વગરનું જતું રહ્યું એવા લોકોને ફરી નિશાળમાં બેસાડવા માટેની વાત કરી. રાત્રીના બાર-બાર વાગ્યે પણ મોટી સંખ્યામાં બહેનો પણ ત્યાં પહોંચતી હોય અને પરિણામ એ આવ્યું કે, મારા વિસ્તારમાં એક રાત્રીએ જ્યારે અમે અમારા કલેકટરશ્રી સાથે ગામડામાં જોવા ગયા કે આ કાર્યક્રમ ચાલે છે ખરો,કઈ રીતે ચાલે છે,શું છે? ત્યારે રાત્રીના અગિયાર વાગ્યા સુધી બહેનો અને ભાઈઓ, ખેતી કામ કરીને આવ્યા પછી એ બધા ભણતા હતા અને બોલતા હતા કે સાહેબ હું ભણવાનું શીખી ગઈ, મને વાંચતા અને બોલતા આવડી ગયું, લાવો હું લખી કે વાંચી બતાવું. ચાળીસ વર્ષ સુધી એના મનમાં પડેલું હતું કે મારે લખવું છે, ભણવું છે,મારે વાંચતા શીખવું છે, પરંતુ આવી કોઈ વ્યવસ્થા નહતી. આ રાજ્ય સરકારે આવી વ્યવસ્થા કરી અને માત્ર એ વિસ્તાર પૂરતું જ નહીં, આખા ગુજરાતમાં જ્યારે આ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે હું આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું કે, આના કારણે જ આવતીકાલનું ગુજરાત બનશે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એ વાત પણ કરવી છે કે, ખેડૂતો માટે આ રાજ્ય સરકારે માત્ર એને લલચાવવાની વાત નથી કરી. ખેડૂતોની ખેતીની આવક કઈ રીતે સુધરી શકે, ખેતીમાં ખેડૂતો પાંચ વર્ષની અંદર પોતાનું ઉત્પાદન ડબલ કઈ રીતે કરી શકે, આ વચન રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આપ્યું અને કહ્યું કે, રાજ્યના

ખેડૂતો આવનારા પાંચ વર્ષમાં પોતાનું ઉત્પાદન ડબલ કરે અને આ મુખ્યમંત્રીશ્રી બોલે છે એ પૂરું કરે છે આવો આખા ગુજરાતને વિશ્વાસ છે. એમણે કહ્યું છે કે, આગામી પાંચ વર્ષમાં ગુજરાતના ખેડૂતોનું ઉત્પાદન ડબલ, એની આવક ડબલ કરવી છે. સાહેબ, ચારેય દિશાએથી આ પ્રયત્નો ચાલી રહ્યાં છે, જીએસએફસી અને જીએનએફસી આ બધી સંસ્થાઓ ખેડૂતોને ખાતર આપતી, આપેલા ખાતરમાંથી ચાળીસ-ચાળીસ વર્ષો સુધી તમે નફો કર્યો હોય, તમે નુકસાન કર્યુ હોય, તમે કયાં પૈસા મૂકયા એ વાતમાં મારે નથી પડવું, પણ આ ખેડૂતોની સંસ્થાના ખાતરમાંથી પૈસા આવે, એમનો નફો થાય, એ નફો બીજી જગ્યાએ કેમ મૂકાય? એ ખેડૂતોના ખેતરમાં જે ખેડૂતો ખાતર લઈ ગયા, ખેડૂતોના ખેતરમાંથી આવેલ નફો એ પાછો ખેડૂતોને આપવાનું તમારા મગજમાં કેમ ન સુઝયું? પહેલી વખત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વાત કરી છે કે, આ બંને સંસ્થાઓમાં જે નફો થતો હોય એમાંથી ખેડૂતોના ખેતર સુધી ફરી પાછા એ પૈસા પહોંચે, એનો નફો અને સ્પ્રિન્કલર અને ડ્રીપ ઈરીગેશનના માધ્યમથી ખેડૂતોની આબાદી વધે એના માટેના પ્રયત્નો ચાલુ કર્યા છે. શું આવો વિચાર આટલા વર્ષો સુધી તમને નહોતો આવતો ? ના, વિચાર કરે તો બાકીનું બધું ગોટાળે થઈ જાય.

હું વાત કરું છું, પહેલાં જ મેં વાત કરી કે ૩૫ લાખ - ૪૦ લાખની આવક જો આર.ટી.ઓ. ચેક પોસ્ટોની હોય તો એના થોડાક ફેરફાર કરવા છે, બે-ચાર વર્ષમાં ૮૦૦ કરોડથી પણ વધારે આવક સુધી પહોંચી શકાય, તો ચાળીસ વર્ષો સુધી શું આ ૪૦-૪૦ કરોડ પ્રમાણે જ આવક આવતી હતી? પહેલાં ચેક પોસ્ટો ઉપર કોઈ વાહનો નીકળતા જ નહોતાં અને પૈસા ટેક્સના ભર્યા હતા એ સરકારની તિજોરીમાં ચાળીસ વર્ષો સુધી સરકારમાં જમા કેમ ન થયા? ૮૦૦ કરોડ સુધીની આવક જો અત્યારે મળી શકતી હોય તો આ ચાળીસ વર્ષ સુધી આ પૈસા જમા કેમ ન થયા એ પ્રશ્ન પૂછું છું? એનો જવાબ આપવો જોઈએ તેમણે. (અંતરાય) અરે વાહનોનું પ્રમાણ એક બે વર્ષમાં વધ્યું, ચાળીસમાંથી સીધા ૮૦ કરોડ, ૮૦૦ કરોડ? સ્વાતંત્ર મળ્યા પછી તમારે કરવા જેવાં કામો નથી કર્યા, સ્વાતંત્ર મળ્યા પછી તમે જો કાંઈ ભેટ આપી હોય તો ભ્રષ્ટાચારની ભેટ આપી છે, મિત્રો શું આપ્યું છે? મહાત્મા ગાંધીજીએ કલ્પના કરી હતી , સરદાર પટેલની કલ્પના હતી, ગ્રામ સ્વરાજની. પણ એ વાત આ કોંગ્રેસને? કોંગ્રેસ મહાત્મા ગાંધીજીની વાત કરે છે પણ ગાંધીજીની વિચારધારા ઉપર કાંઈ લેવાદેવા નથી. આજે વાત કરશે તો શું કહેશે, કોને ઓળખે છે? મહાત્મા ગાંધીજીને નથી ઓળખતા, સરદાર પટેલને નથી ઓળખતા. એમને વાત કરો તો હા, જવાહરલાલ નહેરું, શ્રીમતી ઇન્દિરાજી, માનનીય રાજીવજી એ પછી સાહેબ સોનિયાજી એ પછી પ્રિયંકા આ બધાની યાદી પૂછો તો ખબર હશે અને પ્રિયંકાનો નાનો બાબો એની પણ ખબર હશે પણ આજે જઈને પૂછો કે સરદાર પટેલ કે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર. એમના દીકરાના દીકરાનું નામ શું છે? તો આજે મને જવાબ આપે, નહીં ખબર હોય કારણ કે એમના વિચારો અલગ છે.એ સરદારને ભૂલી ગયા, સરદાર સાથે એમને લેવાદેવા નથી(અંતરાય) બાજપાઈએ લગ્ન નથી કર્યા. બાજપાઈ આ દેશના પનોતા પુત્ર છે જેણે આખું જીવન રાષ્ટ્ર માટે સમર્પિત કર્યું છે. માત્ર હિન્દુસ્તાન નહીં, આખી દુનિયા જેને માટે ગૌરવ લઈ શકે. બાજપાઈએ દિશા આપી એ દિશા ઉપર તમારા લોકો ચાલી રહયા છે. તમારી ઈન્દીરા આવાસ યોજના કે સરદાર આવાસ યોજના હોય અમે કયારેય કિન્નાખોરીની રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કયારેય આ રસ્તો નથી પકડયો. આજે બાજપાઈનું નામ લેવામાં આવતું હોય એવા યુગપુરૂષ જેમણે કયારેય એવી વાત નહોતી કરી કે અગાઉના સમયમાં મુકેલી કોઈ યોજનામાં ઈન્દીરા ગાંધીનું નામ હોય, સરદાર પટેલનું નામ હોય, ત્યારના શાસક પક્ષના નામે હોય, અત્યારના વિરોધપક્ષના નામે હોય એવી એક પણ યોજના હટાવી નથી. પણ દુર્ભાગ્ય એ કહેવાય દેશની અંદર રસ્તા બનાવવાના હોય, આખા દેશને સાંકળવા માટેના રસ્તા બનાવ્યા છે એકસપ્રેસ હાઈવે, રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ તથા વડાપ્રધાન એ વખતના બાજપાઈજીના નામે રસ્તા બન્યા અને એના ફોટા લાગેલા હતા. સરકાર આવવાની સાથે એ કામ કર્યુ બાજપાઈજીના ફોટા રસ્તા ઉપરથી ઉતારવાનું(અંતરાય) સાહેબ, મારે એ કહેવું છે કે રસ્તા ઉપરથી ફોટા ઉતારી શકશો, પણ દેશની પ્રજાના હ્રદયમાંથી બાજપાઈજીનું નામ તમે નહીં મિટાવી શકો. એમનાં આદર્શો, એમનું જીવન અને વહીવટ સદીઓ સુધી દેશ યાદ રાખશે. તમે બાજપાઈના ફોટા ઉતારી શકો બીજું તમે કરી પણ શું શકો? મિત્રો, તમારી પરંપરા રહેલી છે. તમારી પાસે ગુજરાત બીજી અપેક્ષા રાખે તો પણ વધારે પડતું છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે સભાગૃહમાં એ વાત કહેવી હતી કે ગરીબમાં ગરીબ માનવી હોય એનો હાથ પકડવા માટે પંડિત દિનદયાલ ઉપાધ્યાય જેમણે સ્વપ્ન જોયું હતું તેમણે કહયું કે 'ચલો જલાયે દિપ વહાં, જહાં અભી ભી અંધેરા હૈ.' ૪૦ વર્ષ પછી, આટલાં વર્ષોની લોકશાહી પછી એવી કેટલીક જ્ઞાતિઓ છે કે જેમની વાત સાંભળતાં આંખમાં આંસુ આવી જાય. મદારી જ્ઞાતિ એવી છે કે જેને વાદી-મદારીના નામથી લોકો ઓળખે છે. આજથી એક વર્ષ પહેલાં મારી પાસે આવ્યા. હું હોસ્પિટલમાં ગયો હતો. મેલેરીયાના મોટા પ્રમાણમાં દર્દી ત્યાંથી આવતા હતા. એમને મળ્યા પછી વાત કરતાં મને જાણવા મળ્યું કે આટલા વર્ષોથી સ્વતંત્રતા મળી, આટલી પંચવર્ષીય યોજનાઓ હતી, પરંતુ એક પણ લાભ એમના સુધી પહોંચ્યો નથી. ઈવન રેશન કાર્ડમાં નામ પણ એમનું નથી. આ દેશમાં રહેતા હોવાછતાં એમના દાદાના દાદા આ દેશમાં રહે છે. છતાંપણ મતદાર યાદીમાં નામ પણ એમનું નથી. આ દેશની અંદર કોઈપણ ખૂણામાં એમને રહેવા માટે જમીનનો એક ટુકડો પણ નથી. એમના બાળકનો જન્મ પણ ખુલ્લા આકાશ નીચે પ્લાસ્ટીકથી બાંધેલા એક ટેન્ટ કે તંબુમાં અને મૃત્યુ પણ ટેન્ટમાં થાય. વર્ષો સુધી(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : ભીખુભાઈ પ્લીઝ.

શ્રી શંકરભાઈ લ. ચૌધરી : વાસ્તવિકતા સ્વીકારવી જોઈએ. હું એમ નહીં કહું કે આ પાપ કોણે કર્યું. પરંતુ મારે વાત એ કહેવી છે કે આવી વાદી જ્ઞાતિનો કોણ હાથ પકડે. એની સાથે ગયા પછી વિચાર કર્યો કે આનો કોણ ઉત્થાન કરે. એ લોકો કહે કે અમારા બાળકોને ભણાવવા છે. મારા ગામની અંદર ૨૫૦ જેટલા પરિવારોને ત્યાં આગળ લાવ્યા. એ લોકો કહે છે કે અમારે બાળકોને ભણાવવા છે. અમારે ભીખ નથી માગવી. મહેનત કરવી છે, મજૂરી કરવી છે. મજૂરી કરવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપો. રાજ્ય સરકારે લોકોને અહી લાવીને એક જગ્યા ઉપર વસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ સરકાર આવા નિરાધાર લોકોની આધાર બની. પંડિત દીનદયાલ આવાસ યોજના અંતર્ગત અનેક લોકોને આવા નાના નાના સંકુલની અંદર વીસ, પચાસ, સો, દોઢસો લોકોની અલગ અલગ કૉલોની બનાવી અને એમને છત પૂરું પાડ્યું છે. એમનાં બાળકોનો જન્મ ખુલ્લા આકાશ નીચે નહિ થાય. કોઈનું મૃત્યુ ખુલ્લા આકાશ નીચે નહિ થાય. એમને રહેવા માટેની ઘરની વ્યવસ્થા થઈ. કેટલાક લોકો બાકી રહી ગયા છે, એના માટે રાજ્ય સરકારે બજેટની અંદર નવું આયોજન કર્યુ છે. આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને હું અભિનંદન આપું છું કે એમણે આવા ગરીબોનાં આંસુ લૂછવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધનની અંદર, થોડા શબ્દોની અંદર વાત કરું તો એવું કહી શકાય કે ગુજરાતના વિકાસ માટેની આ ગીતા છે. આવનારો ઈતિહાસ આ રાજ્યપાલશ્રીનું જે સંબોધન છે, એ માત્ર સંબોધન નહિ, પરંતુ એક દસ્તાવેજી પુરાવો બનશે. આવનારો સમય એમ કહેશે કે આ ગુજરાતના વિકાસ માટેનો છઠ્ઠીનો લેખ એ અગિયારમી વિધાનસભાના સાતમા સત્રની અંદર આ વિધાનસભાની અંદરથી નખાયો છે. વિધાતાએ નિર્મિત કર્યુ છે આ કામ પૂરું થઈને રહેવાનું છે જ. સાથે ઘણી વખત વાત કરતો હતો કે કેસરિયા રંગથી કેટલાક લોકોને એલર્જી થતી હોય છે. વાત કેસરિયા રંગની આવે, એટલે એવું થતું કે અમારા ઢોર હોય ને એ રાતું કપડું ભાળે એટલે ભડકતા હોય છે. આવું થતું હોય છે. કેસરિયો કલર જનસંઘને ધ્યાનમાં રાખીને બનેલો નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીને ધ્યાનમાં રાખીને નથી બનેલો. કેસરિયો કલર અને કેસરિયો કલરવાળા લોકો આ ગુજરાતને શાંતિનો સંદેશો આપે છે, આવી વાત વર્ષો પહેલા કવિ નમર્દે કરેલી. કવિ નર્મદે કહેલ વાત જે ગુજરાતમાં ગુર્જરીનું વર્ણન કર્યુ છે એની અંદર આ વાત આવે છે. " જય જય ગરવી ગુજરાત, દિશાએ અરૂણ પ્રભાત ધ્વજ પ્રકાશશે ઝળહળ કસુંબી ". એમને જે એલર્જી થાય છે. એ કલર, એ કસુંબી, એ કેસરિયો ઝળહળ કરતો ધ્વજ પ્રકાશશે, એ જ પ્રકાશ આવતા ધ્વજની નીચે રાજ્યની પ્રગતિ થશે અને રાજ્યને શાંતિનો સંદેશો આપશે. વર્ષો પહેલાં જનસંઘની સ્થાપના પહેલા આ વાત કવિ નર્મદે ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું. આ વાત આજે સાચી પડે છે. ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાતની પ્રગતિ વિધાતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હાથે જ નિમિત્ત કરેલ છે. ઘણી વખત બેઠાં બેઠાં વાત કરતા હોઈએ છીએ કે ૧૯૯૦ પછી કોંગ્રેસ સત્તા ઉપર આવતી જ નથી. કેમ ? એમણે વિચાર કરવો જોઈએ. આટલી મહેનત કરે, આટલા ધમપછાડા કરે, આમ કરે તેમ કરે. અહી કોંગ્રેસમાં ગયેલા હોય અને ફરી પાછા લઈ આવે, ભાજપમાંથી ગયેલા હોય એક વાર ગાળો બોલે અને ફરી પાછા લાવી એમના પ્રમુખ બનાવે, અનેક પ્રશ્નો પછી પણ. મિત્રો, વિચાર કરો આ વાત વિચારવાની છે. આ વાતનો ઉકેલ ન મળતો હોય તો અશોકભાઈ પાસે ટ્યૂશન રાખો. તમને કહેશે કે શું કામ નથી આવતી. અનેક વર્ષોથી સ્વપ્ન જુએ છે. આ લોકો અસ્થિરતાની જનની એ કોંગ્રેસ છે, જેના કારણે ગુજરાતની પ્રજા સ્થિરતા ઇચ્છે છે. ગુજરાતની પ્રજા ઇચ્છે છે કે ગુજરાતની પ્રજાનું અલગ અલગ મૂળ હોય છે. એને કોઈ એમ કહે કે મને આપ, મને આપ, મને ગમે તેમ કરીને આપો, મને ગમે તેમ કરીને આપો તો ગુજરાતની પ્રજા કયારેય નથી આપતી. ગુજરાતને ખબર છે જીવરાજ મહેતાની સરકાર તોડવાવાળા કોણ હતા? ગુજરાતની પ્રજાને ખબર છેકે ચીમનભાઈ પટેલની સરકારને તોડવાવાળા કોણ હતા? ગુજરાતની પ્રજાને ખબર છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેશુભાઈ પટેલની સરકારને તોડવામાં મદદ કરવાવાળા કોણ હતા. શંકરસિંહ વાઘેલાને એક વખત ટેકો આપી બીજી વખત, બીજી વખત એમ કહેતા હોય કે (અંતરાય) સાહેબ, મારે એ વાત કરવી છે કે એમ કહેતા હોય કે શંકરસિંહ ભ્રષ્ટાચારી હતા. તેઓની સામે રાજ્યપાલશ્રીને આવેદનપત્ર આપે, રાજ્યપાલશ્રીને આવેદનપત્ર આપી એમ કહે કે સાહેબ અમે આવા ભ્રષ્ટાચારી માણસ કયાંય જોયા જ નથી. અમે ટેકો પાછો ખેંચી લઈએ છીએ અને ફરી એજ વાત કરેલી, એ જ મોંઢે વાત કરેલી. પોતે જ અસ્થિર કરેલી સરકાર અને તે જ વ્યકિતને લાવીને પોતાના ખોળામાં બેસાડીએ, તેટલું જ નહીં માથે બેસાડીએ અને અત્યારે કહે કે આ તો સારા થઈ ગયા છે, દૂધે ધોયેલા છે. આ ઈતિહાસ ગુજરાતની પ્રજાની સામે છે. ગુજરાતની પ્રજાને તમે ભ્રમિત નહીં કરી શકો. ગુજરાતની પ્રજા તમે ઈચ્છતા હોય તેવું બિહાર, તેવું યુ.પી. અને બાકીના પ્રયત્નો કરીને બહારથી ઉદાહરણો લાવીને અમલમાં મૂકો એ શકય જ નથી. તેના માટે પછી ટ્રેક્ટર ઉપર બેસી પ્રજા સાથે આવતી ન હોય તેવી ખેડૂત વગરની રેલીઓ કાઢો તેનાં કારણો પ્રજા તો સમજી શકે છે. પ્રજાને ખબર છે કે અમારા ખભા ઉપર બંદૂક રાખીને ફોડવા માગો છો. ગુજરાતની પ્રજા સમજુ પ્રજા છે. કોગ્રેસના લોકો પારખી શકતા નથી અને તેના કારણે અસ્થિરતા માટે લોકો વારંવાર પ્રયત્નો કરતા હોય છે અને જયારે જયારે અસ્થિરતા માટેના પ્રયત્નો કર્યા છે ત્યારે ત્યારે પ્રજાએ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એ વાત કરવી છે. ના, ના ઘણું નથી. મને લાગે છે કે જવાબ આપવો જોઈએ. અહીં બેઠાં બેઠાં લોકો અલગ અલગ વાતો કરે છે. મારે તમારા ભવ્ય ભૂતકાળનાં દર્શન કરાવવાં નથી. એ નથી યાદ દેવડાવવું કે ગુજરાતની અંદર આતંકવાદને પોષવા માટે આ રાજ્યના મંત્રીશ્રીની ગાડીમાં હથિયારો આવતાં હોય. આ તમારા ભવ્ય ભૂતકાળને અહીં ઉલ્લેખવો નથી. ગુજરાતની પ્રજાને ખબર છે. પ્રજાના રક્ષકો હોય તે રક્ષકોની અંદર પ્રજાને ભક્ષવા માટે કરીને મોતનો સામાન આવતો હોય અને તે પણ લાલ લાઈટવાળી ગાડીઓની અંદર, તેમાં શસ્ત્રો આવતા હોય, કોણે લતીફ નામના બુટલેગરને, દારૂના બુટલેગરને મોટો અંડરવર્લ્ડનો ડોન બનાવ્યો હતો? આ પાપ કોણે કર્યુ છે? કેવો હતો તમારો ઈતિહાસ? તે ઈતિહાસ મારે ખોલવો નથી. આ ભૂતકાળ તમે તમારી પાસે રાખો. તેનાં પાનાં જેટલાં ઢાંકયાં રાખો એટલું તમારું ભલું છે. આની અંદર તમારે પડવા જેવું નથી. મારે એક વાત કરવી છે કે ગુજરાતનું ભલું કયાં છે? ગુજરાતી પ્રગતિ સાચી દિશામાં થઈ રહી છે ત્યારે સાથી પક્ષો પણ તેમાં સમર્થન કરે. માનનીય રાજ્યપાલશ્રીએ જે પ્રવચન કર્યુ છે તે ખરેખર માત્ર કોઈ પાર્ટી, કોઈ સરકાર માટે નહીં. ગૃહના તમામ સભ્યો સાથે મળીને તે દિશામાં આગળ વધે અને તેના માટે વેદની ઋચા છે તેમાંથી પ્રેરણા લઈએ. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે, " સૌ સાથે મળી ચાલીએ, સૌ સાથે મળી વિચારીએ" દેવતાઓ પણ આવું જ કરતા હતા. મને લાગે છે કે એમાંથી પ્રેરણા લઈએ. સંસ્કૃતનો એક શ્લોક છે કે " સંઘત્વધમ સંઘત્વધમ સંઘો મનાસ જાનત, દેવા ભાગે પ્રથાપ્રવે સંજાનાના ઉપાસતે."

શ્રી પ્રબોધકાંતદા.પંડયા(સંતરામપુર): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અગિયારમી ગુજરાત વિધાનસભામાં મહામહિમ નામદાર રાજ્યપાલશ્રીએ જે પ્રવચન આ હાઉસના સભ્યો સમક્ષ કર્યુ અને આ હાઉસના સભ્ય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીએ તે અંગેનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે તેને હું મારું અનુમોદન આપવા માટે ઉભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વિરોધપક્ષના સૌ સાથી સભ્યશ્રીઓ જાણે છે કે, માનવ શરીરમાં રૂધિરાભિસરણ તંત્રમાં બ્લડ એક અગત્યનું પરિબળ છે, એમ રાજ્યના વિકાસમાં રસ્તા, પાણી અને લાઈટ, they are known as the circulatory system of economic body.સમગ્ર રાજ્યના વિકાસ માટે મૂળ પાયામાં રહેલી આ ત્રણ બાબતો છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આ નાડ બરાબર પારખી ગયા છે અને એટલા માટે આ ત્રણે બાબતોને રાજ્યના ગામડાંના ઉત્થાન માટે બેઝીક કન્સેપ્ટ તરીકે સ્વીકારીને જે ભગીરથ પ્રયાસો કર્યા એ માનનીય મંત્રીશ્રીઓના સાથ અને સહયોગથી એને બિરદાવ્યા સિવાય હું રહી શકતો નથી, અથાગ પ્રયત્નોના આધારે નર્મદા બંધની ઊંચાઈ ૧૧૦.૬૪ મિટર કરવાનું, કેન્દ્રમાંથી મંજૂરી મેળવવી અને મેળવ્યા પછી નિયત સમય મર્યાદામાં એ કામગીરી પૂરી કરવી. પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી અટલબિહારી બાજપાઈનું એક સ્વપ્ન હતું. રિવરગ્રીડ યોજનાનું એ જુદી જુદી દશ નદીઓને સરસ્વતી, રૂપેણ, બનાસ, હિરણ, સરસ્વતી, દમણગંગા, સાબરમતી, એ બધી નદીઓને જોડવાનું ભગીરથ કામ કરવાનું કામ કરીને આ રાજ્ય સરકારે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યુ છે. એ વાત વિરોધપક્ષના માનનીય મિત્રઓએ સ્વીકારવી પડે એવી છે. હું કોઈ રાજકીય અવલોકનો કરવા તૈયાર થયો નથી કે ઊભો થયો નથી. (અંતરાય) હા, હું હતોને એટલે તો હું કહું છું પણ જે સત્ય છે એ તો મારે કહેવું જોઈએ. ઉમાશંકર જોષી કવિતાઓ લખતા હતા પણ એને અમલમાં મૂકવાનું કામ હાલના માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ કર્યુ છે. એ ઉમાશંકર જોષી એમ લખતા હતા, આપણે ખાલી કોમેન્ટમાં ના પડીએ. ઉમાશંકર જોષી એમ લખતા હતા કે, "સિંચી સિંચી જળાહ્રદયનાં પથરાળી ધરામાં, કઈ ઉગાડું કઈ વહી શકું અંતરે વાદળેવા."

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતની ધરતીને હરિયાળી બનાવવાનું કોઈએ કામ કર્યુ હોય તો માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને માનનીય સિંચાઈ મંત્રીશ્રી નરોત્તમભાઈ પટેલને ફાળે જાય છે. એનો ઈતિહાસ હું તમને આગળ ધીમે ધીમે આપતો જઈશ. એટલે કોમેન્ટ કરવાનું ટાળજો. દશ નદીઓને રિવરગ્રીડ યોજના હેઠળ...(અંતરાય) હું હતો મારી સરકાર નહોતી કરી શકી એમ કહેવા દો મને, હા, આપની દલીલ એમ છે કે, એ વખતે વરસાદ બહુ પડતો હતો એટલે જરૂર ન હતી, તમારી દલીલ સામે કોઈ ઇતરાજ નથી ધારોકે, એટલે તમે કોમેન્ટ કરવાનું ઓછું કરજો અને બને ત્યાં સુધી એને સમજવાનું, જે સારૂં થયું છે એને આમ હ્રદયભેર ઉમરકાભેર સ્વીકારવાની ખેલદિલી વિધાનસભાના સભ્યો તરીકે આપણે કેળવવી જ જોઈએ. એમાં મહાનતા છે, નાનમ નથી. અને ટીકાટીપ્પણ કરવી એ આપણને એવા તબક્કે લઈ જાય છે, સ્મશાનમેં ખુપડીઓકો ઠુકરાના તો ગીધડ ભી જાનતે હૈં. હું ઇચ્છું કે, આપ એ કામમાં ન પડો એ વધારે આવકારદાયક છે.

અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર રાજ્યમાં ખેતીલાયક વિસ્તાર ૧૨૪ લાખ હેકટર જમીનમાં ખેતીલાયક વિસ્તાર છે. એમાંથી ૬૪ લાખ હેકટર જમીનને સિંચાઈની સુવિધા આપી શકાય એમ છે અને ૬૦ લાખ હેકટર જમીન તો એવી છે કે જેને સિંચાઈની સુવિધા આપી શકાય એવા કોઈ સંજોગો નથી, અને છતાંય આ રાજ્ય સરકાર એ ૬૪ લાખ હેકટર જમીનને સિંચાઈની સુવિધા આપવા માટેના અથાગ પ્રયાસો કરે છે અને વધારાની જે જોગવાઈઓ કરે છે એમાં ૪૦ લાખ હેકટર જમીનને સિંચાઈની સુવિધા આપવાનું કામ આ રાજ્ય સરકારે પહેલી વખત પૂર્ણ કર્યુ છે. પહેલી વખત પૂર્ણ કર્યુ છે. માત્ર હું કોંગ્રેસ સરકારમાં હતો એટલે એ વખતે આપણે

એટલી વાત સ્વીકારવી જોઈએ કે ત્યાં સુધીના બધા વર્ષોમાં થઈને, ૫૦ વર્ષના ગાળામાં ૩૫૦૦ ચેકડેમો તૈયાર નહોતા કર્યા, આપણને જરૂરિયાત નહોતી લાગી, જે હોય તે, આપણને સમજણ નહોતી પડતી, ગમે તે કારણોસર પણ એ બધુ બાકી રહ્યું હતું તે નક્કર હકીકત છે, આ રાજ્ય સરકારે પાંચ વર્ષમાં ૫૦ હજાર ચેકડેમ પૂરા કર્યા છે, એ વિરોધપક્ષના નેતાને અને સૌરાષ્ટ્રના સૌ સભ્યશ્રીઓએ સ્વીકારવું પડે કે જળાશયો અને નદીઓને ભરવા માટે આ રાજ્ય સરકારે સૌરાષ્ટ્ર માટે ૫૧૫ કરોડ રૂપિયાની યોજના અમલમાં મૂકીને ૧૦૭ જેટલા ચેક ડેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પહેલી વખત બાંધ્યા છે. જે સત્ય છે એ સ્વીકારવું પડશે. બે-ત્રણ લાખ રૂપિયાના ૫૦ હજાર ચેકડેમો તૈયાર કર્યા. ઉપરાંત ૩૦-૪૦ લાખના રાજ્યમાં સો જેટલા મોટા ચેકડેમો નદીઓ ઉપરના પૂરા કરવાનું ભગીરથ કાર્ય આ રાજ્ય સરકારે પૂરું કર્યું છે. એટલું જ નહીં પણ, આ રાજ્ય સરકારે નદીઓ ઉપરના મોટા આડબંધો બાંધીને ૫૦૦ જેટલા મોટા ચેકડેમો બાંધવાનું આયોજન પણ કર્યું છે. ફરિયાદ કરવી હોય તો કરી શકાય. એટલે જ મેં પહેલા જ આપને કહ્યું કે 'સ્મશાનમે ખોપડીઓ કો ઠુકરાના ગીદડભી જાનતે હે.' ડોન્ટ ડુ ઈટ. જે સત્ય છે એ સ્વીકારવું પડે કે થયું છે. ચેકડેમો નહોતા થયા એ હવે થયા. સૌરાષ્ટ્રમાં ૫૧૫ કરોડની યોજના અમલમાં આવી, નદીઓના બંધ બંધાયા. સાહેબ, આડબંધો એ આડબંધો છે, બોરી બંધો એ બોરી બંધો છે, ચેકડેમો એ ચેકડેમો છે અને ડેમ એ ડેમ છે. એકબીજા સાથે એની સરખામણી કરીને એના માટે આપણે ટીકા-ટીપ્પણ કરીએ તો એ સ્થિતિ કોઈ સંજોગોમાં આવકારદાયક નહીં ગણી શકાય. જ્યાં ચેકડેમો શકય નથી એવી જગ્યાએ આ રાજ્ય સરકારે ૧૫૦૦ તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરી છે. એક સનાતન સત્ય તો એ છે કે ૫ મિટરથી માંડીને ૨૫ મિટર સુધી ભૂગર્ભજળ મહેસાણામાં ઉપર આવ્યા છે. ૧૦૦૦ મિટર નીચેથી પાણી આવતું હતું, ૧૨૦૦ ફૂટ નીચેથી પણ પાણી મેળવવું મુશ્કેલ પડતું હતું એવા સ્થળોએ પણ અત્યારે ૫ મિટરથી માંડીને ૨૫ મિટરથી પણ વધારે ભૂર્ગભ જળસપાટીનું લેવલ ઉંચું આવ્યું છે. એ એક સનાતન સત્ય પણ આપણે સ્વીકારવું પડે અને રાજ્ય સરકારની સિદ્ધિ તરીકે એ બાબતને પણ આપણે સ્વીકારવી પડે. આ બધી બાબતની ચર્ચામાં હું એટલા માટે ઉતરું છું કે, ધારો કે રીચાર્જ કેનાલ મહેસાણામાં જવાની છે ભૂગર્ભ સપાટી તો સો ટકા ઉંચી આવવાની છે. આ રાજ્ય સરકારે જે રીતે કામ કર્યું છે (અંતરાય) ગોવાભાઈ, કામ થાય તો પાણી ઉંચું આવવાનું છે. બેઠા બેઠા ન બોલો તમારા ભાષણમાં આ અંગે જેટલી ટીકા-ટીપ્પણ કે નિવેદન કરવું હોય આની ક્રોસમાં તો કરવા માટેનું હું તમને આહવાહન આપું છું. આમાં ખાનગીમાં બોલજો એમ કહેતો નથી, આહવાહન આપુ છું. એક પણ બાબત પ્રબોધકાંત પંડયાએ કહેલી હાઉસમાં ખોટી છે એમ જો તમે સાબિત કરી આપો તો હું મારું ધારાસભ્ય પદ પણ છોડી દઉં, પણ ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા મહેરબાની કરીને ટીકા-ટીપ્પણ ન કરશો.

ઉકાઈ લિંક નહેર આ રાજ્ય સરકારે કરી છે કે નથી કરી એ મને કહો, ઉકાઈ પૂર્ણા લિંક નહેર આ રાજ્ય સરકારે કરી છે કે નથી કરી એ મને કહો, ઘરોઈમાંથી જમણાકાંઠા નહેરને લંબાવવાની કામગીરી આ રાજ્ય સરકારે કરી છે કે નથી કરી એ મને કહો, કડાણા જમણાકાંઠા હાઈલેવલ કેનાલનું કામ અત્યારે પુરજોશમાં ચાલે છે આ કામગીરી આ રાજ્ય સરકાર કરે છે કે નથી કરતી? પાનમ હાઈલેવલ કેનાલનું કામ આ રાજ્ય સરકારે કર્યું છે કે બીજી કોઈ રાજ્ય સરકારે કર્યું છે? કડાણા ડાબાકાંઠા હાઈલેવલ કેનાલનું કામ આ રાજ્ય સરકારે કર્યું છે કે બીજી કોઈ રાજ્ય સરકારે કર્યું છે? કડાણા મહીસાગર નદીને ભાદર નદી સાથે લિંક કરવાનું કામ જે અગાઉ મેં ૧૦ નદીઓ કહી એ ૧૦ નદીઓને જોડવાનું રીવરગ્રીડ યોજનાનું કામ આ રાજ્ય સરકાર કરે છે કે અન્ય કોઈ રાજ્ય સરકાર કરે છે એ મને કહો. આ બધી જ કામગીરી આ રાજ્ય સરકારની અદ્વિતિય સિદ્ધિ તરીકે વર્ણવવામાં આવે તો પણ અતિશયોકિત નથી. પણ હું એમ કહેતા ખચકાતો નથી કે આ બધી સિદ્ધિઓ રાજ્ય સરકાર માટે એક કીર્તિકળશરૂપ છે. જોવાની દૃષ્ટિ દરેકની જુદી જુદી હોય શકે. તમારી દૃષ્ટિ પણ જુદી હોય શકે એમાં હું પડવા માગતો નથી. એક જમાનો એવો હતો ગોવાભાઈ, કવિઓ કવિતા લખતા હતા કે, 'ભાંભરતા ભેંસ-ગાય પંખી ગુપચૂપ જોઈ ચાંચો ઉઘાડી-બીડાણી ઓ મેહુલા તોય ન આરજુ કળાણી ઓ મહુલા' જે આરજુ નહોતી સંભળાતી. પ્રજાને પીવાનું શુદ્ધ પાણી પૂરું પાડવાની આરઝુ આ રાજ્ય સરકારે સાંભળી છે. હ્રદયદ્રાવકતા સાથે આ રાજ્ય સરકારે પીવાનું શુદ્ધ પાણી પૂરું પાડવા માટેનો એક કટિબદ્ધ સંકલ્પ કર્યો અને એને કારણે આજે આપણે સ્વીકારવું પડે અમદાવાદનો ભાલ વિસ્તાર હોય, ભાવનગર, અમરેલી, રાજકોટ, જામનગર કે જુનાગઢ, કચ્છ જિલ્લાઓના ૧૮૨૬ ગામોને અને ૫૨ શહેરોને નર્મદાનું પાણી પૂરું પાડવાનો યશ આ રાજ્ય સરકારના ફાળે છે ના હોય તો મને કહો (અંતરાય) બસ એટલું સ્વીકારો છો એ જ અમારા માટે આનંદની વાત છે ફાળો છે એટલું, એટલે હું સાચું જ કહીશ હું કોઈ પોલિટિકલ અવલોકનો નહિ કરું અને જે કહીશ તે તમારે સ્વીકાર્યા વગર છૂટકો નથી એમ કહેતા પણ હું ખચકાતો નથી.

નંબર ટુ, બીજા ૧૭૭૪ ગામોને નર્મદાનું પાણી પૂરું પાડવા માટે ૩૬૬ કિલોમિટરની પાઈપ લાઈન અને ૩૦ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન નેટવર્કના કામો અત્યારે પ્રગતિમાં છે. એ આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ એવી બાબત છે અને એ પણ સ્વીકાર્યા સિવાય બીજો વિકલ્પ નથી. મહી-પરિએજ યોજના દ્વારા ૧૦૦૬ ગામોને અને ૩૨ શહેરોને પાણી પૂરું પાડવાનું ભગીરથ કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. ઘરોઈ જળાશય યોજનામાંથી ૩૧૦ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ૩૪૭ ગામો અને ૪ શહેરોને પાણી પૂરું પાડવાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે.

મુક્તેશ્વર જૂથ યોજનામાંથી ૧૦૬ ગામો અને એક શહેરને પાણી પૂરું પાડવાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. સિપુ જળાશય યોજના બનાસકાંઠાની ગોવાભાઈ, થરાદ, ધાનેરાના ૧૩૦ ગામોની યોજના પણ પહેલી વખત આ રાજ્ય સરકારે બનાવી અને ૪૫ ગામોને હાલમાં પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે એ વાત આપણે સ્વીકારવી પડે તેવી છે (અંતરાય) દાંતા-વડગામની જૂથ યોજનામાં ૩૦ ગામોને પાણી પૂરું પાડવાની કામગીરી પણ આ રાજ્ય સરકારે પૂર્ણ કરી છે. માલપુર-બાયડ, ડેરોલ માઝૂમ યોજનામાં ૫૫ ગામોને પાણી પૂરું પાડવાનું કામ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. ખેરોલી નર્મદા જૂથ યોજનામાં ૧૩૫ ગામો જે પંચમહાલ જિલ્લાના છે એને પણ પાણી પૂરું પાડવાનું કામ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. ગાયપઘલા સુરત જિલ્લામાં ૨૮ ગામોને પાણી પૂરું પાડવાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. ભરૂચ જિલ્લામાં અને સુરત નવસારીમાં ૧૫ જૂથ યોજના દ્વારા ૩૮૪ ગામોને પાણી પૂરું પાડવાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. કડાણા જૂથ યોજનામાં ૧૫૬ ગામોને પાણી પૂરું પાડવાની કામગીરીની યોજના અત્યારે પુરજોશમાં ચાલી રહી છે અને કેટલાય ગામોને પાણી પૂરું પાડવાની કામગીરી ચાલે છે.

રાજ્ય સરકારનો ૨૦૦૦ હેન્ડપંપ બનાવવાનો લક્ષ્યાંક હતો, એ લક્ષ્યાંક આંબી જઈને પણ ૩૦૦ ટકા સિદ્ધિ હાંસલ કરવાનું કામ થયું છે અને ૬૦૦૦ થી પણ વધુ હેન્ડપંપ દ્વારા ગામડાંના લોકોને શુદ્ધ પાણી પૂરું પાડવાનો યશ પણ આ રાજ્ય સરકારના ફાળે ગયો છે. રાજ્યમાં ૧ લાખ ૨૮ હજાર હેન્ડપંપ જે અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે અને પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે એમાં આ રાજ્ય સરકારનો મોટો હિસ્સો અને ફાળો છે. ૬૨૩૭ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે મુખ્યમંત્રીશ્રીની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને કૂનેહને કારણે સુજલામ્-સુફલામ્ યોજના અમલમાં મૂકાઈ. મધ્યગુજરાતમાં ૭૧ ટકા પાણીનો પુરવઠો હોવા છતાં મધ્યગુજરાતમાં એવી સ્થિતિ હતી કે, સિંચાઈનું પાણી કે પીવાનું પાણી ત્યાં ઉપલબ્ધ નહોતું ૪૭ ગામો કડાણા ગામના ડૂબાણમાં ગયા, અનેક ગામો બીજા પણ ડૂબાણમાં ગયા અને છતાં પણ અમારો સૂકોભઠ વિસ્તાર, પાણી વગર એમનેએમ હતો, પહેલીવખત રાજ્ય સરકારે ૧૦૬૫ કરોડ રૂપિયા પંચમહાલ, દાહોદ જિલ્લાને ફાળવીને આ આદિવાસી પ્રજામાં આ કામગીરી કરવાનું ભગીરથ કાર્ય પણ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે એમ હું કહુ છું

બીજો મહત્વનો પ્રશ્ન જે હતો તે ત્રણ જરૂરિયાતો પૈકીનો એક સિંચાઈની સુવિધા, બીજી સુવિધા વીજળીની, સમગ્ર રાજ્યમાં વીજળીની આપણી સ્થાપિત નિજી ક્ષમતા ૮૭૮૩ મેગાવોટની હતી નર્મદા બંધ બાંધીને આ રાજ્ય સરકારે એક મોટામાં મોટી કામગીરી કરી છે. બે પ્રકારના પ્રોજૅકટ શરૂ કર્યા એક કેનાલ હેડ ઈલૅક્ટ્રિસિટી પ્રોજૅકટ કર્યો અને એક રીવર હેડ ઈલૅક્ટ્રિસિટીનો પ્રોજેકટ કર્યો. પાંચ પાંચ યુનિટો પૈકીનું એક યુનિટ અત્યારે ચાલુ છે synchronize થઈ ગયું છે અને ચાર યુનિટો synchronize થવામાં બાકી છે. છતાંય ૨૦૦ મેગાવોટ વીજળીનું ઉત્પાદન અત્યારે તેમાંથી મળ્યું છે અને બધા યુનિટો ચાલુ થતાં વીજ ક્ષમતામાં આ રાજ્યની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે એક હજાર મેગાવોટ જેટલો જંગી વધારો થવાની પૂરી સંભાવના છે. એક અક્રીમોટા ખાતે ૨૫૦ મેગાવોટનો લિગ્નાઇટ પ્રોજેકટ આ રાજ્ય સરકારે હાથ ધર્યો અને તે કાર્યાન્વિત થવાની તૈયારીમાં છે. પાનન્ધ્રો ખાતે એક ૭૫ મેગાવોટનો લિગ્નાઇટ પ્રોજેકટ તે પણ આ રાજ્ય સરકારે પ્રગતિ હેઠળ મૂકયો છે અને તેનું કામ પણ પુરજોશમાં ચાલે છે. વીજ ક્ષેત્રમાં ક્રમશ: વધારો થતાં આ કામગીરી રાજ્ય સરકાર માટે કીર્તિકળશરુપ બનાવવાની છે. સાત હજાર જેટલાં ગામોને થ્રી ફેઈઝ વીજળીકરણથી ઈલેકટ્રીફીકેશનથી ૨૪ કલાક માટે વીજળી મળી શકે તેવી યોજના અમલમાં મૂકવાનો યશ આ રાજ્ય સરકારને ફાળે પહેલી વખત છે. જ્યાં નહીં થયુ હોય ત્યાં દાખલા આપી શકાય કે હજુ વાળુના ટાઈમે જતી રહે છે, ફલાણું થાય છે, ઢીંકણું થાય છે એવું કહી શકાય. પણ જ્યાં થયું છે તે આપણે નક્કર, સનાતન સત્ય સ્વીકારવું પડે. સાત હજાર ગામોને થ્રી ફેઈઝ વીજળીકરણ દ્વારા ગ્રામ જ્યોતિ યોજના દ્વારા મારા ગામડાંઓમાં અત્યારે ૨૪ કલાક વીજળી મળે છે. જ્યાં અમને સાત-સાત, આઠ-આઠ કલાક નહોતી મળતી ત્યાં અત્યારે ૨૪ કલાક વીજળી મળે છે, ઉપલબ્ધ છે જે સનાતન સત્ય છે અને તે સત્ય પણ આપણે સ્વીકારવું પડે તેમ કહેતાં હું અચકાતો નથી.

ગેસ પેટ્રોલિયમના ક્ષેત્રે ૨૮-૨૮ વખત સારકામ થયા પછી મુખ્યમંત્રીશ્રીની દીર્ઘ દ્રષ્ટિના કારણે ધોળકા પાસે ફરી એક વખત વધારાનો પ્રયત્ન કરીને જે ડ્રિલીંગ કરવામાં આવ્યું અને તેલનો વિપુલ જથ્થો મળ્યો છે તે પણ આ રાજ્ય સરકારની એક મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે. તે સ્વીકારવી પડે પછી કહેવું હોય તેમ કહેવાય એક મોટો ભભકાભારી એક સમારંભ યોજીને તમાશો કર્યો આ કહીને નવાજવાની પદ્ધતિ જુદી છે(અંતરાય) જે સત્ય છે તો કહુંને? તે કહેવું પડે કયારેક કહેવું પડે એટલે તેમાં બહુ ચિંતા ના કરશો.

ન્યાયતંત્રમાં આ રાજ્ય સરકારે ૧૮૬ ફાસ્ટ્ર ટ્રેકો સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો. ૧૫૯ ફાસ્ટ ટ્રેકો કાર્યાન્વિત કરી. ઈતિહાસમાં for the first time in the history ૧૫૯ ફાસ્ટ્ર ટ્રેકો કાર્યાન્વિત કરી ૨૩ હજાર કેસોનો નિકાલ કર્યો એક વર્ષમાં કાનૂની સત્તા મંડળો અને લોક-અદાલતોએ મળીને ૨૧ લાખ કેસોનો નિકાલ આ રાજ્ય સરકારે કર્યો તે પણ આ રાજ્ય સરકારની એક મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે. વંચિતો જે લોકો ગરીબ છે અને ઘણી વખત કવિઓ કવિતાઓ લખતા " છે ગરીબોના કૂવામાં તેલનું ટીપું દોહ્યલું ને શ્રીમંતોની કબરો પર ઘીના દીવા થાય છે." કવિતાઓ લખાતી અને પરેશ ભાઈ જેવાને હ્રદય સરસું લાગી જતું. પેલા કવિ કવિતા લખે છે

" એ કિસાન ગાયે જા, પ્યારે હલ ચલાયે જા,
જાલિમોને તેરા સબ સુખ ભૂલા દિયા તો કયા,
તેરે આંસુઓ પર ગર મુસ્કરા દિયા તો કયા,
તેરી આહ પર વાહ વાહ કયા તો કયા,
સબ્ર કર એક દિન તેરા રાજ આયેગા,
કસમ હૈ શિર પર તખ્તોતાજ આયેગા,
એ કિસાન ગાયે જા, પ્યારે હલ ચલાયે જા."

તે કહેવાવાળી આ રાજ્ય સરકાર પહેલી છે. (અંતરાય) બોલવા દઈશું, ભરપેટ બોલવા દઈશું. તમારા અવાજને કયાંય રૂંધાવા નહીં દઈએ. પણ હ્દય ઉપર હાથ રાખીને એટલું કહેજો હું જે બોલીશ તે સાચું બોલીશ, સત્ય બોલીશ અને સાચું હશે તે ઉમળકાભેર સ્વીકારીશ પછી કહેવાની બધી છૂટ છે. વંચિતો માટે, ગરીબ લોકો અને હરિજનો માટે તેમજ છેવાડાના માનવી કે જેમની સામે કોઈ જોવાવાળું નથી એવા લોકો માટે આ રાજ્ય સરકારે ૧૫૫.૮૬ કરોડની જોગવાઈ પહેલી વખત કરી છે. ત્રણ લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને મફત ગણવેશ આપવાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. ૩૫૪ જેટલા કાયદા સ્નાતકોને સિનિયર કાયદા શાસ્ત્રીઓ પાસે તાલીમ લેવા માટે મોકલ્યા. એવું બની શકે કે સામાન્ય સંજોગોમાં જે વિદ્યાર્થીઓ લોઅર કેટેગરીના હોય, એમને સાઈકોલોજીકલ ઈફેકટ એવી હોય છે કે હું આમાં જઈ શકીશ કે કેમ? એટલા માટે રાજ્ય સરકારે એમની લાગણીને લક્ષમાં રાખીને બીજાઓની સ્પર્ધામાં તેઓ ઉભા રહી શકે, એટલા માટે આવા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ તાલીમ માટે ઉચ્ચ ધારાશાસ્ત્રીઓ પાસે મોકલવાની કામગીરી કરી. પહેલી વખત રાજ્ય સરકારે અનુસૂચિત જાતિના બાળકોને વિદેશ ઉચ્ચ અભ્યાસે જવા માટે પાંચ પાંચ લાખ રૂપિયાની લોન આપવા માટેની જોગવાઈ કરી. આ લોનની જોગવાઈ કરવાવાળી આ રાજ્ય સરકાર પહેલી છે. સરસ્વતી સાધના યોજના નીચે પાંચ હજાર બાળાઓને સાઈકલ આપવાની કામગીરીની જાહેરાત પણ આ રાજ્ય સરકારે કરી છે. ગ્રાન્ટેડ અને સરકારી શાળાઓ અને છાત્રાલયોમાં લગભગ ૨૦,૦૦૦ છાત્રોને રહેવા અને જમવાની મફત સગવડ પણ આ રાજ્ય સરકારે પૂરી પાડી છે.તબીબી અને કાયદાના ૪૬ સ્નાતકોને લોન સહાય આપવાની કામગીરી પણ આ રાજ્ય સરકારે કરી છે.

ત્રીજું એક મહત્વનું પરિબળ માર્ગનું છે. રસ્તા સારા હોય તો ગામડાના ખેડૂતો પોતાનું પકવેલું અનાજ, ધાન્ય બજાર સુધી પહોંચાડી શકે. મુસાફરી સારી થઈ શકે, ધારાસભ્યોની ગાડી સારી સચવાય, રસ્તા સારા થાય, ફોરલેન રસ્તા થાય અને પેટનું પાણી પણ ના હલે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ અને ભૂજથી ત્રણથી ચાર કલાકમાં ગાંધીનગર સુધી આવી શકાય એની કાળજી આ રાજ્ય સરકારે લીધી છે. (અંતરાય) ૭૫૫ કિલોમિટરના ધોરીમાર્ગો ૫૫૩ કરોડના ખર્ચે આ રાજ્ય સરકારે પૂર્ણ કર્યા છે. ૯૪૫ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ૮૫૪ કિલોમિટરના કામો હાલમાં પ્રગતિમાં છે. આવતા જતા તમામને અનુભવ થાય છે. બરોડા-અમદાવાદ એકસ્પ્રેસ હાઈવેનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે પૂર્ણ કર્યુ છે. હિંમતનગર, ઈડર, ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર ચીલોડા રસ્તો ચાર માર્ગી અને પહોળો કરવાની કામગીરી પ્રક્રિયામાં છે, પ્રગતિમાં છે.

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનામાં ૯૭૦ કિલોમિટરની લંબાઈના રસ્તાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે પુર્ણ કર્યુ છે. આ રાજ્ય સરકારે માત્ર શહેરી રસ્તાઓની જ કામગીરી કરી છે એવું નથી. ૧૨૮ જેટલા ગ્રામ્ય રસ્તાઓની ડામર સપાટી કરવાનું આયોજન પણ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. ૧૫ લાખ રૂપિયાના વધુ જોબનંબરો જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના રસ્તાને માટી, મેટલ કામ અને ડામર સપાટીથી જોડવા માટે દરેક ધારાસભ્યને વધારાના જોબ નંબર આપવાનો યશ પણ આ રાજ્ય સરકારને ફાળે છે. માનનીય મંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપવાં જોઈએ કે આ જાહેરાત કરીને આ હાઉસના સભ્યો પ્રજાની વધુ સારી સેવા કરી શકે તેવી કામગીરી કરી છે.

સુનામી અસરગ્રસ્તોને મદદ કરવામાં, (અંતરાય) તમે તે દિવસે હસતા હતા, જયારે રાજ્યપાલશ્રીનું સંબોધન હતું અને એ વાંચતા હતા ત્યારે તમે હસતા હતા. એટલા માટે હશે કે આ રાજ્ય સરકારની જુદા જુદા વિસ્તારો માટેની મદદ ૧૦ કરોડ રૂપિયાની અને સાધન સામગ્રીની થઈ. હું સૌ સભ્યોને એક દાખલો આપવા માગું છું. એક અવાજ ઉઠવો જોઈએ. ભગવાન બુદ્ધની પ્રતિમા તૈયાર કરવાની હતી. અનુયાયીઓને સૂચના આપવામાં આવી કે ભેટ સોગાદો લઈ આવો. એક સ્વીપર બેન, વાળવાવાળી બાઈ, તાંબાની ચૂંક મળેલી તે આપતી હતી, પણ અનુયાયીઓએ તે ન લીધી. Metal was melted. Statue of Buddha became ugly. સ્ટેચ્યુ કદરૂપું બની ગયું. એટલે મુખ્ય પાદરીએ તેમને પૂછયું કે આ સ્ટેચ્યુ કદરૂપું કેમ બની ગયું? તમે કોઈએ આપેલ કોઈ વસ્તુનો અનાદર કર્યો છે? જો આવી કોઈ વસ્તુ કોઈ આપતું હોય અને એ ન લેવાનો તમે જો અનાદર કર્યો હોય તો એને પાછી લઈ આવો. તો અનુયાયીઓ એ બાળા કે જેનું નામ યાટોસ હતું એની પાસે પાછા જઈને એ તાંબાનો સિકકો લઈ આવ્યા અને એ metal was poured into. એમાં એ સિકકો નાખવામાં આવ્યો અને metal was melted again and the statue of Buddha became perfect and shining એટલે એ પરફેકટ સાઈનવાળું થયું. એટલા માટે થયું કે The gift was very small but it was given

with great love and humanity. આ ૧૦ કરોડ રૂપિયાની રકમ કદાચ તમને નાની લાગતી હશે, પરંતુ એ આ રાજ્ય સરકારની માનવતાનું અને it is given with great love and humanity of Indian people. આપણા રાષ્ટ્રના લોકો માટેની આ એક બાબત હતી અને એને આપણે માનભેર બિરદાવવી જોઈએ એના બદલે એ દિવસે તમે એની ટિકાટિપ્પણ કરતા હતા ત્યારે મારા આત્માને અંદરથી સહેજ દુઃખ થયું હતું કે આ બાબત આપણે સ્વીકારવા જેવી હતી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય કૃષિમંત્રીશ્રીએ રાજ્યમાં ચાર કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્થાપવા માટેનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે, બધાં જ પોલીસ સ્ટેશનોને કોમ્પ્યુટરાઈઝ કરવાનું કામ આપણા માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રીએ કર્યુ છે, બધા જ તહેવારો શાંતિથી ઉજવાય છે એ આપણે જાણીએ છીએ, તમામ જિલ્લાઓને આવરી લઈને ૭૭૦૦ રહેણાંકનાં મકાનો, પોલીસ કર્મચારીઓ માટે વેલફેરની કાળજી રાખવાનું કામ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે. આરોગ્ય ક્ષેત્રે ટ્રોમા સેન્ટર શરૂ કરવાનો યશ પહેલી વખત આ રાજ્ય સરકારને ફાળે જાય છે, ૧૦ અગ્રગણ્ય હોસ્પિટલોને સાંકળી લઈને ઈમરજન્સી મેડીકલ સર્વિસીસ શરૂ કરવાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારને ફાળે જાય છે. વિચાર આવવો એ પણ એક અગત્યની બાબત છે ને? તો આ કામગીરી પણ આ રાજ્ય સરકારે કરી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમમાં એક કરોડ બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી કરવાનો કાર્યક્રમ આ રાજ્ય સરકારે પહેલી વખત કરેલ છે અને ૨૪૧૭૮ બાળકોને મફત ચશ્મા વિતરણની કામગીરી કરવાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે કર્યુ છે અને સૌથી વધારે કીર્તિકળશરૂપ બાબત એ છે કે નામદાર રાજ્યપાલશ્રીએ તેમના પ્રવચનમાં કહયું છે કે 'સમગ્ર રાજ્યમાં પોલીયોનો એક પણ કેસ સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન નોંધાયેલ નથી.' અને આ રાજ્ય જેવાં સુદ્રઢ રાજ્ય બીજાં રાજ્ય બને અને એના જેવી પધ્ધતિઓ અપનાવે એવું નામદાર રાજ્યપાલશ્રીએ પણ સ્વીકારવું પડે એવી બાબત બની છે. એટલા માટે સૌ માનનીય સભ્યશ્રીઓને મારે કહેવું જોઈએ કે નામદાર રાજ્યપાલશ્રીએ આ હાઉસમાં કરેલું જે પ્રવચન છે અને જેનો પ્રસ્તાવ માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈએ રજૂ કર્યો છે એને આપણે સૌ હૃદયપૂર્વક આવકારીએ અને એ સંદેશો નામદાર રાજ્યપાલશ્રી સુધી પહોંચે કે આ હાઉસે કાંઈ મારા માટે સારું બોલવાની ચેષ્ટા કરી છે અને પછી પાછા એમ કહેશો કે 'અમારા' તો 'અમારા' દેખાય એવો વર્તાવ કરજો.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા (વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના આભાર પ્રસ્તાવ ઉપર બોલવા માટે હું ઉભો થયો છું. નામદાર રાજ્યપાલશ્રી એક વિદ્વાન રાજ્યપાલશ્રી છે અને એમની ભૂતકાળની દેશની જે સેવાઓ હતી એટલે અમને અપેક્ષા એવી હતી કે સરકારશ્રી એમના માટે જે પ્રવચન તૈયાર કરશે એ પ્રવચન સાંભળવા લાયક હશે અને આમેય વિરોધપક્ષના નેતા તરીકે વરણી થયા પછી મારે નામદાર રાજ્યપાલશ્રીનું પ્રવચન સાંભળવાનો પહેલો મોકો હતો અને એના ઉપર બોલવાનો પણ પહેલો મોકો મળ્યો છે એટલે મેં બહુ ધ્યાનથી સાંભળ્યું હતું. અગાઉના રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનો પણ મેં ધ્યાનથી વાંચેલા છે અને આજે જે આભાર પ્રસ્તાવ ઉપરની ચર્ચા ચાલે છે તે પણ હું ધ્યાનથી સાંભળતો હતો. મને એવું હતું કે રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં કંઈક એવી બાબતો હશે કે રાજ્યમાં જે ખૂટતો વિકાસ છે, રાજ્યમાં જે વંચિતો વસે છે, જે યુવાનો વસે છે, જે ખેડૂતો વસે છે અને તેમના જે પ્રશ્નો છે તે પ્રશ્નો એમાં ઉજાગર થશે. એ પ્રશ્નોની આપણે સૌ સાથે મળીને ચર્ચા કરીશું અને તેના ઉકેલ તરફ ગતિ લાવી અને તેના ઉકેલ તરફ આગળ વધીશું. આખરે રાજ્યના પ્રશ્નો અંગે અહીં ચર્ચા કરીએ તે ચર્ચાને અંતે પ્રશ્નોના ઉકેલ તરફ હંમેશાં આપણે આગળ જવાનું હોય છે. પણ જે પ્રવચન થયું એ પ્રવચનમાં પ્રશ્નો કરતાં પ્રશસ્તિ વધારે હતી. એટલા માટે હું એ પ્રવચન સાથે સંમંત થઈ શકતો નથી અને આ આભાર પ્રસ્તાવ સાથે હું સંમંત થઈ શકતો નથી. રાજ્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા કોઈ જગ્યાએ કરવામાં આવી નથી કે આટલા પ્રશ્નો રાજ્યના છે અને રાજ્ય સરકાર તેના ઉકેલ તરફ આટલું આટલું કરવાની છે. આભાર પ્રસ્તાવ માટે વિદ્વાન સભ્યશ્રીઓએ અહીં ચર્ચા કરી. માનનીય પ્રબોધકાંતભાઈ વિદ્વાન અને અભ્યાસુ છે, માનનીય શંકરભાઈ પણ યુવાન છે, અપેક્ષા એવી રાખી હતી કે રાજ્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા પ્રવચનમાં થાય અને તે ન થાય તો વાંધો નહીં, પરંતુ રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનના આભાર પ્રસ્તાવ ઉપરની ચર્ચા થાય તેમાં આની ચર્ચા થાય, પરંતુ જે પ્રવચન સાંભળ્યું તે એવું હતું કે આભાર પ્રસ્તાવ કરતાં મુખ્ય મંત્રીશ્રીની પ્રશસ્તી એમાં વધારે હતી. એ બીજી જગ્યાએ કરી શકયા હોત. આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ એ રાજ્યના પ્રશ્નો ઉપર કેંન્દ્રિત કરી અને તેની અંદર આપણે ગુજરાતની પ્રજાને એક નવી દિશા આપવાનું કામ કરી શકયા હોત. તે થઈ શકયું નથી.

આપણે આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરીએ તેના પહેલાં અગાઉના રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનની અંદર અને આ વખતના રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં જે નવા નવા શબ્દો મૂકયા હતા તેની હું આપના મારફત આ સભાગૃહને યાદ દેવડાવવા માગું છું. આ સરકાર આવી ત્યારે પંચામૃત દ્વારા વિકાસનો ખ્યાલ આ ગૃહને અને ગુજરાતની પ્રજાને અપાયો હતો. જાણે પંચામૃત પહેલી વખત ગુજરાતની પ્રજાને અપાતું હોય તેવી વાત થઈ. એમાં

જનશકિત, જ્ઞાન શકિત, ઉર્જા શકિત, જળ શકિત અને રક્ષા શકિત દ્વારા રાજ્યનો વિકાસ થવાનો છે એવું ગાઈ વગાડીને કહેવામાં આવ્યું અને આ નવા શબ્દો આપી અને ગુજરાતનો વિકાસ થઈ ગયો છે એવો સંતોષ માની અને ફરી પાછા એ શબ્દો ભૂલી જવાયા, મને એવું હતું કે તેના ઉપર આ વખતે વધારે ગોર કરવામાં આવશે. પરંતુ એ ભૂલી જવાયા છે. એટલુ જ નહીં પરંતુ, બોલ્યા તેના કરતાં વિરૂધ્ધ બાબતો તરફ આટલા વર્ષોના અનુભવ પછી આ સરકાર વળી છે. ગ્રામ સ્વરાજથી રામ રાજ્ય સુધીની વાત તો મહાત્મા ગાંધીએ કરી હતી અને તેથી રામ રાજ્યની કલ્પના કદાચ બોલનાર લોકોને નહીં હોય, મહાત્મા ગાંધીએ જે શબ્દો વાપર્યા હતા જેના માટે વપરાયા હતા તે કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય, પરંતુ આજે જે રાજ ચાલે છે તે રામ રાજ ચાલે છે? આ ગ્રામ્ય સ્વરાજ તરફની આપણી ગતિ છે? તેના ઉપર વિચાર કરવાનો સમય આવ્યો છે. મને આનંદ એ વાતનો છે કે આ ગૃહના ઘણા બધા મિત્રો આ બાબતનો અત્યારે વિચાર કરી રહ્યા છે. હું એમ કહેવા જતો હતો કે રામ રાજ્ય કોને કહેવાય? કે સમાજનો છેવાડાનો માનવી રાજાને, સર્વાસત્તાધીશ હોય એને એમ કહી શકે કે રાજા તમે આ ભૂલ કરો છો અને રાજા એ વાતને સ્વીકારે તો માનવાનું કે અહીંયાં રામરાજ ચાલે છે અને રામરાજ ન ચાલતું હોય તો એના તરફની ગતિ છે એ ગતિ છે એમ માનવાને કારણ મળે છે, પરંતુ અત્યારે જે રાજ ચાલે છે એમાં સરકારે આત્મખોજ કરવાની જરૂર છે. એ કેવું રાજ ચાલે છે, અહીંયાં શબ્દો તો ઘણા બધા આપી શકાશે. એ શબ્દોમાં કહું આક્રોશમાં પણ તમાશો કહું તો કોઈને ખરાબ લાગી જાશે. પરંતુ રાજ કેવું ચાલે છે તે અંગેની વાત કહેવી છે.

આ રાજ્યની અંદર સૌથી દુ:ખદ પરિસ્થિતિ હોય તે અંગે એક વાત કહેવામાં આવી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં એવી વાત કહેવામાં આવી કે ૬૦,૦૦૦નું આપણું પોલીસબળ છે. એમને તાલીમ અપાય છે, એના માટેની વ્યવસ્થાઓ અપાય છે. આધુનિકરણ થાય છે અને જેલમાં સારી સગવડતા પણ અપાય છે તેવી વાત પ્રવચનમાં કરી, પરંતુ આટલી વ્યવસ્થા અપાયા પછી ગુજરાતની પ્રજા છે એ શાંતિથી ઊંઘ ા કરે છે ખરી? કયાંય ન્યાયની અંદર શ્રદ્ધા વધી છે કે ઘટી છે એની પણ આત્મખોજ કરવાની જરૂર છે.

કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ એ હંમેશા રાજનીતિથી ઉપર ઊઠીને હોય છે. આજે ગૃહની અંદર વારંવાર મેં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ બાબતે આ સરકારને પણ સમય આવ્યો હોય ત્યારે એમ કહ્યું છે કે સારી કામગીરી કરી છે. પરંતુ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ ચાલે છે એ કયાંય વખાણવા લાયક છે ખરી? પોલીસનું મોરલ સંપૂર્ણપણે તોડી નાખવામાં આવ્યું છે અને હું તો એમ કહીશ કે સરકાર આખી એડહોકીઝમ, પોલીસ તંત્ર એડહોકીઝમથી ચાલે છે. ડાયરૅક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ જે સ્ટેચ્યુટરી પોસ્ટ છે ત્યાં કાયમી નિમણૂક થવી જોઈએ, પરંતુ રોજમદારીના ધોરણે એમની પાસેથી કામ લેવામાં આવે છે. મારા અગાઉના આક્ષેપને હું રિપિટ કરું છું. કારણ એટલું કે લટકતી તલવાર રાખીને અને મનગમતા નિર્ણયો એમની પાસેથી કરાવાની આ એક જગ્યા નથી. એવી અનેક જગ્યાઓ પોલીસતંત્રમાં ખાલી પડેલી છે. એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો આ રાજ્યની અંદર જે વ્યવસ્થા ચાલે છે એની ઉપર કંટ્રોલ રાખે છે એ જગ્યાનો પણ વધારાનો હવાલો આપીને ચલાવવામાં આવે છે. સરકારને શું તકલીફ છે? બે બે વર્ષ થઈ ગયાં હજી શું તકલીફ છે? જગ્યાઓ શા માટે નથી ભરતા? મનગમતા અધિકારીઓ નથી મળતા એટલા માટે? કેટલો સમય આવી રીતે ચલાવશો?

ઓખાથી શરૂ કરીને વાપી સુધીનો દરિયાકાંઠો આવેલો છે. પાકિસ્તાનની સરહદથી શરૂ કરીને આપણા રાજ્યનો છેવાડાનો વિસ્તાર એમાં જેટલા મવાલીઓ, ગુંડાઓ છે એને રાજ્યાશ્રય મળે છે. પોલીસતંત્રને કહેવામાં આવે છે કે સામેના લોકો છે એની ઉપર લૂંટનો ગુનો દાખલ કરો, એની ઉપર ખૂનનો ગુનો દાખલ કરો. હું આપની મારફત ટ્રેઝરી બેંચને વિનંતી કરુ છું કે આવો જેણે જેણે દુરપયોગ કર્યો છે એને સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. હું કહીશ કે પ્રજા આવા કૃત્યોને કયારેય માફ કરતી નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું જુદા જુદા વિસ્તારમાં ગયો છું. હું વેરાવળમાં ગયો છું. કોડીનાર અને વલસાડ સુધી ગયો છું. મેં નજર સામે જોયું છે કે કોઈ પણ કારણ વગર પોલીસ અધિકારીને એમ કહેવામાં આવે કે આની સામે ૩૯૫નો ગુનો દાખલ કરો. ગુનો દાખલ થયો અને ૧૫-૧૫ દિવસ સુધી જીવનમાં જેની સામે ૧૫૧ની કલમ નહોતી લાગી એવા લોકોને જેલમાં રહેવું પડ્યું. હું એવા પોલીસ અધિકારીઓને અભિનંદન આપું છું કે વેરાવળમાં એક પોલીસ ઈન્સ્પૅક્ટરને એમ કહેવામાં આવ્યું કે તમે સંસદસભ્યના ભાઈની સામે ૩૯૫ દાખલ કરો. તેણે ન કર્યું, એટલું જ નહીં, ડાયરૅક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસને ફોન કરીને કહ્યું કે હું આવા ગેરકાયદેસર કૃત્યો છે તેને શરણે નહીં થાઉં. રામરાજ્ય આને ન કહેવાય. રામરાજ્યની કલ્પનામાં રાજ્યના શાસનના વડા પાસે માણસ આવીને ખોળો પાથરે કે મને તકલીફ છે તો તેના માટે થઈને તેનું હૈયું હચમચી ઊઠે અને ન્યાય અપાવે તેને રામરાજ્ય કહેવાય.

માનનીય શંકરભાઈ વાત કરતા હતા. સિંચાઈની. તેમણે એમ વાત કરી કે અમે બોરીબંધો બાંધ્યા. અમે બીજા ડૅમો બાંધ્યા. તળાવો બાંધ્યા. બંધાય, રાજ્યમાં પ્રગતિ ચાલુ રહેતી હોય છે. આપણે શાસનમાં આવીએ એટલે પ્રગતિ ચાલુ થઈ જાય અને બીજાં આવે એટલે બંધ થઈ જાય એવું નથી. ગતિ વધઘટ હોય પણ ચાલુ હોય છે. મને આનંદ એ વાતનો છે કે તેમણે ગોરધનભાઈ ઝડફીયાનું નામ આપ્યું કે ગોરધનભાઈએ માથે બોરી

લઈને બોરીબંધો બાંધ્યા. મને આનંદ છે અને હું ગોરધનભાઈને ધન્યવાદ પણ આપું કે બોરીબંધ બાંધવામાં ઘણી આગેવાની લીધી, પણ રાજ્યનું શાસન ચાલે છે. ગોરધનભાઈ જેવા મારા સામેના વડીલો અને યુવાન મિત્રો છે. કોંગ્રેસના શાસનની સામે વર્ષો સુધી વિરોધ કરીને લડ્યા છે અને ખુમારીથી લડ્યા છે. તેને કારણે કદાચ આપ બધા જ શાસન ઉપર બેઠાં હશો. પણ અમારા રાજ્યમાં ગોરધનભાઈ ઝડફીયાએ એકેય દિવસ રડવું પડ્યું નહોતું. તેણે ભય વ્યક્ત કરવો પડ્યો નહોતો.

શ્રી ગોરધનભાઈ પ્રા. ઝડફિયા : Sir, this is my personal and internal matter of my party.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : મેં એમ નથી કહ્યું કે તમે રડ્યા હતા, મેં એમ કહ્યું કે રડવું પડ્યું નહોતું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું ઇચ્છું કે આ સભાગૃહમાં ચર્ચાઓ થાય, મેં તો જે જે જગ્યાએ મને તક મળી છે ત્યાં કહ્યું છે, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં આપને પણ કહ્યું છે કે ગૃહમાં ચર્ચાઓ થાય, ગૃહની બહાર પણ થાય. તેની મર્યાદાઓ આપણે બધાં જ નક્કી કરી નાખીએ. પણ કિન્નાખોરીની મર્યાદાઓ પણ આપણે નક્કી કરવી પડશે. રાજ્યની અંદર છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ચાલ્યું છે(અંતરાય) ઈનકમટેકસની રેડની વાત છોડો, આ કરો ને, અત્યારે જે કરાવો છો તે. અહીં ગુજરાતમાં ચાલે છે. ત્રણ વર્ષની અંદર તેનો જવાબ દરેકે દરેક તબક્કે આપવાનો હોય છે. એ જવાબ આપવાની અંદર હું પણ ન છટકી શકું અને આપ પણ નથી છટકી શકવાના. કદાચ એવું હશે કે જવાબ નથી આપવો પડવાનો પણ આપવો પડવાનો છે. ગુજરાતની પ્રજાએ સમય આવ્યો ત્યારે જવાબ આપ્યો છે. ગુજરાતની પ્રજાએ સમયે સમયે જવાબ આપ્યો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અત્યારે જે ચાલે છે તેની વાત કરતો હતો. અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં ગુનેગારો પાસેથી પોલીસ અધિકારીઓએ સર્ટિફિકેટ લેવા નહોતા પડતા અને અત્યારે ગુનેગારોનો ઉપયોગ પોલીસ અધિકારીઓને અને રાજકીય માણસોને દબાવવામાં થાય છે. અખબારોને દબાવવામાં થાય છે. પોરબંદરમાં એક આર.ડી.એક્સ.ના ગુનેગાર સાથે એક અધિકારીએ વાત કરી. આ અધિકારીએ વાત કરી તે કોઈએ રૅકૉર્ડ કરી લીધી. અને એ ગુનેગારો અને પોલીસ અધિકારીઓ વચ્ચેની એ ચર્ચા છાપાઓમાં આવી અને ઓફિશિયલ સિક્રેટ એકટ હેઠળ એનો ગુનો નોંધ્યો. હું કહેવા માગું છું કે, મેં જાહેરમાં બહાર કહ્યું છે અને અહીંયાં કહું છું કે, હું એની જવાબદારી લેવા તૈયાર છું. અખબારોનું ગળું ઘોંટાવીને કયારેય રાજ્ય થઈ શક્યું નથી અને કોઈ એમ માનતું હોય કે, ડરાવી, ધમકાવીને શાસન થઈ શકશે તો કોઈ દિવસ ગુજરાતની પ્રજાએ આ પ્રકારનો એપ્રોચ સહન કર્યો નથી.

ઘણી બધી ચર્ચાઓ આની અંદર અપાઈ છે અને ઘણી ખરી પ્રશસ્તિ થઈ છે. પ્રશ્નોની ચર્ચા થઈ હોત તો હું ચોક્કસ સૂચનો કરત. આ દિશાની અંદર ગુજરાતે જવું હોય તો આટલું આટલું કરવું પડે એમ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સાગર કિનારાની વાત કરી. હું પણ બંદરો સાથે સંકળાયેલ છું, એન્જિનિયર છું. આખા દેશની અંદર લાંબામાં લાંબો દરિયા કિનારો ગુજરાત પાસે છે. દેશની અંદર વિકાસની અંદર આ કોરીડોર બની શકે એવો દરિયા કિનારો છે. આ દરિયા કિનારાના વિકાસની વાતો આ રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં કયાંય ઉજાગર કરી શકાયેલ નથી. એની અંદર ટુરિઝમ વિકસાવવાનું શકય છે, પણ એની વાત પણ એમાં આવી નથી અને બીજી મહત્ત્વની વાત ભૂલી જવાઈ છે એ એ છે કે, ૩૦ લાખ હેકટર વિસ્તાર છે એ ખારો થઈ ગયેલ છે. છેલ્લા દાયકાની અંદર એ ખારાશવાળો વિસ્તાર વધીને ૮૦ લાખ હેકટર થયો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સુઝલામ-સુફલામની શ્રી પ્રબોધકાંતભાઈ વાત કરતા હતા. મારે પૂછવું છે કે, આ ૮૦ લાખ હેકટર વિસ્તાર માટે સુઝલામ્-સુફલામ્ કયાં છે કે એને સુઝલામ્-સુફલામ્નું ખારું પાણી આપવાનું છે? સ્ટીલની પાઈપો નાખી એનાથી માત્ર પૂરું નહીં થાય. કેનાલો દ્વારા, ડૅમો દ્વારા અને ખારાશ રોકીને આપણે આ ખેડૂતોના ખેતર સુધી પાણી પહોંચાડી શકીએ એમ છીએ. પણ ૧૬૦૦ કિલોમિટરનો દરિયા કિનારો છે પણ પચાસ-પચાસ કિલોમિટર સુધી ખારાં પાણી આવી ગયાં છે એના માટે એની અંદર કોઈ વાત નથી થઈ. દરિયા કિનારે અમારા સાગરપુત્રો વસે છે અને એ સાગરપુત્રો માટેની યોજનાઓ સંપૂર્ણપણે બંધ કરાવી દેવાઈ છે. સબસિડી કોંગ્રેસના રાજમાં અપાતી હતી. આટલી મોંઘવારી હોવા છતાં પણ ડિઝલની અંદર એક રૂપિયાની પણ સબસિડી અપાતી નથી અને એ પણ સમયસર અપાતી નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બંદરો બાંધવાની યોજનાઓની જાહેરાતો થઈ. પણ ફિશરમેન માટેની કોઈ યોજનાઓ જાહેર થઈ નથી. ટૅન્કરોના ભ્રષ્ટાચારની વાત કરી, સુનામીની વાત કરી, ટૅન્કરો બંધ કરવા જોઈએ એમાં કોઈ બેમત નથી. અને એમાં વાત કરી કે, બધું અમે આવ્યા પછી થયું. પણ ગુજરાતની અંદર આ સરકાર આવી એના પહેલાંની સરકાર આવી એ પહેલાં ૯૯ ટકા ગામડાં સુધી રસ્તાઓ બનાવી દીધા, ૪૦ વર્ષમાં નહોતા બનાવ્યા એવું નથી. ૯૮ ટકા ગામડાંના વિસ્તારની અંદર વીજળીકરણ થઈ ગયેલું. માત્ર ૨ ટકા વિસ્તારની અંદર, ૨ ટકા ખેડૂતોને કનૅક્શન આપવાના બાકી છે. સૌરભભાઈ તમારી પાસે પૈસા નથી એટલે તત્કાળ યોજનાઓ લઈ આવ્યા છો, મફત આપી તો જુઓ? એના માટે ૩૬ ઈંચની છાતી જોઈએ, તમારી તાકાત નથી અને ૩૬ ઈંચની છાતીની વાત કરો છો. ખેડૂતોને વીજળી આપવા માટે ૩૬ ઈંચની છાતીની વાત કરો છો. જે રસ્તાઓ બાકી છે એ તો કરાવો. જે કરવાનું છે એ કરોને એમાં કોઈ વાંધો નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સહકારની વાત થઈ. આમ તો જેટલા વિભાગો છે એમનું કાંઈકને કાંઈક આપવું જોઈએ, પણ સહકાર છે, એ તો એક આંદોલન છે મને આનંદ થાત આ આંદોલનને જો સમજી શકાયું હોત તો અને આ આંદોલન કોઈ રાજકીય પક્ષોએ નહીં પણ આ દેશની પ્રજાએ આપેલું અને મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર પટેલે એને આગળ વધારેલું, આ યોજના છે એ કોઈ રાજ્યની યોજના નથી, પરંતુ અત્યારે ગ્રાસરૂટ લેવલની સહકારી સંસ્થાઓ છે એને તોડી પાડવાની જે પ્રવૃત્તિ થાય છે, એને ફડચામાં લઈ જવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને માત્ર રાજકીય કારણોસર બહુમતી ન હોય એટલે એની ચૂંટણીઓ ન થવા દેવી અને વહીવટદારો મૂકવાની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. તો આ કેટલો વખત ચલાવશો અને આવી રીતે બહુમતી કદાચ જગતની અંદર કોઈ તાનાશાહી લઈ આવ્યા હશે તો પણ એમનું ચાલ્યું નથી અને એ રીતે કોઈપણ જગ્યાએ આપનું પણ આ ચાલવાનું નથી. આખરે સહકારી સંસ્થાઓના સભાસદો નક્કી કરે એ જ વહીવટીતંત્ર આવવાનું છે અને અત્યારે અર્બન બેંકો છે એમાં મુશ્કેલીઓ છે એમાં કોઈ પગલાં લેવામાં આવતાં નથી, પરંતુ જે ખેડૂતો, મહિલાઓની, ગરીબ માણસોની જે સહકારી સંસ્થાઓ છે અને એની જે રાજ્ય કક્ષાની સંસ્થાઓ છે એની અંદર ચૂંટણીઓ થવા દેવાતી નથી. ગુજકોમાસોલની અંદર ૧૫ મહીના સુધી ચૂંટણીઓ થવા ના દીધી. રાજ્યની એપેકસ બેંકની અંદર આજે આટલા વખત પછી પણ ચૂંટણીઓ નથી થવા દેતા. આ લાંબુ ચાલવાનું નથી. ખેતીવાડીની વાત આવે છે એની અંદર ચિંતા થાય છે એમાં અમે પણ સૂર પૂરાવીએ. આખરે ગુજરાતના ખેડૂતો સમૃદ્ધ હશે તો દેશ સમૃદ્ધ થવાનો છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની એક બહુ સારી વાત હું યાદ કરાવવા માગું છું કે કે, ગયા વર્ષે ગુજરાતની અંદર આ વખતે મબલખ ઉત્પાદન થયું એની મહેનતનો યશ હું લેવા માગતો નથી. એની મહેનત ખેડૂતોએ કરી છે એના કારણે થયું છે. વરસાદ બહુ સારો થયો એ કુદરતે આ વરસાદ અપાવ્યો છે એનો યશ પણ હું લેવા માગતો નથી, પરંતુ એક વાત જરૂર કરી હતી ગયા વખતે કે ગુજરાતની અંદર ઉત્પાદનના ભાવ વધારે મળ્યા છે એનો યશ હું લેવા માગું છું અને એના યશનો ભાગીદાર હું છું એવી વાત માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કરી હતી. મારા મિત્રોએ એ વખતે બધી પાટલીઓ થપથપાવીને વાત કરી હતી, પણ આ આજે કપાસના ભાવ તળીયે બેસી ગયા છે એના માટેની જવાબદારી પણ આપે લેવી પડશે અને એમ કહેવું પડશે કે એના અપયશનો જવાબદાર પણ હું છું, પણ એની અંદર કોઈ જવાબદારી લેતું નથી અને નાફેડ હોય કે સી.સી.આઈ. હોય આ બંને સંસ્થાઓ કેન્દ્ર સરકારની છે. મારે એમને અભિનંદન આપવા છે, એમના મંત્રી શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલાને અભિનંદન આપવા છે કે સૌથી વધારેમાં વધારે ૪૬ કેન્દ્રો અહીં ગુજરાતમાં ખોલી અને ગુજરાતના ખેડૂતોની વહારે આવ્યા છે. હું વિનંતી કરીશ આપના મારફતે કે મહારાષ્ટ્રના ધોરણે કપાસની ખરીદી કરો અને ગુજરાતના ખેડૂતોને બચાવો પણ એ કામ નથી કરવું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આર.ટી.ઓ.ની વાત આવે તો આર.ટી.ઓ.ની આવક ઘણી બધી વધી છે અને મને એ વાતનો આનંદ છે. એના માટે મને તકલીફ નથી કોઈ પણ, હું તો માત્ર સરખામણી કરીશ કે ગુજરાતનું એસ.ટી. કોર્પોરેશન ૨૦૦ કરોડ કરતાં વધારે પેસેન્જર ટેકસની આવક આપે છે. મારા સાથી પક્ષના સભ્યોને મારે પૂછવું છે કે છાતી ઉપર હાથ રાખીને ઈશ્વરને સાક્ષી રાખીને વાત કરે કે તમારા ગામડાની અંદર ૧૦ વર્ષ પહેલાં જેટલી બસો આવતી હતી એના ચોથા ભાગની બસો અત્યારે આવે છે કે કેમ અને આજે બસોની હાલત પણ કેવી છે? ૮૦૦૦ બસો હતી એમાંથી ૩૫૦૦ બસો ચાલતી નથી અને બસ નથી આવતી એટલે બિચાર લોકો છકડામાં બેસીને આવે છે. છકડામાં કોઈને બેસવું ગમતું નથી, બધાને સારી ગાડીઓમાં બેસવું છે પણ એમના માટે વાહન નથી. છકડામાં આવે અને એના ઉપર કેસો થાય અને મારા સાથી સભ્ય પરસોત્તમભાઈએ અહીંયાં બોલવું પડે કે ગાંધીનગર આગળથી મોટી મોટી બસો, જીપો પસાર થાય એ દેખાય નહિ અને છકડા છેવાડાના ગામમાં જતા હોય, ગરીબ માણસ ચલાવતો હોય એના ઉપર દંડ કરીને આવક વધારવી હોય તો મને વાંધો નથી. આવક વધી તો શું થયું ખબર છે? ૧૯૯૪-૯૫માં શાસન સોંપ્યું હતું એમાં ૧૨,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાનું કરજ હતું અને જે ડૅફિશિએટ હતી એ વધારી વધારીને ૬૦૦૦ કરોડ સુધી લઈ આવ્યા. ગઈ વખતે વાત કરી હતી કે અમે ૨૫૦૦ કરોડ સુધી લઈ આવીશું, પણ ૩૮૦૦ કરોડથી નીચે આવ્યા નથી અને કરજ ૬૦ હજાર કરોડનું. આટલી આવક વધારી તો ગુજરાતની પ્રજા ઉપર કરજ શા માટે વધાર્યું? વહીવટ સારો છે કે ખરાબ છે એ મારે નથી કહેવું, ગુજરાતની પ્રજાને નક્કી કરવા દેવું છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વીજળીની વાત થઈ. નાનાં કારખાનાં નાખવાનાં, નવાં થર્મલ પાવર સ્ટેશનો નાખવાની વાત થઈ, પણ વીજળીની અને ઉર્જાશકિતની વાત કરવા છતાં ગુજરાત આજે વીજળીની ખાધવાળું રાજ્ય છે એમાંથી એને બહાર લાવી શક્યા નથી એ કેવી નીતિ લઈ આવ્યા આપણે? અમે ઉર્જાશકિતનો પ્રયોગ નહોતો કર્યો છતાં ભૂતકાળમાં ખેડૂતોને ૧૨ કલાક વીજળી આપતા હતા. જ્યારે સિઝનનો સમય હોય, ચોમાસાનો સમય હોય, ખેડૂતોને જરૂર હોય ત્યારે ૨૦ કલાક વીજળી આપી છે. મારા સાથી મિત્રોને અને કનુભાઈને પૂછવું છે, ગોવિંદભાઈને પૂછવું છે, ધીરુભાઈને પૂછવું છે કે છાતી ઉપર હાથ રાખીને નક્કી કરો કે આઠ કલાક નહિ, છ કલાક વીજળી આપી છે ખરી? તમે ભાવો ડબલ કરી નાખ્યા પણ વીજળી આપતા નથી. સિંગલ ફેઈઝની વીજળીમાં ગરીબ માણસો હતા એને મહિને ૧૦૦ યુનિટ વીજળી વાપરે તો ૨૫ ટકાની સબસિડી અપાતી હતી એ સબસિડી પાછી ખેંચી લીધી. સતત પ્રક્રિયાવાળા ઉદ્યોગો હતા એની વીજળીની ડયૂટી

હતી એમાં રાહત આપી. ગરીબ માણસો અને ખેડૂતોને રાહત ન અપાઈ. મારે એ કહેવું છે કે ગામડાંની અંદર આમ કરવાથી રામ રાજ્ય આવવાનું છે? બધાએ આત્મખોજ કરવાની જરૂર છે. એ આત્મખોજ નહિ કરીએ તો ગુજરાતની પ્રજાએ અવાર નવાર શાસકોને આત્મખોજ કરાવી છે અને કરાવતી રહેવાની છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શિક્ષણની વાત થઈ. મને એમ હતું કે આટલું બધું બહારથી કરજ લઈ આવ્યા છીએ અને આટલી બધી ગુજરાતની અંદર જે પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે, ખાસ કરીને કેન્દ્ર સરકારની બધી જગ્યાએ મદદ મળે છે તો મને એમ હતું કે સાક્ષરતાના દરમાં આપણે બીજા રાજ્યો કરતાં આગળ નીકળી અને એક વખત ગૌરવ લઈ શકીશું કે ગુજરાત હવે સંપૂર્ણપણે ૧૦૦ ટકા સાક્ષર રાજ્ય છે. ૧૯૯૧ની વસ્તી ગણતરીનો ત્યારે આંકડો મેં આપ્યો, સ્વીકારવું જોઈએ કે છેલ્લા ૧૦-૧૫ વર્ષમાં સાક્ષરતા પાછળ જોઈએ એવું કામ થયું નથી. રાજ્ય સરકાર કોઈની હોય, કોઈની ન હોય પણ આ વાત ગાઈ-વગાડીને કહેશો તો પ્રગતિ થશે પણ એ વાત સ્વીકારાઈ નહિ, ઉડાવી દેવામાં આવી. આપણું સ્થાન નવમા નંબરનું હતું એ સોળમા નંબરે ગયું અને છતાં એમ કહે છે કે અમે કન્યા કેળવણી રથ લઈને બહાર નીકળ્યાં છીએ. એ કન્યા કેળવણી રથથી નહિ થાય. એના માટે ગામડાંમાં શિક્ષકો મોકલવા પડશે. મારે અહીં ફરીથી કહેવું છે કે તમારી છાતી ઉપર હાથ મૂકીને ઈશ્વરની સાક્ષીએ કહો કે ગામડાંમાં તમારી નિશાળમાં પૂરતા શિક્ષકો આપ્યા છે કે નહિ? ૮૦ હજાર શિક્ષકો ભરવાની વાત કરી. કેટલા નિવૃત્ત થયા અને એની જગ્યાએ કેટલા ભર્યા અને વધારાના શિક્ષકો કેટલા ભર્યા એના આંકડા કોઈક દિવસ આપો. એટલું જ નહિ, હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે અમારા જુનાગઢ જિલ્લામાં શિક્ષકો ભરવાની વાત આવી અને જિલ્લા બહાર દોઢસો શિક્ષકો બદલી કરીને જતા રહ્યા અને ૬૦૦ શિક્ષકો નિવૃત્ત થયાં એની જગ્યા ખાલી થઈ. પેલા શિક્ષણાધિકારીએ ૬૦૦ ખાલી જગ્યા અને ૧૫૦ જિલ્લા ફેર ગયા એના સાડા સાતસો શિક્ષકો છે એની ભરતીના ઑર્ડર કાઢ્યાં અને એમણે દોઢ સો જિલ્લા ફેરવાળા નહિ આપ્યાં. આ જગ્યા ખાલી છે, રજૂઆત કરી એ લોકોએ ઉપવાસ, આંદોલનો કર્યા અને હજુ બેઠા છે, પણ દોઢ સો શિક્ષકોની ભરતી થતી નથી. તો આ રથયાત્રા નહિ પણ ગામડામાં શિક્ષકો છે એમને મોકલો, પીવાનું પાણી આપો. અમારાં જશુબેને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો પાછું એમ કહે કે, પચાસ વર્ષ સુધી કાંઈ ના થયું. પચાસ વર્ષમાં કેટલા ઓરડા બન્યાં, કેટલી નિશાળો બની. પાણી, એ જમાનાની અંદર પાણી નહિ, આપણે ટોયલેટ-બાથરૂમની ક્યાં વ્યવસ્થા હતી. જન્મ થયો ત્યારે આપણે પૂછીએ કે આપણે કઈ નિશાળની અંદર આપણે તો ઠીક આપણાં ઘરમાં પણ ટોયલેટ-બાથરૂમની વ્યવસ્થા હતી? આજે જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે તો આપીએ છીએ. આપણે વિકાસની સાથે આ બધાની જરૂર પડવાની એ આપવાનું છે પણ પાણી તો આપો. કાંઈ નહિ આપો તો કાંઈ વાંધો નહિ, પણ અમારાં બાળકોને ભણવા માટે શિક્ષકો તો મોકલો અને શિક્ષકો નહિ મોકલો તો આ રથયાત્રાથી કાંઈ થવાનું નથી અને પછી અમારે તમાશો કહેવું પડે ત્યારે ગુસ્સે થવાની જરૂર નથી. કોઈ વસ્તુ નહિ તો બચાવનારા લોકો છે એ આજે સામે આવી ગયા છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આદિવાસી વિસ્તારની વાત થઈ. સુજલામ્ સુફલામ્‌ની વાત થઈ અને પાણી હોય, હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે, શિક્ષણ અને પાણી આ બે વસ્તુ એવી રાખીએ જેના અંદર સામૂહિક ચિંતન કરી અને એમાં સાથે મળીને વાત કરીએ અને રાજનીતિ પર રાખીએ પણ ચર્ચા થઈ છે એટલે હું જવાબ આપીશ. હું હમણાં જ દાહોદ-ગોધરા તરફ ગયેલો અને એ વખતે મેં કડાણા ડેમની મુલાકાત લીધેલી. હાઈ લેવલ કેનાલ નીકળે છે, પાણી વિસ્તારમાં જાય છે મને આનંદ થયો છે. કેનાલ બાંધી એના વખાણ કરીએ તો કોઈક દિવસ કડાણા ડેમ બંધાણો એના પણ વખાણ કરજો. કેનાલ બાંધવાની અંદર કોઈ ડિઝાઈનની જરૂર નથી પડતી. કડાણા ડેમ પણ બંધાયો હતો અને એના કારણે કેનાલ નીકળી છે અને મારે એ કહેવું છે કે આજે ૬૦ ટકા ડેમોની આ જે ક્ષમતા છે એ માત્ર કેનાલો ના હોવાને કારણે ખેડૂતોના ખેતર સુધી પાણી પહોંચી શકતા નથી પણ મારે વાત એ કરવી હતી, આ પાણી હાઈ લેવલ કેનાલથી ભલે લઈ જાય છે. પરંતુ એ કેનાલના કાંઠે રહેનારા આદિવાસી લોકો છે એ મારી પાસે આવ્યાં, મને કહ્યું કે અમને આ કેનાલમાંથી પાણી આપવાની ના પાડવામાં આવી છે. જ્યાં પાણી છે જે આદિવાસી વિસ્તાર છે તેને માટે થોડુંક તો સુજલામ્ સુફલામમાં રાખજો.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું વાત એ કહેવા જતો હતો હમણાં અમારા પ્રબોધભાઈ કહેતા હતા કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર સુજલામ્ સુફલામની અંદર ૫૩૭ કરોડની જોગવાઈ કરી. આ વર્ષની અંદર પણ હું કહેવા માગું છું સરકારનો રેકોર્ડ જોઈને કે ૫૩૭ કરોડમાંથી ૩૫ લાખ રૂપિયા ખર્ચ થયો છે અને છતાંય યોજના કાગળ ઉપર બનાવે મને કોઈ વાતનો વાંધો નથી. કચ્છની વાત કરી. મારે કહેવું છે, જ્યારે આ નીતિ-નિર્ધારણ કરનારા નર્મદા યોજનાનો અમલ, જ્યારે એને મંજૂર કરવાની હતી ત્યારે જે પંચ હતું, સુપ્રીમ કોર્ટ હતી એ બધાની પાસે આપણે ખાતરી માગી છે કે ગુજરાતની અંદર જે નપાણિયા વિસ્તાર છે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ એના માટે થઈ આ યોજના બનાવી છે, એનું પાણી ક્યાં સુધી, ક્યારે પહોંચવાનું છે એની ખાતરી નથી અપાઈ. નર્મદા યોજના છે એ ગુજરાતની મા છે એના વિષે મારે કોઈ ટીકા-ટિપ્પણ નથી કરવી. હું એમ પણ નહિ કહું કે રાજસ્થાનની અંદર, મહારાષ્ટ્રની અંદર, મધ્યપ્રદેશની અંદર કોઈની પણ સરકારો છે એની ચર્ચા હું અહીં નહિ કરું. આ બધી બાબતની અંદર અમે તમારી સાથે છીએ એટલી ખાતરી આપવા માગું છું. મહારાષ્ટ્રને વાત કરવી હશે કે કેન્દ્ર સરકાર પાસે વાત કરવી હશે, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન પાસે તમે સક્ષમ છો પણ આની સાથે

કરવી હશે તો હું તમારી સાથે રહેવા માગું છું, અમારો પક્ષ તેની સાથે રહેવા માગે છે. માનનીય મંત્રીશ્રી, મેઘા પાટકરને એક સમિતિની અંદર જે જોડવાની વાત કરી, રાજનીતિની વાત નથી કરતો જેવી આ વાત મને કરી, એમણે જેવી વાત અમારા નેતા અહેમદ પટેલને કરી, બીજે દિવસે મેઘા પાટકરને એ સમિતિ સાથે જોડાવવા માટેના બધા જ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા. આ નર્મદા મુદ્દાની અંદર ગુજરાતે ભૂતકાળની અંદર જે એકતા બતાવી હતી એ બતાવવાની જરૂર છે અને ભૂપેન્દ્રસિંહજી મારે એમને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફતે કહેવું છે કે, જ્યારે એ નર્મદાના ચેરમેન હતા ત્યારે રાજનીતિથી પર રાખવાની વાત કરતા, આજે આપના સાથી સભ્યોને કહેજો કે, નર્મદા યોજનાને રાજનીતિથી પર રાખે. ૨૦૦૫માં સુપ્રીમ કોર્ટમાં આપણે ખાતરી મેળવી છે, ૨૦૦૫ સુધીમાં નર્મદા યોજના પૂરી કરવાની છે જ્યારે એના બધા હર્ડલ્સ, નર્મદા યોજના સામેના દૂર કર્યા, પરંતુ ૨૦૦૫માં શું સ્ટેટસ છે? એનો રિપોર્ટ ગુજરાતની પ્રજાને આપે અને નર્મદા યોજનાનું કામ કયારે પૂરું થવાનું છે એ આપે તો સારું. ૨૦૧૦ સુધીમાં થઈ જાય એવી સ્થિતિ અત્યારે દેખાતી નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કલ્પસર યોજનાની વાત આવે છે, પરંતુ કલ્પસર યોજનાને રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં મૂકવાની જરૂર નહતી. આ યોજના થાય તો સૌથી પહેલાં હું ખુશ થઈશ, પરંતુ જે યોજનાઓ અત્યારે આપણી અસ્તિત્વમાં છે, જેનો લાભ સીધો ગુજરાતની પ્રજાને મળે એમ છે એમાં કોઈ નિષ્ફળતા હોય એને ઢાંકવા માટે કલ્પસર તમને આપીએ છીએ, એ સ્વપનાં વેચવાની જરૂર નથી. બહું સ્વપનાં વેચ્યાં, હવે સ્વપનાં વેચવાની જરૂર નથી. વાસ્તવિક રીતે કઈ યોજના, કયાં સુધી અને કેટલા સમયમાં થવાની છે એનો સમયબદ્ધ કાર્યક્રમ નક્કી કરી ગુજરાતની પ્રજાને પાણી પહોંચાડવાનું કામ રાજનીતિથી પર થઈ આપણે કરીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ફરી પાછો હું શિક્ષણ ઉપરની વાત ઉપર આવું તો સાક્ષરતા દરની વાત કરું તો સાક્ષરતા દરમાં આપણે ખૂબ પાછળ રહી ગયા છીએ. શું પ્રયત્નો કર્યા એના માટે? આખરે જે વર્ગ છે શાળાએ ન જતો એ વર્ગ તો બહુ મર્યાદિત છે. એ વર્ગની ખબર ન હોય સરકારને તો હું કહેવા માગું છું કે શિક્ષણ કયા વર્ગમાં નથી. આદિવાસી વર્ગમાં નથી, દલિત વર્ગમાં નથી, જે રખડતી ભટકતી જાતિ છે એમાં નથી, પછાત વર્ગોમાં નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે આપના મારફતે સરકારને પૂછવું છે કે, તમે એક એનાલીસીસ કરી જુઆ કે શિક્ષણમાં જે રાજ્ય સરકારનું બજેટ આવે છે એ રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી આ વિસ્તારની અંદર માત્ર સાક્ષરતાની જ વાત કરું તો એ લોકોને સાક્ષર બનાવવા માટે કેટલા પ્રયત્નો કર્યા? કેટલો ખર્ચ કર્યો આપે? કેટલી એન.જી.ઓ.ને એની જવાબદારી સોંપી? આખરે કેરળ અને તામિલનાડુ છે એ સો ટકા સાક્ષરતા પ્રાપ્ત કરી છે એમની પાસે કાંઈક તો શીખવું જોઈશે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પણ પી.ટી.સી., બી.એડ કૉલેજો કે એન્જિનિયર કૉલેજો, મારા-તમારાને આપીને સાક્ષરતાનો દર છે એ સો ટકા સુધી ન પહોંચાડી શકાય. બે-પાંચ માણસોને રાજી કરી શકાશે, કોઈનાં ખિસ્સાં ભરાશે, પરંતુ એનાથી ગુજરાતમાં સો ટકા સાક્ષરતા પ્રાપ્ત કરવી છે એ પ્રાપ્ત નહીં થઈ શકે. શ્રી શંકરભાઈ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા છે એ હું માનું છું એટલે એમને વાત કરીશ, સ્ત્રી શિક્ષણની. રાજનીતિમાં આવ્યા એના પહેલાં અમે પણ શિક્ષણ સાથે સો ટકા વરેલા હતા, શિક્ષણની એ.બી.સી.ડી. કોઈ પાસે શીખવાની જરૂર નથી. આજે હું કહેવા માગું છું કે, સરકારના પ્રયત્નોથી નહીં, પરંતુ ઘ ણા સમાજો એવા છે અને શંકરભાઈ, આપનો સમાજ પણ એમાંનો હશે કે જેમાં દીકરાઓ કરતાં દીકરીઓને ભણાવવામાં એને તક આપી એટલે આગળ નીકળી ગઈ છે અને જ્યાં તક નથી મળી એણે નિશાળનો દરવાજો હજુ સુધી દેખ્યો નથી એ નિશાળનો દરવાજો એમને બતાવવાનો સમય આવ્યો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગઈ કાલે વાત કરી કે, આપણે બધાએ જોવું જોઈએ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહની બહાર આ બાબતમાં ચર્ચા કરવી હોય તો અમારી તૈયારી છે. શિક્ષણ અને પાણી એ બે વસ્તુ એવી છે આ રાજ્યમાં એ આખા વિશ્વને એક નમૂનેદાર રાજ્ય બનાવવામાં બે જ બાબત છે રાજ્યની એ આગળ લઈ જઈ શકે એમ છે અને એમાં અમારી તૈયારી છે પણ વાતો એવી કરવી કે ભૂતકાળમાં આમ હતું, ભૂતકાળમાં તેમ હતું. ન્યાય પ્રથા અમારી ઊંચી, અમારું પોલીસ તંત્ર ઊંચું, અમારું શાસન ઊંચું. એમ કહેવાથી ન થાય એના માટે તો દાખલો બેસાડવો પડે છે અને દાખલો બેસાડવાનું કામ રાજ્યના વડાથી માંડી છેવાડાના કર્મચારી સુધી બધાએ દાખલો બેસાડવો પડશે.

અધ્યક્ષશ્રી અધ્યક્ષસ્થાને

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું એ વાત કરતો હતો કે ભારતના જે મોટા રાજ્ય માર્ગો છે એ રાજ્ય માર્ગોને ચાર માર્ગીય બનાવવાનું આયોજન સ્વ. નરસિંહરાવની સરકાર વખતે થયેલું અને મને આનંદ છે કે આ કામ અગાઉની એન.ડી.એ. સરકારે પણ આગળ વધાર્યું અને ચિંતા એ થઈ મારા મિત્રોને કે એ રસ્તાઓ ઉપર આદરણીય બાજપાઈજીના ફોટા હતા એ હટાવી લેવામાં આવ્યા અને બીજી વાત એ કરી કે રસ્તાના કામો બંધ થઈ જશે. આ સરકારે જાહેરાત કરી છે કે આ રસ્તાનાં કામો આગળ વધવાનાં છે અને સંસદ માટે ચૂંટણી થઈ એની પહેલાં ખાતમૂહૂર્ત તો ઘણાં બધાં થયેલાં ચાર માર્ગી રસ્તાનાં અને એમાનું એક ખાતામુહૂર્ત આદરણીય અડવાણીજીના હસ્તે પોરબંદરમાં થયેલું, પણ એ કામ આગળ વધી શક્યું નહોતું. એના પછીની સરકારે આ કામ મંજૂર કર્યા અને ૨૫૦૦ કરોડના ખર્ચે રસ્તા બનાવવાના છે. પોરબંદરથી ડીસા સુધીનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે

એટલે રસ્તાનાં કામો બંધ થશે એવી ચિંતા રાખવાની જરૂર નથી, પરંતુ બાજપાઈજીના ફોટા ઉતરી ગયા એની ચિંતા મિત્રોને છે. દેશ સેવામાં એમણે ઘણાં બધાં વર્ષો ગાળ્યાં છે. અમારા નેતા વિશે બોલશે પણ એમના વિશે કાંઈ નહીં બોલે. ફોટા કેમ ઉતરી ગયા એની આત્મખોજ કરવાની જરૂર છે.બાજપાઈજી અમદાવાદમાં આવ્યા અને અમદાવાદમાં આવીને વાત કરી કે રાજા હોય એમણે રાજધર્મ બજાવવો જોઈએ. રાજધર્મ ન બજાવ્યો અને ચૂંટણી હારી ગયા. સિમલામાં બાજપાઈએ કહયું કે લોકસભાની ચૂંટણીની હારનું મુખ્ય કારણ જે તે વખતની ગુજરાતની સરકાર વખતે થયેલા કોમી રમખાણો છે અને એને કારણે હારી ગયા છીએ. આ બાજપાઈજીનું કહેવું છે, મારા સાથી મિત્રો છે એમની જે તે વખતની સરકારના વડાને અને અત્યારના વડાને સમજાવી શક્યા હોત તો બાજપાઈના ફોટા ઉતારવાનો વખત ન આવ્યો હોત. બાજપાઈ ઘણી વખત ગુજરાતમાં સલાહ આપતા હતા એમાંથી થોડી સલાહ મનાઈ હોત તો આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ન થાત. પરંપરા તો આ દેશની એવી રહી છે કે વડાપ્રધાન આવે અને જાય. નવા વડાપ્રધાન આવે એટલે જે વડાપ્રધાન ગાદી ખાલી કરવાના હોય એને વિવેક ખાતર પણ મળવા જાય. બજેટની ચર્ચા કરવાની હોય કે બીજી વાત કરવાની હોય ત્યારે અરસપરસ આદરભાવ અને અરસપરસ માનથી એક બીજા સાથે વાત કરતા હોય છે. મારે પૂછવું છે અહીના મિત્રોને કે આવી લોકશાહી, આવી પરંપરાઓનું થોડું ઘણું અનુકરણ છે એ અત્યારની સરકાર કરી રહી છે? બાજપાઈ પાસેથી થોડી ઘણી પ્રેરણા લીધી હોત તો આજે અફસોસ કરવો પડ્યો છે એ શંકરભાઈએ કરવો ન પડ્યો હોત. કદાચ એવું માનતા હશે કે એકાદ વખત *(xxx) કરીને ચૂંટણી જીતી શકાશે, પણ વારંવાર *(XXX) થઈ શકશે નહીં.

શ્રીમતી વસુબેન ન. ત્રિવેદી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આવા આક્ષેપ ન કરી શકાય. *(xxx) અર્થ શું થયો? *(XXX) શબ્દનો ઉપયોગ ન કરી શકે. આ આક્ષેપ થયો. સીધો આ પ્રકારનો આક્ષેપ નથી કરી શકાતો.

અધ્યક્ષશ્રી :*('xxx) એ શબ્દ રેકર્ડમાંથી દૂર કરવામાં આવે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : *(xxx) શબ્દ દૂર ન કરી શકાય, એટલા માટે કહું છું કે આની સાથે કોઈને લેવાદેવા નથી. કોર્ટને લેવાદેવા નથી કે નથી પોલીસને લેવાદેવા. પણ વાત હું એ કરતો હતો કે.....

અધ્યક્ષશ્રી : આપે અત્યાર સુધી બહુ સારી વાત કરી છે. એક પણ આક્ષેપ કર્યા નથી. સહેજપણ આક્ષેપ કર્યા સિવાય બોલો એવી મારી વિનંતી છે.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું એ વાત કરતો હતો કે સમાજની અંદર ભાગલા પાડી એકાદ વખત પ્રવાહની અંદર આગળ નીકળી જવાતું હશે, પરંતુ કાયમી ધોરણે સમાજની અંદર ભાગલા પાડી રાજ એકાદ વખત આવતું હશે, પણ વારંવાર રાજ લઈ આવવું હશે તો વિકાસની વાનમાં બેસીને આગળ જવું પડશે. આ સલાહ મેં નથી આપી, જે તે વખતના વડાપ્રધાન બાજપાઈજીએ આપી હતી. એ કોઈએ માની નહિ, કદાચ માની હોત તો આ પરિસ્થિતિ ઊભી ન થઈ હોત. સિદ્ધિઓ સરકારની વર્ણવી શકાય. વાત ઘણી કરી હતી. અમારા નેતા વિષે જેટલું બોલાય તેટલું તે વખતે બોલ્યા હતા. મને આનંદ એ વાતનો છે કે મારા સાથી સભ્યોમાં અને મારા સાથી પક્ષના કેટલાક ટોચના આગેવાનો મને મળ્યા છે. એમણે વાત કરી છે કે બોલવાની અંદર એક સીમા રાખવી જોઈએ, એ સીમા તમારામાંથી ન રખાઈ, એના કારણે બાજપાઈજીના ફોટા ઊતર્યા છે. આ વાત હિંમતપૂર્વક આપનામાંથી પણ કોઈકે કરવી જોઈએ. અહીયા

સુનામીની વાત થઈ. સરકારે મદદ કરી એ નવી વસ્તુ નથી. એકબીજાની સરકારને મદદ કરવી જોઈએ. આપણને એ વાતનું ગૌરવ છે કે ગુજરાતીઓ જ્યારે જ્યારે સમય આવે વિશ્વની અંદર કોઈપણ ખૂણે હોય મદદ કરવાની અંદર પાછીપાની કરી નથી. સરકાર ૧૦ કરોડ રૂપિયા આપે, આપણને વાંધો ન હોવો જોઈએ. આનંદ થવો જોઈએ. એની જાહેરાત ન કરી હોત તો પણ ચાલત, છાપામાં ન અપાયું હોત તો પણ ચાલત. સરકારો આપતી હોય છે. કચ્છની અંદર ધરતીકંપ થયો. વિશ્વના ખૂણેખૂણેથી મદદ આવી હતી. રાજ્યના ખૂણેખૂણેથી મદદ આવી હતી. હું યાદ કરાવવા માગું છું પ્રબોધકાંત ભાઈને કે બધા રાજકીય પક્ષો, બધી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ બધા લોકોએ કામ કરેલ. અમે પણ ત્યાં ૩ મહિના સુધી રોકાયા હતા. અમારાં આદરણીય નેતા સોનીયાજી ૩ દિવસ સુધી રોકાયાં હતાં. અમારા એહમદ પટેલ દોઢ મહિનો રોકાયા હતા. હું આ ગૃહને જાણ કરવા માગું છું કે બધી અમારા શાસન સાથેની કોંગ્રેસ સરકાર હતી. એમની પાસેથી ફંડફાળો મેળવી ત્યાં યોજના બનાવી છે. સરકારના રેકર્ડ ઉપર છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ૭૫ કરોડના ખર્ચે બે ગામ બનાવ્યા. ૩ ગામ રાજસ્થાન સરકારે બનાવ્યા. જવાહરનગર દિલ્હીએ બનાવ્યું. મધ્યપ્રદેશે બનાવ્યું. ૩૨ કરોડ રૂપિયા કર્ણાટક સરકારે આપ્યા. બીજી સરકારોએ ખૂબ પૈસા આપ્યા, પણ એની વાત ગાઈ વગાડીને કરવાની જરૂર નહોતી, આપણી ફરજ હતી તે આપણે કરી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એ જ વાત કરવી છે કે આ મલબા ઉપાડવાની અંદર કેટલાક ગીધડાઓએ પણ કચ્છમાં કામ કરેલ છે. ખૂબ લાંબી વાત થઈ છે એટલે મારે વિશેષ વાત નથી કરવી. સરકારો ઉથલાલવામાં શંકરભાઈએ વાત કરી, અગાઉના વખતના બળવંતભાઈ મહેતાના વખતની વાત યાદ આવી પણ ગુજરાતના એક

* (xxx) આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે.

મુખ્યમંત્રીએ એમ કહયું કે મારો વાંક શું? રાતે કોઈને મોકલ્યા અને બીજા જ દિવસે સોગંદ લેવડાવ્યા તે વાત કેમ યાદ ન આવી. મારો વાંક શું? તે વાતનો જવાબ મારે નથી દેવાનો. મારા સાથી મિત્રો પ્રવચન કરતા હતા તેમને દેવાનો છે. મારે માત્ર એટલી જ વાત કરવાની છે કે રાજ્યપાલશ્રીનું જે પ્રવચન થયું છે તે પ્રવચનની અંદર જો ગુજરાતના જે પ્રશ્નો છે તેની વિષદ છણાવટ હોત અને ગુજરાતના આટલા પ્રશ્નો છે તેના ઉકેલ માટે આટલું આટલું કરવા જેવું છે એ હોત તો જરૂરથી અમે ટેકો આપ્યો હોત. માનનીય શંકરભાઈ જે આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે તેમાં ગુજરાતના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી હોત તો જરૂરથી કર્યુ હોત પણ હમણાં એક નવી પરંપરા શરૂ થઈ છે. *(XXX) પાસે પ્રશ્નો મંજૂર કરવાના એમ પ્રવચન પણ *(XXX) પાસે મંજૂર કરાવ્યું હશે. એટલે માત્ર મુખ્યમંત્રીશ્રીની પ્રશસ્તિ સિવાય કશું જ નથી.(અંતરાય) મેં કયાં તમારું નામ લીધું છે. *(XXX) નામ લીધું છે. તમારું નામ નથી આપ્યું. (અંતરાય) ***(XXXXX)**

અધ્યક્ષશ્રી : શું શબ્દ બોલ્યા? એક મિનિટ, તેઓ શું બોલ્યા ?

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું જ કહી દઉં. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી હું વાત કરતો હતો કે નવી નવી પરંપરા.....

અધ્યક્ષશ્રી : હું જાણવા માગું છું તેઓ શું બોલ્યા?

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું કહેતો હતો કે નવી પરંપરાઓ શરૂ થઈ છે. પ્રશ્નોની મંજૂરી છે તેને *(XXX) પરમીશનથી મૂકવાના. મને ખબર ન હતી કે પ્રવચન પણ *(XXX) પરમીશનથી મૂકવાનું હતું. શંકરભાઈનું નામ નથી આપ્યું. શંકરભાઈનું પ્રવચન બોલ્યો છું.

અધ્યક્ષશ્રી : અર્જુનભાઈ એક મિનિટ, તમે બેસો. હું નિર્ણય આપું છું. અહીં *(XXX)એક જ હોય છે. *(XXX) એક જ હોય છે. તમે *(XXX)* નામ લીધું એટલે વ્યકિતનું નામ આવી ગયું છે. હું તે શબ્દો રેકર્ડમાંથી દૂર કરું છું.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એટલે શંકરભાઈ જે આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે તે આભાર પ્રસ્તાવ કરતાં પ્રશસ્તિ વધારે છે તે કારણોસર હું તે આભાર પ્રસ્તાવની સાથે સંમત થઈ શકતો નથી.

શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ(માંડલ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ ચૌદ ારી જે રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે તે પ્રસ્તાવને મારું અનુમોદન આપું છું. લોકશાહી રાજ્ય વ્યવસ્થામાં લોકોના મતે ચૂંટાયેલી સરકારનું ધ્યેય રાજ્ય વિકાસ અને પ્રજાનું કલ્યાણ હોય છે. ભૂતકાળના ગાળામાં જેમણે લાંબા ગાળાનું શાસન કર્યુ છે, જે લાંબા ગાળાની સત્તા ભોગવી છે તેઓએ આ ધ્યેય પરિપૂર્ણ કર્યા હોત તો મને લાગે છે કે આજે ગુજરાતની આ દશા ન હોત.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વર્તમાન સરકારની સિદ્ધિઓ, સર્વાંગી વિકાસની એટલી બધી છે કે વિરોધપક્ષને આ બધી મુશ્કેલી ઉભી થઈ છે. સૂર્યનાં કિરણ સવારમાં પથરાય છે અને એ કિરણ કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વગર પથરાય છે. માનવ હોય, પશુ કે પંખી હોય એના ઉપર કોઈપણ ભેદભાવ વગર એ પથરાય કિરણ છે એવી જ રીતે આ વર્તમાન સરકાર કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વગર સર્વાંગી વિકાસ કરી રહી છે, ગુજરાતની પાંચ કરોડ જનતાને લોકશાહીનાં મીઠાં ફળ સરખા હિસ્સે પ્રાપ્ત થાય તેવા પ્રયત્નો આ રાજ્ય સરકારના છે, પરંતુ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતા જ્યારે એમના પ્રવચનમાં કહેતા હતા કે પોલીસનું મોરલ તૂટ્યું છે, પણ પોલીસને કાયદા મુજબની કામ લેવાની પૂરતી સત્તા આ સરકારે આપી છે, ઘણા મોટા લાગવગવાળા હોય કે ઘણા મોટા બિલ્ડરો હોય એ આજે જેલની હવા ખાઈ રહ્યા છે એ એનો નમૂનો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કપાસના ભાવની વાત એમણે કરી અને એમણે સ્વીકારી, એમના પ્રવચનમાં કહ્યું કે કપાસના ભાવ ઘટ્યા છે, વાત સાચી પણ એ માટે કોણ જવાબદાર? કેન્દ્ર સરકારની જ્યારે જવાબદારી હોય અને કેન્દ્રમાં તો એમની સરકાર હતી, અમારી સરકાર ગઈ સાલ હતી, માનનીય અટલબિહારી બાજપાઈની સરકાર હતી ત્યારે ૩૫૦ રૂપિયા કાલાંનો ભાવ હતો, જ્યારે આજે એમની સરકારમાં કપાસના ભાવ રૂપિયા ૩૫૦ છે, કેન્દ્રમાં એમની સરકાર છે, જે જવાબદારી એમની છે એ સ્વીકારે છે.

બીજી કન્યા કેળવણી રથયાત્રાની વાત કરી, ગઈકાલે પ્રશ્નોત્તરીમાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં કન્યા કેળવણી રથયાત્રાની ચર્ચા ખૂબ થઈ હતી, ત્યારે એમણે શિક્ષકોની જરૂર છે એમ કહ્યું હતું, એવી વાત એમના પ્રવચનમાં આવી, તો ૮૦ હજાર શિક્ષકો આ રાજ્ય સરકારે મૂકેલા છે, એમાં કોઈપણ જાતનો ભ્રષ્ટાચાર સિવાય એ વાત હું આજે છાતી ઠોકીને કહું છું કે, કોઈપણ નોકરી મેળવવા માટે કોઈપણ લાગવગ વગર, ચા પીવાની કે પાવાની જરૂર નથી પડી, એના મેરિટ ઉપર નોકરી મળી છે, એવા ૮૦ હજાર શિક્ષકો આ રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે મૂક્યા છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતને સમૃદ્ધિના પંથે દોરી જનાર માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સોનેરી સોપાન ઘોર અંધારામાં પણ રાત્રે નરી આંખે દેખાય એટલા ઉજ્જવળ છે, અંધકારને અલવિદા આપવા

* (XXX) આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે.

માટે આ રાજ્ય સરકારે જયોતિગ્રામ યોજના અમલમાં મૂકી છે અને છેક છેવાડાના નાના નાના ગામોને ઝળહળતાં કર્યા છે. જ્યારે જે ગામોમાં ફાનસના અજવાળે વાળુ-પાણી થતાં હતાં ત્યાં આજે એ ગામોમાં શહેરોની જેમ રોશની કરી અને લગ્ન જેવા પ્રસંગો વીજળીના પ્રકાશમાં યોજાય છે. આ વાસ્તવિકતા છે. આજે ગામોમાં કારીગર વર્ગ, સુથાર, લુહારીકામ કરનાર, ટાયર પંચર કરનાર, નાના નાના કારીગર વગાર્એ આજે પોતાને આ ચોવીસ કલાક થ્રી ફેઈઝ વીજળી મળવાથી એમનાં આધુનિક ઇલેક્ટ્રિક મશીન પણ વસાવ્યાં છે. એક ગામમાં હું એક કાર્યક્રમમાં એક ઉદ્‌ઘાટન કરવા ગયો હતો તો એ દિવસે હીરાના કારખાનાનું ઉદ્‌ઘાટન એ ગામમાં થયું,આ ૨૪ કલાક વીજળી મળવાને લીધે થયું, હીરાની નાની નાની ઘંટીઓ ગામડાંમાં ચાલુ થઈ છે. યુવાનો બેકાર ગામડામાં રખડતા હતા તેઓને આજે રોજગારી મળતી થઈ છે, ગામડાંમાં આ જયોતિગ્રામ યોજનાના આધારે એક રોજગારીની તક ઊભી થઈ છે. આ રાજ્યમાં ૧૮ હજાર ગામોમાંથી ૭ હજાર ગામોમાં વીજળી ચાલુ થઈ છે. ૨૪ કલાક થ્રી ફેઈઝ વીજળી મળતી થઈ છે અને મારા મતવિસ્તારના ૧૫૮ ગામોમાંથી ૯૪ ગામોમાં આજે વીજળી મળતી થઈ છે. આ હું વાસ્તવિક વાત કરું છું .

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હમણાં સત્રના પ્રથમ દિવસે જ્યારે પ્રશ્નોત્તરીમાં એક પ્રશ્ન આવ્યો કે ખેતરોમાં રહેનારા લોકો માટે રાજ્ય સરકારે શું વ્યવસ્થા કરી છે? ત્યારે ખેતરોમાં બે બે પાંચ પાંચ મકાનો બનાવીને રહેતા હોય એમને પણ ૨૪ કલાક વીજળી આપવાની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી રાજ્ય સરકારે આપી છે. મેં દક્ષિણ અને ઉત્તર ભારતના ઘણા શહેરોનો પ્રવાસ કર્યો છે. બેંગ્લોરથી માંડીને સીમલા સુધીના શહેરો મેં નજરે જોયાં છે, પાંચ-પાંચ કરોડ રૂપિયાના શોરૂમ એ શહેરોમાં હોય અને એમના આંગણામાં જનરેટર સેટ પડ્યા હોય, એ પડ્યા હોય તો એ શાના માટે હોય?કારણ કે એમને પૂરતી વીજળી કે સતત વીજળી મળતી નથી, પણ ગુજરાતનું એક પણ શહેર એવું નથી કે જેના શોરૂમમાં જનરેટર સેટ મૂકવા પડતા હોય, કારણકે ગુજરાતના શહેરોમાં સતત વીજળી અને પુરતી વીજળી મળે છે આટલી વાસ્તવિકતા હોવા છતા રાજ્ય સરકારે ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડનું પુનઃગઠન કરીને સાત કંપનીઓમાં વિભાજન કરી અને એક અલગ વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરેલ છે. પરંતુ સાથી મિત્રોને આટલી બધી જેને પાંચ કરોડની જનતાએ આવકારી છે એવી યોજના ન દેખાય. મારું એવું માનવું છે કે, આ વાસ્તવિક યોજનાઓ જેમને ન દેખાતી હોય એમને મારું સૂચન છે કે એમણે આંખનો ઈલાજ કરાવવો જોઈએ.

આઝાદી પછી અરધી સદીના અંતે ગુજરાતને વિકાસનો અહેસાસ થયો છે. જે ગામડામાં ધૂળની ડમરીઓ ઉડતી હતી ત્યાં આજે સિમેન્ટ-કોંક્રીટના પાકા રસ્તાઓ બન્યા છે. ગૃહના દરવાજાથી માંડીને ગામડાનાં આંગણાં સુધી પાકા રસ્તાઓ બન્યા છે. જે ગામડામાં જતા પાંચ-પાંચ કલાક લાગતી હતી ત્યાં એક કલાકમાં જઈ શકાય એવા રસ્તો બન્યા છે. જેથી કરીને ગામડામાં દૂધ-શાકભાજી અને ખેત પેદાશો વગેરે ખેડૂત વર્ગ પોતાનો જે માલ વેચવા માગતા હોય એ સમયસર માર્કેટમાં પહોચાડી શકે છે અને એનાથી એને પૂરતું વળતર મળે છે અને પૂરતું ઉત્પાદન પણ મેળવી શકે છે. સરકાર પણ ગામડાના વિસ્તારોની જે એપ્રોચ રોડની બાબત છે એને પુરતું પ્રાધાન્ય આપે છે. ગામડામાં એપ્રોચ રોડની જરૂર છે એ સરકાર સ્વીકારે છે અને એટલે જ કિસાન પથ યોજના મૂકીને રાજ્ય સરકારે ૫૦ કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ આ બજેટમાં ફાળવી છે. તમામ ગામડાંને જોડવા માટે, નગરોને જોડવા માટે ૯૮.૫ ટકા કનેકિટવિટી જેને કહેવાય એમાં ગુજરાત પ્રથમ નંબરે છે અને મોટા નગરોમાં ઘણાં બધાં નગરોને ફોરલેનથી જોડવાનું કામ રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે.

હમણાં સુનામીની પણ વાત થઈ. ગત ડિસેમ્બરમાં ઈન્ડોનેશિયામાં ભૂકંપ આવ્યો અને એના કારણે જે સુનામીની અસરો થઈ અને સમગ્ર દક્ષિણ ભારતમાં જે હાહાકાર થયો અને જે જાનહાનિ થઈ એમાં એને મદદ કરનાર ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય હતું. સૌ કોઈ જાણે છે કે, સરકારે અને ગુજરાતની પ્રજા એમની યાતનાઓ અને એમના દુઃખમાં ભાગીદાર થઈ છે. આંદામાન-નિકોબારમાં આખો વાહન-વ્યવહાર અને સંદેશા-વ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો ત્યારે રાજ્ય સરકારે પોતાના દસ સભ્યોની હેમ રેડિયો ઓપરેટર ટીમ મોકલી અને ત્યાનો સંદેશા-વ્યવહાર ચાલે કરાવ્યો હતો અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમના રાહત ફંડમાંથી ૧૦ કરોડ રૂપિયાની રોકડ રકમ આપી છે, એમાં તામિલનાડુને ૫ કરોડ, આંદામાન-નિકોબારને ૨ કરોડ, પોંડિચેરીને ૧ કરોડ, આંધ્રપ્રદેશને ૧ કરોડ અને ઓરિસ્સાને ૧ કરોડ આપ્યા છે અને હાઈવે-રેલવે અને રસ્તાઓ દ્વારા સાડા ત્રણ હજાર ટન જેટલી સામગ્રી મોકલી છે એમાં ગુજરાત સરકારે ૧૫ કરોડની સામગ્રી પૂરો પ્રયત્ન કરીને મોકલી છે. મને ખબર છે કે, અમારા મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીમંડળના સભ્યો એરપોર્ટ ઉપર જાતે હાજર રહ્યા અને જાતે નજર રાખીને વિમાનમાં સામગ્રી મોકલતા જોયા છે અને વહીવટી સ્ટાફે પણ એટલા જ ઉજાગરા કરીને આ સુનામીના રાહત ફંડમાં જે કાઈ કામ કર્યું છે એ સરાહનીય કામગીરી કરી છે.

રાજ્યની નાણાકીય સુવ્યવસ્થાની વાત કરું તો કેન્દ્રનું જે નાણાકીય આયોજન પંચ છે એમણે સૌથી પહેલાં ગુજરાતના વિકાસની સરાહના કરી છે અને ગુજરાતની નાણાકીય-વહીવટી-મહેસૂલી ખાદ્ય પણ ઘણી ઘટી છે. ૨૦૦૫ અને ૨૦૦૬ ની વાર્ષિક યોજનાની વાત કરું તો વાર્ષિક યોજનાનું કદ કેન્દ્રના આયોજન પંચે ૧૧ હજાર કરોડ જેટલું જે નિર્ધારિત કર્યું હતું. સન ૨૦૦૪-૨૦૦૫ માટે એના કરતાં અઢી હજાર કરોડ એટલે કે ૨૯ ટકા જેટલું વધારે સૂચવ્યું છે. આ રાજ્ય સરકારની કામગીરીને આયોજન પંચે બિરદાવ્યું છે. શિક્ષણ,

જળસંચય, જયોતિગ્રામ યોજના, ગરીબી નિવારણ, આદિજાતિ વિકાસ પેટર્ન અને નાણાકીય શિસ્તની બાબતને કેન્દ્રના આયોજન પંચે આવકારી છે, એની સરાહના કરી છે. ગરીબીનો આંક જોવા જઈએ તો આખા દેશની અંદર ગરીબીનો આંક ૨૬.૧૦ ટકા છે અને ગુજરાતની અંદર ગરીબીનું પ્રમાણ ૧૪.૭ ટકા છે એ બતાવે છે આંકડા કે ગરીબી નિવારણનો લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરવામાં ગુજરાત મોખરે રહ્યું છે.

પાણી પુરવઠાની વાત કરું તો હમણાં અહીંયાં ઘણી ચર્ચાઓ થઈ, મારો મત વિસ્તાર પછાત છે. ખાખરિયા ટપ્પા અને ચુંવાળ પ્રદેશ છે. એમ કહેવાય છે કે, હેડંબાનું વન હતું. આઝાદી પછી પાણીની સુવિધા ન થઈ હોય અને અત્યારે થઈ રહી હોય તો તે આ વર્તમાન સરકાર કરી રહી છે. ૬૦ કરોડ રૂપિયા જેટલું બજેટ અને એનાં કામો અત્યારે ચાલી રહ્યાં છે. પાઈપ લાઈનો ગામેગામ નંખાઈ રહી છે. ચૂંટણી પ્રવાસમાં હું જોતો હતો કે એક બહેન એની પોતાની કેડમાં એક બાળકને તેડી અને માથે બેડાં લઈને દૂરથી પાણી લાવતી હતી ત્યારે એવું લાગતું હતું કે આ રાજ્ય સરકાર પહેલું કામ પાણીનું કરે તો સારું અને આ રાજ્ય સરકારે પહેલું કામ પાણીનું કર્યુ. આજે ૬૦ કરોડ રૂપિયાની સુજલામ્-સુફલામ્ યોજનામાં પાણીનાં કામો ચાલી રહ્યાં છે અને એના માટે રાજ્ય સરકારના પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રીનો હું આભાર માનું છું.

ટુરિઝમની વાત કરું તો રાજ્યની અંદર યાત્રાધામ વિકાસને સરકારે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. એના વિકાસ માટે દરેક ક્ષેત્રે રાજ્ય સરકાર પૂરા પ્રયત્નો કરી રહી છે એમાં મારું એક સૂચન છે કે દ્વાપર, ત્રેતા અને કળિયુગ, આ ત્રણેય યુગોથી ચાલ્યન આવતાં જે દેશ આખાનાં પૌરાણિક સ્થળો છે એમાં આપણા ગુજરાતની અંદર ૧૮ પુરાણના સૌથી મોટામાં મોટા પુરાણ સ્કંધપુરાણની અંદર એનું વર્ણન આપેલું છે. આ બધા સોમનાથથી માંડીને, રામેશ્વરથી માંડી, બદ્રી-કેદારથી માંડી અને તમામે તમામ જ્યોર્તિલિંગોથી માંડી અને દ્વારકાથી માંડી, અયોધ્યાથી માંડીને તમામ યાત્રાધામોનું વર્ણન સ્કંધપુરાણની અંદર આપેલું છે આ સ્કંધપુરાણનો આધાર લઈએ તો એની અંદર પ્રભાસ ખંડની અંદર સોમનાથ અને ભવનાથ તળેટીનું વર્ણન અને એનું મહત્વ સમજાવેલું છે. બીજા એક ખંડમાં કુંભેશ્વરનું મહત્વ સમજાવ્યું છે અને કુમારિકા ખંડમાં મહીસાગર સંગમનું મહત્વ સમજાવ્યું છે અને એનું મહત્વ આપેલું છે. મેં આખો સ્કંધપુરાણ વાંચ્યો છે આ મહીસાગર સંગમ જે કુમારિકા ખંડમાં આપેલ છે એ જંબુસરથી ૩૦ કિલામિટર દૂર કાવીના કાંઠે દરિયાકિનારે આવેલું આ સ્થળ છે ત્યાં ભગવાન શંકરનું શિવલિંગ છે એનું નામ સ્તંભેશ્વર છે. માત્ર શિવલિંગ છે. મંદિર નથી. દરિયા કિનારે આવેલું આ એક પૌરાણિક સ્થળ છે અને ચોવીસ કલાકમાં દરિયો બે વખત આ શિવલિંગનો અભિષેક કરે છે અને આઠ આઠ નદીઓનો આ શિવલિંગ પર જળાભિષેક થાય છે. મારી સભાગૃહને વિનંતી છે કે આવા પૌરાણિક સ્થળ જેનું મહત્વ સ્કંધપુરાણમાં હોય એને વિકસાવવા જોઈએ જેથી રાજ્યનું હિત થાય અને લોકોનું પણ કલ્યાણ થાય.

પશુપાલનની વાત કરું તો પહેલાં એવું લાગતું હતું કે લોકોની સુખાકારી અને આરોગ્ય માટે ધ્યાન અપાતું હતું પણ આજે હમણાં મારા મત વિસ્તારની અંદર એક કાર્યક્રમ રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી દિલીપભાઈ પશુ સારવાર યજ્ઞ ૨૭૦૦ મો લઈને આવ્યા હતા. સ્થળ પર એટલી બધી વ્યવસ્થા, લેબોરેટરી પણ સ્થળ પર, હરતી ફરતી લેબોરેટરી, દરેક પશુઓના નમૂના લઈને અને એ યજ્ઞમાં જે રોગોનું નિદાન કર્યુ અને તાત્કાલિક ઓન ધ સ્પોટ કેમ્પની અંદર જે સારવાર કરી એ આજે એવું લાગે છે કે આ પશુધન જાળવવામાં આ રાજ્ય સરકાર પૂરા પ્રયત્ન કરી રહી છે.

આજસુધી એવું લાગતું હતું કે ભૂતકાળની અંદર વિરોધપક્ષના નેતા સભાગૃહની અંદર પહેલા દિવસે બળદગાડું જોડીને આવતા હતા અને આજે વિરોધપક્ષના સન્માનનીય નેતાશ્રી ટ્રેકટર જોડીને આવેલા છે, જોકે એમાં પ્રગતિ કરી છે. પાંચ-પચ્ચીસ હજારના બળદગાડાથી અઢી-ત્રણ લાખના ટ્રેકટર સુધી પહોંચ્યા છે, પરંતુ મને એક વિચાર આવે છે કે જે દિવસે બળદગાડું જોડીને વિરોધપક્ષના નેતા આવતા હતા ત્યારે રાજ્ય સરકાર એમનું સન્માન કરતી હતી, રાજ્યના મંત્રીશ્રી એમને સન્માનવા જતા હતા, પરંતુ જ્યારે દરવાજા તોડીને આવ્યા હોય ત્યારે રાજ્ય સરકાર કેવી રીતે એમનું સન્માન કરે?

ચીનમાં એક કહેવત છે થોડા સમય માટે થોડા લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકાય, પરંતુ વધુ વખત બધા લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકાતા નથી. આવી ચીનમાં એક કહેવત છે. બહુ વખત ગરીબો હટાવવાના નારા ચાલ્યા. ગુજરાતની પ્રજા જાગૃત છે. વર્તમાન સરકાર જે કામ કરી રહી છે તે સૌ જાણે છે અને આ વર્તમાન સરકારે અમારા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ કામગીરી કરી અને તેમની વાતોના વડાનો ભેદ જનતાને ખોલીને દેખડયો છે.

શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ (સોમનાથ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય શંકરભાઈ ચૌધરી માનનીય ગવર્નરશ્રીના સંબોધન ઉપર જે પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે તેમાં મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છું. અગાઉના મિત્રોએ ઘણી બધી વાત કરી તેમાં વિશેષ વાત નથી કરવી, પરંતુ અમારા વિરોધપક્ષના નેતા ભાઈશ્રી અર્જુનભાઈએ બે વાત આ સભાગૃહમાં કરી છે. નર્મદા બંધની જે વાત છે તેમાં કયારેય ભૂતકાળમાં અને ભવિષ્યમાં પણ કયારેય પણ કોઈ પણ જાતની પક્ષપાત કે કોઈ પણ વાત વચ્ચે લાવ્યા સિવાય બધા સાથે રહીને

આ યોજના પરિપૂર્ણ કરવા માટેની વાત કરી છે. મારે સભ્યશ્રીઓને વાત કરવી છે કે, નર્મદા યોજનાનું શિલારોપણ કોંગ્રેસે કર્યુ હતું તે ભૂલે નહીં અને ૯૦ મિટર સુધીનું જે બાંધકામ છે તે કોંગ્રેસના વખતમાં થયેલું તે પણ ભૂલે નહીં. મારે વાત કરવી છે કે આ નર્મદા બંધનું બાંધકામ કયા વખતમાં બંધ થયું છે? ૧૯૯૫-૯૬માં જે વિવાદ થયો છે ત્યારે કોની સરકાર હતી તે પણ મારે આ સભ્યશ્રીઓને જણાવવું છે. ૧૯૯૫-૯૬માં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હતી ત્યારે આવુ થયું છે.

અધ્યક્ષશ્રી : સીધી વાત કરો.

શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ટીકા-ટિપ્પણમાં પડ્યા સિવાય આ વાત એટલા માટે કરું છું કે, સારાં કામ હંમેશાં કોઈ પણ માણસ કરે છે તેને બે-પાંચ લોકો ભલેગમે તેવી વાત કરે, પ્રજા હંમેશાં સ્વીકારે છે. આજે ૭૫ ટકા ખેડૂત આધારિત આ ગુજરાત રાજયની અંદર બે વીઘાથી માંડીને પચાસ-સો વિઘા સુધીના જમીનદારો તેમાં સીમાંત ખેડૂતોને જે રાહતો આપવી જોઈએ એ વાત નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં કયાંય દેખાતી નથી. મારે ઇલેક્ટ્રિક પાવરની વાત કરવી છે. તો એમાં ત્રણ ગણા ભાવ કર્યા છે તેમાં સબસિડી આપવાની કોઈ વાત નથી કરી. સાત હજાર ગામડાંને જયોતિ ગ્રામની બનાવવાની વાત કરી છે. હું કહેવા માગું છું કે, જરૂરથી જ્યોતિ ગ્રામમાં કદાચ સાત હજાર ગામડાંને પૂરો પાવર ભલે મળતો હશ એ આનંદની વાત છે, પણ આ સાત હજાર ગામડાંની સીમમાં જે ખેડૂતો સીમની અંદર રહે છે તેમને તો છ કલાક જ વીજળી મળે છે. તો તમેને માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવી પડશે. ખેડૂતનો દીકરો હશે તેને ખબર હશે કે ગામડામાં રહેનારા ખેડૂતનો મોટાભાગનો પરિવાર , અભ્યાસ કરતો બાળક તે સીમની અંદર ૫૦ થી ૬૦ ટકા લોકો અમારા સૌરાષ્ટ્રની અંદર લોકો સીમમાં રહે છે. આજે ઇલેક્ટ્રિક પાવર આ જ્યોતિ ગ્રામની અંદર છ કલાક થી આઠ કલાકથી વધારે એક મિનિટ પણ લાઈટ મળતી નથી આના માટે સ્પેશ્યલ વિચાર રાજ્ય સરકારે કરવો પડશે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સૌથી સારી વાત સોમનાથ ભગવાન, જે બાર જયોતિર્લિંગ છે, તે બારમાં પ્રથમ જયોતિર્લિંગ સોમનાથનું છે. એ ભગવાન સોમનાથની દયાથી ત્યાંના પ્રતિનિધિ તરીકે હું આ વિધાનસભામાં આવ્યો છું. સોમનાથ ટ્રસ્ટ જે છે એના એના ટ્રસ્ટી અને પ્રમુખ વડીલ મુરબ્બી શ્રી કેશુભાઈ પટેલ છે. સોમનાથ મુકામે સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીની સ્થાપનાની જે વાત લઈને આવ્યા છે, એ વાત મારે આપના દ્વારા કરવી છે. બહુ સારી વાત છે, પરંતુ નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં એ અંગે કોઈ ચોખવટ કરવામાં આવી નથી. મારે આપના દ્વારા એ વાત કરવી છે કે સોમનાથ, પ્રભાસપાટણ મુકામે સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવે અને એ ત્યાં જ સ્થપાય એવી ચોખવટ સરકારશ્રી દ્વારા થાય. ત્યાં મોટો દરિયાકિનારો છે, પોર્ટ છે. ભૂતકાળમાં જે તે વખતના મિનિસ્ટરે ૫ કરોડ રૂપિયા આ યાત્રાધામના વિકાસ માટે ફાળવ્યા છે. એના વિકાસનાં કામો ચાલુ થયાં છે. યાત્રાધામના મિનિસ્ટરે આ માટે પૈસા ફાળવ્યા છે. એમાં વધારેમાં વધારે યાત્રાધામોનો સમાવેશ થાય અને સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થાય. યુનિવર્સિટીની સાથોસાથ યાત્રાધામનો પણ વિકાસ થાય એવી મારે આપના દ્વારા વિનંતી કરવી છે, કારણ કે હમણાં જ હાઈકોર્ટે જમીન સંપાદનની વાત પૂરી કરી દીધી છે.

મારે આપના દ્વારા બીજી જે વાત કરવી છે તે પીવાના પાણી અને સિંચાઈની વાત કરવી છે. સૌથી સારી વાત એ છે કે સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત આમ ભાગ પડે છે એમાં જરૂરથી સૌરાષ્ટ્રને અન્યાય થાય છે. મારે લાગણી સાથે અને આક્રોશ સાથે વાત કરવી છે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રના નાણામંત્રીએ આ વખતે આ વાત થોડી સુધારી છે. ૮૦:૨૦ ની વાત આ વખતે સ્વીકારી છે, જે ૬૦:૪૦ની હતી. ઉત્તર ગુજરાતમાં ૮૦:૨૦ હોય અને અમારે ત્યાં ૬૦:૪૦. મારે સિંચાઈ અને પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રીને વાત કરવી છે કે કેટલા કરોડ રૂપિયા ઉત્તર ગુજરાતમાં વાપર્યા અને કેટલા કરોડ રૂપિયા સૌરાષ્ટ્રમાં વાપર્યા છે? તેની સરખામણી કરવામાં આવે. દસ ટકા પૈસા વાપરવામાં આવ્યા નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે આપના દ્વારા બીજી વાત કરવી છે. (સમયસૂચક ઘંટડી)

શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પાંચ મિનિટ.

અધ્યક્ષશ્રી : બે મિનિટ.

શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ : (અંતરાય) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શંકરસિંહે તો આ બધી શરૂઆત કરી હતી. બાલગુરૂ યોજના હતી એ શંકરસિંહ વાઘેલાએ શરૂ કરી હતી. આ ઉદ્યોગો લાવ્યા છે ને એ પણ શંકરસિંહ વાઘેલાએ શરૂ કર્યા હતા. એમાં કોઈની તાકાત નથી. તમે એનું અનુકરણ કરો છો. તમે વાત ન કરતા. શંકરસિંહ વાઘેલાએ તો ઐતિહાસિક નિર્ણયો લીધા હતા. (અંતરાય) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો સમય બગાડે છે, તે આપના ધ્યાન પર મૂકવા માગું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કલ્પસર યોજના, જે કેશુભાઈ પટેલ ભૂતપુર્વ મુખ્યમંત્રી હતા, ખેડૂતોના નેતા, હું પોતે સ્વીકારું છું. કલ્પસર યોજનાની જે કલ્પના હતી, કલ્પસરની જે યોજના હતી, એ યોજનામાં માત્ર ને માત્ર સરવેની કામગીરી થાય છે. આ ૫૫ હજાર કરોડની યોજના થાય તો નર્મદાના પાણી તો ઉઠાવીને નાંખ્યા હતા. આ પાણી નાંખીને તમે આખા સૌરાષ્ટ્રને પાણી પાણી કરવાની ખેવના રાખો છો એ પરિપૂર્ણ કરો એવી કલ્પના કરું છું.

હમણાં જ વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીએ સહકારની વાત કરી. માનનીય અમીતભાઈ પણ બેંકમાં છે અને હું પણ ડિરેકટર છું. ચૂંટણી થઈ ગઈ. ૧૫ કોંગ્રેસ અને ૫ ભાજપ. (અંતરાય) જેઠાભાઈ, તમે તો અમારા ભેગા હતા. માથાકૂટ ન કરો. છેલ્લી મિનિટે બોર્ડ ઓફ નોમીનીએ સ્ટે આપી દીધો. અરે, આ તો ખેડૂતોની સંસ્થા છે અને એમાં રાજકારણ ન આવવું જોઈએ અને જમીન વિકાસ બેંકમાં જોઈએ તો માનનીય સહકાર મંત્રીશ્રી અહીં હાજર છે અને આ તો ખેડૂતોની સંસ્થા છે, ખેડૂતોની બેંક છે તો એ ખેડૂતોની બેંક હોવા છતાં એની સાધારણ સભા બોલાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. તો આમાં તો રાજકારણ ના હોવું જોઈએ ને? આજે દોઢ થી પોણા બે કરોડ ખેડૂત સભ્યો એની સાથે જોડાયેલા છે, એમાં એમનું હિત છે, તો એમાં જે કાંઈ કાર્યવાહી કરવાની થતી હોય એ થાય એ આપના વ્દારા કહેવા માગું છું.

કાયદો અને વ્યવસ્થાની વાત કરું તો માનનીય અમીતભાઈ શાહની કામગીરી ઘણી સારી છે એમાં ના નથી, મારે એક નમૂનો આપવો છે કે તા. ૨૬-૭-૨૦૦૪ ના રોજ....(સમયસૂચક ઘંટડી)

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય માધાભાઈ બોરીચા......

શ્રી માધાભાઈ લા. બોરીચા (કેશોદ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચન પર આ ગૃહના સન્માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી જે આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે એને અનુમોદન આપવા અને એના સંદર્ભમાં મારા વિચારો વ્યકત કરવા માટે હું ઉપસ્થિત થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહમાં આ ગૃહના સન્માનનીય સભ્યશ્રીઓએ સાથે મળીને ગુજરાત રાજ્યની અસ્મિતા જળવાય, ગુજરાત રાજ્યનું ગૌરવ વધે, આ ગુજરાત રાજ્યમાં પૂજય મહાત્મા ગાંધીજી, શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, શ્રી સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના જે આદર્શો હતા, એમનું જે સ્વપ્ન હતું, એ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે આઝાદીનાં ૫૭-૫૮ વર્ષ પછીથી અને એમાં પણ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના ૧૯૬૦ માં થઈ ત્યારપછીથી લઈને અત્યારસુધીનાં ૪૫ વર્ષ દરમ્યાન ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાતના લોકોની આકાંક્ષાઓ અને અપેક્ષાઓ સંતોષવામાં કોણ, કયાં અને કેટલું ખરું અને ઉણું ઉતર્યુ એની સમીક્ષા તો ઈતિહાસ કરશે, પરંતુ મારે જે લોકો આ વિકાસને, આ ગુજરાતના સર્વતોમુખી વિકાસ યાત્રાનો જે પ્રારંભ આ રાજ્યની ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં આ સરકારના માધ્યમથી થઈ રહયો છે એ વસ્તુને આ લોકો જોઈ શકતા નથી એ વાતનો મને અફસોસ છે. અહીંયાં કેટલાક માનનીય સભ્યશ્રીઓએ પ્રસ્તાવની ચર્ચામાં એવી વાત કરી જાણે કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીનું પ્રશસ્તિનું ગાન કરતા હોય એવી વાત કરી છે, પરંતુ મારે તેમને કહેવું છે કે જે સમાજ સજજનનું સન્માન કરી શકતો નથી અને જે સમાજ દુર્જનને દેખી શકતો નથી એવો સમાજ કયારેય પણ પ્રગતિ કરી શકતો નથી અને અમને એનું ગૌરવ છે, માન છે, શ્રેય છે કે આ રાજ્યના સર્વતોમુખી વિકાસમાં આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ પછી એ માનનીય કેશુભાઈ પટેલ હોય કે માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય તેમણે આ રાજ્યની સત્તાની ધૂરા તેમના હાથમાં લીધી છે ત્યારથી રાજ્યનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એના માટે રાતદિવસ જહેમત કરીને એના માટેની એકે એક યોજનાઓ પછી એ ગોકુળ ગામ યોજનાની વાત હોય, રસ્તા અને પાણીના વિકાસની વાત હોય એમાં સરકારે કોઈ જ કસર છોડી નથી. આ સરકારો કોઈ ઉણી ઉતરી નથી. આ રાજ્યમાં આ સદીનો ભારેમાં ભારે ભૂકંપ ૨૦૦૧માં આવ્યો, એ ભૂકંપ ભરી પીવામાં આ રાજ્ય સરકારે જે ઉતકૃષ્ટ કામગીરી કરી તે ન ભૂતો ન ભવિષ્યતો જેવી હતી, અને તેનું બીજું ઉદાહરણ આ દુનિયામાં મળી શકે તેમ નથી, દુનિયાના અનેક દેશોમાં ભૂકંપ અને કુદરતી આફતો આવી છે. અમેરીકા જેવી મહાસત્તા ઉપર પણ વર્લ્ડટ્રેડ સેન્ટર ઉપર આતંકવાદીઓએ હુમલો કરી અને નુકસાન કર્યુ છે. મહારાષ્ટ્રમાં પણ લાતુરમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો, અને જે તે વખતે આ કુદરતિ આફતો આવી ત્યારે તેને હલ કરવામાં અમેરીકા જેવી મહાસત્તા અને મહારાષ્ટ્રના ભૂકંપ વખતે જયાં મારા સાથી પક્ષો છે તેમની સરકાર કાર્યરત છે ત્યાં પણ જે કામ થઈ શકયું નથી એવું કામ ગુજરાત સરકારે કરી બતાવ્યું છે. આ સરકારે પુનર્વસનમાં જે કામો કર્યા છે તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ પ્રશંસા થઈ છે તે આપણે સ્વીકારવું પડશે. આપણે સૌ આ સભાગૃહના સન્માનનીય સભ્યોએ વાદ વિવાદથી ઉપર ઉઠીને આ ગુજરાતને સૌ પ્રથમ એવું સુશાસન મળ્યું છે અને તેની ફકત આપણે જ નહીં પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓએ પણ ગુજરાતના શાસનને સર્વોત્તમમુખી શાસનનો એવોર્ડ આપ્યો છે તે ભૂલવું ન જોઈએ. આ કોઈ ગુજરાતના લોકોએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોએ એવોર્ડ નથી આપ્યો, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાએ આપ્યો છે. તેને નજર અંદાજ ન કરી શકીએ.

આ રાજ્યમાં મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્વપ્ન હતું કે આઝાદીના માધ્યમથી આ દેશની ગરીબી દૂર થાય, બેકારી દૂર થાય, ખેતીનો વિકાસ થાય અને આ દેશમાં ઘી-દૂધની નદીઓ વહે. મને કહેતાં ખેદ થાય છે કે આ દેશમાં અને ગુજરાતમાં ગુજરાત રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવ્યું ત્યારથી ૪૫ વર્ષ સુધીના શાસન ગાળામાંથી ૩૫ વર્ષ સુધી જેમણે શાસન કર્યુ તેમના શાસનમાં રસ્તાના વિકાસની વાત, ખેતીના વિકાસની વાત અને જળ સંચયની વાત, આ ત્રણ વસ્તુઓ રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસમાં મહત્વની હતી તેની અવગણના કરવામાં આવી છે, તેની અવહેલના કરવામાં આવી છે. જેને કારણે રાજ્યનો વિકાસ થઈ શકયો નથી. આ વિકાસની કેડીએ આ રાજ્યને મુકવા માટે આ રાજ્ય સરકારે ભગીરથ પ્રયાસો કરેલા છે. અને તેના ભાગરૂપે

મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ અને આ રાજ્ય સરકારે રસ્તા, પાણી અને જળ સંચયના અભિયાનને જોરદાર સમર્થન આપીને ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસ માટે અગત્યનું કામ કર્યુ છે તેનો જોટો જડે તેમ નથી. આજે ગુજરાતમાં જળ વ્યવસ્થાપનનું કામ જોવા માટે બીજા રાજ્યના લોકો અભ્યાસ કરવા માટે આવી રહ્યા છે. પછી તે સરદાર પટેલ જળસંચય યોજના હોય કે સુજલામ સુફલામ યોજના હોય કે પછી રસ્તાઓને અદ્યતન કરવાની વાત હોય. આજે મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે રાજ્યના મુખ્ય મંત્રીશ્રીની નિગાહબાની નીચે રાજ્યના માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રીએ ગુજરાતના ગામડાંને સો ટકા રસ્તાઓની સુવિધાથી જોડ્યા છે. હિન્દુસ્તાનમાં એક પણ એવું રાજ્ય નથી કે જેના ગામડાંને રસ્તાઓની સો ટકા સગવડ પ્રાપ્ય હોય. આ કોઈ જેવી તેવી સિદ્ધિ નથી. આ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જળ શકિત, જ્ઞાન શકિત, ઉર્જા શકિત, રક્ષા શકિત અને જન શકિતના પંચામૃતના પ્રયોગના માધ્યમથી રાજ્યનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તેવું અભિયાન હાથ ધર્યુ છે. એટલે મારે તો સૌને વિનંતી કરવી છે કે આપણે સૌ કોઈ સાથ અને સહયોગ આપીએ અને આપણે ટાંટિયા ખેંચવાની વાત ન કરીએ, નહીંતર ઈતિહાસ આપણને માફ નહીં કરે અને આનાં લેખાં જોખાં ઈતિહાસ કરશે, રાજ્યમાં સર્વાંગી વિકાસ માટે રાત દિવસ જહેમત ઉઠાવીને કામ કરે છે તેની કસોટી ઈતિહાસ કરશે. ઈતિહાસ તેની તુલના કરશે.

માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ કાયદો અને વ્યવસ્થાની વાત કરી અને એક સંસદ સભ્યશ્રીના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો, હું કોઈની ટીકા કરવા માગતો નથી. પણ મારે એ કહેવું છે કે જે વેરાવળના બનાવના સંદર્ભમાં એમણે એમ વાત કરી કે એક સાંસદના ભાઈની સામે પણ છે. એ સાંસદના ભાઈની વાત થઈ છે. આ સાંસદના ભાઈની સામે ૧૯૯૧ અને ૧૯૯૬ની સાલમાં ફોજદારી ધારાની કલમ ૩૦૭ નીચે ગુનો દાખલ થયેલો ત્યારે કોની સરકાર હતી? એની પણ આ લોકોએ વાત કરી. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ રાજ્ય સરકાર દલિતો, વંચિતો, પછાત અને ગીરીજનોના હિતને વરેલી છે. આ રાજ્યની સરકાર રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને સ્થાપિત કરવાને વરેલી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય માધાભાઈ, આપનું પ્રવચન પુરુ થાય છે. માનનીય મહેશભાઈ વસાવા.

શ્રી મહેશભાઈ છો. વસાવા (દેડિયાપાડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપરનો આભાર પ્રસ્તાવ માનનીય શંકરભાઈ ચૌધરી લઈને આવ્યા છે એમાં હું મારા વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે ઊભો થયો છું.

આ સભાગૃહની અંદર હું પહેલીવાર પ્રવચન કરવા માટે ઊભો થયો છું ત્યારે જો કંઈ ભૂલચૂક થઈ જાય અથવા તો નિયમ પ્રમાણે કે કાયદા પ્રમાણે મારું પ્રવચન ન હોય તો મને માફ કરજો.

આ રાજ્યના વિકાસની વાત માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં કરવામાં આવી છે. ત્યારે એના ઉપર અનેક માનનીય સભ્યશ્રીઓએ પોતાનાં મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા છે. એની ઉપર ઘણી ચર્ચાઓ થઈ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના લાભની વાત હોય એમાં એ લોકો તરફથી પાટલીઓ થપથપાવવામાં આવતી અને કોંગ્રેસની વાત હોય સરકારની વિરુદ્ધની વાત હોય એમાં એ લોકો તરફથી પાટલીઓ થપથપાવવામાં આવતી મેં જોઈ છે. અમને તો જ્યારે પણ જે સરકાર રાજ કરે એની સામે વાંધો નથી. ભાજપની સરકાર હોય કે એની આગળની કોંગ્રસની સરકાર હોય, પરંતુ ગુજરાતની પાંચ કરોડની જનતાની વાત કરવાની હોય તો એમાં સૌથી વધારે આદિવાસી વિસ્તાર છે ત્યાં રહેતા ભાઈઓની ચિંતા કરવાની ખાસ જરૂર છે. આ આદિવાસી વિસ્તારમાં શિક્ષણનું પ્રમાણે આજે પણ ઘણું ઓછું છે. જે ઈન્ટીરીયર વિસ્તાર છે ત્યાં રસ્તા નથી જ્યારે જે શહેરી વિસ્તાર છે જે ફોરવર્ડ વિસ્તાર છે ત્યાંના રસ્તાઓ એકદમ સરસ બનાવેલા છે. એની પાછળ વધારે કાળજી લેવામાં આવે છે. જ્યારે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર ખૂબ અંદરના વિસ્તારો છે, જે દુર્ગમ વિસ્તારો આવેલા છે ત્યાંનો રસ્તો એકપણ વાર બનાવવામાં નથી આવ્યો. તેથી રાજ્ય સરકારે એના માટે વધારે બજૅટ ફાળવીને આ વિસ્તારના રસ્તાઓની ખાસ ચિંતા કરવી જોઈએ. કારણ કે રાજ્ય સરકારનું આવકનું જો કોઈ મોટામાં મોટુ સાધન હોય તો એ આ આદિવાસી વિસ્તાર છે. ત્યાં ઉકાઈ ડૅમ, નર્મદા ડૅમ વગેરે આવેલા છે, આ વિસ્તારમાંથી પથ્થરો નીકળે છે, કોલસો નીકળે છે, રેતી નીકળે છે, પરંતુ જે ત્યાંના સ્થાનિક રહેવાસીઓ છે એમને આમાંથી કંઈજ મળતું નથી એના લીધે ત્યાંનો વિકાસ થઈ શક્યો નથી. અહીંની નદીઓનું પાણી છેક સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાત સુધી જાય છે એનો પણ અમને વાંધો નથી, પરંતુ ઉકાઈ કે નર્મદા ડૅમના જે વિસ્થાપિતો છે એને વસાવવા માટે જે જમીન ખરીદવામાં આવી છે એ જમીન સાવ ઓછા ભાવે એટલે કે એકરના ૯૦૦ થી ૧૦૦૦ રૂપિયાના ભાવે ખરીદી લેવામાં આવેલ છે. તેથી એ લોકો આજે રોડ ઉપર આવી ગયા છે. એમને જે પ્લૉટો ફાળવવામાં આવ્યા છે એ સાવ અસ્તવ્યસ્ત છે. આવા લોકોને જે તે ડૅમના પાણીનો લાભ પણ મળ્યો નથી. આ ડૅમોનું પાણી સપાટ વિસ્તારમાં દૂર સુધી જાય છે અને ત્યાંના લોકો શેરડી વગેરે પાકો પકવે છે એની અંદર આ વિસ્થાપિત ભાઈઓ મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. એમના માટે શિક્ષણની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. તેઓ મજૂરી કામે બહારગામ જાય ત્યારે પોતાનાં બાલબચ્ચાં સાથે લઈને જાય

છે અને એ બાળબચ્ચાં શિક્ષણના અભાવે છેવટે મજૂર બને છે. આપણે જો વિકાસ કરવો હોય તો શિક્ષણની જોગવાઈ કરવી પડે અને એના માટેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

જ્યારે આપણે કોલસાની વાત કરીએ, જંગલના લાકડાની વાત કરીએ કે રેતીની વાત કરીએ. આટલી મોટી સંપત્તિ જે લોકો પાસે જે વિસ્તારોમાં છે તેની અંદર ૨૦ ટકા કે ૨૫ ટકા ભાગીદારી આપે તો ગુજરાતના એ લોકોની ચિંતા હોય તો તેનો વિકાસ કરી શકાય. પણ આને લાકડું, પાણી, રેતી, સિમેન્ટ જ્યાં જેની પાસે સવલત છે એવા લોકોને ફાયદો થાય છે. ખરેખર સરકારે ચિંતા કરવી જોઈએ કે આ લોકોને આપીને તેમનો વિકાસ કરવો જોઈએ.

બીજું, આજે ગામડાંમાં રસ્તાને કારણે બસો જતી નથી એ બસો જવી જોઈએ કેમ કે બાળકોના શિક્ષણ માટે એ જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા માટે બસમાં જઈ શકે. એ બસો દોડતી નથી. અંતરિયાળ ગામડાં છે જ્યાં શિક્ષક પણ જઈ શકતો નથી. નર્મદા જિલ્લામાં માતાસર ગામ જે નર્મદાને કિનારે આવેલું છે ત્યાં શિક્ષક મૂકેલ છે, પણ હજુ સુધી શિક્ષક ગામમાં જતો નથી. અમે પોતે ગામના છોકરાને ઊભો કરીને પગાર આપીને ત્યાંનાં છોકરાંને ભણાવીએ છીએ. અમે કલેક્ટરને રજૂઆત કરી છે, શિક્ષણ અધિકારીને લેખિતમાં આપ્યું છે. જ્યારે મુખ્યમંત્રીશ્રી આવેલા ત્યારે અમને શિક્ષણ માટે આનંદ હતો. એ ત્યાં ત્રણ દિવસ રોકાયા છતાં પણ આવી પરિસ્થિતિ થાય. અધિકારીઓ ધ્યાન ન આપે તો કેવી રીતે શિક્ષણ આપી શકાય? શિક્ષણ મુખ્ય વસ્તુ છે. લોકોના વિકાસ માટે જરૂરી છે. શિક્ષિત હોય તો તેને ખ્યાલ આવે કે વિકાસ કેવી રીતે કરવો, પણ જે લોકો આપણા પર આધારિત છે, આપણા પર વિશ્વાસ રાખીને મતદાન કરે છે ત્યારે ગૃહમાં બેઠાં છીએ ત્યારે આવા લોકોની આપણે ચિંતા કરવી જોઈએ. શિક્ષણ વિકાસનો પાયો છે અને બીજું લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ અંગે જોઈએ તો જે તે વિસ્તારમાં કોઈ પણ ફૅક્ટરી હોય કે જ્યાં આજે લોકો જમીન ગુમાવીને બેઠાં છે એવા લોકોને તેમાં નોકરી આપવી જોઈએ. તેનો હિસ્સો જાય છે. જેવી રીતે કોલસાનું ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન થાય છે ત્યાંના સ્થાનિક લોકોની મંડળી બનાવીને તે લોકોને ફાયદો થવો જોઈએ. કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિમાં બીજાં લોકો ટેન્ડર સિસ્ટમથી લઈ જાય છે. ત્યાંના સ્થાનિક લોકોને જો રોજી-રોટી આપવી હોય તો આ વ્યવસ્થા આપણી સરકારે કરવી જોઈએ અને ચિંતા કરવી જોઈએ. મને બે શબ્દ બોલવાની તક મળી તે બદલ આભાર માનું છું.

શ્રી દિલુભા ટે. ચુડાસમા (વડોદરા (ગ્રામ્ય) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીએ આ સભાગૃહને કરેલા સંબોધન બદલ આભાર પ્રસ્તાવ લઈને માનનીય શંકરભાઈ આવ્યા છે તેને હું મારું સમર્થન એટલા માટે આપવા માગું છું કે માનનીય રાજ્યપાલશ્રીએ ગુજરાતના વિકાસની વાત કરી છે. માનનીય વિરોધપક્ષના નેતા શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડીયાએ વાત કરી કે માનનીય રાજ્યપાલશ્રીએ એવું પ્રવચન કર્યું કે એ સાંભળવા જેવું નથી. તો શું તેમને ગુજરાતના વિકાસની વાતમાં રસ નથી? આવી ગુજરાતના વિકાસની સરસ વાત કરતા હોય અને વિરોધપક્ષના નેતા એવું કહે કે આ વાત સાંભળવામાં મને રસ નથી. બીજું એવું કહ્યું કે પંચામૃત, તો મુખ્યમંત્રીશ્રીએ
ઘણા ઉલ્લેખો કર્યા છે. તો આની અંદર પંચામૃતની કોઈ વાત નથી એવું કહેવા માગે છે તો આટલા અભ્યાસુ હોય તો મારી વિનંતી છે કે સારી રીતે આ જે રાજ્યપાલશ્રીનું પ્રવચન છે એ વાંચવું જોઈતું હતું. તેમાં પાંચેય શકિતઓ આવી જાય છે. ઊર્જા શકિત, રક્ષા શકિત, એ બધી શકિતઓને આવરી લીધી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રસ્તાઓની જ્યારે વાત કરી તો આ રસ્તાઓ તો અમે વર્ષોથી કરતા હતા એમ વાત કરી. તો રસ્તા હતા તો મારે ધ્યાન દોરવું છે કે, જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવી ત્યારે એકપણ રસ્તો હતો નહીં. જ્યારે જ્યારે અમે ચૂંટણી વખતે જતા હતા ત્યારે ગામડાંની અંદર લોકો બોર્ડ મારતા હતા કે 'ગામની અંદર પ્રવેશ કરવો નહિ.' મેં કહ્યું કે કેમ ભાઈ? તો કહે કે, અમારા ગામમાં રસ્તાઓ થતા નથી. મેં કહ્યું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવી નથી, એ આવશે તો ખ્યાલ આવશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી ગામડે ગામડે રસ્તાઓ જોઈ શકાય છે. આ ગર્વ લેવા જેવી વાત છે. વિરોધપક્ષમાં બેઠા છો તો સાચી વાતને કબૂલ કરતાં શીખવું પડશે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વીજળીની વાત કરી કે અમારી સરકારમાં તો ખેડૂતોને બાર-બાર કલાક વીજળી અપાતી હતી. તો મારે એમને પૂછવું છે કે, વીજળીનો વપરાશ તે વખતે કેટલો હતો અને આજે કેટલો છે? વીજળીના વપરાશની વાત કરતા હોત અને એ વખતે આયોજન કર્યું હોત તો અત્યારે આ દશા ન હોત અને આ સરકારે વીજળી માટે એટલું બધું આયોજન કર્યું છે કે, ગયા વખતે સત્રમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જ્યોતિ ગ્રામ યોજના જાહેર કરી ત્યારે વિરોધપક્ષના મારા મિત્રો તેની મશ્કરી કરતા હતા કે આવી ખાલી વાતો કરવાની જરૂર નથી. આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, ગામે ગામ જ્યોતિ ગ્રામ યોજનાના કામ ચાલુ છે અને ૧૮,૦૦૦ ગામડાંમાંથી ૭૦૦૦ ગામડાંમાં કામ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. તો મારે વિરોધપક્ષના મિત્રોને કહેવું છે કે, હંમેશાં સાચી વાત હોય એ કબૂલ કરવી જોઈએ અને હમણાં વિરોધપક્ષના નેતાએ એવું પણ કહ્યું કે, (અંતરાય) જ્યારે જ્યારે તે વાત કરે છે ત્યારે ગોધરાની વાત કરે છે. મારે મિત્રોને વિનંતી છે કે, આ ગોધરાની ઘટના કયાંથી ઉભી થઈ? બોલો છો તો સાંભળવાની તૈયારી રાખો. તમારી પોલ ખૂલી જાય છે એટલે?

સાંભળવાની તૈયારી રાખો. જ્યારે ગોધરાની ઘટના બની, નિર્દોષ લોકોને ટ્રેનમાં બાળી મૂક્યા તે કોણ હતા? તે કયાંથી આવ્યા હતા? અને એ વખતે વિધાનસભા ચાલુ હતી.(અંતરાય) ત્યારે તમને કેમ આટલું બધું લાગી આવે છે? એમની આટલી બધી ચિંતા કેમ થાય છે? એ ઘટના બની ત્યારે સામા પક્ષના મિત્રોએ એકપણ શબ્દ નથી ઉચ્ચાર્યો અને જ્યારે ઘટના બની અને તે પછી જાણે કાંઈક થઈ ગયું હોય એમ બધા રજૂઆત કરવા માંડ્યા. તો મારે મિત્રોને પૂછવું છે કે, શાના માટે આ બધું કરો છો? પછી સિક્યોરિટીની વાત કરે છે. આટલી બધી સિક્યોરિટી રાખે છે. મારે મિત્રોને પૂછવું છે કે, કયારેય ગુનાખોરી સામે કે આતંકવાદ સામે, કોઈ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે ખરો? આ સરકારે આતંકવાદ નાબૂદ કરવા માટે પૂરેપૂરાં પગલાં લીધાં છે. જેના કારણે ગુનાખોરી કરવાવાળા ગુનેગારો કયાંય ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે. કેટલાય ગુનેગારો અને આતંકવાદીઓ મંત્રીશ્રીઓના બંગલા પાછળ ફરતા હતા તે ભૂલવું ન જોઈએ અને હંમેશાં સાચી વાત હોય એ સ્વીકારવી પડે. ગુજરાતના વિકાસમાં પણ અને ગુજરાતનો વિકાસ થતો હોય ત્યારે વિરોધપક્ષમાં બેસીને હંમેશાં તમારે કોઈ સૂચન હોય તો અમને આપો, અમારી તૈયારી છે, પણ સારા કામમાં પણ વિરોધ કરવો એ ખોટું છે. જ્યારે પાણીની વાત કરી તો જ્યારે હોય ત્યારે એમ કહે કે આ બધી યોજનાઓ અમે કરી હતી, આ અમે કર્યુ છે, પણ ભૂલી ગયા કે આ સરકારમાંથી અગાઉ ત્યાં પાણીનાં ટૅન્કરો મોકલવાં પડ્યાં હતાં. હું વડોદરામાં રહેતો હતો અને મને ખબર છે કે માલધારીઓ, ઢોરવાળાઓ ઉનાળો આવે અને પોતાનું વતન ત્યજી અને મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જતા રહેતા હતા. પહેલાં વરસાદ હતા ને એવા અત્યારે વરસાદ નથી પડતા. છતાં અત્યારે દરેક ગામમાં પીવાનું પાણી મળે છે, તો ઢોરોને અને ખેતીનું પાણી પણ મળે છે એ આ સરકારની સિદ્ધિ છે. હમણાં ખારા પાણીની જ્યારે વાત થાય છે ત્યારે અમારી આ મહી વિયર યોજના એ આ સરકારે મંજૂર કરી, કામ ચાલુ હતું અને વિરોધ પક્ષના પેટમાં તેલ રેડાયું કે આવું સારું કામ થાય તો તકલીફ પડશે. એ ચૂંટણી વખતે અમારું (અંતરાય) ના, મહી વિયરનું કામ બંધ રખાવ્યું હતું અને આજે પણ મહી વિયરનું કામ ધમધોકાર ચાલે છે તો હું સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આ મહી વિયરથી આખા વડોદરા તાલુકા અને જિલ્લાને પણ ખૂબ પાણી મળવાનું છે.

કન્યા કેળવણીની વાતો કરી, હમણાં વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી અર્જુનભાઈએ વાત કરી કે શિક્ષણ માટે વાતો કરવાથી ન થાય તો આ સરકારે ખાલી વાતો જ નથી કરી. કન્યા કેળવણી માટે મને ખબર છે કે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી હોય કે માનનીય મંત્રીશ્રીઓ હોય એ બધા આદિવાસી વિસ્તારમાં, છેવાડાના વિસ્તારમાં જઈને કન્યા કેળવણી માટે ફર્યા. અરે, ખરા તાપમાં ઘેર ઘેર ફર્યા અને એના હિસાબે એક મોટો સમૂહ શાળામાં પ્રવેશ મેળવતો થઈ ગયો છે અને કન્યા કેળવણી યાત્રામાં આજ સુધીમાં પહેલો બનાવ હશે કે મુખ્યમંત્રીશ્રીને જે ભેટ સોગાદો આવે એ આ કન્યા કેળવણીમાં વાપરી હોય. (અંતરાય) ખાનાર હોય એ તો બધું વાપરી નાખે આડું અવળું. તમે જરા વિચારો જેની પાસે ખાનાર ન હોય એ તો બધું બહુ વાપરતા હોય છે. અત્યારસધી બધું દ ારભેગું થતું હતું. ગ્રામ વિકાસની વાતો કરીએ તો આ ૧૮ હજાર ગામડાંમાંથી ૧૨,૪૮૧ ગામડાંને ડિસેમ્બરમાં સંપૂર્ણપણે ગ્રામ ગોકૂળ તરીકે પૂરા કર્યા છે એટલું જ નહીં, પણ ઘણી યોજનાઓ હતી તો આ લોકો એમ કહે છે કે આ યોજના અમારી હતી. હા ભાઈ, તમારી હતી અને એ વખતે નામ જૂદું હશે, પણ એ બધી યોજના પેપર ઉપર રહેતી હતી. મને ખબર છે કે આવાસ યોજના મને એક પણ બતાવો કે જૂની આવાસ યોજનામાં એક પણ માણસ રહેતો હોય અત્યારે? એક એક સરદાર વસાહત હોય, સરદાર આવાસ હોય, પણ અત્યારે તો ૪૦,૦૦૦નું મકાન પણ થાય છે અને એની અંદર માણસ સુખેથી રહી શકે છે. આજે આવાસમાં શાંતિથી માણસો રહે છે એવા આવાસો બનાવે છે.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા (જસદણ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન ઉપર માનનીય શંકરભાઈ આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે એના ઉપર હું મારા વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે ઉપસ્થિત થયો છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા પહેલાના પૂર્વ વકતાઓએ ઘણી બધી વાતો કરી. હું નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનની બુકલેટ વાંચી ગયો છું અને આની પહેલાનાં પણ પ્રવચનો મેં વાંચ્યા છે.(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : પ્લીઝ..પ્લીઝ.. બિનજરૂરી ટીકાટિપ્પણ નહીં કરો, પછી હું પગલાં ભરીશ તો કોઈને દુ:ખ થશે. મહેરબાની કરીને કોઈ ટીકાટિપ્પણ ના કરે.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પ્રવચનની અંદર એમના સંબોધનની અંદર અલંકારિક ભાષાઓમાં સરસ મજાના શબ્દો મઢીને મૂકવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અંદર મેં વાંચ્યું ત્યારે એમ થયું કે ખરેખર જે કાંઈ વાતો કરવામાં આવી છે અને અંદર શબ્દો મૂકવામાં આવ્યા છે એમાં કંઈક જુદું જ છે. કોઈ શુભ પ્રસંગ વખતે સોનેરી મજાના કાગળથી મોટા બૉક્સમાં પ્રેઝન્ટ આપવામાં આવે અને જ્યારે ખોલવામાં આવે ત્યારે અંદર જ્યારે નાનકડી વસ્તુ નીકળે ત્યારે મોટો હિમાલય જેવો નિસાસો નાખીને એમ થાય કે આમાં કંઈક જુદું જ નીકળ્યું. મારે એક વાત, નક્કર વાત મુકવી છે. ઉર્જાશકિતની વાતો થાય છે. એમાં મારા પહેલાંના વક્તાઓએ જયોતિગ્રામ યોજનાની ઘણી બધી વાતો કરી. સારી વાત છે, પરંતુ જયોતિગ્રામ યોજનાથી જ ગામડાંનો વિકાસ થવાનો નથી. ગામડાંનો વિકાસ કરવા માટે પહેલાં ખેડૂતોને સમૃદ્ધ કરવા પડશે અને

સમૃદ્ધ થાય એવી યોજનાઓ મૂકવી પડશે, ગામડાંમાં વસતો મજૂર એની રોજીરોટી માટેની યોજના મુકવી પડશે, ગામડાંમાં આરોગ્ય વિષયક સુવિધાઓ ઊભી કરવી પડશે. શિક્ષણની સુવિધાઓ ઊભી કરવી પડશે અને પછી આપણે ગામડાંને ઊભાં કરવાની વાત કરીએ તો મને લાગે છે કે યથાર્થ છે.

ઉર્જાશકિતની વાતો કરીને જયોતિગ્રામ યોજનાની વાત કરી છે. મારે આપના ધ્યાન ઉપર એ વાત મૂકવી છે કે જુલાઈ ૨૦૦૪માં તત્કાલ વીજ જોડાણ અંગેની જાહેરાત કરી. ગુજરાત રાજ્યની અંદરથી પાંચ ઝોનમાંથી તત્કાલ યોજના નીચે ૬૬,૫૧૪ અરજીઓ આવી. એક અરજી કરવામાં એક ખેડૂતને ૫૦૦ રૂપિયા ભરવા પડે છે. આ ખેડૂતો પાસેથી ૩,૩૨,૫૭,૦૦૦ રૂપિયા આ ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડે ખંખેરી લીધાં છે. આજે એક પણ ખેડૂતને તત્કાલ વીજ યોજનાનું ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ મળેલ નથી. એટલાથી જ અટકતું નથી, આ સરકારમાં કેવું ચાલે છે એ પણ મારે એમના ધ્યાન ઉપર મુકવું છે. જનરલ કેટેગરી કે જેમાં ખેડૂતે નોંધણી કરાવ્યા પછી રૂપિયા ૧૫૦ ભરવાના અને વારો આવે ત્યારે જોડાણ મળે. આજની તારીખે આ રાજ્યમાં ખેડૂતો જનરલ કેટેગરીમાં વીજ જોડાણ માટે લાઈનમાં ઊભા છે. આવા જનરલ કેટેગરીના ૨,૭૫,૪૧૦ ખેડૂતો લાઈનમાં ઊભા છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આથી વધુ એક વાત આપના દ્વારા ધ્યાન ઉપર મૂકવા માગું છું કે આ રાજ્યમાં કેવી ભેદભાવની નીતિ ચાલે છે. વિદ્યુત બોર્ડ, રાજ્ય સરકાર તરફથી પાંચ ઝોન પાડવામાં આવ્યા છે. સેન્ટ્રલ ઝોન છે જેમાં વડોદરા વિભાગ આવે છે એમાં ૧૯૯૪ સુધીના જનરલ કેટેગરીમાં વીજ જોડાણ મળ્યા છે, સુરત ઝોનમાં ૧૯૯૧ના વીજ જોડાણ મળ્યા છે, સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કે જેને પશ્ચિમ ઝોન કહેવાય છે એમાં આજે ૧૯૯૦નાં કૃષિ વિષયક જોડાણો મળ્યાં નથી એ એક દુ:ખની વાત છે. ચોક્કસ, આ સંબોધનમાં સમર્થન કરવાની મારી તૈયારી હતી, પણ જે ખેડૂતોને આજે વર્ષોથી લાઈનમાં મૂકયા છે એમને વીજ જોડાણ તો આપવામાં આવતા નથી, તત્કાલ વીજ જોડાણ માટેની રૂપિયા ૩.૩૨ કરોડ જેવી મોટી રકમ ખેડૂતોના ખિસ્સામાંથી ખંખેરી લીધી હોય અને તત્કાલ વીજ જોડાણ આપવાની તૈયારી ન હોય તો ફક્ત જયોતિગ્રામ યોજનાની વાતો કરીને સંતોષ માની લેવાનો કોઈ અર્થ નથી લાગતો. એટલા માટે જે કાંઈ આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે એના સમર્થનમાં સમર્થન આપવા હું તૈયાર નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કન્યા કેળવણીની વાતો ઘણી થાય છે. કન્યા કેળવણી માટે કન્યા કેળવણી રથ કાઢવામાં આવે, શાળા પ્રવેશોત્સવ ઉજવવામાં આવે એટલાથી પૂરતું નથી. ચોક્કસ એ સારી વાત છે અને એ સ્વીકારીએ છીએ, પણ માતા પોતાના બાળકને જન્મ આપે એથી એની વાત પૂરી થતી નથી. એ બાળકને ઉચ્છેરવાનું, મોટા કરવાનું, પોષણ કરવાનું એ જવાબદારી માતાની હોય છે. ફકત કન્યા કેળવણી માટે પ્રવેશ ઉત્સવ ઉજવીએ એટલાથી પૂરું થતું નથી. આજે સેકન્ડરી કે હાયર સેકન્ડરી અને ઉચ્ચ શિક્ષણની અંદર આ કન્યાઓને પ્રવેશ માટેની શું હાલત છે? કેટલી કન્યાઓએ વચ્ચેથી ડ્રોપ આઉટ લીધો? શું કામ ઊઠી ગઈ? એના માટે રાજ્ય સરકારે ચિંતા કરવાની જરૂર છે અને ૧૯૮૫ માં જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે મફત કેળવણી માટેની આ કોંગ્રેસની સરકારે યોજના કરેલી અને એના ભાગરૂપે કોંગ્રેસના વખતથી મફત કન્યા કેળવણી આપવામાં આવતી અને એ વખતે એની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. બિનસરકારી એવી નોન-ગ્રાન્ટેડ શાળા છે (સમય સૂચક ઘંટડી)

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં તો હજુ બે જ મુદ્દાની વાત કરી છે. ૧૯૮૫માં કોંગ્રેસની સરકારે યોજના દાખલ કરેલી એની અંદર આજે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈપણ કન્યાને ફી વીના પ્રવેશ પણ મળતો નથી. વિદ્યા દીપ યોજના ૨૦૦૨ માં દાખલ થઈ, ૬૪૦ કેસ જે મૃતક વિદ્યાર્થીના છે એના કેસ પેન્ડિગ છે અને આજસુધી સહાય ચુકવવામાં આવી નથી. જે સેલ્ફ ફાયનાન્સ શાળા-કૉલેજો છે એમાં ગરીબ પછાત અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની બાળાઓ માટે પૂરેપૂરી ફી લેવામાં આવે છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આરોગ્યની મારે એક-બે વાત કરવી છે. ગ્રામ વિસ્તારની અંદર પહેલાં કોંગ્રેસની સરકારમાં ગામડાંમાં હરતાં-ફરતાં દવાખાનાં હતાં, આજે આ રાજ્યના ગ્રામ વિસ્તારની અંદર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોય, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોય એની અંદર પૂરતો સ્ટાફ નથી, દવા નથી. રાજ્ય સરકારની અંદર જે દવાની ખરીદી થાય છે એ બજાર ભાવની કિંમત કરતાં ઊંચી કિંમતના ભાવ દેવાય છે. હું આપને કહું કે મેં માનનીય મંત્રીશ્રીને પણ કાગળ લખ્યો છે, ડિપ્થેરિયા જેવા રોગો છે, પેરાલીસીસ જેવા રોગો છે એ દવાના અભાવે બાળકો મર્યાના દાખલા આપવાની મારી તૈયારી છે અને દવા પણ ખરીદી નથી અને દવાના અભાવે આ રાજ્યની અંદર બાળકો મૃત્યુ પામી રહ્યાં છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે બીજી વાત એ કરવી છે કે, વંચિતોના વિકાસની જ્યારે વાત કરેલ છે ત્યારે રાજ્યની અંદર ૫૪ ટકા જેવી પછાત વર્ગની વસ્તી હોય અને એની અંદર ખાસ કરીને વિકસિત જાતિની ૫૪ ટકા જેવી વસ્તી હોય ત્યારે દુ:ખની વાત છે કે આ સંબોધનની અંદર કયાંય જેમ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિના વિભાગો અલગ છે તેમ આ વિકસિત જાતિના કલ્યાણ માટેનો વિભાગ નથી. રાજ્યની અંદર જો ૫૪ ટકા વસ્તી હોય તો એનો અલગ વિભાગ કરી એના માટેની યોજના એના વિભાગ મારફત થાય એવી કોઈ યોજના આની અંદર મૂકવામાં આવી હોત તો ચોક્કસ હું સમર્થન કરી શક્યો હોત.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બીજી વાત ધ્યાન પર મૂકું કે, કુંવરબાઈનું મામેરું, દીકરી રૂડી સાચી મૂડી, સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન એની અંદર આજે છેલ્લા બે વર્ષથી ૫૦ કરોડ જેવી રકમ હજુ ચૂકવવાની બાકી નીકળે છે. જે આવા ખાસ કરીને વૃદ્ધ, નિરાધાર, વિધવા આ બધાની યોજના છે એને સમયસર યોજનાના પૈસા જે ચૂકવવા જોઈએ એ પૈસા ચૂકવવા માટેની બીજી કોઈ અલગથી જોગવાઈ નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજનાની અંદર ૩૪૦૩ કેસ આ રાજ્યની અંદર પેન્ડિગ છે એની ૩.૨૪ કરોડ જેવી રકમ છે એ ચૂકવવાની બાકી નીકળે છે એટલા માટે હું આ સંબોધનમાં સમર્થન કરી શકતો નથી.

શ્રી ટપુભાઈ લીંબાસિયા (રાજકોટ-૧) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ અગિયારમી ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના આભાર પ્રસ્તાવનો જે ઠરાવ લઈને માનનીય શંકરભાઈ ચૌધરી આવ્યા છે તેમને હું અભિનંદન આપું છું અને એ અંગે મારા વિચારો પ્રદર્શિત કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત એ ગુજરાત છે, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, "આપણું ગુજરાત આગવું ગુજરાત" છે અને આ ગુજરાતની પ્રગતિ માટે હંમેશને માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે સંકલ્પ શકિત અને ઈચ્છા શકિત દ્વારા, ખેડૂત નીતિ અને ઔદ્યોગિક નીતિ દ્વારા ગુજરાતના વિકાસ માટે જે હરણફાળ ભરી છે તેને આજે આપણે સૌ ખેડૂતલક્ષી નીતિને કારણે આજે ગુજરાતનો વિકાસ જે થઈ રહ્યો છે કે ગુજરાતમાં ૨૦૦૩માં નવ હજાર કરોડ રૂપિયાનું ખેડૂતોનું ખેતીનું જે ઉત્પાદન હતું એ ૨૦૦૪માં એકવીસ હજાર કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યું. આ ખેડૂતોનું ઉત્પાદન જો વધ્યું હોય એની પાછળના જે કાંઈ કારણો હોય તો એ ગુજરાત સરકારની ખેડૂત લક્ષી નીતિ અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી કેશુભાઈથી માંડીને આજના સન્માનીય ગૃહના નેતા, માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ સુધીની એક સરખી જે નીતિ ચાલી આવી છે એને આભારી છે.

નર્મદા યોજનાની વાત કોંગ્રેસ પક્ષના કોઈ સભ્યશ્રીએ કરી કે, આ નર્મદા યોજનાનો પાયો કોંગ્રેસે નાખ્યો છે, જરૂર નાખ્યો છે એ હું સ્વીકારું છું, પરંતુ ચાળીસ-ચાળીસ વર્ષ થયાં આ નર્મદા યોજના રાજ્યની અંદર કાનૂની રીતે અટવાયેલી હતી, કહેવાતા પર્યાવરણવાદીઓ અને તજજ્ઞોએ આ યોજનાને બ્રેક મારવા માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યા હતા, પરંતુ રાજ શકિત અને ગુજરાતની પ્રજાની ઇચ્છા શકિત અને સંકલ્પ શકિતના કારણે આજે પર્યાવરણવાદીઓના હાથ હેઠા પડ્યા છે અને આજે આપણે આ યોજના ૧૧૦ મિટર સુધી લાવી શક્યા છીએ એ રાજ્યની સંકલ્પ શકિતને આભારી છે. આજે નર્મદા યોજના દ્વારા પૂર્વ મુખ્યમંત્રીશ્રી કેશુભાઈએ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના સુકાભઠ્ઠ જેવા ગામોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડી અને જે પોતાની સંકલ્પ શકિત હતી એ સંકલ્પ શકિતને આગળ વધારી અને એજ સંકલ્પ શકિત દ્વારા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાત રાજ્યના એકે એક ગામોને પીવાનું પાણી કેવી રીતે મળી શકે, ખેતીવાડી માટે, સિંચાઈ માટે કેવી રીતે પાણી પહોંચાડી શકાય એ માટે પોતે કમર કસી રહ્યા છે અને આજે હું ન ભૂલું તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે ૧૭ નદીઓ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને નાથવા માટે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને પાણી પૂરું પાડવા માટે જે આયોજન ૫૧૫ કરોડ રૂપિયા સુધીનું કર્યુ છે એ ખૂબ જ આવકાદાયક છે.

રાજ્યની જે ઔદ્યોગિક નીતિ છે એ ઔદ્યોગિક નીતિ પણ રાજ્ય સરકાર જે પગલાં લઈ રહી છે એમાં ૨૦૦૩માં ગ્લોબલ મીટ દ્વારા ૬૬ હજાર કરોડ રૂપિયાનાં જે એમ.ઓ.યુ. સાઈન થયાં અને એમાં ગુજરાત પ્રત્યેની વિશ્વની અંદર રહેતા જે ગુજરાતી મિત્રો જે એન.આર.આઈ. તરીકે ઓળખાય છે એમણે, આજે બહાર એવી કલ્પનાઓ હતી, ગુજરાત વિરોધી લોકોએ ગુજરાત વિષે ગુજરાતનું નામ બદનામ કરવા માટે ગુજરાતમાં કોઈ ઉદ્યોગપતિઓ આકર્ષાય નહીં એ માટે જે વાત ફેલાવી રહ્યા હતા એ વાત ખોટી ઠરાવવા માટે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગ્લોબલ મીટ ધ્વારા આ વર્ષે પણ ૨૦૦૫માં એમ.ઓ.યુ. સાઈન ધ્વારા એક હજાર એક લાખ કરોડના એમ.ઓ.યુ. સાઈન થયા છે. એ બતાવે છે કે, બહાર ઉદ્યોગપતિઓ આજે ગુજરાતમાં પોતાના ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે કેટલા આકર્ષાઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર સૌથી પ્રથમ જોઈએ તો એના માટે પાણી અને રસ્તા એ મુખ્ય છે. ગુજરાતના રસ્તાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે આજથી દસ વર્ષ પહેલાં જે હતા એ કઈ ટાઈપના અને કેવા હતા અને આજે એ ફોર લેન રસ્તાઓ ગુજરાતમાં કોઈપણ છેડે જઈ શકીએ છીએ અને એ રસ્તાઓના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકારે પૂરતા પ્રમાણમાં બજૅટ ફાળવ્યું છે આ વર્ષ, રાજ્ય સરકાર "શહેરી વિકાસ વર્ષ" તરીકે ઉજવી રહી છે ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે, ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં વારંવાર દુષ્કાળ પડે છે જેના કારણે શહેરીકરણ થઈ રહ્યું છે અને આ શહેરોમાં વસતિ જે વધી છે તે ૪૦ ટકા વસતિ એવી સ્થિતિમાં છે ઝૂંપડપટ્ટીઓ અને શહેરી ટોચ મર્યાદા કાયદો આવ્યા બાદ માત્ર નાની અને સૂચિત સોસાયટીમાં વસવાટ કરે છે. આ લોકોને કોઈપણ પ્રકારની સુવિધા મળતી નથી. એ સુવિધા પૂર્ણ કરવા માટે રાજ્ય સરકારે આ વર્ષને 'શહેરી વિકાસ વર્ષ' તરીકે ઉજવવાનું આયોજન કર્યું છે અને એ દ્વારા શહેરી વિકાસની અંદર રાજ્ય ધોરી માર્ગ પસાર થતો હોય તો રાજ્ય ધોરીમાર્ગનો રાજ્ય સરકાર પોતાના ખર્ચે એનો વિકાસ કરશે. લાઈટની સગવડથી ઝળહળતો આ રસ્તો શહેર માટે ગૌરવરૂપ હશે. આ જ રીતે કોઈપણ પ્રકારના શહેરની અંદર એક રસ્તો ગૌરવપથ તરીકે રાજ્ય સરકાર પોતાના ખર્ચે શહેરનું ગૌરવ વધે એ રીતે લાઈટની વ્યવસ્થાથી ઝળહળતો કરશે એ ખૂબ આવકારદાયક છે.

મારે એક વસ્તુ કહેવી છે કે ગુજરાત સરકારે જ્યોતિ ગ્રામ યોજના દ્વારા ગામડાંને ૨૪ કલાક લાઈટ પૂરી પાડી. હમણાં મુરબ્બી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાએ વાત કરી, જ્યોતિ ગ્રામ વિશે પણ હું ભૂલતો ન હોઉં તો જસદણ તાલુકાને જ્યોતિ ગ્રામ યોજનામાં પછાત તાલુકો ગણીને રાજ્ય સરકારે પોતાના ખર્ચે જસદણ તાલુકાના બધા ગામોને જ્યોતિ ગ્રામ યોજના નીચે આવરી લેવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. જ્યોતિ ગ્રામ યોજનાને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ, નાના કારીગરોને પોતાની રોજીરોટી મળી રહે એ માટે એ જ ગામમાં પોતાનો ધંધો રોજગાર ચલાવી શકે એ દ્રષ્ટિએ આ સરકારનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. હું એ પણ વાત કરવા માગું છું કે વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીએ એમ કહ્યું કે રામ રાજ્ય. રામ રાજ્યની કલ્પના સન્માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં સૂચક શબ્દ છે. હું માનું છું કે રામ રાજ્યની કલ્પના તરફ ગુજરાત રાજ્ય આગળ વધી રહ્યું છે. છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે અને ૧૦ વર્ષ પહેલાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સૌરાષ્ટ્રથી માંડીને ગુજરાતની અંદર માફીયાટોળીનું શાસન ચાલતું હતું અને આ માફીયાટોળીને જબ્બે કરી હોય તો પૂર્વ મુખ્યમંત્રીશ્રી કેશુભાઈથી માંડીને નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર સુધી આ માફીયા ટોળીને માથું ઉંચકવા દીધું નથી એ આ સરકારની યશકલગી છે, સિદ્ધિ છે એટલા માટે આપના મારફત રાજ્યપાલશ્રીના આભાર પ્રસ્તાવને અનુમોદન આપીને વિરમુ છું. વંદે માતરમ.

ડૉ.અનિલ જોષીયારા (ભીલોડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન ઉપર આભાર પ્રસ્તાવ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી લાવ્યા છે એમાં મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે ઉપસ્થિત થયો છું. મને એમ કે માનનીય રાજ્યપાલશ્રી આ સરકારની કામગીરીનું પ્રતિબિંબ પાડતું પ્રવચન કરશે, પણ એવું આ પ્રવચનમાં કાંઈ દેખાયું નહીં. આ સરકારે જ્યારથી વહીવટ હાથમાં લીધો છે ત્યારથી ખાસ કરીને ગામડાંની પ્રજાનો અવાજ રૂંધાઈ ગયો છે. એ લોકો ગામડાંના અહીં આવી શકતા નથી અને સિકયોરિટીના બહાને એમને રોકવામાં આવે છે તો આ પ્રજા પોતાનો અવાજ કયાં રજૂ કરે, પોતાના વિશે વાત કયારે કરી શકે? અધિકારી પણ વચ્ચે પડે ત્યારે અધિકારીને પોતાને અહીંથી જવું પડે છે. એવા ૪-૫ અધિકારીઓને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે. રામ રાજ્યની વાત કરે છે. રામ રાજ્યમાં દરેક માણસ મંત્રીને મળી શકે, વિધાનસભામાં આવી શકે અને પોતાના પ્રશ્નો રજૂ કરી શકે, પણ એવું કશું છે જ નહીં (અંતરાય) ના. દરવાજા બંધ છે. માણસો ગાળ બોલીને પાછા જાય છે. સરકારમાં વિકાસની વાતો થાય છે એ વિકાસ અસમતુલિત વિકાસ હોય તેમ દેખાઈ રહ્યું છે. કારણકે ગુજરાત પેટર્નની વાત મોટા પાયા પર કરવામાં આવી અને એનું બજેટ જોઈએ ત્યારે ખબર પડે કે દર વર્ષે બજેટ વધવું જોઈએ, જ્યારે આ સરકારમાં અગાઉનું ૨૦૦૩-૨૦૦૪ના વર્ષનું બજેટ ૨૦૮.૯૦ કરોડનું અને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષનું બજેટ ૧૫૬ કરોડ રૂપિયા, જ્યારે નાણા મંત્રીશ્રીના પ્રવચનમાં ૨૦૮ કરોડ રૂપિયા જણાવે છે, જ્યારે ફાળવણી થઈ છે ત્યારે ફક્ત ૧૩૧.૯૩ કરોડની જ ફાળવણી થઈ છે. આમાં ફેબ્રુઆરીના એન્ડ સુધી કેટલી વપરાશ થાય છે? ફક્ત ને ફક્ત ૭૪ કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ વપરાય છે, ૩૦ થી ૩૨ ટકા જેટલી કામગીરી પણ ચાલતી નથી, ત્યારે અમારા વિસ્તારનાં મોટા ભાગનાં વિકાસનાં કામો અટકી ગયાં છે. ગ્રાન્ટ રહી એ તો સરકારી અધિકારીઓના પગારના પૈસા માટે રહે છે. વિકાસ અસમતુલિત થયો છે. મોટા ભાગની જે આર્થિક વિકાસની યોજનાઓ હતી એ યોજના લગભગ બંધ થઈ ગઈ છે. જે મોટર, બોર્ડ, મશીનરી, પાઈપલાઈન વગેરે માટે જે પૈસા ફાળવવામાં આવતા હતા તે પૈસા બંધ થયા છે. અમારા વિસ્તારના ચેકડેમ જે ગુજરાત પેટર્નમાં મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા તે આજની તારીખ સુધી ચાલુ નથી કરી શક્યા. હું કેટલીય વખત માનનીય મંત્રીશ્રીને મળ્યો છું, પ્રભારી મંત્રીશ્રીને મળ્યો છું. તો કયા કારણોસર ચાલુ નથી કરી શક્યા, શું મુશ્કેલી છે, પૈસાની તકલીફ છે, એક વખત મંજૂર થાય છે અને પછી કામ આગળ ચાલતું નથી. મંત્રીશ્રી, આપની વાત સાચી હશે, પણ અમારા વિસ્તારમાં જઈને પ્રયોજના વહીવટદારને ત્યાં તપાસ કરો તો ૩.૩૨ કરોડ સિંચાઈ માટે ફાળવવામાં આવ્યા હતા તેમાંથી ફક્ત ને ફક્ત ૪૪ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા છે. ડિટેઈલમાં આનો અભ્યાસ કરો તો આની ખબર પડશે.

સિંચાઈની વાત કરું તો અમે એમ ઇચ્છતા હતા કે નર્મદાનાં પાણી મળશે. ગઈ વખતે ગૃહમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં અમરસિંહભાઈની આખી ગાડી જતી રહે તેવી પાઈપલાઈનથી પાણી મળશે. તો અમે ખુશ થયા હતા. મુખ્યમંત્રીએ સ્પેશ્યલ આ ગૃહમાં કહેલ ૩૦૦ કરોડ રૂપિયા વધારાના ઉત્તર ગુજરાત ભીલોડા જેવા વિસ્તાર માટે પૈસા ફાળવવામાં આવશે. આ વાત સાંભળીને ગળગળા થઈ ગયા. બજેટમાં જોયું ત્યારે એક પૈસાની ફાળવણી નહિ. અમારા સાબરકાંઠાના ૧૫૦૦ જેટલાં ગામડાં છે. નર્મદા, કડાણાની વાત કરી છે. એમાં ૩૦-૪૦ ગામોને પાણી મળવાનું છે. ચાર આદિવાસી તાલુકામાં એક પણ ગામને પાણી મળવાનું નથી. તો આ વિકાસ કયા ટાઈપનો છે ? ઓલ્ટરનેટિવ બીજી કોઈપણ વ્યવસ્થા છે કે કેમ?

જ્ઞાનશક્તિની વાત કરી. અમારા વિસ્તારનું શિક્ષણ વધ્યું છે એમ કહે છે. સાબરકાંઠામાં જોઈએ તો છેલ્લા ૨ વર્ષમાં ૧૦ મા ધોરણમાં ૧૦ ટકાથી નીચેનાં પરિણામવાળી ૧૩૧ સ્કૂલો છે. ૧૨ મા ધોરણની અંદર ૨૪ સ્કૂલો જે ઝીરો ટકા પરિણામવાળી છે. આવી પરિસ્થિતિ અમારી સ્કૂલોમાં છે. શિક્ષણને સુધારવા માટે

સરકાર શું કરે છે તેની ખબર પડતી નથી. અમારી જે સરકારી સ્કૂલ હતી એને ખાનગીમાં લઈ જવામાં આવે છે. શા માટે ખાનગીમાં? તો પછી કહે છે કે શિક્ષણ સુધારવા માટે. સરકાર આ શિક્ષણની જવાબદારી લેવા માગતી નથી.

કન્યા કેળવણીની વાત થઈ. જે ખાનગી સ્કૂલો, પી.ટી.સી. ખાનગી કૉલેજો થઈ, એના લીધે ગરીબ પછાત વર્ગના ભાઈઓ અને બહેનો માટે શિક્ષણના દરવાજા બંધ થઈ ગયા છે. પ્રિ-ફેબ્રિકેટેડ ઓરડા બનાવવામાં આવ્યા છે એ સારું લાગતું હતું, પણ અત્યારે તૂટેલ હાલતમાં છે. બે-ત્રણ વર્ષમાં તૂટી ગયા છે. ખોટા સર્ટિફિકેટ શોધવા માટે પણ અભિનંદન આપવાં પડે. શિક્ષણમંત્રીશ્રીએ આ શોધ્યા, પણ શોધ્યા પછી પાછળની કામગીરી નથી કરી. બુદેલખંડવાળા માણસો છે તે માણસો દ્વારા સર્ટિફિકેટ અપાય છે. એ લોકો જ સંસ્થા ધરાવે છે, એ એમના જ છોકરા છે. એ સંસ્થા સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. તો આમાં કઈક વિચારવામાં આવે.

જ્યોતિગ્રામની વાત કરી. સરકાર બહુ સારી રીતે જાહેરાતો કરે છે. ૭,૦૦૦ ગામોને ૨૪ કલાકની લાઈટ મળી ગઈ. અમારાં ગામડાંમાં તપાસ કરો. આદિવાસી વિસ્તારમાં એક પણ ગામ જ્યોતિગ્રામમાં લેવામાં આવેલ નથી. એક પણ ઘરને ૨૪ કલાક લાઈટ મળી નથી. હું ગૃહમાં કહું છું. ગામડાં અંધકારમય બન્યાં છે. ૩૦ થી ૪૦ ટકા જેટલાં ગામડાંનું વીજળીકરણ બાકી છે.

વાહનવ્યવહારની વાત કરીએ તો વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ કહ્યું તેમ અત્યારે ૧,૦૦૦ રૂટો બંધ થઈ ગયા છે. વાહનવ્યવહારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે ટાયર-ટ્યૂબ ખલાસ થઈ ગયા છે, ડીઝલ પૂરાવવાના પણ પૈસા નથી એ રીતની પરિસ્થિતિ પેદા થઈ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એસ.ટી.બસો બંધ થઈ છે. કડાણા હાઈલેવલની કેનાલની વાત પહેલાં મંત્રીશ્રી કરતા હતા કે કડાણા હાઈલેવલ કેનાલથી અમારા વિસ્તારને પાણી મળવાનું છે, પણ એ કડાણા હાઈલેવલ કેનાલની વાત એની એ જ રાખી અને આખો પ્લાન બદલીને નર્મદા કેનાલ હતી તેની પેરેલલ બીજી કેનાલ કરીને પાણી બનાસ બાજુ લઈ ગયા, મહેસાણા સાઈડે લઈ ગયા અને તેના લીધે અમારો વિસ્તાર સૂકોભઠ્ઠ રહેવાનો છે. અમારી વિનંતી છે કે આ જાતનું વલણ અપનાવાઈ રહ્યું છે તે ન કરે અને અમારા વિસ્તારને ન્યાય આપે તેવી વિનંતી સાથે માનનીય રાજ્યપાલશ્રીએ જે પ્રવચન આપ્યું છે તેમાં સરકારનું પ્રતિબિંબ થોડું જુદું દેખાય છે એટલે તેને સમર્થન આપી શકતો નથી અને મારી વાત પૂરી કરું છું.

શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા (પાલીતાણા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન ઉપર આભાર પ્રસ્તાવ લઈને માનનીય શંકરભાઈ ચૌધરી આવ્યા છે તેને સમર્થન આપવા માટે ઉભો થયો છું રાજ્યપાલશ્રીનું પ્રવચન જયારે થતું હતું ત્યારે અમે સાંભળતા હતા. તે પ્રવચન ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે રાજ્ય સરકાર સર્વાંગી ક્ષેત્રોમાં અદ્વિતીય રીતે કામ કરી રહી છે. બધા ક્ષેત્રોમાં ખાસ કરીને કૃષિ અને શિક્ષણ તે ઉપરાંત બીજાં વિવિધ ક્ષેત્રો જેવાં કે ઉર્જા આ બધા ક્ષેત્રોમાં રાજ્ય સરકાર જે કામ કરી રહી છે તેમાં નવા સોપાનો સર કર્યા છે.

આ બધા ક્ષેત્રોમાં જયારે પ્રગતિ કરી હોય ત્યારે સરકાર ખૂબ પાયાનો વિચાર કરીને આગળ વધી રહી છે. કારણ કે આ સરકારની અંદર પટાવાળાથી માંડીને એટલે કે કલાસ-૪ થી કલાસ-૧ સુધીના અધિકારીઓને વિકાસની અંદર ભાગીદાર કરવા હોય, કારણ કે સરકાર કોઈ ઈચ્છાશકિત વ્યકત કરે અને તે ઈચ્છાશકિતને પરિણામમાં ફેરવવા માટે વહિવટી તંત્રને સાથે રાખીને વહિવટી તંત્ર પાસેથી કામ લેવું ખૂબ આવશ્યક છે. એટલા માટે રાજ્ય સરકારે આ રાજ્યના તમામ અધિકારીઓને કર્મયોગીની તાલીમ આપી, કર્મયોગીની તાલીમના ભાગરૂપે દરેક કર્મચારીમાં કાર્ય સંસ્કૃતિની નવી દિશા તેમના હિસાબે ખૂલી છે. તેમની જૂની પદ્ધતિ હતી અને જૂની જે સિસ્ટમ હતી તેમાં ધરખમ પરિવર્તન આવ્યું છે. કર્મયોગી યોજનાથી વહીવટી તંત્ર ગતિશીલ બન્યું છે, ચેતનવંતુ બન્યું છે. તેના હિસાબે તેનો આધાર લઈને આ રાજ્ય સરકાર વિકાસ કરી રહી છે ત્યારે આ રાજ્ય સરકારના વિકાસના આંકડા ઉપરથી એ ફલિત થાય છે. ૨૦૦૩-૦૪ની અંદર ૧૫.૪ ટકાનો વિકાસ દર હાંસલ કર્યો છે તે અન્ય રાજ્યોની સાપેક્ષમાં ખૂબ આગળ છે અને આ રાજ્યનું ગૌરવ કહેવાય છે. આ બધા વિકાસને સાકાર કરવો હોય અને સર્વાંગી વિકાસ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આ રાજ્યની અંદર બીલો પોવર્ટી લેન એટલે કે ગરીબી રેખાથી નીચે જે લોકો જીવે છે તેમના જીવન ધોરણમાં ખૂબ ફાયદો થયો છે અને સુધારો થયો છે તેના પણ આંકડા ઉપલબ્ધ છે. ગરીબી રેખાથી નીચે જીવતા લોકોની સંખ્યા ૧૯૯૨-૯૩ માં ૬૨.૧૦ લાખની હતી તે ૧૯૯૯-૨૦૦૦ માં ૩૯.૧૦ લાખે પહોંચી છે. આના ઉપરથી દેખાય છે કે આ સરકારે ગરીબ લોકોનું કામ કર્યુ છે. ગરીબ લોકોના જીવન ધોરણ માટે અગ્રિમ ધોરણે કામ કર્યુ છે. ચાર-પાંચ દિવસ પહેલાં છાપામાં જાહેરાત આવી હતી કે કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યો ટ્રેકટર ઉપર બેસીને વિધાનસભામાં આવશે. મને હતું કે કંઈક ખેડૂતોની ખૂબ વાત કરે છે એટલે સાચી ચિંતા પણ કરી હોય, પરંતુ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વિરોધપક્ષના ધારાસભ્યશ્રીઓએ ગેટ તોડયો, કંઈક ટલ્લો લગાડયો હશે બધું કર્યુ હશે, પણ ગેટ તોડવાથી કે ટલ્લો લગાડવાથી આ કિસાનોનું ભલું થવાનું નથી. કિસાનોનું ભલું પૂર્વ કેન્દ્ર સરકારે એટલે કે બાજપાઈજીની સરકારે બહું સારી રીતે કર્યુ હતું,

અત્યારે ખેડૂતોને પેદાશોના ભાવ મળતા નથી તેના માટે રાજ્ય સરકારની જવાબદારી છે તેવું ઉદ્દબોધન થાય છે ત્યારે મારે કહેવું જોઈએ કે બાજપાઈજીની સરકારમાં ખેત ઉત્પાદન થયું હતું, સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ખેત ઉત્પાદન પુષ્કળ થયું હતું, પરંતુ ભાવ મળ્યા હતા તેનું કારણ શું? કારણ એ હતું કે જયારે રાષ્ટ્રની અંદર કોઈ માલ આયાત થતો હોય ત્યારે તે પેદાશની આયાત ઉપર ભૂતકાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ૪૦ ટકા ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી નાંખી હતી એટલા માટે ખેડૂતોને ૬૦૦ રૂપિયાના ભાવ મળ્યા હતા. તા. ૧૬-૨-૨૦૦૫ ના દિવ્ય ભાસ્કરમાં લખ્યું છે કે પેદાશની આયાતને રોકવા જકાત વધારવા કેન્દ્રનો ઈન્કાર. આ છાપું બોલે છે. *(xxxxx) કહે છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો મરવા હોય તો ભલે મરે, એમને ભાવ ન મળે તો કંઈ નહીં. અમારે તો ઊંચા લોકોનું ભલું કરવું છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય સભ્યશ્રી, આપ બેસો, માનનીય સભ્યશ્રીનો પૉઈન્ટ ઑફ ઑર્ડર છે.

પૉઈન્ટ ઑફ ઑર્ડર
શબ્દો રદ કરવા અંગે

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો પૉઈન્ટ ઑફ ઑર્ડર છે કે, માનનીય સભ્યશ્રીએ *(XXXX) ઉલ્લેખ કરીને એમ કહ્યું કે, 'ગુજરાતના ખેડૂતો મરવા હોય તો ભલે મરે' આ શબ્દ પ્રયોગ *(XXXX) નામે કરવા એ ઉચિત નથી એટલે રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે, *(XXXX)વાત કરી છે અને એમને કપાસના નામે વાત કરી છે કે 'ગુજરાતના ખેડૂતો મરવા હોય તો ભલે મરે' આ પ્રકારના જે શબ્દ પ્રયોગ કરે છે એ વાજબી નથી, એ રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે.

અધ્યક્ષશ્રી : હું રેકર્ડ તપાસી લઈશ, એમાં *(XXXX)કેન્દ્રીય મંત્રી એવો શબ્દ હશે તો એ શબ્દ દૂર કરવામાં આવશે.

રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)(ક્રમશ:)

શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો કહેવાનો હેતુ એ હતો કે, ગુજરાતમાં ખરેખર કપાસના ભાવ નહીં મળવાનું કારણ એ કેન્દ્ર સરકાર છે. કપાસના આયાત ઉપર એ જો ૪૦ ટકા ડ્યૂટી નાખે અને એની રજૂઆતો પણ થઈ છે. તો ગુજરાતના કિસાનોને ખરેખર ઊંચા ભાવ, કપાસના ઉંચા ભાવ મળી શકે એમ છે. હમણાં અવલોકન થતું હતું કે મહારાષ્ટ્રમાં આ રીતે ખરીદી થાય છે, તે રીતે ખરીદી થાય છે, મહારાષ્ટ્રમાંથી રોજ સો-દોઢસોની સંખ્યામાં ગાડીઓમાં કપાસ વેચાવા આવે છે, જો મહારાષ્ટ્રમાં પૂરતા ભાવ મળતા હોય તો ગુજરાતમાં શા માટે કપાસ લઈને વેચવા આવે છે? એટલે લોકોને, ગુજરાતની જનતાને, ગુજરાતના ખેડૂતોને ગુમરાહ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી, સહી રસ્તો પકડવાની આવશ્યકતા છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સરકારે સોઈલ હેલ્થ કાર્ડની જે યોજના બનાવી છે એનાથી ખૂબ સારાં પરિણામો આવવાનાં છે. આખા રાજ્યમાં કામ ચાલે છે, ભૂતકાળની કોઈ રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોની ચિંતા કરી નથી, ખેડૂતોના એકેએક ખેતરની જમીનના નમૂના લેવાઈ રહ્યા છે. એમાં કયાં પોષકતત્ત્વો છે કે કયા પોષક તત્ત્વો નથી એનું એવું આખુ વિશ્લેષણ થાય અને એના કાર્ડ આપવામાં આવે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક વૈજ્ઞાનિક અહેવાલ એવું કહે છે કે, જો એક વખત સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ મળી જાય અને ઘટતા-પૂરતા તત્ત્વોનો જો ખેડૂતોને ખ્યાલ આવે તો વીસ ટકા ઉત્પાદન વધારી શકાય એમ છે. તો ખેડૂતોની ચિંતા ત્યાં થઈ છે અને આ સરકારે ખેડૂતોની ચિંતા કરીને આ વિષય મૂક્યો છે એટલા માટે મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે આ સરકાર ખેડૂતલક્ષી છે, આ સરકાર ગ્રામ્યલક્ષી છે અને એ પરિણામોના આધાર ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે.

આ ઉપરાંત, આ સરકારની એક વિશેષ ઉપલબ્ધિ જોઈએ તો અત્યારે હજારોની સંખ્યામાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યા સહાયકોની ભરતી થઈ છે એ ખૂબ પારદર્શક ભરતી થઈ છે, આ સરકારમાં કાંઈ લાગવગ એ લાયકાત અને પૈસા, એ પરમેશ્વર રહ્યું નથી. ભૂતકાળની સરકારોમાં જે ભરતીઓ થતી હતી એમાં પૈસાની રેલમછેલ થતી હતી, વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર થતો હતો, લાગવગ થતી હતી અને અત્યારે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ત્રણ હજાર પોલીસ કૉન્સ્ટેબલની ભરતીનું કામ ચાલે છે. એ સંપૂર્ણપણે તટસ્થાના ધોરણ, કયાંય પણ કોઈપણ પ્રકારની લાગવગના ધોરણ વગર ચાલે છે એ આ સરકારના પારદર્શક વહીવટનો એક આદર્શ નમૂનો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જયોતિગ્રામ યોજનાને કદાચ વિપક્ષના ધારાસભ્યશ્રીઓ ગામડાની અંદર એક ગોળો ઝગે, ગામડાંમાં સ્ટ્રીટ લાઈટ ઝગે, એટલા નાના હેતુથી લેતા હોય તો અમને ખબર નથી પણ જયોતિગ્રામનો હેતુ, એનો વિષય ખૂબ વિશાળ છે અને એનું પરિણામ અમે જોયું છે. મારા વિસ્તારમાં ૭૦ ટકાથી વધારે

* (XXX) આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે.

ગામોને જયોતિગ્રામ નીચે આવરી લીધાં છે. એક વર્ષ પહેલાં જયોતિગ્રામથી વીજળીકરણ થયું એના પરિણામો અમને એક વર્ષ પછી મળ્યાં છે, ગામડે ગામડે ૨૪ કલાક વીજળી ઉપલબ્ધ થવાથી નાનાં મોટાં હીરાનાં કારખાનાં, એક એક બે ઘંટીઓ ચાલુ થઈ છે, ગામોમાં કામ કરનારા સુથાર અને એનો ડેન્શો વ્યવસ્થિત ચાલવા માંડ્યા છે. ગામડાંની અંદર ગૃહ ઉદ્યોગો વિકસ્યા છે, ગામડાંની અંદર પાયાની સુવિધાઓ પૂરી થઈ છે, આ સરકાર એ ગ્રામ્યલક્ષી સરકાર છે, આ સરકાર ખેડૂતલક્ષી સરકાર છે, આ સરકાર પ્રજાલક્ષી સરકાર છે એ એના કાર્યો ઉપરથી દેખાઈ રહ્યું છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હમણાં જ ઉદ્‌બોધનની અંદર એક વિષય એવો હતો કે, કિસાનપથ યોજનાથી ગામડાંના, છેવાડાના ગામના લોકોને પાકા રસ્તાથી જોડવાનું આયોજન છે એ કંઈ નાનું કામ નથી, આ રાજ્યે ખાસ કરીને પશુપાલન ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ કરી છે, ૨૦૦૧-૨૦૦૨માં ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા ૫૮.૬૭ લાખની હતી જે વધીને ૨૦૦૩-૨૦૦૪માં ૬૪.૨૧ લાખ મેટ્રીકટન જેટલું દૂધ ઉત્પાદન આ રાજ્યે કર્યુ છે એ કંઈ નાનો વિષય નથી, પશુપાલન એ ખેતીનો પૂરક વ્યવસાય છે અને એને વિકસાવવા માટે રાજ્ય સરકારે જે કાંઈ કાર્યો કર્યા છે એ....(સમયસૂચક ઘંટડી) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હજું મારે ઘણા વિષયોમાં કહેવાનું છે....

ડૉ. સી. જે. ચાવડા (ગાંધીનગર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર આ ગૃહના માનનીય સભ્યશ્રી જે આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે એને હું સમર્થન આપી શકતો નથી.

અંગ્રેજીમાં એક બહુ સરસ કહેવત છે કે "How much you speak is not important for the society, but how much you do is important for the society"

તમે કેટલું બધું બોલો છો એ અગત્યનું છે જ નહીં. અશોકભાઈ ભટ્ટ આખી જિંદગી બોલ્યા છે, પણ "How much you eat is not important for the body, but how much to digest is important for the body". પાચન કરવું એ અગત્યનું છે અને કામ કરવું એ અગત્યનું છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં પૈઈઝ નં. ૩૫ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ રાજ્યની કામગીરીની ગુણવત્તાને ધ્યાને લઈને રેટિંગ એજન્સીઓએ ગુજરાત રાજ્યને નંબર આપ્યો છે. મારે આ ગૃહનુ ધ્યાન દોરવું છે કે "ઈન્ડિયા ટુ ડે " માં એક લેખ છે કે, જે રેટિંગ એજન્સીએ ગુજરાત રાજ્યના વહીવટી તંત્રને ત્રીજો ક્રમ આપ્યો હતો અને ત્યારે આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ આખા રાજ્યમાં ૧૦ કરોડના ખર્ચે પોતાના ફોટા લગાવ્યા હતા એજ રેટિંગ એજન્સીએ આજે ગુજરાત રાજ્યને ૧૧મો ક્રમ આપ્યો છે. વર્લ્ડની એક એજન્સીએ આખા વિશ્વના મૂડી રોકાણકારો માટે કયું રાજ્ય, કયો વિભાગ, કયો દેશ એ.બી.સી.અને ડી. વર્ગમાં આવે છે એનું રેંટિંગ કરે છે. આ ગુજરાત રાજ્ય સમગ્ર ભારતમાં બીજા ક્રમે અને સમગ્ર વિશ્વમાં મૂડીરોકાણ માટે રેટિંગમાં 'એ' સ્થાન દ ારાવતું હતું એ રેટિંગ સંસ્થાએ આજે ભારતને એ.બી.સી. અને ડી. મૂડીરોકાણ માટેનું સ્થાન આપ્યું છે એમાં જમ્મુ-કાશ્મિરને પણ 'ડી' સ્થાન આપ્યું છે, પણ ગુજરાત રાજ્યનો એ.બી.સી. કે ડી.માં સમાવેશ થતો નથી એ ગુજરાત માટે શરમજનક બાબત છે. આપણે વાતો કરીએ છીએ ૨૦૦૩ની સાલમાં ૬૬ હજાર કરોડના એમ.ઓ.યુ. થયાં, ૨૦૦૫ની સાલમાં ૧ લાખ કરોડનાં એમ.ઓ.યુ. થયાં અને હજુ કદાચ ૨૦૦૭ની સાલમાં તમે ૧૦ લાખ કરોડનાં એમ.ઓ.યુ. કરશો, પણ મૂડીરોકાણ કેટલું થયું? એ ચિંતન અને મંથનનો વિષય આ ગુજરાતની પ્રજા માટે બન્યો છે અને હજારો કરોડના એમ.ઓ.યુ.ની વાતો કરે છે પણ મૂડીરોકાણ થતું નથી. ૧૧ કરોડનું જ મૂડીરોકાણ થયું છે ત્યારે મધ્યમ અને લઘુઉદ્યોગ જે ગુજરાતને ધમધમતું રાખતો હતો એનો પણ તમે સર્વનાશ નોતર્યો છે. એ મારે આ તબકકે કહેવું છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં આ સરકારે ખેડૂતોની, ખેત-મજૂરોની, પશુપાલકોની, માલધારીઓની, આ રાજ્યના ૧૦ લાખ કર્મચારીઓના વેતનની કે ૧૦ લાખ કર્મચારીઓની સુખાકારીની કોઈની ચિંતા કરી નથી અને આ રાજ્યની બહાર વસતા ૫-૧૦ હજાર એન.આર.આઈ.ની ચિંતા કરી છે. આ દુ:ખદ ઘટના છે. એન.આર.આઈ.ની પણ ચિંતા થવી જોઈએ. વિશ્વમાંથી મુડીરોકાણ આવતું હોય તો આપણે એને વધાવવા જોઈએ, પણ ગુજરાતની પ્રજા રાજ્યનું અંગ છે એવા ખેડૂતો અને ખેત-મજૂરો, કર્મચારીઓ, શ્રમિક સંગઠનો, શ્રમિક લોકો, માલધારીઓ આ બધા લોકોને ભૂલીને એમના પૈસાથી તાગડધિન્ના કરીને કે તમાશાઓ યોજીને નહીં. આ વાત તમારે સમજવી જોઈએ. હમણા ખેડૂતોની વાત ચાલતી હતી, કોટન કોરપોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાની વાત ચાલતી હતી, ભારત સરકારના ટેકાના ભાવની વાત ચાલતી હતી, ટેકાના ભાવો એ તો ભારત સરકાર વર્ષો વર્ષ બાંધે છે, એના નીતિ નિયમો છે. નીતિ નિયમો ખોટા હોય તો ચેલેન્જ કરો અને ભારત સરકારે સી.સી.આઈ.એ એના ભાવો બાંધ્યા છે ૧૯૬૦ રૂપિયા ત્યારે તમારે શું કરવું જોઈએ? ભારત સરકારે શું કરવું જોઈએ? બીજાએ શું કરવું જોઈએ એનો નહીં પણ રાજ્ય સરકારે શું કરવું જોઈએ એનો કોઈ દિવસ ખ્યાલ કર્યો છે ખરો ખેડૂતો માટે? આજે મહારાષ્ટ્રની સરકાર કોંગ્રસ સરકાર છે ત્યાં ૨૫૦૦ રૂપિયાના ભાવે ક્વિન્ટલના ભાવ આપીને ખરીદે છે. ૧૯૬૦ની સામે દર કવીન્ટલે ૬૦૦ રૂપિયાની ખાદ્ય રાજ્ય સરકાર ભોગવે છે અને આજે ૧ હજાર કરોડ રૂપિયાની ખાદ્ય મહારાષ્ટ્રની સરકાર એમના ખેડૂતો માટે ભોગવે છે. છે તમારી છે એ તૈયારી? જયારે શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારે ૧૦૦ કરોડ રૂપિયાની ખાદ્ય ભોગવી હતી,

કેશુભાઈની સરકારે ૨૪ કરોડ રૂપિયાની ખાદ્ય ભોગવી હતી ત્યારે આજે એક રૂપિયો પણ તમે આપવા તૈયાર છો? ના, અને ખેડૂતોની વાત લઈને નિકળ્યા છો ? ખેડૂત સંગઠનોની વાત લઈને નીકળ્યા છો? ખાલી ભાષણો કરવાથી, ખાલી બોલવાથી, સુત્રચારો કરવાથી, શબ્દોની માયાજાળ રચવાથી આ ખેડૂતોનું હિત થવાનું નથી. ખેડૂતોના હિત માટે તો પાયાની વાત લઈને, વિકાસની વાત લઈને, ગામડાં સુધી પહોંચવાની વાત લઈને તમારે આગળ વધવું પડશે અને આવી વાત હશે તો ચોકકસ અમારો પક્ષ તમારા માટે બલિદાનો પણ આપશે. બલિદાન શબ્દ એટલા માટે વાપરું છું કે, કોંગ્રેસ પક્ષે બલિદાનો આપ્યાં છે અને બલિદાનોની પરંપરા છે. (અંતરાય) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ હતી ખેડૂતોની વાત, આ હતી ખેત મજૂરોની વાત.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજય અસ્તિત્વમાં આવ્યું ત્યારથી ગુજરાત રાજ્યમાં કોંગ્રેસની જે સરકારો આવી એ સરકારો આયોજનબદ્ધ વિકાસની ગાથાઓ લઈને નીકળી હતી. નર્મદા ડેમ પર સરદાર સરોવર યોજના દાખલ થતી હોય, ક્યાંક તાપી નદી પર ઉકાઈ ડેમની યોજના દાખલ થતી હોય, મહી નદી પર કડાણા ડેમની યોજના દાખલ થતી હોય, ક્યાંક સિપુ ડેમ, ક્યાંક મુકતેશ્વર ડેમ, ક્યાંક મેશ્વો ડેમ, ક્યાંક સરસ્વતી નદી ઉપર ડેમ બનતેા હોય, આ ડેમો બન્યા કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે વર્ષો સુધી બસ્સો-ત્રણસો વર્ષનું આયોજન ગુજરાતની સરકારે કર્યુ, અમે કોઈ દિવસ ખેડૂતોના પૈસે ક્યાંક એવા તમાશાઓ, રેલીઓ કે મહારેલીઓ કે પ્રસંગો યોજ્યા નહોતા અને તમે ખેતતલાવડી ખોદી એમાં ઢોલ, નગારાં, ત્રાંસા સાથે નીકળી પડ્યા છો ગામેગામ, વાંધો નથી, સારું કામ છે, અમે ખોટું નથી કહેતા, પણ આ એક કામ છે, સરકારનો એક ભાગ છે, જેના ભાગમાં જે કામ આવ્યું હોય તે કરવું પડે. અમે ડેમનું આયોજન કર્યુ, તમે પાણી વિતરણનું આયોજન કરો, અમે જી.ઈ. બોર્ડનાં પાવર સ્ટેશનો બનાવ્યાં, મોટા મોટા પાવર સ્ટેશનો બનાવ્યાં, ૨૩૨ કે.વી., ૧૩૨ કે.વી., ૬૬ કે.વી. ના પાવર સ્ટેશનો અમે બનાવ્યાં અને તમે એની વિતરણ વ્યવસ્થા કરો. અમે શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને સંકુલો બનાવ્યાં તમે એમાં ભણાવવા માટેનું આયોજન કરો. તમારા ભાગમાં જે આવ્યું છે તે તમે કરો. એમાં શાના માટે તમે ખેલ અને તમાશા કરો છો અને જે કંઈ સારા કામો કરો છો એની હંમેશાં અમે પ્રશંસા કરી છે. આટલું મોટું પાટનગર બનાવ્યું, આટલાં બધાં સંકુલો ઉભાં થયાં, આખું સચિવાલય ઉભું થયું આખા પાટનગરમાં મોટાં મોટાં ભવનો કૃષિભવન, પશુપાલનભવન, નર્મદાભવન ઉભાં થયાં, પણ અમે કોઈ દિવસ ઉદ્‌ઘાટનો કર્યા નહોતા અને તમે ચાર ફુવારા બનાવ્યા એમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી ઉદ્‌ઘાટન કરવા જાય? કોઈ સારા ડેમ બનાવ્યા હોય, સારાં વિદ્યુત મથક બનાવ્યાં હોય એમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી જાય તો અમારી છાતી ગજગજ ફૂલે, પણ ચાર ફુવારામાં? હા અમે અભિનંદન ચોક્કસ આપીએ છીએ કે ચાર ફુવારા પણ તમે બનાવ્યા, આજે તમને આપવાની ટેવ પડી છે, ધૂળ આપી દો, ધૂળ આજે આપવાની ટેવ પડી છે, કાલે પૈસા કે દાન કરવાની ટેવ પડશે એ પણ અમે સ્વીકારીએ છીએ, પણ તમે જે કોઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છો તો એમાં બ્રેક મારીને કોઈએ કહેવું પડશે અને આટલા બધા સિનિયર નેતાઓમાંથી કોઈએ ગાઈડલાઈન કે દિશા આપવી પડશે, નહિ તો ભીષ્મ પિતામહની જેમ જો ચૂપ બેસી રહેશો તો જ્યારે ગુજરાતની પ્રજાનો ઉકળાટ ઉકળશે ત્યારે વજુભાઈ વાળા સાહેબ, ભીષ્મ પિતામહને બાણશૈયા પર ઉંઘવું પડ્યું હતું એમ તમારે બધાએ પણ ઉંઘવાનો વારો આવશે. એટલા માટે હું તમને કહું છું કે આ ગુજરાતની પ્રજા માટે ગુજરાતના ખેડૂતો માટે, ખેતમજૂરો માટે ગુજરાતના કર્મચારીઓ માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આપ ચૂપ ન બેસી રહેતા, સાચી દિશા આપવાની વાત કરો તો જ સાચા અર્થમાં કર્મચારીઓ અને આપણે બધા જ કર્મયોગી બનીશું, બાકી કાગળ ઉપર કોઈ ચાર ભાષણ આપવાથી કર્મયોગી થવાશે નહિ અને ગુજરાતનું અહિત થશે એટલા માટે જે જે મુદ્દા ઉપસ્થિત થયા છે અને જે દિશામાં આપ આગળ વધવા માગો છો એમાં ક્યાંક વિકાસની વાત હશે તો કોંગ્રેસ પાર્ટી ચોક્કસ તમારી સાથે ઉભી રહેશે. તમે જૂઓ પેપરના નિવેદનો વાંચો, પ્રેસનોટો વાંચો, અમારા કરતાં તમારા લોકો વધારે બૂમો પાડે છે, ખેડૂત રેલી લઈને તમે આવવાના છો દરવાજા તમે તોડવાના છો પણ અમે તો ખેડૂતોની વાત લઈને આવીએ છીએ કે તમારે આમ કરવું જોઈએ, સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બધાની વધે એમાં આપણે બધાએ સાથે થઈને આગળ વધવું જોઈએ એટલી વિનંતી સાથે વિરમું છું.

શ્રી ભૂપેન્દ્ર ગ. લાખાવાલા (વડોદરા શહેર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન પર આભાર પ્રસ્તાવ લઈને માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી આવ્યા છે અને એમાં માનનીય સભ્યશ્રી પ્રબોધકાંત પંડ્યાએ ટેકો આપ્યો છે જેને હું પણ મારું સમર્થન આપું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નામદાર રાજ્યપાલશ્રીએ જ્યારે આ ગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો અને ત્યારપછી એમણે જે ઉદ્‌બોધન શરૂ કર્યુ તે વખતે હું ઓબ્ઝર્વ કરતો હતો કે જે કંઈ સરકારના વિચારો છે, પછી એ જળશક્તિ હોય, ઉર્જાશક્તિ હોય, રક્ષાશક્તિ હોય એ એમણે આ ગૃહ સમક્ષ મૂક્યા છે. સત્તાધારી પક્ષ તરફથી એ વિચારો જ્યારે એમણે અહીંયાં મૂક્યા ત્યારે એમને આવકારવામાં આવતા હતા સામેપક્ષે જે રીતે એમના હાવભાવ હું જોતો હતો એ એમને ગમ્યા નહિ. ગુજરાતનો વિકાસ થતો હોય એ એમને ન ગમે? એ મને સમજણ પડતી નથી. રાજ્યપાલશ્રીએ રાજ્યના વિકાસની જે આગેકૂચ છે એની વાત કરી છે એમાંય ખાસ કરીને રાજ્યની જે મુખ્ય

જીવાદારી છે નર્મદા ડેમની યોજના, એની શરૂઆત પચાસ વર્ષ પહેલાં કરી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલએ જયારે એનો વિચાર મૂક્યો અને એનો અમલ થતાં થતાં આજે પચાસ વર્ષ પૂરાં થયાં. આ નર્મદા ડેમની જે ગાથા છે એમાં નોડાઉટ મોરારજીભાઈ દેસાઈ હોય, બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલ હોય, ચીમનભાઈ પટેલ હોય, બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલની સરકારમાં તે વખતે નર્મદાના મંત્રી શ્રી કેશુભાઈ પટેલ હતા. કેશુભાઈ પટેલ હતા અને આજે આપણાં મુખ્યમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે રીતે તેને પ્રોત્સાહિત કરી છે આખી યોજનાને અને તેને કારણે જે ૯૦ મિટરથી ૧૧૦ મિટરની હાઈટે આપણે નર્મદા ડેમને જોઈ શકીએ છીએ અને તે ડેમ દ્વારા જે મોટી કેનાલોમાં પાણી વહી રહ્યું છે અને તેને કારણે ગુજરાતના ખેડૂતોને પાણી મળે છે તેનો યશ આ બધાને જાય છે. હું એ કહીશ કે આ નર્મદા ડેમ પાછળ જે કૉંક્રિટ વપરાયું છે તે કૉંક્રિટ ૯૩ લાખ ઘન મિટર જેટલું કૉંક્રિટ વપરાયું છે અને તેને કારણે આ ડેમ પૂરો થયો છે. આમ તો ૯૩ ટકા જેટલો આ ડેમ પૂરો થયો છે અને તેમાં એવું કહી શકાય કે પૃથ્વીને ફરતે જો કૉંક્રિટનો રોડ બનાવવામાં આવે એટલું કૉંક્રિટ આ ડેમમાં વપરાયું છે. ટોટલ ડેમનું કામ આમ જોવા જઈએ તો ૧૧૦ મિટરની હાઈટ પૂરી થઈ છે. ૧૨૧ મિટરની હાઈટની મંજૂરી મળી છે. પર્યાવરણ અને સાથે સાથે પુનઃવસનની સંમતિ મળશે એટલે તે પણ કામગીરી આગળ વધશે અને તેને કારણે જે ડેમની હાઈટ ૧૨૧ મિટર જેટલી થશે. ૯૩ ટકા કામ પૂરું થયુ છે. તે ડેમ માટે જે કેબલ વાપરવામાં આવ્યો છે તે કેબલ ક્રેઈન કહીએ તેની ૧.૫ કિલોમિટરની લંબાઈ છે. એટલે ૧ મિટરની લંબાઈથી તે કૉંક્રિટ જે ડેમ ઉપર નાખવામાં આવે છે તે કેબલ ક્રેઈન ૧૯૮૭માં જર્મનીથી લાવવામાં આવ્યો હતો. આ આપણી જે નર્મદા કેનાલ છે તેની ૫૩૨ કિલોમિટરની વહન શકિત ૪૦ હજાર ક્યુબિક મિટર પર સેકન્ડ છે. એટલે કે સાદી ભાષામાં કહીએ તો ૨૪ કલાકમાં ૧૦ હજાર કરોડ લિટર પાણી આ કેનાલ દ્વારા વહેવડાવવામાં આવે છે. તેની બ્રાન્ચ કેનાલો ૪૨ જેટલી નીકળે છે અને ટોટલ બધી લંબાઈ કહીએ તો ૨૫૦૦ કિલોમિટરની કેનાલોની લંબાઈઓ છે. એક વાત કહીશ કે મુખ્ય કેનાલ, બ્રાન્ચ કેનાલ, પેટા કેનાલનું જે નૅટવર્ક છે એવું કહેવામાં આવે છે કે આ ૬૬ હજાર કિલોમિટરનું છે. દેશની જે ઇન્ડિયન રેલવે છે તેનું નૅટવર્ક ૬૩ હજાર કિલોમિટરનું છે. કહેવાનો આશય એ છે કે, સરદાર સરોવર કેનાલ આધારિત જે બલ્ક પાઈપ લાઈન પણ જે નાખવામાં આવી રહી છે તે ૧૩૪૩ કિલોમિટરની લંબાઈની પાઈપ લાઈન નાખવામાં આવી છે અને તેમાં ૩૧ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું નૅટવર્ક પૂરું કરવામાં આવ્યું છે. ૩૬૦૦ ગામોને તેનાથી પાણી મળવાનું છે. જે કહેવામાં આવ્યું સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના ૬૨૩૭ કરોડ રૂપિયાની આ યોજના છે અને એ કામ પૂરું થવાને કારણે કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના જે ગામો છે જ્યાં આગળ પાણીની ખેંચ છે અને જ્યાં આગળ ફલોરાઈડવાળું પાણી મળે છે, પાણીનાં તળ નીચાં ગયાં છે તે ગામોમાં પાણી વહેવડાવવાને કારણે તળ ઉંચાં આવશે અને તેને કારણે જે ચોખ્ખા પાણીની બૂમ છે તે આ વિસ્તારમાં દૂર થશે. કલ્પસર પ્રોજેકટ પણ હમણાં જ કહ્યું તે પ્રમાણે તેનો પ્રિફિઝિબીલીટી રિપોર્ટ ઓલરેડી તૈયાર થવાની અણીમાં છે. ૫૦ હજારથી ૫૫ હજાર કરોડ રૂપિયા આ યોજના ખંભાતના અખાતથી ભાવનગરની આ યોજના છે અને તેનો જે રીતે રિપોર્ટ તૈયાર થયો છે તેમાં જે પાળો બાંધવામાં આવશે અને તે પછી દરિયાઈ મોજા જે ખંભાત પાસે આવે છે તે ૧૨ મિટર ઉંચા જે મોજા છે તેને કેવી રીતે રોકવા અને પાળો બાંધ્યા પછી મીઠું પાણી ત્યાં ભરવામાં આવશે અને ખારું પાણી જે ફોર્સ છે તે કેટલો ઓછો થાય તે માટેનો પ્રિફિઝિબિલીટી રિપોર્ટ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. પાણીની ઉપલબ્ધતા કેટલી રહેશે, પાળો બાંધ્યા પછી પર્યાવરણ ઉપર શું અસર થશે, ખંભાતના કાંઠાના વિસ્તારમાં ભૌગોલિક અસરો શું થશે તે આ બધીજ શકયતાઓ તપાસવામાં આવી રહી છે. દરિયાઈ પાણી ક્ષાર સંતુલિત અંગેનો અભ્યાસ પણ તેમાં કરવામાં આવશે અને વિદ્યુત ગૃહમાં ભરતી ઓટથી ઉત્પાદિત વીજળીની વહનની ક્ષમતાનો પણ આમાં વપરાશનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

સભાગૃહની પ્રથમ બેઠકનું કામકાજ બપોરના ૧-૦૦ કલાકે પૂરું થતાં અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર સભાગૃહ બીજી બેઠક માટે બપોરના ૨-૩૦ કલાકે ફરી મળવા મુલતવી રહ્યું.

ગુજરાત વિધાનસભા
મંગળવાર, તા.૨૨ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫
ફાલ્ગુન ૩, ૧૯૨૬ શાકે
બીજી બેઠક
સભાગૃહ બપોરના ૨-૩૦ વાગ્યે મળ્યું.
અધ્યક્ષશ્રી પ્રો.મંગળભાઈ પટેલ અધ્યક્ષસ્થાને

તારાંકિત પ્રશ્નો

ગુડાની વિકાસ યોજનાઓ

***૯૫૨૪ શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ (વાઘોડિયા)**: માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

(૧) ગાંધીનગર શહેર માટેની ગુડાની વિકાસ યોજના કયારે મંજૂર થઈ, અને
(૨) ગુડાની વિકાસ યોજનાની મુખ્ય જોગવાઈઓ કઈ કઈ છે?

શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી:

(૧) તારીખ ૧૬-૨-૨૦૪ ના રોજ.
(૨)
---રહેણાંક ઝોન-૧ થી રહેણાંક-૫, વાણિજય ઝોન-૧ થી વાણિજય-૩ અને ઈન્સ્ટિટયુશનલ ઝોન સૂચવેલ છે.
---ન્યુકલીઅસ વિલેજ માટે ૧.૨૫ જયારે જી.એન.એ.ની નજીકના વિસ્તાર માટે ૧.૮ એફ.એસ.આઈ. સૂચવેલ છે.
---જુદા જુદા સેકટરોનો વિકાસ પાટનગરનો હાર્દ જળવાય તેમ તેને અનુરૂપ વિકાસ નિયંત્રણ વિનિયમો બનાવેલ છે.
---જી.આઈ.ડી.સી. વિસ્તારને જી.આઈ.ડી.સી. એસ્ટેટ તરીકે મુકરર છે.
---ફલોરવાઈઝ ભોગવટા પ્રમાણપત્ર (બિલ્ડીંગ યુઝ સર્ટિફિકેટ) આપવાની જોગવાઈ કરેલ છે.
---પાર્કિંગમાં આગળના ભાગે ૧૦% વિઝિટર્સ-પાર્કિંગ રાખેલ છે.
---વિકાસ નિયંત્રણ વિનિયમોના અર્થઘટન માટે અપીલ કમિટીની રચના કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે ગુડા વિસ્તારમાં કેટલી નગર રચના બનાવી અને એ કઈ કઈ યોજનાનું આયોજન છે અને કેટલા સમયમાં બનાવવા માગો છો?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુડાની વિકાસ યોજના પહેલી વખત જાહેર કરવામાં આવી છે અને એ વિકાસ યોજના પહેલી વખત જાહેર કર્યા પછી ન્યુ કલીઅસ સીટી અને બાકીના કન્સેપ્ટ સાથેનો વિચાર પણ આ વિકાસ યોજનામાં કરવામાં આવ્યો છે અને એજ પ્રમાણે વિવિધ નગર રચના યોજના બનાવવાનો પણ વિચાર ગુડા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. લગભગ ૧૯ જેટલી નગર રચના યોજનાઓ ગુડા વિસ્તારમાં હાથ ધરવાની છે અને આ ૧૯ જેટલી નગર રચના યોજનાઓ નોટીફાઈડ એરીયા બહાર ન્યુ કલીઅસ વિસ્તારમાં જે સીટી નકકી કરેલ છે તેમાં અને ગુડા વિસ્તારનાં અન્ય ગામોમાં હાથ ધરવાની છે.

ડૉ. સી. જે. ચાવડા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ ગુડા વિકાસ યોજના અમલમાં મૂકી છે એ ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે, પરંતુ સાથે સાથે ચાલુ વર્ષે આ વિકાસ યોજનામાં ખાસ કરીને ગુડા વિસ્તારના ગામોમાં કઈ રીતે એનો અમલ કરવા માગે છે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુડાની વિકાસ યોજના પ્રથમ એવી એક વિકાસ યોજના છે કે જે જાહેર કરતી વખતે જ ગુડાના વિસ્તારમાં નોટીફાય વિસ્તારની બહાર ગુડાના વિસ્તારમાં કયા પ્રકારની વિકાસ યોજનાઓ રહેશે એની જાહેરાત પણ સાથોસાથ કરવામાં આવેલ છે. ગાંધીનગર નોટીફાય વિસ્તારમાં આર.એન્ડ બી. દ્વારા વિકાસ કામો હાથ ધરાય છે, પરંતુ જયારે ૧૯ જેટલી નગર વિકાસ રચના યોજનાઓ જાહેર થતી હોય અને એ સ્વરૂપમાં ગાંધીનગર એ રાજયનું કેપિટલ અને સરાઉન્ડીંગ વિસ્તારમાં વ્યવસ્થિત રીતે એનો વિકાસ થાય એ માટે વિવિધ જોગવાઈઓ હાથ ધરેલ છે. વિવિધ વિકાસનાં કામો જેવાં કે, પાકા રસ્તા, દીવાબત્તી, પાણી પુરવઠો, ગટર વ્યવસ્થા, સ્ટ્રોંગ વોટર ડ્રેનેજ, ખુલ્લી જગ્યાનો વિકાસ, હેરીટેજ અને પ્રવાસનને લગતો વિકાસ, ગામ તળાવોનો વિકાસ, ઘન કચરાનો નિકાલ, સામાજીક અને આર્થિક રીતે

નબળા વર્ગના લોકોને માટે રહેઠાણ બનાવવાનું આયોજન હાથ ધરાયું છે અને આ બધા જ આયોજનને યોગ્ય સ્વરૂપ અપાય એ પ્રકારની વિવિધ નગર રચના યોજનામાં પણ વ્યવસ્થા ઉભી કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

શ્રી પ્રદિપસિંહ ભ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવું છે કે ગાંધીનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટીમાં કયા કયા પ્રકારનાં કામો હાથ ધરવામાં આવશે અને ઉપરાંત આમાં નોન પોલ્યુટિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ માટે કોઈ અલગ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં હમણાં જેમ કહ્યું તે મુજબના વિવિધ કામોનું ચોક્કસપણે આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સાથો સાથ જેનો શહેરની અંદર સમાવેશ થાય છે તેમાં રહેઠાણ માટે અને કોમર્શિયલ માટેના અલગ અલગ ઝોન નક્કી કરવામાં આવેલા છે. એ જ રીતે જી.આઈ.ડી.સી.ને બે ભાગમાં વહેંચીને જી.આઈ.ડી.સી. નોટિફાઈડ એરિયા ડિકલેર કરીને નોન પોલ્યુટેડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ માટેનો વિસ્તાર પણ નિયત કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી સુનીલ બા. ઓઝા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૨૦૦૧ની સેન્સસ પ્રમાણે ગુડાનું પોપ્યુલેશન કેટલું છે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : ૨૦૦૧ની દૃષ્ટિએ ગુડાની કુલ વસતિ, જી.એન.એ. વિસ્તારમાં ૧,૯૬,૯૨૨ છે, ન્યુકલીયસ ગામોની ૫૫,૧૮૨ અને ગુડાના બાકી રહેલા ગામોની ૧,૨૯,૭૧૫ની વસતિ છે, એટલે કુલ ૩,૮૧,૮૨૨ની વસતિ ૨૦૦૧ની દૃષ્ટિએ પ્રસ્થાપિત થયેલ છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : હું એ જાણવા માગું છું કે ગુડાના વિકાસ માટે કુલ કેટલો ખર્ચ કરવાનો અંદાજ રાખવામાં આવેલ છે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : વિવિધ વિકાસના કામો હાથ ધરીને લગભગ ૪૦૦ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ હાથ ધરવાનું આયોજન ગુડા વિસ્તારના વિકાસ માટે કરેલ છે.

શ્રી ભરત બારોટ : ગાંધીનગર નોટિફાઈડ એરિયા આખા દેશમાં ગ્રીન સીટી તરીકે જાણીતો છે, તો આ ગુડાને પણ એ રીતે પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ જાણીતો કરવા માટે શહેરી વિકાસ વિભાગે નક્કી કર્યુ છે ખરું?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગાંધીનગર અત્યારે સૌથી વધારે ગ્રીનેસ્ટ કેપિટલમાંનું એક સીટી રહેલ છે. માનનીય સભ્યશ્રીની લાગણી છે તે મુજબ ગાંધીનગરના ગુડા વિસ્તારનો વન વિસ્તાર ૧૪૨૨૩.૫૧ હેકટર જેટલો રહેલ છે. એટલે જે એરિયા રહેલો છે એમાંના ૨૫ ટકા જેટલો વિસ્તાર વન વિભાગ હેઠળ એટલે કે વન વિસ્તરણ હેઠળ રહેલ છે. તેની સાથે સાથે હમણાં જ માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ શહેરી વિકાસ વર્ષની જ્યારે ઘોષણા કરી છે તે સમયે વિચાર મૂકેલ છે કે ગાંધીનગરને સોલાર સીટી બનાવવું. તેથી તેના સ્વરૂપમાં અને જુદા જુદા આયોજનના સ્વરૂપમાં ગાંધીનગરના વિકાસની યોજનામાં પર્યાવરણનો વિચાર અવશ્યપણે હાથ ધરાયેલ છે.

ડૉ. અતુલ કે. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એ પૂછવું છે કે ગુડામાં આંતરમાળખાકીય સુવિધા માટે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જયારે ગુડા વિસ્તારમાં ૧૯ જેટલી નગર રચનાઓનું આયોજન હાથ ધરવાનું છે અને એમાં લગભગ જે પ્રકારે મેં કહેલું છે તે મુજબ રસ્તા, ડ્રેનેજ, સુએજ વોટર, પીવાનું પાણી, ઘન કચરાનો નિકાલ, વગેરે માટે ૪૦૦ કરોડ રૂપિયાના કામો હાથ ધરવાના છે ત્યારે પ્રાથમિક તબક્કે ગાંધીનગર નોટિફાઈડ વિસ્તાર બહાર ટી.પી. સ્કીમમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધા આપવા માટેનો વિચાર ચાલી રહયો છે, એના માટે ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપનીને કન્સલ્ટન્ટ તરીકે નિમણૂક આપેલ છે અને ગુડકોએ આ પ્રકારની પ્રાઈમરી કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.

શ્રી નારાયણભાઈ લ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજ્યમાં જ્યાં જ્યાં ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમો થઈ છે ત્યાં નિયત સમયમાં થતી નથી, તો ગાંધીનગરમાં કેટલા ટાઈમમાં તમે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ કરી શકો તેમ છો?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય સભ્યશ્રીએ જે લાગણી વ્યકત કરી છે તે મુજબ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ ચોક્કસ સમય મર્યાદામાં બનાવવી જોઈએ. પણ મને એ કહેતા આનંદ થાય છે કે છેલ્લા બે થી અઢી વર્ષમાં લગભગ ૯૦ જેટલી જુદી જુદી નગર રચના યોજનાઓને મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે. આમ છતાં જયારે રાજય સરકારે અને સમગ્ર રાજયના લોકોએ શહેરી વિકાસ વર્ષ ૨૦૦૫ ઉજવવાનું નકકી કરેલ છે એવા તબક્કે આ નગર રચના યોજના આગામી દિવસોમાં કોમ્પીટેશન, કોન્ટ્રાકટ અને અન્ય કન્સલ્ટન્ટ પદ્ધતિ દ્વારા નગર રચના બનાવવાના કાર્યમાં ઝડપ આવે અને ખૂબ સત્વરે ટૂંકા ગાળામાં નગર રચના યોજનાઓ બની શકે તે પ્રકારનું આયોજન હાથ ધરાયેલ છે. ૧૯ નગર રચનાઓ ગાંધીનગર ગુડા વિસ્તારમાં બનવાની છે એની પણ તબક્કાવાર કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલ છે.

માંગરોળ તાલુકાનો ઘોડાદર-મંડેર ચિગોરીયા રસ્તો બિસમાર હોવા બાબત

***૮૫૮૬ ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા (માંગરોળ)**: માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાનો ઘેડ વિસ્તારના મહત્ત્વના બે તાલુકાને જોડતો અને દ ાોડાદરા-મંડેર ચિગોરીયા રસ્તો બિસમાર છે તે હકીકત સરકાર જાણે છે, અને
(૨) જો હા, તો સરકાર આ રસ્તો કયાં સુધીમાં રિપેર કરવા માગે છે?

માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી:

(૧) અને (૨) રસ્તો વાહનવ્યવહાર યોગ્ય છે. આ રસ્તાના ૩.૦૦ કિલોમીટર લંબાઈમાં રીસરફેસીંગનું કામ મંજૂર થયેલ છે. જે ટૂંક સમયમાં હાથ ધરી પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : મેં જે રસ્તાની વાત કરી એ રસ્તો વાહનવ્યવહાર યોગ્ય નથી તેમ છતાં મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું છે કે વાહનવ્યવહાર યોગ્ય છે. આ રસ્તો માંગરોળ તાલુકો અને પોરબંદર તાલુકો એમ બંને તાલુકાને જોડતો અતિ મહત્ત્વનો રસ્તો છે. જે ખરેખર બિસમાર હાલતમાં છે. આ ઘેડ વિસ્તારનો રસ્તો છે. એ લોકોને માંગરોળ અથવા તો પોરબંદર હૉસ્પિટલમાં આવવું હોય તો આ રસ્તા ઉપર થઈને જ આવવું પડે છે જે અતિ બિસમાર હાલતમાં છે. આ રસ્તાનું ત્રણ કિલોમીટરનું કામ ક્યારે મંજૂર થયું, ક્યારે એ કામ શરૂ થશે? જે બાકીનું ઘોડાદર-મંડેર રસ્તાનું કામ છે એ કામ એ.ડી.બી.માં મૂકીને પ્રાયોરિટી આપીને આગળની કાર્યવાહી કરશો તો બિસમાર રસ્તો છે એ વાહનવ્યવહાર યોગ્ય થશે. આપ કહો છો કે આ રસ્તો વાહનવ્યવહાર યોગ્ય છે તો આપણે આ રસ્તા ઉપર જઈએ અને જો આપને યોગ્ય લાગે તો એમાં કંઈ કરવું નથી અને જો લાગે તો તાત્કાલિક ધોરણે મંજૂર કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : બહેનની રસ્તાની લાગણી ઘોડાદર-મંડેર ચિગોરીયા કુલ ૮.૩૫ કિલોમીટરનો રસ્તો છે. એમાં જે રસ્તાની મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે એ ૧૭.૪૨ લાખના ખર્ચે મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. એની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે. માર્ચ, ૨૦૦૫ સુધીમાં ૩.૭૫ કિલોમીટરનું કામ પૂર્ણ થશે. બીજું કામ એમણે કહ્યું છે એ રસ્તો પંચાયત હસ્તકનો રસ્તો છે. એ રસ્તામાં ઘોડાદર-મંડેર રસ્તા ઉપર લગભગ ૫.૫૦ લાખના ખર્ચે વેન્ટેડ કૉઝવે અને ડીપનું કામ ચાલુ કરાયેલ છે. બહેનની વાત રી-કારપૅટ કરવાનો લાંબા સમયથી બાકી છે. આ વરસે જે પ્રકારે રાજય સરકારે રસ્તાને પ્રાધાન્ય આપીને વિવિધ જોગવાઈઓ હાથ ધરેલ છે એ બાબતમાં નીતિ વિષયક બાબત છે એમાં વિચારણા કરીને ચોક્કસ હકારાત્મક રીતે ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

કડી તાલુકામાં જોબ નંબરો

***૮૯૯૫શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર(કડી)** : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કડી તાલુકામાં કેટલા અને કયા કયા રસ્તાઓના જોબ નંબર ફાળવવામાં આવ્યા,
(૨) કેટલા રસ્તાઓના કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યા,
(૩) કેટલા રસ્તાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું, અને
(૪) બાકીના રસ્તાઓનું કામ ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે?

માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી:

(૧) પત્રક-૧ મુજબ ૧૯ રસ્તાના જોબ નંબર ફાળવવામાં આવેલ છે.
(૨) ૧૫ રસ્તા.
(૩) ૧૫ રસ્તા.
(૪) સને ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન.

પત્રક-૧

તારીખ: ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કડી તાલુકાના જોબ નંબર ફાળવેલ રસ્તાની યાદી.

(૧) થોળ-ઝાલોડા રસ્તો
(૨) નદાણ એપ્રોચ રસ્તો
(૩) સીયાપુર-દુધઈ રસ્તો
(૪) લ્હોર એપ્રોચ રસ્તો
(૫) ફતેપુરા એપ્રોચ રસ્તો
(૬) નંદાસણ-માથાસુર રસ્તો
(૭) બપૈયારા એપ્રોચ રોડ
(૮) પંઢરપુરા-ચુનીપુરા રોડ
(૯) મહારાજપુરા એપ્રોચ રોડ પર નાળાકામ

(૧૦) આલુસણા એપ્રોચ રોડ પર નાળાકામ
(૧૧) થોળ-મેઢા-આગોલ એપ્રોચરોડ પર નાળાકામ
(૧૨) ઝાલોડા-બપૈયારા રસ્તો
(૧૩) ડરણ-મોરવા રોડ
(૧૪) કડી-થોળ-સાણંદ રસ્તો
(૧૫) કડી-કલ્યાણપુરા રસ્તો
(૧૬) કડી-કલ્યાણપુરા રસ્તો નાળાકામ
(૧૭) કડી-ધોરીયા રસ્તો પાઈપ ડ્રેઈન કામ
(૧૮) શેડફા-ભીમાસણ રોડ પાઈપ ડ્રેઈન કામ
(૧૯) કડી-કલ્યાણપુરા રોડ સ્પીલ સેકશન

શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગુ છું કે કડી તાલુકામાં ખાખરીયા વિસ્તારમાં આવેલો આ મહત્ત્વનો રસ્તો છે. નાની કડી -બાવલુ અને ચંદ્રાસર રસ્તાનો જોબ નંબર કયા વર્ષમાં આપવામાં આવેલ. એનું કામ કરવાનું એગ્રીમૅન્ટ ક્યારે આપવામાં આવ્યું અને કામ પૂર્ણ કરવાનું છેલ્લુ વર્ષ ક્યું હતું?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : એમનો મૂળ પ્રશ્ન જે અપાયેલ ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ જોબ નંબરનો પ્રશ્ન છે. એમાંથી ૧૫ રસ્તાના કામો પૂર્ણ થયેલ છે. ચાર રસ્તાના કામો બાકી છે પરંતુ એ સિવાય માનનીય સભ્યશ્રીએ એમના વિસ્તારના એક રસ્તાની માહિતી માગી છે. એ રસ્તાની માહિતી હું આપુ છું અને કહેવા માગું છું કે આ રસ્તાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે, વહેલામાં વહેલી તકે એ કાર્ય પૂર્ણ થશે.

શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર : આ પ્રશ્ન લખેલો પરંતુ એમની ભૂલને કારણે આવેલ નથી. મારો પ્રશ્ન એ છે કે કયા વર્ષની અંદર જોબ નંબર આપવામાં આવેલ. એનું એગ્રીમૅન્ટ ક્યારે કરવામાં આવ્યું અને કામ પૂર્ણ કરવાનું વર્ષ કયું?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : કોઈ ભૂલને કારણે પ્રશ્ન ન આવ્યો હોય તેવું બને નહિ. તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા રસ્તાના જોબ નંબર આપ્યા એમાંથી ભૌતિક રીતે કેટલા પૂર્ણ થયા? વે તમે જે કહો છો એ માહિતી જોઈતી હોય તો આપવા તૈયાર છું. જે તમારો રસ્તો છે, ૨૮ કિલોમીટરનો રસ્તો છે. ૨,૭૫,૮૫,૯૦૦ રૂપિયાની અંદાજીત રકમ છે. બાકીની ટેન્ડરની કાર્યવાહી પૂરી થઈ ગઈ છે અને કામ શરૂ કરવાની તારીખ ૧૬-૫-૨૦૦૨ છે. કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ ૧૫-૧૧-૨૦૦૩ છે પરંતુ આ સભાગૃહને જણાવવા માગું છું કે નાબાર્ડ યોજનાના જે પ્રકારના કામો હાથ ધરાયા, બધા જ સભ્યશ્રીઓ એ વાતથી વાકેફ છે કે ૨૭ જેટલા એવા રસ્તાઓ હતા કે જે નાબાર્ડની ગ્રાન્ટની અનુકૂળતાને કારણે પેન્ડીંગ રહેલા હતા. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ૨૭ રસ્તાની મંજૂરી આપી છે. તમામ કામ શરૂ થઈ ગયા છે. જે રસ્તાનો સભ્યશ્રી ઉલ્લેખ કરે છે એ કામ પણ શરૂ થઈ ગયું છે. નિશ્ચિત સમયમર્યાદામાં ડિસૅમ્બર-૨૦૦૫ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

શ્રી નારાયણભાઈ લ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માલજીભાઈ હાજર નથી. આ અગત્યનો પ્રશ્ન હોઈ આપ મંજૂરી આપો.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : મંજૂરી છે. વાંધો નહીં.

અધ્યક્ષશ્રી : મંજૂરી આપવામાં આવે છે.

રાજયમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું ઓછું પ્રમાણ

***૯૪૮૯શ્રી માલજીભાઈ દે. દેસાઈ (ચાણસ્મા)**: માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) રાજયમાં નવા જન્મેલા સ્ત્રી બાળકોનું પ્રમાણ પુરુષ બાળકો કરતાં ઘણું નીચું આવ્યું છે, તે હકીકત સાચી છે, અને

(૨) સરકારે આ પ્રમાણ યોગ્ય રહે તે માટે શાં પગલાં લીધાં છે?

આરોગ્ય મંત્રીશ્રી:

(૧) હા.

(૨) (૧) રાજયમાં પી.એન.ડી.ટી.એકટના અસરકારક અમલ માટે એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટી, એડવાઈઝરી કમિટી, સ્ટેટ સુપરવાઈઝરી બોર્ડ, સ્ટેટ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટીની રચના કરવામાં આવેલ છે.

(૨) જીનેટીક કાઉન્સિલ, સૅન્ટર , લૅબૉરૅટરી જેવી સંસ્થાઓની નોંધણી ફરજિયાત કરવામાં આવેલ છે.

(૩) પી.એન.ડી.ટી. કાયદાનો ભંગ કરનાર ૧૪ સંસ્થાઓ/ ડૉકટરો સામે કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવેલ છે.

(૪) પી.એન.ડી.ટી. એકટ અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે પોસ્ટર્સ, સ્ટીકર્સ, હેન્ડબીલ,દૂરદર્શન પર સ્પૉટ, આકાશવાણી કાર્યક્રમ, ટીન પ્લેટ વર્કશૉપ (કાર્યશાળા), વસ્તી આયોગ અને એન.જી.ઓ./ સંસ્થાઓના સહયોગ દ્વારા જુદા જુદા કાર્યક્રમો યોજી જનજાગૃતિ લાવવા સઘન પ્રયત્ન કરેલ છે.

શ્રી નારાયણભાઈ લ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે આજના યુગમાં સ્ત્રીઓનો જન્મદર પુરુષોની સરખામણીમાં ઘણો ઓછો છે. સોનોગ્રાફી અને એવા સાધનો દ્વારા લોકો ભૃણહત્યા કરાવે છે. તો આ અંગે શું પગલાં લીધાં અને કેટલા ડૉકટરો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સમગ્ર રાજય માટે ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. હું આ ગૃહના સન્માનનીય સભ્યશ્રીઓ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતના નાગરિકોને અપીલ કરવા માગું છું કે આ કાર્યમાં જનભાગીદારીને મનથી જોડવી જોઈએ. આપે પ્રશ્નની મંજૂરી આપી છે તે માટે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછયો છે એ મુજબ રાજયમાં આ કાયદા નીચે વિવિધ સંસ્થાઓની નોંધણી કરવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે પી.એન.ડી.ટી. એકટ અને બાકીના કાર્યોની અપેક્ષા અનુસાર વિવિધ કાર્યવાહી હાથ ધવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં માનનીય સભ્યશ્રીએ કહ્યું તે મુજબ જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેમાં ૧૪ જેટલા ડૉકટરો અને વિવિધ સંસ્થાઓ સામે વિવિધ કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલ છે. રાજય સરકારે આ કાર્ય માટે એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટીની અને એડવાઈઝરી કમિટીની પણ રચના કરેલી છે. સ્ટેટ સુપરવાઈઝરી બોર્ડની પણ રચના કરેલી છે. દરેક જિલ્લામાં આ પ્રકારની એડવાઈઝરી કમિટીઓને નીમવામાં આવેલી છે. જેના અનુસાર જે કોઈ વિવિધ કાયદાકીય પગલાંઓ સૂચવે તે એડવાઈઝરી કમિટીએ સૂચવેલ પગલાં અનુસાર આ મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે. અત્યારે જે ચાર-પાંચ રાજયોમાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ ઓછું છે તેમાંનું એક ગુજરાત છે. તે સ્થિતિમાં ૧૦૦૦ પુરુષે ૯૨૦ જેટલી સ્ત્રીઓની સંખ્યા રહેલી છે. ૦-૬ ઈયર તો તેનાથી પણ ખરાબ છે. ૧૦૦૦ પુરુષ બાળકોની સામે ૮૮૩ જેટલા સ્ત્રી બાળકો રહેલા છે. એ સ્વરૂપમાં આ કાર્યમાં તમામ પ્રકારની જાગૃતતા ખૂબ જરૂરી છે. તેના માટે આરોગ્ય વિભાગ અને રાજય સરકારે તમામ યોગ્ય પગલાં અને કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.

ડૉ. જીતેન્દ્રભાઈ બા. પટેલ : સ્ત્રી ભૃણહત્યા સામાજિક ચિંતનનો વિષય છે અને 'દૂધપીતી કરવી'નો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ છે. મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવું છે કે કયા કયા જિલ્લાઓમાં સ્ત્રી ભૃણહત્યાનો રેશિયો વધારે પ્રમાણમાં ડિસ્ટર્બ જોવા મળે છે? જે જિલ્લાઓમાં વિશેષતઃ કયા પ્રકારની કામગીરી દ્વારા તેને અટકાવવાનો સરકાર દ્વારા પ્રયાસ થયો છે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સ્ત્રીઓનું સૌથી ઓછું પ્રમાણ જે જિલ્લામાં છે એમાં સૌથી મોખરે સુરત જિલ્લો છે. ૧૦૦૦ પુરુષોએ ૮૩૫ બહેનો રહેલી છે. ૦થી ૬ વર્ષની વય જૂથના બાળકોમાં સ્ત્રી બાળકોનું ઓછું પ્રમાણ મહેસાણા જિલ્લામાં રહેલું છે, એ ૧૦૦૦ પુરુષોએ ૮૩૦ બાળકો રહેલા છે. સ્ત્રીઓનું સૌથી ઓછું પ્રમાણ ઊંઝા તાલુકામાં ૧૦૦૦ પુરુષોએ ૭૪૨ બહેનોનું પ્રમાણ રહેલું છે. સ્ત્રીઓનું સૌથી વધારે પ્રમાણ ડાંગ અને અમરેલી જિલ્લામાં રહેલું છે. ૧૦૦૦ પુરુષોએ ૯૮૭ બહેનોની સંખ્યા રહેલી છે. સ્ત્રીઓનું સૌથી વધારે પ્રમાણ દાહોદ જિલ્લાના દેવગઢ-બારીયા તાલુકામાં ૧૦૦૦ પુરુષોએ ૯૯૯ બહેનો રહેલી છે. ૦થી ૬ વર્ષમાં સ્ત્રીઓનું સૌથી વધુ પ્રમાણ કચ્છ જિલ્લામાં રહેલું છે. ૧૦૦૦ પુરુષ બાળકોએ ૯૨૨ સ્ત્રી બાળકો રહેલા છે.

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપે આ પ્રશ્ન માટે અનુમતિ આપી એ માટે આપનો આભાર માનું છું સાથે સાથે શ્રી માલજીભાઈનો પણ આભાર માનું છું કે જેમણે સમાજને સ્પર્શે એવો ખૂબ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન આ ગૃહમાં ઉઠાવ્યો છે. આ ગૃહને એક જાણકારી મારે આપવી જરૂરી લાગે છે કે, જે ઊંઝાના આંકડા આપ્યા એમાંથી ચિંતા કરીને ઊંઝાના માનનીય ધારાસભ્યશ્રીએ જન જાગૃતિનું એક મોટું આંદોલન ઊભું કર્યું છે અને એમાં અનેક સામાજિક સંસ્થાઓ જોડાઈ છે, એ.પી.એમ.સી. પણ જોડાઈ છે અને પરિણામે ઊંઝાના એક ભદ્ર વર્ગમાં આ ચિંતા તરફ સમાજ વળ્યો છે. એ હું માનું છું કે એ એક ઉમદા કાર્ય માનનીય નારણભાઈ દ્વારા થયું છે. અન્ય જગ્યાએ પણ આમાં સામૂહિક ચિંતા કરવાનો આ વિષય છે. જેને ગૃહે જે સ્પિરિટથી આ વિષયને લીધો છે એ બદલ સમગ્ર ગૃહનો હું આભાર માનું છું.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પ્રશ્નને લઈને લોકસભાના અને ધારાસભાના પ્રતિનિધિઓની એક મિટિંગ બોલાવવામાં આવી હતી અને એમાં ખૂબ સારા સૂચનો થયાં હતાં. ખાતા તરફથી એ સૂચનોનો અમલ કરી અને આ એક સામૂહિક લોકભાગીદારીથી સમાજના મંડળો અને વિવિધ કામ કરતા લોકોને સાંકળી અને કામ કરવાની વાત થઈ હતી. આ બાબતમાં સરકારશ્રીએ શું પગલાં ભર્યાં? વિડિયો કેસેટસ્, પત્રિકાઓ દ્વારા ખૂબ બહોળો પ્રચાર કરવાની અને આ બધું ધારાસભ્યોને અમને પહોંચતું કરવાની વાત થઈ હતી. એમાં સરકારશ્રીએ શું કર્યું?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીએ જે પ્રકારના વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે એ બાબતમાં પોપ્યુલેશન ફાઉન્ડેશન ઑફ ઈન્ડિયા અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા આ પ્રકારનો ધારાસભ્યો સાથેનો એક વિચાર વિમર્શ કાર્યક્રમ, વિધાનસભાના માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના અધ્યક્ષપણા હેઠળ યોજાયેલ. આ ગૃહના તમામ સભ્યશ્રીઓને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે, જે અધિકારીઓ કેન્દ્ર સરકારમાંથી આવ્યા હતા એમણે એ વાતનો ઉલ્લેખ કરેલો કે, એકાદ માસ પહેલાં પંજાબમાં આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ યોજાયેલ. એમાં ફક્ત ૬ ધારાસભ્યો હાજર હતા. આપણે ત્યાં યોજાયેલા આ પ્રકારના કાર્યક્રમમા બધાજ પક્ષનાં સન્માનીય સભ્યો લગભગ ૬૦ જેટલા ધારાસભ્યશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ રહ્યો હતો. અને જે સૂચનો કરેલ હતા એ સૂચનોની અંગ્રેજીમાં બુકસ હતી એનો તાત્કાલિક ધોરણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવામાં આવેલ છે. સાથોસાથ ગામે-ગામ અને ખાસકરીને જે જિલ્લાઓમાં, જે તાલુકાઓમાં, જે વિસ્તારોમાં વધારે જાગૃતિની જરૂરિયાત છે ત્યાં વિડિયો કેસેટસ્, પેમ્ફલેટ અને મિટિંગો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કાર્યક્રમો, જેમ ઊંઝા વિસ્તારમાં માનનીય નારણભાઈ પટેલ લીડ લઈને લગભગ ૧૦૦૦૦-૧૫૦૦૦ બહેનોનું સંમેલન કર્યું અને કાર્યક્રમ યોજ્યો એ રીતે જન જાગૃતિ માટેના વિવિધ કાર્યક્રમો અને પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવી છે.

ડૉ. માયાબેન સુ. કોડનાની : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ખૂબ ગંભીર પ્રશ્ન છે અને એની ચિંતા આ ગૃહ કરી રહ્યું છે. ત્યારે આપના મારફત માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી મારે એ જાણવું છે કે ઓબસ્ટ્રેક ગાયનેક સોસાયટી, ઈન્ડિયન મૅડિકલ એસોસીએશન અને સોનોલોજી આ બધા સાથે પણ સંયુકત રીતે અથવા જૂદી જૂદી રીતે કોઈ ચર્ચા વિચારણા કરવા માગો છો કે કેમ? અથવા કરી છે કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગુજરાતનું હિતકાર્ય છે અને જે કોઈ વ્યકિતઓ એમાં સહયોગ આપે એ તમામ સાથે ચર્ચા કરવા માગીએ છીએ. બહેને જે પ્રશ્ન કર્યો છે ગાયનેકોલોજીસ્ટ અને બાકીના લોકોએ પણ આ કાર્યમાં ખૂબ સારો સહકાર આપેલ છે. છેલ્લે ગાંધીધામમાં જ્યારે આ ગાયનેકોલોજીસ્ટની કોન્ફરન્સ થઈ ત્યારે હાજર રહેલ સ્ટેટના ગાયનેકોલોજીસ્ટ માયાબેન, નીમાબેન બધા એમાં હાજર હતા અને જાહેરમાં સોગંદ લીધા છે કે કયાંય પણ એ લોકો સ્ત્રી ભૃણ હત્યા કરવાના કાર્યમાં કોઈપણ પ્રકારે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સહયોગ નહીં આપે અને બાકીની સંસ્થાઓને પણ આ કાર્યમાં વધુને વધુ જોડવા માગીએ છીએ.

પંચમહાલ જિલ્લામાં પાકા ડામરના રસ્તા બનાવવા બાબત

***૮૧૧૮ શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર (હાલોલ)**: માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે,

(૧) પંચમમહાલ જિલ્લામાં એવા કેટલા રસ્તાઓ છે કે જેને પાકા ડામરના બનાવવા માટે મંજૂરી મળેલ છે, અને જેનાં વર્ક ઑર્ડર પણ આપી દેવામાં આવેલ છે તેમ છતાં તાઃ ૨૫-૧-૦૫ સુધીમાં કામ શરૂ કરવામાં આવેલ નથી,

(૨) આવા રસ્તાઓનું કામ પૂર્ણ કરવા સરકારે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ, અને

(૩) જો હા, તો કેટલા સમયમાં?

માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી :

(૧) ૧૨ (બાર) કામો ભૌતિક રીતે શરૂ કરેલ નથી.

(૨) અને (૩) હા, જી. આ કામો વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને હું પૂછવા માગું છું કે જવાબમાં એમણે જણાવ્યું છે કે ૧૨ (બાર) કામો ભૌતિક રીતે શરૂ કરેલ નથી અને ૨૦૦૫-૦૬માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. જ્યારે આપણી સરકાર ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિકાસ માટે અને ગરીબ લોકોને લાભ થાય એના માટે લાખો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવે છે અને જ્યારે ગ્રાન્ટ ફાળવ્યા પછી એ કામોને મંજૂર કરવામાં આવે અને એના વર્ક ઑર્ડર આપવામાં આવે અને એ કામો શરૂ ન કરવામાં આવે તો જે અધિકારીશ્રીઓની નિષ્કાળજી હોય કે જે એજન્સીઓની નિષ્કાળજી હોય એની સામે પગલાં ભરવા માગે છે કે કેમ? અને બીજું કે આ કામમાં જે સમયમર્યાદા આપે બતાવી છે એ સમયમર્યાદામાં ખરેખર પૂર્ણ કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતમાં પી.એમ.જી.એસ.વાય.માં સૌથી વધારે રસ્તાઓ કોઈપણ જિલ્લાને જો પ્રાપ્ત થયા હોય તો એ પંચમહાલ જિલ્લો છે. લગભગ ૯૦થી પણ વધારે ગામોના રસ્તાઓ પંચમહાલ જિલ્લાને આ ૨ વર્ષમાં પ્રાપ્ત થયા છે એ સ્થિતિમાં ૧૨ કામો ભૌતિક રીતે શરૂ કરવામાં આવેલ નથી અને ૧૨ કામોમાં ૫ કામો ૨૦૦૪-૦૫ના છે અને જેની કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલી છે બાકીના પણ ૭ ગામોની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. માનનીય સભ્યશ્રીએ જે લાગણી વ્યકત કરી છે એ લાગણી મુજબ આ તમામ કામો માટેની વિવિધ કાર્યવાહી હાથ ધરેલી છે. કોન્ટ્રાકટરને નોટિસો આપવામાં

આવી છે. જિલ્લા પંચાયતની બાંધકામ સમિતિમાં પણ વિવિધ ઠરાવો માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને આ બધા જ કામો ૨૦૦૫માં પૂર્ણ થાય એ પ્રકારનું આયોજન છે.

શ્રી હરેશકુમાર ઈ. ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે ભૌતિક દૃષ્ટિએ ૧૨ જે કામો નથી થયાં એ કયાં કયાં કામો છે? બીજું એ કામો કયા કારણોસર નથી શરૂ થયાં અને કયા સમયમાં પૂર્ણ થશે અને કામો નથી થયાં એની કાર્યવાહી શું થઈ છે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષાશ્રી, જે ૧૨ કામો છે એ ૧૨ કામોમાં એક કામ છે ખોજલવાસા સાજીવાવ મહેસાણા રોડ, તાલુકો શહેરા, બીજું કામ છે સુખીયાપુરી વાઘાવારોડ, ગોધરા, ત્રીજું કામ છે ગોધરા સામલી રોડ, દરૂણીયા એપ્રોચ રોડ, ગોધરા, ચોથું કામ છે કંન્સ્ટ્રકટીંગ દામોદ પેટે સરોલી તળાવ રોડ, ક્રોસીંગથી વાયા સરોલી, જલાવગનો રોડ, પાંચમું કામ છે ધુસરથી વાલૈયા નવી વસાહત રોડ, છઠ્ઠું કામ છે ગોધરા રેલવે નં. ૬૦ને ઓરડીથી હોરંગ નવી વસાહત સુધીને જોડતો રોડ, સાતમું કામ છે રતનપુર નવાધરારોડ, ગોધરા, આઠમું કામ છે વાધવાણી ટુ પાંચ મહુડી રોડ હાલોલ, નવમું કામ છે સાંભેરા આંબા ફળીયા રોડ, ભોગંબા, દસમું કામ છે જોરાપુરા રાઠવા ફળીયા રોડ, ભોગંબા, અગિયારમું કામ છે ગોદલી રમાણીફળીયા રોડ, ભોગંબા, બારમું કામ છે બોરતલાવ ફળીયા રોડ, ભોગંબા. આ બધા જ કામોની સામે જ્યાં જ્યાં એ લોકોએ ક્ષતિઓ કરેલ છે એટલે કે કામ શરૂ કર્યું નથી એને વિવિધ તબક્કે નોટિસો આપી છે. બાંધકામ સમિતિમાં પણ વિવિધ તબક્કે મૂકેલ છે અને હમણાં મેં કહ્યું એ મુજબ ૨૦૦૫ માં આ બધા કામો પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

શ્રી કાળુભાઇ હી. માલીવાડ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે એ સિવાયના પણ લુણાવાડા તાલુકાના જે રસ્તાઓના જોબ નંબરો મળેલા છે પણ કામ બાકી છે એ કામો ક્યારે પૂરાં થશે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : જે પણ જોબ નંબરો મળેલા છે એ બધા જ જોબ નંબરોના કામો આ વર્ષમાં કરવા માગીએ છીએ. પણ મેં કહ્યું એ મુજબ પી.એમ.જી.એસ.વાય. યોજના નીચે પંચમહાલ જિલ્લામાં ૨૨૩૯.૫૯ લાખના ૮૫ રસ્તાઓ મળેલા છે. વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં ૩૧૮.૦૩ લાખના રસ્તાઓ છે. એ સ્થિતિમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં કામ હાથ ધર્યું છે. જે કાંઈ રસ્તાઓ બાકી છે એ તમામ કામો આ વર્ષમાં પૂરા કરવાનું આયોજન છે.

શ્રી જેઠાભાઈ ઘે. ભરવાડ : પી.એમ.જી.એસ.વાય. ના રસ્તાઓ પંચમહાલ જિલ્લાને આપ્યા છે એ બદલ હું માનનીય મંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું. એમની પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે, પંચમહાલ જિલ્લામાં કુલ કેટલા ગામો છે? આ ગામોની અંદર કુલ કેટલા પાકા રસ્તાઓ છે અને કુલ કેટલા કાચા રસ્તાઓ છે. એના માટે શું આયોજન કરવા માગો છો?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : પંચમહાલ જિલ્લામાં કુલ ૧૧૯૫ ગામો છે.

અધ્યક્ષશ્રી : બહુ લાંબો પ્રશ્ન છે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું જવાબ આપું છું. જે ૧૧૯૫ ગામો છે એમાં પાકા રસ્તાથી જોડાયેલાં ગામો ૧૧૮૭ છે, ડામરથી જોડાયેલાં ગામો ૧૧૦૯ છે, મેટલ સપાટીથી જોડાયેલાં ૭૮ છે અને કાચા રસ્તાથી જોડાયેલાં ગામોની સંખ્યા ૮ છે. આ ૮ ગામો મોટાભાગે વન વિભાગની જમીનના કારણે ઉપલબ્ધ થવાની મુશ્કેલીના કારણે કાચા રહેલા છે. એનું લિસ્ટ જોઈતું હોય તો આપું.

શ્રી છત્રસિંહ પૂં. મોરી : માનનીય મંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું કે આ ૧૨ રસ્તાઓ મંજૂર તો થયેલ છે. સમગ્ર જિલ્લામાં અમે જોઈએ છીએ તો રસ્તાના જોબ નંબરો મળી જાય પણ પદ્ધતિ એવી હોવી જોઈએ કે જે વર્ષે જોબ નંબર મળે એ જ વર્ષે ખરેખર રોડ પૂરા થઈ જવા જોઈએ. રોડ મંજૂર કરવાની પ્રક્રિયા છે એમાં થોડો સુધારો કરવાની જરૂર છે. એ સુધારો કરીને એવી રીતે કરવું જોઈએ કે ઘણીવાર એજન્સી ધારો કે ન કરે તો બે વર્ષ સુધી રસ્તો મંજૂર થયેલ હોવા છતાં થતો નથી. એવી કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ કે જે વર્ષે જોબ નંબર મળે, જે વર્ષે કાર્યવાહી શરૂ થાય એ જ વર્ષે પૂરી થાય. એવું કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : ગત વિધાનસભામાં જ મેં કહેલું કે માર્ગ અને મકાન વિભાગ જોબ નંબરો આપવા માગે છે એ જ વર્ષમાં હાથ ધરવા માગે છે. ગૃહના સભ્યશ્રીઓને જણાવતાં મને આનંદ થશે કે ગત વર્ષે ૬૦૪૭ કિલોમિટરના રસ્તા બનાવવાનું ગૃહમાં જાહેર કરેલું. આ ગૃહને જણાવું કે ૬૦૬૦ કિલોમિટરથી વધારે રસ્તાના કામો પરિપૂર્ણ કર્યા છે. આમછતાં ક્યાંક હેબીચ્યુઅલ એવા પ્રકારના કોન્ટ્રાકટરો જણાય ત્યાં સખ્તાઈથી કાર્યવાહી કરવા માગીએ છીએ. સાથોસાથ જણાવવા માગું છું કે જોબ નંબર આપીએ એ જ વર્ષમાં કામ શરૂ કરવા માગીએ છીએ. કોઈના પણ વિસ્તારમાં જોબ નંબર અટકાય તો ચોક્કસ ધ્યાન દોરજો, કોઈપણ વ્યકિત હશે, પૂરેપૂરા પગલાં ભરવામાં આવશે.

ખાનપુર તાલુકામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મૅડિકલ ઑફિસરની ખાલી જગ્યા

***૮૬૬૫ શ્રી કાળુભાઇ હી. માલીવાડ (લુણાવાડા)**: માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-
(૧) તારીખ ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં કેટલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો આવેલ છે, તે પૈકી કયા કયા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મૅડિકલ ઑફિસરની જગ્યા ખાલી છે,
(૨) મહેકમ મુજબ તમામ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને
(૩) આ જગ્યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
આરોગ્ય મંત્રીશ્રી:
(૧) ત્રણ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પાંડરવાડા ખાતે મૅડિકલ ઑફિસરની જગ્યા ખાલી છે.
(૨) એક.
(૩) યોગ્ય તબીબી અધિકારી ઉપલબ્ધ થયેથી.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જવાબ છાપ્યા પ્રમાણે છે પરંતુ સુધારા સાથે કે યોગ્ય તબીબી અધિકારીથી જગ્યા ભરાઈ ગઈ છે.

શ્રી કાળુભાઇ હી. માલીવાડ :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના દ્વારા એ જાણવા માગુ છું કે, મારા મત વિસ્તારમાં બે તાલુકા આવે છે લુણાવાડા અને ખાનપુર. ખાનપુર તાલુકો પંચમહાલ જિલ્લાની ઉત્તરે છેવાડે આવેલો છે અને તેમાંય એ તાલુકામાં ઉત્તર વિસ્તારમાં આ પી.એચ.સી. દવાખાનું આવેલું છે, ત્યાં આગળ ડૉકટર, મૅડિકલ ઑફિસર નથી જેના કારણે પછાત વર્ગ છે અને આ આંતરિયાળ વિસ્તારની અંદર જો એમને તબીબી સારવાર લેવી હોય તો છેવાડાનો વિસ્તાર રાજસ્થાન આવે છે ત્યાં તંત્ર કામ કરવામાં નથી. એટલા માટે આ તબક્કે ખાસ મારી રજૂઆત છે કે આ ડોકટરોની જગ્યા વહેલી તકે પૂરાય

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ જગ્યા ૧૬-૨ ના રોજ ભરાઈ ગઈ છે. પરંતુ સાથે સાથે વિભાગે કરેલા પ્રયત્નો માટે પણ હું ગૃહને માહિતગાર કરવા માગું છું કે પંચમહાલ જિલ્લામાં જે ડૉકટરોની ખાલી જગ્યા છે એમાં નવેમ્બર ૨૦૦૩ થી અત્યાર સુધીમાં ૨૩ ડૉકટર્સને ઓડર્સ આપ્યા, એમાંથી ફકત ૧૦ ડૉકટરો હાજર થયા છે. રાજ્યમાં સમગ્ર જગ્યાએથી બધાએ આ અભિપ્રાય વ્યકત કર્યો છે અને બધાને માહિતીમાં છે ઈન્ટિરિયલ વિસ્તાર છે, જ્યાં ટ્રાયબલ બેલ્ટ, રણ વિસ્તાર છે, જ્યાં દરિયાઈપટ્ટી છે એ વિસ્તારમાં ડૉકટરો ઝડપથી પ્રાપ્ત થતા નથી અને એ સ્થિતિમાં યોગ્ય વિચારણા કરીને આ વિસ્તારમાં પણ જ્યાં માનનીય સભ્યશ્રીએ લાગણી વ્યકત કરી છે એ મુજબ ખાસ જરૂરિયાત રહેલી છે અને ઈન્ટિરિયલ એરિયા છે ત્યાં પણ ડૉકટરોની જગ્યા ભરાય અને યોગ્ય સ્વરૂપે ડૉકટર રહે એની સઘન વિચારણા પણ આ વિભાગ કરી રહ્યો છે.

સમલાયા-ગાંયડિયા- ચાંપાનેર રસ્તો ડામરની સપાટીવાળો બનાવવા બાબત

***૮૯૮૨શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર. ગોહિલ (સાવલી)**: માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

(૧) સાવલી તાલુકાના પંચાયત હસ્તકના સમલાયા-ગાંગડીયા-ચાંપાનેર રસ્તાને સમલાયા-ટુંડાવ-રાણીયાા રસ્તાઓની સપાટી પર ડામર કામ કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,
(૨) જો હા, તો કઈ યોજનામાં અને ક્યાં સુધીમાં, અને
(૩) આ માટે કોઈ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે કે કેમ?

માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી :
(૧) સમલાયા-ટુંડાવ-અંજેસર-રાણીયાા ૧૯.૪૦ કિલો મિટર પૈકી ૮.૦ કિલોમિટર રસ્તાને ડામર કરવાનું આયોજન છે. જ્યારે સમલાયાા-ગાંગડીયા-ચાંપાનેર રસ્તાને ડામર સપાટી કરવાનું હાલ કોઈ આયોજન નથી.
(૨) સમલાયા-ટુંડાવ-અંજેસર-રાણીયાા રસ્તાનું ૪.૭ કિલોમિટર ખાસ મરામતનું કામ તા.૧૪.૪.૨૦૦૫ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને ૩.૩ કિલોમિટર બજેટ ઉચ્ચક જોગવાઈનું કામ એજન્સી નક્કી થયા બાદ છ માસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
(૩) કામવાર ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવતી નથી.

શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર. ગોહિલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમ તો મારો પ્રશ્ન સળંગ રાણીયા-અંજેસર-ચાંપાનેર હતો. પરંતુ માનનીય મંત્રીશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સરકાર અને વિભાગનો કે એમણે બે વિભાગમાં સમલાયા-ટુંડાવ--અંજેસર-રાણીયા જે જવાબ આપ્યો છે એ માટે હું મારા ગામડાના લોકો વતી આભાર માનું છું. સાથે સાથે બીજો પ્રશ્ન એ છે કે, સમલાયા-ટુંડાવ-અંજેસર-રાણીયા ૧૯.૪૦ કિલોમિટર રસ્તો

છે તે પૈકી જે ૮ કિલોમિટર ડામર રસ્તાનું કામ કરવાનું આયોજન છે. માનનીય મંત્રીશ્રી કરવાનું કાંઈ હાલ કોઈ આયોજન છે એવો જવાબ આપ્યો છે એટલે એવી માગણી નહિ પણ મારી લાગણી છે કે આ રસ્તો કરવા માટે માનનીય મંત્રીશ્રી મને તાકીદ કરે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કુલ રસ્તાની લંબાઈ ૧૯ કિલોમિટર છે, એના માટે જે પ્રમાણે કહ્યું એ મુજબ ૮ કિલોમિટર રસ્તાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે અને ૮ કિલોમિટર રસ્તો ચોક્કસપણે સત્વરે જે કાંઈ સમય મર્યાદા છે એમાં લગભગ એપ્રિલ ૨૦૦૫ સુધીમાં, એક રસ્તો, અને બાકીનો રસ્તો ૨૦૦૫-૦૬ માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. ૧૧ કિલોમિટર જેટલો રસ્તો ખૂટે છે આ વર્ષે વિવિધ યોજનાજે પ્રમાણે હાથ ધરાયેલ છે એમાં તાલુકા અને જિલ્લાને જોડતા રસ્તા માટે પણ વિવિધ જે પ્રકારની પ્રક્રિયા આ બજેટમાં હાથ ધરાય છે, ત્યારે હકારાત્મક રીતે માનનીય સભ્યશ્રીના બાકી રહેતા ૧૧ કિલોમિટર રસ્તાનો ચોક્કસપણે વિચાર કરવામાં આવશે.

માંડવી તાલુકાના બૌધાનથી ગલતેશ્વરને જોડતો તાપી નદી પરનો પુલ બનાવવા બાબત

***૮૫૭૬ શ્રી અનિલકુમાર મો. પટેલ (બારડોલી)** : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -માંડવી તાલુકાના બૌધાનથી ગલતેશ્વરને જોડતો તાપી નદી પરનો પુલ બનાવવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે કે કેમ,

(૧) જો હા, તો આ કામગીરી ક્યા તબકકામાં છે, અને

(૨) આ કામ સરકાર ક્યારે પૂર્ણ કરવા માગે છે?

માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી :

(૧) (૨) અને (૩) બજેટમાં સમાવિષ્ટ કામો પૈકી પ્રગતિ હેઠળના કામોની જરૂરિયાત તેમજ આ કામની બજેટ જોગવાઈ ધ્યાન લેતા કામગીરી હાલ હાથ ધરી શકાય તેમ નથી. પરંતુ જ્યારે અન્ય નવા પુલોના કામો હાથ ધરવાનું વિચારાય ત્યારે અગ્રતા, નાણાકીય જોગવાઈ વિગેરેને લક્ષમાં લઈ આ પુલના કામની પણ વિચારણા કરવાનું આયોજન છે.

શ્રી અનિલકુમાર મો. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માંડવી, બારડોલી અને કામરેજ તાલુકાને જોડતો આ પુલ છે અને સંપૂર્ણ ટ્રાયબલ વિસ્તારમાં આવેલો આ પુલ છે. એશિયાની સૌથી મોટી સુગર ફેકટરી બારડોલી અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં એનાથી ૨૦૦ કિલોમિટરે આવેલો આ પુલ છે એટલે ખાસ એની જરૂરિયાત છે અને અગાઉ પણ એની રજૂઆત થઈ ચૂકી છે. છતાં પણ રાજ્ય સરકારે આ બાબતમાં કાંઈ પણ વિચાર્યુ નથી ત્યારે સરકાર આ પુલ બનાવવા કોની કોની તરફથી રજૂઆત મળી અને ક્યારે મળી હતી? રાજ્ય સરકારે આ પુલ બનાવવા માટે સરવે રિપોર્ટ અને કોસ્ટિંગ તૈયાર કર્યુ છે કે કેમ? અને જો તૈયાર કર્યુ હોય તો એનો ખર્ચનો અંદાજ બનાવી અને એ મહત્વનો પુલ સરકાર ક્યારે બનાવવા માગે છે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પુલના એસ્ટિમેટ પ્રમાણે અંદાજીત રકમ લગભગ વીસેક કરોડ રૂપિયાની છે. આ રસ્તો એવો રાજ્ય ધોરીમાર્ગ રસ્તો નથી. પરંતુ બે ગામને જોડતો રસ્તો છે, બારમાસી નદી છે, બારમાસી નદીના પાણીના કારણે કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ હાથ ધરી શકાય એ પ્રકારની સ્થિતિમાં નથી અને બંને ગામો છે અને થોડું પાંચ-સાત કિલોમીટરનું અંતર ફરવું પડે છે પરંતુ બંને ગામોને અન્ય રસ્તેથી જોડાણ જ્યારે પ્રાપ્ત થયેલ છે ત્યારે આ ૨૦ કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ અત્યારે કોઈ આયોજનમાં હાથ ધરાયેલ નથી એટલું જ નહીં મેં એમને જવાબ આપ્યો છે કે હાલમાં કોઈ આયોજન નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજય સરકારે, ગત વર્ષે જાહેર કરેલ હતું કે, રાજયમાં વિવિધ ૨૯ જેટલા પુલો એવા રહેલા છે કે, લગભગ ૬૩ જેટલા તાલુકાઓને જોડતા પુલો છે અને એ પુલોના જે ચાલુ કામો હતા , ભૂતકાળની જે જોગવાઈઓ ધ્યાનમાં રાખીને પૂરેપૂરું ધ્યાન આપીને ૨૯ પુલોના કામને આપણે અગ્રિમતા આપેલી અને એ પુલોના કામ ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યા છે જેના કારણે પણ અત્યારે બે ગામોને જોડતા રસ્તા માટે ૨૦ કરોડ રૂપિયાનું આયોજન શકય નથી.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ફેરવવા બાબત

***૯૪૯૭ શ્રી હરજીવન હી. પટેલ(ધાનેરા)** : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લાના કયા કયા તાલુકાઓમાં ડિસેમ્બર'૦૪ની સ્થિતિએ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો નથી,

(૨) જે તાલુકામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ચાલે છે તેવા કેન્દ્રોને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ફેરવવા સરકારની કોઈ યોજના છે, અને

(૩) જો હા, તો કેટલા સમયમાં મંજૂર કરવામાં આવશે?

આરોગ્ય મંત્રીશ્રી :

(૧) દાંતીવાડા તાલુકામાં.

(૨) ના,જી.

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી હરજીવન હી. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બનાસકાંઠા જિલ્લાના બાર તાલુકાઓ આવેલા છે એમાં દાંતીવાડા તાલુકામાં સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર નથી. માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે, દાંતીવાડા તાલુકામાં સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માટેની કોઈ રજૂઆત મળી છે કે કેમ અને જો મળી હોય તો એ કેટલા સમયમાં મંજૂર કરવા માગો છો ?

બીજો પ્રશ્ન એ છે કે, દાંતીવાડા તાલુકાના પાંથાવાડા ગામ મોટું છે, મારા અને કચોરિયાજીને બિલકુલ બૉર્ડર ઉપરનું ગામ છે ત્યાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચાલે છે તો એને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ફેરવવા માગો છો કે કેમ ? અને

ત્રીજું, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મહેકમમાં ઘટ કેટલા સમયમાં પુરવામાં આવશે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય સભ્યશ્રીએ દાંતીવાડામાં સી.એચ.સી. સૅન્ટર આપવા માટેની માગણી કરી છે, એમની લાગણી અને હાર્દ સાથે હું ચોક્કસપણે સંમત છું, પરંતુ હાલમાં એનું કોઈ આયોજન નથી, આમછતાં જે નવા તાલુકાઓ થયા અને નવી ભૌગોલિક સ્થિતિમાં રાજયમાં સાત તાલુકામથકો એવાં છે કે, જ્યાં સી.એચ.સી. અત્યારે નથી અને એ સાત તાલુકાઓમાં સી.એચ.સી.ની યોગ્ય વ્યવસ્થા ઊભી થાય એના માટે સઘન વિચારણા ચાલી રહી છે. આ ગૃહના તમામ સભ્યશ્રીઓના ધ્યાન ઉપર એ બાબત મૂકવા માગું છું કે, પેટા કેન્દ્રો, પીએચસી અને સીએચસીના જે કાંઈ નેશનલ નોમર્સ, રાષ્ટ્રીય ધોરણ અત્યારે પ્રસ્થાપિત રહેલ છે. એમાં ગુજરાત અત્યારે શ્રેષ્ઠ સ્થાને છે. આજે દેશમાં ૨.૪૪ લાખની વસ્તીએ એક સીએચસી સૅન્ટર રહેલું છે જ્યારે ગુજરાત ફક્ત ને ફકત એક એવું રાજય છે કે, જ્યાં૧ લાખ ૧૭ હજાર ૧૨૪ની વસ્તીએ એક સીએચસી સૅન્ટર રહેલ છે. માનનીય સભ્યશ્રીઓને બીજી પણ એ બાબત ધ્યાન ઉપર મૂકવા માગું છું કે, ગત વર્ષે જે સીએચસી આપવાનો આપણે નિર્ણય આપણે કરેલો અને એ સીએચસીમાં સૌથી વધારે કોઈ જિલ્લાને આપ્યા હોય તો એ બનાસકાંઠા જિલ્લાને, ત્રણ સીએચસી આપેલ છે. આમછતાં મેં હમણાં જ કહ્યું એ મુજબ રણ વિસ્તાર, ટ્રાયબલ વિસ્તાર અને દરિયાઈ વિસ્તાર, એ વિસ્તારો માટે થઈને અગ્રિમતા છે અને બનાસકાંઠાને વધુ સીએચસી પ્રાપ્ત થાય એ માટે રાજય સરકાર અને દાંતીવાડા તાલુકામાં જ્યાં સીએચસી નથી એને પ્રાપ્ત થાય એમાં હકારાત્મક રીતે ચોક્કસ વિચાર કરાશે.

શ્રી શંકરભાઈ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ જે બનાસકાંઠા જિલ્લાને વધુ ત્રણ સીએચસી આપ્યા એ બદલ એમનો આભાર માનું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રણ પ્રદેશને અડીને આવેલ એક સૂઈગામ સૅન્ટર છે, ૪૦ ગામોને જોડતું, પાકિસ્તાન સરહદને અડીને છેલ્લું ગામ અને એક બાજુ રણ પ્રદેશ આવે છે, ૪૦ ગામનો વ્યવહાર આ સૂઈગામ સાથે જોડાયેલો છે, ત્યાંથી ૩૦-૩૫ કિલોમીટર દૂરથી નજીકમાં એક પણ હૉસ્પિટલ નથી તો આ વાવ તાલુકામાં એક સીએચસી છે પરંતુ એક કરતાં વધુ અહીંયા આપવામાં આવે તો આ બંને જે વિસ્તારો છે એને સાંકળીને લોકોને સુવિધા મળી શકે અને માનનીય મંત્રીશ્રીએ હમણાં વાત કરી કે, રણ પ્રદેશ કે એવું હોય તો સ્પેશિયલ સુવિધા આપીશું વધારાની, તો આ સૂઈગામની અંદર જે પીએચસી ચાલે છે એને સીએચસીમાં ફેરવવા માગો છો કે કેમ ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ૧૩ સી.એચ.સી. સૅન્ટર કાર્યરત છે. ૧૩ સિવાય જ્યાં જ્યાં ખૂટતી કડી છે, એમાં ચોક્કસપણે હું સંમત છું. બનાસકાંઠા માટે અગ્રિમતાના ધોરણે છે એટલા માટે કોઈ જિલ્લો એવો નહોતો ગયા વર્ષે કે જેને બે સી.એચ.સી. મળ્યા હોય, બનાસકાંઠાને ત્રણ સી.એચ.સી. આપ્યાં છે. શંકરભાઈની લાગણી જ્યારે આયોજન હાથ ધરાશે ત્યારે વિચારણામાં લઈશું.

લુણાવાડા તાલુકાના પાકા એપ્રોચ રોડથી વંચિત ગામો

***૮૨૩૭ શ્રી વજુભાઈ પ. ડોડિયા (વિરમગામ)**:માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

(૧) તારીખ ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ લુણાવાડા તાલુકાના કેટલા ગામો પાકા એપ્રોચ રોડથી વંચિત છે?

(૨) તે પૈકી જુનાગોરડા ગામનો સમાવેશ થયેલ છે કે કેમ, અને

(૩) જો હા, તો આ ગામનો એપ્રોચ રોડ કેટલા સમયમાં બનાવવામાં આવશે?

માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી:

(૧) તારીખ ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ લુણાવાડા તાલુકાનું એક પણ મહેસૂલી ગામ પાકા એપ્રોચ રોડથી વંચિત નથી.

(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી વજુભાઈ પ. ડોડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સુતારી મુવાસાને જોડતો ૩૦૦ કિલોમિટર જેટલો કાચો રસ્તો છે તો પાકા રસ્તા સાથે જોડવા માગો છો કે કેમ? બીજો પ્રશ્ન એ છે કે ધારાસભ્યશ્રીને રસ્તાની ૩૦ લાખની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે એ રીફેવરીંગ માટે આપવામાં આવે છે એમાંથી નવા કોઈ રસ્તા જોડવા માટેનું આયોજન એ ગ્રાન્ટમાંથી થઈ શકે કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં કહ્યું એ પ્રમાણે પાકા એપ્રોચ સિવાય તાલુકામાં એક પણ એવો રસ્તો નથી. તમામ રસ્તા પાકા થયેલા છે. જુના ગોરડા ગામ બે બાજુથી રહેલું છે. એમ.ડી.આર. રસ્તાનું જોડાણ છે ત્યાં ૩૦૦ કિલોમિટર દૂર છે. એને ડામર એટલે કે પાકા રસ્તાની વહેલામાં વહેલી તકે સુવિધા આપીને કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

પારડી તાલુકાના રોહીણા, સાદડવેરી, સુખલાવ રસ્તાને જોબવર્ક આપવા બાબત.

*** ૯૨૪૩ લક્ષ્મણભાઈ બા. પટેલ (પારડી)**: માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

અન્ય જિલ્લા માર્ગથી વલસાડ જિલ્લાની પારડી તાલુકા રોહિણા બરઈ, સાદડવેરી, સુખલાવ રોડ મેટલ માર્ગ પાંચ કી.મી. ધરાવે છે આ રસ્તો અન્ય જિલ્લા માર્ગનો હોઈ તેનો જોબવર્ક કયાં સુધીમાં સરકાર આપશે?

માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી:-

રસ્તો વાહનવ્યવહાર લાયક છે. હાલ જોબ નંબરનું કોઈ આયોજન નથી.

શ્રી લક્ષ્મણભાઈ બા. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહ અને સરકારશ્રી ગરીબ આદિવાસી માટે ખૂબ જ ચિંતિત છે. ત્યારે મારો પ્રશ્ન છે કે અન્ય જિલ્લામાં રોહિણા બરઈથી આગળ નીકળતો પાંચ કિલોમિટર રસ્તો માનનીય મંત્રીશ્રીએ જવાબ આપ્યો છે કે હાલ જોબ નંબર આપી શકાય તેમ નથી. આ રસ્તો પરિવહન માટે યોગ્ય છે. મારો પહેલો પ્રશ્ન છે આ રસ્તો મેટલવાળો છે. આજ સુધી એની ઉપર કોઈ વખત ડામર રોડ થયેલ નથી. વાહનવ્યવહાર તો ઠીક મોટર સાયકલ લઈને જવું પણ ભારે છે. પારડી અને કપરડા તાલુકાને જોડતો રસ્તો હોય અને સમગ્ર વિસ્તાર આદિવાસી હોય ત્યારે જે જવાબ આપવામાં આવ્યો છે એ હું માનું છું કે ખરેખર આ રસ્તા માટે સરકારશ્રીએ ચિંતા કરી નથી. જો ચિંતા કરી હોત તો મને જવાબ કદાચ સાચો મળ્યો હોત. આ જવાબ મળત નહીં કે વાહન વ્યવહાર ચાલી શકે તેવો આ રસ્તો છે. હું આશા રાખું છું સરકારશ્રી અને મંત્રીશ્રી પાસેથી કે આ રસ્તાના કામના જોબ નંબર મને મળે.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ધારાસભ્યશ્રીએ જે લાગણી વ્યકત કરી છે એ મુજબ આ માહિતી આપું તો છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં અનેક રસ્તાના કામો હાથ ધર્યા છે. એમાં અમે હમણાં જે પૂર્ણ કર્યા છે એમાં ૧૨ ગામને ૬૫.૨૯ કિલોમિટરના ૨૬૩.૩૧ લાખના કામો પૂર્ણ થયેલ છે. પ્રગતિ હેઠળ ત્રણ કામો છે. ૩ ગામને એની ૧૦ કિલોમિટર લંબાઈ ૬૪.૧૯ લાખના ધોરણે પ્રગતિમાં છે અને અત્યારે જે મંજૂર થયેલા છે એમાં બે રસ્તા એવા છે કે જેની કિંમત ૬૭ લાખની છે. આંકડા બતાવે છે કે બે વર્ષમાં એમના વિસ્તારમાં ચોકકસપણે કામો હાથ ધર્યા છે. સભ્યશ્રીએ આ રસ્તો સૂચવ્યો હોત તો એમાં ચોકકસપણે ફાળવત પણ ગૃહમાં માહિતી આપ્યા મુજબ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતના રસ્તાના વિકાસ માટે નવી ક્ષમતા અને તાકાત આપવા માટે જયારે નિર્ણય કર્યો છે. નાણામંત્રીશ્રી એમની બજેટ સ્પીચમાં વિવિધ જોગવાઈઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે ત્યારે આ સ્થિતિમાં તાલુકાને અને જિલ્લાને જોડતા રસ્તાનું તમામ પ્રકારનું આયોજન ૨૦૦૫-૨૦૦૬માં હાથ ધરવા સક્ષમ છે. પાંચ કિલોમિટરનો તમારો રસ્તો વિચારણા કરી ચોકકસપણે હાથ ધરીશું.

રાજયમાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવા બાબત

***૮૧૨૭ શ્રી માધાભાઈ લા. બોરીચા (કેશોદ): માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે :

(૧) રાજ્યમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવ્યા અને

(૨) આ મંજૂર કરવામાં આવેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પૈકી કેટલા કાયાન્વિત થયાં?

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી :

(૧) ૨૨ (બાવીસ)

(૨) ૧૪ (ચૌદ)

શ્રી માધાભાઈ લા. બોરીચા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું મારા પૂર્વના પ્રશ્નની અંદર માનનીય મંત્રીશ્રીએ માહિતી આપી, તે પ્રમાણે બીજા રાજયની સરખામણીમાં આપણે ત્યાં ડબલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો છે, તે બદલ હું અભિનંદન આપું છું, પણ આ રાજય સરકાર જનકલ્યાણ માટે આરોગ્ય વિષેશ અગ્રતા આપવા માગે છે,

ત્યારે જે ૨૨ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યાં છે, તે કયાં કયાં ખોલવામાં આવ્યાં, તેમાંથી ૧૪ કાયાન્વિત કેન્દ્રો કયાં છે અને ૮ કેન્દ્રો કયાં છે, આ કાર્યાન્વિત નહિ થવાના કારણ શું છે? તે જાણવા માગું છું.

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા (મંત્રીશ્રી) : જે ૨૨ કેન્દ્રો આપવામાં આવ્યા, તેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુવારલા, રૈયા અને વરલોડા, જૂનાગઢ જિલ્લામાં ડેડકિયાળ, પનસવાડા અને આજોઠા, ભાવનગર જિલ્લામાં મોટીજાગધાર, મોટા આસરાણા, સેરન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચોકડી, વગડીયા, વણા, આણંદ જિલ્લામાં બુધેજ અમરેલી જિલ્લામાં લુણીધાર, દાહોદ જિલ્લામાં મોટીખરજ, પાટીયા, સુડીયા, રઈ, ભુલાવ, દુધિયા અને મોટી ઢઢેલી નર્મદા જિલ્લામાં સેલંબા, વડોદરા જિલ્લામાં કરજવાટ કુલ ૨૨ કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવ્યાં, તેમાંથી ૧૪ પી.એ.સી. સેન્ટરો કાર્યાન્વિત થયેલાં છે, તેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુવારલા, રૈયા અને વરલોડા, જૂનાગઢ જિલ્લામાં પનસવાડા અને આજોઠા, દાહોદ જિલ્લામાં મોટીખરજ, પાટીયા, સુડીયા, રઈ, ભુલાવ, દુધિયા અને મોટી ઢઢેલી, નર્મદા જિલ્લામાં સેલંબા અને વડોદરા જિલ્લામાં કરજવાટ. જે ૮ કેન્દ્રો કાર્યાન્વિત કરવાનાં બાકી છે, એમાં જૂનાગઢ જિલ્લાનું ગામ ડેડકિયાળી તા. મેંદરડા, ભાવનગર જિલ્લાનું મોટી જાગંધાર અને મોટી આસરાણા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ચોકડી, વગડિયા અને વણા આણંદ જિલ્લાનું બુધેજ અને અમરેલી જિલ્લાનું લુણીધર આ ૮ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો આઠે આઠ મકાનના અભાવે કાર્યન્વિત કરવાનાં બાકી છે. મકાનની સુવિધામાં શરૂઆતમાં ગામ કે બાકીની રીતે જ્યાં જ્યાં વિલંબ છે, ત્યાં તરત શરૂ કર્યાં છે. બાકી કાર્યમાં મકાનની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

શ્રી જયંતિલાલ રા. કવાડિયા : ૨૨ નવાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની મંજૂરી આપવામાં આવી, તેમાં ૧૪ ચાલુ કરવામાં આવ્યાં છે, ડૉક્ટર બને છે ત્યારે સૌને શહેરમાં રહેવાની વધારે ઇચ્છા હોય છે, તો રાજ્ય સરકાર ફરજિયાત ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ૧૦-૧૨-૧૫ વર્ષ નોકરી કરવી એવું એગ્રીમૅન્ટ કરીને નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવા માગે છે કે કેમ ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : ગૃહના સભ્યશ્રીને જણાવવા માગીશ કે બે વર્ષનો બોન્ડેડ પિરિયડ હોય છે. આમ છતાં લગભગ ૭૦ ટકા ડૉક્ટરો હાજર થતા નથી. આ વખતે તમામ મૅડિકલ કૉલેજોની બહાર જ બોર્ડ મૂકેલ. પ્રાઇવેટ અને સેલ્ફ ફાઈનાન્સ કૉલેજોમાં ૨,૫૦,૦૦૦ ની ફી ભરીને પ્રવેશ પ્રાપ્ત કરો છો. સરકારી મૅડિકલ કૉલેજોમાં ૫,૦૦૦ ફી ભરીને પ્રવેશ પ્રાપ્ત કરો છો અને આપના વતી સમાજ ૨,૪૫,૦૦૦ ફી ભરે છે, ત્યારે સમાજનું રૂણ ચૂકવવા માટે પ્રયત્નશીલ બનો. આમ છતાં જે વિવિધ યોજનાઓ હાથ ધરેલી છે. આ વિવિધ યોજનામાં આગામી દિવસોમાં ચોક્કસપણે જરૂર પડે તો વિધાનસભામાં કાયદો લાવીને કાર્યવાહી કરવા ઇચ્છીએ છીએ. સાથે સાથે ટ્રાયબલ વિસ્તાર, દરિયાઈ વિસ્તાર, બૉર્ડર વિસ્તાર અને રણ વિસ્તારમાં બાકીની યોજના કયા પ્રકારે મૂકી શકાય તેની સઘન વિચારણા કરીને કાર્યવાહી કરવા વિચારી રહ્યા છીએ.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : ગુજરાતમાં પબ્લિક હેલ્થ સેન્ટરો છે અને કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરની સંખ્યા બીજાં રાજ્યના પ્રમાણમાં ઘણી સારી છે અને આ બાબતે ૧૯૮૫ થી ૧૯૯૦ દરમ્યાન આરોગ્ય મંત્રીશ્રી સ્વ. વલ્લભભાઈ પટેલે લોકભાગીદારીથી પી.એચ.સી. અને સી.એચે.સી. બનાવવાની ઝૂંબેશ ઉપાડેલી. એના કારણે આ આરોગ્ય કેન્દ્રો બન્યાં, પરંતુ સભ્યોએ જે ચિંતા વ્યક્ત કરી તે પ્રમાણે આરોગ્ય કેન્દ્રો છે, તેમાં ગામડાના વિસ્તારોમાં અને ઉંડાણના વિસ્તારોમાં ડોકટરો નથી, પેરા મેડિકલ સ્ટાફ નથી. આ જે સાધનો આપેલાં છે તે સાધનો ચલાવવા માટે ટેકનિશીયન નથી અને નર્સિંગ સ્ટાફ નથી. તો હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે આરોગ્યના લક્ષ્યાંકો તે આરોગ્ય કેન્દ્રો કાર્યાન્વિત નહીં થવાના કારણે સિધ્ધ થઈ શકતા નથી તો તે સિધ્ધ કરવા માટે જો જરૂર પડે તો રાજય બહારના ડોકટરો દસ-અગિયાર મહિનાની કોન્ટ્રાકટ પધ્ધતિથી અને બાકીના સ્થાનિક ઉમેદવારો છે તેમના મારફતે ભરી આ આરોગ્ય કેન્દ્રોને ચાલુ કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાને માહિતગાર કરવા માગું છું કે, ડોકટર કોઈપણ હોય, આપણા રાજયના હોય કે બહારના રાજયના હોય, આપણે વોકઈન ઈન્ટરવ્યુ રાખીએ છીએ અને તેમને એક કલાકમાં ઓર્ડર આપવામાં આવે છે. એટલે કોઈપણ ડોકટર પોતાની ફરજ સ્વીકારી શકે છે. હું બીજું એ ધ્યાન દોરવા માગું છું કે દરેક જગ્યાએ સ્ટાફ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, દવાઓની સઘનતા ચોકકસપણે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. હું ધ્યાન દોરવા માગું છું કે અમે જિલ્લા પંચાયતના દરેક પ્રમુખોને જાણ કરી છે અને આ ગૃહના તમામ સભ્યો મારી લાગણી સાથે સંમત હશે કે શહેરી વિસ્તારોના પી.એચ.સી.માં ૯૫ થી ૧૦૦ ટકા સ્ટાફ ભરાયેલો છે. જયારે ઈન્ટરીયર વિસ્તારોમાં પી.એચ.સી. હોય ત્યાં ૫૦, ૬૦ કે ૭૦ ટકા સ્ટાફ ભરાયેલ છે. એટલે હમણાં અમે ઝૂંબેશ શરૂ કરેલ છે જે સ્ટાફ છે તેને ટ્રાયબલ વિસ્તાર, બોર્ડર વિસ્તાર કે રણ વિસ્તારમાં મૂકી શકાય તે પ્રકારની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

શ્રી નરેન્દ્રસિંહ મા. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે, મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે બોર્ડર વિસ્તાર દા.ત. મારા મત વિસ્તારમાં લખપત અને અબડાસા તાલુકામાં સરકાર દ્વારા ઓર્ડર કરવામાં આવેલ છે અને ડોકટરો ત્યાં હાજર થતા નથી. તો ત્યાં જે ડોકટરો હાજર થાય અને બોર્ડર વિસ્તારની અંદર જે હાજર રહે તેના માટે સરકાર તે ડોકટરો અને સ્ટાફને વધારાનું કોઈ એલાઉન્સ આપવા

માગે છે કે કેમ? લખપત તાલુકાની અંદર એકપણ સી.એચ.સી. નથી તો નવા સી.એચ.સી. ચાલુ કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહને માહિતી આપી કે આ પ્રકારની અન્ય જુદી જુદી યોજનાઓ વિચારણા હેઠળ છે. તે યોજના વિશે વિચારણા કરવામાં આવશે ત્યારે આ તમામ પાસાંઓની વિચારણા કરવામાં આવશે.

શ્રી ફતેસિંહ વ. ચૌહાણ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે પંચમહાલ જિલ્લાની કેટલી માગણીઓ આરોગ્ય કેન્દ્રો માટે આવેલી? અને તે રાજય સરકાર શરૂ કરવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કયા જિલ્લામાંથી કેટલી માગણીઓ આવી તેની માહિતી અત્યારે હોય નહીં. મે ક્હ્યું તે મુજબ રાજયમાં સાત તાલુકા એવા છે કે જે તાલુકાઓમાં અત્યારની બાકીની સ્થિતિએ વધારે સઘનતા આપવાની જરૂરિયાત છે અને તેમનું જે સૂચન છે તે ધ્યાન પર લેવામાં આવશે.

મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના વિકાસ નકશાઓ

***૯૫૨૩ શ્રી કાંતિભાઇ ત્રિ. ભીલ (નસવાડી)**: માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે-

(૧) ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજયની કેટલી મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના વિકાસ નકશાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા, અને

(૨) કઈ કઈ?

શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી :

(૧) ૨ (બે)

(૨) (૧) રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (૨) સુરત મહાનગરપાલિકા

શ્રી કાંતિભાઇ ત્રિ. ભીલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે સુરત અને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નકશા અંદાજો જે મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે તે વિકાસના નકશા બનાવવામાં આવ્યા છે તેમાં આદિજાતિ ઝૂંપડપટ્ટીઓનો સમાવેશ થાય છે કે કેમ?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દરેક શહેરમાં જે વિકાસ યોજના તૈયાર કરવામાં આવે છે તેમાં વિવિધ બાબતોનો સમાવેશ કરવામા આવે છે અને તે સ્થિતિમાં રૂડા અને સુડા વિસ્તારોમાં પણ મહાનગરપાલિકાઓમાં નબળા વર્ગના લોકોના આવસ માટેની જગ્યાઓને અલગ રીતે રાખવામાં આવી છે. રૂડા અને સુડા બંનેમાં આ પ્રકારના નબળા વર્ગના લોકોના આવાસ માટેની જમીનની જોગવાઈ રાખવામાં આવેલ છે.

શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો જે વિસ્તાર વિકાસ નકશો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે એમાં ખાસ કરીને કયા કયા વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે?

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રૂડા વિસ્તારમાં જે કરવામાં આવ્યું છે એ વિકાસ યોજનામાં રહેણાંક, વાણિજય, ઔદ્યોગિક ઝોન....

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પૂરો થાય છે.

અતારાંકિત પ્રશ્નો

(તારાંકિત પ્રશ્નોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ)

વન વિભાગ હસ્તકની જમીનમાં રસ્તા બનાવવા બાબત

૯૪૯૧**શ્રી કાંતિલાલ ધ. કચોરિયા (પાલનપુર) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) વન વિભાગ હસ્તકની જમીનમાંથી પસાર થઈ એક ગામથી બીજા ગામને સાંકળતો રસ્તો બનાવવા સરકાર દ્વારા કોઈ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને	(૧) વન વિભાગ હસ્તકની જમીનમાંથી પસાર થઈ એક ગામથી બીજા ગામને સાંકળતો રસ્તો બનાવવાની કોઈ યોજના અમલમાં નથી.
(૨) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાઈઝ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૦૩-૨૦૦૪માં રસ્તાઓ બનાવવા પાછળ	(૨) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વન વિભાગ હસ્તકની જમીનમાં રસ્તાઓના કામ માટે કોઈ ખર્ચ કરવામાં

કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?	આવેલ નથી.

જિલ્લાની સરકારી હોસ્પિટલમાં રોગી કલ્યાણ સમિતિ બનાવવા બાબત

૯૫૧**શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી(દાંતા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) જિલ્લા કક્ષાની હોસ્પિટલમાં "રોગી કલ્યાણ સમિતિ" બનાવવા સરકારે નિર્ણય કરેલ છે તે વાત સાચી છે,	(૧) હા, જી
(૨) જો હા, તો આ નિર્ણયનો અમલ કયારથી કરવામાં આવ્યો છે, અને	(૨) તારીખ ૧૪-૯-૨૦૦૪ થી
(૩) રાજ્યની કઈ કઈ હોસ્પિટલમાં આવી "રોગી કલ્યાણ સમિતિ" કયારથી કાર્યરત થઈ છે	(૩) કાર્યવાહી ગતિમાં છે.

શૈક્ષિણક સંસ્થાઓના ૨૦૦ મીટરમાં ગુટકાનું વેચાણ અટકાવવા બાબત

૮૫૬૩ **શ્રી મોહંમદફારુક હુ. શેખ(કાલુપુર) માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
શૈક્ષિણક સંસ્થાઓના ૨૦૦ મીટરના વિસ્તારમાં ગુટકાનું વેચાણ પ્રતિબંધ અન્વયે અમદાવાદ શહેરમાં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં છેલ્લા છ માસમાં કેટલી શૈક્ષિણક સંસ્થાઓ આગળ ગુટકાનું વેચાણ કરતા ઈસમો સામે શી કાર્યવાહી કરી?	અમદાવાદ શહેરમાં ૧૩૫ શૈક્ષિણક સંસ્થાઓના વિસ્તારમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હેલ્થ વિભાગ દ્વારા ચેકીંગ કરવામાં આવેલ છે. આ દરમ્યાન કોઈ ઈસમ સામે કાયર્વાહી કરવામાં આવેલ નથી. આ ચેકીંગ દરમ્યાન મળેલ ૧૩૫૪ ગુટકાઓના પાઉચ જપ્ત કરી નાશ કરવામાં આવેલ છે.

મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર દ્વારા ખરીદેલ દવાઓ અને સાધનો

૮૦૫૧ **શ્રી પરેશભાઈ ગો. વસાવા(નિઝર) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર દ્વારા ખરીદાતી દવાઓ/સાધનો માત્ર ઉત્પાદકો પાસેથી જ ખરીદવાના ઠરાવ બાદ તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ વર્ષવાઈઝ કુલ કેટલી દવાઓ/સાધનોના ટેન્ડરો બહાર પાડવામાં આવેલ હતા,

(૧) વર્ષ	બહાર પાડેલ ટેન્ડરો
૨૦૦૨-૦૩	૯૭૪
૨૦૦૩-૦૪	૮૮૮
૨૦૦૪-૦૫	૬૩૪
કુલ...	૨૪૯૬

(૨) તે પૈકી કેટલી દવાઓ/ સાધનો માટે બીલકુલ ભાવો મળેલ ન હતા,

(૨) વર્ષ	ભાવો ન મળ્યા હોય તેવી દવાઓ/સાધનોની સંખ્યા

૨૦૦૨-૦૩	૧૩૭
૨૦૦૩-૦૪	૧૦૦
૨૦૦૪-૦૫	૦૮૦

(૩) કેટલી આઈટમો માટે માત્ર એક અથવા બે-બે ટેન્ડરો મળેલા,

(૩) વર્ષ તેવી — એક અથવા બે ટેન્ડરો મળેલ આઈટમોની સંખ્યા

વર્ષ	એક અથવા બે ટેન્ડરો મળેલ તેવી આઈટમોની સંખ્યા
૨૦૦૨-૦૩	૨૮૦
૨૦૦૩-૦૪	૨૧૫
૨૦૦૪-૦૫	૨૦૮

(૪) ભાવકરાર ન થઈ શકેલ આઈટમોની જરૂરીયાત કઈ રીતે પૂરી કરવામાં આવેલ, અને

(૪) ભાવકરાર ન થઈ શકેલ દવાઓ/સર્જીકલ આઈટમો માટે જે તે માંગણી અધિકારીઓ દ્વારા તેમની ખરીદ સત્તા મર્યાદામાં જરૂરિયાત મુજબનો જથ્થો ખરીદ કરવામાં આવે છે. મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્રની કચેરી દ્વારા ભાવકરાર ન થઈ શકેલ આઈટમો માટે પુનઃટેન્ડરો મંગાવી ભાવકરારની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે.

(૫) ઉપરોક્ત નિયમ બાબત સરકાર કોઈ સમીક્ષા કરવા માંગે છે કે કેમ?

(૫) હાલની જોગવાઈમાં સમીક્ષા કરવાનું વિચારણા હેઠળ નથી.

ભાવનગર જિલ્લામાં દીપડો ધસી આવવા બાબત

૯૫૩૪ **શ્રી સુનીલ બા. ઓઝા(ભાવનગર શહેર (દક્ષિણ) : માનનીય વનમંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે : -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભાવનગર જિલ્લામાં સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ તથા ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના વર્ષમાં તા. ૩૧-૧-૦૫ સુધીમાં રહેણાંકી વિસ્તારમાં દીપડો ધસી આવવાની કેટલી ઘટના બની,	(૧) સને ૨૦૦૩-૦૪માં આવી કોઈ ઘટના બનેલ નથી જ્યારે સને ૦૪-૦૫ના વર્ષમાં તા. ૩૧-૧-૦૫ સુધીમાં આવી ૨ (બે) ઘટના બનેલ છે.
(૨) તે અંગે તુરત જ પગલાં લેવાય તે માટે સરકારે શું વ્યવસ્થા કરી છે, અને	(૨) જે વિસ્તારમાં દીપડો ધસી અવ્યાના સમાચાર મળે છે ત્યારે તુરત જ તે વિસ્તારમાં વન ખાતાના અધિકારીશ્રી/કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી દીપડાને પકડવા પાંજરા ગોઠવવાની વ્યવસ્થા કરે છે. જરૂર પડે સાસણગીર ખાતેની રીસ્કયુ ટીમની મદદ પણ લેવામાં આવે છે.
(૩) ભાવનગર ખાતે કોઈ વ્યવસ્થા સરકાર ગોઠવવા માંગે છે કે કેમ ?	(૩) ભાવનગર ખાતે નીચે મુજબની વ્યવસ્થા ગોઠવેલ છે. દીપડો ધુસી આવવાનો બનાવ બને ત્યારે સ્થાનિક આધિકારી/કર્મચારીઓ દ્વારા દીપડાને પકડવા પાંજરા ગોઠવવા અને જરૂર પડે રીસ્કયુ ટીમની મદદ લેવી.

વેરાવળ, સુત્રાપાડા અને માળીયા હાટીના તાલુકામાં પંચાયત હસ્તકના રસ્તા મંજૂર થવા બાબત

૮૪૪૬ **શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ(સોમનાથ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે : -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જૂનાગઢ જિલ્લાના વેરાવળ, સુત્રાપાડા અને માળીયાહાટીના તાલુકામાં માર્ગ અને મકાન વિભાગ (પંચાયત) દ્વારા ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ સુધીના છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તાલુકાવાર કેટલા રસ્તા મંજુર કરવામાં આવ્યા,	(૧) છેલ્લા ત્રણ વર્ષે, વર્ષ ૨૦૦૨-૦૩ થી ૨૦૦૪-૦૫માં ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં તાલુકાવાર વેરાવળ-૬, સુત્રાપાડા-૩ અને માળીયા (હાટીના)-૫ મળી કુલ ૧૪ રસ્તાના સુધારણા/નવા કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા.
(૨) કેટલા રસ્તા પૂર્ણ થયા, અને કેટલા રસ્તા બાકી છે, કયા કારણોસર બાકી છે, અને	(૨) ઉપરોક્ત ૧૪ કામો પૈકી ૨ કામો ભૌતિક રીતે પૂર્ણ, ૨ કામો પ્રગતિમાં તથા ૧૦ કામોના ટેન્ડર મંજૂરીની વહીવટી પ્રક્રિયા હેઠળ હોવાના કારણે બાકી છે.
(૩) પૂર્ણ થયેલ રસ્તાના કામો પાછળ કેટલો ખર્ચ થયો ?	(૩) ૨ પૂર્ણ થયેલ રસ્તાના કામો પાછળ રૂા. ૩૪.૦૦ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

સ્વનિર્ભર મેડિકલ કોલેજોના સંચાલકો દ્વારા પ્રવેશ પરીક્ષા

૮૯૯૨ **શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી(ડીસા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સને ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં રાજ્યની સ્વનિર્ભર મેડિકલ કોલજોના સંચાલકો દ્વારા પ્રવેશ માટેની સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર પ્રવેશ અંગેની રાજ્યની આર. જે. શાહ સમિતિ દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટી આદેશ કર્યા હતા તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો મોટા પાયે ગેરરીતીઓ થઈ તેની સામે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેવા પ્રકારના પગલાઓ આવી સ્વનિર્ભર કોલેજો સામે લેવામાં આવ્યા અને પગલાઓ ન લીધા હોય તો તેના કારણો શાં છે?	(૨) જી.એસ.એફ મેડીકલ અને પેરા મેડીકલ એસોસીએશન દ્વારા લેવાયેલ પ્રવેશ પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓ અંગે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના રિપોર્ટની વિગતો ધ્યાને લઈ નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટમાં ઇન્ટરલોક્યુટરી એપ્લીકેશન દાખલ કરેલ. નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટના ચુકાદા અનુસાર કાર્યવાહી કરી એસોસીએશન દ્વારા લેવાયેલ પરીક્ષા રદ કરવાનો નિર્ણય જસ્ટીશ આર. જે. શાહ (નિવૃત્ત) કમિટિએ લીધેલ, જે સામે એસોસીએશન દ્વારા નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટમાં ઇન્ટરલોક્યુટરી એપ્લીકેશન દાખલ કરેલ, નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટે કમિટિના નિર્ણય સામે મનાઈ હુકમ આપીને આ મેટરને લાર્જર બેન્ચ સમક્ષ મુકવાનો હુકમ કરેલ છે. આ બાબત હાલ નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટમાં પડતર છે.

દસાડા અને લખતર તાલુકામાં ટેન્ડર વગર રસ્તાના કામો

૮૦૭૮ **શ્રી મનહરલાલ મ. મકવાણા(દસાડા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા અને લખતર તાલુકામાં માર્ગ મકાન (પંચાયત) દ્વારા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫માં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં ટેન્ડરની જાહેરાત વગર કયા કયા રસ્તાઓના કામો હાથ પર લેવામાં આવ્યા,	(૧) અને (૨) રસ્તા અને નાળા બનાવવા કે પુલ/ખાસ મરામતના માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ કોઈ કામ ટેન્ડરની જાહેરાત વિના હાથ ધરેલ નથી રસ્તાની તાત્કાલિક/ચાલુ મરામતની કામગીરી તે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા હોઈ તેના નાના કામો વાર્ષિક ભાવ મંજૂર કરી કે મંજૂર કરેલ વાર્ષિક ભાવો/ભાવોએ તબક્કાવાર કામ કરવા તૈયાર થનાર ઈજારદાર/મંડળી/બેકાર ઈજનેર દ્વારા હાથ ધરેલ છે.
(૨) આ કામો કઈ કઈ એજન્સીને આપવામાં આવ્યા, અને	
(૩) રસ્તાના કામો ટેન્ડર વગર હાથ ધરી શકાય છે કે કેમ ?	(૩) રસ્તાના કામો નિયમોનુસાર નક્કી થયેલ અલગ અલગ પધ્ધતિ અનુસાર હાથ ધરી શકાય છે.

અમદાવાદ શહેરને મેગાસીટી જાહેર કરવા બાબત

૮૬૨૨ **શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઉ. વાઘેલા (શહેર કોટડા) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરને મેગાસીટી જાહેર કરવા માટે સરકારે કેન્દ્ર સરકારમાં દરખાસ્ત કરી છે કે કેમ, અને	(૧) તારીખ ૮-૯-૧૯૯૫, ૨૦-૧-૧૯૯૬, ૨૭-૨-૧૯૯૭, ૧૨-૭-૧૯૯૯, તારીખ ૧૦-૫-૨૦૦૨ તથા તા. ૧૫-૬-૨૦૦૨નાં પત્રોથી દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી.
(૨) જો હા, તો કેન્દ્ર સરકારે તેનો શું પ્રતિભાવ આપેલ છે ?	(૨) કેન્દ્ર સરકારના તારીખ ૬-૧૦-૧૯૯૫, તારીખ ૧૩-૨-૧૯૯૬ તથા તારીખ ૧૭-૮-૧૯૯૯ના પત્રોથી અમદાવાદ શહેરની વસ્તી ૧૯૯૧ની વસ્તી ગણતરી અનુસાર ૪૦ લાખથી ઓછી હોઈ દરખાસ્તનો અસ્વીકાર કર્યાની જાણ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ તારીખ ૧૦-૫-૨૦૦૨ અને તારીખ ૧૫-૬-૨૦૦૨નાં પત્રોથી કરવામાં આવેલ દરખાસ્તોનો કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ મળેલ નથી.

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગરીબ દર્દીઓને ફી માફી આપવા બાબત

૮૩૭૩ **શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા(જમાલપુર) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગરીબ દર્દીઓ માટેની ફી માફી માટે રાહતનાં રેશનકાર્ડની માંગણી કરવામાં આવે છે, તે વાત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) પ્રજાજનો પાસે રાહતના કાર્ડ હોતા નથી અને સરકારે આપવાના બંધ કર્યા છે તે સંજોગોમાં સરકારે આ ગરીબ દર્દીઓને રાહત આપવા શા પગલા ભર્યા ?	(૨) બી. પી. એલ. કાર્ડ (રાહત કાર્ડ) ધરાવતા ના હોય તેવા દર્દીઓની આર્થિક સ્થિતિ અંગે તબીબી અધિક્ષકશ્રી અને ઈન્ચાર્જ ડૉકટર પોતાની વિવેકબુધ્ધિથી નિર્ણય કરી સારવારમાં રાહત આપવામાં આવે છે.

રાજ્યના રસ્તાઓને રાષ્ટ્રીય હાઈવેમાં બદલવાની દરખાસ્તો

૮૧૯૦ **શ્રી જયંતિલાલ રા. કવાડિયા(હળવદ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યના રસ્તાઓને રાષ્ટ્રીય હાઈવેમાં બદલવાની દરખાસ્ત કેન્દ્ર સરકારમાં કરવામાં આવી છે કે, કેમ	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં રાજ્યના કયા કયા રસ્તાઓની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે,	(૨) પત્રક-અ અને પત્રક-બ મુજબ
(૩) જો હા, તો આ દરખાસ્ત કેન્દ્ર સરકારમાં કેટલા સમયથી પડતર છે, અને	(૩) આ એક સતત પ્રક્રિયા છે.
(૪) સરકાર દ્વારા આ દરખાસ્તોને મંજૂરી મળે તે માટે શા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા ?	(૪) માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી અને માન. મંત્રીશ્રી(મા.મ.)ની કક્ષાએથી સમયાંતરે ભારત સરકારમાં રજુઆતો કરવામાં આવે છે.

પત્રક-અ

અ. નં.	**રસ્તાનું નામ**	**લંબાઈ કિ. મી.**
૧	માળીયા-જામનગર-ઓખા-પોરબંદર-વેળાવળ અને ભાવનગર-વટામણ કોસ્ટલ હાઈવે.	૬૬૫.૦૦
૨	રાજકોટ-જામનગર-વાડીનાર રસ્તો	૧૫૦.૦૦
૩	રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૧૫ને ભુજ-ખાવડા ઈન્ડીયા બ્રીજ-ધર્મશાળાથી ઈન્ડીયા બોર્ડર સુધી લંબાવવો.	૧૭૦.૦૦
૪	રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૮-અ અને માંડવીથી જખૌ-નલીયા-નારાયણ સરોવર સુધી લંબાવવા.	૧૧૦.૦૦
૫	વડોદરા-પોર-શીનોર-નેત્રંગ-વ્યારા-સાપુતારા-નાશીક રસ્તાને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૮ અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૬ સાથે જોડાણ.	૨૪૫.૦૦
૬	શામળાજી-મોડાસા-ગોધરા-હાલોલ-રાજપીપળા-વાપી રાજ્ય ધોરીમાર્ગ નંબર-૫	૫૦૫.૦૦
૭	હિંમતનગર-મહેસાણા-ચાણસ્મા-રાધનપુર રાજ્ય ધોરીમાર્ગ.	૧૬૫.૦૦
૮	રાજ્ય ધોરીમાર્ગ નં.૭ અને ૧૭ સરખેજ-સાણંદ-વિરમગામ-માલવણ-ધ્રાંગધ્રા-હળવદ-માળીયાને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.૮ સાથે અમદાવાદ અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૮-કકઅક	૧૮૬.૦૦

	ને માળીયા નજીક જોડવા.	
૯	રાજકોટ-મોરબી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૮-ક્ક્અક્ર અને ૮-ક્ક્બક્ર ને જોડતો રાજ્ય ધોરીમાર્ગ નં. ૨૪ અને તેને નવલખી બંદર સુધી લંબાવવા.	૧૦૯.૦૦
૧૦	બગોદરા-વટામણ-તારાપુર-બોરસદ-પાદરા-કરજણ રસ્તો.	૧૩૦.૦૦
૧૧	રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૧૪ ઉપર પાલનપુરથી ગાંધીનગર-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૮-ક્ક્સીક્ર સુધી લીંક રોડ.	૧૫૦.૦૦
૧૨	નડીયાદ-કપડવંજ-મોડાસા	૧૩૫.૦૦
૧૩	અમદાવાદ-ધોળકા-વટામણ.	૮૦.૦૦
	કુલ	૨૮૦૦.૦૦

પત્રક-બ

અ. નં.	રસ્તાનું નામ	લંબાઈ કિ. મી.
૧	ગાંધીનગર-ગોઝારીયા-વિસનગર-વડનગર-ખેરાલુ-દાંતા-અંબાજી આબુ રોડ	૧૭૦.૦૦
૨	હિંમતનગર-વિજાપુર-વિસનગર-ઉંઝા-પાટણ-સમી-હારીજ-રાધનપુર રોડ	૬૦.૦૦
૩	અમદાવાદ-વિરમગામ-શંખેશ્વર-રાધનપુર	૮૦.૦૦
૪	પાલનપુર-ચંડીસર-દાંતીવાડા-પાંથાવાડા-મંડાર-જાલોર-જોધપુર રોડ	૬૫.૦૦
૫	પાલનપુર-ડીસા-ધાનેરા-નેનાવા બોર્ડર-સાંચોર રોડ	૬૦.૦૦
૬	ભાભર-સિંહોરી-પાટણ-સિધ્ધપુર-વલસાણા-ઈડર-હિંમતનગર રોડ	૨૦૦.૦૦
૭	ભાભર-દિયોદર-ખેમાણા-મુડેઠા-બુકોલી-આનીવાડા-ચારૂપ-પાટણ-ચાણસ્મા-હારીજ-મહેસાણા રોડ	૨૨.૦૦
૮	પાલનપુર-ડીસા-થરાદ-રાજસ્થાન બોર્ડર	૬૨.૦૦
૯	ભચાઉ-ભુજ-પાનેધ્રો રોડ	૧૩૦.૦૦
૧૦	ચિત્રોડ-રાપર-ધોલાવીરા રોડ	૧૨૦.૦૦
૧૧	સિંધવાડા-સુઈગામ	૪૦.૦૦
૧૨	જામનગર-જુનાગઢ	૧૩૦.૦૦
૧૩	રાજકોટ-અમરેલી	૭૨.૦૦
૧૪	બગોદરા-ધંધુકા-વલ્લભીપુર-ઢસા-અમરેલી	૧૮૦.૦૦
	કુલ	૧૩૯૨.૦૦

ગોઠડા ગામના સર્વે નંબર ૧૦૪/૨૧થી ૧૦૪/૨૪નો એવોર્ડ આપવા બાબત

૯૪૫૬ **શ્રીમતી રમીલાબેન રા. દેસાઈ(ખેરાલુ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) શું એ વાત સાચી છે કે સતલાસણા થી આંબાઘાટા રોડ (અંબાજી સ્ટેટ હાઈવે) સતલાસણા તાલુકાના ગોઠડા ગામના સર્વે નં. ૧૦૪/૨૧ તથા સર્વે નં. ૧૦૪/૨૪માંથી પસાર થાય છે.	(૧) ના, જી.
(૨) જો હા, તો આ જમીનના એવોર્ડ ક્યારે, કોના નામે અને કેટલા રૂપિયાના થયેલ છે, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આ અંગે કોઈ ફરિયાદ મળેલ છે, કે કેમ?	(૩) હા, જી.

બાવળા તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનના બાંધકામની મંજૂરી

૯૨૪૬ **શ્રી કાંતિલાલ રા. લકુમ(બાવળા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) બાવળા તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનમાં બાંધકામની મંજૂરી ક્યારે મળી, અને	(૧) વહીવટી મંજૂરી તા. ૧૩-૧૨-૨૦૦૦થી મળેલ છે.
(૨) આ બાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવાનું અને કયાં સુધીમાં પૂરૂ કરવાનું આયોજન છે?	(૨) આ કામ કરાર મુજબ તા. ૧૧-૨-૦૫થી શરૂ કરી તા. ૧૦-૧૧-૦૫ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

વડોદરા જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાના કામો

૮૭૩૪ **શ્રી દિલુભા ટે. ચુડાસમા(વડોદરા (ગ્રામ્ય) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ વડોદરા જિલ્લામાં કુલ કેટલા ગામોને કેટલા કિ.મી. પાકા રસ્તાથી જોડવામાં આવ્યા, અને	(૧) ૨૫ ગામ/પરાને કુલ ૪૩.૧૯ કિ.મી. પાકા રસ્તાથી જોડવામાં આવ્યા છે.
(૨) આ પૈકી વડોદરા તાલુકામાં કેટલા?	(૨) આ પૈકી વડોદરા તાલુકામાં ૧ ગામ અને ૨ પરાને ૪.૩૦ કી.મી.ના પાકા રસ્તાથી જોડવામાં આવ્યા છે.

કોરનેટવર્ક સુવિધાઓ માટે માર્ગ અને મકાન વિભાગનું આયોજન

૯૫૧૮ **શ્રી વેચાતભાઈ હ. બારિયા (પાવી-જેતપુર) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**

તા. ૩૧-૧-૦૫ સુધીમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં કોર નેટવર્ક માળખાગત સુવિધાઓ માટે માર્ગ અને મકાન વિભાગે શું આયોજન વિચારેલ છે ?	માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા કોર નેટવર્કનું માળખા પ્રાથમિક રીતે નિયત કરેલ છે અને આ માર્ગોની નાણાંકીય ઉપલબ્ધતા અનુસાર અગ્રતા આપી સુધારણા કરવા આયોજન વિચારેલ છે.

શાળા આરોગ્ય ચકાસણી કાર્યક્રમ

૯૫૫૨ **શ્રી શંકરભાઈ લ. ચૌધરી(રાધનપુર) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યની શાળા આરોગ્ય ચકાસણી કાર્યક્રમ હેઠળ વર્ષ ૨૦૦૪માં કેટલા બાળકોના આરોગ્યની તપાસણી કરવામાં આવી, અને	(૧) ૮૪,૪૫,૦૩૮
(૨) આ તપાસણી અનુસંધાને કયા પ્રકારની કાર્યવાહી થઈ?	(૨) બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી દરમ્યાન પ્રથમ સ્થળ સારવાર સંદર્ભ સેવા અન્વયે જીલ્લાની સીવીલ હોસ્પિટલમાં સારવાર, ચશ્મા વિતરણ, ખાસ પ્રકારની આરોગ્ય સેવાની જરૂરિયાતવાળા બાળકોને હ્રદય, કિડની તથા કેન્સરની હોસ્પિટલોમાં તજજ્ઞો દ્વારા સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવે છે.

રાજ્યમાં લુપ્ત થતી આયુર્વેદ ઔષધિઓ

૯૪૭૧ **શ્રી બિમલ શાહ(કપડવંજ) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં લુપ્ત થતી આયુર્વેદ વનૌષધી તથા ફાર્મસી, દ્વારા વધુ ન વપરાતી વનૌષધીઓના ઉત્પાદન વૃદ્ધી માટે કોઈ યોજના કાર્યરત છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તેની વિગતો શું છે?	(૨) રાજ્યમાં સ્ટેટ મેડીસીનલ પ્લાન્ટ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે. જેના મારફત ૫૭ પ્રકારની આયુર્વેદ વનૌષધિના વાવેતર માટે સહાય આપવાની યોજના અમલમાં મૂકી છે.

ધંધુકા, રાણપુર અને બરવાળા તાલુકાની વનીકરણ માટે સોંપેલ જમીન

૯૫૪૯ **શ્રી ભરતભાઈ પંડયા (ધંધૂકા) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ધંધુકા, રાણપુર અને બરવાળા તાલુકાના કેટલા ગામોએ ડીસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ વનીકરણ માટે કેટલી જમીન જંગલ ખાતાને સોંપેલી છે, અને	(૧) ધંધુકા, રાણપુર અને બરવાળા તાલુકાના કુલ-૭૦ ગામોએ ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ વનીકરણ માટે કુલ ૮૩૨.૫૦ હેકટર જમીન ઠરાવ કરી જંગલ ખાતાને વાવેતર માટે આપેલ છે.
(૨) તેમાંથી જંગલ ખાતાએ કેટલી જમીન ગામને પરત કરી?	(૨) તેમાંથી જંગલ ખાતાએ વનીકરણ કરેલ ૪.૦૦ હેકટર જમીન ગાંફ ગામને પરત કરેલ છે.

રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર અને ગોંડલ શહેરમાં ગેરકાનુની કતલખાનાં બંધ કરવા બાબતે

૮૨૨૦ **શ્રીમતી જસુબેન સ. કોરાટ(જેતપુર) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં જેતપુર તથા ગોંડલના શહેરી વિસ્તારોમાં ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા અને કઈ કઈ જગ્યાએ ગેરકાનુની કતલખાના તથા મીટ શોપ ચાલે છે.	(૧) એક પણ નહીં.
(૨) તેને બંધ કરવા શી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) તેને ક્યાં સુધીમાં બંધ કરી દેવામાં આવશે.	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કચ્છ જિલ્લામાં મંજૂર કરવામાં આવેલ માર્ગો બાબત

૯૫૪૧ **શ્રી ગોપાલભાઈ ગા. ધુઆ(મુંદ્રા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧/૧૨/૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કચ્છ જીલ્લામાં મુન્દ્રા, ભુજ, અંજાર તથા ગાંધીધામ તાલુકાના કેટલા કયા કયા ગ્રામ્ય માર્ગોને મંજૂર કરવામાં આવેલ છે,	(૧) સામેલ પત્રક-૧ મુજબ
(૨) મંજૂર કરવામાં આવેલ માર્ગો ઉપર કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ, અને	(૨) રૂા. ૯૭.૮૮ લાખ
(૩) મંજૂર થયેલા માર્ગોનું કામ કયા તબક્કે છે?	(૩) ૫-કામ પૂર્ણ ૮-કામ પ્રગતિમાં ૩-કામના ટેન્ડર મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં ૧-કામનું ટેન્ડર મંજૂર

પત્રક-૧

અ.નં.	**તાલુકો**	**રસ્તાનું નામ**
૧	મુંદ્રા	એસ.આર.ટુ ભદ્રેશ્વર ચોખંડા મહાદેવ રોડ
૨	મુંદ્રા	બેરાજા મોટી ખાખર રસ્તા ઉપર નાળાકામ-પુર દુરસ્તી
૩	મુંદ્રા	નાના કપાયા પ્રતાપપર બોરાણા રસ્તા ઉપર નાળાકામ-પુર દુરસ્તી
૪	ભુજ	એસ.આર.ટુ કેલા માનકુવા નિરોણા રસ્તે નાળાકામ
૫	ભુજ	એસ.આર.ટુ ચકાર બંધરા રોડ
૬	ભુજ	એસ.આર.ટુ હોડકો શેરવો રોડ
૭	ભુજ	તુગા જુણા રોડ ઉપર નાળાકામ-પુર દુરસ્તી
૮	ભુજ	રતનાલ ધાણેટી રોડ ઉપર નાળાકમ-પુર દુરસ્તી
૯	ભુજ	ખાવડા લોડીયા અધૌ રોડ
૧૦	અંજાર	એસ.આર.ટુ કુકમા ચકાર ચંદીયા રોડ
૧૧	અંજાર	સતાપર અજાપર મોડવદર રોડ

૧૨	અંજાર	ભીમાસર પશુડા રોડ ઉપર નાળાકામ-પુર દુરસ્તી
૧૩	અંજાર	રતનાલ ચંદીયા ભલોટ રોડ ઉપર નાળાકામ-પુર દુરસ્તી
૧૪	અંજાર	વીડી દેવળીયા કુંભારીયા રોડ
૧૫	ગાંધીધામ	અંતરજાલ સોસાયટી એરીયા રોડ
૧૬	ગાંધીધામ	કીડાણા સોસાયટી એરીયા રોડ
૧૭	ગાંધીધામ	ગળપાદર સોસાયટી એરીયા રોડ

સાબરકાંઠા જિલ્લાના સ્ટેટ અને પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓને પેવર કામ

૯૨૩૮ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા(ભીલોડા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સાબરકાંઠાના જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામા ડીસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ સ્ટેટ અને પંચાયત હસ્તકનાં કુલ કેટલા કિ.મી.ના સ્ટેટ હાઈવે, એમ.ડી.આર. ઓ.ડી. આર. અને વી.આર.ના રસ્તાઓ છે,	(૧) રાજ્ય ધોરી માર્ગઃ ૬૨.૭૭ કિ. મી. મુખ્ય જીલ્લા માર્ગ : ૧૨૩.૩૫ કિ. મી. અન્ય જીલ્લા માર્ગ : ૫૭.૪૨ કિ. મી. ગ્રામ્ય માર્ગ : ૧૭૫.૩૫ કિ. મી.
(૨) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ડામર સપાટી કર્યા વગરના કેટલા કિ. મી.ના રસ્તાઓ છે, અને	(૨) ૩૪૯.૭૩ કિ. મી.
(૩) આ રસ્તાઓને પેવરકામ કરવાનું સરકારનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ?	(૩) ઉપરોક્ત પૈકી ૫૯.૫૫ કિ. મી. ના રસ્તાને પેવર કરવાનું આયોજન છે.

સાબરમતી શુધ્ધિકરણ યોજના

૮૯૭૨ **શ્રી પ્રદિપસિંહ ભ. જાડેજા(અસારવા) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં સાબરમતી નદી શુધ્ધીકરણ યોજના માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કેટલી રકમ મળી છે,	(૧) રૂા. ૮૨૯૧.૮૬ લાખ
(૨) આ કામો અંગે કેટલો ખર્ચ થયેલ છે, અને	(૨) રૂા. ૯૮૬૯.૪૫ લાખ
(૩) આ કામો કયારે પુરાં થવાની ધારણા છે ?	(૩) ડીસેમ્બર ૨૦૦૪માં પ્રથમ તબક્કાના તમામ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

રાજકોટ જિલ્લામાં ડીપ્થેરીયાને કારણે બાળકોના થયેલ મૃત્યુ

૮૯૬૫ **શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા(જસદણ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૧-૧-૦૪ થી ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં રાજકોટ જિલ્લામાં ડીપ્થેરીયાના કારણે કેટલા બાળકોના મૃત્યુ થયા, અને	(૧) ૮ (આઠ)

(૨) આ રોગને કાબુમાં લેવા સરકારે શાં પગલાં લીધા ?

(૨) જિલ્લા આર.સી.એચ. અધિકારી અને સંબંધિત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની ટીમ મારફતે તુરત જ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લઈ સર્વે કરાવી અરક્ષિત બાળકોને ડીપ્થેરીયાની રસીથી રક્ષિત કરવામાં આવેલ છે.

આયુર્વેદ દવાઓનું ઉત્પાદન કરતા એકમો બંધ થવા બાબત

૯૫૩૦ **શ્રી નારાયણભાઈ લ. પટેલ(ઉંઝા)** : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં આયુર્વેદ દવાઓના ઉત્પાદન કરતા ફાર્મસી એકમો કેન્દ્ર સરકારના નવીન નિયમો અનુસાર બંધ છે તે હકીકત ખરી છે, અને

(૨) જો હા, તો સરકાર ઉત્પાદન ફરી શરૂ થાય તે માટે શું આયોજન કરવા માંગે છે ?

જવાબ

(૧) હા. કેટલાક એકમો બંધ છે.

(૨) કેન્દ્ર સરકારના નવા નિયમો અનુસાર કાયદાની જોગવાઈ સંતોષતા ન હોય તેઓને પૂર્તતા કરવા માટે જરૂરી માહિતી સાથે માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ છે. આ એકમોને શકય તેટલી ઝડપથી પૂર્તતા કરવા પણ સમજણ આપેલ છે.

સોનગઢ પેપર મીલ્સને વાંસ કાપવાની પરવાનગી

૮૯૯૮ **શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે(ડાંગ-વાંસદા)** : **માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) સોનગઢ પલ્સ પેપર મીલ્સને રાજયના કયા કયા જિલ્લાઓમાંથી માનવેલ અને કાર્ટસ વાંસ કાપવાની રાજ્ય સરકારે કરેલ કરારમાં કેટલા વર્ષની મુદત સુધીની મંજૂરી આપેલ હતી, અને

(૨) મુદત પૂરી થયા પછી કેટલા વરસની મુદત વધારી આપવામાં આવી છે ?

જવાબ

(૧) રાજ્યના વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, સુરત, ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લામાંથી કાટસ અને માનવેલ વાંસ કાપવાનો કરાર રાજ્ય સરકારે તા. ૨૫-૧૧-૬૦ના રોજ ૪૦ વર્ષ માટે કરેલ હતો.

(૨) ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના તા. ૮-૧-૦૧ના ઠરાવથી આ કરારની મુદત ૧૦ વર્ષ લંબાવવાનું નક્કી થયેલ છે. તે સંદર્ભમાં દર વર્ષે વન વિભાગ દ્વારાએ મંજૂરી આપવામાં આવે છે. હાલમાં આવી મંજૂરી તા. ૩૦-૬-૦૫ના સમય સુધીની આપેલી છે.

જુનાગઢ જિલ્લાની ઉના રેફરલ હોસ્પિટલમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ

૮૨૫૧ **શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ(ઉના)** : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) જુનાગઢ જિલ્લાની ઉના રેફરલ હોસ્પિટલમાં અને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સંવર્ગવારમંજૂર થયેલ જગ્યાઓ પૈકી સંવર્ગવાર કેટકેટલી જગ્યાઓ ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા સમયથી ખાલી છે,

જવાબ

(૧) સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ

અ.નં.	સંવર્ગ	સંખ્યા	કેટલા સમયથી ખાલી
૧	વર્ગ-૧	૩	૧ ૧૩-૩-૨૦૦૨ ૨ ૧-૮-૨૦૦૪

			૨ ૧-૮-૨૦૦૪
૨	વર્ગ-૨	૧	૦ ૧-૯-૨૦૦૪
૩	વર્ગ-૩	૪	૧ ૩-૩-૮૮ ૧ ૪-૬-૨૦૦૨ ૧ ૧-૧૧-૨૦૦૨ ૧ ૧-૧૧-૨૦03
૪	વર્ગ-૪	૨	૧ ૨૮-૧૦-૨૦03 ૧ ૧-૧૧-૨૦૦૪

(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા સરકારે શી કાર્યવાહી કરી, અને

(૨) ૧. વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ની જગ્યાઓ નિયમિત તેમજ એડહોક ધોરણે ભરવા ઉપરાંત વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુથી ભરવા પ્રયત્ન કર્યા.

૨. વર્ગ-૩ તથા વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ ભરવાની કાર્યવાહી ગતિમાં છે.

(૩) કેટલી જગ્યાઓ સંવર્ગવાર ભરવામાં આવી ?

(૩) સંવર્ગવાર ભરાયેલ જગ્યાઓ

અ.નં.	સંવર્ગ	સંખ્યા
૧	વર્ગ-૨	૨
૨	વર્ગ-૩	૯
૩	વર્ગ-૪	૮

કચ્છ જિલ્લામાં ગાંડો બાવળ કાપવા છૂટછાટો આપવા બાબત

૯૫૦૭ **શ્રી શીવજીભાઈ ક. આહીર(ભૂજ) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) કચ્છ જિલ્લામાં ગાંડો બાવળ કાપવા માટે સને ૨૦૦૪ની સાલમાં વિશેષ છુટછાટો આપવામાં આવી છે તે હકીકત સાચી છે,

(૨) જો હા, તો તેમાં ભૂજ તાલુકામાં આવેલ બન્ની વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી તે હકીકત સાચી છે,

(૩) જો હા, તો તેના શા કારણો છે, અને

(૪) આ ફરિયાદ નિવારવા સરકારે શા પગલા લીધા છે ?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨), (૩) અને (૪) કચ્છ જિલ્લાનો ભૂજ તાલુકાનો બન્ની વિસ્તાર રક્ષિત જંગલ તરીકે જાહેર થયેલ હોવાથી તેના માટે તે અંગેના નિયમો લાગુ પડે છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં ટ્રાયબલ સબ પ્લાન હેઠળની ગ્રાન્ટ

૮૩૨૦ **શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ(વાગરા) : માનનીય આદિજાતિ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભરૂચ જિલ્લામાં સને ૨૦૦૩-૦૪ અને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં ટ્રાયબલ સબ પ્લાન હેઠળ સદરવાઈઝ કેટ-કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને	(૧) ભરૂચ જિલ્લામાં સને ૨૦૦૩-૦૪માં આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા-યોજના હેઠળ કુલ રૂા. ૨૯૭૫.૪૦ લાખની ગ્રાન્ટ અને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કુલ રૂા. ૧૮૬૪.૫૨ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે. સદરવાર ફાળવેલ ગ્રાન્ટનું પરિશિષ્ટ-એ આ સાથે સામેલ છે.
(૨) કેટલી ગ્રાન્ટ તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં રીલીઝ કરવાની બાકી છે ?	(૨) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં રૂા. ૧૦૨૦.૩૫ લાખની ગ્રાન્ટ રીલીઝ કરવાની બાકી રહે છે.

પરિશિષ્ટ--એ

વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪ અને વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ (ડીસે.૦૪ અંતિત) સદરવાર ફાળવેલ ગ્રાન્ટનું પત્રક

(રૂા. લાખમાં)

અ. નં.	મુખ્ય સદર	વર્ષ-૨૦૦૩-૦૪ માં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	વર્ષ-૨૦૦૪-૦૫		
			જોગવાઈ	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ (ડીસે.૦૪ અંતિત)	બાકી ગ્રાન્ટ
૧	કૃષિ અને સંલગ્ન સેવાઓ	૨૬૫.૦૪	૪૦૩.૨૪	૨૨૦.૫૬	૧૮૨.૬૮
૨	ગ્રામ વિકાસ અને સમુહ વિકાસ	૫૨૬.૧૮	૫૭૨.૧૮	૪૧૫.૨૬	૧૫૬.૯૨
૩	સિંચાઈ અને પુર નિયંત્રણ	૦.૦૦	૦.૫૦	૦.૦૦	૦.૫૦
૪	વિજળી શક્તિ	૬૨.૪૮	૦.૦૦	૧૦.૫૦	(-)૧૦.૫૦
૫	ઉદ્યોગ અને ખનિજ	૬.૭૦	૨૨.૦૩	૨.૦૮	૧૯.૯૫
૬	પરિવહન અને સંચાર માર્ગ પુલો	૧૨૫.૨૨	૧૦૩.૫૦	૯૧.૦૩	૧૨.૪૭
૭	સામાજિક અને સમુહ સેવાઓ	૭૪૦.૧૭	૭૩૩.૩૨	૨૮૪.૮૩	૪૪૮.૪૯
૮	સામાન્ય સેવાઓ વિકેન્દ્રીત જિલ્લા આયોજન	૧૭૧.૭૦	૧૮૦.૫૦	૧૭૫.૯૦	૪.૬૦
૯	બીજરૂપ અંદાજપત્ર	૯૯.૩૯	૨૨૧.૯૯	૧૬૪.૯૫	૫૭.૦૪
૧૦	ગુજરાત પેટર્ન	૯૭૮.૫૨	૬૪૭.૬૧	૪૯૯.૪૧	૧૪૮.૨૦
	કુલ..	૨૯૭૫.૪૦	૨૮૮૪.૮૭	૧૮૬૪.૫૨	૧૦૨૦.૩૫

જી. જી. હોસ્પિટલ, જામનગરમાં સીટી સ્કેન મશીન બંધ હોવા બાબત

૮૭૮૭ **શ્રી મુળુભાઈ હ. બેરા(ભાણવડ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જામનગર ખાતે આવેલ જી. જી.હોસ્પિટલમાં સીટી સ્કેન મશીન ક્યારે ફાળવવામાં આવ્યું,	(૧) સીટી સ્કેન મશીન તા. ૨૬-૭-૨૦૦૦ના રોજ ફાળવવામાં આવ્યું.
(૨) આ મશીનની ફાળવણી થયા બાદ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૨) સીટી સ્કેન મશીન તા. ૨૬-૭-૨૦૦૦થી કાર્યરત છે.
(૩) જો ના, તો આ મશીન ક્યારે ચાલુ કરવામાં આવશે?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

વ્યારા તાલુકાના ચાકધરા ગામથી સરા-કેવડીનો બિસ્માર રસ્તો

૯૫૧૬ **શ્રી પુનાભાઈ ધે. ગામીત(વ્યારા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વ્યારા તાલુકાના ચાકધરા ગામથી સરા-કેવડીનો રસ્તો હાલમાં બિસ્માર હાલતમાં છે તે સરકાર જાણે છે,	(૧) રસ્તો વાહન વ્યવહાર યોગ્ય છે.
(૨) જો હા, તો આ રસ્તો બનાવવા માટે સરકારનું શું આયોજન છે, અને	(૨) અને (૩) હાલ રસ્તાનો જોબનંબર આપવાનું આયોજન નથી.
(૩) આ રસ્તાને જોબનંબર આપીને સરકાર કેટલા સમયમાં રસ્તો બનાવવા માંગે છે ?	

કરજણ તાલુકાના કરજણનગરમાં રેલ્વેનો ઓવરબ્રીજ ખંડિત થવા બાબત

૯૫૦૧ **શ્રી નરેશકુમાર મી. કનોડિયા(કરજણ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કરજણ તાલુકાના કરજણનગરમાં થોડા સમય પગલાં બનાવેલ રેલ્વેનો ઓવરબ્રીજ તાજેતરમાં ખંડિત થઈ ગયો છે તો આ પુલની સરકારે કોઈ તપાસ હાથ ધરી છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) આ બ્રીજને ફરીથી પૂર્વવત કરવા માટે સરકાર તરફથી કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે કે કેમ?	(૨) આ બ્રીજને પૂર્વવત કરવાની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે.

જામનગરની જી. જી. હોસ્પિટલ, જામનગરમાં ગાયનેકોલોજી વિભાગમાં બાળક બદલાઈ જવા બાબત

૯૫૫૩ **ડૉ. દિનેશ પરમાર(જામનગર (રુરલ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) જામનગર જી. જી. હોસ્પિટલમાં તાજેતરમાં ગાયનેકોલોજી વિભાગમાં બાળક બદલી જવા અંગે કોઈ ઘટના બનેલ કે કેમ,	(૧) ના, જી.
(૨) તે અંગે વાસ્તવિકતા શું છે,	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) બાળક બદલી જવા અંગેની ગંભીર ફરીયાદ બાદ બાળકનું ડી. એન. એ. ટેસ્ટ કરવામાં આવેલ કે કેમ, અને	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૪) જો ના, તો કયા કારણોસર ડી. એન. એ. ટેસ્ટ નથી કરવામાં આવેલ ?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અમદાવાદ શહેરમાં શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઝૂંપડપટ્ટીના વિકાસ માટે આયોજન

૮૬૩૨ **ડૉ. જીતેન્દ્રભાઈ બા. પટેલ(સાબરમતી)** : **માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સને ૨૦૦૫ના વર્ષને રાજ્ય સરકારે શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે જાહેર કરેલ છે, તે હકીકત સાચી છે,	(૧) હા. જી, રાજ્ય સરકારે ૨૦૦૫ના વર્ષને શહેરી વિકાસ વર્ષ ૨૦૦૫ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય કરેલ છે.
(૨) જો હા, તો અમદાવાદ શહેરમાં ઝૂંપડપટ્ટીના વિકાસ માટે સરકારની કઈ કઈ યોજનાઓ છે, અને	(૨) (૧) નેશનલ સ્લમ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ (૨) વાલ્મિકી આંબેડકર આવાસ યોજના (૩) સુવર્ણ જ્યંતિ શહેરી રોજગાર યોજના (૪) ગંદા વિસ્તાર વાતાવરણ સુધારણાલક્ષી યોજના.
(૩) તે માટે કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવશે ?	(૩) મહાનગરપલિકા દ્વારા ઉક્ત યોજનાઓના પ્રોજેકટ રજૂ થયેથી તે મુજબની રકમ ફાળવવામાં આવશે.

સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬નું વર્ષ શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવવા બાબત

૮૪૮૭ **શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી(અમરેલી)** : **માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) શુ એ વાત સાચી છે કે રાજ્ય સરકાર સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬નું વર્ષ શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવવા માંગે છે, અને	(૧) રાજ્ય સરકારે વર્ષ ૨૦૦૫ના વર્ષને શહેરી વિકાસ વર્ષ ૨૦૦૫ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય કરેલ છે.
(૨) જો હા, તો તેમાં કેવા પ્રકારના કામોને અગ્રતા આપવામાં આવશે ?	(૨) વિવિધ વિકાસકીય અને જનભાગીદારી તેમજ લોકસુખાકારીના કામો હાથ ધરાશે.

શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સંસ્થાનું સર્વેક્ષણ

૯૫૦૦ **શ્રી રતિલાલ ગો. સુરેજા(માણાવદર) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) આરોગ્ય વિભાગના શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ અંગે રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની કોઈ સંસ્થાએ તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સર્વેક્ષણ હાથ ધરેલું કે કેમ, અને	(૧) ના, જી.
(૨) જો હા, તો તે અંગે તેનો અભિપ્રાય શું છે ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી, ટંકારા અને મોરબી તાલુકામાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાના રસ્તા

૮૦૮૯ **શ્રી મોહનભાઈ ક. કુંડારીયા(ટંકારા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીના છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા,	(૧) મંજુર કરેલ ૩૩ રસ્તા પૈકી ૨૬ રસ્તા બનાવવામાં આવ્યા,
(૨) તે પૈકી પડધરી, ટંકારા અને મોરબી તાલુકામાં તાલુકાદીઠ તૈયાર કરવા પાત્ર રસ્તાઓ કેટલા કિલોમીટરના છે, અને	(૨) મંજુર કરેલ ૩૩ રસ્તાઓ પૈકી

અ.નં.	તાલુકો	કરવાપાત્ર	રસ્તા
		સંખ્યા	લંબાઈ
૧.	પડધરી	૭	૨૫.૧૪
૨.	ટંકારા	૩	૮.૯૦
૩.	મોરબી	૧૨	૨૨.૮૨
	કુલ	**૨૨**	**૫૬.૮૬**

(૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ આ પૈકી કેટલા કિલોમીટરના રસ્તાઓના કામો કરવામાં આવ્યા અને કેટલા બાકી છે ?

(૩)

અ.નં	તાલુકો	પૂર્ણ	કરેલ રસ્તા	બાકી	રસ્તા
		સંખ્યા	લંબાઈ (કી.મી.)	સંખ્યા	લંબાઈ (કી.મી.)
૧.	પડધરી	૫	૧૪.૭૯	૨	૧૦.૩૫
૨.	ટંકારા	૨	૬.૫૭	૧	૨.૩૩
૩.	મોરબી	૯	૧૪.૨૬	૩	૮.૫૬
	કુલ	૧૬	૩૫.૬૨	૬	૨૧.૨૪

સાબરમતી શુધ્ધિકરણ યોજના

૮૫૮૯ **શ્રી ભાવિનભાઈ ન. શેઠ(એલીસબ્રીજ) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સાબરમતી શુધ્ધિકરણ યોજના માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલી રકમ મળેલ છે,	(૧) રૂ. ૮૨૯૧.૮૬ લાખ
(૨) આ કામો અંગે કેટલો ખર્ચ થયેલ છે, અને	(૨) રૂ. ૯૮૬૯.૪૫ લાખ
(૩) અને તમામ કામો કયારે પૂરા થવાની ધારણા છે ?	(૩) ડીસેમ્બર ૨૦૦૪માં પ્રથમ તબક્કાના તમામ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

રાજકોટ-ભાવનગર શહેરમાં ચક્ષુ બેંક શરૂ કરવા બાબત

૯૨૫૧ **શ્રી પ્રવિણભાઈ મો. માકડિયા(ઉપલેટા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સરકાર દ્વારા રાજ્યનાં રાજકોટ અને ભાવનગર સહિતના શહેરોમાં સરકારી ચક્ષુબેંક શરૂ કરવાનું આયોજન છે કે કેમ,	(૧) રાજકોટમાં ચક્ષુબેંક કાર્યરત છે અને અન્ય શહેરો માટે હાજી.
(૨) જો હા, ક્યારથી ચક્ષુ બેંક શરૂ થશે, અને	(૨) ભાવનગર, સુરત અને વડોદરામાં શક્ય તેટલું જલ્દી.
(૩) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી ચક્ષુ બેંકો છે અને તેમાં કેટલા ચક્ષુઓનું દાન મળેલ છે?	(૩) રાજ્યમાં આઠ ચક્ષુ બેંકો છે જેમાં ૨૫૬૩ ચક્ષુદાન મળેલ છે.

નેશનલ સ્લમ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેકટ હેઠળ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની નગરપાલિકાઓને આપેલ ગ્રાન્ટ

૮૩૯૯ **શ્રી ધનરાજભાઈ કેલા(વઢવાણ) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થતિએ નેશનલ સ્લમ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેકટ યોજના હેઠળ સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાંથી કામગીરી પૂર્ણ ન થવાને કારણે કેટલી નગરપાલિકાઓ પાસેથી કેટલી રકમની રીકવરી કરવામાં આવી,	(૧) વઢવાણ નગરપાલિકા પાસેથી ૯૭,૫૩,૧૯૦/- ની રકમની રીકવરી કરવામાં આવેલ છે.
(૨) કેટલી નગરપાલિકાઓ દ્વારા આ યોજના હેઠળ ફરી રકમની માંગણી કરવામાં આવી, અને	(૨) એકપણ નહી.
(૩) રીકવરી કરેલ રકમમાંથી કઈ કઈ નગરપાલિકાને કેટલી કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી, અને	(૩) રીકવરી કરેલ રકમમાંથી કોઈ નગરપાલિકાને રકમ ચૂકવવામાં આવી નથી.
(૪) બાકીની નગરપાલિકાને સરકાર રકમ ચૂકવવા માંગે છે કે કેમ?	(૪) દરખાસ્ત મળેથી ક્રમાનુસાર મંજૂર કરવાની વિચારણા કરવામાં આવશે.

નગરપાલિકાઓમાં વહીવટદારની નિમણુંક

૮૦૨૧ **શ્રી ધનસુખભાઈ ના. પટેલ(ઓલપાડ) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કુલ કેટલી નગરપાલિકાઓ હતી અને તે પૈકી જિલ્લાવાર કેટલી નવી નગરપાલિકાઓ બનાવવામાં આવી, અને	(૧) ૧૪૧ નગરપાલિકાઓ, નવી નગરપાલિકાઓ એક પણ બનાવેલ નથી.
(૨) કેટલી નગરપાલિકાઓમાં વહીવટદારની નિમણુંક કરવામાં આવી ?	(૨) એકપણ નહીં.

ગાંધીનગર તાલુકામાં પંચાયત અને રાજ્ય હસ્તકના રોડને જોબનંબર આપવા બાબત

૮૧૪૫ **ડૉ. સી. જે. ચાવડા(ગાંધીનગર) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગાંધીનગર તાલુકામાં સને ૨૦૦૩-૦૪ના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પંચાયત વિભાગ અને રાજ્ય હસ્તકના કુલ કેટલા રોડને જોબનંબર આપવામાં આવેલ છે,	(૧) ૧૩ રસ્તાનાં કામો.
(૨) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ જોબનંબર આપેલા રોડની કામગીરી કયા તબક્કે છે, અને	(૨) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ ૧૧ કામો પૂર્ણ અને ૨ કામો પ્રગતિ હેઠળ.
(૩) અધૂરી રહેલ જોબનંબરની કામગીરી ક્યારે પૂર્ણ થશે?	(૩) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ અધુરા-૨ કામો પૂર્ણ થયેલ છે.

નવા સચિવાલયમાં ઉર્જા બચાવવા નવીન ટ્યુબલાઈટો નાખવા બાબત

૮૬૫૯ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધી. પરમાર(ભાદરણ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નવા સચિવાલય ખાતે ઉર્જા બચાવવા માટે સને ૨૦૦૩-૨૦૦૪ અને ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના વર્ષમાં તા.૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ દરેક વિભાગોમાં નવીન ટ્યુબો નાખવામાં આવી છે. તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) અને (૨) ના, જી.
(૨) જો હા, તો આ ટ્યુબોની કુલ કિંમત કેટલી અને તે અન્વયે વિજ બચતમાં કેટલી રકમનો ઘટાડો થયો?	

અમદાવાદ શહેરમાં પ્રદૂષણ ઘટાડવા એકશન પ્લાન

૮૧૬૩ **ડૉ. માયાબેન સુ. કોડનાની(નરોડા) : માનનીય વન અને પયાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદ શહેરનું પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે સરકારે એકશન પ્લાન ઘડ્યો છે તે હકીકત સાચી છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તેનું અમલીકરણ હાલ કયા કયા તબક્કે છે, અને	(૨) એકશન પ્લાનમાં જણાવેલ સમયબધ્ધ કાર્યક્રમ મુજબ વિવિધ વિભાગો દ્વારા હવા-પ્રદૂષણ નિયંત્રણ એકશન પ્લાન તેના અમલીકરણના વિવિધ તબક્કામાં છે.
(૩) આ પ્રદૂષણ ઘટાડવા સરકારે શાં શાં પગલાં લીધાં?	(૩) હવા પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે સરકારે લીધેલાં પગલાંઓમાં સી.એન.જી. આધારિત વાહન-વ્યવહાર માટે જરૂરી માળખાકીય સુવિધાઓની શરૂઆત, ઓટો રીક્ષા અને જાહેર પરિવહનના સાધનો સી.એન.જી. આધારિત કરવા અને આ અંગે ટાસ્ક-ફોર્સની રચના, નવાં અને ચાલુ વાહનો અંગે ધુમાડાના નવા ધોરણોનું અમલીકરણ, બળતણમાં થતી ભેળસેળ અટકાવવા સંયુકત ટુકડીઓ દ્વારા સઘન ઝૂંબેશ તેમજ ઉદ્યોગજન્ય પ્રદૂષણ અંગે હવા-અધિનિયમ ૧૯૮૧ હેઠળ ઉદ્યોગોનું મોનીટરીંગ અને કસૂરવાર એકમો સામે કાયદાકીય પગલાંઓનો સમાવેશ થાય છે.

વિજપડીથી સાતપડા-લુવાર રસ્તાનું લાંબા સમયથી અધુરુ રહેલ કામ

૮૦૪૦ **શ્રી ગોરધનભાઈ પ્રા. ઝડફિયા(રખિયાલ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ભાવનગર જિલ્લાના ગારીયાધાર, પાલિતાણા અને સાવરકુંડલાથી વિજપડીને જોડતા વિજપડી, સાતપડા, લુવાર સુધીના રસ્તાનું કામ ૨૦ વર્ષથી શરૂ થયેલ છે તે છતાં આજ સુધી કામ પૂર્ણ ન થવાના શાં કારણો છે,	(૧) પ્રશ્ન હેઠળનો વિજપડીથી સાતપડા વાયા લુવારા રસ્તાની ૪૪.૭૦ કિ.મી.ની લંબાઈમાં ત્રણ રસ્તાનો સમાવેશ થાય છે. આ રસ્તાના કામો તબક્કાવાર જમીન સંપાદન કરી ગ્રાંટની ઉપલબ્ધતા મુજબ હાથ ધરવાનું આયોજન કરેલ હોઈ પૂર્ણ થયેલ નથી.
(૨) આ રસ્તાનું કામ આટલા લાંબા સમયથી શરૂ થવા છતાં પૂર્ણ ન થવા માટે જવાબદારો સામે સરકારે શાં પગલાં લીધાં, અને	(૨) કોઈ અધિકારી/કર્મચારી સામે પગલાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આ રસ્તાને ડામર સપાટીવાળો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?	(૩) કોર્ટનો મનાઈ હુકમ હોય, સમય મર્યાદા આપવી શક્ય નથી.

રાજયમાં રકતપિત્તના કેસો

૯૪૫૫ **શ્રી અંબાલાલ આ. રોહિત(સોજીત્રા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) રાજ્યમાં રકતપિત્તના કેસો હજુ પણ જોવા મળે છે તે વાત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો રકતપિત્તની નાબુદી માટે રાજ્ય સરકારે શા પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે ?	(૨) રાજ્ય સરકારે રક્તપિત્તની નાબુદી માટે નીચે મુજબના પ્રયાસો હાથ ધરેલ છે. - રકતપિત્તના કેસો શોધી કાઢવા માટે રકતપિત્ત નિર્મુલન અભિયાન અને નવતર રકતપિત્ત નિર્મુલન અભિયાન હાથ ધર્યું. - સ્પેશ્યલ એકશન પ્રોજેકટ ફોર એલીમીનેશન ઓફ લેપ્રેસી (સાપેલ પ્રોજેકટ). - રકતપિત્ત જનજાગૃત્તિ અભિયાન દ્વારા રોગ અને સારવાર વિષે માહિતીનો પ્રચાર-પ્રસાર. - રકતપિત્ત દર્દીઓના કાર્યકરોને રકતપિત્તની તાલીમ આપી.

ભાવનગરથી વડોદરા ધોલેરા ટૂંકા માર્ગને નેશનલ હાઈવેમાં સમાવેશ કરવા બાબત

૮૭૧૬ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી(ભાવનગર શહેર (ઉત્તર) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભાવનગરથી વડોદરા વાયા ધોલેરા-તારાપુર ટૂંકા માર્ગને નેશનલ હાઈવેમાં સમાવેશ કરવાની ભલામણ રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકારને કયારે કરી, અને	(૧) છેલ્લે તા. ૨૭-૮-૨૦૦૪ના રોજ.
(૨) આ બાબતમાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી શો પ્રતિભાવ મળેલ છે ?	(૨) તેઓએ જણાવેલ છે કે જ્યારે ભારત સરકાર હયાત રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગના નેટવર્કને વધારવાની પરિસ્થિતિમાં હશે ત્યારે ગુજરાતની માંગણીઓ, અન્ય રાજ્યોની માંગણીઓની સાથે જરૂરીયાત તેમજ ભલામણ અનુસાર નાણાંની ઉપલબ્ધીને ધ્યાને લઈ તેમજ અન્ય અગ્રિમતાઓને ધ્યાને લઈ યોગ્ય વિચારણામાં લેવામાં આવશે.

રાજ્યમાં એઈડઝના દર્દીઓ

૮૩૮૫ **શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ. સોલંકી(ઘોઘા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્યમાં એઈડઝના કેટલા દર્દીઓ મળેલ છે.	(૧) ૧૩૭૫
(૨) તે પૈકી ભાવનગર જિલ્લામાં આ રોગના કેટલા દર્દીઓ મળેલ છે, અને,	(૨) ૪૫
(૩) સરકારે આ રોગને અટકાવવા શા પ્રયત્નો કરેલ છે ?	(૩) (૧) આ રોગની કોઈ દવા કે રસી ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે લોકોમાં આ રોગ વિષે જાગૃતિ લાવવા વિવિધ માધ્યમો જેવા કે ટીવી, રેડીયો, બસ, પેનલ, વર્તમાનપત્રો વગેરેમાં જાહેરાત દ્વારા

	પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. (૨) દર્દીઓને કાઉન્સેલીંગની સેવાઓ મળી રહે તે માટે રાજ્યની સરકારી મેડીકલ કોલેજો અને જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં કાઉન્સેલીંગ સેન્ટરો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. (૩) રાજ્યની સરકારી અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત કુલ ૬૨ બ્લડ બેંકોને મફત એચ. આઈ. વી. અને એચ. સી. વી. ટેસ્ટ કીટ આપવામાં આવે છે. (૪) સરકારી મેડીકલ કોલેજો તેમજ જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં જાતીય રોગોની સારવાર આપવામાં આવે છે. (૫) જાન્યુઆરી-૨૦૦૫થી એઈડઝના દર્દીઓને એન્ટીરીટ્ર રોવાયરલ દવાઓ મળી રહે તે માટે બી.જે. મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે એક સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.

ફિઝીયોથેરાપીના અનુસ્નાતક અભ્યાસ ક્રમ શરૂ કરવા બાબત

૯૪૫૯ **શ્રી મોહનભાઈ ધ. ઢોડિયા(મહુવા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
રાજ્યમાં ફિઝીયોથેરાપીના અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા માટે કોઈ વિચારણા કરવામાં આવેલ છે કે કેમ ?	સરકારશ્રી દ્વારા ફિઝીયોથેરાપી કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે ૧૫ વિદ્યાર્થીઓની પ્રવેશ ક્ષમતા સાથે અનુસ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે.

માંડલ, દેત્રોજ અને વિરમગામ તાલુકામાં વન વિભાગની આરક્ષિત જમીન

૮૫૯૭ **શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ(માંડલ) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
માંડલ, દેત્રોજ અને વિરમગામ તાલુકામાં વન વિભાગની કેટલી જમીન આરક્ષિત છે ?	અમદાવાદ જિલ્લામાં માંડલ, દેત્રોજ અને વિરમગામ તાલુકામાં જંગલ ખાતાની કોઈ આરક્ષિત જમીન આવેલ નથી.

ઝઘડીયા અને વાલીયા તાલુકામાં રસ્તાની આજુબાજુમાં નડતા વૃક્ષો દૂર કરવા બાબત

૯૫૩૭ **શ્રી છોટુભાઈ અ. વસાવા(ઝગડિયા) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભરૂચ જીલ્લાના ઝઘડીયા અને વાલીયા તાલુકામાં રસ્તાઓની આજુબાજુ ઘણા નડતરરૂપ વૃક્ષો આવેલા છે, એ વાત સાચી છે, અને	(૧) ના. જી.
(૨) જો હા, તો સરકાર આ નડતરરૂપ વૃક્ષો કેટલા સમયમાં દૂર કરવા માંગે છે ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

રાજ્યમાં મહેસૂલી ગામોને પાકા રસ્તાથી જોડવા બાબત

૯૪૬૪ **શ્રી કાંતિભાઈ ભા. તડવી(સંખેડા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧-૦૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કુલ કેટલા મહેસૂલી ગામોને પાકા રસ્તાઓથી જોડવામાં આવ્યા છે, અને	(૧) ૧૭૭૯૩ મહેસૂલી ગામોને મેટલ/ડામર સપાટીથી જોડવામાં આવેલ છે.
(૨) બાકી રહેતા ગામોને પાકા રસ્તાઓથી જોડાવાનું શું આયોજન છે ?	(૨) જોડી શકાય તેવા બાકીના ગામોના ૧૨ કામો પ્રગતિમાં છે અને ૩ કામોના ટેન્ડર મંજૂરીમાં છે. આ ૧૫ ગામો જોડવાનું કામ વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર સામે વીજીલન્સમાં થયેલ ફરિયાદ

૮૦૫૩ **શ્રી છબીલદાસ ના. પટેલ(માંડવી) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ વીજીલન્સ કમિશનમાં મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર સામે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમ્યાન ખરીદીમાં થયેલ અનિયમિતતા/ભ્રષ્ટાચાર/નિયમ ભંગ અંગે કુલ કેટલી ફરિયાદો થયેલ છે,	(૧) ૮ (આઠ).
(૨) તે પૈકી કેટલી ફરિયાદો બાબતે તપાસ થયેલ છે.	(૨) ફરિયાદો અંગે તપાસ ચાલુ છે.
(૩) તે અંગે વીજીલન્સ કમિશ્નરનો કોઈ રીપોર્ટ સરકારને મળેલ છે કે કેમ,	(૩) ના, જી.
(૪) તે રીપોર્ટમાં કોઈ કર્મચારી/અધિકારીની જવાબદારી નક્કી થયેલ છે કે કેમ, અને	(૪) તપાસ ચાલુ હોઈ જવાબદારી નિયત થયેલ નથી.
(૫) તે બાબતે સરકારે કેવાં પગલાં લીધાં ?	(૫) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ભરૂચની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સિવિલ સર્જનની ખાલી જગ્યા

૯૫૫૫ **શ્રી રમેશભાઈ ના. મિસ્ત્રી(ભરૂચ)** : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સિવિલ સર્જનની જગ્યા ખાલી છે, તે ક્યારે ભરવામાં આવશે ?	(૧) બનતી ત્વરાએ.

છોટાઉદેપુરની રેફરલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરની ખાલી જગ્યા

૮૯૯૦ **શ્રી શંકરભાઈ વી. રાઠવા(છોટાઉદેપુર)** : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં છોટાઉદેપુરની રેફરલ હોસ્પિટલમાં કેટલા ડોક્ટર્સની જગ્યા ખાલી છે, આ જગ્યા કેટલા વખતથી ખાલી છે ?	(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં છ ડોકટર્સની જગ્યા ખાલી છે. અધિક્ષક વર્ગ-૧ તા. ૧૩-૧૦-૦૪ થી ગાયનેકોલોજીસ્ટ વર્ગ-૧ તા. ૨-૨-૦૩ થી પેડીયાટ્રીશીયન વર્ગ-૧ તા. ૧૨-૧૨-૦૧ થી ઓર્થોપેડીક સર્જન વર્ગ-૧ તા. ૪-૮-૯૮ થી નિવાસી તબીબી અધિકારી વર્ગ-૧ તા. ૩૧-૩-૦૪થી * તબીબી અધિકારી વર્ગ-૨ ૨૦-૧૦-૦૪ થી * તબીબી અધિકારી વર્ગ-૨ની જગ્યા તા. ૧-૨-૦૫ થી ભરાયેલ છે.
(૨) આદિવાસી વિસ્તારમાં સ્વેચ્છાએ આવવા માટે તૈયાર થાય તેમ કરવા સરકારે કોઇ પ્રયત્ન કર્યો છે, ખરો, અને	(૨) રૂા. ૫૦૦/- ગ્રામ્ય ભથ્થુ પ્રોત્સાહન રૂપે ચૂકવવામાં આવે છે.
(૩) આ જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?	(૩) યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી.

ચોટીલા સાયલા તાલુકામાં રસ્તાના કામો થવા બાબત

૮૮૧૩ **શ્રી પોપટભાઈ સ. જીંજરિયા(ચોટીલા)** : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ચોટીલા સાયલા તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪માં કયા કયા રસ્તાના કામો મંજૂર થયા છે, અને	(૧) પત્રક મુજબ.
(૨) આ કામો ક્યારે પૂર્ણ થશે ?	(૨) ચૌદ (૧૪) કામો પૈકી બાર (૧૨) કામો પૂર્ણ, બે (૨) કામો એપ્રિલ ૨૦૦૫ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

પત્રક

<u>ચોટીલા-સાયલા તાલુકામાં રસ્તાના કામો થવા બાબત</u>

૧. રસ્તાનું નામ ચોટીલા : તાલુકો

૧. ચોટીલા-આણંદપુર, જસદણ રોડ (રા)
૨. ધ્રાંગધ્રા-કોઢ-સરા-તરણેતર-ચોટીલા-થાન રોડ (રા.)
૩. ઉડવી-વરમાધાર-એપ્રોચ રોડ (રા)
૪. નવા ગામ-સરસાણા રોડ (રા)
૫. ગુંદા જીવાપર-આણંદપુર રોડ (રા)
૬. અકાળા-હીરાસર રોડ (રા)

સાયલા તાલુકો

૧. સાયલા-સુદામડા-પાળીયાદ રોડ (રા)
૨. મઢાદ-મોટા એપ્રોચ રોડ (રા)
૩. ગોસળ એપ્રોચ રોડ (રા)
૪. લીબાળા-નડાળા રોડ
૫. ધજાળા-ઢોકવાળી-કેશવાળી રોડ (રા)

૬. ગંગાજળ-નાનામાત્રા રોડ પર કોઝ વેનું કામ (પં.)
૭. સુદામડા-ધાંધલપુર રોડને જોડતો ધજાળા એપ્રોચ રોડ (પં)
૮. સુદામડા-ધાંધલપુર રોડ પર નાળા-કોઝવે સુધારણાનું કામ (પં)

કલોલ શહેરમાં રેલ્વે ઉપર ઓવરબ્રીજ બનાવવા બાબત

૮૯૮૫ **ડૉ. અતુલ કે. પટેલ(કલોલ)** : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કલોલ શહેરમાંથી માણસા રોડ ઉપર આવતા રેલ્વે ઉપર ઓવરબ્રીજ બનાવવાનું આયોજન છે કે કેમ,અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો કેટલા સમયમાં ?	(૨) ૧૯ માસમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

અમરેલી શહેર અને રાજકોટ શહેરમાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ

૮૯૬૯ **શ્રી ધીરૂભાઈ હ. ગજેરા(સુરત શહેર (ઉત્તર)** : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ અમરેલી અને રાજકોટ શહેર અને તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ મંજુર થયેલ છે અને તે પૈકી કેટલી ભરાયેલ છે,	(૧) અમરેલી અને રાજકોટ શહેર અને તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર નથી.
(૨) આ ખાલી જગ્યા ન ભરવાના શાં કારણો છે, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આ જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાં આવશે ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

સોનગઢની સેન્ટ્રલ પેપરમીલનો કરાર

૮૯૭૧ **શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ(રાપર)** : માનનીય વન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સોનગઢની સેન્ટ્રલ પેપરમીલ્સની સાથે ગુજરાતની વન પેદાશ વાંસ કાપી લઇ જવાનો કરાર પૂરો થયેલ નવો કરાર કરવામાં વિલંબના શાં કારણો છે,	(૧) દર વરસે સેન્ટ્રલ પેપરમીલને સરકારશ્રી દ્વારા વાંસ કાપવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવે છે.
(૨) વિલંબના સમય દરમિયાન લઇ જવાયેલ વાંસ પર કોઇ ભાવ વધારો લેવાયો છે, અને	(૨) હા, જી.
(૩) વિલંબીત સમયગાળા દરમિયાન કેટલા વાંસ કાપીને ટન દીઠ કેટલી કિંમતે અપાયા ?	(૩) વિલંબીત સમયગાળા દરમ્યાન નીચે મુજબ રોયલ્ટી લેવામાં આવે છે.

ક્રમાંક	વર્ષ	કાઢવામાં આવેલ વાંસ ટુકડાનો જથ્થો મે. ટન	રોયલ્ટી પ્રતિ મે.ટન	કુલ વસુલેલ રોયલ્ટી રૂપિયા
(૧)	૨૦૦૧-૨૦૦૨	૧૦૨૪૭૩.૯૨૫ બળેલા-૮૩.૫૪૦	૧૯૩.૩૩ ૯૬.૬૬	૧૯૮૧૧૨૮૩ ૮૦૭૫
				૧૯૮૧૯૩૫૮
(૨)	૨૦૦૨-૨૦૦૩	૧૦૭૭૩૭.૭૮૫ બળેલા-૪૦.૦૧૦	૨૧૨.૬૬ ૧૦૬.૩૩	૨૨૯૧૧૫૧૭ ૪૨૫૪
				૨૨૯૧૫૭૭૧
(૩)	૨૦૦૩-૨૦૦૪	૮૨૦૦૭.૭૦૦ બળેલા-૯૩.૭૩૦	૨૪૦ ૧૨૦	૧૯૬૮૧૮૪૮ ૧૧૨૪૭
				૧૯૬૯૩૦૯૫

મહાનગરપાલિકાઓમાં ઇ-ગર્વનન્સ પ્રથા અપનાવવા બાબતે

૯૫૨૭ **શ્રી પુનમ ર. પરમાર(પાદરા)** : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧-૦૫ની સ્થિતિએ રાજ્યની કઇ કઇ મહાનગરપાલિકાઓમાં ઇ-ગર્વનન્સ પ્રથા અપનાવી છે, અને

(૨) મહાનગરપાલિકાઓમાં ઇ-ગર્વનન્સમાં કઇ કઇ બાબતોને આવરી લેવામાં આવી છે ?

જવાબ

(૧) મહદ અંશે સર્વે મહાનગરપાલિકાઓએ ઇ-ગર્વનન્સ પ્રથા આપનાવી છે.

(૨) સામાન્ય રીતે નીચે દર્શાવેલ બાબતોને ઇ-ગર્વનન્સ પ્રથા હેઠળ આવરી લેવાય છે :-

ફરિયાદ નોંધણી, બિલ્ડીંગ પ્લાનની મંજૂરી, જન્મ મરણની નોંધણી, જન્મ મરણ સર્ટીફીકેટ, ગુમાસ્તા ધારા અન્વયે નોંધણી તથા લાયસન્સ રીન્યુની કાર્યવાહી, પ્રોપર્ટી ટેક્ષ, વ્હીકલ ટેક્ષ, હોકર્સ લાયસન્સ, આકારણીનું સ્ટેટસ અને છેલ્લી સ્થિતિ જાણવાની સવલત, ઓક્ટ્રોય બાબત તેમજ વહીવટી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

નડીયાદ તાલુકાના આલજડા ગામે શેઢી નદી ઉપરના પુલનું કામ

૮૪૨૪ **શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર(મહુધા)** : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ તાલુકાના આલજડા ગામે શેઢી નદીનું પુલનું કામ ક્યારે પુર્ણ કરવામાં આવશે?

(૨) ટેન્ડરનું કામ કયા વર્ષમાં થયેલ છે, અને

(૩) આ પુલના કામમાં વિલંબ થવાના કારણો શું છે ?

જવાબ

(૧) કામ ૨૦૦૫-૨૦૦૬ના વર્ષમાં પુર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

(૨) સને ૧૯૯૯.

(૩) પુલના કામમાં વિલંબના કારણો.

(૧) ફાઉન્ડેશન સ્ટેટામાં ફેરફાર થવાથી.

(૨) શેઢી કેનાલમાંથી વધુ પડતા તથા અનિયમિત પાણી છોડવાથી એપ્રોચના કામમાં

વિલંબના કારણો.

(૧) એપ્રોચની પથરેખામાં આવતા વૃક્ષોની મંજૂરી મળવામાં વિલંબ થવાથી.

(૨) એપ્રોચની પથરેખામાં ખાનગી મકાનો આવતા ખાનગી જમીન સંપાદન કરવાની થતાં.

(૩) એપ્રોચ માટે જમીન ઉપલબ્ધ હતી. તે કામમાં ધીમી પ્રગતિના લીધે.

ગાંધીનગર તાલુકામાં આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ

૯૪૬૧ **શ્રી જગદીશ ઠાકોર(દહેગામ)** : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

જવાબ

(૧) ખાલી જગ્યાઓ

સંવર્ગ	સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર	પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર
વર્ગ-૧	૦	૦
વર્ગ-૨	૧	૦
વર્ગ-૩	૨	૪
વર્ગ-૪	૫	૨૦

પ્રશ્ન

(૨) કેન્દ્રવાર મંજુર મહેકમ શું શું છે અને હાજર મહેકમ શું શું છે ?

જવાબ

(૨)

સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર	મંજુર મહેકમ	હાજર મહેકમ
સાદરા	૨૮	૨૫
ચાંદખેડા	૨૭	૨૨
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર	મંજુર મહેકમ	હાજર મહેકમ
અડાલજ	૯	૭
ડભોડા	૯	૭
વડોદરા	૯	૬
ઉવારસદ	૯	૫
સુઘડ	૯	૬
આદરજ	૯	૬
ઉનાવા	૯	૫
રૂપાલ	૯	૬

(૩) આ જગ્યાઓ કેન્દ્રવાર ક્યારથી ખાલી છે,

(૩)

સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ	વર્ગ	ક્યારથી ખાલી
સાદરા	વર્ગ-૨	૨૨-૬-૦૪
	વર્ગ-૩	૨-૧૧-૦૪
	વર્ગ-૪	૩૧-૩-૯૯
ચાંદખેડા	વર્ગ-૩	૩૦-૧૦-૦૨
	વર્ગ-૪	૫-૩-૯૧, ૨૦-૧૦-૦૩, ૬-૧૧-૦૪
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ	**વર્ગ**	**ક્યારથી ખાલી**
ઉવારસદ	વર્ગ-૩	૧૯૯૭થી
સુઘડ	વર્ગ-૩	૧૯૯૭થી
ઉનાવા	વર્ગ-૩	૧૯૯૭થી
રૂપાલ	વર્ગ-૩	૧૯૯૭થી
વડોદરા	વર્ગ-૪	૧૬-૧-૦૧
ઉવારસદ	વર્ગ-૪	૧૬-૧-૦૧
આદરજ	વર્ગ-૪	૧૬-૧-૦૧
અડાલજ	વર્ગ-૪	૧૯૯૩થી
ડભોડા	વર્ગ-૪	૧૯૯૩થી
વડોદરા	વર્ગ-૪	૧૯૯૩થી
ઉવારસદ	વર્ગ-૪	૧૯૯૩થી
સુઘડ	વર્ગ-૪	૧૯૯૩થી
આદરજ	વર્ગ-૪	૧૯૯૩થી
રૂપાલ	વર્ગ-૪	૧૯૯૩થી

(૪) આ જગ્યાઓ ભરવા સરકારે શાં શાં પગલાં ભર્યા, અને

(૪) (૧) વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ની જગ્યાઓ નિયમિત તેમજ એડહોક ધોરણે ભરવા ઉપરાંત વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુથી ભરવા પ્રયત્ન કર્યા.

(૨) વર્ગ-૩ તથા વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ ભરવાની કાર્યવાહી ગતિમાં છે.

(૫) આ જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે?

(૫) સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન નીતિ, કાર્યભારણને ધ્યાને લઇ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી ભરતી ત્વરાએ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

થયેથી બનતી ત્વરાએ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

ભૂકંપગ્રસ્ત શહેરોમાં પુનઃ વસનની ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપની દ્વારા કાર્યવાહી

૯૪૬૭ **શ્રી ભરત બારોટ(દરિયાપુર-કાઝીપુર) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા** કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યના ભૂકંપગ્રસ્ત શહેરોમાં પુનઃવસવાટ અંગે ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપની દ્વારા કેટલી રકમના કામો હાથ ધરેલ છે.	(૧) રૂા. ૪૧૯.૦૨ કરોડ.
(૮) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ આ કામો અંગે કેટલો ખર્ચ થયેલ છે, અને	(૭) રૂા. ૨૧૦.૬૨ કરોડ.
(૯) આ તમામ કામો કયારે પુરા થશે ?	(૮) આ તમામ કામો જુન-૨૦૦૬ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

ગુટકાના સેવનથી નોંધાયેલા કેન્સરના કેસો

૮૨૯૦ **શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિધ્ધપુર) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ડીસેમ્બર-૦૪ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રજ્યમાં ગુટકાના સેવનથી કેટલા કેન્સરના કેસો નોંધાયા, અને	(૧) ૨૯૪૪
(૨) ગુટકાના સેવનથી કેટલી વ્યકિતઓના મરણ થયા.	(૨) ૬૫

લીંબડી તાલુકામાં રોડ રીપેર કરવા બાબત

૮૫૨૭ **શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ(લીંબડી) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૧/૪/૦૪ થી ૩૧/૧૨/૦૪ સુધીમાં લીંબડી તાલુકામાં કેટલા પંચાયત અને સ્ટેટ હસ્તકના રોડ રીપેર કરવામાં આવેલા છે;	(૬) લીંબડી તાલુકામાં પંચાયત હસ્તકના બે રસ્તાઓ ખાસ મરામત સદરે રીકારપેટ કરવામાં આવેલ છે. સ્ટેટ હસ્તક ખાસ મરામત સદરે કોઈ રસ્તો રીકારપેટ કરવામાં આવેલ નથી. ચાલુ મરામત સતત ચાલતી પ્રક્રિયા હોઈ જરૂરીયાત અને ગ્રાટની ઉપલબ્ધતા મુજબ ચાલુ મરામતમાં રસ્તા રીપેર કરવામાં આવે છે.
(૨) કેટલા રોડ નવા બનાવેલ છે, અને	(૨) નવા રોડ બનાવેલ નથી.

(૩) રોડ રીપેરીંગ તથા નવા રોડ બનાવવા માટે કેટલી ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી છે ?	(૩) તાલુકાવાર કે રોડવાર ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવતી નથી, પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાને રૂા. ૧૩૪૮ લાખની ગ્રાન્ટ મરામત માટે ફાળવવામાં આવી છે.

ખેડા અને માતર તાલુકામાં રસ્તાઓ રીપેર કરવા બાબત

૯૪૯૫ **શ્રી રાકેશ રાવ(માતર) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ખેડા અને માતર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના રસ્તાઓ ઓ.એન.જી.સી.ના ભારે વહનોના કારણે તૂટી ગયા છે, તે હકીકત સરકાર જાણે છે, અને	(૧) મા. મ. વિભાગ હસ્તકના રસ્તાઓને ભારે વાહનોથી નુકસાન થાય છે.
(૨) જો હા, તો સરકાર આ રસ્તાઓનું રીપેરીંગ કામ કે નવા રસ્તા કરવા ઓ.એન.જી.સી. ના સહયોગથી કયાં સુધીમાં કરવા માંગે છે ?	(૨) ઓ.એન.જી.સી. તરફથી સહયોગ આપવામાં આવશે તો રસ્તાઓની સુધારણા તબક્કાવાર કરવામાં આવશે.

અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલના મડદાઘરમાંથી માનવ અંગોની ચોરી

૮૩૪૧ **શ્રી દોલતભાઈ પરમાર(વડગામ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાશનું પોસ્ટ મોર્ટમ કર્યા પછી મડદાઘરમાંથી માનવ અંગોચોરી છુપીથી લઈ જવાના અને વેચવાના કેટલા બનાવો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલા ત્રણ વર્ષમાં સરકારના ધ્યાને આવ્યા છે,	(૧) એકપણ નહિ.
(૨) આ અંગેની વિગતો શું છે,	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) માનવ અંગો ચોરવા બાબતે કેટલા લોકો પકડાયા; અને	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૪) સિવિલ હોસ્પિટલના ફરજચૂક જવાબદાર અધિકારીઓ સામે શાં પગલાં લીધાં ?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

તલાલા, સુત્રાપાડા અને વેરાવળ તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ડોકટર, નર્સની ખાલી જગ્યા

૯૫૪૪ **શ્રી ગોવિંદભાઈ વ. પરમાર(તલાલા) :માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) તારીખ ૩૦-૧૧-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ તલાલા, સુત્રાપાડા, અને વેરાવળ તાલુકામાં પ્રાથમિક અને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં કેટલા ડોકટરો-નર્સોની કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૧) ખાલી જગ્યાની માહિતી.

તાલુકાનું નામ	ખાલી જગ્યાની સંખ્યા			
	ડૉક્ટર		નર્સ	
	પીએચસી	સીએચસી	પીએચસી	સીએચસી
તલાલા	૦	૨	૦	૦
સુત્રાપાડા	૨	૩	૦	૭
વેરાવળ	૧	૦	૦	૦

(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૨) સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન નીતિ, કાર્યભારણ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી બનતી ત્વરાએ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

રાજ્યમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું ઓછું પ્રમાણ

૯૪૮૧ **શ્રીમતી રમીલાબેન બે. બારા(ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) રાજ્યમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું જાતિ પ્રમાણ નીચું છે તે હકીકત સાચી છે, અને

(૧) હા.

(૨) જો હા, તો તે સમકક્ષ લાવવા સરકાર દ્વારા શાં પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે?

(૭) (૧) રાજ્યમાં પી.એન.ડી.ટી. એકટના અસરકારક અમલ માટે એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી, એડવાઈઝરી કમિટિ, સ્ટેટ સુપરવાઝરી બોર્ડ, સ્ટેટ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટીની રચના કરવામાં આવેલ છે.

૨. જીનેટીક કાઉન્સિલ, સેન્ટર, લેબોરેટરી જેવી સંસ્થાઓની નોંધણી ફરજીયાત કરવામાં આવેલ છે.

૩. પી.એન.ડી.ટી કાયદાનો ભંગ કરનારા ૧૪ સંસ્થાઓ/ડોકટરો સામે કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવેલ છે.

૪. પી.એન.ડી.ટી. એકટ અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે, પોસ્ટર્સ, સ્ટીકર્સ, હેન્ડબીલ, દૂરદર્શન પર સ્પોટ, આકાશવાણી કાર્યક્રમ, ટીન પ્લેટ વર્કશોપ (કાર્યશાળા), વસ્તી આયોગ અને એન.જી.ઓ./સંસ્થાઓનાં સહયોગ દ્વારા જુદા જુદા કાર્યક્રમો યોજી જનજાગૃતિ લાવવા સઘન પ્રયત્ન કરેલ છે.

સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં એમ્બ્યુલન્સ તથા ડ્રાઈવરની સંખ્યા

૯૨૩૫ **શ્રી મનીષ ન. ગીલીટવાલા(સુરત શહેર (પૂર્વ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નવી સિવિલ હોસ્પિટલ, સુરતમાં ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ એમ્બ્યુલન્સવાન કેટલી છે,	(૧) ત્રણ.
(૨) તે અન્વયે ડ્રાઈવરોની સંખ્યા કેટલી છે, અને	(૨) પાંચ ડ્રાઈવરો કામગીરી બજાવે છે.
(૩) આવી એમ્બ્યુલન્સવાનો દર્દીઓને લાભ આપવાને બદલે ખાનગી કામોમાં વધુ ફરે છે, તેવી ફરીયાદ અન્વયે સરકારે શાં પગલાં લીધાં ?	(૩) આવી કોઈ ફરીયાદ નોંધાયેલ નથી તેથી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પાલીતાણાની માનસિંહજી હોસ્પિટલમાં ડોકટરોની ખાલી જગ્યા

૮૭૫૧ **શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા(પાલીતાણા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પાલીતાણાની માનસિંહજી હોસ્પિટલમાં કુલ કેટલા ડોકટરોની મંજૂર થયેલ જગ્યાઓ છે,	(૧) અને (૨) (see table below)
(૨) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ ની સ્થિતિએ તે પેકી કુલ કેટલી જ્ગ્યાઓ પુરાયેલી છે,	
(૩) બાકીની જગ્યા કયારે પુરવાનું આયોજન છે.	(૮) યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી.

(૧) અને (૨)

સંવર્ગ	મંજુર થયેલ જગ્યા	ભરાયેલ જગ્યા
વર્ગ-૧	૪	૧
વર્ગ-૨	૪	૩

ગુડા વિસ્તારમાં નગર રચના યોજનાઓ

૯૫૨૫ **શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ(વાઘોડિયા) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગાંધીનગર શહેરના 'ગુડા' વિસ્તારમાં કેટલી નગર રચના યોજનાઓ બનાવવાનું આયોજન છે,	(૧) ૧૯ (ઓગણીસ)
(૨) 'ગુડા' વિસ્તારમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી નગર રચના યોજનાઓ બની છે, અને	(૨) ૦૨ (બે).
(૩) બાકીની કયા તબક્કે છે ?	(૩) બાકી રહેલ ૧૭ (સત્તર) નગર રચના યોજના પૈકી. ૧. ૦૨(બે) મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના લોકોના વાંધા સુચનો મેળવવા અધિનિયમની કલમ-૪૨(૧) હેઠળ પ્રસિધ્ધ કરી. ૨. ૦૭ (સાત) નગર રચના યોજના બનાવવા માટે ઈરાદો જાહેર કરેલ છે. ૩. ૦૩ (ત્રણ) નગર રચના યોજનાઓ મુખ્ય નગર નિયોજકશ્રીનો પરામર્શ મેળવવા માટે પાઠવેલ છે, અને ૪. ૦૫(પાંચ) નગર રચના યોજનાઓમાં

પરામર્સ મેળવવા માટે સર્વેની કાર્યવાહી જારીમાં છે.

સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં કર્મચારીઓ દ્વારા બેદરકારી દાખવવા બાબતે થયેલ ફરિયાદ

૮૯૯૭ **શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર(કડી) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દર્દીઓને અપાતી સારવારમાં કર્મચારીઓ દ્વારા બેદરકારી દાખવવા સંદર્ભે સરકારને કેટલી ફરિયાદો મળી, અને	(૧) ૨૧ ફરિયાદો.
(૨) આ ફરિયાદ સંદર્ભે શાં પગલાં ભર્યા ?	(૨) આ ફરિયાદોમાંથી ૧૦ ફિરયાદોનો સંપૂર્ણ અહેવાલ મળેલ છે તે પૈકી (૧) ૪ ફરિયાદોને સમર્થન ન મળતાં દફતરે કરેલ છે. (૨) ૨ ફરિયાદોમાં સંબંધકર્તાને તાકીદ આપવામાં આવેલ છે. (૩) ૨ ફરિયાદોમાં સંબંધકર્તાને કારણદર્શક નાટીસ આપેલ છે. (૪) ૧ ફરિયાદ બાબતે તબીબી અધિકારીશ્રી વર્ગ-૨ અને વર્ગ-૩ના ચાર કર્મચારીઓની બદલીઓ કરવામાં આવેલ છે. (૫) ૧ ફરિયાદ બાબતે નિયમ ૯ x ૧૦ હેઠળ ખાતાકીય તપાસ ચાલુ છે. (૬) ૧૧ ફરિયાદોનો સંપૂર્ણ અહેવાલ મળેલ નથી જે મલ્યેથી પગલાં ભરવામાં આવશે.

મોટપ ગામ નજીક રૂપેણ નદીના છેડાનો રોડ અધૂરો હોવા બાબત

૯૪૯૦ **શ્રી માલજીભાઈ દે. દેસાઈ(ચાણસ્મા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
ધિણોજ--મોટપ--જોટાણા રોડ મોટાપ ગામ નજીક રુપેણ નદીના બંન્ને છેડા ઉપર આ રોડ છેલ્લા ૪૦ વર્ષથી અધૂરો છે, તો સરકાર આ રોડનું કામ કયારે પૂરું કરવા માંગે છે ?	પુલ તેમજ તેના પ્રવેશમાર્ગોના કામ માટે પુરતી નાણાંકીય જોગવાઈ થયે હાથ ધરવાનું આયોજન છે.

રાજ્યના મહત્વના બંદરોને રેલ માર્ગે જોડવા આયોજન

૮૮૮૪ **શ્રી કાળુભાઇ હી. માલીવાડ(લુણાવાડા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યના મહત્વના બંદરોને રેલ માર્ગે સાંકળવા કોઈ આયોજન કરાયું છે, અને	(૧) જી, હા.
(૨) જો હા, તો તે અંગે રાજ્ય સરકારે શું પગલાં લીધાં છે?	(૨) રાજ્યના મહત્વના બંદરોને જેવા કે, દહેજ-હજીરા-પોરબંદર-બેડી (જામનગર)ને બ્રોડગેજ રેલ્વે લાઈનથી સાંકળવા માટે ગુજરાત

મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા તજજ્ઞ મે. રેલ ઈન્ડિયા ટેકનીકલ એન્ડ ઈકોનોમીક સર્વિસીસ લી. (ભારત સરકારનું ઉપક્રમ) દ્વારા ટેકનોઈકોનોમીક ફીઝીબીલીટી રીપોર્ટ તૈયાર કરાવેલ છે.

દહેજ અને હજીરાને બ્રોડગેજ રેલ માર્ગે સાંકળવાની યોજના "સ્પેશીયલ પરપઝ વ્હીકલ" અંતર્ગત હાથ ધરવા આયોજન છે. તે અંગે એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવેલ છે.

આ ઉપરાંત મહત્વના કંડલા બંદરને જોડતી ગાંધીધામ-પાલનપુર રેલ્વે લાઈનને બ્રોડગેજમાં રૂપાંતર કરવાનું કામ હાલ પ્રગિતમાં છે. જે કામગીરી ઝડપી પૂર્ણ કરવા કચ્છ રેલ્વે કંપનીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જેમાં ગુજરાત સરકારની ભાગીદારી છે.

વચ્છેસર-કલ્યાણ માર્ગને રાજ્ય હસ્તક કરવા બાબત

૮૯૮૪ **શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર. ગોહિલ(સાવલી)** : : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
સાવલી તાલુકામાં પંચાયત હસ્તકના વચ્છેસર કલ્યાણ માર્ગને રાજ્ય હસ્તક કરવાનું કોઇ આયોજન છે કે કેમ?	ના, જી.

માંડવી તાલુકાના બોધાનથી વરેલીને જોડતા રસ્તા ઉપર આવેલ પુલ ઉંચો કરવા બાબત

૮૫૭૭ **શ્રી અનિલકુમાર મો. પટેલ(બારડોલી)** : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) માંડવી તાલુકાના બોધાન થી વરેલીને જોડતા રસ્તા ઉપર આવેલ લો-લેવલનો પુલ ઊંચો બનાવવા માટેની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે કે કેમ,	(૧) લો લેવલનો પુલ ઉંચો બનાવવાની મંજૂરીની દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) જો હા, તો હાલમાં આ કામગીરી કયા તબક્કામાં છે, અને	(૨) અને (૩) : પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આ કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે?	

ધાનેરા તાલુકામાં સ્ટેટ અને પંચાયત હસ્તકના રોડને જોબ નંબર આપવા બાબત

૯૪૯૮ **શ્રી હરજીવન હી. પટેલ(ધાનેરા)** : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની પરિસ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ધાનેરા તાલુકામાં કયા કયા રોડ બનાવવા માટે (સ્ટેટ અને પંચાયત) ના જોબ નંબર ફાળવવામાં આવ્યા,	(૧)(અ) ખીમત મેવાડા (બ) રાજોડા એપ્રોચ (ક) ઝેરડા-ધાનેરા (ડ) સીલસાણ-છીદીવાડા રસ્તાની કુમર નજીક ખૂટતી કડી (ઇ) સરાલ થી મહાકાળી મંદિર રસ્તો
(૨) તે પૈકી કયા કયા રોડના કામો ચાલુ કરવામાં આવ્યા, અને	(૨) ઉપરોકત રસ્તા પૈકી (અ), (બ), (ક) અને (ઇ) ચાલુ કરવામાં આવ્યા.
(૩) બાકી રહેલ કામો કયારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે?	(૩) સને ૨૦૦૫-૦૬ દરમ્યાન પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

સાણંદ અને વિરમગામ તાલુકાના એપ્રોચ રોડથી વંચિત ગામો

૮૨૩૮ **શ્રી વજુભાઈ પ. ડોડિયા(વિરમગામ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ સાણંદ તથા વિરમગામ તાલુકાના કેટલા ગામો એપ્રોચ રોડથી વંચિત છે, અને	(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ સાણંદ અને વિરમગામ તાલુકાના એકપણ મહેસૂલી ગામ એપ્રોચ રોડથી વંચિત નથી.
(૨) આ ગામોને એપ્રોચ રોડની સુવિધા સરકાર કયાં સુધીમાં આપવા માંગે છે?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પારડી તાલુકાના ઉદવાડાથી રોહિણા ધગડમાળ માર્ગને પેવર કામ કરવા

૯૨૪૪ **શ્રી લક્ષ્મણભાઈ બા. પટેલ(પારડી) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
સેન્ટર રીઝર્વ ફંડ (સી.આર.એફ.) વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકાના ઉદવાડા નેશનલ હાઇવેથી રોહિણા ધગડમાળ માર્ગ ૧૧ાા કિલોમીટરના પેવર કામ માટે જોબવર્ક કયારે આપવામાં આવશે?	સી.આર.એફ. હેઠળ આ કામ મંજુર કરવા કેન્દ્ર સરકારને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ નથી.

પાલનપુરની નાયબ વન સંરક્ષકની કચેરીનું મકાન બદલવા બાબત

૯૪૯૩ **શ્રી કાંતિલાલ ધ. કચોરિયા(પાલનપુર) : માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પાલનપુર ખાતે નાયબ વન સંરક્ષકની કચેરી અત્યારે જે જગ્યાએ કાર્યરત છે તે જગ્યા અન્ય કચેરીઓથી ખૂબ જ દુર અને તેનું મકાન જર્જરીત હોવાથી અન્ય સ્થળે આ કચેરી ખસેડવા માટે સરકાર દ્વારા કોઇ આયોજન છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો કયારે અને કયાં ખસેડવામાં આવશે?	(૨) બાબત વિચારાધિન છે.

આવશે?

સ્વચ્છ ગુજરાત સમરસ ગુજરાત અભિયાન અંતર્ગત "સ્વચ્છતા જયોત મેરેથોન દોડ"

૯૫૧૨ **શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી(દાંતા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
રાજ્યમાં સને ૨૦૦૪માં "સ્વચ્છ ગુજરાત-સમરસ ગુજરાત" અભિયાન અંતર્ગત "સ્વચ્છતા જયોત મેરેથોન દોડ" પાછળ કેટલો ખર્ચ થયો?	રૂા.૮૨૯૨૦/-

----

અમદાવાદમાં ૧૮ વર્ષની ઉંમરથી નીચેના બાળકોને તમાકુ ગુટકાના વેચાણ બદલ થયેલા કેસો

૮૫૬૪ **શ્રી મોહંમદફારુક હુ. શેખ(કાલુપુર) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
૧૮ વર્ષથી નીચેના બાળકોને તમાકુ-ગુટકાના વેચાણ પર પ્રતિબંધ અન્વયે તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં તેનો ભંગ કરવા બદલ કેટલા ઇસમો સામે કેસો કરવામાં આવ્યા?	અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ફલાઇંગ સ્કવોર્ડ વિભાગને અમદાવાદ શહેરમાં પ્રશ્ન હેઠળના કાયદાનો ભંગ કરતા કોઇ ઇસમ મળી આવેલ નથી, જેથી કોઇ કેસ કરેલ નથી.

ઘોઘા તાલુકાના ગામ તગડીથી ભાવનગર તાલુકાના માલણકા ગામ સુધીનો રસ્તો રીપેર કરવા બાબત

૯૫૩૫ **શ્રી સુનીલ બા. ઓઝા(ભાવનગર શહેર (દક્ષિણ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
ઘોઘા તાલુકાના ગામ તગડીથી ભાવનગર તાલુકાના ગામ માલણકા સુધીના રસ્તાને પેવર કરવા માટેનું સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬ નું આયોજન શું?	વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬ માં આ રસ્તો ડામરનો કરવાનું હાલ કોઇ આયોજન નથી.

જુનાગઢ જિલ્લામાં રોપા ઉછેરવા પાછળ થયેલ ખર્ચ

૮૪૪૭ **શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ(સોમનાથ) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જુનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ સુધીમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વન વિભાગ દ્વારા કેટલા રોપા ઉછેરવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો,	(૧) જુનાગઢ જિલ્લામાં તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ સુધીમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં નીચે મુજબ તાલુકાવાર રોપા ઉછેરવામાં આવેલ છે અને ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	તાલુકો	ઉછેરેલ	થયેલ ખર્ચ
૨૦૦૩-	ભેંસાણ	૧.૨૨	૨.૩૩
	જુનાગઢ	૫.૫૫	૯.૯૯
	વંથલી	૧.૮૪	૩.૦૯
	માણાવદર	૦.૩૭	૦.૪૦
	માંગરોળ	૨.૩૯	૪.૧૭

	માંગરોળ	૨.૩૯	૪.૧૭
	કેશોદ	૨.૬૨	૪.૨૭
	માળીયા	૨.૨૦	૩.૬૩
	વેરાવળ	૨.૧૦	૩.૬૦
	ઉના	૩.૦૪	૪.૬૭
	વિસાવદર	૨.૫૮	૩.૯૦
	તાલાલા	૧.૮૨	૩.૦૬
	મેંદરડા	૨.૩૯	૩.૮૩
	કોડીનાર	૨.૩૬	૩.૮૯
	કુલ :	**૩૦.૪૮**	**૫૦.૮૩**
૨૦૦૪-૦૫	ભેંસાણ	૧.૪૪	૨.૪૩
	જુનાગઢ	૬.૨૯	૯.૭૨
	વંથલી	૧.૬૦	૨.૫૭
	માણાવદર	૦.૭૧	૧.૬૧
	માંગરોળ	૨.૫૨	૪.૦૫
	કેશોદ	૨.૧૮	૩.૨૨
	માળીયા	૨.૫૯	૩.૬૧
	વેરાવળ	૨.૭૫	૩.૮૨
	ઉના	૩.૫૭	૪.૯૮
	વિસાવદર	૨.૨૨	૩.૨૮
	તાલાલા	૧.૭૦	૨.૫૭
	મેંદરડા	૨.૧૯	૩.૨૯
	કોડીનાર	૨.૯૧	૪.૧૯
	કુલ :	**૩૨.૬૭**	**૪૯.૩૪**
	એકંદર કુલઃ	**૬૩.૧૫**	**૧૦૦.૧૭**

(૨) રોપા ઉછેરવામાં થયેલ ગેરરીતિઓ બાબતે કેટલી ફરિયાદો મળી, અને

(૨) રોપા ઉછેરવામાં થયેલ ગેરરીતિઓ અંગે કોઇ ફરિયાદ મળેલ નથી.

(૩) સરકારે શાં પગલાં લીધાં?

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

સ્વનિર્ભર મેડીકલ કોલેજોનાં સંચાલકો સામે ગેરકાનુની એડમીશન બાબતે પગલાં

૮૯૯૩**શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી(ડીસા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન — **જવાબ**

(૧) રાજ્યમાં ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના શૈક્ષિણક વર્ષમાં મેડીકલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે સ્વનિર્ભર કોલેજના સંચાલકોએ લીધેલ પરીક્ષા અન્વયે ઉત્તરવહી સાથે ભૂગર્ભમાં ચાલ્યા ગયા હતા

(૧) હા, જી.

અને ગુજરાત યુનિવર્સીટીએ આ અંગે રાજ્ય સરકારને તાત્કાલિક જાણ કરી હતી તે હકિકત સાચી છે, અને

(૨) આવી ઉત્તરવહીનીઓ રાજ્ય સરકાર શોધી શકી નહિ અને સ્વનિર્ભર કોલેજોએ રાતોરાત વિધાર્થીઓને નાણાં લઇ એડમીશનો આપી દીધા તે અંગે રાજ્ય સરકાર આવી સ્વનિર્ભર કોલેજો સામે સખતાઇથી કયા કયા પ્રકારના પગલાંઓ લીધા?

(૨) જી.એસ.એફ. મેડીકલ અને પેરામેડીકલ એસોસીએશન દ્વારા લેવાયેલ પ્રવેશ પરીક્ષામાં ગેરરીતીઓ અંગે ગુજરાત યુનિવર્સીટીના રીપોર્ટની વિગતો ધ્યાને લઇ નામદાર સુપ્રિમકોર્ટમાં ઇન્ટરલોકયુટરી એપ્લીકેશન દાખલ કરેલ. નામદાર સુપ્રિમકોર્ટના ચુકાદા અનુસાર કાર્યવાહી કરી એસોસીએશન દ્વારા લેવાયેલ પરીક્ષા રદ કરવાનો નિર્ણય જસ્ટીશ આર.જે.શાહ (નિવૃત્ત) કમિટિએ લીધેલ, જે સામે એસોસીએશન દ્વારા નામદાર સુપ્રિમકોર્ટમાં ઇન્ટરલોકયુટરી એપ્લીકેશન દાખલ કરેલ નામદાર સુપ્રિમકોર્ટે કમિટિના નિર્ણય સામે મનાઇ હુકમ આપીને આ મેટરને લાર્જર બેન્ચ સમક્ષ મૂકવાનો હુકમ કરેલ છે. આ બાબત હાલ નામદાર સુપ્રિમકોર્ટમાં પડતર છે.

રાજ્યમાં આવેલી ચક્ષુ બેંકો

૯૫૪૦ **શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઉ. વાઘેલા(શહેર કોટડા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ નેત્રદાનની પ્રવૃત્તિ માટે કેટલી ચક્ષુબેંકો ઉપલબ્ધ છે,	(૧) આઠ ચક્ષુ બેંકો છે.
(૨) છેલ્લા બે વર્ષમાં આ ક્ષેત્રે કેવી કામગીરી થયેલ છે, અને	(૨) છેલ્લા બે વર્ષમાં ૨૦૦૩-૦૪ માં ૬૦૮૨ ૨૦૦૪-૦૫ ડિસેમ્બર-૦૪ માં ૨૫૬૩ ચક્ષુદાનમાં મળેલ છે.
(૩) નવી ચક્ષુબેંક માટે કોઇ આયોજન છે?	(૩) હા, જી.

બાપુનગરની જનરલ હોસ્પિટલને ભૂકંપમાં થયેલ નુકશાન

૮૩૭૪ **શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા(જમાલપુર) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદમાં આવેલી બાપુનગર જનરલ હોસ્પિટલને ભૂકંપમાં નુકશાન થયેલું છે તે વાત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) આ હોસ્પિટલનાં સમારકામ માટે તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી કામગીરી કરવામાં આવી છે?	(૨) આ હોસ્પિટલના સમારકામ માટે તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ નીચે મુજબ કામગીરી કરવામાં આવી છે. (૧) આ હોસ્પિટલનાં સમારકામ બાબતે કામદાર રાજ્ય વીમા નિગમ, નવી દિલ્હી દ્વારા આ હોસ્પિટલના ટાવર બ્લોક સંપૂર્ણ તોડીને

તે નવા બનાવવા માટે નિર્ણય આખરી થયેલ છે.

(૨) નવું બાંધકામ હોસ્પિટલના આધુનિકરણને અનુરૂપ બનાવવામાં આવશે.

(૩) હોસ્પિટલના જુના માળખાને તોડવા માટેના ટેન્ડર તા.૧૦.૭.૦૪ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ હતા અને તેના આખરીકરણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ છે અને તે અંગે જરૂરી આદેશો કામદાર વીમા નિગમ દ્વારા કરી દેવામાં આવેલ છે. તદ્દઅનુસાર બાપુનગર હોસ્પિટલના ટાવર બ્લોકને તોડવાની કામગીરી તા.૧.૨.૨૦૦૫ થી શરૂ થઇ ગયેલ છે.

હળવદ, ધાંગધ્રા અને દસાડા તાલુકામાં ખેડૂતોના પાકને ખચ્ચર ગધેડા દ્વારા નુકશાન

૮૧૯૧ **શ્રી જયંતિલાલ રા. કવાડિયા(હળવદ) : માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના હળવદ, ધાંગધ્રા અને દસાડા તાલુકાઓના રણકાંઠાના ગામડાઓમાં ખચ્ચર ગધેડાઓના ત્રાસથી ખેડૂતોના પાકને નુકશાન થાય છે તે સરકાર જાણે છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો ખેડૂતોના પાકને થતું નુકશાન અટકાવવા છેલ્લા બે વર્ષમાં સરકારે શાં પગલાં લીધા, અને	(૨) નીચે મુજબ પગલાં લીધેલ છે :- (અ) વન ખાતા તરફથી ખેડૂતોના ખેતરની ફરતે લોખંડના કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની યોજના અમલમાં મૂકેલી છે. જેમાં ૫૦% ખર્ચ સરકારશ્રી ભોગવે છે. (બ) વન ખાતાના કર્મચારીઓ દ્વારા જંગલી પ્રાણીઓને હાંકીને ભગાડી મૂકવામાં આવે છે. (ક) લોકોને વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ ધારા ૧૯૭૨ની વધુ જાણકારી મળે તેવી કામગીરી કરવામાં આવે છે.
(૩) તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધી છેલ્લા ૨ વર્ષમાં ખેડૂતોને નુકશાની પેટે કેટલી રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે ?	(૩) સરકારશ્રીની યોજના મુજબ ખેડૂતોને કોઇ રકમ ચૂકવવામાં આવતી નથી. પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ખેડૂતોને ખેતરની ફરતે કાંટાળા તારની વાડ કરવા ૩૩૬૪ રનીંગ મીટર માટે સરકારશ્રીએ રૂા.૩.૦૦ લાખનો ખર્ચ કરેલ છે. જેમાં ૬ લાભાર્થીને લાભ મળેલ છે.

ખળી ચાર રસ્તાથી રામપુરા સુધીના રોડને ડામર સપાટી કરવા બાબત

૯૪૫૭ **શ્રીમતી રમીલાબેન રા. દેસાઈ(ખેરાલુ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સિધ્ધપુરથી ખેરાલુ માર્ગને ખળી ચાર રસ્તાથી રામપુરા સુધી ડામર સપાટી કરવા માટેની	(૧) , (૨) અને (૩) : સિધ્ધપુરથી ખેરાલુ માર્ગના ખળી ચાર રસ્તાથી રામપુરા હયાત ડામર

તાંત્રિક મંજૂરી મળેલ છે કે કેમ,	સપાટીવાળો રસ્તો છે.
(૨) જો હા, તો આ રોડની વહીવટી મંજૂરી મળ્યા પછી તથા તાંત્રિક મંજૂરી મળ્યા પછી રોડનું કામ ન થવાના શાં કારણો છે, અને	
(૩) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ આ રોડ ક્યા તબક્કે છે અને તેને ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?	

બાવળા તાલુકામાં આયુર્વેદીક દવાખાના

૯૨૪૮ **શ્રી કાંતિલાલ રા. લકુમ(બાવળા) :માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ બાવળા તાલુકામાં આયુર્વેદીક દવાખાના કેટલા છે, અને	(૧) બે.
(૨) બાવળામાં આયુર્વેદીક દવાખાનું ક્યારે શરૂ કરવામાં આવશે ?	(૨) આવી કોઇ માગણી આવેલ નથી. માંગણી આવ્યેથી વિચારવામાં આવશે.

વડોદરા શહેરની જૂના વિસ્તારોની ટી.પી. સ્કીમ

૮૭૩૫ **શ્રી દિલુભા ટે. ચુડાસમા(વડોદરા (ગ્રામ્ય) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) વડોદરા શહેરના વધતા જતા વ્યાપ, વધુ ગ્રામ્ય વિસ્તારોના મહાનગરપાલિકા હદમાં થયેલ સમાવેશ સંદર્ભે શહેરના સમતોલ વિકાસ માટે જૂના વિસ્તારો પૈકી પણ કેટલાક વિસ્તારો માટે ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમ અમલમાં નહીં હોવાની વાતથી સરકાર માહિતગાર છે ખરી, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ અંગે સરકાર દ્વારા કરાયેલ આયોજનની શી વિગતો છે ?	(૨) આ વિસ્તાર માટે તબક્કાવાર નગર રચના યોજનાઓ બનાવવાનું આયોજન છે.

રાજ્યમાં મહેસૂલી ગામોને પાકા રસ્તાથી જોડવા બાબત

૯૫૨૦ **શ્રી વેચાતભાઈ હ. બારિયા(પાવી-જેતપુર) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧.૧.૨૦૦૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કુલ કેટલાં મહેસૂલી ગામોને પાકા રસ્તાઓથી જોડવામાં આવ્યા છે, અને	(૧) ૧૭૭૯૩ મહેસૂલી ગામોને મેટલ/ડામર સપાટીથી જોડવામાં આવેલ છે.
(૨) બાકી રહેતા ગામોને પાકા રસ્તાથી જોડવાનું શું આયોજન છે ?	(૨) જોડી શકાય તેવા બાકીના ગામોના ૧૨ કામો પ્રગતિમાં છે અને ૩ કામોના ટેન્ડર મંજૂરીમાં છે. આ ૧૫ ગામો જોડવાનું કામ ૨૦૦૫-૦૬ માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

રાજ્યમાં નવા આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવા બાબત

૯૪૭૩ **શ્રી બિમલ શાહ(કપડવંજ) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવ્યા, અને	(૧) ૨૨ (બાવીસ).
(૨) આ મંજૂર કરવામાં આવેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પૈકી કેટલા કાર્યાન્વિત થયા ?	(૨) ૧૪ (ચૌદ).

ધંધુકા રેફરલ હોસ્પિટલમાં ગાયનેક અને ઓર્થોપેડિક ડોકટરની ખાલી જગ્યા

૯૫૫૦ **શ્રી ભરતભાઈ પંડયા(ધંધૂકા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
ધંધુકા રેફરલ હોસ્પિટલમાં ગાયનેકોલોજી અને ઓર્થોપેડિક ડોકટરની જગ્યા ક્યારે ભરવામાં આવશે?	યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાં આવશે.

જેતપુર અને ગોંડલ તાલુકામાં બિસ્માર અને ભયજનક પુલ અને નાળા

૮૨૨૧ **શ્રીમતી જસુબેન સ. કોરાટ(જેતપુર) :માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં ડીસેમ્બર, ૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા અને ક્યા ક્યા નાળા-પુલ બિસ્માર તથા ભયજનક હાલતમાં છે, અને	(૧) અને (૨) : હયાત નાળા પુલ વાહન વ્યવહાર યોગ્ય છે.
(૨) તેને ક્યાં સુધીમાં રીપેર કરવામાં આવશે અથવા નવા તૈયાર કરવામાં આવશે ?	

કચ્છ જિલ્લામાં સામાજિક વનીકરણ યોજના હેઠળ કિસાન નર્સરીઓ

૯૫૪૨ **શ્રી ગોપાલભાઈ ગા. ધુઆ(મુંદ્રા) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કચ્છ જિલ્લામાં સામાજિક વનીકરણ યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કુલ કેટલી કિસાન નર્સરીઓ હયાત છે, અને	(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કચ્છ જિલ્લામાં સામાજીક વનીકરણ યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કુલ-૯૩ કિસાન નર્સરી નીચે પ્રમાણે હયાત છે.

અ.નં.	તાલુકો	કુલ
૧.	ભુજ	૧૬
૨.	ભચાઉ	૫
૩.	મુન્દ્રા	૧૦

૪.	માંડવી	૨૫
૫.	નખત્રાણા	૭
૬.	અબડાસા	૯
૭.	લખપત	૪
૮.	અંજાર (ગાંધીધામ)	૩
૯.	રાપર	૧૪
	કુલ :	**૯૩**

(૨) છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર કેટલી કિસાન નર્સરીઓ આપવાનું આયોજન હતુ, અને

(૨) છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર કુલ ૬૦ કિસાન નર્સરીઓ આપવાનું આયોજન નીચે પ્રમાણે હતું.

અ.નં.	**તાલુકો**	**વર્ષ**		**કુલ**
		૨૦૦૩-૦૪	**૨૦૦૪-૦૫**	
૧.	ભુજ	૪	૫	૯
૨.	ભચાઉ	૦	૦	૦
૩.	મુન્દ્રા	૨	૬	૮
૪.	માંડવી	૫	૭	૧૨
૫.	નખત્રાણા	૪	૫	૯
૬.	અબડાસા	૨	૦	૨
૭.	લખપત	૨	૫	૭
૮.	અંજાર (ગાંધીધામ)	૨	૨	૪
૯.	રાપર	૪	૫	૯
	કુલ :	**૨૫**	**૩૫**	**૬૦**

(૩) તેની સામે કેટલી કિસાન નર્સરીઓ આપવામાં આવેલ ?

(૩) તેની સામે કુલ-૬૦ કિસાન નર્સરીઓ નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવેલ.

અ.નં.	**તાલુકો**	**વર્ષ**		**કુલ**
		૨૦૦૩-૦૪	**૨૦૦૪-૦૫**	
૧.	ભુજ	૪	૫	૯
૨.	ભચાઉ	૦	૦	૦
૩.	મુન્દ્રા	૨	૬	૮
૪.	માંડવી	૫	૭	૧૨
૫.	નખત્રાણા	૪	૫	૯
૬.	અબડાસા	૨	૦	૨
૭.	લખપત	૨	૫	૭
૮.	અંજાર (ગાંધીધામ)	૨	૨	૪
૯.	રાપર	૪	૫	૯
	કુલ :	**૨૫**	**૩૫**	**૬૦**

મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર દ્વારા ખરીદેલ દવાઓની ગુણવતા બાબત

૮૯૭૫ **શ્રી પ્રદિપસિંહ ભ. જાડેજા(અસારવા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર દ્વારા ખરીદવામાં આવેલ દવાઓમાંથી કેટલી કંપનીઓની દવાઓ સબ-સ્ટાન્ડર્ડ જણાઇ છે, અને	(૧) ૮૦ કંપનીઓની ત્રણ વર્ષમાં કુલ મળીને ૨૦૨ આઇટમોની ૪૮૯ બેચો સબ-સ્ટાન્ડર્ડ જણાઇ છે.
(૨) તેની સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે?	(૨)**અઃ** અપ્રમાણસર બેચોના વપરાયેલ તેમજ વણવપરાયેલ જથ્થા માટે કુલ રૂા.૪૦,૭૦,૫૫૫/-નું રિપ્લેશમેન્ટ મેળવ્યું અને રૂા.૧,૪૮,૪૨,૬૪૧/-ની રીકવરી કરી એટલે કે બન્ને મળીને કુલ રૂા.૧,૮૯,૧૩,૧૯૬-૦૦ની કાર્યવાહી કરી. **બઃ** ૪૬ પેઢીઓને સંબંધિત અપ્રમાણસર થયેલી આઇટમો માટે ત્રણ વર્ષ માટે ધંધાકીય સંબંધોમાંથી બાકાત (ડીબાર્ડ) કરી.

રાજકોટ જિલ્લામાં સરકારી હોસ્પિટલમાં અગત્યના તબીબી મશીનોનો અભાવ

૮૯૬૬ **શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા(જસદણ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં સરકારી હોસ્પિટલમાં એન્ડોસ્કોપી સ્કીન મશીન, લીથોટ્રોપ્સીનું મશીન તેમજ પ્રોસ્ટેટનું મશીન એમ.આર.આઇ. અને સોનોગ્રાફીના સાધનો ઉપલબ્ધ નથી તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, અને	(૧) નીચે મુજબની હોસ્પિટલમાં સોનોગ્રાફી મશીન હાલ ઉપલબ્ધ છે. ૧. પંડિત દીન દયાળ હોસ્પિટલ, રાજકોટ. ૨. પી.કે.હોસ્પિટલ, રાજકોટ. ૩. સરકારી હોસ્પિટલ, ગોંડલ. ૪. સરકારી હોસ્પિટલ, મોરબી. જનરલ હોસ્પિટલ મોરબી ખાતે ૧૧માં નાણાપંચની ભલામણ અન્વયે રીજીયોનલ ડાયગ્નોસ્ટીક સેન્ટર માટે ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના વર્ષમાં સી.ટી.સ્કેન મશીન, આર્થોસ્કોપ મશીન, એન્ડોસ્કોપ,મલ્ટીયુટીલીટી લેપ્રોસ્કોપ સાધનો મંજુર થયેલ છે.
(૨) જો હા, તો આવા સાધનો સત્વરે પૂરા પાડવા શી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી?	(૨) આ સાધનો માટે આનુંસાંગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અને તેના નિષ્ણાતોની ઉપલબ્ધી થયે પુરા પાડવાના થાય.

ડાંગ જિલ્લામાં માલિકીના વૃક્ષો કાપવા બાબત

૮૯૯૯ **શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે(ડાંગ-વાંસદા) : માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ડાંગ જિલ્લામાં ખેડૂતોને ૧૦૦ ટકા માલિકીના વૃક્ષો કાપવાના હક્કો આપવામાં આવેલ	(૧) હા, જી.

છે તે વાત સાચી છે, અને	
(૨) જો હા, તો પોતાની માલિકીના વૃક્ષો કાપવા માટે ડ્રો પધ્ધતિ અપનાવાય છે તે વાત સાચી છે?	(૨) ના, જી.

ભાવનગર જિલ્લાના વરતેજથી બુધેલ સુધીનો રસ્તો બિસ્માર હાલતમાં હોવા બાબત

૮૨૫૨ **શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ(ઉના) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભાવનગર જિલ્લાના વરતેજથી બુધેલ સુધીનો રસ્તો સ્ટેટ હસ્તકનો સંપૂર્ણપણે બિસ્માર હાલતમાં છે તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) અને (૨) : સદર રસ્તો વાહન વ્યવહાર ક્ષમ છે. રસ્તાની મજબુતી કરણની કામગીરીના ટેન્ડર મંજૂરીની પ્રક્રિયા હેઠળ છે.
(૨) સરકારે આ રસ્તાની મરામત કરવા શી કાર્યવાહી કરી ?	

ભુજ તથા નખત્રાણા તાલુકામાં નીલગાય તથા ભૂંડ દ્વારા ખેતીના પાકને નુકશાન

૯૫૦૯ **શ્રી શીવજીભાઈ ક. આહીર(ભૂજ) : માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં ભૂજ તથા નખત્રાણા તાલુકામાં નીલગાય તથા ભૂંડ દ્વારા ખેતીના પાકને નુકશાન થઇ રહયું છે તે હકીકત સરકાર જાણે છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે ખેડૂતોને કાંટાળી વાડ બાંધવા આર્થિક સહાય, લોન કે સબસીડી આપવાની ડિસે-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કોઇ યોજના છે કે કેમ, અને	(૨) આ માટે વન ખાતા તરફથી કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની યોજના અમલમાં છે. જે મુજબ ખેડૂત લાભાર્થીઓના ખેતરની ફરતે લોખંડના કાંટાળા તારની વાડ બનાવી આપવામાં આવે છે. જે તે લાભાર્થીએ આ માટે થનાર ખર્ચની ૫૦% રકમ જમા કરાવવાની હોય છે. જ્યારે બાકીની ૫૦% રકમ સરકારશ્રી ભોગવે છે.
(૩) જો ના, તો આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે સરકારે શી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ભરુચ જિલ્લામાં ડામર સપાટીવાળા બાકી ગામો

૮૬૭૩ **શ્રીમતી રશીદા ઈ. પટેલ(વાગરા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ ભરૂચ જિલ્લામાં મેટલ સપાટીથી ગામ જોડાયેલ છે અને ડામરસપાટી કરવાની બાકી છે તેવા ગામોની સંખ્યા કેટલી છે,	(૧) મેટલ સપાટીથી જોડાયેલ ગામોની સંખ્યા ૬૦ છે.
(૨) આવા રસ્તાને ડામરની સપાટી કરવા સરકારે શું આયોજન કરેલ છે, અને	(૨) અને (૩) : મેટલ સપાટીથી જોડાયેલ ૧૧ ગામોના રસ્તાને ડામર સપાટી કરવાના કામનું આયોજન કરેલ છે. બાકી ૪૯ ગામોને ડામર

	સપાટીના રસ્તા બનાવવાનું હાલ આયોજન નથી.
(૩) કેટલા સમયમાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે ?	

જામનગરની જી. જી. હોસ્પિટલમાં ન્યુરોસર્જનની ખાલી જગ્યા

૮૭૮૮ **શ્રી મુળુભાઈ હ. બેરા(ભાણવડ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ જામનગર ખાતે આવેલ જી. જી. હોસ્પિટલમાં ન્યુરો સર્જનની જગ્યા કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને	(૧) તા. ૩૧.૧૨.૦૪ ની સ્થિતિએ જામનગર ખાતે આવેલ જી. જી. હોસ્પિટલમાં ન્યુરો સર્જરી વિભાગમાં પ્રાધ્યાપકની જગ્યા તા. ૨૧.૯.૯૯ થી, સહપ્રાધ્યાપકની જગ્યા તા. ૨૧.૯.૯૯ થી અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપકની જગ્યા તા. ૪.૬.૦૩ થી ખાલી છે.
(૨) આ જગ્યા કયારે ભરવામાં આવશે ?	(૨) નિયમાનુસાર જરુરી લાયકાત ધરાવતાં ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાં આવશે.

શિનોર તાલુકાના દરિયાપુરા ગામ અને રાજપીપળા તાલુકાના નરખડી ગામને જોડતા પુલ ઉપર ડામર કામ

૯૫૦૨**શ્રી નરેશકુમાર મી. કનોડિયા(કરજણ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા જિલ્લાના શિનોર તાલુકાના દરિયાપુરા ગામ અને નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા તાલુકાના નરખડી ગામને જોડતો નર્મદા નદી ઉપર પુલ બનાવેલ છે, આ પુલનું ડામર કામ બાકી છે તે સરકાર જાણે છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ પુલનું ડામર કામ સરકાર ચોકકસ કયાં સુધીમાં કરવા માંગે છે ?	(૨) ૨૦૦૫માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન વિચારેલ છે.

અમદાવાદ શહેરમાં બ્લડ બેંકોનાં રકતદાન શિબિર યોજવા બાબત

૮૬૩૩ **ડૉ. જીતેન્દ્રભાઈ બા. પટેલ(સાબરમતી) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેરમાં કેટલી બ્લડ બેંકોને રકતદાન શિબિર યોજવા માટે સન ૨૦૦૪ની સાલમાં સરકારી મંજૂરી આપેલ છે, અને	(૧) એક.
(૨) તા. ૧.૧.૨૦૦૪ થી ૩૧.૧૨.૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલું બ્લડ આ સંસ્થા દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવ્યું ?	(૨) ૧૧૪૮ રકતયુનિટ એકત્રિત કરવામાં આવ્યું.

રાજ્યમાં જિલ્લાવાર એચ.આઈ.વી ના દર્દીઓ

૮૪૮૮ **શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી(અમરેલી) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજયમાં જિલ્લાવાર એચ.આઈ.વી. (પોઝીટીવ) નાં કુલ કેટલા દર્દીઓ તા. ૩૧.૧૨.૦૪ સુધી છેલ્લા-૬ માસમાં નોંધાયેલા છે, અને	(૧) રાજયમાં ૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં છેલ્લા છ માસમાં એચ.આઈ.વી. (પોઝીટીવ) નાં કુલ ૨૪૫૩ દર્દીઓ નોંધાયેલ છે. જિલ્લાવાર વિગતો માટે પત્રક-૧ સામેલ છે.
(૨) આ રોગોને અટકાવવા રાજય સરકાર દ્વારા શાં પગલાં લેવામાં આવ્યા ?	(૨) રાજય સરકાર દ્વારા લીધેલા પગલાની વિગતો પત્રક-૨ મુજબ સામેલ છે.

પત્રક - ૧

છેલ્લા ૬ માસમાં રાજ્યમાં તા. ૩૧.૧૨.૨૦૦૪ સુધીમાં જિલ્લાવાર એચ.આઈ.વી. (પોઝીટીવ) નોંધાયેલ દર્દીઓ

જિલ્લાનું નામ	એચ.આઈ.વી. (પોઝીટીવ)
૧. અમદાવાદ	૧૦૩૫
૨. અમરેલી	૩૭
૩. આણંદ	૧૩
૪. બનાસકાંઠા	૪૭
૫. ભરુચ	૧૪
૬. ભાવનગર	૮૧
૭. દાહોદ	૨૨
૮. ડાંગ	૧
૯. ગાંધીનગર	૧૯
૧૦ જામનગર	૧૩૯
૧૧. જુનાગઢ	૪૭
૧૨. ખેડા	૨૦
૧૩. કચ્છ	૨૦

જિલ્લાનું નામ	એચ.આઈ.વી. (પાઝીટીવ)
૧૪. મહેસાણા	૧૯
૧૫. નર્મદા	૧
૧૬. નવસારી	૫૫
૧૭. પંચમહાલ	૮
૧૮. પાટણ	૧૨
૧૯. પોરબંદર	૧૨
૨૦. રાજકોટ	૧૭૩
૨૧. સાબરકાંઠા	૧૧
૨૨. સુરત	૪૬૬
૨૩. સુરેન્દ્રનગર	૧૧
૨૪. વડોદરા	૧૬૯
૨૫. વલસાડ	૨૧
કુલ :	**૨૪૫૩**

પત્રક-૨

એચ.આઇ.વી./એઇડ્સને અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લીધેલ પગલાંની વિગત નીચે મુજબ છે.

(૧) આ રોગની કોઇ દવા કે રસી ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે લોકોને આ રોગ વિષે જાગૃત કરવા વિવિધ માધ્યમો જેવા કે ટીવી, રેડીયો, બસપેનલ, વર્તમાનપત્રો, લોક માધ્યમો દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

(૨) વિવિધ જોખમી વ્યવહારો ધરાવતા જૂથોમાં વિશેષ દરમ્યાનગીરી (ટારગેટેડ ઇન્ટરવેન્શન) કાર્યક્રમો દ્વારા આ વ્યકિતઓ સલામત વ્યવહારો અપનાવે તે માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ કામગીરી રાજ્યની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ મારફતે કરવામાં આવી રહી છે.

(૩) જાતિય રોગો તેમજ એઇડ્સ/એચ.આઇ.વી. પોઝીટીવ વ્યકિતઓને કાઉન્સેલીંગની સેવાઓ મળી રહે તે રાજ્યની સરકારી મેડીકલ કોલેજો અને જિલ્લા હોસ્પિટલો કાઉન્સેલીંગ સેન્ટરો (વાત્સાયન કેન્દ્રો) શરુ કરવામાં આવ્યા છે.

(૪) રાજ્યમાં લોકોને સલામત લોહી મળી રહે તે માટે સરકારી તેમજ સ્વૈચ્છિક સંસ્થા સંચાલિત કુલ ૫૭ બ્લડબેંકોનું આધુનિકરણ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ રાજ્યની સરકારી અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થા સંચાલિત ૬૨ બ્લડબેંકોને મફત એચ.આઇ.વી. અને એચ.સી.વી. ટેસ્ટ કીટ આપવામાં આવે છે.

(૫) એઇડ્સના દર્દીઓને લક્ષણ આધારિત સારવાર આપવા માટે સરકારી હોસ્પિટલમાં કામ કરતા તબીબોને તાલીમ આપવામાં આવી છે. તેમજ આ માટેની દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.

(૬) જાતીય રોગોની સારવાર : સરકારી મેડીકલ કોલેજો તેમજ જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં ૨૯ એસટીડી કલીનીકસને જરૂરી સાધનો, દવાઓ તથા આર્થિક સહયોગ પણ સોસાયટી મારફત પૂરો પાડવામાં આવે છે. આ સિવાય દરમ્યાનગીરી કાર્યક્રમ હેઠળ પણ જાતિય રોગોની સારવાર આપવામાં આવે છે.

(૭) શાળાકીય એઇડ્સ શિક્ષણ કાર્યક્રમ હેઠળ સરકારી તેમજ ખાનગી શાળાઓનાં ધોરણ ૯ અને ૧૧ના બાળકોને એઇડ્સ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. જેમાં રાજ્યની ૨૩૭૦ શાળાઓ આવરી લેવાઇ છે.

(૮) લોકોને એચ.આઇ.વી./એઇડ્સ વિષય માહિતી મળી રહે તે હેતુથી નિઃ શુલ્ક ટેલીફોન હેલ્પલાઇન-૧૦૫૧ દ્વારા અમદાવાદ, સુરત, જામનગર, ભાવનગર, વડોદરા તેમજ રાજકોટ ખાતે આ સેવા શરુ કરવામાં આવી છે.

(૯) જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ થી એઇડ્સના દર્દીઓને એન્ટીરીટ્રોવાયરલ દવાઓ મળી રહે તે માટે બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે એક સેન્ટર શરુ કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ આ દવાઓ દર્દીઓને ઓછી કિંમતે મળી રહે તે માટે સરકારે આ દવાઓ ઉપરથી વેચાણવેરો પણ હટાવી લીધો છે.

પડધરી તાલુકાના નારણકા ગામ પાસે આજી નદી ઉપર પુલ બનાવવા બાબત

૮૦૯૦ **શ્રી મોહનભાઈ ક. કુંડારીયા(ટંકારા)** : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) પડધરી તાલુકાના નારણકા ગામ પાસે આજી નદી પર પૂલ બનાવવા માટે ખાતમૂર્હુત કરવામાં આવેલ એ વાત સાચી છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ કયારે શરુ કરવામાં આવ્યું અને કયારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે, અને	(૨) કરાર મુજબ તા.૭.૨.૦૫ના રોજ શરુ કરી તા.૬.૧.૦૬ ના રોજ પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.
(૩) પુલની કામગીરી પાછળ કુલ કેટલો ખર્ચ થશે?	(૩) રૂા.૨૬.૪૦ લાખ.

ગીરના જંગલોમાં સિંહની વસ્તી

૯૪૮૮ **શ્રી ભાવિનભાઈ ન. શેઠ(એલીસબ્રીજ)** : **માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ડિસે-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ગીરના જંગલોમાં વસતા સિંહની કુલ કેટલી સંખ્યા છે,	(૧) ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ગીરના જંગલોમાં વસતા સિંહની સંખ્યા ૩૨૭ ની છે.
(૨) સિંહોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે તે વાત સાચી છે, અને	(૨) ના, જી.
(૩) જો હા, તો કયા કારણો જવાબદાર છે?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ઉપલેટા કોટેજ હોસ્પિટલમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ

૯૨૫૨ **શ્રી પ્રવિણભાઈ મો. માકડિયા(ઉપલેટા)** : **માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ ઉપલેટા કોટેજ હોસ્પિટલમાં સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે,

(૧)

સંવર્ગનું નામ	**ખાલી જગ્યાની સંખ્યા**	**કયારથી ખાલી છે.**
આર.એમ.ઓ.	૧	૩૦.૯.૨૦૦૧
બાળરોગ નિષ્ણાંત	૧	૩૦.૩.૨૦૦૦
સીની.ફાર્માસીસ્ટ	૧	૧૫.૫.૨૦૦૦
લેબ.આસીસ્ટન્ટ	૧	૨૩.૪.૨૦૦૩
લેબો.ટેકનીસ્યન	૧	૧૧.૧૧.૧૯૯૯
સીનીયર કલાર્ક	૧	૨૭.૧૨.૨૦૦૪
લેડી હેલ્થ વિઝીટર	૧	૨૧.૧૨.૯૨
એ.એન.એમ.	૧	૫.૭.૨૦૦૩
સ્વીપર	૧	૨૪.૯.૨૦૦૩
કુલ :	**૯**	

(૨) આ જગ્યાઓ કયા કારણોસર ખાલી છે, અને

(૨) જગ્યાઓ વયનિવૃત્તિ, રાજીનામું, એડહોક સેવાની સમાપ્તી, બઢતી તથા બદલીના કારણે ખાલી પડેલ છે.

(૩) આ જગ્યાઓ કયાં સુધી ભરવામાં આવશે?

(૩) બનતી ત્વરાએ.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની નગરપાલિકાઓને વાજપાઇ નગર વિકાસ યોજનાનો બીજો હપ્તો ચૂકવવા બાબત

૮૪૦૧ **શ્રી ધનરાજભાઈ કેલા(વઢવાણ) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની કેટલી નગરપાલિકાઓને વાજપાઇ નગર વિકાસ યોજના હેઠળ બીજા તબક્કાનો બીજો હપ્તો ચૂકવવાના બાકી છે કે કેમ,

(૧) ચાર નગરપાલિકા.

(૨) જો હા, તો કેટલી નગરપાલિકાઓને કેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે, અને

(૨) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની નગરપાલિકાઓને બીજા તબક્કાનો બીજો હપ્તો ચૂકવવાનો બાકી હોય તેની વિગત.

નગરપાલિકાનું નામ	**ચૂકવવાની બાકી રકમની વિગત (રૂા.લાખમાં)**	
	બાકી ગ્રાન્ટ	**બાકી લોન**
સુરેન્દ્રનગર	૬૪.૫૬	૭૬.૬૯
ધ્રાંગધ્રા	૫૧.૯૮	૧૫.૭૦
વઢવાણ	૨૬.૧૩	-

થાનગઢ	૩૬.૫૮	-

(૩) બાકીની રકમ સરકાર કયારે ચૂકવી આપશે?

(૩) ગ્રાન્ટ/લોન ઉપલબ્ધ થયેથી.

ગાંધીનગર તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

૮૧૪૬ **ડૉ. સી. જે. ચાવડા(ગાંધીનગર) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગાંધીનગર તાલુકામાં નવીન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર શરૂ કરવાની વિચારણા ચાલુ છે કે કેમ, અને	(૧) ના, જી.
(૨) જો "હા" તો કયાં?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

આણંદ જિલ્લામાં ડામર સપાટી વગરના રસ્તા

૯૨૪૧ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધી. પરમાર(ભાદરણ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧.૧૨.૦૪ ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કયા કયા રસ્તાઓ ડામર સપાટી વગરના છે, અને	(૧) આણંદ જિલ્લામાં ૩૫ પ્લાન રસ્તા ડામર સપાટી વગરના છે તેની વિગત સામેલ પત્રક-૧ મુજબ છે.
(૨) આવા રસ્તાઓને ડામર સપાટીથી બનાવવા માટે સરકારે શું આયોજન કરેલ છે ?	(૨) આવા રસ્તાઓને ડામર સપાટીથી બનાવવા હાલ આયોજન નથી.

પત્રક-૧

ડામર સપાટી વગરના પ્લાન રસ્તાઓની યાદી

અ. નં.	તાલુકો	રસ્તાનું નામ
૧.	આણંદ	અડાસ-સુદણ રોડ
૨.	આણંદ	સંદેસર-અરડી રોડ
૩.	આણંદ	ગાના એપ્રોચ રોડ
૪.	આણંદ	વહેરા ધનાપુરા રોડ
૫.	આણંદ	વહેરા- મહાદેવપુરા રોડ
૬.	આણંદ	બોરીયાવી - ચંદ્રનગર રોડ
૭.	આણંદ	નાપાડ-ચાણસીપુરા-લાલપુરા રોડ
૮.	ઉમરેઠ	સુંદલપુરા એપ્રોચ રોડ

અ. નં.	તાલુકો	રસ્તાનું નામ
૧૯.	બોરસદ	દહેમી-નાપાડા રોડ
૨૦.	બોરસદ	દાવોલ-રણપુરા જોષીકુવા રોડ
૨૧.	બોરસદ	બોયાસણ-લક્ષ્મીપુરા રોડ
૨૨.	બોરસદ	કણભા-નાલીયાપુરા રોડ
૨૩.	બોરસદ	કઠોલ-તાડીયાપુરા રોડ
૨૪.	આંકલાવ	ભેટાસી સુદણ રોડ
૨૫.	આંકલાવ	અંબાવ-બેવડપુરા રોડ
૨૬.	આંકલાવ	કહાનવાડી-આમરોલ રોડ

					રોડ
૯.	ઉમરેઠ	આશાપુરા - ઈન્દીરાનગરી રોડ	૨૭.	પેટલાદ	ભવાનીપુરા આવાસ રોડ
૧૦.	બોરસદ	દહેણાલ - અંબેવપુરા રોડ	૨૮.	પેટલાદ	અગાસ-કાશીપુરા રોડ
૧૧.	બોરસદ	ઉમલાવ - તાડીયાપુરા રોડ	૨૯.	સોજાત્રા	ભલાડા-મઘરોલ-ડભોઉ ત્રંબોવાડ-ઇસણાવ રોડ
૧૨.	બોરસદ	અલારસ ત્રિલોકપુરા રોડ	૩૦.	સોનાત્રા	કાસોર-પાંચલીપુરા રોડ
૧૩.	બોરસદ	ભાદરણ - તોલવાડ - કંસારી રોડ	૩૧.	ખંભાત	પાલડી એપ્રોચ રોડ
૧૪.	બોરસદ	કણભા એપ્રોચ રોડ	૩૨.	ખંભાત	જીણજ એપ્રોચ રોડ
૧૫.	બોરસદ	અમીયાદ પુરલીયાપુરા રોડ	૩૩.	ખંભાત	કલમસર-જહાંગીરપુરા રોડ
૧૬.	બોરસદ	નાપા-સીગવાલ રોડ	૩૪.	ખંભાત	પાંદડ-વૈણજ રોડ
૧૭.	બોરસદ	અલારસા-અભરાપુરા રોડ	૩૫.	ખંભાત	તારાપુર-માટલાકુઇ ગલીયાણા રોડ
૧૮.	બોરસદ	કાંઘરોટી લક્ષ્મીપુરા રોડ			

આરોગ્ય કેન્દ્રોને ટેલીમેડીસીન્સથી જોડવા બાબત

૮૧૬૪ **ડૉ. માયાબેન સુ. કોડનાની(નરોડા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કેટલા સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોને ટેલીમેડીસીન્સથી જોડવામાં આવ્યા છે,	(૧) હાલમાં આરોગ્ય કેન્દ્રોને ટેલીમેડીસીન્સ પધ્ધતિથી જોડવામાં આવ્યા નથી.
(૨) કયા કયા કેન્દ્રોને, અને	(૨) માહિતી શૂન્ય છે.
(૩) કેટલા કેન્દ્રોને અન્ય કેન્દ્રો સાથે જોડીને છેવાડાના દર્દીને આ સેવાઓનો લાભ આપવામાં આવે છે?	(૩) માહિતી શૂન્ય છે.

ભાવનગરની મેડીકલ કોલેજના પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન માટેના અભ્યાસક્રમો

૮૭૧૭ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી(ભાવનગર શહેર (ઉત્તર) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ભાવનગર મેડીકલ કોલેજ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન માટે કુલ કેટલા અભ્યાસક્રમો શરૂ કરવામાં આવ્યા, કયા કયા અને	(૧) ભાવનગર મેડીકલ કોલેજ ખાતે નીચે જણાવેલ કુલ-૬ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યા. ૧. એનેટોમી ૨. એનેસ્થેશીયા ૩. ઓપ્થોમોલોજી ૪. મેડીસીન ૫. સર્જરી ૬. પીડીયાટ્રીક્સ.
(૨) બીજા વધુ અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા શું આયોજન કરાયેલ છે?	(૨) પી.એસ.એમ. વિષયમાં અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા માટે મંજૂરી મળેલ છે. આ વિષયમાં ૨૦૦૫થી એડમીશન આપી શકાશે. જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૫માં ઓબ્સ્ટેટીક અને

ગાયનેક તથા પેથોલોજી વિષયમાં એમ,સી.આઇ. દ્વારા ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવેલ છે.જેના નિર્ણયની રાહ જોવાય છે.

શાળા આરોગ્ય ચકાસણી હેઠળ બાળકોના આરોગ્યની તપાસ

૮૩૮૬ **શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓ. સોલંકી(ઘોઘા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં શાળા આરોગ્ય ચકાસણી કાર્યક્રમ હેઠળ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં તાઃ ૩૧-૧૨-૦૪ ની સ્થિતિએ કેટલા બાળકોના આરોગ્યની તપાસણી કરવામાં આવી હતી, અને	(૧) કુલ-૮૪,૪૫,૦૩૮.
(૨) આ તપાસણી અનુસંધાને કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે?	(૨) બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી દરમ્યાન પ્રથમ સ્થળ સારવાર સંદર્ભ, સેવા અન્વયે જીલ્લાની સીવીલ હોસ્પીટલમાં સારવાર, ચશ્મા વિતરણ, ખાસ પ્રકારની આરોગ્ય સેવાની જરૂરિયાતવાળા બાળકોને હ્રદય, કીડની તથા કેન્સરની હોસ્પીટલોમાં તજજ્ઞો દ્વારા સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવે છે.

માંડલ તાલુકામાં પંચાયત તેમજ ગૌચરની જમીન ઉપર વનીકરણ

૮૫૯૮ **શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ(માંડલ) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) માંડલ તાલુકાના કેટલા ગામોમાં ગ્રામ પંચાયત તેમજ ગૌચરની કેટલી જમીનમાં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ ત્રણ વર્ષમાં વનીકરણ કરેલ છે,	(૧) માંડલ તાલુકાના વિછણ, વનપરડી અને ઉઘરોજ ગામોમાં ગૌચરની કુલ ૧૫ હેક્ટર જમીનમાં ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ ત્રણ વર્ષમાં વનીકરણ કરેલ છે. ગ્રામ પંચાયતની અન્ય જમીનમાં કોઈ વનીકરણ કરેલ નથી.
(૨) કેટલી ગ્રામ પંચાયતો સાથે વન વિભાગના વનીકરણના કરારો પૂરા થયેલ છે, અને	(૨) ત્રણ ગ્રામ પંચાયતે વન વિભાગને ઠરાવ આપેલ છે.
(૩) જો હા, હોય તો, આ બાબતે સરકારનું શું આયોજન છે?	(૩) વન વિભાગે વનીકરણ બાદ ગ્રામ પંચાયતને લાભ આપવાનું આયોજન છે.

ઝઘડીયા અને વાલીઆ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોના આવાસમાં ન રહેતા કર્મચારીઓ

૯૫૩૮ **શ્રી છોટુભાઈ અ. વસાવા(ઝગડિયા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડીયા અને વાલીઆના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રના કર્મચારીઓને રહેવા માટે કેટલા આવાસો છે,

જવાબ

(૧) નીચે મુજબ આવાસો ઉપલબ્ધ છે.

સા.આ.કે.	વર્ગ-૧	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩	વર્ગ-૪
ઝઘડીયા	૧	૩	૧૯	૨૧
વાલીયા		૦	૩	૧૦

૦૨

(૨) આ આવાસોમાં ક્યા ક્યા કર્મચારીઓ રહે છે.

(૨) નીચે મુજબના કર્મચારીઓ રહે છે.

સા.આ.કે.	વર્ગ-૧	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩	વર્ગ-૪
ઝઘડીયા	૦૦	૦૧	૧૧	૦૫
વાલીયા	૦૨	૦૧	૦૨	૧૦

(૩) કેટલાક કર્મચારીઓ આવાસમાં રહેતા નથી, અને આવજા કરે છે તે વાત સાચી છે, અને

(૩) ના, જી.

(૪) જો હા, તો સરકાર આ કર્મચારીઓ સામે શાં પગલાં ભરવા માંગે છે?

(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ગુડા વિસ્તારમાં નગર રચનાનું આયોજન

૯૪૬૬ **શ્રી કાંતિભાઈ ભા. તડવી(સંખેડા) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગાંધીનગર શહેરના 'ગુડા' વિસ્તારમાં કેટલી નગર રચના યોજનાઓ બનાવવાનું આયોજન છે.	(૧) ૧૯ (ઓગણીસ)
(૨) 'ગુડા' વિસ્તારમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલી નગર રચના યોજનાઓ બની છે, અને	(૨) ૦૨ (બે)
(૩) બાકીની ક્યા તબક્કે છે?	(૩) બાકી રહેલ ૧૭ (સત્તર) નગર રચના યોજના પૈકી :- ૧. ૦૨ (બે) મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના લોકોના વાંધા સુચનો મેળવવા અધિનયમની કલમ-૪૨ (૧) હેઠળ પ્રસિધ્ધ કરી. ૨. ૦૭ (સાત) નગર રચના યોજના બનાવવા માટે ઈરાદો જાહેર કરેલ છે. ૩. ૦૩ (ત્રણ) નગર રચના યોજનાઓ મુખ્ય નગર નિયોજકશ્રીનો પરામર્શ મેળવવા માટે પાઠવેલ છે. અને ૪. ૦૫ (પાંચ) નગર રચના યોજનાઓમાં પરામર્શ મેળવવા માટે સર્વેની કાર્યવાહી જારીમાં છે.

દવાઓની કંપનીઓને કાળી યાદીમાં મુકવા બાબત

૮૦૫૪ **શ્રી છબીલદાસ ના. પટેલ(માંડવી) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧)તા. ૩૧-૩-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમ્યાન રાજ્યમાં વર્ષવાર કુલ કેટલી દવાઓની કંપનીઓને કાળી યાદીમાં મુકવામાં આવેલ છે, અને

(૧)

વર્ષ	**કંપનીઓની સંખ્યા**
૨૦૦૧-૦૨	૦૧
૨૦૦૨-૦૩	૦૨
૨૦૦૩-૨૦૦૪	૧૯

(૨) ક્યા ક્યા કારણોસર ?

(૨) (અ) ટેન્ડર અને ભાવકરારની શરતોના ભંગ બદલ.

(બ) સપ્લાય કરેલ દવાઓ પૈકી કેટલીક બેચો અપ્રમાણસર જાહેર થવાના કારણે.

વડોદરા જિલ્લાનો કવાંટ ભાખા રસ્તો બિસ્માર હોવા બાબત

૮૯૯૧ **શ્રી શંકરભાઈ વી. રાઠવા(છોટાઉદેપુર) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા જિલ્લાનો કવાંટ-ભાખા રસ્તો બિસ્માર હાલતમાં છે તે સરકાર જાણે છે, અને	(૧) રસ્તો વાહન-વ્યવહાર યોગ્ય છે.
(૨) જો હા, તો આ રસ્તાનું કામ સરકાર ક્યારે શરૂ કરશે અને કયાં સુધીમાં પૂર્ણ થશે?	(૨) આ રસ્તાની ખાસ મરામતમાં સપાટી સુધારણાનું કામ હાલ મંજૂર કરવાનું આયોજન નથી.

ચોટીલા આણંદપુર રોડ બિસ્માર હાલતમાં હોવા બાબત

૮૮૧૪ **શ્રી પોપટભાઈ સ. જીંજરિયા(ચોટીલા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ચોટીલા-આણંદપુર રોડ ખુબ જ બિસ્માર હાલતમાં છે તે સરકાર જાણે છે,	(૧) (૨) અને (૩) રસ્તો વાહનવ્યવહાર લાયક છે.
(૨) આ રોડનું રીપેરીંગ કામ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવશે, અને	સવાલ હેઠળના અનુભાગમાં ૫ (પાંચ) કી.મી.ની લંબાઈમાં ડામરની કામગીરી થોડા સમય અગાઉ પૂર્ણ કરાયેલ છે. જ્યારે અન્ય ૬ (છ) કી.મી. લંબાઈમાં તાજેતરમાં મંજૂરી આપેલ છે. જેનો ઈજારો નક્કી કરી જેમ બને તેમ જલ્દીથી પુરૂ કરવા આયોજન છે.
(૩) કેટલા સમયમાં રસ્તો રીપેર થશે?	

ખેતરોમાં નિલગાય/રોઝ જેવા પશુઓથી ઉભા પાકને નુકસાન

૯૦૪૦ **ડૉ. અતુલ કે. પટેલ(કલોલ) : માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ખેડૂતોના ખેતરોમાં નીલગાય/રોઝ ઘુસી જાય છે અને ઉભા પાકને નુકસાન કરે છે તો તે નુકસાન રોકવા માટેના સરકારે શાં પગલાં લીધાં છે?	નીચે મુજબના પગલાં લેવામાં આવે છે. (અ) વન ખાતા તરફથી ખેડૂતોના ખેતરની ફરતે લોખંડના કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની યોજના અમલમાં મૂકેલ છે. તે મુજબ જે તે લાભાર્થી ખેડૂતે થનાર ખર્ચની ૫૦% રકમ જમા કરાવવાની હોય છે. જ્યારે બાકીની ૫૦ % રકમ સરકારશ્રી ભોગવે છે.

(બ) વન ખાતાના કર્મચારીઓ દ્વારા જંગલી પ્રાણીઓને હાંકીને ભગાડી મૂકવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

(ક) લોકોને વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ ધારા ૧૯૭૨ની વધુ જાણકારી મળે તેવી કામગીરી કરવામાં આવે છે.

ગાંધીનગર ખાતે વિવિધ કેટેગરીના ખાલી મકાનો

૮૯૭૦ **શ્રી ધીરૂભાઈ હ. ગજેરા(સુરત શહેર (ઉત્તર) : માનનીય પાટનગર યોજના મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૩ થી તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં ગાંધીનગર ખાતે કઈ કક્ષાના સરકારી આવાસો ખાલી છે.

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ નીચે મુજબના આવાસો ખાલી છે.

કક્ષા	**આવાસ સંખ્યા**
જ(૧)	૭૬૪
જ(૨)	૭૦૯
જ	૧૦
છ	૨૧
ચ(૧)	૮૭
ચ	૬૨
ઘ.૧	૫
ઘ	૩૪
ગ(૧)	૭
ગ	૩
ખ	૧૨
કુલ	**૧૭૧૪**

(૨) આ નિવાસોની નિભાવણી પાછળ કેટલો ખર્ચ થયેલ છે?

(૨) ખાલી મકાનોના મરામત અને નિભાવણી ખર્ચ અલગથી રાખવામાં આવતો નથી.

(૩) વરસોથી ખાલી રહેલા નિવાસો અંગે રાજ્ય સરકાર શું વિચારે છે?

(૩) ખાલી રહેલા નિવાસો બોર્ડ/નિગમ, કેન્દ્ર સરકાર, એરફોર્સ, આર્મી, અર્ધલશ્કરી દળો, સહકારી સંસ્થાઓ બેંકો ખાનગી સ્કુલો વિગેરેના કર્મચારીઓને રહેણાંક માટે તથા સરકારી કચેરીઓ માટે માંગણી મુજબ ફાળવવામાં આવે છે.

લાકડીયા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું વાહન પાછું લઈ લેવા બાબત

૯૨૩૩ **શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ(રાપર) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

કચ્છ જિલ્લાનાં લાકડીયા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું વાહન પાછું લઈ કચ્છ બહાર મોકલવાનાં કારણો શાં છે?

જવાબ

વાહન પાછું લઈ બહાર મોકલાયેલ નથી.

સાબરમતી શુધ્ધિકરણ યોજના

૯૫૨૮ **શ્રી પુનમ ૨. પરમાર(પાદરા) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સાબરમતી શુધ્ધિકરણ યોજના માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ સુધીમાં કેટલી રકમ મળેલ છે,	(૧) રૂા. ૮૨૯૧.૮૬ લાખ.
(૨) આ કામ અંગે કેટલો ખર્ચ થયેલ છે, અને	(૨) રૂા. ૯૮૬૯.૪૫ લાખ.
(૩) આ કામ ક્યારે પુરૂ થવાની ધારણા છે ?	(૩) ડીસેમ્બર ૨૦૦૪માં પ્રથમ તબક્કાના તમામ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

ખેડા જિલ્લાના મહુધા અને નડિયાદ તાલુકાના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ડોક્ટર, નર્સની ખાલી જગ્યાઓ

૮૪૨૫ **શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર(મહુધા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં ખેડા જિલ્લાના મહુધા અને નડિયાદ તાલુકાના કેટલા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં કેટલા ડોક્ટર અને કેટલી નર્સોની જગ્યાઓ ખાલી છે,	(૧) ડોક્ટરની એકપણ જગ્યા ખાલી નથી. મહુધા તથા નડિયાદ તાલુકાના એક સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સ્ટાફ નર્સની બે જગ્યા ખાલી છે.
(૨) કયા કયા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં આ જગ્યાઓ ખાલી છે,	(૨) સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મહુધામાં સ્ટાફ નર્સની બે જગ્યા ખાલી છે.
(૩) આ જગ્યાઓ ક્યારથી ખાલી છે, અને	(૩) આ બે જગ્યાઓ તા. ૧-૯-૦૧થી ખાલી છે.
(૪) આ જગ્યાઓ ભરવા સરકારે શા પ્રયત્નો કર્યા ?	(૪) જગ્યાઓ ભરવા ઘટતી કાર્યવાહી કરેલ છે.

ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોકટર અને નર્સની ખાલી જગ્યા

૯૪૬૨ **શ્રી જગદીશ ઠાકોર(દહેગામ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર તથા નર્સોની મંજુર થયેલી કેટલી જગ્યાઓ છે,	(૧) ડૉક્ટર તથા નર્સોની મંજુર થયેલ જગ્યાઓ નીચે મુજબ છે.

(૧) તજજ્ઞ સેવા વર્ગ-૧	૧૮
(૨) તબીબી અધિકારી વર્ગ-૨	૨૩
(૩) મેટ્રન વર્ગ-૩	૦૧
(૪) હેડનર્સ વર્ગ-૩	૦૭
(૫) સ્ટાફનર્સ વર્ગ-૩	૪૧

(૨) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા સમયથી ખાલી છે ?	(૨) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ નીચે મુજબ જગ્યાઓ ખાલી છે.

સંખ્યા ક્યારથી ખાલી

	૧. કાર્ડીયોલોજીસ્ટ ૦૧ તા. ૪-૮-૮૯થી ૨. આર.એમ.ઓ. ૦૧ તા. ૧-૪-૦૪થી ૩. તબીબી અધિકારી વર્ગ-૨ ૦૨ તા. ૨-૧૦-૦૪ અને તા. ૧૬-૧૦-૦૪
(૩) ખાલી જગ્યા ભરવા શું આયોજન થયું છે, અને	(૩) દર મંગળવારે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ ગોઠવવામાં આવે છે. અને જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થતાં નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. આર.એમ.ઓ. વર્ગ-૧ની જગ્યા બઢતી/બદલીથી ભરવામાં આવશે. મેડીકલ ઓફીસર વર્ગ-૨ની જગ્યા હવે ભરાઇ ગયેલ છે.
(૪) તે કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે ?	(૪) યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી.

ગુડાની વિકાસ યોજનાઓ

૯૪૬૮ **શ્રી ભરત બારોટ(દરિયાપુર-કાઝીપુર)** : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગાંધીનગર શહેર માટેની ગુડાની વિકાસ યોજના ક્યારે મંજૂર થઇ, અને	(૧) તા. ૧૬-૨-૨૦૦૪ના રોજ.
(૨) ગુડાની વિકાસ યોજનાની મુખ્ય જોગવાઇઓ કઇ કઇ છે ?	(૨) રહેણાંક ઝોન-૧થી રહેણાંક-૫, વાણિજ્ય ઝોન-૧ થી વાણિજ્ય-૩ અને ઇન્સ્ટીટયુશનલ ઝોન સુચવેલ છે. * ન્યુકિલયસ વિલેજ માટે ૧.૨૫ જ્યારે જી.એન.એ.ની નજીકના વિસ્તાર માટે ૧.૮ એફ.એસ.આઇ. સુચવેલ છે. * જુદા જુદા સેક્ટરોનો વિકાસ પાટનગરનો હાર્દ જળવાય તેમ તેને અનુરૂપ વિકાસ નિયંત્રણ વિનિયમો બનાવેલ છે. * જી.આઇ.ડી.સી. વિસ્તારને જી.આઇ.ડી.સી એસ્ટેટ તરીકે મુકરર છે. * ફલોરવાઇઝ ભોગવટા પ્રમાણપત્ર (બિલ્ડીંગ યુઝ સર્ટિફિકેટ) આપવાની જોગવાઇ કરેલ છે. * પાર્કિંગમાં આગળના ભાગે ૧૦% વિઝીટર્સ પાર્કિંગ રાખેલ છે. * વિકાસ નિયંત્રણ વિનિયમોના અર્થઘટન માટે અપીલ કમિટિની રચના કરવામાં આવેલ છે.

સિધ્ધપુર શહેરના બિંદુ સરોવરના રેલ્વે ફાટકના એપ્રોચ રોડનું બાંધકામ

૮૨૯૧ **શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિધ્ધપુર)** : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ

(૧) સિધ્ધપુર શહેરમાં બિંદુ સરોવર રેલ્વે ફાટક પર રેક ઉપરનું બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે તેની બંને બાજુ એપ્રોચ રોડ અંગેના ટેન્ડરો બહાર પાડવામાં આવેલ હતા પરંતુ આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ નથી, તેના કારણો શું છે,

(૨) આ કામ પૂર્ણ કરવાનું સરકારનું શું આયોજન છે, અને

(૩) આ કામ કેટલા સમયમાં પૂરું કરવામાં આવશે ?

(૧), (૨) અને (૩) સિધ્ધપુર રેલ્વે ઓવર બ્રીજના એપ્રોચના કામના ટેન્ડર મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

કરારની જોગવાઇ અનુસાર ૧૮ માસમાં પુર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

લીંબડી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સીટી સ્કેન સોનોગ્રાફીના બંધ હાલતમાં સાધનો

૮૫૨૮ **શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ(લીંબડી)** : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ લીબડી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સીટી સ્કેન અને સોનોગ્રાફીના સાધનો ઉપલબ્ધ નથી અગર કામ કરતાં નથી તે હકીકત સાચી છે,

(૨) જો હા, તો તેનાં શું કારણો છે, અને

(૩) આ સાધનોના અભાવે કેટલા કેસો અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં સન ૨૦૦૪માં ટ્રાન્સફર થયેલ છે ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ લીંબડી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સીટી સ્કેન મશીન ઉપલબ્ધ નથી. સોનોગ્રાફી મશીન બે (૨) ઉપલબ્ધ છે, આ બંને મશીન કાર્યરત છે.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ખેડા તાલુકાના કલોલી તથા શ્રીજીપુરા ગામે નાના પુલ બનાવવા બાબત

૯૪૯૬ **શ્રી રાકેશ રાવ(માતર) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) ખેડા તાલુકાના કલોલી તથા શ્રીજીપુરા ગામ ખૂબજ વરસાદ પડે ત્યારે ભરાતા પણીના કારણે વીખુટા પડી જાય છે. તેથી આ ગામોના જવાના રસ્તે આવેલા ઉંડા વહેરાઓ (ડ્રીપ) ઉપર નાના પુલ બાંધવા સરકારે કોઈ આયોજન કરેલ છે, અને

(૨) જો હા, તો આ કામ સરકાર કયારે શરુ કરીને કયારે પૂર્ણ કરવા માંગે છે?

જવાબ

(૧) ના, જી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

રાજ્યમાં ઘટતો જતો વન વિસ્તાર

૮૩૪૨ **શ્રી દોલતભાઈ પરમાર(વડગામ) : માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં ડીસે-૦૪ ની સ્થિતિએ વનાનો વિસ્તાર કેટલો છે,

(૨) છેલ્લા બે વર્ષમાં આ વનનો કેટલો વિસ્તાર ઘ

જવાબ

(૧) વર્ષ ૨૦૦૪ની સ્થતિએ કુલ વન વિસ્તાર ૧૮૯૬૧.૫૬ ચો.કી.મી. છે.

(૨) ના, જી.

ાટતો જાય છે.

(૩) વન વિસ્તારનો વિકાસ કરવા સરકારે શાં પગલાં લીધાં છે,

(૩) વન વિસ્તારના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ યોજના હેઠળ વન વિકાસની કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સહભાગી વન વ્યવસ્થા કાર્યક્રમ હેઠળ સ્થાનિક લોકોના સહકારથી વનોનું રક્ષણ અને વિકાસની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જેમાં સંશોધન અને જન જાગૃતિ અભિયાન પણ સામેલ છે.

(૪) છેલ્લા બે વર્ષમાં જંગલોમાં ગેરકાયદે કટીંગના કેટલા ગુનાઓ નોંધાયા છે,

(૪) રાજ્યમાં ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગેરકાયદેસર કટીંગના કુલ ૧૮૦૪૫ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

(૫) ગુનેગારો સામે શાં પગલાં લેવામાં આવ્યા છે ?

ગુનાકામે સંડોવાયેલા શખ્શો સામે ભારતીય વન અધિનિયમ-૧૯૨૭ની જોગવાઈ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.

વેરાવળની મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલ સરકાર હસ્તક લેવા બાબત

૯૫૪૫ **શ્રી ગોવિંદભાઈ વ. પરમાર(તલાલા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) જૂનાગઢ જિલ્લાના વેરાવળ શહેરમાં આવેલ મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલ સરકાર હસ્તક લીધેલ છે, તે વાત સાચી છે.

(૧) હા, જી.

(૨) જો, હા તો હોસ્પિટલમાં બાળરોગ વિભાગ,
એકસ--રે ટેકનિશ્યન લેબોરેટરી
ટેકનિશ્યન એમ.ડી. ડોકટર,
એમ.એસ. ડોકટર, ઓર્થોપેડિક ડોકટર,
આંખના સર્જન, નર્સો વગેરે કેટલી
જગ્યાઓ કયારથી ખાલી છે.

(૨) (અ) હોસ્પિટલમાં નીચે વિગતે ખાલી જગ્યાઓ છે.

જગ્યાનું નામ	ખાલી જગ્યાની સંખ્યા	કયારથી ખાલી છે.
૧. અધિક્ષક વર્ગ-૧	૧	તા. ૧૪-૧૨-૦૩
૨.બાળરોગ નિષણાત	૧	તા. ૧૫-૧-૨૦૦૪
૩. આર.એમ.ઓ.	૧	તા. ૩૧-૧૦-૦૨
૪. ગાયનેકોલોજીસ્ટ	૧	તા. ૧૫-૧-૨૦૦૪
૫.એકસ-રે ટેકનીશીયન	૧	તા. ૧૩-૭-૨૦૦૦
૬. હેડ નર્સ	૨	તા.૧૩-૭-૨૦૦૦
૭. સ્ટાફનર્સ	૩	તા. ૧૩-૭-૨૦૦૦
૮. એ.એન.એમ.	૧	તા. ૧૩-૭-૨૦૦૦

(બ) લેબોરેટરી ટેકનિશ્યનની જગ્યા ભરેલી છે. જ્યારે એમ.ડી. ડોકટર, એમ.એસ. ડોકટર,

	ઓર્થોપેડિક ડોકટર અને આંખના સર્જનની જગ્યા મંજૂર જ થયેલ નથી. જેથી ખાલી જગ્યાનો પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આવી જગ્યાઓ ખાલી હોવાથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના દર્દીઓને ખાનગી ડોકટરો પસે અને બહાર ગામ સારવાર માટે ફરજીયાત જવું પડે છે, તે વાત ખરી છે.	(૩) ના, જી.
(૪) જો હા, તો આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે શું આયોજન કરેલ છે, અને	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. આમ છતાં ખાલી જગ્યાઓ વહેલામાં વહેલી તકે ભરવાનું આયોજન છે.
(૫) આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે ?	(૫) વહેલામાં વહેલી તકે.

રાજ્યમાં વસ્તી આયોગની રચના

૯૪૮૨ **શ્રીમતી રમીલાબેન બે. બારા(ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં વસ્તી પંચની સરકારે રચના કરી છે કે કેમ, અને	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો આ અંગે શી કામગીરી થઈ છે ?	(૨) રાજ્ય પંચની વસ્તી પંચની પ્રથમ બેઠક તારીખ ૭-૧૦-૨૦૦૪ના રોજ મળેલ, જેમાં રાજ્યની વસ્તી વિકાસ અંગે સભ્યશ્રીઓ દ્વારા જુદા જુદા સૂચનો કરવામાં આવ્યા હતા, તે અન્વયે જુદા જુદા ત્રણ કાર્યદળો રચવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચોથા વર્ગની ખાલી જગ્યાઓ

૯૨૩૬ **શ્રી મનીષ ન. ગીલીટવાલા(સુરત શહેર (પૂર્વ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત ખાતે ચોથા વર્ગના સફાઈ કામદારો વોર્ડ સર્વન્ટની કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી તા. ૩૧-૧૨-૦૪ સુધીમાં ખાલી છે, અને

જવાબ

	ખાલી જગ્યાઓની	ક્રમ	જગ્યાઓ ખાલી રહેવાનો સમય-
(૧) સફાઈ	૨	૧ ૨	તા. ૩૧-૮-૦૪
(૨) વોર્ડ	૯	૧	તા. ૬-૧૦-૨૦૦૦
		૨	તા. ૩૧-૩-૨૦૦૧
		૩	તા. ૨૨-૬-૨૦૦૩
		૪	તા. ૩૧-૮-૨૦૦૩
		૫	તા. ૩૧-૮-૨૦૦૩
		૬	તા. ૩૧-૧૦-૨૦૦૩

		૬	તા. ૩૧-૧૦-૨૦03
		૭	તા. ૨૯-૨-૨૦૦૪
		૮	તા. ૨૯-૨-૨૦૦૪
		૯	તા.૨૯-૧૨-૨૦૦૪

(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે ?

(૨) વિચારણા હેઠળ છે.

ફિઝીયોથેરાપીના અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા બાબત

૯૪૭૬**શ્રી મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા(પાલીતાણા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં ફિઝીયોથેરાપીના અનુનાતક અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા માટે કોઈ વિચારણા કરવામાં આવેલ છે કે કેમ ?	(૧) સરકારશ્રી દ્વારા ફિઝીયોથેરાપી કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે ૧૫ વિદ્યાર્થીઓની પ્રવેશ ક્ષમતા સાથે અનુસ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે.

રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સિસ્ટમ

૯૫૨૬ **શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ(વાઘોડિયા) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સિસ્ટમ બાબતે સરકારે કોઈ સૂચના બહાર પાડેલ છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો ક્યારે, અને	(૨) તા. ૨૭-૭-૨૦૦૪ના રોજ
(૩) તેમાં શું જોગવાઈ કરેલ છે?	(૩) ૫૦૦ ચો.મી. થી વધારે અને ૧૫૦૦ ચો.મી. સુધીના બિલ્ડીંગ યુનીટ માટે સમુચિત સત્તામંડળ નિર્દિષ્ટ કરે તે મુજબની રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સિસ્ટમ અપનાવવાની થાય છે. ૧૫૦૦ ચો.મી. થી વધુ અને ૪૦૦૦ ચો.મી. સુધીના બિલ્ડીંગ યુનિટ માટે એક પરકોલેટીંગ વેલ તથા દર ૪૦૦૦ ચો.મી. કે વધુ ક્ષેત્રફળ માટે એક પરકોલેટીંગ વેલ આપવાની જોગવાઈ કરેલ છે.

સુરત જીલ્લાના માંડવી તાલુકાના કોસાડીથી પીપરીયા વરેલીને જોડતો બિસ્માર રસ્તો

૮૫૭૮ **શ્રી અનિલકુમાર મો. પટેલ(બારડોલી) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) માંડવી તાલુકાના કોસાડીથી પીપરીયા થઈ વરેલીને જોડતો રસ્તો ખૂબજ બિસ્માર હાલતમાં છે એ વાત સરકારની જાણમાં છે.	(૧) રસ્તો વાહન વ્યવહાર યોગ્ય છે.

(૨) જો હા, તો આ રસ્તાનું પેવરકામ સરકાર ક્યારે કરવા માંગે છે, અને

(૩) આ કામ ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?

(૨) અને (૩) આ રસ્તાને રિસરફેસ કરવાનું હાલ આયોજન નથી.

વિરમગામ-માંડલ અને દસાડા તાલુકામાં નીલગાય, હરણ દ્વારા ખેડૂતોના પાકને નુકશાન

૮૨૩૯ **શ્રી વજુભાઈ પ. ડોડિયા(વિરમગામ) : માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) વિરમગામ-માંડલ-દસાડા તાલુકાના આજુબાજુના વિસ્તારમાં નીલગાય, હરણ દ્વારા ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાકને ખૂબ જ નુકશાન કરવામાં આવે છે તે હકિકત સરકાર જાણે છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો આ બાબતે સરકારે તાકીદે અસરકારક શાં પગલાં ભર્યા ?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) નીચે મુજબ પગલાં લીધેલ છે.

(અ) વન ખાતા તરફથી ખેડૂતોના ખેતરની ફરતે લોખંડના કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની યોજના અમલમાં મૂકેલી છે. તે મુજબ જે તે લાભાર્થી ખેડૂતે થનાર ખર્ચની ૫૦ % રકમ જમા કરવાની હોય છે. જ્યારે બાકીની ૫૦% રકમ સરકારશ્રી ભોગવે છે.

(બ) વન ખાતાના કર્મચારીઓ દ્વારા જંગલી પ્રાણીઓને હાંકીને ભગાડી મૂકવામાં આવે છે.

(ક) લોકોને વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ ધારા ૧૯૭૨ની વધુ જાણકારી મળે તેવી કામગીરી કરવામાં આવે છે.

બાલારામ-અંબાજી અભયારણ્યનું વ્યવસ્થાપન

૯૫૧૩ **શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી(દાંતા) : માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) સુચિત બાલારામ-અંબાજી અભ્યારણની હદને, વન્યપ્રાણીઓના અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે રેશનલાઈઝ કરવા તેમજ ખનિજ સમૃધ્ધિ ધરાવતા વિસ્તારને અભ્યારણની હદ બહાર લઈ જવા સને. ૨૦૦૪ની સાલ દરમ્યાન સરકારે શી કાર્યવાહી કરી, અને

(૨) કરેલ કાર્યવાહી અને તેના પરિણામની વિગતો શું છે?

જવાબ

(૧) બાલારામ-અંબાજી અભ્યારણની હદને, વન્યપ્રાણીઓના અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે રેશનલાઈઝ કરવા માટેની એક દરખાસ્ત ગુજરાત સરકારશ્રીએ, ભારત સરકારશ્રીને નેસનલ બોર્ડ ફોર વાઈલ્ડ લાઈફની સ્ટેન્ડીંગ કમીટીની મંજૂરી માટે મોકલેલ છે.

(૨) ભારત સરકારશ્રી કક્ષાએ કાર્યવાહી ગતિમાં છે.

વેરાવળ અને સુત્રાપાડા તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ

૮૪૪૮ **શ્રી જેસાભાઈ ભા. બારડ(સોમનાથ) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ જુનાગઢ જીલ્લાના વેરાવળ અને સુત્રાપાડા તાલુકામાં કેટલા પ્રાથમિક અને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો છે તેમાં

જવાબ

(૧)

તાલુકાનું નામ	પ્રાથમિક આરોગ્ય	સામુહિક આરોગ્ય

પ્રાથમિક અને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો છે, તેમાં સંવર્ગવાર કેટ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

	કેન્દ્રની સંખ્યા	કેન્દ્રની સંખ્યા
વેરાવળ	૪	૧
સુત્રાપાડા	૩	૧

સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ.

વર્ગ	પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર	સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર
વર્ગ-૧	૦	૧
વર્ગ-૨	૪	૨
વર્ગ-૩	૨૪	૧૨
વર્ગ-૪	૩૩	૧૧

(૨) આ જગ્યાઓ ખાલી રહેવાનાં કારણો શાં છે, અને

(૨) (૧) વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ની જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થવાને કારણે.
(૨) સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રની વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની જગ્યા પર નિમણુંક પામેલ ઉમેદવારો હાજર ન થવાને કારણે, અને ભરતી પ્રક્રિયા ગતિમાં છે.
(૩) પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ ભરવા સંબધિત જીલ્લા પંચાયત દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે?

(૩) સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન નીતિ, કાર્યભારણ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી બનતી ત્વરાએ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

છોટાઉદેપુર તાલુકામાં ફેલાયેલ ભેદી રોગચાળો

૮૯૯૪ **શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી(ડીસા) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) વડોદરા જિલ્લાના છોટાઉદેપુર તાલુકામાં તા.૩૧-૧૨-૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં ભેદી રોગને કારણે કેટલી વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા,

(૧) ૧૦ બાળકોના મૃત્યુ થયા.

(૨) આ ભેદી રોગની તપાસ માટે રાજ્ય સરકારે શાં પગલાં લીધાં, અને

(૨) આ ભેદી રોગની તપાસ માટે રાજ્ય સરકાર મારફતે પુના રાષ્ટ્રીય વિષાણુ સંસ્થાન અને રાષ્ટ્રીય સંચારી રોગ સંસ્થાન, નવી દિલ્હીની તજજ્ઞોની ટીમ બોલાવીને તપાસ કરાવી હતી. જેમાં પુના રાષ્ટ્રીય વિષાણુ સંસ્થાન દ્વારા સેન્ડ ફલાઈ મારફત જે એન્કેફેલાઈટીસ કે જે ચાંદી પુરાનામના વાયરસ મારફતે ફેલાય છે તે નવું વાયરસ ગુજરાતમાં પહેલી વખત મળી આવેલ હતુ.

(૩) આ ભેદી રોગના પ્રતિકાર માટે શાં પગલાં લીધાં?

(૩) તા. ૧૦-૬-૦૪ના રોજ પ્રથમ કેસ નોંધાયેલ હતો. અને તા.૧૩-૬-૦૪થી તા. ૧૫-૬-૦૪ના રોજ બીજા ચાર કેસ નોંધાતા તા. ૧૫-૬-૦૪થી જ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીની ટીમ અને વિભાગીય નાયબ નિયામકશ્રી, વડોદરા, એસ.એસ.જી હોસ્પિટલની ટીમ દ્વારા સર્વેલન્સની ઘનિષ્ટ કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવેલ.
તા.૨૫-૮-૨૦૦૪ સુધી ૧૦ મેડીકલ ઓફીસર, ૯૦ પેરામેડીકલ કર્મચારીઓની ૪૫ ટીમ દ્વારા સર્વેલન્સની કામગીરી કરી ૧૦૮૯૨ તાવના કેસ શોધી કાઢી સ્થળ

	પર સારવાર આપવામાં આવેલ. સર્વેલન્સ ટીમો દ્વારા રોગ અટકાયત માટે ૩૧૧૪ જગ્યાએ નાના મોટાં પાણીથી ભરાયેલ ખાડાઓ પૂરવામાં આવેલ. ૫૪૬૩ જેટલાં માટલાઓની સફાઈ કરાવેલ ૧૮૧ ટાયરોમાં ભરાયેલ પાણીનો નિકાલ કરાવેલ જે ગામોમાં ભેદી રોગના કેસ નોંધાયેલ તેમાં તરત જ એન્ટોમોજીકલ ટીમ દ્વારા સર્વેલન્સ કરી ૬૦ ગામોમાં ફોકલ સ્પ્રે, ૧૦ ગામોમાં રેગ્યુલર સ્પ્રે (સીન્થેટીક પાઈરોથ્રોઈડ) જંતુનાશક દવાનો છેટકાવ કરવામાં આવેલ. છોટાઉદેપુર તાલુકાઓના ૧૫ ગામોમાં મચ્છરદાનીની વહેંચણી કરવામાં આવેલ. ૨૨ કાયમી મચ્છર ઉત્પતિસ્થાનોમાં પોરાભક્ષક માછલીઓ છોડવામાં આવેલ. રાજ્યકક્ષાએથી, વિભાગીય કક્ષાએથી અને જીલ્લાકક્ષાએથી ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લઈ રોગ અટકાયતી કામગીરી માટે જરૂરી માર્ગદર્શન પુરુ પાડવામાં આવ્યું,

----

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કંપાઉન્ડમાં રાહત દરે ચાલતી દવાની દુકાન બંધ થવા બાબત

૮૩૭૫ **શ્રી સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા(જમાલપુર) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સન ૨૦૦૪ના વર્ષમાં આ હોસ્પિટલના કંપાઉન્ડમાં આવેલી દવાની દુકાનો નહિ નફો નહિ નુકશાનના ધોરણે ચાલતી દવાની દુકાનો બંધ કરવામાં આવતાં દર્દીઓને તેનાથી હાલાકી પડી હતી તે વાત સાચી છે,	(૧) ના, જી.
(૨) જો હા, તો આ દુકાનો બંધ કરાવવાના કારણો શાં છે, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) સિવિલ હોસ્પિટલના કંપાઉન્ડમાં દર્દીઓને ઓછા ભાવે અને ૨૪ કલાક દવાઓ મળી રહે તે માટે સરકારે શું આયોજન કરેલ છે ?	(૩) સિવિલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડમાં દર્દીઓને ૨૪ કલાક દવાઓ મળી રહે તે માટે હોસ્પિટલ કંપાઉન્ડમાં ૨ મેડીકલ સ્ટોર્સ ચલાવવા માટેના ટેન્ડરો મંગાવી આપવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના વિકાસ નકશા

૮૧૯૨ **શ્રી જયંતિલાલ રા. કવાડિયા(હળવદ) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજ્યની કઇ કઇ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના વિકાસ નકશાઓ મંજુર કરવામાં આવેલ છે,	(૧) રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને સુરત મહાનગરપાલિકા.
(૨) કેટલી મહાનગરપાલિકાઓના વિસ્તારના વિકાસ નકશાઓ મંજુર કરવાના બાકી છે, અને	(૨) કોઇ નહીં.

(૩) આ કામગીરી ક્યારે પુરી કરવામાં આવશે?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ઉમતા-જાસ્કા, હિરવાણી, પીલુયા રોડની તાંત્રિક મંજૂરી

૯૪૫૮ **શ્રીમતી રમીલાબેન રા. દેસાઈ(ખેરાલુ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઉમતા-જાસ્કા, હિરવાણી, પીલુયા રોડની વહીવટી અને તાંત્રિક મંજૂરી મળેલ છે તે સાચુ છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ રોડને પૂર્ણ કરવાનો સમય શું હતો,	(૨) તા.૧૮.૧૨.૨૦૦૨ સુધીમાં પુરૂ કરવાનું હતું.
(૩) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ના રોજ આ રોડની પરિસ્થિતિ શું છે, અને	(૩) પ્રોટેક્ટીવ દિવાલનું કામ પૂર્ણ, પહોળો કરી ડામર કરવાની કામગીરી બાકી.
(૪) આ રોડને ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?	(૪) ઇજારદારશ્રી સામે કરારખત મુજબ પગલાં લેવાની કામગીરી જિલ્લા પંચાયત દ્વારા હાથ પર છે આ કામ ૨૦૦૫-૦૬માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

રાજ્યમાં નવા આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજુર કરવા બાબત

૯૪૮૫ **શ્રી કાંતિલાલ રા. લકુમ(બાવળા) :માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજુર કરવામાં આવ્યા, અને	(૧) ૨૨ (બાવીસ).
(૨) આ મંજુર કરવામાં આવેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પૈકી કેટલા કાર્યાન્વિત થયા ?	(૨) ૧૪ (ચૌદ).

વડોદરા શહેરમાં ગૃહનિર્માણ માટે સંપાદિત કરેલ જમીન

૮૭૩૬ **શ્રી દિલુભા ટે. ચુડાસમા(વડોદરા (ગ્રામ્ય) : માનનીય શહેરી ગૃહનિર્માણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા શહેરમાં શહેરી ગૃહનિર્માણ માટે સંપાદિત કરાયેલ અને તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ ખુલ્લી હોય તેવી જમીન કેટલી,	(૧) વડોદરા શહેરમાં ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ દ્વારા ૧૭,૦૦,૫૫૯ ચો.મી. જમીન સંપાદિત કરેલ છે, તે પૈકી ૨,૮૫,૮૮૩ ચો.મી. જમીન ખુલ્લી છે.
(૨) આ પૈકી કુલ કેટલી જમીન દશ વર્ષ ઉપરાંતથી ખુલ્લી છે,	(૨) આશરે ૨,૮૫,૮૮૩ ચો.મી.

(૩) આ સંપાદિત કરાયેલ જમીનમાં જે તે હેતુઓ અનુસાર યોજના નહીં બનવાના કારણો શાં છે,

(૩) ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ દ્વારા અગાઉ બાંધવામાં આવેલ મકાનો ફાળવ્યા વગરના હોવાના કારણે તથા બજારમાં ઓછી માંગના કારણે.

(૪) આવી ખુલ્લી જમીનો માટે શું આયોજન કરેલ છે ?

(૪) વિવિધ કેટેગરીના નીચે મુજબના મકાનો માટે આયોજન કરેલ છે.

(૧) ૯૯ એચ.આઇ.જી.
(૨) ૭૭ એમ.આઇ.જી.
(૩) ૨૫૨ એલ.આઇ.જી.
(૪) ૪૮૮ એમ.આઇ.જી.

જિલ્લાની સરકારી હોસ્પિટલોમાં રોગી કલ્યાણ સમિતિ બનાવવા બાબત

૯૪૭૪ **શ્રી બિમલ શાહ(કપડવંજ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં અગાઉ જિલ્લાની સરકારી હોસ્પિટલોમાં સલાહકાર સમિતિઓ રહેતી હતી તેના બદલે રોગી કલ્યાણ સમિતિ બનાવવાની વાત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો સમિતિનું ગઠન તેમજ દર્દીના હિતમાં ફાયદાની વિગતો શું છે ?	(૨) લોક ભાગીદારીથી કાર્યો હાથ ધરવા, સક્ષમ લોકો અને અન્ય વિવિધ સ્ત્રોતો દ્વારા આર્થિક સહયોગ પ્રાપ્ત કરી તેને હોસ્પિટલના દર્દીઓના હિતાર્થે વાપરવાની અને આ રીતે દર્દીઓને ઉત્તમ તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવા જિલ્લા કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને રોગી કલ્યાણ સમિતિની રચના કરવામાં આવેલ છે. આ સમિતિમાં સરકારી, બિન સરકારી તેમજ સામાજિક કાર્યકરોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

બરવાળાને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જાહેર કરવા બાબત

૯૫૫૧ **શ્રી ભરતભાઈ પંડયા(ધંધૂકા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
બરવાળાને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે ?	નવા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સ્થાપવાની સર્વગ્રાહી વિચારણા સમયે સૂચન ધ્યાને રખાશે.

રાજ્યમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું ઓછું પ્રમાણ

૯૪૮૩ **શ્રીમતી જસુબેન સ. કોરાટ(જેતપુર) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું જાતિ પ્રમાણ નીચું છે તે હકીકત સાચી છે,	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો તે સમકક્ષ લાવવા સરકાર દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે ?	(૨) ૧. રાજ્યમાં પી.એન.ડી.ટી. એક્ટના અસરકારક અમલ માટે એપ્રોપ્રિયેટ ઓથોરીટી

દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે ?	અસરકારક અમલ માટે એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી, એડવાઇઝરી કમિટિ, સ્ટેટ સુપરવાઇઝરી બોર્ડ, સ્ટેટ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટીની રચના કરવામાં આવેલ છે. ૨. જીનેટીક કાઉન્સિલ સેન્ટર, લેબોરેટરી જેવી સંસ્થાઓની નોંધણી ફરજીયાત કરવામાં આવેલ છે. ૩. પી.એન.ડી.ટી. કાયદાનો ભંગ કરનાર ૧૪ સંસ્થાઓ/ડોકટરો સામે કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ૪. પી.એન.ડી.ટી. એક્ટ અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે પોસ્ટર્સ, સ્ટીકર્સ, હેન્ડબીલ, દૂરદર્શન પર સ્પોટ, આકાશવાણી કાર્યક્રમ, ટીન પ્લેટ વર્કશોપ (કાર્યશાળા), વસ્તી આયોગ અને એન.જી.ઓ./સંસ્થાઓના સહયોગ દ્વારા જુદા જુદા કાર્યક્રમો યોજી જનજાગૃતિ લાવવા સઘન પ્રયત્ન કરેલ છે.

કચ્છ જિલ્લામાં રોપા ઉછેરવા બાબત

૯૫૪૩ **શ્રી ગોપાલભાઈ ગા. ઘુઆ(મુંદ્રા)** : **માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) કચ્છ જિલ્લામાં તા.૧.૪.૨૦૦૩ થી તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ સુધીમાં વન વિભાગ દ્વારા વૃક્ષો રોપવામાં કેટલી અને કઇ કઇ નર્સરીમાં કેટલા રોપાનો ઉછેર તાલુકાવાર કરવામાં આવેલ છે,	(૧) કચ્છ જિલ્લામાં સને ૨૦૦૩-૦૪માં તાલુકાવાર સામેલ યાદી પત્રક-૧ મુજબ ૯૮ નર્સરીમાં ૧૦૮.૮૨ લાખ રોપા અને સને ૨૦૦૪-૦૫માં ૭૪ નર્સરીઓ ૬૭.૫૧ લાખ રોપા ઉછેરવામાં આવેલ છે.
(૨) જે નર્સરીમાં રોપા ઉછેરવામાં આવેલ છે તે રોપા કઇ કઇ જાતના છે, અને	(૨) આ નર્સરીઓમાં મુખ્યત્વે દેશીબાવળ, પીલુ, ઉટમોરડ, લીમડા, ગુંદી, લીયાર, બોરડી, ગાંગેટી, હરમો, ગુગળ, લુસ્કા, ફળાઉ, શરૂ, ખીજડો, ગોરાડ અને અન્ય જાતના રોપાઓ ઉછેરેલ છે.
(૩) તે રોપાઓ વાવવા માટે કઇ કઇ જગ્યાએ ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે, અને તાલુકાવાર ખર્ચ કેટલો કરવામાં આવેલ છે ?	(૩) કચ્છ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વન વિભાગ હેઠળ સામેલ યાદી પત્રક-૨ મુજબ વાવેતર કરવામાં આવેલ છે અને સને ૨૦૦૩-૦૪ માં વાવેતર પાછળ રૂ.૧૧૭૦.૦૬ લાખ ખર્ચ થયેલ છે અને સને ૨૦૦૪-૦૫માં વાવેતર પાછળ રૂ.૬૫૨.૬૩ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

*** પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.**

પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ ઓછું હોવા બાબત

૮૯૭૬ **શ્રી પ્રદિપસિંહ ભ. જાડેજા(અસારવા)** : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ ઓછું છે, અને તેમાં ઉત્તરોઉતર વધારો થઇ રહ્યો છે તે વાત સાચી છે,	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો આ પ્રમાણ કેટલું છે, અને	(૨) ૨૦૦૧ની વસ્તી પ્રમાણે ૧૦૦૦ પુરષોએ ૯૨૦ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ છે.

	૯૨૦ સ્ત્રઓનું પ્રમાણ છે.
(૩) આ પ્રમાણ સરખુ કરવા સરકારે ગંભીરતાપુર્વક શાં પગલાં લીધા ?	(૩) ૧. રાજ્યમાં પી.એન.ડી.ટી. એક્ટના અસરકારક અમલ માટે એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી, એડવાઇઝરી કમિટિ, સ્ટેટ સુપરવાઇઝરી બોર્ડ, સ્ટેટ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટીની રચના કરવામાં આવેલ છે. ૨. જીનેટીક કાઉન્સિલ સેન્ટર, લેબોરેટરી જેવી સંસ્થાઓની નોંધણી ફરજીયાત કરવામાં આવેલ છે. ૩. પી.એન.ડી.ટી. કાયદાનો ભંગ કરનાર ૧૪ સંસ્થાઓ/ડોકટરો સામે કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ૪. પી.એન.ડી.ટી. એક્ટ અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે પોસ્ટર્સ, સ્ટીકર્સ, હેન્ડબીલ, દૂરદર્શન પર સ્પોટ, આકાશવાણી કાર્યક્રમ, ટીન પ્લેટ વર્કશોપ (કાર્યશાળા), વસ્તી આયોગ અને એન.જી.ઓ./ સંસ્થાઓનાં સહયોગ દ્વારા જુદા જુદા કાર્યક્રમો યોજી જનજાગૃતિ લાવવા સઘન પ્રયત્ન કરેલ છે.

જસદણ તાલુકાના મોટા હડમતીયા ગામે ભાદર નદી પરનો પુલ બનાવવા બાબત

૮૯૬૭ **શ્રી કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા(જસદણ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ તાલુકાના મોટા હડમતીયા ગામે ભાદર નદી પરનો પુલ ક્યારે મંજુર કરવામાં આવ્યો,	(૧) વહીવટી મંજૂરી તા.૧૯.૯.૨૦૦૦ના પત્રથી પ્રદાન કરવામાં આવેલ.
(૨) આ પુલનું કામ તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે, અને	(૨) ટેન્ડર મંજુર થયેલ છે, ઇજારદારશ્રીને ડીપોઝીટ ભરી કરાર કરવા જણાવેલ હતું પરન્તુ ડીપોઝીટ ન ભરતાં ફરીથી ટેન્ડર માંગેલ છે.
(૩) કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે ?	(૩) વર્કઓર્ડર આપ્યા બાદ ૧૮ માસમાં પુર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

વાંસદાથી સાપુતારા સુધીનો રાજ્ય ધોરી માર્ગ વચ્ચેના ભયજનક વળાંકો દુર કરવા બાબત

૯૦૦૦ **શ્રી માધુભાઈ જે. ભોયે(ડાંગ-વાંસદા) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
ડાંગ જિલ્લામાંથી પ્રસાર થતો વાંસદાથી સાપુતારા સરહદ સુધીનો રાજ્ય ધોરી માર્ગ પર આવેલ ભયજનક વળાંકો સીધા કરવા તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી ?	૯ સ્થળોએ વળાંક સુધારણા તથા ઢાળ સુધારણાની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે.

માર્ગ અને મકાન વિભાગના કેન્દ્ર સરકાર સાથેના પડતર પ્રશ્નો

૮૨૭૫ **શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ(ઉના) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ

(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ માર્ગ અને મકાન વિભાગના કેન્દ્ર સરકાર સાથે ક્યા ક્યા પ્રશ્નો કેટલા સમયથી પડતરમાં છે, અને	(૧) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ માર્ગ અને મકાન વિભાગનો, ગુજરાતમાં નવા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો જાહેર કરવા બાબતનો પ્રશ્ન કેન્દ્ર સરકાર સાથે પડતર છે જે સતત પ્રક્રિયા છે.
(૨) આ પડતર પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે ક્યારે ક્યારે રજુઆતો થઇ અને ક્યા ક્યા પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો ?	(૨) આ પડતર પ્રશ્નના ઉકેલ માટે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તા.૧૫.૨.૨૦૦૨, તા.૨૮.૨.૨૦૦૨, તા.૧૧.૬.૨૦૦૨, તા.૨૭.૧.૨૦૦૩, તા.૧૮.૯.૨૦૦૩, તા.૭.૧.૨૦૦૪, તા.૨૪.૮.૨૦૦૪ અને તા.૨૮.૮.૨૦૦૪ના રોજ રજુઆતો કરવામાં આવેલ છે. રજુઆતની અનુસંધાને ભારત સરકારના સડક પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલય દ્વારા તા.૨૭.૨.૨૦૦૪ના રોજ રાજ્ય ધોરીમાર્ગોને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

કચ્છ જિલ્લાના ભૂજ શહેરમાં મેડિકલ સ્ટોર્સનું ચેકિંગ કરવા બાબત

૯૫૧૦ **શ્રી શીવજીભાઈ ક. આહીર(ભૂજ) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) કચ્છ જિલ્લાના ભૂજ શહેરમાં ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ની સ્થિતિએ કેટલા માન્યતા પ્રાપ્ત મેડિકલ સ્ટોર્સ ચાલી રહયા છે,	(૧) ૮૪, પરવાનેદાર મેડિકલ સ્ટોર્સ પૈકી ૨ મેડિકલ સ્ટોર્સ ફાર્માસીસ્ટ ન હોવાને કારણે બંધ છે.
(૨) કેટલા મેડિકલ સ્ટોર્સમાં સરકારી નિયમ પ્રમાણે નિયમિત રીતે ફાર્માસીસ્ટ કામ કરે છે,	(૨) ૮૨
(૩) સને ૨૦૦૪ની સાલમાં મેડિકલ સ્ટોર્સના કેટલા ચેકીંગ કરવામાં આવ્યા, અને કેવી ગેરરીતિઓ મળી, અને	(૩) સને ૨૦૦૪ન સાલમાં ભૂજ શહેરના મેડિકલ સ્ટોર્સના ૨૮ ચેકીંગ કરવામાં આવ્યા. નીચે મુજબની ગેરરીતિઓ જોવા મળેલ. (૧) મેડીકલ સ્ટોર્સમાં ફાર્માસીસ્ટની ગેરહાજરી. (૨) મેડિકલ સ્ટોર્સમાં સામાન્ય ક્ષતિઓ જેવી કે પરવાના જાહેર જનતા જોઇ શકે તેમ નહિ રાખવા અંગે, મુદત વીતેલ દવાઓ અલગ અલગ રાખેલ હોય પરંતુ તે બાબતે સંબંધિત પેઢી સાથે નિકાલ બાબતે પત્રવ્યવહાર કરેલ ન હોવા અંગે, દવાનું વેચાણ કર્યા બાદ ડૉકટરના પ્રિસ્કીપ્શન પર જરૂરી સ્ટેમ્પ લગાડતા ન હોય તેવા પ્રકારની ક્ષતિઓ જોવા મળેલ.
(૪) જવાબદારો સામે શાં પગલાં લેવાયાં?	(૪) (૧) ૪ પેઢીના પરવાના એકથી બે દિવસ માટે સ્થગિત કર્યા. (૨) ૧૧ પૈઢીઓને ચેતવણી આપી. (૩) ૨ પૈઢીને કારણદર્શક નોટિસ આપેલ છે. (૪) ૫ પેઢીને નોટિસ આપી ખુલાસો પૂછાવેલ છે.

બરડા અભ્યારણ માટે સંપાદન કરવામાં આવેલ જમીન

૮૭૮૯ **શ્રી મુળુભાઈ હ. બેરા(ભાણવડ) : માનનીય વન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) જામનગર જિલ્લામાં બરડા અભ્યારણ માટે સંપાદન કરવામાં આવેલ જમીનનો ફાઇનલ એવોર્ડ જાહેર કરવાનો બાકી છે, તે વાત ખરી છે,	(૧) ના, જી.
(૨) આ સંપાદન માટે ગૌચરની જમીન બાબતે કોઇ ગ્રામ પંચાયતે વાંધા લીધેલા છે ખરા, અને	(૨) અને (૩) : હા, જી, અને નાયબ કલેકટરશ્રીએ તે અંગે તેમના હૂકમમાં જરૂરી ઉલ્લેખ કરેલ છે.
(૩) જો હા, તો આ બાબત હાલમાં કયા તબક્કે છે?	

ઉમજ ગામથી વણછરા ગામને જોડતાં ઢાઢર નદી ઉપરનો પુલ

૯૫૦૩ **શ્રી નરેશકુમાર મી. કનોડિયા(કરજણ) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) વડોદરા જિલ્લાનાં કરજણ તાલુકાના ઉમજ ગામેથી પાદરા તાલુકાના વણછરા ગામને જોડતો ઢાઢર નદી ઉપર પુલ બનાવવા કોઇ આયોજન છે કે કેમ, અને	(૧) બજેટમાં પુરતી નાણાંકીય જોગવાઇ ન હોઇ, હાલ આયોજન નથી.
(૨) જો હા, તો કયાં સુધીમાં?	(૨) પૂરતી નાણાંકીય જોગવાઇ થયે કામગીરી હાથ ધરવાનું આયોજન છે.

અમદાવાદમાં નેશનલ સ્લમ ડેવલપમેન્ટ યોજના અંતર્ગત પાયાની સુવિધાઓ

૮૧૬૫ **ડૉ. માયાબેન સુ. કોડનાની(નરોડા) :માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) નેશનલ સ્લમ ડેવલપમેન્ટ યોજના અંતર્ગત અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં, કયા કયા સ્લમ વિસ્તારોમાં પાયાની સુવિધાઓ આપવાની કામગીરી થઇ,	(૧) નીચેના સ્લમ વિસ્તારમાં પાયાની સુવિધાઓ આપેલ છે. (૧) સિહેશ્વરીનગર (૨) શરીફખાન પઠાણની ચાલી (૩) શિવાજીનગર-૧ (૪) હનુમાનનગર-૧ (૫) હનુમાનનગર-૨ (૬) જય શકિતનગર (૭) મેલડીનગર (૮) ઘનશ્યામનગર (૯) પ્રવિણનગર-ગુપ્તાનગર (૧૦) બાવાલવલીનગર (૧૧) શિવાજીનગર-૨ (૧૨) મચ્છીપીરના (૧૩) છાપરા (૧૪) આઝાદનગર (૧૫) આશાપુરીનગર (૧૬) પાટણનગર.
(૨) આ યોજનામાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારનો કેટલો ફાળો હતો, અને	(૨) ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના છે. જે પૈકી ૭૦ ટકા લોન અને ૩૦ ટકા સબસીડી કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે.

(૩) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થિતિએ અમદાવાદ શહેરમાં ફાળવણી સામે કેટલા કામો થયા?	(૩) પાટણનગરના રોડના કામો સિવાય બાકીના કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલા છે.

ભાવનગરમાં ટાઉન પ્લાનીંગ ઓફિસરની ખાલી જગ્યા

૮૭૧૮ **શ્રી મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી(ભાવનગર શહેર (ઉત્તર) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભાવનગર ખાતે ટાઉન પ્લાનીંગ ઓફિસરની જગ્યા કેટલા સમયથી ખાલી છે,	(૧) તા.૧.૮.૨૦૦૪ થી
(૨) કેટલા સમયમાં આ જગ્યા પર કાયમી નિમણૂંક કરાશે, અને	(૨) વિભાગની તા.૨૯.૧.૨૦૦૫ ની અધિસુચનાથી આ જગ્યા પર કાયમી નિમણૂંક કરવામાં આવેલ છે.
(૩) હાલમાં આ જગ્યાનો ચાર્જ કોની પાસે છે, અને કેટલા સમયથી છે?	(૩) શ્રી એમ.એસ.ગજ્જર, જુનિયર ટાઉન પ્લાનર, વર્ગ-૨, ભાવનગર શાખા (કચેરીના વડા) પાસે ચાર્જ તા.૨૧.૧૨.૨૦૦૩ થી છે.

રાજ્યમાં એઇડઝના દર્દીઓ

૮૫૯૯ **શ્રી પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ(માંડલ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં તા.૧.૧.૦૪ થી તા.૩૧.૧૨.-૦૪ સુધી એઇડસનાં કેટલા દર્દીઓ મળેલ છે, અને	(૧) ૧૩૭૫
(૨) સરકારે આ રોગને અટકાવવા શા વિશિષ્ટ અને અસરકારક પ્રયત્નો કરેલ છે?	(૨) (૧) આ રોગની કોઇ દવા કે રસી ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે લોકોમાં આ રોગ વિષે જાગૃતિ લાવવા વિવિધ માધ્યમો જેવા કે ટીવી, રેડીયો, બસ પેનલ, વર્તમાનપત્રો વગેરેમાં જાહેરાત દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહયા છે. (૨) દર્દીઓને કાઉન્સેલીંગની સેવાઓ મળી રહે તે માટે રાજ્યની સરકારી મેડીકલ કોલેજો અને જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં કાઉન્સેલીંગ સેન્ટરો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. (૩) રાજ્યની સરકારી અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત કુલ ૬૨ બ્લડ બેંકોને મફત એચ.આઇ.વી. અને એચ.સી.વી.ટેસ્ટ કીટ આપવામાં આવે છે. (૪) સરકારી મેડીકલ કોલેજો તેમજ જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં જાતીય રોગોની સારવાર આપવામાં આવે છે. (૫) જાન્યુઆરી-૨૦૦૫ થી

	એઇડઝના દર્દીઓને એન્ટીરીટ્રો વાયરલ દવાઓ મળી રહે તે માટે બી.જે મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે એક સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

પેરાપ્લેજીયા ઇન્સ્ટીટયુટમાં એન.જી.ઓ.ના સહયોગથી પ્રોજેકટ

૯૪૭૦ **ડૉ. અતુલ કે. પટેલ(કલોલ) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડમાં આવેલ પેરાપ્લેજીયા ઇન્સ્ટીટયુટમાં એન.જી.ઓ.ના સહાયથી કોઇ પ્રોજેકટ ચાલે છે, અને	(૧) હા, જી. બે પ્રોજેકટ
(૨) જો હા, તો કેટલા અને કયા પ્રકારના?	(૨) એ લેગ ટુ સ્ટેન્ડ ઓન. વિકલાંગતાની જલ્દી ઓળખ.

ભચાઉ શહેરમાં પ્લાન પાસ માટે લેવામાં આવતી રકમ

૯૨૩૪ **શ્રી બાબુભાઈ મે. શાહ(રાપર) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) કચ્છ જિલ્લાનાં ભૂકંપગ્રસ્ત ભચાઉ શહેરનાં પુનઃ સ્થાપન/વસન અંગે ભચાઉ એરીયા ડેવલપેન્ટ ઓથોરીટી દ્વારા અસરગ્રસ્તો પાસેથી પ્લાન પાસ કરવા કે જુદી જુદી મંજૂરીઓ અન્વયે કેટલી રકમ તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં જમા લેવામાં આવી, અને	(૧) રૂા.૯૬,૬૩,૬૦૮/-
(૨) આ રકમનો ઉપયોગ શા હેતુ માટે કરવામાં આવે છે?	(૨) ભચાઉ શહેરના ભૂકંપગ્રસ્ત લાભાર્થીઓના મનોરંજન માટે બગીચા બનાવવામાં, અસરગ્રસ્ત લાભાર્થીઓને વિકાસ પરવાનગી મેળવવામાં આર્થિક સહાય મળી રહે તે માટે પ્લાનીંગ સેલ ઉભું કરવામાં તેમજ ભચાઉ શહેરને ગ્રીન સીટી બનાવવા માટે વનીકરણ કરવા અંગેની કામગીરીમાં આ રકમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ભૂકંપગ્રસ્ત શહેરોમાં પુનઃ વસવાટ માટે હાથ ધરેલ કામો

૯૫૨૯ **શ્રી પુનમ ર. પરમાર(પાદરા) : માનનીય શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યના ભૂકંપગ્રસ્ત શહેરોમાં પુનઃ વસવાટ અંગે ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપની દ્વારા કેટલી રકમના કામો હાથ ધરેલ છે,	(૧) રૂા.૪૧૯.૦૨ કરોડ
(૨) તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૪ની સ્થિતિએ આ કામો અંગે કેટલો ખર્ચ થયેલ છે, અને	(૨) રૂા.૨૧૦.૬૨ કરોડ
(૩) આ તમામ કામો કયારે પૂરાં થશે ?	(૩) આ તમામ કામો જુન-૨૦૦૬ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે

કરવાનું આયોજન છે.

ગાંધીનગર જિલ્લાની હોસ્પિટલોને ઓરેટ પ્રોગ્રામ નીચે મળેલ અદ્યતન સાધનો

૯૪૬૩ **શ્રી જગદીશ ઠાકોર(દહેગામ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) ઓરેટ કાર્યક્રમ અન્વયે ડિસેમ્બર-૨૦૦૪ ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકારને મળેલ અદ્યતન સાધનો ગાંધીનગર જિલ્લાની કઇ કઇ હોસ્પિટલોને ફાળવવામાં આવ્યા છે,	(૧) ગાંધીનગર જિલ્લાની નીચે મુજબની બે હોસ્પિટલોને ફાળવવામાં આવ્યા છે. ૧. જનરલ હોસ્પિટલ, ગાંધીનગર ૨. સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, માણસા
(૨) આ પૈકી કઇ હોસ્પિટલમાં કયુ સાધન કાર્યાવિન્ત છે, અને	(૨) જનરલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગર પત્રક-૧ મુજબ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, માણસા પત્રક-૨ મુજબ.
(૩) આ સાધનો પૈકી કેટલા સાધનો કેટલા સમયથી બંધ હાલતમાં છે?	(૩) જનરલ હોસ્પિટલ, ગાંધીનગર ખાતે એક ઓટોકલેવ મશીન તા.૧૬.૧૨.૨૦૦૪ થી બંધ છે.

પત્રક-૧

ઓરેટ કાર્યક્રમ હેઠળના સાધન સામગ્રીની વિગત દર્શાવતું પત્રક તા.૩૧.૦૧.૦૫ની સ્થિતિ.

સંસ્થાનું નામ : જનરલ હોસ્પિટલ, ગાંધીનગર.

અનુ.નં.	**સાધનની વિગત**	**કુલ સંખ્યા**	**ચાલુ/બંધ**	**બંધ હોય તો કઇ તારીખથી**	**રીપેરીંગ માટે કરેલ કાર્યવાહીની વિગત. તારીખ વાર**	**કન્ડમ કરવાપાત્ર છે કે કેમ તેની વિગત**
1.	Electro Surgical Unit	6	Working	---	---	---
2.	Cryo Machine (Gynac.)	1	Working	---	---	---
3.	Colposcope	1	Working	---	---	---
4.	Blood Gas Analyser	1	Working	---	---	---
5.	Suspension frame with tight Strips	1	Working	---	---	---
6.	Suction Machine	4	Working	---	---	---
7.	Cardiac Monitor	3	Working	---	---	---
8.	Defibrilator	1	Working	---	---	---
9.	Digital Radient Heat Warmer	2	Working	---	---	---
10.	Servo Control Radient Heat	2	Working	---	---	---

અનુ.નં.	સાધનની વિગત	કુલ સંખ્યા	ચાલુ/બંધ	બંધ હોય તો કઇ તારીખથી	રીપેરીંગ માટે કરેલ કાર્યવાહીની વિગત. તારીખ વાર	કન્ડમ કરવાપાત્ર છે કે કેમ તેની વિગત
	Warmer					
11.	Sarvo Control Premature baby Incubator	2	Working	---	---	---
12.	Transport baby Incubator	3	Working	---	---	---
13.	Heart Rate Monitor	2	Working	---	---	---
14.	Digital Premature baby Incubator	2	Working	---	---	---
15.	Biochem Analyser	2	Working	---	---	---
16.	Doppler	3	Working	---	---	---
17.	Foetal Monitor	7	Working	---	---	---
18.	Servical Traction Unit	1	Working	---	---	---
19.	Ultrasound Machine (Sonopuls)	1	Working	---	---	---
20.	I.F.T. Machine	1	Working	---	---	---
21.	Tilt Table Manumed	1	Working	---	---	---
22.	Infrared Therapy Unit	1	Working	---	---	---
23.	Treatment Table	2	Working	---	---	---
24.	Parallel Bar with mirror	1	Working	---	---	---
25.	Wall Bars with Head Section	1	Working	---	---	---
26.	Exercise Table with Chair	1	Working	---	---	---
27.	Paraffin Wax Bath	1	Working	---	---	---
28.	Lumber Traction Unit	1	Working	---	---	---
29.	S.W.D. Machine (Curapuls-970)	1	Working	---	---	---
30.	Wood Turning Lathe	1	Working	---	---	---
31.	Autoclave Machine	1	Not Working	૧૬.૧૨.૦૪	Quotations were invited but not	---

અનુ.નં.	સાધનની વિગત	કુલ સંખ્યા	ચાલુ/બંધ	બંધ હોય તો કઇ તારીખથી	રીપેરીંગ માટે કરેલ કાર્યવાહીની વિગત. તારીખ વાર	કન્ડમ કરવાપાત્ર છે કે કેમ તેની વિગત
					received. So again quotations will be invited.	
32.	Steriliser	1	Working	---	---	---
33.	M.R.S.X-Ray Machine	1	Working	---	---	---
34.	Rotory Microtome Machine	1	Working	---	---	---
35.	Syringe Infusion Pump	4	Working	---	---	---
36.	Volumetric Pump	4	Working	---	---	---
37.	Refrigrator Godrej	1	Working	---	---	---
38.	Incubator 37' C	1	Working	---	---	---
39.	Billirubinometer	1	Working	---	---	---
40.	Re-Sucsitation (Adult)	3	Working	---	---	---
41.	Neonatal re-Sucsitation Unit	2	Working	---	---	---
42.	Ventilatory Bag	1	Working	---	---	---
43.	Easy Diagnost	1	Working	---	---	---
44.	Ultrasound Sonography-250	1	Working	---	---	---
45.	P.M.I. Camera	1	Working	---	---	---
46.	Micro Centrifuse	1	Working	---	---	---
47.	Platelet Rotator	1	Working	---	---	---
48.	Platelet Incubator	1	Working	---	---	---
49.	Blood Bank Centrifuse	1	Working	---	---	---
50.	Minor Hydrolic Operation Table	3	Working	---	---	---
51.	Binocular Microscope (C.X.L. Plus)	1	Working	---	---	---
52.	Anaesthesia Trolly	1	Working	---	---	---
53.	Anaesthesia Unit Small Titus Portable	2	Working	---	---	---

અનુ.નં.	સાધનની વિગત	કુલ સંખ્યા	ચાલુ/બંધ	બંધ હોય તો કઇ તારીખથી	રીપેરીંગ માટે કરેલ કાર્યવાહીની વિગત. તારીખ વાર	કન્ડમ કરવાપાત્ર છે કે કેમ તેની વિગત
	Small-Titus Portable					
54.	Pulse Oxymeter	2	Working	---	---	---
55.	Vital Sign Monitor Dialog-2000	2	Working	---	---	---
56.	C-Pep Equipment	2	Working	---	---	---
57.	Ventilator ICU Microvent	1	Working	---	---	---
58.	Plasma Extractor	2	Working	---	---	---
59.	Ultrasound Scanner (SD100)	1	Working	---	---	---
60.	Shadowless Light Mobile	4	Working	---	---	---
61.	Laryngoscope	2	Working	---	---	---
62.	Cardiogram with leads Patients	1	Working	---	---	---
63.	Shadowless Light Fixed	1	Working	---	---	---
64.	Hand Driers	2	Working	---	---	---
65.	Infant Laryngoscope	1	Working	---	---	---
66.	Ventilator New Born baby log	1	Working	---	---	---
67.	Elisa Set	1	Working	---	---	---
68.	Incubator	1	Working	---	---	---
69.	Shadowless Lamp	1	Working	---	---	---
70.	Single formet Camera	1	Working	---	---	---
71.	Quadriceps Table	1	Working	---	---	---
72.	Fret Saw Machine	1	Working	---	---	---
73.	Treatment Plinth	2	Working	---	---	---
74.	Incubator 37' C	1	Working	---	---	---

પત્રક-૨

સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, માણસાના કાર્યાન્વિત સાધનોની યાદી

અ.નં.	સાધનનું નામ	સંખ્યા	સાધન ચાલુ છે કે કેમ
૧	અલ્ટ્રા સાઉન્ડ સ્કેનર	૧	હા
૨	સીરીઝ પંપ	૨	હા

અ.નં.	સાધનનું નામ	સંખ્યા	સાધન ચાલુ છે કે કેમ
૩	ઇન્ફયુઝેશન પંપ	૨	હા
૪	વેલા હીન્ગ સ્કેલ (વેઇટ મશીન)	૧	હા
૫	લેરીંગો સ્કોપ વીથ ૪ બ્લેડ	૧	હા
૬	ઇન્ફન્ટ લેરીંગોસ્કોપ	૨	હા
૭.	ઇન્ફન્ટ ફેઇસ માસ્ક	૨	હા
૮.	એરવે	૩	હા
૯.	બ્રેસ્ટ પંપ	૧	હા
૧૦	બાયોસ્પીનીડલ રેબલ	૨	હા
૧૧	બાયોસ્પીનીડલ બોન	૧	હા
૧૨	માઉથ સકસન ડેવીસ	૧	હા
૧૩	સકસન એપ્રેટર્સ	૨	હા
૧૪	સકસન એન્ડ ઇવોમેશન યુનિટ	૧	હા
૧૫	શેડોલેસ લેમ્પ	૧	હા
૧૬	ડોપલર	૩	હા
૧૭	લેબર કોટસ	૪	હા
૧૮	હાર્ટરેટ મોનીટર	૧	હા
૧૯	ફીટલ મોનીટર	૧	હા
૨૦	ડી.પી.બી. ઇન્કયુબેટર	૧	હા
૨૧	ડી.પી.બી. ઇન્કયુબેટર	૧	હા
૨૨	ટી.પી.બી. ઇન્કયુબેટર	૨	હા
૨૩	ડી.આર.બેચ વોરનીર	૧	હા
૨૪	વેન્ટીલેરીબેગ નીયોનેટસ	૧	હા
૨૫	કાડીર્યાક મોનીટર	૧	હા
૨૬	પ્લેઇન કોટસ	૬	હા
૨૭	સી.વી.એ.પી. ફેબ્રીકેશન	૧	હા
૨૮	એસ.આર.એચ. વોર્મર	૧	હા
૨૯	એસ.પી.બી. ઇન્કયુલેટર	૧	હા
૩૦	બીલીરુબીનમીટર બીઆર-૨	૧	હા
૩૧	હેન્ડ ડ્રાર્વસ	૨	હા
૩૨	માઇક્રોવેન્ટ ફેબ્રીકેશન	૧	હા
૩૩	ડાયલોગ વાઇટલ સાઇન મોનીટર	૧	હા
૩૪	કાડીયોગ્રામ નીડલ્સ	૧	હા
૩૫	કાલ્પોસ્કોપ	૧	હા
૩૬	ઓકસીજન સીલીન્ડર	૪	હા
૩૭	મોક્સ રફ રેગ્યુલેટર	૪	હા
૩૮	કોલો કોમ્પ્યુસર	૧	હા
૩૯	ડ્રાયો સુપર ગાયનેક	૧	હા
૪૦	ઇલેકટ્રો સર્જીકલ યુનિટ	૧	હા
૪૧	હાયડ્રોલીક ઓપરેશન ટેબલ	૧	હા
૪૨	શેડોલેશ લેમ્પ ફીક્સ	૧	હા
૪૩	સર્જીકલ ઇનફયુ.	બધાજ	હા

અ.નં.	સાધનનું નામ	સંખ્યા	સાધન ચાલુ છે કે કેમ
૪૪	એનેસ્થેસીયા એપ્રેટર્સ સિસ્ટમ	૧	હા

માર્ગ-પુલના વિકાસ માટે વિશ્વબેન્કની સહાય

૮૨૯૨ **શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિધ્ધપુર) : માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતિએ રાજયમાં માર્ગ-પુલના વિકાસ માટે વિશ્વબેંકની કુલ કેટલી સહાય મળી છે અને આમાંથી કેટલા રસ્તાઓ બનાવ્યા ?

જવાબ

(૧) વિશ્વ બેંક સહાયિત રાજય માર્ગ યોજના અન્વયે ડિસેમ્બર-૦૪ની સ્થિતએ રૂા. ૬૮૪.૭૭ કરોડની રકમ મંજુર કરવામાં આવી અને ૨૩ રસ્તાઓ પર કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી.

લીંબડી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ

૮૫૩૦ **શ્રી ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ(લીંબડી) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧.૧૨.૦૪ની સ્થતિએ લીંબડી સીવીલ હોસ્પિટલમાં કેટલા સર્જનો, ડોકટરો, નર્સો, વોર્ડબોયની ઘટ છે.

જવાબ

(૧) તા. ૩૧.૧૨.૦૪ ની સ્થિતિએ લીંબડી સીવીલ હોસ્પિટલ ખાતે ડોકટરો, નર્સો, તથા વોર્ડબોયની નીચે મુજબની જગ્યાઓ ખાલી છે.

તજજ્ઞ વર્ગ-૧	૪
આર.એમ.ઓ.વર્ગ-૧	૧
તબીબી અધિકારી વર્ગ-૨	૨
નર્સ	૧૪
વોર્ડબોય	૫

પ્રશ્ન

(૨) આ જગ્યાઓ ભરવા રાજય સરકારે શું વ્યવસ્થા કરી છે.

જવાબ

(૨) ૧. તજજ્ઞોની જગ્યા ભરવા માટે દર મંગળવારે કમિશ્નરશ્રીની કચેરી દ્વારા વોકઈન ઈન્ટરવ્યુ યોજવામાં આવે છે, અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી નિમણુંક આપવામાં આવે છે.
૨. આર.એમ.ઓ. વર્ગ-૧ની જગ્યા બઢતીથી ભરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે, નર્સ અને વોર્ડ બોયની જગ્યાઓ કામગીરીના પ્રમાણમાં પૂરતી છે.

પ્રશ્ન

(૩) આ જગ્યાઓ કયારે અને કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે ?

જવાબ

(૩) યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી

ખાસ મરામત કાર્યક્રમ નીચે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રસ્તાઓની મરામત

૮૩૪૩ **શ્રી દોલતભાઈ પરમાર(વડગામ) :માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન

(૧) ખાસ મરામત કામ નીચે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ૨૦૦૪-૦૫ના નાણાકીય વર્ષમાં તા.૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં તાલુકાવાર કેટલા રસ્તાઓની મરામતની કામગીરી હાથ ધરવામાં

જવાબ

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સન ૨૦૦૪-૦૫ના વર્ષમાં નીચે મુજબ રસ્તાના તાલુકાવાર ખાસ મરામતના કામો હાથ ધરવામાં આવ્યા.

રસ્તાઓની મરામતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી, અને

તાલુકો	રસ્તાની સંખ્યા
કાંકરેજ	૪
દિયોદર	૪
ભાભર	૪
વાવ	૫
થરાદ	૨
ધાનેરા	૩
ડીસા	૧૩
દાંતા	૩
પાલનપુર	૯
દાંતીવાડા	૨
અમીરગઢ	૨
વડગામ	૮

(૨) તા. ૩૧.૧૨.૦૪ સુધીમાં કેટલા રસ્તાઓની કામગીરી પૂર્ણ થઈ અને તેની પાછળ કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

(૨) તા.૩૧.૧.૨૦૦૪ સુધીમાં ૩૪ રસ્તાનાં કામો પૂર્ણ થયા અને તે ઉપર રૂા. ૩૭૯.૩૨ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

વેરાવળ તાલુકામાં પ્રભાસ પાટણ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું મકાન જર્જરીત હાલતમાં

૯૫૪૬ **શ્રી ગોવિંદભાઈ વ. પરમાર(તલાલા) : માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જુનાગઢ જિલ્લાના વેરાવળ તાલુકામાં પ્રભાસ પાટણ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પી.ડબલ્યુ.ડી. હસ્તક તબદીલ થઈ ગયેલ છે,	(૧) ના,જી
(૨) આ આરોગ્ય કેન્દ્રનું મકાન જર્જરીત હાલતમાં છે, તે સરકારના જાણમાં છે, અને	(૨) હા,જી.
(૩) હા, તો અદ્યતન સુવિધા સાથે નવું મકાન બનાવવા શં આયોજન કરેલ છે ?	(૩) જમીનની ઉપલબ્ધી તથા નાણાંકીય જોગવાઈ થયેથી નવુ મકાન બનાવી શકાશે.

સુરતની નવી સીવીલ હોસ્પિટલમાં તબીબી અધિક્ષકની ખાલી જગ્યા

૯૨૩૭ **શ્રી મનીષ ન. ગીલીટવાલા(સુરત શહેર (પૂર્વ) : માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે -

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત ખાતે તબીબી અધિક્ષકની જગ્યા કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને	(૧) નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત ખાતે તબીબી અધિક્ષકની જગ્યા તા.૧૯.૬.૦૩ થી ખાલી છે,
(૨) આ ખાલી જગ્યા સમયસર નહીં ભરવાના કારણો શાં છે, અને	(૨) બઢતી સમિતિની બેઠકમાં બઢતીપાત્ર ઉમેદવારોની ભલામણ મેળવવાની કાર્યવાહી ગતિમાં છે.
(૩) આ જગ્યા કયારે ભરવામાં આવશે ?	(૩) બઢતીની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયેથી આ જગ્યા ભરવામાં આવશે.

તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (નિયમ-૧૧૬)
ગૃહ
પાટણ તાલુકાના સાંપ્રા ગામે યુવાન ખેડૂતોના ખૂન અંગે

શ્રી નારાયણભાઈ લ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નિયમ ૧૧૬ અન્વયે નીચે જણાવેલી તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ગૃહ)નું ધ્યાન દોરું છું અને તે અંગે તેમને નિવેદન કરવાની વિનંતી કરું છું.

પાટણ જિલ્લાના પાટણ તાલુકાના સાંપ્રા ગામે એક અઠવાડિયામાં એક જ કુટુંબના બે યુવાન ખેડૂતના ઉપરા ઉપરી ખૂન થતાં તથા પોલીસે તેમાં સતર્કતા ન દાખવતાં આ વિસ્તારની પ્રજામાં ફેલાયેલ ભય અને રોષની લાગણી દૂર કરવા તથા નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટે સરકારે લીધેલ કે લેવા ધારેલ પગલાં.

શ્રી અમિત અ. શાહ (રાજય કક્ષાના ગૃહમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પાટણ તાલુકાના સાંપ્રા ગામે તા. ૨૨-૧-૦૫ના રોજ ઠાકોર બનુજી અગરાજી તથા તેમના ત્રણ ભાઈઓએ મળીને પૈસાની લેવડદેવડમાં અદાવત રાખીને ઠાકોર સોનાજી જકતાજીનું ખૂન કરેલ, આ બાબતે પાટણ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧/૦૫, ઈ.પી.કો. કલમ-૩૦૨, ૩૪, ૫૦૬(૨) વગેરે અંગેનો ગુનો તા. ૨૨-૧-૨૦૦૫ના રોજ ૧૬.૧૫ કલાકે દાખલ કરવામાં આવેલ તથા આ ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓને તા. ૩૧-૧-૨૦૦૫ના રોજ અટક કરવામાં આવેલ છે.

ત્યાર બાદ પાટણ જિલ્લાના પાટણ તાલુકાના સાંપ્રા ગામે તા. ૨૯-૧-૨૦૦૫ના રોજ ઠાકોર કુંવરજી ભોમાજી તથા બીજા ત્રણ ઇસમોએ મળીને ઠાકોર લક્ષ્મણજી દીવાનજીને જૂની અદાવત રાખીને ખૂન કરેલ, જે અંગેનો ગુનો તા. ૨૯-૧-૨૦૦૫ના રોજ ગુ. ર. નં. ૧૩/૦૫, આઈ. પી. સી. કલમ-૩૦૨, ૪૩, ૪૪૧ વગેરે દાખલ કરવામાં આવેલ. આ ગુનાના આરોપીઓને બનાવ બન્યાના ચાર દિવસની અંદર અટક કરવામાં આવેલ છે.

આ બંને ગુનાઓ અલગ અલગ તારીખે બનેલ છે, બંનેનો હેતુ જુદો છે. આ બંને કેસના તહોમતદારો જુદા છે અને મરણ પામનાર ઇસમો સગા ભાઈઓ નથી, આ બંને કેસોના આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ હોઈ આ બે ખૂનના લીધે ગામમાં કોઈપણ જાતના ભય કે રોષની લાગણી ફેલાયેલ નથી. ગામમાં પોલીસ બંદોબસ્ત મૂકવામાં આવેલ છે અને પોલીસ પેટ્રોલિંગ પણ ચાલુ છે.

શ્રી નારાયણભાઈ લ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમ તો કોઈપણ બાબત હોય માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રીને ફોન ઉપર કહીએ તો તરત કામ થતું હોય છે પણ અંતરિયાળ ગામમાં કોઈ ધારાસભ્ય ના પહોંચ્યા હોય અને એ વખતે જો પોલીસ ખાતું એની દાદ-ફરિયાદ સાંભળતું ના હોય, મારી પાસે આ બાબતે ત્યાંના ગામના લોકો આવ્યા, મેં માનનીય ગૃહ મંત્રીશ્રીને ટેલિફોન કર્યો અને કાર્યવાહી ઝડપથી શરૂ થઈ, ગુનેગારો પકડ્યા એ બદલ ધન્યવાદ પણ એના પછી બીજો એવો બનાવ બન્યો કે વારંવાર ધમકીઓ મળતી હતી અને ધમકીઓના કારણે ૨૨ જણા ઉપર જામીન અરજી માટે ત્યાંના સાંપ્રાના લોકો ગયા પણ પી.આઈ.એ હડધૂત કર્યા, આવું વર્તન કરીને ફરિયાદ ના લીધી, એ લોકો વકીલ પાસે ગયા અને વકીલ પાસે ગયા પછી ફરિયાદ લીધી, એમાં પણ વકીલને ગર્ભિત ધમકી આપવામાં આવી તો એવા અધિકારી ઉપર પગલાં લેવા માગો છો કે કેમ અને એને ઝડપથી દૂર કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમ તો નોટિસમાં જે માનનીય સભ્યશ્રીએ ઉલ્લેખ કર્યો એ ઘટનાનો ઉલ્લેખ નથી, નોટિસમાં જે ઉલ્લેખ છે એ બંને ઘટનાઓના આરોપીઓ સંપૂર્ણપણે, પૂરેપરા, અને બંનેમાં ચાર ચાર છે, બંને પકડાઈ ગયા છે, અને જેલમાં પણ છે અને અત્યારે માનનીય સભ્યશ્રીએ ધ્યાન દોર્યું છે, માનનીય નારાયણભાઈ પટેલ એક વરિષ્ઠ સભ્યશ્રી છે, જો કોઈ આવી ઘટના થઈ હોય કોઈ મિસબિહેવ કોઈ જો કક્ષાએ થઈ હોય અને રેન્જ આઈ.જી.ઓએ તપાસ કરી નિશ્ચિત એ લોકો ઉપર પગલાં ભરવા માટે અમે કાર્યવાહી કરીશું.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે લોકોના મૃત્યુ થયાં અથવા એના સગાસંબંધીઓએ આ બનાવ બન્યા પહેલાં કોઈ લેખિત ફરિયાદ અથવા મૌખિક ફરિયાદ કરી હતી ખરી?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બંને ઘટનાઓ બિલકુલ જુદાજુદા પ્રકારની છે, પહેલી ઘટના પૈસાની તકરારની છે, બીજી ઘટના એ કોઈક વ્યકિતનો સામૂહિક બહિષ્કાર કરવા માટે મિટિંગ થઈ હોય

એનાથી ઊભી થયેલી તીવ્રતાને લીધે થઈ છે પણ એ વાત સાચી છે કે, બંને મૃત્યુ પામનાર ઇસમો એ દૂરના પિતરાઈ ભાઈ થાય છે, બંનેમાં આરોપીઓ પણ જુદા જુદા છે અને બંને આરોપીઓ વચ્ચે પણ કોઈ લેવાદેવા નથી, જ્યાં સુધી તકેદારીનો સવાલ છે ત્યાં સુધી પહેલી ઘટના બન્યા પછી ગામમાં પોલીસ ફૉર્સ, ડીવાયએસપી, અને પીઆઈની, ત્રણેની તકેદારી રાખી છે પણ ગામથી દૂર લગભગ ચારેક કિલોમીટર દૂર જુદા ઝઘડાના કારણે બીજી હત્યા થયેલી છે એટલે એમાં કોઈ બેકાળજીનો એવો કોઈ પ્રશ્ન નથી.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ફરિયાદ મળી હતી કે નહોતી મળી, એ મારો સવાલ છે .

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં કહ્યું કે અગાઉ જે ઘટના થઈ એ પછી ફરિયાદ મળી છે એને અને બીજી ઘટનાને કોઈ લેવાદેવા નથી.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય બળવંતભાઈનો સવાલ એ હતો કે, જે લોકોના ખૂન થયા છે એ ત્યાં બનાવ બન્યો એ પહેલા એ લોકો દ્વારા અથવા એમના સગા-સબંધીઓ દ્વારા કોઈ મૌખિક રજૂઆત અથવા લેખિત ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવી હતી કે કેમ? બન્ને બનાવોમાં.

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પહેલા બનાવ માટે કોઈ લેખિત ફરિયાદ પહેલા આપવામાં આવી નથી. પહેલો બનાવ બન્યા પછી પહેલા બનાવના વીકટીમ દ્વારા ફરિયાદ અપાઈ છે પણ એને અને બીજા બનાવને કોઈ લેવાદેવા નથી.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી એમ કહે છે કે બીજા બનાવને કોઈ લેવાદેવા નથી. પણ પ્રશ્ન એ છે કે, આ બન્ને કેસોમાં આપને અથવા આપના ખાતામાં અથવા પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ આ બાબતની ફરિયાદ આવી હતી કે અમારું ખૂન થઈ જશે, ઝગડો થશે, મારામારી કરશે એવી આપના પોલીસ સ્ટેશનમાં, આપને ત્યાં આપના વિભાગમાં કોઈ અરજી મળી છે?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં કહ્યું કે પહેલી ઘટના બની પછી એના વીકટીમ દ્વારા અરજી આપવામાં આવી છે. પણ આ ઘટના અને બીજી ઘટનાના જે આરોપી છે એ અને વીકટીમ છે એ બન્ને અલગ છે.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમણે એમ કહ્યું છે કે મને બચાવો, મને મારી નાખશે અને એ પછી એમનું ખૂન થયું છે. માનનીય સભ્યશ્રીએ ચોખ્ખી વાત કરી છે કે ખૂન થયા પછી પણ એમના પરિવારના સભ્યો ફરિયાદ આપવા એ વકીલને લઈને જાય છે તો પણ પોલીસ ધમકી આપે છે અને આવી ગંભીર બાબતમાં માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી આવો જવાબ આપે છે ત્યારે હું આપના દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રી બહુ સ્પષ્ટ જવાબ આપે એવી આશા રાખું છું.

શ્રી અમિત અ. શાહ : સાહેબ, હું ચોકકસ માનું છું કે, (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય સભ્યશ્રી ફકત એ પૂછવા માગે છે કે, પહેલા કેસમાં પહેલા કોઈ ફરિયાદ મળી હતી? પહેલા કેસમાં એડવાન્સમાં કોઈ ફરિયાદ મળી હતી કે કેમ? એટલું જ જાણવા માગે છે.

શ્રી અમિત અ. શાહ : પહેલા કેસમાં કોઈ એડવાન્સ ફરિયાદ મળી નથી. પહેલો કેસ બન્યા પછી ફરિયાદ મળી એ ફરિયાદ અને બીજા કેસને કોઈ લેવાદેવા નથી. પહેલા કેસમાં જે વ્યકિત માટે ફરિયાદ થઈ છે એમની હત્યા થઈ નથી.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પહેલો બનાવ બન્યા પછી એ લોકોએ કોઈ રજૂઆત કરી હતી કે કેમ? (અંતરાય)

શ્રી અમિત અ. શાહ : જગદીશભાઈ, બે મિનિટ બેસો, બચાવવાની વાત નથી. દિનેશભાઈ, જોરથી બોલવાથી કોઈ વાત સાચી ન થઈ જાય. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી વાત હું બહુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક ત્રણવાર રિપિટ કરી ગયો છું પણ જો કોઈએ ન સમજવું હોય તો મારી પાસે ઉકેલ નથી. હું ફરી એક વાર આપશ્રી મારફત સૌ સભ્યશ્રીઓને કહેવા માગુ છું કે, પહેલી ઘટના બની એના પહેલા કોઈ આ પ્રકારની ફરિયાદ મળી નથી આ એક વાત. ઘટના બન્યા પછી જે વીકટીમ હતા જેમની હત્યા થઈ છે એના પરિવારજનોએ પોલીસમાં અરજી આપી છે પરંતુ એ જે લોકોએ અરજી આપી છે એમના ઉપર બીજી ઘટના નથી થઈ. એ બીજા સ્વતંત્ર લોકો ઉપર ઘટના બની છે અને સ્વતંત્ર લોકોએ કરી છે એટલે આ ફરિયાદ અને બીજી ઘટનાને સાંકળવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઉભો નથી થતો. (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : બન્ને અલગ અલગ ઘટના છે. (અંતરાય) પ્લીઝ બેસો.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સિરિયલ મર્ડરનો કેસ છે અને માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી એને હળવાશથી લે એ ચાલે નહીં ત્યારે માનનીય મંત્રીશ્રીને હું આપના દ્વારા પૂછવા માગું છું કે, જે વિસ્તારમાં આ ઘટના બની અને આમાં એક વખત ફરિયાદ થઈ કે અમારા જાનનું જોખમ છે, આમાં ગામડામાં કોઈ એક કુટુંબ એટલે ખાલી પતિ-પત્ની નહીં, ગામડામાં બૃહદ કુટુંબ હોય છે ત્યારે એના પિતરાઈ ભાઈનું ખૂન થયું છે એટલે આ સિરિયલ મર્ડરની ઘટના છે અને અધિકારીઓએ નિષ્ક્રિયતા દાખવેલ છે તો આવા અધિકારીઓ સામે તપાસ કરીને એની સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાં માગો છો કે કેમ?

શ્રી અમિત અ. શાહ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં અગાઉ જ જવાબ આપ્યો કે આ સિરિયલ મર્ડર નથી, બન્ને મર્ડરના કારણો જુદાં છે, મર્ડર કરવાવાળા વ્યકિત જુદા છે અને બન્ને વસ્તુ જુદી છે. પરંતુ તેમ છતાં માનનીય નારાયણભાઈએ જે લાગણી રજૂ કરી કે આમાં કોઈ પણ લીફાપોથી થઈ હોય અથવા કોઈ ફરિયાદ ન લેવામાં આવી હોય તો મેં રેન્જ આઈ.જી. જોડે તપાસ કરી કન્સન અધિકારી પર પગલાં ભરવામાં આવશે એની વાત કરી જ છે.

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો

ગુજરાત મ્યુનિસિપલ નાણા બોર્ડનો સન ૨૦૦૨-૨૦૦૩નો વાર્ષિક અહેવાલ

શ્રી ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ. જાડેજા (શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણમંત્રીશ્રી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું ગુજરાત મ્યુનિસિપલ નાણા બોર્ડનો સન ૨૦૦૨-૨૦૦૩નો વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ તથા આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલ વિલંબ અંગેના કારણો દર્શાવતું નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અહેવાલ તથા નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ કોરપોરેશનનો સન ૨૦૦૦-૨૦૦૧નો વાર્ષિક અહેવાલ

શ્રી મંગુભાઈ છ. પટેલ (આદિજાતિ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ કોરપોરેશનનો સન ૨૦૦૦-૨૦૦૧નો વાર્ષિક અહેવાલ તથા આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલ વિલંબ અંગેના કારણો દર્શાવતું નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની રજા લઉં છું.

અહેવાલ તથા નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)

અધ્યક્ષશ્રી : નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટે તા.૧૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ના રોજ માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી તરફથી જે આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને જેને માનનીય સભ્યશ્રી પ્રબોધકાંત પંડયાએ અનુમોદન આપ્યું છે તે આ પ્રમાણે છે.

રાજ્યપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેશો પાઠવવો-

" અમો આ સત્રમાં એકત્ર થયેલા ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો રાજ્યપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ સમક્ષ કરેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ. "

હવે રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ ઉપરની ચર્ચા આગળ ચાલશે, માનનીય અશોકભાઈ.

શ્રી અશોક ભટ્ટ (કાયદો અને ન્યાયતંત્રમંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સભાગૃહમાં રાજ્યપાલશ્રી આવીને પ્રવચન કરીને ગયા અને આ સભાગૃહના સભ્ય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીએ આભાર પ્રસ્તાવ લાવતાં આ પ્રસ્તાવના પ્રભારીશ્રી શંકરભાઈએ ખૂબ સરસ શબ્દોથી એનું સ્વાગત કર્યુ અને એમણે એમ કહ્યું કે રાજ્યપાલશ્રીનું પ્રવચન એ ગુજરાતના વિકાસ માટેની એક ગીતા છે અને એના ઉપર વિપક્ષના નેતાશ્રીના અવલોકનો પણ હું સાંભળતો હતો. મારે એ કહેવું છે કે, એમણે એમ કહ્યું કે અમે આ સંમત એટલા માટે નથી થઈ શકતા કે આમાં પ્રશસ્તિ છે, કેટલાક લોકોનો એ સ્વભાવ હોય છે કે એમને પ્રશસ્તિ કરવી ગમે, એમને સારું જોવું ગમે, પ્રશસ્તિ કોની છે? પ્રશસ્તિ રાજ્યની પ્રજાની છે, પ્રશસ્તિ સુવ્યવસ્થાની છે, પ્રશસ્તિ રાજ્યની પ્રગતિની છે. આપણા પોતાના ગુજરાતની આવતીકાલે જવાની દિશાની છે અને એટલા માટે કે આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વ નીચે સમગ્ર ગુજરાતે જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે એનું ગુજરાતની પ્રજા ગૌરવ અનુભવી રહી હોય ત્યારે આ ગૃહે પણ એનું ગૌરવ અનુભવવામાં જરાય શરમ રાખવી જોઈએ નહિ. શું બન્યું ગુજરાતની અંદર? એમ કહી શકાય કે આ સમગ્ર દેશની અંદર, સમગ્ર એશિયાઈ રાષ્ટ્રોની અંદર ગુજરાત નંબર વન બની રહ્યું છે કોઈપણ રાજ્યની રાજ્ય વ્યવસ્થા જો માપવી હોય તો એના માપદંડ કયા હોય અને એ જ માપદંડોના આધારે હું રાજયની સુવ્યવસ્થાને આ ગૃહ સમક્ષ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. સમગ્ર એશિયાઈ રાષ્ટ્રોની અંદર, એશિયા પેસિફિક દેશોની અંદર કોઈ એક રાજ્યનો ૧૫.૭ ટકા વિકાસ થયો હોય તો એ ગુજરાતનો છે અને એમાં ગુજરાતની પ્રજાનું યોગદાન છે, ગુજરાતના મહાજનોનું યોગદાન છે, ગુજરાતના પ્રજાજનોનું યોગદાન છે, ગુજરાતની શાસન વ્યવસ્થાનું યોગદાન છે હું એ કહેવા માગું છું કે, ખાધ વધી, દેવું

આટલું થયું, દેવું કોના વખતથી શરૂ થયું અને કેટલું થયું એ સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય કોઈનો હોય તો જેણે રાજ કરવાનું છે એને હોય છે અને જેણે રાજ કરવાનું છે એણે દેવું ઘટાડવા માટેના પ્રયત્નો જે કર્યા હોય તો દેવું મૂકી જનારાઓએ એને અભિનંદન આપવા જોઈએ અને એટલા માટે હું આ સભાગૃહ દ્વારા જે હકીકતો છે એ હકીકતો મૂકીને કહેવા માગું છું કે રાજ્યની આર્થિક ખાધ ૭૫૦૦ કરોડની હતી તે ઘટીને ૨૨૦૦ કરોડ સુધી રાજ્યનો નાણાં વિભાગ લાવી શકેલ છે અને એ માટે રાજ્યના નાણાંમંત્રીશ્રીને આ સભાગૃહે અભિનંદન આપવા જોઈએ. જે રાજય આર્થિક શિસ્ત તરફ જતું હોય અને તેનું આર્થિક શિસ્ત સમગ્ર દેશના અર્થશાસ્ત્રીઓ માટે એક ઉદાહરણ બનતું હોય અને અન્ય રાજયની અંદર હું જાઉં કે અર્જુનભાઈ જાય ત્યારે ગૌરવથી કહી શકે અમારું રાજય, અમારું ગુજરાત તે આર્થિક ખાધને ઘટાડી રહ્યું છે તેનો ગૌરવ લઈ શકાય. આપણે શું કરી શકાય આ સમગ્ર વિકાસને ભારત સરકારના આયોજન પંચની સામે મૂક્યું અને આયોજન પંચે પહેલી વખત ૧૯૬૦ની રચના પછી દેશના આયોજન પંચે પહેલી વખત ૨૯ ટકાની ઐતિહાસિક વૃદ્ધિ આપી હોય તો ગુજરાતને, ગુજરાત નંબર વન બની રહ્યું છે અને એટલા માટે ૧૧ હજાર કરોડ રુપિયા આયોજન પંચે મંજૂર કર્યા તે અગત્યનું નથી પણ ૨૯ ટકાની વૃદ્ધિ આપી. કયાં વૃદ્ધિ આપી તો ગુજરાતના અર્થતંત્રની ઉપર અને ગુજરાતના વિકાસની જે મનોવૃત્તિ છે અને ગુજરાતની જનતાની જે ક્ષમતા છે અને તે ક્ષમતાનું જે નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે તેની ઉપર આયોજન પંચે વિશ્વાસ મૂક્યો કે આ એક વ્યકિત એવા છે કે સમગ્ર ગુજરાતની પાંચ કરોડની પ્રજાને વિકાસના માર્ગે લઈ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપણે તેને ૨૯ ટકાની વૃદ્ધિ આપવી જોઈએ. અનેક પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.

ગુજરાત નંબર-૧ એટલા માટે બન્યું કે મેં કહ્યું તેમ ગુજરાત કેવી રીતે નંબર-૧ બન્યું. ગુજરાત તે તેના ઔદ્યોગિક વિકાસની અંદર સ્પેશ્યલ ઈકોનોમિક ઝોનનો કાયદો આપણે પસાર કર્યો. આખા દેશની અંદર ગુજરાત પહેલું રાજય એવું છે કે જેણે સ્પેશ્યલ ઈકોનોમીક ઝોનનો કાયદો પસાર કર્યો અને બે સ્પેશ્યલ ઈકોનોમીક ઝોનની ઓલરેડી શરૂઆત કરી ચૂક્યા તે કાર્યાન્વિત કરી ચૂક્યા અને આવનારા એક બે વર્ષની અંદર બીજા પાંચ સ્પેશ્યલ ઈકોનોમી ઝોન બનશે અને પરિણામ શું આવશે? પરિણામ એ આવશે કે સમગ્ર ગુજરાતના ઉદ્યોગના વિકાસ કરનારાઓ તે ગુજરાતમાંથી વિશ્વના બધા રાષ્ટ્રોને ગુજરાતમાં થયેલી પેદાશ બતાવવાની છે. એટલા માટે મારે આ સભાગૃહના પ્રત્યેક સભ્યને કહેવું છે કે, આપણે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વની અંદર જવાનું છે ત્યારે તેની ઓળખ શું બની શકે? એટલા માટે આ સભાગૃહનો એકે એક ધારાસભ્ય ઉપરાંત તે જો નક્કી કરે કે અમે ગુજરાતના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છીએ. ગુજરાત તેની ઓળખ તે ગુજરાત છે અને ગુજરાતના સાત સ્પેશ્યલ ઈકોનોમીક ઝોનમાં બનેલી વસ્તુઓ તે વિશ્વના બજારોમાં જાય ત્યારે જેમ મેઈડ ઈન જાપાન તરીકે લોકો સ્વીકારે છે પણ આવનારા દિવસોની અંદર એવું બનવાનું છે કે મેઈડ ઈન ગુજરાતનો માલ તે વિશ્વના બજારમાં સ્વીકારવાના છે. આનું ગૌરવ લેવાનું અને ભાગીદાર થવાનું સૌભાગ્ય આપણને પ્રાપ્ત થયું છે અને તે માટે હું આ સભાગૃહનો આભારી છું.

હું એ વિષયો ઉપર જવા માગતો નથી કે કોંગ્રેસના રાજયની અંદર શું હતું અને આજે શું થઈ રહ્યું છે. હું એટલા માટે નથી જવા માગતો કે એક દિવસ અમદાવાદ શહેરની અંદર ચર્ચા શું થતી હતી ગોવાભાઈ, એ ચર્ચા થતી હતી કે આ સભાગૃહની અંદર ડાઈંગ અમદાવાદ, મરતું શહેર અમદાવાદ. અમદાવાદ શહેરની ૧૦૦ જેટલી મિલો તે ૧૯૮૦ થી ૯૦ના ગાળામાં મૃત્યુ પામી હતી. આજે તેની ઉપર અંબિકા મિલ મૃત્યુ પામી ગઈ, તે બંધ થઈ ગઈ. તેની અંદર ફરી એક વખત એસઈઝેડ એપરલ પાર્ક બની રહ્યો છે અને સમગ્ર વિશ્વના રોકાણકારો તે અંબિકા મિલની અંદર આવીને રેડીમેડ કાપડનો ઉદ્યોગ અને ગારમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કરીને તેને વિશ્વના બજારમાં મૂકી રહ્યો છે. ...અંતરાય... કેટલાક લોકોને દુ:સ્વપ્ન જોવાની ટેવ છે. પરેશભાઈ, કોઈ માનસિક રોગના ચિકિત્સકને બતાવી જોજો. કયાંક ખોટાં દુ:સ્વપ્નો તો આવતાં નથીને?

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સરકાર કોઈ કલ્પનાના આધાર ઉપર ચાલતી નથી, પરંતુ વાસ્તવિકતાના આધાર ઉપર આ સરકાર ચાલે છે. અગાઉની સરકારો કેવી રીતે કલ્પનાના આધાર ઉપર ચાલતી હતી એની અંદર હું જવા માગતો નથી કારણ કે પરેશભાઈ, આપ તો આ વખતે ચૂંટાઈને આવ્યા છો, પરંતુ હું તો આ સભાગૃહમાં ૭ મી વખત ચૂંટાઈને આવ્યો છું અને સાતમી વખતે આ વિધાનસભાગૃહમાં ચૂંટાઈને બેસું છું. એટલે મારે એ નહોતું કહેવું, પરંતુ હું કહું છું કે તમારા ત્યાં તમે જરા એક પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રી જીતુભાઈને જઈને પૂછી જુઓ કે તે વખતના રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી હતા એમણે એમના ઘેર ઈન્કમટેકસની રેઈડ પડાવી હતી. (અંતરાય)

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર છે કે....

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અહીંયાં કોઈનું નામ લઈને વાત કરવી તે યોગ્ય નથી, કોઈની હાજરી ના હોય એની વાત કરવી એ. યોગ્ય નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : તેમણે કોઈનું નામ લઈને વાત કરી નથી. (અંતરાય)

શ્રી અશોક ભટ્ટ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં કોઈનું નામ લીધું નથી.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં ફકત હોદ્દા સાથે વાત કરી હતી ત્યારે આપણે એ શબ્દો રદ કર્યા હતા. મેં પણ નામ નહોતું લીધું અને આપે એ રદ કર્યા હતા તો આ પણ રદ કરવું જોઈએ અને માનનીય અશોકભાઈ તમે પણ કાળજી રાખો. તમારા સભ્યો, પૂર્વ મંત્રીશ્રીની હાલત શું છે એ આપના સભ્યોને પૂછી જુઓ....અહીંયાં પૂછી જુઓ કે તમારા સભ્યોની શું હાલત કરો છો એ પૂછી જુઓ અમને ઉપદેશ ન આપો. અહીંયાં જ પૂછી જુઓ કે તમારા સભ્યોની હાલત શું કરો છો?

શ્રી અશોક ભટ્ટ : માનનીય અર્જુનભાઈ, અમારી જરા પણ ચિંતા ના કરતા, ભાજપનો સભ્ય...(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : અશોકભાઈ, આપ પણ બીજાં કોઈ અવલોકન ના કરો તો સારું. કોઈ બીજું અવલોકન ના કરો.

શ્રી અશોક ભટ્ટ: હું પણ એ વાતમાં પડવા માગતો નહતો, પરંતુ તેમણે કહયું ત્યારે મેં કહયું છે.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી : હું તો આ વખત આવ્યો છું અને એ તો સાતમી વખત આવ્યા છે તો પણ સુધરતા નથી.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું એ વાત કરતો હતો કે અમદાવાદ શહેરને ડાઈંગ અમદાવાદ કહેવામાં આવતું હતું. આજે વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતની ચર્ચા થઈ નથી, ગુજરાતની કલ્પના થતી નથી, પરંતુ વાસ્તવિકતાની ચર્ચા થઈ રહેલ છે અને એટલા માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં જે ગયા વર્ષે કહેવામાં આવ્યું હતું કે ૬૬ હજાર કરોડ રૂપિયાના એમ.ઓ.યુ. સાઈન થયા હતા. તો હું આ સભાગૃહના સભ્યોને કચ્છના પ્રભારી મંત્રીશ્રી તરીકે નિમંત્રણ આપું છું અને કચ્છના ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ અહીં ઉપસ્થિત છે. તો તમે આવો અને જુઓ કે આજે કચ્છની ધરતી ઉપર જે ઉદ્યોગો આવી રહયા છે એ ઉદ્યોગો આપણને વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતની પ્રતિતિ કરાવી રહયા છે. ૨૭ હજાર કરોડ રૂપિયાના ઉદ્યોગો કોઈ એક જિલ્લામાં આવી રહયા હોય તો એ કચ્છમાં આવી રહયા છે અને હું એટલા માટે આ કહું છું કે આ કોઈ કલ્પનાના આધાર ઉપર નથી (અંતરાય) માનનીય પ્રવિણભાઈ, કયા ઉદ્યોગ કયાં લાવવા એ અગત્યનું નથી, પરંતુ ઉદ્યોગો ગુજરાતમાં આવે તે વાત અગત્યની છે, માત્ર આપણે નડીએ નહીં તો પણ ઉદ્યોગો આવે અને એટલા માટે હું જે કહેતો હતો કે ગુજરાતમાં ઉદ્યોગો આવી રહયા છે અને જે ઉદ્યોગો ગુજરાતમાં આવી રહયા છે તે ઉદ્યોગો આ ગુજરાતની આવતીકાલ બનવાના છે. ગુજરાતનો જે ઓદ્યોગિક વિકાસ થઈ રહયો છે અને પરિણામે સમગ્ર દેશના માટે મુંબઈ એ ગેઈટ વે ઓફ ઈન્ડિયા હવે નહીં રહે, પરંતુ હું એમ કહીશ કે ૨૧ મી સદીમાં ભારતનું સમૃદ્ધિનું પ્રવેશદ્વાર એ ગુજરાત બની રહેશે, એ આપણા સૌના માટે ગૌરવની વાત છે. આ પાટલી કે પેલી પાટલી ઉપરના સભ્યશ્રીઓ હોય, પરંતુ આજે ગુજરાતની સમૃદ્ધિ વધી રહી છે, ગુજરાતે આ દેશની સમૃદ્ધિમાં અને વિકાસમાં યોગદાન કરેલ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ઔદ્યોગિક વિકાસની સાથે સાથે ગુજરાતે જે જળક્રાંતિ કરેલ છે એ જળક્રાંતિની વિગતો આ સભાગૃહમાં મારા અનેક સાથીઓએ આપી છે, પરંતુ એ સાથીઓની સાથે રહીને આપણે ગુજરાતમાં નર્મદાનાં પાણી પહોંચાડયાં, ગુજરાતમાં નદીઓને નાથી, ગુજરાતમાં સરીતાઓનો સંગમ જોયો, અમદાવાદ શહેરમાં સાબરમતી નદી સૂકીભઠ્ઠ નદી ગણાતી હતી. બારે મહિના સૂકી રહેતી સાબરમતી નદીમાં હવે બાર મહિના નર્મદાનું પાણી વહેતું થયું છે એ કંઈ નાની સિદ્ધિ નથી. આ સિદ્ધિના વધામણા કરવા તે આપણી ફરજ છે. અને તે ફરજને કારણે, બંધ કોણે બાંધ્યો, કયારે બંધાયો મને ખબર છે જેસાભાઈ, આ બંધનો પાયો નંખાયો તે જવાહરલાલ નહેરુજીના હસ્તે નખાયો હતો. હું સ્વીકારું છું. અભિનંદન આપું છું. પરંતુ આ બંધ માટે પર્યાવરણના પ્રશ્નો પેદા કરીને રાજીવ ગાંધીના સમયમાં તે ફાઈલ કેટલા વર્ષો સૂધી.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ રાજીવ ગાંધીનું નામ ન આપે, રાજીવ ગાંધી અને ઈન્દિરા ગાંધીના કારણે આ બંધ આવેલો છે, આપને આદત છે આંખમાં કંઈક આંજીને રડવાની, તે આદત રહેવા દો અશોકભાઈ, ભૂતકાળમાં આપે શું ધંધા કર્યા હતા તે મને ખબર છે.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : પર્યાવરણના પ્રશ્નના કારણે ખોસલા કમિશનને આ પ્રશ્ન સોંપવામાં આવેલ હતો અને એ પ્રશ્ન......

અધ્યક્ષશ્રી : આજની ચર્ચામાં અવલોકન ન કરો, પ્લીઝ ચર્ચા ઉપર જાઓ.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : રાજીવ ગાંધીની વાત કરી છે તે રેકર્ડ ઉપરથી રદ કરવી જોઈએ સાહેબ, રાજીવ ગાંધીનું નામ લઈ અને ટીકા થઈ છે તે રદ કરો.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : હું એમ કહું છું કે રાજીવ ગાંધી વડાપ્રધાન હતા ત્યારે....

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : હું એમ કહું છું કે આ યોજના બાજપાઈજીના વખતમાં બંધ થઈ છે, કોઈકને મોકલી તમે બાજપાઈના વખતમાં બંધ કરાવી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય અશોકભાઈ, આજે અવલોકનો કરવાની જરૂર નથી, સીધા ચાલીએ, પ્લીઝ.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : જો ૧૯૫૨માં આ યોજનાનો પાયો નંખાયો તે વખતે પૂરી થઈ હોત તો નર્મદાના પાણી ત્યારે પહોંચી ગયા હોત, ખોસલા કમિશનને આ નર્મદા યોજનાનો પ્રશ્ન સોંપવાની કોઈ જરૂર નહોતી, એ તો પછી વડાપ્રધાન મોરારજીભાઈ દેસાઈ થયા ત્યારે ૧૯૭૭માં એનો ચૂકાદો આવ્યો. (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : પર્યાવરણનો પ્રશ્ન ઉભો થયો એમ કહે છે, ટીકા નથી કરી, પ્લીઝ.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ખોસલા કમિશનને સોંપવામાં આવ્યો હતો, આ નર્મદા યોજનામાં કેમ વિલંબ થયો તેની વાત કરું છું, ખોસલા કમિશનને પ્રશ્ન કોના સમયમાં સોંપાયો? ખોસલા કમિશનનો રિપોર્ટ કોના વખતમાં આવ્યો? એ મોરારજીભાઈ દેસાઈ હતા ત્યારે આવ્યો અને ત્યાર પછી આ યોજના શરૂ થઈ. તે વખતે કેશુભાઈ પટેલ રાજયના સિંચાઈ મંત્રી હતા. આ યોજનાના વિલંબના કારણો હું આપું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : હવે યોજના પૂરી થઈ ગઈ છે. એટલે એમાં જવાની જરૂર નથી, બીજી ઘણી વાતો કરી શકો એમ છો.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : અમે આપનામાંથી પ્રેરણા લઈએ એવું કંઈક કહો.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ગોવાભાઈ, બસ.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : હું એમ કહું છું કે સમગ્ર દેશમાં ૨૧મી સદીમાં પ્રગતિનું કારણ ગુજરાત બનવાનું છે. અને સમગ્ર દેશની પ્રગતિનું કારણ ગુજરાત બનવાનું છે એટલા માટે કે સમગ્ર દેશમાં બે પોર્ટ ગુજરાતના એલ.એન.જી. પોર્ટ બન્યા છે, તેના કારણે સમગ્ર દેશનો વિકાસ એલ.એન.જી. ગેસના નેટવર્કના કારણે થવાનો છે. અને દહેજ તથા હજીરાના પોર્ટના કારણે ગુજરાત સમગ્ર દેશનું પેટ્રો કેપિટલ બની રહ્યું છે એટલું જ નહીં પણ પ્રશંસા એ કરવી જોઈએ કે આ ગુજરાતની ધરતીમાં રહેલ ક્ષમતા, ધોળકામાં આજથી ૩૦ વર્ષ પહેલા ઓ.એન.જી.સી.એ કૂવા ખોદ્યા હતા તે બંધ કરી દીધા હતા. રાજયના આ મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ ફરી એક વાર ૩૬ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને એ ધોળકાના બંધ પડેલા તેલ ક્ષેત્રોને બહાર કાઢયા અને એ તેલ ક્ષેત્રમાંથી નીકળતું તેલ એ કાળું સોનું છે, તેના માટે આપણે કેન્દ્ર સરકાર પાસે જઈએ, જો ઓફર આપી છે તો અમારી તૈયારી છે કે કેન્દ્ર સરકારને કહીએ કે ગુજરાતમાં જે તેલનો ભંડાર છે તે રીવાઈવ કરવા માટે, ફરીને પુનઃજીવિત કરવા માટે ગુજરાતનું પેટ્રોનેટ કૉર્પોરેશન છે એને સત્તા આપી દો, એ કાર્ય આપણને સોંપાય તો જે ધોળકાની અંદરથી તેલ નીકળ્યું છે એ રીતનું ખનીજતેલ ગુજરાત આપે અને સમગ્ર દેશને ૮૦હજાર કરોડ રૂપિયાનું તેલ આપણે આપી શકીએ તેમ છીએ. આ ગુજરાતની ધરતીની અંદર એટલી ક્ષમતા રહેલી છે. એ ક્ષમતા કોણે ઓળખી? એ ક્ષમતા ઓળખવા માટેના વૈજ્ઞાનિક પ્રયાસો કોના વખતમાં થયા? છેલ્લા બે વર્ષની અંદર આ થયું છે. તેના લીધે રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી માટે આભાર પ્રસ્તાવ લાવતા જો માનનીય શંકરભાઈ કે બાકીના સભ્યો રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી અંગેની વાત કરતા હોય તો સારું એ લાગે કે વિરોધપક્ષના નેતા તરીકે આપે પણ એની અંદર આપનો સૂર પુરાવ્યો હોત તો એ સૂર ગુજરાતના વિકાસની ગાથાની અંદર જોડાત અને ગુજરાતના વિકાસમાં આપ ભાગીદાર છો એ રીતે જોવાત.

શ્રી અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા : આપને આરબ કન્ટ્રીની અંદર મોકલવા જોઈએ. કારણ કે અહીંયા બહુ ખર્ચ કરો છો.

શ્રી અશોક ભટ્ટ : આપ ચિંતા ન કરતા. કોઈકવાર આરબ કન્ટ્રી ગુજરાતના પૅટ્રોલિયમ ડિપાર્ટમૅન્ટને બોલાવશે અને એની સાથે વાટાઘાટો કરશે. આપની કહેલી વાત આવતી કાલે સાચી પડશે. (અંતરાય) આપ સૂચન કરજો, આ નવી ટૅક્નૉલૉજી અપનાવી એના કારણે આ બન્યું છે.

ગુજરાતની અંદર લોકભાગીદારીનો કાર્યક્રમ અપનાવ્યો છે. એ કાર્યક્રમની અંદર ૧ લાખ ૩૭ હજાર ખેત તલાવડીઓ ગુજરાતના ખેડૂતોએ કરી છે. ૫૦ હજાર જેટલા બોરીબંધ કર્યા. ૫૦ હજાર જેટલા ચેકડેમો કર્યા છે. ૧૦૦ દિવસની અંદર ૧ લાખ ૩૭ હજાર ખેત તલાવડીઓ કરી. ભારત સરકારને પણ મોડે મોડે સૂઝયું અને એમણે એમ કહ્યું કે ૨૦૦૫ના વર્ષની અંદર ભારત સરકારે ૧ લાખ ખેત તલાવડીઓ બનાવવાનું કામ સમગ્ર દેશમાં નક્કી કર્યું. ગુજરાત ૧૦૦ દિવસમાં ૧ લાખ ૩૭ હજાર ખેત તલાવડીઓ બનાવી હવે ભારત સરકાર આખા વર્ષમાં એ કરશે. આ રીતે ગુજરાતના પગલે પગલે ભારત સરકાર ચાલી રહી છે.

આપણે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી બનાવી એ કાર્યાન્વિત થઈ. જેને ત્યારબાદ ભારતના ગૃહમંત્રીએ જાહેરાત કરી કે અમે પણ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી કરીએ છીએ. ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીનો એકટ આ સભાગૃહે પસાર કર્યો હતો એ ભારત સરકારને મોકલી આપ્યો. એટલે ગુજરાત સમગ્ર દેશની અંદર સારી પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રેરણાદાઈ રાજય બની રહ્યું છે. એનું ગૌરવ ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપવા માગતા નથી. એના ભાગીદાર બનવાનું હવે આપને આમંત્રણ આપુ છું. આપ એના ભાગીદાર અને સાથીદાર બનો, આના કારણે ગુજરાત શ્રેષ્ઠ રાજય બની રહ્યું છે, એમાં આપ ભાગીદાર બનો.

ગુજરાતની અંદર જળ ક્રાંતિ થઈ તેથી ગુજરાતના સામાન્ય ખેડૂતોનું અને કિસાનોનું દર વરસે કૃષિ ઉત્પાદન પહેલા નવ હજાર કરોડ થતું હતું એ ૨૧ હજાર કરોડ રૂપિયાનું થયું છે. (અંતરાય) માનનીય ગોવાભાઈ, આપને ખેડૂતોનું ખેત ઉત્પાદન વધ્યું છે એમાંય દુઃખ થાય છે? મને સમજ નથી પડતી કે તમે એકબાજુ એમ કહો છો કે હું ખેડૂત છું. મારે ખેતર નથી અને હું તો ખેડૂત પણ નથી. ખેડૂતનું ખેત ઉત્પાદન વધ્યું એ ખેડૂતની મહેનતના કારણે વધ્યું છે, ખેત તલાવડીના કારણે વધ્યું છે, ચેકડેમોના કારણે વધ્યું છે,

ડૅમોના કારણે વધ્યું છે, જળક્રાંતિના કારણે વધ્યું છે. તેને આવકારવા માટેના બે શબ્દો ગોવાભાઈ, તમને ન આવડતાં હોય તો ન બોલો. સારું ન દેખાતું હોય તો ન જૂઓ.(અંતરાય)

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતનું ગૌરવ શું છે એ હું કહેવા માગું છું. એ ગૌરવ હું નથી કહેતો. ગુજરાત એ ગૌરવશાળી રાજય છે એ હું નથી કહેતો. ભારતની યુ.પી.એ. સરકાર કહે છે. યુ.પી.એ. સરકારના શ્રમ વિભાગનો એક અહેવાલ આવ્યો. તેમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે ગુજરાત એક એવું રાજય છે કે જેણે સૌથી વધારે લોકોને રોજગારી આપી છે. સમગ્ર દેશમાં રોજગારી આપનારું કોઈ રાજય હોય તો ગુજરાત છે. એટલા માટે હું વિરોધપક્ષના નેતા દ્વારા યુ.પી.એ. સરકારના ભાગીદારોને નિમંત્રણ આપું છું કે તેઓ ગુજરાતની મુલાકાતે આવે. આવું રાજય પશ્ચિમ બંગાળ ન બની શક્યું, કેરલા ન બની શક્યું. ગુજરાત એક એવું રાજય બન્યું કે જે સૌથી વધારે રોજગારી આપી શક્યું. સૌથી વધારે રોજગારી આપનારા રાજય તરીકે સર્વશ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત થઈ. આને કોણે કોણે આવકાર્યું? ગુજરાતની રાજય વ્યવસ્થાને કોણે કોણે આવકારી? આ દેશના લોકો તો આવકારે છે પણ વિશ્વના લોકો આવે છે. સુવ્યવસ્થા, સુશાસન અને જાહેર વ્યવસ્થા માટે ગોલ્ડન એવોર્ડ કોમનવેલ્થ એસોસિએશને આપ્યો. આ કોઈ નાની સિદ્ધિ છે? આ ગુજરાતની પ્રજાની સિદ્ધિ છે. આ ગુજરાતના મહાજનોની સિદ્ધિ છે. આ ગુજરાતની કામ કરનારી શાસનવ્યવસ્થાની સિદ્ધિ છે અને આનું નેતૃત્વ એ ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીનું છે એમ કહેતાં આપણને સૌને ગૌરવ થવું જોઈએ.

ભૂકંપના પુનઃવસનના કાર્ય માટે યુનોએ સાસાકાવા એવોર્ડ આપ્યો. બીજાં કોઈને ન મળ્યો. લાતુરને ન મળ્યો, તુર્કીને ન મળ્યો. જાપાનને ન મળ્યો. ભૂકંપ માટે જે લોકોની કુશળતા ગણાતી હતી એ લોકોને યુનોનો આ એવોર્ડ ન મળ્યો. યુનોનો આ સાસાકાવા એવોર્ડ ગુજરાતને મળ્યો. તેના કરતાં પણ વિશિષ્ટ રીતે જે વિશ્વબેંકે ગુજરાતને એમ કહ્યું હતું કે અમે તમારી લોન બંધ કરી દઈશું. એક સમય એવો હતો કે ગુજરાતની લોન બંધ કરવાની વાત કરી કે તમને જે ધિરાણ આપીએ છીએ તે બંધ કરી દઈશું. વિશ્વબેંકે આવું કહ્યું હતું. એ જ વિશ્વબેંકે આજે ગુજરાતની ભૂકંપની પુનઃવસનની કામગીરીમાં પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે ઉત્કૃષ્ટ કાળજી રાખવા માટે વિશ્વબેંકનો ગ્રીન એવોર્ડ આપે છે. આ સિદ્ધિઓ સિદ્ધિઓ નથી? આ સિદ્ધિઓને આપણે સિદ્ધિઓ નહીં ગણીએ? એટલા માટે કહું છું કે સુશાસન એ ગુજરાતની લોક સંસ્કૃતિ છે. ગુજરાત એ શું છે જેને આપણે તમાશો કહીએ? ઉત્તરાયણ તમાશો કહેવાય? નવરાત્રિ એ તમાશો કહેવાય? ૧લી મેએ ગુજરાત રાજયની રચનાનો કાર્યક્રમ થાય તેને તમાશો કહેવાય? તમાશો એટલા માટે કહે છે કે તેના માટે એક પણ બલિદાન કૉંગ્રેસે નથી આપ્યું. ૧લી મેની ઉજવણી કોંગ્રેસના વખતમાં નથી થઈ. ૧૯૫૬ની ૮મી ઑગસ્ટે કોંગ્રેસ તો એવું કહેતી હતી કે અમારી લાશો ઉપર ગુજરાતનું રાજય થશે અને ગોળીઓ છોડતી હતી. નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ રાજયના મુખ્યમંત્રી તરીકે આવ્યા ત્યારે ગુજરાત રાજયના ૧લી મેના ઉત્સવોની શરૂઆત કરી. મહાગુજરાતના એક કાર્યકર્તા તરીકે કહું છું કે ગુજરાતના એ શહીદોના બલિદાનને યાદ આપનારો આ ઉત્સવ ઊજવાય છે.(અંતરાય) પ્રવિણભાઈ, આપ આપની ચિંતા કરો. આ પાટલીની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. (અંતરાય) ભાઈ, તમે રડો તેની ચિંતા તમે કરો. પ્રવિણભાઈ, મેં કયારેય તમને દખલ નથી કર્યા. હું એ કહેવા માગતો હતો કે ગુજરાત રાજયના ઉત્સવ દ્વારા ગુજરાતમાં કાર્ય કરનારાઓની પ્રતિષ્ઠા વધારવાનું કામ ગુજરાત સરકારે કર્યું છે એટલા માટે હું કહેવા માગું છું.

એક નવું ચિંતન દેશની અંદર આવી રહ્યું છે એ ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીનું છે. ટ્રેડ એન્ડ ટ્રેડીશન, કલ્ચર એન્ડ કોમર્સ, એન્ટરપ્રિન્યરશિપ એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ. આ ગુજરાતનો વિકાસ એની સાંસ્કૃતિક ધરોહરને આધારે થવાનો છે અને સમગ્ર દેશના વિકાસના લેખકોએ લખવું પડશે કે, ગુજરાત એ સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદની પ્રયોગભૂમિ છે. અને એટલા માટે હું શંકરભાઈના આ પ્રસ્તાવને આવકારું છું કે એમણે ખૂબ સારો શબ્દ કવિ નર્મદની કવિતામાંથી લીધો છે - કસુંબીનો રંગ, હર્ષનો રંગ કયો હોય? એની ચિંતા ન કરતા, મોસંબી પાકશે એટલે એનો રંગ પણ એ જ થશે. પરંતુ અમે એ રંગ જોડે નથી જોડાયા કે, જ્યારે સોમનાથ ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું, સોમનાથ ઉપરના આક્રમણ વખતે જે ધજા લઈને આક્રમણ કરનારા આવ્યા હતા એ રંગ જોડે અમે નથી જોડાયા, અમે જોડાયા છીએ એ રંગ છે કસુંબીનો રંગ. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જે રંગ ગાયો, એ કસુંબીના રંગ સાથે અમે જોડાયેલા છીએ. આ પક્ષ આ દેશની અંદર ક્રાંતિ લાવશે અને એ ક્રાંતિને કહેવાશે સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદની ક્રાંતિ. આ ક્રાંતિ ગુજરાતમાંથી શરૂ થશે અને ભારતમાં પ્રસરશે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત (સિધ્ધપુર): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય શંકરભાઈ માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચન પર આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે એમાં મને જણાવતાં એ વાતનું દુઃખ છે કે, રાજ્યપાલ સાહેબના પ્રવચનની અંદર રામ રાજયની વાત કરી. મને એમ થાય કે, રામ રાજયનું નામ, રામનું નામ રામ એ સત્ય વચન બોલે અને કદાપિ ફરે નહીં. આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હમણાંજ આપણા વડીલ મુરબ્બીશ્રી અશોકભાઈએ આ રાજયની સિદ્ધિઓની વાતો કરતા હતા. આજે મને કહેવાનું મન એ થાય કે જનશકિત, સુઝલામ્- સુફલામ્, પીવાના પાણીની કલ્પસર યોજના, ગ્રામ શકિત, કન્યા કેળવણી, સાયન્સ સિટી, જયોતિગ્રામ યોજના, ઉર્જાશકિત, રક્ષાશકિત આવા અનેક જુદા જુદા નામો આપ્યા. એમને પૂછી તો જુઓ છાતી ઉપર હાથ દઈને કહ કે, આ યોજનાઓમાં કેટલી પૂરી

થઈ? આજે ૫૦ ટકા કરતાં અનેકગણી ઓછી થઈ છે? બીજી બધી વાતો કરતા હતા. જ્યારે મારા પક્ષના નેતાશ્રી અર્જુનભાઈએ નર્મદા યોજનાની વાત કરી. એ પછી પાણીની વાત હોય, શિક્ષણની વાત હોય આપણે બધા સાથે જોડાઈને, હમણાં અશોકભાઈએ નર્મદા માટે કહેતા હતા. મને એમ થાય કે, જે વાત એમના પ્રવચનમાં કહેવામાં આવતી કે, કડીથી રાજસ્થાન સુધીની નહેર અમે લંબાવીશું, આજે એની શું સ્થિતિ છે? સૌરાષ્ટ્ર શાખાની નહેર. ભાસ્કર ગામમાં આવેલ તળાવની કેપેસિટી અમે ડબલ કરીશું. નર્મદા યોજના માટે ૯૦૦ કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરીશું. લાભાર્થી રાજયો પાસેથી ૭૦૦ કરોડ રૂપિયા લાવવાની વાત કરતા હતા. મધ્યપ્રદેશની અંદર અને રાજસ્થાનની અંદર એમની સરકાર હોય ત્યારે એ કેટલા પૈસા લાવ્યા? એ પૂછવાનું મન થાય. સુઝલામ્-સુફલામ્ યોજના દ્વારા સૂકા વિસ્તારને પાણી આપવાની વાત થઈ. હમણાં એમણે લાખો તલાવડીઓની વાત કરી. સુઝલામ્-સુફલામ્ યોજનાની અંદર જે તલાવડીઓ થઈ એ કેટલે અંશે સફળ થઈ? કેટલા ભૂગર્ભમાં પાણી ગયા? ટૅક્નીકલ પ્રશ્ન માટે મેં ગઈ વખતે પણ કહ્યું હતું. ટૅક્નીકલ મૂકો. એનાથી શું ફાયદા થાય, એ જોવું જોઈએ.

પ્રત્યેક ખેડૂતને સોઈલ કાર્ડ આપવાની વાત કરવામાં આવી હતી. આજે શું સ્થિતિ છે? ખેડૂતોની ચિંતા એટલા માટે થાય કે જ્યારે વિશ્વની અંદર ડબલ્યુ ટી.ઓ.ના કરાર ૨૦૦૬-૦૭માં થવાના છે ત્યારે આપણો ખેડૂત, ગુજરાતનો ખેડૂત એ વિશ્વના ખેડૂત સાથે કદમ મિલાવી શકે એવી યોજનાઓ થાય તો જે આપણે નિર્ભય રહી શકીએ, માત્ર કાગળ ઉપરની વાત ઉપર કદાપી આ થઈ શકતું નથી. એગ્રો એકસપોર્ટ ઝોનની રચના કરવાની માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રીએ વાત કરી છે. સૌરાષ્ટ્રની અંદર ડેરી ઉદ્યોગો બંધ પડેલા છે, એને પુર્નસ્થાપિત કરવાની જે વાત કરી હતી, કડાણા ડેમ ઉપર બનાસ વિયર સુધીની ૨૮૦ કિલોમિટર સુધીની સુજલામ્ સુફલામ્ની કેનાલ તૈયાર કરવાની જે વાત કરી હતી, મુકતેશ્વર, શીપુ જેવા નવા ડેમો છે એને ૧૦૦ ટકા ભરવાની જે વાત કરી હતી, મહાનગરોમાં સી.એન.જી. સંચાલિત વાહનો ફરતા કરવાની જે વાત કરી હતી, ગ્રામસભાઓનું જે આયોજન કરી લોકોના પ્રશ્નો હલ કરવાની જે વાત હતી, પંમામૃત શકિતના ફળ ગામના છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે એની વાત જે અહીં કરવામાં આવી હતી, ગુજરાત પેટ્રોલ કેમિકલ સ્ટેટ બનાવવાની જે વાત કરી હતી, ઓટોબાઈક સેકટર સી.એમન.જી. ના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાની જે વાત કરી હતી અને પોલીસ વિભાગની જે ખાલી જગ્યાઓ છે એ ભરવાની જે વાત કરી હતી, ગુજરાતમાં સૈનિક સ્કૂલો અને સોસાયટીની વાત કરી હતી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બધી જ વાત એમણે કરી હતી. આજે એમને પૂછો કે આ યોજનાઓ કયા સ્ટેજે અને કેટલે અંશે પૂર્ણ થઈ છે? જો એ આજે પૂરી કરી હોત તો અમે ચોક્કસ એમને આવકાર આપત કે ખરેખર આ તમે બહુ મહત્ત્વનું કામ કર્યુ છે. આ બધી યોજનાઓની અંદર જવાને બદલે હું જે મુખ્યત્વે અહીં આગળ વાત કરવા ઉપસ્થિત થયો છું.

ગુજરાતની જીવાદોરી નર્મદા છે અને નર્મદાનું કામ પૂર્ણ થાય જેના કારણે આપણો જે ખેડૂત છે એ બીજાની હારની અંદર ઉભો રહી શકે તો મને એમ લાગે છે કે ગુજરાતનો આપણે સાચો વિકાસ કર્યો એ તરફ આપણે જઈ શકીએ. ૨૦૦૪-૦૫ના પ્રથમ તબક્કામાં ૨૭૧ કિલોમિટરની જે લંબાઈ અને બીજા તબક્કાની અંદર ૬૪૧ કિલોમિટરની લંબાઈ કેનાલ શાખા નહેરનું જે લાઈનીંગ કામ પૂર્ણ કરવાનું જણાવ્યું હતું આજે એ મંત્રીશ્રીને પૂછો કે સો ટકા લક્ષ્યાંકમાં માત્ર ૮૮ ટકા જ કામ પૂર્ણ થયું છે. આ સરકારની એ જબરજસ્ત નબળાઈ આપણને દેખાઈ આવે છે. આપણને એમ થાય કે આ નર્મદાની અંદર ૧ લાખ ૩૩ હજાર હેકટર જમીનને સિંચાઈ આપવાની વાત અહીં આગળ કરવામાં આવી હતી, આજે માત્ર ૨૫ હજાર હેકટર જમીનમાં પાણી પૂરું પાડયું છે. આપણે વાત તો ૧ લાખ ૩૩ હજારની કરતા હોઈએ અને માત્ર ૨૫હજાર હેકટર જમીનને આપણે પાણી પૂરું પાડીએ તો ખરેખર એ પાણી પૂરું પાડવાની યોજનાની નબળાઈ પૂરવાર થઈ રહી છે. ૨૦૦૪-૦૫ની અંદર ૧૫૮૫કરોડ રૂપિયાની ફાળવણીની વાત કરી હતી. ડિસેમ્બર ૨૦૦૪ની અંદર માત્ર ૯૫૮ કરોડ રૂપિયા નર્મદા માટે ફાળવ્યા છે. નર્મદાની ચિંતા કરતા હોવાની વાત કરતા હોઈએ અને માત્ર ૬૦ ટકા જ ખર્ચ કરવામાં આવે એ આ સરાકારની નબળાઈ પૂરવાર થાય છે. એના ઉપરથી આ સાબિત થાય છે કે નર્મદાની મુખ્ય નહેરને સાંકળવા માટે ૧૪૪ કિલોમિટર વચ્ચે ૭ શાખાઓ, નહેરો છે અનું માઈનોર અને સબ માઈનોર કામ જે બાંધકામની સી.સી. એના કામના ટેન્ડરો છે એ મંજૂરી માટે આજે પણ બાકી છે. સૌરાષ્ટ્રની શાખાની નહેરનું પેટા શાખાનું ૧૦૪ કિલોમિટર સુધીનું માટીકામ અને અસ્તરકામ ગોકૂળગાયની ગતિએ આજે થઈ રહ્યું છે.

કચ્છ જિલ્લાની ચિંતા કરવાની વાત થતી હતી. મને એમ થાય કે કચ્છ જિલ્લાની અંદર જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો માટે કચ્છ જિલ્લાની અંદર સારી સુવિધાઓ થાય એના માટેની સરકાર વાત કરે, જ્યારે નર્મદા નહેરનું માત્ર ૭૮ કિલોમિટરની લંબાઈવાળું કામ આજે પણ બાકી છે. નર્મદાની જે વાત કરવામાં આવી હતી કે અમે ૨૧ નદીઓને પાણી પૂરું પાડવાના છીએ. આજ સુધીમાં તો માત્ર ૧૦ નદીઓને પાણી પૂરું પાડયું છે. કાગળ ઉપર વાત જુદી છે. મારે આજે કહેવું છે કે આપ જે કાગળ ઉપર બોલો છો એ કરો તો જ રામ રાજય બાકી રામના નામે વાત શું કરવી અને કામ શું કરવા? એ આખી જુદી પ્રક્રિયા છે.

સુજલામ્-સુફલામ્થી ખેતી અને ખેડૂતો સમૃદ્ધ અને આબાદ થાય એનો યશ આપને મળશે. ખેડૂતોના પસીનાની મહેનત હશે એનો અહેસાસ કરાવશે. મને થયું કે ખરેખર આપણા ખેડૂતોને ચોક્કસ એનો અહેસાસ થશે. મને એ વાતનું ભારોભાર દુઃખ છે કે રાજયમાં ૫૦ ટકાથી વધારે ખેડૂતોની આમદાની ઘટી છે. માનનીય અશોકભાઈ કહેતા હતા, પણ મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે હિતરક્ષક મેગેઝિનમાં ખેડૂતોએ દેવા નીચે આ ગુજરાતની અંદર ચાર લોકોએ આત્મહત્યા કરી. આંધ્રની જેવી પરિસ્થિતિ હતી એવી ગુજરાતની અંદર પરિસ્થિતિ ઊભી થવા માંડી છે. જે રીતે મોરબીના ડેમમાં મોટું બાંકોરું પડ્યું હતું એમ પંચમહાલ જિલ્લાના ડેમોમાં ઠેરઠેર બાંકોરા પડ્યાં છે. એક દિવસ એવી પરિસ્થિતિ ન થાય કે આના કારણે પંચમહાલ જિલ્લાને મોટી મુશ્કેલી આવી પડે. સરદાર સરોવર યોજનાની ઊંચાઈ બાબતમાં સુપ્રીમ કોર્ટે અવાર નવાર આપણને જે રીતે કહ્યું છે કે પુનઃવસનનું કામ ઝડપી થાય, જેના કારણે નર્મદાનો પ્રશ્ન દૂર કરી શકાય. આજે પણ એ પુનઃવસનની કામગીરીમાં કોઈ ઝડપ આવતી નથી. તેના કારણે આપણને અવાર નવાર બહુ મોટી તકલીફો પડે છે અને નર્મદાની કામગીરી પૂર્ણ કરી શકાતી નથી.

નર્મદા કેનાલ આધારિત પાણી પુરવઠામાં ઠેરઠેર નેટવર્કો નબળાં જોવા મળે છે અને સરદાર સરોવર નર્મદા કેનાલ આધારિત પાણી પુરવઠામાં જે સાત હજાર કરોડ રૂપિયાનો માસ્ટર પ્લાન હતો એમાં ૨૦૦૪ સુધીમાં માત્ર ૧૬૮૯ કરોડનો ખર્ચ કર્યો છે. આ પાણીની વિતરણ વ્યવસ્થા આજે પણ બાકી છે. મહત્ત્વની વાત જે અહીંયા થાય છે ત્યારે સુજલામ્-સુફલામ્ માટેની વાત થાય છે. વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં ૧૧૬૫ કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ અને નાબાર્ડ અને ઈફકો પાસેથી ૧૨૦૦ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની વાત હતી. આમ કુલ ૨૩૬૫ કરોડનું રોકાણ કરશે એવી માત્ર જાહેરાતો ગુમરાહ કરવા માટે હતી. આજે વાસ્તવિકતા આ યોજના માટેની જુદી છે. યોજનાના સાત નામ છે. વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫માં આ સાતેય યોજનાઓમાં સુધારેલા અંદાજો હતા એમાં કરોડોમાં કેટલાય રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજનામાં ૫૫ કરોડ હતા એ સુધારેલા અંદાજમાં ૪૮.૮૫ કરોડ, એટલે ૬.૧૫ કરોડનો ઘટાડો કર્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતની સિંચાઈની વિતરણ વ્યવસ્થા છે એમાં ૩૫ કરોડ હતા એ આજે ૧૫.૯૪ કરોડ એટલે કે ૧૯ કરોડનો ઘટાડો છે. મોટા બોરીબંધ હતા એમાં ૩૫ કરોડ હતા એની જગ્યાએ આજે ૨૭ કરોડ રૂપિયા એની અંદર ઘટાડ્યા છે. ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના આદિવાસી વિસ્તારમાં જળ સપાટીમાં વધારો કરવાની કામગીરી હતી એના માટે ૩ કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા હતા, સુધારેલા અંદાજમાં એક રૂપિયો પણ ન ફાળવ્યો અને ત્રણે ત્રણ કરોડ રૂપિયા આ વિસ્તારના ઘ ટાડ્યા છે. કાળુભારથી ધારાવાડ માટે ૭૧ કરોડ રૂપિયા હતા એની અંદર ૭૦ કરોડ ઘટાડ્યા છે. સરદાર સરોવર યોજનાનું માળખું હતું એમાં ૧૬૦ કરોડ હતા એની અંદર ૧૪ કરોડ રૂપિયા ઘટાડ્યા છે. નર્મદા મુખ્ય નહેરથી જુદી જુદી નહેર, તળાવો અને પાઈપ સિંચાઈની યોજના હતી એ ૩૬૦ કરોડની હતી એના અંદર ૨૬૫ કરોડ રૂપિયા. કુલ ૭૩૫ કરોડ રૂપિયામાંથી માત્ર ૪૧૫ કરોડ રૂપિયા સુધારેલા અંદાજમાં આપ્યા છે. આટલો મોટો ઘટાડો કર્યો છે. માત્ર એક નમૂનો આપું કે સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજના હતી એ ૬૪ ડેમોનું કામ પૂરું થયું છે. આજની તારીખમાં ૧૧૧ ચેકડેમોની એજન્સી નક્કી થઈ નથી. આ યોજનાની આ પરિસ્થિતિ છે. સુજલામ્-સુફલામ્માં ૫૬ ટકા જે કામ કરવાનું હતું તેમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ૧૫૦૦ તળાવો ભરવાની વાત હતી. આદિવાસી વિસ્તાર અને કચ્છ જિલ્લામાં ૧૮ ચેકડેમોની વાત હતી. આજે એનું કામ માત્ર નેવર એટલે ઓછામાં ઓછી સ્થિતિમાં થયું છે એવું આજે થઈ રહ્યું છે અને જ્યાં જ્યાં ખેત તલાવડીઓ અને ચેકડેમો થયા છે એવા નબળા કામો થયા છે કે કંઈક જગ્યાએ તો આ ચેકડેમો તૂટી ગયા જેના કારણે આજે પણ પાણી ભરી શકાય નહિ તેવી સ્થિતિમાં આજે અહીંયા આગળ થઈ રહ્યું છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું એ વાતની યાદ દેવડાવવા માગુ છું કે આજની સ્થિતિની અંદર જ્યારે આપણે નર્મદા માટેની આટલી મોટી ચિંતા કરવાની વાત કરતા હોઈએ અને આજની સ્થિતિમાં જે આંકડા સાથે ઘડાય. આપણને એમ થાય કે આ યોજના ક્યારે પૂર્ણ થશે? માત્ર જે કાગળ ઉપરની વાતો કરે એના કરતાં વાસ્તવિકતા તરફ આગળ વધે તો આપણને એમ થાય કે આ ગૃહની અંદર સાચી દિશામાં કામ કર્યું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, યુવક અને સાંસ્કૃત્તિક પ્રવૃત્તિ માટે નિરસતાથી માત્ર ૫૦ ટકા આજે પૂર્ણ થયું છે. એવી રીતે માહિતી અને પ્રસારણ અને પછાત જાતિનું કલ્યાણ છે એ બાબતમાં પણ આવી સ્થિતિ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નાણા અને આયોજન, કુટિરમાં ૧૦૦ ટકાના બદલે માત્ર ૪૩ ટકા જ એ પ્રમાણે સિદ્ધિઓ હાંસલ કરવામાં પણ નબળો દેખાવ કરવામાં આવ્યો છે. લોકાભિમૂખ વહીવટની જે વાતો કરતા હતા, બુદ્ધિસાગર પરિષદ માટેની જે વાત કરતા હતા આજે પણ એનો ઝીરો ટકા છે એ એમણે પોતે બૂકની અંદર સ્વીકારેલ છે. સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રની વાત હતી ૪૦ ટકા સિદ્ધિનું લક્ષ છે એ ૪૦ ટકા સુધી જ પહોંચી શક્યા છે. આવી અનેક સંપૂર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના જે હતી એની અંદર ૧૫૦ ટકા ગુજરાતને ફાળવણી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ એની અંદર ૪૭ ટકા ખર્ચ થયો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઈન્દિરા આવાસ યોજના છે જે ગરીબો માટેની યોજના છે જેથી નાનામાં નાના લોકોના મકાનો બને અને ગરીબ લોકોને ફાયદો થાય એની અંદર જે ૫૫ કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા હતા, એમાં

૫૫ કરોડમાં ૫૫ ટકા જ એની સિદ્ધિનું લક્ષનું કામ થયું છે, એની અંદર પણ એટલો બધો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે અવારનવાર આ સરકારમાં એની પણ ઘણી બધી ફરિયાદો આજે અહીંયા આગળ આવી છે.

સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી અને અહિંસા યુનિવર્સિટીની જે સરકાર ૨૦૦૨-૦૩ માં જાહેરાત કરી હતી એનો કોઈ ખર્ચ હજુ સુધી કરવામાં આવ્યો નથી. કૃષિ યુનિવર્સિટીની જે વાત હતી એનો જે ૧૦.૮૧ કરોડ ઘટાડો, માત્ર ૮૧ લાખનો જ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. ૧૫૦૦૦ જેટલા જે ગામો છે એને અર્ધ અછત પરિસ્થિતિમાં આજની તારીખે પણ સરકારે પછી એ અમરેલી, બનાસકાઠાં, સાબરકાંઠા અને દાહોદ હોય છતાંય સરકાર એના લક્ષમાં આજની તારીખમાં લેતી નથી. કલ્પવૃક્ષની જે યોજના છે એના ૧૦ કરોડની જોગવાઈમાં માત્ર ૧૬ ટકા જ એનો માત્ર ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આદિ જાતિ ગુજરાત પેટર્ન યોજનાની અંદર ૨૦૦૪ માં ૪૧.૪૪ ટકા જ એનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામસભાની જે વાતો અહીંયા આગળ કરતા હોય છે. જેની અંદર ગામના તમામ લોકોના પ્રશ્નો ઉકલી જાય તો આપણને કહેતા દુ:ખ થાય કે માત્ર ગ્રામસભાની અંદર ૮ ટકા જ લોકો હાજર રહે છે. એ બતાવે છે કે લોકોના ગ્રામસભાની અંદર જે પ્રશ્નો ઉકલાતા નથી. આજે પણ ૩૦,૦૦૦ જેટલા પ્રશ્નો ગ્રામસભાની અંદર બાકી છે. ડાંગ જિલ્લાની અંદર ૩૧૧ ગામોને જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ ૫૭૦૦ જેટલા કનેકશનો આજે પણ કપાઈ નાંખ્યા છે. આવી દરેક પ્રકારની યોજનાની વાતો છે એ બધી યોજનાઓને જો પરિપૂર્ણ કરી હોત તો અને આ બધું અહીં આગળ લાવ્યા હોત તો આપણને એમ થાત આખી વાત જુદી ટાઈપની કરવાની અને જુદી સિસ્ટમથી કરવાની થાત.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉદ્યોગ માટે હમણાં મુરબ્બીશ્રી અશોકભાઈ વાત કરતા હતા, ઉદ્યોગ એક મારો વિષય છે. હું રાજકારણની ટિપ્પણી ઉપર નહિ પડું, પણ ચોક્કસ ગૃહનું એક ધ્યાન દોરીશ જે કચ્છની અંદર ઉદ્યોગો આવી રહ્યા છે અને એની અંદર જ્યાં એકસાઈઝનો લાભ છે. ઘણી જગ્યાએ સેલ્સટેકસનો લાભ નથી પણ એકસાઈઝનો લાભ લઈ જે ઉદ્યોગો આવ્યા એના કારણે જે નાના મોટા ઉદ્યોગો છે એ ઉદ્યોગો આજે ગુજરાતમાં દિનપ્રતિદિન એટલા બધા પડી ભાંગ્યા છે કે, જેના કારણે આપણને એમ થાય કે, મલ્ટિનેશનલ કંપનીઓ આવવાથી નાના ઉદ્યોગો ઉપર એટલી મોટી અસર થાય છે કે, જેના કારણે આજે પણ કહી શકાય કે ગુજરાતમાં ૨૪ થી ૩૦ ટકા નાના ઉદ્યોગો આજે બંધ થયા છે. જયારે ૨૦૦૩-૨૦૦૪માં ૧૩ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : વિરામનો સમય થાય છે, આપનું પ્રવચન પૂરું થાય છે.

(વિરામ : બપોરના ૪.૩૦ થી ૫.૦૦)

(સભાપતિ શ્રી મહેન્દ્ર લી. મશરૂ અધ્યક્ષસ્થાને)

શ્રી દોલતરાય ના. દેસાઈ (વલસાડ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનની ઉપર આભાર દરખાસ્ત લઈને ભાઈશ્રી શંકરભાઈ આવ્યા છે એને અનુમોદન આપવા ઉપસ્થિત થયો છું.

મારે સામી પાટલીએ બેઠેલા મારા ખાસ સ્નેહી જેને હું ખૂબ જ માનપૂર્વક જોઉં છું એવા વિરોધપક્ષના નેતા ભાઈશ્રી અર્જુનભાઈ, એ વિદ્વતાભર્યુ વ્યકિતત્વ ધરાવે છે અને એના સભ્યો પણ ધરાવે છે પણ મારે સાહેબ આજે એટલું જ કહેવું છે, મારે લાંબી ટીકાટિપ્પણમાં પણ ઊતરવું નથી, મારે ફક્ત એટલું જ કહેવું છે કે, રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનની આભાર દરખાસ્ત ઉપર જે કંઈ ચર્ચા થઈ છે તે ચર્ચાના સંદર્ભમાં હું તો એ કહેવા માગું છું કે, રાજ્યપાલશ્રીનો આભાર જ નહીં, રાજ્યપાલશ્રીને અભિનંદન આપવા માગું છું કે જે રાજ્યપાલે, આજ સુધીની મારી વીસ વર્ષની કારકિર્દીમાં મેં કોઈપણ રાજ્યપાલને પૂરું ભાષણ વાંચતા જોયા નથી, જ્યારે આ રાજ્યપાલે ગંભીરતા સમજી છે કે આ રાજયને વિકાસના પંથે લઈ જવા માગે છે, એ ગંભીરતા આ રાજ્યપાલ સમજી શકયા છે, એ વિરોધપક્ષના મારા આટલા વિદ્વતા ધરાવતા સભ્યો સમજી શકતા નથી એટલું મને દુ:ખ છે એટલે હું અભિનંદન આપવા જ આવ્યો છું, મારે બીજી કોઈ જ વાતો કરવી નથી.

બીજી વાત મારે એ કરવી છે કે, સામા પક્ષે જે કોંગ્રેસ છે એની આજે દિલ્હીમાં સરકાર છે અને એમણે રચેલ આયોજન પંચ શ્રી આહલુવાલિયાના ઉપાધ્યક્ષસ્થાને, એ પંચના સભ્યોએ બે-બે કલાક સુધી આ સરકારની તારીફ કરી અને વિકાસની ચર્ચા કરી અને વિકાસની સરાહના કરીને અગિયાર હજાર કરોડ રૂપિયા, એક પણ પૈસો કાપ્યો નથી અને આજ સુધી મેં જોયું છે, વીસ વર્ષના મારા ઈતિહાસમાં કે અમારી સરકાર હોવા છતાં પૂરેપૂરી કોઈ દિવસ આયોજનમાં અમારી દરખાસ્ત સ્વીકારી નથી, જ્યારે આજે દરખાસ્ત સ્વીકારવાના કયા કારણો છે? એ આપણે બધાએ વિચારવાનું છે અને સમજવાનું છે. એનું કારણ એ છે કે, શ્રી નરેન્દ્રભાઈની સરકારે જે કાંઈ યોજનાઓની ચર્ચાઓ કરી એ યોજનાઓની સરાહના, વિરોધપક્ષના હોવા છતાં એમણે કરી છે અને એટલા માટે હું આજે એ પ્લાનિંગ કમિશનના ચેરમેનને અને પ્લાનિંગ કમિશનને અભિનંદન આપવા ઉપસ્થિત થયો છું. મારે બીજું ઘણું કહેવાનું છે અને મને તો એમ લાગે છે કે, સાહેબ હવે તો મારી વિનંતી એ છે કે, સભ્યોને કેટલા મોટા અવાજે બોલવું તે પણ નિર્ણય કરવો પડશે એવું લાગે છે. કારણ કે, જે રીતે અશોકભાઈએ વાત કરી તેનાથી ડબલ અવાજે ભાઈશ્રી બળવંતસિંહજીએ વાત કરી, એટલે. મારું તો અડધું જે

કહેવાનું હતું તે ભૂલી ગયો, આખું મગજ જ મારું બગડી ગયું એટલે મહેરબાની કરીને સાહેબ સ્વરનું પણ કાંઈ થતું હોય કે કેટલા અવાજે બોલવું તે પણ નિર્ણય થાય અધ્યક્ષસ્થાનેથી તે પણ કરવા જેવું છે.

શ્રી ગોવાભાઈને ખાસ મારે કહેવાનું કારણ કે, એ ખેડૂત છે. હું અહીંયા રજૂઆત જ કરવા માગું છું અને સાચી રજૂઆત, કે તમે અને આપણે જોઈએ છીએ કે, સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ, આપને કોઈને વિચાર આવેલો? હું વીસ વર્ષથી આવું છું અને ગુજરાત રાજયની આટલી સરકારો આવી અને ગઈ પણ આ સરકારને એ વિચાર આવ્યો, સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ, આપણે જો આપણું સ્વાસ્થ્ય સાચવતા હોઈએ તો, આપણે સ્વાસ્થ્યની તપાસણી કરાવીએ છીએ તેમ આ સરકાર છે, પ્રગતિવાળી સરકાર કે જેણે ખેડૂતોનું વિચાર્યુ અને ખેડૂતોને સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ, એટલે સોઈલ નહીં, એકે એક ટુકડો ખેડૂતના એક ટુકડાનું પૃથ્થકરણ કરીને એ ટુકડામાં કઈ જાતની ખેતી થઈ શકે, કેટલું પાણી આપવુ જોઈએ, કયું ખાતર આપવું જોઈએ એની ચિંતા જો કોઈએ કરી હોય તો આ સરકારે કરી છે. કારણકે આ સરકાર જાણે છે કે ખેડૂતો આબાદ તો દેશ આબાદ અને અમે જાણીએ છીએ. આજ સુધી આવી આબાદી જોઈ નથી તમે જોઈ શકો છો. એક વર્ષમાં તમારી ખેતીમાં તમને સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ મળી જવાનું છે. આ તો ડાયાબીટીસ થાય અને બીજી દવા લીધા કરીએ. ખાતરનો જેપ્રયોગ કરવાનો હોય હું એમ માનું કે ગોવાભાઈ બે મણ નાખે તો હું ચાર મણ નાખું એવી હરિફાઈને લીધે ખેતી બગડે છે એવી કાળજી પણ એમણે લીધી છે.

બલવંતસિંહ બહુ ટીકા કરતા હતા સુજલામ સુફલામની. સુજલામ સુફલામમાં ઈનબેલેન્સ વોટર છે. મારા વલસાડ વિસ્તારમાં, દક્ષિણ ગુજરાતમાં અમે પાંચ હોર્સ પાવર કે ૧૦ હોર્સ પાવરની મોટરથી ખેતી કરી શકીએ છીએ જ્યારે અહીં ૧૦૦ હોર્સ પાવરવાળી મોટર જોઈએ. સુજલામ સુફલામ યોજના છે એમાં નર્મદા, કડાણા, ખેત તલાવડી, તળાવ, ચેકડેમ મળીને તમારા પાણીનું સ્તર ઉંચુ લાવવા માગીએ છીએ. આજે વીજળી ખાસ છે. અમારે પાંચ હોર્સપાવરવાળી મોટર જોઈએ તમારે સો હોર્સપાવરવાળી મોટર જોઈએ. ૯૦ હોર્સ પાવર બચાવવાના છે. આ જાતની પ્રગતિ કરતી સરકારે બધો વિચાર કર્યો છે. એક જ બાજુ ગાયા કરવાનું? ટીકાકરવાની? હકારાત્મક અભિગમ કેળવો એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. સૂચન એવા કરો જેનાથી અમે વધારે પ્રગતિ કરી શકીએ. મારે લાંબુ કહેવું નથી. આજે મારે બે જ વસ્તુઓ કહેવાની છે મારે રાજયપાલશ્રીને અભિનંદન આપવા છે અને આયોજન પંચ, પ્લાનીંગ કમિશન કે જેને તમારે કહેવું હતું કે આ શું કામ પાસ કરો છો? ત્યાં કેમ ન ચાલ્યું? કારણકે તમારી વાત સાચી હોય તો ને? ખોટું કેવી રીતે સમજાવી શકાય? સાચું જ સમજાવી શકાય અને સાચું સમજાવીને અમે ૧૧૦૦૦કરોડ લાવ્યા. એ તો તમે સમજી શક્યા હશો કે આજ દિવસ સુધી કોઈપણ સરકારે આયોજન મંડળને જેકાંઈ દરખાસ્ત કરી છે એ કોઈએ સ્વીકારી નથી અને કાપ આવે છે જ્યારે આ દરખાસ્ત સંપૂર્ણ સ્વીકારી છે. ૧૧૦૦૦કરોડ નહીં ૨૦૦ કરોડ વધારીને આપ્યા છે એવું મેં છાપામાં વાંચ્યુ છે.મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારી નમ્ર વિનંતી છે કે મહેરબાની કરીને હકારાત્મક અભિગમ અપનાવો, આપણા સહિયારા પુરુષાર્થથી ગુજરાત સરકાર, ગુજરાત રાજય પ્રગતિશીલ માર્ગે જાય અને એ માર્ગે જવા માટે ઈશ્વર વિરોધ પક્ષના સભ્યોને સદ્‌બુદ્ધિ આપે અને તાકાત આપે એવી પ્રાર્થના કરીને વિરમું છું.

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન કા. ચુડાસમા (માંગરોળ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી જે આભાર પ્રસ્તાવ લાવ્યા છે તેમાં મારાં સૂચનો આપું છું. રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર ગઈકાલથી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. આજે સવારે, બપોરે અને સાંજે ચર્ચામાં તમામ ગૃહના સભ્યશ્રીઓએ એક યા બીજા બહાના નીચે ગુજરાત રાજયના વિકાસ અને પાંચ કરોડની પૂજાના સુખ, દુ:ખના ભાગીદાર કેમ થવાય એ માટે પ્રયત્નો અને સૂચનો કર્યા છે. આ રાજયપાલશ્રીનું પ્રવચન સાંભળ્યું, અભ્યાસ કર્યો, જોયું તો શબ્દો અલંકારિક ભાષા, દરેક યોજના પાછળ નવા નવા નામો, અને યોજનાને માત્ર કાગળ ઉપર રાખવાની પ્રક્રિયા એમાં મને સમજણ નથી પડતી. આ રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર મુરબ્બીશ્રી દોલતભાઈ અમારા વડીલ છે અમે એમને વંદન કરીએ છીએ. દોલતભાઈએ વાત કરી મને ખૂબ ગમ્યું કે રાજયપાલશ્રીએ પ્રવચન પૂરું વાંચ્યુ. રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનની ગઈ બજેટ કોપીનો મેં ઉંડો અભ્યાસ કર્યો હતો. મારે એટલું કહેવું છે કે એ જ યોજના, શબ્દો, રૂપાળા નામ, બહુ સુંદર વિંટળાયેલા પોટલાની અંદરની જે વાત છે એનું સરવૈયું કરીએ તો એમાં સરવૈયામાં કેટલા ટકા સફળતા મળી એ મહત્વનો હિસ્સો છે. માત્ર નામથી, સંદર યોજના કરવાથી કે માત્ર જાહેરાત કરવાથી પછી કોઈને દુ:ખ લાગે કે તમાશો શબ્દ બોલ્યા, ન બોલવો જોઈએ, સારું ના કહેવાય પણ માત્ર જાહેરાત કરવાથી, ખોટી વાતો કરવાથી પ્રજાને પરિણામ મળવાનું નથી.

માનનીય નરોત્તમકાકા નથી. મારે કહેવું છે કે નર્મદાના નીર ગામડે ગામડે આવ્યા. કર્યા વધામણા, નર્મદાના નીર ગામડે ગામડે પોહોંચાડ્યા તે સાચી વાત છે. મુરબ્બીશ્રી દોલતભાઈ આપને કહું કે ગામડાની ગ્રામ પંચાયતને જ્યાં આગળ પૈસા ભરવાની તાકાત નથી, ત્યાં નર્મદાના પાણી ભાડે આપવામાં આવે છે, તે પાણી ગ્રામપંચાયત આજે પણ લઈ શકતી નથી. અમે અમારા વિસ્તારમાં નર્મદાના પાણી મળ્યા તે અંગે તમામ ગ્રામ પંચાયતે ઠરાવ કરી દીધો, નગરપાલિકાએ ઠરાવ કર્યો. આ પૈસા ભરવાની તાકાત અમારામાં નથી. પ્રજામાં તાકાત નથી. મારે સ્પષ્ટપણે કહેવું છે કે સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. પાણી આપવું એ આપણું વચનબદ્ધ છે. ગામડાની પ્રજાને નર્મદાનું પાણી વગર પૈસે આપવામાં શું વાંધો છે. બધી જ યોજનામાં પૈસા મળે તેવું નથી

હોતું. માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી કહેતા હતા કે દેવું થાય એ વિકાસની ગાથા છે, પરંતુ એ દેવું કોના માટે થાય છે ? દેવું કયા કામ માટે થાય છે એ જોવું મહત્ત્વનું છે, એટલે જ રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં કહ્યું હોત કે નર્મદાના પાણી અમે ગામડે ગામડે મફત આપીશું, તો હું અભિનંદન આપત.

જ્યોતિ ગ્રામ યોજના. જ્યોતિ ગ્રામ યોજનામાં ગામમાં ૨૪ કલાકની વીજળી એ સારી વાત છે. ગામમાં વીજળી મળે સૌ કોઈને અને અહી બેઠેલા સભ્યશ્રીને આનંદ હોય, પરંતુ આપના માધ્યમથી મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને કહેવું છે એ કહેવું છે કે વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ પ્રવચનમાં વાત કરી છે કે કાંઠાળ વિસ્તાર, દરિયાઈ પટ્ટીનો વિસ્તાર, ડાંગ અને દાહોદનો વિસ્તાર જે વિસ્તારના લોકો ગામમાં રહેતા નથી, પરંતુ ગામડાની વાડીએ રહે છે. એટલા માટે કે દરરોજ ૩-૪ કિલોમિટર વાડીએ જવાના બદલે ત્યાં રહેવું અને ભેંસો દોહવી, કામ કરવું આ વ્યાખ્યા સાથે જોડાયેલ અને એમાં જ્યોતિગ્રામ આવવાના કારણે શું થયું. હું એક ગામમાં ગઈ. મેં એમ કહ્યું કે, જ્યોતિ ગ્રામ. લોકો ફફડવા મંડ્યા, બીવા મંડ્યા. મેં પૂછયું કે શું થયું ? તેમણે કહ્યું બહેન જ્યોતિ ગ્રામ આવવાથી અમને ૬-૮ કલાક પણ લાઈટ નથી મળવાની અને ૧૮ કલાક અંધારામાં ફસાવવાનું. જ્યોતિ ગ્રામ યોજના કરી, ૨૪ કલાકની યોજના કરી છે, તો વાડીએ રહેતા વિસ્તારમાં તમે શું કરવાના ? સ્પષ્ટ વાત કરી દીધી છે કે ૮ કલાક આપવાના નથી, તો કોઈ યોજના કરી છે ખરી ? જાહેરાત કરો. રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનમાં લખવું હતું, રાજયપાલશ્રીનો ઉદેશ આપવો હતો, એવી કોઈ વાત કરી નથી. એવી વાત થાય તો મને ગમશે. વીજળીની બાબતમાં ગુજરાત ખેડૂત આધારિત રાજ્ય છે. જે વિસ્તારનો તાત દુ:ખી હોય તે વિસ્તારની રાજ્ય સરકાર સુખી ન હોઈ શકે. મારે સ્પષ્ટપણે કહેવું છે કે આ ખેડૂત માથે દેવું મૂકીને રડે છે. આજે આ ખેડૂતની સ્થિતિ વિચારવાનો સમય આવ્યો છે. ખેડૂતને વચન આપ્યું હતું કે મીટર નહિ મૂકીએ. હોર્સપાવર વધારીશું નહિ. ભાવ આપીશું, જોઈએ તે આપીશું. માનનીય મંત્રીશ્રી, સભ્યશ્રી કહેશે કે ૫ કરોડની પ્રજાએ અમને અહીયા બેસાડ્યા છે. કબુલ. કદાચ ખોબેધોબે મત આપીને પ્રજાએ વિશ્વાસ મૂકી બેસાડ્યા. આપણી રીતિ-નીતિ, આપણું વહીવટી તંત્ર પ્રજા ત્રાહીમામ થઈ ગઈ છે. પરિણામ સંસદની ચૂંટણીમાં બતાવી દીધું કે સંસદમાં ચૂંટાયેલા સભ્યો આજે લોકસભામાં તમારા કેટલા થયા ? ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોને આપેલા ખોબેધોબે મત અને સંસદનું પરિણામ કેમ જુદું આવ્યું ? પ્રજાએ એલાર્મ વગાડ્યું, પ્રજાએ ઘંટી મારી. હવે સમજી જવાની જરૂર છે. સમજવાની જરૂર એટલા માટે છે કે અહીયા બેઠેલા લોકો છે ને તેમને પ્રજાએ એલાર્મ, ઘંટડી મારી હતી, પરંતુ નહોતા સમજ્યા. બહુ અહંમમાં દોડવાની જરૂર નથી. સમજવાની જરૂર છે. ખેડૂતોને તત્કાળ યોજના નીચે અપાયેલા કનૅક્શન આજે ખેડૂતને અપાયેલા એ ટાઈપના કનૅક્શન એમાં ખેડૂતોને ચોરીમાં પકડે છે. મારે આપને વિનંતી છે કે ૫ વીઘાનો નાનો ખેડૂત કનૅક્શન પાંચ-પાંચ, દસ-દસ વર્ષથી માગણીની લાઈનમાં ઊભો છે, તેને કનૅક્શન નથી મળતું. તેઓનો પાક સૂકાય છે. ઘરમાં રોટલા વગર બાળકો ટળવળે છે. ત્યારે તે લોકો લંગર મારીને પાવાનો પ્રયત્ન ન કરે તેનો માટે હું એમ કહું છું કે તમે લંગર મારીને કે કનેકશન મેળવીને પાણી પાવું હોય તો પાઓ પણ છોકરાને ભૂખ્યા ન મારો. શા માટે કનેકશન નથી આપતા અને ખેડૂતોની વીજળીની ચોરી પકડવા માટે થઈ જે રીતે ગાડીઓનો ધમધમાટ છે તો તેમાં પણ વિચાર કરવો પડે તેમ છે.

વાતો કરવી હશે તો રાજયપાલશ્રીએ પ્રવચન કર્યુ છે તેમાં ઘણી બધી વાતો થાય. મારે એક વાત કરવી છે અને તે વાત છે કન્યા કેળવણીની. કન્યા કેળવણીની વાતમાં કોઈએ કહ્યું કે રથ ફેરવ્યો, કોઈએ એમ કહ્યું કે શું કર્યુ તે મહત્ત્વનું નથી. મારે એ જાણવું છે કે આ દેશની દીકરીઓ હોય, રાજયની દીકરીઓ હોય અને જ્યાં સુધી દીકરી સંપૂર્ણ જ્ઞાની ન થાય, દીકરી સંપૂર્ણ શિક્ષિત ન થાય ત્યાં સુધી રાજયનો વિકાસ હોય કે દ ારના સામાજિક વ્યવહારો હોય અથવા તો કુરિવાજો હોય તે દૂર કરવામાં તકલીફ પડશે. ત્યારે કન્યા કેળવણી મફત આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે? કન્યા કેળવણી મૅડિકલમાં કે એન્જિનિયરીંગમાં, નવી ખૂલતી મૅડિકલ કે એન્જિનિયરીંગ કૉલેજોમાં ભણતી તમામ દીકરીઓને મફત અને ફ્રી શિક્ષણ આપવા માગો છો ખરા? ત્યારે રાજય સરકાર તે બાબતની વાત કરે. માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી મારે બીજી વાત કરવી છે બાળ વિકાસની. બાળ વિકાસમાં ત્રણ વર્ષ પછીની આંગણવાડીઓ છે, ત્રણ થી છ વર્ષની છે. પરંતુ બાળકના જન્મથી ત્રણ વર્ષ સુધીમાં તેની બુદ્ધિનો વિકાસ થઈ જાય છે ત્યારે આ ઝીરોથી ત્રણ વર્ષ સુધીના બાળકો માટે કોઈ યોજના નથી. તેની રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનમાં વાત કરી હોત તો આનંદ થાત. ઝીરોથી ત્રણ વર્ષની કોઈ યોજના નથી. આગળ વધીને કાયદો અને વ્યવસ્થા અને રક્ષાશકિત, માનનીય બળવંતભાઈએ વાત કરી. ઘણા બધા નામો આપ્યા છે.

મારે રક્ષાશકિતની વાત કરવી છે. કાયદો અને વ્યવસ્થાની એક વાત કરવી છે. એ વાત એટલા માટે કરવી છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિમાં મારા આંકડાઓ નથી પરંતુ સરકારશ્રીએ આપેલા આંકડા છે, વિધાનસભાની પ્રશ્નોત્તરીમાં પુછાયેલા આંકડા છે તેના જવાબમાં મહિલાઓ ઉપરના બળાત્કારો, મહિલાઓની છેડતીના કેસો, મહિલાઓના અપહરણના કેસો, બાળકોના અપહરણના કેસો અને આ આંકડા સરકારશ્રીએ આપ્યા છે. તે ચોકવનારા છે. છતાં આપણે શંકરભાઈ એમ કહીએ કે રામરાજય. રામરાજય હોય તો કયાંય ફરિયાદ ન હોય. રામરાજય હોય તો કોઈના મનમાં દુઃખ ન હોય. અહીંયાં તો તકલીફ એ છે કે આ રામરાજયમાં સુખી કોણ છે તેને ગોતવો પડે. હું કોઈ પોલિટીકલ વાતમાં નથી પડતી. પરંતુ આ સરકારના

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમના હ્રદયથી તેમના આત્માના અવાજને વળગીને કહે કે અમે આ સરકારમાં કેટલા સુખી છીએ. મને એમ લાગે છે કે આ રામરાજય નથી તેથી હું તેને અનુમોદન આપી શકતી નથી.

ડૉ. કનુભાઇ કળસરિયા (મહુવા): માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, મહામહિમ રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર આભાર પ્રસ્તાવ લઈને માનનીય શંકરભાઈ ચૌધરી આ ગૃહ સમક્ષ આવ્યા છે, તેમાં મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે ઉપસ્થિત થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, બે બેઠકથી સતત ચર્ચા ચાલી રહી છે. માનનીય રાજયપાલશ્રીએ જે પ્રવચન વાંચ્યું તેની ખૂબ જ કદર કરવામાં આવી છે. સતત દોઢ કલાક સુધી સાતત્યપૂર્ણ વાંચ્યું તેનાથી સમગ્ર ગૃહ પ્રભાવિત થાય તે સ્વાભાવિક હતું પણ પ્રભાવિત થવાનાં બીજાં કારણો છે. તે કારણો એ પ્રવચનનો સાર છે. તેનો મુખ્ય સાર સિમાચિહ્નરૂપ છે. ગામડા અને શહેરની ભેદરેખા મટાડવા માટેના પ્રયત્નો તેમાં મળે છે. આઝાદી મળે ૫૦-૫૫ વર્ષ થઈ ગયા પછી પણ ગામડાઓ અને શહેરનો ભેદ સતત વધી રહ્યો હતો અને તેના કારણે ગામડા તરફથી લોકોની દોટ સતત શહેર તરફ રહેતી હતી. તેના કારણો આપણે જાણતા હતા છતાં પ્રયત્નો કરવામાં ન આવ્યા અને તેના કારણો બહુ સ્પષ્ટ છે. ગામડાઓમાં રહીએ તો બાળકોનું ભણતર બગડે, ગામડાઓમાં રહીએ તો પીવાનું શુદ્ધ પાણી ન મળે, ગામડાઓમાં રહીએ તો ૨૪ કલાક વીજળીની સુવિદ્યા ન મળે આવા અનેક પ્રશ્નો હતા. એક પછી એક આ પ્રશ્નો ઉકેલવાના પ્રયત્નો સરકાર સતત કરતી આવી છે અને એમાં જેને જબરજસ્ત પ્રતિભાવ મળ્યો છે એવી એક યોજના જયોતિગ્રામ યોજના છે કારણકે કાયમ માટે લોકોને એવું થાય કે, શહેરોમાં શું કામ આવે છે? તો કહે કે શહેરોમાં આ બધી સગવડો છે, લાઈટની સગવડ છે, પાણીની સગવડ છે, શહેરમાં સારા રસ્તા મળે, સંદેશા વ્યવહારની સગવડ મળે, ટી. વી., રેડિયો અને સાથે સાથે ટેલિફોન, એ બધી સુવિધાઓ છે, એ સુવિધાઓ અત્યારે તો ચોક્કસપણે બધે પહોંચી ગઈ છે પણ જે રસ્તા અને લાઈટની સુવિધા બાકી હતી એમાં ૨૪ કલાક વીજળીની યોજના દ્વારા એક જબરજસ્ત ફરક પડી ગયો છે. સાત હજાર ગામની યોજના પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, મારા મહુવા તાલુકાના ૪૧ ગામમાં જયોતિગ્રામની યોજના થઈ ચૂકી છે અને એ ગામોના લોકો ખૂબ ખુશી વ્યક્ત કરે છે. સાથે સાથે અમુક માનનીય સભ્યશ્રીઓએ એમ કહ્યું કે, ખેતરોમાં જે લોકો રહે છે એમને તકલીફ છે, એ વાત સાચી છે એની રજૂઆત પણ થઈ છે એના માટે યોગ્ય ઉકેલની દિશામાં આ સરકાર પ્રયત્નશીલ છે જ અને એનો પણ ઉકેલ આવશે જ એટલે એ માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.

બીજો પ્રશ્ન છે કે પાણી, તો નર્મદા અને મહીનું પાણી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે ખારું પીનારા અને કડવું પીનારા ગામડાંઓ હતા, ખાસ કરીને અમારો વિસ્તાર છે એ દરિયા કિનારાનો વિસ્તાર છે, આપણો જ્યારે ૧૬૦૦ કિલોમીટર દરિયાકિનારો છે, ત્યારે એ દરિયા કિનારાની ખારાશ દિવસે દિવસે જમીનમાં વધતાં તરના પાણીને ખારાં બનાવી દે છે. તો એના માટે પીવાના પાણીનો મોટો પ્રશ્ન હતો એ પીવાનું પાણી મોટા ભાગના બધા ગામડાંમાં મળતું થઈ ગયું છે, અને થઈ રહ્યું છે. બાકી યોજનાઓ જે કોઈ છે એમાં પણ ઝડપભેર આગળ વધી રહ્યા છે. માનનીય ડો. ચંદ્રિકાબહેને કહ્યું કે મફત પાણી આપવું જોઈએ, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે આ ભાજપની સરકારનો પ્રયત્ન એ છે કે લોકોની ભાગીદારીથી આગળ વધવું. લોકોને અંદર જોડવા. જો લોકોને જોડીશું નહીં તો એને પોતાપણું નહીં લાગે, મફત આપવું, અને મફત આપીને લોકચાહના તો મેળવી શકાય, રાજકીય લાભ ચોક્કસપણે મેળવી શકાય અને ખૂબ સારું પણ લાગે પણ એકંદરે લોકોને પોતાપણું ન લાગે એટલે એમણે એટલું સૂચન કર્યુ હોત તો મને સારું લાગે કે ભાવ ઓછા રાખવા જોઈએ, આ બરોબર છે ભાવ ઓછા રાખવા જોઈએ પણ મફત તો ન જ આપવું જોઈએ, કોઈપણ વસ્તુ મફત મળતી હોય તો એની લોકોને કદર નથી રહેતી, આપણે જ કલ્પના કરીએ કે, માનો કે, ૨૪ કલાક વીજળી મળે છે અને કલ્પના કરીએ કે ૨૪ કલાક વીજળી મફત આપવા માટેની જાહેરાત આવી ગઈ છે, એવી જાહેરાત કરવામાં આવે તો શું થાય? આપણા ઘરમાં જ્યારે આપણે લાઈટ બાળતા હોઈએ ત્યારે આપણને ખબર છે, આપણા સદસ્ય નિવાસમાં લાઈટનું બિલ બહુ મિનિમમ ભરવાનું આવતું હોય, ના આવતું હોય તો જે જે લોકોને લાઈટ બિલ પોતાને ભરવાનું નથી હોતું એ લોકો આના વિશે ઝાઝા સજાગ નથી હોતા, સજાગ રહેવું હોય તો પણ સજાગ રહી શકાતું નથી કેમકે જે મફતની ભાવના છે એ સ્વભાવ સાથે એવી રીતે જોડાઈ જાય છે કે ભાઈ, આપણે કયાં બિલ ભરવાનું છે? એ તો ભરાયા કરે, અને એટલે પંખા અને લાઈટ જેમ ફાવે એમ અવિરત ચાલતા રહેતા હોય છે એટલે પાણી અને લાઈટ એ બંને વસ્તુ ચોકકસ ચાર્જ સાથે, નિયમિત એ ચાર્જ લેવો જ જોઈએ, તો જ એની સાથે લોકો કરકસરપૂર્વક એનો ઉપયોગ કરી શકે. લોકોના જોડાણની જે યોજના છે ૬૦:૪૦ની , જે ચેકડેમ પુષ્કળ પ્રમાણમાં બન્યા અને ઘણા બધા સારા બન્યા એને ૮૦:૨૦ ની યોજનામાં કન્વર્ટ કરવામાં આવી છે. એ પણ સુંદર વાત છે. એનાથી પાણીના તર ઊંચા આવશે અને વધારે પ્રગતિ થઈ શકશે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શિક્ષણની વાત કરીએ તો, ગામડાંઓ સારા શિક્ષણથી વંચિત હતાં, ગામડાંમાં શિક્ષકો ન હતા, ઓરડાઓ ન હતા તો માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રીએ છેલ્લા સાત આઠ વર્ષમાં અવિરત પ્રયાસો કર્યા છે, વિદ્યા સહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી છે, બાકી રહેતા ઓરડાઓ બાંધ્યા છે અને આપણો સૌનો

અનુભવ છે કે વિદ્યા સહાયકો જે ગામડાંમાં ગયા છે અને ભણતરનું કાર્ય કર્યુ છે એનાથી ત્યાંના લોક ખૂબ ખુશ છે, લોકો વિદ્યા સહાયકોની કદર કરે છે અને કહે છે કે, આવું પહેલાં ભણાવતા ન હતા અને એટલા સુધી જોયું છે કે, જે જૂના શિક્ષકો હતા એમને પણ સારું ભણાવવાની ફરજ પડી છે અને એવી રીતે વિદ્યા સહાયકોની ભણાવવાની કાર્ય શૈલી છે એ ઉદાહરણરુપ બની છે, વિદ્યાસહાયકો એટલું સુંદર ભણાવે છે, નિષ્ઠાપૂર્વક ભણાવે છે એનું એક કારણ એ છે કે, એ લોકોની ભરતી કરવાની પ્રક્રિયા એકદમ શુદ્ધિપૂર્વક પૂરી કરવામાં આવી છે. સો ટકા પ્રમાણિકતાથી આ ભરતી કરવામાં આવી છે અને એના કારણે આપણને ખબર છે કે, જો કોઈ કર્મચારી ભ્રષ્ટાચાર કરીને, લાંચ-રુશ્વત આપીને નોકરી લે તો પછી એ પણ લાંચ-રુશ્વત લઈને પોતે પોતાના પૈસા પાછા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો જ છે. આખી જિંદગી એ એમજ કોશીશ કરવાનો છે. પૈસા આપી જે આવે છે ત્યારે, ભ્રષ્ટાચાર કરીને જે આવે છે ત્યારે. જયારે કોઈ પ્રમાણિકતાથી પોતાના બળથી અને પોતાની આવડતથી એને જયારે નોકરી મળે છે, પછી એ વિદ્યાસહાયકની હોય કે કોઈ પણ નોકરી હોય ત્યારે એના દિલમાં એક એવી ઉચ્ચ ભાવના કાયમ માટે રહે છે કે મને જે પ્રેમથી અને પ્રમાણિકતાથી નોકરી મળી છે તો મારે પણ મારી ફરજ અદા કરવી જોઈએ. તો આ કારણે વિદ્યાસહાયકો ખૂબ પવિત્રતાથી ફરજ બજાવે છે અને એનાથી ચોક્કસ આગળ ઉપરનું જે શિક્ષણ છે એ સુધરી રહ્યું છે તો એનો ફાયદો નવી પેઢીને જરૂરથી મળશે.

બીજી મારે વાત કરવાની છે કર્મચારી અંગેની. તો આપણે વાત કરીએ છીએ કે જયારે પણ આપણે આગળ વધવું હોય તો ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવો જોઈએ. તો આ સરકારે આ દિશામાં ખૂબ મોટું કદમ લીધું છે, ખૂબ મોટું કામ કર્યું છે. એના માટેનો એક મહાભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો છે એ એવો છે કે કર્મયોગી દ્વારા આજે તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને પણ પોતે માત્ર કર્મચારી નથી, પોતે માત્ર સરકારના નોકર નથી એવી ભાવના પેદા કરીને પોતે પોતાના એક એવા કાર્યથી લોકોની સેવા કરી રહ્યા છે. એ સેવાની ભાવના ઉભી કરવા માટે કર્મયોગી એવી તાલિમ યોજવામાં આવી અને મુખ્યમંત્રીની એ આગવી વિચારસરણી છે એના કારણે સમગ્ર રાજયમાં એક એવું વાતાવરણ બન્યું છે કે જેથી આવનારા દિવસોમાં, આવનારા વર્ષોમાં ભ્રષ્ટ્રાચાર ઉપર જે કાબૂ લાવવા માગીએ છીએ એ કાબૂ તો આવ્યો જ છે અને હજુ કદાચ આવનારા દિવસોમાં ભ્રષ્ટાચારને આપણે રોકવામાં ચોક્કસ સફળ થઈશું એવો મને વિશ્વાસ છે અને ૨૦૨૦માં જયારે આપણા મહામહીમ રાષ્ટ્રપતિજીએ કલ્પના કરી છે કે વિકસીત રાષ્ટ્રોની હરોળમાં આપણે પહોંચી જઈશું. તો એ રાષ્ટ્રોની હરોળમાં આ દેશને મુકવા માટે ગુજરાત રાજય એ સૌથી અગ્રિમ હરોળમાં ઉભેલું રાજય હશે એવો મને વિશ્વાસ છે અને એ દિશામાં આપણું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે બીજી એક વાત કરવી છે કે, આપણે લાંબો દરિયા કિનારો છે અને બંદરોના વિકાસ માટે ખૂબ સારું કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને હમણા હમણા ૧ લાખ ૬ હજાર કરોડના એમ.ઓ.યુ. થયા છે. અગાઉ પણ ૬૬ હજાર કરોડના એમ.ઓ.યુ. થયા હતા. તો આમાં મારે આનંદ સાથે કહેવું જોઈએ કે, અમારા મહુવા બંદરનો પણ ફિસિબિલિટિ સર્વે માટેના એમ.ઓ.યુ. હચીસન નામની કંપનીએ કર્યા છે. પ્રશ્નોતરી દરમિયાન જે માહિતી આપવામાં આવી છે એમાં એનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો છે. તો આવી રીતે વિકાસની તમામ દિશામાં જયારે આપણું રાજય પ્રગતિ કરી રહ્યું છે ત્યારે ગાંધીજીનું ગુજરાત, સરદાર પટેલનું ગુજરાત એની જે વિચારધારા છે એ વિચારધારા અહીંની ધૂળમાં, અહીંની માટીમાં ભળેલી છે અને એટલા માટે ગુજરાતની પ્રજાના જીન્સમાં પણ એ અસર આવી છે અને એટલા માટે ભાજપની સરકાર પણ આ વિચારધારાને વળગીને સુંદર કાર્ય કરવા માટે આગળ વધી રહી છે અને એ ચોકકસ સફળ થશે અને પ્રગતિશીલ સરકારોમાં અને વિકાસ પામેલા રાષ્ટ્ર તરીકે દેશને આગળ મૂકવામાં વિકાસ પામેલું રાજય ગુજરાત બની રહેશે એવી આશા રાખું છું.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી (ડીસા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનનો આભાર પ્રસ્તાવ ભાઈશ્રી શંકરભાઈ લઈને આવ્યા છે એમાં હું મારા વિચારો વ્યકત કરું છું.

રાજયપાલશ્રીનું પ્રવચન થયું એના પહેલા અમને એમ હતું કે સરકાર એવું પ્રવચન લખીને તૈયાર કરીને આપશે કે આપણે પણ અહીંથી સાંભળીને કંઈક ગુજરાતની જનતાને વાત કરીશું. ખેડૂતોની વાત હશે, બેરોજગારોની કંઈક વાત હશે, ગુજરાતના ઉત્કર્ષ માટેની કોઈક વાત હશે પરંતુ એમના પ્રવચન પછી કોપી વાચી તો ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો ગત સત્રની હતી એની એજ રેકર્ડ ફેરવાય છે. થોડા અક્ષરો ફેરવ્યા છે બાકી એની એ જ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય શંકરભાઈએ ખૂબ કૂદી-કૂદીને કહ્યું ત્યારે મને એમ હતું કે તેઓ ખેડૂતના દિકરા છે એટલે એમાં સંમત નહીં થાય પણ એમણે ખૂબ કૂદી-કૂદીને કહ્યું નર્મદાની વાત કરી. આ મિત્રોને ખબર હશે, બીજા મિત્રોને પણ ખબર છે કે ૯૦ મિટર પછી થાડુંક વધારે કર્યું એ પણ સ્ટે હતો સુપ્રિમ કોર્ટનો એટલે બાકી રહી ગયું હતું એ, બાકી નર્મદાના તૈયાર સ્ટ્રકચર ઉપર બેસીને એમણે પેલી ચકલી ચાલુ કરી છે અને કાયમ માટે (અંતરાય)...

શ્રી હરજીવન હી. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કૂદી કૂદીને બોલવું એ શબ્દ અસંસદીય છે કૂદી કૂદીને એ શબ્દ ન બોલાય, આ શબ્દોને રેકર્ડ પરથી દૂર કરવા જોઈએ.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નર્મદા માટે કાયમ દરેક પક્ષોએ સર્વપક્ષીય સંમતિથી કામ કરેલ છે. નર્મદાની અંદર કોઈપણ પાર્ટી જશ લે મેં આ કર્યુ, અમે આ કર્યુ તો એ બરાબર નથી. આ તો ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન યોજના છે અને એની અંદર અમે કદીયે કોઈ ફંકશનો નથી કર્યા, નર્મદાને લઈને લોકોમાં ઢંઢેરો નથી પીટ્યો, આટલા બધા કામો કર્યા, આટલા મોટા મોટા ડેમો કર્યા, આખી નદીઓની નદીઓ બાંધી નાંખી, એમને પૂછો તો ખરા કે તમારા પચાસ હજાર ચેકડેમો બરાબર કેટલા મોટા આ ડેમ છે ચોક્કસ તમે ચેકડેમ કર્યા સારું કર્યુ પરંતુ ઉછળી ઉછળીને કહો છો તમે ત્રણ હજાર નહોતા કર્યા અમે પચાસ હજાર કર્યા છે.

શ્રી હરજીવન હી. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રી ઉછળી ઉછળીને શબ્દ વારંવાર વાપરે છે કૂદી કૂદીને શબ્દ પણ વારંવાર વાપરે છે આ શબ્દો અસંસદીય છે એને રેકર્ડ પરથી દૂર કરવા જોઈએ.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમને કહો કે ચોપડી વાંચે, આ આ અસંસદીય શબ્દો નથી.

શ્રી હરજીવન હી. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉછળી ઉછળીને, કૂદી કૂદીને આ શબ્દો અસંસદીય છે આપ ચોપડી વાંચો અસંસદીય શબ્દો છે.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે હરજીવનભાઈને કહેવું છે કે, ગયા સત્રમાં ઉભા થઈ થઈને કહેતા હતા કે ગોવાભાઈ બેસો બેસો આ નર્મદામાંથી બનાસ અને સિપુ છલકાશે, હું એમને પુછું છું કે કોઈ ઠેકાણાં છે પાયા ખોદવાના પણ?, છલકાવાની વાત તો છલકાવે જ છે. આ જ જગ્યાએથી મારા મિત્ર બોલ્યા હતા ગોવાભાઈ જપો નદીઓ છલકાઈ જશે, બનાસ નદી અને સિપુ નદી છલકાઈ જશે, હરજીવનભાઈ, વાતો કરવી સહેલી છે, કામ કરવું બહુ કઠિન છે, માત્ર વાતો અને ભાષણોથી વિકાસ થતો નથી. વિકાસ માટે નક્કર યોજનાઓનો અમલ થવો જોઈએ. તમે ગત સત્રનું પ્રવચન વાંચો અને અત્યારનું વાંચો એમાં પણ એકાવન હજાર ચેકડેમ અને આ વખતે પચાસ હજાર ચેક ડેમ, ગયા વખતના પ્રવચનમાં સત્તર નદીઓ છલકાશે આ વખતે પણ સત્તર નદીઓ છલકાશે, એકજ વાત છે બાકી તો ભગવાન જાણે એમના અધિકારીઓ એમના ચોપડામાં હોય એ જાણે. એમાં તો મારે બીજું શું કહેવું? મારે કોઈ ટીકા નથી કરવી દોલતબાપાએ કહ્યું છે એટલે, પણ સાચી વાત તમારી સમક્ષ મૂકવી છે,

પીવાના પાણીની વાત કરું, પીવાનું પાણી એમને પૂછો કે એ વખતે હરજીવનભાઈ પૈસા નહોતા આપણે તો આઝાદી પછીના જન્મવાળા છીએ અને આઝાદી પહેલાંના વજુભાઈ વાળા છે એમને પૂછો કે શું હતું એ વખતે? અને એમાંથી શું બનાવ્યું છે તમે તો આવીને બેસી ગયા છો, પેવર રોડ પર બીજો પેવર કર્યો છે, ટ્રેકટરો નહોતા ચાલતા એવા રસ્તાઓ પાકા પેવર કર્યા છે ત્યારે શું પરિસ્થિતિ હતી ગુજરાતની એ પૂછો આ વડીલોને. કહેવું સહેલું છે પણ (અંતરાય) હું વાત કરું છું એ કરવા દેતા નથી, સાચી વાત કરું છું કોઈ ટીકા કરતો નથી તમે કર્યુ છે તો અમે કયાં ના પાડી છે અમારો પેવર રોડ કરેલો છે એના પર ચોમાસામાં ખાડો પડ્યો તો પુરીને ફેર પેવર કર્યો છે પણ આ રોડ કેવી રીતે કર્યો હતો.

નર્મદાનો ડેમ ૯૦ મીટર સુધીની ઉંચાઈ માટે જે જમીન સંપાદન કરવાની, લોકોને વસાવવા હરનજીવનભાઈ સહેલા નથી આપણે બેય જણાએ સિપુ ડેમ બનાવ્યો હતો હજી વસાવી શક્યા નથી નર્મદા ડેમ માટે ઓછી વત્તી વાત નથી નર્મદા ડેમ માટેની કોઈ ટીકા કરવી એ નકામી છે. ગુજરાતનો સર્વજનતાનો સર્વપક્ષીય આ પ્રોજેક્ટ છે અને એ થવો જોઈએ અને ગુજરાતને હરિયાળું બનાવવું જોઈએ. નર્મદા વખતે ગયા વખતે જ્યારે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની અંદર કોંગ્રેસની સરકારો હતી ત્યારે ઉભા થઈ થઈને કહેતા હતા કે આટલા હજાર કરોડ રૂપિયા બાકી છે અપાવી દો મારે હવે એમને કહેવું છે તમારી સરકારો છે અને પૈસાના અભાવે નર્મદાનું કામ ધીમી ગતિએ ચાલે છે તો તમે લાવી દો, કોને પૂછો છો ફટાફટ ડ્રાફ્ટ લાવીને વટાવી દો, કામ કેમ ધીમી ગતિએ ચલાવો છો. આપને ત્યાંથી કહેતા હતા એના માટે હું કહું છું, અમે કોઈ દિવસ એવું નથી કહેતા.

પીવાના પાણીના ૧૩૪૩ બ્લોક પાઈપથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે એવું ગયા વખતે હતું અને એમાં મહેસાણાનો સમાવેશ થતો હતો આ વખતે શોધીશોધીને થાકી ગયો પણ મહેસાણાનું નામ જ નથી ૧૩૪૩ ગામોને ફરીથી બ્લોક પાઈપમાં જોડ્યા છે પણ મહેસાણા આખું ગાયબ, કાં તો આખા જિલ્લાને પાણી નારણકાકાએ અપાવી દીધું કાં તો આમાંથી બાકાત કરી દીધું છે. આ પીવાના પાણીની વાત કરું છું. આમાં પ્રવચનમાંથી જ વાત કરું છું મારી પોતાની વાત નથી કરતો (અંતરાય) એ રીતે ભલે નારણકાકા બોલો પણ તમારા આત્માને તો પૂછો બધે રાડ ઉડી રહી છે.

મને પંડ્યા સાહેબે કહ્યું કે મહેસાણાની અંદર ઉત્તર ગુજરાતમાં પંદરથી વીસ મીટર પાણીના તળ ઉંચા આવ્યા છે. હજુ કોઈ ચેક ડેમ બન્યો જ નથી. કુદરતી વરસાદ જ નથી કયાંથી ભરાય? હજુ ભરાશે અને આવશે તે જુદી વાત છે પણ આજથી કહે કે ૧૫ મીટર ઉંચુ આવી ગયું. અરે ભાઈ, અમે ત્યાં રહીએ છીએ હજુ તે

ભરાયુ જ નથી તો પછી કયાંથી ઉંચુ આવ્યું. આ રીતે ખાલી વાતો કરવી અમારે ત્યાં એક કહેવત છે કે "જેનો રાજા વેપારી હોય તેની પ્રજા ભિખારી હોય. એસ.ટી.ની વાત કરીએ આજે આપણે ગરીબ માણસોની વાત કરીએ, ગામડાંની વાત કરીએ તમે ૨૪ કલાક ગામડાંને વીજળી આપી છે સારું કર્યુ છે. તેમાં અમે વિરોધ કરતા નથી પરંતુ આજની તારીખે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ૮૦ ટકા ખેડૂતો ખેતરોમાં વસે છે.આ ખેડૂતોને ના આપવાનું કારણ શું? કહે તમે ચોરી કરો છો, કોઈ ખેડૂતને ચોરી કરવી નથી. ખેડૂતને તમે માત્ર ૧૪ કલાક વીજળી આપો તમારી ૨૪ કલાક પણ નથી જોઈતી. હોર્સ પાવર ઉપર જે ટૅરિફના ભાવ નક્કી કર્યા છે તે માત્ર ૧૪ કલાકને લક્ષમાં રાખીને કર્યા છે નહીં કે છ કલાક જે આજે આપી રહ્યા છે એટલું જ નહીં પણ ખેડૂતને જો આજે મિલિટ્રીના કમાન્ડો જે દશ દશ ગાડીઓ લઈને રેડ પાડે જાણે લૂંટી લીધું છે, આખા રાજયને આ ખેડૂતોએ એ રીતે ખેડૂત (અંતરાય) નારાયણકાકા તમે બોલો છો

એક હજાર ફૂટે પાણી છે મૂંગા રહો. ખેડૂતોની અંદર જે કંઈ ચોરી કરતો હશે હું એમ નથી કહેતો નહીં કરતો હોય પરંતુ ચોરી કરીને તે વીજળી તેના છોકરાના બેંકના ખાતામાં જમા નથી કરતો. અમારા ગામડાંમાં કોઠી હોય છે તે કોઠીમાં વીજળી નથી ભરતો. માત્ર પૂરતી વીજળી નથી આપતાં તેની તેનો પાક બળે છે, તેના ઢોક મરે છે, છોકરાં મરે છે તેથી તે પાક જીવાડવા માટે થઈને ક્યાંક અને ક્યાંક થોડા ઘણું ટેટુ બેટું નાંખતો હશે બાકી તો ચોરી કરીને તેના છોકરાં માટે નથી લેતો છતાં પણ આ સરકારે આ ખેડૂતને એક નંબરનો ચોર, ડાકુ બનાવી દીધો. તેને ખેડૂત સિવાય કોઈ દેખાતું નથી. લોડ વધારો મોટર લાવ્યો હોય પણ લોડ આપવાનો છે જે વોલ્ટેજ આપવાના છે ગુજરાતના કાયદામાં છે કે ૪૦૦ વોલ્ટેજ ખેડૂતને મળવા જોઈએ. આજે હું ચેલેન્જથી કહું છું કે ખેડૂતને ૪૦૦ નહીં ૩૦૦ મળે ૨૫૦ મળે તો તે કોને ફરિયાદ કરે? ફરિયાદ કરીને તેનું વળતર કયાં માગવું? તેમણે નક્કી કરેલો પાવર પૂરાં કલાક ના મળે તો ખેડૂતે કોને ફરિયાદ કરવી, કોને કરવી, કયાંથી વળતર લેવું? તમારા આગળ એક ઈંચ લોડ વધારે લીધો તો ૫૦ હજાર દંડ દીધો

સભાપતિશ્રી :પૂરું કરો.

શ્રી ગોવાભાઈ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બે મિનિટ ખેડૂતોને ભાવ માટે ૧૯૯૫ની સાલમાં બાજરીના ૯૦ રુપિયા હતા.

શ્રી ઇશ્વરભાઇ ધ. મકવાણા (જોટાણા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપણા આદરણીય રાજયપાલશ્રી જેમણે આ ગૃહને જે પ્રવચન આપ્યું અને આ પ્રવચન સ્વભાવિક રીતે જ મારા મને એક શ્વેત પત્ર છે. શ્વેત પત્ર નરી આંખે જોઈ શકાય તેવું એક સુંદર આલેખન અને એક મનનીય અર્થઘટન જેનું કરી શકાય મૂલ્યાંકન થઈ શકે અને કોઈ પણ પ્રકારના પરીક્ષણમાંથી તે પસાર થઈ શકે એવું ઉત્તમ પ્રવચન આદરણીય રાજયપાલશ્રીએ આપ્યું. આ ગૃહની અંદર આ માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ શંકરભાઈ લઈ આવ્યા છે, તેના સમર્થનમાં હું મારી વાત કરવા ઉભો થયો છું. હકીકતમાં રાજયપાલશ્રીએ પોતાના પ્રવચનમાં તેમની સૌમ્યતા અને તેમની જૈફ વયની પરિપકવતાનાં દર્શન કરાવ્યાં છે, હું તેમને વંદન કરું છું. હું એ વાત કહેવા માગું છું કે, હું આ ગૃહમાં ચૂંટાઈને આવ્યો ૧૯૯૮થી અત્યાર સુધીમાં આ પહેલી જ વાર દોઢ કલાક આ ગૃહમાં નામદાર રાજયપાલશ્રીએ પ્રવચન કર્યુ અને એ વિપક્ષના મિત્રોએ શાંતિથી સાંભળ્યું હોય એ કદાચ એક ઐતિહાસિક ઘટના છે અને એટલા માટે વિપક્ષના મિત્રોને મારે અભિનંદન આપવાં છે કે આપે પણ સૌમ્યતા બતાવી છે, એને જાળવી રાખીએ.

માનનીય અધયક્ષશ્રી, હું તો એક સામાન્ય માણસ છું અને એક સાધારણ પરિવારમાંથી આવું છું, પરંતુ જે મને સમજાય છે તેનો પણ જો આપણે સ્વીકાર ન કરીએ તો જાગતાં ભૂલ કરવાનો આપણને કોઈ અધિકાર નથી. એટલે ૫૦ વર્ષની આઝાદીના પાંચ દાયકા આ રાજયમાંથી અને દેશમાંથી પસાર થઈ ગયા છે અને વંચિતોના વિકાસની વાતો એ સામાન્ય રીતે આજે એક શોખ બનતો જાય છે. વંચિતોની વાતો કરવાની હોય એમાં દલિત, આદિવાસી, વનવાસી અને પછાતવર્ગના જે આર્થિક, સામાજીક, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક રીતે પછાત એવા આ માનવીઓના હિતની વાતો આવે ત્યારે મારે કહેવું છે કે આ રાજયમાં, આ દેશમાં જો કોઈ સૌથી વધુ છેતરાયેલો સમાજ હોય તો એ અમારો સમાજ છે. અમે ખૂબ છેતરાયા છીએ અને વાતોનાં વડાં કરીને સતત એમણે અમને એમની સાથે રાખ્યા અને વોટ બેંકના આધારે ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે એવું થયું છે કે વાસ્તવિકતા જયારે નજર સમક્ષ આવે ત્યારે ગોવાભાઈ, કોઈપણ માણસ એના અસ્તિત્વ માટે જાગૃત્ત બને એ સ્વાભાવિક છે. આજે વંચિત વર્ગ, દલિત વર્ગ, આદિવાસી વર્ગ, પછાતવર્ગ, લઘુમતી સમાજ, ગરીબ સમાજનો વર્ગ એ બધા વર્ગના લોકો જાગૃત્ત બન્યા છે અને એમને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટેની ખાતરી થઈ ગઈ છે કે અમારે અમારું અસ્તિત્વ કઈ રીતે ટકાવવું? ૫૦-૫૦ વર્ષો સુધી જેમના વચનો ઉપર આધાર રાખીને તેમને મતો આપ્યા છે અને એ મતોનો આધાર એ અમારા વિકાસનો આધાર ના બની ગયો. ચૂંટણી આવે એટલે મત લેવા આવે અને ચૂંટણી ગઈ એટલે એ ગયા તે ગયા અને પછી એમની પાસે દેખાય જ નહીં. એમણે ગરીબી હટાવવાની વાતો પણ બહુ કરી, પરંતુ મને ખબર પડતી નથી કે આ ગરીબી હટી ગઈ કે પછી ગરીબો હટી ગયા એનો નિર્ણય હજુ પણ અમે કરી શકતા નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વંચિતોના વિકાસની વાત જયારથી ૧૯૯૫ થી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવી અને આમ માનવીની ચિંતા મતોના આધાર ઉપર નહીં, એ સમાજમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો

ઉમેદવાર ચૂંટાઈને આવે છે કે નહીં, એ વિસ્તારમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને મતો મળ્યા છે કે નહીં એવાં કોઈપણ જાતના લેખાંજોખાં કર્યા વિના માત્ર ને માત્ર દલિત સમાજ, આદિવાસી સમાજ, પછાતવર્ગના વિકાસ માટેની યોજનાઓ બની એ યોજનાઓને આપણે ન સ્વીકારીએ તો વાત અલગ છે, એ રાજકીય દ્વેશ હોઈ શકે, એ ઈર્ષાવૃત્તિ હોઈ શકે અને રાજકીય અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની મથામણ હોઈ શકે અને એ કોંગ્રેસને માટે બની શકે, પરંતુ એનાથી સૂર્ય ધોળા દિવસે દેખાતો નથી એવું કહેવું એ પણ મૂર્ખામીનું પ્રતિક છે અને એટલા માટે હું આ ગૃહને કહું છું કે ૫૦-૫૦ વર્ષથી દલિત, આદિવાસી, પછાતવર્ગનો વિદ્યાર્થી એ પ્રાથમિક શાળામાં ભણે અને ગરીબીના કારણે સાતમું ધોરણ પૂરું ના થાય , પૂરતો આહાર ન મળવાના કારણે, પૂરતો ડ્રેસ ના મળવાને કારણે એ આગળ ભણી ના શકે...(અંતરાય) મધ્યાહ્ન ભોજનની વાત કરશો નહીં, સાંભળો તો ખરા? આવી ગરીબાઈના કારણે દીકરીઓ તો પહેલું ધોરણ પણ પસાર કરી શકતી ન હતી અને કન્યા કેળવણીનું સ્તર એટલું બધું નીચે ગયું હતું અને આમેય આ પ્રમાણેના પછાતવર્ગોમાં એકદમ નિમ્ન કક્ષાનું કન્યા કેળવણીનું સ્તર હતું. આ રાજય સરકારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને માનનીય શિક્ષણમંત્રીશ્રી આનંદીબહેનના નેતૃત્વમાં કન્યા કેળવણીનો રથ લીધો અને વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ આપવાની યોજના કરી. આ હકીકતો છે, તમે તમારા પગારમાંથી એક પણ વિદ્યાર્થીને વિદ્યા લક્ષ્મી બોન્ડના ૨૦૦ રૂપિયા આપ્યા છે? હુંઆ ગૃહને કહેવા માગું છું કે, ગામડાંના લોકો પોતાનો પરસેવો પાડીને મેળવેલા પૈસામાંથી માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીના આદેશને, માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીની વિનંતીને ધ્યાનમાં રાખી અને પોતાની મજૂરીમાંથી ૫૦૦ રૂપિયાના બોન્ડ પોતાની કન્યાના નામે આપ્યા છે. અને એટલા માટે કન્યા કેળવણી રથ આજે પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જે રીતે લોકભાગીદારી થઈ, તેમાં મારા પોતાના બે પગાર મે પોતે મારા વિસ્તારમાં વાપર્યા છે. કોઈ ધારાસભ્ય એમ કહે કે મેં કન્યા કેળવણીમાં પોતાના પગારમાંથી પોતાની સ્વેચ્છાએ સરકારની સહાય સિવાય મેં આ યોગદાન કર્યું છે. તો હું એને દંડવત કરવા માગું છું.

જ્યોતિ ગ્રામ યોજનાની વાત કરી છે. અંધારું છે, અંધારું છે, અરે ભાઈ, આ રાજ્ય સરકારે જે રીતે લોકભાગીદારીનું, લોક સહકારનું અભિયાન ચલાવ્યું છે, લોકોને સાથે રાખીને, લોકોની સામેલગીરી કરીને તેમને પોતાના પગ ઉપર ચાલતા રાખીને યોજનાઓ બનાવી છે તેને નજર અંદાજ કરવી તે પણ પાપ છે. સમજવાની કોશીશ કરો મારા મિત્રો, આ જ્યોતિ ગ્રામ યોજના, મને કહેવા દો, અમે જ્યારે ચૂંટણીમાં ઊભા રહી અને મત લેવા જતા હોઈએ, જ્યારે જાહેરસભામાં ભાષણ કરતા હોઈએ, ત્યારે ગામમાં બેઠેલી, મા, બહેન કે દીકરી ઊભી થઈને અમને એમ કહે છે કે તમે શહેર વાળા માણસો છો, અને અમે ગામડાંના માણસો માણસ નથી? તમારે શહેરમાં વીજળી ૨૪ કલાક મળે, અમારા ઘરમાં ટી.વી. છે, ફ્રીજ છે, અમારા છોકરા પણ એસ.એસ.સી.માં ભણે છે, ઉચ્ચ અભ્યાસ કરે છે, અમારા ઘરમાં લાઈટ નથી, અમે રાંધવા બેઠા હોઈએ અને લાઈટ ન હોય, અમે ૨૪ કલાક વીજળી વગર ટળવળીએ, તમે શહેરમાં મોજ મજા કરો, એ.સી.માં બેસીને આરામ કરો. આ પ્રજાની વેદના હતી, માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ હકીકત સાબિત કરી, હું આ માનનીય સભ્યશ્રીઓને કહીશ કે જે ગામો પછાત વિસ્તારમાં હતા, લોકફાળો ભરી શકતા નહોતા, એવા બક્ષી પંચના ગામો, આદિવાસી વિસ્તારના ગામડાંઓ છે, જ્યાં ધારાસભ્ય પોતે પોતાના ફંડમાંથી જ્યોતિ ગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકતા હતા પણ મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે અમારા મહેસાણા જિલ્લાનું એક પણ ગામ આજે જ્યોતિ ગ્રામ યોજનાથી વંચિત નથી. મારે કહેવું છે કે રાજ્ય સરકારે ધારાસભ્યોના ફંડની જોગવાઈ અમલી કરાવી અને ધારાસભ્યો પોતાના ફંડમાંથી જ્યોતિ ગ્રામ બનાવી શકે છે. હું કોંગ્રેસના ધારાસભ્યશ્રીઓને પૂછવા માગું છું કે પોતાના ફંડમાંથી એકપણ ગામને જ્યોતિ ગ્રામ બનાવવામાં સહયોગ આપ્યો છે? મેં મારા પોતાના ધારાસભ્યના ફંડમાંથી ૫૦ લાખ રૂપિયા મુકી અને જોટાણાના સો ટકા ગામોને જ્યોતિ ગ્રામ યોજનામાં આવરી લીધાં છે. આ શક્ય છે, પરંતુ મારે વંચિતોની વાત કરવી છે,

વંચિતોની વાત મેં અધૂરી મૂકી હતી, વચ્ચે જ્યોતિ ગ્રામ યોજના આવી ગઈ હતી, પ્રાથમિક શાળામાંથી ખસી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ આજે વિદેશમાં જાય છે અને તેના માટે ૫ લાખ રૂપિયાની સહાય મળે છે. આ અભૂતપૂર્વ બાબત છે. આ રાજ્ય સરકારે આ વખતે ૨૦ દલિત સમાજના વિદ્યાર્થીઓને, આદિવાસી અને પછાત વર્ગના અલગ, એ સિવાયના લોકોના વિદ્યાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ માટે મોકલ્યા છે, આજે મને કહેતાં ગૌરવ થાય છે કે આ વાત સમગ્ર દલિત સમાજમાં પ્રશંસાને પાત્ર બની છે, ત્યારે આપના મારફત હું રાજ્ય સરકારને અભિનંદન આપું છું અને મારા સમર્થન સાથે વાત પૂરી કરું છું. ભારત માતા કી જય.

શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી (દાંતા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભાઈ શ્રી શંકરભાઈ માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચન પરનો આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે, એમાં હું મારા વિચારો વ્યકત કરું છું. આજે સવારના સાડા આઠ વાગ્યાથી અત્યારસુધીમાં ઘણા બધા વકતાઓએ, મારા સાથી સભ્યશ્રીઓએ જુદી જુદી વાતો કરી. હું શાંતિથી ચિંતન અને મનન કરતો હતો કે આ બધા જ સભ્યો કહી રહ્યા છે એમને વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ છે ખરો? શું તેઓ પોતાની ફરજમાંથી મુક્ત થઈ રહ્યા છે? એમને ખરેખર ચૂંટીને મોકલ્યા છે તો શા માટે મોકલ્યા છે? એમને જે કામ કરવા માટે લોકોએ જે પ્રેરણા આપી છે તે પ્રેરણા જાહેરાતમાં ફેરવવા માટે અહીં મૂક્યા છે? માત્ર એમની ફરજનો ભાગ છે. વિકાસની કેડીમાં આપણે વધારો કરીએ એતો આપણી એક ફરજ છે.

આપણા વડીલોએ મકાન બનાવ્યું હોય અને એની મરામત જ્યારે કરાવવાની વાત આવે ત્યારે આપણે એમ કરીએ કે આ મકાન મેં ધોળ્યું છે. અરે મકાન તો તારા બાપે બનાવ્યું છે તેં તો ફક્ત ધોળ્યું છે. સાચી વાત મકાન મારા બાપે બનાવ્યું છે. એ જ રીતે રસ્તો કેવી રીતે બનાવવો એની જમીન સંપાદન કેવી રીતે કરવી એનો ઘણો લાંબો પ્રોસેસ હોય છે. આગળની સરકારોએ બંધારણ નક્કી કરેલ એમાંથી બધું પસાર કર્યુ અને પસાર કર્યા પછી સરકારે કબજા મેળવ્યા. એ કબજા મેળવ્યા પછી આજે યાદ કરો ૧૯૬૨-૬૩ની અંદર ચૂંટણી લડી હોય એને પૂછો કે એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય તો એ શેમાં જતા હતા? (અંતરાય) ત્યાં જતા હતા કે નહોતા જતા તોયે મતો મળતા હતા. પ્રજાને એમના ઉપર વિશ્વાસ હતો. આ ભાજપવાળા નહિ સાંભળી શકે એની પાછળના પણ કારણો છે. એમણે નક્કી કર્યુ છે કે જોરથી બોલવું અને જુઠું બોલવું. એ લોકો નહિ સાંભળી શકે.

મારે આપની સમક્ષ એક વાત મૂકવી છે. આપણે હમણાં ઉદ્યોગોની વાત કરતા હતા. કચ્છની અંદર ખૂબ વિકાસ થયો, ખૂબ ઉદ્યોગો આવ્યા. જો આવ્યા હોય તો અભિનંદનનેપાત્ર છે. આપણા ગુજરાતમાંથી ફાર્માસ્યુટીકલ કંપનીઓ હિમાચલમાં શા માટે ગઈ? આપણા ગુજરાતની ૭૦ ટકા ફાર્માસ્યુટીકલ કંપનીઓ હિમાચલ પ્રદેશમાં જવા માંડી છે એનું શું કારણ? આપણે એની તપાસ કરી છે ખરી? આપણો કાપડ ઉદ્યોગ બહાર જવા માંડ્યો છે, એની કોઈ તપાસ કરી છે ખરી? હું એમ કહું છું કે આપ સૌ વાસ્તવિકતા ઉપર આવો. હું એમ નથી કહેતો કે તમે આ કર્યુ અને આ નથી કર્યુ. કર્યુ છે પણ સાથે સાથે એક નિયમ કરો કે નવા ઉદ્યોગ આવે એની સાથેસાથે જૂના જે ઉદ્યોગો છે એ સર્વાયવર થઈ ઊભા થઈ શકે તો આપણે સાચી રોજગારી આપી શકીશું.

ખેડૂતોની વાત કરી. મારા મિત્રોએ હમણાં જ વાત કરી. પરંતુ મારે કહેવું છે કે ૧૦ થી ૧૫ ખેડૂતોનું જૂથ સ્વાભાવિક છે કે બાપદાદાએ લીધેલી જમીન એમાં ઉમેરો થયો હોય ત્યારે એના બાળકો ખેડૂતોએ ફાર્મ હાઉસ બનાવ્યું હોય, એમાં મકાન બનાવ્યું હોય, જો એ ત્યાં ન રહે તો પાકને મુશ્કેલી થાય. આજની તારીખે પરિસ્થિતિ એવી છે કે સાત કલાક જ થ્રીફેઈઝ વીજળી મળે છે. એ સિવાય પણ એમને સીંગલ ફેઈઝ વીજળી મળતી નથી. તેથી એમના બાળકોનો અભ્યાસ બગડે છે, એના કારણે એમને જીવન જીવવાનું દોહ્યલું બની ગયું છે. જો એ પાકને મૂકીને આવે તો પાકને નુકસાન થાય અને ત્યાં ખેતરમાં જ રહે તો બાળકનું ભણતર બગડે. (અંતરાય) આવા ખેતરોની અંદર રહેતા ખેડૂતોને ૨૪ કલાક વીજળી મળે એના માટે સરકારે વિચારણા કરી છે ખરી? અમારી રજૂઆતના અનુસંધાને કયાંય જાહેરાત કરી છે ખરી?

બીજી ખેત તલાવડીની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. મારે પૂછવું છે કે ખેત તલાવડી ખેડૂતોએ જાતે બનાવી સારી બાબત છે. પણ એવા કેટલાક કિસ્સાઓ નોંધાયા છે કે જેમાં ખેત તલાવડી જે.સી.બી.મશીન દ્વારા બનાવી હોય અને પછી એના ૫૦ ટકા જે ઘઉં આપવામાં આવ્યા હોય તે બજારોમાં વેચાયા હોય એની તપાસ કરવા કોઈ તૈયાર છે ખરું?

બીજી વાત કર્મયોગી યોજનાની વાત કરી છે. કર્મયોગી યોજના બની, દુ:ખની વાત એ છે કે અધિકારીઓ જ્યારે નોકરીની અંદર જોડાય છે અને પદાધિકારીઓ ચૂંટાઈને જોડાય છે. સભ્ય તરીકે અહીં વિધાનસભામાં સોગંદ લે છે. ત્યારે તે વાતને ચોક્કસ તેમના સોગંદમાં કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનને માથે રાખીને કામ કરજો. એવા સોગંદ અહીં પોતે લેતા હોય છે. એ સોગંદ લીધા પછી પણ તેમના ઉપર વિશ્વાસ નહીં હોવાના કારણે કર્મયોગીની યોજના લાવવામાં આવી. એટલું જ નહીં, કર્મચારીઓને પોતાની ઑફિસમાં ફરજ પાડવામાં આવી કે તમે કર્મયોગીની શિબિરમાં જાવ નહીં તો તમારું સસ્પૅન્શન થશે અથવા તમારી બદલીઓ કરવામાં આવશે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તેમને ખાસ કિસ્સામાં ટી.એ.,ડી.એ આપવામાં આવ્યું. પદાધિકારીઓને બોલાવવામાં આવ્યા, પદાધિકારીઓને પણ ફરજ પાડવામાં આવી. એટલે આ બધી વાત એટલા માટે વાજબી નથી કે આપણે નરી જાહેરાતો કરવાથી કે પોકળ પ્રચાર કરવાથી વહીવટ નથી ચાલવાનો. આપણે વાસ્તવિકતા ઉપર આવો. આપણે છેવાડાના માનવીને કઈ રીતે લાભ અપાવવા માગીએ છીએ, ગામડામાં રહેતા ખેડૂતને કઈ રીતે લાભ અપાવવા માગીએ છીએ, આપણે કઈ રીતે ખેતમજૂરને કે મજૂરને એ પોતાના કુટુંબનું ભરણ-પોષણ કરી શકે એવી વ્યવસ્થા કરવા માગીએ છીએ. આ દિશામાં વિચાર કરીને ભ્રામક પ્રચારો અને ખોટી ભ્રમણામાંથી બહાર આવીને વાસ્તવિકતા ઉપર આવો, નહીં તો ૯૨ મતવિસ્તારમાંથી છ મહિનામાં કોંગ્રેસને વધારે સીટ મળી છે એ વાત આપ સૌ જાણો છો.

શ્રી કાળુભાઇ વી. વીરાણી (કુંડલા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સભાગૃહના સભ્યશ્રી શંકરભાઈ માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપરનો આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે તેને મારું અનુમોદન આપવા ઊભો થયો છું. (અંતરાય) સાચું બોલું છું છે. ઈશ્વરની સાક્ષીએ છાતી ઉપર હાથ રાખીને બોલવાનું. અમારા સાથી સભ્યશ્રીઓ બોલતા હોય તો મને લાગે છે કે તૈયારી કરતા હોય કે ન કરતા હોય, વિરોધપક્ષના નેતા બોલતા હતા. મને યાદ છે. ગુંડાગીરીની વાત કરતા હતા. પણ મારે વિરોધપક્ષના નેતા અર્જુનભાઈને પૂછવું છે કે કદાચ ૧૯૯૫માં જો ભા.જ.પ.ની સરકાર ગુજરાતમાં ન આવી હોત તો અર્જુનભાઈને અહીં આવવાનો બનાવ ન બનત. આ રાજયમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ૧૯૮૫-૯૦માં ગુંડાગીરી ફાટી નીકળી હતી. ૧૯૮૦-૮૫ અને

૧૯૮૫-૯૦માં અમારે સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂત હિતરક્ષક સમિતિ રચવી પડેલી. સ્વ. સવજીભાઈ કોરાટ તેના ચેરમેન બન્યા હતા. મારે એટલું જ કહેવું છે કે નાની નાની બાબતમાં અર્જુનભાઈ ગુંડાગીરીની વાત કરતા હતા. મને યાદ આવ્યું જ્યારે ૧૯૮૦-૮૫ અને ૧૯૮૫-૯૦માં કોંગ્રેસની સરકાર હતી. તેમને મારે પૂછવું છે કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પોપટભાઈ સોરઠીયા ૧૫મી ઑગસ્ટના દિવસે જ્યારે ધ્વજવંદન કરાવતા હતા, ત્યારે હજારો માણસોની વચ્ચે ગોળી મારીને તેમનું ખૂન કરવામાં આવ્યું. આવી ગુંડાગીરી કોંગ્રેસના શાસનમાં હતી. તેનાથી આગળ વધીને વાત કરવા માગું છું કે કોઈ ખેડૂતના દીકરાની સલામતી નહોતી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તેનાથી આગળ વધીને વાત કરું તો શાસક કોંગ્રેસ પક્ષના આરોગ્ય મંત્રી, કૅબિનૅટ મંત્રી વલ્લભભાઈ પટેલ રામજી મંદિરની ઉપર જાહેર સભાને સંબોધીને નીચે ઊતરતા હતા ત્યારે જાહેરમાં તેમની હત્યા થઈ હતી, આ શરમજનક બાબત છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જેવું કંઈ આ ગુજરાતમાં હતું જ નહીં. ત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે કે ૧૯૯૫માં ભા.જ.પ.ની સરકાર આવી અને કેશુભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા અને હવે નરેન્દ્રભાઈ મોદી મુખ્યમંત્રી બન્યા તો મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે ગુજરાતની સલામતી ભા.જ.પ. સરકારના હાથમાં છે. આ લોકોને બોલવાનો કોઈ અધિકાર નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રસ્તાઓની વાત કરે છે. માનનીય ગોવાભાઈ રસ્તાઓની વાત કરતા હતા કે અમે આમ કર્યું તેમ કર્યું. મારે પૂછવું છે, ૧૯૯૫ પહેલાં ઈશ્વરની સાક્ષીએ પૂછો કે તમારા તાલુકામાં કેટલા રસ્તા ચાલી શકાય એવા હતા? હા, તેમનો વિકાસ હશે પણ ૧૯૭૫-૮૦ અને ૧૯૮૫-૯૦માં આખા ગુજરાતની કઠણાઈ બેસાડી દીધી. એ પહેલાં કદાચ કોંગ્રેસના લોકો સારું કામ કરતા હતા. ૧૯૯૮માં હું સાવરકુંડલામાં પહેલી વખત મત માગતો હતો ત્યારે ૮૧ ગામોમાંથી ૪૩ ગામોમાં કાચા રસ્તા હતા. મારે ગોવાભાઈને પૂછવું છે કે એમની હાલત શું હતી? એમની હાલત પણ એ જ હશે. કોંગ્રેસની કાર્યપદ્ધતિ હતી એ અંગેના એમના હ્રદય ઉપર હાથ મૂકીને પૂછે.આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર શું કરી શકે? જી.ઈ.બી.ની વાત શ્રી ભીખાભાઈને કરવી છે, સાચી વાત કરવી છે. એક તો એમની સરકારના વિચારો સારા ન હોવાથી સૌરાષ્ટ્રમાં અને ગુજરાતમાં ૧૦૦૦ ફૂટના ઊંડા બોર કરીને પાણી ખેંચી લીધું ત્યાં સુધી સાચી વાત નથી કરતા, પીવાનું પાણી પણ નથી રહેવા દીધું. આડેધડ વહીવટ કર્યો. હું ખેડૂતનો દીકરો છું એટલે સાચી વાત કરીશ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જ્યોતિ ગ્રામ યોજના હોય, પણ મારે કોંગ્રસના મિત્રોને પૂછવું છે કે, એટલી બધી ઈર્ષા શું કામ છે? તમારા બાળકો ૨૪ કલાક લાઈટ હશે તો સારું ભણશે, સારા વિચારો આવશે, સારી રીતે જીવન જીવી શકશે. હાથે કરીને કુહાડો પગ ઉપર શું કામ મારો છો? આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી એક સારી સૂઝથી કામ કરી રહ્યા છે. રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનની ચોપડી જોઈશું તો ખબર પડશે. શ્રી ઈશ્વરભાઈ કહેતા હતા કે, અત્યાર સુધી કોંગ્રેસના લોકોએ ગરીબોને છેતર્યા છે એમ કહું તો ખોટું નથી. એ લોકો મત માગવા જાય ત્યારે એવું કહેતા હતા કે, તમારી ગરીબી અમે હટાવીશું. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, ગરીબો જ હટી ગયા છે. ઈન્દિરા આવાસ યોજનામાં ૭૦૦૦ આપતા હતા. એનાથી એમના ઘરની દીવાલો માંડ થતી. બીજી ચૂંટણી આવે એટલે કહે કે તમે અમને મત આપો અમે તમને આ ઘરના નળિયાં આપીશું, એમ કહીને વચન આપીને મત લઈ જાય અને ત્રીજી ચૂંટણીમાં મત લેવા જાય ત્યારે પેલો ગરીબ માણસ જતો રહ્યો હોય. તમે ભાજપના શાસનમાં જુઓ. આ ગરીબોને એકેએકને સારાં પાકાં મકાનો બનાવીને આપ્યાં છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ખેડૂતોના હિતોની વાતો કરતા હતા. ભાવ મળતા નથી. બહુ સાચી વાત કરી, ખેડૂતોને ભાવ મળતા નથી. ગયા વર્ષે સમગ્ર ગુજરાતમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં અનેકગણો પાક પાક્યો હતો અને પુષ્કળ સીંગ પાકી હતી, કપાસ પુષ્કળ થયો હતો. એ વખતે દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હતી. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી બાજપાઈજીની સરકાર હતી. એ વખતે સીંગના ભાવ ૨૭૫ હતા એના ૩૫૦ - ૪૦૦ થયા હતા એથી ખેડૂતના દીકરા ખુશ થયા હતા. આજે કપાસ ૨૫૦ અને ૨૭૫માં પણ કોઈ લેતું નથી, એનું કારણ શું છે? દેશમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે, એણે આયાત રૂની ૪૦ ટકા ડયુટી હતી એના ૧૦ ટકા કર્યા. એનું પાપ આ ગુજરાતના ખેડૂતો ભોગવી રહ્યા છે અને એના પાપના ભાગીદાર આ કોંગ્રેસ પક્ષના લોકો છે. આજે લોકો કહે છે કે, મત લેવા આવજો ત્યારે ખબર પડશે. મારે કહેવું છે કે, આ સરકાર આવી રીતે ચાલવાની છે? ખેડૂતોને પૂછો કે એમની શું પરિસ્થિતિ થઈ છે? એ પૂછો તો ખબર પડે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયના રસ્તાની વાત કરું તો આજે એકપણ ગામ રસ્તા વગરનું નથી. ગોકુળીયા ગામની યોજના, સમરસ ગામની યોજના લાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસને ૪૦ વર્ષમાં જે કામ નથી થયું એવું કામ આ સમયગાળામાં થયું છે. (સમયસૂચક ઘંટડી) મારે આરોગ્યની વાત કરવી છે, શિક્ષણની વાત કરવી છે. ગુજરાતના ગામડાઓમાં માધ્યમિક શાળાઓ નહોતી, પ્રાથમિક શાળાઓના ઓરડાઓ નહોતા, ભણાવવા માટે પૂરા શિક્ષકો નહોતા. આજે ટૅક્નીકલ શિક્ષણની વાત કરું તો આ રાજયપાલના પ્રવચનમાં ૧૧ ફાર્મસી કૉલેજો આપી છે, ૮ બી.એસ.સી.ની કૉલેજો આપી છે. આપણા અનેક બાળકોને કર્ણાટક અને બેંગ્લોરમાં જવું પડતું હતું. મારે વિપક્ષના મિત્રોને પૂછવું છે કે, આપના પક્ષના લોકો રાજય કરતા હતા. ખરેખર એટલે કહેવું છે કે, ૧૯૯૫ પછી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પક્ષનું શાસન આવ્યું ત્યારે, આ સાત વર્ષમાં જે કામગીરી થઈ છે એ કયારેય થઈ નથી.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર (દહેગામ): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આદરણીય ગુજરાતના રાજયપાલશ્રીના આભાર પ્રસ્તાવને માનનીય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી લઈને આવ્યા છે એમાં મારો સૂર પૂરાવી શકતો નથી અને મારા વિચારો વ્યકત કરું છું.

(અધ્યક્ષશ્રી અધ્યક્ષસ્થાને)

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનના બીજા ફકરામાં દેશની લોકશાહીમાં ઉચ્ચ પ્રણાલિકા પ્રસ્થાપિત કરવામાં જેણે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે એવા ગૌરવવંતા ગૃહને સંબોધવાનું લખ્યું છે. આ ગૃહ એક ગૌરવવંતુ ગૃહ , સમગ્ર ગુજરાતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, સમગ્ર ગુજરાતની વ્યથાને વાચા આપી શકે એ માટેનું ગૃહ રામ રાજયની વાત અને ઐતિહાસિક લોકશાહીના કેટલાક પ્રસંગોમાંથી આપણે લોકશાહી વિશે કયાંક થોડું ઘણું શીખ્યા છીએ અને જાણીએ પણ છીએ. રાજા રામ વનવાસ ગયા પછી કયાંક ધોબીની વાતને પણ ન્યાય આપી અને કોઈક નિર્ણય લઈ શક્યા છીએ એવું આપણે રામાયણમાં જોઈએ છીએ. ૧૫૧૨માં ઈંગ્લેન્ડના રાજા અને એના સુબા કે સેનાપતિ સાથે કરાર થયા હતા કે રાજાનું કર્તવ્ય કેવું હોવું જોઈએ. એ સુબાઓએ એની ફરજ કેવી રીતે નિભાવવી જોઈએ એવા કરાર થયા હતા અને એ કરારોમાંથી પછી કાયદાઓ અમલમાં આવ્યા અને પછી વિશ્વયુદ્ધ થયું. એ પછી લીગલ ઓફ નેશન બન્યું અને એ પછી યુનોની સ્થાપના થઈ અને દુનિયાના લોકશાહી દેશોના અનુભવોમાંથી આપણે કંઈક શીખ્યા અને એમાં જે દેશના અને રાજયના બંધારણો ઘડાયા એમાં મૂળભૂત અધિકારો મૂકવામાં આવ્યા. ધારાસભ્યો ટ્રેકટરમાં આવે કે ગાડામાં આવે એ એનો અધિકાર છે. ધારાસભ્યો ચાલતા આવે કે એની ગાડીમાં આવે એ એનો અધિકાર છે પણ જે કમનસીબ બીનાઓ જે બની છે એના તરફ આપનું ધ્યાન દોરવા માગુ છું કે તમામ દરવાજાઓ બંધ કર્યા, સચિવાલયને લશ્કરી છાવણીમાં ફેરવી દીધું, એક નંબરના દરવાજાને પણ સાંકળોથી તાળાં મારવામાં આવ્યા કારણ કે વિપક્ષ રાજયપાલશ્રીનું પ્રવચન સાંભળી ન શકે, એને બહાર રાખવાના જે કાવતરાં થયાં એ આ લોકશાહીના ગૌરવવંતા ગૃહને લાંછન લાગે એવા પ્રયત્નો થયા છે. વાસ્તવિકતા સાથે ચાલો. દરવાજા ઉઘાડા રાખી શકયા હોત સાહેબ. જે રીતે લોકશાહી પ્રક્રિયામાં વિપક્ષની ભૂમિકા છે એ ભૂમિકા અદા કરી અને વિધાનસભામાં ભોંયતળીયે આવીએ છીએ ત્યારે પણ દરવાજાઓ બંધ રાખવામાં આવે છે. આ ગૌરવવંતા ગૃહની વાતો કરે છે મારા અભ્યાસુ ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાહેબ દશા તો જુઓ. ગયા ગૃહમાં ગૃહના માનનીય માયાબેનને રડવાનો વારો આવે, આ ગૃહમાં માન. ગોરઘનભાઈને રડવાનો વારો આવે સાહેબ, આ દશા? મુખ્યમંત્રીશ્રીને જેટલા ઉપનામથી સંબોધવામાં આવ્યા છે એ અમે નથી સંબોધ્યા, આ પાટલીમાં બેઠેલા નેતાઓએ અને એમના વડવાઓએ સંબોધ્યા છે એમાં અમે કયાંય દોષિત નથી. વાત કરવી છે તો એમને કરો, એમની પાસે ખુલાસો કરવાની ક્યાંક અનુકૂળતા કરી આપો. એ એટલા માટે આ વાત છે કે ઘરના મોભી તરીકે સાથે લઈને ચાલતા નથી. એનું પરિણામ સમગ્ર ગુજરાત ભોગવી રહ્યું છે અને ગુજરાત જે ભોગવી રહ્યું છે એમાંથી બહાર કાઢવા માટે આપ થોડાક પ્રયત્નો કરો. મારા માનનીય સી.જે. ચાવડા સાહેબે કહ્યું, ભિષ્મ પિતામહની ભૂમિકામાં ન રહો. ક્યાંક તમે ચિંતા કરો (અંતરાય) અને અમે પતીશું કે તમે પતશો એ તો આવતો સમય બતાવશે, માનનીય રમણભાઈ. એટલા માટે જે બનાવો ગુજરાતમાં બન્યા અને એ બનાવોની સાથોસાથ અહીંયા જે બીનાઓ બની રહી છે ગુજરાતના લોકશાહી રાજયમાં એ લોકશાહી રાજયની ચિંતા કરવાનો અવસર આવીને આપણી વચ્ચે ઊભો છે. જળસંચયની વાત થાય છે. જળ સિંચન થઈ ગયું અને તળાવોના પાણી ઊંચા આવી ગયા તો ડાર્ક ઝોન ઉઠાવી લો. શા માટે ડાર્ક ઝોન રાખ્યા છે? શેના માટે ડાર્ક ઝોન? ભારત સરકારમાં રૂપિયા ભરી દો. ગત સરકારે રૂપિયા ભરીને ડાર્ક ઝોન ઉઠાવ્યા હતા. પણ ગરીબ ઘરનો દીકરો બોર કરતો થાય, પછાત તાલુકામાં એક વીઘાનો પાટો ન થાય એટલે ડાર્ક ઝોન નાખી દો. કારણ કે એક દોઢ વીઘાવાળાને બોર કરવાનો અધિકાર નથી. બોર કરવાવાળાના બોર થઈ ગયા. ભણવાનું હતું એણે ભણી લીધું. હવે ભણવાનો વારો ગરીબ સમાજનો આવે ત્યારે સ્વનિર્ભર શાળા અને કૉલેજો કરી નાખવાની? એટલા માટે કર્યું છે?

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ચેકડેમ ખૂબ સારી વાત છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ૧૫૦૦-૨૦૦૦ ફૂટે પાણી જઈ રહ્યાં છે એમાં સુજલામ્-સુફલામની વાતથી સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતને જો આનો મોટો ફાયદો થવાનો હોય તો ચોક્કસપણે આ યોજનાને સ્વીકારું છું, આવકારું છું. અહીંયાં જે બૂમો પાડે એ તાલુકાને જ ધ્યાનમાં રાખવાના? વાચાળ લોકોની વાતોને જ મહત્ત્વ આપવાનું? રજૂઆત કરી શકે અને સચિવાલયના દરવાજા સુધી કે માનનીય મંત્રીશ્રી કે સરકાર સુધી પહોંચી શકે એવા લોકોના જ તમારે કામ કરવાના છે? કે પછી અવિકસિત તાલુકા રહી ગયા છે એને આઈડેન્ટીફાઈ કર્યા? નો-સોર્સ તાલુકા કયા છે, સિંચાઈની સગવડ વગરના અને બી.પી.એલ.ના કાર્ડ ધારકો કયા તાલુકામાં વધારે છે, ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો કયા તાલુકામાં વધારે આવે છે, એવા તાલુકાઓનો કોઈ અભ્યાસ કરીને આપણે આપણી યોજના એ માગે નહીં તો પણ આપવાની તૈયારી બતાવી છે કે નહીં? એ પણ આજના સમયે મહત્ત્વનું છે. પાણી પુરવઠાની યોજના એ ખૂબ સારું કામ છે અને પીવાના પાણી માટે માનનીય નરોત્તમભાઈ આગળ જઈ રહ્યા છે. પણ એક બોર બને છે એના તરફ ધ્યાન દોરીશ. પદ્ધતિ કેવી? બોર બંધ થઈ જાય એટલે રજૂઆત આવે, રજૂઆત આવ્યા પછી એનો સરવે થાય, પ્લાન

એસ્ટિમેટ બને અને એ પ્લાન એસ્ટિમેટ બન્યા પછી એના ફંડની વ્યવસ્થા કરવા માટે ૧૦ ટકા લોકફાળો ન ભરે ત્યાં સુધી પ્રજા એ બોર અને પાણી વગર ટળવળે છે. એમાં પણ સરકારે કંઈક કરવું પડશે. બધી જગ્યાએ વેપાર ન હોય. અંતરિયાળ, આદિવાસી કે બક્ષીપંચના ગામડાંમાં ડૉકટરો મળતા નથી એની ચિંતા સરકારે કરવી પડશે. અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ટયૂબવેલ કે હેન્ડપંપ નથી. તેને પોતાની આજીવિકા જીવવા માટે કપરા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હોય, પછાતો પાસે આવકના કોઈ સાધનો ન હોય ત્યારે ૧૦ ટકા લોકફાળાની વાતને બાજુમાં મૂકી પીવાના પાણીમાં સરકાર વેપાર ન કરે એવું નમ્ર સૂચન કરું છું. મારા વિદ્વાન સાથી ઈશ્વરભાઈ કહી રહ્યા હતા કે ગરીબ સમાજ ક્યાંક ભરમાઈ ગયો. માનનીય ઈશ્વરભાઈ, આજે ગૃહમાં બેઠા છો એ ગૃહમાં બેસવાનો અવસર કદાચ કોંગ્રેસ જાગૃત ન થઈ હોત તો મળ્યો ન હોત.

શ્રી ઇશ્વરભાઇ ધ. મકવાણા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો પૉઈન્ટ ઑફ ઑર્ડર છે. આ ગૃહમાં હું બેઠો છું એના માટે કોંગ્રેસ જવાબદાર બને છે એ વાત બરાબર નથી. આ દેશની લોકશાહી અને બંધારણે કરેલ જોગવાઈ મુજબ......

અધ્યક્ષશ્રી : પૉઈન્ટ ઑફ ઑર્ડર શું છે?

શ્રી ઇશ્વરભાઇ ધ. મકવાણા : એમણે જે કહ્યું કે આ ઈશ્વરભાઈ સીટ ઉપર બેઠા છે એ કોંગ્રેસના .....

અધ્યક્ષશ્રી : કોંગ્રેસની ભૂલના કારણે બરાબર છે, બેસો.

શ્રી ઇશ્વરભાઇ ધ. મકવાણા : કોંગ્રેસના કહેવાથી નથી થયો.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એસ.ટી.ની વિગતો છે. અત્યારે ડ્રાઈવરો રિપેરીંગ કરવા માટે, ક્યાંક સ્ટોપર લાવવાની હોય તો ડ્રાઈવરો એના પગારમાંથી લાવે. એકિસલેટરના વાયર તૂટી ગયા હોય તો ડ્રાઈવર સુતળી કે દોરી નાખીને એસ.ટી. ચલાવતા હોય છે.

શ્રી ગોવિંદભાઈ વ. પરમાર (તલાલા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનનો આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આ ગૃહના મારા સાથી સભ્ય ભાઈશ્રી શંકરભાઈ આવ્યા છે, તેમને સમર્થન આપવા માટે ઊભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વિપક્ષની પાટલીઓ પરથી ગૃહ સવારના બેઠાં બેઠાં અમે સાંભળી છીએ પણ આ ગુજરાતનો વિકાસ આ સરકારે ૧૫.૭ ટકા જેવો કર્યો છે અને ગુજરાત આખા હિન્દુસ્તાનમાં નંબર વન રાજ્ય થવા માટે જઈ રહ્યું છે. મુરબ્બી મારા વડીલ ગોવાભાઈ ખેડૂતોની બહુ ચિંતા કરતા હતા, પણ ગોવાભાઈ આજસુધી જો ખેડૂતોની ચિંતા કરી હોત તો માત્ર ને માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ કરી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જ્યારથી સત્તા ઉપર આવી છે ત્યારથી આ ગૃહમાં અને હિન્દુસ્તાનમાં ખેડૂતો વિષે લોકો બોલતા થયા છે. ૧૯૮૯ માં એક વિદ્યાર્થી તરીકે અહીંયા પ્રેક્ષકદીર્ધામાં આવેલો અને જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્યશ્રીએ, નામ નથી યાદ એણે ખેડૂત વિષેનો પ્રશ્ન ઊભો કરેલો ત્યારે આ તમારાં જ કોંગ્રેસના સભ્યોએ એ પ્રશ્ન ઉડાવી દીધેલો. એવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે નર્મદા વિષે નર્મદાનો પણ ૧૧૦.૬૬ મીટર સુધી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લઈ ગઈ હતી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વિરોધપક્ષના નેતા વડીલ, મુરબ્બી અભ્યાસુ છે. ભાઈશ્રી અર્જુનભાઈ કાયદો અને વ્યવસ્થાની વાત કરતા હતા પણ આ સરકારે ગુંડાગીરી નાબૂદ કરી છે. આંતકવાદી પ્રવૃત્તિને નાબૂદ કરીને રાજ્યને સલામત બનાવ્યું છે. જો આ સરકારે ગુંડાગીરી નાબૂદ કરી ના હોત તો તો માનનીય વિરોધપક્ષના નેતા પોરબંદરથી ચૂંટાત કે કેમ તે પણ એક સવાલ હતો. લોકશાહી રીતે ચૂંટાણાં છે. ગામડાંનો વિકાસ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યો છે. જ્યોતિગામની વાત હોય, સૌ વડીલ ગામડામાં રહેતા હશે એમને ખબર હશે કે જ્યારે અમે બધા વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હતા ત્યારે વાંચવા માટે સાહેબ, ફાનસ અને દીવો રાખીને વાંચવું પડતું હતું. આજે અમારાં બાળકો ૨૪ કલાક લાઈટના હિસાબે વાંચે છે એ દેન ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની છે અને મિત્રો જે તમે પરાઓની ચિંતા કરી છે, ખેતીમાં રહેતા લોકોની ચિંતા કરી છે એ ચિંતા અમારી સરકારે સૌથી પહેલા કરી છે સાંભળ્યું હશે અહીંયા હાઉસમાં અમારા મંત્રીશ્રી એ બાબતમાં જવાબ આપી એમ કહીએ કે પરાઓમાં પણ પાવર આપવામાં આવશે. આમાં નથી લીધું પણ એ હકીકત છે. તમે માત્ર આજ ન વાંચો, બીજું બધું પણ જુઓ, ઘણું બધું આની બહારનું છે મિત્રો કે ખેતરમાં પણ પાવર આપવાનો છે. અમારા મંત્રીશ્રીએ ખાતરી આપી જ છે અને આપવાના જ છે મુકેશભાઈ.

સાહેબ, અમારા એક વિદ્યાર્થી મિત્ર ઉદ્યોગપતિનો દીકરો થોડા સમય પહેલા મને ભેગો થયો, નોકરી કરતો હતો, મેં કહ્યું શું કરે છે ભાઈ ? તો મને કહે કે હું નોકરી કરું છું. કેમ શું થયું ? તો કહે, મારા બાપા એ.સી.માં બેઠા રહ્યા અને એ.સી.માં બેઠા બેઠા નિર્ણયો કર્યા એટલે અમારી આ હાલત થઈ. એમ આ દેશ ઉપર અને રાજય ઉપર કોંગ્રેસ ઈટિંગ, મિટિંગ અને સિટિંગમાંથી જ નવરી ન પડી અને એના કારણે આજે અમે પ્રગતિના પથ ઉપર જઈ રહ્યા છીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બીજી વાત કે, નર્મદા નદી, નર્મદાનો ડેમ, આખા રાજયનો..

અધ્યક્ષશ્રી : પરેશભાઈ ધાનાણી.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી (અમરેલી): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનમાં સાથી મિત્ર શ્રી શંકરભાઈ જે આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે, તેના ઉપર મારા વિચારો રજૂ કરવાની સંમતિ લઉં છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સુયોગ્ય શાસન પ્રણાલિમાં સરકારી સિદ્ધિઓની સફળતાનું માપ માત્ર પ્રજાના સહકારથી જ આંકી શકાય પરંતુ પ્રજાતંત્રનો અવાજ રૂંધી અને માત્ર ગુણગાનોથી નિષ્ફળતાઓ ઢાંકવાનો એક સરમુખત્યારશાહી અભિગમ આકાર લઈ રહ્યો હોય તેવું માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપરથી જણાય છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને એવું લાગતું હતું કે, * (xxxxx)

અધ્યક્ષશ્રી : પરેશભાઈ.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી : કોઈ રાજકીય કોમેન્ટ નથી કરતો.(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : શબ્દોનો દૂરુપયોગ ન કરો.(અંતરાય) બેસો બધા (અંતરાય) આમાં રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન માટે આવા શબ્દો ન વાપરી શકાય, એમને ગૌરવપ્રદ ન હોય એવા શબ્દો ન વપરાય. એમણે જે કાંઈ આવા શબ્દો વાપર્યા છે એ તમામ શબ્દો દૂર કરવાનો હું આદેશ કરું છું.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું વિનંતી કરું છું કે કોઈ બિનસંસદીય શબ્દોનો પ્રયોગ નહોતો કર્યો.(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : હંમેશ માટે માનનીય રાજયપાલશ્રીને ગૌરવપ્રદ હોય એવી વાત કરાય, ગમે તેવી વાત ન થાય, બેસી જાઓ.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી : જે અસંસદીય શબ્દો હોય એ આપના આદેશનું પૂર્ણ પાલન કરવા માગું છું, આવી કોઈ મારી વાત નહતી, મારી જો પૂરી વાત સાંભળી હોત તો બધા મિત્રો મને અભિનંદન આપવાના હતા એ હકીકત છે પણ મને સાંભળ્યો નહીં, બિલકુલ મારી કોમેન્ટ નહતી, મને એવું લાગ્યું હતું પરંતુ મને પાછળથી (અંતરાય) રાજકીય કોમેન્ટ નથી. (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : પાંચ મિનિટ પૂરી થઈ જશે, વાત કરો.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી : આજના આ ગુજરાતમાં પાંચ કરોડની જનતા ઈચ્છે છે, સસ્તું શિક્ષણ, સરળ વાહનવ્યવહાર, સુદૃઢ આરોગ્ય જાળવણી માટેની સુવિધા, સ્વમાનભેર જીવવા માટે રોજગારીની તકો, જીવનનિર્વાહ માટે સસ્તું રેશન અને પીવાનું પાણી, અસામાજિક તત્ત્વો સામે રક્ષણ, ઝડપી અને સરળ એવી વિશ્વનીય ન્યાય પ્રણાલી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયની વારસાગત ધરોહર સમાન ખેતી અને ખેડૂત એના માટે સસ્તી અને પૂરતી વીજળી, સુયોગ્ય સિંચાઈ વ્યવસ્થા તથા પરસેવાની કમાણી સમાન એમના ખેત ઉત્પાદનોના પોષણક્ષમ ભાવો.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી,માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના શાસનમાં આપણું ગુજરાત, આગવું ગુજરાત છે. આજકાલ આ સૂત્ર પ્રજાની વચ્ચે ચર્ચાય છે.ત્યારે હું તો માત્ર વાત રજૂ કરવા માગતો હતો કે આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાની ધરોહર સમાન અમારા સૌરાષ્ટ્રની તળપદી ભાષામાં આપની સંમતિ હોય તો, કોઈ રાજકીય અવલોકન નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : કોઈ સંમતિ નથી. આગળ વધો.

શ્રી પરેશભાઈ ધી. ધાનાણી : વાત કરવા માગું છું. રાજય સરકાર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજી રહી હતી. આ કાર્યક્રમની અંદર મારી બહેનો ગીત ગુનગુનાવતી હતી. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું નામ આવ્યું એટલે મને થયું કાંઈક વળી પાછું નવું થયું હશે ચાલો સાંભળી લઉં. ગીતા આ પ્રમાણે હતું.

* (XXXXX)

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય સભ્યશ્રી, અહીં ભજન ન ગવાય (અંતરાય) આ ભજનને રેકર્ડમાંથી દૂર કરવામાં આવે. નહીં, નહીં તમે બેસી જાઓ. (અંતરાય)

શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ(વાઘોડિયા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર આભાર પ્રસ્તાવ શંકરભાઈ લઈને આવ્યા છે એમાં મારો સૂર પૂરાવું છું...અંતરાય...ધોંધાટ..

અધ્યક્ષશ્રી : બધા બેસો પ્લીઝ.

શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીને વિનંતી છે કે તમે બોલો છો ત્યારે કોઈ ઊભા થઈને બોલતું નથી. (અંતરાય) વિચાર કરી લેજો.. (અંતરાય) ઘોંઘાટ.દાદાગીરી કરવી હોય તો કરો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર જે આભાર પ્રસ્તાવ શંકરભાઈ લઈને આવ્યા છે તેમાં મારો સૂર પૂરાવું છું. મારી એક વિનંતી છે કે જ્યારે આપ સૌ બોલતા હો ત્યારે અમે આપને શાંતિથી સાંભળીએ છીએ.

---

* (xxxxx)(આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા.)
* (XXXXX) આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે.

અમારે મોકો બોલવાનો આવે ત્યારે આપ લોકો શાંતિથી સાંભળો તેવી મારી વિનંતી છે. મારી ત્રીજી ટર્મ છે. ત્રીજી ટર્મના આધારે રાજ્યપાલશ્રીનું જે પ્રવચન હતું, તે પ્રવચન પહેલી વખત જ મેં શાંતિપૂર્વક રાજયપાલશ્રીને સાંભળ્યા છે. મારી ત્રીજી ટર્મ દરમ્યાનમાં આજસુધી જ્યારે પણ રાજયપાલશ્રી બોલવા ઊભા થતા હોય ત્યારે વિરોધપક્ષ ઊહાપોહ કરીને રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનને સાંભળતા ન હતા, પણ હું અભિનંદન પાઠવીશ કે આપ લોકોએ શાંતિથી સાંભળ્યા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન દરમ્યાન જે યોજના થઈ છે એ યોજના ગુજરાતની ૫ કરોડની પ્રજાની સામેની યોજના છે, જે યોજના સુજલામ્ સુફલામ્, જ્યોતિ ગ્રામ યોજના કે જેમાં છેવાડાનાં ગામના આદિવાસીઓને પાણી અને રોડની સુવિધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં થઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન દરમ્યાન જે ગુંડા તત્ત્વોની વાત કરતા હતા તે ગુજરાતની અંદર એકેએક ગુંડા તત્ત્વો ભૂગર્ભમાં દ ટૂસી ગયા છે. આ ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં રાતના સમયે આપણી વહુ, દીકરીઓ એક-એક વાગ્યા સુધી ફરે છે. આપણી વહુ, દીકરીઓની ઇજ્જત લૂંટવામાં નથી આવતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન દરમ્યાન ગુજરાતનાં જે વિકાસનાં કામો થયાં છે. ગુજરાતના બહારના રાજયમાં આપણે જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે વિકાસ કેવો થયો છે. વિકાસ તો ગુજરાતની અંદર થયો છે. નક્કર કામો થયાં છે, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં થયાં છે અને ૫૦ વર્ષ સુધી કોંગ્રેસ શાસન કરતી આવી, આ ૫૦ વર્ષના શાસન દરમ્યાનમાં ખાલી કાગળ ઉપર જ કામ ચાલતું આવ્યું અને ટકાવારીને લેતા આવ્યા છે, તે મેં મારી નજર સમક્ષ જોયું છે. જે રીતે ટીકા કરી છે, તે રીતની ટીકા કરતા અમને પણ આવડે છે.

અધ્યક્ષશ્રી : આપણે ટીકા કર્યા સિવાય પ્રવચન કરીએ.

શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ : નામ લઈને હું નથી બોલતો. આ લોકો અમારા મુખ્યમંત્રીશ્રી અંગે ગીતો ગાતા હોય, મિનિસ્ટર માટે જે ખોટું ખોટું બોલતા હોય તો....

અધ્યક્ષશ્રી : એમને મેં ત્યારે અટકાવ્યા છે.

શ્રી મધુભાઈ બા. શ્રીવાસ્તવ : એ લોકો ગીતો ગાય તો પછી અમને ગઝલ ગાતા પણ આવડે છે. જ્યોતિ ગ્રામ યોજના જે ૨૪ કલાક લાઈટ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતના ૧૮,૦૦૦ ગામડાં છે, એની અંદર ૭,૦૦૦ ગામડાઓને ૨૪ કલાક વીજળી જ્યોતિ ગ્રામ યોજનામાં આપી છે. ૧૮,૦૦૦ ગામડાને ૨૦૦૫ ના એન્ડની અંદર આખા ગુજરાતમાં ૨૪ કલાક વીજળી મળશે, એવો અમારો સંકલ્પ છે.

નર્મદા યોજનાની વાત. નર્મદા યોજનાની અંદર પણ છેક સૌરાષ્ટ્ર સુધી પાણી પહોંચાડવાનો અમારી સરકારે પ્રયત્ન કર્યો છે અને કરતી આવી છે. આજે અમારા મધ્ય ગુજરાતની અંદર નર્મદાના પાણી ખેડૂતોને મળતા થઈ ગયા છે. વિકાસ જે કર્યો છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યો છે અને નક્કર કર્યો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શિક્ષણના વિષયમાં જયારે આ રાજયમાં કોંગ્રેસનું શાસન હતું ત્યારે (સમયસૂચક દ ઇંટડી) શિક્ષણના વિષયમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન દરમ્યાન કોંગ્રેસમાં તો માસ્તરોને ભણાવતા ન હતા અને અમે માસ્તરોને ભણાવીને મૂકયા છે. તેમના શાસનમાં સાતમા ધોરણમાં અંગ્રેજી ચાલતી હતી જયારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં પહેલા ધોરણથી અંગ્રેજી ચાલુ કરવાના છીએ. માનીય સભ્યો જુદી જુદી વાત કરે, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વિશે વાત કરે પણ હું તો એ કહેવા માગું છું કે ગુજરાતના ઈતિહાસની અંદર આ પહેલા એવા મુખ્યમંત્રી છે તે મુખ્યમંત્રી ગુજરાતમાં દસ વર્ષ રહી જાય તો ગુજરાતને અમેરિકા ટાઈપ કરી દે. મને કોઈની બીક નથી લાગતી. ડરવાનો કોઈ સવાલ નથી. મોત તો બધાને આવવાનું છે. કોઈ અમરફળ લઈને નથી આવ્યું. વહેલા અને મોડા બધાને જવાનું જ છે. અમે સાચુંબોલીએ છીએ એટલે ડરવાનો સવાલ નથી.

શ્રી પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ (ગઢડા): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર જે આભાર પ્રસ્તાવ માનનીય શંકરભાઈ ચૌધરી લઈને આવ્યા છે તેને હું અનુમોદન નથી આપી શકતો. રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનના પહેલા પાના ઉપર ગાંધીજી અને સરદારના મૂલ્યો અને ગાંધીજીની નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતા વિશે વાત કરી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારના જે મિત્રો છે તે વારંવાર ગાંધીજીના મૂલ્યો અને ગાંધીજીની નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતાની વાતો કરે છે. ત્યારે ગાંધીજીના આ ગુજરાતમાં આ સરકાર વારંવાર જે મૂલ્યોની વાત કરે છે તેમાં હું જણાવું છું કે ગાંધીજીના જીવનમાંથી પ્રેરણા લેવી હોય તો એમણે જે બ્રિટિશ શાસનને હટાવ્યું, હું એ જ કહેવા માગું છું કે ગાંધીજીના મૂલ્યોની વાત કરવી હોય તો જે રીતે ગાંધીજીએ અહિંસાત્મક લડત કરી અંગ્રેજોને હાંકી કાઢયા હતા તે મૂલ્યોને યાદ કરવા પડે. આ સરકારની નીતિ જોઈએ તો ધારાસભ્યશ્રીઓને ગૃહમાં પ્રવેશતા રોકવામાં આવે છે, ફુવારા ઉપર લોકો ઉપવાસ ઉપર બેસીને આંદોલન કરીને થાકીને ઘરે જતા રહે છે પણ સરકારના કોઈ મંત્રી કે મિત્રો તેમની ખબર લેતા નથી. સરદારની વાત કરનારા મિત્રોએ સરદારના મૂલ્યોને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાની જરૂર છે. આઝાદીને ૫૭ વર્ષ થયા પછી પણ આ સરકારની ભ્રષ્ટ નીતિ રહી છે અને સરમુખત્યારશાહી છે તેની સામે અમારા સોનિયા ગાંધીને તેરમી માર્ચે દાંડીયાત્રાનું આંદોલન કરવાની ફરજ પડી છે. ગાંધીજીના પૌત્ર તુષાર ગાંધીની આગેવાની નીચે સરકારનું ધ્યાન દોરવાના છીએ. આઝાદીના ૫૭ વર્ષ પછી ગુજરાતનો નાગરિક પોતે સ્વતંત્રતા અનુભવી શકતો નથી. સરકાર

જુદી જુદી યોજનાઓના નામ આપે છે. હું એક દ્રષ્ટાંત આપવા માગું છું કે, એક માણસ મિત્રને એમ પૂછે છે કે....

અધ્યક્ષશ્રી : આપ ગૃહમાં દ્રષ્ટાંત નહીં આપી શકો, નો... નો..

શ્રી પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કેન્દ્ર સરકારમાંથી જે નાણાં આપવામાં આવે છે અને એમાં ગુજરાત સરકારે ૫૦ ટકા નાણાં ઉમેરવાના હોય છે, કેન્દ્ર સરકારમાંથી અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ માટેની જે યોજનાઓ છે એમાં જે ફાળો આપવામાં આવે છે એમાં બે હેડ નીચે ફાળો આપવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકારના, એમાં કોમ્પોનન્ટ પ્લાન, કે જે એસ સી માટેનો છે અને એસસીપી, સ્પેશિયલ કોમ્પોનન્ટ પ્લાન, અનુસૂચિત જનજાતિ માટે એટલે કે એસ.સી. માટે, ટ્રાઈબલ સબ પ્લાન અને એ ઉપરાંત સેન્ટ્રલ સ્પેશિયલ આસિસ્ટંટ, કેન્દ્ર સરકાર જે ફાળો આપે છે. પણ ગુજરાત સરકાર એમાં એનો ફાળો આપતી નથી. જે સાત ટકા અનુસૂચિત જાતિ માટે વાપરવાના હોય છે કેન્દ્ર સરકારના ફાળાના અને ગુજરાત સરકાર જે ફાળો આપે એમાં એ સાત ટકાનો એમાં ઉપયોગ થતો નથી. અનુસૂચિત જાતિના જે લોકો છે એમના માટે ચૌદ ટકા વાપરવાના હોય છે એ ચૌદ ટકા પણ એમાં ફાળવવામાં આવતા નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતની હાઈકોર્ટે, વડી અદાલતે બેકલોગની જગ્યાઓ ભરવા માટે ગુજરાતની રાજય સરકારે એમાં એફિડેવિટ ફાઇલ કર્યુ છે કે આ એફિડેવિટ દ્વારા એવું વચન આપ્યું છે કે, બેકલોગની ૨૮ હજાર જેટલી જગ્યાઓ ભરી દેવામાં આવશે.પણ આજ દિવસ સુધી એ કદમ ઉઠાવવામાં આવ્યું નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે આપણે એસ.ટી.ની વાત કરતા હોય ત્યારે આજે ગુજરાતમાં બસો વારંવાર બ ંધ થઈ જતી હતી, માનનીય અશોકભાઈ બોલતા હતા કે, અમે કેસરી રંગ એટલા માટે કરીએ છીએ કે એ શૂરવીરતાની નિશાની છે, તો મારે એમને એક સૂચન છે કે, તેઓશ્રી શરૂઆત એમના ઘરેથી કરે, એમને એમનું ઘર આખું કેસરી કરી નાખવું જોઈએ, સોફા, પલંગ, વગેરે ઘરની જે ચીજવસ્તુઓ છે એનો રંગ કેસરી કરી નાખો, એમાં મને કોઈ વાંધો નથી પણ સરકારની એસ.ટી.નો એક વખત કલર થયા પછી એના ઉપર કેસરી રંગ કરવાનો આદેશ કરવામાં આવે એ તો સરકારી નાણાંનો દુર્વ્યય કહેવાય, તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તેઓશ્રી એમના ઘરથી પહેલાં શરૂઆત કરે તો અમને આનંદ થશે અને અમે એમને અભિનંદન આપીશું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નોકરી માટે, જે શિક્ષણ માટે અનામતની જોગવાઈ છે પ્રવેશ માટે એમાં પણ કોઈ જાતની સરકારે ખેવના કરી નથી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે પ્રવેશ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે એમાં પણ જનરલ કેટેગરીમાં જે વિદ્યાર્થીઓ અનુસૂચિત જાતિના આવતા હોય એમને લેવામાં આવતા નથી, ભાવનગરનો એક દાખલો હું આપું તો, યુનિવર્સિટીમાંમારે રૂબરૂ જઈ ૧૪ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવા માટેની ફરજ પડી હતી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારશ્રીનું ધ્યાન દોરવાની જરૂર છે, આજે અનુસૂચિત જાતિની વાત કરનારા ખાનગીકરણ તરફ થઈ રહ્યા છે, આજે જે જયોતિગ્રામની યોજનાની વાત થતી હોય ત્યારે મારે કહેવું જોઈએ કે, આ જયોતિગ્રામના નામે સરકાર પોતે (સમયસૂચક ઘંટડી) આ યોજનાને બારોબાર વેચી નાખવાનું ષડ્યંત્ર છે.

શ્રી રાજેશભાઈ પાઠક (બાલાસિનોર): માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મહામહિમ રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર આભાર પ્રસ્તાવ માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ લઈને આવ્યા છે એમાં હું મારા વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે ઊભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનમાં શરૂઆતમાં જ કહ્યું છે કે, મારી સરકાર ગ્રામ સ્વરાજ્યથી રામરાજ્ય સ્થાપવાની દિશામાં જઈ રહી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રામરાજ્યની કલ્પના તો માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જ કરી શકે, મન હોય તો માળવે જવાય, જ્યારે રામરાજ્યની કલ્યના નથી કરી, જ્યારે રામ સાથે નિસબત નથી ત્યારે એ લોકો રામરાજ્યની વાત સમજી નહીં શકે.

માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનમાં રિવરગ્રીડ યોજનાની વાત કરવામાં આવી, નર્મદાની કેનાલ હાલ જે નદીઓ ઉપરથી પસાર થાય છે એ દશ નદીઓમાં નર્મદાની કેનાલથી પાણી નાખવામાં આવી રહ્યું છે. હું જે મતવિસ્તારમાંથી આવું છું, જે મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરું છું એ બાલાસિનોર, ત્યાં આવતા સુધીમાં ચાર નદીઓ આવે છે, મોર નદી, મેશ્વો નદી, વાત્રક નદી અને સાબરમતી નદી, આ નદીઓ અગાઉના વર્ષોમાં સાવ સુકીભઠ જોવા મળતી હતી, ચોમાસામાં વરસાદ આવે, ઘોડાપૂર આવે અને પાણી વહી જાય, નદીઓ ખાલી ખટ થઈ જાય, પણ અત્યારે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે ચારેબાજુ લીલોતરી, હરિયાળી નજરે પડે છે, આપણી નજર ઠરે છે, સાચા અર્થમાં નદીઓ લોક માતા બને એ કામ ભાજપની સરકારે કર્યુ છે, એ દિશામાં આગળ વધી રહી છે. સુજલામ સુફલામની યોજના વિશે મને યાદ છે કે ગઈ વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન એક સન્માનનીય સભ્યશ્રી નેતાએ એમ કહયું હતું કે, સુજલામ સુસલામ, એવા શબ્દો એમણે વાપર્યા હતા એ વખતે મને ઘણું દુ:ખ થયું હતું. આપણી સંસ્કૃતિમાં આપણા દેશમાં, આપણા રાજયમાં આપણી નદીઓને લોકમાતા તરીકે ગણેલી છે, એમાં મહીસાગર માતા હોય કે નર્મદા માતા હોય, મારા વિસ્તારમાં જે મહીસાગર નદી પસાર થાય છે, આ મહિસાગર નદીનો લોકો એટલો બધો આદર રાખે છે કે, હું આપને કહું કે જે રીઢા ગુનેગારો છે જેની ઉપર

પોલીસ સ્ટેશનમાં થર્ડ ડીગ્રી વાપરવા છતાં બોલતા નથી એને મહિસાગર માતાનું પાણી હાથમાં આપીને બોલાવવામાં આવે તો એ રીઢો ગુનેગાર સાચી વાત કહી દે છે. એટલે મહિસાગર પ્રત્યે લોકોનો આટલો આદર છે અને એના વિરુધ જઈને સુફલામ-સુજલામ વિશે જે શબ્દો બોલાઈ છે ગૃહમાં એ ખરેખર નિંદાને પાત્ર છે. સુફલામ-સુજલામની વાત આ ગૃહમાં જે ખેડૂતોની વાત કરે છે માનનીય જગદીશભાઈ અને માનનીય ગોવાભાઈ મારું એમને આમંત્રણ છે મારા મત-વિસ્તારમાં આવો તો બતાવું મારા વિસ્તારમાં ૫૦૦-૫૦૦ ફૂટ ઉંડા રીંગ કરવા છતાં પાણી મળતું નથી. આજે સુફલામ-સુજલામ કેનાલ ત્યાં ખોદાઈ રહી છે આ યોજના આવવાથી, આ યોજનાનું કામ અત્યારે ચાલું છે ત્યારે ત્યાં આવીને જુએ તો ખ્યાલ આવે કે ખેડૂતોના મનમાં કેટલો આનંદ છે. સુફલામ-સુજલામ આવવાથી આ સરકારને લાખો લાખો આશીર્વાદ ખેડૂતો આપી રહ્યા છે. આ યોજના થવાથી અમારા વિસ્તારના પાણીના તળ ઉંચા અવવાના છે. અમારા વિસ્તારના ખેડૂતો આશા લઈને બેઠા છે કે આ ડિસેમ્બરમાં સુફલામ-સુજલામ યોજના ચાલુ થઈ જશે તો અમારા વિસ્તારના ખેડૂતો એનાથી સુખી થવાના છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રસ્તાઓની વાત કરું તો માનનીય સભ્યશ્રી ગોવાભાઈ કહેતા હતા કે અમે તો કાર્પેટ કરી હતી પણ તમે માથે રિકાર્પેટ કરો છો. ઉછળી-ઉછળીને ગોવાભાઈ આ શબ્દો બોલતા હતા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા વિસ્તારમાં ૮૦-૯૦ ટકા રસ્તાઓ અત્યારે ખરાબ થઈ ગયા છે, આ લોકોની કાર્યક્ષમતાનું પરિણામ છે અને માનનીય આઈ. કે. જાડેજાને એમાં રિકાર્પેટ કરવાનો વારો આવ્યો છે એ એમની કાર્યક્ષમતાનું પરિણામ છ. અત્યારે આ રસ્તાઓનું કામ સુધરી રહ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી અત્યારે જે ધારાસભ્યો આ ગૃહમાં આવે છે એ એક્ષપ્રેસ હાઈવે ઉપરથી આવતા હોય છે. આ એક્ષપ્રેસ હાઈવેમાં વડોદરાથી અમદાવાદનું અંતર માત્ર એક કલાકમાં સમાપ્ત થાય છે.આ એક્ષપ્રેસ હાઈવેનું કામ ખોરંભે પડયું હતું. આ ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર આવી અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકારે આ હાઈવેનું કામ પૂરું કર્યું છે એટલે આ સરકાર ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે.

ચેકડેમની વાત કરું તો સરદાર સહભાગી જળસંચય યોજના હેઠળ રાજયમાં ૫૦ હજાર ચેકડેમ બનાવવામાં આવ્યા છે. મારા વિસ્તારમાં પણ આશરે ૨૫૦ જેટલા ચેકડેમો બન્યા છે. હું દાવા સાથે વાત કરવા માગુ છું, હવામાંની વાત નથી. મારા વીરપુર તાલુકાના ખાડિયા ગામે ચેકડેમ બન્યા છે, બે ચેકડેમ બન્યા છે એનાથી આજુબાજુના ખેડૂતોને ગઈ સાલ એક હજાર મણ ઘઉંનો ઉતારો વધારે આવ્યો છે અને એની સાબિતી જોઈતી હોય તો મારું આમંત્રણ છે, મારા વિસ્તારમાં આવો તો હું તમને બતાવું, ખેડૂતો પાસે લઈ જઈને પ્રત્યક્ષ બતાવું. જો માત્ર બે ચેકડેમોથી એક હજાર મણ ઘઉંનો ઉતારો વધારે આવતો હોય તો આ ૫૦ હજાર ચેકડેમોથી કેટલા ખેડૂતોને લાભ થયો હશે એ કલ્પના કરવાની વાત છે. માનનીય જગદીશભાઈ આ ગૃહમાં કહેતા હતા કે, માયાબેન અને ગોરધનભાઈને રોવાનો વારો આવ્યો છે. અમારા કોઈ સભ્યશ્રીને રોવાનો વારો આવતો નથી. પણ જગદીશભાઈ એ વાત યાદ કરે કે એમના પ્રભારી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ આવ્યા હતા ત્યારે એનેક્ષીમાં એમના નેતા સ્વર્ગસ્થ અમરસિંહભાઈ ચૌધરીએ પોલીસ રક્ષણ માગવું પડયું હતું. આ વાત જગદીશભાઈ કેમ ભૂલી જાય છે? આ કોંગ્રેસ પક્ષે યાદ રાખવા જેવું છે.

જયોતિગ્રામની વાત કરું તો ૧૮ હજાર ગામડાંમાંથી ૭ હજાર ગામો જયોતિગ્રામ થઈ ગયાં છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં ગામડાં તૂટી ગયાં હતાં.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય રાજેશભાઈ, આપનું પ્રવચન પૂરું થાય છે.

શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર(મહુધા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપરનો આભાર પ્રસ્તાવ લઈને માનનીય ધારાસભ્યશ્રી શંકરભાઈ આવ્યા છે એમાં હું મારા વિચારો વ્યકત કરું છું અને એનો હું વિરોધ કરું છું.

પહેલાં આ દેશમાં બધાં રજવાડાં હતાં, બધાં જુદાં જુદાં રાજયો હતાં એમાં ઘણાં રજવાડાં સારાં હતાં અને

ઘણાં ખરાબ પણ હતાં અને ઘણા સુબાઓ પણ હતા. પણ જે રાજા પોતાની પ્રજાને સાચવી ન શકે એ રાજ કેવી રીતે કરી શકે? કારણ કે, પેલા ફતેસિંહ ઉપર ફાયરીંગ થયું તો પણ કશું કરી શકયા નહીં. ફતેસિંહને પૂછી જુઓ તમારી ઉપર ફાયરીંગ થયું તોય કશું કરી શકયા? એટલે આવા રાજયમાં પોતાના સભ્યનું પણ રક્ષણ ન થઈ શકતું હોય તો એવું રાજ શા કામનું? આ રાજયની પ્રજાએ આ બધાને શા માટે ચૂંટયા છે? આ ધારાસભ્યો છે એ બધા જેમ રજવાડામાં સુબાઓ હતા એમ આ સુબાઓ છે. પણ સુબાઓ બરાબર ન રહે તો લોકો એમને કાઢી મૂકે છે.લોકોની સુખાકારી કેવી રીતે વધે એ બધાએ વિચારવાનું છે, પણ આપણે તો એ વિચારતા જ નથી, આપણે તો ખુરશી મળી એટલે બધા મોટા બાદશાહ બની જાય છે, પણ એમ બાદશાહ ન બનાય, આપણે લોકોના સેવક બનવું પડે, જે જે યોજનાઓ હોય એનો અમલ કરવો પડે. આ રાજ્યમાં એનો અમલ થતો જ નથી. આ ભા.જ.પ. નું રાજ કેવું છે, (અંતરાય) તો સરમુખત્યાર જ છે, પાકિસ્તાનના મુશરફ જેવા, અલ્યા ભાઈ મુશરફ જેવા ન થશો, નહિતર આ લોકો તમને કાઢી મૂકશે, બરાબર? લોકો ના કાઢી મૂકે એવું કંઈક કરો, નહિતર હવે તૈયારી છે તમારી, સામી પાટલીએ તમે બેઠા છો.

અધ્યક્ષશ્રી : એમને કાઢી મૂકશો તો તમારો વારો આવશે.

શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર : આવવાનો જ છે સાહેબ, અમારો વારો સો ટકા આવવાનો જ છે. આ સીધા નહિ રહે એટલે અમારો વારો આવવાનો જ છે. સીધા રહે તો ના આવે પણ સીધા નથી રહેવાના કારણકે આ લોકોએ અંદરોઅંદર બાખડવાનું તો ચાલુ જ કરી દીધું છે, હવે થોડીવાર છે વહેલો મોડો વારો તો અમારો આવવાનો જ છે. આ રાજ્યમાં પહેલું તો જે સુખાકારી જોઈએ, શિક્ષણ જોઈએ, અમારી માધવસિંહની સરકાર વખતે કન્યાઓ માટે મફત શિક્ષણ હતું, અત્યારે પરિપત્ર તો છે કે શિક્ષણ મફત, પણ ફી એટલી બધી લેવાય છે, સ્વનિર્ભર કોલેજો છે એ કેટલી બધી ફી લે છે? કઈ રીતે ભણવાના લોકોના બાળકો, ગરીબ જનતાના બાળકો કઈ રીતે ભણવાના? માટે એનું કંઈક કરવું જોઈએ. કારણકે ભણશે તો સૂઝ અને સમજ આવવાની છ, જો ભણેલ ગણેલ હશે તો રાજમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવશે, ભણ્યા ગણ્યા વિના સુખ-સમૃદ્ધિ નથી આવવાની. આ લોકો આ તો સમજતા જ નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય નટવરસિંહ, તો શું કરવું જોઈએ? કોઈ સજેશન હોય તો કહો.

શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર : આ કોંગ્રેસના રાજમાં આવું નહોતું. અમારું રાજ તો બહુ સારુ હતું. બધુ મફત, કન્યા કેળવણી મફત, શિક્ષણ મફત, કોલેજોમાં ફી હતી જ નહિ. આ લોકોએ તો સ્વનિર્ભર કોલેજોની મંજૂરી આપી દીધી છે ટેકનોલોજીના જે અભ્યાસો છે એમાં તો કોઈને ગરીબ બાળકોને પ્રવેશ જ મળતો નથી. તો ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ભણવાની સગવડ મળે એ પણ કરવું જોઈએ, હા જે હોંશીયાર વિદ્યાર્થી હોય એ જો મહેનત કરે તો એને ઘણા ચાન્સીસ છે. ખેતીવાડીમાં પણ એવું છે, ખેતીવાડી એટલી બધી આ ગુજરાતમાં છે, પણ એમાં પણ આ લોકો કશું કરી શકતા નથી. કોઈપણ વિભાગમાં એમનું કામ સારું નથી. સારું કામ હોય એ આ લોકો કરી શકતા જ નથી. આમ બધા હોંશિયાર છે, પણ હોંશિયારીમાં અને હોંશિયારીમાં આ લોકો રહી જવાના છે.

સભાગૃહની બેઠકનો સમય લંબાવવા અંગે

શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ : (મુખ્ય દંડકશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રીઓના પ્રવચન પૂરા થાય ત્યાંસુધી ગૃહનો સમય લંબાવવામાં આવે.

અધ્યક્ષશ્રી : એવું નહિ, જે બાકી હોય એ બધા નહિ પણ દશથી પંદર મિનિટ સભાગૃહનો સમય લંબાવીએ.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : દશથી પંદર મિનિટ લંબાવવામાં આવે તો અમને વાંધો નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : દરેકને પાંચ મિનિટ આપવામાં આવશે. સભાગૃહ સંમત છે ? (થોડીવાર બાદ) સભાગૃહનું કામકાજ નક્કી કરેલ સભ્યશ્રીઓ પ્રવચન પૂરું કરે ત્યાં સુધી સમય લંબાવવામાં આવે છે.

શ્રી હરેશકુમાર ઈ. ભટ્ટ(ગોધરા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી જે મહામહિમ્ રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચનનો આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે એના સમર્થનમાં મારા વિચારો પ્રદર્શિત કરવા માટે હું ઉપસ્થિત થયો છું સૌથી પહેલાં તો આજે આ બીજું વર્ષ પૂરું થયું છે. બે વર્ષમાં બે રાજ્યપાલશ્રીઓના મેં પ્રવચન સાંભળ્યા છે. રાજનીતિમાં પહેલીવાર આવ્યો છું..

અધ્યક્ષશ્રી : દરેકને પાંચ મિનિટ મળે છે ટૂંકમાં જે મુદ્દા કહેવા હોય તે કહે તો સારું.

શ્રી હરેશકુમાર ઈ. ભટ્ટ(ગોધરા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મુદ્દાઓ તો લેવા જ પડશે. મુદ્દા વગર તો આ પ્રવચન નહિ થાય, પણ એમનો આભાર પણ માનવો પડશે, મેજ પર મૂકવો પડશે એટલા માટે છેલ્લી જ્યારે પાંચ મિનિટમાં વકતવ્ય આપવાની વાત કરો અને સમય ઓછો આપો, આપ શરૂઆતમાં વધારે સમય ફાળવો છો તેથી પાછળના વક્તાઓને હંમેશ અન્યાય થતો હોય છે. આપ ન્યાયિક રીતે બધાને સરખો સમય આપો તો આ પરિસ્થિતિ નિર્માણ ન થાય સાહેબ. બે રાજ્યપાલશ્રીઓના પ્રવચનો મેં સાંભળ્યા છે. અહીંયાં આજે હું રાજ્યપાલશ્રીએ જે પ્રવચન કર્યુ એના આભાર અને એને બિરદાવવા માટેની વાત નહિ, આ રાજ્યપાલશ્રીએ સરકારની ખૂબ સુંદર પ્રસંશા કરી છે એટલા માટે હું આભાર વ્યક્ત નથી કરતો, પરંતુ સમાજ અને કુટુંબના વડા ગુજરાતના પ્રથમ નાગરિક તરીકે જ્યારે એમણે જે પણ ઉદ્‌બોધન કર્યુ હોય ત્યારે એને સન્માનવું જોઈએ એ આપણી સંસ્કૃતિ છે. ગયા વખતે કેન્દ્ર સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની હતી અને જ્યારે જ્યારે રાજયપાલશ્રીને મૂકવામાં આવ્યા અને તેમને જે પ્રવચન કર્યુ ત્યારે મારા સાથી પક્ષોએ તેનો વિરોધ કર્યો. પ્રવચન સાંભળવા નહીં દીધું અને આજે જ્યારે કોંગ્રેસ દિલ્હીમાં સરકારમાં બેઠી છે અને તેમણે જ્યારે રાજયપાલશ્રીને નિયુક્ત કર્યા ત્યારે તે એક કલાક અને પાંત્રીસ મિનિટ સુધી તેમને રૂચે કે ના રૂચે તે પ્રવચન તેમણે સાંભળ્યું છે. એટલે તેમના સભ્યે કહ્યું કે કંટાળાજનક પ્રવચન સાંભળવું પડ્યું. એ તેમની જ પાર્ટી તરફથી મૂકેલા વ્યકિતને તેમણે સન્માનવા જોઈએ તે પણ તેમનામાં ગટ્સ નથી.

શ્રી જગદીશ ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ગવર્નરશ્રી કોઈના મુકાતાં(અંતરાય) ગવર્નરશ્રી મૂકયા છે તેમને માટે આવા શબ્દ પ્રયોગ ના થાય તેમને માન સાથે સંબોધવા જોઈએ. આ વાત વાજબી નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : રાજયપાલશ્રીનું ગૌરવ સચવાય તે રીતે વાત કરો

શ્રી હરેશકુમાર ઈ. ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તે કેન્દ્રની સરકાર નિયુક્ત કરે છે તે મને ખબર છે. મારો સમય નહીં બગાડો મારે ઘણું કહેવાનું છે. મેં તમને તમારા સમયમાં ડિસ્ટર્બ નથી કર્યા, અમે પણ તમને સાંભળ્યા છે, ઘણું બધુ ખોટું સાંભળ્યું છે અને તો પણ બરદાસ્ત કર્યુ છે. એટલે શાંતિથી સાંભળ્યા છે માટે હું અભિનંદન પાઠવીશ કે કમસેકમ એટલી ક્ષમતા તો દર્શાવી. આજે જે વિષયો લઈને રાજયપાલશ્રીએ પ્રવચન કયુ, આપણે ત્યાં કથા વાર્તા કહેતા હોઈએ છીએ ત્યારે પૂર્ણાહૂતિમાં આપણે પંચામૃતના પ્રસાદનું વિતરણ કરીને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. રાજયપાલશ્રીએ પણ આ જ કર્યુ. ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક વર્ષના શાસનની અંદર તેમણે જે સુધારાઓ કર્યા છે તેની પ્રશસ્તિ સ્વરૂપ તે એક એક સોપાનો વાંચીને ગણાવ્યા અને છેક અદના અને છેવાડાના માનવી સુધી તે સંદેશ પહોંચાડવાનું જ્યારે કામ કર્યુ ત્યારે તે પંચામૃતના ધ્યેય સાથે તેમણે શકિતઓનું પ્રદર્શન બતાવીને આખા ગુજરાતને એક વિકાસના માર્ગ ઉપર લઈ જતા અહીં પ્રદર્શિત કરીને સમાજ સુધી પહોંચાડવાનું તે કાર્ય કર્યુ છે અને એટલા માટે આ પ્રવચનને આપણે બિરદાવવું જોઈએ અને તેમને અભિનંદન પાઠવવાં જોઈએ. (અંતરાય) સૌથી પહેલાં વાત કરી કે આજે કોઈ પણ રાષ્ટ્રનો વિકાસ હોય તો આપણે ત્યારે જ સમજી શકીએ જ્યારે આપણે સુરક્ષિત હોઈએ અને આજે ગુજરાત એટલું સુરક્ષિત છે, એટલું સલામત છે તેનું એક જ માત્ર ઉદાહરણ છે આજે જે જગ પ્રસિદ્ધ એવું અમારું ગોધરા. ત્રણ ત્રણ વર્ષ સુધી જયાં કરફયુ લાગ્યો હોય એવા આ ગોધરા શહેરની અંદર, ગોધરા તાલુકાની અંદર છેલ્લાં બે વર્ષમાં એક નાનકડું છમકલું પણ નથી થયું અને એક નાનકડો કરફયુ પણ નથી લાગ્યો, આ સુરક્ષા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની. સુરક્ષાની વાત કરી તે દિવસે પોરબંદરની વાત થતી હતી પોરબંદરની જેલો બંધ કરવી પડી હતી એવી ગુંડાગર્દી ત્યાં ચાલતી હતી આજે ગોધરાની અંદર સ્કૂટર ના ચાલી શકે એવા વિસ્તારની અંદર આજે ટ્રકો ફરતી થઈ છે એટલી સુરક્ષા વ્યવસ્થા આજે ત્યાં ગોઠવવામાં આવી છે.

શ્રી અમિત ચાવડા(બોરસદ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજયપાલશ્રીના સંબોધન ઉપર માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ જે આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે તેના ઉપર આ ગૃહમાં પહેલી વખત ભાગ લેવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો છે તેમાં મારા વિચારો રજૂ કરું છું. માનનીય રાજયપાલશ્રીએ ખૂબ જ લંબાણથી ૮૫ મિનિટ સુધી આ રાજયના વિકાસની ગાથાઓ ઉપરનું પ્રવચન કર્યુ તેમાં જે આ રાજયની ખૂબ જ ગંભીર બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી તેની ઉપર હું થોડોક પ્રકાશ પાડવા માગું છું. રાજયમાં વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪ની સ્થિતિએ ૪૦૪૨૫ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૮૨.૬૫ લાખ બાળકો અભ્યાસ કરે છે એ જ રીતે માધ્યમિક શાળાઓ અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં ૨૪.૭૬ લાખ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. આ બાળકો/વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં આવતીકાલના ગુજરાતનું ભવિષ્ય સોંપીશું ત્યારે બોગસ ડિગ્રીધારી ખોટા પ્રમાણપત્રોના આધારે જે શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવી છે એ ખૂબ જ દુ:ખદ બાબત છે અને આપણા ગુજરાતના બાળકોના આવનાર ભવિષ્ય સાથે એક ચેડાં સમાન છે. નામદાર રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનમાં આવી ગંભીર બાબતનો કોઈ જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નથી એ ખૂબ જ દુ:ખદ બાબત છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા એ કોઈ એકાદ બે દિવસની ભરતી પ્રક્રિયા ન હોઈ અને એક જ વ્યકિત દ્વારા થતી ભરતી પ્રક્રિયા ના હોઈ એમાં સમગ્ર રાજયની શાળાઓથી માંડીને શિક્ષણ વિભાગ સુધી દરેકની સંડોવણી સાબિત થાય છે ત્યારે સમગ્ર જવાબદારો સામે પગલાં લેવાની ગંભીરતા આપણે સૌએ સમજવી જોઈએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઈ-ગર્વનન્સ અને ઈ-ગ્રામ વિશે વાતો કરવામાં આવી છે. તો ગત ૨૦૦૪-૨૦૦૫ ના વર્ષને ઈ-ગર્વનન્સ વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કરવામાં આવેલ હતું. મારા જિલ્લાની વાત કરું તો મારા જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ખૂબ જ દબાણ કરીને અને દરેક ગ્રામ પંચાયતને ફરજ પાડી કે કોઈપણ હિસાબે ગ્રામપંચાયતમાં કોમ્પ્યુટર વસાવો. તો કેટલીક ગ્રામ પંચાયતોએ કોમ્પ્યુટર વસાવ્યાં અને બાકી રહી ગઈ એ પંચાયતોને ૧૧ મા નાણા પંચની ગ્રાન્ટમાંથી તેમને ના જોઈતાં હોય તો પણ કોમ્પ્યુટરની ફાળવણી કરવામાં આવી અને આજે એક વર્ષનો સમય થયો હોવા છતાં ગ્રામ પંચાયતોમાં તલાટીઓને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ન આપવાને કારણે અથવા તો કોઈ યોગ્ય વ્યકિતને કોમ્પ્યુટર ચલાવવા માટે નીમવા માટેની કોઈ નાણાકીય જોગવાઈ નહીં કરવાને કારણે આજે ગ્રામ પંચાયતોમાંથી આ કોમ્પ્યુટર દૂર થઈ રહયાં છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમારા વિરોધપક્ષના માનનનીય નેતાશ્રીએ વાત કરી કે આ રાજય સરકાર દ્વારા રાજયમાં આવેલ લાખો હેકટર પડતર જમીન કોતર લેન્ડ એ લાખો હેકટર જમીનમાં ખારાશનું પ્રમાણ વધી રહયું છે એ બાબતે પણ નામદાર રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનમાં કોઈ જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નથી એ એક દુ:ખદ બાબત છે.

આ રાજય સરકારની ભેદભાવભરી નીતિની વાત કરીએ તો મારા વિસ્તારમાં ઉમેટા-સીંગરોડ પાસે એક આડબંધ બની રહયો છે. ભાદરણ, પાદરા અને જંબુસરના ધારાસભ્ય હશે અને વડોદરા(ગ્રામ્ય) ના

ધારાસભ્ય પણ હશે અને તેમને ખ્યાલ હશે કે મહીસાગર નદીમાં આ ઉમેટા-સીંગરોડ પાસે આડબંધ થાય તો મહસાગર નદીનું જે વહેણ એને ઉમેટા પાસે રોકવામાં આવશે તો ખંભાતના અખાતની ભરતીનાં પાણી ત્યાં રોકાશે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં આશરે ૫૦ થી ૬૦ ગામના ભૂગર્ભ જળને અસર થશે અને તળનાં પાણી ખારાં થશે એ બાબતની આ સમગ્ર વિસ્તારના લોકો અને ધારાસભ્યશ્રીઓની રજૂઆતને આ સરકારે ધ્યાને નહીં લઈને અને મૂઠ્ઠીભર ઔદ્યોગિક ગૃહો, વડોદરાના અને વડોદરા શહેરના લોકોને પાણીની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે આ આડબંધનું કામકાજ ચાલુ રાખીને આ ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને અન્યાય કરવામાં આવી રહયો છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહમાં ચર્ચામાં ભાગ લેવાનો પ્રથમ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો છે અને આજ સવારથી માનનીય શંકરભાઈ જેવા વિદ્વાન યુવાન વકતાથી માંડીને માનનીય અશોકભાઈ સાહેબ જેવા વિદ્વાન વકતાઓનાં પ્રવચન મેં સાંભળ્યાં. મને તો એમ હતું કે શાસક પક્ષના સભ્યો સમગ્ર રાજયના ગરીબ લોકોના પ્રશ્નો માટેની ચિંતા કરતા હશે, પરંતુ મારે દુ:ખ સાથે કહેવું પડે છે કે ફકત એક જ વ્યકિતનાં ગુણગાન ગાઈને એક જ વ્યકિતની સ્તુતી કરવામાં આ સમગ્ર દિવસ પસાર થઈ ગયો છે.

શ્રી ફતેસિંહ વ. ચૌહાણ(રાજગઢ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રવચન ઉપર આભાર પ્રસ્તાવ લઈને માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી આવ્યા છે તેને સમર્થન આપવા માટે ઊભો થયો છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જેટલી યોજનાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે બહાર પાડી છે એમાં આ કોંગ્રેસને સફળતા દેખાઈ નથી પણ માત્ર નિષ્ફળતા જ દેખાઈ છે અને નિષ્ફળતા ઉપર જ આરોપો મુકયા છે અને આ ગૃહનો કિંમતી સમય વેડફવા સિવાય કોઈ કામ કર્યુ નથી એવું મને સવારથી દેખાઈ રહ્યું છે.

શ્રી મુકેશ ભૈ. ગઢવી : એવા શબ્દો વાપરી શકાય નહીં.

શ્રી પુંજાભાઈ ભી. વંશ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રી એવું કહે કે સભ્યશ્રીઓ કિંમતી સમય વેડફી રહ્યા છે તે શબ્દો બરાબર નથી, કોઈપણ ધારાસભ્ય, પછી તે આ પક્ષના હોય કે પેલા પક્ષના હોય, તેઓ પોતાની વાત કરે તેને સમય વેડફી રહ્યા છે તેમ કહેવું વાજબી નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : એમણે શબ્દો પાછા ખેંચ્યા છે.

શ્રી ફતેસિંહ વ. ચૌહાણ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે મંત્ર છે, પંચામૃત શક્તિ છે, મારે જળ શક્તિ ઉપર બોલવું છે. ભાઈ બોલી રહ્યા હતા અમારા બળદેવજી, *(XXX) તો મારે યાદ દેવડાવવું છે કે અમારા પંચમહાલમાં.....

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ફતેસિંહ, આપણે ગૃહમાં બોલી રહયા છીએ, તે ધ્યાન રાખો. (XXX) એવું ન બોલાય. તે શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરું છું.

શ્રી ફતેસિંહ વ. ચૌહાણ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સુજલામ સુફલામ યોજનામાં અમારા શહેરા, કાલોલ, હાલોલ, જાંબુઘોડા કે ઘોઘંબા તાલુકાઓ હોય પંચમહાલ જિલ્લાની જનતાને પહેલીવાર એવું થયું છે કે અમે લોકશાહીમાં છીએ, આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે સુજલામ સુફલામ યોજના મારફત કડાણા હાઈ લેવલ યોજનાની નહેર હોય કે પાવાગઢની જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના હોય, માત્ર શહેરા તાલુકામાં ૧૬૫ કરોડની હાઈ લેવલ કેનાલની યોજના ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લાવી છે ત્યારે મારે કહેવું છે કે જળ શકિત યોજનામાં અમારા પંચમહાલ જિલ્લામાં હાલના તબક્કે ૨૪૯૧ ચેક ડેમો પૂર્ણ થયા છે, ૧૧૦૦ થી ૧૧૫૦ ચેકડેમોના કામો હાલમાં ચાલુ છે. અમારા પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રીએ દાહોદ જિલ્લામાં અનાસ નદી ઉપર બે ચેક ડેમોનું ખાત મૂહુર્ત કરેલ છે, આ યોજનાઓ મશ્કરી કરવા માટે મૂકી નથી. પણ ગરીબ જનતા, જેને આઝાદીથી આજ સુધી કોંગ્રેસના લોકોએ, દાહોદ અને પંચમહાલના મજૂર વર્ગને ફકત મજૂર તરીકે જ અપનાવેલા તે આ સરકારે નેસ્ત નાબૂદ કરવા માટે સ્થાનિક આદિવાસી જનતાને રોજગારી મળે તેના માટે ભગીરથ કાર્ય કરેલ છે તેનો ઉમદા દાખલો છે.

હમણાં જ શિક્ષણની વાત કરતા હતા. મારે પૂછવું છે કે શિક્ષણનું માત્ર લેબલ મારીને શિક્ષણ વધાર્યુ નથી. પણ કન્યા કેળવણી રથ માથે લઈ અને રાજ્યના મુખ્ય મંત્રીશ્રીથી માંડીને મંત્રીશ્રીઓ અને તમામ આઈ.એ.એસ. કેડરના અધિકારીઓ ગામડે ગામડે જઈ અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં આ કન્યા કેળવણીની ઝૂંબેશ આગળ વધારી છે તે ઐતિહાસિક કામ છે. એ કામ કોંગ્રેસના મગજમાં આવ્યું નહોતું. શિક્ષણ ક્ષેત્રે આ સમાજને પછાત રાખવાનું મોટામાં મોટું દૂષણ કોંગ્રેસે કર્યુ હતું. મારે પૂછવું છે કે તમે રાજ કર્યુ ત્યારે તમારા હસ્તક કેટલા આઈ.એ.એસ. અધિકારીઓ પેદા કર્યા હતા આ ગુજરાતમાંથી? એક પણ નહીં, તમને સૌને ખ્યાલ નહોતો.....

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ફતેસિંહભાઈ, તમે વિષય ઉપર આવો, પ્લીઝ.

શ્રી ફતેસિંહ વ. ચૌહાણ : સાહેબ હું વિષય ઉપર જ બોલું છું. હું શિક્ષણ ઉપર બોલું છું. શિક્ષણના ક્ષેત્રે માનનીય સભ્યશ્રી પરેશભાઈ ધાનાણી બોલી રહ્યા હતા ત્યારે મારે એમને ખૂબ કહેવું છે, કે અમારા એક પણ

---

* (XXXXX) આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે.

મંત્રીની સામે ભ્રષ્ટાચારના આરોપો હોય તો દાખલો તમે આપો. સુદ્રઢ વહીવટનો દાખલો છે. પણ રાજ્યના મંત્રી મંડળની સામે કોઈપણ મંત્રીશ્રીની સામે આક્ષેપ હોય કે પૂરાવા હોય તો રજૂ કરે. મારે કહેવું છે કે રાજયમાં અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના વહીવટમાં કોઈ ચમરબંધીને પણ અમે જેલમાં મોકલતા અચકાયા નથી. કોઈની શેહ શરમ રાખી નથી અને રાજયના મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ કોઈની ભલામણ કર્યા વગર આવા ચમરબંધીઓ જેલની હવા ખાઈ રહ્યા છુ, મારે કહેવું છે કે ગુજરાતમાં ગુનાખોરી અને કેસો વધ્યા છે એમ સ્વીકારીએ, પણ કોંગ્રેસના રાજયમાં ગુજરાતના રાજકીય નેતાઓના ઘરમાં વાસો રહ્યા હોય તેવા કેસો થાય તે કેટેગરી અહીં નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આજે કોઈ જાહેર ક્ષેત્રમાં હોય કે સરકારી કે સહકારી ક્ષેત્રમાં હોય ગમે તે ગુનેગારને જેલમાં મોકલવાનું કામ કર્યુ છે. અને તેના કેસો નોંધાયા છે. ગુનાખોરી વધી નથી, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજયમાં આ સત્ય કેસો થયા છે તેનો દાખલો છે.આદિવાસી વિસ્તારની અંદર દાહોદ જિલ્લો હોય કે પંચમહાલ જિલ્લો હોય એમાં એક પણ કોંગ્રેસનો સભ્ય ચૂંટાયો નથી. કોંગ્રેસે એકલું જંગલ લૂંટવાનું અને આદિવાસીભાઈઓને મજૂરી કરાવા સિવાય કાંઈ કર્યુ નથી એનો ઉત્તમ નમૂનો પૂર્વપટ્ટીમાં વલસાડથી લઈને સાબરકાંઠા સુધી આદિવાસી પટ્ટી છે એની અંદર જેટલા પણ જંગલો હતા...

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ફતેસિંહભાઈ, આપનું પ્રવચન પુરુ થાય છે. માનનીય લક્ષ્મણભાઈ...

શ્રીલક્ષ્મણભાઈ બા. પટેલ(પારડી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મહામહીમ્ રાજયપાલશ્રીના સંબોધન પર માનનીય સભ્યશ્રી શંકરભાઈ આભાર પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે ત્યારે આ ગૃહની અંદર હું મારા વિચારો દર્શાવવા ઉપસ્થિત થયો છું. અહીં રાજયપાલશ્રીના સંબોધનની અંદર કામદારો, માછીમારો અને આદિવાસીઓ ઉપર જે વિશેષ ધ્યાન અપાવવું જોઈતું હતું એ અપાયું નથી એની ચિંતા કરવામાં આવી નથી. તેથી હું માનનીય રાજયપાલશ્રીના પ્રવચનને સમર્થન આપી શકતો નથી. રામ રાજયની વાત આ ગૃહની અંદર ઘણી થઈ છે ત્યારે હું થોડી માનવતાની વાત તરફ જઈશ. નર્મદાની ઘણી બધી વાતો કરવામાં આવી છે. જાણે કોંગ્રેસે કશું કર્યુ જ નથી એમ કહેવામાં આવે છે તેમ છતાં હું આનંદની લાગણી અનુભવુ છું. તે સાથે થોડું કહેવાનું મન થાય છે કે દમણગંગા યોજના જે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર અને ખાસ કરીને વલસાડ જિલ્લાની જીવાદોરી છે જે કોંગ્રેસના રાજની અંદર પૂર્ણ થઈ હતી. મને કહેતાં દુઃખ થાય છે કે આ દમણગંગા યોજના કોંગ્રેસના રાજમાં થયેલ અને અત્યારે ભાજપના રાજની અંદર જે લીકેઝનું પ્રમાણ છે એ લીકેઝ બંધ કરી શકતા નથી એનું મને દુઃખ છે. અત્યારે જ્યાં જોઈએ ત્યાં લીકેઝનું પ્રમાણ એટલું બધું છે કે ખેડૂતોનો ઊભો પાક બગડી ગયો છે. અમારે ત્યાં હાફુસનાં ઝાડો ખૂબ જ છે જે વલસાડનો રાજા કહેવાય છે. અમારી હાફુસની ખેતી આજે ખલાસ થઈ ગઈ છે. મારે માનવતાની દૃષ્ટિએ બીજું પણ કહેવું છે.

ઉદ્યોગો આજે બંધ પડી રહ્યા છે. તેના લીધે કામદારો બેકાર થઈ રહ્યા છે રાજય સરકારને એની જરા પણ ચિંતા કે ફિકર નથી. કામદારો બેકાર થઈ રહ્યા છે, કારખાનાં બંધ થઈ રહ્યા છે. આ ગૃહની અંદર જ્યારે ચર્ચા થાય છે ત્યારે સામે પાંચ કરોડની જનતાનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. કદાચ આ પાંચ કરોડની જનતાને ભૂલી જઈશું તો તે દિવસે આપણી શું અવદશા થશે એ વિચારવા જેવું છે. સામાન્ય રીતે કામદારો કારખાનાની અંદર કામ કરતા હોય ત્યારે અચાનક ફૅકટરીઓ બંધ કરવામાં આવે છે. સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો છે કે રાજય સરકારની પૂર્વ મંજૂરી વગર એક પણ ફૅકટરી બંધ કરી શકાતી નથી. તેમ છતાં કેટલીક ફૅકટરીઓ હાલ રાજય સરકારની પૂર્વ મંજૂરી લીધા વગર બંધ કરી દીધેલ છે. તેના લીધે કામદારો બેકાર થઈ રહ્યા છે. આ ખૂબ ગંભીર બાબત છે. હું નામ સાથે કહેવા માગુ છું. સાઈનામાઈડ કંપની છે એણે બે-ત્રણ નામો બદલ્યા છે એ પછી એગ્રીમોર કંપનીનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. પંદર દિવસ પહેલા જ એને લોખંડી તાળાં લાગી ગયાં છે. ૨૦૦ કારીગરો, તેના ઉપર નિર્ભર ૧૦૦૦ જેટલા લોકો આજે બેકાર બની ગયા છે. ભૂખે-તરસે છે. તેની આ સરકારે ચિંતા કરવાની જરૂર છે. જો કદાચ આ સરકાર આ ન કરે તો કદાચ અમારે અતુલ કંપનીમાં, એગ્રીમોર કંપનીમાં જવાની અમારે ફરજ પડશે.

માછીમાર ભાઈઓની વાત કરું, અમારા માછીમાર ભાઈઓની કોઈ દિવસ કોઈએ ચિંતા કરી નથી. અમારા માછીમાર ભાઈઓ માટે કોઈ દિવસ કોઈએ ચિંતા કરી નથી. બૉમ્બે જઈને અમારા માછીમાર ભાઈઓ માર ખાય છે. આ સરકારે તેની ચિંતા કરી નથી તેનું અમને અતિ દુઃખ છે.

શ્રી શંકરભાઈ વી. રાઠવા(છોટાઉદેપુર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મહામહિમ્ રાજયપાલશ્રીના સંબોધન ઉપર આભાર પ્રસ્તાવ લઈને માનનીય શંકરભાઈ ચૌધરી આવ્યા છે ત્યારે મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે ઊભો થયો છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયપાલશ્રીનું સંબોધન આપણે સાંભળ્યું હોય તો તેમના દરેક શબ્દ ઉપર અને દરેક વાક્ય ઉપર આ ગુજરાતની ગૌરવની ગાથા ગવાતી હતી. એ ગુજરાતની ગૌરવગાથા હોય અને ગુજરાતની અસ્મિતાની વાત હોય, ગુજરાતને વિકાસના પંથે લઈ જવાની વાત હોય, તેની કેડી કંડારવાની વાત હોય ત્યારે સાથી મિત્રોને તેમનું સંભાષણ ન ગમે એ બરાબર નથી. આ સભાગૃહમાં આ રાજયના વિકાસ માટે, તેના ઉત્થાન માટે માનનીય રાજયપાલશ્રી, ગુજરાત રાજયના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પંચામૃત યોજના લઈને આ રાજયને વિકાસના પંથે લઈ જવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય ત્યારે સાથી મિત્રો અમદાવાદથી ગાંધીનગરના ગૃહ સુધી ટ્રૅક્ટરમાં બેસીને આવે અને આવીને ભારતીય સંસ્કૃતિ આપણને બતાવે

છે, આપણી ગળથૂથીમાં છે કે કોઈ દેવસ્થાન હોય, દેવસ્થાનની આગળ જતાં સ્વાભાવિક રીતે આપણે નતમસ્તક બની જઈએ અને શ્રદ્ધાથી આપણે નમન કરીએ. આ સભાગૃહ પણ સન્માનનીય ગૃહ છે અને સન્માનનીય ગૃહની અંદર પ્રવેશવા માટે સાંકળ તોડીને આવે, અંદરની વ્યવસ્થાના સાધનો ઉપર તોડ-ફોડ કરવામાં આવે, તેના ઉપર પગથી લાત મારવામાં આવે એ કેટલા અંશે વાજબી છે? આવું જો આ સભાગૃહના સભ્યો કરતા હોય તો એ બરાબર નથી.

મારે એક વાત કહેવી છે. મારા પૂર્વપટ્ટીના આદિવાસી વિસ્તારમાં શિક્ષણ માટે સારો પ્રયત્ન થયો છે. કોઈ પણ રાજયનો વિકાસ કરવો હોય, કોઈ તાલુકા કે જિલ્લાનો વિકાસ કરવો હોય, કોઈ કુટુંબનો વિકાસ કરવો હોય તો તેના પાયામાં શિક્ષણ છે. શિક્ષણની જે વાત છે એ વાતને લઈને આ ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રી અને શિક્ષણમંત્રીશ્રીએ નક્કી કર્યું કે પૂર્વ પટ્ટીના આદિવાસી વિસ્તારમાં કન્યા કેળવણી કયાં ઓછી છે તેનો સરવે કરવામાં આવ્યો. તેની શરૂઆત કરી પૂર્વપટ્ટીનો છેવાડાનો નવો તાલુકો કવાંટ તાલુકો. કવાંટ તાલુકામાં કન્યા કેળવણી માટે પ્રવેશોત્સવ માટે કન્યા કેળવણીનો રથ લઈને આ રાજયના શિક્ષણ મંત્રી માનનીય આનંદીબેન પટેલે ત્રણ-ત્રણ દિવસ સુધી કવાંટ તાલુકાના ઊંડાણના ગામડાંમાં પ્રવાસ કર્યો અને બળબળતા બપોરે મને યાદ છે કે કંઈ લીધું નહીં, માત્ર એક રોટલી અને પાકેલી કેરીની ચીરી માત્ર લીધી અને કામે લાગી ગયા. આ કામ કરવાનું હતું. આજે ગુજરાત રાજયમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ૮૦,૪૭૭ વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી અને એના માટે વાંચન, ગણન અને નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રિ-વર્ગ કરવામાં આવ્યા છે અને એના માટે સતત શિક્ષણના કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. રમત-ગમતના સાધનો, પ્રયોગશાળાઓ, શિક્ષકદીઠ ઓરડાઓ આપવામાં આવ્યા છે અને દરેક જગ્યાએ આ માટે ઉત્સવો ઉજવવામાં આવ્યા અને તે વખતે આપણે એમ કહીએ કે, ગુજરાત રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓની અંદર સાથી મિત્રો એમ કહેતા હતા કે, બ્લેક બોર્ડ પણ નથી, એ તો ભૂતકાળની વાત હતી. એમના જમાનામાં પ્રાથમિક શાળાઓના ઓરડાઓ જ નહોતા તો પછી બ્લેક બોર્ડ કયાંથી હોય?

સભાગૃહની બીજી બેઠકનું કામકાજ સાંજના- ૭-૨૧ વાગ્યે પુંરું થતાં અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર સભાગૃહ તા.૨૩મી ફેબ્રુઆરી,૨૦૦૫ના રોજ બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે ફરી મળવા મુલતવી રહયું.

	વિષય	પાના નંબર
અંબાલાલ આ.રોહિત	અમદાવાદ શહેરના વિસ્તારની આંગણવાડીઓ	૧૯૪
	ગરુડેશ્વર વિયરના બાંધકામ બાબત	૧૫૬
	રાજયમાં રકતપિત્તના કેસો	૩૬૪
	રીવર બેડ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન બાબત	૯૭
	સરદાર સરોવર યોજના વિદ્યુત મથકની ક્ષમતા	૧૩૬
અતુલ કે. પટેલ	કલોલ શહેરમાં રેલ્વે ઉપર ઓવરબ્રીજ બનાવવા બાબત	૩૬૯
	ખેતરોમાં નિલગાય/રોઝ જેવા પશુઓથી ઉભા પાકને નુક	૩૯૭
	પેરાપ્લેજીયા ઇન્સ્ટીટયુટમાં એન.જી.ઓ.ના સહયોગથી પ્રો	૪૧૫
	ફોરેન્સીક લેબોરેટરી દ્વારા ન્યાયાધીશો અને એડવોકેટો મ	૧૫૪
	ફોરેન્સીક લેબોરેટરીની આધુનિકરણની યોજના	૧૨૯
	મહેસાણા જિલ્લામાં જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ લાભાન્વિત	૯૨
અનિલ જોષીયારા	ભિલોડા તાલુકાની શાળાઓ ખાનગી સંસ્થાને આપવા અં	૨૪૧
	ભિલોડા, વિજયનગર, મેઘરજ અને ખેડબ્રહમા તાલુકાઓ	૨૧૪
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૮
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચ	૩૨૭
	સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં જી.આઈ.ડી.સી.ન	૧૦૩
	સાબરકાંઠા જિલ્લાના સ્ટેટ અને પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઅ	૩૫૫
	સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ખૂન, લૂંટ અને દારૂના કેસો	૧૩૯
	સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભિલોડા તાલુકામાં આદિવાસી ગામં	૧૫૯
અનિલકુમાર મો.પટેલ	બારડોલી તથા માંડવીપોલીસ સ્ટેશનમાં મંજૂર અને ખાલી	૧૦૩
	માંડવી તાલુકાના બોધાનથી વરેલીને જોડતા રસ્તા ઉપર	૩૭૮
	માંડવી તાલુકાના બૌધાનથી ગલતેશ્વરને જોડતો તાપી ન	૩૪૧
	સુરત જિલ્લામાં માટી ચોરીની ફરિયાદ	૧૪૦
	સુરત જીલ્લાના માંડવી તાલુકાના કોસાડીથી પીપરીયા વરેલીને જોડતો બિસ્માર રસ્તો	૪૦૪
અમિત અ. શાહ	પાટણ તાલુકાના સાંપ્રા ગામે યુવાન ખેડૂતોના ખૂન અંગે	૪૨૩
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૫
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૭
અમિત ચાવડા	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૯
અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૫

	વિષય	પાના નંબર
અર્જુનભાઇ દે. મોઢવાડીયા	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૧૦
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૩૯
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૨૬૧
અશોક ભટ્ટ	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૨૫
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૧
	સભાગૃહની બેઠક મુલતવી રાખવા અંગેનો પ્રસ્તાવ	૫૦
ઇન્દ્રવિજયસિંહ કિ.જાડેજા	ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)(સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૬૮
	ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)(સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૦
	જોબનંબરની રકમમાં વધારો કરવા અંગે	૨૯૧
	ધાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનું) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૯૪
	ધાંગધ્રા નગરપાલિકા (કર નાખવાની બાબત) (કાયદેસર ઠરાવવા અંગેનું) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૯૪
ઇશ્વરભાઇ ધ. મકવાણા	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૩૮
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૬
ઉપેન્દ્રસિંહજી પ્ર.ગોહિલ	વચ્છેસર-કલ્યાણ માર્ગને રાજ્ય હસ્તક કરવા બાબત	૩૭૮
	વડોદરા જિલ્લાની માધ્યમિક શાળાઓ ખાનગી ટ્રસ્ટોને સોંપવા અંગે	૨૫૭
	સમલાયા-ગાંયડિયા- ચાંપાનેર રસ્તો ડામરની સપાટીવાળો બનાવવા બાબત	૩૪૦
	સરદાર સરોવરના પાણીથી સાવલી તાલુકાના ગામોને સિંચાઇનો લાભ	૧૩૪
	સાવલી તાલુકામાં શાળાના ઓરડાઓની ઘટ	૨૧૧
	સાવલી તાલુકામાં શિક્ષકોની ખાલી જગાઓ	૨૪૧
	સાવલી તાલુકામાંથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલ દ્વારા તળાવ ભરવા અંગે	૯૬
કનુભાઇ કળસરિયા	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૩૫

	વિષય	પાના નંબર
કાંતિભાઇ ત્રિ.ભીલ	નવી ઔદ્યોગિક નીતિ અન્વયે લીધેલાં પગલાં	૧૪૧
	ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરીદ્વારા ન્યાયાધીશો અને એડવોકેટો માટેનો તાલીમકોર્ષ	૧૦૪
	મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના વિકાસ નકશાઓ	૩૪૫
કાંતિભાઇ ભા. તડવી	ગુડા વિસ્તારમાં નગર રચનાનું આયોજન	૩૯૬
	જીસ્વાન દ્વારા જોડાયેલી કચેરીઓ	૧૫૩
	ધોળકા વિસ્તારમાં તેલ ભંડારો મળી આવવા અંગે	૧૨૪
	રાજ્યમાં મહેસૂલી ગામોને પાકા રસ્તાથી જોડવા બાબત	૩૬૭
	લિગ્નાઈટ આધારિત પાવર પ્રોજેકટ અંગે લીધેલાં પગલાં	૮૭
કાંતિલાલ ધ.કચોરિયા	ઉનાવા ખાતે મીરાંદાતરમાં હિન્દુ યુવતીઓને ધર્માંતરણ કરાવવા અંગે ફરિયાદ	૧૦૫
	ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમીટ ૨૦૦૫માં થયેલ એમ.ઓ.યુ.	૧૪૩
	પાલનપુરની નાયબ વન સંરક્ષકની કચેરીનું મકાન બદલવા બાબત	૩૭૯
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અકસ્માતના પડતર કેસ	૨૦૩
	વન વિભાગ હસ્તકની જમીનમાં રસ્તા બનાવવા બાબત	૩૪૫
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૩
કાંતિલાલ રા. લકુમ	ધોળકા તાલુકાના ગામોમાંથી ઢોરોની ચોરી થવાના બનાવો	૧૩૯
	ધોળકા વિસ્તારમાં રાત્રીના સમયે વાયર ચોરીના બનાવો	૧૫૯
	ધોળકા, બાવળા અને સાણંદ તાલુકાની શાળાઓમાં વીમા સહાય	૨૧૮
	બાવળા તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનના બાંધકામની મંજૂરી	૩૫૨
	બાવળા તાલુકામાં આયુર્વેદીક દવાખાના	૩૮૪

	વિષય	પાના નંબર
કાંતિલાલ રા. લકુમ	મધ્યસ્થ જેલમાં ઈલેક્ટ્રોનિકવીડિયો લીકેજ સીસ્ટમથી આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા અંગે	૧૦૩
	રાજ્યમાં નવા આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજુર કરવા બાબત	૪૦૮
કાળુભાઇ વી. વીરાણી	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૦
કાળુભાઇ હી. માલીવાડ	ખાનપુર તાલુકામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મૅડિકલ ઑફિસરની ખાલી જગ્યા	૩૪૦
	પંચમહાલ જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં ટ્રેઝરી કચેરી શરૂ કરવા બાબત	૨૧૨
	રાજયના બંદરોની કાર્ગોની હેરફેરની ક્ષમતા	૫૨
	રાજ્યના મહત્વના બંદરોને રેલ માર્ગે જોડવા આયોજન	૩૭૭
કુંવરજીભાઈ મો. બાવળિયા	ઉપલેટા તાલુકાના ખીરસરા ગામે પોલીસ અને લોકો વચ્ચે અથડામણ	૧૧૧
	જસદણ તાલુકાના મોટા હડમતીયા ગામે ભાદર નદી પરનો પુલ બનાવવા બાબત	૪૧૧
	નવરાત્રી અને પતંગ મહોત્સવ દરમ્યાન એમ.ઓ.યુ. થયેલા ઉધોગોના કામ	૧૪૭
	બોગસ પ્રમાણપત્રોને આધારે શિક્ષકોની નિમણુંક	૨૧૧
	રાજકોટ જિલ્લામાં ડીપ્થેરીયાને કારણે બાળકોના થયેલ મૃત્યુ	૩૫૫
	રાજકોટ જિલ્લામાં સરકારી હોસ્પિટલમાં અગત્યના તબીબી મશીનોનો અભાવ	૩૮૭
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૨૪
	લાંચ રૂશ્વત અંગે પોલીસ અધિકારીઓને પકડવા અંગે	૧૬૧
	સેલ્ફ ફાઈનાન્સ શાળાઓની તપાસણી અને પગલાં	૨૪૧
કૌશિકભાઈ જ. પટેલ	ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૬૬
	ભારત સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક ૨૦૦૫	૨૭૩

	વિષય	પાના નંબર
કૌશિકભાઈ જ. પટેલ	મુંબઈ માપબંધી સંબંધી (તૈયારી અને તે ચાલુ રાખવા બાબતના) ઉપાય બાબતનું (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક,૨૦૦૫.	૨૭૨
	મુંબઈનું વજન અને માપ (અમલ) (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૬૭
ગણપતભાઈ વે.વસાવા	માંગરોળ ઉમરપાડા તાલુકામાં કૉલેજ શરૂ કરવા અંગે	૧૯૯
ગોપાલભાઈ ગા. ઘુઆ	કચ્છ જિલ્લામાં ગુમ થયેલ કે ખોવાયેલ ગયેલ વ્યકિતઓ	૧૨૮
	કચ્છ જિલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ભરતી અને ઘટ	૨૨૮
	કચ્છ જિલ્લામાં મંજૂર કરવામાં આવેલ માર્ગો બાબત	૩૫૪
	કચ્છ જિલ્લામાં રોપા ઉછેરવા બાબત	૪૧૦
	કચ્છ જિલ્લામાં વિધવા, અને નિરાધારોના સહાયના પડતર કેસ	૨૦૧
	કચ્છ જિલ્લામાં વીજળીની જરૂરિયાત	૯૧
	કચ્છ જિલ્લામાં વેચાણવેરાની બાકી રકમ	૨૫૧
	કચ્છ જિલ્લામાં સામાજિક વનીકરણ યોજના હેઠળ કિસાન નર્સરીઓ	૩૮૫
	નર્મદા કચ્છ શાખા નહેરનું કામ	૧૫૪
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૫
ગોરઘનભાઈ પ્રા.ઝડફિયા	ડીગ્રી ઈજનેરી કોલેજોમાં ભરાયેલ સીટોની સંખ્યા	૨૦૩
	નર્મદા યોજના બંધની ૧૧૦ મીટરની ઊંચાઈથી સરફેસ ઈરીગેશનમાં વધારો થવા બાબત	૮૧
	પવિત્ર યાત્રાધામોમાં દારૂ-ઈંડા- માંસ-મરઘીના વેચાણનો પ્રતિબંધ	૨૩૩
	વિજપડીથી સાતપડા-લુવાર રસ્તાનું લાંબા સમયથી અધુરુ રહેલ કામ	૩૬૪
ગોવાભાઇ હ. રબારી	એપેરલ પાર્કનું ઉદ્‌ઘાટન	૧૫૭
	ઓકટોબર--૦૩ નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન થયેલા મુડી રોકાણના પ્રોજેક્ટોની કાર્યવાહી	૯૮
	ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૬૬

	વિષય	પાના નંબર
ગોવાભાઇ હ. રબારી	છોટાઉદેપુર તાલુકામાં ફેલાયેલ ભેદી રોગચાળો	૪૦૬
	નાણાપંચ દ્વારા રાજય સરકારને ફાળવેલ રકમ	૧૮૭
	માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શાળાઓને મોકલેલ પ્રોગ્રામમાં ભૂલો	૨૨૫
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૬
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૩૬
	વીજ ખાધ ઘટાડવા કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળેલી સહાય	૧૩૬
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૬
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૨૬૧
	સ્વનિર્ભર મેડિકલ કોલેજોના સંચાલકો દ્વારા પ્રવેશ પરીક્ષા	૩૪૮
	સ્વનિર્ભર મેડીકલ કોલેજોનાં સંચાલકો સામે ગેરકાનુની એડમીશન બાબતે પગલાં	૩૮૧
ગોવિંદભાઈ વ.પરમાર	જુનાગઢ જિલ્લાની સિવિલ કોર્ટમાં અકસ્માત અંગેના નિકાલ વગરના પડતર કેસ	૨૦૬
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વિધવા મહિલા સહાયના પડતર કેસ	૨૫૬
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે આશ્રિતોને રહેમરાહે નોકરીની અરજીઓ	૨૩૫
	તલાલા, સુત્રાપાડા અને વેરાવળ તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથમિકઆરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ડોકટર, નર્સની ખાલી જગ્યા	૩૭૪
	ફાયરીંગના બનાવમાં વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશનમાં અધૂરી તપાસ સામે પગલાં લેવા અંગે	૮૫
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૩
	વેરાવળ તાલુકામાં પ્રભાસ પાટણ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું મકાન જર્જરીત હાલતમાં	૪૨૨
	વેરાવળની મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલ સરકાર હસ્તક લેવા બાબત	૪૦૨

	વિષય	પાના નંબર
ચંદ્રિકાબેન કા.ચુડાસમા	ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)(સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૬૮
	નર્મદા યોજના બંધની ઉંચાઇનું કામ	૧૬૦
	પતંગ મહોત્સવ પાછળ થયેલ ખર્ચ	૧૪૦
	ભારત સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક ૨૦૦૫	૨૭૪
	મહિલા આયોગની રચના થયા બાદ મળેલ મિટિંગો	૧૯૨
	માંગરોળ અને શીલ પોલીસ સ્ટેશન નીચે બનેલા ખૂનના ગુનાઓ	૧૦૩
	માંગરોળ તાલુકાનો ઘોડાદર- મંડેર ચિગોરીયા રસ્તો બિસમાર હોવા બાબત	૩૩૪
	મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.	૨૯૨
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૩૩
	રાજયમાં રૂા. ૧ કરોડથી વધુ વેચાણવેરાની બાકી રકમ	૨૫૧
	સિમેન્ટ કંપનીઓ પાસે વેચાણવેરા પેટે વસૂલ લેવાની બાકી રકમ	૨૨૯
છનાભાઇ કો.ચૌધરી	ધરમપુર તાલુકામાં ખૂન, લૂંટ અને આત્મહત્યાના ગુનાઓ	૧૪૨
	ધરમપુર તાલુકામાં વડાપ્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના હેઠળ મળેલી અરજીઓ	૧૦૫
	વાંસદા તાલુકામાં શિક્ષકોની ઘટ	૨૧૭
છબીલદાસ ના. પટેલ	કચ્છ જિલ્લામાં પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની ઘટ	૧૮૮
	દવાઓની કંપનીઓને કાળી યાદીમાં મુકવા બાબત	૩૯૬
	મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર સામે વીજીલન્સમાં થયેલ ફરિયાદ	૩૬૭
	રાજ્યમાં ગેસીફાયર વીજ મથકો	૯૨
છોટુભાઈ અ.વસાવા	ઝઘડીયા અને વાલીઆ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોના આવાસમાં ન રહેતા કર્મચારીઓ	૩૯૫
	ઝઘડીયા અને વાલીયા તાલુકામાં રસ્તાની આજુબાજુમાં નડતા વૃક્ષો દૂર કરવા બાબત	૩૬૬

	વિષય	પાના નંબર
છોટુભાઈ અ.વસાવા	ટ્રાયબલ વિસ્તારમાં કર્મચારીઓને ટ્રાયબલ એલાઉન્સ આપવા અંગે	૨૦૦
	ભરૂચ જિલ્લામાં બોગસ પ્રમાણપત્રોને આધારે નોકરી કરતા શિક્ષકો	૨૨૫
જગદીશ ઠાકોર	ગાંધીનગર જિલ્લાનાં ગામો અને પેટા પરાઓનું બાકી વિજળીકરણ	૧૨૩
	ગાંધીનગર જિલ્લાની શાળાઓમાં ગેરરીતિ અને અનિયમિતતાઓ	૨૩૧
	ગાંધીનગર જિલ્લાની હોસ્પિટલોને ઓરેટ પ્રોગ્રામ નીચે મળેલ અદ્યતન સાધનો	૪૧૬
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં વિવિધ ગુનાઓ	૮૪
	ગાંધીનગર જિલ્લામાંડી.પી.ઈ.પી.યોજના હેઠળ નવા રૂમો સીમ શાળાઓના રીપેરીંગ અંગે	૧૯૭
	ગાંધીનગર તાલુકામાં આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ	૩૭૧
	ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોકટર અને નર્સની ખાલી જગ્યા	૩૯૯
	દહેગામ તાલુકાની માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ	૨૫૨
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૯
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૨
	વાહનવ્યવહારના નિયમોના અમલના અભાવે અકસ્માતો થવા અંગે	૧૫૧
જયંતિલાલ રા.કવાડિયા	એન્જીનીયરીંગ, બી.એડ. પી.ટી.સી. કોલેજોની સીટોમાં કરેલ વધારો	૨૪૪
	મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના વિકાસ નકશા	૪૦૭
	રાજ્યના રસ્તાઓને રાષ્ટ્રીય હાઈવેમાં બદલવાની દરખાસ્તો	૩૫૦
	રાજ્યમાંથી આતંકવાદીઓ પકડવા અંગે	૧૩૩
	વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં થયેલ ઘટાડો	૨૧૮
	હળવદ, ધાંગધ્રા અને દસાડા તાલુકામાં ખેડૂતોના પાકને ખચ્ચર ગધેડા દ્વારા નુકશાન	૩૮૩

	વિષય	પાના નંબર
જયદ્રથસિંહજી ચં.પરમાર	પંચમહાલ જિલ્લામાં પાકા ડામરના રસ્તા બનાવવા બાબત	૩૩૮
	હાલોલ તાલુકામાં આવેલી શિવરાજપુર માઈન્સ ચાલુ કરવા બાબત	૮૪
જસુબેન સ.કોરાટ	જેતપુર અને ગોંડલ તાલુકામાં દહેજને કારણે સ્ત્રીઓને આપઘાતની ફરજ અને મૃત્યુ	૯૧
	જેતપુર અને ગોંડલ તાલુકામાં બિસ્માર અને ભયજનક પુલ અને નાળા	૩૮૫
	જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકાની રમત-ગમતના મેદાનોથી વંચિત શાળાઓ	૨૨૬
	જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં એફ.આઈ.આર. નહીં નોંધવા અંગે	૧૨૯
	જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં સાક્ષરતા અભિયાન	૨૫૦
	જેતપુર તથા ગોંડલ તાલુકામાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ વગરની શાળાઓ	૧૮૯
	રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર અને ગોંડલ શહેરમાં ગેરકાનુની કતલખાનાં બંધ કરવા બાબતે	૩૫૪
	રાજ્યમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું ઓછું પ્રમાણ	૪૦૯
	વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૦૫ અન્વયે રાજકોટ જિલ્લા માટે થયેલા એમ.ઓ.યુ.	૧૫૪
જીતુભાઇ હ. ચૌધરી	વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં ગ્રામીણ વીજળીકરણ યોજનાનો લાભ	૫૩
	વલસાડ જિલ્લામાં ખૂન, લૂંટ અને આત્મહત્યાના બનાવો	૧૧૮
	વલસાડ જિલ્લામાં બંધ પડેલા ઉધોગો	૧૪૯
જીતેન્દ્રકુમાર ઉ.વાઘેલા	અમદાવાદ શહેરને મેગાસીટી જાહેર કરવા બાબત	૩૪૯
	અમદાવાદ શહેરમાં અનુસૂચિત જાતિના લોકો ઉપર અત્યાચારના બનાવો	૧૪૨
	અમદાવાદ શહેરમાં એપરલ પાર્ક બનાવવાની યોજના	૧૬૦

	વિષય	પાના નંબર
જીતેન્દ્રકુમાર ઉ.વાઘેલા	અમદાવાદ શહેરમાં જી.એસ.ટી.સી. હેઠળની બંધ મીલો અને કામદારોને ચૂકવાયેલ નાણા અંગે	૧૦૫
	રાજ્યમાં આવેલી ચક્ષુ બેંકો	૩૮૨
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૮
જીતેન્દ્રભાઈ બા.પટેલ	અમદાવાદ શહેરમાં અપમૃત્યુ, ચોરી, લૂંટ અને છેતરપીંડીના બનાવો	૧૫૭
	અમદાવાદ શહેરમાં પી.આઇ.ની અને પોલીસ કર્મચારીઓની ખાલી જગ્યાઓ	૧૩૭
	અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં સલાહકાર સમિતિની રચના અને મુદત	૧૦૦
	અમદાવાદ શહેરમાં બ્લડ બેંકોનાં રકતદાન શિબિર યોજવા બાબત	૩૮૯
	અમદાવાદ શહેરમાં શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઝૂંપડપટ્ટીના વિકાસ માટે આયોજન	૩૬૦
	રાજ્યની ખાનગી શાળા/કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લેવાતી વધારે ફી	૨૨૪
જેઠાભાઈ ઘે.ભરવાડ	શહેરા અને લુણાવાડા તાલુકામાં પેન્શનરોના પડતર કેસો	૨૨૨
જેસાભાઈ ભા. બારડ	ઘોઘા તાલુકાના ગામ તગડીથી ભાવનગર તાલુકાના માલણકા ગામ સુધીનો રસ્તો રીપેર કરવા બાબત	૩૮૦
	જુનાગઢ જિલ્લામાં તત્કાળ વીજ જોડાણ યોજના હેઠળ આવેલી અરજીઓ	૧૧૯
	નવરચિત તાલુકાઓમાં જુનિયર ડીવીઝન કોર્ટ શરૂ કરવા અંગે	૨૪૬
	માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કન્યા શાળાઓને મંજૂરી	૨૫૯
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૧૯
	વેરાવળ અને સુત્રાપાડા તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ	૪૦૫
	વેરાવળ શહેરમાં કોમી રમખાણ બાબત	૮૨
	વેરાવળ, સુત્રાપાડા અને માળીયા હાટીના તાલુકામાં પંચાયત હસ્તકના રસ્તા મંજૂર થવા બાબત	૩૪૮

	વિષય	પાના નંબર
જેસાભાઈ ભા. બારડ	સિમેન્ટ કંપની પાસેથી વેચાણવેરાની બાકી વસુલાત	૨૧૯
જ્યંતિલાલ રા.કવાડિયા	નવલખી બંદરને કુદરતી હોનારતો દરમ્યાન થયેલ નુકસાન	૧૫૫
	હીરા ઉદ્યોગને ધબકતો કરવાનું આયોજન	૯૫
ટપુભાઇ લીંબાસિયા	ગુજરાતનું પ્રેત ભોજન (નિયંત્રણ) (રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૬૬
	રાજકોટ જેલની ક્ષમતા અને કેદીઓની સંખ્યા	૯૩
	રાજકોટ શહેરમાં વિવિધ ગુનાઓ	૧૫૪
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૨૬
	રાજ્યમાં મોલાસીસનું ઉત્પાદન અને નિકાસ	૧૩૧
દિનેશ પરમાર	જામનગરની જી. જી. હોસ્પિટલ, જામનગરમાં ગાયનેકોલોજી વિભાગમાં બાળક બદલાઈ જવા બાબત	૩૫૯
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૪
દિપસિંહ શં.રાઠોડ	અમદાવાદ શહેરમાં સી..એન.જી.ના સ્ટેશનો	૧૧૭
દિપસિંહ શં.રાઠોડ	રાજ્યમાં પાઈપલાઈન મારફતે ગેસ પૂરો પાડવા સંબંધમાં પગલાં બાબત	૮૦
દિલુભા ટે. ચુડાસમા	પગાર વિસંગતતા સમિતિના અહેવાલ પર કરાયેલ નિર્ણય	૨૦૬
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૨૩
	વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ ગામોનો સમાવેશ	૧૩૨
	વડોદરા જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાના કામો	૩૫૨
	વડોદરા જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર હસ્તકનાં દેવસ્થાનો	૨૩૫
	વડોદરા શહેરની જૂના વિસ્તારોની ટી.પી. સ્કીમ	૩૮૪
	વડોદરા શહેરમાં ગૃહનિર્માણ માટે સંપાદિત કરેલ જમીન	૪૦૮
	વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૦૫માં થયેલા એમ. ઓ. યુ.	૯૫

	વિષય	પાના નંબર
દોલતભાઇ પરમાર	અનામતની ટકાવારી મુજબ વિદ્યાસહાયકોની બાકી નિમણુંક અંગે	૨૪૯
	અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અનામતની બાકી જગાઓની નિમણુંકની માધ્યમિક શાળાઓ	૨૦૧
	અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલના મડદાઘરમાંથી માનવ અંગોની ચોરી	૩૭૪
	ખાસ મરામત કાર્યક્રમ નીચે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રસ્તાઓની મરામત	૪૨૧
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એટ્રોસીટીના કેસો અંગે	૧૦૬
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક સુવિધાવાળી પ્રાથમિક શાળાઓ	૨૨૫
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિવિધ ગુનાઓ	૧૪૪
	રાજ્યમાં ઘટતો જતો વન વિસ્તાર	૪૦૧
દોલતરાય ના. દેસાઈ	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૩૨
ધનરાજભાઇ કેલા	નેશનલ સ્લમ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેકટ હેઠળ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની નગરપાલિકાઓને આપેલ ગ્રાન્ટ	૩૬૨
	વઢવાણ તાલુકામાંથી બાંધકામના પત્થરની રોયલ્ટી ચોરી અંગે દંડ	૧૩૮
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની નગરપાલિકાઓને વાજપાઇ નગર વિકાસ યોજનાનો બીજો હપ્તો ચૂકવવા બાબત	૩૯૨
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી મળી આવેલ બિનવારસી લાશો	૧૦૨
ધનસુખભાઇ ના. પટેલ	રાજ્યમાં જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ ગામો	૧૪૮
	ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)(સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૬૯
	નગરપાલિકાઓમાં વહીવટદારની નિમણુંક	૩૬૩
	રાજ્ય સરકારના દેવસ્થાનો પાછળ ફાળવેલ રકમ	૨૩૯
	સુરત જિલ્લા અને શહેરમાં કોર્ટોના મકાનો	૨૧૦
	સુરત જિલ્લા અને શહેરમાં પાસા હેઠળ અટકાયત	૧૧૨

	વિષય	પાના નંબર
ધારશીભાઇ લ.ખાનપુરા	બનાસ નદીમાં નર્મદાનું પાણી આપવા અંગે	૧૩૫
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં માર્ગ અકસ્માતો	૯૭
ધીરૂભાઇ હ. ગજેરા	અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અનેરાજકોટ શહેર તથા જિલ્લામાંથી પકડાયેલા ઘાતક શસ્ત્રો	૧૦૭
	અમરેલી શહેર અને રાજકોટ શહેરમાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ	૩૬૯
	ગાંધીનગર ખાતે વિવિધ કેટેગરીના ખાલી મકાનો	૩૯૮
	જસ્ટીસશ્રી આર.જે. શાહ સમિતિની કામગીરી	૨૪૬
	નર્મદા યોજનાના ભાગીદાર રાજ્યો પાસેથી લેણી રકમ	૧૪૪
	બી. એડ. અને બી. પી. એડ. ના અભ્યાસક્રમોના નિયમો અંગે	૨૫૯
	લખતર ખાતેની ફાર્મસી કોલેજ પુનઃ શરૂ કરવાનું આયોજન	૨૨૧
નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર	ખેડા જિલ્લાના મહુધા અને નડિયાદ તાલુકાના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ડોક્ટર, નર્સની ખાલી જગ્યાઓ	૩૯૯
	નડીયાદ તાલુકાના આલજડા ગામે શેઢી નદી ઉપરના પુલનું કામ	૩૭૦
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૮
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૭
	રાજયમાં પી.એસ.આઈ., પી.આઈ. અને ડી.એસ.પી. ની ખાલી જગ્યાઓ	૫૬
	રાજ્ય સરકાર દ્વારા લીધેલ ઓવરડ્રાફ્ટ	૨૦૬
નરેન્દ્રભાઈ મોદી	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૩૬
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૨૬૧
નરેશકુમાર મી.કનોડિયા	ઉમજ ગામથી વણછરા ગામને જોડતાં ઢાઢર નદી ઉપરનો પુલ	૪૧૩
	કરજણ અને શિનોર તાલુકાના પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોનું સેટઅપ	૨૦૭

	વિષય	પાના નંબર
નરેશકુમાર મી.કનોડિયા	કરજણ અને શિનોર તાલુકાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ	૨૩૬
	કરજણ તાલુકાના કરજણનગરમાં રેલ્વેનો ઓવરબ્રીજ ખંડિત થવા બાબત	૩૫૯
	ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ સમીટ ૨૦૦૫માં થયેલ એમ.ઓ.યુ. બાબત	૮૩
	પ્રજા અને પોલીસ વચ્ચે સહકાર અને માહિતીના આદાન પ્રદાન માટે લોક દરબાર	૧૫૦
	રાજ્યમાં ઓદ્યોગિક મૂડી રોકાણની દરખાસ્તો	૧૨૦
	શિનોર તાલુકાના દરિયાપુરા ગામ અને રાજપીપળા તાલુકાના નરખડી ગામને જોડતા પુલ ઉપર ડામર કામ	૩૮૯
નારાયણભાઈ લ. પટેલ	આયુર્વેદ દવાઓનું ઉત્પાદન કરતા એકમો બંધ થવા બાબત	૩૫૬
	પાટણ તાલુકાના સાંપ્રા ગામે યુવાન ખેડૂતોના ખૂન અંગે	૪૨૩
	મહેસાણા જિલ્લામાં ઘરફોડ ચોરીના બનાવો	૧૩૩
	રાજ્યમાં સીધી ભરતીની પી. એસ.આઈ. ની ખાલી જગ્યાઓ	૯૫
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૨
નીમાબેન આચાર્ય	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૩
પરસોત્તમભાઈ ઓ.સોલંકી	જયોતિગ્રામ યોજના હેઠળ ભાવનગર જિલ્લાના ગામોનો સમાવેશ	૧૫૧
	ભાવનગર જિલ્લાના અલંગ અને મણાર ખાતે જી.આઈ.ડી.સી. નહી બનાવવા બાબત	૧૨૨
	ભાવનગર જિલ્લામાં ડીટેઈન કરેલા વાહનો અને દંડ	૭૭
	ભાવનગર જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળામાં નબળા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવા અંગે	૨૩૯
	ભાવનગર જીલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઘટ અંગે	૨૧૦
	રાજ્યમાં એઈડઝના દર્દીઓ	૩૬૫
	શાળા આરોગ્ય ચકાસણી હેઠળ બાળકોના આરોગ્યની તપાસ	૩૯૫
પરેશભાઇ ધી. ધાનાણી	અધિકારી/કર્મચારીઓને કર્મયોગીની તાલીમ	૧૩૪

	વિષય	પાના નંબર
પરેશભાઇ ધી. ધાનાણી	અમરેલી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખૂન, લૂંટ, બળાત્કાર અને આત્મહત્યાના બનાવો	૧૫૬
	નાણા પંચ દ્વારા ફાળવેલ તેમજ વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટ	૨૪૨
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૮
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૪
	રાજ્યની માથાદીઠ આવક અને દેવું	૨૧૬
	રાજ્યમાં ખૂન, લૂંટ, ચોરી અને આત્મહત્યાના બનાવો	૯૬
	રાજ્યમાં જિલ્લાવાર એચ.આઈ.વી ના દર્દીઓ	૩૯૦
	સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬નું વર્ષ શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવવા બાબત	૩૬૦
પરેશભાઈ ગો.વસાવા	મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર દ્વારા ખરીદેલ દવાઓ અને સાધનો	૩૪૬
પુંજાભાઇ ભી. વંશ	ઉના તાલુકામાં દેશી તથા વિદેશી દારુ પકડવા અંગે	૧૨૧
	જુનાગઢ જિલ્લાની ઉના રેફરલ હોસ્પિટલમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ	૩૫૬
	જુનાગઢ જિલ્લામાં આઈ.સી. ડી. એસ. બ્લોક ખાનગી સંસ્થાને સોંપવા અંગે	૨૨૯
	જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી મનોરંજન કરની વસૂલાત	૧૫૦
	બંદર વિકાસ નીતિ અન્વયે બંદરો વિકસાવવાનું આયોજન	૭૫
	ભાવનગર જિલ્લાના વરતેજથી બુધેલ સુધીનો રસ્તો બિસ્માર હાલતમાં હોવા બાબત	૩૮૮
	માર્ગ અને મકાન વિભાગના કેન્દ્ર સરકાર સાથેના પડતર પ્રશ્નો	૪૧૧
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૧
	રાજ્યમાં માથાદીઠ આવક અને દેવું	૨૦૨
	શબ્દો રદ કરવા અંગે	૩૨૯
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૭

	વિષય	પાના નંબર
પુનમ ર. પરમાર	પોલીસ દળને ચુસ્ત રાખવા માટેની નવી તાલિમ સંસ્થાઓ સ્થાપવા અંગે	૮૭
	ભૂકંપગ્રસ્ત શહેરોમાં પુનઃ વસવાટ માટે હાથ ધરેલ કામો	૪૧૫
	મહાનગરપાલિકાઓમાં ઇ-ગર્વનન્સ પ્રથા અપનાવવા બાબતે	૩૭૦
	રમત ગમત ક્ષેત્રે મહિલાઓની સિદ્ધિઓ	૧૯૫
	સાબરમતી શુધ્ધિકરણ યોજના	૩૯૯
પુનાભાઈ ધે. ગામીત	ઉદ્યોગોના ગંદા પાણીને શુદ્ધ કરવાના પ્રોજેકટ માટે અમેરિકન કંપની સાથે કરાર	૧૨૫
	ડૂબત નિધિ હેઠળ મૂકેલ રકમો અંગે	૨૧૭
	રાજ્ય સરકાર ધ્વારા લઘુઉદ્યોગકારોને સબસીડીમાં કાપ	૮૮
	વ્યારા તાલુકાના ચાકધરા ગામથી સરા-કેવડીનો બિસ્માર રસ્તો	૩૫૯
પોપટભાઈ સ. જીંજરિયા	ચોટીલા અને સાયલા તાલુકામાં મંજૂર થયેલા ૬૬ કે.વી. સબસ્ટેશનો	૧૦૪
	ચોટીલા આણંદપુર રોડ બિસ્માર હાલતમાં હોવા બાબત	૩૯૭
	ચોટીલા સાયલા તાલુકામાં રસ્તાના કામો થવા બાબત	૩૬૮
	રાજય સરકાર દ્વારા લીધેલ ઓવર ડ્રાફ્ટ	૨૫૩
	રાજ્ય સરકારનું આંતરિક અને બાહ્ય દેવું	૨૩૩
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સેલ્સટેક્ષની આવક અને ચોરીના કેસ	૨૦૪
પ્રદિપસિંહ ભ.જાડેજા	અમદાવાદ શહેરમાં સી. એન. જી. સ્ટેશનો	૯૦
	પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ ઓછું હોવા બાબત	૪૧૦
	મધ્યસ્થ ઔષધ ભંડાર તંત્ર દ્વારા ખરીદેલ દવાઓની ગુણવતા બાબત	૩૮૭
	રાજ્યને પેટ્રોકેપિટલ બનાવવાનું આયોજન	૧૨૭
	સાબરમતી શુધ્ધિકરણ યોજના	૩૫૫
	સાયન્સસીટી ખાતે યોજાયેલ વિજ્ઞાન મેળો	૨૧૧
પ્રબોધકાંત દા.પંડયા	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૦૬
પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૧

	વિષય	પાના નંબર
પ્રવિણભાઈ ટી. મારૂ	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૫
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૯
પ્રવિણભાઈ મો.માકડિયા	ઉપલેટા કોટેજ હોસ્પિટલમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ	૩૯૧
	યાત્રાધામ વિકાસ માટે બ્લ્યુ પ્રિન્ટ	૧૯૩
	રાજકોટ જિલ્લામાં વેચાણ ખાતાના દરોડા અંગે	૨૩૦
	રાજકોટ-ભાવનગર શહેરમાં ચક્ષુ બેંક શરૂ કરવા બાબત	૩૬૨
	રાજ્યમાંથી જાલી નોટો પકડવાના કેસો	૧૨૧
	હિન્દુ કન્યાઓને અન્ય ધર્મના લોકો દ્વારા ઉઠાવી જવાના કિસ્સા	૮૩
પ્રાગજીભાઈ ના. પટેલ	"બાયસેગ" પ્રવૃત્તિઓ અને વિકાસનું આયોજન	૧૪૯
	કન્યા કેળવણી નિધિમાં જમા થયેલ ભંડોળ	૨૩૧
	જીસ્વાન દ્વારા જોડાયેલી તાલુકાની કચેરીઓ	૧૧૮
	માંડલ તાલુકામાં પંચાયત તેમજ ગૌચરની જમીન ઉપર વનીકરણ	૩૯૫
	માંડલ, દેત્રોજ અને વિરમગામ તાલુકામાં વન વિભાગની આરક્ષિત જમીન	૩૬૬
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૦
	રાજયમાં કન્યા કેળવણી રથયાત્રા દરમ્યાન મળેલ પ્રવેશ	૧૯૭
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૧૭
	રાજ્યમાં એઇડઝના દર્દીઓ	૪૧૪
	વિરમગામ, દેત્રોજ અને માંડલ તાલુકામાં જયોતિગ્રામ યોજનામાં સમાવિષ્ટ ગામો	૫૪
ફતેસિંહ વ.ચૌહાણ	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૫૦
બલવંતસિંહ ચં.રાજપૂત	ગુટકાના સેવનથી નોંધાયેલા કેન્સરના કેસો	૩૭૩
	પાટણ જિલ્લામાં વિધવા મહિલાઓને બાકી પેન્શનની ચૂકવણી	૨૫૪
	માર્ગ-પુલના વિકાસ માટે વિશ્વબેન્કની સહાય	૪૨૧

	વિષય	પાના નંબર
બલવંતસિંહ ચં.રાજપૂત	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૨૯
	રાજ્ય સરકાર દ્વારા લીધેલ ઓવરડ્રાફ્ટ	૨૦૫
	રાજ્યની શાળાઓમાં શિક્ષકો અને ઓરડાઓની ઘટ	૨૩૪
	રાજ્યમાં વીજ માંગ અને વીજ ઉત્પાદન	૧૪૬
	વૈશ્વિક મૂડી રોકાણ વધારવા માટે રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓનો વિદેશ પ્રવાસ	૧૦૯
	સિધ્ધપુર શહેરના બિંદુ સરોવરના રેલ્વે ફાટકના એપ્રોચ રોડનું બાંધકામ	૪૦૦
બળદેવજી ચં.ઠાકોર	કડી તાલુકામાં જોબ નંબરો	૩૩૫
	કડી તાલુકામાં દારુના અડ્ડાઓ ઉપર દરોડા	૧૩૨
	કડી તાલુકામાં વેચાણવેરાની કરચોરી	૨૫૮
	કડી તાલુકામાં રાજ્ય સરકાર હસ્તકના દેવસ્થાનો	૨૧૬
	ખાનગી એકમો પાસેથી વીજળીની ખરીદી કરવા બાબત	૯૪
	પ્રાથમિક શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ	૨૪૩
	સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં કર્મચારીઓ દ્વારા બેદરકારી દાખવવા બાબતે થયેલ ફરિયાદ	૩૭૭
બાબુભાઈ મે. શાહ	ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)(સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૬૯
	ભચાઉ શહેરમાં પ્લાન પાસ માટે લેવામાં આવતી રકમ	૪૧૫
	ભારત સ્ટેમ્પ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક ૨૦૦૫	૨૭૪
	રાજ્યના ભૂકંપગ્રસ્ત વિસ્તાર માટે જમા થયેલ રકમ અને વ્યાજ	૨૩૫
	રાહતો આપેલ એકમો પૈકી ગ્રામ વિકાસના એકમોએ ભરેલ રકમ અંગે	૨૦૫
	લાકડીયા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું વાહન પાછું લઈ લેવા બાબત	૩૯૮
	વેચાણવેરાની માફી અંગેના એકમો	૨૫૫
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૧
	સોનગઢની સેન્ટ્રલ પેપરમીલનો કરાર	૩૬૯
બિમલ શાહ	જિલ્લાની સરકારી હોસ્પિટલોમાં રોગી કલ્યાણ સમિતિ બનાવવા બાબત	૪૦૯

	વિષય	પાના નંબર
બિમલ શાહ	નર્મદાની ઊંચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં રાજ્યને થનાર લાભ	૮૫
	રાજયમાં ૧૦ ટકા થી ઓછા પરિણામવાળી માધ્યમિક શાળાઓ	૨૦૯
	રાજ્યની શાળાના વિદ્યાર્થીઓને મફત પાઠ્યપુસ્તકો પૂરા પાડવા અંગે	૨૩૯
	રાજ્યમાં નવા આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવા બાબત	૩૮૫
	રાજ્યમાં લુપ્ત થતી આયુર્વેદ ઔષધિઓ	૩૫૩
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૭
	સરદાર સરોવર ડેમની ૧૨૧.૯૨ મીટરની ઉંચાઈએ સાથી રાજ્યોને લાભ	૧૨૩
	સરદાર સરોવર બંધની ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઊચાઇએ રાજયને લાભ	૧૫૨
ભરત બારોટ	ગુડાની વિકાસ યોજનાઓ	૪૦૦
	નર્મદા બંધની ૧૨૧.૯૨ મીટરની ઊંચાઈએ થનાર લાભ	૧૧૯
	ભૂકંપગ્રસ્ત શહેરોમાં પુનઃ વસનની ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપની દ્વારા કાયર્વાહી	૩૭૩
	રાજ્યમાં ગરબા મહોત્સવના આયોજન	૨૫૮
	રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી સ્પર્ધા	૨૪૨
	સરકારી ગ્રંથાલયો કોમ્પ્યુટરાઈઝડ કરવા અંગે	૨૧૫
	સરદાર સરોવર ડેમની ૧૨૧.૯૨ મીટરની ઊંચાઈએ સાથી રાજ્યોને લાભ	૮૨
ભરતભાઈ પંડયા	ધંધુકા રેફરલ હોસ્પિટલમાં ગાયનેક અને ઓર્થોપેડિક ડોકટરની ખાલી જગ્યા	૩૮૫
	ધંધુકા, રાણપુર અને બરવાળા તાલુકાની વનીકરણ માટે સોંપેલ જમીન	૩૫૩
	ધોલેરા બંદર વિકસાવવાનો પ્રોજેકટ	૧૦૫
	બરવાળાને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જાહેર કરવા બાબત	૪૦૯
ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ	ખાનગી શાળાઓમાં કન્યાઓ પાસેથી લેવાતી ગેરકાનૂની ફી	૨૨૫
	બાલાસડી સૈનિક સ્કૂલ જામનગર ખાતે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લેવાતી ફી	૨૪૮

	વિષય	પાના નંબર
ભવાનભાઈ જી. ભરવાડ	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૫
	લીંબડી તાલુકામાં રોડ રીપેર કરવા બાબત	૩૭૩
	લીંબડી શહેરમાં દારુના અડ્ડાઓ અંગે મળેલ ફરિયાદો	૧૩૧
	લીંબડી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ	૪૨૧
	લીંબડી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સીટી સ્કેન સોનોગ્રાફીના બંધ હાલતમાં સાધનો	૪૦૧
	સરકારની તાલીમ સંસ્થા હોવા છતાં કર્મયોગીની તાલીમનો કોન્ટ્રાક્ટ બીજી સંસ્થાને આપવા બાબત	૯૪
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઘટ	૧૮૫
ભાવિનભાઈ ન.શેઠ	ગીરના જંગલોમાં સિંહની વસ્તી	૩૯૧
	સાબરમતી શુધ્ધિકરણ યોજના	૩૬૨
ભીખાભાઈ ગ. જોષી	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૯
ભૂપેન્દ્ર ગ. લાખાવાલા	બાળકોની વિમા સુરક્ષાની યોજના અંગે	૨૨૧
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેનાઆભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૩૧
મંગુભાઈ છ. પટેલ	રાષ્ટ્રીય પક્ષીની ક્રૂર હત્યા કરવા અંગે	૨૬૨
મધુભાઈ બા.શ્રીવાસ્તવ	આંગણવાડી કાર્યકરોને તાલીમ	૨૧૫
	ગુડા વિસ્તારમાં નગર રચના યોજનાઓ	૩૭૬
	ગુડાની વિકાસ યોજનાઓ	૩૩૩
	ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરીના આધુનિકરણની યોજના	૯૯
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૪
	રાજ્યમાથી મીઠાની નિકાસ	૧૩૭
	રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સિસ્ટમ	૪૦૪
મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા	ટ્રેકટરને ગાડાનો દરજજો આપવા અંગે	૫૫
	થ્રી વ્હીલ ટેમ્પોરીક્ષામાં પેસેન્જર બેસાડવાની મંજૂરી	૧૧૮
	પવિત્ર યાત્રાધામ પાલીતાણા પાછળ કરેલ ખર્ચ અંગે	૨૨૪
	પાલીતાણાની માનસિંહજી હોસ્પિટલમાં ડોકટરોની ખાલી જગ્યા	૩૭૬

	વિષય	પાના નંબર
મનસુખભાઈ લ. માંડવિયા	ફિઝીયોથેરાપીના અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા બાબત	૪૦૪
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૨૮
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેનાઆભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૨૯
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૮
મનહરલાલ મ.મકવાણા	દસાડા અને લખતર તાલુકામાં જી.આઈ.ડી.સી. સ્થાપવાની કામગીરી	૯૯
	દસાડા અને લખતર તાલુકામાં ટેન્ડર વગર રસ્તાના કામો	૩૪૯
	રાજ્યમાં ખાનગી માધ્યમિક સંસ્થાઓને મંજૂરી	૨૦૫
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર અને દસાડા તાલુકામાં પ્રાથમિક શિક્ષકો દ્વારા હેડકવાર્ટરમાં ન રહેવા બાબત	૨૩૩
મનીષ ન. ગીલીટવાલા	કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના અન્વયે વિદેશી લોનો, બહારનું અનુદાનના વ્યાજ અંગે	૨૦૪
	સુરત શહેરમાં ખૂન, બળાત્કાર, અને આત્મહત્યાના બનાવો	૧૪૬
	સુરત શહેરમાં મંજૂર અને ખાલી પોલીસ મહેકમ	૧૦૮
	સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં એમ્બ્યુલન્સ તથા ડ્રાઈવરની સંખ્યા	૩૭૬
	સુરતની નવી સીવીલ હોસ્પિટલમાં તબીબી અધિક્ષકની ખાલી જગ્યા	૪૨૨
	સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચોથા વર્ગની ખાલી જગ્યાઓ	૪૦૩
મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી	બી.એડ. થયેલા ઉમેદવારને વિદ્યા સહાયકની જગ્યા પર નિમણુંક	૨૪૭
	ભાવનગર જિલ્લામાં લૂંટના નોંધાયેલ ગુનાઓ	૧૩૩
	ભાવનગર જિલ્લામાં સામુહિક આત્મહત્યાના બનાવો	૯૬
	ભાવનગર શહેરમાં ટ્રાફીક અડચણના કેસો	૧૫૫
	ભાવનગરથી વડોદરા ધોલેરા ટૂંકા માર્ગને નેશનલ હાઈવેમાં સમાવેશ કરવા બાબત	૩૬૫

	વિષય	**પાના નંબર**
મહેન્દ્ર શાં. ત્રિવેદી	ભાવનગરની મેડીકલ કોલેજના પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન માટેના અભ્યાસક્રમો	૩૯૪
	ભાવનગરમાં ટાઉન પ્લાનીંગ ઓફિસરની ખાલી જગ્યા	૪૧૪
	રાજ્યમાં સંપૂર્ણ સાક્ષરતા અભિયાન હેઠળના જીલ્લાઓ	૨૨૩
	વિધવા મહિલાઓને રોજગારની તાલીમ આપવા અંગે	૨૬૦
મહેશભાઇ સો.ભુરિયા	એસ.ટી.ની સમાંતર ગેરકાયદે ચાલતા પરિવહન અંગે વસૂલ આવેલ દંડ	૧૩૮
	દાહોદ જિલ્લા પોલીસ સંવર્ગવાર મહેકમ અને ખાલી જગ્યાઓ	૧૦૦
	દાહોદ જિલ્લામાં પ્રોહીબીશન એક્ટ હેઠળ થયેલા કેસો	૧૫૮
મહેશભાઈ છો. વસાવા	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૨૨
માધાભાઈ લા. બોરીચા	૧૨૧.૯૨ મીટર સુધી નર્મદા ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરીની પ્રક્રિયા	૮૬
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૩
	રાજયમાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવા બાબત	૩૪૩
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૨૧
માધુભાઈ જે. ભોયે	ડાંગ જિલ્લામાં માલિકીના વૃક્ષો કાપવા બાબત	૩૮૭
	ડાંગ, વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં શાળાના વર્ગો વધારવાની મંજૂરી	૨૧૭
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૬
	રાંધણ ગેસના વેચાણવેરા પેટે થયેલ આવક	૨૪૪
	વઘઈ ખાતે આવેલ આર.ટી.ઓ. ચેકપોસ્ટમાં થયેલી આવક	૭૮
	વાંસદાથી સાપુતારા સુધીનો રાજ્ય ધોરી માર્ગ વચ્ચેના ભયજનક વળાંકો દુર કરવા બાબત	૪૧૧
	સોનગઢ પેપર મીલ્સને વાંસ કાપવાની પરવાનગી	૩૫૬

	વિષય	પાના નંબર
માયાબેન સુ.કોડનાની	અમદાવાદ શહેરમાં પ્રદૂષણ ઘટાડવા એકશન પ્લાન	૩૬૪
	અમદાવાદમાં નેશનલ સ્લમ ડેવલપમેન્ટ યોજના અંતર્ગત પાયાની સુવિધાઓ	૪૧૩
	આરોગ્ય કેન્દ્રોને ટેલીમેડીસીન્સથી જોડવા બાબત	૩૯૪
	ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ સમીટ-૨૦૦૪ના આયોજન દરમ્યાન થયેલા એમ.ઓ.યુ.	૧૧૯
	તોશાખાનામાં જમા થયેલ ચીજ વસ્તુઓની કન્યા કેળવણી પાછળ કરેલ ખર્ચ અંગે	૨૪૧
	ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટો દ્વારા નિકાલ થયેલ કેસો	૨૫૮
	રાજ્યના ધાર્મિક સ્થાનો પાછળ કરેલ ખર્ચ	૨૧૨
	રાજ્યમાં મહિલાઓને લગતા વિવિધ ગુનાઓ બાબત	૮૧
માલજીભાઈ દે. દેસાઈ	મોટપ ગામ નજીક રૂપેણ નદીના છેડાનો રોડ અધૂરો હોવા બાબત	૩૭૭
	રાજયમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું ઓછું પ્રમાણ	૩૩૬
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૩
મુકેશ ભૈ. ગઢવી	કન્યા કેળવણી રથયાત્રામાં થયેલ ખર્ચ અને મળેલ સૂચનો	૨૨૩
	જિલ્લાની સરકારી હોસ્પિટલમાં રોગી કલ્યાણ સમિતિ બનાવવા બાબત	૩૪૬
	દાંતા, અમીરગઢ અને પાલનપુર તાલુકાની શાળાઓમાં નવીન ઓરડાઓ	૨૪૭
	પાલનપુર શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખીત ફરિયાદો પરથી દાખલ થયેલા ગુના	૯૨
	પાલનપુર શહેરમાં ચોરીના બનાવો	૧૨૯
	બાલારામ-અંબાજી અભયારણ્યનું વ્યવસ્થાપન	૪૦૫
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૩૯
	સ્વચ્છ ગુજરાત સમરસ ગુજરાત અભિયાન અંતર્ગત "સ્વચ્છતા જયોત મેરેથોન દોડ"	૩૮૦
મુળુભાઈ હ. બેરા	"સ્વાગત કાર્યક્રમ" માં મળેલ પ્રશ્નો અને નિકાલ	૧૪૭

	વિષય	પાના નંબર
મુળુભાઈ હ. બેરા	ઓખા અને બેટ દ્વારકા વચ્ચે પુલ બાંધવા અંગે	૧૬૧
	જામનગર જિલ્લાના સ્મારકોની જાળવણી અંગે	૨૦૩
	જામનગર જિલ્લામાં વડાપ્રધાનશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી બનાવેલ શાળાઓ	૨૩૨
	જામનગર જિલ્લામાં વિધાદીપ યોજનાના લાભાર્થીઓ	૨૫૨
	જામનગરની જી. જી. હોસ્પિટલમાં ન્યુરોસર્જનની ખાલી જગ્યા	૩૮૯
	જી. જી. હોસ્પિટલ, જામનગરમાં સીટી સ્કેન મશીન બંધ હોવા બાબત	૩૫૮
	બરડા અભ્યારણ માટે સંપાદન કરવામાં આવેલ જમીન	૪૧૩
	વાડીનાર બંદરને કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટમાંથી મુકત કરવા કેન્દ્ર સરકારમાં રજૂઆત	૧૧૦
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૯
મોહંમદફારુક હુ.શેખ	અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નરનીહકુમત હેઠળના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલાવિવિધ ગુના	૧૨૬
	અમદાવાદ શહેરની શાળાઓમાં ડોનેશનની ફરિયાદો	૨૦૮
	અમદાવાદ શહેરમાં ક્રિકેટ અને બીજી રમતોના સટ્ટાઓ રમવા અંગે ધરપકડ કરવા બાબત	૧૫૩
	અમદાવાદ શહેરમાં સેલ્સટેક્ષના ખોટા નંબરો અંગે	૨૩૮
	અમદાવાદ શહેરમાં સોનાના દોરાની ચીલ ઝડપના નોંધાયેલા બનાવો	૮૯
	અમદાવાદમાં ૧૮ વર્ષની ઉંમરથી નીચેના બાળકોને તમાકુ ગુટકાના વેચાણ બદલ થયેલા કેસો	૩૮૦
	શૈક્ષિણક સંસ્થાઓના ૨૦૦ મીટરમાં ગુટકાનું વેચાણ અટકાવવા બાબત	૩૪૬
મોહનભાઇ ક. કુંડારીયા	પડધરી તાલુકાના નારણકા ગામ પાસે આજી નદી ઉપર પુલ બનાવવા બાબત	૩૯૧

	વિષય	પાના નંબર
મોહનભાઇ ક. કુંડારીયા	મોરબી સિરામીક ઉદ્યોગ વિસ્તારમાં લૅબૉરેટરી ઊભી કરવા અંગે	૭૯
	રાજકોટ જિલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર બાજપાઇ સ્વરોજગાર યોજના અન્વયે મળેલ અરજીઓ	૧૪૯
	રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી, ટંકારા અને મોરબી તાલુકામાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાના રસ્તા	૩૬૧
	રાજકોટ જિલ્લાના પેન્શનના બાકી પડતર કેસો	૧૯૪
	રાજકોટ જિલ્લાના પેન્શનપાત્ર કર્મચારીઓને સમયસર પેન્શન ન ચૂકવવા અંગે	૨૩૦
	રાજકોટ જિલ્લામાં ઉદ્યોગોને ચૂકવવાની સબસીડી	૧૧૩
	રાજય સરકારને થયેલ આવક અને વહીવટી ખર્ચ	૨૫૧
મોહનભાઇ ધ. ઢોડિયા	નર્મદા નહેરના પાણીનોશિસ્તપૂર્વક લઘુતમ વપરાશ કરવાનું આયોજન	૧૫૨
	નર્મદા નહેરમાં ડૂબવાના બનાવો અટકાવવા બાબત	૧૨૪
	નર્મદા યોજનામાં જમીન સંપાદનની કાર્યવાહી ઝડપી બનાવવા પગલાં	૮૭
	ફિઝીયોથેરાપીના અનુસ્નાતક અભ્યાસ ક્રમ શરૂ કરવા બાબત	૩૬૬
યોગેશભાઈ ના. પટેલ	કેનાલ ડેમ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન	૧૩૧
	મહિલાઓ માટે સ્વરક્ષણ યોજના	૨૩૬
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૪
	રમતગમત ક્ષેત્રે આપવામાં આવતા એવોર્ડ	૨૦૭
	વડોદરા શહેરમાં વિધવા મહિલા સહાયની ચૂકવણી અંગે	૨૫૭
	સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની કામગીરી સમયસર થવા બાબત	૯૩
રતિલાલ ગો. સુરેજા	ચોમાસા દરમ્યાન નર્મદા બંધમાંથી પાણીનો ઓવરફલો	૧૪૩
	શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સંસ્થાનું સર્વેક્ષણ	૩૬૧

	વિષય	પાના નંબર
રતિલાલ ગો. સુરેજા	સરદાર સરોવર યોજના વિદ્યુત મથકોની ક્ષમતા	૧૦૬
રમણલાલ ઈ. વોરા	મુંબઈ મજૂર કલ્યાણ ફંડ (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૦૫.	૨૯૧
રમીલાબેન બે. બારા	"સ્વાગત કાર્યક્રમ" માં મળેલ પ્રશ્નો અને નિકાલ	૧૬૩
	રાજ્યમાં કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે તાલીમની જોગવાઈ બાબત	૧૧૩
	રાજ્યમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું ઓછું પ્રમાણ	૩૭૫
	રાજ્યમાં વસ્તી આયોગની રચના	૪૦૩
	વી-ગવર્નન્સ તાલીમના પરિણામો	૧૪૮
	શાળાના નબળા વિદ્યાર્થીઓને સારૂ શિક્ષણ આપવા અંગે	૨૨૨
રમીલાબેન રા. દેસાઈ	ઉમતા-જાસ્કા, હિરવાણી, પીલુયા રોડની તાંત્રિક મંજૂરી	૪૦૮
	ખળી ચાર રસ્તાથી રામપુરા સુધીના રોડને ડામર સપાટી કરવા બાબત	૩૮૩
	ગોઠડા ગામના સર્વે નંબર ૧૦૪/૨૧થી ૧૦૪/૨૪નો એવોર્ડ આપવા બાબત	૩૫૨
	સતલાસણા તાલુકા મથકે કોર્ટની સુવિધા	૨૨૪
	સતલાસણા સબ ટ્રેઝરી કાર્યરત કરવા અંગે	૨૪૮
રમેશભાઈ ના.મિસ્ત્રી	ભરૂચની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સિવિલ સર્જનની ખાલી જગ્યા	૩૬૭
રશીદા ઈ. પટેલ	ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમીત, ૨૦૦૫નો ખર્ચ	૧૫૦
	તમાકુ યુક્ત ગુટખા પાઉચ પેકિંગ ઉપર સુખ સુવિધા કરની આવક	૨૨૪
	ભરુચ જિલ્લામાં ડામર સપાટીવાળા બાકી ગામો	૩૮૮
	ભરૂચ જિલ્લામાં ટ્રાયબલ સબ પ્લાન હેઠળની ગ્રાન્ટ	૩૫૭
	ભરૂચ જીલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઘટ	૨૬૦
	રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં આચાર્ય તેમજ પ્રાધ્યાપકોની ખાલી જગાઓ	૨૪૮
	રાજ્યમાં વીજ માંગ અને વીજ ઉત્પાદન	૧૨૦
	વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ-૨૦૦૫ હેઠળ થયેલા એમ.ઓ.યુ.	૫૯

	વિષય	પાના નંબર
રાકેશ રાવ	ખેડા અને માતર તાલુકામાં રસ્તાઓ રીપેર કરવા બાબત	૩૭૪
	ખેડા તાલુકાના કલોલી તથા શ્રીજીપુરા ગામે નાના પુલ બનાવવા બાબત	૪૦૧
	રાજ્યમાં વિદેશ મોકલવાના નામે છેતરપીંડીના બનાવો	૧૦૨
રાજેન્દ્રસિંહ ધી.પરમાર	આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ આવરી લીધેલાં ગામો	૧૧૧
	આણંદ જિલ્લામાં ડામર સપાટી વગરના રસ્તા	૩૯૩
	આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વિધવા મહિલા લાભાર્થીઓ	૨૩૪
	આણંદ જિલ્લામાં નિરંતર શિક્ષણ યોજના હેઠળ ખરીદી	૨૦૫
	નવા સચિવાલયમાં ઉર્જા બચાવવા નવીન ટ્યુબલાઈટો નાખવા બાબત	૩૬૩
રાજેશભાઈ પાઠક	નર્મદાની મહેમદાવાદ શાખાની કામગીરી	૧૧૦
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૬
લક્ષ્મણભાઈ બા. પટેલ	પારડી તાલુકાના ઉદવાડાથી રોહિણા ધગડમાળ માર્ગને પેવર કામ કરવા	૩૭૯
	પારડી તાલુકાના રોહીણા, સાદડવેરી, સુખલાવ રસ્તાને જોબવર્ક આપવા બાબત.	૩૪૩
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૫૧
	વલસાડ જિલ્લામાં કેળવણી નિરીક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ.	૧૯૬
વજુભાઇ પ. ડોડિયા	અમદાવાદ શહેરમાંથી આતંકવાદ ધારા હેઠળ નોંધવામાં આવેલા કેસો	૧૦૬
	રાજ્યમાં પોલીસ અનામત દળનો વધારો કરવા અંગે	૧૬૦
	લુણાવાડા તાલુકાના પાકા એપ્રોચ રોડથી વંચિત ગામો	૩૪૨
	વિજ્ઞાનપ્રવાહનું ઓછું મેરીટ હોવાથી વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંકમાં થતા અન્યાય અંગે	૨૨૨

	વિષય	પાના નંબર
વજુભાઇ પ. ડોડિયા	વિરમગામ તાલુકામાં સોકલીથી જાલમપુરા નર્મદા પેટા કેનાલનું કામ	૧૪૩
	વિરમગામ-માંડલ અને દસાડાતાલુકામાં નીલગાય, હરણ દ્વારા ખેડૂતોના પાકને નુકશાન	૪૦૫
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૪
	સાણંદ અને વિરમગામ તાલુકાના એપ્રોચ રોડથી વંચિત ગામો	૩૭૯
વજુભાઈ વાળા	અંદાજપત્રની રજૂઆત	૧૬૫
	ખર્ચના પૂરક પત્રકની રજૂઆત	૧૬૫
	મુંબઈનો બિન-વ્યાપારી કોરપોરેશન (ગુજરાત રદ કરવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૦૫	૨૯૫
વેચાતભાઈ હ. બારિયા	અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપરથી અનૈતિક ધંધા હેઠળ મહિલાઓ પકડાવા અંગે	૫૮
	કોરનેટવર્ક સુવિધાઓ માટે માર્ગ અને મકાન વિભાગનું આયોજન	૩૫૨
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૪
	રાજ્યમાં મહેસૂલી ગામોને પાકા રસ્તાથી જોડવા બાબત	૩૮૪
શંકરભાઇ વી. રાઠવા	ઔદ્યોગિક નીતિ જાહેર કર્યા બાદ લીધેલાં પગલાં	૧૩૫
	ક્વાંટ અને છોટા ઉદેપુરમાં ખુનના બનાવો	૯૭
	છોટાઉદેપુરની રેફરલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરની ખાલી જગ્યા	૩૬૭
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૫૧
	વડોદરા જિલ્લાનો કવાંટ ભાખા રસ્તો બિસ્માર હોવા બાબત	૩૯૭
શંકરભાઈ દે. વાઘેલા	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૩
શંકરભાઈ લ. ચૌધરી	ગુજરાત સિનેમા (નિયમન)(સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૭૦
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ	૩૫

	વિષય	પાના નંબર
શંકરભાઈ લ. ચૌધરી	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૦૦
	રીવર બેડ પાવર હાઉસમાં વીજ ઉત્પાદન બાબત	૯૦
	શાળા આરોગ્ય ચકાસણી કાર્યક્રમ	૩૫૩
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૫૦
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૨૬૧
શિવજીભાઇ ક. આહીર	કચ્છ જિલ્લાના ભૂજ શહેરમાં મેડિકલ સ્ટોર્સનું ચેકિંગ કરવા બાબત	૪૧૨
	કચ્છ જિલ્લામાં ગાંડો બાવળ કાપવા છૂટછાટો આપવા બાબત	૩૫૭
	કચ્છ જિલ્લામાં ગૌવંશની હત્યા અંગે પાસા હેઠળ અટકાયત બાબત	૧૧૧
	કચ્છ જિલ્લામાં બંધ પડેલા બંદર વિકસાવવા આયોજન	૧૬૨
	કચ્છી સાહિત્ય અકાદમીની કામગીરી	૨૫૭
	પવિત્ર યાત્રાધામોમાં માંસ-ઈંડા- મચ્છી તથા માંસાહારી પદાર્થોના વેચાણનો પ્રતિબંધ	૨૦૭
	ભુજ તથા નખત્રાણા તાલુકામાં નીલગાય તથા ભૂંડ દ્વારા ખેતીના પાકને નુકશાન	૩૮૮
	મહિલા આયોગની રચના	૨૩૬
	રાષ્ટ્રીય પક્ષીની ક્રૂર હત્યા કરવા અંગે	૨૬૨
	વાયબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫ અન્વયે થયેલા એમ.ઓ.યુ.	૧૪૭
સાબીરભાઇ અ.ખેડાવાળા	અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક શાખા દ્વારા વસૂલ કરવામાં આવેલા દંડ	૧૫૩
	અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં આપઘાત, ખૂન અને લૂંટના બનાવો	૧૨૫
	અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કંપાઉન્ડમાં રાહત દરે ચાલતી દવાની દુકાન બંધ થવા બાબત	૪૦૭
	અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગરીબ દર્દીઓને ફી માફી આપવા બાબત	૩૫૦
	ધો-૮ના પુસ્તકમાં રહી ગયેલી ક્ષતિ	૨૨૭
	બાપુનગરની જનરલ હોસ્પિટલને ભૂકંપમાં થયેલ નુકશાન	૩૮૨
	રાજયમાં ઉર્દૂ શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ	૧૯૧

	વિષય	**પાના નંબર**
સાબીરભાઈ અ. ખેડાવાલા	રાજ્યમાં "પોટા" હેઠળ ધરપકડ બાબત	૮૯
	વેટ કાયદાના અમલ અન્વયે વેચાણવેરાની આવકમાં થનાર વધઘટ	૨૫૦
સી. જે. ચાવડા	કર્મયોગી તાલીમ અંગે ખર્ચ	૮૬
	ગાંધીનગર અને ભાવનગર જિલ્લામાં રમત-ગમતના ખોટા સર્ટિફીકેટ મેળવી વિદ્યાસહાયકમાં થયેલ ભરતી	૨૦૮
	ગાંધીનગર તાલુકામાં પંચાયત અનેરાજ્ય હસ્તકના રોડને જોબનંબર આપવા બાબત	૩૬૩
	ગાંધીનગર તાલુકામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૩૯૩
	જી. એ. એસ. વર્ગનું કેડર શિડયુલ બહાર પાડવા બાબત	૧૨૩
	નોન ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને ગ્રાન્ટેબલ કરવા અંગેની પડતર અરજીઓ	૨૩૭
	રાજ્યપાલશ્રીના સંબોધન માટેનાઆભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (પહેલો દિવસ)	૩૩૦
સી. ડી. પટેલ	નર્મદા બંધની ઊંચાઈએ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં રાજ્યને થનાર લાભ	૧૦૭
	યોગાસનની પ્રવૃત્તિના પ્રચાર પ્રસાર અંગે	૨૨૩
	સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઇ ૧૨૧.૯૨ મીટર થતાં સાથી રાજ્યોને થનાર લાભ	૧૪૫
	સરદાર સરોવર બંધની ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઇએ રાજ્યને મળતો લાભ	૧૬૧
સી.જે.ચાવડા	કલ્પસર યોજનાનો ખર્ચ	૧૫૨
સુનીલ બા.ઓઝા	ઘોઘા તાલુકાના ગામ તગડીથી ભાવનગર તાલુકાના માલણકા ગામ સુધીનો રસ્તો રીપેર કરવા બાબત	૩૮૦
	ભાવનગર જિલ્લામાં નર્મદા નહેરોનું કામ શરૂ કરવા અંગે	૯૩
	ભાવનગર જિલ્લામાં ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ અંગે	૨૩૮
	ભાવનગર જિલ્લામાં દીપડો ધસી આવવા બાબત	૩૪૭
	વેચાણવેરાની ચોરી અટકાવવા ચેક પોસ્ટ દ્વારા મેળવેલ રકમ અંગે	૨૦૯
હરજીવન હી. પટેલ	અંબાજી મંદિરના ભંડારમાંથી ચોરીનો બનાવ	૨૦૦

	વિષય	પાના નંબર
હરજીવન હી. પટેલ	ધાનેરા તાલુકામાં સ્ટેટ અને પંચાયત હસ્તકના રોડને જોબ નંબર આપવા બાબત	૩૭૮
	નર્મદા બંધની ૧૨૧.૯૨ મીટરઊંચાઈએ રાજ્યને થનાર લાભ અંગે	૧૦૧
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ફેરવવા બાબત	૩૪૧
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૪૨
	શોકદર્શક ઉલ્લેખો	૨૬૧
	સરદાર સરોવર બંધની ૧૧૦.૬૪ મીટરની ઉંચાઇએ રાજ્યને મળતો લાભ	૧૫૯
	સરદાર સરોવર બંધની ૧૨૧.૯૨ મીટરની ઊંચાઇએ સાથી રાજ્યોને મળનાર લાભ	૧૩૮
હરેશકુમાર ઈ.ભટ્ટ	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૮
	રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (બીજો દિવસ)	૪૪૮
હેમાજી દ. રાજપૂત	ધારાસભ્યશ્રી ઉપર હુમલો કરી લૂંટ કરવાનો બનાવ	૧૦૭
	મુંબઈ નશાબંધી (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક,૨૦૦૫	૨૮૬
	વાવ-થરાદ તાલુકામાં નર્મદાનું ખેતી માટે પાણી આપવાનું આયોજન	૧૪૪